

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

ECONOMICS

- | | |
|--|--|
| 1 सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण की प्रविधि | डॉ. डी. पी. घाटे |
| 2 भारतीय बैंकिंग | डॉ. ए. बी. मिश्रा |
| 3 लोक वित्त | डॉ. डी. एन. गुट्टे |
| 4 माइक्रो इकोनामिक थ्योरी | डॉ. डी. एन. गुट्टे |
| 5 मैक्रो इकोनामिक थ्योरी | डॉ. डी. एन. गुट्टे |
| 6 अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र | डॉ. डी. एन. गुट्टे |
| 7 आर्थिक विकास के सिद्धान्त एवं भारत में आर्थिक नियोजन | प्रो. जी. एस. गुप्ता |
| 8 प्रमुख देशों की बैंकिंग प्रणालियाँ | प्रो. के. बी. सक्सेना |
| 9 सामग्री प्रबन्ध | प्रो. जे. आर. कुम्भट |
| 10 माइक्रो इकोनामिक थ्योरी | तेजा, शर्मा, गुप्ता |
| 11 आधुनिक आर्थिक सिद्धान्त | तेजा, शर्मा, गुप्ता |
| 12 इन्फ्लेशन, रकत एवं जायान का आर्थिक विकास | डॉ. चौधरी, डोपरी, शाह, मेहता, माथुर |
| 13 आर्थिक संगठन | डॉ. गणवान, कोचर, शाह |
| 14 कृषि अर्थशास्त्र के सिद्धान्त | प्रो. के. एन. शाह |
| 15 भारत एवं विदेशों में कृषि विकास | प्रो. के. एन. शाह |
| 16 धन अधिनियम | डॉ. बी. एस. माथुर एवं प्रो. जे. आर. कुम्भट |
| 17 उत्पादन प्रबन्ध | प्रो. जे. आर. कुम्भट |
| 18 व्यावसायिक नीति एवं सामाजिक उत्तरदायित्व | डॉ. आर. के. बजाज |
| 19 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा | प्रो. सी. एम. चौधरी |
| 20 औद्योगिक सम्बन्ध | प्रो. सी. एम. चौधरी |
| 21 सांख्यिकी | प्रो. पी. आर. गणेर |
| 22 सरकार, समाज और व्यवसाय | डॉ. आर. के. बजाज एवं प्रो. बी. एस. पोरवाल |
| 23 भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएँ | डॉ. टी. एन. जलुबंदी, डॉ. नमता गणवाल आदि |
| 24 प्रबन्ध के सिद्धान्त | प्रो. सी. एम. चौधरी |

प्राक्कथन

द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त जिस युग का शुभारम्भ इस विश्व में हुआ उसकी दो मुख्य उपलब्धियाँ उल्लेखनीय हैं। एक ओर तो राजनीतिक परतन्त्रता को समाप्त करने का बीड़ा उठाया गया और दूसरी ओर आर्थिक विकास की सभावनाओं पर अधिकाधिक प्रकाश डाल कर पिछड़े हुए राष्ट्रों का निराशायुक्त निद्रा से जगाने के अनेक प्रयास किए गए। सम्भवतः पहली उपलब्धि में सफलता की अधिक ब्रलक देखी जा सकती है क्योंकि भारत तथा विश्व के अनेक उपनिवेशों ने इस युग के अन्तर्गत दासत्व की घेड़ियों को काट कर स्वतन्त्रता प्राप्त की। साम्राज्यवादी राष्ट्रों ५ भी प्रायः इस बात का आभास हो गया कि किसी दूसरे राष्ट्र की भूमि पर शासन करना न तो व्यावहारिक ही है और न लाभदायक।

किन्तु आर्थिक क्षेत्र का इतिहास कुछ भिन्न प्रतीत होता है। यद्यपि विकास के सिद्धान्त को आगे बढ़ाने में विश्व के प्रमुख अर्थशास्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है (जिसकी पुष्टि का प्रतीक 1969 से अब तक के अनेक नोबेल प्राइज विजेताओं को माना जा सकता है), चिन्ता का विषय यह है कि विकसित राष्ट्रों को आर्थिक क्षेत्र में उपनिवेशवादी नीति का अन्त दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि राजनीतिक उपनिवेशवाद की बहुत कुछ प्रतिभा का आर्थिक नीतियों में समावेश हो गया है जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक उपनिवेशवाद ने भयंकर रूप धारण कर लिया है। यह स्पष्ट है कि इसी प्रवृत्ति का सामना करने के लिए 1973 में खनिज तेल का उत्पादन एवं निर्यात करने वाले देशों (O P E C) ने मूल्य वृद्धि की कटु नीति अपनाई, और उसी के परिणामस्वरूप 1974 में अन्तर्राष्ट्रीय सघ की महा सभा द्वारा नए अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रारूप (New International Economic Order) स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। किन्तु जब मई 1976 में अन्तर्राष्ट्रीय सघ के व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD) में इस प्रारूप को व्यवहार में लाने का प्रश्न उठा तो कुछ शक्तिशाली राष्ट्रों के विरोध के कारण केवल यह सहमति प्रकट करके सम्मेलन भंग हो गया कि कठिन समस्याओं पर फिर कभी विवाद किया जाए।

इस पृष्ठभूमि में श्री जी एल गुप्ता की पुस्तक 'आर्थिक विकास के सिद्धान्त एवं भारत में आर्थिक नियोजन' विशेष महत्त्व रखती है। इस पुस्तक में आर्थिक सिद्धान्त का गहन विश्लेषण किया है और दूसरी ओर भारत में आर्थिक नियोजन का विद्वतापूर्ण दृश्य प्रस्तुत किया है। नवीनतम आंकड़े उपलब्ध करके सामयिक विषयों पर—जैसे बेरोजगारी, आय की असमानता तथा पाँचवी पंचवर्षीय योजना (1974-79) की प्रगति पर रोचक टिप्पणी प्रस्तुत की गई हैं। राजस्थान में आर्थिक नियोजन का विशेष रूप से सर्वेक्षण किया गया है।

प्रकाशक का प्रयास प्रशंसनीय है। मुझे आशा है कि यह पुस्तक भारतीय विश्वविद्यालयों के वाणिज्य तथा अर्थशास्त्र के छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

आदिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग,
स्कूल ऑफ कॉमर्स, राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर

डॉ० ओमप्रकाश
बलिष्ठ प्रोफेसर

नये संस्करण के दो शब्द

'आर्थिक विकास के सिद्धान्त एवं भारत में आर्थिक नियोजन' अपने सशोधित संस्करण के रूप में आपके सामने हैं। पूर्व संस्करण का जो स्वागत हुआ और विभिन्न क्षेत्रों से जो रचनात्मक सुझाव प्राप्त हुए, उन्हें सामने रखकर पुस्तक में कितने ही परिवर्तन और सशोधन किए गए हैं। इस संस्करण में अनेक अध्याय तो सर्वथा नए जोड़े गए हैं और उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन पर विषय-सामग्री हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकों में प्रायः उपलब्ध नहीं है। उदाहरणार्थ, विकास के दौरान उत्पादन, उपभोग, रोजगार, विनियोग और व्यापार में संयन्त्रात्मक परिवर्तन, विकास-दर के विभिन्न तथ्यों के योगदान के सन्दर्भ में डेनीसन का अध्ययन, योजनाओं में नियोजित तथा वास्तव में प्राप्त बचत एवं विनियोग दरें, योजनाओं में क्षेत्रीय लक्ष्य, वित्तीय आवंटन और उपलब्धियाँ, विनियोग-वृद्धि और उत्पादितता, सुधार के उपाय, भारत में गरिबी और असमानता आदि टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर सामग्री हिन्दी पुस्तकों में प्रायः कम उपलब्ध है और जो हैं वह अधिकांशतः अपर्याप्त हैं। प्रस्तुत संस्करण में इन विषयों पर प्रामाणिक ग्रन्थों के आधार पर व्यवस्थित ठोस जानकारी देने का प्रयास किया गया है। आवश्यकतानुसार गणितीय विधि का प्रयोग किया गया है, लेकिन पुस्तक बोलिबल न बने, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। प्रथासाध्य नवीनतम आंकड़े देकर विषय-सामग्री को अद्यतन बनाया गया है। पुस्तक के परिशिष्ट भी विशेष महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्वीकृति के उपरान्त 25 सितम्बर 1976 को पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो सशोधित रूप सामने आया है, उसे भी विस्तार से परिशिष्ट के रूप में जोड़ दिया गया है। पुस्तक में अगस्त सितम्बर 1976 तक के आंकड़े प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर दिए गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के बुलेटिनो, भारत सरकार की 1975-76 की वार्षिक रिपोर्टों, विभिन्न आर्थिक पत्र-पत्रिकाओं आदि से सभी आवश्यक सहायता ली गई है।

इस संस्करण में हमारा यह प्रयास रहा है कि विद्यार्थियों को आर्थिक विकास के सिद्धान्तों और देश के आर्थिक नियोजन के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पहलुओं का सुगमतापूर्वक किन्तु समुचित ज्ञान प्राप्त हो सके। पुस्तक के अन्त में विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रश्न पत्र भी दिए गए हैं ताकि विद्यार्थियों को प्रश्न-मैली का बोध हो सके।

जिन अधिकारिक विद्वानों की कृतियों से पुस्तक के प्रणयन में सहायता ली गई है, उसके लिए लेखक हृदय से आभारी हैं।

—लेखक

अनुक्रमणिका

भाग-1. आर्थिक विकास के सिद्धान्त (Theory of Economic Growth)

1. आर्थिक विकास का अर्थ और अवधारणा (The Meaning & Concept of Economic Growth)	1
आर्थिक विकास का अर्थ एवं परिभाषा	2
आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक उन्नति	6
आर्थिक विकास की प्रकृति	8
आर्थिक विकास का माप	11
आर्थिक विकास का महत्व	13
2. अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की विशेषताएँ (Characteristics of Under-developed Economies)	16
अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था का आशय और प्रमुख परिभाषाएँ		17
‘अर्द्ध-विकसित’, ‘अविकसित’, ‘निधन’ और ‘पिछड़े हुए’ देश	21
अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था की विशेषताएँ या लक्षण	22
अर्द्ध-विकसित देशों की समस्याएँ	39
अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास की सामान्य आवश्यकताएँ	42
पश्चिमी देशों का अर्थशास्त्र पिछड़े देशों के लिए अनुपयुक्त	45
पश्चिमी देशों के आर्थिक साम्राज्यवाद के विरुद्ध तीसरी दुनिया की रणनीति	48
3. आर्थिक विकास के अन्तर्गत संरचनात्मक परिवर्तन : उत्पादन, उपभोग, रोजगार, निवेश और व्यापार के संगठन में परिवर्तन (Structural Changes under Development : Changes in the Composition of Production, Consumption, Employment, Investment & Trade)	50
आर्थिक विकास के अन्तर्गत संरचनात्मक परिवर्तन	—	50
उत्पादन की संरचना, उपयोग व प्रवृत्तियाँ	53
उपभोग में संरचनात्मक परिवर्तन	56
व्यापार में संरचनात्मक परिवर्तन	60
वित्तियोग के स्वरूप में परिवर्तन	64
रोजगार के ढाँचे में परिवर्तन	69

4	आर्थिक विकास के प्रमुख तत्त्व एवं डेनिसन का प्रप्येन (Major Growth Factors, Denison's Estimate of the Contribution of different Factors to Growth Rate)	72
	आर्थिक विकास के प्रमुख तत्त्व	72
	आर्थिक विकास के कारक और उनकी सापेक्षिक रैन	83
	आर्थिक विकास की अवस्थाएँ	85
	विकास दरों के विभिन्न कारकों के योगदान का डेनिसन का मूल्यांकन	89
5	आर्थिक विकास से सम्बन्धित विचारधाराएँ : लेविस, हैरड-डोमर, महालनोबिस तथा अन्य (Approaches to the Theory of Development : Lewis, Harrod-Domar, Mahalanobis and Others)	97
	आर्थिक लेविस का आर्थिक वृद्धि का सिद्धान्त ✓	97
	हैरड/डोमर मॉडल	105
	✓ महालनोबिस मॉडल <i>Sub</i>	119
	नर्कसे, रोडन, हर्षमैन, मिन्ट एव लेवेन्स्टीन की विचारधारा	125
6	आर्थिक विकास के लिए नियोजन (Planning for Economic Growth)	147
	नियोजित और अनियोजित अर्थ-व्यवस्था की तुलना	148
	नियोजित अर्थ-व्यवस्था की श्रेष्ठता	149
	नियोजन के लिए निर्धारित की जाने वाली बातें	158
	नियोजन की सफलता की शर्तें	162
7	बचत दर व विकास-दर को प्रभावित करने वाले तत्त्व (Factors Effecting the Saving Rate and the Over-all Growth Rate)	168
	बचत-दर को प्रभावित करने वाले तत्त्व	168
	विकास-दर और उसे प्रभावित करने वाले तत्त्व	173
8	वित्तीय साधनों की गतिशीलता (Mobilisation of Financial Resources)	174
	साधनों के प्रकार	174
	गतिशीलता को निर्धारित करने वाले कारक	175
	साधनों का निर्धारण	177
	योजना के लिए वित्तीय साधनों की गतिशीलता	177
	बचत और विकास : भारत में राष्ट्रीय बचत आन्दोलन	188

9 उपभोग वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए मांग के अनुमान, आदा-प्रदा गुणांकों का उपयोग (Demand Projections for Consumption Goods and Intermediate Goods The Use of Input-Output Co-efficients)	192
आय-लोच द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं की मांग के अनुमान	192
आदा-प्रदा तकनीकी	194
10 उत्पादन-संक्षेपों का निर्धारण (Determination of Output Targets)	200
भारतीय नियोजन में संक्षेप-निर्धारण	203
11 उत्पादन क्षेत्रों में विनियोगों का आवंटन (Allocation of Investment between Production Sectors)	208
विनियोग विकल्प की आवश्यकता	208
अर्द्ध-विकसित देशों की विनियोग सम्बन्धी विशिष्ट समस्याएँ	210
विनियोग मापदण्ड	211
अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्र	219
किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए?	219
कृषि में विनियोग क्यों?	221
उद्योगों में विनियोग	224
सेवा-क्षेत्र में विनियोग	226
तीनों क्षेत्रों में समानान्तर व सन्तुलित विकास की आवश्यकता	227
12 विभिन्न क्षेत्रों में विनियोगों का आवंटन (Allocation of Investment between Different Regions)	230
विभिन्न क्षेत्रों में विनियोगों का आवंटन	230
भारतीय नियोजन और सन्तुलित प्रादेशिक विकास	232
13 निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में विनियोगों का आवंटन (Allocation of Investment between Private and Public Sectors)	235
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का अर्थ	236
आर्थिक विकास में निजी क्षेत्र का महत्त्व	236
आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्त्व	239
विनियोगों का आवंटन	242
भारत में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में विनियोग	243
14 विदेशी विनिमय का आवंटन (Allocation of Foreign Exchange)	249
विदेशी विनिमय का महत्त्व और आवश्यकता	249
विदेशी विनिमय का आवंटन	251
भारतीय नियोजन में विदेशी विनिमय का आवंटन	255

15' मूल्य-नीति और वस्तु-नियन्त्रण (Price Policy and Commodity Control)	258
मूल्य नीति का महत्त्व	259
मूल्य नीति का उद्देश्य	260
मूल्य-नीति और आर्थिक विकास	260
मूल्य-नीति के दो पहलू	264
मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में मूल्य-नीति के सिद्धान्त	..	267
विभिन्न प्रकार के पदार्थों से सम्बन्धित मूल्य नीति	268
वस्तु-नियन्त्रण	271
भारतीय नियोजन में मूल्य और मूल्य नीति	273
16 परियोजना मूल्यांकन के मानदण्ड, विशुद्ध वर्तमान मूल्य और प्रतिफल की आन्तरिक दर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत एवं लाभ (Criteria for Project Evaluation, Net Present Value and Internal Rate of Return, Direct and Indirect Costs and Benefits)	281
परियोजना मूल्यांकन के मानदण्ड	281
विशुद्ध वर्तमान मूल्य विधि	286
आन्तरिक प्रतिफल दर	290
आन्तरिक प्रतिफल दर तथा शुद्ध वर्तमान मूल्य		
मानदण्डों की तुलना	294
परियोजना मूल्यांकन की लागत-लाभ विश्लेषण		
विधि की आलोचना	296
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लागतें व लाभ	297

भाग-2 भारत में आर्थिक नियोजन (Economic Planning in India)

1 भारतीय नियोजन (Indian Planning)	301
निर्देशात्मक योजना	301
राष्ट्रीय आयोजन समिति	302
बम्बई योजना	..	302
जन योजना	303
गांधीवादी योजना	304
अन्य योजनाएँ	..	305
स्वतन्त्रता के बाद नियोजन	305
भारत में नियोजन : समाजवादी समाज का आदर्श	309

v अनुक्रमणिका

2 योजनाओं में विकास, बचत एवं विनियोग दरें—नियोजित तथा वास्तव में प्राप्त	319
(Growth Rates and Saving (Investment) Rates—Planned and Achieved in the Plans)	..	
भारत में नियोजित बचत एवं विनियोग की स्थिति	320
विकास दर	326
3 प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाएँ—क्षेत्रीय लक्ष्य, वित्तीय आवंटन तथा उपलब्धियाँ	332
(First Three Five Year Plans—Sectoral Targets, Financial Allocation and Achievements)		
योजनाओं में वित्तीय आवंटन	332
योजनाओं में क्षेत्रीय लक्ष्य	341
प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों का मूल्यांकन ...		347
4 विनियोग-वृद्धि के उपाय और उत्पादकता-सुधार के उपाय	352
(Measures to Increase Investment and Measures to Improve Productivity)		
विनियोग वृद्धि के उपाय	354
उत्पादकता सुधार के उपाय	357
5 भारतीय योजना-परिचय के आवंटन का मूल्यांकन	366
(Criticisms of Plan Allocation in India)		
प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएँ	366
द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएँ	367
तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएँ	369
चतुर्थ योजना में प्राथमिकताएँ	371
6 चतुर्थ योजना का मूल्यांकन	372
(Appraisal of the Fourth Plan)		
परिचय और निवेश	372
परिचय की वित्त व्यवस्था और उपलब्धियाँ	373
7 पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79)	380
(Fifth Five Year Plan)		
पाँचवी योजना का विस्तृत विवरण	380
पाँचवी योजना के कुछ प्रश्न चिह्न	396
1974-75 और 1975-76 के लिए वार्षिक योजनाएँ	400
1976-77 के लिए वार्षिक योजना का दस्तावेज	401
आज का आयोजन	404
वार्षिक कामाफल के प्रति निराशा का कोई कारण नहीं	408

8	भारत में योजना-निर्माण प्रक्रिया और क्रियान्वयन की प्रशासकीय मशीनरी	414
✓	(The Administrative Machinery for Plan Formulation Process and Implementation in India)	
	भारत में योजना-निर्माण की प्रक्रिया	414
	भारत में योजना-निर्माण की तकनीक	418
	योजना-निर्माण और क्रियान्वयन की प्रशासकीय मशीनरी	422
	योजना का क्रियान्वयन	429
	भारतीय योजना-निर्माण प्रक्रिया की समीक्षा	431
9	भारत में गरीबी और असमानता	435
	(Poverty and Inequality in India)	
	भारत में गरीबी और विषमता की एक भन्क	435
	(क) दांडेकर एवं नीलकण्ठ रथ का अध्ययन	436
	(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का अध्ययन	439
	(ग) डॉ. रामाश्रय राय का आर्थिक विषमता पर अध्ययन	440
	(घ) भारतीय व्यापार एवं उद्योग-मण्डलों के महासंघ द्वारा किया गया अध्ययन	443
	(ङ) भारत में गरीबी की 1974-75 में स्थिति	444
	गरीबी का मापदण्ड और भारत में गरीबी	445
	गरीबी और असमानता के मापदण्ड	446
	भारत में गरीबी और असमानता के कारण	447
	गरीबी एवं असमानता को दूर अथवा कम करने के उपाय	450
	पाँचवी पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण में गरीबी और असमानता को दूर या कम करने सम्बन्धी नीति	452
	बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम और गरीबी पर प्रहार	454
10	भारत में बेरोजगारी-समस्या का स्वरूप तथा वैकल्पिक	457
	रोजगार नीतियाँ	
	(The Nature of Unemployment Problem and Alternative Employment Policies in India)	
	भारत में बेरोजगारी का स्वरूप और किस्म	457
	बेरोजगारी की माप	459
	भारत में बेरोजगारी के अनुमान	460
	भारत में ग्रामीण बेरोजगारी	462
	शिक्षित बेरोजगारी	466
	बेरोजगारी के कारण	468
	बेरोजगारी : उपाय और नीति	470
	बेरोजगारी सम्बन्धी भगवती समिति की सिफारिशें	471

पाँचवी पंचवर्षीय योजना और बेरोजगारी	475
भारत के संगठित क्षेत्र में रोजगार (1974-75)	479
राष्ट्रीय रोजगार सेवा (N. E. S.)	480

11 राजस्थान में आर्थिक नियोजन का संक्षिप्त सर्वेक्षण (A Brief Survey of Economic Planning in Rajasthan)	482
राजस्थान में प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाएँ	..	482
राजस्थान की तीन वार्षिक योजनाएँ (1966-69)	487
राजस्थान की पाँचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप एवं 1974-75 की वार्षिक योजना	...	491
राज्य की वार्षिक योजना (1974-75)	...	495
राज्य की वार्षिक योजना (1975-76)	496
राज्य की वार्षिक योजना (1976-77)	502

APPENDIX

1 भारी उद्योगों का विकास	504
2 लघु उद्योगों का विकास	.	510
3 ग्रामीण विकास	.	517
4 सिंचाई का विकास	523
5 राष्ट्रीय विकास और आंकड़े	525
6 राष्ट्र के आर्थिक कार्यक्रम के लिए परिवार नियोजन	529
7 जनगणना 1971 तथा एक दृष्टि में		533
8 राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय	535
9 मूल उद्योग के अनुसार निम्न राष्ट्रीय उत्पाद के अनुमान प्रतिशत विभाजन	536
10 सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा निम्न राष्ट्रीय उत्पाद	537
11 चुने हुए उद्योगों में उत्पादन	538
12 गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार	541
13 सरकारी क्षेत्र में रोजगार	..	542
14 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम	..	543
15 पाँचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप	545
16 प्रश्न-कोश	548
17 ग्रन्थ-कोश	561

भाग-1

आर्थिक विकास के सिद्धान्त

(THEORY OF ECONOMIC GROWTH)

आर्थिक विकास का अर्थ और अवधारणा

(The Meaning and Concept of Economic Growth)

“भविष्य में बहुत वर्षों तक अल्पविकसित देशों का विकास अमेरिका और रूस के बीच गहन प्रतियोगिता का क्षेत्र रहेगा। विश्व की समस्याओं में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ऐसे अर्द्ध-विकसित क्षेत्र विशेष रुचि का विषय रहेंगे जो या तो ऐसे सुविशाल प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न हो जिनकी आवश्यकता विश्व-शक्तियों को हो अथवा जो सैनिक दृष्टि से सामरिक महत्व की स्थिति रखते हों।”

—एच डब्लू शैनन

विकास का अर्थशास्त्र मुख्यतः अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास की समस्याओं का निरूपण करता है। द्वितीय महायुद्ध के बाद आर्थिक विकास विश्व की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या बन गया है और विश्व के पिछड़े देशों के विकास में, मूलतः अपने प्रभाव-क्षेत्र की वृद्धि के लिए, विश्व की महाशक्तियों के बीच गहन प्रतियोगिता छिड़ी हुई है। वर्तमान शताब्दी के पाँचवें दशक में और विशेषकर द्वितीय महायुद्ध के बाद ही विकसित देशों तथा अर्थशास्त्रियों ने अल्पविकसित देशों की समस्याओं के विश्लेषण की ओर, उनके आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने की ओर ध्यान देना शुरू किया और आज तो अल्पविकसित देशों में आर्थिक विकास के प्रति यह जागरण पैदा हो चुका है कि विकास एक युग-नारा बन गया है।

विकसित राष्ट्र दुनिया के अल्पविकसित देशों की ओर यकायक ही सहानुभूति से उमड़ पड़े हों, यह बात नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि विकसित देश महायुद्ध के बाद खासतौर पर यह महसूस करने लगे हैं कि “किसी एक स्थान की दरिद्रता प्रत्येक दूसरे स्थान की समृद्धि के लिए खतरा है।” एशिया और अफ्रीका में राजनीतिक पुनर्स्थापन की जो लहर फैली उसने भी विकसित देशों को यह महसूस

2 आर्थिक विकास के सिद्धान्त

करने के लिए बाध्य किया कि यदि वे अल्पविकसित देशों की आकांक्षाओं की पूर्ति की दिशा में सहयोगी नहीं हुए तो उनके अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव-क्षेत्र को गहन और व्यापक आघात पहुँचेगा। विश्व की महाशक्तियाँ आर्थिक-राजनीतिक प्रभाव-क्षेत्र के विस्तार में एक दूसरे से पिछड़ जाने के भय से अल्पविकसित देशों को आर्थिक सहयोग देने की दिशा में इस तरह प्रतियोगी हो उठी।

इसमें सन्देह नहीं कि अल्पविकसित देशों में व्याप्त गरीबी को दूर करने में धनिक राष्ट्रों की रुचि कुछ हद तक मानवतावादी उद्देश्यों से भी प्रेरित है, लेकिन मूल रूप से और प्रधानतया प्रेरणा-स्रोत प्रभावक्षेत्र के विस्तार की प्रतिस्पर्धा ही है। प्रो० एल डब्लू शैनन ने वास्तविकता का सही मूल्यांकन किया है कि "भविष्य में बहुत वर्षों तक अल्पविकसित देशों का विकास अमेरिका और रूस के बीच गहन प्रतियोगिता का क्षेत्र रहेगा। विश्व की समस्याओं में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ऐसे अर्द्ध-विकसित क्षेत्र विशेष रुचि का विषय रहेंगे जो या तो ऐसे सुविशाल प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न हो जिनकी आवश्यकता विश्व-शक्तियों को हो अथवा जो सैनिक दृष्टि से सामरिक महत्त्व की स्थिति रखते हों।"¹

आर्थिक विकास का अर्थ एवं परिभाषा

(Meaning and Definition of Economic Growth)

आर्थिक विकास से अभिप्राय विस्तार की उस दर से है जो अर्द्ध-विकसित देशों की जीवन-निर्वाह-स्तर (Subsistence level) से ऊँचा उठाकर अल्पकाल में ही उच्च जीवनस्तर प्राप्त कराए। इसके विपरीत पहले से ही विकसित देशों के लिए आर्थिक विकास का आशय वर्तमान वृद्धि की दर को बनाए रखना या उसमें वृद्धि करना है। आर्थिक विकास का अर्थ किसी देश की अर्थ-व्यवस्था के एक नहीं बरन् सभी क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि करना और देश की निर्धनता को दूर करके जनता के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है। आर्थिक विकास द्वारा देश के प्राकृतिक और अन्य साधनों का समुचित उपयोग करके अर्थ-व्यवस्था को उन्नत स्तर पर ले जाया जाता है। आर्थिक विकास के विभिन्न पक्षों पर यद्यपि आज भी काफी असहमति है, तथापि इसको हम एक ऐसी प्रक्रिया (Process) कह सकते हैं जिसके द्वारा किसी भी देश के साधनों का अधिकारक्षम कुशलता के साथ उपयोग किया जाए। आर्थिक विकास की कोई निश्चित और सर्वमान्य परिभाषा देना बड़ा कठिन है। विभिन्न लेखकों ने इसकी परिभाषा भिन्न भिन्न विकास के माप के आधारों पर की है।

(क) विद्वानों के एक पक्ष ने कुल देश की आय में सुधार को आर्थिक विकास कहा है। प्रो० कुजनेत्स, पाल एल्वर्ट मेयर एव वाल्डविन, ऐ जे यंगसन आदि इस विचारधारा के प्रतिनिधि हैं।

(ख) विद्वानों का दूसरा पक्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में सुधार को आर्थिक विकास मानता है। इस विचारधारा के समर्थक डॉ० हिगिंस, आर्थर लेविस, विलियमसन, बाइनर, होवेल लिबिस्टीन आदि हैं।

(ग) अनेक विद्वान आर्थिक विकास को सर्वांगीण विकास के रूप में लेते हैं। अग्रिम पक्तियों में हम इन तीनों ही पक्षों को लेंगे।

(क) आर्थिक विकास का अर्थ राष्ट्रीय आय में वृद्धि

श्री मेयर और बाल्डविन के अनुसार "आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी अर्थ-व्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है।"¹

आर्थिक विकास की इस परिभाषा में तीन बातें विचारणीय हैं।—

1. प्रक्रिया (Process)—इसका आशय अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न अंगों में परिवर्तन से है। आर्थिक विकास में वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक चल-राशियों (Variables) में परिवर्तन के परिणामस्वरूप होती है। इन परिवर्तनों का सम्बन्ध साधनों की मांग और उनकी पूर्ति में परिवर्तन से है। साधनों की पूर्ति में परिवर्तन के अन्तर्गत जनसंख्या में वृद्धि, अतिरिक्त साधनों का पता, पूँजी का संचयन, उत्पादन की नवीन विधियों का प्रयोग तथा अन्य सस्यागत परिवर्तन सम्मिलित हैं। साधनों की पूर्ति में परिवर्तन के साथ ही साथ इनकी मांग के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। आय-स्तर तथा उसके वितरण के स्वरूप में परिवर्तन, उपभोक्ताओं के अधिमान में परिवर्तन, अन्य सस्यागत तथा सगठनात्मक परिवर्तन मांग के स्वरूप में परिवर्तन के उदाहरण हैं। इस प्रकार आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप मांग और पूर्ति के स्वरूप में कई परिवर्तन होते हैं। किन्तु ये परिवर्तन आर्थिक विकास के कारण और परिणाम दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की सीमा आर्थिक विकास की गति तथा समय पर निर्भर करती है। आर्थिक विकास के क्षेत्र में हम विकास प्रक्रिया के कारण होने वाली वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि का ही अध्ययन नहीं करते अपितु इसके लिए उत्तरदायी इस प्रक्रिया या इन परिवर्तनों का अध्ययन भी करते हैं।

2. वास्तविक राष्ट्रीय आय (Real National Income)—आर्थिक विकास का सम्बन्ध वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से है। वास्तविक राष्ट्रीय आय का आशय मूल्य-स्तर में हुए परिवर्तनों के लिए समायोजित शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन (Net National Product adjusted for Price Changes) से है। इसका अर्थ देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल योग के समायोजित मूल्य से है। मूल्यों में वृद्धि के कारण प्रकट होने वाली राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक विकास नहीं कहलाती है। अर्थ-व्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन वस्तुतः

निरन्तर बढ़ना चाहिए। सर्वप्रथम निश्चित वर्ष में देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का वर्तमान मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। इसके पश्चात् इस राशि को किसी आधार वर्ष के मूल्य-स्तर के सदृश में समायोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास मापने के लिए कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रयोग न करके शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का प्रयोग किया जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में पैदा की जाने वाली समस्त अन्तिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। इसे उत्पन्न करने के लिए जिन साधनों, यन्त्रों आदि का उपयोग किया जाता है उनमें मूल्य ह्रास या घिसावट (Depreciation) होता है जिनका प्रतिस्थापन आवश्यक है। अतः कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से मूल्य ह्रास की राशि निकाल देने के पश्चात् शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बचता है। आर्थिक विकास में मूल्य-स्तर में हुए परिवर्तन के लिए समायोजित इस शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन या वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होनी चाहिए।

3. दीर्घ काल (Long period of time)—आर्थिक विकास का सम्बन्ध दीर्घकाल से है। आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में दीर्घ-काल तक वृद्धि हो। आय में होने वाली अस्थायी वृद्धि को आर्थिक विकास नहीं कहा जा सकता। किसी वर्ष विशेष में यथोचित वर्षों के कारण कृषि उत्पादन में विशेष वृद्धि आदि अनुकूल परिस्थितियों के कारण राष्ट्रीय आय में होने वाली अस्थायी वृद्धि आर्थिक विकास नहीं है। इसी प्रकार व्यापार-चक्रों (Trade cycles) के कारण तेजी के काल में हुई राष्ट्रीय आय में वृद्धि भी आर्थिक विकास नहीं है। आर्थिक विकास पर विचार करते समय पन्द्रह, बीस या पच्चीस वर्षों की अवधि तक राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान देना होता है।

(ख) आर्थिक विकास का अर्थ प्रति-व्यक्ति आय में वृद्धि

उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि आर्थिक विकास का आशय वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि से है। किन्तु कुछ अर्थशास्त्रियों के मतानुसार आर्थिक विकास को राष्ट्रीय आय की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय के सदृश में परिभाषित करना चाहिए। वस्तुतः आर्थिक विकास का परिणाम जनता के जीवन-स्तर में सुधार होना चाहिए। यह संभव है कि राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि हो, किन्तु जनता का जीवन-स्तर ऊँचा न उठे। जनसंख्या में वृद्धि की दर अधिक होने के कारण प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर भी नहीं बढ़े या कम हो जाय। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होते हुए भी देश विकासोन्मुख नहीं कहा जायगा। जब प्रति व्यक्ति आय घटने के कारण लोगों का जीवन-स्तर गिर रहा हो तो हम यह नहीं कह सकते कि आर्थिक विकास हो रहा है। अतः आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होनी चाहिए। इस प्रकार का मन कई विकासवादी अर्थ-शास्त्रियों ने प्रकट किया है।

प्रो लेविस के अनुसार "आर्थिक वृद्धि का अभिप्राय प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि से है।"¹

प्रो वलियमसन के अनुसार "आर्थिक विकास या वृद्धि से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी देश या क्षेत्र के लोग उपलब्ध साधनों का प्रति व्यक्ति वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में स्थिर वृद्धि के लिए उपयोग करते हैं।"²

प्रो वेरन के शब्दों में "आर्थिक विकास या वृद्धि को निश्चित समय में प्रति व्यक्ति मौलिक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए।"

बुकानन और एलिस ने भी इसी प्रकार की परिभाषा देते हुए लिखा है कि "विकास का अर्थ अर्द्ध-विकसित क्षेत्रों की वास्तविक आय की संभावनाओं में वृद्धि करना है जिसमें विनियोग का उपयोग उन परिवर्तनों को प्रभावित करने और उन उत्पादक साधनों का उपयोग करने के लिए किया जाता है जो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि का वादा करते हैं।"

(ग) आर्थिक विकास सर्वांगीण विकास के रूप में

अधिकांश आधुनिक अर्थ-शास्त्री आर्थिक विकास की उपर्युक्त परिभाषाओं को अपूर्ण मानते हैं। वास्तव में उपरोक्त परिभाषाएँ आर्थिक प्रगति को स्पष्ट करती हैं जबकि आर्थिक विकास आर्थिक प्रगति से अधिक व्यापक है। आर्थिक विकास में उपरोक्त आर्थिक प्रगति के अतिरिक्त कुछ परिवर्तन भी सम्मिलित हैं। आर्थिक विकास का आशय राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से ही नहीं है। यह संभव है कि प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि होने पर भी जनता का जीवन स्तर उच्च न हो क्योंकि प्रति व्यक्ति उपभोग कम हो रहा हो। जनता बड़ी हुई आय में से अधिक बचत कर रही हो या सरकार इस बड़ी हुई आय का एक बड़ा भाग स्वयं सैनिक कार्यों पर उपयोग कर रही हो। ऐसी दशा में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर भी जनता का जीवन-स्तर उच्च नहीं होगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर भी संभव है। अधिकांश जनता निर्धन रह जाए और उसके जीवन-स्तर में कोई सुधार न हो क्योंकि बड़ी हुई आय का अधिकांश भाग विशाल निर्धन वर्ग के पास जाने की अपेक्षा सीमित धनिक वर्ग के पास चला जाए। अतः कुछ अर्थ-शास्त्रियों के अनुसार आर्थिक विकास में धन के अधिक उत्पादन के साथ-साथ उनका न्यायोचित वितरण भी होना चाहिए। इस प्रकार कुछ विचारक आर्थिक विकास के साथ कल्याण का भी सम्बन्ध जोड़ते हैं। उनके अनुसार आर्थिक विकास पर विचार करते समय न केवल इस बात पर ही ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए कि कितना उत्पादन

1 W A Lewis *The Theory of Economic Growth* p 10

2 Williamson and Buttrick *Principles and Problems of Economic Development*, p 7

किया जा रहा है अपितु इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि किस प्रकार उत्पादन किया जा रहा है। अतः आर्थिक विकास का आशय राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जनता के जीवन-स्तर में सुधार, अर्थ-व्यवस्था की संरचना में परिवर्तन, देश की उत्पादन-शक्ति में वृद्धि, देशवासियों की मान्यताओं एवं दृष्टिकोणों में परिवर्तन तथा मानव के सर्वांगीण विकास से है। विकास को परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों पक्षों से देखा जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से समुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट में दी गई आर्थिक विकास की यह परिभाषा अत्यन्त उपयुक्त है “विकास मानव की भौतिक आवश्यकताओं से नहीं अपितु उसके जीवन की सामाजिक दशाओं के सुधार से भी सम्बन्धित है अतः विकास न केवल आर्थिक वृद्धि ही है, किन्तु आर्थिक वृद्धि और सामाजिक, सांस्कृतिक, सस्थागत तथा आर्थिक परिवर्तनों का योग है।”

किन्तु वस्तुतः उपरोक्त परिवर्तनों को माप सकना अत्यन्त असम्भव है और जैसा कि श्री मेयर और बाल्डविन ने बतलाया है, “विकास की अनुकूलतम दर की व्याख्या करने के लिए हमें आय के वितरण, उत्पादन की संरचना, पसंदगियाँ, वास्तविक लागतें (Real costs) एवं वास्तविक आय में वृद्धि से सम्बन्धित अन्य विशिष्ट परिवर्तनों के बारे में मूल्य-निर्णय (Value-Judgements) देने होंगे।”

अतः मूल्य निर्णय से बचने एवं सरलता के लिए अधिकांश अर्थशास्त्री आर्थिक विकास का तात्पर्य जनसंख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वास्तविक आय में वृद्धि से लेते हैं।

अन्य परिभाषाएँ

श्री पाल एलवर्ट के अनुसार, “यह (आर्थिक विकास) इसके सबसे बड़े उद्देश्य के द्वारा सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है जो वास्तविक आय में विस्तार के लिए एक देश के द्वारा अपने समस्त उत्पादक साधनों का शोषण है।”

प्रो ए जे यंगसन के अनुसार “आर्थिक प्रगति का आशय आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की शक्ति में वृद्धि है।” उन्होंने वास्तविक राष्ट्रीय आय को आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की शक्ति का सूचकांक माना है।

प्रो० डी० ब्राइटसिंह के मत में, “आर्थिक वृद्धि का अर्थ एक देश के समाज के अविकसित स्थिति से आर्थिक उपलब्धि के उच्च स्तर में परिवर्तित होने से है।”

श्री साइमन कुजनेत्स के शब्दों में, “आर्थिक विकास को मापने के लिए हम उसे या तो सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय में वृद्धि के रूप में या स्थिर कीमतों पर सम्पूर्ण जनसंख्या के उत्पादन के रूप में अथवा प्रति व्यक्ति उत्पादन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं।”

आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक उन्नति
(*Economic Development, Economic Growth and Economic Progress*)

आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक उन्नति एवं दीर्घकालीन परिवर्तन

(Secular Change) आदि बहुधा एक ही अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। किन्तु शुम्पीटर, श्रीमती उसुल्सा हिक्स आदि अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास (Economic Development) और आर्थिक वृद्धि (Economic Growth) में अन्तर किया है।

आर्थिक विकास का सम्बन्ध अर्द्ध-विकसित देशों की समस्याओं से है जबकि आर्थिक वृद्धि का सम्बन्ध विकसित देशों की समस्याओं से है। आर्थिक विकास का प्रयोग विकासशील देशों के लिए किया जाता है जहाँ पर अप्रयुक्त या अशोषित साधनों के शोषण की पर्याप्त संभावनाएँ होती हैं। इसके विपरीत आर्थिक वृद्धि का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के लिए किया जाता है जहाँ अधिकांश साधन विकसित होते हैं। इसी प्रकार शुम्पीटर ने भी आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में भेद स्पष्ट किया है। उनके अनुसार विकास स्थिर स्थिति (Static situation) से असतत (Discontinuous) और स्वतः (Spontaneous) परिवर्तन है जो पूर्व स्थित साम्य की स्थिति को भंग कर देता है जबकि आर्थिक वृद्धि जनसंख्या और वचन की दर में सामान्य वृद्धि के द्वारा आने वाला धीरे-धीरे और निरन्तर परिवर्तन है। एवरीमेन्स इवानामिक डिक्सनेरी ने इन दोनों के भेद को निम्नलिखित शब्दों में और भी स्पष्ट किया है—

“सामान्य रूप से आर्थिक विकास का आशय केवल आर्थिक वृद्धि से ही है। अधिक विशिष्टता के साथ इसका उपयोग वृद्धिमान अर्थ-व्यवस्था के परिमाण-आत्मक माप (जैसे प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि की दर) का नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनके कारण वृद्धि होती है। अतः वृद्धि मापनीय एवं वस्तुगत है। यह धन, शक्ति, पूँजी व्यापार की मात्रा और उपभोग में विस्तार का वर्णन करती है और आर्थिक विकास निहित आर्थिक वृद्धि के निर्धारक तत्त्व जैसे उत्पादन तकनीक, सामाजिक दृष्टिकोण और संस्थाओं में परिवर्तन आदि का वर्णन करने के उपयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार के परिवर्तन आर्थिक वृद्धि को जन्म देते हैं।”

इसी प्रकार आर्थिक वृद्धि (Economic Growth) तथा आर्थिक प्रगति (Economic Progress) में अन्तर किया जाता है। श्री एल० एन० बरेरी के अनुसार आर्थिक प्रगति का अर्थ प्रति व्यक्ति उपज (Per capita Product) में वृद्धि से है जबकि आर्थिक वृद्धि का आशय जनसंख्या और कुल वास्तविक आय दोनों में वृद्धि से है। उनके अनुसार आर्थिक वृद्धि के तीन रूप हो सकते हैं। प्रथम प्रगतिशील (Progressive) वृद्धि जो तब होती है जबकि कुल आय में वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि की अपेक्षा अनुपात से अधिक होती है। द्वितीय अधोगामी वृद्धि (Regressive growth), जब जनसंख्या में वृद्धि कुल आय में वृद्धि की अपेक्षा अधिक अनुपात में होती है। तृतीय स्थिर आर्थिक वृद्धि (Stationary growth), जब दोनों में एक ही दर से वृद्धि होती है।

इतना सब होते हुए भी आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक प्रगति आदि शब्दों को अधिकांश अर्थशास्त्री पर्यापवाची शब्द के रूप में ही प्रयुक्त करते हैं। प्रो० पाल० ए० बेरन का कथन है कि, “विकास” और “वृद्धि” की धारणा ही कुछ ऐसे परिवर्तन का संकेत देती है जो समाप्त हुए पुराने कुछ की अपेक्षा नया है। प्रो० विलियम आर्थर लेविस ने ‘वृद्धि’ शब्द का उपयोग किया है किन्तु परिवर्तन के लिए यदा-कदा ‘विकास’ और ‘प्रगति’ शब्द का भी उपयोग करना उन्होंने वांछनीय समझा है।

आर्थिक विकास की प्रकृति (Nature of Economic Growth)

आर्थिक विकास के अर्थ को विशद् रूप से समझ लेने के उपरान्त इसकी प्रकृति बहुत कुछ स्वतः स्पष्ट हो जाती है। हम यह जानते हैं कि प्रत्येक अर्थ-व्यवस्था जन्म (Birth), विकास (Growth), पतन (Decay) और मृत्यु (Death) की प्रक्रियाओं से गुजरती है। आर्थिक विकास इसका कोई अपवाद नहीं है। अविकसित अथवा अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था शन-शन विकास की ओर अग्रसर होती है और पूर्ण विकास की अवस्था प्राप्त करने के बाद तमश पतन की ओर बढ़ती है। हाँ, आज के वैज्ञानिक युग में इस पतन की क्रिया पर अकुश लगाना अवश्य बहुत कुछ संभव हो गया है। आज वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के कारण किसी भी राष्ट्र को पुराने होने की सजा देना मुश्किल है पर ऐसे देशों को दूढ़ निकालना असंभव नहीं है जिनकी अर्थ-व्यवस्थाएँ पुरानी हो गई हैं और अपनी अवनत अवस्था के कारण न केवल अपने देश के लिए बरन् अन्य देशों के लिए भी समस्या बनी हुई है। किन्तु इतना सब कुछ होते हुए भी यह सुनिश्चित है कि आर्थिक विकास की ओर बढ़ते रहना एक सतत प्रक्रिया है, जो समाप्त नहीं होती। आर्थिक विकास की प्रकृति गतिशील है जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक प्रगति के अध्ययन के आधार पर दीर्घकालीन अवस्था में आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषण करके महत्वपूर्ण और मूल्यवान् निष्कर्ष प्राप्त करना है। आर्थिक विकास के सम्बन्ध में आर्थिक उत्सार चढ़ावों का अध्ययन अल्पकाल में नहीं किया जा सकता। आर्थिक विकास दीर्घकाल की देन है। आर्थिक विकास में एक देश की अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना होता है और इसके लिए आर्थिक शक्तियों में आवश्यकतानुसार फेर बदल करते रहना पड़ता है और इन सब का अध्ययन करना पड़ता है। आर्थिक विकास की प्रकृति को समझने के लिए हमें स्थिर (Static) और गतिशील (Dynamic)—इन दो आर्थिक स्थितियों को समझ लेना चाहिए।

भौतिक-शास्त्र में स्थिर अथवा स्थैतिक (Static) दशा वह होती है जिसमें गति हो होती है, किन्तु परिवर्तन नहीं अथवा दूसरे शब्दों में गति का पूर्ण अभाव नहीं होता, किन्तु फिर भी गति की दर समान रहती है। यह गति एवरस रहती है अर्थात् इसमें सामयिक रूप से अचानक भटके नहीं लगते। इसमें अनिश्चितता का

अभाव रहता है। कहने का अर्थ यह है कि स्थिरावस्था कोई अव्यवस्था की अवस्था नहीं है वरन् यह अर्थ-व्यवस्था का एक ऐसा रूप है जिसमें कार्य बिना किसी बाधा के समान गति और सरल रूप में चलता रहता है। जब अर्थशास्त्र में प्रयुक्त की गई आर्थिक मात्राएँ समान होती हैं तो इसे स्थिरता की अवस्था कहा जाण्गा। अर्थ-व्यवस्था इन स्थिर मानाओं की सहायता से ही प्रगतिके पथ पर बढ़ती रहती है। मार्शल के कथनानुसार, "किसी कार्यशील, निन्तु अपरिवर्तनीय प्रणाली को स्थिर अर्थशास्त्र का नाम दिया जाता है।"

प्रो मैक्फाई ने माना था कि स्थिर अवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा वितरण को नियन्त्रित करने वाले साधन स्थिर होते हैं अथवा स्थिर मान लिए जाते हैं। जनसंख्या उन्न अथवा मात्रा की दृष्टि से बढ़ती ही नहीं है और यदि बढ़ती है तो उत्पादन की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है। प्रो स्टिगलर (Stigler), प्रो क्लार्क (Clark) तथा प्रो टिन्बर्गन (Tinbergen) आदि ने भी स्थिर अर्थशास्त्र का अर्थ स्थिर अर्थ-व्यवस्था से लिया है। क्लार्क का कहना है कि "वह अर्थ-व्यवस्था स्थिर है जिसमें जनसंख्या, पूँजी, उत्पादन प्रणाली मनुष्य की आवश्यकता और वैयक्तिक इवाइयों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता।" स्टिगलर महोदय का मत था कि "स्थिर अर्थ-व्यवस्था में रुचि, साधन एवं तकनीकी—इन तीनों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता।" प्रो जे के मेहता ने स्थिरता का अर्थ बताते हुए इसे ऐसी स्थिति माना है जो निश्चित समय के बाद भी उसी रूप में बनी रहती है। यदि निश्चित समय के बाद उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाए तो वह गत्यात्मक स्थिति कहलाएगी।

स्थिर अर्थशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है। इसके कई लाभ हैं। यदि इसकी सहायता न ली जाए तो परिवर्तनशील अर्थ-व्यवस्था का अध्ययन करना अत्यन्त जटिल बन जाए। आर्थिक परिवर्तनों की प्रकृति स्वमेव ही जटिलतापूर्ण होती है। गतिशील अर्थ-व्यवस्था का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने के लिए छोटी से छोटी स्थिर अवस्थाओं में विभाजित कर लिया जाता है। निरन्तर होने वाले परिवर्तन पर्याप्त अनिश्चितता ला देते हैं और इसलिए गतिशीलता का अध्ययन कठिन बन जाता है। इस सम्बन्ध में यह कहना उपयुक्त है कि गतिशील अर्थशास्त्र स्थिर अर्थशास्त्र पर लगातार टिका है इसलिए स्थिर अर्थशास्त्र के कानून गतिशील अर्थशास्त्र पर भी लागू होने चाहिए।

स्थिर अर्थशास्त्र के विपरीत गतिशील अर्थशास्त्र परिवर्तन से सम्बन्ध रखता है। दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन स्थिर अर्थशास्त्र में नहीं किया जा सकता। गतिशील अर्थशास्त्र अर्थ-व्यवस्था में निरन्तर होने वाले परिवर्तनों, इन परिवर्तनों की प्रक्रियाओं और परिवर्तन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारणों का अध्ययन करता है। गतिशील अर्थशास्त्र को अनेक प्रकार से परिभाषित किया गया है। रिचर्ड लिप्से (Richard Lipsay) के वचन अनुसार इसमें

10 आर्थिक विकास के सिद्धान्त

व्यवस्था की प्रणालियाँ, वैयक्तिक बाजारों अथवा सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था की असंतुलित दशाओं का अध्ययन किया जाता है।" अर्थ-व्यवस्था में प्रायः परिवर्तन होते रहते हैं। इनके फलस्वरूप असंतुलन उत्पन्न होता है। इस असंतुलन का अध्ययन गतिशील अर्थशास्त्र करता है। जे बी क्लार्क (J B Clarke) के मतानुसार गतिशील अर्थ व्यवस्था में जनसंख्या, पूँजी, उत्पादन की प्रणालियाँ और औद्योगिक संगठन का रूप बदलता रहता है। इसमें उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं में वृद्धि होनी रहती है। गतिशील विश्लेषण में इन समस्त परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाता है।

हैरोड (Harod) यह मानते थे कि गतिशील अर्थशास्त्र अर्थ-व्यवस्था में निरन्तर होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण है। उनके शब्दों में 'गतिशील अर्थशास्त्र विशेष रूप से निरन्तर होने वाले परिवर्तनों के प्रभावों और निश्चित किए जाने वाले मूल्यों में परिवर्तन की दरों से सम्बन्ध रखता है।'

जीवन की विभिन्न समस्याएँ गतिशील अर्थशास्त्र के अध्ययन को आवश्यक बना देती हैं क्योंकि स्थिर विश्लेषण उनके सम्बन्ध में अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं होता। एक सन्तुलन बिन्दु से लेकर दूसरे सन्तुलन बिन्दु तक जो परिवर्तन हुए उनका अध्ययन स्थिर अर्थशास्त्र में नहीं किया जा सकता। वे केवल गतिशील अर्थशास्त्र के अध्ययन द्वारा ही जाने जा सकते हैं।

वास्तव में गतिशील और स्थिर विश्लेषण दोनों की ही अपनी अपनी सीमाएँ हैं और इन सीमाओं में रहते हुए वे अपने कार्य सम्पन्न करते हैं तथापि वास्तविकता तो यह है कि इनमें कोई भी विश्लेषण अपने आप में पूर्ण नहीं है। प्रत्येक दूसरे के बिना अधूरा है। यहाँ तक कि वह जिन कार्यों को सम्पन्न कर सकता है उन्हें भी दूसरे की सहायता के बिना सन्तोषजनक रूप से नहीं कर पाएगा। इनमें गतिशील अर्थशास्त्र अपेक्षाकृत एक नई शाखा है और इसका विकास अभी भी बाँझित स्तर को प्राप्त नहीं कर सका है। यद्यपि अनेक विचारकों ने इसके विकास में अपना योगदान किया है, किन्तु अभी तक इसका कोई अत्यन्त सामान्य सिद्धान्त आविष्कृत नहीं हो सका है।

विकास का अर्थशास्त्र (Economics of Growth) एक गतिशील अथवा प्रावर्गिक (Dynamic) अर्थशास्त्र है। आर्थिक विकास का एक क्रमिक चक्र होता है जिसमें सदैव परिवर्तन चलते रहते हैं। एक देश की अर्थ-व्यवस्था में अनेक घटक होते हैं जिनमें समय-समय पर परिवर्तन होते ही रहते हैं और इन परिवर्तनों से आर्थिक विकास की गति तथा दिशा का भान होता है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए गतिशील अर्थशास्त्र का ही सहारा लेना पड़ता है और इसीलिए यह कहना समीचीन है कि आर्थिक विकास की प्रकृति गतिशील है। इसका अध्ययन स्तर यथा स्थैतिक न होकर मूलतः गतिशील या प्रावर्गिक होता है।

आर्थिक विकास का माप

(Measurement of Economic Growth)

आर्थिक विकास का सम्बन्ध दीर्घकालीन परिवर्तनों से होता है, अतः इसकी कोई सही या निश्चित माप देना बड़ा कठिन है। आर्थिक विकास के माप के सम्बन्ध में प्राचीन और आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अपने-अपने विचार प्रकट किए हैं।

(क) प्राचीन अर्थशास्त्रियों के विचार

प्राचीन अर्थशास्त्रियों में बालिज्यवादियों का विचार था कि देश में सोना-चांदी के कोष में वृद्धि होना ही आर्थिक विकास का माप है। इसी दृष्टिकोण के आधार पर उन्होंने देश के आर्थिक विकास के लिए निर्यात बढ़ाने के सिद्धान्तों पर बल दिया और ऐसे उपायों का पक्ष लिया जिनमें निर्यात में वृद्धि सम्भव हो। बाद में एडम स्मिथ ने विचार प्रकट किया कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होने से देश का आर्थिक विकास होता है। अपने इसी विचार के आधार पर उसने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में सरकार द्वारा स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए ताकि लोग अधिकाधिक उत्पादन कर सकें और अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर सकें जिससे लोक-कल्याण में अधिकाधिक वृद्धि हो। एडम स्मिथ के समकालीन अर्थशास्त्रियों ने भी कुछ इसी प्रकार के विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि यदि देश में उत्पादन की मात्रा तीव्र होगी तो स्वतः ही आर्थिक विकास की गति बढ़ेगी, अन्यथा आर्थिक विकास सम्भव नहीं हो सकेगा। इन सब अर्थशास्त्रियों के विपरीत कालेमाकर्म ने सहकारिता के सिद्धान्त का समर्थन किया। उसने कहा कि पूंजीवाद को समाप्त करके साम्यवाद या समाजवाद पर चलने में ही कुशल है और तभी देश में लोक-कल्याण व आर्थिक विकास लाया जा सकता है। जे एस मिल ने स्वतन्त्र व्यापार की नीति के कुपरिणामों को दिखाकर, यह विचार प्रकट किया कि लोक कल्याण और आर्थिक विकास के लिए सहकारिता के सिद्धान्त को महत्त्व देना चाहिए। उसने कहा कि सहकारिता ही आर्थिक विकास का माप है और जिस देश में जितनी अधिक सहकारिता का चलन होगा, वह देश उतना ही अधिक लोक-कल्याण और आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होगा।

(ख) आधुनिक विचारधारा

आधुनिक अर्थशास्त्र ने उत्पादन के साथ-साथ वितरण को भी आर्थिक विकास का माप माना। उन्होंने आर्थिक विकास के माप के लिए किसी एक तत्त्व पर नहीं बरन् सभी आवश्यक तत्वों पर बल दिया और कहा कि इन तत्वों के सामूहिक प्रयासों के फलस्वरूप ही किसी राष्ट्र का आर्थिक विकास सम्भव हो सकता है। यदि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचारों का विश्लेषण करें तो आर्थिक विकास के मुख्य मापदण्ड ये ठहरते हैं—

12 आर्थिक विकास के सिद्धान्त

1. राष्ट्रीय आय—आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास की दृष्टि से सकल राष्ट्रीय उत्पादन को न लेकर शुद्ध उत्पादन को ही लिया है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन आर्थिक विकास का माप इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें मशीनों व उपकरणों पर होने वाली घिसाई या ह्रास की राशि को घटाने की व्यवस्था नहीं की जाती, जबकि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में ऐसा किया जाता है। इस शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की मात्रा में वृद्धि आर्थिक विकास का सूचक होती है, पर शर्त यह है कि यह वृद्धि दीर्घकालीन और निरन्तर होनी चाहिए।

2. आय का वितरण—आधुनिक विचारधारा के अनुसार आर्थिक विकास का दूसरा माप-दण्ड आय का वितरण है। राष्ट्रीय आय तो बढ़ रही हो, किन्तु उसका व्यापकित ढंग से वितरण न हो तो उसे विकास की अवस्था नहीं कहा जा सकता। आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय आय का इस ढंग से वितरण हो कि सबको पर्याप्त आय प्राप्त हो सके। यदि बड़ी हुई राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग केवल गिने चुने व्यक्तियों को ही मिलता है तो इस स्थिति को आर्थिक विकास का सूचक नहीं माना जा सकता। इस बात की पूरी सम्भावना है कि राष्ट्रीय आय बढ़ने पर भी देश में दरिद्रता व्याप्त हो। उदाहरणार्थ भारत में नियोजन के प्रथम 15 वर्षों में राष्ट्रीय आय 9,530 करोड़ रुपये से बढ़ कर 20,010 करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक पहुँच गई और इस तरह प्रति व्यक्ति आय 266 रुपये से बढ़ कर 421 रु. वार्षिक हो गई, लेकिन फिर भी अमीर अधिक अमीर और गरीब अधिक गरीब होते गए, क्योंकि बड़ी हुई राष्ट्रीय आय का व्यापकित ढंग से वितरण नहीं हो पाया। यही स्थिति आज भी विद्यमान है।

3. गरीब जनता को अधिक लाभ—जब तक देश की गरीब जनता की आय में वृद्धि होकर उसे अधिकाधिक लाभ प्राप्त नहीं होगा तब तक उस देश की आर्थिक व्यवस्था विकसित नहीं कही जा सकती। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो और गरीब जनता को अधिकाधिक लाभ मिले।

4. सामान्य एवं वास्तविक विकास दर—आर्थिक विकास का चौथा मापक सामान्य और वास्तविक विकास की दर है। सामान्य विकास की दर वह है जिस पर प्रति वर्ष विकास सामान्यतः हुआ करता है। यह दर अनुमान पर आधारित होती है। वास्तविक दर वह है जो वास्तव में होती है। जिस देश की अर्थ-व्यवस्था में सामान्य दर और वास्तविक दर समान होती है वहाँ आर्थिक विकास की स्थिति पाई जाती है। यदि सामान्य विकास दर वास्तविक विकास दर से कम होती है तो वह अर्थ-व्यवस्था अर्द्ध-विकसित मानी जानी चाहिए। इसी प्रकार यदि सामान्य विकास दर वास्तविक दर से अधिक होती है तो उस अर्थ-व्यवस्था को अधिक विकासशील स्थिति में माना जाना चाहिए।

5. प्रति व्यक्ति आय—राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ ही प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना भी आवश्यक है। यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि न हो तो आर्थिक विकास की स्थिति नहीं मानी जायेगी। यह सम्भव है कि राष्ट्रीय आय बढ़ने पर भी जनता की निधनता बढ़ती जाए। उदाहरणार्थ राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या की मात्रा में भी तेजी से वृद्धि हो रही है तो प्रति व्यक्ति आय समान रह सकती है या कम हो सकती है और तब ऐसे राष्ट्र को आर्थिक विकास की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

इस प्रकार निष्कर्ष यही निकलता है कि एक देश में आर्थिक विकास का कोई एक निश्चित माप नहीं हो सकता। प्रो डी ब्राइटसिंह ने लिखा है "एक देश द्वारा प्राप्त की गई आर्थिक सम्पत्ति के स्तर का माप उस देश द्वारा प्राप्त की गई उत्पादक सम्पत्ति की मात्रा से लगाया जा सकता है। अर्थ-व्यवस्था के विकसित होने पर नए उत्पादक साधनों को खोज लिया जाता है, विद्यमान साधनों का अधिक उपयोग सम्भव होता है तथा उपलब्ध राष्ट्रीय एवं मानवीय सम्पत्ति का उपयोग किया जाता है। एक देश में जितने अधिक साधन होते हैं उतनी ही अच्छी उसकी आर्थिक स्थिति होती है।"

आर्थिक विकास का महत्व (Importance of Economic Growth)

पूर्व विवरण से आर्थिक विकास का महत्व स्वतः स्पष्ट है। आधुनिक युग में आर्थिक विकास ही एकमात्र ^{साधन} वह है जिसके द्वारा मानव अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। आर्थिक विकास के अभाव में किसी भी देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने और निर्धनता व बेरोजगारी को मिटाने के लिए आर्थिक विकास ही एकमात्र और सर्वोत्तम उपाय है। आज के भौतिकवादी युग का नारा ही आर्थिक विकास का है।

आर्थिक विकास का महत्व प्रत्येक क्षेत्र में प्रकट है। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ने से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है जिससे बचत क्षमता का विकास होता है। बचत बढ़ने से पूँजी निर्माण बढ़ता है और फलस्वरूप विनियोग दर में पूर्वपक्ष अधिक वृद्धि हो जाती है।

आर्थिक विकास के फलस्वरूप देशों में नए-नए उद्योगों का जन्म और विकास होता है। नए उद्योगों के पनपने से जनता को रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। परिणामस्वरूप बेरोजगारी मिटने लगती है। इनके अतिरिक्त श्रमिकों के समुचित प्रशिक्षण, विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन, श्रम गतिशीलता आदि को पर्याप्त प्रोत्साहन मिलता है। उत्पादन के विभिन्न साधनों का समुचित उपयोग होने से उत्पादन में वृद्धि होती है और राष्ट्रीय आय अधिकतम होने की सम्भावना बढ़ जाती है।

आर्थिक विकास के कारण पूँजी निर्माण और विनियोजन दर में वृद्धि होने लगती है जिससे पूँजी की गतिशीलता बढ़ जाती है और फिर भविष्य में पूँजी निर्माण और भी अधिक होने लगता है। आर्थिक विकास से देश में औद्योगिकरण प्रोत्साहित होता है। फलतः जनता की आय में वृद्धि होती है और उसकी कर दान क्षमता बढ़ जाती है। आर्थिक विकास के कारण नए-नए उद्योगों की स्थापना होने से व्यक्ति का चुनाव क्षेत्र भी अधिक व्यापक हो जाता है। उसे मन चाहे क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर मिलता है।

आर्थिक विकास के फलस्वरूप जब व्यक्ति को हचि के अनुकूल कार्य मिलता है तो उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है जिससे देश में कुल उत्पादन प्रोत्साहित होता है। साथ ही जनता को अधिकाधिक सेवाएँ और पदार्थ उपलब्ध होने लगते हैं। इसके अतिरिक्त नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से उनका मनोवैज्ञानिक झुकाव मानवता की ओर अधिक होने लगता है। जब नागरिक भूखे और नमो नहीं रहते तो वे अधिक दयालु और सहनशील बन जाते हैं। आर्थिक विकास के कारण देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का कुशलता और मितव्ययितापूर्वक विदोहन सम्भव हो जाता है। कृषि पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। निष्क्रिय भूमि पर कृषि होने लगती है। नवीन वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग के कारण प्रति हेक्टर उत्पादन में वृद्धि होती है और साथ ही भूमि पर जनसंख्या का भार भी घटने लगता है।

आर्थिक विकास के कारण मनुष्य प्राकृतिक प्रकोपों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ होता है। तकनीकी साधनों के बल पर अल्प श्रम से ही पर्याप्त खाद्य सामग्री और उत्पादन की अन्य वस्तुएँ प्राप्त की जाना सम्भव हो जाता है जिससे अकाल और अभाव आदि के कष्ट बहुत कम हो जाते हैं। सामाजिक सेवाओं और मनोरंजन के साधनों में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। फलस्वरूप मृत्यु दर घटकर लोगों की औसत आयु बढ़ जाती है। आर्थिक विकास का महत्व सामरिक क्षेत्र में भी प्रकट होता है। औद्योगिक दृष्टि से सम्पन्न देश अपनी सामरिक व प्रतिरक्षा शक्ति को भली प्रकार सुरक्षित बना सकता है। आर्थिक विकास के कारण देश में इस प्रकार के साधन जुटाना सम्भव हो जाता है जिनसे सामाजिक व्यवस्था को सुचारु ढंग से विकसित किया जा सके।

इस प्रकार प्रकट है कि आर्थिक विकास के फलस्वरूप एक देश के सम्पूर्ण जीवन में विकास होने लगता है। आर्थिक विकास इस भौतिक युग में सर्वांगीण विकास की कुँजी है।

आर्थिक विकास के दोष—इस सतार में कोई भी वस्तु सिद्धान्त या विचार सर्वथा दोषमुक्त नहीं माना जा सकता और आर्थिक विकास भी इसका कोई अपवाद नहीं है। जहाँ आर्थिक विकास एक राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए आवश्यक है वहाँ इसके कुछ दोष भी हैं जिनसे यथा-सम्भव बचते रहना चाहिए। आर्थिक विकास में विशाल पैमाने पर उत्पादन की जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है और

उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत रुचि पर ध्यान नहीं दिया जाता। आर्थिक विकास के कारण मनुष्य का जीवन मशीनी हो जाता है। विशिष्टीकरण के कारण वह सदैव एक ही क्रिया दोहराता रहता है और इस प्रकार नीरसता का वातावरण पनपता है। पूँजी और श्रम के झगड़े भी सामाजिक-आर्थिक जीवन को अभिगन्त किए रहते हैं। पूँजीपति उद्योगों से अशिकाधिक लाभ कमाने के लिए श्रमिकों का शोषण करने लगते हैं। फलस्वरूप पूँजीपतियों और श्रमिकों में विवाद उठ खड़े होने हैं जो ताला-बन्दी, हड़ताल और हिंसा का रूप ले लेते हैं। इन झगड़ों के कारण कभी-कभी तो देश की सम्पूर्ण आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाती है।

आर्थिक विकास से एकाधिकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। भौतिकवाद इतना छा जाता है कि मानवीय मूल्यों का ह्रास होने लगता है और नास्तिक मनोवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। आर्थिक विकास व्यक्तिवादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देता है जिसमें समुक्त और व्यापक परिवार प्रथा समाप्त होने लगती है। व्यक्ति धीरे-धीरे इतना स्वार्थी बन जाता है कि उसे अपने परिवार और गाँव की चिन्ता नहीं रहती। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है।

आर्थिक विकास के फलस्वरूप उद्योगों के केन्द्रीयकरण का भय बढ़ जाता है। महत्त्वपूर्ण उद्योग पूँजीपतियों के हाथों में केन्द्रित हो जाते हैं जिनसे प्राप्त होने वाले लाभ का अधिकांश भाग वे खुद ही हड़प जाते हैं। आर्थिक केन्द्रीयकरण की इस प्रवृत्ति के कारण समाज में आर्थिक बल्याण की वृद्धि नहीं हो पाती और गरीब वर्गों, बीमारियों आदि के दोष देश में धर कर जाते हैं।

आर्थिक विकास देश में धन के असमान वितरण के लिए भी बहुत कुछ उत्तरदायी होता है। पूँजीपति और उद्योगपति औद्योगिक क्षेत्र में छा जाते हैं। वे लाभ का बहुत बड़ा भाग स्वयं हड़प जाते हैं जब कि श्रमिकों को बहुत कम भाग मिल पाता है। फलस्वरूप आर्थिक विषमताएँ पूर्वपेक्षा बढ़ जाती हैं। इसके अतिरिक्त देश के कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। मशीनों के उपयोग के कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन करके बड़े पैमाने के लाभ प्राप्त करने का लालच बना रहता है। लघु और कुटीर उद्योगों की ओर पूँजीपतियों की रुचि नहीं जाती। इसके अतिरिक्त इन उद्योगों की वस्तुएँ भी महंगी होती हैं जो प्रतिस्पर्द्धा में टिक नहीं पाती।

निष्कर्षतः आर्थिक विकास के अच्छे और बुरे दोनों ही पहलू हैं। कुल मिलाकर अच्छे पहलू ही अधिक सबल और ग्राह्य हैं। आर्थिक विकास के अभाव में कोई देश व समाज जिन बुराइयों और अभिशापों से ग्रस्त रहता है उनकी तुलना में आर्थिक विकास की अवस्था में पाई जाने वाली बुराइयाँ बहुत कम गंभीर और पीडाकारक हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास की बुराइयाँ ऐसी नहीं हैं जिनका कोई समाधान न हो सके। प्रयत्न करने पर इसकी अनक बुराइयों को बहुत कम किया जा सकता है।

अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की विशेषताएँ

(Characteristics of Under-developed Economies)

“एक अर्द्ध-विकसित देश अफ्रीका के जिराफ की तरह है जिसका वर्णन करना कठिन है, किन्तु जब हम उसे देखते हैं तो समझ जाते हैं।”

—सिंगर

आधुनिक आर्थिक साहित्य में विश्व की अर्थ-व्यवस्थाओं को विकसित और अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में वर्गीकरण करने का चलन-सा हो गया है। पूर्व प्रचलित शब्द अर्थात् ‘पिछड़े हुए’ (Backward) और ‘उन्नत’ (Advanced) के स्थान पर अर्द्ध-विकसित एवं विकसित शब्दों का प्रयोग श्रेष्ठ समझा जाने लगा है। ‘पिछड़े हुए’ शब्द की अपेक्षा ‘अर्द्ध-विकसित’ शब्द वास्तव में अच्छे भी हैं, क्योंकि इसमें विकास की सम्भावना पर बल दिया गया है।

अर्थ-व्यवस्था का विकास एक अत्यन्त जटिल प्रक्रिया है। यह अनेक प्रकार के भौतिक और मानवीय घटकों के अन्तर्सम्बन्धों एवं व्यवहारों का परिणाम होता है। इसीलिए विकसित या अल्प-विकसित अथवा अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं का अन्तर स्पष्ट करना और उनके लक्षणों को सर्वमान्य रूप में ढूँढ़ पाना बहुत कठिन है।

विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं अथवा देशों के ज्ञान और परिभाषा के सम्बन्ध में प्रायः इतनी कठिनाई पंदा नहीं होती जितनी अर्द्ध-विकसित या अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में। विकास के अर्थ-शास्त्र में अर्द्ध-विकसित व्यवस्था की कोई ऐसी परिभाषा देना जिसमें इसके सब आवश्यक तत्त्व शामिल किए गए हों, अत्यन्त कठिन है। एच. डब्लू. सिंगर (H. W. Singer) का मत है कि अर्द्ध-विकसित देश की परिभाषा का कोई भी प्रयास समय और धन का अपव्यय है क्योंकि “एक अर्द्ध-विकसित देश अफ्रीका के जिराफ की भाँति है जिसका वर्णन करना कठिन है, लेकिन जब हम उसे देखते हैं तो समझ जाते हैं।”

वस्तुतः अर्द्ध-विकसित अवस्था एक तुलनात्मक व्यवस्था है। विभिन्न देशों में उपस्थित विभिन्न समस्याओं और दशाओं के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं पर यह

भिन्न अर्थों को सूचित करता है। अधिक जनसंख्या वाले कई देश जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर के कारण अपने-आपको अर्द्ध-विकसित कहते हैं। कम जन-संख्या और साधनों के विकास की विशाल सम्भावनाओं वाले देश पूँजी की स्वतंत्रता को अर्द्ध-विकास का निर्णायक तत्त्व मानते हैं। परतन्त्र देश चाहे उनमें विदेशी शासन के अन्तर्गत पर्याप्त आर्थिक विकास हुआ हो, जब तक विदेशी शासन में रहेगे अपने आपको अर्द्ध-विकसित रहेगे। इसी प्रकार किसी देश में सामन्तवादी व्यवस्था की उपस्थिति 'अर्द्ध-विकसित' होने का पर्याप्त प्रमाण माना जायेगा चाहे इस प्रकार के कुछ समाजों में लोगों की स्वीकृत न्यूनतम जीवन-स्तर उपलब्ध हो। वास्तव में विश्व के मान-चित्र में एक प्रतिनिधि अर्द्ध-विकसित देश को बता सकना बड़ा कठिन कार्य है तथा यह इसलिए और भी कठिन है कि अर्द्ध-विकसित विश्व विभिन्न प्रकार के देशों का समूह है जिसमें स्वयं में विभिन्नताएँ पाई जाती हैं।

अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था का आशय और प्रमुख परिभाषाएँ (Meaning and Definitions of Under-developed Economy)

कोई देश अर्द्ध-विकसित है या विकसित है इसका निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि हम विकसित देश किसे मानते हैं या विकास का आधार किसे मानते हैं। प्रो एस हरबर्ट फ्रेंकेल ने कहा है कि "एक देश आर्थिक दृष्टि से विकसित है या अर्द्ध-विकसित है यह उस विशिष्ट मापदण्ड पर निर्भर करेगा जिसे व्यक्ति द्वारा विकास का आधार माना गया है। इस आधार की अनुपस्थिति या कम उपस्थिति अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था की सूचक होगी।" यही कारण है कि अर्द्ध-विकसित देशों की विभिन्न आधारों पर व्याख्या की जाती है। पाल हॉफ मेन ने एक अर्द्ध-विकसित देश का निम्न शब्दों में चित्रण किया है :—

"प्रत्येक व्यक्ति जब किसी अर्द्ध-विकसित देश को देखता है तो उसे जान जाता है। यह एक ऐसा देश होता है जिसमें निर्धनता होती है, नगरों में भिखारी होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जन-जीवन निर्वाह भर कर लेते हैं। यह एक ऐसा देश होता है जिसमें स्वयं के कारखाने नहीं होते हैं और बहुधा शक्ति और प्रकाश की अपर्याप्त पूर्ति होती है। इसमें बहुधा अपर्याप्त सबकें, रेलें, सरकारी सेवाएँ और पिछड़े कृषि-संचार साधन होते हैं। इसमें थोड़े ही अल्पताल और उच्च शिक्षण संस्थाएँ होती हैं। इसके अधिकांश लोग लिख और पढ़ नहीं सकते हैं। सामान्य जनता निर्धन होने पर भी इसमें कुछ व्यक्ति धनी होते हैं और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। इसकी बैंकिंग प्रणाली अविकसित होती है और छोटे-छोटे ऋण, ऋणदाताओं के द्वारा प्राप्त करने होते हैं जो शोषण करते हैं। अर्द्ध-विकसित देश का एक प्रमुख लक्षण यह होता है कि बहुधा इसके सब निर्यातों में कच्चा माल, कच्चे खनिज, फल या कुछ रेशों का उत्पादन होते हैं जिनमें कुछ विलासितापूर्ण दस्तकारियाँ होती

18 आर्थिक विकास के सिद्धान्त

हैं। बहुधा निर्यात किए जाने वाले इन पदार्थों का उत्पादन या उत्खनन विदेशी कम्पनियों के हाथों में होता है।¹

अर्द्ध-विकसित देश अथवा अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था का विवरण कुछ अन्य प्रमुख विद्वानों ने इस प्रकार किया है—

श्री पी टी बावर एव बी एस यामे के मतानुसार "अर्द्ध-विकसित देश शब्द बहुधा मोटे रूप से उन देशों या प्रदेशों की ओर संकेत करते हैं जिनकी वास्तविक आय एवं प्रति व्यक्ति पूँजी का स्तर उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और आस्ट्रेलिया के स्तर से नीचा होता है।"²

इसी प्रकार की परिभाषा समुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रकाशन में भी दी गई है जो इस प्रकार है—

"एक अर्द्ध-विकसित देश वह है जिसकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, समुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया और पश्चिमी यूरोपीय देशों की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की तुलना में कम हो।"³

उपरोक्त परिभाषाओं के अनुसार जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और आस्ट्रेलिया आदि देशों की प्रति व्यक्ति आय से कम होती है उन्हें अर्द्ध-विकसित कहते हैं। ये परिभाषाएँ अर्द्ध-विकसित देश का एक अच्छा आधार प्रस्तुत करती हैं, किन्तु प्रति व्यक्ति आय ही किसी देश के विकसित और अविकसित होने का उचित मापदंड नहीं है। प्रति व्यक्ति आय विश्व में सबसे ज्यादा रखने वाला कुर्वंत केवल इसी आधार पर विकसित नहीं कहला सकता है।

प्रो जे. आर. हिक्स के मतानुसार, "एक अर्द्ध-विकसित देश वह है जिसमें तकनीकी और मौद्रिक सीमाएँ व्यवहार में उत्पत्ति और बचत के वास्तविक स्तर के बराबर नीची होती है जिसके कारण श्रम की प्रति इकाई (प्रति कार्य-शील व्यक्ति) पुरस्कार उससे कम होता है जो ज्ञात तकनीकी ज्ञान का ज्ञात साधनों पर उपयोग करने पर होता।"³

इस परिभाषा में मुख्यतः तकनीकी तत्वों पर ही अधिक जोर दिया गया है और इसमें प्राकृतिक साधन, जनसंख्या आदि आर्थिक तथा अन्य अनार्थिक तत्वों पर जोर नहीं दिया गया है।

1 Ban-r and Yame *Economics of Under-developed Countries* p 3

2 United Nations *Measures for the Economic Development of Underdeveloped Countries*, p 3

3 J R Hicks . *Contribution to the Theory of Trade Cycles*

भारतीय योजना आयोग के अनुसार “एक अर्थ-विकसित देश वह है जिसमें एक और अधिक या कम अर्थ में अप्रयुक्त मानव शक्ति और दूसरी ओर अशोषित प्राकृतिक साधनों का सह-अस्तित्व हो।”¹

यह परिभाषा इस आधार पर अधिक अच्छी है कि इसमें अशोषित साधनों की अर्थ-विकास का संकेत माना गया है जो अर्थ-विकसित देश का एक प्रमुख लक्षण होता है, किन्तु इसमें इस बात का स्पष्टीकरण नहीं मिलता कि ऐसा क्यों हुआ है। इसके अतिरिक्त यदि ये साधन पूँजी, साहस आदि की कमी के कारण अशोषित हैं तब तो ठीक है किन्तु यदि अधिक मदी आदि के कारण मानवीय या अन्य साधन अप्रयुक्त रहते हैं तो यह अनिवार्य रूप से अर्थ-विकसित देश की पहचान नहीं है।

प्रो जेकब वाइनर के मतानुसार, “एक अर्थ-विकसित देश वह है जिसमें अधिक पूँजी या अधिक श्रम-शक्ति या अधिक उपलब्ध साधनों या इनमें से सभी के उपयोग की अधिक संभावनाएँ होती हैं जिससे इसकी वर्तमान जनसंख्या का उच्च जीवन-स्तर पर निर्वाह किया जा सके या यदि इस देश की प्रति व्यक्ति आय का स्तर पहले से ही ऊँचा हो तो जीवन स्तर को नीचा किये बिना ही अधिक जनसंख्या का निर्वाह किया जा सके।”²

उपरोक्त परिभाषा का सार यह है कि अर्थ-विकसित देश वह होता है जहाँ आर्थिक विकास की ओर संभावनाएँ समाप्त नहीं हुई हो और जहाँ पर वर्तमान जनसंख्या के जीवन स्तर को उच्च करने या वर्तमान जीवन स्तर पर अधिक जनसंख्या का निर्वाह किये जाने की गुंजाइश हो। इस परिभाषा की एक अच्छी बात यह है कि इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि ऐसे देशों में साधनों का उपयोग करके जीवन स्तर को उच्च बनाया जा सकता है, किन्तु यह परिभाषा प्राकृतिक साधनों के पूँजी द्वारा प्रतिस्थापना को कम महत्व देती है जैसा कि जापान, हॉलैंड और स्विट्जरलैंड में हुआ है। डॉ. आस्करलेन्गे के शब्दों में, “एक अर्थ-विकसित अर्थ-व्यवस्था वह है जिसमें उपलब्ध पूँजीगत वस्तुओं का स्टॉक उत्पादन की आधुनिक तकनीक के आधार पर कुल उपलब्ध श्रमशक्ति को नियोजित करने के लिए अपर्याप्त होता है।”

प्रो० नर्कसे ने भी उन देशों को अर्थ-विकसित देश बतलाया है जो प्रगतिशील देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या और प्राकृतिक साधनों के सम्बन्ध में कम पूँजी से सम्पन्न होते हैं।

डॉ० लेंगे और नर्कसे ने पूँजी की कमी पर ही जोर दिया है अतः ये परिभाषाएँ एकांगी होने के साथ-साथ विकास की सम्भावनाओं तथा सामाजिक और

1. *India's First Five Year Plan.*

2. *Jacob Viner : International Trade and Economic Development, p. 128.*

राजनीतिक दशाग्रो के महत्व के बारे में कुछ नहीं बताती हैं जैसा कि स्वयं प्रो० नर्वंसे ने लिखा है—

“आर्थिक विकास का मानव व्यवहार, सामाजिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दशाग्रो और ऐतिहासिक आकस्मिकताग्रो से गहरा सम्बन्ध है। पूँजी आवश्यक है किन्तु यह प्रगति की पर्याप्त शक्ति नहीं है।” अतः अर्द्ध-विकसित देशों की परिभाषा में वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री यूजीन स्टेनले ने अर्द्ध-विकसित देश की व्याख्या करते हुए बतलाया है कि “यह एक ऐसा देश होता है जिसमें जन-दरिद्रता व्याप्त होती है, जो किसी अस्थायी दुर्भाग्य का परिणाम नहीं होकर स्थायी होती है, जिसमें उत्पादन तकनीक पुरानी और सामाजिक संगठन अनुपयुक्त होता है, जिसका अर्थ यह है कि देश की निर्धनता पूर्ण रूप से प्राकृतिक साधनों की कमी के कारण नहीं होती है और इसे अन्य देशों में परीक्षित उपायों द्वारा कम किया जा सकता है।”¹

श्री स्टेनले की उपरोक्त परिभाषा में अर्द्ध-विकसित देश के कुछ लक्षणों की ओर सचेत किया गया है, किन्तु अर्द्ध-विकास की परिभाषा इन तीन लक्षणों के आधार पर पर्याप्त नहीं हो जाती। इस परिभाषा में सामाजिक दशाग्रो पर भी आर्थिक विकास की निर्भरता स्वीकार की गई है।

वस्तुतः प्रति व्यक्ति उत्पादन एक और प्राकृतिक साधनों पर और दूसरी ओर मानव व्यवहार पर निर्भर करता है। लगभग समान प्राकृतिक साधन होने हुए भी कई देशों की आर्थिक प्रगति में अन्तर प्रतीत होता है। इसका एक प्रमुख कारण मानव व्यवहार का अन्तर है। श्री अल्फ्रेड बोन के अनुसार मानव व्यवहार विशेष रूप से जन-रुचि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। श्री डबल्यू० ए० लेविस ने भी इसी बात पर बल देते हुए लिखा है कि “जन उत्साह योजना के लिए स्निग्धता देने वाला तैल और आर्थिक विकास का पेट्रोल है।” अतः अर्द्ध-विकसित देशों की परिभाषा में इस तत्व की भी अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में डॉ० डी० एस० नाग की परिभाषा उचित जान पड़ती है जो इस प्रकार है—

“एक अर्द्ध-विकसित देश या प्रदेश वह होता है जिसमें इसकी वर्तमान जनसंख्या को उच्च जीवन स्तर पर निर्वाह करने या यदि जनसंख्या बढ़ रही हो, तो जनसंख्या वृद्धि की दर से अधिक गति से जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए अधिक पूँजी, या अधिक श्रम-शक्ति या अधिक उपसब्ध या सम्भाव्य प्राकृतिक साधनों या उनके संयुक्त उपयोग के लिए पर्याप्त सम्भावनाएँ हों और इसके विरुद्ध जनता में उत्साह हो।”

‘अर्द्ध-विकसित’, ‘अविकसित’, ‘निधन’ और ‘पिछड़े हुए’ देश (‘Under-developed’, ‘Undeveloped’, ‘Poor’ and ‘Backward’ Countries)

कभी-कभी इन सभी शब्दों को पर्यायवाची शब्द माना जाता है और अर्द्ध-विकसित देशों को ‘अविकसित’, ‘निधन’ और ‘पिछड़े हुए’ आदि शब्दों से संबोधित किया जाता है। किन्तु आजकल इन शब्दों में भेद किया जाता है और अर्द्ध-विकसित शब्द ही अधिक उपयुक्त माना जाने लगा है। अधिकांश साम्राज्यवादी देशों के लेखकों ने अपने उपनिवेशों के बारे में लिखते हुए ‘गरीब’ या ‘पिछड़े हुए’ शब्दों का प्रयोग किया है। बहुधा इन शब्दों से और जिस प्रकार इनका प्रयोग किया गया है यह निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर ने विश्व को धनी और गरीब दो भागों में विभाजित किया है, एक गरीब देश इसलिए गरीब है क्योंकि इसके प्राकृतिक साधन कम हैं और उसे अधिक स्थिरता के उसी निम्न स्तर पर रहता है किन्तु अब यह नहीं माना जाता है कि इन निधन देशों के प्राकृतिक साधन भी कम हैं और यही इनकी निधनता का मुख्य कारण है। इसके अतिरिक्त ‘निधनता’ केवल देश की प्रति व्यक्ति निम्न आय को ही इंगित करती है, अर्द्ध-विकसित देश की अन्य विशेषताओं को नहीं। इसीलिए ‘निधन’ एवं ‘पिछड़े हुए’ शब्दों का प्रयोग अलोकप्रिय हो गया है। इसी प्रकार (Undeveloped) शब्द भी अर्द्ध-विकसित देश का समानार्थक माना जाता है किन्तु दोनों में भी यह स्पष्ट अन्तर किया जाता है कि अविकसित देश वह होता है जिसमें विकास की संभावनाएँ नहीं होती हैं। इसके विपरीत अर्द्ध-विकसित देश वह होता है जिसमें विकास की पर्याप्त संभावनाएँ हों। अन्टार्क्टिक, आर्कटिक और सहारा के प्रदेश अविकसित कहला सकते हैं क्योंकि वर्तमान तकनीकी ज्ञान एवं अन्य कारणों से इन प्रदेशों के विकास की संभावनाएँ सीमित हैं। किन्तु भारत, पाकिस्तान, बोलम्बिया, युगांडा आदि अर्द्ध विकसित देश कहलाएँगे क्योंकि इन देशों में विकास की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। इस प्रकार अविकसित शब्द सैद्धांतिक स्थिति का द्योतक है। वस्तुतः किसी देश के बारे में यह धारणा बना लेना कठिन है कि उस देश में निरपेक्ष रूप से साधनों की स्वल्पता है क्योंकि साधनों की उपयोगिता तकनीकी ज्ञान के स्तर, मार्ग की दशाएँ और नई खोजों पर निर्भर करती है। वस्तुतः इन देशों के प्राकृतिक साधन, तकनीकी ज्ञान और उपकरण के इन साधनों पर उपयोग नहीं किए जाने के कारण अधिकांश में अविकसित दशा में होते हैं पर इनके विकास की पर्याप्त संभावनाएँ होती हैं। संयुक्त राष्ट्र सभ की एक विशेष शक्ति के अनुसार, “सब देश, चाहे उनके प्राकृतिक साधन कितने ही हों, वर्तमान में अपने इन साधनों के अधिक अच्छे उपयोग के द्वारा अपनी आय को बड़ी मात्रा में बढ़ा सकने की स्थिति में हैं।”

अतः ‘अविकसित’ शब्द के स्थान पर ‘अर्द्ध-विकसित’ शब्द का उपयोग किया जाने लगा है। ये अर्द्ध-विकसित देश आजकल आर्थिक विकास का प्रयत्न कर रहे हैं

जिसके परिणामस्वरूप इन्हें 'विकासशील' (Developing) देश भी कहते हैं; किन्तु सामान्यतया इन सब शब्दों को लगभग समान अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है।

अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था की विशेषताएँ या लक्षण (Characteristics of Under-developed Economies)

अर्द्ध-विकसित विश्व विभिन्न प्रकार के देशों का समूह है। इन देशों की अर्थ-व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के अन्तर पाए जाते हैं। किन्तु इतना सब होते भी इन अर्द्ध-विकसित देशों में एक आधारभूत समानता पाई जाती है। यद्यपि किसी एक देश को प्रतिनिधि अर्द्ध-विकसित देश की सजा देना कठिन है, किन्तु फिर भी कुछ ऐसे सामान्य लक्षणों को बताना संभव है जो कई अर्द्ध-विकसित देशों में आमतौर से पाए जाते हैं। यद्यपि ये सामान्य लक्षण सब अर्द्ध-विकसित देशों में समान अंशों में नहीं पाए जाते और न केवल ये ही अर्द्ध-विकसित देशों के लक्षण होते हैं, किन्तु ये सब मिलकर एक अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था को बनाने में समर्थ हैं। अर्द्ध-विकसित देशों के इन लक्षणों को मुख्यतः निम्नलिखित वर्गों में विभाजित करके अध्ययन किया जा सकता है—

- (अ) आर्थिक लक्षण
- (ब) जनसंख्या सम्बन्धी लक्षण
- (स) सामाजिक विशेषताएँ
- (द) तकनीकी विशेषताएँ
- (ई) राजनीतिक विशेषताएँ

(अ) आर्थिक लक्षण

(Economic Characteristics)

आर्थिक लक्षणों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं—

1. अर्द्ध-विकसित प्राकृतिक साधन (Under-developed Natural Resources)—अर्द्ध-विकसित देशों का एक प्रमुख लक्षण इनके साधनों का अर्द्ध-विकसित होना है। इन देशों में यद्यपि ये साधन पर्याप्त मात्रा में होते हैं, किन्तु पूँजी और तकनीकी ज्ञान के अभाव तथा अन्य कारणों से इन साधनों का देश के विकास के लिए पर्याप्त और उचित विदोहन नहीं किया गया होता है। उदाहरणार्थ एशिया, अफ्रीका, लेटिन अमेरिका, आस्ट्रेलिया एवं द्वीप-समूहों में बहुत बड़ी मात्रा में भूमि ससाधन अप्रयुक्त पड़े हुए हैं। श्री केलोग (Kellogg) के अनुसार उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका तथा न्यूग्विनिया, मेडागास्कर, बोनिनो आदि द्वीपों की कम से कम 20% अप्रयुक्त भूमि कृषि योग्य है जिसका कृषि कार्यों में उपयोग करके विश्व की कृषि भूमि में एक बिलियन एकड़ अतिरिक्त भूमि की वृद्धि की जा सकती है। प्रो० थोन द्वारा हाल ही में किए गए मध्यपूर्व के आठ देशों के सर्वेक्षण से ज्ञात होता

है कि इन देशों के कुल 118 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से केवल एक तिहाई से भी कम भूमि में कृषि की जाती थी और 85 मिलियन एकड़ कृषि योग्य भूमि बेकार पड़ी हुई थी। श्री वालिन क्लार्क ने बतलाया है कि विश्व की वर्तमान कृषि योग्य भूमि से उपभोग और कृषि के डेनिश स्टैंडर्ड के अनुसार 12,000 मिलियन व्यक्तियों का निर्वाह किया जा सकता है जबकि वर्तमान में केवल 2,300 मिलियन लोगों का ही निर्वाह किया जा रहा है। स्पष्टतः भूमि के ये अप्रयुक्त साधन अधिकांश में अर्द्ध-विकसित देशों में ही हैं।

इसी प्रकार अर्द्ध-विकसित देशों में खनिज एवं शक्ति के साधनों की सम्पन्नता है, किन्तु यहाँ इनका विकास नहीं किया गया है। अफ्रीका में विश्व की सम्भावित जल-शक्ति के 44% साधन हैं, किन्तु यह महाद्वीप केवल 0.1% जल साधनों का ही उपयोग कर रहा है। श्री बोयटिन्सकी और बोयटिन्सकी के अनुसार एशिया, मध्य-अमेरिका और दक्षिण अमेरिका भी अपने जल-विद्युत साधनों के प्रमत्त केवल 13%, 5% और 3% भाग का ही उपयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार अफ्रीका में तंबा, टिन और सोने के तथा एशिया में पेट्रोल, लोहा, टिन और बाक्साइट आदि के अपार भंडार हैं, किन्तु इनका भी पूरा विदोहन नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार बर्मा, थाइलैंड, इण्डोचीन तथा अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिकी देशों की वन सम्पत्ति का उपयोग नहीं किया गया है या साम्राज्यवादी शासकों द्वारा शासक देशों के हित के कारण दुरुपयोग किया गया है।

भारत में भी उसके खनिज सम्पत्ति, जल-साधन, भूमि-साधन और वन-साधन पर्याप्त मात्रा में हैं, किन्तु उनका पर्याप्त विकास और उचित विदोहन नहीं किया गया है। उदाहरणार्थ भारत में विश्व में उपलब्ध लोहे का लगभग 25 प्रतिशत अर्थात् 2,160 करोड़ टन लोहा भण्डार होने का अनुमान है, किन्तु यहाँ लोहे का वार्षिक खनन लगभग 1.70 करोड़ टन से कुछ ही अधिक है। इसी प्रकार 1951 तक देश में सिंचाई के लिए उपलब्ध जल का केवल 17 प्रतिशत और कुल जल-प्रवाह का केवल 5.6 प्रतिशत ही उपयोग में लाया जा रहा था तथा 31 मार्च, 1970 तक भी सिंचाई के लिए उपलब्ध जल का केवल 39 प्रतिशत ही उपयोग में था।

2 कृषि की प्रधानता और उसकी निम्न उत्पादकता (Importance of Agriculture and its Low Productivity)—अर्द्ध-विकसित देशों में कृषि की प्रधानता होती है। उन्नत देशों में जितने लोग कृषि करते हैं, अर्द्ध-विकसित देशों में उससे प्रायः चार गुना अधिक लोग कृषि में लगे होते हैं। साधारणतया 65 से 85 प्रतिशत तक लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि और उससे सम्बन्धित उद्योगों पर आश्रित रहते हैं। हम भारत को ही ले तो यहाँ लगभग 70 प्रतिशत लोग आज भी कृषि पर आश्रित हैं। अर्द्ध-विकसित देशों में राष्ट्रीय आय का लगभग आधा या इससे भी अधिक भाग कृषि से प्राप्त होता है। प्रमुख उत्पादन खाद्य-

सामग्री और कच्चा माल रहता है। कृषि में इतना अधिक सकेन्द्रण वस्तुतः पिछड़ेपन और दरिद्रता का चिह्न है। प्रमुख व्यवसाय के रूप में भी कृषि अधिकतर अनुत्पादक है क्योंकि कृषि पुराने ढंग से और उत्पादन के अप्रचलित और पिछड़े हुए तरीकों से की जाती है जिससे पैदावार अनिश्चित रूप से कम रहती है और किसान प्रायः गुजारे के स्तर पर जीवित रहते हैं। कृषि पर अत्यधिक भार होने से भूमि के पट्टे, उप-विभाजन, उपखण्डन, अनाधिक जोत, भूमिहीन ग्रामीण आदि की समस्याएँ उत्पन्न रहती हैं। कृषि-साख की कमी रहने से कृषक प्रायः ऋण-ग्रस्त होते हैं। अर्द्ध-विकसित देशों में कृषि को “मानसून का जुआ” कहा जाता है। अम्बरिट, हन्ट एव किन्टर के शब्दों में—“इन देशों में कृषि का मानसून पर अत्यधिक निर्भर होने से आज के राजकुमार कल के भित्तारी और आज के भित्तारी कल के राजकुमार बन जाते हैं।”

अर्द्ध-विकसित देशों में भूमि की उत्पादकता अत्यन्त कम रहने अर्थात् कृषि का लाभदायक व्यवसाय न बन पाने का अनुमान हम कतिपय विकसित देशों के मुकाबले भारत की स्थिति की तुलना द्वारा सरलता से लगा सकते हैं—

विभिन्न देशों में भूमि उत्पादित, 1966-67

फसल	देश	प्रति हेक्टर भूमि उत्पादित (00 किलोग्राम)
चावल (धान)	जापान	50 90
	अमेरिका	48 50
	सोवियत संघ	28 70
	भारत	12 90
कपास	सोवियत संघ	8 30
	सं० अ० गणराज्य	5 90
	अमेरिका	5 40
	भारत	1 10
गेहूँ	इंग्लैंड	38 40
	फ्रांस	28 30
	इटली	22-00
	भारत	8 90

यदि कुल राष्ट्रीय आय में कृषि से प्राप्त आय का प्रतिशत लें तो स्थिति निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है—

देश	वर्ष	कुल राष्ट्रीय आय में कृषि से प्राप्त आय का प्रतिशत
1. कनाडा	1960	70
2. अमेरिका	1960	40
3. इंग्लैंड	1960	40
4. भारत	1964	470

कृषि-उत्पादन की मात्रा कम होने का एक बड़ा कुप्रभाव यह होता है कि बड़ी मात्रा में छिपी बेरोज़गारी बनी रहती है।

3 औद्योगीकरण का अभाव (Lack of Industrialisation)—इन अर्द्ध-विकसित देशों का एक प्रमुख लक्षण यह है कि इनमें आधुनिक उद्योगों के बड़े पैमाने के उद्योगों का अभाव रहता है। यद्यपि इन देशों में उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग तो यत्र तत्र स्थापित होने लगते हैं, किन्तु आधारभूत उद्योगों जैसे मशीन, यन्त्र, स्पाट आदि उद्योगों का लगभग अभाव रहता है और शेष उद्योगों के लिए भी ये मशीन आदि के लिए आयात पर निर्भर होते हैं। विकसित देशों में जब कि आधुनिक उद्योगों की बड़े पैमाने पर स्थापना होती है वहाँ ये देश मुख्यतः प्राथमिक उत्पादन में ही सगे रहते हैं। कुछ अर्द्ध-विकसित देशों में इन प्राथमिक व्यवसायों का उदाहरण खान खोदना है। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व विश्व में टिन उत्पादन में महत्त्व के क्रम में मलाया, इण्डोनेशिया, बोलिविया, श्याम और चीन थे और ये सभी देश अर्द्ध-विकसित देश हैं। एशिया और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों में विश्व के 58% टंगस्टन और 44% तंबाकू का उत्पादन होता है। एशिया और अफ्रीका में विश्व का 52% मैंगनीज और 61% क्रोमाइट का उत्पादन होता है। एशिया महाद्वीप से विश्व के पेट्रोल का एक तिहाई भाग और दक्षिणी अमेरिका से 16% प्राप्त होता है। इस प्रकार इन अर्द्ध-विकसित देशों में प्राथमिक व्यवसायों में ही अधिकांश जनसंख्या नियोजित रहती है और औद्योगिक उत्पादन का अभाव रहता है। अग्रलिखित तालिका से आर्थिक विकास और औद्योगीकरण का घनात्मक सह-सम्बन्ध स्पष्ट होता है—

राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान¹

प्रति व्यक्ति आय वर्ग	कुल राष्ट्रीय धन का प्रतिशत			
	प्राथमिक उत्पादन	उद्योग	सेवाएँ	कुल
125 डॉलर से कम आय वाले देश	47	19	33	100
125 से 249 डॉलर आय वाले देश	40	25	35	100
250 से 374 डॉलर आय वाले देश	30	26	45	100
375 या अधिक डॉलर वाले देश	27	28	46	100
अधिक आय वाले विकसित देश	13	49	30	100

आधुनिक युग में किसी देश के औद्योगीकरण में शक्ति के साधनों का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान होता है और प्रति व्यक्ति विद्युत शक्ति के उपयोग से भी किसी देश के औद्योगिक विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। अर्द्ध-विकसित देशों में प्रति व्यक्ति विद्युत शक्ति का उपयोग बहुत कम होता है जो इन देशों में औद्योगीकरण के अभाव का प्रतीक है।

4. प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर (Low level of Per Capita Income)—अर्द्ध-विकसित अथवा विकासमान देशों का एक प्रमुख लक्षण इनकी निर्धनता अथवा सामान्य दरिद्रता है जो प्रति व्यक्ति आय के निम्न स्तर में झलकती है। इस दृष्टि से विकसित और अर्द्ध-विकसित देशों में जमीन-आसमान का अन्तर है। विकसित देशों में जहाँ समृद्धि इठलाती है वहीं अर्द्ध-विकसित देशों में निर्धनता का गन्ग नृत्य होता है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के आँकड़ों के अनुसार सातवें दशक के शुरू में विकसित पूँजीवादी राज्यों में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय 1,037 डॉलर और नवोदित स्वाधीन देशों में 83 डॉलर थी। इन आँकड़ों की तुलना करने से प्रकट होता है कि भूतपूर्व उपनिवेश और अर्द्ध-उपनिवेश अपने आर्थिक विकास में 12 गुना (1,037/83) पीछे है।² 1964 में जेनेवा में वाणिज्य तथा विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ के सम्मेलन में भाषण देते हुए कीनिया ने प्रतिनिधि, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जे० जी० कियानो ने सकेत किया था कि "सैद्धान्तिक रिपोर्टों और

1 Source U. N. World Economic Survey 1961

2 यू० जूकोव व अन्य : तीसरी दुनिया, पृ 112

अर्थशास्त्र-सम्बन्धी पाठ्यपुस्तकों में विरासमान देशों में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 30 डॉलर, 60 डॉलर, यहाँ तक कि 100 डॉलर बताई जाती है, परन्तु विरासमान देशों के लाखों लोग वस्तुतः जिन विपन्न परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं वे इन आंकड़ों से प्रकट नहीं होती। उनमें बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कोई आय नहीं है। वे नहीं जानते कि बल उन्हें खाना नसोव होगा या नहीं, अथवा रात में वे कहाँ सोएंगे। पाठ्यपुस्तकों में उद्धृत प्रति व्यक्ति आय में उनका कोई हिस्सा नहीं होता है।¹ वक्ता ने यथार्थ का विलकुल सच्चा चित्र प्रस्तुत किया है, जिसमें वास्तविक विपन्नता की ओर ध्यान आकृष्ट होता है और जिस पर औसत आय सम्बन्धी आंकड़े आवरण डालते हैं।² विश्व बैंक के 1968 के एक सर्वेक्षण के अनुसार उस समय भारत का GNP 100 डॉलर था।

निम्न जीवन-स्तर और निम्न जीवन-आयु-स्तर (Low Standard of Living and Low Level of Life-age)—आर्थिक विपन्नता की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करने वाले अन्य आंकड़ों को लें तो भी पूँजीवादी दुनिया के अति-विकसित औद्योगिक राज्यों से एजिप्ता, अफ्रीका और सेंट्रल अमेरिका के पिछड़े देशों की भिन्नता स्पष्ट प्रकट होती है। यह पता चलता है कि अर्द्ध-विकसित अथवा गवोदित स्वाधीन देशों में मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता भी भली प्रकार पूरी नहीं हो पाती। "एक मनुष्य की दैनिक आहार आवश्यकता 2,500 से 4,000 कैलोरी तक होती है, जो इस पर निर्भर करता है कि वह किस तरह का काम करता है। औसत आवश्यकता 3,000 कैलोरी निश्चित की जा सकती है। आगे दी गई तालिका पर विचार करते समय इसे ध्यान में रखना होगा। आप देखेंगे कि भूतपूर्व उपनिवेशों तथा अर्द्ध-उपनिवेशों से सम्बन्धित आंकड़े हमेशा ही औसत आंकड़ों से और कई अवस्थाओं में तो 2,200 कैलोरी की न्यूनतम सीमा से भी कम हैं, जो अपर्याप्त पोषण अर्थात् भुखमरी के द्योतक हैं।"

"इन आंकड़ों से केवल एक ही निचोड़ निकाला जा सकता है, वह यह कि भूतपूर्व उपनिवेशों और अर्द्ध-उपनिवेशों के निवासी अपौष्टिक भोजन ग्रहण करते हैं जिसका परिणाम उनके बीच व्याप्त कुपोषण तथा ऊँची मृत्यु-दर है। बेरीबेरी, सूखे का रोग, स्कर्वी, पिल्लू, क्वाशिओर्कोर आदि अनेक रोग सीधे अपौष्टिक भोजन तथा पोष्टिकता की कमी के फलस्वरूप होते हैं। मिसाल के लिए, मध्य पूर्व में पाँच साल तक के बच्चों में से एक तिहाई इन्हीं रोगों के शिकार होकर मरते हैं। अफ्रीका में 6 महीने से 6 साल तक की उम्र के 96 प्रतिशत बच्चों को प्रोटीन की कमी से पैदा होने वाली क्वाशिओर्कोर नामक बीमारी हो जाती है।"

1 Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development, Geneva, March 23—June 16, 1964, Vol. II, Policy Statements, p 251 (तीसरी दुनिया' से उद्धृत)

2. यू० जूकोव एवं अन्य : तीसरी दुनिया, पृ. 112.

सारांश रूप में प्रति व्यक्ति निम्न आय लोगों के निम्न जीवन स्तर की सूचक है। अर्द्ध-विकसित देशों में खाद्य पदार्थ उपभोग की प्रमुख वस्तु है जिस पर लोगों की आय का 65 से 70 प्रतिशत तक खर्च होता है जबकि उन्नत देशों में लगभग 20 प्रतिशत। अर्द्ध-विकसित देशों की अधिकांश जनसंख्या के भोजन में मांस, अण्डा, मछली, दूध, मक्खन आदि पोषक खाद्य पदार्थ बिलकुल नहीं होते। लोग बड़ी अस्वास्थ्यप्रद परिस्थितियों में रहते हैं और समुचित चिकित्सा सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं होती। वास्तव में निर्धनता अर्द्ध-विकसित देशों का एक ऐसा रोग है जो उन्हें विभिन्न संकटों में उलझाए रखता है। प्रो० कैरनक्रास ने ठीक ही लिखा है कि अर्द्ध-विकसित देश विश्व अर्थ-व्यवस्था की गंदी बस्तियाँ हैं। प्रति व्यक्ति आय कम होने से ही अन्ततोगत्वा लोगों की कार्य-क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

खाद्य खपत और जीवन-अवधि के दो महत्वपूर्ण सूचकों को लेकर विकसित पूँजीवादी राज्यों और पिछड़े देशों के बीच जो भारी अन्तर है, उसे सोवियत संघ की विज्ञान अकादमी के सदस्य यू० जूकोव एव उनके सहलेखकों ने नीचे दी गई दो तालिकाओं के आँकड़ों से बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है—

सातवें दशक में कुछ देशों में खाद्य-खपत

(देश में उत्पादित + आयातित खाद्य-पदार्थ प्रति दिन प्रति व्यक्ति)

कैलोरी	देश	प्रोटीन (ग्राम)
3,510	न्यूजीलैण्ड	109
3,270	ग्रेट ब्रिटेन	89
3,140	ऑस्ट्रेलिया	90
3,100	संयुक्त राज्य अमेरिका	92
3,100	कनाडा	94
3,000	जर्मन संघात्मक गणराज्य	80
औसत आवश्यकता—		औसत आवश्यकता—
3,000 कैलोरी		80 ग्राम
2,690	ब्राजील	65
2,620	संयुक्त अरब गणराज्य	77
निम्नतम निरापद—		
2,500 कैलोरी		
2,490	बेनिजुएला	66
2,330	सीरिया	78

2,200 बंलोरी—

इससे नीचे अपर्याप्त पोषण की बंलोरी स्थिति आती है	देश	प्रोटीन (ग्राम)
2,100	लीबिया	53
2,050	पेरू	51
2,040	भारत	53
1,980	पाकिस्तान	44
1,830	फिलिपाइन	43

सातवें दशक मे विकसित पूँजोवादी राज्यों और नवोदित स्वाधीन
राज्यों मे तुलनात्मक (प्रति एक हजार आवादी के हिसाब से)

विकसित पूँजोवादी राज्य	78—125
पश्चिमी यूरोप	77—84
उत्तरी अमेरिका	73
जापान	86
आस्ट्रेलिया	
स्वाधीनता प्राप्त उपनिवेश और मद्व-उपनिवेश	19—24
एशिया	256—333
अफ्रीका	67—170
लैटिन अमेरिका	

सातवें दशक मे

कुछ इलाकों मे औसत जीवन-अवधि	70-73
उत्तरी अमेरिका	70-73
आस्ट्रेलिया	68-70
पश्चिमी यूरोप	50-55
लैटिन अमेरिका	40-50
एशिया	30-40
अफ्रीका	

नोट . कुछ अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशो मे औसत जीवन-आयु उन्नी
स्तर पर है, जिसपर प्राचीन रोम के समय मे थी—30 वर्ष 1”¹

1. यू० जूकोव एव अन्य : तीसरी दुनिया, पेज 114-115.

5 पूँजी की कमी (Deficiency of Capital)—अर्द्ध-विकसित देशों की अर्थ-व्यवस्थाएँ पूँजी में निर्धन (Capital Poor) और कम बचत और विनियोग करने वाली (Low Saving and low investing) होती है। देश के साधनों के उचित उपयोग नहीं होने और साधनों के अविकसित होने के कारण पर्याप्त मात्रा में उत्पादन के साधनों का सृजन नहीं हो पाता और साथ ही इसी कारण वहाँ की पूँजी की मात्रा वर्तमान तकनीकी ज्ञान के स्तर पर साधनों के उपयोग और आर्थिक विकास की आवश्यकताओं से बहुत कम होती है। किन्तु इन देशों में न केवल पूँजी की ही कमी होती है अपितु पूँजी निर्माण की दर (Rate of Capital Formation) भी बहुत निम्न होती है। इन अर्द्ध-विकसित देशों में आय का स्तर बहुत नीचा होता है अतः बचत की मात्रा भी कम होती है। स्वामाविक रूप से बचत की मात्रा कम होने का परिणाम कम विनियोग और कम पूँजी निर्माण होना है। इन अर्द्ध-विकसित देशों में उपभोग की प्रवृत्ति (Propensity to Consume) अधिक होती है और आर्थिक विकास के प्रयत्नों के फलस्वरूप आय में जो वृद्धि होती है उसका अधिकांश भाग उपभोग पर व्यय कर दिया जाता है। बढ़ी हुई आय में से बचत की मात्रा नहीं बढ़ने का एक कारण जैसा कि श्री नर्कसे ने बतलाया है प्रदर्शनात्मक प्रभाव (Demonstration effect) है जिसके अनुसार व्यक्ति अपने समृद्धशाली पड़ोसी के जीवन स्तर को अपनाने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही इन देशों में जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है। इन सब कारणों से उत्पादन के लिए उपलब्ध धरेलू बचते बहुत कम होती हैं। डॉ. प्रोन की गणना के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की 90% जनसंख्या के पास व्यय के ऊपर आय का कोई आधिक्य नहीं होता।

इस प्रकार अर्द्ध विकसित देशों में बचत की दर कम होती है जिससे विनियोग के लिए पूँजी प्राप्त नहीं होती। जो कुछ थोड़ी बहुत बचत होती है वह उच्च आय वाले वर्गों में होती है जो इन्हे विदेशी प्रतिभूतियों में विनियोजित करना चाहते हैं जिनमें जोखिम कम होती है। अर्द्ध-विकसित देशों की विनियोग की आवश्यकताओं की इस कमी को विदेशी पूँजी के द्वारा पूरा करने का प्रयास किया जाता है, किन्तु इन देशों की साख, भुगतान की योग्यता और राजनैतिक स्थिति इस दृष्टि से बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं होती। अतः अर्द्ध-विकसित देशों में पूँजी निर्माण की दर 5-6% होती है। इसके विपरीत विकसित देशों में कुल राष्ट्रीय आय के 15 से 20% तक कुल विनियोग होता है। श्री कालिन क्लार्क के कुछ वर्षों पूर्व के एक अध्ययन के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी यूरोप के देशों में पूँजी निर्माण की दर 15 से 18%, स्वेडन में 17%, नार्वे में 25% थी जबकि यह भारत में केवल 6% ही थी।

(6) निर्यातों पर निर्भरता और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रतिकूलता—अर्द्ध-विकसित देशों का एक प्रमुख लक्षण निर्यातों पर उनकी अत्यधिक निर्भरता है।

अधिकांश पिछड़े देशों से कच्चा माल भारी मात्रा में निर्यात किया जाता है। यू. जूकोव के अनुसार, "अधिकांश देश विश्व-भण्डारों में अपनी कृषि उपज बेचने हैं और औद्योगिक माल खरीदने हैं।" सोवियत मध्य की विज्ञान अकादमी के सदस्य यू. जूकोव और उनके सह-लेखकों ने अग्रिम तालिका में 24 देशों के नाम सम्मिलित किए हैं जो उपनिवेश अथवा अर्द्ध-उपनिवेश रह चुके हैं पर आज स्वाधीन हैं अर्थात् जो अर्द्ध-विकसित देशों की पंक्तियों में हैं। इनमें से प्रत्येक के सामने ऐसी वस्तु का उत्पादन सम्बन्धी आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, जिसका उसकी अर्थ-व्यवस्था में विशेष महत्त्व है। देश के निर्यात तथा राष्ट्रीय आय में भी उसका हिस्सा दिखाया गया है। इन आंकड़ों से यह पुष्टि होती है कि इन देशों का आर्थिक ढाँचा अधिकांशतः एक ही फसल पैदा करने वाला एकांगी है। साथ ही इन आंकड़ों से तीसरी दुनिया के अर्द्ध-विकसित देशों तथा औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध विकसित पूँजीवादी देशों के बीच वर्तमान सम्बन्धों के आर्थिक ढाँचे के एक पहलू पर भी प्रकाश पड़ता है और हमें पता चलता है कि दोनों को पृथक् करने वाली आर्थिक खाई चौड़ी होनी जा रही है।

विकासमान देशों की अर्थव्यवस्था और निर्यात का एकांगी विशेषीकरण¹

देश	मुख्य पैदावार और निर्यात	निर्यात से प्राप्ति, प्रतिशत में	
		कुल निर्यात से हुई प्राप्ति का भाग	कुल राष्ट्रीय आय का भाग
कुवैत	खनिज तेल	99	97
इराक	खनिज तेल	99	40
सेनेगाल	मूँगफली	92	—
वेनिजुएला	खनिज तेल	91	55
सऊदी अरब	खनिज तेल	90	83
नाइजीरिया	मूँगफली	87	—
ईरान	खनिज तेल	85	33
कोलम्बिया	काँफी	74	29
बर्मा	चावल	74	26
हैटी	काँफी	77	25
साल्वेडोर	काँफी	73	—
ग्वाटेमाला	काँफी	73	25
मिस्र	कपास	70	18
पनामा	केला	67	12

देश	मुख्य पंदावार और निर्यात	निर्यात से प्राप्त, प्रतिशत में कुल निर्यात से हुई प्राप्ति की माँग	कुल राष्ट्रीय आय का भाग
श्रीलंका	चाय	66	41
घाना	कोकोआ	66	40
चिली	ताम्बा	63	20
मलाया	रबड़	62	40
लाइबेरिया	रबड़	62	—
ब्राजील	काँफी	62	12
पाकिस्तान	जूट	58	9
उरुग्वे	ऊन	58	9
बोलीविया	टीन	57	29
इक्वेडोर	केला	56	25

जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सवाल है, गैर-समाजवादी दुनिया के विदेश व्यापार में विकासमान देशों का हिस्सा 1953 के 28 प्रतिशत से गिरकर 1966 में 21 प्रतिशत रह गया था। इस बीच इनका कूज बढ़ता जा रहा है और उनकी स्वयं तथा मुद्रानिधि कम होती जा रही है।

यू. जूकोव ने अपने अध्ययन में आगे लिखा है—“1964 में जेनेवा में हुए वाणिज्य एवं विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सच के सम्मेलन ने 1970 के पूर्वानुमान सहित कुछ दस्तावेजों प्रचारित की थी। अन्य बातों के साथ-साथ उनमें यह चेतावनी भी दी गई थी कि 1970 तक विकासमान देशों के निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की अपेक्षा 9 अरब से 13 अरब डॉलर कम होगा। इसके अलावा उन्हें ऋण को निबटाने, कर्ज का ब्याज चुकाने तथा विदेशी कम्पनियों को प्राप्त होने वाले मुनाफे तथा लाभांश की रकम को अदा करने के लिए करीब 8 अरब डॉलर की और जरूरत पड़ेगी। इस हिसाब को समाने वालों ने सुझाव दिया था कि तीसरी दुनिया के बकायों में जो भारी बमी है, उसकी पूर्ति अशत नूतन विदेशी पूँजी-निवेश और सरकारी ऋणों से की जा सकती है। यह आशा प्रकट करते हुए वे स्पष्टतः काफी आशावादी थे, क्योंकि उनके अनुसार इन साधनों से होने वाली प्राप्तियाँ 12 अरब डॉलर तक पहुँच सकती हैं। यदि उनका तखमीना ठीक साबित हो, तो भी 5 अरब से 9 अरब डॉलर तक की कमी बनी रहेगी। परन्तु इससे भी अधिक निराशाजनक पूर्वानुमान लगाया गया है, संयुक्त राष्ट्र सच के कुछ विशेषज्ञों के मतानुसार 1975 तक विकासमान देशों को केवल अपने आयात के भुगतान के लिए शायद दसियों अरब डॉलर की कमी का सामना करना पड़ सकता है।”¹

स्तर नीचा होता है। जिससे बचत दर और परिणामस्वरूप विनियोग दर कम होती है। फलस्वरूप उत्पादकता भी कम होती है और इसी प्रकार यह क्रम चलता रहता है।

9 बाजार की अपूर्णताएँ (Imperfections of the Market)—डॉ. डी. एस. नाग के अनुसार, “आर्थिक गत्यात्मकता में साधनों के अनुकूलतम आवंटन और राष्ट्रीय प्रयोज्यवस्था में अधिकतम उत्पादक क्रमता प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है …… किन्तु स्थिर प्रयोज्यवस्था में कई बाजार की अपूर्णताएँ इसे ‘उत्पादन सीमा’ (Production Frontier) की ओर बढ़ाने से रोकती हैं।” निर्धन देश इस दृष्टिकोण से स्थिर प्रयोज्यवस्था वाले होते हैं। जाति, धर्म, स्वभाव, प्रवृत्तियों की भिन्नता, निर्धनता, अज्ञानता, यातायात के साधनों का अभाव आदि श्रम की गतिशीलता में बाधा पहुँचाते हैं। इसी प्रकार पूँजी की गतिशीलता भी कम होती है। अर्द्ध-विकसित देशों में साधनों की इस गतिहीनता के अतिरिक्त एकाधिकारिक प्रवृत्तियाँ, देश-विदेश के बाजारों का ज्ञान नहीं होना, बेलोव आर्थिक ढाँचा, विनिष्ठीकरण का अभाव, पिछड़ी हुई समाज व्यवस्था आदि के कारण साधनों का समुचित और उचित आवंटन नहीं हो पाता है। अर्थ-व्यवस्था गतिहीन होती है जिससे इसके विभिन्न क्षेत्र के मूल्य आय के प्रति संवेदनशील नहीं होते। इस प्रकार साधनों का असन्तुलित संयोग, अर्द्ध-विकसित देशों के अर्द्ध-विकास का कारण होता है।

10 आर्थिक विषमता (Economic Disparities)—अर्द्ध-विकसित देशों में व्यापक रूप में धन और आय की विषमता तथा उन्नति के अवसरों की असमानता पाई जाती है। देश की अधिकांश सम्पत्ति, आय और उत्पात्ति के साधनों पर एक छोटे से समृद्ध वर्ग का अधिकार होता है जबकि देश के बहुत बड़े निर्धन वर्ग को आय का थोड़ा सा भाग प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्रगति के अवसर भी योग्यता की अपेक्षा जाति और आर्थिक क्षमता पर निर्भर करते हैं। धनिक वर्ग में बचन क्षमता अधिक होती है जिसके द्वारा और अधिक धन कमाने के साधन इनके हाथ में आते जाते हैं। निर्धन वर्ग को लाभ पहुँचाने वाले कार्यों जैसे, सामाजिक सुरक्षा, समाज सेवासो, श्रम-संधि, प्रगतिशील करारोपण आदि संस्थाएँ अधिक विकसित नहीं होती हैं। परिणामस्वरूप, इन निर्धन देशों में धनी देशों की अपेक्षा व्यापक आर्थिक विषमता पाई जाती है। प्रो. साइमन कुजनेट्स के अप्रॉकित अनुमान इस तथ्य के परिचायक हैं—

देश	सम्पूर्ण आय का जनसंख्या के 20% धनिक वर्ग को प्राप्त होने वाला प्रतिशत	सम्पूर्ण आय का जनसंख्या के 70% निर्धन वर्ग को प्राप्त होने वाला प्रतिशत
विकसित देश		
स. रा. अमेरिका	44	34
ब्रिटेन	45	35
अर्द्ध विकसित देश		
भारत	55	28
थ्रीलका	50	30

उपरोक्त विवरण में स्पष्ट है कि विकसित देशों की अपेक्षा अर्द्ध-विकसित देशों में आर्थिक असमानता अधिक है। प्रो महालनवीस रिपोर्ट के अनुसार सन् 1955-56 में देश के 5% लोगों के पास देश की कुल आय का 23% भाग था और इसमें भी सर्वोच्च वर्ग के 1% व्यक्तियों को 11% आय प्राप्त होती थी। इसके विपरीत सबसे निम्न वर्ग के 25% लोगों को समस्त आय का केवल 10% भाग प्राप्त होता था।

(ब) जनसंख्या सम्बन्धी लक्षण

(Demographic Characteristics)

समस्त अर्द्ध विकसित देशों में जनसंख्या सम्बन्धी विशेषताएँ समान नहीं पाई जाती। ये देश जनसंख्या के घनत्व, आयु संरचना और जनसंख्या में परिवर्तन की दर में भी भिन्नता रखते हैं। वावर एव यामे के अनुसार भारत और पाकिस्तान में सन् 1800 के पश्चात् जनसंख्या वृद्धि की दर कई पश्चिमी देशों की जनसंख्या वृद्धि की दरों से भिन्न नहीं रही है। इसके अतिरिक्त अधिक जनसंख्या वाले देशों की जनसंख्या वृद्धि की दर ही सर्वाधिक हो, ऐसी बात नहीं है। फिर भी अर्द्ध विकसित देशों की जनसंख्या सम्बन्धी निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं—

1 जनसंख्या की अधिकता (Over Population)—बड़े अर्द्ध-विकसित देशों की जनसंख्या अधिक होती है। यद्यपि इन अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए भी निरपेक्ष (Absolute) रूप में अधिक आबादी वाले देश बहना उचित नहीं है, क्योंकि जनसंख्या की अधिकता या न्यूनता (Over population or under population) को उस देश के प्राकृतिक साधनों के सन्दर्भ में देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी अर्द्ध विकसित देश जनसंख्या की समस्या से ग्रसित नहीं हैं। लेटिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कम जनसंख्या (Under Population) वाले देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप भी तकनीकी ज्ञान के वर्तमान स्तर पर कम जनसंख्या वाला क्षेत्र ही कहा जा सकता है। इसी प्रकार भारत आदि कुछ देशों में अधिक जनसंख्या हो सकती है किन्तु समस्त अर्द्ध-विकसित देश अधिक जनसंख्या के भार से ग्रस्त नहीं हैं।

2 जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर (High rate of population growth)—अर्द्ध-विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर भी अधिक है। इसी क्षेत्र के 17 देशों में से 8 देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर 2% और 3% के मध्य है और कुछ देशों की इससे भी अधिक है। लेटिन अमेरिका में भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके विपरीत विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर कम है। अर्द्ध-विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि की उच्च दरों का कारण जन्म-दर का ऊँची होना और मृत्यु दर का कम होना है।

3 जीवनावधि की अल्पता (Low life Longevity)—जीवनावधि का आशय देशवासियों की औसत आयु है। अर्द्ध-विकसित देशों में आय की कमी के कारण जीवन स्तर नीचा होता है और निर्धनता तथा आर्थिक विपन्नताओं की अधिकता के कारण औसत आयु कम होती है। वस्तुतः प्रति व्यक्ति आय और

जीवनावधि में सकारात्मक भूत सम्भव होता है यही कारण है कि जहाँ विकसित देशों में लोग अधिक समय तक जीवित रहते हैं, वहाँ अर्द्ध विकसित देशों में औसत आयु बहुत कम होती है। अर्द्ध विकसित देशों में जीवनावधि कम होने का परिणाम है—धनी देशों की अपेक्षा इन देशों में अधिक व्यक्ति छोटी आयु में मर जाने हैं एवं इस प्रकार कार्य करने की अवधि भी कम ही होती है।

4 आयु वितरण (Age distribution)—अर्द्ध विकसित देशों की जनसंख्या में कम उम्र वाले लोगों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है और इनमें बालकों की संख्या अधिक होती है। एशिया अफ्रीका और लेटिन अमेरिकी देशों में जो अर्द्ध-विकसित क्षेत्र हैं 15 वर्ष से कम आयु वाली संख्या कुल जनसंख्या का 40% है जबकि संयुक्तराज्य अमेरिका और इंग्लैंड आदि में यह अनुपात केवल 23 से 25% तक है। इस प्रकार इन देशों में अनुत्पादक उपभोक्ताओं का भाग अधिक होता है।

5 सक्रिय जनसंख्या का भाग कम होना (Less active population)—अर्द्ध विकसित देशों की जनसंख्या में बालकों का अनुपात अधिक होने के कारण सक्रिय जनसंख्या का भाग कम होता है। यहां कार्य न करने वाले प्राथमिकों का भाग अधिक होता है। बालकों और अनुत्पादक व्यक्तियों का अनुपात अधिक होने के कारण उनके जन्म पालन पोषण आदि पर अधिक व्यय होता है और अर्थ-व्यवस्था पर बोझ बढ़ जाता है। भारत में सन् 1961 में 14 वर्ष तक का आयु-वर्ग जनसंख्या का 41% था जबकि जर्मनी में 21% और फ्रांस में 24.7% था।

6 ग्रामीण क्षेत्र की प्रधानता (Pre dominance of Rural Sector)—अर्द्ध विकसित देशों में ग्रामीण क्षेत्र की प्रधानता रहती है। इन देशों की अधिकांश जनता ग्रामीण में निवास करती है और ग्रामीण व्यवसायों जैसे कृषि, वन मत्स्य पालन आदि में जीविक निर्वाह करती है। प्राथमिक विकास के साथ-साथ इस स्थिति में परिवर्तन होता है। प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के अनुपात में छात्राओं की माँग में वृद्धि नहीं होती और दूसरी ओर कृषि में पूँजी के अधिक उपयोग के कारण गहन और विस्तृत दोनों प्रकार की कृषि प्रणालियों द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ता है। परिणामस्वरूप कृषि एवं ग्रामीण व्यवसायों में जनसंख्या का अनुपात कम होता जाता है और दूसरी ओर औद्योगीकरण के कारण बड़े बड़े नगरों का विकास होता है और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ता जाता है।

(स) सामाजिक विशेषताएँ (Social Characteristics)

अर्द्ध विकसित अव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास की दृष्टि से पाए जाने वाली मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1 अर्द्ध विकसित मानव पूँजी (Under-developed human capital)—आर्थिक विकास में मानव पूँजी का निर्धारक महत्व है। विकसित मानवीय पूँजी अर्थात् स्वस्थ शिक्षित कुशल एवं नैतिकता सम्पन्न शैक्षणिक आर्थिक विकास में बहुत सहायक होते हैं किन्तु दुर्भाग्यवश अर्द्ध विकसित देशों में यह मानव पूँजी भी अर्द्ध विकसित ही होती है। देश में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा का तथा कुशल श्रमिकों

का अभाव होता है। स्वास्थ्य का स्तर भी प्रायः नीचा होता है। लोगों में विवेकपूर्ण विचारधारा का भी अभाव होता है। इसके अनिश्चित धनाभाव के कारण लोगों के विकास के लिए अधिक पूँजी लगाना सम्भव नहीं होता। उदाहरणार्थ, भारत में जहाँ वैज्ञानिक अनुपचान पर प्रति व्यक्ति लगभग 15 पैसे वार्षिक व्यय किया जाता है वहीं अमेरिका और रूस में यह व्यय राशि क्रमशः लगभग 154 रुपये और 110 रुपये है।

2 अथ सामाजिक विशेषताएँ—ग्रह-विकसित ग्रथ-व्यवस्थाएँ अनेक सामाजिक दोषों से ग्रस्त होती हैं। प्रायः समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित होता है और ये वर्ग अलग-अलग रुढ़िगत परम्पराओं पर आचरण करते हैं तथा नवीन प्रयत्नों को सरलता से एक प्रसन्नतापूर्वक अमान्यता को तैयार नहीं होते। समाज में गृहों का प्रयोग लोकप्रियता के लिए होता है। स्त्रियों के अनिश्चित पुरुष भी गृह पवित्रता पसन्द करते हैं। रीति रिवाज बहुत महत्त्व होते हैं जिन्हें निभाने में प्रायः का बड़ा अग्र व्यय करना पड़ता है। फलस्वरूप वचन की मात्रा कम हो जाती है और पूँजी का निर्माण नहीं हो पाता। स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा गौण स्थान प्राप्त होता है। उनकी जाति पर तरह-तरह के अक्रुश होने हैं। आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से पराधीनता की बेडियों में जकड़े रहने के कारण स्त्रियाँ समाज के उत्थान में सहायक नहीं हो पाती। सामाजिक स्तर (Status) का भी विशेष महत्त्व होता है। मजदूरी आदि के निर्धारण में सविदा की अपेक्षा परम्पराओं का प्रभाव अधिक पड़ता है। इन सब बातों का कुल मिला कर यह प्रभाव होता है कि ग्रह-विकसित देश की ग्रथ-व्यवस्था तेजी से आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर नहीं हो पाती।

(द) तकनीकी विशेषताएँ (Technological Characteristics)

ग्रह-विकसित ग्रथ-व्यवस्थाओं में उत्पादन की प्राचीन परम्परागत विधि का उपयोग किया जाता है। फलस्वरूप प्रति व्यक्ति उत्पादन विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा बहुत कम रहता है। तकनीकी और सामान्य दोनों ही प्रकार की शिक्षा का अभाव होने के कारण ग्रह-विकसित देशों में विकसित देशों की अपेक्षा उत्पादन में बहुत अधिक निष्प्राप्त रहना है। परिवहन और संचार साधनों का अभाव भी ग्रथ-व्यवस्था को पीछे धकेलता रहता है। प्राविधिक ज्ञान के अभाव के कारण अकुशल श्रमिकों की संख्या अधिक होती है और इसलिए आर्थिक विकास के लिए प्रयत्नशील ग्रह-विकसित देशों को तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए विकसित देशों का मुँह देखना पड़ता है। वास्तव में प्राविधिक प्रगति और आर्थिक विकास एक दूसरे के कारण और परिणाम है। ग्रह-विकसित देशों में जहाँ तकनीकी प्रगति के कारण द्रुत आर्थिक विकास नहीं हो पाता वहाँ अग्रगण्य आर्थिक साधनों के कारण तकनीकी प्रगति के लिए अधिक प्रयास करना भी सम्भव नहीं हो पाता।

(इ) राजनीतिक विशेषताएँ (Political Features)

राजनीतिक क्षेत्र में ग्रह-विकसित राष्ट्रों की स्थिति प्रायः बड़ी दयनीय होती है। ये राष्ट्र राजनीतिक दृष्टि से प्रायः कमजोर होते हैं और उन पर अन्य देशों के

दबाव अथवा आक्रमण का सदैव भय बना रहता है। समुचित साधन उपलब्ध न होने के कारण देश की रक्षाार्थ आधुनिक शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित मैनिन शक्ति का अभाव भी बहुत कष्टप्रद होता है। जनता गरीब होने के कारण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में ही लगी रहती है और राजनीतिक अधिकारों के प्रति विशेष सजग नहीं होती। अधिकांश व्यक्तियों में यथार्थ रूप में राजनीतिक अधिकारों के बारे में अज्ञानता ही पाई जाती है। अर्द्ध-विकसित देशों में प्रथम तो मध्यम वर्ग का अभाव पाया जाता है और यदि यह वर्ग होता भी है तो सामान्यतः बहुत निर्बल होता है। प्रायः विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मध्यम वर्ग के इस अभाव की समस्या नहीं होती। आर्थिक विकास की दृष्टि से यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि अधिकांशतः मध्यम वर्ग से ही साहसी, कुशल प्रशासक और योग्य व्यक्ति प्राप्त होते हैं।

(ई) अन्य विशेषताएँ (Other Characteristics)

अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्थाओं की अन्य उल्लेखनीय विशेषताओं में हम योग्य प्रशासन के अभाव, उत्पत्ति के साधनों में असमानता स्थिर व्यावसायिक ढाँचे दोषपूर्ण प्राशुलिक व मौद्रिक संगठन आदि को ले सकते हैं। इन देशों में जो प्रशासनिक यन्त्र होता है वह प्रायः कुशल और योग्य नहीं होता। अधिकारीयण व्यक्तिगत स्वार्थों को ऊँचा स्थान देते हैं। ईमानदार अधिकारियों के अभाव में आर्थिक विकास के साधनों का दुरुपयोग होता है और राष्ट्र की प्रगति अवर्द्ध होती है।

उत्पत्ति के साधनों में असमानता होने से आणानुकूल उत्पादन सम्भव नहीं होता। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत अर्द्ध विकसित देशों में उत्पत्ति के साधनों में बाँझित गतिशीलता नहीं पाई जाती। फलस्वरूप राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में अधिकतम उत्पादन सम्भव नहीं हो पाता। अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्थाओं का व्यावसायिक ढाँचा प्रायः स्थिर रहता है। इस कारण भी उत्पत्ति के साधनों में गतिशीलता नहीं पाई जाती। परिणामतः न तो उद्योगों में विशिष्टीकरण ही हो पाता है और न देश आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर होता है।

ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में प्राशुलिक और मौद्रिक संगठन प्रायः दोषपूर्ण होता है। राजस्व प्रायः अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से प्राप्त होता है जिनकी प्रकृति अधोगामी (Regressive) होती है। प्रायः के साधन के रूप में प्रत्यक्ष करों का महत्व कम होता है। प्रगतिशील कर प्रायः नहीं पाए जाते। कर-संग्रह विधि मितव्ययी नहीं होती और कर अपवहन भी बहुत कम होता है। मुद्रा बाजार प्रायः अविकसित होते हैं। सरकारी मौद्रिक नीति पणिष्ठितिवश प्रायः इतनी दुर्बल होती है कि देश की अर्थव्यवस्था को समुचित ढंग से नियमित नहीं कर पाती।

निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि प्रायः उपरोक्त सभी विशेषताएँ अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्थाओं में न्यूनतम मात्रा में पाई जाती हैं। विश्व के समस्त अर्द्ध-विकसित देशों की सम्मिलित ढंग से एक प्रकार की विशेषताएँ बतलाना बहुत कठिन है क्योंकि विभिन्न देशों की आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक और कृषि सम्बन्धी अवस्थाएँ व प्रवृत्तियाँ भिन्न-भिन्न हैं। यद्यपि इन देशों में विकास की पद्धतियाँ, गतिर्या

जनसंख्या की विशेषताएँ और आन्तरिक परिस्थितियाँ भी भिन्न भिन्न हैं तथापि इन भिन्नताओं के बावजूद अधिकांश परिस्थितियों में एक बड़ी मात्रा तक उनकी विशेषताओं में एकता व समानता पाई जाती है। इसी विशेषताओं के आधार पर हम अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं को, विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं से भिन्न करके भली प्रकार पहचान पाते हैं।

अर्द्ध-विकसित देशों की समस्याएँ (Problems of Under-Developed Countries)

अर्द्ध-विकसित देशों की समस्याएँ निम्नलिखित वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं—

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| (1) आर्थिक समस्याएँ | (4) राजनीतिक समस्याएँ, |
| (2) सामाजिक समस्याएँ | (5) अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ, |
| (3) प्रशासनिक समस्याएँ, | |

आर्थिक समस्याएँ

अर्द्ध-विकसित देश अनेक आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त हैं, जैसे—

- (1) बचत एवं पूँजी-निर्माण की समस्या, (2) निर्धनता का विप्लव कुचक्र,
(3) उपभोग और घरेलू बाजार की अपर्याप्तता, (4) समुचित आर्थिक रचना का न होना, (5) कृषि एवं भूमि से सम्बन्धित बाधाएँ तथा (6) बेरोजगारी।

अर्द्ध विकसित देशों में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है, भ्रत बचत नहीं हो पाती। बचत न होने से पूँजी का वांछित निर्माण नहीं होता फलस्वरूप आर्थिक विकास के क्रिया कलाप गति नहीं पाते। प्रति व्यक्ति आय कम होने से देश में उपभोग की मात्रा कम होनी है, परिणामतः घरेलू बाजार का क्षेत्र सीमित रहता है अतः देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आय कम होने से बचत और पूँजी निर्माण को आघात पहुँचता है और माँग व उपभोग के कम होने से पूँजी विनियो के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह पाता। लघु पैमाने पर उत्पादन कार्य होने से बड़े उत्पादन की बचत सम्भव नहीं हो पाती। समुचित आर्थिक रचना का अभाव इन समस्याओं को और भी विषम बना देता है। आर्थिक संरचना में रेलों सड़की परिवहन के अन्य साधनों, चिकित्सालयों, स्कूलों, बिजली, पानी, पुर्तों, आदि को सम्मिलित किया जाता है। यदि इन साधनों की समुचित व्यवस्था नहीं होती तो आर्थिक विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। कृषि एवं भूमि से सम्बन्धित विभिन्न समस्याएँ अर्द्ध विकसित देशों को ग्रस्त किए रहती हैं। प्रायः यह देखा गया है कि अर्द्ध-विकसित देश कृषि पर अधिक दबाव, कृषि जोतों के उप-विभाजन व उप-खण्डन, कृषि ऋण, अधिक लगान, सिंचाई साधनों के अभाव, कृषि विपणन की असुविधा, प्रति इकाई कम उपज, सुख सुविधाओं की कमी आदि विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त रहती हैं। आर्थिक विकास अवरुद्ध होने से देश में बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो जाती है। अर्द्ध-विकसित देशों में बेरोजगारी के अतिरिक्त अर्द्ध बेरोजगारी (Under-employment) अथवा अदृश्य बेरोजगारी (Disguised un employment) की समस्या भी विशेष रूप से गम्भीर होती है।

सामाजिक समस्याएँ

अर्द्ध-विकसित देश विभिन्न सामाजिक समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। आर्थिक विकास की दृष्टि से इन देशों की मूलभूत सामाजिक समस्याएँ निम्नलिखित होती हैं—(1) जनसंख्या में वृद्धि और जनसंख्या का निम्न गुण स्तर होना, (2) सामाजिक और सस्वागत बाधाएँ व रुढ़ियाँ, एवं (3) कुशल साहित्यों का अभाव।

अर्द्ध-विकसित देशों की प्रमुख सामाजिक-आर्थिक समस्या जनसंख्या की तीव्र वृद्धि है। एक ओर तो आय और पूँजी का अभाव होता है तथा दूसरी ओर जनसंख्या की तीव्र वृद्धि आर्थिक विकास के प्रयत्नों को विफल बनाती है। इन देशों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि जनसंख्या-वृद्धि के भार को वहन कर सकें एवं रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध करा सकें। सामाजिक और सस्वागत रुढ़ियाँ व कुरीतियाँ भी देश को आगे बढ़ने से रोकती हैं। इनके कारण जनता नवीन परिवर्तनों और परिस्थितियों को ग्रहण करने से यथासम्भव बचना चाहती है, फलस्वरूप देश में तकनीकी और वैज्ञानिक क्रान्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाता। अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में साहसी वर्ग का भी अभाव पाया जाता है जबकि यही वर्ग मूलतः उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को जुटाने और सक्रियता देने का उत्तरदायित्व वहन करता है। अव्यवस्थित सामाजिक राजनीतिक-आर्थिक ढाँचे के कारण अर्द्ध-विकसित देशों में आर्थिक वातावरण ऐसा नहीं होता जो साहसी वर्ग को आगे लाए। परिणामतः देश की प्रगति धीरे-धीरे होती है।

राजनीतिक समस्याएँ

अर्द्ध-विकसित देशों की प्रमुख राजनीतिक समस्याओं में हम राजनीतिक अस्थिरता, नियोजन के प्रति उदासीनता, श्रमिकों के शोषण व वन्दन आदि को ले सकते हैं। राजनीतिक जागरूकता का अभाव होने से प्रायः दीर्घजीवी राजनीतिक गुट या दल नहीं बन पाते और शासन-सत्ता में स्थायित्व नहीं आ पाता। यह राजनीतिक अस्थिरता एक ओर तो आर्थिक विकास के लिए हड़ और स्थाई नीतियों को प्रवृद्ध करती है, दूसरी ओर राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को निर्बल बनाने की है। अशिक्षित और रुढ़िवादी जनता नियोजन के महत्व को स्वीकार नहीं करती। राजनीतिक दृष्टि से अस्थिर सरकारें जनता में नियोजन कार्यक्रमों के प्रति विश्वास पैदा नहीं कर पाती। फलस्वरूप देश को नियोजन के लाभ नहीं मिल पाते। अर्द्ध-विकसित देश विभिन्न श्रमिक समस्याओं से भी ग्रस्त रहते हैं। प्रायः स्थायी श्रमिक वर्ग की कमी बनी रहती है। रुढ़िवादिता और सामाजिक वन्दन के कारण श्रम की गतिशीलता नहीं पाई जाती। राजनीतिक जागरूकता के अभाव के कारण श्रमिकों में श्रम-संघों जैसी संस्थाएँ समुचित ढंग से नहीं बन पाती। जब देश का श्रमिक वर्ग ही प्रकुशल, अजागरूक और अशिक्षित हो तो देश के आर्थिक विकास को स्वभावतः गति नहीं मिल सकती।

प्रशासनिक समस्याएँ

अर्द्ध विकसित देश प्रशासनिक दृष्टि से बहुत अकुशल, अज्ञानिक और पिछड़े हुए होते हैं। देश की गरीबी और अगिज्ञा जनता में चारित्रिक स्तर को ऊँचा नहीं उठने देती, फलस्वरूप कुशल और ईमानदार प्रशासनिक अधिकारियों की सदा कमी बनी रहती है और राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा निजी हितों को अधिक महत्त्व दिया जाता है। भ्रष्टाचार का दाना देश के आर्थिक विकास का गला घोटता रहता है। इसके अनिरीक्त प्राथमिकता की समस्या भी बनी रहती है। अर्द्ध विकसित देश सभी क्षेत्रों में पिछड़े होते हैं और इन सभी क्षेत्रों का समुचित रूप में विकास करना आवश्यक होता है, लेकिन पूँजी और उन्नति के आवश्यक साधनों के अभाव के कारण यह सम्भव नहीं हो पाता कि सभी क्षेत्रों का समुचित विकास किया जा सके। फलस्वरूप प्राथमिकता की समस्या निरन्तर विद्यमान रहती है। देश के समुचित विकास के लिए विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता का भ्रम देना पड़ता है।

अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ

‘गरीब की जोरू सब की भाभी’ वाली कहावत अर्द्ध-विकसित देशों पर पूरी तरह लगी होती है। ये देश आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से तो परेशान ही हैं लेकिन विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ भी इन्हें दबाए रहती हैं। विकसित राष्ट्र इस प्रकार की प्रतिस्पर्द्धात्मक परिस्थितियों में दबा कर देते हैं जिनका अविकसित देश प्रायः समुचित ढंग से सामना नहीं कर पाते और उन्हें अनेक रूपों में विकसित राष्ट्रों का आश्रय स्वीकार करना पड़ता है।

अन्य समस्याएँ

उपर्युक्त समस्याओं के अतिरिक्त अर्द्ध विकसित देश और भी अनेक समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। अर्द्ध विकसित देशों में आर्थिक विकास के साथ साथ मूल्य भी बढ़ते हैं। यदि यह बढ़ोतरी मौद्रिक आय की अपेक्षा कम होती है तब तो कोई समस्या पैदा नहीं होती, किन्तु यदि यह वृद्धि मौद्रिक आय की अपेक्षा अधिक हो जाती है तो समाज मुद्रा स्फीति के संकट में फँसने लगता है। दूसरी गम्भीर समस्या विदेशी मुद्रा की होनी है। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक अनेक साधनों को विदेशों से आयात करना होता है जिसके लिए बाँझित विदेशी मुद्रा नहीं मिल पाती। विदेशी मुद्रा के अभाव में आवश्यक साधनों के आयात को रोकने से आर्थिक विकास की गति अवरोध होने का खतरा रहता है, इसलिए अर्द्ध-विकसित देशों को सहायता व ऋण के लिए विकसित राष्ट्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह निर्भरता पूँजी व यान्त्रिक ज्ञान दोनों क्षेत्रों में होती है।

अर्द्ध-विकसित देशों की इन विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न उपायों के अतिरिक्त एक प्रभावशाली और अनुशासित राजकोपीय नीति का महत्त्व सर्वोपरि है। राजकोपीय नीति का अर्थ विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे महत्त्वपूर्ण यह होना चाहिए कि वह पूँजी निर्माण और पूँजी की गति को बढ़ाने में सहायक बने ताकि यहाँ स्थाई वृद्धि की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिले। इस उद्देश्य की पूर्ति में

प्रभावशाली कर-नीति, सार्वजनिक व्यय-नीति, सार्वजनिक ऋण-नीति और हीनार्थ प्रगल्भ की नीति, बड़ी सहायक हो सकती है जिन्हे आवश्यकतानुसार प्रयुक्त किया जाना चाहिए। प्रभावशाली राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था की उन्नति में निर्यातिक योगदान कर सकती है।

अर्द्ध-विकसित देशों की एक कठिन समस्या विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित है। इन राष्ट्रों को कृषि, मन्नी, खाद्यान्नों, सिचाई साधनों, खाद, बीज आदि की पूर्ति के लिए बहुत कुछ विदेशी पर निर्भर करना पड़ता है। इन साधनों की उपलब्धि तभी सम्भव है जब या तो निर्यात किया जाए अथवा भुगतान हेतु पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाए। विदेशी मुद्रा के अभाव में आर्थिक विकास अवहट्ट न हो इसके लिए अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों से समय-समय पर पूँजी व तकनीकी ज्ञान दोनों रूपों में सहायता माँगनी पड़ती है। कभी-कभी यह सहायता ऋणों के रूप में भी मिलती है। आयात नियन्त्रण व निर्यात प्रोत्साहन के द्वारा भी विदेशी विनिमय की समस्या को हल करने का प्रयास किया जाता है। कभी-कभी अवमूल्यन का सहारा भी लिया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ विदेशी मुद्रा सम्बन्धी सहायता विभिन्न शर्तों पर प्रदान करती हैं।

अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास की सामान्य आवश्यकताएँ (General Requisites for Development of Under-developed Countries)

अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए केवल समस्याओं को दूर करना ही काफी नहीं है और न ही पूँजी-निर्माण अथवा नवीन खोजों से ही समस्या का पूर्ण समाधान सम्भव है बल्कि आर्थिक विकास के लिए निम्नलिखित सामान्य आवश्यकताओं का होना भी आवश्यक है—

1. स्वदेशी शक्तियाँ (Indegenious Forces)—अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास की प्रक्रिया स्वदेशी शक्तियों पर आधारित होनी चाहिए। बाह्य शक्तियाँ केवल स्वदेशी शक्तियों को प्रोत्साहन दे सकती हैं, किन्तु उनका प्रतिस्थापन (Substitute) नहीं बन सकती। यदि केवल विदेशी सहायता के बल पर ही किसी योजना को प्रारम्भ किया गया और लोगों की विकास-सम्बन्धी बेतना को जागरूक न बनाया गया तो आर्थिक विकास धीरक होगा। विदेशी सहायता पर पूर्ण रूप से निर्भरता के परिणामस्वरूप देश के प्राकृतिक साधनों का उपयोग भले ही हो जाए, लेकिन श्रमिकों की कार्यक्षमता नहीं बढ़ सकेगी। अतः आर्थिक विकास के लिए विदेशी सहायता को केवल सीमान्त रूप में ही हितकर मानते हुए अन्तिम रूप से उसे स्वदेशी शक्तियों पर ही आधारित करना चाहिए। विदेशी सहायता अल्पकालीन रूप में ही हितकारी सिद्ध हो सकती है, स्थायी रूप से नहीं। मेयर और वाल्डविन के अनुसार “अदि विकास की प्रक्रिया संचयी और दीर्घकालीन (Cumulative and long-lasting) हो तो विकास की शक्तियाँ विकासशील राष्ट्र के अग्रगंत ही होनी चाहियें।”

2. पूँजी-संचय में वृद्धि (Increase in Capital Accumulation)— अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के लिए वास्तविक पूँजी का संचय अत्यावश्यक है। पूँजी-संचय मुख्यतः तीन बातों पर निर्भर करता है—(i) वास्तविक बचतों की मात्रा में वृद्धि हो (ii) देश में पर्याप्त मात्रा में वित्त एवं साख सुविधाएँ हो, तथा (iii) पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विनियोग कार्य हो। अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में पूँजी निर्माण आन्तरिक और बाह्य दोनों ही साधनों द्वारा किया जा सकता है। घरेलू संचयों में वृद्धि तभी सम्भव है जब कि बचत की मात्रा में वृद्धि, श्रम-शक्ति और प्राकृति साधनों का उपयोग उपभोग पर रोक गतिशीलता एवं उचित निर्देशन आदि हो। घरेलू पूँजी का निर्माण सम्भव न होने पर बाह्य साधनों से अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय साधनों से पूँजी-निर्माण किया जा सकता है। इन साधनों में प्रत्यक्ष वास्तविक विनियोग विदेशी अनुदान, सहायता व ऋण आदि सम्मिलित हैं। पूँजी-संचय की वृद्धि के साथ ही यह भी आवश्यक है कि उसके उपभोग या विनियोग करने की समुचित व्यवस्था हो। इसके अतिरिक्त प्राविधिक और संगठन सम्बन्धी विकास भी उच्च स्तर का होना चाहिए।

3 बाजार पूर्णता (Perfectness of the Market)— बाजार की अपूर्णताओं को दूर करने के लिए सामाजिक एवं आर्थिक संगठनों के वैकल्पिक स्वरूपों का होना आवश्यक है। अधिक उत्पादन के लिए वर्तमान साधनों का अधिकतम उपयोग किया जाना जरूरी है। यह आवश्यक है कि बाजार में एकाधिकारी प्रवृत्तियों को दूर या कम कर पूँजी और साख का पूर्ण रूप से विस्तार करने, उत्पादन की सीमाओं को पर्याप्त रूप से बढ़ाने उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि करने, वृष्टि पर निर्भरता को कम करने जरूरतमन्द लोगों को साख सुविधाएँ समय पर उपलब्ध कराने आदि के लिए प्रभावशाली और सफल प्रयत्न करना आवश्यक है। मेयर और वाल्डविन के अनुसार “देश की राष्ट्रीय आय को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए नवीन आवश्यकताओं नवीन विचारधाराओं, उत्पत्ति के नए ढंगों और नई संस्थाओं की आवश्यकता है। आधुनिक आर्थिक विकास में धार्मिक रुकावटें आदि होने से या तो प्रगति कम गति से होगी या उसके स्वभाव को ही बदलना होगा।”

4 पूँजी संचय की शक्ति (Capital Absorption)— अर्द्ध विकसित राष्ट्रों में पूँजी-निर्माण की मन्द गति प्राविधिक ज्ञान की कमी कुशल श्रमिकों के अभाव आदि के कारण पूँजी सोखने या विनियोग करने की शक्ति प्रायः सीमित होती है। इन देशों में एक बार विकास आरम्भ हो जाने पर पूँजी सोखने या विनियोग करने की शक्ति बढ़ने लगती है, यद्यपि प्रारम्भ में मुद्रास्फीति (Inflation) का भय सदा बना रहता है। इसके अतिरिक्त यदि इन राष्ट्रों में पूँजी संचय उनकी सोखने की शक्ति से अधिक हो जाता है तो वहाँ भुगतान-सन्तुलन सम्बन्धी कठिनाइयाँ उठ खड़ी होती हैं अर्थात् अर्द्ध-विकसित देशों में पूँजी निर्माण की मात्रा के अनुरूप ही पूँजी-विनियोग करने की शक्ति बढ़नी चाहिए।

5 मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आवश्यकताएँ (Sociological and Psychological Requirements)—ग्रह विकसित देशों में आर्थिक विकास के लिए मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं का भी महत्त्व है। राष्ट्र की विनियोग-नीति पर सामाजिक-सांस्कृतिक-राजनीतिक-धार्मिक-प्राथमिक मूल्यों और प्रेरणाओं का संयुक्त प्रभाव पड़ता है। देश के नागरिकों द्वारा नवीन विचारों और विवेक का आश्रय लेने पर तथा धार्मिक और रुढ़िवादी पंथविश्वासों और परम्पराओं से उन्मुक्त रहने पर वहाँ आर्थिक विकास तीव्र गति से होना सम्भव है। ग्रह-विकसित देश आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर हो, इसके लिए आवश्यक है कि देशवासियों में भौतिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने वाली सामाजिक परिस्थितियाँ पैदा की जाएँ और यह भावना जाग्रत की जाए कि मनुष्य प्रकृति का स्वामी है। यह भी उपयोगी है कि संयुक्त परिवार-प्रथा के स्थान पर एकाकी परिवार प्रथा को स्थान दिया जाए। ग्रह विकसित देशों के निवासियों में प्रायः साहस की भारी कमी रहती है। इसकी पूर्ति मुख्यतः तीन बातों पर निर्भर करती है—योग्यता, प्रेरक शक्ति एवं सामाजिक तथा आर्थिक वातावरण। योग्यता में दूरदर्शिता, बाजार-प्रवृत्तियों को पहचानने की क्षमता, कार्य की वैकल्पिक सम्भावनाओं को पहचानने का विवेक, व्यक्तिगत योग्यता आदि बातें सम्मिलित रहती हैं। प्रेरक शक्ति में मोद्रिक लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि को सम्मिलित किया जाता है जिससे कि व्यक्ति को प्रेरणा प्राप्त हो। आर्थिक सामाजिक वातावरण में आन्तरिक शान्ति, सुरक्षा आर्थिक स्थिरता आदि बातें सम्मिलित की जाती हैं। आर्थिक विकास में नेतृत्व का भी बहुत महत्त्व है। बारबारा बार्ड का यह कथन बिल्कुल ठीक है कि “आर्थिक विकास की प्रभावशाली नीति के लिए यह विचारधारा आवश्यक है कि अपेक्षित पूँजी व संचालन के लिए योग्यता एवं कुशल व्यक्ति हो। अण्डाचार और स्वार्थ से उत्पत्ति नहीं हो सकती।”

6 विनियोग का आधार (Investment Criteria)—ग्रह विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए विनियोग का सर्वोत्तम आवंटन करना कठिन कार्य है। इसके लिए कोई निश्चित मापदण्ड निर्धारित करना भी सुगम नहीं है क्योंकि उद्योगों का उत्पादन विभिन्न ढंगों से प्रभावित होता है। फिर भी अर्थशास्त्रियों ने विनियोग का आधार निर्धारित करने के लिए कुछ बातें आवश्यक ठहराई हैं। प्रो मौरिस डोब (Maurice Dobb) के अनुसार ग्रह-विकसित देशों को अपनी विनियोग नीति (Investment Policy) के सम्बन्ध में निम्नांकित बातों का ध्यान रखना चाहिए—

- (1) विनियोग राशि का कुल आय से अनुपात,
- (ii) विनियोग की जाने वाली राशि का विभिन्न क्षेत्रों में वितरण, एवं
- (iii) उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली तकनीक का चुनाव।

इनके अतिरिक्त अनेक अर्थ-शास्त्रियों ने विनियोग के अन्य मापदण्ड भी बताए हैं जैसे—

- (i) न्यूनतम पूँजी उत्पादन-अनुपात (Minimum Capital Output Ratio),

(ii) अधिकतम रोजगार एवं

(iii) अधिकतम दबन की जाने वाली राशि की मात्रा जिसका पुन विनियोजन किया जा सके।

व्यावहारिक रूप में उपर्युक्त मापदण्डों का उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि इनका क्रियान्वयन प्रत्यक्ष कठिन है तथा ये मापदण्ड प्रायः परस्पर संगत (Consistent) नहीं होने। यद्यपि विनियोग के लिए प्रस्तावित साधनों का सर्वोत्तम आवंटन 'सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त' (Marginal Productivity Theory) द्वारा किया जाना चाहिए लेकिन इस सिद्धान्त के व्यावहारिक क्रियान्वयन में भी अनेक बाधाएँ उपस्थित हो जाती हैं जिनके कारण यह मापदण्ड भी प्रायः अव्यावहारिक बन जाता है तथापि इसके द्वारा विविध योजनाओं को चुनने या रद्द करने के औचित्य को तो जांचा ही जा सकता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय को अधिकतम करने के लिए कम-पूँजी-उत्पादन-अनुपात (Low capital output ratio) की नीति अपनाना श्रेयस्कर है, किन्तु जब ध्येय भविष्य में प्रति व्यक्ति उर्जा को अधिकतम करना हो तो पूँजी-प्रधान तकनीक को अपनाना अधिक अच्छा है। प्रो हार्वेल्लिर्वेस्टिन की मान्यता है कि विकसित देशों के नीति निर्माताओं को चाहिए कि वे विविध उद्योगों में सीमान्त प्रति व्यक्ति पुनर्विविनियोग अंश (Marginal per Capita re-investment Quotient) की चिन्ता करें, न कि पूँजी की सीमान्त उत्पादकता बराबर करने की।

पश्चिमी देशों का अर्थशास्त्र पिछड़े देशों के लिए अनुपयुक्त

पश्चिमी देशों का अर्थशास्त्र नवोदित और पिछड़े देशों के शासकों को सम्मोहित किए जा रहा है। यह एक विशेष मनोवृत्ति की उर्जा है। औपचारिक रूप से साम्राज्यों का अन्त भले ही हो गया हो, लेकिन आर्थिक साम्राज्य अब भी कायम हैं, और वे पुरानी तर्क पद्धति को ही नए तरीके से पोषित करते हैं। यद्यपि तीसरी दुनियाँ के देशों ने अन्टार्क सयुक्तराष्ट्र सघ, निगुंट देश सम्मेलन आदि मंचों से सामूहिक स्वर से इस तर्क पद्धति का विरोध करना शुरू कर दिया है। स्वीडन के विख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर गुन्नार मिडेल ने अपने 'एशियन ड्रामा' में सकलित तथ्यों के आधार पर पश्चिम के असंतुलित अर्थशास्त्र का मायाजाल ध्वस्त करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई और उसमें जो कमी रह गई उसे उन्होंने अपनी पुस्तक 'द चैलेंज ऑफ वॉर्ल्ड पावरटी' में पूरा कर दिया है। इस पुस्तक में गुन्नार मिडेल ने यद्यपि इस बात का विवेचन विस्तार से नहीं किया है कि अल्प विकसित देशों के विकास को सम्भव बनाने और तीव्र करने के लिए विकसित तथा अविकसित देशों को क्या प्रमुख नीतियाँ अपनानी चाहिए, तथापि उन्होंने पश्चिमी देशों के दृष्टिकोण की कमियों को बताते हुए नीति-निर्धारकों के लिए सोचने-विचारने की यथेष्ट सामग्री प्रस्तुत की है।

गुन्नार मिडेल ने प्रथम अध्याय में ही पश्चिमी देशों के दृष्टिकोण की कमियाँ बताते हुए कहा है कि "उन देशों में अनुसंधान भी प्रायः राजनयिक होता है और अनुसंधान का समारम्भ विश्लेषणात्मक पूर्वसंकल्पनाओं अथवा मान्यताओं के आधार

पर होता है।" उनकी मान्यता है कि विकसित देशों में शुद्ध आर्थिक दृष्टि से किया गया विश्लेषण अल्प-विकसित देशों पर इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि उनकी सकल्पनाएँ नमूने और सिद्धान्त विकसित देशों के यथार्थ के अनुरूप होती हैं।

इस अनुमधान में बुनियादी कमी है कि यह दृष्टिकोण प्रवृत्तियों और समस्याओं से प्रेरित होता है। विकसित देशों में ये या तो इस दृष्टि से सगत बन गए हैं कि वे विकास के उत्साह का मार्ग प्रशस्त करते हैं अथवा तीव्रता से और बिना किसी व्यवधान के व्यवस्थित होकर विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं, लेकिन यह मान्यता कम विकसित देशों के बारे में सही नहीं हो सकती। इनकी प्रवृत्तियाँ अथवा रुझान संस्थाएँ ऐसी हैं कि वे बाजारों के सम्पर्क में विश्लेषण को अव्यावहारिक बना देती हैं।

विकसित तथा अल्पविकसित देशों के वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में उनका निष्कर्ष है कि "इस समय वह कार्य जिस रूप में हो रहा है, साधारणतया उनमें अल्पविकसित देशों की उन परिस्थितियों को छिपाने का प्रयास किया जाता है जो आमूल और दूरगामी सुधारों की आवश्यकता को सर्वाधिक प्रमाणित करते हैं। इसने अर्थशास्त्र के एक प्राचीन पूर्वाग्रह का भी अनुसरण किया है। यह कार्य सीधे ढंग से यह मानकर किया गया है कि समानतावादी सुधार आर्थिक विकास के विपरीत हैं जबकि स्थिति यह है कि ये सुधार आर्थिक विकास को प्रेरणा देते हैं और इसकी गति तीव्र बनाते हैं।"

एक अन्य प्रसंग में पश्चिम के व्यापारियों के बारे में उनका विचार है कि "जन समुदाय की प्रायः गम्भवन् निष्क्रियता और अल्प-विकसित देशों में सुधारों के प्रयास का अभाव पश्चिम के उन व्यापारिक हितों को अछूता लगता है जो अल्प विकसित देशों में अपनी पूँजी लगाना और अपने उद्योग चालू रखना चाहते हैं। सत्तारूढ़ समूह इन कम्पनियों के स्वाभाविक सहयोगी होते हैं। यह उपनिवेशी नीति को उसी रूप में जारी रखने का प्रमाण है और इससे इस आरोप का औचित्य सिद्ध होता है जो पश्चिम के व्यापारियों पर उन्हें 'नव पूँजीवादी' कहकर लगाया जाता है।"

भूमि सुधार और खेती—अल्प विकसित देशों में भूमि की उत्पादकता का प्रश्न भूमि-वितरण, खेती के तरीकों सामाजिक विषमता आदि अनेक परिस्थितियों से सम्बद्ध होता है, जिसका कोई उचित समाधान नहीं है। काफी छानबीन और विश्लेषण के पश्चात् अध्येता मिडेल ग्राग्रह करते हैं कि विकासशील देशों में "नई कृषि विधियाँ तथा टेक्नोलॉजी ऐसी हो जिसमें श्रम का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता हो, यह इस कारण भी जरूरी है कि खेती में लगे श्रम-शक्ति का इस समय कम उपयोग हो रहा है और अधिकांश अल्प विकसित देशों में 'म' अनेक दशकों तक कृषि में लगी श्रम शक्ति में निरन्तर तेजी से वृद्धि होत रहेगी।" लेकिन किसी नई व्यवस्था के लिए जरूरी है कि खेतिहर का भूमि से लगाव हो : "गट्टाई पर खेती करने की व्यापक प्रणाली न तो टेक्नोलॉजी गम्बन्धी परिवर्तन के उपयोग की दृष्टि से लाभदायक है और न ही श्रम और धन के रूप में विनियोग

की दृष्टि से।" गुनार मिडेल की दृष्टि में यह एक ऐसा बुनियादी कार्य है जिसे किए बिना जो कुछ भी किया जाएगा उसका लाभ केवल ऊँचे स्तर के लोग उठाते रहेंगे और असमानता में वृद्धि होती रहेगी।

मिडेल की दृष्टि में, अल्पविकसित देशों में अनाज की पूर्ति बढ़ाने के लिए उनका काम उचित स्तर से ऊँचा बनाए रखने का तर्क भी, अमीर किसानों के ही हित में होगा, क्योंकि बटाईदार या छोटा किसान मुश्किल से जरूरत भर का अनाज पैदा करता है—यदि कटाई के समय उसे बर्ज की अदायगी या अन्य आवश्यकताओं के लिए गल्ला बेचना पड़ा तो बाद में अपना पेट भरने के लिए और महंगे दामों में खरीदना पड़ता है।

यही स्थिति उन्नत बीज, उर्वरक आदि के कारण उपजे, 'अतिशय तकनीकी आशावाद के सन्दर्भ में पाई जाती है' "नए बीजों के उपलब्ध होने की बात का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर मू-स्वामित्व और दस्तकारी प्रणाली के सुधारों की बात को पीछे डाल दिया गया है। इन सुधारों के अभाव में नए बीज का उपलब्ध होना उन अन्य प्रतिक्रियावादी शक्तियों से गठजोड़ करेगा जो इस समय अन्य विकसित देशों में ग्रामीण जनमर्या और असमानता बढ़ाने में सहायक बन रही है।

शिक्षा—वर्तमान शिक्षा प्रणाली ने जो उपनिवेशवादी प्रणाली का मान विस्तार है, समाज में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया है, और न ही वह कर सकती है क्योंकि इस प्रणाली में प्रगामको अध्यापको विद्याविद्यो और सर्वाधिक शक्तिशाली उच्च वर्ग के परिवारों के शक्तिशाली स्वार्थ निहित है। यदि दक्षिण-पूर्वी एशिया में साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा के सन्दर्भ में यह वाक्य खास दिलचस्प है—'जब बयस्को को शिक्षा देने के प्रयासों को एक ओर उठा कर रख दिया गया तो साक्षरता के लक्ष्य की प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की भर्ती की सख्या में तेजी से वृद्धि के कार्यक्रम में बदल दिया गया।'

नरम राज्य—अन्य पश्चिमी लेखकों की तरह मिडेल का भी यह मत है कि विभिन्न सीमाओं तक सभी अल्प विकसित देश नरम राज्य हैं लेकिन उनकी यह भी मान्यता है कि विकसित देशों में भी नरम राज्य के लक्षण पाए जाते हैं—अमेरिका के लोग, अल्पविकसित देशों के लोगों के समान, लेकिन उत्तर-पश्चिम यूरोप के देशों के लोगों के विपरीत, अपने कानूनों में ऐसे आदेशों को स्थान देते हैं, जिन्हें सयुक्तराज्य अमेरिका में कभी भी प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं किया गया। यद्यपि सयुक्तराज्य अमेरिका में प्रशासन कभी भी बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं रहा तथापि इस देश ने बहुत तेजी से आर्थिक उन्नति की। यह उन अनेक परिस्थितियों के कारण सम्भव हुआ, जो आज गरीबी से ग्रस्त अल्पविकसित देशों से बहुत भिन्न थी। विकासशील देशों में होता यह है कि राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसे कानून नहीं बनने देती जो लोगों के ऊपर अधिक उत्तरदायित्व डालते हों। जब कभी कानून बन जाते हैं तो उनका पालन नहीं होता और इन्हें लागू करना भी आसान नहीं होता। इसका मूल कारण यह है कि स्वाधीनता के प्रारम्भिक दौर में सत्ता

राजनीतिक दृष्टि से विशिष्ट लोगो ने ये नए कानूनी अधिकार (व्यस्क मताधिकार आदि) लोगो को दिए लेकिन वे लोग इन अधिकारो को वास्तविकता के आधार पर स्थापित करने के लिए उत्सुक नहीं थे। इस कार्य से बच निकलना भी आसान था, क्योंकि नीचे से कोई दबाव नहीं था। ऐसी स्थिति में यदि सरकार बदलती है और सत्तन सरकार (जैसे पाकिस्तान में जब अख्तर की तानाशाही आई) बागडोर भालती है तो भी वह नरम ही रहती है क्योंकि (1) वह उपयोगी सांस्थानिक परिवर्तन नहीं करा पाती और (2) सरकार में परिवर्तन समाज के सर्वोच्च वर्ग के लोगो के आपसी झगडे के परिणामस्वरूप होते हैं। ये परिवर्तन कही भी गरीब जन समुदाय द्वारा अपने उत्पीडन के विरुद्ध विद्रोह के परिणामस्वरूप नहीं आए।¹

पश्चिमी देशो के आर्थिक साम्राज्यवाद के विरुद्ध तीसरी दुनिया की रणनीति

तीसरी दुनिया के राष्ट्र, जो पश्चात्य अधिक साम्राज्यवाद के दीर्घकाल तक शिकार रहे हैं और आज भी हैं अब एक नए अर्थतन्त्र और नए समाज की रचना के लिए प्रयत्नशील हैं। पश्चिम के अधिक साम्राज्यवाद के प्रति उनकी रणनीति बदल रही है जो पिछले कुछ अर्से में सम्पन्न हुए विभिन्न सम्मेलनो में प्रकट हुई हैं।

तीसरी दुनिया के देश जिन्हे औपनिवेशिक जुगा उतार फेंकने के बाद आशा थी कि संयुक्तराष्ट्र संधि के माध्यम से या सीधे पश्चिमी देशो की आर्थिक सहायता (अनुदान और मुख्यतः ऋण) उनकी औद्योगिकी और उनसे व्यापारिक लेनदेन नया अर्थतन्त्र और नए समाज की रचना का मोका देगा समझ गए हैं कि उन्नत देशों के सामन्तीतन्त्र को उनसे सहानुभूति नहीं है। यही नहीं उन्होंने यह भी महसूस कर लिया है कि सभी क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मंचो पर पश्चिमी देशो के विरुद्ध जेहाद (घर्ष युद्ध) छेड़ा जाना चाहिए। इसका स्वर दिल्ली में 'एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक सामाजिक आयोग के वार्षिक अधिवेशन (26 फरवरी से 7 मार्च 1975) में ही नहीं बल्कि तेल उत्पादक देशों के अल्जियर्स सम्मेलन (मार्च, 1975) में भी सुनाई पड़ा।" लीमा में संयुक्तराष्ट्र उद्योग विकास सगठन के दूसरे सम्मेलन और हवाना में तटस्थ देशों के सम्मेलन में यही स्वर मुखर हुआ है। इसका लक्ष्य औद्योगिक देशो से अधिक साधन और सुविधाएँ प्राप्त करना तो है ही साथ ही विकासशील देशो को एकता के सूत्र में बाँधना। तीसरी दुनिया के साधनो का उपयोग करना और आपसी लेनदेन बढ़ाना ताकि स्वावलम्बन के मार्ग पर बढ़ा जा सके। तेल उत्पादक देशो द्वारा मूल्य बढ़ाने से उसे एक नई शक्ति मिली है—विश्व के उत्पादन में विकासशील देशो के वर्तमान 7 प्रतिशत योग को सन् 2000 तक बढ़ाकर 25 फीसदी करने का तारा हाल के अल्जियर्स सम्मेलन में ही दिया गया था—मगर उतना नहीं जितना होता चाहिए था क्योंकि तेल उत्पादक देशो में पश्चिम से जुड़ने का मोह पैदा हो गया है।²

1 दिनमान, 25-31 जुलाई 1976, पृष्ठ 9-10

2 दिनमान, मार्च, 1965

“लीमा में भारत के उद्योग और नागरिक प्रति मंत्री श्री टी ए पें ने संयुक्तराष्ट्र उद्योग विकास संगठन के दूसरे सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय सामंती प्रभुत्व की खाती बखिया उछोड़ी। श्री पें ने कहा कि विकासशील देशों के प्रयत्नों के बावजूद विकसित और विकसित देशों में औद्योगिक अन्तर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अमीर देश पूँजी निवेश की मात्रा बढ़ाने में समर्थ हैं। यही नहीं, वे अन्य उन्नत देशों से ही व्यापार करना पसंद करते हैं। उन्होंने अपने बाजार और लाभ सुरक्षित रखने के लिए तरह तरह के प्रतिबन्ध ईजाद कर रखे हैं। धनिक देशों की मुनाफाखोरी और शोषण की प्रवृत्ति का उदाहरण देते हुए भारतीय उद्योग मंत्री ने बताया कि विकासशील देशों को विवश किया जाता है कि वे बिना घुना कपड़ा (Gray cloth) निर्यात करें। यह कपड़ा धनिक देशों में रासायनिक तथा अन्य विधियों द्वारा साफ होकर ऊँचे दामों में बिकता है। इसी प्रकार, उन्होंने पूछा, क्या वजह है कि हमारी चाय सिर्फ पेटियों में ही खरीदी जाती है? क्या इसलिए कि फिर उसे आकर्षक डिब्बों में भरकर मुनाफा कमाया जा सके? विकासशील देशों को कच्चा माल मुहैया कराने वाला क्षेत्र ही माना जाता है। विकासशील देश जो जिसे निर्यात करते हैं उसका भाव भी विकसित देशों के ग्राहक इस तरह नियन्त्रित करते हैं कि तीसरी दुनियाँ के देशों की ग्रामदनी में उतनी बढ़ोत्तरी नहीं होती जितनी कि आयात करने वाले माल के—मशीन, उर्वरक आदि के—भाव में हो जाती है। श्री पें ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पश्चिमी देशों के माल—इस्पात तैयार माल, मशीन आदि सबके मूल्य तेल का भाव बढ़ने के पहले से चढ़ने लगे थे।”

“आयात निर्यात सहायता अथवा बहुत औद्योगिकी आदि के अलावा विकासशील देशों की लीमा में कोशिश यह रही कि इस उद्योग संगठन को संयुक्त राष्ट्र का स्थायी और स्वतन्त्र संगठन बना दिया जाए। लेकिन पश्चिमी देश इसके पक्ष में नहीं थे। ब्रितानी प्रतिनिधि ने स्पष्ट शब्दों में कहा—हमें सदेह है कि इससे आप लोगों को कोई लाभ होगा। स्विटजरलैंड के प्रतिनिधि ने औद्योगिक उत्पादन का सक्षम 25 / निर्धारित करने का विरोध किया—यह व्यावहारिक नहीं है।”

आर्थिक विकास के अन्तर्गत संरचनात्मक परिवर्तन : उत्पादन, उपभोग, रोजगार, निवेश और व्यापार के संगठन में परिवर्तन

(Structural Changes under Development : Changes
in the Composition of Production, Consumption,
Employment, Investment and Trade)

आर्थिक विकास के अन्तर्गत संरचनात्मक परिवर्तन (Structural Changes under Development)

किसी देश के औद्योगिक उत्पादन में दीर्घकालीन और सतत वृद्धि को प्रायः आर्थिक विकास कहा जाता है। पैंरीवलीज युग का यूनान, ऑगस्टवालीन रोम, मध्ययुगीन फ्रांस, आधुनिक अमेरिका और भारत तथा मिस्र के कुछ युग इस परिभाषा की परिधि में आते हैं।¹ संरचनात्मक परिवर्तनों की ओर सचेत करते हुए साइमन कुजनेट्स ने लिखा है—“आधुनिक युग में, मुख्य संरचनात्मक परिवर्तनों का लक्ष्य कृषि मंदो के स्थान पर औद्योगिक मंदो का उत्पादन (शहरीकरण की प्रक्रिया), ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण (शहरीकरण की प्रक्रिया), लोगों की सामेल आर्थिक स्थिति में परिवर्तन (रोजगार की स्थिति तथा आय स्तर आदि के द्वारा) और माँग के अनुरूप वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण रहा है।”²

एक अन्य स्थल पर साइमन कुजनेट्स ने लिखा है—“आधुनिक आर्थिक विकास सारभूत रूप में औद्योगिक व्यवस्था को लागू करना अर्थात् आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के बढ़ते हुए प्रयोग पर आधारित उत्पादन की एक व्यवस्था को लागू करना है, किन्तु इसका अर्थ संरचनात्मक परिवर्तनों से ही है, क्योंकि महत्त्व की दृष्टि से नए उद्योग स्थान लेते हैं और विकसित होते हैं जबकि पुराने उद्योग लुप्त होने जाते हैं—यह प्रक्रिया बदले में समाज की उस क्षमता की माँग करती है जो ऐसे परिवर्तनों को

1 Simon Kuznets Six Lectures on Economic Growth, p 13

2 Simon Kuznets Modern Economic Growth, p 1

ग्रहण कर सके। एक समाज को इतना समय और योग्य होना चाहिए कि वह प्रति व्यक्ति उत्पादन में अभिवृद्धि करने वाले उत्तरोत्तर नव-प्रवर्तनों को ग्रहण कर सके और स्वयं उनके अनुकूल ढाल सके। इस प्रकार प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक रूप से सम्मिलित है और ये परिवर्तन प्राविधिक नव-प्रवर्तनों तथा समाज की बढ़ती हुई माँगों और परिवर्तनों के अनुकूल समाज के ढलने की क्षमताओं के फलस्वरूप होते जाते हैं।¹

नियमित आर्थिक विकास के दो मूल स्रोत हैं—(1) प्राविधिक ज्ञान (Technology) एवं (2) सामाजिक परिवर्तन (Social Change)। इन दोनों की अन्त क्रिया का परिणाम ही आर्थिक विकास होता है। इस सम्बन्ध में साइमन कुजनेट्स के मतानुसार 'किसी भी युग में आर्थिक वृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्र प्राविधिक ज्ञान अथवा सामाजिक परिवर्तनों के कारण ही नहीं होती बल्कि यह कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप होने वाले कतिपय सरचनात्मक परिवर्तनों के कारण होती है।'² पुराने उद्योगों का नवीनीकरण होने लगता है तथा नए उद्योग अस्तित्व में आते हैं। आय के वितरण की स्थिति परिवर्तित होने लगती है। उत्पादन, उपभोग, रोजगार, विनियोजन, व्यापार आदि के ढाँचों में क्रान्तिकारी परिवर्तन होने लगते हैं।

सरचनात्मक परिवर्तनों को निम्नलिखित कुछ मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा सकता है जैसे—

- (1) औद्योगिक ढाँचे में परिवर्तन,
- (2) औद्योगिक क्षेत्र के आन्तरिक ढाँचे में परिवर्तन,
- (3) आय के वितरण में परिवर्तन, एवं
- (4) जनसंख्या के विकास की प्रवृत्तियाँ।

1 औद्योगिक ढाँचे में मुख्यतः दो परिवर्तन होते हैं। प्रथम, उत्पादन में कृषि क्षेत्र का अंश कम हो जाता है तथा द्वितीय, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का उत्पादन प्रतिशत अधिक हो जाता है। कुजनेट्स के अनुसार, सामान्यतः विकास से पूर्व की स्थिति में कृषि क्षेत्र के उत्पादन में औसतन योग लगभग 50% था, और कुछ देशों में तो यह अनुपात दो तिहाई से भी अधिक था। विकास की एक लम्बी अवधि के पश्चात् कृषि उत्पादन का भाग घटकर 20% और कुछ देशों में 10% से भी कम हो गया। आस्ट्रेलिया की स्थिति इस दृष्टि से अपवाद रही। उद्योग का अंश जो विकास से पूर्व इन देशों में कुल उत्पादन का 20 से 30% था, वह दो तिहाई अवधि में बढ़कर 40 से 50% हो गया।³

2 औद्योगिक क्षेत्र के आन्तरिक ढाँचे के परिवर्तन तकनीकी (Technology) तथा अन्तिम माँग (Final Demand) से सम्बन्धित होते हैं। इन परिवर्तनों के अन्तर्गत अग्रकित परिणाम आते हैं।

1 Simon Kuznets Six Lectures on Economic Growth, p 15

2 Simon Kuznets Modern Economic Growth p 13

3 Ibid, p 47, Tab 3 1

- (i) उत्पादन वस्तुओं का अनुपात अधिक हो जाता है।
- (ii) खाद्य और वस्तुओं के उपभोग में कमी होती है, किन्तु कान्ज, धातु तथा रासायनिक पदार्थों का उपभोग बढ़ जाता है।
- (iii) उत्पादक इकाइयों का आकार बढ़ जाता है।
- (iv) शहरीकरण की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है।
- (v) निजी व्यवसाय में रहने की प्रवृत्ति के स्थान पर वेतनभोगी व्यवसायों के प्रति आकर्षण बढ़ता है।
- (vi) श्वेत-पोषी व्यवसायों के प्रति लोग अधिकाधिक आकर्षित होते हैं।

3. सरचनात्मक-परिवर्तन आय के वितरण से सम्बन्धित होते हैं। इन परिवर्तनों के अन्तर्गत परिवारों की आय का राष्ट्रीय आय में प्रतिशत घट जाता है। प्रसंगान्तर अध्ययन के अनुसार यह 90% से घटकर लगभग 75% रह जाता है। सरकार की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है और निगमों का महत्व भी बढ़ जाता है। सरकारी अनुदानों की राशि और हस्तान्तरण आय (Transfer incomes) से भाग में वृद्धि होती है। इनके अतिरिक्त सम्पत्ति से प्राप्त आय (Property Income) का भाग 20-40% से घटकर केवल 20% या इससे भी कम हो जाता है। निजी व्यवसाय में सलग्न व्यक्तियों के स्थान पर वेतनभोगियों की संख्या बढ़ने लगती है। व्यक्तिगत आय की विषमताएँ कम हो जाती हैं। उत्पादन साधनों को मिलने वाली आय और व्यक्तिगत आय के वितरण (Distribution of the Factorial and Personal Income) में परिवर्तन आने लगता है।

4. अर्थ व्यवस्थाओं में कुछ सरचनात्मक परिवर्तन जनसंख्या के ढाँचे से सम्बन्धित होते हैं। आर्थिक वृद्धि की स्थिति में जनसंख्या भी तीव्र गति से बढ़ती है। पश्चिमी यूरोप के अनेक देशों में जहाँ पूँजी प्रचुर और श्रम दुर्लभ था, वहाँ जनसंख्या की वृद्धि का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योग रहा है। किन्तु ऐसे अल्प विकसित देशों में जहाँ पूँजी दुर्लभ और श्रम प्रचुर होता है, जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव विपरीत होता है। आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप प्रायः शैशवकालीन मृत्यु दर कम हो जाती है। शैशवकालीन मृत्यु-दर में कमी के कारण उत्पादक आयु का अनुत्पादक आयु में अनुपात बढ़ जाता है। श्रमिकों में स्त्रियों का अनुपात कम हो जाता है, किन्तु सेवा क्षेत्र में शिक्षित स्त्रियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि होती है।

प्रायः पूर्व विकास की स्थिति में कुल जनसंख्या का अधिकतम अनुपात 15 वर्ष की आयु तक होता है। भारत में जनसंख्या का 50 प्रतिशत से भी अधिक भाग 18 वर्ष की आयु से कम वाला है। आर्थिक विकास के कारण मृत्यु-दर में कमी आती है, परिणामस्वरूप उत्पादकीय वर्ग का अनुपात बदल जाता है।

आर्थिक विकास की प्रक्रिया विदेशी व्यापार के अनुपातों को भी प्रभावित करती है। विदेशी व्यापार के अंतर्गत विकसित देशों में लगभग 31% तथा अविकसित देशों में 20% से भी कम रहे हैं। अविकसित देशों के लिए विदेशी व्यापार का अत्यधिक महत्व होते हुए भी उत्पादन की आधुनिक तकनीकों के

अभाव में, विकसित देशों की प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाते। आर्थिक विकास की गति के साथ-साथ एक ओर जहाँ उत्पादन में पूँजी निर्माण का अनुपात बढ़ने लगता है तथा कुछ उपभोग-व्यय में भोजन तथा आवास सम्बन्धी व्यय का अनुपात घटने लगता है, वही दूसरी ओर विदेशी व्यापार की मात्रा, स्वरूप तथा दिशा में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं।

आर्थिक विकास के कारण न केवल आर्थिक ढाँचे में ही परिवर्तन होने हैं, बल्कि गैर-आर्थिक ढाँचे में भी अनेक ऐसे क्रान्तिकारी परिवर्तन होते हैं जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से देश की आर्थिक संरचना को प्रभावित करते हैं। प्रायः अविकसित देशों में राजनीतिक अस्थिरता, राष्ट्रीय हित के विषयो पर भी राजनीतिक दलों में मतभेद का अभाव प्रभावहीन सरकार आदि इन देशों के आर्थिक विकास तथा आर्थिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। सांस्कृतिक मूल्यों के अन्तर्गत एकता, सहयोग तथा सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति आदि वे मूल्य लिए जाते हैं जो प्रत्यक्ष रूप में श्रम विभाजन व बाजार सम्बन्धों को प्रभावित करते हैं तथा अप्रत्यक्ष रूप से उन राजनीतिक साठन को प्रभावित करते हैं जो देश के आर्थिक विकास से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय लेने व नीति-निर्धारण की शक्ति रखते हैं।

संक्षेप में, आर्थिक विकास के कारण सभी प्रकार के आर्थिक कार्यों (Economic Functions) की संरचना में परिवर्तन आते हैं। उत्पादन-कार्यों (Production Functions) में तकनीकी भूमिका प्रमुख हो जाती है। बचत के अन्तर्गत विकास की स्थिति में व्यक्तिगत बचत (Personal Savings) का अनुपात कम हो जाता है। सरकारी बचत का अनुपात प्रायः बहुत कम होता है। अविकसित देशों में व्यक्तिगत बचत का अनुपात बहुत अधिक होता है। बचत की यह स्थिति आर्थिक संकट की ओर संकेत करती है अर्थात् अविकसित देशों में असंगठित क्षेत्रों से बचत प्राप्त होनी है जबकि विकसित देशों में संगठित क्षेत्र का कुल बचत में अनुपात सर्वाधिक होता है। विदेशी व्यापार की स्थिति में भी अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तन होते हैं।

उत्पादन की संरचना, उपयोग व प्रवृत्तियाँ (Structure, Use & Trends of Output)

कृषि, उद्योग, आदि क्षेत्र मिलकर राष्ट्रीय उत्पादन करते हैं। उत्पादन का उपभोग तीन मंचों पर होता है—(i) उपभोग, (ii) पूँजी निर्माण, तथा (iii) निर्यात।

(i) उपभोग दो प्रकार के है—(a) निजी उपभोग, एवं (b) सरकारी उपभोग। निजी उपभोग की मद में भूमि व आवासीय भवनों के सभी प्रकार के उपभोग पदार्थों के ऋण सम्मिलित हैं। यह तीनों उपभोगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विकसित देशों में उत्पादन का लगभग 64 प्रतिशत निजी उपभोग पर व्यय होता है। सरकारी उपभोग के अन्तर्गत वस्तुओं व सेवाओं की खरीद आती है। इसमें से उन वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा को घटा दिया जाता है जिसकी पुनः बिक्री की जाती

है। राजकीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व निगमों द्वारा क्रय को सरकारी उपभोग में सम्मिलित नहीं किया जाता, किन्तु सुरक्षा व्यय को इस मद के अन्तर्गत लिया जाता है। "इस प्रकार परिभाषित सरकारी व्यय राष्ट्रीय उत्पादन के लगभग 14 प्रतिशत से कुछ अधिक भाग के लिए उत्तरदायी रहा है।"¹

(ii) पूँजी निर्माण वस्तुओं के उस मूल्य को प्रकट करता है जिससे देश के पूँजी-सचय में वृद्धि होती है। विशुद्ध पूँजी-निर्माण में पूँजी के उपभोग व ह्रास पर विचार भी किया जाता है। कुजनेट्स के अनुसार कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 20 से 25 प्रतिशत भाग सकल पूँजी-निर्माण हेतु काम आता है। विशुद्ध पूँजी-निर्माण में राष्ट्रीय उत्पादन का 15 प्रतिशत भाग होता है। देश की वचत राष्ट्रीय पूँजी निर्माण को प्रकट करती हैं तथा देश के पूँजी-सचय में होने वाली वृद्धि घरेलू पूँजी-निर्माण कहलाती है। अधिकांश देशों में सकल पूँजी निर्माण में यह अनुपात 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ गया। विकास में वृद्धि के साथ-साथ यह अनुपात 10 से 20% तक बढ़ जाता है। किन्तु इंग्लैंड एवं अमेरिका में 19वीं शताब्दी के मध्य से यह अनुपात स्थिर चला आ रहा है। उल्लेखनीय है कि एक शताब्दी की दीर्घ अवधि के उपरान्त भी कुल वचतों का अनुपात इन दो देशों में स्थिर बना रहा जबकि प्रति व्यक्ति उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई।

इस प्रकार राष्ट्रीय उत्पादन में पूँजी-निर्माण का भाग या तो स्थिर रहा अथवा कुछ बढ़ा किन्तु सरकारी उपभोग व्यय के अनुपात में वृद्धि के साथ, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में निजी उपभोग व्यय के अनुपात में निश्चित रूप से गिरावट आई। विश्व युद्ध से पूर्व यह अनुपात 80 प्रतिशत था जो युद्ध से दो दशकों बाद की अवधि में गिरकर 60 प्रतिशत रह गया। अर्थात् कुल राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि दर की अपेक्षा कुल घरेलू उपभोग की वृद्धि-दर बहुत कम रही।

इस सन्दर्भ में सोवियत रूस के आँकड़े अधिक दिलचस्प हैं, क्योंकि स्वतन्त्र बाजार वाले देशों की भाँति वहाँ भी विकास के परिणामस्वरूप घरेलू उपभोग का अनुपात कम तथा सरकारी उपभोग व कुल पूँजी का राष्ट्रीय उत्पादन में अनुपात अधिक हुआ किन्तु इन परिणामों की प्राप्ति रूस ने स्वतन्त्र उद्यम वाली अर्थ-व्यवस्थाओं की तुलना में देवल-के अवधि में ही कर ली।

देश की स्थायी सम्पत्ति में पूँजी निर्माण की वृद्धि के रूप को देखते हुए दो महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं—प्रथम स्थायी सम्पत्ति में वृद्धि, तथा द्वितीय, वस्तुओं की सचित मात्रा में कमी। इस कमी की पृष्ठभूमि में यातायात व संचार के साधनों में सुधार कृषि क्षेत्र के अश्व में कमी तथा माँग में अल्पकालीन परिवर्तनों की पूर्ति के लिए वस्तुओं की सचित-आवृत्ति के स्थान पर बड़ी हुई उत्पादन-क्षमता का प्रयोग है। इसके प्रतिरिक्त स्थायी सम्पत्ति व कुल पूँजी-निर्माण में भवन-निर्माण के अनुपात में गिरावट आती है, किन्तु उत्पादक साज सामान (Producer's Equipment) के अनुपात में वृद्धि होती है। उत्पादन-वृद्धि का कारण विकास

के परिणामस्वरूप जनसंख्या की वृद्धि-दर में कमी तथा औद्योगिक समयों का विस्तार होना है।

कुजनेट्स ने कुछ देशों की पूँजी प्रदा अनुपातों (Capital Output Ratios) की गणना की है। इनके अनुसार, "इटली के राष्ट्रीय उत्पादन की दर न, पूँजी-प्रदा अनुपातों में कमी के कारण, पर्याप्त वृद्धि प्रदर्शित की। नाबो में पूँजी-प्रदा अनुपातों में गिरावट बहुत कम रही। किन्तु इंग्लैंड, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, अमेरिका, कनाडा आस्ट्रेलिया, जापान आदि देशों में सकल सीमान्त पूँजी-प्रदा अनुपातों (Gross Incremental Capital-output Ratios) ने वृद्धि प्रदर्शित की—प्रारम्भिक अवधि में वृद्धि 3 व 4 5 के मध्य थी तथा वर्तमान अवधि में 4 व 6 के बीच रही।"¹

सीमान्त पूँजी-प्रदा अनुपातों में इस वृद्धि का कारण न तो सकल घरेलू पूँजी-निर्माण की संरचना में परिवर्तन रहे है, और न ही कृषि, खान व निर्माण आदि उद्योगों द्वारा पूँजी-निर्माण में उत्पन्न संरचनात्मक परिवर्तन। श्रम साधन में हुए परिवर्तनों के कारण भी इन अनुपातों में होने वाली वृद्धि प्रमाणित नहीं होती। यह स्थिति इस सिद्धान्त को अत्यंत प्रमाणित करती है कि जब श्रम-शक्ति में वृद्धि की दर घटती है तब पूँजी-प्रदा अनुपात बढ़ते हैं। इन अनुपातों में वृद्धि के कारण तथा विभिन्न देशों में पाए जाने वाले इन अनुपातों के स्तर में अन्तर उन अनेक अवस्थाओं में अन्तर्निहित हैं जो भौतिक पूँजी की माँग को प्रभावित करती हैं तथा जिनके कारण उत्पादन की एक ही मात्रा श्रम व पूँजी के विभिन्न संयोगों द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

इंग्लैंड व अमेरिका के अतिरिक्त अधिकांश देशों में पूँजी-निर्माण का उत्पादन अधिक हुआ। यदि पूँजी-निर्माण का भाग अधिक होता है तो सीमान्त पूँजी-प्रदा अनुपात उसी स्थिति में स्थिर रहने हैं जब राष्ट्रीय उत्पादन में सांख्यिक वृद्धि होती है।² इस स्थिति को कुजनेट्स ने एक उदाहरण द्वारा प्रस्तुत किया है। मान लीजिए कुल घरेलू उत्पादन = \$ 1000, सकल घरेलू पूँजी-निर्माण = \$ 150, वास्तविक वृद्धि दर = 50 प्रतिशत तथा सीमान्त सकल पूँजी-प्रदा अनुपात = 3 0 है। यदि कुल उत्पादन में पूँजी-निर्माण का अनुपात $\frac{150}{1000}$ से बढ़कर $\frac{210}{1000}$ (40% की वृद्धि) हो जाता है, तब सीमान्त पूँजी-प्रदा अनुपात उसी स्थिति में 3 0 रहेगा जब उत्पादन की वृद्धि दर 5 से बढ़कर 7 (अथवा 40% की वृद्धि) हो जाती है।

उत्पादन की संरचना में जनसंख्या का वृद्धि-दरों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। "यदि जनसंख्या घटती हुई दर से बढ़ती है, जैसाकि अनेक विकसित देशों में होता है, तो कुल उत्पादन में स्थिर दर से भी वृद्धि होने पर, प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। पूँजी-निर्माण के भाग में निरन्तर वृद्धि होती रहने की

1. Ibid, p 122

2 Ibid, p 123

स्थिति में यदि पूँजी-प्रदा अनुपात को स्थिर रखना है और कुल उत्पादन की वृद्धि में तीव्र से तीव्रतर गति बनाए रखनी है तो प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि की दर कुल उत्पादन की वृद्धि-दर से भी कहीं अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार, प्रति व्यक्ति उत्पादन की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दरों के कारण अधिक बचतें होती हैं। अधिक बचत के परिणामस्वरूप पूँजी-निर्माण का भाग भी बढ़ता है—जिसका आशय यह है कि यदि सीमान्त पूँजी प्रदा अनुपात को बढ़ती हुई स्थिति में रखना है तो कुल उत्पादन व प्रति व्यक्ति उत्पादन की वृद्धि दर और भी अधिक तीव्र की जानी चाहिए।¹

उपभोग में संरचनात्मक परिवर्तन (Structural Changes in the Composition of Consumption)

उपभोग की संरचना की विवेचना व्यक्तिगत बचत व उपभोग्य आय (Disposable Income) के अनुपातों की दीर्घकालीन प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। व्यक्तिगत करो (आयकर आदि) के भुगतान के पश्चात् जो आय परिवारों के पास शेष रहती है, उसे उपभोग्य आय कहते हैं। यह वह आय होती है जिसे लोग अपनी रुचि के अनुसार खर्च कर सकते हैं अथवा बचा सकते हैं। इस आय का वह भाग जिसे वे वस्तुओं व सेवाओं पर व्यय नहीं करते, व्यक्तिगत बचत की श्रेणी में आता है।

विगत वर्षों में, विशुद्ध बचत का लगभग 48 से 49% भाग परिवारों से प्राप्त हुआ है। विशुद्ध बचत कुल बचतों का 60 प्रतिशत व कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 23 प्रतिशत रही। इस प्रकार परिवारों की विशुद्ध बचत का भाग कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 67 प्रतिशत रहा। उपभोग्य आय कुल उत्पादन का 70.3 प्रतिशत रही। अतः विशुद्ध बचत, उपभोग्य आय का औसतन $\frac{67}{70.3}$ अथवा 9.5% रही।²

कुजनेट्स के अध्ययनानुसार गत एक शताब्दी की अवधि में प्रति व्यक्ति उपभोग्य आय की वृद्धि-दर अवधि के अन्त में अपने प्रारम्भिक मूल्य का 45 गुना हो गई। उपभोग्य आय में इतनी अधिक वृद्धि के बावजूद, बचत का अनुपात बहुत कम रहा, क्योंकि उपभोग्य आय का बड़ा भाग उपभोग व्यय के रूप में काम आया। उपभोग प्रवृत्ति के अधिक रहने के मुख्यतः दो कारण हैं—आधुनिक आर्थिक उत्पादन के गहरी ढाँचे के कारण जीवन-लागत में अतिरिक्त वृद्धि तथा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए मानव पर अधिकाधिक विनियोजन।³

सारणी 5.2 में कुजनेट्स ने उपभोग के ढाँचे में परिवर्तनों को पाँच श्रेणियों में प्रस्तुत किया है—भोजन, पेय, वस्त्र, आवास तथा अन्य। इन मदी में सरकार द्वारा प्रदत्त शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाएँ सम्मिलित नहीं हैं।

1 Ibid, p 124

2 Ibid, p 125

3 Ibid, p 128, Table 5.2

उपभोग (वर्तमान मूल्यों पर)
(Current Prices)

	भोजन	पैय पदार्थ व तम्बाकू	वस्त्र	आवास	अन्य
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
इंग्लैण्ड					
1880-99	34.2	13.8	—	10.7	41.3
1950-1959	31.3	14.1	11.7	12.8	30.1
इटली					
1861-80	52.0	17.2	—	5.8	25.0
1950-1959	46.6	10.7	11.5	5.2	26.0
नार्वे					
1865-1875	45.2	7.0	10.9	19.8	17.1
1950-59	30.3	8.1	16.7	10.1	34.7
कनाडा					
1870-1890	32.2	5.7	16.9	26.7	18.5
1950-59	23.7	8.3	10.2	21.2	36.6

निष्कर्ष—कुल उपभोग में भोजन व्यय का भाग कम हुआ वस्त्रों के व्यय का भाग अधिक हुआ। आवासीय भवनों पर किए गए व्यय की स्थिति स्पष्ट नहीं है। 'अन्य' मदों के अन्तर्गत घर के फर्नीचर व साज सामान, वाहन, चिकित्सा-सुविधा, मनोरंजन आदि को जो भार दिया गया है उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जैसे जैसे प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुओं के क्रय में वृद्धि होती है उक्त वस्तुओं के भाग में वृद्धि होगी।

वस्त्र वाली मद में पाए जाने वाले अन्तर और भी अधिक उल्लेखनीय हैं। जर्मनी, नार्वे व स्वीडन में वस्त्रों की मद वाले भाग में पर्याप्त वृद्धि होती है किन्तु इंग्लैण्ड में वस्त्रों का अनुपात वर्तमान कीमतों पर स्थिर रहता है, स्थिर कीमतों पर यह अनुपात गिरता है।

कुल उपभोग में आवासीय व्यय के अनुपात में उक्त मदों की अपेक्षा अधिक अन्तर पाए गए हैं। किन्तु कुजनेट्स द्वारा प्रस्तुत अनुमानों के अनुसार नार्वे स्वीडन व इंग्लैण्ड में आवासीय भवनों के अनुपात में गिरावट रही। अमेरिका व कनाडा में इस मद की प्रवृत्ति स्थिरता की रही—विशेषकर द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व की अवधि में प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व जर्मनी में इस मद में वृद्धि की प्रवृत्ति रही। उक्त निष्कर्षों से दो तथ्य स्पष्ट होते हैं। प्रथम, प्राधुनिक प्राथमिक वृद्धि के दौरान, उपभोग वस्तुओं की क्रय के स्तर व ढाँचे का यदि विश्लेषण किया जाता है तो उपभोग प्रवृत्ति की सीमा का अधिक रहना निश्चित है, किन्तु दूसरी ओर उपभोग की मदों के उपवर्गों

की प्रवृत्तियों में स्वाभाविक अनुमानों के विपरीत अनेक असंगतियाँ सम्भव हैं। भोजन की किसी विशेष मद पर व्यय की प्रवृत्ति गिरने के स्थान पर बढ़ने की हो सकती है और इसी प्रकार वस्त्रों के किसी मद पर व्यय की प्रवृत्ति बढ़ने के स्थान पर घटने की हो सकती है।

उपभोग की उक्त समस्त मदों के निष्कर्षों के कारणों को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है—(1) आधुनिक अर्थव्यवस्था के बदलते हुए उत्पादन—ढाँचे में परिवर्तनों के कारण जीवन की अवस्थाएँ भिन्न हो गई हैं; जिन्होंने उपभोग की संरचना व स्तर में अनेक बड़े परिवर्तन ला दिए हैं, (2) प्रायोगिक परिवर्तन (Technological Changes)—विशेषकर उपभोग-वस्तुओं के क्षेत्र में तथा (3) क्रियाशील जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण व आय-वितरण के विभिन्न पहलुओं में परिवर्तन। इन तत्त्वों के कारण उपभोग प्रवृत्ति प्रभावित होती है तथा कुल उपभोग में अनेक उपग्रहों का अनुपात परिवर्तित होता रहता है। यद्यपि ये तत्त्व परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, किन्तु पृथक् रूप से इनका विश्लेषण श्रेष्ठ हो सकता है।

रहन-सहन की अवस्थाओं में परिवर्तनों के अन्तर्गत सबसे प्रमुख प्रवृत्ति शहरीकरण की है। श्रम-विभाजन व विशिष्टीकरण की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, परिवारों की क्रियाएँ बाजारोन्मुख (Shifts from non-market activities to market activities) होने लगती हैं।

यह क्रिया पूँजी-निर्माण के अनुपात में उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन को निश्चित रूप से बढ़ाती हो, यह प्रावश्यक नहीं है, क्योंकि अतीत में भी विशिष्टीकरण व श्रम-विभाजन की स्थिति से पूर्व पूँजीगत वस्तुओं का उत्पादन सापेक्ष रूप से इतना अधिक होता रहा है जितना कि उपभोग्य वस्तुओं का। किन्तु इस परिवर्तन का प्रभाव उपभोग्य वस्तुओं के क्रय के ढाँचे की प्रवृत्तियों पर अवश्य होता है।

द्वितीय, शहरीकरण से जीवन-साधन बढ़ जाती है। जीवन-साधन की इस वृद्धि का उपभोग्य वस्तुओं के क्रय पर प्रभाव पड़ता है। वचन व पूँजी-निर्माण भी प्रभावित होते हैं। इस स्थिति का विभिन्न उपभोग्य वस्तुओं पर भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ, शहरी आबादी की खरीदों का शहरों में उत्पादित उन वस्तुओं की अपेक्षा जिनका ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग होता है, कुपि-पदार्थों पर वही अधिक प्रभाव पड़ता है।

शहरी जीवन 'प्रदर्शनकारी प्रभाव' (Demonstration Effect) से प्रभावित होता है। प्रदर्शनकारी प्रभाव के कारण उपभोग का स्तर बढ़ जाता है। नए उपभोग्य पदार्थों के प्रति आकर्षण में वृद्धि होती है। इसके परिणामस्वरूप सापेक्ष रूप से वचन व पूँजी-निर्माण की अपेक्षा उपभोग-व्यय की प्रवृत्तियाँ अधिक स्पष्ट रूप से प्रभावित होती हैं।

उपभोग के ढाँचे को प्रभावित करने वाले अन्य परिवर्तन प्रायोगिक परिवर्तन (Technological Changes) हैं। ये परिवर्तन ही आधुनिक आर्थिक वृद्धि के

मूल स्रोत हैं। इन परिवर्तनों के कारण नई प्रकार की उपभोग्य वस्तुएँ अस्तित्व में आती हैं और पुरानी वस्तुओं में अनेक सुधार होते हैं। खाद्य पदार्थों के अन्तर्गत भी रेफ्रिजरेशन, केनिंग (Refrigeration and Canning) आदि नवीन प्रक्रियाओं के कारण भोजन की कुल माँग और विभिन्न वर्गों में इसके वितरण पर प्रभाव पड़ता है। मानव निर्मित वस्त्रों, विद्युत प्रसाधनों, रेडियो, टेलीविजन, मोटरगाड़ियाँ, हवाई यातायात आदि नई उपभोग्य वस्तुओं का बढ़ता हुआ उपभोग इसी प्रकार के परिवर्तनों के कारण होता है। यद्यपि तकनीकी परिवर्तनों के पूँजीगत वस्तुओं व उपभोग्य वस्तुओं पर सापेक्ष प्रभाव की माप कठिन है, तथापि प्रायः के विकसित देशों में अनेक प्रकार के नए से नए उपभोग पदार्थों के बढ़ते हुए उपभोग में प्रायोगिक परिवर्तनों का प्रभाव उपभोग की संरचना पर स्पष्टतः परिलक्षित होता है।

प्रायोगिक प्रगति के कारण उपभोक्ता के अधिमानों में भी क्रान्तिवारी परिवर्तन आते हैं। उदाहरणार्थ, पोषण तत्त्वों के सम्बन्ध में अधिगम ज्ञान-वृद्धि के कारण भोजन की वस्तुओं के प्रति उपभोक्ताओं की रुचि में अन्तर आ जाता है। यह निर्विवाद सत्य है कि प्रायोगिक प्रगति के परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय का स्तर काफी अधिक बढ़ा है तथा समाज के विभिन्न वर्गों में उपभोग्य वस्तुओं के वितरण की स्थिति में मौलिक भिन्नता आ गई है।

उपभोग प्रभावित करने वाले तीसरे प्रकार के परिवर्तन आय वितरण से सम्बन्धित होते हैं। जब क्रियाशील श्रमिक निजी व्यवसाय से हटकर सेवा क्षेत्र के प्रति आकर्षित होते हैं तब वेतनभोगी श्रमिकों का कुल श्रम शक्ति में अनुपात अधिक हो जाता है। परिणामस्वरूप, उपभोग्य वस्तुओं का वितरण व बचतें प्रभावित होती हैं। अप्रशिक्षित व्यवसायों से हटकर श्रमिकों का श्वेतपोशी व्यवसायों की ओर उन्मुख होना भी उपभोग के ढाँचे में बड़ा परिवर्तन लाता है। निजी व्यवसायियों की अपेक्षा श्वेतपोशी व्यवसायों में कार्यरत वेतनभोगी-वर्ग जीवन का न्यूनतम स्तर अधिक ऊँचा रहता है। उनकी इस प्रवृत्ति का उपभोग की संरचना पर विशेष प्रभाव होता है।

“आय वितरण सम्बन्धी परिवर्तनों के कारण व्यक्तियों का जीवन-स्तर इस प्रकार प्रभावित होता है कि उपभोग व्यय का उन वस्तुओं पर अनुपात बढ़ जाता है जिनकी आय लोच इकाई से कम होती है तथा जिन वस्तुओं की आय लोच इकाई से अधिक होती है, उन पर उपभोग व्यय का अनुपात कम हो जाता है। इसी कारण भोजन की मद का व्यय आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप कम हो जाता है क्योंकि विकसित देशों में इस मद की आय लोच सामान्यतः 5 तथा निर्धन देशों में 7 पाई जाती है। दूसरी ओर वस्त्रों के मद की आय लोच इकाई से अधिक प्रायः 17 के लगभग होती है। कुछ देशों में मोटर आदि ओटोमोबाइल्स की आय लोच 18 तथा शराब आदि मादक पदार्थों के लिए आय लोच 19.4 पाई जाती है। अतः आय में वृद्धि के कारण इकाई से अधिक आय लोच वाली वस्तुओं—वस्त्र, ओटोमोबाइल्स-

मादक पदार्थ आदि पर उपभोग व्यय का अनुपात आय में वृद्धि से अधिक हो जाता है।¹

उपभोग की संरचना में परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी उक्त तत्वों के अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी हैं जिनमें प्रमुख जीवन के मूल्यों से सम्बन्धित होते हैं। यदि आज का व्यक्ति वर्तमान में उपभोग को अधिक महत्व देता है, भौतिक आवश्यकताओं की तुष्टि के प्रति अधिक व्यय रहता है अपेक्षाकृत भविष्य के लिए बचत की राशि में वृद्धि करने के, तो ऐसी स्थिति में उपभोग का अनुपात, उपभोग्य आय में, बचत व पूँजी निर्माण की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ जाता है।

सामान्यतः उपभोग के लिए राष्ट्रीय आय का 85 से 100 प्रतिशत उपयोग किया जाता है। अतः पूँजी निर्माण में राष्ट्रीय आय का भाग प्रायः शून्य से 15 प्रतिशत तक रहता है। अल्पकाल में अथवा किसी व्यापार चक्रीय अवधि के कालान्तर में उपभोग व पूँजी निर्माण में राष्ट्रीय आय के अनुपात उक्त अनुपातों की तुलना में कुछ कम अथवा अधिक हो सकते हैं। किन्तु हम उपभोग के विश्लेषण को दीर्घकाल से सम्बन्धित रखते हुए यह मान्यता लेकर चलते हैं कि दीर्घकाल में राष्ट्रीय आय का उपभोग पर अनुपात 82 से 98 प्रतिशत की सीमाओं में रहता है। विकसित देशों में यह प्रतिशत यदि 82 तथा अर्द्ध-विकसित देशों में 98 रहता है तो अर्द्ध विकसित क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय जो विकसित क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय का लगभग 17वाँ भाग होती है उपभोग पर इस प्रकार व्यय होती है कि अर्द्ध-विकसित क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति उपभोग का स्तर विकसित क्षेत्रों की अपेक्षा 1/13 रहता है।²

व्यापार में संरचनात्मक परिवर्तन

(Structural Changes in the Composition of Trade)

आर्थिक विकास के कारण उपभोग व उत्पादन की संरचना में होने वाले परिवर्तन आय के स्तर पर निर्भर करते हैं। किन्तु विकास की अवस्था विदेशी व्यापार की संरचना के लिए सापेक्ष रूप से कम उत्तरदायी है। विदेशी व्यापार के अनुपात (Foreign Trade Proportions) मुख्यतः देश के आकार द्वारा निर्धारित होते हैं। देश के आकार व विदेशी व्यापार के अनुपातों में विपरीत सम्बन्ध होता है। छोटे देश के विदेशी व्यापार-अनुपात प्रायः बड़े तथा बड़े देश के व्यापार अनुपात छोटे होते हैं। इसके दो मुख्य कारण हैं—(i) प्राकृतिक साधनों की विविधता क्षेत्रफल के आकार पर निर्भर करती है। इसीलिए छोटे आकार वाले देश के आर्थिक ढाँचे में कम विविधता पाई जाती है, (ii) छोटे देश आधुनिक स्तर के औद्योगिक सद्यः के अनुकूलतम पैमाने (Optimum Scale of Plant) के संचालन की क्षमता नहीं रखते हैं। अतः विदेशी बाजारों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कुछ छोटे राष्ट्र कतिपय प्राकृतिक ससाधनों की दृष्टि से एक विशेष लाभ की स्थिति

1 Ibid, p 135

2 Simon Kuznets, Economic Growth and Structure, p 149

मे हो सकते हैं। अरब राष्ट्रों का उदाहरण लिया जा सकता है। तेल के क्षेत्र में इन्हे विशेष लाभ प्राप्त है। इस विशेष स्थिति के कारण विश्व के सभी बाजार इन छोटे राष्ट्रों को अपने व्यापार के लिए उलझते होते हैं। अतः विशेष लाभ की स्थिति वाला छोटा देश अपने साधनों को एक बड़े अनुपात में एवं अथवा कुछ चुने हुए क्षेत्रों में केन्द्रित कर सकता है। दूसरी ओर एक बड़ा राष्ट्र तुलनात्मक लाभ की दृष्टि से अपने साधनों को अनेक क्षेत्रों में लगाने की स्थिति में होता है।

व्यापार की सरचना से सम्बन्धित दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य माँग ढाँचा (Structure of Demand) अथवा उपभोग व पूँजी-निर्माण में वस्तुओं का प्रवाह है। दोनों प्रकार के देशों में माँग के ढाँचे में विविधता पाई जाती है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय का स्तर बढ़ा हुआ होने पर एक छोटे देश में भी उन वस्तुओं की माँग होगी, जिनका वहाँ उत्पादन नहीं होता है।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि घरेलू उत्पादन के केन्द्रित ढाँचे व अन्तिम माँग के विविधतापूर्ण ढाँचे में अन्तर की सीमा बड़े राष्ट्रों की अपेक्षा छोटे राष्ट्रों में अधिक होगी। घरेलू उत्पादन के केन्द्रित ढाँचे व अन्तिम माँग के विविधतापूर्ण ढाँचे की यह विषमता (Disparity) विदेशी व्यापार के कारण ही सम्भव हो सकी है।

एक देश की विविधतापूर्ण माँग की पूर्ति आयातों द्वारा की जा सकती है। छोटे राष्ट्रों के बाजारों में बड़े राष्ट्रों की अपेक्षा विदेशी प्रतियोगिता अधिक होती है। प्रत्येक देश के विदेशी व्यापार-अनुपात की गणना वस्तुओं के निर्यात व आयातों के योग को राष्ट्रीय आय तथा आयातों के योग से विभाजित करके की गई है।

यह अनुपात चरम स्थितियों में शून्य व इकाई हो सकता है। यह अनुपात शून्य तब होता है जब किसी देश में आयात निर्यात शून्य होते हैं तथा यह अनुपात इकाई तब होता है जब देश में घरेलू उत्पादन बिल्कुल नहीं होता है तथा सम्पूर्ण माँग की पूर्ति केवल आयातों से की जाती है व आयातों का भुगतान पुनः निर्यातों (Re exports) से किया जाता है। यदि आयात घरेलू उत्पादन के बराबर होते हैं और निर्यात व आयात परस्पर समान होते हैं तब भी यह अनुपात 1 होता है। आयातों के बराबर निर्यातों के होने पर, 2 अनुपात यह प्रदर्शित करता है कि आयात राष्ट्रीय उत्पादन के दसवें भाग से कुछ अधिक होते हैं तथा 4 अनुपात का अर्थ यह होता है कि राष्ट्रीय उत्पादन में आयातों का भाग 25 है।

समान आकार वाले विभिन्न देशों को यदि विभिन्न समूहों में रखा जाए तब भी देश के आकार व विदेशी व्यापार-अनुपात में विपरीत सम्बन्ध मिलेगा। प्रति व्यक्ति आय की अपेक्षा प्रस्तुत स्थिति में देश का आकार विदेशी व्यापार के अनुपात को प्रभावित करने वाला अधिक महत्वपूर्ण तत्त्व है। जनसंख्या के आकार की उपेक्षा करते हुए प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जब देशों को विभिन्न समूहों में रखा जाता है, तब आय के पैमाने पर नीचे की ओर आने पर विदेशी व्यापार के अनुपात में कोई क्रमिक परिवर्तन नहीं पाया जाता है।

Relation Between Foreign Commodity Trade, Size of Country and Level of Income per Capita
(1938-39 and 1950-54)

Groups of Countries		Number of Countries	1938-39 Average Population (Millions) or Average Income per Capita (\$)	Average Foreign Trade Ratio	Number of Countries	1950-54 Average Population (Millions) or Average Income per Capita (\$)	Average Foreign Trade Ratio
		1	2	3	4	5	6
A. Countries Arrayed in Descending Order of Population Size							
1.	I	10	135.4	0.17	10	103.9	0.21
2.	II	10	16.2	0.24	10	22.0	0.24
3.	III	10	7.3	0.31	10	10.4	0.41
4.	IV	10	3.7	0.38	10	5.3	0.41
5.	V	12	1.5	0.38	10	2.7	0.41
6.	VI				7	0.8	0.41
B. Countries Arrayed in Descending Order of Income per Capita							
7.	I	10	429	0.29	10	1,021	0.35
8.	II	10	214	0.32	10	514	0.41
9.	III	10	106	0.19	10	291	0.40
10.	IV	10	66	0.36	10	200	0.24
11.	V	12	40	0.24	10	115	0.38
12.	VI				7	67	0.26

Source : Simon Kuznets : Six Lectures on Economic Growth, p. 96

छोटे देशों के विदेशी व्यापार की दो महत्वपूर्ण विशेषताएँ होती हैं। प्रथम, इन देशों के निर्यात एक अथवा दो वस्तुओं से केन्द्रित रहते हैं। तेल, चाफ़ी, टिन आदि कुछ इसी प्रकार की मर्चें हैं जिनकी निर्यात माँग विश्व में बहुत अधिक पाई जाती है। निर्यातों का यह केन्द्रीकरण बड़े अविकसित देशों में पाया जाता है जिनमें निम्न-स्तरीय उत्पादन तकनीकी प्रयोग में ली जाती है। निम्न-स्तरीय तकनीकी के कारण ऐसे देशों में कुछ ही वस्तुओं में तुलनात्मक लाभ की स्थिति पाई जाती है। द्वितीय, छोटे देशों के आयात व निर्यातों का सीधा सम्बन्ध किसी एक बड़े राष्ट्र से होता है, किन्तु बड़े आकार वाले देशों का आयात-निर्यात व्यापार अनेक देशों के साथ होता है।

विदेशी व्यापार बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। इन देशों में घरेलू उत्पादन कुछ ही क्षेत्रों में केन्द्रित रहता है। अतः घरेलू उत्पादन का क्षेत्र सीमित होने के कारण अन्तिम माँग के एक बड़े भाग की पूर्ति विदेशी व्यापार द्वारा ही संभव है किन्तु छोटे देशों के व्यापार की भी सीमाएँ होती हैं। इन सभी सीमाओं को विदेशी व्यापार द्वारा दूर कर पाना संभव नहीं है। सरकारी हस्तक्षेप व अन्तर्राष्ट्रीय संधियों के कारण विदेशी व्यापार में अवरोध उपस्थित हो जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ आवश्यक वस्तुओं के निर्यात का अर्थ बहुत बड़ी लागत चुकाना होता है।

जनसंख्या के आकार में कमी के साथ-साथ एक विशेष बिन्दु तक ही विदेशी व्यापार का औसत अनुपात बढ़ता है। उन बिन्दु के पश्चात् अनुपात का बढ़ना रुक जाता है। उदाहरणार्थ, उक्त सारणी में 1938-1939 के वर्ष में समूह IV में यह अनुपात 38 तक पहुँचना है आगे वाले समूह में जनसंख्या में 1.5 मिलियन की कमी होने पर भी यह अनुपात 38 ही बना रहता है। 1950-54 में अनुपात की उच्चतम सीमा सम्बन्धी तथ्य की अधिक पुष्टि होती है। समूह III में 10.5 मिलियन जनसंख्या की स्थिति में भी यह अनुपात 41 का अधिकतम स्तर प्राप्त कर लेता है और इस स्तर के बाद एक मिलियन से कम वाले समूह में भी इस अनुपात में कोई वृद्धि नहीं होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समय विशेष में वर्तमान राजनीतिक सन्स्थागत व आर्थिक परिस्थितियों में कुल उत्पादन के उस भाग की जो व्यापार के लिए उपलब्ध होता है एक उच्चतम सीमा होती है।

विदेशी व्यापार पर बड़े देशों की तुलना में छोटे देशों की निर्भरता अधिक होती है। “विदेशी व्यापार का प्रति व्यक्ति आय के स्तर के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। अतः बड़े देश अपेक्षाकृत वही छोटे विदेशी व्यापार के अनुपातों से ‘आर्थिक वृद्धि’ करने की स्थिति में होते हैं। आर्थिक वृद्धि की क्रिया व राष्ट्रीय उत्पादन की एक महत्वपूर्व दिशा (विदेशी व्यापार) में छोटे व बड़े देशों की स्थिति में अन्तर पाया जाता है अर्थात् विभिन्न घरेलू व विदेशी क्षेत्रों के योगदानों के अनुपातों की दृष्टि से छोटे व बड़े देशों की स्थिति भिन्न होती है।”¹

विदेशी व्यापार के क्षेत्र में अविकसित देशों की राष्ट्रीय आय व निर्यातों का अनुपात प्रायः 10% होता है जबकि समृद्ध अथवा विकसित देशों के लिए प्रायः 20 से 25% पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अविकसित देश मुख्यतः कच्चे माल के निर्यातक होते हैं, जबकि विकसित देश निर्मित वस्तुओं के निर्यातक होते हैं।

GATT के अनुसार अल्प-विकसित देश निर्मित वस्तुओं के कुल उपभोग का केवल एक-तिहाई भाग का ही आयात करते हैं और यह अनुपात उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है।¹

आर्थिक पिछड़ेपन की स्थिति (Under development) विदेशी व्यापार के अनुपातों पर दो विपरीत तरीकों से प्रभाव डालती है। प्रथम, यह स्थिति कुल उत्पादन के आकार को सीमित करती है, परिणामस्वरूप विदेशी व्यापार के अनुपात में वृद्धि होती है तथा आर्थिक हीनता की स्थिति निम्नस्तरीय तकनीकों को प्रकट करती है।

विनियोग के स्वरूप में परिवर्तन

(Changes in the Composition of Investment)

अविकसित देशों की मुख्य समस्या उत्पादकता में कमी होना है और यही इनकी दरिद्रता के लिए उत्तरदायी है। उत्पादकता में वृद्धि पूँजी-संचय की वृद्धि पर तथा पूँजी-संचय की वृद्धि विनियोग की मात्रा पर निर्भर करती है अर्थात् आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के प्रारम्भ तथा इनकी गति को तीव्र करने के लिए अधिक से अधिक विनियोगों की आवश्यकता है। किन्तु विनियोग नीति बिना प्रकार की होनी चाहिए, इस सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण हैं—(i) क्रमिक विकास का दृष्टिकोण (Gradual Approach) तथा (ii) विनियोग की विशाल योजना का दृष्टिकोण (Big Push Approach)। प्रथम दृष्टिकोण के अनुसार विनियोगों का प्रयोग प्रारम्भ में कृषि विकास, सामाजिक ऊपरी पूँजी निर्माण (Social Overhead Capital) तथा सघु उद्योगों के विकास के लिए होना चाहिए। फिर जैसे जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, शर्न-शर्न क्रमिक रूप से भी उद्योगों में विनियोग किया जाना चाहिए। लेटिन अमेरिका, अफ्रीका के पूर्वी भाग तथा दक्षिणी एशिया के कुछ भागों में यही नीति अपनाई गई है।

दूसरा दृष्टिकोण विनियोग की विशाल योजना का समर्थन करता है। यह विचार इस मान्यता पर आधारित है कि जब तक सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों में विशाल पैमाने पर परिवर्तन नहीं होते तब तक विकास प्रक्रिया स्वतः संचालित व संचर्न गति प्राप्त नहीं कर सकती। इस मत के समर्थकों में लिबिन्स्टोन (Leibenstein) व नैलसन (Nelson) उल्लेखनीय हैं। लिबिन्स्टोन का 'आवश्यक शून्यतम प्रयास का विचार' (Critical Minimum Effort Thesis) तथा नैलसन का 'निम्नस्तरीय समतुलन जाल' (The low level Equilibrium Trap) का सिद्धान्त इस दृष्टिकोण की श्रेणी में आते हैं। इन सिद्धान्तों के अनुसार

भारी विनियोगों की आवश्यकता होती है ताकि उत्पादन में वृद्धि की दर जनसंख्या की विकास दर से अधिक हो सके।

विनियोग बचत पर निर्भर करते हैं, किन्तु अर्द्ध-विकसित देशों में बचत-दर बहुत कम है। इन देशों में बचत-दर जहाँ 4 व 5 प्रतिशत के बीच है, वहाँ विकसित देशों में यह दर 15 प्रतिशत व इससे भी अधिक है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए बचत की निरन्तर बढ़ती हुई दर आवश्यक होती है और विनियोग के स्तर को 5 प्रतिशत बढ़ाकर राष्ट्रीय आय के 15 से 18 प्रतिशत तक करना आवश्यक हो जाता है।

“1870-1913 की अवधि में ब्रिटेन के जो तथ्य उपलब्ध हैं, वे यह प्रमाणित करते हैं कि इस अवधि में वहाँ विनियोग की औसत दर 10 प्रतिशत थी तथा समृद्ध वर्षों में यह 15 प्रतिशत भी रही। अमेरिका में 1867-1913 की अवधि में शुद्ध विनियोग दर 13 से 16 प्रतिशत रही, जबकि कुल विनियोग 21 से 24 प्रतिशत के मध्य रहा। जापान में 1900-1901 में 12 प्रतिशत तथा पाँचे की दशान्दियों में इसके 17 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है।¹ इसके विपरीत भारत में पूँजी-निर्माण की दर बहुत कम है, परिणामस्वरूप विनियोग-दर यथेष्ट विकास दर प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त है। अर्द्ध-विकसित देशों में पूँजी-निर्माण की निम्न दर निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत की गई है—

कुल राष्ट्रीय उत्पादन में पूँजी निर्माण का अनुपात²

विकसित देश	वर्ष	कुल पूँजी-निर्माण	अर्द्ध विकसित देश	वर्ष	कुल पूँजी निर्माण
नार्वे	1959	29%	बर्मा	1960	17%
ऑस्ट्रिया	1960	24%	पुर्तगाल	1959	17%
नीदरलैंड	1960	24%	श्रीलंका	1960	13%
कनाडा	1960	23%	आयरलैंड	1959	13%
स्विट्जरलैंड	1959	23%	चिली	1959	11%
स्वीडन	1960	22%	फिलीपाइन्स	1959	8%
ब्रिटेन	1960	16%	भारत	1959	8%
अमेरिका	1960	16%			

इसके अतिरिक्त साइमन कुजनेट्स ने भी विकसित व अविकसित देशों में पूँजी-निर्माण की औसत दर के अन्तर को अप्रलिखित प्रकार प्रस्तुत किया है।

1 Planning Commission-The First Five Year Plan, p 13

2 U. N Statistical Year Book, 1961

प्रति व्यक्ति आय स्तर व पूँजी निर्माण की दर¹

देशों के समूह	कुल उत्पादन में कुल पूँजी निर्माण की दर
1	21.3%
2	23.3%
3	17.2%
4	15.7%
5	18.2%
6	13.3%
7	17.1%

प्रथम व द्वितीय समूह की औसत पूँजी निर्माण दर 22.2% तथा तृतीय, चतुर्थ व पंचम समूहों की औसत दर 16.3% तथा 5, 6 और 7 में इसका औसत 15.2% प्रतिशत है। इस प्रकार घनी देशों में निम्न आय वाले देशों की अपेक्षा पूँजी-निर्माण की दर काफी कम है। अतः स्पष्ट है कि अधिक पूँजी निर्माण वाले देशों में प्रति व्यक्ति पूँजी का उपभोग दर कम आय वाले देशों की अपेक्षा बहुत कम है। इस विषयता को निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत किया गया है—

कुछ उद्योगों में प्रतिव्यक्ति नियोजित पूँजी²

उद्योग	अमेरिका	मैक्सिको	भारत
श्रेष्ठ और बेकरी उद्योग	5.0	1.7	3.5
वस्त्र उद्योग	8.7	2.1	1.8
इस्पात उद्योग	32.1	10.8	5.7
चीनी उद्योग	26.8	8.2	2.6
कागज, लुग्दी व कागज के सामान से सम्बन्धित उद्योग	10.2	8.9	6.6

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया के अन्तर्गत सर्वाधिक महत्व विनियोगों का दिया जाता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री केंज के अनुसार रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण माँग (Effective Demand) पर निर्भर करता है। प्रभावपूर्ण माँग के दो अनुभाग होते हैं—(i) उपभोग माँग व (ii) विनियोग माँग। अल्पकाल में उपभोग के प्रति अधिमानों में परिवर्तन लाना कठिन होता है। विनियोगों का वर्गीकरण निजी विनियोग, सार्वजनिक विनियोग व वित्तीय विनियोगों के रूप में किया जा सकता है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों व परिवारों द्वारा किए गए ऐसे व्यय जो पूँजी संचय में वृद्धि करते हैं, निजी विनियोग कहलाते हैं। राजकीय प्रतिष्ठानों द्वारा पूँजी निर्माण के लिए व्यय सार्वजनिक विनियोग की श्रेणी में आता है। एक व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठान जब अन्य व्यक्ति या प्रतिष्ठान से केवल परिसम्पत्ति

1. Simon Kuznets Six Lectures on Economic Growth pp 72 & 73

2. Tinbergen The Design of Development 1958, p 73

का क्रय विक्रय करना है, जिससे किसी नई परिसम्पत्ति का निर्माण नहीं होता है, वित्तीय विनियोग कहलाता है।

विकासोन्मुख देशों में जहाँ विकास दर को अधिक से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य होता है, विनियोग का स्वरूप निर्धारित करने से पूर्व विनियोग नीति के लक्ष्य निश्चित करना अनिवार्य है। इन देशों में विनियोग के लक्ष्य रोजगार को अधिकतम करना, निर्यातों को अधिकतम करना, सम्बन्धित विकास, आय व पूँजी का न्यायोचित वितरण आदि हो सकते हैं। यदि अल्पकाल में अधिकतम उत्पादन का लक्ष्य रखा जाता है तो कृषि तथा उपभोग वस्तुओं के उद्योगों में विनियोग किया जाता है, क्योंकि इन उद्योगों की परिपक्वता अवधि (Gestation Period) कम होती है। यदि उत्पादन में दीर्घकालीन एवं सतत् वृद्धि आवश्यक समझी जाती है तो पूँजीगत वस्तुओं के उद्योगों (Capital Goods Industries) में विनियोग वांछनीय होता है। अर्थात् विनियोगों की संरचना का निर्धारण आर्थिक विकास के लक्ष्यों पर निर्भर करता है। अतः सभी अविकसित देशों के लिए समान विनियोग नीति संभव नहीं है।

सामान्यतः आर्थिक विकास के दौरान ऐसे उद्योगों में विनियोगों को प्राथमिकता दी जाती है, जिनमें (i) वर्तमान उत्पादन व विनियोग का अनुपात (Ratio of Current Output to Investment), (ii) धर्म व विनियोग का अनुपात (Ratio of Labour to Investment) तथा (iii) निर्यात वस्तुओं व विनियोग का अनुपात (Ratio of Export Goods to Investment) अधिकतम होना संभव हो।

पूँजी के उचित वितरण तथा आय की विषमताओं को दूर करने की दृष्टि से कृषि व लघु उद्योगों में विनियोग आवश्यक होता है। विकासोन्मुख देशों में आय की विषमताएँ बहुत अधिक पाई जाती हैं, अतः विकास के दौरान प्रायः कृषि व लघु उद्योगों में विनियोग की मात्रा बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है, किन्तु दीर्घकालिक व स्थायी विकास की दृष्टि से भारी उद्योगों में विनियोग भी आवश्यक होता है। अतः आर्थिक विकास के दौरान इन दोनों लक्ष्यों में सन्तुलन (Balance) रखा जाता है।

आर्थिक विकास की दीर्घकालिक अवधि में सरकारी प्रतिष्ठानों में विनियोग का अनुपात बढ़ता जाता है तथा निजी विनियोग के अनुपात में कमी की प्रवृत्ति प्रारम्भ हो जाती है। अल्प-विकसित देशों में विकास के लिए अर्द्ध-संरचना (Infra structure) जैसे रेलों, सड़कों, नहरों, शक्ति परियोजनाओं तथा अन्य प्रकार की आर्थिक और सामाजिक ऊपरी पूँजी (Economic and Social Overheads) आवश्यक होती है। निजी विनियोगों द्वारा इन कार्यों के लिए पूँजी-समर्थन संभव नहीं होता है। यद्यपि निजी विनियोगों की तुलना में सार्वजनिक विनियोग दर प्रायः कम होती है, तथापि सार्वजनिक क्षेत्र का आर्थिक विकास के साथ-साथ अधिक से अधिक विस्तार किया जाता है, क्योंकि सार्वजनिक विनियोगों का मुख्य उद्देश्य प्रतिफल की दर की अधिकता न होकर, सामाजिक उत्पादकता (Social

Productivity) को अधिक से अधिक बढ़ाना एवं निजी विनियोगों के आकर्षण के लिए बाह्य बचत (External Economies) को उत्पन्न करना होता है।

इटली में राजकीय प्रतिष्ठानों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। अधिकांश उद्योग सरकारी क्षेत्र में आते हैं। इनमें से अनेक उद्योगों में लाभ-दर काफी ऊँची है। किन्तु बी. लुत्ज के अनुसार, "रोजगार के स्तर को बनाए रखने के लिए अनेक हानिकारक उद्योगों में भी विनियोग किया गया है।"¹ सार्वजनिक विनियोग व निजी विनियोग का अनुपात लगभग 60 : 40 है।

विनियोग के क्षेत्र में सरकार की दूसरी भूमिका अनुदान, सहायता आदि देने की होती है। सरकारी अनुदान व सहायता के माध्यम से नए स्थानों पर उद्योग विकसित करने के प्रयत्न होते हैं। इंग्लैण्ड व फ्रांस न लन्दन व पैरिस से कारखानों की अन्यत्र स्थापित करने में सरकारी अनुदानों का प्रयोग किया है। नार्वे ने जनसंख्या का उत्तर से स्थानान्तरण रोकने का प्रयत्न किया है।

सरकार निजी क्षेत्र के विनियोगों पर भी अपना नियन्त्रण रखती है। अब प्रश्न उठता है कि विनियोग नियोजन (Investment Planning) में सरकार की बढ़ती हुई भूमिका आवश्यक है अथवा अहितकर। सभी देशों के लिए इस प्रश्न का एक उत्तर संभव नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर निजी व्यवसाय के प्रतिस्पर्द्धा, सरकारी अधिकारी तथा व्यापारियों की सापेक्ष कुशलता व योग्यता पर निर्भर करता है। फ्रांस की नियोजन पद्धति में सरकार व निजी व्यवसाय की दोहरे सहयोग से विनियोग निर्णयों में पर्याप्त सुधार हुए हैं। परिणामतः फ्रांस विनियोगों से विकास की बढ़ती हुई दर प्राप्त करने में समर्थ रहा है।

पूँजी-प्रदा अनुपात (Capital Out-put Ratio)

किसी भी देश के लिए पूँजी की आवश्यकता के अनुमान पूँजी-प्रदा अनुपात (Capital Out put Ratio) की धारणा पर निर्भर करते हैं। अर्थ-व्यवस्था के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पूँजी-प्रदा अनुपात भिन्न होता है। अर्द्ध-विकसित देशों के कृषि क्षेत्र में यह अनुपात कम होता है तथा औद्योगिक क्षेत्र में अधिक रहता है। सार्वजनिक कल्याण के उद्योगों (Public Utilities) में यह अनुपात और भी अधिक होता है। अतः विनियोग की संरचना में पूँजी-प्रदा अनुपात की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

तकनीकी (Technology)

विनियोगों पर तकनीकी स्तर का भी प्रभाव पड़ता है। अर्द्ध-विकसित देशों में तकनीकी स्तर निम्न होने के कारण पूँजी की उत्पादकता कम होती है और इसलिए पूँजी-प्रदा अनुपात अधिक रहता है। किन्तु जब कोई नई तकनीकी किसी अर्द्ध-विकसित देश में प्रयोग में ली जाती है तो आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होते हैं। यदि अधिक पिछड़े हुए देशों में पूँजी का विनियोजन शिक्षा, प्रशिक्षण आदि पर

किया जाता है तो विकसित देशों की अपेक्षा कहीं अधिक तेजी से विकास की बढ़ती हुई दरों को प्राप्त किया जा सकता है।¹

संक्षेप में, विनियोग की संरचना वृद्ध-दर, आर्थिक लक्ष्य, पूँजी-प्रदा अनुपात, तकनीकी आदि के स्तर पर निर्भर करती है। सभी अर्द्ध-विकसित देशों के लिए कोई एक विनियोग नीति उपयुक्त नहीं हो सकती।

रोजगार के ढाँचे में परिवर्तन (Structural Changes in Employment)

आर्थिक विकास की प्रक्रिया के दौरान रोजगार की दिशा, स्तर व संरचना के परिवर्तनों को मुख्यतः निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

- (1) कार्यारम्भ की आयु व कार्य-भुक्ति की आयु में परिवर्तन
- (2) क्रियाशील श्रम-शक्ति का व्यावसायिक वितरण
- (3) कार्यशील श्रम शक्ति में स्त्री व पुरुष का अनुपात
- (4) कुशल व अकुशल श्रम के अनुपात
- (5) निजी व्यवसायवर्त्ता व कर्मचारी वर्ग का अनुपात।

सामान्यतः, आर्थिक विकास के कारण विकसित देशों में कार्यारम्भ करने की आयु में जहाँ एक ओर उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वहाँ साथ ही कार्य-भुक्ति की आयु में कमी की गई है।

साइमन कुजनेट्स के अध्ययन के अनुसार प्रारम्भ में कर्मचारियों का कुल राष्ट्रीय आय में जो अनुपात 40 प्रतिशत था, वह बढ़कर वर्तमान वर्षों में 60 और 71 प्रतिशत हो गया है। इस प्रवृत्ति का मुख्य कारण श्रम-शक्ति में कर्मचारी वर्ग की संख्या में वृद्धि रहा है। साहसी व निजी उद्यमकर्त्ताओं का प्रतिशत 35 से घटकर केवल 20 रह गया। दूसरी ओर कर्मचारियों का प्रतिशत 65 से बढ़कर 80 हो गया। इस प्रवृत्ति के लिए औद्योगिक ढाँचे के परिवर्तन उत्तरदायी हैं।

आज भी अर्द्ध-विकसित देशों के कृषि क्षेत्र में लगी कुल श्रम-शक्ति में उद्यमियों का अनुपात, उद्योग व सेवा क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत अधिक है। यह अनुपात क्रमशः 66, 31 और 35 प्रतिशत है जबकि विकसित देशों में यह अनुपात क्रमशः 61, 11 व 17 प्रतिशत पाया जाता है। आर्थिक विकास के कारण कृषि में श्रम का अनुपात कम होने लगता है, परिणामस्वरूप, साहसियों व निजी उद्यमकर्त्ताओं का कुल श्रम शक्ति में अनुपात भी बहुत कम रह जाता है। उद्योग व सेवा क्षेत्र के आकार में वृद्धि तथा इनके असंगठित से संगठित स्वरूप में परिवर्तन के कारण भी साहसियों व निजी व्यावसायियों की कुल श्रम-शक्ति का अनुपात गिर जाता है।

छोटे किसान, व्यवसायी, आदि का अपने निजी व्यवसायों से हट कर कर्मचारी वर्ग की ओर आकर्षित होना, देश के आर्थिक-जीवन व योजना के आधार में एक मूलभूत परिवर्तन उत्पन्न करता है। व्यावसायिक स्तर में इस अन्तर का कई

दिशाओं में प्रभाव होता है—परिवार व बच्चों के प्रति सुख में परिवर्तन, उपभोग के स्तर में भिन्नता, बचत करने की अपेक्षा शिक्षा व प्रशिक्षण में विनियोजन की प्रवृत्ति आदि।

कुजेन्ट्स ने कर्मचारियों के व्यावसायिक ढाँचे में परिवर्तन निम्नलिखित सारणी द्वारा स्पष्ट किए हैं—

कर्मचारियों का व्यावसायिक ढाँचा (1900-1960)

	व्यावसायिक समूहों का अनुपात (%)		स्त्रियों का व्यावसायिक अनुपात (%)	
	1900	1960	1900	1960
1. कुल श्रम शक्ति में कर्मचारियों का अनुपात (%)	74.9	93.0	22.7	34.3
व्यावसायिक समूह				
2. व्यवसायी तकनीशियन	5.7	12.2	35.2	38.1
3. प्रबन्धक व अधिकारी	8	5.8	17.4	36.4
4. दफ्तरी बाबू	4.0	16.0	24.2	67.6
5. द्विकी अभिवृत्ति	6.0	8.0	17.4	36.4
6. श्वेतपोशी कर्मचारी	16.6	42.0	24.5	45.6
7. फ़ैक्टरी, फ़ोरमैन आदि	14.1	15.4	2.5	2.9
8. शारीरिक एव ऐस ही अन्य लोग	17.1	15.4	34.0	28.1
9. खेत व खानों के अतिरिक्त श्रमिक	16.6	5.9	3.8	3.5
10. खेत पर काम करने वाले श्रमिक तथा फ़ोरमैन	23.6	2.6	13.6	17.3
11. Manual Workers	71.4	45.4	14.0	15.7
12. मृत्यु वर्ग	4.8	9.6	34.3	52.4
13. घरेलू श्रमिक	7.3	3.0	96.6	96.4

उपयुक्त सारणी से स्पष्ट है कि—

- (1) शारीरिक श्रम का अनुपात 1900 की तुलना में 1960 में बहुत अधिक गिरा है। श्वेतपोशी बाबूओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है परन्तु अकुशल श्रम के स्थान पर कुशल श्रम का अनुपात अधिक हुआ है।
- (2) ये परिवर्तन सेवा क्षेत्र में श्रम-शक्ति के अनुपात में वृद्धि तथा कृषि क्षेत्र में गिरावट को प्रदर्शित करते हैं।
- (3) व्यावसायिक (Professionals), तकनीकी कर्मचारी, प्रबन्धक, अधिकारी बाबू आदि की माँग में वृद्धि हुई है।
- (4) अधिक कुशलता की माँग में वृद्धि हुई है तथा अकुशल श्रम के अवसर कम हुए हैं।

सामान्यतः लोगो का भुकाव मजदूरी के कार्यों से हटकर वेतनभोगी व्यवसायो की ओर रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में इन दोनों प्रकार के श्रमिकों के अनुपात में भारी अन्तर पाया जाता है—कृषि में वेतनभोगी कर्मचारियों का अनुपात 4 से 13 प्रतिशत, उद्योग में 11 से 18 प्रतिशत तथा सर्वाधिक सेवा क्षेत्र में 42 से 83 प्रतिशत रहा है।

60 वर्ष की अध्ययन अवधि में स्त्रियों का अनुपात 23 से 34% तक बढ़ा है। इसका कारण, आर्थिक विकास के कारण स्त्रियोचित कार्यों की सुविधाओं में वृद्धि होना है।

अधिक जनसंख्या वाले देशों में आर्थिक विकास से पूर्व की स्थिति में गुप्त बेरोजगारी (Disguised Unemployment) की स्थिति पाई जाती है। तकनीकी व उत्पादन साधनों के दिए हुए होने पर, कृषि में श्रम की सीमान्त उत्पादकता का शून्य पाया जाना गुप्त बेरोजगारी की स्थिति को प्रकट करता है। बेरोजगारी की यह स्थिति प्रायः उस स्थिति में पाई जाती है, जब रोजगार के विकल्प कम होने के कारण अधिकांश श्रम कृषि में लगा हुआ होता है। आर्थिक विकास के कारण उद्योग व सेवा क्षेत्रों का विस्तार होता है। वैकल्पिक रोजगारों के अवसरों में वृद्धि होती है परिणामतः गुप्त बेरोजगारी विलुप्त होने लगती है। विकसित देशों में गुप्त बेरोजगारी नहीं पाई जाती।



आर्थिक विकास के प्रमुख तत्त्व एवं डेनिसन का अध्ययन

(Major Growth Factors, Denison's Estimate of the Contribution of Different Factors to Growth Rate)

आर्थिक विकास के प्रमुख तत्त्व (Major Growth Factors)

विभिन्न संशोधकोंने आर्थिक विकास के आधार के रूप में विभिन्न तत्वों का उल्लेख किया है। इस प्रकार के तत्व जो विकास का प्रारम्भ करते हैं 'प्राथमिक तत्व' या 'प्रधान चालक' (Prime-mover) या 'उपक्रमक' (Initiator) कहलाते हैं। जब विकास की गति प्रारम्भ हो जाती है तो कई अन्य ऐसे तत्व जो इस विकास को तीव्रता प्रदान करते हैं, 'गोण तत्व' या 'प्रभावक' या 'पूरक तत्व' कहलाते हैं। उक्त तत्वों का वर्गीकरण आर्थिक और अर्थनिरपेक्ष तत्वों (Economic and Non-economic Factors) के रूप में भी किया जाता है। विभिन्न राष्ट्रों के आर्थिक विकास में भिन्न-भिन्न तत्व महत्वपूर्ण रहे हैं। आर्थिक विकास के मुख्य कारक या घटक निम्नलिखित हैं—

- 1 प्राकृतिक साधन (Natural Resources)
- 2 मानवीय साधन (Human Resources)
- 3 पूँजी (Capital)
- 4 तकनीकी ज्ञान (Technical Knowledge)
- 5 साहसी एवं नव प्रवृत्तन (Entrepreneur and Innovation)
- 6 संगठन (Organisation)
- 7 राज्य की नीति (State Policy)
- 8 संस्थाएँ (Institutions)
- 9 अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ (International Circumstances)

1 प्राकृतिक साधन (Natural Resources)—प्राकृतिक साधनों का आशय उन भौतिक साधनों से है जो प्रकृतिप्रदत्त हैं। एक देश में उपलब्ध भूमि, पानी, खनिज सम्पदा, वन, घर्षा, जलवायु आदि उस देश के प्राकृतिक साधन कहलाते हैं। किसी भी

देश के आर्थिक विकास में इन प्राकृतिक साधनों का अस्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। किसी देश के प्राकृतिक साधन जितने अधिक होंगे वहाँ उतना ही आर्थिक विकास अधिक होगा। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन की माना अत्यधिक सीमा तक इसकी मिट्टी और उसका स्थानीय वन संपदा—कोयला, लोहा, खनिज तेल एवं अन्य कई पदार्थों पर निर्भर करता है। जैसाकि रिचार्ड टी गिल ने लिखा है, 'जनसंख्या एवं धर्म की पूर्ति के समान प्राकृतिक साधन भी एक देश के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। उर्वर भूमि और जन के अभाव के कारण कृषि का विकास नहीं हो पाएगा। लोहा, कोयला आदि खनिज संपदा के अभाव में औद्योगीकरण द्रुतगति नहीं ले पाएगा। प्रतिकूल जलवायु आदि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आर्थिक क्रियाओं के विस्तार में बाधा पहुँचेगी। अतः प्राकृतिक साधनों का आर्थिक विकास को सीमित करने या प्रोत्साहित करने में निर्णायक महत्त्व होता है। आर्थिक विकास के उच्च स्तर पर पहुँचे हुए अमेरिका, कनाडा आदि देश प्राकृतिक साधनों में भी सम्पन्न हैं।'

आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक साधनों की बहुलता ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उनका सुविचारित उपयोग देश की आर्थिक प्रगति के लिए होना चाहिए। इन साधनों का विदोहन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे देश को अधिकतम लाभ प्राप्त हो और देश की आर्थिक स्थिरता में सहायता मिल सके। इनका देश की आवश्यकताओं के लिए इस प्रकार योजनाबद्ध उपयोग होना चाहिए जिनसे इनका न्यूनतम अपव्यय हो और भविष्य के लिए भी अधिक समय तक उपयोग में आते रहे। तभी दीर्घकालीन आर्थिक विकास में महायत्ना मिल पाएंगी। यदि इनके वर्तमान को ध्यान में रखकर ही उपयोग किया गया तो यद्यपि वर्तमान काल में आर्थिक प्रगति कुछ अधिक सम्भव है किन्तु उनके शीघ्र समाप्त हो जाने या कम प्रभावपूर्ण रह जाने के कारण भावी आर्थिक विकास कुठित हो जाएगा। आर्थिक विकास के लिए न केवल वर्तमान साधनों अपितु सम्भावित (Potential) साधनों का भी महत्त्व है। अतः नए प्राकृतिक साधनों की खोज तथा वर्तमान प्राकृतिक साधनों के नए नए उपयोग भी खोजे जाने चाहिए। अमेरिका, कनाडा आदि विकसित देशों में उनका विकास प्रारम्भ होने के पूर्व भी सम्पन्न प्राकृतिक साधन थे, किन्तु उनका उचित विकास और विदोहन (Exploitation) नहीं किया गया था। इस प्रकार किसी देश के प्राकृतिक साधनों की अधिकता और उनका उचित उपयोग आर्थिक विकास में बहुत सहायक होते हैं। प्राकृतिक साधनों की अपर्याप्तता में भी अन्य तत्वों द्वारा द्रुत आर्थिक विकास किया जा सकता है। स्विट्जरलैंड और जापान प्राकृतिक साधनों में अपेक्षाकृत कम सम्पन्न हैं, किन्तु फिर भी विकास अन्य तत्वों के द्वारा इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को अत्यधिक विकसित किया है।

2. मानवीय साधन (Human Resources)—मानवीय साधन का आशय उस देश में निवास करने वाली जनसंख्या से है। यद्यपि केवल कार्यशील जनसंख्या (Working Population) ही, जो कुल जनसंख्या का एक भाग होती है, आर्थिक

विकास को प्रत्यक्ष रूप से अधिक प्रभावित करती है किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से समस्त जनसंख्या का ही आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। वस्तुतः देश की जनसंख्या, उसका आकार (Size), कार्यक्षमता (Efficiency), संरचना (Composition), वृद्धि दर (Growth rate), विभिन्न व्यवसायों में वर्गीकरण आदि उस देश के आर्थिक विकास पर गहरा प्रभाव डालते हैं। आर्थिक विकास का आशय उत्पादन में वृद्धि है और श्रम, या जनशक्ति (Man-Power) उत्पादन का एक प्रमुख, सक्रिय (Active) और अत्यावश्यक (Indispensable) साधन है। अतः देश का आर्थिक विकास उस देश के मानवीय साधनों पर ही बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि किसी देश में विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप जनसंख्या है, यदि उस देश के निवासी स्वस्थ, परिश्रमी, शिक्षित, कुशल, उच्च चरित्र और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण वाले हैं तो अन्य बातें समान होने पर उस देश का आर्थिक विकास भी अधिक होगा। जैसा कि श्री रिचार्ड टी गिल का कथन है, “आर्थिक विकास एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है” अन्तिम रूप से यह एक मानवीय उपक्रम है एवं अन्य मानवीय उपक्रमों के समान इसका परिणाम अन्तिम रूप से इसको संचालित करने वाले मनुष्यों की कुशलता, गुण और प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है।”

किन्तु जनसंख्या और आर्थिक विकास का सम्बन्ध दिलचस्प और जटिल है। मनुष्य आर्थिक क्रियाओं का साधन और साध्य दोनों ही है। साथ ही जनसंख्या में वृद्धि जहाँ एक ओर उत्पादन के आधारभूत साधन श्रम की पूर्ति में वृद्धि करके उत्पादन वृद्धि में सहायक होती है दूसरी ओर यह उन व्यक्तियों की संख्या में भी वृद्धि कर देती है जिनमें उत्पादन का वितरण होता है। इस प्रकार आर्थिक विकास में बाधक सिद्ध होती है। किन्तु ऐसा केवल उन अर्द्ध-विकसित देशों के बारे में ही कहा जा सकता है जहाँ जनसंख्या और श्रम-शक्ति का बाहुल्य है। शेष अर्द्ध-विकसित देशों में जहाँ जनसंख्या की अधिकता नहीं है जैसे लेटिन अमेरिकी देशों में तथा अन्य विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि अब भी आर्थिक विकास में सहायक है। वस्तुतः इतिहास के प्राचीन काल से आधुनिक समय तक जनसंख्या में वृद्धि विश्व में उत्पादन वृद्धि का एक बड़ा साधन (Major source) रहा है।

अतः बढ़ती हुई जनसंख्या विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में विकास में सहायक होती है क्योंकि इससे उत्पादन और आर्थिक क्रियाओं के विस्तार के लिए आवश्यक श्रम प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त वृद्धिमान जनसंख्या से वस्तुओं और सेवाओं की माँग में वृद्धि होती है बाजार का विस्तार होता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। किन्तु अर्द्ध-विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के भोजन, वस्त्र, आवास एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु देश के बहुत से साधन प्रयुक्त हो जाते हैं और विकास की गति धीमी हो जाती है। इस प्रकार इन अर्द्ध-विकसित देशों में अतिरिक्त मानव शक्ति (Surplus Man Power) विकास में बाधक बन जाती है। किन्तु कुछ लोगों के मतानुसार इन अर्द्ध-विकसित देशों में इस अप्रयुक्त,

अतिरिक्त अर्द्ध-नियोजित और अनियोजित (Un employed) मानव शक्ति में ही पूँजी-निर्माण की सम्भावनाएँ छिपी हुई हैं। लार्ड कीन्स के अनुसार छिपी हुई वचन की सम्भावनाएँ (Concealed saving potential) है। प्रो ए वी माउन्टजोय के अनुसार, 'कुछ परिस्थितियों में अनेक अर्द्ध-विकसित देशों में पाई जाने वाली अपार श्रम-शक्ति एक महान् आर्थिक सम्पत्ति है जिसका पूरा पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। मानव शक्ति पूँजी का उपयोग करने के साथ साथ पूँजी निर्माण (कार्य द्वारा) भी करती है।' इन प्रकार विराम के प्रयत्नों में सलग्न अर्द्ध-विकसित देशों में भी अधिक जनसंख्या विकास में सहायक बन सकती है। यदि उसका उचित नियोजन द्वारा उपयोग (Proper Planning) किया जाए। अतः स्पष्ट है कि आर्थिक विकास में विकसित मानवीय साधन एक महत्वपूर्ण कारक है। आर्थिक विकास के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण अनुभव, प्रेरणा, संगठन आदि द्वारा मानवीय साधनों का विकास किया जाना चाहिए। डा. बी के आर वी राव के अनुसार उत्पादन प्रक्रिया में मानवीय साधन (Human Factor) की कुशलता मानव सम्बन्धी चार तत्वों (अ) शारीरिक (Physical), (ब) मानसिक (Mental), (स) मनोवैज्ञानिक (Psychological) और (द) संगठनात्मक (Organizational) पर निर्भर करती है।

3. पूँजी (Capital)—वास्तव में पूँजी आधुनिक आर्थिक विकास की कुंजी है। एक देश की पूँजी उत्पादित या मानव-कृत उत्पादन के साधनों जैसे भवन, कारखाने, मशीनें यन्त्र उपस्कर रेलें आदि होती हैं। इन पूँजीगत वस्तुओं के अभाव में आर्थिक विकास सम्भव नहीं है। जिस देश के पास पूँजीगत साधनों (Capital Goods) की अपर्याप्तता होगी वह देश अपेक्षाकृत अधिक पिछड़ा हुआ पाएगा। अतः आर्थिक विकास की मुख्य समस्या इन पूँजीगत वस्तुओं में वृद्धि या पूँजी के संचय अथवा पूँजी निर्माण (Capital formation) की है। आर्थिक विकास हेतु साधनों में वृद्धि आवश्यक है और यह वृद्धि पूँजी संचय से ही हासिल होती है। पूँजी संचय (Capital accumulation) यन्त्र, मशीन, भवन आदि में वृद्धि करने की प्रक्रिया है। यदि पूँजीगत वस्तुओं की मात्रा वष के आरम्भ की अपेक्षा अन्त में अधिक है तो देश में पूँजी-संचय हुआ है और इस अन्तर के बराबर देश में पूँजी की वृद्धि हुई है। इसे विभाजन भी कहते हैं। इस प्रकार पूँजीगत वस्तुओं की वृद्धि का आशय है कि देश में पहले से अधिक कारखाने, बाँध, नहर, रेलें, सड़कें यन्त्र उपस्कर, कच्चा माल इंधन, इन्वेन्ट्रीज (Inventories) आदि हैं जिसका परिणाम अधिक उत्पादन और आर्थिक विकास के रूप में प्रकट होता है। प्रो नर्वे के शब्दों में—'आर्थिक विकास की प्रक्रिया का अर्थ भविष्य में उपभोग की वस्तुओं का विस्तार करने के लिए वर्तमान समय में समाज के उपलब्ध साधनों के कुछ भाग को पूँजीगत वस्तुओं के कोष में वृद्धि के लिए लगाना है। आर्थिक विकास का आशय उत्पादन में वृद्धि है और इसके लिए कृषि के क्षेत्र में उर्वरक, गन्ना, गीला गीला धान की पूर्ति और सिंचाई योजनाओं का निर्माण, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के लिए

विभिन्न कारखानों की स्थापना और सम्पूर्ण उत्पादन में वृद्धि के लिए विद्युत एवं शक्ति तथा यातायात एवं संचार साधनों का विकास करना आवश्यक है और इसके लिए पूँजी आवश्यक है। रिचार्ड टी गिल के अनुसार “पूँजी सचय वर्तमान युग में निर्धन देशों को धनवान बनाने और औद्योगिक युग का प्रारम्भ करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक है।”

अतः पूँजी निर्माण के लिए वर्तमान उपभोग को कम करके बचत में वृद्धि करना आवश्यक है। तत्पश्चात् बैंक, बीमा कम्पनियों आदि वित्तीय संस्थाओं के द्वारा इस बचत को एकत्र करके विनियोग कर्त्ताओं के पास पहुँचाया जाता है। इसके बाद पूँजी-निर्माण के लिए आवश्यक है कि इस बचत को विनियोग करके नई पूँजीगत वस्तुओं का निर्माण किया जाए। अर्द्ध-विकसित देशों में पूँजी की अत्यन्त कमी रहती है और पूँजी का यह अभाव उसके विकास में प्रमुख बाधक तत्त्व बन जाता है। अतः आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि इनमें पूँजी-निर्माण की दर बढ़ाई जाए। इसके लिए यह जरूरी है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जाए, बड़ी हुई आय में से अधिक बचत की जाए एवं उसे विनियोजित किया जाए जैसा कि प्रो पाल ग्रोवट ने लिखा है, “आर्थिक विकास की उच्चतम दरें आम तौर से उन्हीं देशों में पाई गई है जहाँ उत्पादन के विनियोग के लिए आवंटित अनुपात अपेक्षाकृत ऊँचा रहा है।” किन्तु यदि घरेलू पूँजी निर्माण आवश्यकता से कम हो तो विदेशी पूँजी के द्वारा भी आर्थिक विकास में योग लिया जा सकता है। भारत जैसे अर्द्ध-विकसित देश अपनी बचत (Saving) और निवेश (Investment) की मात्रा बढ़ाकर तथा निजी पूँजी (Domestic Capital) की कमी को विदेशी पूँजी (Foreign Capital) से पूरी करके आर्थिक विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं।

4 तकनीकी ज्ञान (Technical Knowledge)— विभिन्न देशों के आर्थिक विकास में तकनीकी ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है। तकनीकी ज्ञान का अभाव एक अर्द्ध-विकसित देश के मार्ग में बड़ी बाधा उपस्थित करती है और तकनीकी ज्ञान का विस्तार और उत्पादन की नई-नई प्राविधियों की खोज उत्पादन की मात्रा में वृद्धि गुणों में श्रेष्ठता और मूल्यों में स्थूलता के द्वारा आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष सहायता करती है। डब्ल्यू ए एल्टिस के अनुसार, “तकनीकी ज्ञान की प्रगति को ऐसे नवीन ज्ञान के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसके कारण या तो वर्तमान वस्तुएँ कम लागत पर पैदा की जा सकें या नई वस्तुओं का उत्पादन हो सके।” इस प्रकार तकनीकी ज्ञान के द्वारा वस्तुओं का मूल्य कम किया जा सकता है, उनके गुणों में विस्तार किया जा सकता है, विभिन्न प्रकार की नई वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है, पदार्थों के विभिन्न उपयोग किए जा सकते हैं नवीन साधनों का पता लगाया जा सकता है। इसके कारण मार्ग में वृद्धि, बाजार में वृद्धि उत्पादन वृद्धि और अन्ततः पारिष्कृत विकास होता है। उत्पादन की तकनीक में सुधार करके या नवीन प्राविधियों का उपयोग करके ही अर्द्ध-विकसित देश अपने कृषि व्यवसाय का विकास कर सकते हैं। भारत में 3/4 जनसंख्या कृषि पर निर्भर होते हुए भी

साधनों की कमी और कृषि की दशा शोचनीय है। इसका मुख्य कारण कृषि की परम्परागत विधियों का अनुसरण करना है। ऐसे देशों के आर्थिक विकास के लिए कृषि का विकास अत्यन्त आवश्यक है और वह उपलब्ध तकनीकी ज्ञान के पूर्ण उपयोग और उसमें वृद्धि करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार अर्द्ध-विकसित देशों में अनिज व्यवसाय, मत्स्य पालन, उद्योग-धन्धा आदि में भी परम्परागत तरीकों का ही उपयोग किए जाने के कारण ये पिछड़ी हुई अवस्था में रहते हैं। इनके विकास के लिए अध्ययन, अनुसंधान द्वारा तकनीकी ज्ञान में वृद्धि तथा उत्पादन में उपयोग आवश्यक है।

केवल अर्द्ध-विकसित देशों के लिए ही तकनीकी ज्ञान का महत्त्व नहीं है, बल्कि विकसित देशों के विकास में भी इसका उपयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इन देशों ने नवीन प्राविधियों के सहारे अपने प्राकृतिक साधनों का पर्याप्त विदोहन करके तथा श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ा कर द्रुत आर्थिक विकास किया है। इन विकसित देशों की भावी आर्थिक वृद्धि के लिए भी तकनीकी ज्ञान का विशेष महत्त्व है। डब्ल्यू ए एल्टिस के मतानुसार, 'इसकी (पूर्ण रोजगार वाले देश की) वृद्धि दर बुनियादी रूप से तकनीकी प्रगति और जनसंख्या में वृद्धि पर निर्भर करती है। कोई भी नीति जिससे तकनीकी प्रगति होती है, वृद्धि की दर को बढ़ाती है।' इसी प्रकार रिचार्ड टी गिल का मत है—“आर्थिक विकास अपने लिए महत्त्वपूर्ण पोषकता नवीन विचारों, आविष्कारों, विधियों और तकनीकों के स्रोतों से प्राप्त करता है जिसके अभाव में चाहे अन्य साधन कितने ही पक्ष में हों, आधुनिक विकास अनिवार्य रूप से असम्भव था।”

आर्थिक विकास की प्रक्रिया में तकनीकी ज्ञान के विकास और उपयोग का जहाँ इतना अधिक महत्त्व है वहाँ दूसरी ओर ये देश इस क्षेत्र में अत्यन्त पिछड़े हुए हैं। यही नहीं, ये देश ज्ञान, विज्ञान और तकनीक के विकास के लिए अध्ययन, अनुसंधान आदि पर अधिक धन व्यय नहीं कर पाते। किन्तु इनके समक्ष विकसित देशों द्वारा अपनाए गए तकनीकी ज्ञान का कोष होता है जिसे अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार प्रयुक्त करके ये देश अपने यहाँ आर्थिक विकास कर सकते हैं। वस्तुतः भारत जैसे अर्द्ध विकसित देश, विकसित देशों में अर्जित तकनीक और प्राविधियों में अपनी परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करके उत्पादन में वृद्धि करने में सक्षम हैं।

डब्ल्यू ए एल्टिस के अनुसार तकनीकी ज्ञान में वृद्धि दो प्रकार की होती है। जिस तकनीकी प्रगति का नई पूँजी के अभाव में विदोहन नहीं किया जा सकता उसे 'Embodied' तकनीक प्रगति कहते हैं तथा दूसरी प्रकार की Disembodied तकनीकी प्रगति कहलाती है जिसका बिना नवीन पूँजी के ही विदोहन किया जा सकता है।

अतः आर्थिक विकास में तकनीकी ज्ञान एक महत्त्वपूर्ण साधन बन गया है। एल्टिस के अनुसार “तकनीकी प्रगति सम्भवतः आर्थिक विकास की सम्भव बनाने वाला महत्त्वपूर्ण साधन है।”

5 साहसी एवं नव-प्रवर्तन (Entrepreneur and Innovation)—नए आविष्कार और तकनीकी ज्ञान आर्थिक विकास में, उपयोगी नहीं हो सकते जब तक कि इनका आर्थिक रूप से विदोहन नहीं किया जाए या उत्पादन में उपयोग नहीं किया जाए। रिचार्ड टी गिल के अनुसार “तकनीकी ज्ञान आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावपूर्ण तभी होता है जबकि इसका नव-प्रवर्तन के रूप में प्रयोग किया जाए जिसकी पहल समाज के साहसी या उद्यमकर्त्ता करते हैं।” श्री याले ब्राजन के मतानुसार, “न तो आविष्कार की योग्यता और न केवल आविष्कार ही आर्थिक विधि का उत्पादन करते हैं या उस विधि को कम मिसव्ययतापूर्ण विधियों के स्थान पर प्रयुक्त करने को तैयार करते हैं।” किसी आविष्कार या उत्पादन की नवीन तकनीक की खोज के पश्चात् भी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो दूरदर्शी होता है, जिसमें आत्म-विश्वास होता है और जो इसे उत्पादन में प्रयुक्त करता है जिससे उत्पादन में वृद्धि या इसकी लागत में कमी होती है। तत्पश्चात् यह तकनीकी ज्ञान या आविष्कार उपयोगी सिद्ध होता है। ऐसे व्यक्ति को ‘साहसी और उत्पादन में उसके नवीन विधियों के प्रयोग को नव-प्रवर्तन’ कहते हैं। शुम्पीटर के अनुसार, ‘नव-प्रवर्तन का आशय किसी भी सृजनात्मक परिवर्तन (Creative Change) से है।’ इसका सम्बन्ध आर्थिक क्रियाओं के किसी भी पहलू से हो सकता है। उत्पादन में इनके उपयोग का परिणाम आर्थिक विकास होता है। इस प्रकार आर्थिक विकास में नव प्रवर्तन और उद्यमी एक महत्त्वपूर्ण घटक प्रमाणित होते हैं। प्रसिद्ध अर्थ-शास्त्री शुम्पीटर विश्वास था कि साधनों की वृद्धि से भी बढ कर ये ही वे घटक हैं जो आर्थिक विकास की कुञ्जी हैं क्योंकि आर्थिक विकास वर्तमान साधनों को नवीन विधियों से प्रयुक्त करने में निहित है। प्रो याले ब्राजन के अनुसार भी “आर्थिक विकास उद्यम या साहस के साथ इस प्रकार सम्बद्ध है कि उद्यमी को उन व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है जो ‘नवीन संयोगों’ का सृजन करते हैं।” के ई. बोल्डिंग के अनुसार “आर्थिक प्रगति की समस्याओं में से एक व्यक्तियों को ‘नव-प्रवर्तक’ बनने को प्रोत्साहन देने की है।’

क्लेरेन्स डानहोफ ने उद्यमियों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया है—

1 नव प्रवर्तक उद्यमी (Innovating Entrepreneurs) जो आकषक सम्भावनाओं और प्रयोगों को सर्वप्रथम कार्य रूप में परिणत करते हैं।

2 अनुकरण करने वाले उद्यमी (Imitative Entrepreneurs) जो सफल नव-प्रवर्तकों को ग्रहण करने को प्रस्तुत रहते हैं।

3 ‘फैबियन’ उद्यमी (Fabian Entrepreneurs) बड़ी सावधानी से उठा समय ही नव प्रवर्तकों को ग्रहण करते हैं जब यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा नहीं करने पर उन्हें हानि होगी।

4 ड्रोन उद्यमी (Drone Entrepreneurs) जो ग्रन्थ समान उत्पादकों की प्रपेक्षा अपनी आय कम होने पर भी उत्पादन में परिवर्तन नहीं करते।

अतः स्पष्ट है कि विभिन्न देशों के आर्थिक विकास में उद्यमी और नव प्रवर्तन महत्त्वपूर्ण साधन हैं, किन्तु अर्द्ध-विकसित देशों में इन उद्यमियों की कमी रहती है।

इन देशों में विभिन्न उत्पादन क्रियाओं को अपनाए जाने के विस्तृत क्षेत्र रहते हैं जिनके विदोहन हेतु उद्यमियों की आवश्यकता होती है। स्वदेश में योग्य माहसियों की कमी रहती है जिनकी पूर्ति विदेशों से उद्यम का आयात करके की जाती है। प्रजातान्त्रिक पद्धति वाले देशों में अधिकांश निजी उद्यम होते हैं जबकि समाजवादी देशों में समस्त आर्थिक क्रियाएँ सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं। अल्प स्वतन्त्र अर्थव्यवस्थाओं में भी ये आर्थिक क्रियाएँ सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं क्योंकि निजी उद्यमियों से वांछनीय आर्थिक विकास की आशा नहीं की जा सकती अतः सरकार आर्थिक क्रियाओं में उद्यमों के रूप में सम्मिलित हो रही है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा देश के आर्थिक विकास में निजी उद्यमियों के साथ-साथ सरकार ने भी कोई उद्योग व्यवसाय स्थापित किए हैं। विदेशी उपक्रमों का भी लाभ उठाया जा रहा है।

6 संगठन (Organisation)—आर्थिक विकास का एक प्रमुख तत्त्व उचित व्यवस्था या संगठन है। वांछनीय गति से आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि आर्थिक एवं अन्य क्रियाएँ उचित ढंग से संगठित की जाएं। उत्पादन वृद्धि के लिए उत्पादन के साधनों में वृद्धि आवश्यक है, किन्तु यदि समाज बिना उत्पादन की तकनीक और संगठन में परिवर्तन किए केवल उत्पादन के साधनों में वृद्धि करने पर ही पूर्णतः निर्भर रहता तो पिछले दो सौ वर्षों में हुए आर्थिक विकास का होना कठिन था। जिस किसी भी देश में आर्थिक विकास हुआ है उसका यह एक प्रमुख लक्षण रहा है कि कुल उत्पादन वृद्धि उससे अधिक तीव्र गति से हुई है जो उत्पादन के साधनों में हुई है अर्थात् इसका अर्थ उत्पादन के साधनों के उचित संगठन को है। वज्र भूमि को कृषि योग्य बनाना उसमें सिंचाई की व्यवस्था करना, अच्छे खाद, बीज एवं यन्त्रों का उपयोग करना, देश के खनिज, वन, जल एवं शक्ति के साधनों तथा मानव शक्ति का उचित उपयोग और विकास करना, उद्योगों का उचित पैमाने तक विस्तार करना, विशिष्टीकरण आदि आर्थिक संगठन से सम्बन्धित ऐसे प्रश्न हैं जिनमें सुधार से आर्थिक विकास की गति मिलती है। प्रो. पी. आर. पी. डॉब के कथनानुसार "आर्थिक विकास की समस्या मुख्यतः वित्तीय समस्या नहीं है बल्कि आर्थिक संगठन व व्यवस्था की समस्या है।"

इस प्रकार आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में उत्पादन के साधनों के उपयोग के तरीकों में परिवर्तन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार का एक परिवर्तन या संगठन से सम्बन्धित एक तत्त्व उत्पादन के पैमाने और विशिष्टीकरण में वृद्धि है। प्रो. रिचार्ड टी. गिल ने तो उत्पादन के पैमाने और विशिष्टीकरण वृद्धि को आर्थिक विकास का प्राकृतिक साधन, मानवीय साधन और पूँजी के संचय के समान एक अलग ही कारक माना है। वस्तुतः बड़े पैमाने पर उत्पत्ति (Large Scale Production), श्रम विभाजन (Division of Labour) और विशिष्टीकरण (Specialization) आर्थिक विकास में अत्यन्त सहायक है। बड़े पैमाने के उत्पादन से आन्तरिक और बाह्य मितव्ययिताएँ प्राप्त होती हैं जिसमें बड़ी मात्रा में सस्ती

वस्तुओं का उत्पादन होता है। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक कुछ विशाल सामग्री का निर्माण भी विस्तृत पैमाने के उत्पादन पर ही सम्भव है। श्रम-विभाजन उत्पादकता में वृद्धि करता है। अर्थ-शास्त्र के जनक स्वयं एडम स्मिथ के अनुसार, "श्रम की उत्पादक शक्तियों में सर्वाधिक सुधार श्रम-विभाजन के प्रभावों के परिणामस्वरूप हुआ प्रतीत होता है।" जैसा कि रिचार्ड टी. गिल ने बतलाया है, "अर्थव्यवस्था को व्यक्तिगत कुशलता या विशेष प्रादेशिक या भौगोलिक लाभों का उपयोग करने के योग्य बना कर, वृद्धिमान विशेषज्ञता का विकास करके, उत्पादन का प्रमाणीकरण और यन्त्रीकरण को सुविधाजनक बना कर, उद्योगों के संगठन में इस प्रकार के परिवर्तन आर्थिक विकास में शक्तिशाली योगदान देते हैं।"

अर्द्ध-विकसित देशों में आर्थिक विकास के लिए अनुकूल आर्थिक संगठन नहीं होता। उत्पादन छोटे पैमाने पर बहुधा कुटीर और लघु उद्योगों के द्वारा होता है। श्रम-विभाजन और विशिष्टीकरण का अभाव होता है क्योंकि बाजारों का विस्तार सीमित होता है और बहुधा उत्पादन जीवन-निर्वाह के लिए किया जाता है नियम के लिए नहीं। व्यवसायिक संगठन के विभिन्न विकसित रूपों जैसे संयुक्त पूंजी कम्पनी सहकारिता आदि का प्रभावपूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। अतः ऐसे अर्द्ध-विकसित देशों के आर्थिक संगठन में उचित परिवर्तन अपेक्षित है। भारत में भी इस ओर प्रयास किया जा रहा है। विस्तृत पैमाने पर उत्पादन, श्रम-विभाजन, विशिष्टीकरण आदि बढ़ रहे हैं। लघु उद्योगों का भी पुनर्गठन किया जा रहा है। संयुक्त पूंजी कम्पनियाँ, सार्वजनिक निगम (Public Corporations) और सहकारिता का क्षेत्र विस्तृत हो रहा है।

7. राज्य की नीति (State Policy)—विभिन्न देशों के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण तत्त्व उपयुक्त सरकारी नीति है। आर्थिक विकास के लिए सर्व-प्रथम आवश्यकता राजनीतिक स्थिरता, आन्तरिक और बाह्य सुरक्षा तथा शांति है। बिना स्थिर सरकार के आर्थिक विकास असम्भव है। इसके साथ ही आर्थिक विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि सरकार आर्थिक विकास के उपयुक्त नीति अपनाए यद्यपि प्राचीन काल में राज्य का क्षेत्र सीमित था, किन्तु आधुनिक सरकारें ऐसे बहुत से आर्थिक कार्य सम्भाल करती हैं जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यदि किसी देश की सरकार ऐसी है जो आर्थिक विकास में रुचि नहीं रखती और उसके लिए प्रयत्न नहीं करती तो उस देश के आर्थिक विकास की कोई सम्भावना नहीं है। इसके विपरीत यदि किसी देश की सरकार आर्थिक विकास के लिए रुचि रखती है और प्रयत्न करती है तो अन्य बातें समान रहने पर भी उस देश के आर्थिक विकास की गति अधिक होती है। प्रो. डब्ल्यू. ए. लेविस का कथन है कि कोई भी देश बुद्धिमान सरकार से सक्रिय प्रोत्साहन के अभाव में आर्थिक विकास नहीं कर सका है।

अर्द्ध-विकसित देशों में पूंजी, कुशल श्रम, तकनीकी ज्ञान का अभाव रहता है। इन देशों में विकास के लिए यातायात और सन्देशवाहन के साधन, शक्ति के साधन,

नवीन तकनीक आदि का विकास करना होता है तथा इस प्रकार की कर नीति, मूल्य नीति, मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति, विदेशी व्यापार नीति, औद्योगिक नीति, श्रम नीति अपनाती होती हैं जिससे विकास के लिए आवश्यक वित्तीय साधन उपलब्ध हो सकें, लोग पूँजी की वृद्धि और विनियोजन को प्रोत्साहन दें, देश में आवश्यक उद्योगों की स्थापना हो सके, विकास के लिए आवश्यक देशी और विदेशी कच्चा माल, यन्त्र उपकरण उपलब्ध हो सकें, विदेशों से आवश्यक साज-सज्जा मगाने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके, कुशल जनशक्ति का सृजन हो सके। यही नहीं अर्द्ध-विकसित देशों में विनियोजन के कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ निजी उद्यमी पूँजी विनियोजन नहीं करते या जो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ऐसे क्षेत्रों में सरकार को स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उद्यमी का कार्य करना पड़ता है। आर्थिक विकास का आशय देश वर्तमान और सम्भाव्य माधनों का इस प्रकार उपयोग करना है जिससे अधिकतम उत्पादन हो और अधिकतम लाभ हो। यही कारण है कि आज विश्व के समस्त अर्द्ध-विकसित देशों में आर्थिक विकास का कार्य सरकार द्वारा एक योजनाबद्ध तरीके से संचालित किया जाता है जिसमें सरकार का उत्तरदायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है। नियोजित अर्थव्यवस्था वाले देशों में सरकारी क्षेत्र (Public Sector) का विस्तार होता जाता है। अर्द्ध-विकसित देशों के आर्थिक विकास में सरकारी नीति का महत्व भारत के उदाहरण से पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है जिसने सरकार द्वारा निमित्त पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा पर्याप्त आर्थिक विकास किया है।

8 संस्थाएँ (Institutions)—आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण भी आवश्यक है। इसके लिए न केवल आर्थिक संस्थाएँ ही अपितु राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और धार्मिक वातावरण, मान्यताएँ एवं संस्थाएँ इस प्रकार की होनी चाहिए जो विकास को प्रोत्साहित करें। राष्ट्रमण्डल समिति रिपोर्ट के अनुसार, “उपयुक्त वातावरण की अनुपस्थिति में आर्थिक प्रगति असम्भव है। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि मनुष्यों में प्रगति की इच्छा हो और उनकी सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक एवं वैज्ञानिक संस्थाएँ इस इच्छा को क्रियामय करने में सहायक हों।” प्रोफेसर पॉल अलबर्ट के मतानुसार, “किसी भी आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य शर्त इसकी सम्प्रदाय में लोच होने के साथ-साथ इसके समाज और अर्थव्यवस्था की संरचना परिवर्तन की सम्भावनाओं के लिए खुली हो।” “आर्थिक विकास के लिए घनात्मक प्रेरणा एक ऐसी सम्प्रदाय है जो अपने मूल्यों (Values) में भौतिक समृद्धि को उच्च प्राथमिकता देती है।” इसी प्रकार के विचार हरमन फाइनर ने भी प्रकट किए हैं, “वर्तमान संदर्भ में ‘वातावरण’ का क्या आशय हो सकता है? इसका अर्थ जीवन निर्वाह स्तर में उच्चता की इच्छा की उपस्थिति है जो अन्य मूल्यों की अपेक्षा उच्च प्राथमिकता रखती है।”

इस प्रकार स्पष्ट है कि आर्थिक विकास में जनता के जीवन स्तर को उच्च बनाने की इच्छा एक चालक शक्ति (Motive Power) है जो उस देश की संस्थाओं पर निर्भर रहती है। जहाँ भारत जैसी जमींदारी या जागीरदारी प्रथा प्रचलित होगी,

जिसके कारण कृषकों के परिश्रम द्वारा उत्पन्न कमाई का उपयोग शोषण द्वारा जमींदार और आगीरदार लोग करते हो, वहाँ कृषक की अधिक परिश्रम की प्रेरणा समाप्त होगी और कृषि का द्रुत आर्थिक विकास नहीं हो सकेगा। इसके विपरीत जहाँ लोगों को अपने प्रयत्नों का पूरा प्रतिफल मिलने की व्यवस्था होगी, वहाँ लोगों को अधिक परिश्रम की प्रेरणा मिलेगी और आर्थिक विकास होगा।

अर्द्ध-विकसित देशों में कई संस्थान ऐसे होते हैं जो आर्थिक विकास में बाधक होते हैं। भू-धारण की प्रतिगामी प्रणालियाँ, संयुक्त-परिवार प्रथा, जाति-प्रथा, उत्तराधिकार के नियम, स्त्रियों की स्थिति, भूमि का मोह, नविदा (Contract) की अपेक्षा स्तर (Status) पर निर्भरता, अधविश्वास, परम्परागत रुढ़िग्रस्तता, सामाजिक अपव्यय, परिवर्तन के प्रति असहिष्णुता, प्राध्यात्मिक दृष्टिकोण कुछ धार्मिक भावनाएँ आदि आर्थिक विकास को हतोत्साहित करते हैं। ये संस्थाएँ आर्थिक विकास के लिए आवश्यक परिवर्तन को कठिन बनाकर आर्थिक विकास में बाधा उपस्थित करती हैं। अतः अर्द्ध-विकसित देशों में उन धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं में इस प्रकार परिवर्तन करना चाहिए और नवीन संस्थाओं का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे आर्थिक विकास में सहायता मिले। इन देशों की सामाजिक संस्थाओं में विकास के लिए क्रान्तिवारी परिवर्तनों की आवश्यकता है जो वैधानिक तरीकों से या शिक्षा का प्रचार करके या उच्च जीवन की इच्छा जाग्रत करके की जानी चाहिए।

संक्षेप में किसी देश के आर्थिक विकास में उन संस्थाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है जो देशवासियों में मितोपयोग की इच्छा, भौतिक समृद्धि की आकांक्षा, आर्थिक लाभ के अवसरों को प्राप्त करने की अभिलाषा जाग्रत करती हो।

9. अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ—आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्त्व अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ हैं। आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय परस्पर निर्भरता के युग में दूसरे देशों के सहयोग के बिना आर्थिक विकास की तो बात ही क्या, कोई भी देश जीवित नहीं रह सकता। यदि कोई देश दीर्घकालीन युद्ध में सलग्न है तो उसका आर्थिक विकास असम्भव है। अर्द्ध-विकसित देशों के आर्थिक विकास में तो अनुकूल बाह्य परिस्थितियों का भी महत्त्व होता है। इन देशों में पूँजी का अभाव होता है जिसे विदेशों से अनुदान, ऋण एवं प्रत्यक्ष विनियोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार का हो सकता है। इन देशों में तकनीकी ज्ञान का भी अभाव होता है जिसे विकसित देशों में देशवासियों के प्रशिक्षण या विदेशियों की सहायता द्वारा पूरा किया जाता है। आर्थिक विकास के लिए कृषि और औद्योगिक विकास आवश्यक है। कृषि के विकास के लिए उर्वरक, औपघर्षियाँ, यंत्रोपकरण तथा विशाल सिंचाई योजनाओं के लिए आवश्यक सामग्री विदेशों से प्राप्त करनी होती है। औद्योगीकरण के लिए कच्चे माल मशीनों आदि का भारी मात्रा में आयात करना पड़ता है जिसका भुगतान निर्यातों में वृद्धि द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के द्वारा करना होता है। यह कार्य अभी अच्छी प्रकार से सम्पन्न हो सकता है

जबकि अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण सद्भावनापूर्ण हो, सम्बन्धित देश का विदेशी से अधिकाधिक मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध हो और वे उस देश के आर्थिक विकास में पर्याप्त सहायता देने हो। यदि एक देश दीर्घकालीन युद्ध में सलग्न हो तो उसके आर्थिक विकास की सम्भावनाएँ अत्यन्त क्षीण होगी। अतः अनुकूल बाह्य परिस्थिति, आर्थिक विकास का एक प्रभावशाली तत्त्व है।

आर्थिक विकास के कारक और उनकी सापेक्षिक देन (Relative Contribution of Growth Factors)

सब कारक परस्पर सम्बन्धित होते हैं और एक की वृद्धि से दूसरे का विकास होता है। उदाहरणार्थ, यदि प्राकृतिक साधन अधिक होंगे तो उत्पादन अधिक होगा। पूँजी का निर्माण अधिक होगा जिससे विनियोजित करके आय में वृद्धि की जा सकेगी। आय में इस वृद्धि के कारण मानवीय साधनों का विकास होगा, अध्ययन एवं अनुसंधान पर अधिक धन व्यय करके तकनीकी ज्ञान का विकास किया जा सकेगा और सरकार भी आर्थिक विकास के उत्तरदायित्व को अच्छी प्रकार निर्वाह कर सकेगी। इसी प्रकार यदि देश में स्थिर सरकार है जो आर्थिक विकास के अनुरूप नीतियों को अपनाती है तो देश के प्राकृतिक साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जा सकेगा। देश में विकास के लिए आवश्यक सत्याग्रो का सृजन किया जाएगा जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी और पूँजी-निर्माण की गति बढ़ेगी। इसी प्रकार यदि देश में विकसित जनशक्ति होगी तो अपनी योग्यता और परिश्रम से प्राकृतिक साधनों का अच्छा विदोहन कर सकेगी। यदि पूँजी की पर्याप्तता होगी तभी प्राकृतिक साधनों और नवीन तकनीकी ज्ञान का उचित उपयोग किया जा सकेगा। यदि सगठन या व्यवस्था अच्छी होगी तो उत्पादन के साधनो-श्रम, पूँजी, प्राकृतिक साधनों का उचित और लाभप्रद उपयोग किया जा सकेगा और उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी। इसी प्रकार यदि देश में स्थिर, ईमानदार और विकास-नीतियों को अपनाने वाली सरकार होगी और प्राकृतिक साधनों के विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ होंगी तो विदेशों से अधिकाधिक सहायता उपलब्ध हो सकेगी।

अतः आर्थिक विकास के उपरोक्त समस्त कारक परस्पर सम्बन्धित हैं और समान रूप से आवश्यक हैं। एक के अभाव में अन्य का महत्त्व कम हो सकता है। उदाहरणार्थ, यदि देश में प्राकृतिक साधनों का अभाव है तो अन्य षटक कितनी ही सशक्त हो आर्थिक विकास सीमित ही होगा। जापान, स्विट्जरलैण्ड आदि देशों के अतिरिक्त समस्त विकसित देशों में प्राकृतिक साधनों का आर्थिक विकास में अत्यधिक योगदान रहा है। भूतकाल में आर्थिक विकास में प्राकृतिक साधनों की देन कितनी महत्त्वपूर्ण रही है, इसके बारे में प्रो. रिचार्ड टी गिल ने लिखा है, “पश्चिमी सभ्यता का अधिकांश इतिहास भूमि और साधनों के अधिग्रहण के समर्पण में लिखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त आधुनिक विश्व के सर्वोच्च जीवन-स्तर वाले देश कनाडा और अमेरिका में आर्थिक विकास की प्रक्रिया तथा नवीन साधनों की खोज और उपयोग दोनों साथ साथ होते रहे।” इस प्रकार भूतकाल में प्राकृतिक साधनों की

देन महत्त्वपूर्ण रही है, किन्तु इनका भविष्य में क्या महत्त्व रहेगा, यह अनिश्चित है; क्योंकि अब समस्त विश्व के दृष्टिकोण से साधनों में घनी ग्रन्थिने क्षेत्र कम हो है, यद्यपि मानव में नवीन 'साधनों' के सृजन की क्षमता को भी नजर-अन्दाज नहीं किया जा सकता।

इसी प्रकार, आर्थिक विकास में पूँजी की देन भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। पूँजी के बिना प्राकृतिक साधनों का विदोहन नहीं किया जा सकता, वर्तमान युगीन विशालकाय कारखानों की स्थापना नहीं हो सकती, श्रम की उत्पादकता नहीं बढ़ाई जा सकती। सच तो यह है कि आर्थिक विकास में पूँजी का योगदान भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। प्रो डब्ल्यू ए लेविस ने पूँजी-निर्माण को आर्थिक विकास की एक केन्द्रीय समस्या बतलाते हुए लिखा है, "यह एक केन्द्रीय समस्या है क्योंकि आर्थिक विकास का केन्द्रीय तथ्य (ज्ञान और कुशलता को सम्मिलित करते हुए) तीव्रता से पूँजी संचय है।" कुछ अर्थशास्त्री आर्थिक विकास का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व तकनीकी ज्ञान को मानते हैं। वस्तुतः तकनीकी ज्ञान की इतनी अधिक प्रगति के बिना आर्थिक विकास इस सीमा तक असम्भव होता है। इसी प्रकार कुछ अर्थशास्त्री नव-प्रवर्तन (Innovation) और उद्यम (Enterprise) को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारक स्वीकार करते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री शुम्पीटर के अनुसार उद्यमी और उनकी नव-प्रवर्तन की क्रियाओं को ही आर्थिक विकास का श्रेय है। किन्तु आर्थिक विकास में उत्पादन के साधनों की उचित व्यवस्था अनुकूल वातावरण, विकास की इच्छा को प्रेरित करने वाली सामाजिक संस्थाओं का भी कम महत्त्व नहीं रहा है। इनके अभाव में भौतिक मानवीय और वित्तीय साधनों की पर्याप्तता होने पर भी उनका सदुपयोग या दुरुपयोग नहीं होने पर आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार कुछ लोग राज्य की उचित नीति को आर्थिक विकास का मुख्य घटक बतलाते हैं। सोवियत रूस और अन्य समाजवादी देशों की उच्च आर्थिक प्रगति का बहुत बड़ा श्रेय वहाँ की विकास के लिए प्रयत्नशील सरकारों को ही है। किन्तु वस्तुतः इन सब में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटक किसी देश की कुशल, विवेकपूर्ण दृष्टिकोण और दृढ़ सकल्प वाली जन शक्ति ही है। उत्पादन के अन्य कारकों जैसे प्राकृतिक साधन, वित्तीय साधन, तकनीकी ज्ञान संगठन, वातावरण संस्थान, सरकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण का निर्माण और विकास मनुष्यों के द्वारा ही किया जाता है। डॉ बी के आर वो राव ने इन सम्बन्ध में लिखा है कि आर्थिक विकास सम्बन्धी अध्ययन से पता चलता है कि पूँजी संचय आर्थिक विकास की मात्रा और गति को निर्धारित करने वाले कारकों में से केवल एक है। नव-प्रवर्तन, प्राविधि और ज्ञान आदि भी उन्ने ही महत्त्वपूर्ण हैं जिनसे यन्त्र और उपकरण। किन्तु ये सब मानवीय तत्त्व से बहुत अधिक सम्बन्धित हैं और आर्थिक विकास के लिए अपना कार्य मानवीय प्रयत्नों की गहनता और गुणों पर इनके प्रभाव द्वारा ही करते हैं।

इस प्रकार यद्यपि कई विचारकों ने आर्थिक विकास के लिए भिन्न भिन्न कारकों को महत्त्व दिया है किन्तु वे सभी आवश्यक और महत्त्वपूर्ण हैं। विस्तृत

देशों के आर्थिक विकास का श्रेय किसी तत्त्व को नहीं दिया जा सकता यद्यपि भिन्न-भिन्न देशों में विभिन्न कारकों का कुछ अधिक महत्त्व हो सकता है। अमेरिका के आर्थिक विकास में न केवल भौगोलिक दशाग्रो, किन्तु सामाजिक, राजनीतिक सभी परिस्थितियों ने योग दिया है। सोवियत रूस के आर्थिक विकास में सरकार का योगदान सराहनीय है। डॉ. मोल्स ने इंग्लैंड की औद्योगिक क्रान्ति का श्रेय वहाँ के लोगों की साहस भावना को दिया है। जापान आदि में प्राकृतिक साधनों का योगदान कम रहा है। अतः आर्थिक विकास में किस कारक का अधिक महत्त्व है यह विभिन्न देशों की परिस्थितियों, विकास की अवस्था और विकास की विचारधाराओं पर निर्भर करता है। ये सब कारक परस्पर सम्बन्धित हैं और उनके महत्त्व में विभिन्न परिस्थितियों के सन्दर्भ में अन्तर हो जाता है। अन्त में हम बी. शेपर्ड से सहमत हैं जिनके अनुसार किसी एक कारक से नहीं अपितु विभिन्न महत्त्वपूर्ण कारकों को उचित अनुपात में मिलाने से आर्थिक विकास होता है। इस सम्बन्ध में जोसफ एल फिशर का यह कथन उल्लेखनीय है कि “आर्थिक विकास के लिए किसी एक विशेष तत्त्व को पृथक् करना और इसे ऐसे आर्थिक विकास का प्रथम या प्राथमिक कारण बताना न तो ठीक ही है और न ही विशेष सहायक है। प्राकृतिक साधन, कुशल श्रम, मशीनें और उपकरण, वैज्ञानिक एवं प्रबन्धात्मक साधन एवं आर्थिक स्थानीयकरण सभी महत्त्वपूर्ण हैं। यदि उन्हें आर्थिक समृद्धि प्राप्त करनी है तो दोनों और राष्ट्रीय को इन कारकों को प्रभावपूर्ण ढंग से मिलाना चाहिए।”

आर्थिक विकास की अवस्थाएँ (Stages of Economic Growth)

विश्व के विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की गति और प्रक्रिया में पर्याप्त अन्तर रहा है। अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के ऐतिहासिक क्रम को विभिन्न अवस्थाओं में विभक्त करने का प्रयत्न किया। इस सम्बन्ध में प्रो. रोस्टो का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आर्थिक विकास की अवस्थाओं को निम्न श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है—

- (1) परम्परागत समाज की स्थिति (Stage of Traditional Society),
- (2) स्वयं स्कूर्त-विकास से पूर्व की स्थिति (Stage of Pre condition of take off),
- (3) स्वयं स्कूर्त की स्थिति (Stage of take off),
- (4) परिपक्वता की स्थिति (Stage of Maturity), एवं
- (5) उच्च-स्तरीय उपभोग की अवस्था (Stage of Mass consumption).

1 परम्परागत समाज की स्थिति—प्रो. रोस्टो के अनुसार, “परम्परागत समाज से आशय एक ऐसे समाज से है जिसका ढाँचा समिति उत्पादन कार्यों के अन्तर्गत विज्ञान, प्रविधि एवं भौतिक विश्व की न्यूनतम के पूर्व की स्थिति के आधार पर विकसित हुआ है।” परम्परागत समाज में साधारणतः कृषि और उद्योगों में परम्परागत तरीकों से कार्य किया जाता है। यन्त्रों, विशेषकर शक्ति-च,

सामान्यतः उपयोग नहीं किया जाता। उद्योग अत्यन्त अविकसित अवस्था में पाए जाते हैं और सीमित उत्पादन होने के कारण विनिमय व्यवस्था भी सीमित रहती है। परम्परागत समाज में राजनीतिक सत्ता प्रायः भूस्वामियों में हाथ में केन्द्रित होती है। अपनी भूमि की उपज के बल पर ही यह वर्ग आर्थिक शक्ति हथिया कर समाज के अन्य वर्गों पर शासन करने लगता है। कहीं कहीं उद्योग और कृषि में नवीन पद्धतियाँ दिखाई देनी हैं किन्तु मूलतः सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था अविकसित और स्थिति पाई जाती है।

2. स्वयं स्फूर्त विकास से पूर्व की स्थिति—रोस्टो ने इसे विकास की दूसरी अवस्था माना है। यह अवस्था वस्तुतः स्वयं स्फूर्त अवस्था (Stage of Take off) की भूमिका (Prelude) मात्र है। इससे एक ऐसे समाज का बोध होता है जिसमें परिवर्तन होने प्रारम्भ हो जाते हैं और समाज परम्परागत स्थिति से निकलकर द्वितीय अवस्था की ओर अग्रसर होने लगता है। समाज को इतनी सुविधाएँ मिलना शुरू हो जानी हैं कि वह आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों को अपना सके नवीन तकनीकों का उपयोग कर सके तथा इनके आधार पर अपने विकास की गति में तेजी ला सके। सारांश में, जब परम्परागत समाज में पुराने मूल्यों के स्थान पर नवीन वातावरण को प्रस्थापित करने के प्रयास होने लगते हैं तभी 'स्वयं स्फूर्त विकास से पूर्व की स्थिति' उत्पन्न होती है। इस अवस्था में बैंको बीमा कंपनियों व्यावसायिक संस्थाओं आदि विभिन्न आर्थिक संस्थाओं का आविर्भाव होता है और सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था या इनके एक बड़े भग्न में चेतना जागृत हो जाती है। परम्परागत समाज की सभी अवस्था अधिकांश परिस्थितियों में मूलआधार परिवर्तन होने लगते हैं। उत्पादन प्रविधि में बाष्प शक्ति या किसी सीमा तक बिजली शक्ति का उपयोग होता है तथा वृद्ध स्तर पर उत्पादन होने के कारण विनिमय का क्षेत्र भी विस्तृत हो जाता है। परिवहन को सुगम बनाने के लिए सामाजिक ऊपरी लागतों (Social overheads) का निर्माण होने लगता है, कृषि में प्राविधिक क्रान्ति (Technological Revolution) आने लगती है तथा अधिक कुशल उत्पादन और प्राकृतिक साधनों के विक्रय से वित्त प्राप्त करके आयात में वृद्धि की जान लगती है और जहाँ तक सम्भव हो पूँजी का आयात प्रोत्साहित होता है। इस अवस्था में जो भी परिवर्तन प्रारम्भ होते हैं उनमें विदेशी पूँजी और प्रविधि का योगदान मुख्य रहता है। फिर भी इन अवस्था में आर्थिक विकास का एक सामान्य क्रम नहीं बन पाता। इसके पश्चात् अर्थव्यवस्था स्वयं स्फूर्त (Take-off) की ओर अग्रसर हो जाती है।

3 स्वयं स्फूर्त अवस्था—आर्थिक विकास की तृतीय अवस्था को रोस्टो ने स्वयं-स्फूर्त-अवस्था (Stage of Take-off) की संज्ञा दी है। इस अवस्था को परिभाषित करना कठिन है, रोस्टो के अनुसार स्वयं-स्फूर्त एक ऐसी अवस्था जिसमें विनियोग की दर बढ़ती है और वास्तविक प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि हो जाती है तथा इस प्रारम्भिक परिवर्तन से उत्पादन-नकलीकी में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाते हैं और धन का प्रवाह इस तरह होने लगता है कि विनियोग द्वारा प्रति व्यक्ति उत्पादन की प्रवृत्ति बढ़ती रहती है।

स्वयं स्फूर्त प्रवस्था में आर्थिक विकास कुछ सीमित क्षेत्रों में तीव्र गति से होने लगता है और आधुनिक औद्योगिक-तकनीकी का प्रयोग होता है। विकास सामान्य एवं नियमित गति से होने लगता है तथा प्राविधि अथवा पूँजी के लिए देश पर निर्भर नहीं रहता। विकास मार्ग में आने वाली प्राचीन रुढ़ियाँ एवं बाधाएँ समाप्त हो जाती हैं तथा शक्तियाँ अधिक शक्तिशाली होकर विकास में सहयोग प्रदान करती हैं। नई प्राविधियों के माध्यम से उद्योगों और कृषि में उत्पादन वृद्धि का क्रम स्वयमेव चलता रहता है। औद्योगिक विकास की गति कृषि की अपेक्षा सामान्यतः अधिक तीव्र रहती है। देश की अर्थव्यवस्था बिना किसी बाहरी सहायता के विकास कर सकती है और उत्पादन की अधिकतम सीमा तक पहुँचाना सम्भव हो जाता है। विनियोग और बचत का राष्ट्रीय आय में अनुपात 10 प्रतिशत या इससे अधिक रहता है। कल्याणकारी उद्योगों का तीव्र गति से विकास होता है और ऐसे सस्यागत ढाँचे का निर्माण होने लगता है जो घरेलू साधनों से विकास के लिए पूँजी एकत्रित करने की क्षमता रखता हो। रोस्टो के अनुसार विकास की इस अवस्था में शिक्षा तथा प्राविधिक प्रशिक्षण के साथ-साथ रेलों, सड़कों और संचार वाहन के साधनों का भी विकास हो जाता है। प्रो. रोस्टो न कुछ प्रमुख देशों की स्वयं स्फूर्त अवस्था की अवधियाँ भी दी हैं—

स्वयं स्फूर्त अवस्था

देश	स्वयं स्फूर्त अवस्था की अवधि	देश	स्वयं स्फूर्त अवस्था की अवधि
ग्रेट ब्रिटेन	1783-1802	रूस	1870-1914
फ्रांस	1830-1860	कनाडा	1896-1914
बेल्जियम	1833-1860	अर्जेंटीना	1935
स. रा. अमेरिका	1843-1860	टर्की	1937
जर्मनी	1850-1873	भारत	1952
स्वीडन	1868-1890	चीन	1952
जापान	1878-1900		

प्रो. रोस्टो के अनुसार स्वयं स्फूर्त अवस्था की अनेक आवश्यक शर्तों में मुख्य ये हैं—राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से अधिक वृद्धि निर्धारित में वृद्धि, मूल्यों में स्थायित्व, मातायात एवं शक्ति के साधनों का विस्तार, मानवीय साधनों का उपयोग, सहकारी संस्थापन पूँजीगत एवं आधारभूत उद्योगों की स्थापना कृषि-क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि कुशल प्रबंधक और साहसी बग का उदय, सरकारी क्षेत्र में व्यवसाय आदि।

4 परिपक्वता की स्थिति—चौथी अवस्था में अर्थव्यवस्था परिपक्वता की ओर उन्मुख होती है। रोस्टो के शब्दों में, 'आर्थिक परिपक्वता को परिभाषित करने की विविध पद्धतियाँ हैं, किन्तु इस उद्देश्य के लिए इसे काल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जब समाज अपने अधिकांश साधनों में आधुनिक तकनीकी को प्रभावपूर्ण ढंग से अपनाए हुए है।' परिपक्वता की स्थिति में विनियोग और बचत की दर

20 प्रतिशत तक पहुँच जाते हैं। विभिन्न नए उद्योगों की स्थापना हो जाती है और देश की अन्य देशों पर सामान्य निर्भरता समाप्त हो जाती है। आधुनिक प्राविधियों के इच्छित उपयोग द्वारा राष्ट्रीय आय की वृद्धि का क्रम जारी रहता है। जनसंख्या की वृद्धि की अपेक्षा आय वृद्धि की दर अधिक हो जाती है। स्वयं-सफूर्त-अवस्था के प्रमुख क्षेत्रों की सहाय्यार्थ नवीन क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिलने लगता है। रोस्टो के अनुसार साधारणतः स्वयं-सफूर्त अवस्था से परिपक्वता की स्थिति में पहुँचने में किसी देश को 60 वर्ष लग जाते हैं। परिपक्वता के लिए सभी राष्ट्रों में एक ही समान नियम, विशेषता और प्रकृति का होना जरूरी नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, जापान, रूस आदि देशों ने विभिन्न ढंगों से परिपक्वता की अवस्था को प्राप्त किया है।

5 उच्च स्तरीय उपभोग की अवस्था—विकास की अन्तिम अवस्था उच्च स्तरीय उपभोग की अवस्था है। प्रथम तीन अवस्थाओं में जिन वस्तुओं के उपभोग को विलासिता माना जाता है, वही वस्तुएँ विकास की इस अन्तिम अवस्था में सामान्य बन जाती हैं और सर्व-साधारण जनता उनका उपयोग करने की स्थिति में आ जाती है। उच्च स्तरीय अथवा अधिक उपयोग की अवस्था (Stage of Mass Consumption) में औद्योगिक विकास अपनी धर्म सीमा पर होने लगता है। अब समाज में रहने वाले पूर्ति की अपेक्षा माँग को अधिक महत्व देने लगते हैं। उत्पादन की समस्या से ध्यान हटा कर उपभोग की समस्या और कल्याण की ओर उन्मुख हो जाते हैं। उपभोग में वृद्धि, शक्ति-प्राप्ति के प्रयास, कल्याणकारी राष्ट्र की स्थापना के प्रयास, आदि के द्वारा प्रत्येक राष्ट्र इस अवस्था में आर्थिक कल्याण में वृद्धि करने में जुट जाता है। इससे पूर्व की अवस्थाओं में उत्पादन की वृद्धि को उपयोग की अपेक्षा अधिक प्राथमिकता दी जाती है पर इस अवस्था में उपभोग की वस्तुओं की प्राप्ति साधारण मूल्यों पर होने लगती है। आर्थिक अवस्था के परिपक्व स्तर के बाद वास्तविक आय में सीमान्त ह्रास का उपयोगिता नियम लागू हो जाता है और अर्थव्यवस्था को इस स्थिति से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अर्थशास्त्रियों ने विकास दर का अनेक विधियों से विश्लेषण किया है। एडवर्ड डेनिसन ने जिस विधि से इटली, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, नार्वे, बेल्जियम, इंग्लैंड, संयुक्तराज्य अमेरिका आदि 9 पश्चिमी देशों की विकास दरों का विश्लेषण किया है, उसमें उत्पादन कारकों के परिवर्तनों के योगदान तथा उत्पादन में प्रति इकाई साधन के परिवर्तनों के योगदान का पृथक् पृथक् विवेचन किया गया है। धर्म पूँजी, भूमि तथा इनके परिवर्तनों की भाव के लिए सर्वप्रथम इन साधनों को सम्भव अनुभागों (Components) में विभक्त किया है, साधन के प्रत्येक अनुभाग की विकास दर में अंशदान की गणना की है तथा इसके पश्चात् सभी अनुभागों के अंशों के योग से प्रत्येक साधन की विकास दर पर होने वाले प्रभाव को पृथक् से ज्ञात किया गया है। अतः प्रत्येक साधन की विकास दर को उस साधन के राष्ट्रीय आय के प्रतिफल से गुणा किया गया है। यह गुणनफल राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर में उस साधन के अंश को प्रकट करता है। इस प्रकार सभी साधनों के सम्पत्ति

योगदान की कुल साधनों की विकास दर (Growth rate of total factor input) की परिभाषा दी है।

इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम डेनिसन ने 1909 से 1957 की अवधि में अमेरिका के अन्तिम विकास के विश्लेषण के लिए किया। प्रस्तुत अध्ययन में जिन 9 पश्चिमी देशों की आर्थिक प्रगति का अध्ययन किया गया है उनकी विकास दरें 1950-1962 की अवधि में निम्नांकित प्रकार से रही—

	(प्रतिशत बिन्दुओं में)
पश्चिमी जर्मनी	7.3
इटली	6.0
फ्रांस	4.9
नीदरलैंड्स	4.7
डेनमार्क	3.5
नार्वे	3.5
संयुक्तराज्य अमेरिका	3.3
बेल्जियम	3.2
यू.के.	2.3

किसी साधन का प्रति इकाई उत्पादन में क्या योगदान रहता है, इसे देखने के लिए उत्पादन के प्रत्येक स्रोत के लिए एक भिन्न तकनीकी आवश्यक समझी गई। इस सन्दर्भ में डेनिसन ने प्रत्येक स्रोत के योगदान का निम्न तत्त्वों के आधार पर विवेचन करने का प्रयास किया है—

- (1) साधन आवंटन में महत्वपूर्ण परिवर्तन
- (2) पैमाने की बचतें
- (3) पूँजी की औसत जीवन अवधि में परिवर्तन
- (4) पूँजी-सचय का प्रारम्भिक वर्षों में सतुलन

इसके अतिरिक्त प्रयुक्त साधनों (Employed Resources) पर माँग के दबाव का जिन अवधियों में उत्पादन पर विशेषकर कृषि उत्पादन पर प्रभाव रहा है, उन अवधियों के अन्तर को दृष्टि में रखते हुए साधन का प्रति इकाई उत्पादन की विकास दर पर जो प्रभाव हुआ है उसको भी विवेचना करने का प्रयत्न किया गया है।

उक्त स्रोतों के अतिरिक्त भी विकास दर को प्रभावित करने वाले कुछ स्रोत शेष रह जाते हैं—जैसे ज्ञान में प्रगति (Advances in Knowledge), प्रौद्योगिक प्रगति (Technological Progress) मनुष्य किस सीमा तक कठिन परिश्रम करते हैं, विकास दर में अक्षतिपूर्ण क्षतियाँ (Non-compensating Errors in Growth rates) आदि को डेनिसन ने अवशिष्ट स्रोतों (Residuals) की संज्ञा दी है। संक्षेप में जिन स्रोतों का पृथक् से स्पष्ट रूप से विवेचन व वर्गीकरण संभव नहीं हो सका उन स्रोतों को डेनिसन ने अवशिष्ट स्रोतों की श्रेणी में लिया है।

धन के योगदान की माप के लिए निम्नलिखित तत्त्वों का अध्ययन किया है—

- (1) रोजगार में परिवर्तन

- (2) रोजगार में लगे हुए काम के वार्षिक घण्टों में परिवर्तन
- (3) आयु व लिंग के आधार पर वर्गीकृत श्रमिकों में मानव घण्टों (Man hours) का वितरण
- (4) प्रत्येक श्रमिक की शिक्षा के स्तर के अनुसार प्रदत्त भारों (Weights) के आधार पर मानव घण्टों की संरचना में परिवर्तन।

1950-62 की अवधि में रोजगार में वृद्धि की दृष्टि से जर्मनी का प्रथम तथा अमेरिका का द्वितीय स्थान रहा। रोजगार की संरचना को स्थिर मानते हुए भी, रोजगार की मात्रा में निरपेक्ष वृद्धि के परिणामस्वरूप विभिन्न देशों की विकास दर उनके सामने दिए हुए प्रतिशत बिन्दुओं से प्रभावित हुई—

जर्मनी	15
संयुक्तराज्य अमेरिका	9
नीदरलैंड, डेनमार्क यू के, इटली व बेल्जियम	8 से 4 तक
फ्रांस व नार्वे	1

पूरे समय काम करने वाले मजदूरों व वेतनभोगी गैर कृषि श्रमिकों द्वारा किए गए काम के वार्षिक घण्टों में गिरावट की प्रवृत्ति उक्त अवधि में प्रायः नगण्य रही। संयुक्तराज्य अमेरिका व फ्रांस की स्थिति में तो इस सन्दर्भ में कोई अन्तर नहीं आया किन्तु जर्मनी में गिरावट का प्रतिशत 93 रहा। कुछ अन्य देशों में स्थिति मध्यवर्ती रही। संयुक्त राज्य अमेरिका में रोजगार की मात्रा में वृद्धि का मूल कारण स्त्रियों व विद्यार्थियों द्वारा अपने अवकाश के समय कार्य करने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति रहा है। स्त्रियों व छात्रों द्वारा सप्ताह में केवल कुछ घण्टों काम करने के कारण अमेरिका में श्रमिकों के घण्टों का औसत गिर गया। इटली में इसके विपरीत रोजगार के अवसरों में वृद्धि के कारण Involuntary Part time Employment कम हो गया। अन्यत्र आधे समय रोजगार (Part time Employment) की स्थिति में बहुत कम परिवर्तन हुए।

डेनिसन ने काम के पूरे घण्टों में जिस वर्ष परिवर्तन हुए है उनके काम पर पड़ने वाले शुद्ध प्रभाव का अनुमान भी लगाया है। औद्योगिक उत्पादकता की क्षति की मान्यता लेते हुए अर्द्ध-कालीन रोजगार के महत्त्व में परिवर्तनों पर भी विचार किया है। इन सबके परिणामस्वरूप अमेरिका की विकास दर में 2 की कमी पाई और शेप 8 में से 5 देशों में कमी का यही स्तर रहा। जर्मनी में सर्वाधिक कमी आई। फ्रांस में कमी की स्थिति नगण्य रही किन्तु इटली में यह कुछ घनात्मक रही।

श्रम की औसत कुशलता पर आयु तथा लिंग की संरचना में परिवर्तनों का क्या प्रभाव होता है, इसकी माप प्रति घण्टा प्राप्त आय भारों (Hourly earning rates) के आधार पर की गई। स्त्रियों के काम के घण्टों के अनुपात में प्रत्यधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप संयुक्तराज्य अमेरिका में उक्त परिवर्तन का प्रभाव सर्वाधिक प्रतिकूल रहा। इससे वहाँ की विकास दर में 1% की कमी आई, किन्तु अनेक देशों जैसे फ्रांस व इटली में लगभग 1% की वृद्धि हुई।

शिक्षा में विस्तार के कारण श्रमिकों की कुशलता में औसत वृद्धि के प्रतिशत विभिन्न देशों में इस प्रकार रहे—

संयुक्तराज्य अमेरिका	•5
बेल्जियम	4
इटली	3
फ्रांस व यू.के.	2
नीदरलैंड, डेनमार्क व जर्मनी	•1

श्रम के उक्त चारों अनुभागों के सम्मिलित परिणामस्वरूप संयुक्तराज्य अमेरिका की विकास दर में 1.1% की वृद्धि हुई। जर्मनी में वृद्धि की मात्रा इससे भी अधिक रही।

इस अध्ययन में पूँजी को चार वर्गों में विभाजित किया गया है। विकास दर में आवासीय भवनों के योगदान की माप राष्ट्रीय खातों में आवासीय सेवाओं के शुद्ध मूल्य को देखकर प्रत्यक्ष रूप से की जा सकती है। इस मद के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में विकास दर की वृद्धि 25% तथा जर्मनी में 14% रही। अन्तर्राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों के योगदान को भी प्रत्यक्षतः मापा जा सकता है। अमेरिका में इसका योगदान 0.5% तथा नीदरलैंड में इससे कुछ अधिक रहा। गैर-आवासीय निर्माण इन्विजमेण्ट व वस्तु सूचियों के समूहों का अमेरिका में योगदान 5% रहा और बेल्जियम को छोड़कर यूरोप के अन्य देशों में इस मद का विकास दर में योग कम रहा, किन्तु जर्मनी में सर्वाधिक वृद्धि इस स्रोत से 1.4% की हुई।

सभी प्रकार की पूँजी में 1950-62 की अवधि में विकास दर में अमेरिका में 8% की वृद्धि हुई तथा यूरोप के सभी देशों में वृद्धि का यही स्तर रहा। नीदरलैंड व डेनमार्क में यद्यपि अमेरिका की तुलना में पूँजी के कारण विकास दर में कुछ अधिक वृद्धि हुई, किन्तु बेल्जियम व यू.के. में वृद्धि स्तर बहुत ही कम रहा।

उत्पादन वारकों के विकास दर में योगदान की दृष्टि से तथा यह मानते हुए कि सभी देशों में पैमाने का स्थिर प्रतिफल नियम (Constant Returns to Scale) त्रिघाशील है। 1950-62 की अवधि में विभिन्न देशों में विकास-दर की स्थिति निम्न प्रकार रही—

जर्मनी	2.8
डेनमार्क	1.6
संयुक्तराज्य अमेरिका	2.0
फ्रांस व बेल्जियम	1.2
नीदरलैंड	1.9
यू.के.	1.1
नार्वे	1.0

इस अवधि में राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन साधनों की वृद्धि दर में इतनी कम अनुसूचता देखी गई कि साधनों के आवंटन की दृष्टि से इसके समाधान के लिए तीन पहलुओं का विश्लेषण किया गया है—(1) कृषि का संकुचन (Contraction of Agriculture), (2) गैर-कृषि निजी व्यवसाय का संकुचन (The contraction of non-farm self-employment), और (3) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिबन्धों की कमी (The reduction of barriers to International Trade)।

1950 में, सभी देशों में साधनों का एक बड़ा अनुपात, विशेषकर मानव-श्रम कृषि में लगा हुआ था। 1950-62 की अवधि में उक्त सभी 9 देशों में कृषिगत रोजगार का प्रतिशत 30 से 47 तक कम हो गया। कृषि में लगे हुए मानव श्रम की सभी देशों में भारी कमी हुई, किन्तु कृषिगत रोजगार के महत्त्व और गैर-कृषि रोजगार पर इसके प्रभाव में इन देशों में भारी असमानता रही। 1950 में यू. के. में कुल रोजगार में कृषिगत रोजगार का प्रतिशत 5 था, बेल्जियम में 11, अमेरिका में 12, जर्मनी, डेनमार्क व फ्रांस में 25 से 29 तथा इटली में 43 % था।

प्रति इकाई साधन (Input) से सामान्यतः कृषि में गैर-कृषि उद्योगों की तुलना में राष्ट्रीय उत्पादन बहुत कम होता है। इसके अतिरिक्त एक दी हुई अवधि में गैर-कृषि क्षेत्र की आय को साधनों की वृद्धि के अनुपात में बढ़ाया जा सकता है जबकि कृषि पहले से ही साधनों के भार से इतनी अधिक दबी हुई होती है कि कृषि क्षेत्र से यदि श्रम की सम्पूर्ण मात्रा को हटा भी लिया जाता है तो कृषि उत्पादन पर कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो सकता।

1950-62 में कृषि-क्षेत्र से गैर-कृषि क्षेत्र के उद्योगों में साधनों का स्थानान्तरण करने के परिणामस्वरूप विकास दर में वृद्धि की स्थिति इस प्रकार रही—

यू. के	1 से कुछ कम
संयुक्त राज्य अमेरिका	2
बेल्जियम	7
फ्रांस	8
जर्मनी	10
इटली	10

गैर-कृषि निजी व्यवसाय (Non-farm self-employment) में श्रम की अधिक मात्रा के लगे रहने का प्रभाव भी कृषि की भांति श्रम की सीमांत उत्पादकता का बहुत कम होने के रूप में होता है। गैर-कृषि व्यवसायों पर स्वामित्व के अधिकार रखने वाले, बिना किसी पारिश्रमिक के कार्य करने वाले श्रमिक भिन्न-भिन्न देशों में गैर-कृषि रोजगार के भिन्न-भिन्न अनुपातों को दर्शाते हैं। 9 में से 5 देशों में यह अनुपात 1950-1962 की अवधि में कम हुआ है। श्रमिकों की एक बड़ी सत्ता को इन क्षेत्रों से हटा कर वेतन व मजदूरी के रूप में पारिश्रमिक देने वाले रोजगारों में

सगाया गया। इन हटाए गए व्यक्तियों का कार्य या तो शेष श्रमिकों द्वारा कर लिया गया और इस प्रकार उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं हुआ अथवा हटाए गए श्रमिकों की संख्या के अनुपात से बहुत कम अनुपात में नए श्रमिक लगा कर उनके हिस्से के कार्य को करवा लिया गया। इस परिवर्तन के लाभों की स्थिति निम्न प्रकार रही—

अमेरिका व इंग्लैंड में	04
इटली, फ्रांस, नार्वे व नीदरलैंड्स में	22 से 26 तक

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबन्धों को हटाने से लाभ इस प्रकार रहे—

अमेरिका	0
इंग्लैंड	2
बेल्जियम, नीदरलैंड्स, नार्वे और इटली	15 या 16

साधन आवंटनों के इन तीन पहलुओं के योग से 1950-1962 की अवधि में विकास दरों पर जो संयुक्त प्रभाव हुआ, उसकी स्थिति निम्न प्रकार रही—

यू के	1
अमेरिका	3
बेल्जियम	5
नीदरलैंड्स	6
नार्वे	9
फ्रांस	10
जर्मनी	10
इटली	14

ये अन्तर सापेक्ष रूप से बहुत अधिक हैं।

1950-1962 की अवधि में साधनों (Inputs) व साधन आवंटनों की विकास दरों में सम्मिलित योगदान के आधार पर अध्ययनगत 9 देशों को एक श्रेणी क्रम (Ranking) दिया जाता सम्भव हो सका। किन्तु माँग के दबाव व भौसम के परिवर्तनों के कारण साधनों का प्रति इकाई उत्पादन पर जो प्रभाव हुआ, उसकी परस्पर तुलना सम्भव नहीं हो सकती थी। इस तथ्य का विवेचन अवशिष्ट साधनों (Residuals) के संदर्भ में किया गया। अवशिष्ट साधनों के योगदान को डेनिसन ने विकास दर की कुल वृद्धि में स्पष्ट रूप से अनुमानित साधनों के योगदान को घटाकर प्राप्त किया। अमेरिका में अवशिष्ट (Residuals) का योगदान 1950-55 व 1955-62 की अवधियों में 76 रहा तथा कुछ मामूली समायोजनों के बाद 1920 से आगे तक की अवधि के परिणाम भी यही रहे हैं। अवशिष्ट में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अमेरिका में शिक्षा में वृद्धि (Advances in Knowledge) की रही है। 1955-1962 की अवधि में 7 अन्य देशों में अवशिष्ट साधनों का प्रभाव 75 से 97 के मध्य रहा। अमेरिका के अतिरिक्त ये देश बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, जर्मनी यू के व नार्वे थे। फ्रांस में अवशिष्ट साधनों का योगदान 150 तथा इटली में 130 रहा। इस प्रकार फ्रांस में इस

स्रोत की वृद्धि अमेरिका से भी अधिक रही। फ्रांस में इन साधनों के अन्तर्गत तकनीकी प्रगति, प्रबन्ध कुशलता में सुधार, गैर कृषि मजदूरी व वेतन वाले रोजगार से अतिरिक्त धन को हटाना, साधनों के आवंटन में सुधार, प्रोत्साहन देने की कुछ श्रेष्ठ विधियाँ, अधिक कड़ा परिश्रम करने की प्रवृत्ति और इसी प्रकार के कुछ अन्य साधन अपनाए गए।

1950-1955 की अवधि में जर्मनी में अधिक तथा इटली में कुछ कम अंशों में विकास दरों में जो भारी वृद्धि हुई उसका मुख्य कारण युद्धकालीन विध्वनों (Distortions) की पुनर्रचना था।

सामान्य निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि विकास दर की दृष्टि से देशों का श्रेणीकरण (1950-1962 की अवधि में) कुल मिलाकर साधनों में परिवर्तनों, श्रेष्ठ साधन आवंटन, तकनीकी सुधार तथा युद्धकालीन विध्वनों की पुनर्रचना आदि द्वारा निर्धारित हुआ है।

विकास दर में अन्तर में वृद्धि का मूल कारण पैमाने की बचतें (Economics of Scale) भी रही हैं। कुछ सीमा तक यह इसलिए भी होता है, क्योंकि पैमाने की बचत के लाभ बाजारों के आकार के विस्तार पर निर्भर करते हैं, इसलिए जहाँ एक ओर विकास दर में अन्य कारणों से वृद्धि होती है, यह वृद्धि पैमाने की बचतों व बाजारों के विस्तार के कारण कहीं अधिक बढ़ जाती है।

यूरोपीयन कीमतों के स्थान पर यदि अमेरिकी कीमतों के भावों के आधार पर उपभोग की मदों को पुन मूल्यंकित किया जाए तो यूरोपीयन देशों की विकास दर और अधिक कम होगी। 1950-1962 में कुल मिलाकर इस कमी की सीमा बेल्जियम, नार्वे और यू. के में 1, डेनमार्क व नीदरलैंड्स में 2, फ्रांस में 5, इटली में 6 तथा जर्मनी में 9 रही। विकास दर में उक्त कमी इसलिए भी होता है कि विभिन्न वस्तुओं का यूरोप में उपभोग अमेरिका की तुलना में कम रहता है, जबकि यूरोप की कीमतें अमेरिका की कीमतों की तुलना में अधिक ऊँची रही हैं तथा वस्तु की आय लाभ भी अधिक है।

यूरोप के देशों में प्रति इकाई उपभोग में वृद्धि ऊँची आय स्रोत वाली वस्तुओं में केन्द्रित रही है तथा जिन वस्तुओं की कीमतें अमेरिका की तुलना में अधिक थी, प्रति इकाई उपभोग में जितनी अधिक वृद्धि हुई, विकास दरों का अन्तर उतना ही अधिक बढ़ता गया। इन निष्कर्षों का परीक्षण उपभोग कीमतों के भारों के आधार पर किया जा सकता है। डेनिसन की यह भाव्यता है कि सर्वाधिक उत्तरदायी तत्त्व पैमाने की बचतें हैं। विकसित देशों में जैसे ही प्रति इकाई उपभोग में वृद्धि हुई, वृद्धि का केन्द्र वे वस्तुएँ अधिक रही, जिनका उत्पादन कम मात्रा में हुआ और विशेषकर वे वस्तुएँ जिनकी प्रति इकाई लागत अमेरिका की तुलना में अधिक ऊँची रही। अमेरिका में बड़े पैमाने के उत्पादन की तकनीकी उपलब्ध थी और इसलिए जैसे ही बाजारों का विस्तार हुआ, इस तकनीकी का अपनाना सम्भव हो सका।

विकास दर के स्रोतों के अतिरिक्त डेनिसन ने रोजगार में लगे हुए प्रति व्यक्ति के अनुसार राष्ट्रीय आय के स्तर सम्बन्धी प्रगति के स्रोतों का भी पृथक् से

अध्ययन करने का प्रयास किया है। अमेरिका की कीमतों ने माप करने पर रोजगार में लगे हुए प्रति व्यक्ति के अनुसार यूरोप के देशों की राष्ट्रीय आय, इटली को छोड़कर 1960 में अमेरिका की आय की लगभग 58 से 65 प्रतिशत थी। इटली में यह 40 प्रतिशत थी।

विकास के स्रोतों व आय के अन्तरों की तुलना के आधार पर डेनिसन दो प्रकार के निष्कर्ष (Observation) प्रस्तुत करते हैं।

डेनिसन की प्रथम प्रत्यालोचना (Comment) का सम्बन्ध साधनों के आवंटन से है। अमेरिका की तुलना में फ्रांस व जर्मनी में गैर-कृषि रोजगार की वृद्धि द्वारा तथा कृषिगत निजी स्वामित्व वाले रोजगार की कमी द्वारा राष्ट्रीय आय वृद्धि की अधिक सम्भावना (Potentiality) थी। यह तथ्य इस निष्कर्ष की पुष्टि करता है कि साधनों की प्रति इकाई से उत्पादन की मात्रा में फ्रांस व जर्मनी में अधिक वृद्धि क्यों हुई। फ्रांस व जर्मनी इस स्रोत का तेजी से विदोहन (Exploitation) कर रहे हैं किन्तु राष्ट्रीय आय के अन्तर को अमेरिका की तुलना में विशेष कम नहीं कर पाएगा।

साधनों का पुनर्वांटन भी इसकी बड़े अंशों में पुष्टि करते हैं कि ब्रिटेन की विकास दर में फ्रांस व जर्मनी की विकास दर अधिक क्यों रही? किन्तु प्रति श्रमिक राष्ट्रीय आय का स्तर 1960 में इंग्लैंड में भी उतना ही ऊँचा था जितना कि फ्रांस व जर्मनी में। इसका कारण इंग्लैंड में साधनों के आवंटन में असमत्तियों को कम किया जाना माना जाता है। गैर कृषि उद्योगों में इंग्लैंड का प्रति व्यक्ति उत्पादन इटली से भी कम था। साधनों के आवंटन में सुधार एक ओर इंग्लैंड, फ्रांस एवं जर्मनी में आय के अन्तर का मार्ग खोल रहा है तथा दूसरी ओर यू.के. व इटली में इस अन्तर को समाप्त कर रहा है।

कृषि व निजी व्यवसाय की प्रवृत्ति इटली की आय के स्तर को बहुत अधिक गिरा रही है। इटली में यूरोप के अन्य देशों की तुलना में आय के कम होने का यही मुख्य कारण है। शिक्षा व पूँजी की कमी के कारण भी अन्तर में वृद्धि होती है।

डेनिसन की दूसरी प्रत्यालोचना (Comment) का सम्बन्ध अवशिष्ट साधनों की उत्पादकता (Residual Productivity) से है। डेनिसन का निष्कर्ष है कि यदि प्रति श्रमिक, मात्रा व कुशलता में, भूमि व पूँजी के अनुपात में, बाजारों के आकारों में, साधनों के मूल्य आवंटन की लागतों में, साधनों पर शक्ति के दबाव आदि में कोई अन्तर नहीं होते तो यूरोप के देशों में अवशिष्ट उत्पादकता 1960 में इटली के अतिरिक्त अमेरिका से 28 प्रतिशत कम होती। किसी भी प्रकार के सुधार किए जाएँ या अन्तर उत्पन्न किए जाएँ, यूरोप की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के स्तर पर तब तक नहीं पहुँच सकती जब तक कि इस अवशिष्ट उत्पादकता के अन्तर को कम नहीं किया जाता। डेनिसन के अनुसार, 1962 तक फ्रांस व अतिरिक्त किसी भी देश में यह अन्तर नहीं आ सका।

1925 में इटली के अतिरिक्त अमेरिका का राष्ट्रीय आय का स्तर इतना

ऊपर पहुँच चुका था जितना कि यूरोप के देशों का 1960 में था। 1960 में अवशिष्ट उत्पादकता (Residual Productivity) यूरोप के देशों में 1925 के अमेरिका से भी कम थी। अमेरिका की विकास दर में इन 35 वर्षों में अधिक बढ़ते रहने का कारण शिक्षा, तकनीकी व विज्ञान की प्रगति रहा है।

निष्कर्ष यह है कि महाद्वीपीय देश (Continental Countries) अमेरिका की तुलना में विकास की अधिक दर प्राप्त करने में इसलिए असफल रहे कि उनका मुख्य लक्ष्य 1950 से 'आर्थिक विकास' न होकर केवल 'आर्थिक वृद्धि' रहा। गुणात्मकता के स्थान पर परिमाणात्मकता पर उनका ध्यान केन्द्रित रहा। अमेरिका में स्त्रियों को रोजगार में अधिक लगाया गया, श्रम शक्ति में शिक्षण-प्रशिक्षण में वृद्धि की गई। शक्ति, अन्वेषण व विकास कार्यक्रमों की ओर अधिक ध्यान लगाया गया। कृषि व्यवसाय को कम किया गया तथा लघु स्तरीय गैर-कृषि निजी व्यवसायों को निरस्त/हटाने की नीति अपनाई गई। पूँजी के संचय को भी सापेक्ष रूप से इतना नहीं बढ़ाया गया जितना कि यूरोप के अधिकांश देशों में हुआ। केवल जर्मनी ही ऐसा देश रहा जो अमेरिका की अपेक्षा विकास की अधिक दर प्राप्त कर सका।¹

1. 'Sources of Post war Growth in Nine Western Countries,' American Economic Review, May 1967, p p 325 to 332.

आर्थिक विकास से सम्बन्धित विचारधाराएँ : लेविस, हैरड-डोमर, महालनोबिस तथा अन्य

(Approaches to the Theory of Development : Lewis,
Harrod-Domar, Mahalanobis and others)

“आर्थिक विकास का सभी देशों के लिए सभी परिस्थितियों में सर्वमान्य कोई प्रामाणिक सूत नहीं है, अतः आर्थिक विकास का एक सामान्य सिद्धान्त बताना अति कठिन है।”
—प्रो फ्रीडमेन

आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कम आय वाली आर्थिक व्यवस्था का अधिक आय वाली व्यवस्था में रूपान्तरण होता है। यदि आर्थिक विकास को इस रूप में परिभाषित करें तो स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा होती है कि यह रूपान्तरण किस प्रकार और किन परिस्थितियों में होता है। आर्थिक विकास के सिद्धान्त इस जिज्ञासा को बहुत कुछ शान्त करने में सहायक होते हैं। उनसे पता चलता है कि अर्द्ध विकसित देश किस प्रकार दूषित चक्रों (Vicious Circles) को तोड़कर सतत विकास की शक्तियों का सृजन कर सकता है। आर्थिक विकास के सिद्धान्तों से ज्ञात होता है कि विश्व के कुछ राष्ट्र विकसित और दूसरे राष्ट्र अविकसित क्यों रह गए।

आर्थिक विकास का विचार नया नहीं है। समय-समय पर अर्थशास्त्री आर्थिक विकास के कारकों और सिद्धान्तों पर विचार प्रकट करते रहे हैं। कीन्स के ‘सामान्य सिद्धान्त’ के प्रकाशन के बाद आर्थिक विकास के आधुनिक मॉडलों (Models) का निर्माण किया जाने लगा। आर्थिक विकास से सम्बन्धित निम्नलिखित तीन विचारधाराएँ हैं—

- (1) लेविस का आर्थिक विकास का सिद्धान्त,
- (2) हैरड डोमर मॉडल,
- (3) महालनोबिस मॉडल।

आर्थर लेविस का आर्थिक वृद्धि का सिद्धान्त
(W Arther Lewis' Theory of Economic Growth)

पृष्ठभूमि (Background)

‘आर्थिक वृद्धि’ के सिद्धान्त की रचना में आर्थर लेविस ने प्रतिष्ठित अर्थ-शास्त्रियों (Classical Economists) की परम्परा का ही अनुसरण किया है। स्मिथ से लेकर मार्क्स तक सभी अर्थशास्त्रियों ने इसी अभिमत की पुष्टि की

है कि अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 'निर्वाह-मजदूरी पर श्रम की अससीमित पूर्ति उपलब्ध है।' इन अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वृद्धि का कारण पूँजी संचय (Capital Accumulation) में खोजने का प्रयत्न किया है। इसकी व्याख्या इन्होंने आय-वितरण के विश्लेषण के रूप में की है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के मॉडलों में 'आय-वृद्धि' (Income-growth) व 'आय वितरण' (Income distribution) का विवेचन एक साथ हुआ है। लेविस भी इन अर्थशास्त्रियों की भाँति आर्थिक वृद्धि के अपने मॉडल में यही मान्यता लेकर चलते हैं कि 'अर्द्ध-विकसित देशों में निर्वाह-मजदूरी पर अससीमित मात्रा में श्रम उपलब्ध है।' लेविस ने अपने मॉडल में दो क्षेत्र लिए हैं—(1) पूँजीवादी क्षेत्र (Capitalist Sector) व (2) निर्वाह क्षेत्र (Subsistence Sector)।

परिकल्पना (Hypothesis)

मॉडल में यह परिकल्पना की गई है कि आर्थिक वृद्धि पूँजी संचय का फलन है और पूँजी संचय तब होता है जब श्रम को निर्वाह क्षेत्र से स्थानान्तरित करके पूँजीवादी क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है। पूँजीवादी क्षेत्र पुन उत्पादित होने वाली पूँजी (Reproducible Capital) का प्रयोग करता है, जबकि निर्वाह क्षेत्र में इस प्रकार की पूँजी प्रयुक्त नहीं होती तथा इस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रदा (Per Capita Output) पूँजीवादी क्षेत्र की अपेक्षा कम होता है।

मॉडल की सैद्धान्तिक संरचना

(Theoretical Frame-work of the Model)

लेविस के मॉडल का मुख्य केन्द्र-बिन्दु इस तथ्य की विवेचना करना है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के मूल सैद्धान्तिक ढाँचे में रहते हुए, वितरण, संचय व विकास से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान किस प्रकार सम्भव है। इन समस्याओं का विवेचन बन्द एवं खुली दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में किया गया है।

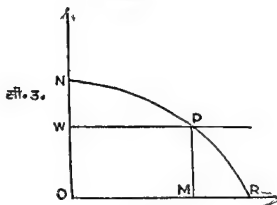
(i) बन्द अर्थव्यवस्था (Closed Economy)—बन्द अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित मॉडल का प्रारम्भ लेविस इस मान्यता से करते हैं कि निर्वाह मजदूरी पर श्रम की पूर्ति पूर्णतः लोचदार (Infinitely Elastic) होती है। वे इस कथन को विश्व के सभी भागों में क्रियाशील मानकर नहीं चलते हैं। इस मान्यता की क्रियाशीलता को लेविस केवल उन देशों से ही सम्बद्ध करते हैं जो घनी आबादी वाले हैं तथा जहाँ पूँजी व प्राकृतिक साधनों की तुलना में जनसंख्या इतनी अधिक है कि उनकी अर्थव्यवस्थाओं में अधिकांशतः 'श्रम की सीमान्त उत्पादकता नगण्य, शून्य या ऋणात्मक पाई जाती है।' कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस स्थिति को गुप्त बेरोजगारी (Disguised Unemployment) की संज्ञा दी है तथा मूलतः कृषि-क्षेत्र को गुप्त बेरोजगारी के प्रति उत्तरदायी पाया है।

(ii) श्रम की सीमान्त-उत्पादकता शून्य है या नगण्य—लेविस अपने मॉडल में इसे विशेष महत्वपूर्ण न मानते हुए, इस तथ्य पर अधिक बल देते हैं कि अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्थाओं में श्रम का प्रति इकाई मूल्य निर्वाह-मजदूरी के स्तर पर

होता है। अतः जब तक इस मूल्य पर श्रम-पूर्ति माँग से अधिक बनी रहती है, तब तक श्रम-पूर्ति को असीमित कहा जाता है। श्रम-पूर्ति की इस स्थिति में मजदूरी के वर्तमान स्तर पर निर्वाह क्षेत्र से श्रम को पूँजीवादी क्षेत्र में स्थानान्तरित करते हुए एक बड़ी सीमा तक नए उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं तथा पुराने उद्योगों का विस्तार किया जा सकता है। श्रम की न्यूनता रोजगार के नए स्रोतों के निर्माण में किसी अवरोध (Constraint) का कार्य नहीं करती। कृषि, प्राकृतिक श्रम, छोटे-मोटे व्यापारी, घरेलू सेवक, गृह-सेविकाएँ, जनसंख्या-वृद्धि आदि वे स्रोत हैं जिनसे निर्वाह मजदूरी पर श्रम, पूँजीवादी क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जा सकता है। किन्तु यह स्थिति अकुशल श्रम के लिए ही लागू होती है। जहाँ तक कुशल श्रम का प्रश्न है, समय विशेष पर किसी विशेष प्रकार के कुशल श्रम की पूँजीवादी क्षेत्र में कमी सम्भव है। कुशल श्रम के अतर्गत वस्तुकार, विद्युत कार्यकर्ता (Electricians), वेल्डर्स (Welders), जीव-विशेषज्ञ (Biologists), प्रशासक (Administrators) आदि आते हैं। सेविस के मतानुसार, कुशल श्रम का अभाव केवल आंशिक बाधा (Quasi-bottleneck) है। प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करके अकुशल श्रम की इस बाधा को दूर किया जा सकता है। विकास या विस्तार के मार्ग में वास्तविक बाधाएँ (Real bottlenecks) पूँजी और प्राकृतिक साधनों का अभाव हैं। अतः सेविस के अनुसार जब तक पूँजी व प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं, आवश्यक कुशलताएँ (Necessary Skills) कुछ समयान्तर (Time lag) से प्राप्त की जा सकती हैं।

(iii) यदि श्रम असीमित पूर्ति में उपलब्ध है और पूँजी दुर्लभ है तो पूँजी का श्रम के साथ उस बिन्दु तक प्रयोग किया जाना चाहिए जहाँ श्रम की सीमान्त उत्पादकता मजदूरी के वर्तमान स्तर के समान रहती है। इसे चित्र 1 में दर्शाया गया है¹—

चित्र-1



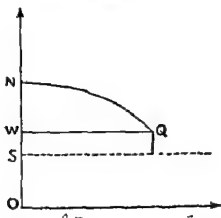
अज की मात्रा

उक्त चित्र में क्षितिजीय अक्ष पर श्रम की मात्रा तथा लम्बवत् अक्ष पर सीमान्त उत्पादकता की माप की गई है। पूँजी की मात्रा स्थिर (Fixed) है। OW = वर्तमान मजदूरी, OM = पूँजीवादी क्षेत्र में प्रयुक्त श्रम, MR = निर्वाह क्षेत्र में प्रयुक्त श्रम, OR = कुल श्रम, $OWPM$ = पूँजीवादी क्षेत्रों के श्रमिकों की मजदूरी, WNP = पूँजीवादियों का अतिरेक (Capitalists Surplus) प्रकट करते हैं। यदि पूँजीवादी क्षेत्र से बाहर श्रम की सीमान्त उपयोगिता शून्य हो तो श्रम की OR मात्रा को रोजगार में रखा जाना चाहिए था, किन्तु पूँजीवादी क्षेत्र में श्रम की OM मात्रा को रोजगार देने पर ही लाभ कमाया जा सकता है। श्रम की इस मात्रा से पूँजीपति $OWPM$ के बराबर मजदूरी देकर $ONPM$ के बराबर आय अर्जित करते हैं, अतः दोनों का अन्तर ($ONPM - OWPM$) = WNP पूँजीपतियों का अतिरेक दर्शाता है। M से आगे की श्रम-मात्रा निर्वाह-मजदूरी प्राप्त करती है।

(iv) पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्थाओं में पूँजीपतियों को कुछ विशेष प्रकार के विनियोगों का अधिक अनुभव होता है—विशेषकर व्यापार व कृषि सम्बन्धी विनियोगों का तथा निर्माण-उद्योगों का अनुभव कम अथवा नगण्य होता है। परिणामतः ये अर्थव्यवस्थाएँ इस अर्थ में असन्तुलित (Lopsided) रहती हैं कि कुछ क्षेत्रों में अनुकूलतम से अधिक (More than optimum) तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में अनुकूलतम से बहुत कम (Much less than optimum) विनियोग किया जाता है। कुछ कार्यों के लिए वित्तीय संस्थाएँ (Financial Institutions) अत्यधिक विकसित होती हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बच रहते हैं जिनको वित्तीय संस्थाओं का सहयोग नहीं मिल पाता है। व्यापार हेतु पूँजी सस्ती मिल सकती है, किन्तु गृह-निर्माण अथवा कृषि के लिए नहीं।

(v) लेविस के अनुसार निर्वाह-मजदूरी की तुलना में पूँजीवादी-मजदूरी 30 प्रतिशत या अधिक होती है। इस अन्तर के प्रभाव को चित्र-2 में प्रदर्शित किया गया है—

चित्र-2



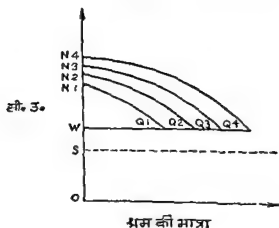
OS = निर्वाह क्षेत्र की प्रति इकाई आय

OIV = पूँजीवादी क्षेत्र की प्रति इकाई आय (वास्तविक)

“समुद्र से उपमा लेते हुए यह कहा जा सकता है कि पूँजीपति-श्रम व निर्वाह-श्रम के मध्य प्रतिस्पर्धा की सीमान्त रेखा अब किनारे के रूप में नहीं, अपितु एक शिखर के रूप में प्रतीत होती है।”¹ (To borrow an analogy from the sea, the frontier of competition between capitalist and subsistence labour now appears not as a beach but as a cliff)

उपरोक्त अन्तर पर पूँजी-निर्माण निर्भर करता है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्त्व इस तत्त्व का है कि पूँजीवादी अतिरेक का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। यदि इसका उपयोग नई पूँजी की उत्पत्ति के लिए होता है तो इसका परिणाम पूँजीवादी क्षेत्र का विस्तार होता है। निर्वाह क्षेत्र से हट कर अधिक सख्या में श्रमिक पूँजीवादी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। इससे पूँजीवादी अतिरेक में और वृद्धि होती है तथा अतिरेक की अधिकता पूँजी-निर्माण की मात्रा को अधिक से अधिकतर करती जाती है। जब तक अतिरिक्त श्रम पूँजीवादी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक यह क्रम क्रियाशील रहता है। इस स्थिति को चित्र-3 में दर्शाया गया है।—

चित्र-3



चित्र-2 के समान OS = निर्वाह-मजदूरी और OIV = पूँजीवादी-मजदूरी। WN_1Q_1 = प्रारम्भिक अतिरेक (Initial Surplus)। चूँकि इसका कुछ भाग पुन विनियोजित कर दिया जाता है, जिससे स्थायी पूँजी की मात्रा में वृद्धि होती है और इसलिए उसकी सीमान्त उत्पादकता N_2Q_2 स्तर तक बढ़ जाती है। इस दूसरी स्थिति में अतिरेक व पूँजीवादी रोजगार दोनों अधिक हो जाते हैं। यह क्रम N_2Q_2 से

N_3O_3 तक तथा N_3O_3 से N_4O_4 तक और इसी प्रकार उस समय तक चलता रहता है, जब तक कि अतिरिक्त श्रम की स्थिति रहती है। तकनीकी

(vi) लेविस के मॉडल में पूँजी, प्राथमिक प्रगति तथा उत्पादकता के सम्बन्धों की विवेचना की गई है। पूँजीवादी क्षेत्र के बाहर तकनीकी ज्ञान की प्रगति से मजदूरी का स्तर बढ़ता है, परिणामस्वरूप पूँजीवादी अतिरिक्त की मात्रा घटती है। किन्तु लेविस की यह मान्यता है कि पूँजीवादी क्षेत्र में ज्ञान-वृद्धि व पूँजी एक ही दिशा में इस प्रकार कार्य करते हैं कि मजदूरी में कोई वृद्धि नहीं होती है, बल्कि राष्ट्रीय आय में लाभो का अनुपात अधिक हो जाता है। नए तकनीकी ज्ञान के व्यावहारिक उपयोग के लिए नया विनियोग आवश्यक है। नया तकनीकी ज्ञान चाहे पूँजी को बचाने वाला हो, चाहे श्रम को, इससे उपरोक्त चित्र में प्रदर्शित स्थिति में कोई अन्तर नहीं आता है। लेविस के मॉडल में 'तकनीकी ज्ञान की वृद्धि और उत्पादक-पूँजी में वृद्धि' एक ही तत्त्व के रूप में मान गए हैं।

पूँजी-निर्माण (Capital Formation)

लेविस ने पूँजी-निर्माण के दो स्रोतों का विवेचन किया है—

- (1) लाभो द्वारा पूँजी-निर्माण, और
- (2) मुद्रा पूर्ति में वृद्धि द्वारा पूँजी-निर्माण।

बचत की बड़ी राशि लाभो से प्राप्त होती है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में बचत का अनुपात बढ़ रहा है तो हम उस अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि वहाँ राष्ट्रीय आय में लाभो का अंश वृद्धि पर है। समान आय वाले दो देशों में से जिस देश में लगानों की तुलना में लाभो का राष्ट्रीय आय में अंश अधिक होता है, वहाँ अपेक्षाकृत वितरण की विषमताएँ कम पाई जाएँगी तथा बचत की मात्रा अधिक होगी। आय की असमानता यदि लगान की तुलना में लाभो का अंश अधिक होने के कारण होती है तो यह स्थिति पूँजी-निर्माण के अधिक अनुकूल मानी जाती है।

नव प्रतिष्ठापित मॉडल (Neo-classical Model) में पूँजी-निर्माण केवल उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन क्षेत्र से साधनों के स्थानान्तरण द्वारा ही सम्भव है किन्तु लेविस के मॉडल में भूमि व पूँजी को वैकल्पिक उपभोगों में से हटाए बिना ही श्रम द्वारा पूँजी-निर्माण सम्भव है तथा उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा को बिना कम किए ही पूँजी-निर्माण किया जा सकता है।

यदि किसी अर्थव्यवस्था में पूँजी का अभाव है, किन्तु कुछ साधन अग्रयुक्त अवस्था में हैं, जिनके प्रयोग से पूँजी-निर्माण किया जा सकता है तो यह अत्यन्त वांछनीय है कि उनके प्रयोग के लिए अतिरिक्त मुद्रा का निर्माण भी आवश्यक हो तो किया जाना चाहिए। अतिरिक्त मुद्रा से किसी प्रकार की अन्य दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है। जिस प्रकार लाभो द्वारा पूँजी-निर्माण से उत्पादन व रोजगार में वृद्धि होती है, उसी प्रकार साख द्वारा वित्तीयकरण में भी

रोजगार व उत्पादन के स्तर बढ़ते हैं। लाभो द्वारा निमित पूँजी व साख द्वारा निमित पूँजी का अन्तर उत्पादन पर प्रभाव के रूप में परिलक्षित नहीं होता किन्तु कीमतों व आय-वितरण पर इस अन्तर का तत्काल प्रभाव होता है।

लेविस के मॉडल में, प्रतिरिक्त श्रम से पूँजी-निर्माण की स्थिति में, विशेषकर जब श्रम का भुगतान प्रतिरिक्त मुद्रा से दिया जाता है, मूल्य बढ़ जाते हैं, किन्तु उपभोग वस्तुओं का उत्पादन स्थिर रहता है। रोजगार में कार्यरत एवं श्रमिकों के बीच उपभोग वस्तुओं का पुन वितरण (Redistribution) अवश्य होता है किन्तु इस प्रक्रिया का अर्थ 'बलपूर्वक बचत' (Forced Saving) के रूप में नहीं लगाया जाना चाहिए। लेविम के मॉडल में नव-प्रतिष्ठापित मॉडल की भाँति 'बलपूर्वक बचत' की स्थिति न होकर बलपूर्वक उपभोग वस्तुओं के पुन वितरण की स्थिति अवश्य विद्यमान है (There is a forced redistribution of consumption, but not forced saving)। जैसे ही विनियोग वस्तुओं के कारण उत्पादन बढ़ने लगता है, उपभोग स्तर भी ऊँचा होने लगता है। लेविस के अनुसार मूल्यों में प्रसार की स्थिति केवल अल्पावधि के लिए रहती है जब तक कि प्रारम्भिक अवस्था में आय तो बढ़ती है किन्तु उपभोग वस्तुओं का उत्पादन नहीं बढ़ता, किन्तु थोड़े समय बाद ज्यों ही पूँजीगत वस्तुएँ उपभोग वस्तुओं का उत्पादन प्रारम्भ कर देती हैं मूल्य गिरने प्रारम्भ हो जाते हैं। लेविस का तो मत इस सम्बन्ध में यह कि "पूँजी निर्माण के लिए मुद्रा प्रसार स्वयं विनाशक होता है और इससे यह भी आशा की जा सकती है कि मूल्य चढ़कर उस स्तर से भी नीचे गिर सकते हैं जहाँ से उन्होंने गिरना शुरू किया था।" इस प्रकार ज्यों ज्यों पूँजी-निर्माण होता है, उत्पादन और रोजगार में निरन्तर वृद्धि होती रहती है। परिणामस्वरूप लाभ बढ़ते हैं, जिन्हें विनियोजित करके पुन पूँजी निर्माण को बढ़ाया जा सकता है और आर्थिक विकास का यह क्रम जारी रहता है। किन्तु विकास की यह प्रक्रिया बन्द अर्थव्यवस्था में अनिश्चित काल तक नहीं चल सकती। निम्नलिखित परिस्थितियों में यह प्रक्रिया रुक जाती है—

- (i) जब पूँजी निर्माण के परिणामस्वरूप प्रतिरिक्त श्रम शेष नहीं रहता।
- (ii) पूँजीवादी विस्तार की तीव्र गति के कारण निर्वाह क्षेत्र की जनसंख्या इतनी कम हो जाती है कि पूँजीवादी व निर्वाह दोनों क्षेत्रों में श्रम की सीमान्त उत्पादकता बढ़कर मजदूरी का स्तर ऊँचा कर देती है।
- (iii) निर्वाह क्षेत्र की अपेक्षा पूँजीवादी क्षेत्र का तीव्र विस्तार, कुपिगत पदार्थों के मूल्यों में इतनी अधिक वृद्धि कर देता है कि व्यापार की शर्तें (Terms of Trade) पूँजीवादी क्षेत्र के प्रतिकूल हो जाती हैं, परिणामस्वरूप, श्रमिकों को अधिक मजदूरी देनी पड़ती है।
- (iv) निर्वाह क्षेत्र में उत्पादन की नई तकनीकी के अपनाए जाने से पूँजीवादी क्षेत्र में भी वास्तविक मजदूरी बढ़ जाती है।
- (v) पूँजीवादी क्षेत्र में यदि श्रम ग्रान्दोलन ऊँची मजदूरी प्राप्त करने में सफल हो जाता है।

उपरोक्त परिस्थितियों में पूँजीवादी अतिरेक पर विपरीत प्रभाव होता है। यदि अन्य देशों में अतिरिक्त श्रम की स्थिति विद्यमान हो तो पूँजीवादी अपने अतिरेक को विपरीत प्रभाव से निम्नलिखित किसी एक विधि से बचा सकते हैं—

जब देश में श्रम की असमीमित पूर्ति की स्थिति समाप्त हो जाती है तो पूँजीवादी असमीमित श्रम वाले अन्य देशों से सम्बन्ध बनाते हैं। वे श्रमिकों का बड़े पैमाने पर आवास करते हैं या पूँजी का निर्यात करने लगते हैं—

(i) श्रमिकों का बड़े पैमाने पर आवास (Mass Immigration)—सैद्धांतिक दृष्टि से यह सम्भव है कि कुशल श्रमिकों का आवास (Immigration) देश के अकुशल श्रमिकों की माँग को घटा सकता है, किन्तु व्यवहार में अत्यन्त कठिन है। अधिक सम्भावना इस बात की है कि इस प्रकार के आवास से नए विनियोगों और नए उद्योगों की सम्भावनाएँ बढ़कर पूर्ति की तुलना में सभी प्रकार के श्रम की माँग में वृद्धि कर सकती है।

(ii) पूँजी का निर्यात करना (Exporting Capital)—दूसरा उपाय ऐसे देशों को पूँजी का निर्यात करना है जहाँ जीवन निर्वाह मजदूरी के स्तर पर पर्याप्त माना में श्रम शक्ति उपलब्ध हो। इससे पूँजी निर्यातक देश में श्रम की माँग कम हो जाती है और मजदूरी की दर गिरने लगती है। यद्यपि इसके परिणामस्वरूप मजदूरी का जीवन स्तर और इस प्रकार वास्तविक मजदूरी बढ़ भी सकती है।

आलोचनात्मक समीक्षा—प्रो. लेविस की उपरोक्त विचारधारा की निम्न आधारों पर आलोचना की जा सकती है—

(i) प्रो. लेविस के सिद्धान्त का आधार अर्द्ध-विकसित देशों में असमीमित मात्रा में श्रम की पूर्ति पर आधारित है किन्तु दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के कई देशों में ऐसी परिस्थितियाँ उपस्थित नहीं हैं। अतः इस सिद्धान्त का क्षेत्र सीमित है।

(ii) लेविस के सिद्धान्त का आधार अर्द्ध-विकसित देशों में उपलब्ध पर्याप्त अकुशल श्रम शक्ति है। उनके विचार से कुशल श्रमिकों का अभाव एक अस्थायी अवरोध उपस्थित करता है जिसे श्रमिकों के प्रशिक्षण आदि के द्वारा दूर किया जा सकता है। किन्तु वस्तुतः पर्याप्त मात्रा में श्रम शक्ति के उचित प्रशिक्षण आदि में काफी समय लगता है और इस प्रकार कुशल श्रम शक्ति की कमी एक बड़ी कठिनाई उपस्थित करती है।

(iii) लेविस का उपरोक्त सिद्धान्त इस तथ्य पर आधारित है कि इन अर्द्ध-विकसित देशों में पूँजीपति वर्ग और उपक्रम (Enterprise) पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है किन्तु अधिकांश अर्द्ध विकसित देशों में इसकी कमी होती है।

(iv) इस सिद्धान्त के अनुसार पूँजीपति वर्ग द्वारा लाभों को विनियोजित करते रहने से पूँजी वचय होता है। इसका प्राणय है कि यहाँ 'विनियोग गुणक' (Investment Multiplier) क्रियाशील रहता है, किन्तु अर्द्ध-विकसित देशों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता।

(v) लेविस के विकास के इस द्वैध अर्थव्यवस्था वाले प्रारूप (Dual Economy Model) में कुल माँग (Aggregate Demand) की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया है। इस सिद्धान्त में यह माना गया है कि पूँजीवादी क्षेत्र में जो कुछ उत्पादन किया जाता है उसका या तो इसी क्षेत्र में उपभोग कर लिया जाता है या निर्यात कर दिया जाता है। किन्तु इससे निर्वाह क्षेत्र को बेचे जाने की सम्भावना है और यदि ऐसा होता है तो विकास की प्रक्रिया पहले ही एक सकती है।

उपरोक्त दोषों के बावजूद भी लेविस के इस विकास-प्रारूप की यह विशेषता है कि इसमें विकास प्रक्रिया को स्पष्ट रूप में समझाया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि पूँजी की कमी और श्रमिकों की बहुलता वाले अर्द्ध-विकसित देशों में पूँजी-मंचय किस प्रकार होता है। इसके अतिरिक्त इस सिद्धान्त के सदस्यों में किए गए 'साख प्रसार' (Credit Inflation) जनसंख्या वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रीय तथा तकनीकी प्रगति सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन भी वास्तविकता लिए हुए है।

हैरड-डोमर मॉडल

(The Harrod-Domar Model)

हैरड और डोमर ने पूँजी-संचय (Capital Accumulation) की आर्थिक वृद्धि के अपने मॉडल में निम्नलिखित चल (Crucial Variable) के रूप में लिया है। पूँजी संचय को वे विनियोग का फलन मानते हैं तथा विनियोग की दो मूलिकाओं की विवेचना करते हैं—(1) विनियोग आय का निमाण करता है, और (2) यह उत्पादन क्षमता (Productive Capacity) में वृद्धि करता है। इन मॉडलों में प्रमुख परिकल्पना यह है कि प्रारम्भ में आय का सतुलित स्तर यदि पूर्ण रोजगार के बिन्दु पर है तो प्रति वर्ष सतुलन के इस स्वायत्तत्व को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि विनियोग द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त कय शक्ति की मात्रा इतनी होनी चाहिए जो विनियोग द्वारा बढ़ाए गए उत्पादन को खपाने (Absorb) के लिए पर्याप्त हो। यदि वास्तविक आय बढ़ती नहीं है, बल्कि स्थिर रहती है तो इस स्थिति के निम्नलिखित प्रभाव होने—

- (1) नई पूँजी अप्रयुक्त रहेगी।
- (2) नई पूँजी का उपयोग पूर्व उत्पादित पूँजी की लागत पर होगा।
- (3) नई पूँजी का धर्म के लिए प्रतिस्थापन किया जाएगा।

इस प्रकार यदि पूँजी संचय के साथ आय में वृद्धि नहीं होती है तो इसका परिणाम यह होगा कि श्रम और पूँजी दोनों ही अप्रयुक्त (Unemployed) रहेंगे। अतः विनियोग वस्तुओं की अधिकता व बेरोजगार श्रम की स्थिति से अर्थव्यवस्था को मुक्त रखने के लिए आय में स्थायी व निरन्तर वृद्धि आवश्यक है। दूसरे शब्दों में जिस समस्या का इन मॉडलों में अध्ययन किया गया है, वह यह है कि क्या कोई ऐसी स्थाई निरन्तर विकास-दर सम्भव है जो दोहरा पूर्ण रोजगार मापदण्ड (The double full employment criterion) की पूर्ति करती है अर्थात् जिसके कारण पूँजी व श्रम के लिए पूर्ण रोजगार की स्थिति कायम रहती है। हैरड व डोमर के मॉडल

समान निष्कर्षों पर पहुँचते हैं, अतः इनका मॉडल संयुक्त रूप में आधारभूत हैरड डोमर मॉडल (Basic Harrod Domar Model) के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल का सामान्य लक्ष्य, पूर्ण क्षमता सम्बन्धी स्टॉक की शर्त (Full Capacity Stock Condition) तथा बचत/विनियोग सम्बन्धी बहाव की शर्त (Flow Condition of Saving/Investment) के साथ वस्तु-बाजार (Product Market) में संतुलन रखना तथा इसके साथ श्रम बाजार के संतुलन को सम्बद्ध करना है।

मान्यताएँ (Assumptions)

हैरड डोमर मॉडल की निम्नलिखित मान्यताएँ हैं—

1. केवल एक प्रकार की वस्तु का उत्पादन होता है अर्थात् कुल आय अथवा उत्पादन एक समरूप प्रकृति अथवा आकृति का होता है (Total income is a homogeneous magnitude)।

2. पूँजी के स्टॉक तथा आय में एक निश्चित तकनीकी सम्बन्ध (a fixed technological relationship) होता है।

3. आय में बचत का अनुपात स्थिर रहता है अर्थात् बचत की औसत प्रवृत्ति व सीमान्त प्रवृत्ति परस्पर समान होती है अर्थात् $APS = MPS$ पूँजी गुणांक (Capital Coefficient) स्थिर रहता है।

4. विनियोग तथा उत्पादन क्षमता की उत्पत्ति के मध्य कोई विशेष समयान्तर (Significant time-lag) नहीं होता है।

5. राष्ट्रीय उत्पादन के केवल दो ही उपयोग होते हैं—

(i) उपभोग (Consumption)

(ii) विनियोग (Investment)

6. केवल एक ही उत्पादन-कारक पर विचार होता है अर्थात् केवल पूँजी का ही विवेचन किया जाता है।

7. पूँजी का ह्रास नहीं होता है अर्थात् पूँजी के स्टॉक की जीवनावधि अनन्त होती है।

8. श्रम शक्ति में एक स्थिर दर (Constant rate) से वृद्धि होती है तथा इस वृद्धि हुई श्रम शक्ति के लिए वस्तु बाजार में पूर्ण माँग रहती है।

9. पूँजी व श्रम दोनों में पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है।

10. विदेशी व्यापार नहीं होता है और न ही किसी प्रकार का राजकीय हस्तक्षेप होता है।

11. हैरड मॉडल में बचत व विनियोग वास्तविक अथवा 'एक्सपोस्ट' (Expost) के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं।

हैरड डोमर मॉडल को पूर्णतः समझने के लिए हैरड व डोमर के मॉडलों का पृथक्-पृथक् विवेचन आवश्यक है।

हैरड-मॉडल (The Harrod Model)

हैरड मॉडल प्रतिष्ठापित सत्य $S=I$ (बचत=विनियोग) के साथ प्रारम्भ होता है। इसे हैरड निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं—

$$GC=S$$

उपरोक्त समीकरण इस तथ्य को प्रतिपादित करता है कि “विकास दर त्वरक और बचत की सीमान्त प्रवृत्ति का अनुपात होती है, अथवा वास्तविक बचत विनियोगों के बराबर होगी।” अतः

एक्सपोस्ट (Expost) अर्थ में वास्तविक विनियोग आवश्यक रूप से प्राप्त बचत (Realized Savings) के बराबर होता है : इस प्रकार

$$SY_t = C(Y_t - Y_{t-1}) \quad (1)$$

प्राप्त विकास दर (Realized rate of growth) को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

$$G = Y_t - Y_{t-1} \quad (2)$$

समीकरण (1) के दोनों पक्षों को CY_t से विभाजित करते हुए—

$$\frac{S}{C} = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_t}$$

और इससे हम निम्न Identity प्राप्त कर लेते हैं—

$$G = \frac{S}{C} \quad \text{or} \quad GC = S$$

हैरड की यह मान्यता है कि एक्सपोस्ट बचतें (Expost Saving) सदैव एक्सएन्टे पूर्ण रोजगार के स्तर (Exante full employment level) के बराबर होगी। किन्तु विनियोजित की जाने वाली राशि स्वयं में इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि प्राप्त विकास-दर के कारण न तो पूँजी का अर्वाञ्छित संचय (Unintended accumulation) ही हो और न ही पूँजी के वर्तमान स्टॉक में ही किसी प्रकार की कमी आए। यदि अर्वाञ्छित संचय होता है तो वास्तविक आय अपेक्षाकृत कम होगी और बचत अर्वाञ्छित स्तर से नीचे गिर जाएँगी, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि द्वारा समस्त वर्तमान विनियोग राशि वा उपयोग नहीं हो सकेगा। पूँजी के अर्वाञ्छित ह्रास की स्थिति में, बचत अर्वाञ्छित स्तर से अधिक होगी और उत्पादक यह अनुभव करने लगेंगे कि उत्पादन में वृद्धि के अनुपात में, उन्होंने पर्याप्त विनियोजन नहीं किया है। किन्तु यदि हम यह मानते हैं कि $S_t = S_t^1$ तो उत्पादकों द्वारा किया जाने वाला विनियोजन उत्पादन में वृद्धि की दृष्टि से उचित प्रमाणित होगा। इस औचित्य के कारण वे त्वरक C_t के अनुरूप विनियोजन करना चाहेंगे, जो विनियोग की गत समानुपाती दर C (Past Proportional rate C) के बराबर होगा, क्योंकि वे वास्तव में प्राप्त विकास दर के बराबर भावी विकास दर को जारी रखना चाहते हैं। इसलिए भावी वास्तविक विकास दर आवश्यक विकास दर के रूप में जारी रहेगी। इस प्रकार, जब तक $C_t = C$, तब तक प्राप्त विकास दर (G) अर्वाञ्छित विकास दर (G_w or Warranted Growth Rate) के बराबर होगी। इस सम्पूर्ण व्यवस्था

को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है, $C_t = C$, तब $G = G_{\infty}$ तथा सभी अपेक्षाएँ इसमें पूरी होती हैं। अब

$$G = \frac{S}{C} = \frac{Y_t + Y_{t+1}}{Y_t} \text{ और } G_{\infty} = \frac{S}{C_t} = \frac{Y_{t+1} - Y_t}{Y_{t+1}}$$

जब $G = G_{\infty}$, तब $G_{t+1} = G_t$

$G = G_{\infty}$ होने पर, व्यवस्था इस प्रकार के विकास पथ से बच जाती है जिससे उत्पादन में परिवर्तन की वास्तविक दर के कलन के रूप में विनियोग सदैव उत्पादन के वर्तमान स्तर पर प्राप्त बचतों के बराबर होगा।

सन्तुलन की आवश्यकताओं को पुनः निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है—

$$\frac{\Delta Y}{Y} \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{S}{Y}$$

$$\text{जो } GC = S \text{ अथवा } \frac{\Delta K}{Y} = \frac{S}{Y} \text{ है}$$

अब चूँकि $\frac{\Delta K}{\Delta Y}$ वह पूँजी स्टॉक है, जो उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि के लिए आवश्यक है, अन्य शब्दों में वांछित विनियोग की यह वह राशि है, जो वर्तमान बचत के बराबर होनी चाहिए। इसलिए इसे हम निम्न प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं—

$$\frac{\Delta K}{Y} = \frac{I}{Y} = \frac{S}{Y}$$

सन्तुलन मार्ग की सन्तुष्टि के लिए आवश्यक शर्तों से सम्बन्धित विभिन्न विधियों (Approaches) को निम्नलिखित सारणी में स्पष्ट किया गया है।

सारणी-1 सन्तुलन शर्तें (Equilibrium Conditions)¹

शर्त (Condition)	संरचनात्मक प्राचल (Structural Parameters)			वांछित विकास दर (Required Growth Rate)		
	$\frac{S}{Y}$	$\frac{\Delta K}{\Delta Y}$	$\frac{\Delta Y}{Y}$	$\frac{S}{Y}$	$\frac{\Delta K}{\Delta Y}$	$\frac{\Delta Y}{Y}$
(1) $\frac{S}{Y} = \frac{\Delta Y}{Y} \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{\Delta K}{Y}$, $S = I$			4	0.05	0.20	
(2) $\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\frac{S}{Y}}{\frac{\Delta K}{\Delta Y}}$, $G = \frac{S}{C}$	0.20	4				0.05
(3) $\frac{\Delta K}{Y} = \frac{\frac{S}{Y}}{\frac{\Delta Y}{Y}}$, $C = \frac{S}{G}$	0.20		0.05		4	

सारणी-1, पैनाल 1 में, विकास दर या आय वृद्धि $= 0.05$ प्रति अवधि और सीमान्त पूँजी-प्रदा अनुपात $= 4$ होने पर, इस विकास दर को बनाए रखने के लिए, बचत और विनियोग आवश्यक होंगे $= 20 / [1 - 4(0.05)] = 0.20 = S$ यदि इस राशि से कम या अधिक बचत रहती है तो तरुणरूप ही आय में वृद्धि की दर 5% से अधिक अथवा कम रहेगी, परिणामस्वरूप, विनियोगों का परिवर्तन अनिवार्य होगा और इस परिवर्तन के कारण विकास दर भी बदल जाएगी।

पैनाल 2 के अनुसार, यदि संरचनात्मक प्राचल (Structural Parameters) अर्थात् बचत $\left(\frac{S}{Y}\right)$ और सीमान्त पूँजी प्रदा अनुपात $\left(\frac{\Delta K}{\Delta Y}\right)$ दिए हुए होते हैं तो विकास दर ज्ञात हो जाती है ($\text{i.e. } G = \frac{20}{4} = 0.05$)। इस विकास दर का स्थायी बने रहना प्राचलों के स्थायित्व (Stability) पर निर्भर करता है।

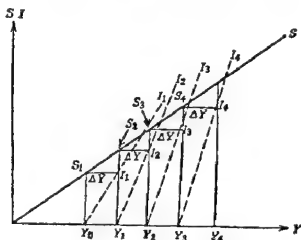
पैनाल 3 के अनुसार, यदि कोई भी दो चल (Variables) दिए हुए होते हैं, तो आवश्यक तीसरा चल ज्ञात किया जा सकता है। जैसे $\frac{S}{Y}$ अथवा I (विनियोग) $= 20$ तथा विकास दर $\left(\frac{\Delta Y}{Y} \text{ or } G\right) = 0.05$ दिए हुए हैं। इनकी सहायता से तीसरा चल सीमान्त पूँजी प्रदा अनुपात $\left(\frac{\Delta K}{\Delta G}\right)$ इस प्रकार ज्ञात किया गया है— $\frac{20}{0.05} = 4$

उपरोक्त सन्तुलन-पथ की पूर्ण रोजगार-पथ के रूप में विवेचना इसलिए नहीं की गई है क्योंकि यह मान्यता आवश्यक नहीं है कि केवल पूर्ण रोजगार की अवस्थाओं के अन्तर्गत ही स्थायी व निरन्तर विकास दर की विशेषताओं (Properties) का स्वतः संचालन सम्भव होता है। उदाहरणार्थ हिक्स की $E E$ रेखा (Hicksian $E E$ line) पूर्ण रोजगार से पूर्व-स्थिति में भी स्थायी विकास (Steady growth) को दर्शाती है। पूर्ण रोजगार की मान्यता के लिए प्रारम्भिक शर्तें (Initial condition) के रूप में यह मान कर चलना आवश्यक है कि $G =$ पूर्ण रोजगार के है, अथवा हैरड की शब्दावली में यह कहा जाना चाहिए कि $G = G_n$ G_n का आणव्य स्वाभाविक विकास दर (Natural Growth Rate) से है। यह वह दर (Rate of advance) है जिसकी अधिकतम सीमा जनसंख्या की वृद्धि और तकनीकी सुधारों पर आधारित होती है। इसे एक अन्तिम उच्चतम विकास दर (Ceiling Growth Rate) के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जो G के अधिकतम औसत मूल्य की सीमा निर्धारित करती है। $G = G_w = G_n$ सन्तुलन मार्ग के निर्धारण के लिए हमको न केवल स्वतन्त्र रूप से निर्धारित S और C चलों के ही संयोग को लेना चाहिए बल्कि साथ ही यह भी निश्चित कर लेना चाहिए कि विकास की यह दर तथा वह दर जिससे श्रम शक्ति में वृद्धि होती है,

परस्पर बराबर हैं। श्रम शक्ति की वृद्धि दर अधिकतम उत्पादन की वृद्धि से स्वतन्त्र होती है। इसका निर्धारण डेमोग्राफिक शक्तियों द्वारा होता है।

ज्यामितीय विश्लेषण द्वारा इस स्थिति को और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है।

चित्र-4



मॉडल का ज्यामितीय विश्लेषण

(Geometric Analysis of the Model)¹

चित्र-4 में Y_0 से Y_1 तक उत्पादन में परिवर्तन (ΔY) प्रेरित (Induced) विनियोग की Y_1 पर वास्तविक राशि $= I_1 = S_1 (Y_1)$ होगी। विनियोग की इस राशि से उत्पादित आय $= Y_2$ होगी। पुनः उत्पादन में परिवर्तन $= Y_2 - Y_1 = \Delta Y_2$ से प्रेरित विनियोग की राशि $I_2 = S_2 (Y_2)$ होगी। टूटी हुई विनियोग रेखा (Dashed Investment Line) तथा Y-अक्ष के समानान्तर दोस रेखा का कटाव बिन्दु (Intersection point) उस आवश्यक विनियोग को प्रदर्शित करता है जो आय वृद्धि के कारण किया जा रहा है (i.e., it indicates the required investment that is forthcoming)। यदि हम विनियोग गुणांक (Investment coefficient) में किसी परिवर्तन के न होने की मान्यता लेते हैं तो वृद्धि का अनुपात जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक वृद्धि दर उत्पादन अथवा आय में होनी चाहिए जिससे सन्तुलन के लिए पर्याप्त विनियोग प्रेरित हो सके।² (The greater the proportion of savings the greater must the rate of increase in output be to induce sufficient investment to maintain Equilibrium, if we assume no change in the investment coefficient)

1 H Pitman A Geometric Analysis of Recent Growth Models AER 42, Sept, 1952 pp 594-595

2 Ibid p 261

सारणी-2 में उन विभिन्न विकास दरों को दर्शाया गया है जो S और C (S =बचत की सीमान्त प्रवृत्ति और C =पूँजी-प्रदा अनुपात) के विभिन्न संयोगों (Different Combinations) पर आवश्यक होती हैं।

सारणी-2. भिन्न शर्तों के अन्तर्गत आवश्यक विकास दर¹
(Required Growth Rate under Different Combinations)

S	C			
	$\frac{1}{2}$	1	4	10
0	0	0	0	0
0.10	0.20	0.10	0.025	0.01
0.20	0.40	0.20	0.05	0.02

यदि $S=10$ और $C=\frac{1}{2}$ हो तो $G=20$ होगी, किन्तु $S=20$ होने पर G (ie $=20$) को स्थिर रखने के लिए C को $\frac{1}{2}$ से बढ़ाकर 1 किया जाना आवश्यक होगा। परन्तु यदि हमको सारणी का विश्लेषण उत्पादन में आवश्यक वृद्धि-दर के रूप में करना है, तो बचत का अनुपात $=10$ के दिए हुए होने पर, पूँजी-प्रदा-अनुपात में $\frac{1}{2}$ की कमी, अर्थात् 1 से $\frac{1}{2}$ होने की स्थिति में, सन्तुलन कायम रखने के लिए विकास दर में 100 प्रतिशत वृद्धि आवश्यक होती है। अर्थात् किसी दी हुई औसत बचत प्रवृत्ति (APS) का त्वरक गुणांक (Acceleration Coefficient) जितना कम होगा, उतना ही अधिक पूर्ण रोजगार की स्थिति बनाए रखने के लिए पर्याप्त विनियोग को प्रेरित करने के उद्देश्य से विकास-दर को ऊँचा रखना होगा। इसके अतिरिक्त, जैसा कि सारणी में प्रदर्शित किया गया है, जितना ऊँचा गुणांक (C) होगा, उत्पादन में वृद्धि दर उतनी कम होगी—यथा जब $C=\frac{1}{2}$, तब $G=40$ है और जब $C=10$ है तब $G=0.2$ है। उदाहरणार्थ, विनियोग फलन जितना अधिक लेटा हुआ (Flatter) है, उतना ही अन्तर Y के स्तरों में पाया जाता है, बशर्ते कि, $S=I$ हो।

डोमर मॉडल (The Domar Model)

हैरड के मॉडल को सरलता से डोमर के मॉडल में परिवर्तित किया जा सकता है। दोनों के ही मॉडल यह प्रतिपादित करते हैं कि पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के लिए, पूर्ण रोजगार के स्तर वाली आय से प्राप्त वांछित बचत की राशि वांछित विनियोगों के बराबर होनी चाहिए। डोमर मॉडल का मूल प्रश्न यह है कि बढ़ते हुए पूँजी संचय से प्रतिफलित बढ़ती हुई उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए किस दर से अर्थव्यवस्था का विकास किया जाना चाहिए? इसके विपरीत हैरड मॉडल में अन्तर्निहित प्रश्न इस प्रकार है कि अर्थव्यवस्था में किस दर

1 Paul A. Samuelson 'Dynamic Process Analysis', Survey of Contemporary Economics, H S Ellis (Ed.), AEA-Series, p 362

से वृद्धि होनी चाहिए कि विनियोजक विनियोजन की अपनी वर्तमान दर को जारी रखने में औचित्य का अनुभव करें। डीमर जहाँ बदलती हुई उत्पादन-क्षमता के तकनीकी प्रभाव से सम्बन्ध रखते हैं, वहाँ हैरड अपने को मूलतः विनियोग निर्णयों पर केन्द्रित रखते हैं।

मॉडल की विवेचना (Interpretation of the Model)

उक्त मॉडल में—

σ = उत्पादन क्षमता में वृद्धि + नए विनियोग की राशि। सामान्यतः σ का मूल्य विनियोग के मूल्य से भिन्न होगा क्योंकि नई उत्पादन-क्षमता के एक अंश के लिए वर्तमान सुविधाएँ (Existing facilities) उत्तरदायी होती हैं। इस प्रकार—

$I\sigma$ = ग्रंथव्यवस्था की 'उत्पादन सम्भावना' (Productive Potential)

I में परिवर्तन से गुणक द्वारा कुल मांग (Aggregate demand) में परिवर्तन होता है, जिसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है—

$$\Delta Y = \frac{1}{S} \Delta I,$$

जहाँ $\frac{I}{S}$ = गुणक, ΔI = विनियोग में परिवर्तन, ΔY = मांग में वृद्धि,

S = बचत की सीमान्त प्रवृत्ति या MPS विनियोग में परिवर्तन तथा साथ ही, उत्पादन-क्षमता में भी वृद्धि उत्पन्न करता है, जिसे $I\sigma$ से दर्शाया जाता है। व्यवस्था में उत्पादन-क्षमता में न आधिक्य की स्थिति रहे और न शून्यता की, इसके लिए कुल मांग व कुल पूर्ति की सापेक्ष वृद्धि दरें, स्थिर रहनी चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि—

$$\Delta I \frac{I}{S} = \sigma I$$

उपरोक्त समीकरण के दोनों पक्षों को S से गुणा करते हुए और I से विभाजित करने पर प्राप्त परिणाम होगा—

$$\frac{\Delta I}{I} = \sigma S$$

इस समीकरण से स्पष्ट है कि पूर्ण क्षमता के उपयोग का सतुलन मार्ग तभी बना रह सकता है, जबकि विनियोग में सापेक्ष परिवर्तन की दर विनियोग की उत्पादकता दर के बराबर रहती है। यदि यह दर कम है अर्थात् जब $\frac{\Delta Y}{Y} < \sigma S$ परिणाम अतिरिक्त क्षमता की उत्पत्ति होगा। आय का वर्तमान पर्याप्त स्तर कल और भी अधिक आय के स्तर की आवश्यकता पैदा करेगा। ग्रंथव्यवस्था के निर्वाध गति से चलने रहने के लिए विनियोग दर का तीव्र गति से निरंतर बढ़ते रहना आवश्यक होगा।

मॉडल का गणितीय उदाहरण (Numerical Example of the Model)¹

यदि हम यह मानते हैं कि $S=0.25$ और $\sigma=0.10$ तो \$ 10 के नए विनियोग से \$ 1 के बराबर नयी उत्पादन क्षमता का निर्माण होता है। निम्नलिखित सारणी में $t=1$ अवधि से सतुलन की स्थिति प्रारम्भ करते हुए, हम देखते हैं कि यदि विनियोग में $\sigma S=2.5\%$ की वांछित दर से वृद्धि होती है तो प्रत्येक अवधि में उत्पादन क्षमता की वृद्धि को पूर्ण उपयोग में रखने के लिए, आय में जो परिवर्तन होता है, वह पर्याप्त होगा। दूसरी अवधि में पूँजी का स्टॉक $400(0.025)=\$10$ से बढ़ता है, जिसके कारण उत्पादन क्षमता में $10(0.10)=1$ की वृद्धि होती है। $t=2$ अवधि में 2.5% की दर से विनियोग बढ़कर 10.25 हो जाता है। इस विनियोग से वास्तविक माँग में जो वृद्धि होगी, वह बढ़ी हुई क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए आवश्यक है, किन्तु इस प्रक्रिया के क्रम में $t=3$ अवधि में पूँजी का स्टॉक बढ़कर 420.25 हो जाता है तथा उत्पादन-क्षमता 1.025 से बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई उत्पादन-क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए विनियोग 2.5% की दर से बढ़कर 10.506 हो जाएगा। इस प्रकार जब तक विनियोग में वांछित दर से वृद्धि जारी रहनी है, पूर्ण क्षमता वाला पथ सतुलित बना रहता है (The full capacity path is maintained as long as investment keeps rising at the required rate).

सारणी के पैनल B में विनियोग स्थिर रहता है। इस स्थिति में हम यह देखते हैं कि प्रत्येक अवधि में उत्पादन क्षमता (Output Capacity) और वास्तविक माँग (Actual Demand) का अन्तर बढ़ना जाता है। यह स्थिति डोमर के मूल दृष्टिकोण को इन शब्दों में स्पष्ट करती है, 'जब प्रत्येक अवधि में विनियोग और आय स्थिर रहते हैं, तब क्षमता निरन्तर बढ़ती जाती है। इस क्रम में एक ऐसा बिन्दु आ पहुँचेगा जिस पर साहसियों की अपेक्षित प्रत्याशाओं (Anticipations) के पूरा न होने पर, विनियोग में गिरावट की प्रवृत्ति प्रारम्भ होने लगती है। इस प्रकार विकास क्रम की समाप्ति विनियोगों में गिरावट लाने के लिए पर्याप्त है (Thus a cessation of growth is sufficient to cause a decline)।'

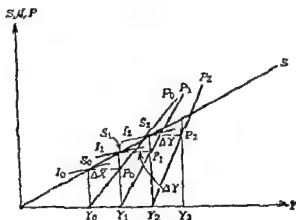
पैनल C के अनुसार विनियोग में वृद्धि की धीमी दर से उत्पादन क्षमता में अतिरेक की स्थिति उत्पन्न होती है; पूर्ति और माँग में अन्तर स्पष्ट होता जाता है, क्योंकि विनियोग में 2.5% के स्थान पर केवल 1% से ही वृद्धि होती है।

डोमर मॉडल की स्थितियाँ (The Domar Model Conditions)¹

t	पूँजी का स्टॉक (Capital Stock)	क्षमता-उत्पादन (Capacity Output) पूर्ति (Supply)	माँग (Demand)	उपभोग (Consumption)	वित्तियोग (Investment)
टैबल A					
1	400	40	40	30	10
2	410	41	41	30.75	10.25
3	420.25	42.025	42.025	31.518	10.506
टैबल B					
1	400	40	40	30	10
2	410	41	40	30	10
3	420	42	40	30	10
टैबल C					
1	400	40	40	30	10
2	410	41	40.4	30.3	10.1
3	420.1	42.01	40.8	30.6	10.2

डोमर-मॉडल के सतुलन-माँग को निम्न चित्र द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है—

चित्र 5



चित्र-5 में I_0 और S का कटाव बिन्दु (Intersection point) आय का पूर्ण क्षमता स्तर (Full capacity level of income) प्रदर्शित करता है। इसके

1 H Pitva, op cit, quoted from Stanley Bober, op cit, p 267

प्रतिरिक्त, टूटी हुई लम्बवत् रेखा (The vertical dashed line) I_0 विनियोग के परिणामस्वरूप S_0P_0 मात्रा से बढ़ी हुई उत्पादन-क्षमता को प्रदर्शित करती है। उत्पादन क्षमता में इस वृद्धि के कारण आय में भी इसी दर से वृद्धि आवश्यक हो जाती है। जब विनियोग I_0 से बढ़कर I_1 हो जाता है तब जिस दर से आय बढ़ती है, उससे $I_1 S_1$ पर नया सतुलन स्थापित हो जाता है। इस नए सतुलन पर आय वृद्धि की सीमा S_2P_2 हो जाती है तथा विनियोग राशि में भी वांछित परिवर्तन आवश्यक हो जाता है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि—

1 क्षमता गुणांक (Capacity coefficient) जितना कम होता है अथवा क्षमता रेखा (Capacity Line) का ढाल जितना अधिक (Steeper) होता है, विनियोग मात्रा में उतना ही कम परिवर्तन आवश्यक होता है।

2 किसी दिए हुए क्षमता गुणांक पर, बचत रेखा जितनी ढालू होगी जितनी अथवा जितनी अधिक बचत की सीमान्त प्रवृत्ति होगी, विनियोग राशि उतनी ही अधिक सतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक होगी।

3 जिस प्रकार हैरड मॉडल में जब एक बार आवश्यकता सतुलन के मांग से हट जाती है तब बचत फलन और विनियोग फलन में परिवर्तन के मध्य नीति-विकल्प (Policy Choices) रहते हैं, किन्तु डोमर मॉडल हमको σ तत्त्व के रूप में विनियोग के लिए तकनीकी आधार के प्रति सतर्क करता है।

दोनों मॉडल में परस्पर सम्बन्ध

(Relation between two Models)

डोमर मॉडल में

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \Delta I \left(\frac{I}{S} \right) = \text{Demand (मांग)}$$

$$\frac{\Delta I}{I} = \sigma I = \text{Supply (पूर्ति)}$$

$$\text{और } \frac{\Delta Y}{Y} = \sigma I = G_r \text{ (Required Growth Rate)}$$

इस प्रकार के सतुलन मार्ग में $S=I$ होता है। यदि I से S अधिक या कम होता है तो इसका परिणामस्वरूप आवश्यक स्तर से कम अथवा अधिक उत्पादन क्षमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है अथवा विनियोग दर बहुत अधिक अथवा बहुत कम रहती है। डोमर साहसियों को कोई ऐसा व्यवहार करने का सुझाव प्रस्तुत नहीं करते हैं, जो उनके लिए विनियोग की मात्रा के उचित परिवर्तन की निश्चयात्मकता का आधार बनता हो। वे केवल उस राशि का उल्लेख करते हैं जिससे विनियोग की मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए।

हैरड मॉडल में—

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \Delta I \left(\frac{I}{S} \right) = \text{Demand (मांग)}$$

$$\frac{\Delta I}{I} = \frac{S}{C} = \text{Supply (पूर्ति)}$$

$$\text{और } \frac{\Delta Y}{Y} = \frac{S}{C_r} = G_w \text{ (Warranted Rate of Growth)}$$

इस प्रकार के सतुलन में $S = I = C_r$, यदि $I > S$ है तो साहसी अपने गत विनियोग निरूपणों पर असंतुष्ट होते हैं इसलिए विनियोग को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं। हैरड साहसियों के लिए इस प्रकार के आचरण अथवा कार्य करने की प्रेरणा प्रस्तुत करते हैं, जिसके करने पर विकास की उचित दर जारी रहती है और विकास की इस दर के फलस्वरूप विनियोग में उचित परिवर्तन स्वतः प्रेरित होता है, जबकि डोमर मॉडल में विनियोग की उचित राशि एक बाह्य चल या तत्त्व (Exogeneous Variable or Element) के रूप में प्रयुक्त होती है।

दोनों के सतुलन भागों को परस्पर सम्बन्धित करते हुए हम यह पाते हैं कि डोमर-मॉडल की निरंतर बढ़ती हुई उत्पादन-क्षमता, प्रेरित विनियोग की उचित राशि का परिणाम होती है, अर्थात्

$$\frac{\Delta I}{I} = \sigma I = \frac{S}{G_r}$$

और विकास की वह दर भी जो क्षमता को बढ़ाने करती है, साहसियों के गत निरूपणों के औचित्य को प्रमाणित करती है, अर्थात्

$$G_r = G_w = G.$$

मॉडल की अर्थ-विकसित क्षेत्रों के लिए व्यावहारिकता (Applicability of the Models for UDCs)

प्रथम, मॉडल में 'अस्थायित्व' (Instability) की समस्या वास्तव में अर्थ-विकसित देशों की नहीं बल्कि विकसित देशों की समस्या है। अर्थ-विकसित देशों की समस्या स्वयं 'आर्थिक वृद्धि' (Growth) है।

द्वितीय, इस मॉडल में 'सैक्यूलर स्टेगनेशन' (Secular Stagnation) की विवेचना की गई है, जो कम आय वाले देशों की विशेषताओं के प्रत्यक्ष नहीं आता है।

इसके अतिरिक्त ये प्रयुक्त चल अवयववस्था के समष्टि स्वरूप को दर्शाते हैं। समूहों (Aggregates) के आधार पर निर्मित मॉडल क्षेत्रों के मध्य अन्तःसम्बन्धों को प्रदर्शित नहीं कर सकता है इसलिए अर्थ-विकसित देशों की अन्य अवस्थाओं में विकासजन्य-संरचनात्मक परिवर्तनों को प्रस्तुत करने में अनुपयुक्त होता है।

अधिकतम ये मॉडल मान्यताओं एवं Abstractions पर आधारित हैं, इसलिए यथार्थता से दूर हैं।

उत्पादन फलन को स्थिर माना गया है, इसलिए उत्पादन-कारकों में परस्पर प्रतिस्थापन के लिए इन मॉडलों में कोई स्थान नहीं है।

यद्यपि अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए इन मॉडलों की व्यावहारिकता बहुत कम है, तथापि कुल मिलाकर आय, विनियोग और बचत के लक्ष्यों के सम्बन्ध में एक उचित जानकारी प्रदान करने में बड़े उपयोगी है। साथ ही इन लक्ष्यों की पारस्परिक अनुकूलता (Consistency) के परीक्षण हेतु भी ये मॉडल उपयुक्त समझे जाते हैं। कम आय वाले देश मुद्रा-प्रसार के प्रति बड़े Susceptible होते हैं, इस तथ्य की विवेचना भी इन मॉडलों में की गई है। इन देशों में विनियोग-दर में अल्प वृद्धि के परिणाम अथवा प्रभाव अत्यधिक तीव्र होते हैं, क्योंकि प्रारम्भिक विनियोग दर एवं विकास-दर बहुत निम्न होती है। इस तथ्य का प्रतिपादन भी इन मॉडलों में समुचित रूप से किया गया है। इस प्रकार, मूलतः विकसित अर्थव्यवस्थाओं से सम्बन्धित होते हुए भी हैरड डोमर मॉडल की अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए उपयोगिता है।

हिक्स द्वारा हैरड-मॉडल की समालोचना (Hicks's Comments on Harrod Type Macro Dynamics)

प्रो हिक्स के शब्दों में, “किसी ऐसी अर्थव्यवस्था की क्रियाओं को, जिसमें सम्पूर्ण विनियोजन प्रेरित विनियोजन होता है, सम्भक्त एक दिलचस्प स्थिति है।” प्रो हिक्स ने हैरड डोमर मॉडल की निम्नलिखित समालोचनाएँ प्रस्तुत की हैं—

1 पूँजी की समरूपता (Homogeneity of Capital) की मान्यता अनावश्यक है। यदि हम इसे मान भी ले तब भी $K_t = K_t^*$ (K_t = पूँजी का प्रारम्भिक स्टॉक और K_t^* = पूँजी का वांछित स्टॉक) स्टॉक सन्तुलन की पर्याप्त शर्त न होकर, केवल एक आवश्यक शर्त है, क्योंकि योग (Aggregates) समान हो सकते हैं, किन्तु कुछ पूँजीयों के वास्तविक स्टॉक का कुछ अथवा सभी उद्योगों में वांछित स्तर से अधिक तथा कुछ अन्य उद्योगों में वांछित स्तर से कम होना संभव है।

2 प्रति अवधि में बचत गुणांक (S) को स्थिर मानना भी तर्क-युक्त नहीं है। मॉडल के बीजगणितीय स्वरूप में यह अन्तर्निहित है कि अवधि के प्रारम्भ व अन्त में पूँजी-प्रदा अनुपात बही रहता है, किन्तु सामान्यतः वांछित पूँजी-उत्पादन पर आश्रित रहना आवश्यक नहीं है।

3 हैरड की G_w (Warranted Rate of Growth) सन्तुलन-मार्ग के निर्धारण के लिए पर्याप्त नहीं है। $GC = S$ केवल एक बहाव शर्त (Flow Condition) है, क्योंकि हैरड मॉडल में पूँजी का कोई ऐसा भाग नहीं है जो स्वतः निर्धारित होता हो, इसलिए एक निर्यादिक सन्तुलन-पथ के लिए कुछ अधिक सरलीकरण (Simplification) की आवश्यकता है।

4 हैरड मॉडल को अधिक अर्थयुक्त बनाने हेतु यह शर्त आवश्यक है कि $C^* > S$ (C^* = पूँजी-प्रदा अनुपात और S = बचत गुणांक) यदि विचाराधीन अवधि केवल एक माह है, C^* काफी बड़ा होना चाहिए, किन्तु यदि अवधि दीर्घ हो तो यह शर्त $C^* > S$ बहुत कम संतुष्ट हो सकेगी। परन्तु यह स्पष्ट है

कि $C^* > S$ की शर्त मॉडल में आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण विचार है, क्योंकि 'हैरड मॉडल की अस्थायित्वता (Instability) सम्बन्धी केन्द्रीय स्थिति' इसी पर निर्भर करती है।

5. आय के साथ-साथ बचत में वृद्धि की प्रवृत्ति को प्रकट करने का अन्य विकल्प उपभोग विलम्बन (Consumption Lags) के माध्यम द्वारा हो सकता है। अतः यदि हम इस मान्यता को छोड़ दें कि वांछित पूँजीगत अवधि के उत्पादन पर निर्भर करती है तब भी 'अस्थायित्वता' (Instability) के प्रमाण पर कोई गहरा प्रभाव नहीं होगा।

6. हैरड ने G_n (Natural Growth Rate) की परिकल्पना विकास की इसी उच्च-दर के रूप में की है, जिसकी अधिकतम सीमा निर्धारण श्रम-पूर्ति की उच्चतम सीमा (Ceiling) करती है। हैरड के अनुसार श्रम-पूर्ति की इस सीमा के उपरान्त उत्पादन का विस्तार आगे नहीं हो सकेगा, बल्कि उत्पादन में कमी की प्रवृत्ति पैदा होगी, किन्तु यह आवश्यक नहीं है। वास्तव में, श्रम-पूर्ति की अधिकतम सीमा के आ जाने के पश्चात्, पूँजी-प्रदा अनुपात बढ़ने लगेगा और श्रम के रोजगार में वृद्धि न होने की स्थिति में भी उत्पादन का विस्तार जारी रह सकता है। श्रम-पूर्ति के स्थिर रहते हुए पूँजी की मात्रा में वृद्धि द्वारा उत्पादन का विस्तार किए जाने की सम्भावना पर नव-प्रतिष्ठापित अर्थशास्त्रियों (Neo-classical Economists) द्वारा विचार किया गया है। इस सम्बन्ध में कैल्डोर (Kaldor) का नाम उल्लेखनीय है।

जॉन रॉबिनसन द्वारा समालोचना

(A Comment by John Robinson)¹

1. जॉन रॉबिनसन का $G = \frac{S}{V}$ के सम्बन्ध में मत है कि पूँजी से प्राप्त लाभ (π) S और V को प्रभावित करता है। अतः विभिन्न लाभ-दरों की स्थिति में विकास-दर कोई एक न होकर अनेक हो सकती है।

एक विकास-दर के स्थान पर विभिन्न लाभ-दरों के अनुरूप अनेक विकास-दरों की सम्भावना का उत्तर देते हुए हैरड ने कहा है कि यद्यपि एक गतिशील संतुलन की अवस्था में (In a State of Dynamic Equilibrium) एक से अधिक लाभ-दरों की सम्भावना को अस्वीकारा नहीं जा सकता है, तथापि हैरड इसे एक असामान्य स्थिति मानते हैं।

2. जॉन रॉबिनसन के अनुसार पूरी अवधि के दौरान स्थिर रहने वाली विकास-दर अर्थात् $G = \frac{I}{K}$ होती है। हैरड के अनुसार इसका तात्पर्य है कि सीमान्त पूँजी-प्रदा अनुपात, अर्थव्यवस्था में दीर्घत पूँजी-प्रदा अनुपात के समान होता है किन्तु हैरड इस मान्यता को असंगत मानते हुए, रॉबिनसन की विरासत-दर

1 John Robinson : "Harrod After Twenty One Years". Sept. 1970, Vol LXXX, p 731

ie $G = \frac{I}{K}$ की अवधारणा को अस्वीकार करते हैं।

3 तीसरी आलोचना है कि हैरड मॉडल में यह मान्यता ली गई है कि 'सम्पूर्ण शुद्ध लाभ परिवारों में वितरित होता है।' किन्तु इस आलोचना का उत्तर देते हुए हैरड का मत है कि अपने मॉडल में उन्होंने इस प्रकार की मान्यता की कही भी किसी प्रकार से कल्पना नहीं की है।

निष्कर्ष (Conclusion)

हैरड-डोमर मॉडल के विश्लेषण का सारांश निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

1. स्थायी व निरन्तर विकास की समस्या में विनियोजन की भूमिका केन्द्रीय होती है।

2. बड़ी हुई उत्पादन क्षमता के परिणामस्वरूप अधिक उत्पादन अथवा अधिक बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह स्थिति आय के व्यवहार पर निर्भर करती है।

3. आय के व्यवहार के लिए ऐसी शर्तों की कल्पना की जा सकती है, जिनके अन्तर्गत पूर्ण रोजगार की स्थिति को कायम रखा जाना सम्भव है।

4. डोमर के अनुसार सन्तुलन-विकास-दर गुणक के आकार तथा भए विनियोग की उत्पादकता पर निर्भर करती है। यह बचत की प्रवृत्ति गुणा त्वरक के विलोम के बराबर होती है। अतः यदि पूर्ण रोजगार को बनाए रखना है तो संचय ब्याज-दर से आय में वृद्धि होना आवश्यक है।

5. व्यापार चक्रों को स्थायी आर्थिक वृद्धि के मार्ग में एक विचलन के रूप में विचारा गया है।

महालनोबिस मॉडल (The Mahalanobis Model)

महालनोबिस मॉडल विकास-नियोजन (Development-planning) का एक चार क्षेत्रीय अर्थमिति मॉडल (A four Sector Econometric Model) है। मॉडल का निर्माण अर्थमिति की सकाय प्रणाली (Operational-System) द्वारा किया गया है। मॉडल में कुछ सीमा दशावरो (Boundary-Conditions) तथा संरचनात्मक प्राचल (Structural Parameters) व साथ ही कुछ साधन-चलो (Instrument-Variables) एवं लक्ष्य-चलो (Target-Variables) के एक समूह का प्रयोग किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को चार क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है (1) विनियोग वस्तु क्षेत्र (The Investment Goods Sector), (2) फॅक्टरी उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र (The Factory Consumer Goods Sector), (3) लघु-इकाई उत्पादन क्षेत्र अथवा घरेलू उद्योग क्षेत्र (Small Unit Production Sector or House-hold Industries' Sector), तथा (4) सेवा उत्पादन क्षेत्र (The Sector Producing Services)। इन क्षेत्रों के लिए क्रमशः K, C_1, C_2, C_3

चिह्नो (Symbols) को प्रयोग में लिया गया है। आय-निर्माण (Income Formation), रोजगार-वृद्धि (Employment Generation) तथा बचत व विनियोग की विधि (The Pattern of Saving and Investment) की दृष्टि में इन क्षेत्रों में परस्पर सरचनात्मक सम्बन्धों (Structural Relations) को देखा गया है। महालनोबिस के इस चार क्षेत्रीय अर्थमिति मॉडल का निर्माण सन् 1955 में हुआ। इससे पूर्व 1952 में महालनोबिस ने एक क्षेत्रीय मॉडल तथा 1953 में पूँजीगत वस्तु क्षेत्र तथा उपभोग वस्तु क्षेत्र वाले द्विक्षेत्रीय मॉडल की संरचना की थी।

परिकल्पना (Hypothesis)

प्रस्तुत मॉडल में देश में अनुमानित 5,600 करोड़ की धनराशि से द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में 5% वार्षिक विकास-दर (5% Annual Growth Rate) व 11 मिलियन व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार की उपलब्धि की परिकल्पना की गई है। अनुमानित धन-राशि को अर्थव्यवस्था के चारों क्षेत्रों में स प्रकार वितरित करने का प्रयास किया गया है कि प्रत्येक क्षेत्र में जन्म राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि तथा रोजगार वृद्धि का योग कमतः 5% तथा 11 मिलियन अतिरिक्त व्यक्ति हो सकें। इसीलिए इस मॉडल को आर्थिक विकास के मॉडल के स्थान पर प्रायः वितरण मॉडल (Allocation Model) की संज्ञा दी जाती है।

मॉडल का ऋरूप (Structure of the Model)

मॉडल में लिए गए चारों क्षेत्रों—विनियोग वस्तु क्षेत्र, फैक्टरी उत्पादित उपभोग वस्तु क्षेत्र, लघु या गृह उद्योगों द्वारा उत्पादित उपभोग वस्तु क्षेत्र, तथा सेवा उत्पादन क्षेत्र, के लिए चार उत्पादन-पूँजी अनुपात (Output Capital Ratios) अथवा उत्पादकता गुणांक (Productivity Coefficient) लिए गए हैं, जिनको β 's (बीटाज) प्रकट करते हैं, पूँजी श्रम अनुपातों (Capital Labour Ratios) के लिए θ 's (थीटाज), वितरण प्राच्यों (Allocation Parameters) के लिए λ 's (लैम्बडाज) का प्रयोग किया गया है, जो कुछ विनियोग का प्रत्येक क्षेत्र में अनुपात प्रदर्शित करते हैं। मॉडल में विभिन्न आर्थिक मात्राओं (Economic Magnitudes) के समाधान हेतु युगपद समीकरण प्रणाली (System of Simultaneous Equations) अपनाई गई है। सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए कुल आय तथा कुल रोजगार के रूप में लक्ष्य चलो की मान्यता लेते हुए, दिए हुए उत्पादकता गुणांकों और पूँजी श्रम अनुपातों तथा कुल विनियोग की मात्रा की सहायता से युगपद समीकरणों द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में जनित रोजगार व आय के अनुभागों (Components) को ज्ञात किया गया है।

मॉडल में निम्नलिखित तत्त्व अज्ञात (Unknown) हैं—

K	C_1	C_2	C_3
Y_k	Y_1	Y_2	Y_3
N_k	N_1	N_2	N_3
λ_k	λ_1	λ_2	λ_3

जिसमें γ 's (गामाज) = क्षेत्रों में जनित आय-वृद्धि,

N 's = रोजगार वृद्धि,

और λ 's (लेम्ब्डाज) = वितरण प्राचल (Allocation Parameters)

के लिए प्रयुक्त हुए हैं।

मॉडल में आँकड़ों (Dats) के लिए निम्न चिह्न प्रयोग में लिए गए हैं —

$$\begin{array}{cccc} I & & & \\ \beta k & \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ \theta k & \theta_1 & \theta_2 & \theta_3 \end{array}$$

जिसमें β 's = उत्पादन पूँजी अनुपात, I = कुल विनियोग

θ 's = पूँजी श्रम अनुपात

मॉडल के समीकरण (Equations of the Model)

मॉडल में 11 समीकरण तथा 12वाँ अज्ञात तत्त्व है। समीकरण निम्न प्रकार हैं—

(1) $\gamma k + \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3 = \gamma$ (प्रथम कल्पित स्थिरांक—First Arbitrary Constant)

(2) $Nk + N_1 + N_2 + N_3 = N$ (द्वितीय कल्पित स्थिरांक—Second Arbitrary Constant)

(3) $\lambda K I + \lambda_1 I + \lambda_2 I + \lambda_3 I = I$ (तृतीय स्थिरांक—Third Constant)

(4) $\gamma K = I \lambda K \beta K$

(5) $\gamma_1 = I \lambda_1 \beta_1$

(6) $\gamma_2 = I \lambda_2 \beta_2$

(7) $\gamma_3 = I \lambda_3 \beta_3$

(8) $NK = \frac{I \lambda K}{\theta K}$

(9) $N_1 = \frac{I \lambda_1}{\theta_1}$

(10) $N_2 = \frac{I \lambda_2}{\theta_2}$

(11) $N_3 = \frac{I \lambda_3}{\theta_3}$

11 समीकरण तथा 12वाँ अज्ञात तत्त्व होने के कारण, समीकरणों की इस व्यवस्था में एक अंश की स्वतन्त्रता (One Degree of Freedom) है। महालनोबिस ने इस स्वतन्त्रता का उपयोग निम्न समीकरण में किया है—

(12) $\lambda K = \frac{1}{3} \text{ or } 33$

युगपद समीकरणों की उपरोक्त व्यवस्था में

$$\begin{bmatrix} \gamma \\ N \\ I \end{bmatrix} = \begin{cases} \text{काल्पनिक स्थिरांक, मॉडल की सीमा-दशाओं के प्रतीक हैं।} \\ \text{ये कुल मिलाकर लक्ष्य (Overall Targets) को भी प्रकट करते हैं।} \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} \theta's \\ \beta's \end{bmatrix} = \begin{cases} \text{प्रायोगिकी द्वारा दिए हुए संरचनात्मक प्राचल (Techno-} \\ \text{logically given Structural Parameters), जिनको} \\ \text{योजनावधि में अपरिवर्तनशील (Unchanged) माना गया है।} \end{cases}$$

$\lambda's$ = वितरण प्राचल (Allocation Parameters), जिनको वास्तविक नियोजन प्राचल (Actual Planning Parameters) माना जा सकता है। ये प्राचल व्यवस्था में दिए हुए नहीं होने, किन्तु व्यवस्था की प्रक्रिया में से स्वयं उभर कर प्रकट होते हैं तथा ये नियोजकों द्वारा की गई अपेक्षाओं की स्थिति को दिखाते हैं।

$$\begin{bmatrix} Y's \\ N's \end{bmatrix} = \begin{cases} \text{प्रमुख क्षेत्रीय लक्ष्य चल (Vital Sectoral Target-vari-} \\ \text{ables तथा माडल के हल के रूप में निर्धारित होते हैं।} \end{cases}$$

उपयुक्त युग्मद समीकरण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि वितरण प्राचलों को क्या मूल्य दिए जाने चाहिए अथवा विनियोजन के लिए उपलब्ध साधनों को अव्यवस्था के विभिन्न चार क्षेत्रों में किस प्रकार वितरित किया जाना चाहिए कि क्षेत्रों में जनित आय व रोजगार-वृद्धि का कुल योग निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कुल आय तथा कुल रोजगार की पूर्ति कर सकें। महालनोबिस के समक्ष द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में वार्षिक विकास दर का तथा 11 मिलियन व्यक्तियों के लिए रोजगार की उपलब्धि का प्रश्न था, जिसके समाधान हेतु उन्होंने देश के साधनों का अनुमान 5,600 करोड़ रुपये प्रथम बार लगाया इससे पश्चात् सांख्यिकी विधियों से $\beta's$ और $\theta's$ का मूल्य निर्धारित करते हुए, समीकरणों के हल द्वारा, अव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के लिए विनियोग का वितरण निश्चित किया।

मॉडल का सख्यात्मक हल

(Numerical Solution of the Model)

प्रो. महालनोबिस ने अपने माडल का निम्नलिखित सख्यात्मक हल प्रस्तुत किया है—

क्षेत्र (Sectors)	प्राचल (Parameters)	
	$\beta's$	$\theta's$
λ	$\beta K = 20$	$\theta K = 20,000$ रु
C_1	$\beta_1 = 35$	$\theta_1 = 8,750$
C_2	$\beta_2 = 1.25$	$\theta_2 = ,500$
C_3	$\beta_3 = 45$	$\theta_3 = 3,750$

$\beta's$ व $\theta's$ को तकनीकी की स्थिति (State of Technology) निर्धारित करती है। मॉडल में विनियोग वस्तु क्षेत्र के लिए वितरण प्राचल अनुपात (λK) दिया हुआ होता है तथा शेष तीन क्षेत्रों के अनुपात λ_1 , λ_2 व λ_3 उपरोक्त युग्मद समीकरणों के हल द्वारा प्राप्त होते हैं।

चूँकि $\lambda K = \frac{1}{3}$ or 33 प्रति 100 $I = 5,600$ करोड़ रु. दिया हुआ है, अतः दिए गए आँकड़ों के आधार पर क्षेत्र (K) में विनियोजन की मात्रा का निर्धारण निम्न प्रकार किया गया है—

$$\lambda K.I = 33 \times 5600 = \frac{33}{100} \times 5600 = 1850 \text{ करोड़ रु.}$$

इस विनियोजन के परिणामस्वरूप आय में वृद्धि निम्न प्रकार होगी—

$$YK = I \lambda K \beta K \\ = \frac{1850 \times 20}{100}$$

i.e. 370 करोड़ रु., जबकि क्षेत्र K में रोजगार वृद्धि निम्न प्रकार होगी—

$$NK = \lambda K I / \theta K \\ = \frac{1850}{20,000} = 9 \text{ मिलियन या 9 लाख}$$

इसी प्रकार योजनावधि के 5 वर्षों में अन्य क्षेत्रों की आय-वृद्धि तथा रोजगार-वृद्धि को ज्ञात किया जा सकता है। सभी क्षेत्रों के संस्थात्मक हलों को निम्नलिखित सारणी में प्रदर्शित किया गया है—

क्षेत्र (Sectors)	विनियोजन (I) (करोड़ रु.)	आय-वृद्धि ΔY	रोजगार-वृद्धि (लाखों में) ΔN
K	1850	370	90
C ₁	980	340	11.0
C ₂	1180	1470	47.0
C ₃	1600	720	43.0
	5610	2900	110.0

मालोचनात्मक मूल्यांकन (A Critical Appraisal)

विकास नियोजन का महालनोबिस मॉडल 'प्राथमिक वृद्धि' का एक स्पष्ट व सुनियोजित (Clear and well arranged) ऐसा मॉडल है, जिसमें एक अर्द्ध-विकसित देश की विकास-नीति के आवश्यक तत्व अन्तर्निहित हैं। मॉडल की संरचना में भारतीय सांख्यिकी संस्थान (Indian Statistical Institute) द्वारा किए गए सांख्यिकी अन्वेषणों (Statistical Investigations) के निष्कर्षों का लाभ उठाया गया है। मॉडल का मौलिक स्वरूप अर्थमिति की सहाय प्रणाली पर आधारित है। इस मॉडल का उपयोग भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया। इस प्रकार मॉडल का व्यावहारिक स्वरूप (Operational Character) होते हुए भी, इसमें अनेक कमियाँ हैं। ये कमियाँ संक्षेप में अप्रतिबिम्बित हैं—

1 अधिक सुनिश्चित नहीं (Not so Deterministic)—यह मॉडल अधिक सुनिश्चित नहीं है। किसी मॉडल की पूर्णता समीकरणों तथा अज्ञातों (Unknowns) की संख्याओं की समानता पर निर्भर करती है, किन्तु प्रस्तुत मॉडल में 11 समीकरण और 12वाँ अज्ञात है। परिणामस्वरूप, समीकरण-व्यवस्था के एक अज्ञात को काल्पनिक मूल्य दिया गया है ($\lambda K = \frac{1}{3}$ Assumed)। काल्पनिक मूल्य देने की स्वतन्त्रता की इस स्थिति में स्पष्ट है कि विभिन्न काल्पनिक मूल्यों के आधार पर भिन्न-भिन्न हल सम्भव होंगे। यह कमी मॉडल की पूर्णता अथवा सुनिश्चितता को कम करती है किन्तु साथ ही यह विशेषता नियोजकों को अपनी निजी अवधारणाओं के प्रयोग की स्वतन्त्रता प्रदान करती है (This, however, introduces the element of choice into the model)।

2 कल्पित मूल्य के लिए केवल λK ही कमी चुना गया, अन्य अज्ञात तत्त्व क्यों नहीं लिए गए? इस प्रश्न का मॉडल में कोई उत्तर नहीं है।

3 एक अर्थ की स्वतन्त्रता वाले मॉडल में अनुकूलतम हल (Optimum Solution) के लिए पूर्वनिर्धारित सामाजिक कल्याण फलन (A Predetermined Social Function) का होना आवश्यक है, किन्तु दुर्भाग्यवश हमारे नियोजकों के समक्ष, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण के समय, इस प्रकार का कोई निश्चित कल्याण फलन (Welfare Function) नहीं था।

4 मॉडल में माँग-फलनों की उपेक्षा की गई है। नियोजकों की यह मान्यता है कि एक नियोजित अर्थव्यवस्था में जो कुछ उत्पादित किया जाता है, उसका उपयोग, उपभोक्ताओं के माँग-प्रधानता (Demand Preferences) तथा विभिन्न मूल्यों के दावपूद निश्चित है। इस प्रकार की मान्यता ने मॉडल को से (Say) के नियम 'Supply has its own demand' जैसा यांत्रिक स्वरूप (Mechanistic Type) प्रदान कर दिया है।

5 एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था के विकास नियोजन के दौरान बाजार तत्त्व, मनोवैज्ञानिक वातावरण, लोक-उत्साह, विशिष्ट दबाव बिन्दु (Specific Pressure Points) आदि से सम्बन्धित जो महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, उनकी महालनोबिस ने अपने मॉडल में, गणितीय सरलता के लिए, उपेक्षा की है।

6 मॉडल में, विनियोजन के एकल-समरूप-कोष (Single Homogeneous Fund) का संकेत है, जिसका समरूप विनियोजन वस्तुओं के लिए ही उपयोग किया जा सकता है, किन्तु विनियोजन वस्तुएँ प्रायः विजातीय (Heterogeneous) होती हैं, जिनके लिए विनियोजन-मैट्रिक्स (Investment Matrix) के प्रयोग की आवश्यकता है। इसलिए जहाँ व्यवस्था समरूप (Homogeneous) नहीं होती है, वहाँ इस मॉडल का प्रयोग, खुली अर्थव्यवस्था (Open Economy) में सम्भव नहीं है।

7 कृषिगत पदार्थों तथा धर्म की पूर्ति भी पूर्णतः बेलोच नहीं होती है। इनकी पूर्ति को मॉडल में पूर्णतः बेलोच माना गया है।

8 मॉडल में उत्पादन तकनीकियों को स्थिर मानना भी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि विकास-प्रक्रिया के क्रम में उत्पादन-तकनीकियाँ, प्रायः परिवर्तित होती रहती हैं।

9 सरचनात्मक प्राचली को बाल्पनिक मूल्य प्रदान किए गए हैं।

10 विनियोजन में निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्रों के अनुपातों के सम्बन्ध में मॉडल शान्त है।

सारांश—कुछ सरचनात्मक सम्बन्धों के समूह को लेकर सकाम प्रणाली द्वारा किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक ढाँचे का इस प्रकार विश्लेषण करना कि नियोजन प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध कुछ विनियोग-राशि का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठतम वितरण किया जा सके, मॉडल की मुख्य विशेषता है। किन्तु अन्य अर्थमिनि मॉडलों के समान ही इस मॉडल की भी अनेक अव्यावहारिक व बाल्पनिक मान्यताओं के कारण व्यावहारिक उपयोगिता बहुत कम हो गई है। प्रस्तुत मॉडल में आंकड़ा से सम्बन्धित चलो (Data Variables i.e. β 's and θ 's) के लिए अनेक अव्यावहारिक मान्यताएँ ली गई हैं।

किन्तु फिर भी भारतीय परिस्थितियों में, साहसपूर्ण द्वितीय पंचवर्षीय योजना (Bold Second Five Year Plan) के निर्माण में एक सरचनात्मक आधार विकसित करने हेतु महालनोबिस मॉडल ने रचनात्मक भूमिका सम्पादित की है। अपनी यान्त्रिक विधियों के बावजूद, अत्यधिक भ्रामक स्थिति वाले समय में, यह मॉडल भारतीय नियोजन को एक साकार दिशा देने में समर्थ हो सका है।

कुछ अन्य दृष्टिकोण (Some Other Approaches)

आर्थिक विकास के सम्बन्ध में निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोणों का अध्ययन भी उपयोगी है—

- (1) नर्कसे (Nurkse)
- (2) रोडन (Rodan)
- (3) हर्षमैन (Hirschman)
- (4) म्यिन्ट (Myint)
- (5) लेबेन्स्टीन (Leibenstein)

नर्कसे का दृष्टिकोण (Approach of Nurkse)

प्रो. रेगना नर्कसे ने अपनी पुस्तक 'Problems of Capital Formation in Under developed Countries' में प्रदर्शित देशों में पूँजी के महत्व, पूँजी-निर्माण, सन्तुलित विकास आदि से सम्बन्धित विषयों एवं छिपी हुई बेरोजगारी और उसके द्वारा पूँजी निर्माण के सम्बन्ध में विचार प्रकट किए हैं।

प्रो. नर्कसे के विकास सम्बन्धी विचारों का सारांश यह है कि अर्द्ध विकसित अथवा अल्प विकसित देश आर्थिक विषमता से ग्रस्त हैं, इस विषमता को दूर करने के लिए सन्तुलित विकास (Balanced Growth) आवश्यक है और यह सन्तुलित विकास तभी सम्भव है जब अतिरिक्त जन शक्ति का प्रयोग करके पूँजी प्राप्त की

जाए। प्रो नर्कसे के अनुसार "अर्द्ध-विकसित देशों में पूँजी की मात्रा बहुत कम होती है।" ये देश अपनी राष्ट्रीय आय का 5 से 8% तक ही बचा पाते हैं। इसके विपरीत विकसित देशों में बचत की मात्रा कुल राष्ट्रीय आय की 10 से 30% तक होती है। अर्द्ध विकसित देशों में इस शोचनीय स्थिति का मुख्य कारण है बचत की पूर्ति को भी कमी रहती है और बचत की माँग को भी कमी रहती है। बचत की पूर्ति की कमी इसलिए रहती है क्योंकि प्रायः उसकी माँग कम होती है। इस प्रकार माँग इसलिए कम होती है क्योंकि उसकी पूर्ति कम होती है। यह आर्थिक विषमता का चक्र (Vicious circle) निरन्तर चलता रहता है जो अर्द्ध-विकसित देशों को आर्थिक विकास की ओर अप्रसर नहीं होने देता। प्रो नर्कसे के अनुसार, 'आर्थिक दुष्चक्र की प्रक्रिया में कम पूँजी के कारण विनियोजन कम होता है। फलस्वरूप उत्पादकता कम होती है। कम उत्पादकता के कारण लाभ कम होता है परिणाम-स्वरूप, उत्पादन कम होता है। उपरोक्त उत्पादन से रोजगार के अवसर कम रहते हैं और इसलिए आय कम होती है। परिणामतः बचत कम होती है और पूँजी-निर्माण भी कम होता है।'

प्रो नर्कसे ने अर्द्ध-विकसित देशों की इस आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए सन्तुलित विकास पर बहुत बल दिया है। उनका सबसे अधिक आग्रह कृषि-क्षेत्रों की अतिरिक्त जन-शक्ति (Surplus Man-power) को अन्य पूँजीगत परियोजनाओं में नियोजित करके प्रभावपूर्ण बचत (Effective Saving) और पूँजी निर्माण की अभिवृद्धि पर है। नर्कसे के कथनानुसार कृषि करने की तकनीक को स्थानित रखते हुए भी कृषि उत्पादन में कमी किए बिना, कृषि में नियोजित जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि क्षेत्र से हटाया जा सकता है। "वहाँ समान कृषि उत्पादन बिना तकनीक में परिवर्तन किए हुए कम धर्म शक्ति से भी प्राप्त किया जा सकता है।" किन्तु नर्कसे की यह साम्यता है कि इस अनउत्पादक धर्म शक्ति को उत्पादक धर्म-शक्ति में बदलने की समस्त प्रक्रिया की वित्त-व्यवस्था स्वयं इसमें से ही की जानी चाहिए। ऐसा होने पर ही देश में बचत और पूँजी निर्माण की मात्रा में वृद्धि हो सकेगी। इसीलिए नर्कसे ने ग्रामीण छिपी हुई बेरोजगारी (Disguised Unemployment) को छिपी हुई बचत की सम्भावनाएँ (Disguised Saving Potential) माना है। इस प्रकार उन्होंने अर्द्ध-विकसित देशों की अप्रयुक्त जन-शक्ति के उपयोग द्वारा पूँजी-निर्माण पर बल देकर इन देशों के आर्थिक विकास पर जोर दिया है।

सन्तुलित विकास का विचार (Concept of Balanced Growth)

प्रो नर्कसे ने आर्थिक विकास के लिए सन्तुलित विकास पद्धति का प्रतिपादन किया है। उनके मतानुसार, "अर्द्ध-विकसित देशों में निर्धनता का विषैला चक्र (Vicious circle) व्याप्त रहता है जो आर्थिक विकास को अवरोध करता है। यदि इस दूषित चक्र को किसी प्रकार दूर कर दिया जाए, तो देश का आर्थिक विकास

सम्भव हो सकेगा। निर्धन देशों में निधनता का यह चक्र माँग और पूर्ति दोनों ओर से क्रियाशील रहना है। पूर्ति पहलू से विचार करें तो वास्तविक आय की कमी के कारण बचाने की क्षमता कम होती है। आय की कमी का कारण, निम्न उत्पादकता और निम्न उत्पादकता का कारण पूँजी की स्वल्पता होती है। पूँजी की कमी बचन के नीचे स्तर का परिणाम होती है। यदि माँग पहलू से विचार करें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि आय की कमी के कारण क्रय की क्षमता भी सीमित होती है। इससे माँग कम होती है।" परिणामस्वरूप, उत्पादकों में विनियोग करने का कम उत्साह होता है। अर्थव्यवस्था की उत्पादकता विनियोजित पूँजी पर निर्भर करती है। विनियोगों की कमी के कारण उत्पादन और आय का स्तर कम होता है। पुनः वही चक्र प्रारम्भ होता है। इस प्रकार इन दूषित चक्रों के कारण, अर्द्ध-विकसित देशों के विकास में बाधाएँ उपस्थित होती हैं।

आर्थिक विकास के लिए इस विपरीत चक्र को दूर करना आवश्यक है। विनियोग सम्बन्धी व्यक्तिगत निर्णयों द्वारा सीमित क्षेत्रों में अल्प मात्रा में किए गए विनियोग से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, प्रो नर्कसे के मतानुसार, "विपरीत चक्रों को दूर करने के लिए विभिन्न उद्योग विस्तृत रूप से एक साथ प्रारम्भ किए जाने चाहिए या एक दूसरे के लिए विस्तृत बाजारों की स्थापना करेंगे और एक दूसरे के पूरक होंगे।" उनके अनुसार, समस्या का हल इस बात में निहित है कि 'व्यापक क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों में एक साथ पूँजी लगाई जाए और बहुत से उद्योगों को एक साथ विकसित किया जाए ताकि सभी एक दूसरे के ग्राहक बन सकें और सभी का पाल बिक सके।' प्रो नर्कसे रोज़स्टेन रोज़न (Roseinstein Rodan) के जूते के प्रसिद्ध कारखाने का उदाहरण देकर सन्तुलित विकास की आवश्यकता पर बल देने हैं। मानलो एक जूते का कारखाना स्थापित किया जाता है। इससे इसमें काम करने वाले श्रमिकों, पूँजीपतियों और नियोजकों को आय प्राप्त होगी किन्तु वे सपस्त आय जूतों को खरीदने के लिए ही तो नहीं व्यय करेंगे। वे अन्य वस्तुएँ भी क्रय करेंगे। इसी प्रकार साथ ही इस उद्योग के श्रमिक ही सारे जूते नहीं खरीद सकते। दूसरे उद्योगों के श्रमिक ही तो प्रतिरिक्त जूते खरीदेंगे। यदि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों या उद्योगों का विकास नहीं किया जाएगा तो यह कारखाना प्रसफल हो जाएगा। अतः यह कठिनाई एक साथ ही अनेक पूरक उद्योगों की स्थापना करने से हल हो सकती है। जो एक दूसरे के ग्राहक बन जाते हैं। इस सम्बन्ध में प्रो नर्कसे ने लिखा है कि 'अधिकांश उद्योग जो जन उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं इस अर्थ में पूरक होते हैं कि वे एक दूसरे के लिए बाजार की व्यवस्था करके परस्पर सहारा देते हैं।' उनके अनुसार शारीरिक विकास के लिए सन्तुलित आहार (Balanced diet) जिस प्रकार आवश्यक है उसी प्रकार अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सन्तुलित विकास (Balanced Growth) पद्धति आवश्यक है।

प्रो नर्कसे ने सन्तुलित विकास की धारणा का अक्षर जे बी से (J B Say) के इस कथन से प्राप्त किया है कि पूर्ति अपनी माँग स्वयं बना लेती है (Supply

creates its own demand) । उन्होंने इस नियम सम्बन्धी जे. एस. मिल की व्याख्या को उद्धृत किया है कि “प्रत्येक प्रकार की उत्पादन वृद्धि यदि निजी हित द्वारा निर्देशित अनुपात में सब प्रकार की उत्पत्ति में गलत गणना के बिना विभाजित की जाए तो न केवल स्वयं अपनी भाग का निर्माण कर लेती है, बल्कि उसे अपने साथ रखती है ।” लेकिन किसी व्यक्तिगत उद्यमी द्वारा किसी विशिष्ट उद्योग में बड़ी मात्रा में लगाई गई पूँजी बाजार के छोटे आकार के कारण लाभहीन हो सकती है । किन्तु विभिन्न उद्योगों में व्यापक क्षेत्र में एक साथ सुव्यवस्थित रूप से पूँजी विनियोग से बाजारों के आकार का विस्तार होता है और इससे अधिक कुशलता के सामान्य स्तर में सुधार होता है । अतः विभिन्न उद्योग विस्तृत रूप से एक साथ आरम्भ किए जाने चाहिए और विभिन्न प्रकार के उद्योगों में पूँजी विनियोग की लहर (a wave of capital investments in a number of different industries) उठनी चाहिए । ऐसे होने पर उद्योग एक दूसरे के पूरक होंगे, जिससे विस्तृत बाजारों की स्थापना होगी और तीव्रता से आर्थिक विकास होगा । इसे ही नकते ने ‘सन्तुलित विकास’ का नाम दिया है । अतः ‘सन्तुलित विकास’ का आशय उत्पादन-क्रियाओं में विभिन्न प्रकार के सन्तुलन से है । यह सन्तुलन दो प्रकार का हो सकता है—प्रथम सम्मुखी (Forward) एवं द्वितीय विमुखी (Backward) । सम्मुखी सन्तुलन के अनुसार कृषि-उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ उन उद्योगों में भी विस्तार आवश्यक है जो इसके अतिरिक्त उत्पादन को चाहेंगे । विमुखी सन्तुलन के अनुसार यदि किसी उद्योग का विस्तार करना है तो इस उद्योग के संचालन के लिए आवश्यक कच्चा माल, ईंधन, यन्त्रपोकरण आदि से सम्बन्धित उद्योगों का भी विकास किया जाना चाहिए ।

सन्तुलित विकास के प्रभाव—सन्तुलित विनियोग से आर्थिक विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ता है । इसके साथ ही सन्तुलित विकास के कारण बाह्य मितव्ययिताओं (External economies) में वृद्धि होती है । ये मितव्ययिताएँ दो प्रकार की होती हैं, प्रथम, क्षैतिजीय मितव्ययिताएँ (Horizontal economies) एवं द्वितीय, उद्गीय मितव्ययिताएँ (Vertical economies) । वस्तुतः आकार प्रकार वाले विभिन्न उद्योगों में बड़े पैमाने पर पूँजी विनियोग से उद्योगों का उद्गीय और क्षैतिजीय एकीकरण सम्भव होता है और इससे भी दोनों प्रकार की मितव्ययिताओं का निर्माण होता है । अम के अधिक अच्छे विभाजन, पूँजी, कच्चे माल और तकनीकी कुशलता का सामूहिक प्रयोग, बाजारों का विस्तार तथा आर्थिक और सामाजिक ऊपरी पूँजी (Economic and Social overhead capital) का अधिक अच्छा और सामूहिक उपयोग आदि के कारण भी उत्पादन इकाइयों को लाभ होता है ।

सन्तुलन के क्षेत्र—प्रो नकते द्वारा प्रतिपादित, सन्तुलित विकास का यह सिद्धान्त विकास प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सन्तुलन की आवश्यकता पर बल देता है । कृषि और उद्योगों के विकास में समुचित सन्तुलन रखा जाना

चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था के घरेलू क्षेत्र (Domestic Sector) और विदेशी क्षेत्र (Foreign Sector) में भी सन्तुलन स्थापित किया जाना चाहिए। विकास की वित्त-व्यवस्था में निर्यात-आय (Export earnings) महत्वपूर्ण है। अतः घरेलू क्षेत्र के साथ साथ निर्यात क्षेत्र में पूँजी-विनियोग किया जाना चाहिए। प्रो नर्कसे के अनुसार “सन्तुलित विकास अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अच्छा आधार है।” उनके विचार से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए यातायात सुविधाओं में सुधार, उनकी लागत में कमी, नटकर बाधाओं की समाप्ति और मुक्त व्यापार क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिए। इससे विकासशील देश परस्पर एक दूसरे के लिए बाजारों का कार्य करेंगे और उनका विकास होगा। कृषि और उद्योगों, घरेलू और निर्यात क्षेत्रों के सन्तुलित विकास के समान ही भौतिक-पूँजी और मानवीय-पूँजी में साथ साथ विनियोग किया जाना चाहिए। दोनों के सन्तुलित विकास के प्रयत्न किए जाने चाहिए क्योंकि ‘भौतिक पूँजी’ में विनियोग तब तक व्यर्थ रहेगा जब तक कि उसके संचालन के लिए जनता शिक्षित और स्वस्थ न हो। इसी प्रकार प्रत्यक्ष उत्पादन क्रियाओं और आर्थिक तथा सामाजिक ऊपरी सुविधाओं में भी सन्तुलित विनियोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार नर्कसे ने तीव्र आर्थिक विकास हेतु सन्तुलित विकास की शैली का प्रतिपादन किया है जिसके अनुसार “अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में तथा एक उद्योग का विकास करने के लिए उससे सम्बन्धित अन्य उद्योगों में एक साथ विनियोग किया जाना चाहिए।” कुछ क्षेत्रों या उद्योगों पर ही ध्यान देने से अन्य उद्योग ‘प्रलम्ब विकसित सन्तुलन’ से ग्रस्त रहेंगे और विकास में बाधाएँ उपस्थित होंगी। प्रो ए डब्ल्यू लेविस के अनुसार ‘विकास कार्यक्रमों में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास होना चाहिए ताकि उद्योग और कृषि के मध्य तथा घरेलू उपभोग के लिए उत्पादन और निर्यात के लिए उत्पादन में उचित सन्तुलन रखा जा सके।”

सरकार एवं सन्तुलित विकास—प्रगट विकसित देशों में निजी उपक्रम के द्वारा व्यापक क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं में पूँजी-विनियोग की लहर का एक साथ संचार किया जाना दुष्कर कार्य है। इसलिए सन्तुलित विकास में राज्य द्वारा विकास प्रक्रिया के आयोजन, निर्देशन एवं समन्वय के लिए पर्याप्त स्थान है। सरकार से यह आशा की जाती है कि वह उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ विनियोजन का आश्वासन दे। अतः सन्तुलित विकास के लिए केन्द्रीय नियोजन आवश्यक होना चाहिए। किन्तु नर्कसे के अनुसार “सन्तुलित विकास के लिए केन्द्रीय आर्थिक नियोजन अनिवार्य नहीं है। सरकारी नियोजन के पक्ष में कई महत्वपूर्ण कारण हैं लेकिन सन्तुलित विकास उनमें से कोई कारण नहीं है।”

नर्कसे की यह भी मान्यता है कि निजी उपक्रम द्वारा भी वांछनीय प्रभाव कुछ प्रेरणाओं और प्रोत्साहन से प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने बतलाया है कि सामान्य मूल्य प्रेरणाओं द्वारा अल्प अंश में सन्तुलित विकास किया जा सकता है किन्तु बढ़ती हुई जनमर्यादा की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के साथ सन्तुलित विकास

की नीची स्तर भी सह विस्तार को प्राप्त कर लेती है। प्रारम्भिक विनियोग के मौद्रिक एवं अन्य प्रभावों के द्वारा विभिन्न उद्योगों में पूँजी-विनियोग की नई लहर दोड़ाई जा सकती है। इस प्रकार प्रो नर्कसे का सन्तुलित-विकास का सिद्धान्त निजी उपक्रम वाली अर्थव्यवस्था में लागू होता है। उनके सिद्धान्त में बाजार विस्तार, बाध्य मितव्ययताओं और मूल्य प्रेरणाओं द्वारा ही सन्तुलित विकास पर बल दिया गया है। उनके मतानुसार, “आवश्यक विनियोग के लिए सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का उपयोग प्रधानतः प्रशासकीय कुशलता का प्रश्न है।”

नर्कसे के विचारों की आलोचना—नर्कसे के सन्तुलित विकास के विचारों की हर्षमैन, सिगर, कुरिहारा आदि ने निम्न आधारों पर आलोचनाएँ की हैं—

1 सन्तुलित विकास के अन्तर्गत बहुत सी उत्पादन इकाइयों या अनेक उद्योगों का एक साथ विकास करने के लिए बड़ी मात्रा में पूँजी, तकनीकी ज्ञान, प्रबन्ध कुशलता आदि की आवश्यकता होगी। अर्द्ध-विकसित देशों में एक साथ प्रयोग के लिए इन साधनों का अभाव होता है। ऐसी स्थिति में, इन उत्पादन इकाइयों की स्थापना से, इनकी मौद्रिक और वास्तविक लागत में वृद्धि होगी और उनका मितव्ययतापूर्वक संचालन कठिन हो जाएगा।

2 प्रो बिन्डल बर्जर के अनुसार, नर्कसे के विकास प्राक्षप (Model) में नए उद्योगों की स्थापना की अपेक्षा वर्तमान उद्योगों में लागत कम करने की सम्भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया गया है।

3 नर्कसे ने विभिन्न उद्योगों को परिपूरक माना है, किन्तु हंस सिगर (Hans Singer) के अनुसार ये परिपूरक न होकर प्रतिस्पर्धी होते हैं। जैसा कि जे मारकस फ्लेमिंग (J Marcus Flemming) ने लिखा है—“जहाँ सन्तुलित विकास के सिद्धान्त में यह माना जाता है कि उद्योगों के मध्य अधिकांश सम्बन्ध परिपूरक हैं साधनों की पूर्ति की सीमाएँ प्रकट करती हैं कि यह सम्बन्ध अधिकतर प्रतिस्पर्धात्मक है।”

हर्षमैन (Hirschman) के अनुसार “सन्तुलित विकास का सिद्धान्त विकास सिद्धान्त के रूप में असफल है।” विकास का आशय, एक प्रकार की अर्थव्यवस्था से अन्य प्रकार की और उन्नत अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया से है, किन्तु ‘सन्तुलित विकास’ का आशय एक पूर्णरूप से नई और स्वयं सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की ऊपर से स्थापना से है। हर्षमैन के मतानुसार, यह विकास नहीं है, यह तो किसी पुरानी वस्तु पर नई वस्तु की कलम लगाना भी नहीं है। यह तो आर्थिक विकास का पूर्णरूप से बौद्ध तरीका है।”

4 अर्द्ध-विकसित देशों में उत्पादन के साधन अनुपात में नहीं होते। कुछ देशों में श्रम अत्यधिक है तथा पूँजी एवं साहस कुशलता की कमी है। कुछ देशों में धन और पूँजी दोनों की कमी है किन्तु अन्य साधन पर्याप्त मात्रा में हैं। सन्तुलित विकास की धारणा को व्यावहारिक रूप देने में ऐसी स्थिति बड़ी बाधक है।

5. सन्तुलित विकास का सिद्धान्त इस मान्यता के आधार पर चलता है कि

अर्द्ध-विकसित देश बहुत ही प्रारम्भिक स्थिति से विकास आरम्भ करते हैं। किन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं होता। वास्तव में प्रत्येक अर्द्ध-विकसित राष्ट्र एक ऐसी प्रवृत्ति से विकास की शुरुआत करता है जहाँ पूर्ण-विनियोग या पूर्ण विकास की छाया विद्यमान रहती है। ऐसी स्थिति में विनियोग के कुछ ऐसे मौखिक कार्यक्रम होने हैं जो स्वयं सम्पन्न नहीं होते, किन्तु जो वर्तमान असन्तुलन के पूरक के रूप में असन्तुलित विनियोग का स्वरूप ग्रहण करते हैं।

6 कुरिहारा के अनुसार "सन्तुलित विकास निजी उपक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए वांछनीय नहीं है किन्तु जहाँ तक अर्द्ध-विकसित देशों का सम्बन्ध है, यह स्वयं इसके लिए ही वांछनीय है। नर्कसे की अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्था के सीमित बाजार और निम्न वस्तुविक्रय आय द्वारा निजी व्यक्तियों की विनियोग की प्रेरणा को बाधा पहुँचाने की शिकायत प्रभावशाली होगी यदि क्षमता-विस्तारक और आय उत्पादक प्रकृति के स्वशासी सार्वजनिक विनियोग को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने दी जाएगी।"

7 सन्तुलित विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विनियोग के लिए बड़ी मात्रा में साधन होने चाहिए। किन्तु अर्द्ध विकसित देशों के साधन सीमित होते हैं यदि इन थोड़े से साधनों को ही विभिन्न और अधिक क्षेत्रों में फैलाया जाएगा, तो उनमें वांछनीय गति नहीं आ पाएगी और सम्भव है कि किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं हो पाए तथा साधनों का अपव्यय हो। अतः सन्तुलित विकास का सिद्धान्त इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है—'एक सौ पुष्प भी उम भूमि पर उग सकते हैं जहाँ पोषक तत्वों के अभाव में एक पौधा भी मुर्झा सकता है।' डॉ. इस सिंगर के अनुसार, 'सन्तुलित विकास की नीति को अपनाने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है उनकी मात्रा इतनी अधिक होती है कि उनको जुटाने वाले देश वास्तव में अर्द्ध-विकसित नहीं हो सकते।' इसीलिए उन्होंने इन देशों के लिए 'Think Big' को तो उचित बतलाया है, किन्तु 'Act Big' के सुभाव को अविवेकपूर्ण बतलाया है।

8 सन्तुलित विकास के लिए केन्द्रीय नियोजन, निर्देशन आदि आवश्यक है जिसका अर्द्ध विकसित देशों के विकास में पर्याप्त महत्व है। नर्कसे ने सन्तुलित विकास के लिए इस बात को पूर्णरूप से नहीं स्वीकारा है।

9 नर्कसे का सन्तुलित विकास का सिद्धान्त वस्तुतः विकसित देशों के अवसाद साम्य (Slump Equilibrium) की स्थिति की ही व्याख्या करता है, किन्तु अर्द्ध-विकसित देशों में अर्द्ध-विकास साम्य की स्थिति होती है और यह उसकी व्याख्या नहीं करता है।

वस्तुतः सन्तुलित विकास का सिद्धान्त कीन्स के व्यापार चक्र के सिद्धान्त का ही परिवर्तित रूप है। कीन्स के इस सिद्धान्त के अनुसार "एक साथ बहुमुखी विनियोग से आर्थिक क्रियाओं में सन्तुलित पुनर्स्थापन (Balanced Recovery) लाया जा सकता है क्योंकि वहाँ उद्योग, मशीनें, प्रबन्धक, श्रमिक तथा उपभोग की

अदत्त आदि सब कुछ प्रभावपूर्ण माँग की कमी के कारण अस्थायी रूप से स्थगित कार्यों को पुनः संचालित करने की प्रतीक्षा में विद्यमान होते हैं।' विन्तु अर्द्ध-विकसित देशों में समस्या माँग की कमी की नहीं, साधनों के अभाव की होती है, जिसके कारण व्यापक विनियोग दुष्कर होता है।

10 विभिन्न देशों के आर्थिक विकास का इतिहास भी यही स्पष्ट करता है कि इनमें आर्थिक विकास का स्वरूप असन्तुलित ही रहा है। इंग्लैण्ड में सर्वप्रथम, वस्त्र उद्योग, अमेरिका में रेलों और जापान में लोहा एवं इस्पात उद्योगों का विकास हुआ, जिससे अन्य उद्योगों के विकास को दम मिला। जे. आर टी हेग के अनुसार "सन्तुलित विकास अन्तिम परिणाम था, जो नवीन क्रियाओं के नवीन उत्पादन पतन तथा परिवर्तनीय साधनों के संयोग द्वारा उपाहित तथा घोषित हुआ। यह एक ऐसी घटना नहीं है जो परस्पर पोषक क्षेत्रों (Mutually Supporting Sectors) के एक साथ बहुमुखी विस्तार के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हो।"

रोजेन्स्टीन रोडान की विचारधाराएँ

(Approach of Roseinstein Rodan)

रोजेन्स्टीन रोडान ने भी सन्तुलित विकास का समर्थन किया है, परन्तु वे चाहते हैं कि यह सन्तुलित विकास-पद्धति 'बड़े धक्के' (Big Push) के रूप में अपनाई जाए। 'बड़े धक्के के सिद्धान्त' (Theory of Big Push) के अनुसार स्थिर अर्थव्यवस्था (Stagnant Economy) की प्रारम्भिक जड़ता को समाप्त करने के लिए और इसे उत्पादन तथा आय के उच्च स्तरों की ओर बढ़ने के लिए न्यूनतम प्रयत्न या 'बड़े धक्के' (Big Push) की आवश्यकता है। यह बड़ा धक्का तब होता है, जब एक साथ ही विभिन्न प्रकार की कोई पूरक परियोजनाओं को प्रारम्भ किया जाए।

रोडान के मतानुसार, "अर्द्ध-विकसित अथवा अल्प विकसित देशों में आर्थिक व सामाजिक ऊपरी सुविधाओं (Social and Economic overheads) की नितान्त कमी होती है जिनकी पूर्ति करने की न तो निजी साहसियों में क्षमता होती है और न ही इच्छा।' शत राज्य को चाहिए कि वह इन ऊपरी सुविधाओं (Social and Economic overheads) अर्थात्, यातायात, संचार, शक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक, ट्रेनिंग आदि में अधिक मात्रा में धन लगाए और इस प्रकार निजी विनियोजकों तथा औद्योगीकरण के इच्छुक लोगों को उद्योग खोलने की प्रेरणाएँ और सुविधाएँ प्रदान करे। जो रोडान के अनुसार, अर्द्ध-विकसित देशों में धीरे-धीरे विकास करने की पद्धति अमाननी ठीक नहीं है। इन देशों में वास्तविक विकास तो केवल 'बड़े धक्के' (Big Push) से ही सम्भव है क्योंकि तभी हम 'उत्पादन की बाह्य मित्यपपत्ता' अथवा उत्पत्ति वृद्धि के नियम के लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

"यदि विकास की किसी भी आयोजना में सफल होना है तो इसके लिए एक न्यूनतम मात्रा में विनियोजन आवश्यक होगा। किसी देश को स्वयं स्फूर्त विकास की स्थिति में पहुँचने के लिए प्रयत्न करना भूमि से हवाई जहाज के उड़ान के समान है। हवाई जहाज को नभ में उड़ान के लिए एक निश्चित गति पकड़ना आवश्यक

है। धीरे धीरे बढ़ने से काम नहीं चल सकता। इसी प्रकार विकास कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रत्यक्षता को स्वयं स्फूर्ति दगाने में पहुँचने के लिए बड़े धक्के के रूप में एक निश्चित मात्रा में समस्त क्षेत्रों में विनियोजन अनिवार्य है।”

‘विकास की बाधाओं को लगने के लिए बड़ा धक्का ही आवश्यक है। एक निश्चित न्यूनतम मात्रा से कम मात्रा में उत्साह और कार्य से काम नहीं चल सकता। छोटे-छोटे और यदा कदा किए जाने वाले प्रयत्नों से विकास सम्भव नहीं हो सकता। विकास का वातावरण तभी उत्पन्न होना है जब एक न्यूनतम मात्रा का विनियोजन एक न्यूनतम गति में किया जाय।”

प्रो. रोडान के ‘बड़े धक्के के सिद्धन्त’ के पक्ष में प्रमुख तर्क अर्द्ध-विकसित देशों में बाह्य मित्तव्ययताओं के अभाव पर आधारित है। बाह्य मित्तव्ययताओं का आशय उन लाभों से है जो समस्त अर्थव्यवस्था या कुछ क्रियाओं या उपक्रमों को मिलने हैं किन्तु जो विनियोजित इकाइयों को प्रत्यक्ष रूप में कोई प्रत्याय (Returns) नहीं देने हैं। पूर्ति की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाह्य मित्तव्ययताएँ यातायात, शक्ति आदि के रूप में सामाजिक ऊपरी सुविधाएँ (Social overhead facilities) हैं जो अन्य क्षेत्रों में भी विनियोग के अवसर बढ़ाते हैं। रोजेन्स्टीन रोडान ने निम्नलिखित तीन प्रकार से बाह्य मित्तव्ययताओं और अविभाज्यताओं (Indivisibilities) में भेद किया है—

(i) उत्पादन-कार्य में विशेष रूप से सामाजिक ऊपरी पूँजी की पूर्ति में अविभाज्यता (Indivisibility of production function, specially in the supply of social overhead capital)

(ii) माँग की अविभाज्यता या माँग की पूरक प्रकृति (Indivisibility of demand or the complementary character of demand)

(iii) बचत की पूर्ति में अविभाज्यता (Indivisibility in the supply of savings)

सामाजिक ऊपरी पूँजी की पूर्ति की अविभाज्यता स्वाभाविक है, क्योंकि इसका न्यूनतम आकार आवश्यक रूप से ही बड़ा (necessarily large minimum size) होता है। उदाहरणार्थ, आधी रेल लाइन निर्माण से कोई लाभ नहीं होगा, अतः पूरी रेल लाइन के निर्माण के लिए आवश्यक मात्रा में विनियोग करना अनिवार्य है। साथ ही, इस प्रकार का विनियोग प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं के पूर्व होना चाहिए। निर्यात के लिए कृषि क्षेत्र के विकास के लिए विनियोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि खेतों से बन्दरगाहों पर कृषि-उपज को पहुँचाने के लिए सड़क का निर्माण नहीं कर दिया जाता। रोजेन्स्टीन रोडान का माँग की अविभाज्यता का विचार इस तथ्य पर आधारित है कि एकाकी विनियोग परियोजना को बाजार की कमी की भारी जोखिम को उठाना पड़ सकता है। इसके विपरीत, यदि कई पूरक परियोजनाओं को एक साथ प्रारम्भ किया जाता है तो वे एक दूसरे के लिए बाजार प्रस्तुत कर देने हैं और उनके असफल होने की संभावना नहीं रहती है। रोजेन्स्टीन रोडान इस बात को एक जूते के कारखाने के उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते

हैं। मानलो कि एक स्थितिक और बड़े अर्थव्यवस्था में एक दूतों का कारखाना स्थापित किया जाता है जिसमें 100 श्रमिकों को जो पहले अर्द्ध-नियोजित थे काम पर लगाया जाता है। उनकी दी जाने वाली मजदूरी उनकी आय होगी किन्तु इसका बहुत थोड़ा भाग ही दूतों को खरीदने में व्यय किया जाएगा। ऐसी अर्थव्यवस्था में क्योंकि अतिरिक्त क्रय-शक्ति का कोई साधन नहीं है और निर्यात की भी कोई सम्भावना नहीं है, बाकी बचे हुए दूतों की बिक्री नहीं हो पाएगी और कारखाना असफल हो जाएगा। किन्तु स्थिति उस समय एकदम भिन्न और अधिक अच्छी होगी यदि एक नहीं अपितु 10 000 पहले के अर्द्ध-नियोजित श्रमिकों को काम पर लगाने वाले 100 कृषि और औद्योगिक उपक्रम स्थापित किए जाएं जिनमें अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र की तुलना में उत्पादकता के उच्च स्तर पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ उत्पन्न की जाएँ। ऐसी स्थिति में उत्पन्न की गई अतिरिक्त आय अतिरिक्त उत्पादन को खरीदने के काम में लाई जा सकेगी और कुल विनियोगों की सफलता सुनिश्चित हो जाएगी।

‘बड़े धक्के के सिद्धान्त के सन्दर्भ में तीसरी अर्थात् ‘बचत की पूर्ति’ की अविभाज्यता की धारणा का उदय इस बात से होता है कि विशाल स्मून्तम विनियोग कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था के लिए ऊँची स्मून्तम बचत अनिवार्य है। रोजेन्स्टीन रोडान के मतानुसार ‘आय के नीचे स्तर वाली अर्द्ध विकसित अवस्थाओं में बचत की ऊँची दरों को प्राप्त करने का एक मात्र तरीका विनियोगों में वृद्धि ही है जिसे इन देशों में यहाँ के अविकसित और अप्रयुक्त जन शक्ति तथा अन्य साधनों की गतिशील बना कर ही प्राप्त किया जा सकता है।’

इस प्रकार उपरोक्त अविभाज्यताओं का पूरा लाभ उठाने और वाह्य-मित्तव्ययताओं से लाभान्वित होने के लिए विशाल मात्रा में विभिन्न क्षेत्रों में पूँजी विनियोग करना चाहिए, अर्थात् अर्थव्यवस्था को ‘बड़ा धक्का’ विकास की ओर लगाना चाहिए। प्रो नर्कसे ने भी रोजेन्स्टीन रोडान की उपरोक्त अविभाज्यताओं के आधार पर ही सतुलित विकास की पद्धति का समर्थन किया है। बड़े धक्के के सिद्धान्त में सस्यागत परिवर्तन पर भी जोर दिया गया है। किन्तु इस सिद्धान्त को भी पूर्ण नहीं माना गया है। अर्द्ध विकसित देशों के औद्योगीकरण और आर्थिक विकास के कार्यक्रम में ‘बड़ा धक्का’ (Big push) लगाना बड़ा कठिन है क्योंकि, इन देशों के साधन अत्यल्प होने हैं। इनके अतिरिक्त सन्तुलित विकास के सिद्धान्त के विरुद्ध जो आलोचनाएँ की जाती हैं वे सामान्यतया इस सिद्धान्त पर भी लागू होती हैं।

हर्षमैन की विचारधारा (Approach of Hirschman)

असंतुलित विकास की शैली—नर्कसे की सतुलित विकास की शैली के विपरीत, ए ओ हर्षमैन (A. O. Hirschman) ने आर्थिक विकास के लिए असंतुलित विकास की शैली को अपनाने का सुझाव दिया है। हर्षमैन के ‘असंतुलित विकास के सिद्धान्त’ के अनुसार, ‘अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विनियोजन नहीं

करने कुछ ऐसे चुने हुए क्षेत्रों में सीमित साधनों का उपयोग किया जाता है जिससे उसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है और धीरे-धीरे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में क्रिया-प्रतिक्रिया द्वारा श्रृंखलाबद्ध विधि द्वारा आर्थिक विकास होता है। अर्द्ध-विकसित देशों में साधनों का अभाव रहता है और यह सम्भव नहीं होता कि बहुमुखी विकास के लिए सभी क्षेत्रों में विशाल मात्रा में इन साधनों का विनिर्गोजन कर सकें। इसके अतिरिक्त इन सीमित साधनों को सभी क्षेत्रों में फैला दिया जाए तो उनका उतना प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। अतः हर्षमैन ने यह मत व्यक्त किया है कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों या उद्योगों में विनियोजन करने से, विनियोग के नए अवसर उत्पन्न होंगे और इससे आगे आर्थिक विकास का पथ प्रशस्त होगा। उन्होंने लिखा है कि 'विकास इसी प्रकार आगे बढ़ा है जिसके अनुसार पारिषद वृद्धि अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्रों में, एक उद्योग से दूसरे उद्योग में और एक फर्म से दूसरी फर्म में पहुँचाई गई है।' वह विकास को असंतुलनों की एक श्रृंखला (Chain of disequilibria) मानते हैं, जिन्हें समाप्त करने की अपेक्षा बनाए रखा जाना चाहिए। हर्षमैन के मतानुसार पूर्व-निर्धारित योजना के अनुसार अर्थव्यवस्था में जानबूझ कर असंतुलन उत्पन्न करना, अर्द्ध-विकसित देशों में आर्थिक विकास को प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है।

हर्षमैन के अनुसार विश्व के किसी भी देश में असंतुलित विकास नहीं हुआ है। आधुनिक विकसित देश भी विकास के वर्तमान स्तर पर संतुलित विकास शैली द्वारा नहीं पहुँचे हैं। संयुक्तराज्य अमेरिका की सन् 1950 की अर्थव्यवस्था की, सन् 1850 की अर्थव्यवस्था से तुलना करने पर ज्ञात होता है कि उसके कई क्षेत्र विकसित हुए हैं किन्तु पूरी शान्दी में सभी क्षेत्र एक ही दर से विकसित नहीं हुए हैं। अतः अर्द्ध-विकसित देशों के विकास के लिए भी असंतुलित विकास की पद्धति उपयोगी है। हर्षमैन की यह भी मान्यता है कि 'यदि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने रहना है तो विकास की नीति का उद्देश्य तनाव (Tension), व्यनुपात (Disproportions) और असाम्य बनाए रखें। आदर्श स्थिति यह है, जबकि एक असाम्य विकास के प्रयत्नों के लिए प्रेरित करें जिससे पुनः इसी प्रकार का असाम्य उत्पन्न हो और इसी प्रकार चलता रहे।'

उनके अनुसार नई परियोजनाएँ पूर्व निर्धारित परियोजनाओं द्वारा सृजित बाह्य मित-व्ययताओं को हस्तगत (Appropriate) कर लेती हैं और बाद वाली परियोजनाओं के उपयोग के लिए कुछ बाह्य मित-व्ययताओं का स्वयं भी सृजन करती हैं। किन्तु कुछ परियोजनाएँ ऐसी होती हैं, जो स्वयं सृजित मित-व्ययताओं से अधिक का शोषण करती हैं। इस प्रकार की परियोजनाओं में लगाई गई पूँजी को 'प्रेरित विनियोग (Induced investment)' कहा जाता है क्योंकि उनसे बाह्य मित-व्ययताओं को कुल मिलाकर कोई लाभ नहीं होता है। इसके विपरीत कुछ परियोजनाएँ ऐसी होती हैं जो उपयोग में लाई गई बाह्य मित-व्ययताओं से अधिक मित-व्ययताओं का सृजन करती हैं। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से दूसरे प्रकार की

परियोजनाओं में निजी लाभदायकता (Private profitability) की अपेक्षा अधिक सामाजिक वांछनीयता (Social desirability) होती है। अतः विक्रम-नीति का उद्देश्य प्रथम प्रकार के विनियोगों को रोकना और दूसरे प्रकार के विनियोगों को प्रोत्साहन देना है। इस प्रकार, विकास की आदर्श सरचना एक ऐसा अनुक्रम (Sequence) है, जो साम्य से दूर ले जाता है और इस अनुक्रम में प्रत्येक प्रयत्न पूर्व असाम्य से प्रेरित होता है और जो अपने बारे में नया असंतुलन उत्पन्न करता है। इसके लिए पुनः प्रयत्नों की आवश्यकता होती है। पॉल एलपर्ट (Paul Alpert) के अनुसार 'अ' उद्योग का विस्तार ऐसी मितव्ययताओं को जन्म देता है जो 'अ' के लिए बाह्य होती है लेकिन जो 'ब' उद्योग को लाभ पहुँचाती हैं। अतः 'ब' उद्योग अधिक लाभ में रहता है और इसका विस्तार होता है। 'ब' उद्योग का विस्तार भी अपने साथ मितव्ययताएँ लाता है जिससे उद्योग 'अ' 'भ' और 'द' लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कदम पर एक उद्योग, दूसरे उद्योगों के पूर्वविस्तार द्वारा सृजित बाह्य मितव्ययताओं का लाभ उठाता है और साथ ही दूसरे उद्योगों के लाभ के लिए बाह्य मितव्ययताओं का सृजन करता है। ऐसा बहुधा हुआ है कि रेलवे निर्माण ने विदेशी बाजारों तक पहुँच (Accessibility) उत्पादन करके निर्यात के लिए कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया है। मस्ते घरेलू कपास की उपलब्धि ने सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना में योग दिया है। रेलों वस्त्र उद्योग, निर्यात के लिए कृषि के विकास में मरम्मत करने वालों और अन्त में मशीनी यंत्रों के निर्माण के लिए माँग तैयार की है। इसके विस्तार से धीरे-धीरे स्वदेश में इस्पात उद्योगों को जन्म मिला है और यह क्रम निरन्तर चलना रहता है। एक उद्योग द्वारा प्रस्तुत बाह्य मितव्ययताओं के द्वारा दूसरे उद्योगों की स्थापना का क्रम कई अर्द्ध-विकसित देशों में चला है। भारत और ब्राजील का नाम इस दृष्टि से उल्लेखनीय है।

असंतुलन की विधि—हर्षमैन के विचारानुसार अर्द्ध विकसित देशों में बुनियादी कमी समाधानों की होती है। पूँजी का भी उतना अभाव नहीं होता, जितना कि उन उद्यमियों का, जो जोखिम सम्बन्धी निर्णय लेकर इन समाधानों का उपयोग करते हैं। इस समस्या के समाधान हेतु अधिकाधिक उद्यमियों को विनियोग के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कुछ सीमा तक पूर्व विकास के द्वारा ऐसी परिस्थितियों का सृजन किया जाना चाहिए जिससे नवीन विनियोग लाभदायक और उचित प्रतीत होता हो और वे उसके लिए विवश हो जाएँ। हर्षमैन ने विनियोग के लिए अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया है और उनमें से किसी एक के भी द्वारा असंतुलन उत्पन्न किया जा सकता है। ये दो क्षेत्र सामाजिक ऊपरी पूँजी (Social Overhead Capital S O C) और प्रत्यक्ष उत्पादन क्रियाएँ (Directly Productive Activities) हैं।

सामाजिक ऊपरी पूँजी द्वारा असंतुलन (Unbalancing with S O C)—सामाजिक ऊपरी पूँजी के अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, संचार, पानी, विद्युत,

प्रकाश तथा सिंचाई आदि जनोपयोगी सेवाएँ प्राप्ती हैं। इनमें विनियोग करने से इनका विकास होगा जिससे प्रत्यक्ष उत्पादन क्रियाओं में भी निजी विनियोग को प्रोत्साहन मिलेगा। उदाहरणार्थ, सस्ती बिजली से लघु और कुटीर उद्योगों का विकास होगा। सिंचाई की सुविधाओं से कृषि उद्योग का उचित विकास होगा। सामाजिक ऊपरी पूँजी में किए गए विनियोग कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के आदानों (Inputs) को सस्ता करके इसकी प्रत्यक्ष सहायता करेंगे। जब तक पर्याप्त विनियोगों द्वारा सामाजिक पूँजी सम्बन्धी सस्ती और ध्रुव सेवाओं की उपलब्धि नहीं होगी, प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में निजी विनियोग को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। सस्ते यातायात के साधनों और सस्ती विद्युत शक्ति की पर्याप्त उपलब्धि से ही विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित हो सकेंगे। अतः सामाजिक ऊपरी पूँजी में विनियोग द्वारा एक बार अर्थव्यवस्था को असंतुलित किया जाए तब, उसके सद्प्रभावों के कारण बाद में प्रत्यक्ष उत्पादक-क्रियाओं में भी विनियोग अधिकारिक हो और अर्थव्यवस्था का विकास हो। जैसा कि प्रो. हर्पमैन ने लिखा है—“सामाजिक ऊपरी पूँजी में विनियोगों का समर्थन अन्तिम उत्पादन पर इसके प्रत्यक्ष लाभों के कारण नहीं किया जाता, अपितु, इसलिए किया जाता है क्योंकि यह प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं को आन की इजाजत देते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं (DPA) में विनियोग की पूर्ण आवश्यकता है।”

प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं द्वारा असंतुलन (Unbalancing with DPA)—अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं (DPA) के द्वारा भी असंतुलन उत्पन्न किया जा सकता है और उसके द्वारा अर्थव्यवस्था के विकास का भी प्रयत्न किया जा सकता है। यदि प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में प्रारम्भिक विनियोग बढ़ाया जाएगा तो सामाजिक ऊपरी पूँजी (SOC) पर दबाव पड़ेगा तथा उसकी कमी अनुभव की जान लगेगी। पर्याप्त सामाजिक ऊपरी पूँजी निर्माण के अभाव में यदि प्रत्यक्ष-उत्पादक-क्रियाएँ प्रारम्भ की गईं तो उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। इन सब कारणों से स्वाभाविक रूप से सामाजिक ऊपरी पूँजी (SOC) का भी विस्तार होगा। इसी प्रकार प्रत्यक्ष उत्पादक-क्रियाओं के प्रारम्भ से होने वाली आय में वृद्धि और राजनीतिक दबाव से भी सामाजिक ऊपरी पूँजी पर विनियोग को प्रोत्साहन मिलेगा।

विकास का पथ (Path to Development)—सामाजिक ऊपरी पूँजी (SOC) से प्रत्यक्ष उत्पादन-क्रिया (SOC to DPA) के प्रथम अनुक्रम (Sequence) को हर्पमैन ने सा. ऊ. पू. की अतिरिक्त क्षमता द्वारा विकास (Development via excess capacity of SOC) और प्र. उ. क्रि. से सा. ऊ. पू. (From DPA to SOC) के द्वितीय अनुक्रम को सा. ऊ. पू. की स्वल्पता द्वारा विकास (Development via shortage of SOC) कहा है। प्रथम प्रकार के विकास पथ में विनियोग अनुक्रम लाभ की आशाओं से और द्वितीय प्रकार के राजनीतिक दबावों से होता है, क्योंकि सा. ऊ. पू. और प्र. उ. क्रि. दोनों का ही एक साथ विस्तार नहीं किया जा सकता। अतः विकास के लिए किसी एक पथ की चुनना पड़ता है। दोनों

मार्गों में से किम मार्ग का अनुसरण किया जाए ? इस सम्बन्ध में हर्षमैन सा ऊ. पू. की स्वल्पता (Development via shortage of SOC) को पसन्द करते हैं।¹

अग्रणी और पिछली शृंखलाएँ (Forward and Backward Linkage)—
आर्थिक विकास के लिए असतुलन का महत्त्व समझ लेने के पश्चात् अग्रणी समस्या इस बात को ज्ञात करने की है कि किस प्रकार का असतुलन विकास के लिए अधिक प्रभावशाली है। अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र इतने महत्त्वपूर्ण और प्रभावशाली होते हैं कि उनके विकसित होने पर अन्य क्षेत्र स्वयमेव प्रगति करने लग जाते हैं। उदाहरणार्थ, इस्पात कारखानों की स्थापना से पिछली शृंखला के प्रभाव (Backward linkage effects) के कारण, कच्चा लोहा, कोयला, अन्य धातु-निर्माण-उद्योग, सीमेंट आदि की मांग बढ़ने के कारण इन उद्योगों का विकास होता है। इसी प्रकार अग्रणी शृंखलाओं के प्रभाव (Forward linkage effects) के कारण मशीन निर्माण उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग यन्त्र उद्योग तथा सेवाओं की प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार इस्पात उद्योग की स्थापना से अर्थव्यवस्था को एक गति मिलती है। उत्पादन की पूर्व और बाद वाली अवस्थाओं में विनियोग बढ़ने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। अतः विकास-प्रक्रिया का उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं को ज्ञात करना है जिनका अधिकाधिक शृंखला-सम्बन्ध प्रभाव हो। पिछली और अग्रणी शृंखलाओं का प्रभाव आदान प्रदान (Input-output) सारणियों द्वारा मापा जा सकता है यद्यपि इनके बारे में अर्द्ध-विकसित देशों में विश्वसनीय जानकारी नहीं होती है। ऐसी परियोजनाएँ जिनका शृंखला प्रभाव अधिक हो, विभिन्न देशों और विभिन्न समयों में भिन्न भिन्न होती हैं। लोहा और इस्पात उद्योग इसी प्रकार की एक परियोजना है। हर्षमैन के अनुसार “सर्वोच्च शृंखला प्रभाव वाला उद्योग लोहा तथा इस्पात है (The industry with the highest combined linkage score is iron and steel)” किन्तु अधिकतम शृंखला प्रभाव वाले लोहे और इस्पात उद्योग से ही औद्योगिक विकास का प्रारम्भ नहीं हो सकता है क्योंकि, अर्द्ध विकसित देशों में अन्तर्निर्भरता और शृंखला प्रभावों की कमी होती है। इन देशों में कृषि आदि प्राथमिक उत्पादन उद्योग होते हैं जिनके दोनों प्रकार के प्रभाव निर्बल होते हैं परिणामस्वरूप, रोजगार या कुल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि के रूप में अर्थव्यवस्था पर इनके विकास के प्रभाव बहुत कम होते हैं।

इसीलिए हर्षमैन ‘अन्तिम उद्योग पहले’ (Last industries first) की बात का समर्थन करते हैं। इन उद्योगों को ‘Import Inclave Industries’ भी कहते हैं, जो पिछली शृंखला के व्यापक और गम्भीर प्रभाव उत्पन्न करते हैं। वस्तुतः पिछली शृंखलाओं के प्रभाव जो कई अन्तिम अवस्था वाले उद्योगों (Last stage Industries) के समुक्त परिणाम होते हैं, अधिक महत्त्व वाले होते हैं। पिछली शृंखलाएँ मांग में वृद्धि के कारण उत्पन्न होती हैं। प्रारम्भ में ‘Import Inclave industries’ में

विदेशों से किसी वस्तु के हिस्से मंगाकर देश में उनको सम्मिलित (Assemble) करने के रूप में अन्तिम उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए। पिछली श्रृंखलाओं के द्वारा भाद में इनकी माँग में वृद्धि होने पर इन हिस्सों के उद्योग भी स्वदेश में ही स्थापित किए जाने चाहिए और इन आयात प्रतिस्थापन करने वाले उद्योगों को संरक्षण या अनुदान (Subsidy) आदि के रूप में सहायता दी जानी चाहिए।

सक्षेप में, प्रो. हर्षमैन की 'आर्थिक विकास की प्रमतुलित शैली' को उन्हीं के शब्दों में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है—“आर्थिक विकास असमान वृद्धि के मार्ग का अनुसरण करता है कि दबावों, प्रेरणाओं और अनिवार्यताओं के परिणामस्वरूप सतुलन की स्थापना की जाती है कि आर्थिक विकास का कुशलतापूर्ण मार्ग अव्यवस्थित होता है और कठिनाइयों और कुशलताओं, सुविधाओं, सेवाओं और उत्पादों की कमियों तथा कठिनाइयों से युक्त होता है; कि औद्योगिक विकास अधिकांश में पिछली श्रृंखलाओं के द्वारा प्रागे बढ़ता प्रगति यह अपना मार्ग अन्तिम स्पर्श (Last touches) से मध्यवर्ती और आधारभूत उद्योगों की ओर लेता।”

हर्षमैन के दृष्टिकोण का मूल्यांकन (Critical Appraisal of Hirschman's Approach)—हर्षमैन द्वारा प्रतिपादित 'प्रमतुलित विकास का सिद्धान्त' प्रद्ध-विकसित देशों में आर्थिक विकास की गति में तीव्रता लाने का एक उपयोगी उपाय है। विकास के लिए प्रेरणाओं और उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं आदि का इस सिद्धान्त में उचित रूप से विवेचन किया गया है। पिछली और अगली श्रृंखलाओं के प्रभावों और अन्तिम अवस्था उद्योग (Import Inclave Industries) का विवेचन भी उपादेय है। प्रद्ध-विकसित देशों के लिए अत्यधिक बांछनीय निर्यात सबद्धन और आयात प्रतिस्थापन तथा प्रारम्भिक अवस्थाओं में उद्योगों को संरक्षण और सहायता पर भी इस सिद्धान्त में उचित बल दिया गया है। हर्षमैन के इस सिद्धान्त में न तो रूस जैसी पूर्ण केन्द्रीकृत-नियोजन-पद्धति का समर्थन किया गया है, न ही पूर्णरूप से निजी उपक्रम द्वारा विकास की समर्थता को अमिद्विध माना गया है। सामाजिक ऊपरी पूँजी के विकास में वह सार्वजनिक उत्तरदायित्व पर बल देता है क्योंकि, निजी-उपक्रम द्वारा इनका बांछित विकास असम्भव है और इसके अभाव में प्रत्यक्ष उत्पादन क्रियाएँ प्रोत्साहित नहीं हो सकती। इस प्रकार, हर्षमैन मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्ष में प्रतीत होते हैं। जो प्रद्ध-विकसित देशों के सदर्भ में पूर्ण उपयुक्त विचार हैं।

आलोचना—हर्षमैन के सिद्धान्त की निम्नलिखित आलोचनाएँ की गई हैं—

1. पाल स्ट्रीटन (Paul Streeten) ने हर्षमैन के उक्त सिद्धान्त की आलोचना करते हुए लिखा है कि “महत्त्वपूर्ण प्रश्न असतुलन उत्पन्न करने का नहीं है बल्कि विकास को गति देने के लिए असतुलन का अनुकूलतम अंश क्या हो, कितना और कहाँ असतुलन पैदा किया जाए, महत्त्वपूर्ण बिन्दु (Growing Points) क्या हैं?” इस प्रकार इस सिद्धान्त में असतुलन की संरचना, दिशा और समय पर पर्याप्त ध्यान केन्द्रित नहीं हुआ है।

2. पॉल स्ट्रीटन के अनुसार इस सिद्धान्त में विस्तार की प्रेरणाओं पर ही ध्यान दिया गया है तथा असंतुलन द्वारा उत्पन्न अवरोधों की अवहेलना की गई है।

3 असंतुलित विकास के सिद्धान्त के अनुसार अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में ही विनियोग किया जाता है। इससे प्रारम्भिक अवस्था में जब तक परिपूरक उद्योगों का विकास नहीं हो, साधन प्रयुक्त और निष्क्रिय रहते हैं। इस प्रकार आधिक्य क्षमता (Excess Capacity) के कारण एक ओर काफी अव्यय होता है जब कि दूसरी ओर साधनों के अभाव में उद्योग स्थापित नहीं होते।

4 इस सिद्धान्त के अनुसार, एक क्षेत्र में विनियोगों को केन्द्रित किया जाता है जिससे अर्थव्यवस्था में असंतुलन दबाव और तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हें दूर करने के लिए दूसरे क्षेत्रों में विनियोग किया जाता है और इस प्रकार आर्थिक विकास होता है। किन्तु अर्द्ध-विकसित देशों में ये दबाव और तनाव आर्थिक विकास को अवरुद्ध करने की सीमा तक गम्भीर हो सकते हैं।

5 कुछ आलोचकों के अनुसार तकनीकी अविभाज्यताओं गणना और अनुमान की त्रुटियों एवं माँग तथा पूर्ति की सारणियों के बेलोच स्वभाव के कारण, अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्थाओं में स्वाभाविक रूप से ही असंतुलन उत्पन्न होते रहते हैं। अतः अर्थशास्त्रियों द्वारा नीति के रूप में यह बताया जाना आवश्यक नहीं है।

6 इस सिद्धान्त का समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के लिए सीमित महत्त्व है क्योंकि वहाँ विनियोग सम्बन्धी निश्चय, बाजार-तन्त्र और प्रेरणाओं द्वारा नहीं अपितु राज्य द्वारा किए जाते हैं।

7 असंतुलित विकास के लिए आवश्यक प्रेरणा तान्त्रिकता (Inducement mechanism) का उपयोग वही व्यावहारिक हो सकता है, जहाँ साधनों में आन्तरिक लोच और गतिशीलता हो, किन्तु अर्द्ध-विकसित देशों में साधनों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानान्तरण कठिन होता है।

8 असंतुलित विकास के सिद्धान्त के विरुद्ध सबसे बड़ा तर्क यह प्रस्तुत किया जाता है कि इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसारक प्रवृत्तियों को जन्म मिलता है। इस सिद्धान्त के अनुसार, अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में विनियोग किया जाता है जिससे माँग में वृद्धि होती है। परिणामस्वरूप उपभोक्ता वस्तुओं की माँग और मूल्य अपेक्षाकृत बढ़ जाते हैं। अर्द्ध-विकसित देशों में इन्हें रोकने के लिए मौद्रिक और राजकोपीय उपाय भी प्रभावपूर्ण नहीं हो पाते। इस प्रकार, मुद्रा प्रसारक प्रवृत्तियाँ विकसित होने लगती हैं।

9 हर्षमैन द्वारा उल्लिखित 'शृंखला प्रभाव' (Linkage effects) भी अर्द्ध-विकसित देशों में इतने सक्रिय और प्रभावपूर्ण नहीं सिद्ध होते।

उपरोक्त सीमाओं के होते हुए भी असंतुलित विकास की तकनीक अर्द्ध-विकसित देशों के द्रुत विकास के लिए अत्यन्त उपयोगी है और कई अर्द्ध-विकसित देशों ने विकास के लिए इस युक्ति को अपनाया है। सोवियत रूस ने इस पद्धति को अपना कर अपना द्रुत विकास किया है। भारतीय योजनाओं में भी विशेष रूप से

दूसरी योजना में इस शैली को अपनाया गया है। योजना में विशेषरूप से भारी और आधारभूत उद्योगों के विकास को पर्याप्त महत्त्व दिया गया है। सार्वजनिक विनियोगों में उद्योगों का भाग प्रथम योजना में केवल 5% से भी कम था। किन्तु द्वितीय योजना में यह अनुपात बढ़ कर 19% और तृतीय योजना में 24.2% हो गया था।

प्रो. मिन्ट की विचारधारा

(Approach of Prof Myint)

प्रो मिन्ट (Myint) के अनुसार विदेशी उद्यमियों द्वारा उपनिवेशों में अपनाई गई दुर्भाग्यपूर्ण नीतियों ने इन देशों में विकास की प्रक्रिया के प्रारम्भ को रोक रखा है। इन देशों में संचालित खनन और बागान (Mining and Plantation ventures) व्यवसायों में इनके प्रबन्धकों का यह दृष्टिकोण था कि स्थानीय श्रमिकों में विकास क्षमता नहीं है। अतः न्यून आय वाले देशों के श्रमिकों में प्रचलित आय के स्तर के लगभग बराबर ही मजदूरी दी गई। मजदूरी की यह न्यून दरें जहाँ पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों को आकर्षित नहीं कर सकी, वहाँ पर श्रमिकों का भारत, चीन आदि कम आय वाले देशों से आयात किया। इस सन्दर्भ में प्रो मिन्ट ने एल सी. नोयल्स (L C Knowles) के इस कथन का उद्धरण दिया है कि ब्रिटिश उपनिवेशों की तीन मातृभूमियाँ थी—ब्रिटेन, भारत और चीन। इस प्रकार इन उपनिवेशों में मजदूरी बहुत कम दी गई। प्रो मिन्ट ने सुझाव दिया है कि यदि नियोजकों ने इन्हे उँची मजदूरी दी होती और स्थानीय श्रमिकों की उत्पादकता में उम स्तर तक वृद्धि के लिए प्रयत्न किए होते जिस स्तर ने इस मजदूरी नीति को लाभदायक बनाया होता, तो सम्भवतः उन्होंने विकास की गतिविधियों को प्रेरणा दी होती।

प्रो. मिन्ट के विचारानुसार यदि गाँवों में नई और आकर्षक प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएँ विक्री के लिए पहुँचाई जाती हैं और अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रचलन किया जाता है तो निर्वाह अर्थव्यवस्था (Subsistence Economy) को भी विकास की उत्तेजना मिलती है। नई उपभोक्ता वस्तुओं के परिचय द्वारा विकास की उत्तेजना का विचार मिन्ट के पूर्व भी बतलाया गया था। ये विचार नई आवश्यकताओं के मानव व्यवहार पर प्रभाव के साधारण मनोविज्ञान पर आधारित हैं।

लेबेन्स्टीन की विचारधारा

(Leibenstein's Approach)

प्रो हार्बर्ट लेबेन्स्टीन ने अपनी पुस्तक 'Critical Minimum Effort Thesis' में प्राथमिक विकास से सम्बन्धित बहुत महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए हैं। अपने इस ग्रन्थ में लेबेन्स्टीन ने भारत, चीन, इन्डोनेशिया आदि उन अर्द्ध-विकसित या अल्प-विकसित देशों की समस्याओं का अध्ययन किया है, जिनमें जनसंख्या का घनत्व अधिक है। यद्यपि उनका लक्ष्य इन देशों की समस्याओं को समझना है, उनका समाधान प्रस्तुत करना नहीं तथापि उन्होंने समस्याओं के समाधानार्थ कुछ महत्वपूर्ण उपाय अवश्य सुझाए हैं। लेबेन्स्टीन ने अपनी पुस्तक में यह अध्ययन किया

है कि अर्द्ध-विकसित देशों के पिछड़ेपन से किस प्रकार मुक्ति पाई जा सकती है। उन्होंने अपने ग्रन्थ में विकास के समस्त घटकों और नीतियों को अपनी अध्ययन सामग्री नहीं बनाया है बरन् उनका मुख्य लक्ष्य उनके 'न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न' (Critical Minimum Effort) के बाद या मत (Thesis) को समझाना रहा है।

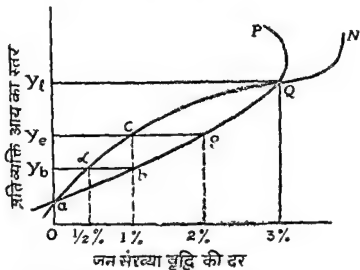
लेबेन्स्टेन के मतानुसार दीर्घकालीन स्थाई और स्वयं स्फूर्त विकास के लिए यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में जो विनियोजन किया जाए वह इतनी मात्रा में हो, जिससे पर्याप्त स्फूर्ति मिल सके। लेबेन्स्टेन के अनुसार मान इसी उपाय से अर्द्ध-विकसित देश अपने आर्थिक दुष्चक्र से मुक्ति पा सकते हैं।

लेबेन्स्टेन के कथनानुसार अर्द्ध-विकसित या अल्प-विकसित देशों में पाए जाने वाले दुष्चक्र उन्हें प्रति व्यक्ति आय के निम्न साम्य की स्थिति में रखते हैं। यद्यपि ऐसे देशों में श्रम और पूँजी की मात्रा में परिवर्तन होते हैं किन्तु उनके प्रभाव के कारण प्रति व्यक्ति आय के स्तर में नगण्य परिवर्तन होते हैं। इस स्थिति से निकलन के लिए कुछ न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न (Critical Minimum Efforts) की आवश्यकता है, जो प्रति व्यक्ति आय को ऐसे स्तर तक बढ़ा दे जहाँ से सतत् विकास-प्रक्रिया जारी रह सके। उन्होंने बताया है कि पिछड़ेपन से हम निरन्तर दीर्घकालीन विकास की आशा कर सकें, यह आवश्यक (यद्यपि सदा पर्याप्त नहीं) शर्त है कि किसी बिन्दु पर या कुछ अवधि में अर्थव्यवस्था को विकास के लिए ऐसी उत्तेजना (Stimulus) मिले जो निश्चित न्यूनतम आवश्यक प्रयत्नों से अधिक हो। लेबेन्स्टेन के मतानुसार प्रत्येक अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की शक्तियाँ क्रियाशील रहती हैं। एक और कुछ उत्तेजक (Stimulants) तत्त्व होते हैं जिनका प्रभाव प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने वाला होता है। दूसरी ओर कुछ पीछे धकेलने वाले (Shocks) तत्त्व होते हैं जो प्रति व्यक्ति आय को घटाने का प्रभाव रखते हैं। अर्द्ध विकसित देशों में प्रथम प्रकार के तत्त्व कम और द्वितीय प्रकार के तत्त्व अधिक प्रभावशील होने हैं। अतः आय घटाने वाले तत्त्वों से कहीं अधिक आय में वृद्धि करने वाले तत्त्वों की उत्तेजित करने पर ही अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगी और ऐसा तभी सम्भव होगा, जबकि न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न (Critical Minimum Efforts) किए जाएँगे।

प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या-वृद्धि का सम्बन्ध—लेबेन्स्टेन का सिद्धान्त इस अनुभव पर आधारित है कि जनसंख्या वृद्धि की दर प्रति व्यक्ति आय के स्तर का फलन (Function) है और यह विकास की विभिन्न अवस्थाओं से सम्बन्धित है। आय के जीवन निर्वाह साम्य स्तर (Subsistence level of income level) पर जन्म और मृत्यु दरें अधिकतम होती हैं। आय के इस स्तर से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर मृत्यु-दरें गिरना प्रारम्भ होती है, यद्यपि प्रारम्भ में जन्म दरें कम नहीं होती है परिणामस्वरूप, जनसंख्या वृद्धि की दर बढ़ जाती है। इस प्रकार, प्रारम्भ में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि की दर को बढ़ाती है किन्तु ऐसा एक सीमा तक ही होता है और उसके पश्चात् प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से

जन्म-दर गिरने लगती है, क्योंकि ड्यूमोंट (Dumont) की 'Social Capillarity' की धारणा के अनुसार, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ-साथ बच्चों की संख्या में वृद्धि द्वारा माता पिताओं की आय में वृद्धि करने की इच्छा कम होती जाती है। इसके अतिरिक्त विशिष्टीकरण सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता तथा नौकरी व्यवस्था आदि में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि आदि कारणों से बड़े परिवार का पालन पोषण कठिन और व्ययसाध्य हो जाता है। अतः आय की वृद्धि के साथ पहले जन्म दरें स्थिर होती हैं तत्पश्चात् गिरना प्रारम्भ कर देती है। इस प्रकार ज्यों-ज्यों अर्थ-व्यवस्था विकास की ओर बढ़ती जाती है जनसंख्या वृद्धि की दर त्यों-त्यों कम होती जाती है। जापान और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों में इस प्रकार के उदाहरण देखे जा सकते हैं। लेवेन्स्टीन के मतानुसार, जीव विज्ञान की दृष्टि से जनसंख्या की अधिकतम वृद्धि की दर 3% से 4% के बीच में होती है। जनसंख्या की इस ऊँची वृद्धि की दर पर काबू पाने और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करके जनसंख्या वृद्धि की दर को घटाने के लिए न्यूनतम आवश्यक प्रयत्नों की आवश्यकता है। इसे निम्न चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है—

चित्र-6



उपरोक्त चित्र में N और P वक्र आय में वृद्धि दर और जनसंख्या में वृद्धि-दर को निर्माण करने वाली प्रति व्यक्ति आय के स्तर को प्रदर्शित करते हैं। a बिन्दु पर जो कि निर्वाह साम्य का बिन्दु है, आय वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि की दर समान है। यदि प्रति व्यक्ति आय में थोड़ी वृद्धि होती है, मानलो यह OY_b हो जाती है, तो जनसंख्या-वृद्धि की दर और आय वृद्धि की दर दोनों बढ़ती है, किन्तु आय-वृद्धि की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि तेजी से होती है। प्रति व्यक्ति आय के इससे भी उच्च स्तर OY_c पर जनसंख्या वृद्धि की दर 2% है जबकि आय-वृद्धि की दर केवल 1% है। चित्र में $Y_b g$ जनसंख्या वृद्धि की दर $Y_c c$ आय वृद्धि की दर से अधिक है। इस

समस्या के समाधान के लिए प्रति व्यक्ति आय की दर इतनी बढ़ानी चाहिए, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर जनसंख्या वृद्धि की दर को पीछे छोड़ दे। ऐसा प्रति व्यक्ति आय के स्तर के Y_0 से अधिक होने पर ही हो सकता है। यहाँ से जनसंख्या-वृद्धि की दर गिरना शुरू हो जाती है अतः निरन्तर आर्थिक विकास की स्थिति को लाने के लिए Y_0 न्यूनतम आवश्यक प्रति व्यक्ति आय का स्तर है और इसे प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न किए जाने चाहिए।

प्रति व्यक्ति आय का स्तर आय में वृद्धि करने वाला तत्त्व है और इसके द्वारा प्रेरित जनसंख्या में वृद्धि, आय घटाने वाला तत्त्व है। अतः निरन्तर आर्थिक विकास की स्थिति में अर्थव्यवस्था को पहुँचाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रारम्भिक पूँजी-निवेश ही निश्चित न्यूनतम स्तर से अधिक हो जो स्वयं उद्भूत या प्रेरित आय घटाने वाली शक्तियों पर काबू पाने योग्य प्रति व्यक्ति आय का उच्च स्तर प्रदान करे।

अर्द्ध-विकसित देशों में जनसंख्या-वृद्धि के अनिरीक भी उत्पादन साधनों की अविभाज्यता के कारण होने वाली आन्तरिक अमितव्ययताएँ, बाह्य-परस्पर निर्भरता के कारण होने वाली बाह्य अमितव्ययताएँ सांस्कृतिक, सामाजिक और सत्यागत बाधाओं की उपस्थिति तथा उन्हें दूर करने की आवश्यकता भी इन देशों में बड़ी मात्रा में आवश्यक न्यूनतम प्रयत्नों की अनिवार्यता सिद्ध करती है। किन्तु अर्द्ध-विकसित देशों में आय केवल जीवन निर्वाह स्तर योग्य होती है और इसका समस्त व्यय प्रचलित उपभोग के लिए ही होता है। बहुत थोड़ी राशि ही मानव और भौतिक पूँजी निर्माण के लिए व्यय की जा सकती है। अतः सतत आर्थिक विकास का पथ प्रणाल्य करने के लिए न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न (Critical Minimum Efforts) आय के जीवन-निर्वाह से अधिक ऊँचे स्तर पर होना चाहिए।

विकास-अभिकर्ता (Growth Agents)—लेवेन्स्टीन ने अपने सिद्धान्त को इस तर्क पर आधारित किया है कि अर्थव्यवस्था में विकास के लिए उपयुक्त कुछ आर्थिक दशाएँ उपस्थित रहती हैं जो आय-वृद्धि की शक्तियों की आय में कमी करने वाली शक्तियों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ाती हैं। 'विकास अभिकर्ता' (Growth Agents) इन दशाओं को जन्म देते हैं। 'विकास अभिकर्ता' वे होते हैं, जो विकास में योग देने वाली क्रियाओं (Growth Contributing Activities) को संचालित करते हैं। उद्यमी (Entrepreneur), वित्तियोजक (Investor), बचत करने वाले (Saver) एवं नव प्रवर्तक (Innovator) आदि उल्लेखनीय विकास अभिकर्ता हैं। विकास साधकों का इस विकास में योगदान देने वाली क्रियाओं के कारण पूँजी और बचत की दर धर्म-शक्ति की कुशलता, ज्ञान और जोखिम की मात्रा में वृद्धि होती है। लेवेन्स्टीन के अनुसार 'विकास साधकों का विस्तार होगा या नहीं यह इन क्रियाओं के सम्भावित और वास्तविक परिणाम तथा सम्भावनाओं, क्रियाओं और परिणामों की अन्त क्रिया द्वारा उत्पन्न प्राये विस्तार (Expansion) और संकुचन (Contraction) के लिए प्रेरणाओं पर निर्भर करते हैं। ये प्रेरणाएँ दो प्रकार की होती हैं।

(i) शून्य-राशि प्रेरणाएँ (Zero sum Incentives)—इनसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं होती है, इनका केवल वितरणात्मक प्रभाव होता है।

(ii) धनात्मक राशि-प्रेरणाएँ (Positive sum Incentives)—जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती हैं केवल दूसरे प्रकार की प्रेरणाओं द्वारा ही आर्थिक विकास हो सकता है। किन्तु अर्द्ध-विकसित देशों में प्रथम प्रकार की क्रियाओं में ही व्यक्ति सचन रहने हैं और दूसरे प्रकार की क्रियाएँ अत्यल्प मात्रा में संचालित की जाती हैं। जो कुछ इस प्रकार की क्रियाएँ की जाती हैं वे अर्थव्यवस्था में विशुद्ध विकास की अनुपस्थिति के कारण प्रभावहीन ही रहती हैं। इसके प्रतिरिक्त प्रति व्यक्ति आय पर विपरीत प्रभाव डालने वाली निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ भी क्रियाशील रहती हैं—

- (i) सम्भावित वृद्धिमान आर्थिक अवसरों में कटौती और रोक द्वारा वर्तमान आर्थिक प्रियायतों (Privileges) को बनाए रखने वाली (Zero-sum Activities) शून्य राशि प्रेरणाएँ।
- (ii) परिवर्तन के प्रतिरोध में की गई संगठित और असंगठित श्रम द्वारा की जाने वाली अनुदार कार्यवाहियाँ।
- (iii) नवीन ज्ञान और विचारों का अवरोध।
- (iv) निजी और सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा अनुत्पादक प्रकृति के व्यय में वृद्धि।
- (v) जनसंख्या-वृद्धि के परिणामस्वरूप होने वाली श्रम-शक्ति में वृद्धि जिसके कारण प्रति व्यक्ति उपलब्ध पूँजी की मात्रा कम हो जाती है।

आर्थिक प्रगति पर विपरीत प्रभाव डालने वाले उपरोक्त तत्त्वों को प्रभावहीन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न (Sufficiently large critical minimum efforts) किए जाने चाहिए, जो धनात्मक-राशि क्रियाओं को उत्तेजित करें। ऐसा होने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी जिसके कारण बचत और विनियोग की मात्रा बढ़ेगी। परिणामस्वरूप, 'विकास अभिकर्ताओं' (Growth Agents) का विस्तार होगा, विकास में उनका योगदान बढ़ेगा, विकास में बाधक तत्वों की प्रभावहीनता बढ़ेगी, सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता को बढ़ाने वाले सामाजिक वातावरण का निर्माण होगा, विशिष्टीकरण बढ़ेगा और द्वितीयात्मक और तृतीयात्मक उद्योगों का विस्तार होगा। इन सबके कारण सामाजिक वातावरण में ऐसे परिवर्तनों का मार्ग साफ होगा जिससे जन्म-दर और जनसंख्या वृद्धि की दरें गिर जाएँगी। प्रो लेवेन्स्टीन ने अर्द्ध-विकसित देशों के लिए इस न्यूनतम आवश्यक प्रयत्नों की मात्रा का भी अनुमान लगाया है।

समीक्षा—प्रो लेवेन्स्टीन ने अपनी पुस्तक के प्राक्कथन में लिखा है कि उनका उद्देश्य स्पष्टीकरण और व्याख्या करना है, न कि कोई नुस्खा बताना है। किन्तु उनके इस सिद्धान्त ने कई अर्थशास्त्रियों और नियोजकों को आकर्षित किया है और यह अर्द्ध-विकसित देशों के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने का एक उपाय माना जाने लगा है। इसका एक कारण तो यह है कि उसका यह विचार अधिकांश अर्द्ध-विकसित देशों द्वारा अपनाई गई जनतान्त्रिक नियोजन (Democratic Planning)

पद्धति से मेल खाता है। इसके साथ ही यह रोजेन्स्टीन रोडान (Rosenstein Rodan) के 'बड़े धक्के' (Big Push) के सिद्धान्त की अपेक्षा वास्तविकता के अधिक निकट है, क्योंकि, अर्द्ध-विकसित देशों के औद्योगीकरण के लिए एक बार ही 'बड़ा धक्का' देना कठिन होता है, जबकि लेबेन्स्टीन के 'न्यूनतम आवश्यक प्रयत्नों' की छोटे प्रयत्नों के रूप में टुकड़ो-टुकड़ो में विभाजित करके प्रयोग में लाया जा सकता है।

किन्तु यह सिद्धान्त भी आलोचना मुक्त नहीं कहा जा सकता। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर एक बिन्दु तक जनसंख्या-वृद्धि की दर बढ़ती जाती है और उसके पश्चात् उसमें गिरावट आने लगती है। किन्तु वस्तुतः यह प्रथम प्रक्रिया, अर्थात्, जनसंख्या-वृद्धि की दर बढ़ने का कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं, अपितु चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि के कारण घटने वाली मृत्यु-दर है। उदाहरणार्थ, भारत में 1911-21 में मृत्यु-दर 48.6 प्रति हजार से घट कर 1951-61 में 22.8 प्रति हजार रह जाने के कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं, अपितु रोगों पर नियंत्रण और चिकित्सा व जन-स्वास्थ्य का अधिक ज्ञान और इन सुविधाओं में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार इस बिन्दु के पश्चात् जन्म-दर में कमी का श्रेय न्यूनतम आवश्यक स्तर पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को नहीं है। अर्द्ध-विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जन्म दर को नहीं घटा सकती है। जापान एवं अन्य प्रगतिशील देशों में जिनके आधार पर लेबेन्स्टीन ने अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया है, यह सत्य हो सकता है। किन्तु अर्द्ध-विकसित देशों में जन्म-दर को घटाने के लिए लोगों के दृष्टिकोण समग्र सामाजिक संस्थाओं आदि में परिवर्तन और शिक्षा प्रचार की आवश्यकता है। वस्तुतः जन्म दर में कमी करने के लिए प्रति व्यक्ति आय में न्यूनतम आवश्यक स्तर से अधिक वृद्धि होने तक कोई भी अर्द्ध-विकसित देश प्रतीक्षा नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या की स्थिति विस्फोटक दशा ग्रहण कर सकती है।



आर्थिक विकास के लिए नियोजन

(Planning for Economic Growth)

“आयोजन का अर्थ केवल कार्य-सूची बना लेने से नहीं होता और न ही यह एक राजनीतिक आदर्शवाद है। आयोजन एक बुद्धिमत्तापूर्ण, विवेकपूर्ण तथा वैज्ञानिक पद्धति है जिसके अनुसार हम अपने आर्थिक व सामाजिक उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं व प्राप्त कर सकते हैं।” — जवाहरलाल नेहरू

नियोजित अर्थ-व्यवस्था आधुनिक काल की एक नवीन प्रवृत्ति है। 19वीं शताब्दी में पूँजीवाद, व्यक्तिवाद और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का बोल बाला रहा तथा अठ्ठाईस देश स्वतन्त्र व्यापार-नीति और आर्थिक स्वतन्त्रता के समर्थक रहे। लेकिन पिछली अर्द्ध-शताब्दी में रूस की क्रान्ति, सन् 1929-32 की विश्व-व्यापी आर्थिक-मन्दो, दो भीषण महायुद्धों व उपनिवेशवाद की समाप्ति, लोक-वित्त, तकनीकी प्रगति, एवं सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रवृत्तियाँ आदि के कारण आर्थिक नियोजन का महत्त्व स्थापित हो चुका है और आज प्रत्येक देश में किसी न किसी अंश में नियोजन का मार्ग अपनाया जा रहा है। ससार के लगभग सभी देश अपने आर्थिक विकास और उन्नति के लिए आर्थिक नियोजन में जुटे हुए हैं।

आर्थिक नियोजन इतना महत्त्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध हुआ है कि अमेरिका, ब्रिटेन आदि स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था वाले देश भी व्यापक अर्थ में नियोजन का सहारा लेने लगे हैं। अर्द्ध-विकसित देशों में तो नियोजन अत्यधिक लाभदायक है ही क्योंकि इसके द्वारा शीघ्र पूँजी-निर्माण की प्रक्रिया को गति देकर द्रुत आर्थिक विकास किया जाना सम्भव है। अर्द्ध विकसित देशों की मूल समस्या कीमत स्थायित्व के साथ आर्थिक वृद्धि करना है। आर्थिक वृद्धि की उच्च दर, आर्थिक नियोजन पर निर्भर करती है। नियोजित अर्थ व्यवस्था में ही एक अभीष्ट सीमा तक पूर्ण रोजगार, समानता, स्थायित्व आत्म-निर्भरता आदि आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति सम्भव है। अनियोजित अथवा निजी उद्यम वाली स्वचालित अर्थ व्यवस्था में संतुलन की स्थिति तो सम्भव है, किन्तु आर्थिक विकास की उच्च दर के लिए स्वचालित अर्थ-व्यवस्था के निम्न स्तरीय संतुलन को नष्ट करना आवश्यक है। कीन्स के अर्थशास्त्र में स्पष्ट संकेत

मिलता है कि स्वतः प्राप्त पूर्ण रोजगार जैसी कोई स्थिति नहीं होती है (There is no automatic full employment)। 'पैरेटो उत्तमावस्था' (Pareto-optimality) का सिद्धान्त भी यह स्पष्ट करता है कि सम्पत्ति व आय का वितरण इस सिद्धान्त की मुख्य शर्तों के अन्तर्गत नहीं आता अर्थात् विकास, समानता, स्थायित्व, आत्म-निर्भरता, पूर्ण रोजगार आदि आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक नियोजन आवश्यक है। इसीलिए अर्द्ध-विकसित देशों में आर्थिक वृद्धि की उच्च दर प्राप्त करने के लिए नियोजन का मार्ग अपनाया जाता है।

नियोजित और अनियोजित अर्थ-व्यवस्था की तुलना (Comparison of Planned and Un-planned Economies)

जो देश आर्थिक विकास तथा अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आर्थिक नियोजन की पद्धति को अपनाते हैं, उस देश की अर्थ-व्यवस्था को नियोजित अर्थ-व्यवस्था (Planned Economy) कहते हैं। 'नियोजित अर्थ-व्यवस्था' में केन्द्रीय नियोजन सत्ता द्वारा सचेत रूप से निर्धारित आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है जिन पर सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है। नियोजित अर्थ-व्यवस्था के विपरीत अनियोजित अर्थ-व्यवस्था वह होती है जो आर्थिक नियोजन को नहीं अपनाती है। नियोजित और अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में होने वाले निम्नलिखित प्रमुख अन्तर हैं—

नियोजित अर्थ-व्यवस्था (Planned Economy)	अनियोजित अर्थ-व्यवस्था (Un planned Economy)
1 इसमें समस्त अर्थ-व्यवस्था को एक इकाई मान कर सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्र के लिए योजना बनाई जाती है।	1 इसमें व्यक्तिगत मांग के अनुसार व्यक्तिगत उत्पादक इकाई के लिए योजना बनाई जाती है।
2. आर्थिक क्रियाओं के निर्देशन के लिए केन्द्रीय नियोजन अधिकारी होता है।	2 इसमें ऐसा नहीं होता है।
3 सावजनिक हित सर्वोपरि होता है।	3. निजी लाभ अधिक महत्त्वपूर्ण होता है।
4. आर्थिक क्रियाओं पर राज्य नियन्त्रण होता है।	4. आर्थिक क्रियाएँ राज्य-नियन्त्रण और हस्तक्षेप से मुक्त होती हैं।
5 उत्पादन राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है।	5. उत्पादन मांग के अनुसार किया जाता है।
6 मूल्य-तान्त्रिकता महत्त्वहीन होती है।	6. मूल्य तान्त्रिकता महत्त्वपूर्ण होती है।
7. यह नियमित अर्थ-व्यवस्था होती है।	7 यह स्वतन्त्र प्रतियोगिता पर आधारित होती है।

नियोजित अर्थ-व्यवस्था (Planned Economy)	अनियोजित अर्थ-व्यवस्था (Un-planned Economy)
8. इसमें समस्त राष्ट्र के दृष्टिकोण से उद्देश्य निश्चित होते हैं।	8. बहुधा समस्त राष्ट्र के दृष्टिकोण से उद्देश्य निश्चित नहीं किए जाते।
9. उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक निश्चित अवधि होती है।	9. इसमें कोई निश्चित अवधि नहीं होती।
10. यह समाजवाद के अधिक निकट है।	10. यह पूँजीवाद से सम्बन्धित है।
11. यह एक विवेकपूर्ण अर्थ-व्यवस्था है।	11. यह आकस्मिक अर्थ-व्यवस्था है।

नियोजित अर्थ-व्यवस्था की श्रेष्ठता (Superiority of Planned Economy)

नियोजित अर्थ-व्यवस्था की उपयोगिता का आभास हमें पूर्वोक्त विवरण से मिल चुका है। आज विश्व के लगभग सभी देश किसी न किसी रूप में आर्थिक नियोजन को अपनाए हुए हैं और इसका कारण नियोजन से होने वाले प्रतिशत लाभ ही है। ये लाभ इतने महत्वपूर्ण हैं कि कोई भी आधुनिक राष्ट्र इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। अधिकांश अर्द्ध-विकसित देशों ने द्रुत आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन की तकनीक अपनाकर अपने यहाँ नियोजित अर्थ-व्यवस्था स्थापित करके उसके सुन्दर फलों को चखा है और हम भी आर्थिक विकास को और तेजी से बढ़ाने लगे हैं। कई देशों में पूर्ण रूप से नियोजित अर्थ-व्यवस्था (Planned Economies) है। आर्थिक नियोजन के सहारे ही सोवियत रूस ने इतनी आश्चर्यजनक प्रगति की है कि प्रो एस. ई. हेरिस के इस मत से कोई मतभेद नहीं हो सकता कि 'विश्व के अन्य किसी भी देश ने इतनी द्रुतगति से एक पिछड़ा हुआ कृषि-प्रधान देश से अत्यधिक औद्योगिक, औद्योगिक शक्ति सम्पन्न देश में परिवर्तित होने का अनुभव नहीं किया है।' लेकिन अनेक व्यक्ति आर्थिक नियोजन के मार्ग के कटु आलोचक हैं। प्रो हेयक (Prof Hayek) नियोजन को दासता का मार्ग मानते हैं। हमारे लिए इन विरोधी विचारों का मूल्यांकन करने के लिए यह उपयुक्त होगा कि हम आर्थिक नियोजन के पक्ष और विपक्ष, दोनों पहलुओं को देख लें।

नियोजन के पक्ष में तर्क (Arguments for Planning)

आर्थिक नियोजन की श्रेष्ठता के पक्ष में निम्नलिखित प्रमुख तर्क दिए जाते हैं—

1. तीव्र आर्थिक विकास सम्भव—आर्थिक नियोजन की पद्धति को अपना कर ही तीव्र आर्थिक विकास किया जा सकता है। जैसे तो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि पश्चिमी देश आर्थिक नियोजन के बिना ही आर्थिक प्रगति के उच्च स्तर पर पहुँच गए हैं। किन्तु इनमें इन्हे पर्याप्त समय लगा है और इनकी प्रगति अपेक्षाकृत

बम भी रही है, जबकि, रूस, चीन आदि देशों ने नियोजन का सहारा लेकर अत्यल्प समय में ही द्रुत आर्थिक विकास किया है। आधुनिक अर्थ-विकासन देशों के लिए भी तेजी से आर्थिक विकास उनके जीवन मरण का प्रश्न बन गया है। अतः उनके लिए नियोजन-पद्धति अपनाना अधिक वांछनीय है। आर्थिक नियोजन से इन देशों का द्रुत आर्थिक विकास तो होगा ही, साथ ही, ऐसा इन देशों की ग्रंथ व्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में होगा। आर्थिक नियोजन में कृषि, उद्योग शक्ति सिंचाई, यातायात, संचार, सेवाओं आदि सभी क्षेत्रों में विवेकपूर्ण और सतृलित कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। अतः नियोजन पद्धति अपनाने पर इन देशों में उत्पादन, राष्ट्रीय आय आदि में वृद्धि होगी जिससे देशवासियों का जीवन-स्तर उच्च होगा और जनता की सुखी एवं परिपूर्ण जीवन बिता पाने की आकांक्षाएँ मूर्त रूप ग्रहण कर पाएँगी।

2 निर्णयों एवं कार्यों में समन्वय—अनियोजित अर्थ-व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें असंय्य उद्योगपति व्यापारी उत्पादक आदि अलग अलग आर्थिक और उत्पादक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं और उनके निर्णयों एवं कार्यों में समन्वय करने की कोई व्यवस्था नहीं होती। वे अपनी इच्छानुसार मनमाने निर्णयों के अनुसार उत्पादन करते हैं और उनमें कोई ताल मेल नहीं होता। प्रो. लर्नर (Prof Lerner) के अनुसार ऐसी अर्थ व्यवस्था उस मोटर के समान है जो चालक रहित है किन्तु जिसके सब यात्री इसके स्टियरिंग व्हील के पास इन्हीं अपनी इच्छानुसार घुमाने के लिए पहुँचने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके विपरीत नियोजित अर्थ-व्यवस्था में एक केन्द्रीय नियोजन अधिकारी की देख रेख में देश की आवश्यकताओं और साधनों के अनुसार उत्पादन सम्बन्धी निर्णय किए जाते हैं, जिन्हें पूर्ण करने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम बनाया जाता है। इससे अर्थ-व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं होती।

3 दूरदर्शितापूर्ण अर्थ व्यवस्था—एक नियोजित अर्थ-व्यवस्था, अनियोजित अर्थ-व्यवस्था की अपेक्षा अधिक दूरदर्शितापूर्ण होती है। इसीलिए, इसे 'खुले हुए नेत्र वाली अर्थ-व्यवस्था' (An economy with open eyes) कहते हैं। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में नियोजन-सत्ता अर्थ व्यवस्था में बहुत ही धीरे धीरे होने वाली और सूक्ष्म-परिवर्तनों पर भी विचार कर लेती है, जिनके बारे में अनियोजित अर्थ-व्यवस्था के व्यक्तिगत उत्पादक की बिस्कुल जानकारी भी नहीं हो पाती। एक केन्द्रीय अधिकारी इस बात का पता लगा सकता है कि कच्चे माल का तेजी से शोषण तो नहीं हो रहा है, साधनों का अपव्यय तो नहीं हो रहा है, मानवीय शक्ति का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है या जनमस्या तेजी से तो नहीं बढ़ रही है। यदि ऐसा हो तो इनकी रोकथाम के लिए तुरन्त कदम उठाए जा सकते हैं। इस प्रकार, नियोजित अर्थ-व्यवस्था में साधनों का भी दूरदर्शितापूर्ण उपयोग होता है।

4 व्यापार चक्रों से मुक्ति—व्यापार-चक्र अनियोजित अर्थ-व्यवस्थाओं की सबसे बड़ी दुर्बलता है। इन अर्थ-व्यवस्थाओं में आर्थिक तेजी और मंदी के चक्र नियमित रूप से आते रहते हैं, जिनके लिए पूँजीवाद की कुछ विशेषताएँ जैसे स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा, लाभ-उद्देश्य (Profit Motive) एवं अनियमित निजी उपभोग आदि

उत्तरदायी हैं। व्यापार-चक्र अर्थ-व्यवस्था में अस्थिरता और अनिश्चितता पैदा करके भारी आर्थिक बुराइयों को जन्म देते हैं। नियोजन रहित अर्थ-व्यवस्था में व्यक्तिगत उत्पादक, अपनी इच्छानुसार, उत्पादन करते हैं और इससे उत्पादन कभी माँग से कम और कभी अधिक होने की सब सम्भावनाएँ रहती हैं। यही कारण है कि अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में समय-समय पर आर्थिक उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, जबकि अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में प्रायः ऐसा नहीं होता। सन् 1930 की विश्वव्यापी मंदी से अमेरिका, इंग्लैण्ड आदि बहुत बुरी तरह ग्रस्त थे।

5. उत्पत्ति के साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग—अर्द्ध-विकसित देशों में उत्पत्ति के साधनों की बड़ी कमी होती है इसलिए देश के अधिकतम लाभ और सामाजिक कल्याण की दृष्टि से इन सीमित साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। किन्तु अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में आवश्यक और अनावश्यक पदार्थों के उत्पादन के बीच साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, क्योंकि व्यक्तिगत उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जो उसे अधिकाधिक लाभ दे, न कि उन वस्तुओं का, जो सामाजिक दृष्टि से आवश्यक हों। यदि अनाज के उत्पादन की अपेक्षा मादक पदार्थों के उत्पादन में विनियोग से उसे अधिक लाभ होगा तो वह अनाज के स्थान पर इन मादक पदार्थों का ही उत्पादन करेगा। इस प्रकार, अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में साधन अनावश्यक कार्यों में भी लगा दिए जाते हैं जबकि, आवश्यक परियोजनाएँ साधनों के अभाव में शुरू नहीं हो पाती। किन्तु नियोजित अर्थ-व्यवस्था में सामाजिक आवश्यकताओं की दृष्टि में रखते हुए साधनों का विवेकपूर्ण आवंटन होता है।

6. प्रतिस्पर्धाजनित दोषों से मुक्ति—प्रतिस्पर्धा के कारण, जो अनियोजित पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था की एक प्रमुख सस्या है, बहुमूल्य साधनों का अपव्यय होता है। सम्भावित ग्राहकों को आकर्षित करने और अपनी विश्नी बढ़ा कर लाभ कमाने के लिए विभिन्न प्रतिस्पर्धी फर्में विज्ञापन, विक्रय कला आदि पर विपुल धन-राशि व्यय करती हैं। कभी-कभी गलघोट्ट प्रतिযোগिता (Cut-throat Competition) के कारण कई फर्में बरबाद हो जाती हैं। प्रतिस्पर्धा के कारण प्रतिस्पर्धी फर्मों में कर्मचारियों और औद्योगिक उपकरणों का दुहराव भी होता है। प्रा डबिन (Durbin) के अनुसार 'प्रतिस्पर्धा की सस्या आर्थिक जीवन को बुद्धिमत्तापूर्ण दशा में नहीं ले जाती है।' नियोजित अर्थ-व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा को अत्यन्त सीमित कर दिया जाता है। अतः यहाँ इन दोषों से मुक्ति मिल जाती है।

7. आर्थिक समानता की स्थापना—अनियोजित अर्थ-व्यवस्था की कुछ सस्याओं जैसे निम्नी-सम्पत्ति, उत्तराधिकार और मूल्य-प्रक्रिया आदि के कारण इसमें भारी आर्थिक विषमता पायी जाती है, जिसे किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता है। इन सस्याओं के कारण आय की विषमता, धन की विषमता और अवसरों की विषमता उत्पन्न होती है, जिससे एक ओर समाज के कतिपय व्यक्तियों के पास समाज का धन केन्द्रित हो जाता है तो दूसरी ओर अधिकांश जनता की बुनियादी आवश्यकताएँ भी पूरी नहीं हो पाती हैं। प्रो. डबिन के अनुसार, "अनियोजित

अर्थ-व्यवस्था में सामाजिक समानता नहीं हो सकती है।" ऐसी स्थिति में सामाजिक कटुता उत्पन्न होती है और वर्ग-संघर्ष बढ़ता है। यही नहीं, ऐसी स्थिति में, समाज कुछ योग्य व्यक्तियों की सेवा से भी वंचित हो जाता है। किन्तु नियोजित अर्थ-व्यवस्थाओं में, अनियोजित अर्थ-व्यवस्थाओं की अपेक्षा बहुत कम आर्थिक समानता की ओर बढ़ना है इसलिए इन देशों के लिए नियोजित अर्थ व्यवस्था उपयुक्त है।

8. शोषण की समाप्ति—अनियोजित पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्थाओं में एक अन्य बुराई सामाजिक परोपजीविका (Social Parasitism) की पाई जाती है। अनेक व्यक्ति बिना श्रम किए ही अनाजित आय (Unearned Income) के द्वारा जीविका निर्वाह करते हैं। कई व्यक्तियों को उत्तराधिकार में भारी सम्पत्ति मिल जाती है। कई व्यक्ति लगान, व्याज लाभ, के रूप में भारी मात्रा में आय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वे बिना श्रम किए ही इस प्रकार की आय प्राप्त करने में समर्थ होने हैं। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में इस प्रकार के शोषण और परोपजीविका को समाप्त किया जाता है। अनियोजित अर्थ-व्यवस्था विशाल जनमनुदाय को आय और रोजगार की सुरक्षा प्रदान करने में भी अक्षम रहती है। किन्तु नियोजित अर्थ-व्यवस्था में कार्य और आवश्यकता के अनुसार पारिश्रमिक दिए जाने की व्यवस्था की जाती है और जनता की अधिक सामाजिक सुरक्षा (Social Security) का प्रदम्ब किया जाता है।

9. कृत्रिम अभावों के सृजन का भय नहीं—अनियोजित अर्थ-व्यवस्थाओं में धनप्राप्ति के कृत्रिम अभावों का सृजन किया जाता है ताकि उपभोक्ताओं से ऊँचे मूल्य लेकर अधिकाधिक लाभ कमाया जा सके। इसके साथ ही एकाधिकार और आर्थिक संघर्षवाद के द्वारा भी मूल्य-वृद्धि करके उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। किन्तु नियोजित अर्थ-व्यवस्थाओं में उत्पादन के साधनों, व्यवसाय आदि पर बहुधा सरकारी स्वामित्व रहता है या उद्योगपतियों, व्यापारियों आदि पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। अतः इस प्रकार शोषण सम्भव नहीं है।

10. अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में सामाजिक लागतों की वृद्धि—पंचालन के परिणामस्वरूप उद्योगों के निजी-उपक्रम द्वारा समाज को कुछ हानिकारक परिणाम भुगताने पड़ने हैं जिन्हें सामाजिक लागतें (Social Costs or Un-compensated Disservices) कहा जाता है। ये लागतें प्रौद्योगिक बीमारियों, चनीय बेकारी, औद्योगिक बेकारी, गंदी वस्तुओं का निर्माण, धुँआँ-पूँछ वानावरण आदि के रूप में होती हैं। इनका भार निजी उद्योगपतियों को नहीं अपितु, समाज को उठाना पड़ता है। निजी उपक्रमियों द्वारा लागू की गई तकनीकी प्रगति से भी कुछ स्थितियों में मशीनों और श्रमिकों की अप्रयुक्तता बढ़ती है किन्तु नियोजित अर्थ-व्यवस्था में इस प्रकार की समस्याओं से बचना सम्भव है क्योंकि इन समस्याओं के समाधान की पूर्ण व्यवस्था कर ली जाती है।

11. जन-कल्याण के ध्येय की प्रमुखता—अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में आर्थिक क्रियाएँ और उत्पादन-कार्य निजी उद्योगपतियों द्वारा निजी लाभ के लिए किया जाता है। वही सामाजिक-कल्याण पर ध्यान नहीं दिया जाता। यही कारण है कि

अनियोजित पूँजीवादी व्यवस्था में वस्तुओं के गुणों में गिरावट, खराब वस्तुओं की मिलावट और मूल्य वृद्धि द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। कम मजदूरी देकर या अधिक समय काम करा करके श्रमिकों का भी शोषण किया जाता है। इस प्रकार अनियोजित अर्थव्यवस्था में निजी-लाभ को प्रमुखता दी जाती है। इसके विपरीत, नियोजित अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं अपितु अधिकाधिक जनता के अधिकतम कल्याण के लिए आर्थिक क्रियाएँ संचालित की जाती हैं।

12. जनता का विशेष रूप से श्रमिक वर्ग को सहयोग मिलना—नियोजित अर्थव्यवस्था में सरकार को जनता का अधिकाधिक सहयोग उपलब्ध होता है क्योंकि उनका विश्वास होता है कि नियोजन के लाभ एक व्यक्ति या एक वर्ग को नहीं अपितु समस्त जनता को मिलने वाले हैं। ऐसी व्यवस्था में श्रमिकों का भी अधिकाधिक सहयोग मिलता है क्योंकि उनके हितों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। इसके विपरीत, अनियोजित अर्थव्यवस्था में निजी-उत्पादकों को श्रमिकों का पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाता है और उनके सहयोग के अभाव में उत्पादन में अधिक प्रगति नहीं की जा सकती है। श्रम-संधी द्वारा अपनाई जाने वाली 'धीरे चलो' (Go slow) नीति का उत्पादन और आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

13. पूँजी निर्माण की ऊँची दर—नियोजित अर्थव्यवस्था में एक विवेकपूर्ण योजना के अनुसार कार्य किया जाता है। साथ ही इसमें वर्तमान के साथ भावी प्रगति पर भी ध्यान दिया जाता है। इसलिए उद्योगों को कम करके बचत-विनियोग और पूँजी निर्माण की दर तेजी से बढ़ाई जा सकती है। सार्वजनिक उपक्रमों का विस्तार होता है और उसके लाभों का भी पुनर्विनियोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, सोवियत रूस में विगत कुछ वर्षों में पूँजी-संचय की दर सब पूँजीवादी अनियोजित अर्थव्यवस्था वाले देशों से अधिक रही है। अर्द्ध-विकसित देशों की एक बड़ी समस्या पूँजी का अभाव है, जिसका आर्थिक विकास में बहुत महत्व है। अतः ये देश नियोजित पद्धति द्वारा पूँजी निर्माण दर में तेजी से वृद्धि करके ही तेजी से आर्थिक विकास कर सकते हैं।

14 अधिकतम तकनीकी कुशलता (Maximum Technical Efficiency)—अधिकतम तकनीकी कुशलता के सिद्धान्त के अनुसार एक नियोजित अर्थव्यवस्था में उत्पादन साधनों को संगठित करके कई प्रकार की मितव्ययताएँ प्राप्त की जा सकती है। एफ. ज़्वेनिग (F Zvenig) के अनुसार नियोजित अर्थव्यवस्था में उत्पादक साधनों के संगठन के पैमाने में विस्तार, निजी-स्वत्वों और इच्छाओं पर ध्यान दिए बिना उनके पुनर्व्यवस्था की सम्भावनाएँ, एक ओर यन्त्र और श्रम के विशिष्टीकरण के नए अवसर प्रदान करेगी वही दूसरी ओर ससाधन का केन्द्रीकरण करेगी। परिणामस्वरूप उद्योगों का अधिक लाभदायक स्थानों में हस्तान्तरण, उत्पादन की अच्छे संगठित कारखानों का आवंटन और औद्योगिक इकाइयों का विलीनीकरण या परस्पर अधिक सहयोग सम्भव होगा। इसके अतिरिक्त अनियोजित अर्थव्यवस्था में ससाधनों का पूर्ण उपयोग सम्भव नहीं होता। ऐसी स्थिति में विशाल

माना में प्राकृतिक और मानवीय साधन अत्यधिक रहने हैं। अर्द्ध-विकसित देशों में पूँजी की अपेक्षा प्राकृतिक और मानवीय साधन ही अधिक रहने हैं और ये देश एक निश्चित योजनानुसार इनका दुरुपयोग कच्चे तेजी से आर्थिक विकास कर सकते हैं।

15 राष्ट्रीय संकट के समय सर्वाधिक उपयुक्त व्यवस्था—अनियोजित अर्थव्यवस्था युद्ध या संकटकालीन स्थिति में सर्वथा अपेक्षणीय होती है। ऐसे संकटों में मुक्ति के लिए अर्थव्यवस्था पर विभिन्न प्रकार के नियन्त्रण लगाए जाते हैं। यहाँ तक कि पूँजीवाद का गढ़ कहलाने वाले संयुक्तराज्य अमेरिका ने भी द्वितीय महा युद्ध में विजय पाने के लिए बड़ी सीमा तक आर्थिक नियोजन को अपनाया था। इस प्रकार ऐसे समय अनियोजित अर्थव्यवस्था भी नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तित हो जाती है।

नियोजित व्यवस्था के विपक्ष में तर्क (Arguments against Planned Economy)

नियोजित अर्थव्यवस्था में कमियाँ भी हैं जिनके कारण कुछ लोगो ने इसके विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था के विरुद्ध निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं—

1 अस्त-व्यस्त (Muddled) अर्थव्यवस्था—नियोजित अर्थव्यवस्था में बाजार और मूल्य तान्त्रिकता (Market and Price Mechanism) पर आधारित स्वयं संचालकता (Automaticity) समाप्त हो जाती है। अतः आर्थिक क्रियाओं में विवेकशीलता नहीं रहती क्योंकि योजना अधिकारी द्वारा किए गए मनमाने निर्णयों के आधार पर उत्पादन का कार्यक्रम बनाया जाता है। इसीलिए नियोजित अर्थव्यवस्था को अंधेरे में छलांग (Leap in the dark) कहा जाता है। किन्तु इसका आशय यह नहीं है कि नियोजित अर्थव्यवस्था से मूल्य प्रक्रिया बिल्कुल समाप्त हो जाती है। उदाहरणार्थ, सोवियत रूस में नियोजन सत्ता द्वारा निर्धारित कीमतों (Assigned Prices) की नीति को अपनाया जाता है। वहाँ न केवल पदार्थों के मूल्य अपितु उत्पादन के साधनों की कीमतें भी नियोजन सत्ता द्वारा निर्धारित की जाती हैं।¹

2 अकुशलता में वृद्धि—पूर्णरूप से नियोजित अर्थव्यवस्था में समस्त उत्पादन कार्य सरकार द्वारा किया जाता है और उत्पादन में सम्मिलित अधिकांश कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हो जाते हैं। सरकारी कर्मचारी स्वाभाविक रूप से ही निजी स्वतन्त्रता के अभाव में अकुशलता में वृद्धि करते हैं। उत्पादन की शर्त-संस्थानों (Service Conditions), वेतन, प्रेम, उत्प्रेक्षा के अभाव आदि पूर्व-निर्धारित होते हैं अतः उत्तम अधिक कुशलता से कार्य करने की प्रेरणा तथा पहल की भावना समाप्त हो जाती है। पूर्ण नियोजित अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है तथा सनकता, कुशलता, मित-व्यय, नव प्रयत्न आदि प्रतिस्पर्धाजनित लाभों से समाज वंचित रह जाता है।

3 तानाशाही और लाल फीताशाही का भय—प्रालोचको का यह कथन है कि नियोजित अर्थ-व्यवस्था में तानाशाही और लाल फीताशाही का पोषण होता है। समस्त देशवासी केवल मजदूर बन जाते हैं तथा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ही सब निर्णय लिए जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को कोई महत्व नहीं दिया जाता और सरकार ही सर्वशक्तिमान बन जाती है। बहुधा यह कहा जाता है कि तानाशाही के बिना नियोजन अमम्भव है किन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है। विगत कुछ वर्षों में सोवियत रूस में भी तत्कालीन प्रधानमंत्री ख्रुश्चेव ने सरकारी मशीनरी के विकेन्द्रीकरण की योजना बनाई थी। इसके अतिरिक्त जनतान्त्रिक नियोजन (Democratic Planning) में तो यह समस्या उदय ही नहीं होती। प्रो लास्नी और श्रीमती बारबरा ऊटन के अनुसार नियोजन से मानवीय स्वतन्त्रता बढ़ती है।

4. भ्रष्टाचार और अनियमितताएँ—प्रालोचको का मत है कि नियोजित व्यवस्था में राज्य कर्मचारियों में भ्रष्टाचार बढ़ता है। सरकारी कर्मचारियों के पास व्यापक अधिकार होते हैं और वे इसका उपयोग अपने हित के लिए कर सकते हैं। इस प्रकार की शका निरावार नहीं है पर साथ ही यह भी है कि नियोजित अर्थ-व्यवस्था में निजी सम्पत्ति और उत्तराधिकार जैसी सत्याग्रो की समाप्ति पर सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार स्वयमेव समाप्त हो जान की प्रबल सम्भावना रहती है।

5 विशाल मानव-शक्ति की आवश्यकता—प्रायः यह भी कहा जाता है कि योजनाग्रो के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए बड़ी मात्रा में जनशक्ति की आवश्यकता पड़ती है। प्रो लेविस (A W Lewis) ने इस सन्दर्भ में कहा है कि नियोजन की सफलता के लिए पर्याप्त मात्रा में कुशल, योग्य और अनुभव प्राप्त अधिकारियों की आवश्यकता होती है और मजदूर-वर्कसित देशों में इतनी बड़ी मात्रा में कुशल व्यक्तियों का मिलना अमम्भव होता है।¹ किन्तु क्या स्वतन्त्र और अनियोजित अर्थव्यवस्था में विशाल जनशक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहाँ भी मध्यस्थ, विज्ञापक, वितरक, सेल्समैन आदि के रूप में काफी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।

6 उपभोक्ता की सार्वभौमिकता का अन्त—प्रालोचको के अनुसार नियोजित अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता अपनी प्रभुपत्ता को खो देता है। अनियोजित अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट समझा जाता है क्योंकि, उसकी इच्छाग्रो और माँगों के अनुसार ही उत्पादन किया जाता है, किन्तु नियोजित अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को उसी वस्तु का उपभोग करना पड़ता है, जो राज्य उसे देता है। इसके उत्तर में नियोजन के समर्थकों का कहना है कि क्या अनियोजित अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता वस्तुतः सम्राट होता है? क्या मुद्राविहीन उपभोक्ता को जो कुछ भी खरीदने योग्य न हो, सम्राट बताना हास्यास्पद नहीं है। उपभोक्ता की पसन्द की नियोजित अर्थ-व्यवस्था में प्रवहेलना नहीं की जा सकती। सोवियत-संघ में भी राज्य उपक्रमों द्वारा उत्पादन योजनाग्रो को बनाते समय उपभोक्ताग्रो की पसन्दगियों पर ध्यान दिया जाता

है। मारिम डाब के अनुसार वहाँ उद्योगिकों के अधिमानों को जानने के लिए प्रदर्शनियों आदि में जनता के चयन (Choice) को अंकित किया जाता है।

7. श्रमिकों के व्यवसाय चुनने की स्वतन्त्रता की समाप्ति—नियोजित अर्थ-व्यवस्था में श्रमिकों को स्वेच्छा से व्यवसाय चुनने की स्वतन्त्रता नहीं रहती और उन्हें विभिन्न कार्यों में आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार लगाया जाता है। नियोजकों के मतानुसार अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में भी श्रमिकों को इच्छानुसार व्यवसाय चुनने की सुविधा और सामर्थ्य कहीं होनी है। वहाँ भी जनता द्वारा अपनाए जाने वाले व्यवसाय, अभिभावकों की सम्पत्ति, हैमियन, सामाजिक प्रभाव और सिकारिश पर निर्भर करते हैं। इसके अनिर्दिष्ट नियोजित अर्थव्यवस्था में भी श्रमिकों को उनकी योग्यता, इच्छा, भुक्ताव के अनुसार ही कार्य देने का अधिकाधिक प्रयत्न किया जाता है। श्रीमती बारबरा ऊटन के अनुसार, नियोजन के बिना रोजगार का स्वतन्त्रतापूर्वक चयन नहीं हो सकता, जबकि नियोजन में ऐसा सम्भव है।

8. संक्रमण-काल में अव्यवस्था की संभावना—प्रायः यह भी कहा जाता है कि अनियोजित से नियोजित अर्थ-व्यवस्था में संक्रमण-काल में पर्याप्त मात्रा में अव्यवस्था और गड़बड़ी हो जाती है जिससे उत्पादन और राष्ट्रीय आय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है; किन्तु ऐसा किमी आधारभूत परिवर्तन के समय होता है। अतः देश के दीर्घकालीन और द्रुत आर्थिक विकास के लिए इस प्रकार की समस्याई गड़बड़ी वहन करनी ही पड़ती है।

9. आर्थिक गोपनीयता—नियोजन के विरुद्ध एक तर्क यह प्रस्तुत किया जाता है कि नियोजित अर्थव्यवस्थाएँ गुप्त रूप से संचालित की जाती हैं और इनमें गोपनीयता को बहुत अधिक महत्त्व दिया जाता है जिससे जनता का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता है। किन्तु यह तर्क भी निराधार है। साम्यवादी रूप में भी नियोजन नीचे से प्रारम्भ किया जाता है जिसके निर्माण में कारखानों के श्रमिकों और सामूहिक कृषकों का हाथ होता है। इसके अतिरिक्त योजनाएँ सदा ही विचार-विमर्श, वाद-विवाद आदि के लिए जनता के समक्ष रखी जानी हैं और उन पर मुभाव धामनित किए जाते हैं। जनतान्त्रिक नियोजन में तो नियोजन के सभी स्तरों पर जनता को सम्बन्धित किया जाता है और उसे अधिकाधिक जानकारी दी जाती है।

10. राजनीतिक कारणों से अस्थिरता का भय—नियोजित अर्थव्यवस्था राजनीतिक कारणों से भी अस्थिर होती है। जो राजनीतिक दल इसे चाहता है, इसके मन्त्रों से अलग होते ही नियोजन का त्याग किए जाने की सम्भावना हो सकती है क्योंकि नई सरकार नियोजन के पक्ष में न हो। इस परिवर्तन के कारण अर्थव्यवस्था को हानि उठानी पड़ती है। प्रो जेक्स (Jewkes) के अनुसार राजनीतिक अस्थिरता के ऐसे वातावरण में दीर्घकालीन औद्योगिक परियोजनाएँ नहीं पनप सकती हैं। किन्तु आर्थिक नियोजन एक अच्छी चीज है और कोई भी अच्छी चीज को हर राजनीतिक दल मानता है। हाँ, नियोजन को लागू किए जाने के तरीके में अन्तर हो सकता है।

11 सदैव किसी न किसी प्रकार के आर्थिक संकट की उपस्थिति—आलोचना के अनुसार नियोजित अर्थव्यवस्था में सदैव किसी न किसी प्रकार का सकट विद्यमान रहता है, किन्तु अनियोजित अर्थव्यवस्था कौनसी आर्थिक प्रवृत्ति के सन्दर्भ से मुक्त रहती है। इसमें सदैव मुद्रा-स्फीति, मुद्रा-मकुचन, बेकारी, व्यापार चक्र, पदार्थों का अभाव, वर्ग-मर्ष आदि सकट बने ही रहते हैं। क्या यह एक तथ्य नहीं है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में युद्धोत्तर-काल में अनेक व्यापारिक उतार-चढ़ाव आए। यह भी एक तथ्य है कि वहाँ इस प्रकार के सकटों से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अत्यधिक व्यय सघन सगठन का निर्माण किया गया है। वस्तुन नियोजित की अपेक्षा अनियोजित अर्थव्यवस्था अधिक सकट प्रस्त रहती है।

12. बहु-वर्षीय नियोजन अनुचित है—इस परिवर्तनशील सत्तार में परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। साथ ही, भविष्य भी अनिश्चित होता है। किन्तु योजना में बहुधा बहु-वर्षीय उदाहरणार्थ पाँच या सात इसी प्रकार कई वर्षों के लिए बनाई जाती हैं। इस बीच परिस्थितियाँ और आवश्यकताएँ बदल जाती हैं। परिणामस्वरूप, नियोजन न केवल निरर्थक अपितु हानिप्रद भी हो सकता है किन्तु इस आलोचना में कोई सार नहीं है, क्योंकि बहुधा योजनाएँ सचीली होती हैं और उनमें परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन कर लिया जाता है।

13 अन्तर्राष्ट्रीय सघर्ष की संभावना—व्यक्तिगत राष्ट्रो द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय नियोजन से अन्तर्राष्ट्रीय वैमनस्य और सघर्ष उत्पन्न हो सकता है। प्रो रॉबिन्स (Prof Robins) के अनुसार राष्ट्रीय नियोजन का विश्व अर्थव्यवस्था पर बहुत गम्भीर प्रभाव पड़ता है। वस्तुतः अधिकांश देशों द्वारा राष्ट्रीय नियोजन अपनाने से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सकुचन श्रमिकों की अन्तर्राष्ट्रीय गतिशीलता में बाधाएँ, पूँजी के विमुक्त प्रवाह पर अवरोध बढ़ते हैं जिससे अन्त में, राष्ट्रो में पारस्परिक तनाव और वैमनस्य का वातावरण पनपता है किन्तु वस्तुतः यह आलोचना निराधार है। अन्तर्राष्ट्रीय सघर्ष राष्ट्रीय नियोजन से नहीं, उग्र राष्ट्रवाद से उत्पन्न होता है जो अनियोजित अर्थव्यवस्था में भी हो सकता है। वास्तव में नियोजन के परिणामस्वरूप पारस्परिक सहयोग बढ़ता है। अच्छी योजनाएँ प्रस्तुत करने और नियोजित पद्धति को अपनाने के कारण ही भारत को विकसित देशों, विश्व बैंक तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय-संस्थाओं से सहायता प्राप्त हुई है।

नियोजित अर्थव्यवस्था के पक्ष और विपक्ष में उक्त तर्कों पर विचार करने पर ज्ञात होता है कि नियोजन का पक्ष प्रबल है और जो कुछ तर्क इसके विरुद्ध प्रस्तुत किए गए हैं वे अविश्वसनीय नहीं हैं। अनियोजित अर्थव्यवस्था के पक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले तर्क जैसे अर्थव्यवस्था की स्वयं संचालकता, उद्योगिकता की सार्वभौमिकता और बाजार तानिकता का मुक्त कार्यवाहन आदि बातें भी सीमित मात्रा में ही सही हैं। अनियोजित अर्थव्यवस्था में असमानता, अस्थिरता असुरक्षा और एकाधिकार आदि कई बुराइयाँ होती हैं जिन्हें केवल उपाचार से ही दूर नहीं किया जा सकता है अतः इन बुराइयों को जड़ अनियोजित अर्थव्यवस्था का ही समाप्त कर नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना ही श्रेयस्कर है।

नियोजन के लिए निर्धारित की जाने वाली बात (Tasks of Planning)

अब प्रश्न उठता है कि किस प्रकार के नियोजन में अधिकतम आर्थिक वृद्धि सम्भव है—केन्द्रित नियोजन म अथवा विकेन्द्रित नियोजन में ? यह एक विवादास्पद प्रश्न है। केन्द्रित नियोजन (Centralised Planning) में, समस्त आर्थिक निर्णय केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए जाते हैं, जबकि विकेन्द्रित नियोजन में, निर्णय लेने की सत्ता व्यक्तिगत इकाइयों में निहित होती है। पूर्ण केन्द्रित नियोजन अथवा पूर्ण विकेन्द्रित नियोजन असामान्य स्थितियाँ हैं। वास्तव में, आर्थिक नियोजन राज्य व निजी उद्यम दोनों का संयुक्त फलन है। किसी देश से सम्बन्धित आर्थिक निर्णयों में सरकार व निजी उद्यम का पृथक्-पृथक् तथा दोनों का संयुक्त अनुपात कितना रहता है ? यह राजनीति का प्रश्न है तथा प्रत्येक देश में इस सम्बन्ध में भिन्नता पाई जाती है। इसी प्रकार उत्पादन के कुछ साधनों का स्वामित्व सरकार तथा कुछ का निजी उद्यम के हाथों में पाया जाता है। आर्थिक नियोजन किसी भी प्रकार का हो, सभी में निम्नलिखित पाँच बातें निर्धारित की जाती हैं—

- (1) वृद्धि के लक्ष्यों का निर्धारण (Fixing of the Growth Targets)
- (2) अन्तिम माँग व अन्तः उद्योग माँग का निर्धारण (Determination of Final and Inter industry Demand)
- (3) विनियोग लक्ष्यों का निर्धारण (Determination of Investment Targets)
- (4) योजना के लिए साधनों का संग्रह (Mobilisation of Resources for the Plan)
- (5) परियोजनाओं का चुनाव (Project Selection)

1 वृद्धि के लक्ष्यों का निर्धारण (Fixing of the Growth Targets)— आय-वृद्धि, रोजगार-वृद्धि, उत्पादन-वृद्धि आदि लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आर्थिक आयोजन किया जाता है। किसी देश की आर्थिक योजना के आय, रोजगार, उत्पादन आदि से सम्बन्धित उद्देश्यों को एक सुनिश्चित व अर्थ युक्त दिशा प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि इन उद्देश्यों को संख्यात्मक लक्ष्यों में (Quantified Targets) परिवर्तित किया जाए। योजना के उद्देश्य जब संख्यात्मक रूप में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, तब वे योजना के लक्ष्य कहे जाते हैं (Targets are quantified objectives)।

एक योजना के अन्तर्गत लक्ष्यों का निर्धारण, उत्पादन, विनियोग, रोजगार, निर्यात, आयात आदि से सम्बन्धित हो सकता है। योजना के लक्ष्य पूरे देश के स्तर पर क्षेत्रानुसार या विशेष औद्योगिक इकाइयों अथवा परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं। लक्ष्यों का निर्धारण, उत्पादन अथवा उत्पादन कारकों की भौतिक इकाइयों के या मूल्य-इकाइयों के रूप में किया जाता है। लक्ष्यों का निर्धारण कच्चे माल की मात्रा, श्रम-शक्ति, प्रशिक्षण सुविधाएँ, धरेलू तथा विदेशी मुद्रा में उपलब्ध

विनीय कोष व अन्य साधनों की मात्रा को निश्चित करने में सहायक होते हैं। निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार ही इन साधनों का अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में आवंटन किया जाता है।

कुछ योजनाएँ कतिपय सामूहिक लक्ष्यों (Aggregative Targets) तक सीमित होती हैं जबकि कुछ अन्य योजनाओं के अन्तर्गत लक्ष्यों की एक लम्बी सूची तैयार की जाती है। उदाहरणार्थ यूगोस्लाविया की पंचवर्षीय योजनाओं में लगभग 600 वस्तु-समूहों से सम्बन्धित लक्ष्यों की प्रामाण्य रूप से विस्तृत विवरण के साथ निर्धारित किया गया है। किन्तु लक्ष्यों की संख्या अधिक बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में निर्धारित विस्तृत स्तरों वाले लक्ष्यों को प्राप्त करना अनेक कठिनाइयों से पूर्ण होता है। लेविस के मतानुसार 'लक्ष्यों की एक लम्बी सूची बनाना और इसे प्रकाशित करना अधिक से अधिक अच्छे रूप में मात्र एक अनुमान या भावी परिक्ल्पना (Forecast or a Projection) हो सकता है तथा अपने निकृष्टतम रूप में केवल एक गणितीय परम्परा-मान रह जाता है जिसका कोई व्यावहारिक महत्त्व नहीं होता है।'¹

2 अन्तिम माँग व अन्त उद्योग माँग का निर्धारण (Determination of Final and Inter industry Demand)—वृद्धि के लक्ष्यों को निर्धारित करने के बाद विकास-दर निश्चित की जाती है। विकास-दर के निर्धारण के पश्चात् सेवाओं की माँग में वृद्धि व वस्तुओं की माँग में वृद्धि को पृथक् रूप से ज्ञात किया जाता है तथा राष्ट्रीय विकास-दर को क्षेत्रीय विकास दरों में विभक्त किया जाता है। इस कार्य में दो तकनीकी प्रक्रियाएँ की जाती हैं—

- (1) अन्तिम उत्पादन का निर्धारण
- (2) अन्त क्षेत्रीय माँग का निर्धारण

उपभोक्ताओं द्वारा अन्तिम माँग व अन्त क्षेत्रीय माँग का योग वस्तु की कुल माँग को प्रकट करता है। अतः कुल माँग के भावी अनुमानों के लिए उपभोक्ता की माँग तथा अन्त क्षेत्रीय माँग के अनुमान लगाना आवश्यक है। कुल माँग के अनुमान माँग की आय-लोच की सहायता से लगाए जा सकते हैं। मान लीजिए भोजन व वस्त्र की आय-लोच—क्रमशः 6 व 15 दी हुई हैं। इस स्थिति में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 10% होती है तो भोजन की माँग में वृद्धि $6 \times 10 = 6\%$ तथा इसी प्रकार वस्त्र की माँग में $15 \times 10 = 15\%$ वृद्धि होगी। जब इस तरह प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तथा आय की लोच दी हुई हो तो प्रत्येक वस्तु की माँग को ज्ञात किया जा सकता है। सब वस्तुओं की माँग का योगफल कुल माँग होती है। कुल माँग को ज्ञात करने की इस विधि में दो बड़े दोष हैं—(1) यह कीमत के परिवर्तनों पर विचार नहीं करती है। (2) इसमें आय की लोच को योजनावधि के लिए स्थिर माना जाता है।

अन्त उद्योग माँग के अनुमानों के लिए आदा प्रदा प्रणाली (Input output System) अपनाई जाती है। इस प्रणाली में आदा प्रदा के अनुपात स्थिर माने जाते हैं। आदा प्रदा के इन अनुपातों को तकनीकी गुणांक (Technical Coefficients) कहा जाता है। मैट्रिक्स की भाषा में इन गुणांकों को 'Aij' में प्रगट किया जाता है। इन तकनीकी गुणांकों के आधार पर अन्त-उद्योग माँग की संगणना की जाती है। तकनीकी गुणांकों के प्रयोग का एक बड़ा दोष यह है कि इन गुणांकों को स्थिर माना जाता है। यह एक दोषपूर्ण मान्यता है क्योंकि साधन बदलते हैं, तकनीकी बदलती है अतः गुणांकों का परिवर्तित होना स्वाभाविक है।

3 विनियोग लक्ष्यों का निर्धारण (Determination of Investment Targets)—माँग-निवारण के पश्चात् दूसरा प्रश्न भौतिक लक्ष्यों को विनियोग लक्ष्यों में परिवर्तित करने का है। इस कार्य के लिए पूँजी-गुणांक अथवा पूँजी-उत्पादन अनुपातों की आवश्यकता होती है। इन अनुपातों के योग द्वारा हम कुल विनियोग-राशि का अनुमान लगा सकते हैं। पूँजी उत्पादन अनुपात, पूँजी की वह इकाई है जिसकी उत्पादन की एक इकाई उत्पन्न करने के लिए आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, यदि 8 लाख रुपये की पूँजी विनियोग से 2 लाख रु का माल तैयार होता है या 2 लाख रु का माल तैयार करने के लिए 8 लाख रु की पूँजी विनियोजित करनी पड़ती है तो पूँजी उत्पादन अनुमान इस स्थिति में 4:1 होगा।

जब कृषि, उद्योग, सेवा आदि क्षेत्रों के भी तक लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैं तथा इन क्षेत्रों के लिए पूँजी-उत्पादन अनुपात निश्चित हो जाते हैं तब सरलता से प्रत्येक क्षेत्र के लिए आवश्यक विनियोग की मात्रा निकाली जा सकती है। प्रो महालनोबिस ने अपने चार क्षेत्रीय विकास माडल में इसी प्रकार वित्तीय आवंटन करने का प्रयास किया है। प्रो महालनोबिस माडल के आधार पर ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विनियोग की राशि निर्धारित की गई है।

4 योजना के लिए साधनों का संग्रह (Mobilisation of Resources for the Plan)—कुल विनियोग-राशि का अनुमान लगाने के पश्चात् यह देखा जाता है कि विनियोगों की वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार सम्भव हो सकेगी। यह योजना का भाग कहलाता है। आर्थिक नियोजन द्वारा विकास करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और बड़ी मात्रा में परियोजनाएँ प्रारम्भ की जाती हैं। इन कार्यक्रमों को संचालित करने और परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए बड़ी मात्रा में साधनों की आवश्यकता होती है। विवास की इन विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के संचालन के लिए आवश्यक साधनों की व्यवस्था एवं उनकी गतिशीलता आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण समस्या है। डा राज के अनुसार, 'एक योजना नहीं के बराबर है यदि इसमें निर्धारित विकास का कार्यक्रम साधनों के एकत्रित करने के कार्यक्रम पर आधारित और समन्वित नहीं किया हो।'

आर्थिक विकास के लिए राजकीय, मानवीय और वित्तीय साधनों की

आवश्यकता होती है। इन साधनों का अनुमान और उनको गतिशील बनाना मुख्यतः निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है—(i) राजवित्त की मशीनरी, (ii) उद्देश्यों की प्रकृति, (iii) योजनावधि, (iv) श्रम और पूँजी की स्थिति, (v) शिक्षा एवं राष्ट्रीय चेतना, (vi) अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, (vii) मूल्यस्तर और जनता की आर्थिक दशा, (viii) विदेशी विनिमय कोष, (ix) सरकार की आर्थिक स्थिति, एवं (x) आर्थिक विपत्तियों की मात्रा।

5 परियोजनाओं का चुनाव (Project Selection)—वित्तीय व्यवस्था के पश्चात् विनियोग-परियोजनाओं (Investment Projects) का चुनाव किया जाता है। विनियोग परियोजनाएँ विनियोगों के उत्पादन से जोड़ने वाली श्रृंखला का कार्य करती हैं। किन्तु परियोजना-चुनाव एक तकनीकी कार्य है जिसमें परियोजना के लिए स्थान का चुनाव, तकनीकी का चुनाव, बाजारों का चुनाव आदि तकनीकी निर्णय सम्मिलित हैं। परियोजनाओं का चुनाव योजना-निर्माण का पाँचवाँ बड़ा कार्य है।

प्रायः किसी योजना की मूलभूत कमजोरी परियोजनाओं के चयन को लेकर होती है। ठोस व लाभदायक परियोजनाओं के अभाव में योजना असफल रहती है। पाकिस्तान योजना आयोग के अधिकारी डॉ. महबूब उल हक के अनुसार 'पहली और दूसरी योजनाओं की कमजोरी यह रहती है कि आयोजन का निर्माण गहराई में नहीं है। एक ओर जहाँ विभिन्न क्षेत्रों में ताल-मेल रखते हुए एक समष्टि योजना (Aggregative Plan) का प्रारूप निर्मित करने में पूरे प्रयत्न किए गए किन्तु दूसरी ओर योजना के विभिन्न क्षेत्रों के प्रारूपों को सुविचारित व सुनियोजित परियोजनाओं से परिपूरित करने के प्रयत्न नहीं हुए।'

खाटेमाला ने सन् 1960 में एक सार्वजनिक विनियोग कार्यक्रम का उद्घाटन किया, किन्तु एक वर्ष बाद ही अमेरिकी राज्यों के संगठन ने यह प्रतिवेदित किया कि "विभिन्न मन्त्रालयों के लिए पूर्ण विकसित परियोजनाओं को पर्याप्त सख्या में ज्ञात करना कठिन हो रहा है।"

परियोजनाओं का चयन करने की अनेक विधियाँ हैं। सामान्यतः परियोजनाओं का चयन वर्तमान मूल्य-विधि अथवा लागत-लाभ विश्लेषण विधि द्वारा किया जाता है।

6 योजना की क्रियावृत्ति—योजना के क्रियान्वयन का यह कार्य सरकारी विभागों, सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यक्रमों का संचालन सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा तथा निजी-क्षेत्र के कार्यक्रम निजी उपक्रमियों द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। सरकार भी इन्हें निर्धारित नियमानुसार सहायता देती है। इस प्रकार योजना की सफलता बहुत कुछ इसी अवस्था पर निर्भर होती है। अनेक देशों में योजना-निर्माण पर अधिक एवं क्रियान्वयन पर कम ध्यान दिया जाता है। अतः योजना की सफलता के लिए इस स्तर पर कोई निष्क्रियता एवं शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिए।

योजना की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि समय समय पर उसके संचालन और उसकी प्रगति का मूल्यांकन किया जाता रहे। अतः समय समय पर इन बात का लेना-जोखा लिया जाता है कि योजना में लक्ष्यो के अनुगत में कितनी प्रगति हुई और उसमें कमियाँ कहाँ और क्यों है? इसके लिए उत्पादन की प्रत्येक शाखा की तांत्रिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से समालोचना की जानी चाहिए। भारत में योजना के मूल्यांकन का कार्यक्रम 'मूल्यांकन समूह' (Programme Evaluation Organisation) द्वारा किया जाता है।

नियोजन की सफलता की शर्तें (Conditions for Success of Planning)

आर्थिक विकास के लिए आधुनिक युग में नियोजन कई अर्थ-विकसित देशों में अपनाया जा रहा है। किन्तु नियोजन कोई ऐसी प्रणाली नहीं है जिसके द्वारा स्वयंमेव ही आर्थिक विकास हो जाए। योजनाओं की सफलताओं के लिए कुछ शर्तों का होना आवश्यक है। सफलता की ये शर्तें विभिन्न देशों और परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। किन्तु सामान्य रूप से ये शर्तें सर्वत्र आवश्यक हैं—

1. पर्याप्त एवं सही आँकड़ों और सूचनाएँ—नियोजकों को योजना निर्माण और क्रियान्वयन के लिए सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का, वर्तमान परिस्थितियों का तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं का ज्ञान होना चाहिए। वर्तमान स्थिति क्या है और इसमें कितना सुधार किया जाना चाहिए? यह सुधार किस प्रकार किया जा सकता है और इसके लिए कौन से साधनों की कितनी मात्रा में आवश्यकता है। इन सब बातों का निर्णय विश्वस्तरीय और पर्याप्त आँकड़ों के आधार पर ही किया जा सकता है अतः नियोजन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन, उपभोग, आय, व्यय, बचत, विनियोग, उपलब्ध कच्चे माल, शक्ति के साधनों की मात्रा, बाजार की माँग, आयात निर्यात मूल्य स्तर, जनसंख्या आदि के बारे में विश्वस्तरीय और पर्याप्त आँकड़ों का सफलतापूर्वक संग्रह किया जाए। असत्य तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर बनाई गई योजनाएँ असफल हो सकती हैं। अतः सांख्यिकीय स्थिति ऐसी होनी चाहिए जो नियमित रूप से निरन्तर सूचना प्रदान करती रहे ताकि परिस्थितियों में परिवर्तन आने पर योजनाओं में भी यथासमय समायोजन किया जा सके।

2. सुनिश्चित और स्पष्ट उद्देश्यों का होना—नियोजन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसके सुनिश्चित और सुस्पष्ट उद्देश्य निश्चित किए जाएँ जो देश की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। परिस्थितियों के अनुरूप उद्देश्यों और लक्ष्यों का विचारण नहीं करने से पूर्ण रूप से वे परिपूर्ण नहीं हो पाते। इसी प्रकार, यदि लक्ष्य सुनिश्चित और स्पष्ट नहीं हुए तो बावरीय दिशा में तत्परता के साथ प्रयत्न नहीं किए जाएँगे। परिणामस्वरूप लक्ष्यों की पूर्ति अनुरी होगी तथा नियोजन असफल हो जाएगा। अतः परिस्थितियों के उन्मुक्त तथा सुनिश्चित उद्देश्य होने चाहिए। साथ ही परिस्थितियों में परिवर्तन की गुंजाइश होनी चाहिए।

3 नियोजन माँग विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए—आर्थिक विकास की प्रक्रिया में विभिन्न उत्पादक इकाइयों का विस्तार होता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। अतः विकास उत्पादन की विभिन्न शाखाओं में विनियोग, कच्चे माल का उपयोग और रोजगार की माँग में वृद्धि होती है जिससे उत्पादन वृद्धि के साथ-साथ मौद्रिक आय बढ़ती है। किन्तु ऐसी स्थिति में आय उपाजित करने वाले विभिन्न वर्गों के आय-वितरण की प्रकृति में भी परिवर्तन होना है, क्योंकि इस प्रक्रिया के विभिन्न क्षेत्र या उत्पादक इकाइयों का विकास विभिन्न मात्रा में हो सकता है यहाँ तक कि कुछ के संकुचन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अतः इस विकास प्रक्रिया की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार की उत्पादित की गई इन वस्तुओं और सेवाओं की माँग और पूर्ति के मध्य सन्तुलन रखा जाए।

4 प्राथमिकताओं का निर्धारण (Fixing of Priorities)—आर्थिक नियोजन को अपनाने वाले कार्यक्रम और आवश्यकताएँ अनन्त होते हैं किन्तु भौतिक और वित्तीय साधन अपेक्षाकृत सीमित होते हैं अतः वैज्ञानिक नियोजन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि इन विभिन्न कार्यक्रमों में देश की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार प्राथमिकताएँ निर्धारित कर ली जाएँ। नियोजन का मुख्य उद्देश्य उत्पादन में अधिकतम वृद्धि करना है, इस हेतु देश की समाधान स्थिति, आवश्यकताएँ और विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण उद्योगों के विकास को प्राथमिकता और महत्व दिया जाना चाहिए। योजना में ऐसी परियोजनाओं को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनसे राष्ट्रीय कल्याण में अधिकतम योग प्राप्त हो सके। योजना में यह निश्चय कर लिया जाना चाहिए कि विभिन्न क्षेत्रों में से किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए जैसे उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी जाए अथवा कृषि को इन विभिन्न क्षेत्रों (Sectors) में से भी यह निर्णय किया जाना चाहिए कि इनके किम पहलू पर अधिक बल दिया जाए और किन परियोजनाओं पर पहले ध्यान दिया जाए। इस प्रकार साधनों, विदेशी विनिमय की उपलब्धि राष्ट्रीय महत्व के सदर्भ में विवेकपूर्ण निर्णय के आधार पर प्राथमिकताएँ निर्धारित की जानी चाहिए और साधनों का आवंटन भी इसी के अनुसार किया जाना चाहिए। प्राथमिकताओं का निर्धारण जितना उपयुक्त होगा, योजना की सफलता उतनी ही अधिक होगी।

5. साधनों की उपलब्धि (Availability of Resources)—योजना में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। इनकी सफलता पर ही योजना की सफलता निर्भर होती है। योजना के इन कार्यक्रमों और विभिन्न परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में भौतिक (Physical) और वित्तीय (Financial) साधनों की आवश्यकता होती है। योजना की सफलता के लिए बड़ी मात्रा में भौतिक साधन जैसे कच्चा माल, मशीनें, यन्त्र, औजार, रसायन, इस्पात, सीमेंट, तकनीकी जानकारी आदि की आवश्यकता होती है जिसे

देश और विदेश से उलब्ध किया जाना चाहिए। इसी प्रकार वित्तीय साधनों की आवश्यकतानुसार उपलब्धि भी बहुत महत्वपूर्ण है जो आन्तरिक या बाह्य स्रोतों से प्राप्त की जानी चाहिए। वित्तीय साधनों की व्यवस्था बड़ा दुष्कर कार्य होता है क्योंकि इसमें सफलता कई बातों पर निर्भर करती है जैसे राष्ट्रीय आय की मात्रा, पूँजी-उत्पादन का अनुपात (Capital-output ratio), आन्तरिक ध्वन और विनियोग-दर, भुगतान सन्तुलन की मात्रा, जनता की वर-देय क्षमता, सरकार की वर एकत्रीकरण की क्षमता, योजनाओं में जनता का विश्वास, सरकार की प्राथिक स्थिति, घाटे की वित्त-व्यवस्था की सीमा, विदेशी सहायता आदि। अतः योजनाओं की सफलता इन भौतिक और वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर अधिक निर्भर करती है। कई बार साधनों के अभाव में योजना के कार्यक्रमों में कटौती करनी पड़ती है।

6. विभिन्न क्षेत्रों में सन्तुलन बनाए रखना (Maintaining Balance Between Different Sectors)—योजना की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों और उद्योगों का सन्तुलित विकास किया जाए। अर्थव्यवस्था में एक उद्योग और यहाँ तक कि उत्पादक की एक इकाई भी माँग और पूर्ति के द्वारा अन्य से परस्पर सम्बन्धित होती है। अतः उद्योग का विकास तब तक असम्भव है जब तक कि अन्य के उत्पादन में भी वृद्धि न हो। एक उद्योग का द्रुतगति से विकास करने और अन्य उद्योगों की अवहेलना करने से अर्थव्यवस्था में कई प्रकार की जटिलताएँ और अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं। अतः नियोजन की सफलता के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, यातायात, विद्युत्, सामाजिक सेवाओं आदि का सन्तुलित विकास किया जाना चाहिए। इसी प्रकार देश के समस्त प्रदेशों या भागों का भी सन्तुलित विकास किया जाना चाहिए। वास्तव में नियोजन की सफलता इसी बात में निहित है।

7 उचित आर्थिक संगठन (Suitable Economic Organisation)—उचित आर्थिक संगठन की उपस्थिति में ही नियोजन सफल हो सकता है। अतः नियोजन की सफलता के लिए उचित आर्थिक ही नहीं, अपितु सामाजिक संगठन का भी निर्माण किया जाना चाहिए। अर्द्ध विकसित देशों में इस दृष्टि से वर्तमान सामाजिक आर्थिक संगठन और संरचना के पुनर्गठन की आवश्यकता है। उपयुक्त वातावरण के अभाव में आर्थिक प्रगति असम्भव है। इसलिए, विकासार्थी नियोजन की सफलता के लिए वर्तमान आर्थिक संगठन में इस प्रकार परिवर्तन करना चाहिए और नवीन आर्थिक संस्थाओं का सृजन करना चाहिए जिससे योजनाएँ सफल और आर्थिक विकास तीव्रता से हो सकें। इस सम्बन्ध में अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियन्त्रण में वृद्धि, सहकारिता का विकास, भूमि सुधार कार्यक्रमों की क्रियान्विति, सांस्कृतिक क्षेत्र का विस्तार, विदेशी व्यापार का पुनर्गठन आदि कदम अविशेष अर्द्ध विकसित देशों के लिए आवश्यक हैं।

8 योजना के क्रियान्वयन की उचित व्यवस्था (Proper Machinery for Plan Implementation)—योजना निर्माण से भी अधिक महत्वपूर्ण क्रियान्वयन

की अवस्था है। घन इसको क्रियान्वित करने और निर्धारित कार्यक्रमों पर पूर्ण रूप से प्रमत्त कराने के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में कुशल संगठनों का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। योजना की सफलता उन व्यक्तियों पर निर्भर करती है जो इसे कार्यरूप में परिणत करने में सक्षम होते हैं। अतः यह कार्य ऐसे व्यक्तियों को सुपुर्न किया जाना चाहिए जो योजना के उद्देश्यों को समझते हों, उनमें आस्था रखते हों और जिनमें योजना के कार्यक्रमों को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक कुशलता, प्रभुत्व, ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता हो। योजना के संचालन का मुख्य कार्य सरकार का होता है और इसके लिए 'दृढ़ सशक्त और भ्रष्टाचार रहित प्रशासन' की आवश्यकता है। अर्द्ध विवक्षित देशों में बहुधा निर्वय सरकार होती है, आन्तरिक अशांति होती है और कभी कभी विदेशी सरकार उनकी योजनाओं में हस्तक्षेप करती है और उनमें अपनी इच्छानुसार परिवर्तन पर बल देती है। नियोजन की सफलता के लिए इन परिस्थितियों की समाप्ति आवश्यक है। नियोजन की सफलता के लिए यह भी वांछनीय है कि वहाँ की केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की अपेक्षा शक्तिशाली हो और उसे विशेष अधिकार मिलें हों जिनसे वह अपनी राजनीतिक इकाइयों में भी योजनाओं को लागू करने में सफल हो सके।

9. जनता का सहयोग (Public Co operation Forthcoming)— योजनाओं की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसे पूरा जन समर्थन और जन सहयोग मिले। प्रजातान्त्रिक नियोजन में तो इसका विशेष महत्त्व है, क्योंकि वहाँ सरकार को भी शक्ति जनता द्वारा प्राप्त होती है। प्रो ग्रार्थर लविस के अनुसार 'जन उत्साह आर्थिक विकास के लिए स्तम्भता प्रदान करने वाला तेल और पेट्रोल दोनों ही हैं। यह एक ऐसी गतिमान शक्ति है जो लगभग समस्त बातों को सम्भव बनाती है।' योजनाओं में जनता द्वारा अधिकाधिक सहयोग तब प्राप्त होता है जब वह योजनाओं में अपने आपकी भागीदार (Participant) समझे। वह यह समझे कि "यह योजना हमारी है, हमारे लिए है, हमारे द्वारा है तथा इससे जनता को ही समान रूप से लाभ मिलने वाला है।" साथ ही, उन्हें यह भी विश्वास होना चाहिए कि योजनाएँ उपयुक्त हैं और योजनाओं में घन का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसा तभी हो सकता है, जबकि योजना निर्माण और क्रियान्वयन में जनता का सहयोग हो। भारतीय योजनाओं में जन-प्रतिनिधि संस्थाओं के रूप में विभिन्न स्तरों पर ग्रामपंचायतों, पंचायत समितियों जिला परिषदों तथा राज्य और केन्द्रीय विधान मण्डलों को सम्बन्धित किया जाता है। जनता का समर्थन और लोक सहयोग प्राप्त करने का एक तरीका यह भी है कि योजनाओं का अधिकाधिक प्रचार किया जाए जिससे जनता 'योजनाओं की सिद्धि में अपनी समृद्धि' समझे।

10 उच्च राष्ट्रीय चरित्र (High National Character) — राष्ट्रीय चरित्र की उच्चता लगभग सभी बातों को सम्भव बनाती है। योजना की सफलता के लिए भी यह तत्त्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यदि देश में परिश्रमशील, कर्तव्य-परायण, ईमानदार और राष्ट्रीयता की भावना से युक्त उच्च चरित्र वाले व्यक्ति होंगे तो

योजनाओं की सफलता की अधिक सम्भावनाएँ होगी किन्तु, अधिकांश अर्द्ध-विकसित देशों में उच्च राष्ट्रीय खर्च का अभाव होता है। वहाँ स्वदेश से अधिक स्व-उदर को समझा जाता है। ऐसी स्थिति में योजनाओं में अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है। वस्तुतः निर्धनता के दयनीय निम्न-स्तर पर उच्च-नैतिकता की बात करना व्यावहारिकता की अपेक्षा करना है, किन्तु इस मध्यावधि में भी शिक्षा, प्रचार आदि के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है।

11. राजनीतिक एवं प्राकृतिक अनुकूलता (Favourable Political and Natural Conditions)—आर्थिक विकास के लिए अपनाए गए नियोजन के लिए राजनीतिक परिस्थितियों का अनुकूल होना आवश्यक है। विदेशों से विशेष रूप से विकसित देशों से अच्छे सम्बन्ध होने पर अधिक विदेशी सहायता और सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। अर्द्ध-विकसित देशों के लिए इसका बहुत महत्त्व है। किन्तु यदि किसी देश को अन्य देशों के आक्रमण का मुकाबला करना पड़ रहा हो या इस प्रकार की आशंका हो तो उसके साधन आर्थिक विकास की अपेक्षा सुरक्षा प्रयत्नों पर व्यय किए जाते हैं। परिणामस्वरूप, आर्थिक नियोजन की सफलता संदिग्ध हो जाती है। तृतीय योजना की सफलता पर भारत पर चीनी और पाकिस्तानी आक्रमणों का विपरीत प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार बाढ़, भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि प्राकृतिक प्रकोप भी अच्छी से अच्छी योजनाओं को असफल बना देते हैं। अर्द्ध-विकसित देशों में तो इन प्राकृतिक प्रकोपों का विशेष कुपरिणाम होता है, क्योंकि ऐसी अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में प्रकृति का प्रभाव अधिक होता है। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना की कम सफलता का एक प्रमुख कारण सूखा, बाढ़ और मौसम की खराबी रही है। गत वर्षों में अर्थव्यवस्था में सुधार के जो संकेत प्रकट हुए हैं, उसका बड़ा ध्येय भी प्रकृति की अनुकम्पा को ही है।

अग्य शर्तें—नियोजन सफलता के लिए अपर्याप्त शर्तों के अतिरिक्त निम्न-लिखित अन्य शर्तों का होना भी आवश्यक है—

1. योजना के प्रभावशाली क्रियान्वयन की व्यवस्था और इसके लिए सरकारी व निजी दोनों ही क्षेत्रों में कुशल संगठन का निर्माण।

2. योजना-पूर्ति के समस्त साधनों का उचित मूल्यांकन किया जाए और उत्पादन के लक्ष्यों का निर्धारण उचित व सन्तुलित ढंग से हो।

3. दीर्घकालीन और अल्पकालीन नियम यथासम्भव साथ-साथ चलें, अर्थात्, दीर्घकालीन योजना के साथ-साथ वार्षिक योजना भी बनाई जाए, ताकि योजना के विभिन्न वर्षों में साधनों का समान उपयोग हो और समान रूप से प्रगति की जा सके।

4. योजना की उपलब्धियों का मध्यावधि मूल्यांकन किया जाए, ताकि, कमियों का पता लगा कर उन्हें दूर किया जा सके।

5. विकेंद्रित नियोजन किया जाए अर्थात्, योजनाएँ स्थानीय स्तर पर बनाई जाएँ और राज्य-स्तर व केन्द्रीय स्तर पर उनका समन्वय किया जाए।

6 योजना के उद्देश्यो, लक्ष्यो, प्राथमिकताओ, साधनो आदि का जनता में पर्याप्त प्रचार और विज्ञापन किया जाए तथा लोगो में योजना के प्रति चेतना, जागृति व रुचि उत्पन्न की जाए ।

7 नियोजन राष्ट्र के लिए हो, न कि किसी वर्ग विशेष या दल विशेष के लिए ।

उपरोक्त आवश्यकताओ (अपेक्षाओ) के प्रतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि पर उचित नियन्त्रण रखा जाए । जनसंख्या का विस्फोट अच्छे से अच्छे नियोजन को असफल बना सकता है । पुनश्च यह भी जरूरी है कि नियोजन को एक निरन्तर होने वाली प्रक्रिया के रूप में ग्रहण किया जाए । एक योजना की सफलता दूसरी एवं दूसरी योजना की सफलता तीसरी योजना की सफलता के लिए सीढ़ी तैयार करती है और इस प्रकार उन सीढ़ियो का सिलसिला निरन्तर चलता रहता है वरन्कि आर्थिक विकास की कोई सीमा नही होती ।

बचत-दर एवं विकास-दर को प्रभावित करने वाले तत्त्व

(Factors Affecting the Saving Rate and the
overall Growth Rate)

आर्थिक विकास पूँजी निर्माण दर पर निर्भर करता है। पूँजी निर्माण-दर विनियोग दर द्वारा निर्धारित होती है तथा विनियोग-दर घरेलू बचन और विदेशी सहायता पर निर्भर करती है। विदेशी ऋण देग की पर्याप्तवस्था में देश का व भूतपन के सुगतान के रूप में प्रार स्वरूप समझे जाने हैं। अत घरेलू बचन ही पूँजी निर्माण का मुख्य स्रोत होती हैं। बचन में वृद्धि आन्तरिक व बाह्य स्रोतों द्वारा की जा सकती है। आन्तरिक स्रोतों के अन्तर्गत बचन में वृद्धि ऐच्छित रूप में उपभोग में कटौती द्वारा की जा सकती है तथा प्रतिवार्य रूप से बचन में वृद्धि अनिश्चित कर्गों तथा सरकार के लिए ऋण देकर की जाती है। अर्द्ध-वैश्वीकरण श्रम को उत्पादन में लगाकर तथा मुद्रा-स्फीति के माध्यम द्वारा भी बचन में वृद्धि सम्भव है। बाह्य स्रोतों के अन्तर्गत आर्थिक विकास की वित्तीय व्यवस्था विदेशी पूँजी के विनियोग, उपभोग वस्तुओं के आयातों में कटौती तथा देश की व्यापार-शर्तों में सुधार द्वारा की जा सकती है।

बचत-दर को प्रभावित करने वाले तत्त्व

1 घरेलू बचत (Domestic Savings)—घरेलू बचत उत्पादन में वृद्धि अथवा उपभोग में कटौती या दोनों प्रकार से बढ़ायी जा सकती है। अर्द्ध-विकसित देश में, देश की जनसंख्या का अधिकांश भाग, निर्वाह स्तर पर जीवनयापन करता है। इसलिए ऐच्छित बचन की मात्रा बहुत कम होती है। किन्तु इन देशों में उच्च धाय वाले भूमिस्वामियों, व्यापारियों तथा व्यवसायियों का एक छोटा वर्ग भी होता है, जो प्रदर्शनकारी उपभोग (Conspicuous Consumption) पर एक बड़ी राशि व्यय करता है। इस प्रकार के उपभोग को प्रतिबन्धित करके बचन में वृद्धि की जा सकती है।

इन देशों में मजदूरी व बेतनभोगी वर्ग के व्यक्तियों की प्रवृत्ति बचन करने की अपेक्षा व्यय करने की अधिक होती है। यह वर्ग भी प्रदर्शन प्रभाव (Demonstration Effect) से प्रभावित होता है; फलस्वरूप इस वर्ग की बचत और भी कम हो जाती है।

भूस्वामियों को लगान-आय इन देशों में उत्तरोत्तर वृद्धि द्वारा हो सकती है किन्तु समाज वा यह वर्ग अपनी बचत को उत्पादक-विनियोगों के रूप में प्रयुक्त नहीं करता है। विकसित देशों में लगान भी उत्पादक विनियोगों के लिए बचत का एक स्रोत है।

इस अर्थव्यवस्था में वितरित व अवितरित दोनों प्रकार के लाभ, बचत के महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। “यदि लाभों को बचतों का मुख्य स्रोत माना जाता है तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय में, जिसमें बचत दर 5 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत हो जाती है, लाभों के अनुपात में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि परिलक्षित होनी चाहिए।”¹

बचत आय स्तर पर निर्भर करती है। आय के निम्न स्तरों पर बचतें प्रायः नगण्य होती हैं। जैसे जैसे आय बढ़ती है, बचत दर में भी वृद्धि होती है। किन्तु प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से बचत में वृद्धि आवश्यक नहीं है। बचत आय के वितरण पर निर्भर करती है। लाभ-अर्जित करने वाले साहसियों के वर्ग के उदय के कारण बचत दर में वृद्धि होती है। यह वर्ग अपने लाभों का पुनः विनियोजन करता है। लेविस के अनुसार, “राष्ट्रीय आय में बचत का अनुपात केवल आय की असमानता का ही फलन नहीं है, बल्कि अधिक सूक्ष्म रूप में यह राष्ट्रीय आय में लाभों के अनुपात का फलन है।”²

2 करारोपण (Taxation)—अर्थव्यवस्था में अनिवार्य बचत की उत्पत्ति के लिए करों का प्रयोग किया जा सकता है। यदि कर लाभों पर लगाए जाते हैं तो बचत दर कम होती है तथा विनियोगों पर इनका विपरीत प्रभाव होता है। यद्यपि लोगों की बचत को कर कम करते हैं किन्तु सरकार के विनियोग व्यय में वृद्धि करते हैं, तो ऐसे करों से पूँजी निर्माण दर कम नहीं होती है। ‘जब सरकार लाभों पर भारी दर से कर लगाती है, परिणामस्वरूप, निजी बचत दर कम होती है, तब कुल बचत-दर को गिरने से रोकने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि सरकारी बचत में वृद्धि की जाए।’³

3 सरकार को अनिवार्य ऋण देना (Compulsory Lending to Government)—करों का एक विकल्प सरकार को अनिवार्य ऋण देने की योजना है। एक निश्चित राशि से अधिक उपार्जित करने वाले व्यक्तियों से सरकार उनकी आय का एक भाग, अनिवार्य रूप से ऋण के रूप में ले सकती है। बचत दर में वृद्धि का एक साधन यह भी है, किन्तु इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि सरकारी प्रतिभूतियाँ इस प्रकार की हो जो सम्भावित बचत कर्ताओं (Potential Savers) को आकर्षित कर सकें।

1 W A Lewis Theory of Economic Growth, p 233

2 W A Lewis Ibid, p 227

3 W A Lewis Ibid, p 242

4 उपभोग आयातों पर प्रतिबंध (Restriction of Consumption Imports)—आयातित-वस्तुओं के उपभोग में कटौती द्वारा भी बचत दर को बढ़ाया जा सकता है। उपभोग वस्तुओं के आयातों में कटौती द्वारा विदेशी विनिमय की बचत होगी, पूँजीगत-वस्तुओं के आयात पर व्यय किया जा सकता है। उपभोग-वस्तुओं के स्थान पर, पूँजीगत वस्तुओं के आयातों से आर्थिक विकास दर बढ़नी है। एक ओर जहाँ आयातित उपभोग-वस्तुओं में कटौती की जाती है, वहाँ दूसरी ओर उपभोग वस्तुओं का घरेलू उत्पादन नहीं बढ़ने दिया जाना चाहिए अन्यथा बचत दर में इस तत्त्व से वृद्धि नहीं हो पाएगी।

5 मुद्रा स्फीति (Inflation)—मुद्रा-स्फीति भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। जब मूल्यों में वृद्धि होती है तब लोग उपभोग में कटौती करते हैं। परिणामस्वरूप, उपभोग-वस्तुओं का उत्पादन कम होता है। भूत उपभोग वस्तुओं के क्षेत्र से साधन-मुक्त होकर पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार की बचत अनैच्छिक बचतें (Forced Savings) कहलाती हैं।

6 गुप्त-बेरोजगारी को समाप्त करना (To Remove Disguised Unemployment)—भूतिरिक्त-श्रम को निर्वाह क्षेत्र से पूँजीवादी-क्षेत्र में स्थानान्तरित करके पूँजी-निर्माण किया जा सकता है। जिन श्रमिकों की सीमान्त-उत्पादकता कृषि में शून्य है, उनको कृषि से हटाकर पूँजी-परियोजनाओं पर लगाया जा सकता है। इस प्रकार सम्पूर्ण निर्वाह-कोष (Subsistence Fund) को पूँजीगत परियोजनाओं में प्रयुक्त किया जा सकता है। परन्तु इस प्रक्रिया में कुछ बाधाएँ आती हैं। प्रथम, गैर-कृषि क्षेत्र में स्थानान्तरित श्रमिक पूर्वापेक्षा भोजन की अधिक मात्रा की माँग करते हैं। द्वितीय, कृषि क्षेत्र में बचे हुए श्रमिक भी भोजन के उपभोग में वृद्धि करना चाहते हैं। तृतीय, कृषि क्षेत्र से पूँजीगत परियोजनाओं तक भोजन सामग्री ले जाने की यातायात लागत भी निर्वाह कोष को कम करती है। यदि निर्वाह कोष के इन छिद्रों (Leakages) की पूर्ति गैर-कृषि क्षेत्र से साधनों के समूह द्वारा की जा सकती है तो यह व्यवस्था पूँजी-निर्माण का एक श्रेष्ठ स्त्रोत हो सकती है।

7 विदेशी ऋण (Foreign Borrowing)—विदेशी ऋण दो विधियों द्वारा पूँजी निर्माण करते हैं—(1) विदेशी ऋणों का प्रयोग पूँजीगत सामग्रियों के आयात के लिए किया जा सकता है, (2) जिस सीमा तक विदेशी ऋणों की सहायता से एक देश अपने आयातों की वृद्धि करता है, उस सीमा तक आयात स्थानापन्न का उत्पादन तथा देश के निर्यात, घटाए जा सकते हैं। इन उद्योगों के उत्पादन में गिरावट के कारण जो साधन-मुक्त होते हैं, उनको पूँजीगत-वस्तुओं के क्षेत्र में लगाया जा सकता है। इस प्रकार विदेशी ऋण प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पूँजी निर्माण की दर को बढ़ाने में सहायक होते हैं।

8. विदेशी व्यापार (Foreign Trade)—विदेशी व्यापार भी पूँजी निर्माण की दर को बढ़ाने में सहायक होता है। यदि निर्यातों के मूल्यों में वृद्धि होती है तो देश की आयात क्षमता में भी वृद्धि होती है। यदि आयात-क्षमता में वृद्धि को

जीवन-वस्तुओं के आयात हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो इससे पूँजी-निर्माण की दर में वृद्धि होती है।

अतः पूँजी-निर्माण को तथा फलतः वचन-दर को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्त्व निम्नलिखित हो सकते हैं—

- (1) उत्पादन में वृद्धि अथवा उपयोग में कटौती, (2) प्रदर्शन प्रभाव, (3) लगान-मात्र में वृद्धि, (4) लागो में वृद्धि, (5) करारोपण, (6) सरकार को दिया जाने वाला अनिवार्य ऋण, (7) उपभोग आयातों पर प्रतिबन्ध, (8) मुद्रा-स्फीति, (9) गुप्त बेरोजगारी की समाप्ति, (10) विदेशी ऋण तथा, (11) विदेशी व्यापार।

— — — विकास-दर और उसे प्रभावित करने वाले तत्त्व

विकास की विकास-दर के निर्धारक तत्त्वों में वचन भी महत्वपूर्ण है। विकास-दर के अन्य निर्धारक-तत्त्वों की विवेचना से पूर्व विकास-दर का सामान्य अर्थ समझना आवश्यक है। सामान्यतः विकास-दर का निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जाता है—

$$\text{विकास-दर} = \frac{\text{वचन}}{\text{पूँजी-गुणांक}}$$

पूँजी-गुणांक अथवा पूँजी-प्रदा अनुपात का आशय पूँजी का उस मात्रा से है, जो उत्पादन की एक इकाई के लिए आवश्यक होती है। पूँजी-उत्पादन अनुपात दो प्रकार के होते हैं—(क) औसत पूँजी-प्रदा अनुपात और (ख) सीमान्त पूँजी-प्रदा अनुपात। औसत पूँजी-प्रदा अनुपात का अर्थ देश के कुल पूँजी-नचय तथा वार्षिक उत्पादन के अनुपात में लगाया जाता है। सीमान्त पूँजी-प्रदा अनुपात से आशय पूँजी-नचय में वृद्धि तथा उत्पादन में वार्षिक वृद्धि के अनुपात से है।

(क) औसत पूँजी-प्रदा अनुपात के निर्धारक तत्त्व (Factors Determining the Average Capital Output Ratio)—जिनो अर्थव्यवस्था में औसत पूँजी-प्रदा अनुपात विभिन्न तत्त्वों पर निर्भर करता है, जो उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। ये मुख्य तत्त्व निम्नलिखित हैं—

1. तकनीकी सुधार (Technological Improvements)—तकनीकी सुधारों द्वारा पूँजी की उत्पादकता में वृद्धि होती है। इससे पूँजी-प्रदा अनुपात घटता है।

2. श्रम-उत्पादकता (Labour Productivity)—यदि श्रम उत्पादकता में वृद्धि होती है, तो पूँजी की पूर्व-मात्रा से अधिक उत्पादन किया जा सकता है। इस स्थिति में पूँजी-प्रदा अनुपात घटता है।

3. विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्ष महत्व में परिवर्तन (Shift in the Relative Importance of Different Sectors)—औसत पूँजी-प्रदा अनुपात, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के पूँजी-प्रदा अनुपातों पर निर्भर करता है। यदि किसी देश में

औद्योगिक विकास पर अधिक बल दिया जाता है तो औद्योगिक क्षेत्र के सापेक्ष महत्त्व में वृद्धि होगी परिणामस्वरूप पूँजी प्रदा अनुपात बढ़ जाएगा ।

4 विनियोग का ढंग (Pattern of Investment)—यदि विनियोग-योजना में सावर्जनिक-उपयोग तथा पूँजीगत-वस्तुओं के औद्योगिक विकास पर बल है तो औसत पूँजी-प्रदा अनुपात अधिक होगा । इसके विपरीत, यदि घरेलू उद्योगों तथा कृषि विकास को अधिक महत्त्व दिया जाता है तो पूँजी प्रदा अनुपात घटेगा ।

5 तकनीकी का चुनाव (Choice of Technique)—श्रम-गहन तकनीकी में पूँजी प्रदा अनुपात कम तथा पूँजी-गहन तकनीकी में यह अनुपात अधिक होता है ।

(ख) सीमान्त पूँजी-प्रदा अनुपात (Marginal Capital Output Ratio)—कुछ अर्थशास्त्रियों के मतानुसार अर्द्ध-विकसित देशों में यह अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है । अर्थशास्त्री विपरीत मत रखते हैं । इस अनुपात के अधिक होने के निम्नलिखित कारण हैं—

1 पूँजी का दुरुपयोग (Waste of Capital)—अर्द्ध-विकसित देशों में श्रम अकुशल होता है, इसलिए मशीनों का उपयोग कुशलता से नहीं होता है । परिणामस्वरूप उत्पादन कम होता है । इस कारण विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की अपेक्षा अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यह अनुपात अधिक पाया जाता है ।

2 तकनीकी (Technology)—अर्द्ध विकसित देशों में पूँजी उत्पादकता कम होती है । इसका कारण निम्नस्तरीय तकनीकी है । इस कारण उत्पादन की एक इकाई के लिए अधिक पूँजी आवश्यक होती है । इस स्थिति में यह अनुपात बढ़ जाता है ।

3 सामाजिक ऊपरी पूँजी (Social Overhead Capital)—अर्द्ध-विकसित देशों में सामाजिक ऊपरी पूँजी के लिए बड़े विनियोग किए जाते हैं । ये विनियोग पूँजी-गहन होते हैं, परिणामस्वरूप पूँजी-प्रदा अनुपात अधिक रहता है । विकसित देशों में भी निर्माण-उद्योगों की अपेक्षा सावर्जनिक उपयोग के उद्योगों में यह अनुपात अधिक होता है । अर्द्ध-विकसित देशों में यह अनुपात और भी अधिक ऊँचा रहता है ।

यदि भारी उद्योगों में विनियोग किया जाता है तो पूँजी प्रदा अनुपात अधिक होगा ।

निम्नलिखित अवस्थाओं में पूँजी प्रदा अनुपात अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्थाओं में नीचा रहता है—

(i) यदि देश की विकास नीति ऐसी है कि कृषि व लघु उद्योगों पर अधिक बल दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में सीमान्त पूँजी प्रदा अनुपात कम रहेगा ।

(ii) आर्थिक विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में पूँजी की अल्प राशि के विनियोजन से भी अप्रयुक्त उत्पादन-क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सकता है ।

परिणामस्वरूप उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होती है। उत्पादन में इस प्रकार की वृद्धि से पूँजी प्रदा अनुपात कम रहेगा।

(iii) निम्नस्तरीय तकनीकी के कारण अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्थाओं में प्रायः पूँजी प्रदा अनुपात अधिक रहता है। किन्तु कभी-कभी जब नई तकनीकी प्रयोग में आती है तो आवश्यकतानुसार लाभ परिलक्षित होते हैं। इसीलिए अधिक पिछड़े हुए देशों में पूँजी विनियोजित की जाती है। साथ ही, शिक्षा व प्रशिक्षण पर आवश्यक व्यय किया जाता है, ताकि विकसित देशों की अपेक्षा अर्द्ध-विकसित देशों में अधिक ऊँची विकास दरें प्राप्त की जा सकें। इस मत की पुष्टि में अर्थशास्त्रियों द्वारा सोवियत रूस व जापान के उदाहरण दिए जाते हैं।¹

(iv) जब पूँजी का प्रयोग नए प्राकृतिक साधनों के विशोहन (Exploitation) हेतु किया जाता है तो उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होती है, परिणामस्वरूप, पूँजी-प्रदा अनुपात कम रहता है।

अतः स्पष्ट है कि विकास-दर के दो मूल घटक होते हैं—(1) बचत तथा (2) पूँजी-गुणांक। इन घटकों को जो तत्त्व प्रभावित करते हैं, उनसे विकास दर प्रभावित होती है। बचत व पूँजी-गुणांक को प्रभावित करने वाले तत्त्वों को ही विकास-दर के निर्धारक तत्त्व कहा जाता है।

आर्थिक-नियोजन द्वारा विकास करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और विशाल मात्रा में परियोजनाएँ प्रारम्भ की जाती हैं। इन कार्यक्रमों को संचालित करने एवं परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए बड़ी मात्रा में साधनों की आवश्यकता होती है। विकास की इन विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के संचालन के लिए आवश्यक साधनों की व्यवस्था एवं उनकी गतिमयता आर्थिक-नियोजन की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या है। इन साधनों के विकास के लिए विकास-दर गतिमयता पर ही निर्भर करती है। यदि ये साधन आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में होंगे तो विकास की अधिक सम्भावना होगी। इसी प्रकार, इन्हे जितना अधिक योजनाओं के लिए गतिशील बनाया जा सकेगा, विकास की गति उतनी ही तीव्र होगी। साधनों की उपलब्धि और उनको गतिशील बनाने की क्षमता की तुलना में यदि विकास के कार्यक्रम और गति अधिक रही गई, तो ऐसी योजना की सफलता संदिग्ध रहेगी। डॉ. राज के अनुसार “एक योजना नहीं के बराबर है, यदि इसमें निर्धारित विकास का कार्यक्रम साधनों के एकत्रित करने के कार्यक्रम पर आधारित और समन्वित नहीं किया गया हो।”

साधनों के प्रकार (Types of Resources)

आर्थिक-विकास के लिए मुख्य रूप से भौतिक साधन, मानवीय साधन और वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है। ‘भौतिक साधन’ देश में स्थित प्राकृतिक साधनों पर निर्भर करते हैं। एक देश प्राकृतिक साधनों में जितना सम्पन्न होगा, भौतिक साधनों की उतनी ही प्रचुरता होगी। यद्यपि अधिकांश अर्द्ध-विकसित देश प्राकृतिक साधनों में सम्पन्न हैं, तथापि उनका उचित विद्रोहन नहीं किया गया है और उनके विकास की व्यापक सम्भावनाएँ हैं।

इसी प्रकार, अधिकांश अर्द्ध-विकसित देशों में मानवीय साधन भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। अतः योजनाओं का विस्तार, उनकी सफलता और विकास की

गति उनके लिए उपलब्ध वित्तीय साधनों, उनकी गतिमयता, उनके उचित आवंटन तथा उपयोग पर निर्भर करती है।

‘वित्तीय साधनों का महत्त्व देश के आर्थिक विकास में बहुत है। आर्थिक योजना के लिए वित्तीय साधन और उनको एकत्रित करने का तरीका योजना सिद्धि हेतु प्रमुख स्थान रखता है। वित्त एक देश के ससाधनों को गतिशील बनाता है चाहे वे भौतिक साधन हो या वित्तीय अथवा आन्तरिक साधन हो या बाह्य।

गतिशीलता को निर्धारित करने वाले कारक (Factors Determining Mobilisation)

साधनों का अनुमान और उनको गतिशील बनाना मुख्यतः निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है।¹

(i) राज वित्त की यन्त्र प्रणाली (Machinery of Public Finance)—यदि देश की अर्थव्यवस्था सुसंगठित हो जिसमें विकास हेतु उपयुक्त और कुशल राजकोपीय नीति को अपनाया गया हो तो आन्तरिक साधनों को अधिक सफलतापूर्वक गतिशील बनाया जा सकता है। इसके विपरीत यदि मार्बजिनिक वित्त की यन्त्र प्रणाली अकुशल होगी तो अपेक्षाकृत कम साधन जुटाए जा सकेंगे।

(ii) उद्देश्यों की प्रकृति (Nature of Objectives)—उद्देश्य की प्रकृति पर भी साधनों की गतिशीलता निर्भर करती है। यदि योजना का उद्देश्य मुद्रा लड़ना है तो बाह्य साधन कम प्राप्त हो सकेंगे। किन्तु यदि इसका उद्देश्य द्रुत गति से आर्थिक विकास करना हो तो विदेशी साधन भी अधिक गतिशील हो सकेंगे। यदि योजना के लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी होंगे तो कुल एकत्रित साधन अधिक होंगे और जनता पर भार भी अधिक होगा।

(iii) योजना की अवधि (Period of Plan)—यदि योजना एक वर्षीय है तो कम मात्रा में कोषों की आवश्यकता होगी और इससे देश के आन्तरिक साधनों पर अधिक दबाव नहीं पड़ेगा। किन्तु यदि योजनाओं की अवधि लम्बी होगी तो बड़ी मात्रा में साधनों को गतिशील बनाने की आवश्यकता होगी।

(iv) श्रम और पूँजी की स्थिति (Situation with regard to Labour and Capital)—यदि देश में श्रम शक्ति की बहुलता है तो साधनों को गतिशील बनाने में श्रम प्रधान तरीके (Labour intensive) उपयुक्त होंगे। इसके विपरीत यदि देश में पूँजी की विपुलता है और अनिश्चित श्रम शक्ति नहीं है तो साधनों को गतिशील बनाने में अधिक पूँजी गहन (Capital intensive) तकनीकी अपनाई जाएगी।

(v) शिक्षा एवं राष्ट्रीय चेतना (Education and National Consciousness)—वित्तीय साधनों को योजना की वित्त व्यवस्था के लिए गतिशील बनाने में देशवासियों की शिक्षा और राष्ट्रीय भावना का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि

देशवासी शिक्षित हैं, उनमें राष्ट्रीय भावना है और वे अपने उत्तरदायित्व को समझने वाले हैं तो योजना के लिए अधिक वित्त जुटाया जा सकेगा। अल्प बचत, बाजार ऋण यहाँ तक कि करो से भी अधिक साधन, एकत्रित किए जा सकेंगे।

(vi) अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति (International Situation)—यदि अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण शांति और सहयोगपूर्ण है और विश्व में तनाव कम है तो बाह्य साधनों से अधिक वित्त उपलब्ध हो सकेगा। इसके अतिरिक्त, यदि योजना को अपनाते वाले देश के अन्य धनी देशों से अच्छे सम्बन्ध हैं या वह युद्ध, सुरक्षा प्रयत्न या आक्रमण के लिए नहीं, अपितु आर्थिक विकास के लिए नियोजन को अपना रहा है तो इन विकसित देशों से तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अधिक मात्रा में योजनाओं के संचालन के लिए वित्त उपलब्ध हो सकेगा। ऐसी स्थिति में, योजनाओं की वित्त-व्यवस्था में बाह्य साधनों का महत्त्व बढ़ जाएगा।

(vii) मूल्य-स्तर और जनता की आर्थिक स्थिति (Price level and Economic condition of the people)—यदि मूल्य बढ़ रहे होंगे और इसके कारण जीवन स्तर-व्यय बढ़ रहा होगा तो लोगों के पास बचत कम होगी। साथ ही, जनता भी सरकार के इस साधन को गतिशील बनाने के कार्यक्रम में अधिक सहयोग नहीं करगी। परिणामस्वरूप, आन्तरिक साधन कम जुटाए जा सकेंगे।

(viii) विदेशी विनिमय कोष (Foreign Exchange Reserves)—यदि एक देश के पास पर्याप्त विदेशी विनिमय कोष है तो साधनों की गतिमय बनाना सुगम होगा। ऐसी स्थिति में, 'हीनार्थ प्रबन्धन' भी वित्त का एक स्रोत बन सकता है और उसमें अन्य स्रोतों पर कम भार होगा। राजस्व, बाजार, बचत आदि वित्त के कम महत्त्वपूर्ण साधन हो जाएंगे। इसके विपरीत, यदि विदेशी विनिमय कोष छोटा है तो 'हीनार्थ प्रबन्धन' (Deficit Financing) भी कम होगा और वित्त के अन्य स्रोतों पर कर भार बढ़ जाएगा।

(ix) सरकार की आर्थिक नीति (Economic policy of the Government)—यदि देश की अर्थव्यवस्था सोवियत रूस की तरह पूर्णतः केन्द्रित हो तो साधनों को अधिक मात्रा में सरलतापूर्वक गतिशील बनाया जा सकता है। किन्तु यदि देश में जनतान्त्रिक शासन प्रणाली और निरुत्पन्न पूर्ण अर्थव्यवस्था हो तो अपेक्षाकृत कम मात्रा में साधन गतिशील बनाए जा सकेंगे।

(x) आर्थिक विषमता की मात्रा (Degree of Economic Inequality)—यदि देश में आर्थिक विषमता तथा आय की असमानता कम होगी और उत्पादन के साधनों पर समाजिक स्वामित्व का विस्तार हो रहा होगा ऐसी स्थिति में सार्वजनिक उपक्रमों की श्रम के रूप में साधनों की अधिक वृद्धि होगी। वितरण की श्रेयस्वीकृत प्रणाली और उत्पादन के सामूहिक स्वामित्व से राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी और विकास की गतिशील बनाने के लिए साधन अधिक उपलब्ध हो सकेंगे। किन्तु यदि समाज में आर्थिक विषमता है और उत्पादन निजी-क्षेत्र में ही संचालित किया जाता है तो योजनाओं की वित्त-व्यवस्था के मुख्य साधन कर, ऋण, बचत आदि होंगे।

साधनों का निर्धारण (Determination of Resources)

एक देश के द्वारा बनाई जाने वाली योजना के कार्यक्रमों के निर्धारण हेतु साधनों का अनुमान लगाना पड़ता है। अनुमानित साधनों पर ही योजना का आकार और कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। इसीलिए उपलब्ध या गतिशील बनाए जा सकने वाले साधनों की मात्रा का अनुमान लगाना आवश्यक होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि देश और उसके बाहर ऐसे क्रियाशील घटकों पर विचार किया जाए जो योजनाओं की वित्त व्यवस्था को प्रभावित करने वाले हों। सर्वप्रथम विदेशी सहायता और बाह्य साधनों का अनुमान लगाया जा सकता है। यद्यपि सोवियत रूस ने अपनी योजना को आन्तरिक साधनों से ही संचालित किया था, किन्तु ऐसी स्थिति में देशवासियों को भारी त्याग करना पड़ता है और कष्ट उठाना पड़ता है। आधुनिक भ्रष्ट-विकसित देशों के लिए अपने देशवासियों से इस मात्रा में भारी त्याग और कष्टों का वहन कराना वांछनीय नहीं है साथ ही इतना आसान भी नहीं है। अतः इन देशों की योजनाओं की वित्त-व्यवस्था में बाह्य साधनों का पर्याप्त महत्त्व है। इन्हीं यथासम्भव आन्तरिक साधनों को अधिकतम मात्रा में गतिशील बनाना चाहिए। किन्तु ऐसा जनता पर बिना विशेष कष्ट दिए हुए होना चाहिए और इन आन्तरिक साधनों की कमी की पूर्ति बाह्य साधनों द्वारा की जानी चाहिए। यद्यपि, किसी देश को विकास के लिए बाह्य साधनों पर ही पूर्णरूप से निर्भर नहीं होना चाहिए किन्तु भ्रष्ट विकसित देश बिना बाह्य साधनों के वांछित दर से प्रगति भी नहीं कर सकते। अतः दोनों स्रोतों का ही उचित उपयोग किया जाना चाहिए। कोलम्बो योजना में भी इस विचार को स्वीकार किया गया है कि इन दशों को विशाल मात्रा में विदेशी विनियोगों के रूप में प्रारम्भिक उत्तेजक (Initial Stimulus) की आवश्यकता है। कई देशों की योजनाओं में लगभग 50% तक वित्तीय साधनों के लिए बाह्य स्रोतों पर निर्भरता रखी गई है।

योजना के लिए वित्तीय साधनों की गतिशीलता (Mobilisation of Financial Resources)

वित्तीय साधनों की गतिशीलता का तात्पर्य, योजना की वित्त व्यवस्था के लिए इनके एकत्रीकरण से है। योजनाओं की वित्त-व्यवस्था करने के प्रमुख रूप से निम्नलिखित दो स्रोत हैं—

- (अ) बाह्य साधन (External Resources) तथा
- (ब) आन्तरिक साधन (Internal Resources)

बाह्य साधन (External Resources)

भ्रष्ट विकसित देशों में न केवल पूँजी की उपलब्ध मात्रा ही कम होती है अपितु चालू बचत दर भी निम्न स्तर पर होती है। एक अनुमान के अनुसार लेटिन अमेरिका, मध्य पूर्व अफ्रीका, दक्षिण मध्य एशिया और सुदूर-पूर्व के निर्धन देशों की घरेलू बचत दर 5% से भी कम रही है। ऐसी स्थिति में ये देश स्वयं स्फूर्त अर्थव्यवस्था

में पहुँचने और द्रुत आर्थिक विकास हेतु आवश्यक बड़ी मात्रा में विनियोग नहीं कर सकते हैं। बाँझोंन विनियोग और उपलब्ध वचत के मध्य के इस अन्तर को पूरा करने के लिए विदेशी सहायता अपेक्षित है। बाह्य साधनों का योजना की वित्त व्यवस्था में इसलिए भी महत्व है क्योंकि इन देशों की जनता निर्धन होती है और आर्थिक करारोपण द्वारा अधिक धन-संग्रह भी नहीं किया जा सकता है। निर्धनता और कम आय के कारण ऋणों द्वारा भी अधिक अर्ध संपन्न नहीं किया जा सकता। हीनार्थ प्रवर्धन (Deficit financing) का भी असंमित मात्रा में आश्रय नहीं लिया जा सकता है क्योंकि इसमें मुद्रा प्रसारित प्रवृत्तियों को जन्म मिलता है। इसीलिए योजनाओं की आवश्यकताओं और आन्तरिक साधनों में जो अन्तर रह जाता है उसकी पूर्ति हेतु बाह्य साधनों का सहारा लेना पड़ता है। पहले यह धारणा थी कि केवल परियोजनाओं की विदेशी विनिमय की आवश्यकताओं तक ही बाह्य सहायता सीमित रहनी चाहिए किन्तु अब यह माना जाना लगा है कि न केवल विदेशी विनिमय की आवश्यकता के समान अपितु, घरेलू आवश्यकताओं के लिए भी विदेशी सहायता आवश्यक है।

इस प्रकार योजनाओं की वित्तीय आवश्यकताएँ और आन्तरिक साधनों का अन्तर विदेशी सहायता की मात्रा का निर्धारण करता है। जितनी विदेशी सहायता इस अन्तर के बराबर होगी उतना ही देश का द्रुत आर्थिक विकास होगा। किन्तु अर्थ-प्रयत्नों के बावजूद भी बाह्य साधनों से इतना वित्त उपलब्ध हो जाए यह आवश्यक नहीं है क्योंकि बाह्य सहायता की उपलब्धता कई आर्थिक और सामाजिक बातों पर निर्भर करती है जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं—

(i) विदेशी व्यापार की स्थिति (ii) विदेशी विनिमय का अर्जन (iii) घरेलू और विदेशी वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन (iv) बाह्य विश्व में स्थायित्व की मात्रा (v) स्वदेश और विदेशों में मुद्रा-प्रसार या मुद्रा-संकुचन की मात्रा (vi) विनियोग के अनुपादक रहन की अवधि (vii) विनियोगों की उत्पादकता अर्थात् पूँजी उत्पाद अनुपात (viii) आन्तरिक स्थायित्व (ix) अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण (x) विश्व में विदेशी सहायता की इच्छा (xi) उचित योजना निर्माण। विशुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण में विदेशी सहायता का आपदर्श सहायता प्राप्त करने वाले देश के अपने की साख, का उद्देश्य और चुकाने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए किन्तु आधुनिक विश्व में विदेशी सहायता में राजनीतिक दृष्टिकोण को ही प्रमुखता दी जाती है। इस सम्बन्ध में श्री ब्लैक (Eugene R. Black) (भूतपूर्व अल्पसंख्यक विश्व-बैंक) ने लिखा है कि विदेशी सहायता कभी-कभी केवल कूटनीतिक सैनिक मिशनों की कप के लिए ही दी जाती है।" ऐसी स्थिति में तटस्थता की नीति में विश्वास करने वाले और मुतकरी से दूर रहने वाले अर्द्ध-विकास देश, विदेशी सहायता प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव करते हैं, किन्तु इनके बावजूद भी इन अर्द्ध-विकसित देशों को अपनी योजनाओं की वित्त-व्यवस्था हेतु बाह्य साधनों से पर्याप्त सहायता मिलती रही है।

बाह्य साधनों के रूप (Forms of External Resources)—बाह्य साधन प्रमुख रूप से निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं—

(i) **निजी पूँजी (Private Capital)**—बाह्य साधन विदेशों में स्थित निजी व्यक्तियों और गैरसरकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध होने हैं। निजी पूँजी को मुख्यतः प्रत्यक्ष विनियोग द्वारा ही गतिशील बनाया जा सकता है, किन्तु आजकल नियोजित अर्थव्यवस्था में इसके लिए सीमित क्षेत्र होता जा रहा है क्योंकि नियोजित अर्थव्यवस्था में निजी-उपक्रम के लिए सीमित क्षेत्र होता है। साथ ही विदेशी विनियोगकर्ता को सरकार अधिक लाभ नहीं लेने देनी। बहुधा इन देशों की सरकारों द्वारा विदेशी पूँजी पर घने नियन्त्रण और ऐसी शर्तें लगाई जाती हैं, जिन्हें विदेशी विनियोगकर्ता स्वीकार नहीं करते। इसके अतिरिक्त इन अर्द्ध-विकसित देशों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थायित्व का अभाव रहता है। अनेक बार सरकारें बदलती रहती हैं, जिनसे इन विदेशी विनियोगों के बारे में विरोधी नीति हो सकती है। राष्ट्रीयकरण तथा विनिमय नियन्त्रण द्वारा भविष्य में इस विदेशी पूँजी और इस पर लाभ के स्वदेश में हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध का भय भी विकसित देशों से, अर्द्ध-विकसित देशों में निजी पूँजी-प्रवाह में कमी लाता है।

भारत में निजी-पूँजी विदेशी निजी अभिकरणों (Private Agencies) द्वारा विनियोगों और भारतीय कम्पनियों द्वारा विश्व बैंक से लिए गए ऋणों के रूप में पर्याप्त मात्रा में विदेशी निजी पूँजी का आर्थिक विकास में योगदान रहा है किन्तु गत वर्षों में विश्व बैंक के ऋणों का महत्त्व बढ गया है। भारत की कुल निजी पूँजी में से विदेशियों द्वारा नियन्त्रित उपक्रमों या प्रत्यक्ष विदेशी विनियोगों का भाग अधिक है। सन् 1957 में यह भाग 90% था जिसमें विगत वर्षों में निरन्तर कमी होती रही है।

(ii) **सार्वजनिक विदेशी विनियोग (Public Foreign Investments)**—

अर्द्ध-विकसित देशों की योजना विनियोगों का बहुत महत्त्व है। विदेशी सरकारों द्वारा दिए गए ऋण, अनुदान या प्रत्यक्ष विनियोगों द्वारा इन पिछड़े हुए देशों में अनेक महत्त्वपूर्ण परियोजनाएँ प्रारम्भ और पूर्ण की गई हैं। विकसित देशों की सरकारें, अर्द्ध-विकसित देशों के आर्थिक विकास में उनके उत्तरदायित्व को पूर्वापेक्षा अधिक समझने लगी हैं, इसीलिए ये इन विकासशील देशों को अधिक सहायता देने लगी हैं। किन्तु सार्वजनिक विदेशी विनियोगों द्वारा सहायक देश की सरकारें सहायता के इच्छुक देश को राजनीतिक रूप से प्रभावित करना चाहती हैं और अपनी शर्तें सहायता के साथ लगा देती हैं। भारत में सरकारी क्षेत्र के बोकारो में स्थापित होने वाले चौथे इस्पात कारखाने में अमेरिका ने सहायता देना इसलिए स्वीकार नहीं किया था क्योंकि यह सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा था। इसी प्रकार अन्य शर्तें भी जोड़ दी जाती हैं और स्वतन्त्र तथा तटस्थनीति को अपनाते वाले या स्वाभिमानी राष्ट्र इस प्रकार की विदेशी वित्तीय सहायता आवश्यकतानुसार प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते हैं। फिर भी विकसित देशों की सरकारों से कई

आन्तरिक वित्त के साधन—आन्तरिक वित्त के निम्नलिखित प्रमुख साधन हैं—

- (i) चालू राजस्व से बचत (Surplus from Current Revenues)
- (ii) सार्वजनिक उपक्रमों से लाभ (Profit from Public Enterprises)
- (iii) जनता से ऋण (Public Borrowings)
- (iv) हीनार्थ प्रबन्धन (Deficit Financing)
- (v) प्राविधिक जमा-निधि (Provident Fund etc.)
- (i) चालू राजस्व से बचत (Surplus from Current Revenues)—

योजनाओं की वित्त-व्यवस्था का चालू राजस्व से बचत सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। चालू राजस्व से अधिक बचन हो इस हेतु करो का लगाना और पुराने करो की दर में वृद्धि करना होता है। करारोपण, आन्तरिक साधनों में एक प्रमुख है, क्योंकि इससे कुछ बचत में वृद्धि होती है। यह एक प्रकार की विवशतापूर्ण बचत है। कर व्यवस्था इस प्रकार से सगठित की जानी चाहिए जिससे न्यूनतम सामाजिक त्याग से अधिकतम कर राशि एकत्रित की जा सके। इसके लिए अधिकाधिक जनसंख्या को कर परिधि में लाया जाय। करो की चोरी रोकी जाए और प्रगतिशील करारोपण लागू किया जाए जिससे प्राप्त कर-राशि का अधिकांश भार उन व्यक्तियों पर पड़े जो इस बोझ को वहन करने में सक्षम हों, साथ ही इससे आर्थिक विषमता कम हो। किन्तु साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि करो के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े तथा बचत, विनियोग और कार्य करने की इच्छा हनोत्पाहित न हो। विकासार्थ, अपनाए गए नियोजन के प्रारम्भिक काल में मुद्रा प्रसारिक प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि इस समय भारी मात्रा में पूँजी विनियोग होता है। ऐसा उस समय अधिक होता है जबकि लम्बे समय में फल देने वाली योजनाएँ होती हैं। करो द्वारा जनता से अतिरिक्त कृपणता लेकर मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियों का दमन करने में भी सहायता मिलती है और इन प्रवृत्तियों का दमन योजनाओं की सफलता के लिए अतिप्रावश्यक है। अतः कर-नीति इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कम से कम कुपरिणाम हो और अधिक से अधिक वित्तीय-साधन गतिशील बनाए जा सकें।

अधिकांश अर्द्ध-विकसित देशों में जनता की आय अति न्यून होने के कारण वित्त-व्यवस्था के साधन के रूप में करारोपण का महत्व विकसित देशों की अपेक्षा कम होता है। वहाँ जीवन-स्तर उच्च बनाने की आवश्यकता होती है और इसलिए किसी भी सीमा तक कम बढ़ाते जाना वांछनीय नहीं होता है। अर्द्ध-विकसित देशों में करदान क्षमता (Taxable Capacity) कम होती है और राष्ट्रीय आय का अन्य भाग ही कर संग्रह में प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, गत वर्ष पँचू भारत में कुल करो से प्राप्त-आय, कुल राष्ट्रीय आय की केवल 9% ही थी जबकि यह इंग्लैण्ड, संयुक्तराज्य अमेरिका, जापान, न्यूजीलैण्ड, कनाडा और लका में क्रमशः 35%, 23%, 23%, 27%, 19% और 20% थी।

भारतीय विकास योजनाओं में विकास के हेतु विशाल कार्यक्रम सम्मिलित किए गए और समस्त स्रोतों से वित्तीय साधनों को गतिशील बनाने का प्रयत्न किया गया। कर साधनों का पूर्ण उपयोग किया गया। करो की दर में वृद्धि की गई और नवीन कर लगाए गए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में देश के अपने साधनों (mainly through own resources) से 740 करोड़ रु की वित्त-व्यवस्था का अनुमान लगाया गया जबकि वास्तविक प्राप्ति 725 करोड़ रु (कुल वित्त-व्यवस्था का 38.4 प्रतिशत) हुई। इसमें कराधान की योजना पूर्व दरों पर चालू राजस्व से बचत 382 करोड़ रु थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देश के अपने साधनों से वास्तविक प्राप्ति 1,230 करोड़ रु (कुल वित्त-व्यवस्था का 26.3 प्रतिशत) हुई जिसमें कराधान की योजना पूर्व दरों पर चालू राजस्व से बचत 11 करोड़ रु थी। तृतीय योजना में देश के अपने साधनों से 2,908 करोड़ रु (कुल वित्त व्यवस्था का 33.9 प्रतिशत) प्राप्त हुए जिसमें कराधान की योजना पूर्व दरों पर चालू राजस्व से बचत (—) 419 करोड़ रु की थी। चतुर्थ योजना में अन्तिम उलटबिग अनुमानों के अनुसार देश के अपने साधनों से 5,475 करोड़ रु (कुल वित्त-व्यवस्था का 33.9 प्रतिशत) प्राप्त हुए जिसमें कराधान की योजना पूर्व दरों पर चालू राजस्व से बचत (—) 236 करोड़ रु थी।¹ पाँचवी योजना में सरकारी क्षेत्र में देशीय बचत 15,075 करोड़ रु और गैर-सरकारी क्षेत्र में देशीय बचत 30,055 करोड़ रु अनुमानित की गई है।²

(ii) सार्वजनिक उपक्रमों से लाभ (Profit from Public Enterprises)—पूर्ण नियोजित अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन का लगभग समस्त कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन रहता है। किन्तु अन्य प्रकार की नियोजित अर्थ व्यवस्थाओं में भी सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन उत्पादक इकाइयों की संख्या में वृद्धि होती रहती है और सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार होता है। इस कारण वित्तीय साधनों में राजस्व का भाग घटकर, सार्वजनिक उपक्रमों के लाभों का भाग बढ़ता जाता है। उदाहरणार्थ सोवियत रूस में जनता आय का केवल लगभग 13% भाग ही कर के रूप में देती है। सरकारी आय का प्रमुख साधन सार्वजनिक उद्योगों का आधिकार्य ही होता है। सार्वजनिक उपक्रम केवल अपने लाभ-आधिकार्य के द्वारा ही योजनाओं की वित्त-व्यवस्था के लिए धन उपलब्ध नहीं कराते, अपितु इन उपक्रमों में कई प्रकार के बोध होते हैं जिनसे सरकारें समय-समय पर अपने वित्तीय उत्तरदायित्वों का निर्वाह करती हैं।

सार्वजनिक उपक्रमों का लाभ मुख्यतः उन देशों में एक बड़ा वित्तीय साधन के रूप में प्रकट होता है जहाँ पूर्णरूप से नियोजित अर्थ व्यवस्था हो और समस्त उत्पादन कार्य सरकार द्वारा ही किया जाता हो, किन्तु अधिकांश अर्द्ध-विकसित देशों में इस प्रकार की पूर्ण-नियोजित अर्थ व्यवस्था और सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार नहीं

1 इण्डिया 1976, पृष्ठ 173.

2 योजना, 22 दिसम्बर, 1973, पृष्ठ 7.

होता है, वहाँ उत्पादन क्षेत्र में निजी-उद्यम भी क्रियाशील रहता है। इसलिए, वहाँ सार्वजनिक उपक्रमों की सख्या और स्वभावतः उनके लाभ की मात्रा भी ग्यून होती है। इन देशों में जो कुछ सार्वजनिक उपक्रम हैं वे हाल ही स्थापित किए गए हैं और उन्होंने अभी पर्याप्त मात्रा में लाभ कमाना आरम्भ नहीं किया है। अनुभव अभाव के कारण इनकी सफलता का स्तर बहुत भीचा है। इन सब कारणों से इन देशों में नियोजन हेतु, वितीय साधनों को गतिशील बनाने में स्रोत से अधिक अपेक्षा नहीं की जा सकती। साथ ही, यह प्रश्न भी दिवादास्पद हुआ है कि इन सार्वजनिक उपक्रमों को लाभ के उद्देश्य (Profit Motive) पर संचालित किया जाय या इन्हे लाभ का साधन नहीं बनाया जाए। यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि निजी-उपक्रम में मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए जाने चाहिए जिससे कर सहित उत्पादन लागत निकलने के पश्चात् इतना लाभ प्राप्त हो जिससे पूँजी और उपक्रम इस और आकर्षित हो सकें। किन्तु सरकारी उपक्रमों के समक्ष व्यावसायिक और आर्थिक दृष्टिकोण की अपेक्षा जन-कल्याण का ध्येय प्रमुख होता है। इसी कारण बहुधा सार्वजनिक उपक्रमों की स्थिति एकाधिकारिक होने हुए भी इनके मूल्य कम हो सकते हैं। किन्तु अब यह माना जाने लगा है कि सार्वजनिक उपक्रम लाभ नीति के आधार पर संचालित किए जाने चाहिए जिससे सरकार को आत्म निर्भर बनने में मदद मिलेगी। उनके पाम योजनाओं की वित्त-व्यवस्था के लिए मुगमतापूर्वक साधन उपलब्ध हो सकेंगे और साथ ही मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियों को रोकने में भी सहायता मिलेगी।

भारत में योजनायुद्ध आर्थिक विकास का मार्ग अपनाने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार निरन्तर होता गया। गत 25 वर्षों में औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों का केन्द्रीय सरकार का निवेश 20 करोड़ रुपये से बढ़कर अब 6 000 करोड़ रुपये से भी अधिक हो गया है। जहाँ 25 वर्ष पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू होत समय केवल पाँच उपग्रम थे, वहाँ अब देश के चारों कोनों में ऐसे लगभग 200 उपक्रम चल रहे हैं। देश की योजनाओं ने सार्वजनिक क्षेत्र से निरन्तर बढ़ती हुई मात्रा में वित्त उपलब्ध होने की आशा की गयी है। पर रेलों के योगदान के अतिरिक्त अन्य उद्योगों से वित्त की उपलब्धि का चित्र अधिकशत निराशाजनक ही रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में रेलों से 115 करोड़ रुपये और द्वितीय योजना में 167 करोड़ रुपये, तृतीय योजना में केवल 62 करोड़ रुपये रहा। चौथी योजना में स्थिति तेजी से बिगड़ी, जहाँ प्रारम्भिक अनुमान 265 करोड़ रुपये की प्राप्ति का था, वहाँ अन्तिम उपलब्ध अनुमान (-) 165 करोड़ रुपये का रहा। अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्रथम और द्वितीय योजना में उपलब्धि नगण्य रही जबकि, तृतीय योजना में वास्तविक प्राप्ति 373 करोड़ रुपये की रही। चौथी योजना में अन्तिम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार यह प्राप्ति 1 300 करोड़ रुपये की रही। प्रारम्भिक अनुमान 1,764 करोड़ रुपये था। भारत में सार्वजनिक उपक्रम अपेक्षित पूर्ति-स्तर से अभी बहुत दूर हैं और इस स्थिति के लिए इन उद्योगों की निम्न कार्यकुशलता, इन उद्योगों

अशान्ति, अमितव्ययितापूर्ण योजनाओं का निर्माण आदि तत्त्व उत्तरदायी है। भारतीय योजनाओं के लिए इस स्रोत से अधिक वित्तीय साधन अधिक गतिशील बनाए जाएँ, इसके लिए आवश्यक है कि इनकी कुशलता का स्तर ऊँचा हो, ये अपने पैरों पर खड़े हो और योजनाओं के लिए दुर्बल साधन जुटाने की दृष्टि से इन्हें उचित लाभ प्राप्त हो। यह उत्साहवर्द्धक बात है कि पिछले कुछ समय से सरकार सार्वजनिक उपक्रमों के प्रति विशेष रूप से जागरूक हो गई है। केन्द्रीय सरकार के वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा अधिक लाभ कमाया जाने लगा है। वार्षिक समीक्षा 1975-76 के अनुसार, 1974-75 में कुल 121 चालू उपक्रमों के प्रवर्तन सम्बन्धी परिणामों से कुल मिलाकर 312 करोड़ रुपये के कर की अदायगी से पूर्व निबल लाभ हुआ है। यह लाभ 1973-74 में 114 चालू उपक्रमों द्वारा प्राप्त 148.7 करोड़ रुपये के लाभ की रकम से दगुनी रकम से भी अधिक है। लाभ कमाने वाले उपक्रमों की संख्या 82 थी। उन्होंने कुल मिलाकर 451 करोड़ रुपये का वास्तविक लाभ कमाया, घाटे में चलने वाले उपक्रमों की संख्या 39 थी और उनको हुए कुल घाटे की रकम 139 करोड़ रुपये थी।

(iii) जनता से ऋण (Public Borrowings)—करो से प्राप्त आय और सार्वजनिक उपक्रमों के आधिक्य से आर्थिक विकास के लिए बनाई गई योजनाओं के संचालन के लिए आवश्यक राशि प्राप्त नहीं होने पर जनता से ऋण प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार, योजनाओं की वित्त व्यवस्था में जनता से प्राप्त ऋणों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किन्तु योजनाओं की वित्त व्यवस्था हेतु ऋणों का उपयोग अत्यन्त सोच विचार करके करना चाहिए, क्योंकि इनकी प्राप्ति के साथ ही इनकी व्याज सहित अदायगी का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही अर्द्ध-विकसित देशों में आय और जीवन स्तर की निम्नता के कारण इस साधन द्वारा योजनाओं के लिए पूँजी-संचय की बहुत अधिक सम्भावना नहीं होती, क्योंकि निर्धनता के कारण बचत या अक्सर कम होता है और बड़ी हुई आय में भी उपभोग की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण बचत कम होती है। धनिक वर्ग भी प्रतिष्ठा सम्बन्धी उपभोग पर काफी व्यय करता है। साथ ही, आय तथा अक्सर की समानता में वृद्धि करने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। इससे विकासार्थ पर्याप्त बचत उपलब्ध नहीं होती है। प्रो सेबिस के अनुसार, “विकास सम्बन्धी विनियोजन के लिए उन्हीं अर्थव्यवस्थाओं में ऐच्छिक बचत उपलब्ध होती है जहाँ उद्यमियों का राष्ट्रीय आय में अधिक भाग होता है और धन तथा आय की समानता के प्रयत्नों से यह भाग घटता जाता है। इन सभी कारणों से पिछड़े हुए देशों में जनता से प्राप्त ऋण या ऐच्छिक बचत आर्थिक नियोजन हेतु वित्त प्रदान करने में अधिक सहायक नहीं होती है।” किन्तु जनता को अधिकाधिक मात्रा में बचत करने को प्रोत्साहित करके इस साधन को, विशेष रूप से, अल्प बचतों को गतिशील बनाया जाना चाहिए। मुद्रा-प्रसारक मूल्यों में वृद्धि को रोकने की दृष्टि से यह उपभोग को प्रतिबन्धित करन का भी अच्छा

उपाय है। इसीलिए, बैंक, जीवन-बीमा विभाग, ढाक-विभाग, सहकारी संस्थाओं का विस्तार करके ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वचत की प्रादत को बढ़ाना चाहिए और इस वचत को ऋणों के रूप में प्राप्त कर लेना चाहिए। ये सार्वजनिक ऋण दो प्रकार के होते हैं प्रथम, अल्प वचत (Small Savings) और द्वितीय, बाजार-ऋण (Market Loans)। विवासायं नियोजन की वित्त-व्यवस्था हेतु इन दोनों ही साधनों को गतिशील बनाया जाना चाहिए।

भारत में योजनाओं के साधनों को गतिशील बनाने में सार्वजनिक ऋण के साधन का भी उपयोग किया गया है। देश के भीतर और विदेशों से लिए गए सार्वजनिक ऋण की राशियाँ इस प्रकार हैं—

भारत सरकार का सार्वजनिक ऋण¹

(करोड़ रु में)

विवरण	1950-51	1960-61	1965-66	1974-75 (समाधित)	1975-76 (बजट)
1 देश के भीतर ऋण					
(क) स्थाई ऋण					
(1) बालू ऋण	1,438 46	2,555 72	3,417 28	6,434 96	6,759 81
(2) प्रतिभूति बाण्ड	—	—	—	83 80	83 80
(3) इनामी बाण्ड	—	+15 63	11 35	104	0 94
(4) 15 वर्षीय वचत-पत्र	—	3 45	3 78	1 40	1 00
(5) अवधारणी के दौरान के ऋण	6 49	2 2 73	33.72	54 19	54 19
योग—स्थानीय ऋण	1,444 95	2 597 53	3,466 13	6,575 39	6 899 74
(ख) चल ऋण					
(1) सरकारी ट्रेजरी बिल	358 02	1,106 29	1,611 82	4,709 43	5,165 51
(2) विश्व चल ऋण	212 60	274 18	340 70	733 36	732 36
(3) कोष जमा प्राप्तिवाँ एवं अन्य चल ऋण	6 73	—	—	—	—
योग चल ऋण	577 35	1,380 47	1 952 52	5 442 79	5 897 87
योग देश के भीतर ऋण	2,022 30	3 978 00	5,418 65	1,2018 18	1,2797 61
2 विदेशी ऋण	3 2 0	760 96	2 590 62	6 419 26	7 031 95
योग सार्वजनिक ऋण	2 054 33	4 738 96	8 009 27	1 8437 44	1 9829 56

(iv) हीनार्थ प्रबन्धन (Deficit Financing)—योजना की वित्त-व्यवस्था के लिए जब उपरोक्त स्रोतों से पर्याप्त साधन गतिशील नहीं बनाए जा सकें तो सरकारें 'हीनार्थ-प्रबन्धन' का सहारा लेती हैं। सरकार के बजट में जब व्यय की जाने वाली राशि, आन्तरिक ऋण तथा विदेशी सहायता से प्राप्त राशि से कम हो जाती है, तो इस अन्तर की पूर्ति मुद्रा विस्तार करके अर्थात् नोट छाप के की जाती है। इसे 'हीनार्थ-प्रबन्धन' या 'घाटे की अर्थ-व्यवस्था' कहते हैं। जब सरकार के बजट में घाटा होने पर वह केन्द्रीय बैंक के अधिकारियों से ऋण ले जो इसकी पूर्ति चलन में वृद्धि अर्थात् पत्र-मुद्रा छाप करके करे तो यह 'हीनार्थ प्रबन्धन' कहलाता है। डॉ० बी. के. आर. बी. राव के अनुसार, "जब सरकार जान-बूझ कर किसी उद्देश्य से अपनी आय से अधिक व्यय करे जिससे देश में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाए, तो उसे 'घाटे की अर्थ-व्यवस्था' कहना चाहिए।" भूतकाल में 'हीनार्थ प्रबन्धन' का उपयोग युद्ध-काल में वित्तीय साधन जुटाने या मन्दी-काल में इसके उन्धार-स्वरूप किया जाता था किन्तु आधुनिक युग में विकासार्थ नियोजन की वित्त-व्यवस्था हेतु इस प्रकार की निर्मित मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। विकास के लिए प्रयत्नशील राष्ट्रों की वित्तीय आवश्यकताएँ अधिक होती हैं। इन देशों में आन्तरिक बचत, कर, आय और विदेशी सहायता से प्राप्त साधन बहुधा एक ओर कम पड़ जाते हैं और घाटे की पूर्ति हीनार्थ-प्रबन्धन द्वारा की जाती है। इससे जहाँ मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है। वहाँ दूसरी ओर साधनों को पूँजीगत वस्तुओं में लगाया जाता है जिससे सामान्यतः मूल्य-वृद्धि होती है और जनता अनुपात से कम उपयोग कर पाती है। घाटे की अर्थ-व्यवस्था बहुधा अन्तर्काल में मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियों को जन्म देती है। अतः साधन का सहारा एक निश्चित सीमा तक ही किया जाना चाहिए, अन्यथा इससे मूल्य-वृद्धि होगी, जिससे योजनाओं की वित्त-व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। परिणामस्वरूप, मुद्रा स्फीति तब होती है, जबकि हीनार्थ प्रबन्धन द्वारा उत्पादन और बचतों में सीढ़ी बूढ़ि हो। साथ ही, इसके लिए विभिन्न प्रकार के नियन्त्रण लगाए जाएँ। इसीलिए भारतीय योजना-आयोग ने यह अन्त व्यक्त किया है कि "नियन्त्रणों के बारे में दृढ़ और स्पष्ट नीति के अभाव में, और साथ ही, समय की एक निश्चित अवधि में कम नीति के जारी रहने के अभाव में बिना न केवल हीनार्थ-प्रबन्धन का खेव ही सीमित हो जाता है, अपितु सापेक्षिक रूप से बजट के प्रत्य घाटे से भी मुद्रा-प्रसारिक दबावों के उत्पन्न होने का निरन्तर खतरा बना रहता है।"

कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार हीनार्थ-प्रबन्धन या उसमें निहित साख विस्तार नीति तथा नियोजन परस्पर सम्बन्धित हैं। जब कभी मुद्रा या साख का विस्तार होता है तो इसके लिए न केवल मुद्रा-चलन, मूल्य-मजदूरी आदि पर ही केन्द्रीय नियन्त्रण होता है, बल्कि अन्य कई पहलुओं जैसे—उपभोग उत्पादन, प्रतिभूति-बाजार, बैंक-वैलेंस आदि पर भी नियन्त्रण रखा जाता है। इसकी सफलता के लिए नियोजित पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं। इसी प्रकार नियोजन में कुछ सीमा तक मुद्रा और साख विस्तार का अवलम्बन अनिवार्य-सा है क्योंकि विकास की विभिन्न परियोजनाओं की

वित्त व्यवस्था अकेले अन्य साधनों से नहीं हो पाती, इसके लिए कुशल प्रशासनिक यन्त्र प्रणाली, विशेषज्ञ और ईमानदार व्यक्तियों द्वारा नियोजन तथा उचित नियोजन और नियन्त्रण आवश्यक हैं। यदि चलन यन्त्र की विस्तारवादी युक्ति को बुद्धिमता, कुशलता तथा सीमाओं में और अधिक पगुपन को दूर करने या सर्वांगीण विस्तारवादी अर्थव्यवस्था की आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने लिए संचालित किया जाए, न कि अनुत्पादक सैनिक या सामाजिक व्यय पर नष्ट किया जाए तो परिणाम लाभदायक होंगे अन्यथा इसके हानिकारक परिणाम हो सकते हैं।

भारतीय विकास योजनाओं में वित्त-व्यवस्था के लिए हीनार्थ-प्रबन्धन के साधनों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में हीनार्थ प्रबन्धन से प्राप्त वास्तविक वित्त व्यवस्था क्रमशः 333 करोड़ रुपये, 954 करोड़ रुपये, और 1,133 करोड़ रुपये की रही। चतुर्थ योजना में हीनार्थ-प्रबन्धन की वित्त-राशि अन्तिम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, 2,060 करोड़ रुपये रही। चतुर्थ योजना में प्रारम्भ में 850 करोड़ रुपये की हीनार्थ-प्रबन्धन-राशि अनुमानित की गई थी, लेकिन यह 2,060 करोड़ रुपये तक इसलिए बढ़ी, क्योंकि बंगलादेश के स्वतन्त्रता-संग्राम में भारत को सक्रिय योगदान देना पड़ा। सन् 1971 में भारत-पाक युद्ध हुआ, 1971-72 और 1972-73 में कृषि-उत्पादन निराशाजनक रहा, तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में भारी वृद्धि हो गई। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में बजट घाटा 295 करोड़ रुपये का रहा, 1975-76 का संशोधित अनुमान 490 करोड़ रुपये रहा, जबकि बजट अनुमान 247 करोड़ रुपये का ही था, और अब 1976-77 के बजट में कुल घाटा 320 करोड़ रुपये का अनुमानित किया गया है। विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में हीनार्थ-प्रबन्धन के साधन का समयपूर्वक आश्रय लिया जाना चाहिए। मुद्रा-पूर्ति उत्पादन-वृद्धि के अनुसार समायोजित होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश भारत में ऐसा सम्भव नहीं हो सका है और हीनार्थ प्रबन्धन के फलस्वरूप मूल्यों में भारी वृद्धि हुई। विकासोन्मुख में अर्थ व्यवस्था में हीनार्थ-प्रबन्धन का अपना महत्त्व है किन्तु इसका आश्रय सीमित मात्रा में उचित नियन्त्रणों के साथ लिया जाना चाहिए। देश में व्याप्त मुद्रा-प्रसारित प्रवृत्तियों को दबाने के लिए हीनार्थ प्रबन्धन को न्यूनतम रखने के प्रयास अभी तक अधिकांशतः असफल ही रहे हैं। भारत में, गत वर्षों के हीनार्थ-प्रबन्धन के दुष्परिणामों को देखते हुए अब इस व्यवस्था का आगामी वर्षों में कोई क्षेत्र नहीं है, लेकिन यह भी स्वीकार करना होगा कि हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था में योजना के लिए साधनों की प्राप्ति की दृष्टि से और अर्थव्यवस्था को सक्रिय बनाने के लिए अभी हीनार्थ-प्रबन्धन के साधन से तुरन्त बच निकलना सम्भव नहीं है। यदि घाटे के वित्त-प्रबन्धन में अचानक ही भारी कटौती कर दी गई तो आशंका है कि अर्थव्यवस्था में कुल माँग के घट जाने से निष्क्रियता की स्थिति (Recessionary Situation) पैदा हो जाएगी। यदि सरकार बहुत सावधानी और समय के साथ उपयुक्त समय पर, उपयुक्त मात्रा में हीनार्थ-प्रबन्धन का आश्रय कुछ समय तक लेती रहे तो साधनों की गतिशील बनाने की दृष्टि से यह उपाय कारगर सिद्ध हो सकता है। वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति न

लगे और जनता मूल्य वृद्धि से परेशान न हो, इसीलिए ऐसे समुचित प्रशासनिक और आर्थिक कदम उठाने होंगे जिससे कृत्रिम मूल्य-वृद्धि न हो सके और स्फीतिजनक दबाव कम हो जाए। निष्कर्षतः “जिनका शीघ्र घाटे की अर्ध-व्यवस्था और मूल्य वृद्धि चक्र रोका जाएगा, उतना ही हमारे स्वस्थ आर्थिक विकास के लिए कल्याणकारी होगा।”

बचत और विकास : भारत में राष्ट्रीय बचत आन्दोलन

बचत से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का कल्याण होता है। बचत पूँजी-निर्माण का सर्वोत्तम साधन है, जिससे देश प्रगति के पथ पर तीव्रता से बढ़ता है और जन-साधारण का जीवन-स्तर ऊँचा उठता है। बचत द्वारा हम विकासशील अर्ध-व्यवस्था से उत्पन्न महंगाई पर अकुश लगा सकते हैं। बचत भी एक खर्च है, जिसे सरकार, व्यापारी तथा अन्य कोई व्यक्ति करता है। बचत की धनराशि किसी कार्य विशेष के लिए व्यय की जाती है। व्यक्ति और व्यापारी समुदाय जो बचाते हैं, वही संचार की बचत है। सरकार के बचत विभागों द्वारा बचाई गई रकम भी इसी श्रेणी में आती है। भारत में सरकार ने बचत प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के प्रचुर प्रयास किए हैं, इसी कारण देश में राष्ट्रीय बचत आन्दोलन सफलता के साथ आगे बढ़ा है।

एक अध्ययन के अनुसार भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में बचत दर 8.6% थी, जो द्वितीय योजना में बढ़कर 9.9% हो गई। किन्तु तृतीय योजना में यह घटकर 8% रह गई और चतुर्थ योजना में बढ़कर फिर 10% हो गई। इस समय बचत दर 11% है। गत 20 वर्षों में औसत, व्यक्तिगत और सरकारी बचत 13.6% थी।¹ वस्तुतः, चतुर्थ योजना में राष्ट्रीय बचत जुटाने के कार्य को उत्तेजनीय सफलता मिली। चतुर्थ योजना के दौरान राष्ट्रीय बचत में 1,385 करोड़ रुपये जुटाए गए जबकि लक्ष्य केवल 1,000 करोड़ रुपये के एकत्रित करने का था। राष्ट्रीय बचत की दिशा में यह बात अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि कुल बचत में व्यक्तिगत बचत का योग, जो 1972-73 में 49% था, 1973-74 में 56% और 1974-75 में 62% हो गया।²

देश में आपात-स्थिति और समाज के कमजोर वर्गों की स्थिति सुधारने के लिए आर्थिक विकास के 20 सूत्री कार्यक्रम की धोरणा के बाद एक नया वातावरण बना है, जो अल्प बचत द्वारा देश के आन्तरिक साधन जुटाने हेतु अत्यन्त अनुकूल है। अल्प बचत करने वालों के लिए योजनाएँ

भारत सरकार ने अल्प बचत योजनाएँ प्रमुख रूप से अल्प बचत करने वाले लोगों—जैसे छोटे किसानों, कारखाना मजदूरों, सामान्य परिवारों की गृहस्थियों और ऐसे ही अन्य लोगों के लिए बनाई है। राष्ट्रीय बचत संगठन, जो विभिन्न बचत योजनाओं का संचालन करता है, आम आदमी को बचत का सचय करता है और

1. योजना 7 व 22 विप्लव 1975, पृष्ठ 26

2. भारत सरकार. राष्ट्रीय बचत, नवम्बर 1975

उन्हें 1,16,800 डाकघरों के माध्यम से, जिनमें 90% देहाती क्षेत्रों में है, इकट्ठा करता है।

ये बचत योजनाएँ समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों की आवश्यकताएँ पूरी करती हैं। इनमें सर्वप्रथम डाकघर बचत योजना है, जो सन् 1834 में सरकारी बचत बैंक के रूप में शुरू हुई थी। इन वर्षों के दौरान बचत बैंक की जमा में निरन्तर वृद्धि होती है और इस समय बचत बैंक में जमा-राशि 1,274 करोड़ रु है तथापि वास्तव में वह जनता का बैंक है, क्योंकि यहाँ 5 रु की अल्प-राशि से बैंक खाता खोला जा सकता है और बाद में 1 रु तक की राशि नकद जमा कराई जा सकती है।

परम्परा से ही डाकघर-बचत बैंक का व्याज प्रायः कर से मुक्त है। कर-दाताओं को अल्प बचत में धन लगाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देने के लिए अधिक व्याज देने वाली (10.25% प्रति वर्ष) कर-योग्य सिक्युरिटीयें हैं। इन सभी बचत योजनाओं पर वाणिज्य बैंकों द्वारा दी जाने वाली दरों पर व्याज दिया जाता है। लेकिन इन पर कुछ अतिरिक्त रियायतें दी जाती हैं। जैसे—कर-मुक्त व्याज, आर्थिक कर से मुक्ति, आय कर से मुक्ति और सामाजिक सुरक्षा।

इस समय डाकघर बचत बैंक के अतिरिक्त अल्प बचत करने वालों के लिए दस और योजनाएँ हैं। इनमें से उन लोगों के लिए है जो एक साथ राशि जमा करना चाहते हैं, और 1, 2, 3, 4, 5 और 7 वर्ष बाद उसकी वापसी चाहते हैं। दो योजनाएँ मासिक बचत करने वालों के लिए हैं, जो प्रत्येक महीने नियत राशि जमा कराते हैं और निश्चित अवधि के पश्चात् आकर्षक व्याज राशि वापस पाते हैं। इसके अतिरिक्त एक लोक प्रविष्य निधि योजना भी है। यह योजना स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के माध्यम से चलाई जाती है। यह योजना अपना स्वतन्त्र कारोबार करने वाले लोगों, जैसे—ड्राफ्टरों, वकीलों और छोटे व्यापारियों के लिए है। 1975 के अन्त से बापिकी बचत पत्रों की एक अन्य योजना शुरू की गई है। यह योजना उन लोगों के लिए है, जो इस समय एकमुश्त राशि जमा कराना चाहते हैं और कुछ वर्षों के पश्चात् मासिक भुगतान चाहते हैं।

बचत वृद्धि

योजना आयोग ने यह अनुभव करके कि, अल्प बचत द्वारा काफी साधन जुटाए जा सकते हैं, प्रथम योजना में अल्प बचत के लिए 255 करोड़ रु का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अल्प बचत संचित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए—जैसे नए बचत-पत्रों की विक्री, राज्यवार लक्ष्य निर्धारित करना, एजेन्सी सिस्टम की पुनः शुरूआत आदि। प्रथम योजनावधि में कुल मिलाकर 242 करोड़ रु अल्प बचत में एकत्र किए गए, जबकि लक्ष्य 225 करोड़ रु का था। यह राशि अल्प बचत में प्रथम योजनावधि में जमा कुल राशि में से इसी अवधि में निकाली गई राशि घटाकर

निकलती है। द्वितीय योजना में अल्प बचत में 400 करोड़ रु., तृतीय योजना में 575 करोड़ रु. और चतुर्थ योजना में 1385 करोड़ रु. एकत्र किए गए, जबकि द्वितीय योजना में 500 करोड़ रु. तृतीय में 600 करोड़ रु. और चतुर्थ योजना में 1,000 करोड़ रु. एकत्र करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

अल्प बचत में 31 मार्च, 1975 को कुल मिलाकर लगभग 3,600 करोड़ रु. जमा थे। यह राशि वर्तमान सरकारी (भारत सरकार के) बाजार ऋण में, 6,435 करोड़ रु. के आधे से अधिक है और भारत सरकार के भविष्य निधि खाते में जमा 1,291 करोड़ रु. की लगभग तीन गुनी है।

कुछ नई योजनाएँ

अल्प बचत आन्दोलन की एक सामाजिक-आर्थिक विचारधारा है। इस आन्दोलन ने सर्वथा जनता का समर्थन पाने पर जोर दिया गया है और इसके लिए जनता को हमेशा यह समझाने का प्रयत्न किया गया है कि निजी और राष्ट्रीय दोनों दृष्टिकोण से बचत से क्या लाभ है, इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बचत संगठन ने अनेक नई योजनाएँ आरम्भ की हैं और अल्प बचत में पूर्ण लगे हुए लोगों को प्रतिरिक्त प्रोत्साहन दिया है। प्रमुख योजनाओं के नाम निम्नलिखित हैं—वेतन द्वारा बचत योजना, महिला प्रधान बचत योजना, सचयिका, ग्रामीण डाकघरों के ब्रांच पोस्टमास्टर एंव यूनिट ट्रस्ट। राष्ट्रीय बचत योजनाओं को अधिक आकर्षक बनाने और सामाजिक सुरक्षा के साथ सम्बद्ध करने हेतु दो नई योजनाएँ शुरू की गई हैं। प्रथम, सरक्षित बचत-योजना इसके अधीन पाँच वर्षीय आयु की जमा खाते में जमा की गई 20 रुपये प्रति महीने तक की राशि सरक्षित है। यदि इस खाते में पैसा जमा करने वाला व्यक्ति दो वर्ष तक बिना पैसा निकाले अपनी जमा देता रहता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को तुरन्त ही खाते का कुल परिपक्व मूल्य दे दिया जाएगा। दूसरी योजना उन खातेदारों के लिए है, जो अपने बचत-बैंक खाते में कम से कम छ महीने तक 200 रुपये लगातार जमा रखते हैं। यह ड्रा योजना है।

राज्य सरकारों के सहयोग से किसानों से सम्पर्क स्थापित करने हेतु विशेष अभियान चलाए गए हैं। किसानों के पास फसल के दौरान अतिरिक्त पैसा होता है और अभियान द्वारा उन्हें अपना यह पैसा आकर्षक अल्प बचत योजनाओं में लगाने के लिए तैयार करने का प्रयत्न किया जाता है। गन्ना, कपास आदि का विक्रय करने वाली सरकारी समितियों के साथ यह व्यवस्था की गई है कि वे किसानों को दी जाने वाली राशि में से अल्प बचत के लिए उनके हिस्से की राशि काट लें। राष्ट्रीय बचत संगठन इस बात का भी प्रयत्न करता है कि कारखाना मजदूर अपने बोनस की राशि अथवा बकाया वेतन की राशि का कुछ हिस्सा अल्प बचत में लगाएँ।

अल्प बचत योजनाओं के अधीन जमा की गई राशि का अधिकांश हिस्सा राज्य सरकारों को विकास योजनाओं को लागू करने के लिए दीर्घावधि ऋण के रूप

में दिया जाता है। राज्यों को अल्प बचत में अधिक धन जुटाने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं।

पाँचवी योजना के दौरान राष्ट्रीय बचत संगठन, बचत करने वाले व्यक्तियों की संख्या, जनसंख्या के 7% से बढ़ाकर 15% करने का प्रयत्न करेगा। साथ ही वेतन से बचत करने वाले समूहों की संख्या भी रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के 20% से बढ़ाकर 40% करने का प्रयत्न किया जाएगा। महिला बचत योजना कार्यक्रमों की संख्या 4 हजार से बढ़ाकर 10,000 कर दी जाएगी। साथ ही, देश के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन करने वाले एक तिहाई छात्रों को सचयिका बचत बैंक योजना के अधीन ले लिया जाएगा।

बचत आन्दोलन की सफलता जनता के समर्थन पर निर्भर करती है। पिछले कार्य को देखते हुए उपर्युक्त भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना और पाँचवी योजना के लिए निश्चित 1,850 करोड़ रु. जुटाना पूर्वरूप से सम्भव प्रतीत होता है।

उपभोग-वस्तुओं और मध्यवर्ती- वस्तुओं के लिए माँग के अनुमान, आदा-प्रदा गुणांकों का उपयोग

*Demand Projections for Consumption Goods and Inter-
mediate Goods, the Use of Input-Output Co-efficients*

किसी भी देश की आर्थिक विकास योजना के लिए उस देश के साधनो तथा उपभोक्ता-वस्तुओं की वर्तमान तथा भावी स्थिति की जानकारी आवश्यक है। इसीलिए योजना-निर्माण से पूर्व साधनो तथा उपभोक्ता-वस्तुओं की माँग की समझना की जाती है। उपभोक्ता वस्तुओं की माँग को 'अन्तिम माँग' (Final Demand) तथा साधनो की माँग को 'व्युत्पन्न-माँग' (Derived Demand) कहा जाता है। जो वस्तुएँ अन्य वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त होती हैं उनको मध्यवर्ती वस्तुएँ (Intermediate Goods) तथा जिनका अन्तिम प्रयोग (Final use) उत्पादन के लिए न होकर उपभोग के रूप में होता है, उनको उपभोक्ता वस्तुएँ (Consumer Goods) कहा जाता है।

मध्यवर्ती वस्तुओं से सम्बन्धित मध्यवर्ती माँग को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—(1) प्रारम्भिक आदान (Primary input) अथवा श्रम की माँग तथा (2) अन्तिम उत्पादन में प्रयुक्त वस्तुओं की माँग। उपभोक्ता-वस्तुओं की माँग का अनुमान घाय लोच के आधार पर लगाया जाता है तथा श्रम की माँग व मध्यवर्ती वस्तुओं की माँग की समझना आदा-प्रदा तकनीकी (Input-Output Technique) द्वारा की जाती है।

घाय-लोच द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं की माँग के अनुमान (Demand Projections of Consumer Goods)

घाय लोच की सहायता से कुछ माँग के अनुमान अप्रतिष्ठित से प्रकार लगाए जाते हैं—

मान लीजिए भोजन और वस्त्र की घाय लोच क्रमशः 6 व 1.5 दी हुई है। यदि प्रति व्यक्ति घाय में वृद्धि-दर 10% हो तो, घाय-लोच के आधार पर भोजन की माँग में $6 \times 10 = 6\%$ तथा वस्त्र की माँग में, $1.5 \times 10 = 15\%$ वृद्धि होगी।

इस प्रकार, प्रति व्यक्ति आय-वृद्धि तथा आय-लोच दी हुई हो तो, प्रत्येक वस्तु की माँग को माँगा जा सकता है तथा सब वस्तुओं के माँग के योग द्वारा कुल माँग की सगणना की जा सकती है।

ग्रॉथर लेविस ने एक दस वर्षीय कल्पित आर्थिक योजना का उदाहरण लेते हुए माँग के अनुमानों की समष्टि सगणना (Macro Exercise) प्रस्तुत की है। इन्होंने माँग के अनुमानों के लिए मुख्यतः तीन तत्वों का उल्लेख किया है— (1) जनसंख्या, (2) उपभोग व्यय में प्रति व्यक्ति वृद्धि का तत्त्व तथा (3) उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन का तत्त्व। इनके अनुसार सर्वप्रथम माँग के अनुमानों के लिए प्रारम्भिक वर्ष (Year 0) के उपभोग की जनसंख्या वाले वृद्धि तत्त्व से गुणा करना चाहिए और इसके पश्चात् गुणनफल को प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि वाले तत्त्व से और अन्त में उपभोक्ता की रुचि में होने वाले परिवर्तन सम्बन्धी तत्त्व से गुणा करना चाहिए। इसे निम्नलिखित सारणी द्वारा स्पष्ट किया गया है¹—

	Year 0	आय-लोच	Year 10
खाद्य वस्तुएँ	200	·5	266
पशुओं से प्राप्त वस्तुएँ	100	1.2	144
स्थानीय निम्न वस्तुएँ	30	1.1	43
निर्माण प्रक्रिया के अन्तर्गत वस्तुएँ	70	1.2	101
अन्य निमित्त वस्तुएँ	48	1.5	71

(a) जनसंख्या वृद्धि-दर 2.3% प्रति वर्ष है। इसीलिए पूरे 10 वर्ष के लिए जनसंख्या तत्त्व 1.256 है।

इसे निम्न सूत्र द्वारा निकाला गया है—

$$P_{10} = P_0(1+r)^{10} \text{ अथवा } P_{10} = P_0(1+0.023)^{10}$$

$$P_{10} = P_0 \times 1.256$$

(b) उपभोग-व्यय में प्रति व्यक्ति वृद्धि 11.9% होती है। इस तत्त्व में प्रत्येक वस्तु की आय-लोच का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(c) रुचि में परिवर्तन तीसरा गुणक तत्त्व है जो जनसंख्या वृद्धि अथवा माँग प्रवृत्ति से प्रभावित नहीं होता। केवल रुचि में परिवर्तन के कारण नई वस्तुएँ, पुरानी वस्तुओं का स्थान लेने लगती हैं।

उक्त तीनों गुणक तत्वों का प्रयोग करते हुए 10वें वर्ष में खाद्य-सामग्रियों की माँग होगी, जबकि प्रारम्भिक माँग 200 है—

$$(200)(1.256)(1.0+119 \times .5) = 266$$

इसी प्रकार उक्त सारणी में प्रदर्शित अन्य वस्तुओं की माँग को निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है—

पशुओं द्वारा प्राप्त वस्तुओं की माँग—

$$(100)(1.256)(1.0+119 \times 1.2) = 144$$

स्थानीय निमित्त वस्तुओं की माँग—

$$(30) (1\ 256) (1\ 0 + 119 \times 1.1) = 43$$

निर्माण प्रक्रिया के अन्तर्गत वस्तुओं की माँग—

$$(70) (1\ 256) (1\ 0 + 119 \times 1.2) = 101$$

अन्य निमित्त वस्तुओं की माँग—

$$(48) (1\ 256) (1\ 0 + 119 \times 1.5) = 71$$

मध्यवर्ती वस्तुओं (Intermediate Goods) तथा श्रम की माँग व कुल उत्पादन की समष्टि व आदा-प्रदा तकनीकी के आधार पर की जाती है।

आदा-प्रदा तकनीकी

(Input-Output Technique)

आदा प्रदा तकनीकी उत्पादन का एक रेखीय स्थायी गुणांक मॉडल (A Linear Fixed Coefficient Model) है। इस मॉडल के प्रवर्तक प्रो. लियनटिफ थे।

इस्पात उद्योग का उत्पादन अनेक उद्योगों में आदा (Input) के रूप में प्रयुक्त होता है। इसलिए उत्पादन का सही स्तर तभी मालूम हो सकेगा, जबकि सभी n उद्योगों के लिए आवश्यक आदा (Inputs) की आवश्यक मात्राएँ ज्ञात हों। अनेक अन्य औद्योगिक उत्पादन भी स्वयं इस्पात उद्योग के लिए आदा के रूप में प्रयुक्त होगा। परिणामतः अन्य वस्तु के उत्पादन के उचित स्तर आंशिक रूप से इस्पात उद्योग की आदा सम्बन्धी आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा। अन्य उद्योग निर्भरता की दृष्टि से n उद्योगों के उत्पादन का उचित स्तर वह होता है जो ग्रन्थ व्यवस्था की समस्त आदा आवश्यकताओं (Input Requirements) के अनुकूल (Consistent) हो।

अतः स्पष्ट है कि उत्पादन नियोजन में आदा प्रदा विश्लेषण का प्रमुख स्थान है। किसी भी देश के आर्थिक विकास की योजना अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के कार्यक्रमों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है।

यदि विशिष्ट रूप से देखा जाए तो इस पद्धति को सामान्य सन्तुलन विश्लेषण का प्रकार नहीं कहा जा सकता। यद्यपि इस मॉडल में विभिन्न उद्योगों की पारस्परिक अन्तर्निर्भरता पर बल दिया जाता है तथापि तकनीकी माप में उत्पादन के सही स्तर वे होने हैं जो वाजार सन्तुलन की शर्तों को पूरा करने की अपेक्षा तकनीकी आदा-प्रदा सम्बन्धों को सन्तुष्ट करते हैं।

आदा-प्रदा मॉडल का ढाँचा¹

इस प्रणाली में सम्पूर्ण ग्रन्थव्यवस्था में n उद्योगों की कल्पना की जाती है। प्रत्येक उत्पादक इकाई एक ही वस्तु का उत्पादन करती है। उस वस्तु के उत्पादक की j^{th} इकाई के लिए आदा की एक निश्चित मात्रा प्रयोग में आती है, जिसे ' a_{ij} ' द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। चूँकि मॉडल एक रेखीय है इसलिए j^{th} उत्पादन की x_j मात्रा के लिए i^{th} आदा की $a_{ij} x_j$ मात्रा आवश्यक होगी।

इस मॉडल में उत्पादन के स्थिर गुणांक होते हैं इसलिए आदाओं के मध्य कोई प्रतिस्थापन नहीं होता अतः x_j उत्पादन के लिए सदैव $a_{ij} x_j$ मात्रा i^{th} आदा की मात्रा आवश्यक होगी तथा k^{th} आदा की $a_{kj} x_j$ मात्रा आवश्यक होगी। इस प्रकार के मॉडल को ही आदा-प्रदा मॉडल कहते हैं। a_{ij} को आदा-गुणांक (Input Coefficient) कहते हैं तथा $[a_{ij}]$ मैट्रिक्स (Matrix) को आदा-मैट्रिक्स कहते हैं। आदा-प्रदा के निम्नलिखित दो मॉडल होते हैं—

(1) बन्द मॉडल (Closed Model)

(2) खुला मॉडल (Open Model)

यदि आदा-प्रदा के मॉडल में आदा वस्तुओं का समूह पूर्ण प्रणाली में केवल एक बार ही प्रकट होता है तथा जिसे अन्य ऐसी वस्तुओं के समूह से जाना जाता है, जो अन्तिम उत्पादन के रूप में भी एक ही बार प्रकट होते हैं और वर्तमान उत्पादन के अतिरिक्त आदाओं का कोई अन्य स्रोत नहीं होता और अन्तिम उत्पादन का भी आदाओं के अतिरिक्त कोई अन्य उपयोग नहीं होता, तो इन विशेषताओं वाले मॉडल को बन्द मॉडल (Closed Model) कहते हैं।

खुला मॉडल (Open Model) सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था का मॉडल होता है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं—

(i) n वस्तुओं का उत्पादन-क्षेत्र जहाँ एक ओर अन्तिम वस्तुओं के उत्पादन को प्रकट करता है, साथ ही उत्पादन-क्षेत्र के लिए आवश्यक आदाओं का भी प्रतीक होता है (Production Sector of n output which are also inputs within the Sector)।

(ii) एक ऐसा अतिरिक्त आदा जो किसी भी उत्पादन-क्रिया जिसका उत्पादन क्षेत्र से सम्बन्ध होता है, प्रयोग में नहीं लिया जाता।

(iii) अन्तिम वस्तुओं की माँग आदाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् भी बनी रहती है।

उत्पादन-क्षेत्र $n \times n$ आदा-मैट्रिक्स का होता है। मैट्रिक्स की यह प्रणाली अर्द्ध-धनात्मक (Semi-positive) होती है तथा जिसका विघटन (Decomposition) सम्भव नहीं माना जाता है। ऐसी मैट्रिक्स के लिए A का प्रयोग किया जाएगा। X को भौतिक उत्पादन का वेक्टर (Vector) मानने पर AX आदा की आवश्यकताओं का वेक्टर (Vector) होगा तथा $X - AX = (I - A)X$ शुद्ध उत्पादन का वेक्टर कहलाएगा अर्थात् यह वेक्टर वस्तुओं की उन मात्राओं को प्रकट करेगा जो उत्पादन-क्षेत्र के बाहर विक्रय हेतु उपलब्ध होती हैं। यह वेक्टर Value added की मात्रा को प्रकट करता है।

मान्यताएँ (Assumptions)

इस मॉडल की निम्नलिखित प्रमुख मान्यताएँ हैं—

(1) प्रत्येक उद्योग एक समरूप (Homogeneous) वस्तु का उत्पादन करता है।

- (2) आदा अनुपात (Input Ratio) स्थिर रहना है।
- (3) पैमाने के स्थिर प्रतिफल क्रियाशील रहते हैं।
- (4) यह उत्पादन-फलन एकरेखीय (Linear) है।
- (5) उत्पादित वस्तुओं का संयोग स्थिर (Fixed Product Mix) रहता है।

तत्त्व की आदा (Inputs) एक निश्चित अनुपात में प्रयुक्त होते हैं, यह निम्नलिखित समीकरण द्वारा स्पष्ट होता है—

$$\frac{a_{ij}}{a_{ki}} = \frac{X_{ij}}{X_{ki}}$$

उक्त समीकरण में आदा-प्रदा अनुपातों को रखने से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होता है—

$$X_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} X_j + F_i \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

जो एकरेखीय समीकरणों के मांडल को प्रकट करता है जिसमें स्थिर गुणांक होते हैं तथा जो n उत्पादन प्रभावों के साथ एक दूसरे से सम्बन्धित होते हैं एवं अन्तिम मांग से भी सम्बन्धित होते हैं (F_1, \dots, F_n)।

एक n उद्योग वाली अर्थव्यवस्था के लिए आदा गुणांकों को A मैट्रिक्स के रूप में $A = [a_{ij}]$ निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है—

Output (अन्तिम उत्पादन)

आदा (input)		Output (अन्तिम उत्पादन)				
		I	II	III	...	N
	I	a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{1n}
	II	a_{21}	a_{22}	a_{23}	a_{2n}
	III	a_{31}	a_{32}	a_{33}	a_{3n}

	N	a_{n1}	a_{n2}	a_{n3}	a_{nn}

यदि कोई उद्योग अपने द्वारा उत्पादित वस्तु को आदा के रूप में प्रयुक्त नहीं करता है, तो मैट्रिक्स के मुख्य करण (Diagonal) पर आने वाले सभी तत्त्व (Elements) शून्य होते हैं।

आदा-प्रदा गुणांकों के उपयोग

(Uses of Input-Output Coefficient)

इन गुणांकों की सहायता से, यदि अन्तिम मांग का वेक्टर (Vector) दिया हुआ हो तो प्रत्येक क्षेत्र का कुल उत्पादन और कुल मूल्य-वृद्धि ज्ञात की जा सकती है। कुल उत्पादन की गणना (Calculation of Gross Output)

आदा-प्रदा तकनीकी के आधार पर कुल उत्पादन की गणना को निम्न प्रकार उदाहरण द्वारा समझाया गया है—दो उत्पादन क्षेत्र दिए हुए हैं—

$$A = \begin{bmatrix} .2 & .4 \\ .1 & .5 \end{bmatrix}$$

दिया हुआ माँग वेक्टर $D = \begin{bmatrix} 60 \\ 40 \end{bmatrix}$ है। उक्त सूचनाओं से कुल उत्पादन निम्न प्रकार मैट्रिक्स इनवर्स (Inverse) करके ज्ञात किया गया है—

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} (I - A) = \begin{bmatrix} 8 & -4 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$$

Co factor Matrix

$$\begin{aligned} & 8(5) - (-4)(-1) \\ & -(-1)(-4) + 5(8) \\ & \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Adj A = Transpose of Co Factor Matrix—

$$\text{Adj } A = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 8 \end{bmatrix}$$

Inverse of Matrix

$$\frac{\text{Adj}}{D} = \frac{1}{36} \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\text{अथवा } \begin{bmatrix} \frac{50}{36} & \frac{40}{36} \\ \frac{10}{36} & \frac{80}{36} \end{bmatrix}$$

$$\therefore \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{50}{36} & \frac{40}{36} \\ \frac{10}{36} & \frac{80}{36} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 60 \\ 40 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{50 \times 60}{36} & \frac{40 \times 40}{36} \\ \frac{10 \times 60}{36} & \frac{80 \times 40}{36} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{250}{3} & \frac{400}{9} \\ \frac{50}{3} & \frac{800}{9} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1150}{9} \\ \frac{950}{9} \end{bmatrix}$$

इस प्रकार X_1 का कुल उत्पादन $= \frac{1150}{9}$ तथा X_2 का कुल उत्पादन

$\frac{950}{9}$ होगा X_1 कृषि क्षेत्र का उत्पादन प्रकट करता है तथा X_2 गैर कृषि-क्षेत्र का उत्पादन प्रकट करता है।

मध्यवर्ती वस्तुओं की सगणना

(Calculation of Intermediate Goods)

मध्यवर्ती वस्तुओं की सगणना निम्न प्रकार की जाती है—

$$\begin{bmatrix} a_{11} & X_1 \\ a_{21} & X_2 \end{bmatrix} = \text{क्षेत्र I की मध्यवर्ती वस्तुएँ।}$$

$$\begin{bmatrix} a_{12} & X_2 \\ a_{22} & X_2 \end{bmatrix} = \text{क्षेत्र II की मध्यवर्ती वस्तुएँ।}$$

$$\text{अथवा } 2 \times \frac{1150}{9} = \frac{2300}{9}$$

$$1 \times \frac{1150}{9} = \frac{1150}{9}$$

$$\frac{2300}{9} + \frac{1150}{9} = \frac{3450}{9}$$

= क्षेत्र I की मध्यवर्ती वस्तुओं का कुल मूल्य

$$4 \times \frac{950}{9} = \frac{3800}{9}$$

$$5 \times \frac{950}{9} = \frac{4750}{9}$$

$$\frac{3800}{9} + \frac{4750}{9} = \frac{8550}{9}$$

= क्षेत्र II की मध्यवर्ती वस्तुओं का कुल मूल्य ।

मध्यवर्ती वस्तुओं की सगणना करने के पश्चात् अर्थ-व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र की शुद्ध मूल्य वृद्धि (Value added) ज्ञात की जा सकती है। इस वृद्धि को ज्ञात करने के लिए कृषि क्षेत्र कुल उत्पादन में से मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य घटा दिया जाता है। उपरोक्त उदाहरण के क्षेत्र I व II की मूल्य-वृद्धि निम्नलिखित प्रकार निकाली जा सकती है—

$$\therefore \text{क्षेत्र I का कुल उत्पादन} = \frac{1150}{9}$$

$$\therefore \text{I की मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य} = \frac{3450}{9}$$

$$\therefore \text{क्षेत्र I की शुद्ध मूल्य वृद्धि} = \frac{1150}{9} - \frac{3450}{9} = \frac{805}{9}$$

$$\text{इसी प्रकार क्षेत्र II की शुद्ध मूल्य वृद्धि} = \frac{950}{9} - \frac{8550}{9} = \frac{95}{9}$$

ज्ञात की जा सकती है।

प्राथमिक आदा (Primary Input) या धर्म की मात्रा ज्ञात करना खुले मॉडल वाले क्षेत्र में आदा गुणों के प्रत्येक खाने में तत्वों (Elements) का योग एक से लागत (Partial Input Cost) प्रदर्शित करता है, जिसमें प्राथमिक आदा (Primary Input) का मूल्य शामिल नहीं होता। अतः यदि योग एक से अधिक या एक के बराबर होना है, तो आर्थिक दृष्टि से उत्पादन लाभदायक नहीं माना जाता है। इस तथ्य को निम्न प्रकार प्रकट किया जा सकता है—

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} < 1 \quad (j=1, 2, \dots, \dots, n)$$

चूँकि आदा की एक रुपये लागत उत्पादन के समस्त साधनों के भुगान करने में समाप्त हो जानी चाहिए, इसलिए कालम का योग एक रुपये से जितना कम होता है, वह प्राथमिक आदा के मूल्य को प्रकट करता है। 1^{th} वस्तु की एक इकाई के उत्पादन में लगने वाला प्राथमिक आदा का मूल्य निम्न प्रकार प्रकट किया जा सकता है—

$$1 - \sum_{i=1}^n a_{ij}$$

निम्नलिखित उदाहरण द्वारा इसे ज्ञात किया जा सकता है—

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 4 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}^4$$

इस मैट्रिक्स से उक्त विधि के द्वारा प्रत्येक क्षेत्र का कुल उत्पादन ज्ञात किया जा सकता है, जो निम्नलिखित है, X_1 अथवा क्षेत्र I का कुल उत्पादन = 24 84, X_2 अथवा क्षेत्र II का कुल उत्पादन = 20 68 तथा क्षेत्र III का कुल उत्पादन = 18 36 होगा। इसके पश्चात् मैट्रिक्स के कॉलमों का योग किया जाता है तथा योग को एक में से घटाकर प्राथमिक आदा का गुणांक ज्ञात कर लिया जाता है। इस गुणांक से क्षेत्रीय उत्पादन को जब गुणा किया जाता है तो प्राथमिक आदा का मूल्य ज्ञात हो जाता है। उक्त मैट्रिक्स के अनुसार प्राथमिक आदा के गुणांक होंगे—

$$1 - \sum_{i=1}^n a_{ij} = 3 \quad 3 \quad 4$$

[प्रथम कॉलम का योग $2 + 4 + 1 = 7$ जिसे एक में से घटाने पर 3 शेष रहता है। इसी प्रकार, कॉलम दो व कॉलम तीन के अंक 3 व 4 निकाले गए हैं।]

क्षेत्र I = $3 \times 24\ 84 = 7\ 452$ का प्राथमिक आदा मूल्य,

क्षेत्र II = $3 \times 20\ 68 = 6\ 204$ का प्राथमिक आदा मूल्य,

क्षेत्र III = $4 \times 18\ 36 = 7\ 344$ का प्राथमिक आदा मूल्य,

कुल प्राथमिक आदा मूल्य = $7\ 452 + 6\ 204 + 7\ 344 = 21\ 000$ होगा।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उत्पादन योजना में इस मॉडल का बहुत महत्व है। इसकी सहायता से अर्थ व्यवस्था के प्रत्येक उत्पादन-क्षेत्र का कुल उत्पादन कुल मूल्य-वृद्धि व प्राथमिक आदा का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य भी ज्ञात किए जा सकते हैं।

अर्द्ध-विकसित देशों में विकासाथं नियोजन की सफलता के लिए कुछ पूर्व आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। इसमें एक महत्वपूर्ण शतं विश्वसनीय और पर्याप्त प्रांकड़ों के आधार पर उचित उत्पादन-लक्ष्यों का निर्धारण है। लक्ष्य निर्धारित करने का कार्य बहुत कुछ देश की आधारभूत नीतियों पर आधारित होता है। सर्वप्रथम, नियोजन-सम्बन्धी व्यापक नीतियाँ निर्धारित कर ली जाती हैं। इन व्यापक नीतियों के अनुरूप नियोजन के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। ये उद्देश्य, देश विशेष की परिस्थितियों, आवश्यकताओं, विचारधाराओं, साधनों आदि को दृष्टि में रखते हुए सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संरचना के सम्दर्भ में निश्चित किए जाते हैं। विकास योजना के लिए निर्धारित इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाता है और विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादन-लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

लक्ष्य-निर्धारण का महत्त्व—आर्थिक नियोजन का लक्ष्य दी हुई अवधि में देश के साधनों का अनुकूलतम उपयोग करके अधिकाधिक उत्पादन वृद्धि करना और देशवासियों के जीवन-स्तर को उच्च बनाना है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में सर्वतोमुखी विकास की आवश्यकता होती है किन्तु किसी भी देश के साधन, विशेष रूप से अर्द्ध-विकसित देशों के, सीमित होते हैं। अतः इन साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। इनके अभाव में अधिकतम उत्पादन और अधिकतम सामाजिक लाभ सम्भव न होगा। वस्तुतः, साधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही 'आर्थिक नियोजन' कहते हैं। अतः यह आवश्यक है कि उन कार्यक्रमों को पहले पूरा किया जाए जो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं या जो अन्य प्रकार से आवश्यक हैं या जिनसे आगे द्रुत आर्थिक विकास करने में बहुत योगदान मिल सकता है। इसीलिए, आर्थिक नियोजन में पहले प्राथमिकताओं (Priorities) का निर्धारण कर लिया जाता है तत्पश्चात् इन प्राथमिकताओं के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन लक्ष्य (Targets of Output) निर्धारित किए जाते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने पर ही

उन लक्ष्यो की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। यही कारण है कि योजनाओं में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन—लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैं। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ही, नियोजन में प्रयत्न किए जाते हैं और नियोजन की सफलता भी इन लक्ष्यो की पूर्ति से ही माँकी जाती है। नियोजन के लक्ष्य व्यापक और विषयगत होते हैं। इन लक्ष्यो की पूर्ति के आधार पर नियोजन की सफलता का मूल्यांकन भी पूर्ण नहीं हो सकता। किन्तु नियोजन के लक्ष्य भौतिक रूप में निर्धारित किए जाते हैं जिनके पूर्ण होने या न होने का अपेक्षाकृत सही मूल्यांकन किया जा सकता है।

लक्ष्य-निर्धारण की विधि—अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए लक्ष्य-निर्धारण का कार्य विभिन्न मन्त्रालयों और समूहों से लिए गए विशेषज्ञों के कार्यशील समूहों (*Working Groups*) द्वारा किया जाता है। लक्ष्य-निर्धारण समग्र नियोजन के व्यापक उद्देश्यों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। इन लक्ष्यो की पूर्ति के लिए आवश्यक साधनों की उपलब्धि को भी ध्यान में रखा जाता है। लक्ष्यो के निर्धारण में इन कार्यशील दलों को योजना आयोग के द्वारा समय-समय पर पथ प्रदर्शन और निर्देशन भी मिलता रहता है। लक्ष्य-निर्धारण में संगठित जनमत (*Organised Public Opinion*) पर भी ध्यान दिया जाता है और उसे भी इसमें भागीदार और उत्तरदायी बनाया जाता है। निर्धारित लक्ष्यो पर आधारित योजना को, असंगति (*Inconsistency*) से बचाने के लिए योजना आयोग, विभिन्न प्रकार से जाँच करता है। इसके पश्चात् ही योजना को अपनाया जाता है। असंगति होने पर अर्थव्यवस्थाओं में अन्तःक्षेत्रीय असन्तुलन (*Inter-Sectoral Imbalances*) उत्पन्न हो सकते हैं। उत्पादन के ये लक्ष्य सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र, प्रत्येक उद्योग, प्रत्येक परियोजना एवं उत्पादन इकाई के लिए निश्चित किए जा सकते हैं।

विभिन्न विश्लेषणों पर आधारित—लक्ष्य-निर्धारण में मात्रात्मक दृष्टिकोण से विभिन्न लक्ष्य सम्मिलित होते हैं उदाहरणार्थ, इतने अधिक मिलियन टन खाद्यान्न, इस्पात, उर्वरक, ईंधन, सीमेंट आदि का उत्पादन अमुक मात्रा में किलोवाट बिजली की नवीन क्षमता का सृजन, इतनी अधिक मील लम्बी रेलवे लाइनों और सड़कों का निर्माण, इतनी अधिक प्रशिक्षण और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, राष्ट्रीय आय में अमुक मात्रा में वृद्धि आदि। ओ के घोष के अनुसार—“इस प्रकार के लक्ष्य न केवल सरकारी उपक्रमों के लिए ही निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है, बल्कि कम से कम बड़ी निजी फर्मों के लिए भी निर्धारित किए जाने चाहिए, ताकि कम पूर्ति वाले पदार्थों वॉंछित उद्देश्यों के लिए हो उपयोग में लाए जा सकें।”¹

डब्ल्यू ए. लेविस के अनुसार, निजी-क्षेत्र के लिए लक्ष्य-निर्धारण में “बाजार और मूल्यों का उन्ही हिसाब और सांख्यिकीय तकनीकों से विश्लेषण किया जाना चाहिए, जिनको इस उद्देश्य से निजी फर्में अपनाती हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ

कही अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से लाभ या हानि, निजी फर्मों की अपेक्षा अधिक या कम होने की सम्भावना हो, वहाँ आवश्यक समायोजन किया जाना चाहिए।" प्रत्येक उद्योग के सम्बन्ध में अलग-अलग ऐसा किया जाना चाहिए और जाँच की जानी चाहिए कि प्रत्येक उद्योग के लिए लगाए गए अनुमान परस्पर और समग्र अर्थव्यवस्था के लिए लगाए अनुमान से सगत तो है। प्रत्येक उद्योग अन्य घरेलू उद्योगों से कुछ क्रय करता है। वह कुछ आपातित वस्तुएँ भी क्रय करता है। यह अन्य उद्योगों को अपनी वस्तुएँ बेचता भी है। इसके उत्पादन (Products) उपभोक्ताओं को बेचे भी जाते हैं और कुछ का निर्यात भी किया जा सकता है। यह उद्योग बचत भी करता है, कर भी चुकाता है और विनियोग भी करता है। प्रत्येक उद्योग के लिए निर्धारित उत्पत्ति का योग कुल निर्धारित उत्पत्ति के बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार की स्थिति प्रत्येक उद्योग के विनियोग, इसके उत्पादन का उपभोग, निर्यात और इसी प्रकार कई घातों के लिए होना चाहिए। गार्थर लेविस के अनुसार, "लक्ष्यों की सगति की जाँच का एकमात्र तरीका प्रत्येक उद्योग के लिए और सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए 'Set of Inter-locking tables' का निर्माण करना है। इसके लिए राष्ट्रीय आय और आदा-प्रदा (Input-Output) विधियों को काम में लाया जाता है।"

लक्ष्य निर्धारण में ध्यान देने योग्य बातें—योजना के विभिन्न लक्ष्य इस प्रकार से नियंत्रित किए जाने चाहिए ताकि राष्ट्र के लिए उपलब्ध सभी साधनों का सर्वोत्तम उपयोग सम्भव हो सके। योजना के लिए ये लक्ष्य निश्चित व्यापक उद्देश्यों और प्राथमिकताओं के अनुसार निर्धारित किए जाने चाहिए। वे परस्पर सम्बन्धित और सन्तुलित होने चाहिए। विभिन्न अनुपातों की गणना की जानी चाहिए एवं इन अनुपातों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विभिन्न शाखाओं में बनाए रहना चाहिए। इन्हें 'समष्टि आर्थिक (Macro-Economic) अनुपात' कहते हैं। अर्थव्यवस्था की इन विभिन्न शाखाओं में भी प्रत्येक पहलू के अधिक विस्तृत अनुपातों को बनाए रखना चाहिए। इन्हें 'व्यष्टि आर्थिक (Micro Economic) अनुपात' कहते हैं। योजना के लक्ष्य समस्त अर्थव्यवस्था को एक इकाई मान कर निर्धारित किए जाने चाहिए। उत्पादन-लक्ष्य, न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को, अपितु भावी और सम्भावित आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किए जाने चाहिए।

अर्थव्यवस्था में सन्तुलन बनाए रखने के लिए छोटी सन्तुलन-प्रणाली (Cross-wise balances) द्वारा कुल उत्पादन-लक्ष्य तथा कुल उपलब्ध साधनों जैसे जनशक्ति, खनिज पदार्थ, यातायात, शक्ति आदि के बीच सन्तुलन स्थापित किया जाना चाहिए। एक सन्तुलन उत्पादन-लक्ष्य तथा उपलब्ध जनशक्ति के मध्य होना चाहिए। उपलब्ध धन शक्ति को नियोजित करने से जितना उत्पादन किया जा सकता है, यदि उत्पादन-लक्ष्य इससे कम निर्धारित किए जाएंगे, तो जनशक्ति का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सकेगा और बेरोजगारी फैलेगी। इसी प्रकार, यदि किसी वस्तु के उत्पादन लक्ष्य बहुत कम या अधिक निर्धारित किए गए, तो उस वस्तु के

उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल आदि का या तो पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा या उनकी कमी पड़ जाएगी। उत्पादन-लक्ष्यो के निर्धारण में स्थानीयकरण सन्तुलन (Location Balance) और वित्तीय सन्तुलन (Financial Balance) भी स्थापित किए जाने चाहिए। वित्तीय साधनों की अपेक्षा भौतिक लक्ष्य अधिक ऊँचे निर्धारित किए गए तो वित्तीय साधनों के अभाव में अप्रयुक्त भौतिक साधन एकत्रित हो जाएँगे और अर्थव्यवस्था में बाधाएँ उत्पन्न हो जाएँगी। इसके विपरीत, यदि उत्पादन-लक्ष्यो की अपेक्षाकृत वित्तीय साधनों को अधिक गतिशील बनाया गया तो मुद्रा-प्रसारक प्रवृत्तियों को जन्म मिलेगा। इसके अतिरिक्त, अघोषाधीन-सन्तुलन (Backward Balances) भी स्थापित किया जाना चाहिए। इस प्रकार का सन्तुलन अन्तिम उत्पादों (Finished Products) तथा इस वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक विभिन्न वस्तुओं (Components) के मध्य सम्बन्धों को प्रकट करता है। यदि नियोजन की अवधि में कुछ प्रतिशत से ट्रेक्टरों का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य निश्चित करते हैं, तो ट्रेक्टरों के निर्माण के लिए आवश्यक आदा (Input) जैसे, लोहा एवं इस्पात, ईंधन, शक्ति एवं अन्य पदार्थों का उत्पादन भी बढ़ाना होगा।

साथ ही, योजना के लक्ष्य यथार्थवादी होने चाहिए। वे इतने कम भी नहीं होने चाहिए जिनकी प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाए और जिनके लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़े। यदि ऐसा होगा तो राष्ट्रीय शक्तियाँ विकासोन्मुख नहीं हो पाएँगी। इसके अतिरिक्त लक्ष्य नीचे रखने से देश का आर्थिक-विकास तीव्रता से नहीं हो पाएगा और जनता का जीवन-स्तर ऊँचा नहीं हो पाएगा। इसलिए आर्थिक नियोजन के लक्ष्य बहुत अधिक नीचे नहीं रखने चाहिए, अपितु, ये कम महत्वाकांक्षी होने चाहिए। ऐसा होने पर ही देश के साधन और शक्तियाँ विकास के लिए प्रेरित होंगी तथा द्रुत आर्थिक विकास होगा। देश को स्वयं-सूक्त अर्थव्यवस्था में पहुँचाने के लिए न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न (Critical Minimum Efforts) करने होंगे। इसीलिए, उत्पादन-लक्ष्य ऊँचे रखे जाने चाहिए किन्तु वे इतने ऊँचे भी नहीं होने चाहिए, जो प्राप्त होने में कठिन हो या जिन्हें प्राप्त करने में जनता को बहुत त्याग करना पड़े अथवा कठिनाइयाँ उठानी पड़ें। ये लक्ष्य न बहुत नीचे और न बहुत ऊँचे होने चाहिए। इनके निर्धारण में व्यावहारिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। निर्धारित किए गए लक्ष्य बेल्कोच नहीं होने चाहिए और इनमें परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार, परिवर्तन किए जाने की गुंजाइश होनी चाहिए।

भारतीय नियोजन में लक्ष्य-निर्धारण

भारत में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य-निर्धारण का कार्य विभिन्न कार्यशील समूहों द्वारा किया जाता है। इन कार्यशील समूहों (Working Groups) के सदस्य विभिन्न मंत्रालयों और विशिष्ट समूहों से लिए गए विशेषज्ञ होते हैं। ये दल योजना आयोग द्वारा भेजे गए सुझावों, निर्देशों आदि के अनुसार लक्ष्य-निर्धारित करते हैं। इस कार्य में संगठित जनमत पर भी ध्यान दिया जाता है। लक्ष्यों को

अन्तिम रूप से स्वीकार करने के पूर्व इनकी सगति (Consistency) की विभिन्न प्रकार से जाँच की जाती है।

कृषि-क्षेत्र में लक्ष्य-निर्धारण—कृषि क्षेत्र के लिए उत्पादन वृद्धि के लक्ष्य निर्धारित करते समय मुख्यतः दो बातों का ध्यान रखा जाता है—

- (1) योजनावधि में भोजन, औद्योगिक कच्चे माल और निर्यातों के लिए अनुमानित आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।
- (2) जिन्हें प्राप्त करना व्यावहारिक रूप से सम्भव हो।

कृषि क्षेत्र में लक्ष्य-निर्धारण के कुछ प्रमुख तत्त्व हैं, जैसे—प्रशासनिक, तकनीकी तथा समुदाय स्तर पर संगठन, साख, विशेष रूप से मध्यम और दीर्घकालीन तथा उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यन्त्र आदि के लिए विदेशी विनिमय आदि पर विचार किया जाता है। इन तत्त्वों की उपस्थिति के अनुसार ही कृषि क्षेत्र में लक्ष्य-निर्धारित किए जाते हैं और इन तत्त्वों की कमी हो लक्ष्यों की सीमाएँ निर्धारित करती है। कृषि क्षेत्र के ये लक्ष्य कृषि सम्बन्धी विभिन्न कार्यों जैसे सिंचित क्षेत्रफल, भूमि को कृषि योग्य बनाना, भूमि में भू-संरक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना, सुघरे हुए बीजों का उपयोग, खाद और उर्वरकों का उत्पादन एवं उपयोग, सुघरे हुए यन्त्रों और उपकरणों का उपयोग आदि के बारे में निर्धारित किए जाते हैं। कृषि के इन भादानों के अतिरिक्त कृषि क्षेत्र के उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य भी निर्धारित किए जाते हैं। उदाहरणार्थ, प्रमुख मात्रा में गेहूँ, चावल, गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, खाद्यान्न, दालें आदि का उत्पादन किया जावेगा। समस्त देश के बारे में इन लक्ष्यों को स्थानीय, प्रादेशिक और राज्य योजनाओं के लक्ष्यों के आधार पर निश्चित किया जाता है।

औद्योगिक क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारण—उद्योगों से सम्बन्धित लक्ष्य-निर्धारण में सर्वप्रथम अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों से उद्योगों के अनुपात पर विचार किया जाता है। साथ ही, आधारभूत वस्तुओं, जैसे स्पात, सीमेन्ट, कोयला, रसायन आदि की माँग का अनुमान लगाया जाता है। प्रत्येक स्थिति में वर्तमान स्थिति पर विचार किया जाता है। इसमें देश में उत्पादन, आयात, पूँजीगत लागतें, कच्चे माल की उपलब्धि, विदेशी-विनिमय की आवश्यकता आदि पर विचार किया जाता है। आधारभूत उद्योगों के बारे में ही नहीं अपितु, अन्य उद्योगों के बारे में भी इसी प्रकार की बातों को ध्यान में रख कर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। निम्नो-क्षेत्र में संचालित उद्योगों के लिए योजना आयोग मुख्य उत्पादक इकाइयों, उद्योग के प्रतिनिधियों या प्रतिनिधि संस्थाओं से विचार-विमर्श करता है। इस प्रकार, व्यक्तिगत उद्योग और अन्य सभी उद्योगों के अस्थाई लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैं। तत्पश्चात् इनमें पारस्परिक सम्बन्ध (Mutual Inter relationship) और मुख्य उद्योगों के मादा-प्रदा (Input-output) के आधार पर समायोजन कर लिया जाता है। कई छोटे उपभोक्ता उद्योगों के लिए इस प्रकार के विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते,

अपितु प्रचिकांश उद्योगो के बारे मे उत्पादन या स्थापित क्षमता के स्तर के बारे मे योजना मे जानकारी दे दी जाती है ।

शक्ति एवं यातायात—शक्ति एवं यातायात के लक्ष्यो को कृषि और उद्योगो के विकास तथा उत्पादन के अनुमानो के आधार पर निश्चित किया जाता है । यह अनुमान लगाया जाता है कि कृषि और उद्योगो का किन्ना विकास होगा और इनके लिए तथा उपभोग आदि के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता होगी । साथ ही, कृषि-उत्पन्न मण्डियो, उपभोक्ताओ तथा बन्दरगाहो तक पहुँचाने के लिए कृषि आदानो (Agricultural inputs) को कृषको तक पहुँचाने के लिए तथा उद्योगो के लिए कच्चे माल को कारखानो मे पहुँचाने, कारखानों से निमित्त माल बाजारो, उपभोक्ताओ तथा बन्दरगाहो तक पहुँचाने के लिए किस मात्रा मे यातायात के साधनो की आवश्यकता होगी । इन अनुमानो के अनुसार योजना मे यातायात के साधनो के विकास के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं । शक्ति और यातायात के साधन सम्बन्धी लक्ष्यो को निर्धारित करने मे एक बठिनाई यह होती है कि इन सुविधाओ की व्यवस्था इनकी आवश्यकता के पूर्व ही की जानी चाहिए, क्योंकि इनको भी पूरे होने मे समय लगना है । किन्तु कृषि और उद्योगो के लक्ष्य योजना प्रक्रिया मे बहुत बाद मे अन्तिम रूप ग्रहण करने हैं । अतः कृषि और उद्योगो के विकास की दीर्घकालीन योजना पूर्व ही तैयार होनी चाहिए जिनके आधार पर शक्ति और यातायात के लक्ष्य समय पर निर्धारित किए जा सक । भारत मे इस प्रकार के दीर्घकालीन नियोजन के कारण ही भूतकाल मे शक्ति और यातायात के लक्ष्य उनकी माँग से पिछड़ गए हैं । इस कमी की पूर्ति के लिए भारतीय नियोजन मे प्रयास किए गए हैं ।

शिक्षा क्षेत्र मे लक्ष्य निर्धारण—तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के प्रशिक्षण मे अधिक समय लगना है । किसी अभियन्ता या चिकित्सक या कृषि विशेषज्ञ आदि को तैयार करने मे कई वर्ष लग जाते हैं । अतः आगे आने वाली योजना के लिए वर्तमान योजना के प्रारम्भ मे ही लक्ष्यो को निश्चित कर लिया जाता है । आगामी योजना मे किन्ने कुशल अभिको या तकनीकी कर्मचारियो अथवा विशेषज्ञो की आवश्यकता पडेगी । इन अनुमानो के अनुसार व्यक्तियो को तैयार करने के लिए वर्तमान योजना मे लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैं । इसलिए भारत मे योजना-आयोग कई वर्षों स जन शक्ति के दीर्घकालीन प्रशिक्षण के कार्यक्रम बनाता रहा है । मानव शक्ति पर अव्यय अनुपदान के लिए व्यावहारिक जन-शक्ति अनुपदान सस्थान की दिल्ली मे स्थापना की गई है । विभिन्न प्रकार की जन-शक्ति की आवश्यकताओ के अनुमान लगाए जाते हैं और तन्नुसार प्रशिक्षण, शिक्षा आदि के कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं ।

सामान्य शिक्षा-सम्बन्धी लक्ष्य निर्धारण मे भारतीय संविधान और उसमे वर्णित नीति-निर्देशक तत्वो (Directives of State Policy) तथा उसमे समय-समय पर हुए संशोधनो को ध्यान मे रखा जाता रहा है । इस सम्बन्ध मे योजनाओ मे लक्ष्यो का निर्धारण 6 से 11 वर्ष की आयु के समस्त बालको को निःशुल्क और

अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था तृतीय योजना के अन्त तक और 14 वर्ष तक की आयु के समस्त बालको को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था चौथी या पाँचवी योजना के अन्त तक करने के ध्येय और व्यापक निर्देशों के आधार पर किया जाता रहा है। इस व्यापक लक्ष्य के अनुरूप प्रत्येक योजना में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय खोलने का अध्यापकों को नियुक्त करने और शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों को प्रविष्ट कराने के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक कल्याण के लक्ष्य निर्धारण, इन सुविधाओं के लक्ष्य दीर्घकालीन दृष्टिकोण से विकसित की जाने वाली सुविधाओं पर विचार-विनिमय के पश्चात् निर्धारित किए जाते हैं। भारत इन क्षेत्रों में बहुत पिछड़ा है और इन सुविधाओं में तेजी से वृद्धि की आवश्यकता है। किन्तु इन कार्यक्रमों को उनकी आवश्यकताओं की अपेक्षा बहुत कम राशि आवंटित की जाती है। परिणाम-स्वरूप इनके लक्ष्य कम ही निर्धारित होते रहे हैं।

अन्तिम लक्ष्य निर्धारण—इस प्रकार, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं जिन्हें मिलाकर समग्र योजना का निर्माण किया जाता है। इन लक्ष्यों के आधार पर सम्पूर्ण योजना के लिए स्थिर और स्थिर पूँजी तथा विदेशी विनिमय आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है। तत्पश्चात् इस बात पर विचार किया जाता है कि आन्तरिक और बाह्य स्रोतों से ये किस मात्रा में साधनों को गतिशील बनाना सम्भव है और कितने पूँजीगत साधन और विदेशी विनिमय योजना के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। इनकी उपलब्धि के सम्बन्ध में समस्त योजना या किसी विशेष क्षेत्र के लक्ष्यों के कम करने या बढ़ाने की गुंजायश पर विचार किया जाता है। लक्ष्यों को अन्तिम रूप देने में रोजगार वृद्धि के अवसरों और आधारभूत कच्चे माल की उपलब्धि पर भी विचार किया जाता है। इन सब बातों पर विचार करने के पश्चात् योजना के लक्ष्य निर्धारण को अन्तिम रूप दिया जाता है।

लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया की कमियाँ—भारतीय योजनाओं के लिए लक्ष्य-निर्धारण प्रक्रिया में कई कमियाँ हैं। कई अर्थशास्त्रियों ने लक्ष्य-निर्धारण में और विभिन्न वित्तीय-गणनाओं की दूसरी योजनाओं की तकनीक और आधारों की आलोचना की है। योजना आयोग ने बड़े-बड़े लक्ष्यों के बारे में तो विचार किया किन्तु विनियोग व्यय के प्राकृतिक विश्लेषण पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। इन लक्ष्यों का निर्धारण कई गलत और अपूर्ण मान्यताओं के आधार पर किया। लक्ष्य-निर्धारण में, गणार्थ पूँजी-उत्पादन अनुपात का उपयोग नहीं किया गया। एम एल सेठ (M L Seth) ने भारत में लक्ष्य-निर्धारण-प्रक्रिया में निम्नलिखित कमियाँ बताई हैं—

(1) योजना के अन्तिम वर्ष के लिए लक्ष्य-निर्धारित करने में बहुत ध्यान दिया जाता है किन्तु इन लक्ष्यों को योजनावधि के सभी वर्षों के लिए विभाजित नहीं किया जाता।

(ii) अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों जैसे-उद्योग, शक्ति, सिंचाई, यातायात आदि की परियोजनाओं में जहाँ भारी मात्रा में विनियोग हो और जिनके पूर्ण होने की अवधि अधिक लम्बी हो।

इन परियोजनाओं के आर्थिक, तकनीकी, वित्तीय और अन्य परिणामों पर पूरा विचार नहीं किया जाता। इसी कारण, परियोजना की प्रारम्भिक अवस्थाओं में पर्याप्त प्रशिक्षित व्यक्ति और आवश्यक संगठन उपलब्ध नहीं हो पाते।

(iii) किसी परियोजना के निर्माण की स्थिति में बाढ़ में, जाकर अप्रत्याशित तत्वों के कारण विभिन्न परिवर्तन और समायोजन करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए योजना उससे प्राप्त होने वाले लाभों, लागत अनुमानों और वित्तीय साधनों के दृष्टिकोण से लचीली होनी चाहिए। भारतीय नियोजन के लक्ष्य-निर्धारण में इस और अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता है।

आर्थिक विकास और योजना-कार्यक्रमों की सफलता के लिए भारी मात्रा में पूँजी का विनियोग आवश्यक होता है। अधिक बचत का सृजन करके इन्हे बाजार तात्त्विकता तथा वित्तीय समस्याओं द्वारा गतिशील बना कर, उत्पादक आदेशों में रूपान्तरित करके विनियोगों की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। ग्रंथव्यवस्था में विनियोगों की यह मात्रा उपलब्ध बचत की मात्रा और ग्रंथव्यवस्था की पूँजी-शोषण-क्षमता (Absorptive Capacity) पर निर्भर करती है। पूँजी शोषण क्षमता का आशय समाज और व्यक्तियों में उपलब्ध पूँजीगत आदेशों के उपभोग करने की योग्यता से है।

आर्थिक विकास के लिए विशाल मात्रा में पूँजी का विनियोजन ही पर्याप्त नहीं है अपितु पूँजी का विनियोग सुविचारित और युक्ति-युक्त होना चाहिए। अर्द्ध-विकसित देशों में विनियोजित किए जाने वाले साधनों की अत्यन्त स्वल्पता होती है। साथ ही उनकी माँग और उपयोगों में वृद्धि भी होती रहती है। अतः इन विनियोजित किए जाने वाले साधनों के विभिन्न वैकल्पिक उपयोगों में से चयन करना पड़ता है। अतः यह समस्या पैदा होती है कि विभिन्न क्षेत्रों में अर्थात् कृषि उद्योग या सेवाओं में, निजी या सार्वजनिक उद्योगों में, पूँजीगत या उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में और देश के विभिन्न क्षेत्रों में से किस में अधिक मात्रा में विनियोग किया जाए और इन सभी क्षेत्रों के सभी भागों में किस प्रकार विनियोगों का आवंटन किया जाए। सामान्यतः इन विभिन्न क्षेत्रों और उनके भागों में विनियोगों के लिए वास्तविक साधनों का प्रवाह आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तत्त्वों से प्रभावित होता है। किन्तु यह आर्थिक विकास में तीव्रता लाने के लिए केवल विनियोगों की अधिकता के साथ-साथ उनका विवेकपूर्ण आवंटन भी आवश्यक है।

विनियोग विकल्प की आवश्यकता (Need for Investment Choice)

सैद्धांतिक रूप से आदर्श अवस्था में पूर्ण और स्वतन्त्र प्रतियोगिता होती है और उत्पादन के साधनों एवं विनियोगों के विभिन्न उपयोगों में अनुकूलतम वितरण की प्राप्ति की जाती है। यहाँ मजदूरी और ब्याज दरें माँग और पूर्ति की शक्तियों के

द्वारा निर्धारित होती हैं और प्रत्येक साधन का उपयोग सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त के अनुसार उभ विन्दु तक किया जाता है, जिस पर इसकी सीमान्त उत्पत्ति उसके लिए चुकाई जाने वाली कीमत के बराबर होती है। श्रम, पूँजी आदि किसी साधन की पूर्ति में वृद्धि होने पर इसका मूल्य घटने लगेगा और इससे इस साधन के अधिक प्रयुक्त किए जाने को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके विपरीत किसी साधन की पूर्ति में कमी आने पर उसके मूल्य में वृद्धि होगी है और उसका उपयोग हतोत्साहित होता है। इस प्रकार स्वतन्त्र उपक्रम अर्थव्यवस्था में मूल्य-प्रक्रिया और बाजार-तान्त्रिकता के द्वारा न केवल साधनों का पूर्ण नियोजन हो जाता है, अपितु उनका सर्वाधिक प्रभावपूर्ण और अनुकूलतम उपयोग भी होता है।

किन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं हो पाता है। एक तो स्वयं पूर्ण प्रतियोगिता का होता असम्भव है और दूसरे उत्पादन में बाह्य मितव्ययताओं का प्राबुर्भाव और उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन के साथ लागतों का बढ़ना या घटना साधनों के आदर्श वितरण में बाधाएँ उत्पन्न कर देने हैं। इस प्रकार स्वतन्त्र उपक्रम में साधनों और विनियोगों का अनुकूलतम आवंटन पक्षिण होता है। इसके अतिरिक्त, उत्पादन की आधुनिक तकनीकी दशाएँ किसी भी दीर्घकालीन उत्पादन-प्रक्रिया में सीमान्त उत्पादन और लागत के समायोजन को कठिन बना देती हैं, क्योंकि जब एक बार उत्पादन की किसी तकनीक को ग्रहण कर लिया जाता है, तो तदनुसृत साधनों के अनुपात को भी स्वीकार करना पड़ता है। निजी उद्यमियों का विनियोग सम्बन्धी निर्णय तकनीकी ज्ञान का स्तर, श्रम पूर्ति, मजदूरी, ब्याज और मूल्य स्तर, उपयोग के लिए उपलब्ध कोषों की मात्रा और पूँजी और श्रम के तकनीकी सम्बन्ध आदि के ज्ञाता या अज्ञात सूचनाओं के अनुसार निर्णय लेने पड़ते हैं।

अनियन्त्रित मुक्त उपक्रम प्रणाली में विनियोग के आवंटन में अन्त्य कमियाँ भी होती हैं। निजी उद्यमियों का उद्देश्य निजी-लाभ को अधिकतम करना होता है। इसके आगे वे सामाजिक-कल्याण की उपक्षा कर जाते हैं। साथ ही उनकी दूरदर्शिता की शक्ति भी सीमित होती है। विनियोग की किसी विशेष परियोजना की अर्थ-व्यवस्था पर और किसी विशेष नए उद्योगों की स्थापना या पुराने उद्योगों के विस्तार का, अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों या आय के वितरण और उसकी संरचना, उत्पादन के साधनों की पूर्ति और लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात को विचारने की चिन्ता निजी उद्यमकर्त्ता नहीं करते और न ही वे इस कार्य के लिए सक्षम होते हैं। परिणाम-स्वरूप अर्थव्यवस्था में होने वाले समय प्रभावों का ज्ञान एक ऐसे अभिकरण द्वारा ही हो सकता है जिसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के व्यवहार और प्रतिक्रिया का विस्तृत और पर्याप्त ज्ञान हो। निजी-उद्यमियों द्वारा लिए गए विनियोजन सम्बन्धी उक्त कमियों के कारण ही सरकार द्वारा विनियोग कार्यक्रमों में भागीदार बनने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। निजी-उपक्रम व्यवस्था में साधनों का अनुकूलतम आवंटन नहीं हो पाता है। आवश्यक कार्यों के लिए पूँजी उपलब्ध नहीं हो पाती, जबकि सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टि से अनावश्यक परियोजनाओं पर बहुत अधिक

साधन विनियोजित किए जाते हैं। अतः सरकार को प्रत्यक्ष विनियोग द्वारा या निजी उद्यमियों द्वारा किए जा रहे विनियोगों को नियन्त्रित करके विभिन्न क्षेत्रों, उद्योगों और प्रदेशों में विनियोगों का अनुकूलतम आवंटन करना चाहिए। वस्तुतः सरकार विनियोगों के आवंटन और उनकी तकनीकी सम्बन्धी समस्याओं के बारे में दीर्घकालीन और अच्छी जानकारी रखने और उन्हें हल करने की स्थिति में होती है। उसके साधन भी अपरिमित होते हैं। वह देश के उपलब्ध और सम्भावित साधनों और विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं सम्बन्धी सूचनाओं से भी सम्पन्न होते हैं। सरकार निजी उपक्रमियों की अपेक्षा विनियोगों की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम-स्वरूप, विभिन्न क्षेत्रों और समूची अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का अधिक अच्छा अनुमान लगा सकती है। अतः राज्य प्राथमिक क्रियाओं में भाग लेकर और विनियोग नीति द्वारा वित्तीय साधनों का उपयुक्त वितरण करने में समर्थ हो सकती है। विशेषतः वह यात्रायात के साधनों, सिंचाई और विद्युत योजनाओं द्वारा बड़ी मात्रा में बाह्य मितव्ययनाओं का सृजन करके आर्थिक विकास को तीव्रगति प्रदान कर सकती है। वह निजी उद्यमियों द्वारा उपेक्षित क्षेत्रों में स्वयं पूँजी विनियोजन कर सकती है। इस प्रकार एक उद्योग या क्षेत्र का विस्तार दूसरे उद्योग या क्षेत्र में होता है।

अर्द्ध-विकसित देशों की विनियोजन सम्बन्धी विशिष्ट समस्याएँ (Special Investment Problems in Underdeveloped Countries)

अर्द्ध विकसित देशों की विशिष्ट सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं के कारण इन देशों में विनियोगों के आवंटन की समस्या, विकसित देशों की अपेक्षा अधिक जटिल होती है। साधनों की अपर्याप्त उपलब्धि और साधनों के तकनीकी प्रतिस्थापन के सीमित अंतर उचित विनियोग नीति अपनाने में बाधाएँ उपस्थित करते हैं। प्रो किंडलबर्गर (Prof Kindleberger) के अनुसार, अर्द्ध-विकसित देशों में 'साधन स्तर पर संरचनात्मक असाम्य' (Structural disequilibrium at the factor level) होता है। यहाँ पूँजी स्वल्पता और श्रम शक्ति की बहुलता होती है। परिणामस्वरूप ये देश पर्याप्त माना में बेरोजगारी और अर्द्ध-बेरोजगारी से ग्रस्त रहते हैं। श्रम की सीमान्त-उत्पादकता शून्य या शून्य के लगभग होती है, किन्तु मजदूरी की वास्तविक दर उससे भिन्न होती है जो श्रम की माँग और पूर्ति की शक्तियों के निर्धारण द्वारा होती है। इसका प्रमुख कारण इन देशों की अर्थव्यवस्था में संगठित और प्रमगठित दो भिन्न भिन्न क्षेत्रों की उपस्थिति है। संगठित क्षेत्र में श्रम संगठनों, सामाजिक सुरक्षा-समिथियों और सरकार की श्रम कल्याणवादी नीति के कारण मजदूरी की दरें असंगठित क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होती हैं। अतः उत्पादन की तकनीक अधिक पूँजी गहन होती है और ऐसी परिवोजनाओं में पूँजी विनियोजित की जाती है किन्तु दूसरी ओर पूँजी का प्रभाव अपनी स्वयं की कठिनाइयाँ उपस्थित करती है। पूँजी के प्रभाव के प्रतिरिक्त सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियाँ भी

उत्पादन की आधुनिक और कुशल प्रणालियों के ग्रहण करने में बाधाएँ उपस्थित करता है। उदाहरणार्थ, छोटे खेतों को बड़ी कृषि सम्पत्तियों में परिवर्तित करने के कृषि विनियोग कार्यक्रम (Agricultural Investment Programme) का ऐसे देश में विरोध किया जाता है, जहाँ अधिक भूमि का स्वामित्व सामाजिक सम्मान का होता है। डी ब्राइटसिंह (D Bright Singh) के अनुसार "आवश्यक पूँजी उपलब्ध होने पर भी भारी उद्योगों में पूँजी विनियोग दृढ़ औद्योगिक आधार का निर्माण करने और आर्थिक विकास की गति देने में तभी सफल हो सकता है जबकि समाज आर्थिक-विस्तार के उपयुक्त सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करे।" अतः इन अर्द्ध-विकसित देशों में विनियोग कार्यक्रम का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो विकास कार्यक्रम और परियोजनाएँ अपनाई जाएँ, वे यथासम्भव वर्तमान सामाजिक और आर्थिक समस्याओं और मूल्यों में कम से कम हस्तक्षेप करें। साथ ही इन सस्याधी और मूल्यों में भी शन-शन परिवर्तन किया जाना चाहिए। अर्द्ध विकसित देशों द्वारा इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि वे विकसित देशों का अध्यानुकरण करके ही विनियोग के लिए परियोजनाओं का चयन नहीं करें अपितु देश की साधन-पूर्ति (Factor supply) की स्थिति के अनुसार उन्हें समायोजित भी करें।

अधिकांश अर्द्ध-विकसित देशों में कृषि की प्रधानता होती है। कृषि वहाँ के अधिकांश व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करती है, राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग उत्पन्न करती है और विदेशी विनिमय के अर्जन में भी कृषि का महत्व होता है। किन्तु कृषि व्यवसाय अत्यन्त पिछड़ी अवस्था में होता है। अतः यहाँ कृषि विकास कार्यक्रमों पर विशाल पूँजी विनियोजन की आवश्यकता होती है, किन्तु इन देशों में औद्योगिक विकास की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती क्योंकि कृषि के विकास के लिए औद्योगिक विकास आवश्यक है। अतः औद्योगिक परियोजनाओं पर भी भारी मात्रा में पूँजी-विनियोग आवश्यक होता है। अतः अर्द्ध विकसित देशों में उद्योग कृषि सेवाओं आदि में उचित विनियोग नीति अपनाने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार, अर्द्ध-विकसित देशों में सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार को बहुत समर्थन मिलता है।

विनियोग मानदण्ड (Investment Criteria)

आर्थिक विकास के लिए नियोजन हेतु वित्तीय साधनों की गतिशील बनाना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही विनियोग की प्रकृति का निर्धारण करना है। इन देशों को न केवल विनियोग-दर के बारे में ही निर्णय करना पड़ता है, अपितु विनियोग संरचना के बारे में भी उचित निर्णय करना पड़ता है। सरकार का यह कर्तव्य होता है कि इस प्रकार के विनियोग कार्यक्रम अपनाएँ, जो समाज और राष्ट्र के लिए सर्वाधिक लाभप्रद हों। अतः विभिन्न क्षेत्रों, परियोजनाओं, उद्योगों और प्रदेशों में विनियोग कार्यक्रम को निर्धारित करते समय अत्यधिक सोच-विचार की आवश्यकता है। गत वर्षों में, अर्थशास्त्रियों द्वारा द्रुत आर्थिक विकास के उद्देश्य से

विनियोगों पर विचार करने के लिए कई मानदण्ड प्रस्तुत किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं—

1. समान सीमान्त-उत्पादकता का मानदण्ड

(Criteria of Equal Marginal Productivity)

इस सिद्धान्त के अनुसार विनियोग और उत्पादन के साधनों का सर्वोत्तम आवंटन तब होता है कि जब विभिन्न उपयोगों में इसके परिणामस्वरूप सीमान्त विनियोग सर्वाधिक लाभप्रद नहीं होंगे, क्योंकि उनको एक क्षेत्र में स्थानांतरित करके कुल लाभ में वृद्धि करने की पुंजायत्त रहेगी। अतः विभिन्न क्षेत्रों, उद्योगों और प्रदेशों में विनियोगों का इस प्रकार वितरण किया जाना चाहिए जिससे उनकी सीमान्त-उत्पादकता समान हो। अर्द्ध-विकसित देशों में श्रम की बहुलता और पूँजी की सीमितता होती है। अतः विनियोग नीति इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें, कम मात्रा में पूँजी से ही अधिक मात्रा में श्रम को नियोजित किया जा सके। अन्य शब्दों में विनियोग नीति देश में उपलब्ध श्रम और पूँजीगत साधनों का पूर्ण उपयोग करने में समर्थ होनी चाहिए। यदि देश में पूँजी का अभाव और श्रम की बहुलता है, जैसा कि अर्द्ध-विकसित देशों के बारे में सत्य है, तो यह देश निम्न पूँजी श्रम अनुपात वाली परियोजनाओं को अपनाकर अधिक तुलनात्मक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार, विनियोग कार्यक्रमों को निर्धारित करते समय हेक्सचेर-ओह्लिन (Heckscher Ohlin) के तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त (Doctrine of Comparative Cost) पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यद्यपि पूँजी की सीमित उपलब्धता की स्थिति में श्रम-शक्ति के पूर्ण उपयोग से श्रम की प्रत्येक इकाई की सीमान्त उत्पादकता में कमी आती है तथापि अधिक श्रमिकों के नियोजित हो जाने के कारण कुल उत्पत्ति में वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार विनियोग अधिकतम लाभप्रद हो जाते हैं। यह सिद्धान्त साधन उपलब्धता (Factor Endowment) पर आधारित है, जिसमें श्रम और पूँजी आदि उपलब्ध साधनों के पूर्ण उपयोग पर बल दिया गया है। अतः अर्द्ध-विकसित देशों में जहाँ पूँजी का अभाव और श्रम की बहुलता है, श्रम-प्रधान और पूँजी विरल विनियोगों को अपनाना चाहिए। सीमान्त-उत्पादकता को समान करने का सिद्धान्त केवल स्थैतिक दशाओं के अन्तर्गत अल्पकाल में ही विनियोगों का कुशल आवंटन करने में सक्षम होता है। मॉरिस डॉब (Maurice Dobb) के अनुसार ससाधन स्थिति के अनुसार, पूँजी-विरल परियोजनाओं को अपनाना एक प्रकार से प्रगति या परिवर्तन की आकांक्षा के बिना वर्तमान निम्न दशा को ही स्वीकार करना है। जबकि द्रुत आर्थिक विकास के लिए उत्पादन के संगठन, संरचना और तकनीकों में परिवर्तन आवश्यक है। इसी प्रकार इन देशों में पूँजी-गहन परियोजनाओं से सर्वथा बचा नहीं जा सकता। यहाँ पर्याप्त मात्रा में जल, खनिज आदि प्राकृतिक साधन समोपित हैं जिसकी विकसित करने के लिए प्रारम्भ में भारी विनियोगों की आवश्यकता होती है। इस्पात कारखाने, तेल-शोधक शालाएँ, यातायात संचार, बन्दरगाह आदि आर्थिक

विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक होते हैं और इन सभी में बड़ी मात्रा में पूँजी विनियोग की आवश्यकता होती है।

2. सामाजिक सीमान्त उत्पादकता का मापदण्ड (Criteria of Social Marginal Productivity)

विनियोगों का एक महत्वपूर्ण मापदण्ड सामाजिक 'सीमान्त उत्पादकता' है जो एक प्रकार से, 'समान सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त' का सशोधित रूप है। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 1951 में ए. ई. काहन (A E Kahn) ने किया जिसे बाद में हॉलिस बी चेनेरी (Hollis B Chanery) ने विकसित किया। इस सिद्धान्त के अनुसार, यदि विनियोगों द्वारा आर्थिक विकास को गति देना है, तो पूँजी ऐसे कार्यक्रमों में विनियोजित की जानी चाहिए, जो सर्वाधिक उत्पादक हों अर्थात् जिनकी सीमान्त सामाजिक उत्पादकता सर्वाधिक हो। सीमान्त सामाजिक उत्पादकता सिद्धान्त के अनुसार, विनियोग की अतिरिक्त इकाई के लाभ का अनुमान इस आधार पर नहीं लगाया जाता है कि इससे निजी उत्पादक को क्या मिलता है किन्तु इस बात से लगाया जाता है कि इस सीमान्त इकाई का राष्ट्रीय उत्पादन में कितना योगदान रहा है। इसके लिए न केवल आर्थिक, अपितु सामाजिक लागतों और सामाजिक लाभों पर भी ध्यान दिया जाता है ए. ई. काहन (A E Kahn) के अनुसार सीमित माधनों से अधिकतम आय प्राप्त करने का उपयुक्त मापदण्ड 'सीमान्त सामाजिक उत्पादकता' है जिसमें सीमान्त इकाई के राष्ट्रीय उत्पत्ति के कुल योगदान पर ध्यान दिया जाना चाहिए, न कि केवल इस योगदान (या इसकी लागतों) के उस भाग पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए जो निजी विनियोगकर्ता को प्राप्त हो।" इस सिद्धान्त के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में विनियोगों की सीमान्त सामाजिक उत्पादकता समान होनी चाहिए। भारत जैसे अर्द्धविकसित देशों के संदर्भ में विकासार्थ नियोजन में किए जाने वाली सीमान्त सामाजिक उत्पादकता की उच्चता वाले विनियोग निम्नलिखित हैं—

(i) जो सर्वाधिक उत्पादकता वाले उपयोगों में लगाए जाएं, ताकि विनियोगों से प्रचलित उत्पादन का अनुपात अधिकतम हो या पूँजी उत्पादन अनुपात न्यूनतम हो। अर्थ शब्दों में पूँजी उन क्षेत्रों, उद्योगों, परियोजनाओं और प्रदेशों में विनियोजित की जानी चाहिए, जिनमें लगी हुई पूँजी से अपेक्षाकृत अधिक उत्पत्ति हो।

(ii) जिनमें श्रम विनियोग अनुपात (Labour Investment Ratio) अधिकतम हो अर्थात् जो पूँजी से श्रम के अनुपात में वृद्धि करें। अर्थ शब्दों में, पूँजी ऐसे क्षेत्रों, उद्योगों, परियोजनाओं और भौगोलिक क्षेत्रों में विनियोजित की जानी चाहिए, जिनमें लगी हुई पूँजी से अधिक श्रमिकों को नियोजित किया जा सके।

(iii) जो ऐसी परियोजनाओं में लगाए जाएँ, जो व्यक्तियों की बुनियादी आवश्यकताओं की वस्तुओं का उत्पादन करें और बाह्य मितव्ययताओं में वृद्धि करें।

(iv) जो पूँजी के अनुपात में निर्यात पदार्थों में वृद्धि करें, अर्थात् जो निर्यात सबद्धन या आयात प्रतिस्थापन में योगदान दे।

(v) जो अधिकतर घरेलू कच्चा-माल तथा अन्य साधनों का अधिकाधिक उपयोग करें।

(vi) जो शीघ्र फलदायी हो, ताकि मुद्रा प्रसार, विरोधी शक्ति के रूप में कार्य कर सके।

सीमान्त सामाजिक उत्पादकता के मानदण्ड की श्रेष्ठता इस बात में निहित है कि इसमें किसी विनियोग कार्यक्रम की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले समग्र प्रभावों पर ध्यान दिया जाता है। अतः यह सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त की अपेक्षा अधिक अच्छा है किन्तु इसकी अपनी भी सीमाएँ हैं। आर्थिक विकास के दौरान न केवल सामाजिक आर्थिक तत्त्वों, अपितु जनसंख्या की मात्रा, गुण, स्वभाव और उत्पादन तकनीक आदि में भी परिवर्तन आता है। अतः इस मानदण्ड का उपयोग एक अर्थव्यवस्था की सम्पूर्ण गत्यात्मक परिस्थितियों के सदृश में करना चाहिए। कुछ सामाजिक उद्देश्य परस्पर विरोधी हो सकते हैं। अतः विभिन्न उद्देश्यों में से कुछ का चयन करना एक कठिन कार्य होता है। इसमें नैतिक निर्णयों की भी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार विनियोगों की दिशा और उनके अन्तिम परिणामों के बारे में भी विचारों में अन्तर हो सकता है। उदाहरणार्थ, किसी विनिष्ट परियोजना में पूँजी का विनियोग करने से राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि हो, किन्तु उससे आय वितरण असम हो। इसी प्रकार कुछ परियोजनाओं में विनियोग से राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति उपभोग निश्चित भविष्य में ही बढ़ सकता है, जबकि किन्हीं अन्य परियोजनाओं से ऐसा दीर्घकाल में हो सकता है। अतः सामाजिक उद्देश्यों के निर्धारित किए बिना विनियोगों की दिशा, संरचना और प्रगति के बारे में निर्णय लेना बहुत कठिन है।

इसके अतिरिक्त, सीमान्त सामाजिक-उत्पादकता की यह धारणा अवास्तविक है। यह निजी-लाभ से मानदण्ड की अपेक्षा कम निश्चित है। बाजार मूल्य, सामाजिक मूल्यों (Social Values) को ठीक प्रकार से प्रकट नहीं करते। अतः विनियोगों में निहित सामाजिक लाभ और सामाजिक लागतों का सख्यात्मक माप असम्भव है। मानदण्ड की सबसे बड़ी कमी यह है कि, इसमें विनियोगों के एक बार के प्रभावों पर ही ध्यान दिया जाता है। वस्तुतः हमें किसी विनियोग से प्राप्त तत्काल लाभों पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, अपितु भावी लाभों एवं पूँजी संचय पर भी विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त विनियोग के अप्रत्यक्ष प्रभाव जैसी भावी वृद्धि, उपभोग संरचना, जनसंख्या वृद्धि आदि पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

3. तीव्र विकास विनियोग मानदण्ड

(Criteria of Investment to Accelerate Growth)

गेलेन्सन और लीबेन्स्टीन (Galenson and Liebenstein) ने षष्ठ-विंशति देशों में विनियोग के मापदण्ड के लिए सीमान्त प्रति व्यक्ति पुनर्विनियोग क्षम्य

(Marginal per Capitare Investment Quotient) की धारणा का समर्थन किया है। किसी अर्थव्यवस्था के उत्पादन की पुनर्विनियोग क्षमता एक ओर प्रति श्रमिक उपलब्ध पूँजी से प्रति श्रमिक उत्पादन की मात्रा और दूसरी ओर जनसंख्या का उपयोग और पूँजीगत साधनों के प्रतिस्थापन आदि का अन्तर है। प्रति श्रमिक पूँजी से इस आधिक्य का अनुपात पुनर्विनियोग लब्धि (Re-investment Quotient) कहलाता है। उचित विनियोग नीति वह होती है, जिसके द्वारा साधन उपभोगों की अपेक्षा अधिक अनुपात में पूँजी-कार्यों की ओर बढ़े। देश की पूँजी में इस दृष्टि से मानव पूँजी को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। लीबेन्स्टीन के अनुसार, पूँजीगत-पदार्थों और मानव-पूँजी के रूप में कुल पूँजी निर्माण प्रनिवर्ण सामान्य पुनर्विनियोग और जनसंख्या के आकार में वृद्धि पर निर्भर करता है। यदि पुनर्विनियोग वर्ष प्रति वर्ष बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय में लाभों का भाग बढ़ाना पड़ेगा। पुनर्विनियोग लब्धि मानदण्ड के अनुसार, दीर्घकालीन पूँजीगत वस्तुओं (Long-lived Capital Goods) में पूँजी विनियोजित की जानी चाहिए। अर्द्ध-विकसित देशों को यदि सफलतापूर्वक तेजी से विकास करना है तो उत्पादन में वृद्धि के लिए विकास प्रक्रिया के प्रारम्भ में ही बड़े पैमाने पर प्रयत्नों की आवश्यकता है, जिसे लीबेन्स्टीन ने न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न कहा है। अन्य शब्दों में विनियोग आवंटन (Investment Allocation) इस प्रकार का होना चाहिए जिससे विकास-प्रक्रिया की प्रारम्भिक अवस्था में ही तेजी से पूँजी निर्माण हो।

पुनर्विनियोग लब्धि में उक्त मानदण्ड की भी आलोचनाएँ की गई हैं। इस सिद्धान्त की यह माय्यता कि लाभों की अधिकता के कारण पुनर्विनियोग भी अधिक होंगे, उचित नहीं मानी गई है। ए के सेन (A K Sen) के मतानुसार पूँजी की प्रति इकाई पर ऊँची दर से पुनर्विनियोग योग्य आधिक्य देने वाले विनियोगों से ही विकास दर में तेजी नहीं लाई जा सकती। यह आधिक्य अधिक हो सकता है किन्तु इस उत्पादन कार्य में लगे व्यक्तियों की उपभोग की प्रवृत्ति में वृद्धि हो जाए तो पुनर्विनियोग योग्य आधिक्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, इस मानदण्ड में सामाजिक कल्याण के सादृश्यों की अपेक्षा की गई है। पूँजी-गहन विनियोगों और तकनीकों के अपनाए जाने से श्रमिकों का विस्थापन (Displacement) होगा। साथ ही इस मानदण्ड में वर्तमान की अपेक्षा भविष्य पर अधिक ध्यान दिया गया है।

4. विशिष्ट समस्याओं को नियन्त्रित करने का मानदण्ड (Investment criteria which aim at controlling specific problems)

इस मानदण्ड का उद्देश्य विकास प्रक्रिया में उत्पन्न विशिष्ट समस्याओं को नियन्त्रित करके स्थायित्व के साथ आर्थिक विकास करना है। विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में भुगतान सन्तुलन की प्रतिकूलता और मुद्रा प्रसारिक दबावों के कारण विकास में अस्थायित्व आ सकता है। अर्द्ध-विकसित देशों को बड़ी मात्रा में पूँजीगत

सामग्री और कच्चा माल आदि मँगाना पड़ता है। औद्योगीकरण और विनियोगों के कारण मौद्रिक आय बढ़ती है जिससे उपभोग वस्तुओं का आयात भी बढ़ जाता है। इससे विदेशी मुद्रा की कमी एक बड़ी कठिनाई बन जाती है। इसी प्रकार लोगों की मौद्रिक आय बढ़ने के कारण वस्तुओं की माँग बढ़ जाती है और मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियाँ जन्म लेने लगती हैं। अतः ऐसे क्षेत्रों में विनियोग किया जाना चाहिए जिससे निर्यात वृद्धि और आयात-प्रतिस्थापन द्वारा देश की विदेशी विनिमय सम्बन्धी स्थिति सुदृढ़ हो और मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियों का भी प्रादुर्भाव नहीं हो सके। जे जे पोलक (J J Polak) ने भुगतान सन्तुलन पर पड़ने वाले प्रभावों के दृष्टिकोण से विनियोगों को निम्नलिखित तीन प्रकार से विभाजित किया है—

- (i) ऐसे विनियोग, जो निर्यात वृद्धि करने या आयात-प्रतिस्थापन करने वाली वस्तुएँ उत्पन्न करें। परिणामस्वरूप निर्यात आधिक्य उत्पन्न होगा।
- (ii) ऐसे विनियोग जो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करें जो पहले देश में ही बेचने वाली वस्तुओं या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का प्रतिस्थापन करें। इस स्थिति में भुगतान सन्तुलन की स्थिति में विनियोगों का प्रभाव तटस्थ होगा।
- (iii) ऐसे विनियोग जिनके कारण जो स्वदेश में ही बेची जाने वाली वस्तुओं की मात्रा में माँग से भी अधिक वृद्धि हो। वहाँ भुगतान सन्तुलन पर विपरीत प्रभाव होगा।

अतः विनियोगों के परिणामस्वरूप किसी भुगतान सन्तुलन की स्थिति पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों को स्थूलतम करने के लिए उपरोक्त वर्णित प्रथम श्रेणी के उत्पादक कार्यों पर विनियोगों को केन्द्रित करना चाहिए और तृतीय श्रेणी को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। द्वितीय श्रेणी के विनियोगों को बड़ी सावधानी के पश्चात् भुगतान सन्तुलन की स्थिति पर उनके विपरीत प्रभावों और अर्थव्यवस्था पर उनके लाभों की पारस्परिक तुलना के पश्चात् चुनना चाहिए।

किन्तु पोलक (Polak) के उपरोक्त मत की भी सीमाएँ हैं। ए. ई. काहन (A E Kahn) के अनुसार कुछ विनियोगों से मौद्रिक आय में वृद्धि हुए बिना ही वास्तविक आय में वृद्धि हो और जिसे आयातों पर व्यय किया जाए। यहाँ तक कि विनियोगों के परिणामस्वरूप वास्तविक आय में वृद्धि के साथ-साथ जब मौद्रिक आय में वृद्धि हो तो ऐसी स्थिति में आयातों का बढ़ना अनिवार्य नहीं है। वस्तुतः अर्द्ध-विकसित देशों में बड़ी मात्रा में आयातों के लिए इन देशों के उत्पादन की क्षमताएँ प्रवृत्ति ही बहुत सीमा तक उत्तरदायी हैं और उद्यो-उद्यो अर्थव्यवस्था का विकास रूढ़िवादी है तथा विभिन्न उद्योगों की स्थापना होती है। त्यो-त्यो देश के घरेलू उद्योग के लिए वस्तुओं की पूर्ति बढ़ जाती है और आयात की प्रवृत्ति (Propensity to Import) कम होने लग जाती है। साथ ही निर्यात-मुख उद्योगों में विनियोगों को केन्द्रित करना ही आर्थिक विकास की गारण्टी नहीं है। उदाहरणार्थ, भावन एवं अन्य उपनिवेशों में प्रथम युद्ध के पूर्व वागानो और निस्सारक (Extractive) उद्योगों

में बड़ी मात्रा में पूँजी विनियोजित की गई थी, जिनसे नियत-पदार्थों का उत्पादन होता था, किन्तु फिर भी इन विनियोगों का देश में आय और रोजगार बढ़ान तथा आर्थिक विकास को गति देने में योगदान अत्यल्प था। वास्तव में किसी भी विनियोग कार्यक्रम के भुगतान सन्तुलन पर पड़ने वाले प्रभावों का बिना समस्त विकास कार्यक्रम पर विचार किए हुए बिल्कुल अलग से कोई अनुमान लगाया जाना सम्भव नहीं है।

जिस प्रकार आर्थिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था में भुगतान सन्तुलन की विषयता की समस्या उत्पन्न होती है उसी प्रकार मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियों की समस्या भी बहुधा सामने आ खड़ी होती है जो आन्तरिक प्रसारण का संकेत है। आर्थिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था में बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर विशाल राशि व्यय की जाती है। बहुधा ये परियोजनाएँ दीर्घकाल में ही फल देने लगती हैं, अर्थात् इनका 'Gestation Period' अधिक होता है। इन कारणों से मौद्रिक आय बहुत बढ़ जाती है, किन्तु उस अनुपात में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन नहीं बढ़ पाता। परिणामस्वरूप मूल्य बढ़ने लग जाते हैं। कुछ देश बड़ी मात्रा में प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात करते हैं और इन देशों में कभी-कभी आर्थिक स्थिरता आयातक देश में आने वाली तेजी और मन्दी के कारण इन पदार्थों के उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न हो जाती है अतः विभिन्न क्षेत्रों में विनियोगों का आवंटन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे उपरोक्त दोनों प्रकार की आर्थिक स्थिरता या तो उत्पन्न ही नहीं या शीघ्र ही समाप्त हो जाए। यदि मुद्रा प्रसारिक प्रवृत्तियों का जन्म सामाजिक ऊपरी लागतों (Social Overhead Costs—SOC) में अत्यधिक विनियोग के कारण हुआ है तो कृषि उद्योग आदि प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं (Direct Productive Activities—DPA) में अधिक विनियोग किया जाना चाहिए। यदि यह विशाल पूँजी-गहन-परियोजनाओं में भारी पूँजी विनियोग के कारण हुआ है तो ऐसे उपभोक्ता उद्योगों और कम पूँजी-गहन-परियोजनाओं में विनियोगों का आवंटन किया जाना चाहिए, जो शीघ्र फलदायी हों। इसी प्रकार विदेशी व्यापार के कारण उत्पन्न होने वाली आन्तरिक स्थिरता को दूर करने के लिए उत्पादन की विविधीकरण करना चाहिए, अर्थात् विनियोगों को थोड़े से निर्यात के लिए उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में ही केन्द्रित नहीं करना चाहिए अपितु कई विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में सगुन कर अर्थव्यवस्था को लोचपूर्ण बनाना चाहिए। कृषि-व्यवस्था में अस्थिरता निवारण हेतु सिंचाई की व्यवस्था और मिश्रित खेती की जानी चाहिए।

5. काल श्रेणी का मानदण्ड

(The Time Factor Criteria)

किसी विनियोग कार्यक्रम पर विचार करते समय न केवल विनियोग की कुल राशि पर ही विचार करना चाहिए अपितु इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि उक्त परियोजना से कितने समय पश्चात् प्रतिफल मिलने लगेगा। इस विषय पर विचार करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अर्द्ध-विकसित देश सामाजिक

राजनीतिक और आर्थिक कारणों से विनियोगों के फलों से लाभान्वित होने के लिए दीर्घकाल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। अतः विनियोग-निर्धारण में बाल श्रेणी का भी बहुत महत्व है। इसलिए ए. के. सेन ने काल श्रेणी का मानदण्ड प्रस्तुत किया है। इस दण्ड में एक निश्चित अवधि में उत्पादन अधिक प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। यदि पूँजी और उत्पादन के अनुपात और बचत दर समान बनी रहे, तो पूँजी प्रधान और धर्म-प्रधान तकनीकों के मार्गों की रेखा खींची जा सकती है और यह ज्ञात किया जा सकता है कि दोनों में से किससे अधिक प्रतिफल प्राप्त होगा।

6. अन्य विचारणीय बातें

(i) आय वितरण—विभिन्न विकास कार्यक्रमों का आय के वितरण पर भी भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ता है। अतः नवीन विनियोग इस प्रकार के होने चाहिए जो आय और धन की असमानता को बढ़ाने की अपेक्षा कम करें। आर्थिक समानता और उत्पादकता के उद्देश्यों में लाभदायक समन्वय की आवश्यकता है।¹

(ii) मात्रा के साथ मूल्य और माँग पर भी ध्यान—विनियोग कार्यक्रम निर्धारित करते समय इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि उत्पादित वस्तु का मूल्य क्या है? केवल भौतिक मात्रा में अधिक उत्पत्ति करने वाला विनियोग अच्छा नहीं कहलाया जा सकता, यदि उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का न कोई मूल्य हो और न माँग ही हो। उदाहरणार्थ, अपेक्षाकृत कम पूँजी से जूतों की अधिक मात्रा उत्पादित की जा सकती है, किन्तु यदि इन जूतों की माँग और इनके लिए बाजार नहीं है, तो ऐसे विनियोग और उत्पादन से अर्थ-व्यवस्था लाभान्वित नहीं होगी।

(iii) विदेशी-विनिमय—भारत जैसे विकासशील देशों के लिए विदेशी विनिमय की भारी समस्या है। विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं और क्षेत्रों में पूँजी विनियोग विदेशी-विनिमय की स्थिति को भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। एक कारखाना दूसरे की अपेक्षा अधिक निर्यात की वस्तुएँ तैयार करने वाला हो सकता है। इसी प्रकार एक उद्योग दूसरे उद्योग की अपेक्षा आयातित वस्तुओं का अधिक उपयोग करने वाला हो सकता है। अतः ऐसे कार्यक्रमों क्षेत्रों, उद्योगों और परियोजनाओं में पूँजी विनियोजित की जानी चाहिए, जो निर्यात की क्षमता में वृद्धि करें और आयात की आवश्यकता को कम करें।

(iv) सन्तुलित विकास—इसके अतिरिक्त विनियोगों द्वारा अर्थ-व्यवस्था के सन्तुलित विकास पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पूँजी विनियोग के परिणाम-स्वरूप कृषि, उद्योग, यातायात तथा सन्देश-वाहन, सिंचाई, विद्युत और सामाजिक सेवाओं का समानान्तर विकास किया जाना आवश्यक है। ये सब एक-दूसरे के पूरक हैं।

विनियोगों के आवंटन में न केवल अर्थ-व्यवस्था के कृषि, उद्योग आदि विभिन्न क्षेत्रों के सन्तुलित विकास को ध्यान में रखा जाना चाहिए, अपितु देश के भौगोलिक क्षेत्रों के सन्तुलित विकास पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। रिछड़े हुए प्रदेशों में अपेक्षाकृत अधिक विनियोग किए जाने चाहिए।

अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्र (Sectors of Economy)

अर्थ-व्यवस्था को निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है—

(क) कृषि-क्षेत्र (Agricultural Sector)—अर्थ-व्यवस्था के इस क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि और तरसम्बन्धी कार्यक्रम, जैसे मिर्चाई, पशुपालन, मत्स्य-पालन, बागान, सामुदायिक विकास, वनारोपण, सहकारिता, भू-संरक्षण आदि कार्यक्रम सम्मिलित हैं। कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत, उन्नत और अल्पे खाद, बीज, यन्त्र और औजारों की व्यवस्था, कीट और रोगनाशक औषधियों की उपलब्धता, उचित-दर पर पर्याप्त मात्रा में साख सुविधाओं की उपलब्धि आदि कार्यक्रम सम्मिलित किए जाते हैं। मुख्यतः अर्द्ध-विकसित देश कृषि प्रधान होते हैं और उनकी अर्थ-व्यवस्था में कृषि-क्षेत्र का बहुत महत्त्व है।

(ख) उद्योग क्षेत्र (Industrial Sector)—इस क्षेत्र के अन्तर्गत निर्माण-उद्योग (Manufacturing Industries) तथा खनिज-व्यवसाय आते हैं। अर्धविकसित देशों में, उद्योग-धन्य कम विकसित होते हैं तथा वहाँ आर्थिक विकास की तीव्रगति देने और अर्थ-व्यवस्था का विविधीकरण करने के लिए तत्ती से औद्योगीकरण की आवश्यकता होती है। अतः नियोजन में इस क्षेत्र को भी पर्याप्त मात्रा में विनियोगों का आवंटन किए जाने की आवश्यकता है।

(ग) सेवा क्षेत्र (Service Sector)—सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत व्यवसाय प्रमुख रूप से, यातायात एवं सन्देश वाहन के साधन आते हैं, इसके अतिरिक्त, वित्तीय संस्थाएँ, प्रशासनिक सेवाएँ, शिक्षा, चिकित्सा, श्रमिक और पिछड़े वर्गों का कल्याण आदि कार्यक्रम भी इसी क्षेत्र में सम्मिलित किए जा सकते हैं। विकासार्थ नियोजन के परिणामस्वरूप कृषि और उद्योगों की प्रगति के लिए यातायात और अन्य सामाजिक ऊपरी पूँजी तथा जन-शक्ति के विकास के लिए सेवा-क्षेत्र पर ध्यान दिया जाना भी अत्यावश्यक है।

किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए ?

(Problem of Priority)

इस सम्बन्ध में विभिन्न विचार प्रस्तुत किए गए हैं। विवाद का मुख्य विषय यह है कि विनियोग कार्यक्रमों में कृषि को प्राथमिकता दी जाए या उद्योगों को। नियोजित आर्थिक विकास विनियोग कार्यक्रमों में कुछ लोग कृषि को महत्त्व अधिक देने का आग्रह करते हैं तो कुछ विचारक औद्योगीकरण के लिए अधिक मात्रा में विनियोगों को आवंटित किए जाने पर बल देते हैं। कृषि क्षेत्र में विशाल मात्रा में विनियोजन का समर्थन करने वाले इंग्लैण्ड आदि विकसित देशों का उदाहरण देते

हुए बहते हैं कि औद्योगीकरण के लिए कृषि का विकास एक आवश्यक शर्त है। यहाँ तक कि ब्रिटेन में भी 18वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में हुई कृषि की उल्लेखनीय प्रगति ने ही वहाँ होने वाली औद्योगिक क्रान्ति के लिए आधार तैयार किया। फिर अर्द्ध-विकसित देशों में तो, जिनकी अर्थ-व्यवस्था प्रमुख रूप से कृषि-प्रधान है, जब तक इनके कृषि आदि प्राथमिक क्षेत्रों को विकसित नहीं किया जाता, तब तक इनकी आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती। प्रोफेसर थियोडोर शुल्ज (Prof Theodore Schultz) के अनुसार “उच्च खाद्य वहाव वाली अर्थ-व्यवस्था में जहाँ समाज की अधिकांश आय का खाद्य पदार्थ प्रतिनिधित्व करते हैं कृषि के प्रतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में नई और अधिक अच्छी उत्पादन सम्भावनाओं की बहुत थोड़ी गुंजाइश होती है, क्योंकि खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए आवश्यक उत्पादन प्रयत्न ही कुल का बहुत बड़ा भाग होते हैं।”

इसके विपरीत दूसरे समुदाय के विचारकों का दृढ़ मत है कि अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में कृषि उत्पादकता बहुत कम होती है। साथ ही, जनसंख्या का भारी दबाव होता है। अतः इन देशों की मुख्य समस्या आय में तेजी से वृद्धि करने और बढ़ती हुई जनसंख्या को गैर कृषि-क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने की है। अतः इन देशों में कृषि पर ही विनियोगों को केन्द्रित करने से कार्य नहीं चलेगा। यह बुद्धिमत्तापूर्ण भी नहीं होगा अतः इन परिस्थितियों में कृषि की अपेक्षा उद्योगों में विनियोगों को अधिक केन्द्रित करने की आवश्यकता है। अप्रैल 1957 में टोकियो में हुई आर्थिक विकास की अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (International Conference on Economic Growth) में प्रो. कुरिहारा (Prof Kurihara) ने अर्द्ध-विकसित देशों के विकास के लिए कृषि आधारित विकास की नीति की निम्नलिखित कारणों से अनुपयुक्त बतलाया—

(i) उद्योगों की अपेक्षा कृषि की सीमान्त-उत्पादकता कम होती है। अतः इन देशों के सीमित साधनों को कृषि पर विनियोजित करना अमितव्ययितापूर्ण होगा।

(ii) कृषि क्षेत्र में उद्योगों की अपेक्षा बचत की प्रवृत्ति (Propensity to Save) कम होती है क्योंकि घनिक कृषकों में प्रदर्शन उपभोग (Conspicuous Consumption) की प्रवृत्ति होती है।

(iii) बढ़ती व्यापार की शर्तें कृषि पदार्थों के प्रतिकूल हो रही हैं, अतः, कृषि के विकास को महत्व देने और औद्योगिक विकास की उपेक्षा करने से इन देशों की भुगतान संतुलन की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

अतः प्रो. कुरिहारा के मतानुसार ‘कृषि और औद्योगिक उत्पादन में समतुलित वृद्धि एक बिलासिता है, जिसे केवल पर्याप्त वास्तविक पूँजी वाली उन्नत अर्थ-व्यवस्था ही सुगमतापूर्वक अपना सकती है, किन्तु जिसे पूँजी वाले देश कठिनाई से ही सह सकते हैं। एक अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था के लिए जहाँ सीमित बचत होती है और पूँजी को प्रयुक्त करने वाली विभिन्न परियोजनाएँ जिन्हें प्राप्त करने के लिए परस्पर

प्रतिस्पर्धा करती हैं, यह उपयुक्त होगा कि वे अपने प्रयत्नों को औद्योगिक क्षेत्र के द्रुत विकास के लिए ही केन्द्रित करें और कृषि-क्षेत्र को प्रतिक्रिया एवं प्रभावों द्वारा ही विकसित होने दें।¹

इसी प्रकार, कुछ विचारक सामाजिक ऊपरी पूँजी (SOC) के रूप में यातायात एवं संचार, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी आदि जनोपयोगी सेवाओं को महत्त्व देते हैं। उनका विश्वास है कि इन कार्यक्रमों में पूँजी का विनियोजन किया जाए जिससे कृषि और उद्योग आदि प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं के लिए आधार का निर्माण हो और ये तेजी से विकसित हो सकें।

कृषि में विनियोग क्यों ?

(Why Investment in Agriculture ?)

अधिकांश अर्द्ध-विकसित देश कृषि-प्रधान हैं और उनकी वर्तमान व्यवस्था में कृषि का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन देशों में कृषि, देशवासियों के रोजगार, राष्ट्रीय आय के उत्पादन, जनता की खाद्य सामग्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति, उद्योगों के लिए कच्चा माल, निर्यातों द्वारा विदेशी-विनिमय के अर्जन आदि का एक मुख्य साधन है। अतः देश के आर्थिक विकास के किसी भी कार्यक्रम में इस क्षेत्र के विकास की तकनीक भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। वास्तव में इन देशों में योजनाओं की सिद्धि बहुत बड़ी मात्रा में कृषि-क्षेत्र में विनियोगों के केन्द्रित करने पर ही निर्भर है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

1 कृषि-विकास से औद्योगिक विकास के लिए साधन उपलब्ध होना—कृषि विकास न केवल स्वयं अपने लिए, अपितु औद्योगिक विकास के लिए भी आवश्यक होता है। आज के प्रमुख उद्योग, विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में समृद्ध और विकासमान कृषि ने ही निर्माण उद्योगों के विकास के लिए आधारशिला प्रस्तुत की थी। कृषि-विकास से इसकी उत्पादकता और कुल उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे कृषि क्षेत्र में आय में वृद्धि होती है। इससे इस क्षेत्र में बचत की सम्भावनाएँ बढ़ती हैं, जिसको ऐच्छिक या बाधित रूप से कर या कृषि पदार्थों के अनिवार्य भुगतान आदि के द्वारा एकत्रित करके गैर-कृषि-क्षेत्रों में विकास के लिए साधन जुटाए जा सकते हैं। जापान ने अपने आर्थिक विकास में इस पद्धति का बड़ा उपयोग किया। सन् 1885 से 1915 तक की द्रुत आर्थिक विकास की अवधि में कृषि की उत्पादकता अच्छी कृषि पद्धतियों के कारण दुगुनी से भी अधिक हो गई। कुप्रकृ जनसंख्या की इस बढ़ी हुई आय का अधिकांश भाग भूमि पर भारी कर लगाकर ले लिया गया और इसका उपयोग गैर-कृषि-क्षेत्रों में प्रमुख रूप से उद्योगों के विकास में विनियोजित किया गया। वहाँ कृषि-क्षेत्र से इतनी अधिक आय प्राप्त की गई कि उस समय वहाँ की केन्द्रीय सरकार की कुल कर आय का 93.3% भाग भूमि पर करारोपण द्वारा प्राप्त किया जाता था। सोवियत रूस ने कृषि की उत्पादकता को

तेजी से बढ़ाया और कृषि क्षेत्र के आधिकार को द्रुत औद्योगीकरण की वित्त-व्यवस्था करने के उपयोग में लिया। इसी प्रकार चीन में 1953 और 1957 के बीच कृषि से प्राप्त कर आय का 40% से भी अधिक भाग गैर-कृषि-क्षेत्रों में विकास के लिए प्रयुक्त किया गया। सोल्हकोस्ट, इर्मा, युगांडा आदि भी कृषि आय के बहुत बड़े भाग को अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों की वित्त-व्यवस्था के लिए उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र का विकास बचत में वृद्धि करके विनियोजित किए जाने वाले कोषों में वृद्धि करता है, जिसका उपयोग यदि अन्य क्षेत्रों में उपयोग करके समग्र आर्थिक विकास की गति को तीव्र किया जा सकता है।

2. वृद्धिमान जनसंख्या को भोजन की उपलब्धि—अर्द्ध-विकसित देशों में वृद्धिमान जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराने और उनके भोजन तथा उपयोग स्तर का ऊँचा उठाने के लिए भी कृषि-कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर संचालित किया जाना आवश्यक है। कई अर्द्ध-विकसित देशों में जनसंख्या अधिक है और इसमें तेजी से वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त भारत जैसे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या की तो बात ही क्या, वर्तमान जनसंख्या के लिए भी खाद्यान्न उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं? एक अनुमान के अनुसार एशिया और अफ्रीका के निर्धन देशों की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए ही इन देशों में खाद्यान्न उत्पादन को 15% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत जैसे देश में तो यह जनसंख्या वृद्धि-दर 2.5% वार्षिक है, अतः इस दृष्टि से ही खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। साथ ही इन देशों में गुण और मात्रा दोनों ही दृष्टिकोणों से भोजन का स्तर निम्न है, जिसका इनकी कार्यक्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। धीलका, भारत और फिलीपीन्स में भोजन का वास्तविक उपभोग न्यूनतम आवश्यकता से भी 12 से 18% कम है। आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप ज्यों-ज्यों इन देशों की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, त्यों-त्यों प्रतिव्यक्ति भोजन पर व्यय में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप, शहरी जनसंख्या में वृद्धि होगी तथा गैर-कृषि व्यवसायों में नियोजित व्यक्तियों के अनुपात में वृद्धि होगी। उद्योग-धन्धों और अन्य व्यवसायों में लगे इन व्यक्तियों के खिलाने के लिए भी खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। इन सब कारणों से देश में खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता है जिसे कृषि के विकास द्वारा ही पूरा किया जा सकता है, अन्यथा भारत की तरह करोड़ों रुपये का अन्न विदेशों से आयात करना पड़ेगा और दुर्लभ विदेशी-मुद्रा को व्यय करना होगा।

3. औद्योगीकरण के लिए कच्चे माल की उपलब्धि—किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि औद्योगिक कच्चे माल के उत्पादन में भी वृद्धि हो। बहुत से उद्योगों में कृषि-जन्य कच्चे माल का ही उपयोग किया जाता है। कई अन्य उपभोक्ता उद्योगों के लिए धन्य उपज की आवश्यकता होती है। अतः जब तक पर्याप्त मात्रा में अच्छे किस्म के सस्ते कच्चे माल की उपलब्धि नहीं

हो सकती, तब तक औद्योगिक विकास नहीं हो सकता और न इन उद्योगों की प्रतिस्पर्धा शक्ति-वृद्धि सकती है। अतः, उद्योगों के लिए औद्योगिक कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि के लिए भी कृषि का विकास आवश्यक है।

4 विदेशी वित्तियोग की समस्या के समाधान में सहायक—यदि आर्थिक विकास कार्यक्रमों में कृषि विकास को महत्त्व नहीं दिया गया, तो देश में खाद्यान्नों और औद्योगिक कच्चे माल की कमी पड़ सकती है, और इन्हें विदेशों से प्रयात करने के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ेगी। वैसे भी किसी विकासमान अर्थव्यवस्था की विकास की प्रारम्भिक अवस्था में विदेशों से बड़ी मात्रा में मशीनें और अन्य पूँजीगत सामग्रियों का आयात करना पड़ता है। इसका भुगतान कृषि जन्य और अन्य कच्चे माल के निर्यात द्वारा ही किया जा सकता है। अतः कृषि में प्रतिस्पर्धा लागत पर उत्पादन वृद्धि आवश्यक है। नियोजन में विशाल परिपोजनाओं पर बड़ी मात्रा में धनराशि व्यय की जाती है। इससे लोगों की मौद्रिक आय बढ़ जाती है। साथ ही वस्तु और सेवा उत्पादन में भी वृद्धि नहीं होती। अतः अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा प्रसारक प्रवृत्तियाँ बढ़ने लगती हैं जिनका दमन वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति में वृद्धि से ही किया जा सकता है। इसके लिए भी या तो बहुत सीमा तक कृषि-उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ेगी या विदेशों से आयात करना पड़ेगा जिनके लिए पुनः विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। अतः इस समस्या के समाधान की विधि निर्यात योग्य पदार्थों की उत्पादन वृद्धि है जो अधिकांश अर्द्ध-विकसित देशों में प्राथमिक पदार्थ है। यद्यपि आर्थिक विकास के साथ-साथ देश में अर्द्ध निर्यात योग्य पदार्थों का उत्पादन भी बढ़ जाता है किन्तु जब तक अर्थ व्यवस्था इस स्थिति में नहीं पहुँचती, तब तक ऐसे देशों की विदेशी वित्तियोग स्थिति बहुत अधिक सीमा तक कृषि-पदार्थों के उत्पादन और निर्यात पर ही निर्भर करेगी। अतः इन देशों में निर्यातों द्वारा अधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन करने या अपने कृषि जन्य पदार्थों के आयात में कमी करने के लिए भी कृषि विकास का महत्त्व दिया जाना चाहिए।

5. औद्योगिक-क्षेत्र के लिए बाजार प्रस्तुत करना—विकासार्थ नियोजन में कृषि विकास, औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार प्रस्तुत करता है। ऐसे औद्योगिक विकास में, जिसमें उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की माँग नहीं हो कोई लाभ नहीं हो सकता। यदि केवल औद्योगिक विकास की ओर ही ध्यान दिया गया, तो अन्य क्षेत्रों की आय में वृद्धि नहीं होगी जिससे औद्योगिक वस्तुओं की माँग नहीं बढ़ पाएगी। किन्तु, यदि पूँजी वित्तियोजन के परिणामस्वरूप कृषि-उत्पादन में वृद्धि होती है तो कृषि में सलग्न व्यक्तियों की आय में वृद्धि होगी, जिसको औद्योगिक-वस्तुओं के क्रय पर व्यय किया जाएगा। ऐसा भारत जैसे अर्द्ध-विकसित देश के लिए तो और भी आवश्यक है, जहाँ की अधिकांश जनता कृषि व्यवसाय में सलग्न है।

6. उद्योगों के लिए श्रमिकों की पूर्ति—कृषि-विकास, औद्योगिक-क्षेत्र के लिए आवश्यक श्रम की पूर्ति सम्भव बनाता है। कृषि विकास के कार्यक्रमों से कृषि उत्पादन और कृषक की उत्पादकता में वृद्धि होती है और देश की जनसंख्या के लिए आवश्यक

कृषि उत्पादन हेतु कृषि व्यवसाय के संचालन के लिए कम व्यक्तियों की ही आवश्यकता रह जाती है, शेष व्यक्तियों में से औद्योगिक क्षेत्र अपने विकास के लिए श्रमिकों को प्राप्त कर सकता है।

7. कम पूँजी से बेरोजगारी की समस्या के समाधान में सहायता—अर्द्ध विकसित देश व्यापक बेरोजगारी, अर्द्ध-बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या से ग्रस्त हैं। वहाँ जन-शक्ति के एक बहुत बड़े भाग को रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इन देशों की विकास-योजनाओं का उद्देश्य, समस्त देशवासियों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना भी है। दूसरी ओर इन देशों में पूँजी की अत्यन्त कमी है। उद्योगों की स्थापना हेतु अपेक्षाकृत अधिक पूँजी की आवश्यकता होगी है, किन्तु कृषि-व्यवसाय में कम पूँजी से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता है।

उद्योगों में विनियोग (Investment in Industries)

योजना विनियोग में कृषि-क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देने का आशय यह नहीं है कि उद्योग एवं सेवाओं को कम महत्व दिया जाए। इनका विकास भी कृषि विकास के लिए आवश्यक है। आर्थिक विकास के किसी भी कार्यक्रम में इनकी प्रगति के लिए पर्याप्त प्रयत्न किए जाने चाहिए। कुछ व्यक्ति आर्थिक विकास का अर्थ औद्योगीकरण से समझते हैं। आर्थिक विकास प्रक्रिया में औद्योगीकरण का महत्व निम्नलिखित कारणों से है—

1 औद्योगिक विकास से कृषि-पदार्थों की माँग में वृद्धि—औद्योगिक-विकास द्वारा कृषि जन्य एवं अन्य प्राथमिक पदार्थों की माँग बढ़ती है। औद्योगिक-विकास के कारण, अधिक मात्रा में कृषि जन्य कच्चे माल की आवश्यकता होती है। औद्योगीकरण के कारण औद्योगिक-क्षेत्र में श्रमिकों की आय बढ़ती है, जिसका एक भाग भोजन पर व्यय किए जाने से भी कृषि पदार्थों की माँग बढ़ती है। इस प्रकार, औद्योगिक विकास, कृषि विकास को प्रभावित करता है। जिस प्रकार से कृषि क्षेत्र की बढ़ी हुई आय गैर कृषि क्षेत्र के निर्मित माल की खपत बढ़ाने में सहायक होती है उसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में होने वाली आय में वृद्धि कृषि पदार्थों की माँग में वृद्धि करके उसके विकास के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं।

2 अप्रयुक्त जन-शक्ति को रोजगार देने हेतु आवश्यक—निर्धन देशों में जनसंख्या की अधिकता और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कृषि पर जनसंख्या का भार अधिक है। वैकल्पिक उद्योगों के अभाव के कारण अधिकांश जनता जीविका-निर्वाह हेतु कृषि का अवलम्बन लेती है। किन्तु परम्परागत उत्पादन विधियों और कृषि व्यवसाय के अत्यन्त पिछड़े होने के कारण श्रमिकों की एक बहुत बड़ी संख्या या तो बेरोजगार रहती है या अर्द्ध-बेरोजगारी की शिकार रहती है। कृषि-व्यवसाय में यह महश्य बेरोजगारी अधिक व्याप्त रहती है। अनेक अनुमानों के अनुसार, कृषि-क्षेत्र की $\frac{1}{2}$ से $\frac{3}{4}$ जनसंख्या कृषि व्यवसाय की आवश्यकताओं से अधिक होती

है। औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप, देश की इस अप्रयुक्त जन-शक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकेंगे। इससे कृषि पर जनसंख्या का भार भी कम होगा और कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति उत्पादकता में वृद्धि होगी।

3 अर्थ-व्यवस्था को बहुमुखी बनाने के लिए आवश्यक—केवल कृषि या प्राथमिक व्यवसायों पर ही विनियोगों को केन्द्रित करने से अर्थ-व्यवस्था एकाकी हो जाती है। निर्धन देशों में जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि-व्यवसाय में लगा रहता है। निर्धन देशों की कृषि-क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता एकांगी तथा असन्तुलित अर्थ-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करती है। अर्थ-व्यवस्था को बहुमुखी बनाने के लिए इन देशों में द्वय औद्योगीकरण आवश्यक है। वैसे भी कृषि आदि व्यवसाय प्रकृति पर निर्भर होते हैं, जिनसे इस व्यवसाय में स्थिरता और निश्चितता नहीं आ पाती। अतः अर्थ-व्यवस्था का विविधीकरण आवश्यक है और इसके लिए द्वय औद्योगीकरण किया जाना चाहिए।

4 कृषि के लिए आवश्यक आदानों (Inputs) की उपलब्धि—कृषि-विकास की योजनाओं में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक औषधियाँ, ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यन्त्र तथा मीनार, सिंचाई के लिए पम्प, रहट आदि की आवश्यकता होती है। अतः इन वस्तुओं का उत्पादन और इनसे सम्बन्धित औद्योगिक विकास आवश्यक है। औद्योगीकरण मुख्यतः कृषि-उत्पन्न उद्योगों (Agro-industries) से कृषि विकास को प्रत्यक्ष सहायता मिलती है और कृषि-विकास के किसी भी कार्यक्रम में उक्त उद्योगों की कभी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

5 गैर-कृषि पदार्थों की माँग पूर्ति—आर्थिक विकास के कारण जनता की आय में वृद्धि होती है और कृषि पदार्थों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के गैर-कृषि पदार्थों की माँग में भी वृद्धि होती है। ऐसा नागरिक जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि के कारण भी होता है जो सुख-सुविधा की नई नई चीजों का उपयोग करना चाहती है। गैर-कृषि पदार्थों की बढ़ती हुई इस माँग की पूर्ति हेतु उद्योगों में भी पूँजी विनियोग की आवश्यकता होती है।

6 उद्योगों में श्रमिकों की सीमान्त उत्पादकता की अधिकता—कृषि में, उद्योगों की अपेक्षा, श्रम का सीमान्त उत्पादन-मूल्य कम होता है। औद्योगिक विकास से श्रमिकों का कृषि से उद्योगों में हस्तान्तरण होता है, जिसका आशय गैर-कृषि क्षेत्र की अपेक्षा-वृत्त कम मूल्य पर श्रम पूर्ति से होता है। इससे अर्थ-व्यवस्था में श्रम ससाधनों के वितरण में कुशलता बढ़ती है और श्रम एवं पूँजी विकास में अच्छा सन्तुलन स्थापित होने की अधिक सम्भावना रहती है।

7 सामाजिक एवं अन्य लाभ—ग्रामीण-समाज बहुधा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं। औद्योगीकरण से मानवीय कुशलताओं में वृद्धि होती है, जोखिम उठाने की प्रवृत्ति जाग्रत होती है तथा इससे सामाजिक सरचना अधिक प्रगतिशील और गतिशील (Dynamic) होती है। औद्योगीकरण द्वारा नागरिक जनसंख्या का अनुपात बढ़ता है, जो अधिक विवेकपूर्ण व तर्कशील

होती है। इससे व्यक्तिवादी और भौतिकवादी दृष्टिकोण का भी विकास होता है जो आर्थिक विकास के लिए अधिक उपयुक्त है। औद्योगिक विकास में शहरी बाजारों का विस्तार होना है, जिससे यातायात और संचार-साधनों का विकास होना है। साथ ही, इससे कृषि व्यापारीकरण भी होता है और कृषि क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियों को जन्म मिलता है।

सेवा-क्षेत्र में विनियोग (Investment in Services)

कृषि और उद्योग आदि की प्रत्यक्ष उत्पादक-क्रियाओं के अतिरिक्त, आर्थिक विकास के लिए सामाजिक ऊपरी पूंजी (SOC) का निर्माण आवश्यक है। इसके अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, संचार तथा पानी, विद्युत प्रकाश आदि जनोपयोगी सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। अर्थ-व्यवस्था के इस सेवा क्षेत्र में पूंजी-विनियोग करने से इनका विकास होगा, जिससे प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में भी निजी-विनियोग को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, ये सेवाएँ, प्रत्यक्ष रूप से कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए भी अनिवार्य हैं। कृषि उत्पादन को खेतों से मण्डियों, नगरों, बन्दरगाहों और विदेशों तक पहुँचाने के लिए सड़कें, रेलों बन्दरगाहों और जहाजरानी का विकास अनिवार्य है। इसी प्रकार, कारखानों और नगरों से कृषि के लिए आवश्यक आदानों जैसे—खाद, बीज, कृषि योजार, कीटनाशक, तकनीकी ज्ञान आदि खेतों तक पहुँचाने के लिए भी यातायात और संचार के साधन आवश्यक हैं। विभिन्न स्थानों से कारखानों तक कच्चे माल, ईंधन आदि को पहुँचाने और उद्योगों के निर्मित माल को बाजारों तक पहुँचा कर, औद्योगिक विकास में सहूल्यता देने के लिए भी यातायात एवं संचार साधनों का महत्व कम नहीं है। वास्तव में यातायात और सन्देशवाहन क्रिया भी अर्थ-व्यवस्था के स्नायु तन्तु हैं और अर्थ-व्यवस्था रही शरीर के पुष्कर संचालन के लिए यातायात और सन्देशवाहन के साधनों का विकसित होना अत्यन्त आवश्यक है। इनकी उपेक्षा करने पर कृषि और औद्योगिक विकास में भी निश्चिन्ता रूप से अवरोध (Bottle Necks) उपस्थित हो सकते हैं।

इसी प्रकार, सस्ती और पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्ध भी आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। सस्ती बिजली द्वारा लघु और कूटीर उद्योगों के विकास के बड़ी सहायता मिल सकती है। सिंचाई के लिए लघु और मध्यम सिंचाई योजनाओं में क्रिया-व्ययन में भी बिजली द्वारा बहुत सहायता मिलती है। बिजली द्वारा छोटे-छोटे पम्पिंग सेट और ट्यूब वेल चलाकर खेतों को सिंचित किया जा सकता है। बड़े उद्योगों के लिए सस्ती और पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्ध बहुत सहायक है। इस प्रकार विद्युत विकास द्वारा कृषि और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। शिक्षा, प्रशिक्षण तथा चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास देश की जन-शक्ति के विकास में सहायक होता है। अम, कल्याण और पिछड़ी जाति के कल्याण-कार्यक्रम इन वर्गों के विकास के लिए आवश्यक हैं। इन

समस्त सेवाओं द्वारा देश की जन-शक्ति की कार्य-कुशलता बढ़ती है और मानव-पूँजी का निर्माण होता है। देश के आर्थिक विकास के लिए मानवीय-पूँजी निर्माण में साधनों को विनियोजित करना भी आवश्यक है।

इस प्रकार, सामाजिक ऊपरी पूँजी (SOC) और सेवा-क्षेत्र में किए गए विनियोग कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के आदानों को सस्ता करके इनकी प्रत्यक्ष सहायता करते हैं। जब तक पर्याप्त विनियोगों द्वारा सस्ती और श्रेष्ठ सेवाओं की उालबि नही होगी, तब तक प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में विनियोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और न ही ये लाभप्रद होंगे। अतः अर्थ-व्यवस्था के इस क्षेत्र में भी पर्याप्त मात्रा में विनियोगों को आवंटित किया जाना चाहिए, जिससे सद्प्रभावों के कारण, बाद में, प्रत्यक्ष-उत्पादक-क्रियाओं में विनियोग अधिकाधिक किए जाएँगे और अर्थ-व्यवस्था विकास पथ पर अग्रसर होगी। प्रो हर्षमैन (Prof Hirschmann) के मतानुसार सामाजिक ऊपरी पूँजी (SOC) का निर्माण प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं को आने का आमन्त्रण देता है।

तीनों क्षेत्रों में समानान्तर व सन्तुलित विकास की आवश्यकता (Need of Balanced Growth in all the Three Sectors)

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि नियोजन प्रक्रिया में अर्थ-व्यवस्था के इन तीनों क्षेत्रों का अपना-अपना महत्त्व है और इन तीनों के समानान्तर और सन्तुलित विकास की आवश्यकता है। इसके अभाव में एक क्षेत्र का कम विकास, दूसरे क्षेत्र के विस्तार के लिए बाधा बन सकता है। उदाहरणार्थ यदि औद्योगिक उत्पादन का विस्तार होता है, किन्तु कृषि-क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं होती, तो औद्योगिक-क्षेत्र की अतिरिक्त आय प्राथमिक क्षेत्र की सीमित पूर्ति पर दबाव डालेगी और मुद्रा प्रसारिक प्रवृत्तियों का उदय होगा या बाह्य साधनों पर कुप्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार यदि गैर-कृषि-क्षेत्रों में वृद्धि हुए बिना कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है तो कृषि, पदार्थों की माँग पूर्ति की अपेक्षा कम हो जाएगी। परिणामस्वरूप, मूल्य कम होंगे, आय भी कम होगी और विकास में बाधाएँ पहुँचेंगी। अतः सभी क्षेत्रों का समानान्तर और सन्तुलित विकास किया जाना चाहिए।

किन्तु सन्तुलित विकास का आशय सभी क्षेत्रों में समान दर से आर्थिक विकास नहीं है। बहुधा आय-वृद्धि के साथ साथ आय का भाग अधिक अनुपात में, निमित्त-वस्तुओं पर व्यय किया जाता है। साथ ही, औद्योगिक विकास की गति बहुधा घटती रहती है, उसे तीव्र करने की आवश्यकता है। इसलिए विनियोग कार्यक्रमों में औद्योगिक-क्षेत्र का अपेक्षाकृत तीव्रता से विस्तार होना चाहिए, किन्तु, एक क्षेत्र या क्षेत्रों की अपेक्षा करके अन्य क्षेत्र या क्षेत्रों में विनियोगों को, केन्द्रित करना बुद्धिमत्तापूर्ण-नीति नहीं है। रोम में हुई विश्व जन-संख्या सम्मेलन (World Population Conference, 1954) के प्रतिवेदन के अनुसार विगत वर्षों में अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के कम आवादी वाले देशों में पूँजी और साधनों को कृषि क्षेत्र से उद्योगों की ओर प्रवृत्त करने से, न केवल कृषि विकास को ही प्रभावित किया, अपितु सामान्य अर्थ-व्यवस्था

में भी वांछनीय दबाव उत्पन्न कर दिए। वस्तुतः अर्द्ध-विकसित देशों में कृषि-क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और विनियोग कार्यक्रमों का निर्धारण करते समय अधिकांश राशि कृषि-विकास-कार्यक्रमों हेतु आवंटित की जानी चाहिए। आर्थिक इतिहास के अनुसार औद्योगीकरण और पूँजीनिर्माण के किसी भी कार्यक्रम की सफलता इस बात में निहित है कि उसके साथ शीघ्र फलदायक कृषि विकास परियोजनाएँ भी साथ-साथ प्रारम्भ की जाएँ। डी एस नाग के मतानुसार "कृषि-क्षेत्र में विनियोग कृषि उत्पादनता और कृषि पर अत्यन्त उल्लेखनीय प्रभाव पैदा कर सकते हैं। इसे अन्य क्षेत्रों के लिए माँग का सृजन करने और विशाल मात्रा में पूँजी-निर्माण में योगदान देने हेतु पहलकर्ता के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।"¹ जहाँ कहीं भी कृषि की उपेक्षा की गई है वहाँ या तो अर्थ-व्यवस्थाएँ स्थिर हो गई हैं या उनकी विकास-दरें गिर गई हैं। इंग्लैण्ड और चीन की अपेक्षा फ्रांस की अर्थ-व्यवस्था की सापेक्षिक स्थिरता का कारण, वहाँ कृषि-क्षेत्र की धीमी प्रगति है।

अतः विनियोग कार्यक्रमों में कृषि, उद्योग सेवाओं को यथोचित महत्त्व दिया जाना चाहिए। इन तीनों क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धा नहीं बरन् पूरक सम्भूता चाहिए। ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे से सम्बन्धित हैं और परस्पर निर्भर हैं। साथ ही, एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्र को विकास की प्रेरणा देता है।

विनियोग आवंटन सम्बन्धी कुछ नीतियाँ (Some Policies of Allocation of Investment)—समस्त देशों में एक ही परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं रहती। अतः इस सम्बन्ध में कोई सामान्य सिद्धान्त नहीं बनाया जा सकता। अर्द्ध-विकसित देशों को आज के विकसित देशों में अपनाई गई प्राथमिकताओं को भी उसी रूप में नहीं ग्रहण कर लेना चाहिए क्योंकि उनकी परिस्थितियाँ भिन्न थीं। अतः प्रत्येक देश को अपनी परिस्थितिनुसार विभिन्न क्षेत्रों में विनियोगों का आवंटन करना चाहिए। इस सम्बन्ध में अग्र पृष्ठ पर कुछ नीति सकेत दिए हुए हैं जिन्हें स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सशोधित करके अर्द्ध-विकसित देश अपना सकते हैं—

(i) किसी एक क्षेत्र के उद्योग अथवा आर्थिक क्रिया को दूसरी से अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए। इस प्रकार, एक क्षेत्र की उपेक्षा करके अन्य क्षेत्र में विनियोगों को केन्द्रित नहीं करना चाहिए। प्राथमिकताओं के निर्धारण में 'सीमान्त सामाजिक उत्पादकता के सिद्धान्त' का अनुसरण किया जाना चाहिए।

(ii) विनियोग-आवंटन पर विचार करते समय, स्थानीय परिस्थितियों जैसे—साधनों की स्थिति, आर्थिक विकास का स्तर, तकनीकी स्तर, सस्यागत घटकों एवं इसी प्रकार के अन्य तत्वों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

(iii) अन्य विकसित और अर्द्ध-विकसित देशों के अनुभव द्वारा भी लाभ उठाना चाहिए।

(iv) ऐसे देशों में जहाँ अतिरिक्त श्रम-शक्ति और सीमित पूँजी हो विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में कृषि, सिंचाई, यातायात एवं अन्य जनोपयोगी सेवाओं पर पूँजी विनियोजन अधिक लाभप्रद रहता है। इन क्षेत्रों में अल्प पूँजी से ही अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता है, साथ ही, निर्माणी उद्योगों को भी विकसित किया जाना चाहिए।

(v) विकासमान अर्थ-व्यवस्था में यह सम्भव नहीं होता कि अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्र पूर्ण-संतुलित रूप से समान-दर से प्रगति करें। आर्थिक विकास अवधि में कहीं आधिक्य और कहीं कमी का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। किन्तु इस सम्बन्ध में अधिकाधिक सूचनाएँ तथा आँकड़े एकत्रित करके सीमित साधनों को उन क्षेत्रों में प्रयुक्त करना चाहिए, जहाँ उनका सर्वोत्तम उपयोग हो।



आर्थिक विकास की दृष्टि से नियोजन को अपनाने वाले, अर्द्ध-विकसित देशों के पास मुख्यतः साधनों तथा पूँजी का अभाव होता है। इसके विपरीत, पूँजी विनियोग के लिए क्षेत्रों, परियोजनाओं और उद्योगों की बहुलता होती है। इनमें से प्रत्येक में पूँजी का समुचित विनियोग करने पर ही आर्थिक विकास को गति दी जा सकती है। अतः इन देशों की प्रमुख समस्या यह होती है कि इन विनियोगों का उचित और विवेकपूर्ण आवंटन किन प्रकार हो, पिछले अध्यायों में हम विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में विनियोगों के आवंटन पर विचार कर चुके हैं। इस अध्याय में हम विशेषतः भौगोलिक क्षेत्रों या प्रदेशों में विनियोगों के आवंटन पर विचार करेंगे।

विभिन्न क्षेत्रों में विनियोगों का आवंटन

(Allocation of Investment Between Different Regions)

विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विनियोगों के आवंटन के सम्बन्ध में कई विकल्प हो सकते हैं। एक विकल्प यह है कि देश के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में अधिक विनियोग किया जाए। अन्य विकल्प यह हो सकता है कि विकास की अधिक संभावना वाले क्षेत्रों में, अधिक राशि विनियोजित की जाए। एक और विकल्प यह हो सकता है कि सब क्षेत्रों में समान रूप से विनियोगों का आवंटन किया जाए।

1 पिछड़े क्षेत्रों में अधिक आवंटन - किसी देश के स्याथित्व और समृद्धि के लिए न केवल द्रुत गति से आर्थिक विकास आवश्यक है अपितु यह भी आवश्यक है कि उस देश के सभी क्षेत्रों का तीव्रता से और समतुलित आर्थिक विकास हो। सभी क्षेत्र और भारी जनता उस विकास और समृद्धि में भागीदार बनें। यह तभी सम्भव है, जबकि देश के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में अधिक पूँजी का विनियोजन किया जाए। अधिकांश विकासशील देश न केवल अर्द्ध-विकसित ही हैं, अपितु इनके विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति और समृद्धि में भी भारी अन्तर है। विभिन्न क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय में बड़ी विषमता है। उदाहरणार्थ, भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में, अर्थात् 1965-66 में, बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय केवल

212 91 रु थी। इसके विपरीत, पश्चिमी बंगाल की प्रति व्यक्ति आय उक्त वर्ष में 433 43 रु थी, जो बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय की तुलना से भी अधिक थी। असंतुलित विकास के कारण ही देश के कुछ राज्य अन्य राज्यों से बहुत पिछड़े हुए हैं। विभिन्न क्षेत्रवासियों के जीवन स्तर में भारी अंतर है। यह बात कदापि उचित नहीं है। किसी एक क्षेत्र की निर्बलता से अन्य समृद्ध क्षेत्र के लिए भी कभी-कभी खतरा पैदा हो सकता है। फिर आर्थिक-नियोजन का उद्देश्य देश की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना है। राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तब तक सम्भव नहीं है जब तक इन क्षेत्रों की आय में वृद्धि नहीं हो और यह अभी सम्भव है जबकि इन पिछड़े हुए क्षेत्रों में पर्याप्त पूँजी विनियोजन किया जाए। देश के सभी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए भी इन प्रदेशों में अधिक पूँजी विनियोग और उद्योग-धन्धों की स्थापना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ विकास हेतु आवश्यक सामाजिक और आर्थिक ऊपरी सुविधाओं, रेलों, सड़कों, विद्युत सिंचाई की सुविधाओं, शिक्षा तथा चिकित्सा आदि की सुविधाओं का अभाव होता है। इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति देने के लिए तथा कृषि और उद्योगों के विकास हेतु इन आधारभूत सुविधाओं के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता होती है और इनमें भारी पूँजी-विनियोग की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यदि देश के समस्त भागों में प्रति व्यक्ति आय में समान दर से वृद्धि करना चाहे तब भी पिछड़े क्षेत्रों में अधिक विकास कार्यक्रम आरम्भ किए जाने चाहिए। किन्तु आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टि से केवल यही आवश्यक नहीं है कि देश के सभी क्षेत्र समान-दर से विकसित हो अर्थात् यह भी अनिवार्य है कि पिछड़े क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक गति से विकास करें। इसके लिए यह आवश्यक है कि देश के इन पिछड़े और निर्धन क्षेत्रों में विनियोगों का अधिकाधिक भाग आवंटित किया जाए। सार्वजनिक-क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना के समय इस असंतुलित क्षेत्रीय-विकास की विचारधारा को अधिक ध्यान में रखा जाए। असंतुलित क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य की प्राप्ति अल्पकाल में नहीं हो सकती। यह एक दीर्घकालीन उद्देश्य है जिसकी पूर्ति करने के लिए पिछड़े हुए क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक ऊपरी लागतों पर बड़े पैमाने पर पूँजी-विनियोग की आवश्यकता है।

2 विकास की सम्भावना वाले क्षेत्रों में विनियोग—वस्तुतः पिछड़े क्षेत्रों में अधिक विनियोग किए जाने का तर्क आर्थिक की अपेक्षा सामाजिक कारणों पर अधिक आधारित है। अतः विकास कार्य अथवा कार्यक्रम वहाँ संचालित किए जाने चाहिए, जहाँ उनकी सफलता की अधिक सम्भावना हो। इन अर्द्ध विकसित देशों में विनियोग योग्य साधनों का अत्यन्त अभाव होता है। अतः इनका उपयोग उन स्थानों एवं परिस्थितियों में किया जाना उपयुक्त है जहाँ इनकी उत्पादकता अधिक हो और देश को अधिकतम लाभ हो। प्रत्येक देश में सब क्षेत्र द्रुत विकास के लिए विशेष रूप से समग्र अर्थ-व्यवस्था के दृष्टिकोण से, समान रूप से उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि सब स्थानों और क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियाँ समान नहीं होती। कुछ क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियाँ विकास के अधिक अनुकूल होती हैं तो कुछ क्षेत्रों में विकास में बाधक

सत्त्व अधिक प्रबल होते हैं। इसलिए सब क्षेत्रों में संतुलित विकास और विनियोगों के समान आवंटन की नीति वांछनीय नहीं हो सकती। अत्यधिक रेगिस्तानी क्षेत्रों या पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक पूँजी-विनियोग करना उत्पादन-वृद्धि की दृष्टि से अधिक लाभप्रद नहीं होगा। इसके विपरीत यदि यही विनियोग विद्यालय कृषि-क्षेत्रों में कृषि-विकास के व्यापक कार्यक्रमों और गहन-कृषि के लिए किए गए, खनिज संपदा में समृद्ध क्षेत्रों में किए गए, किसी विशाल नदी घाटी परियोजना के संचालन के लिए किए गए तो ऐसा न केवल उस क्षेत्र के लिए अपितु समग्र अर्थ-व्यवस्था के लिए हितकर होगा। प्रत्येक अर्थ-व्यवस्था में कुछ वृद्धिमान बिन्दु (Growing Points) होते हैं। उसी प्रकार, कुछ क्षेत्रों में विकास की सम्भावनाएँ अधिक होती हैं और विनियोगों द्वारा इन्हीं सम्भावनाओं का विदोहन करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक साधनों में धनी क्षेत्रों में विनियोग आवंटन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

3 सभी क्षेत्रों में समान-रूप से विनियोग आवंटन—विनियोग आवंटन के लिए देश के सभी क्षेत्रों में समान रूप से विनियोगों का आवंटन किया जाना चाहिए, यह सिद्धान्त ग्यापपूर्ण है और समानता के सिद्धान्त पर आधारित है किन्तु अधिक व्यावहारिक नहीं है। सब क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियाँ और प्राकृतिक साधन भिन्न-भिन्न होते हैं। इन विभिन्न क्षेत्रों की विकास क्षमताएँ भी भिन्न-भिन्न होती हैं। जनसंख्या और क्षेत्रफल में अन्तर होता है साथ ही विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताएँ भिन्न-भिन्न होती हैं। अतः सब क्षेत्रों के लिए समान विनियोगों की नीति व्यावहारिक है।

उचित विनियोग-नीति—उचित विनियोग-नीति में उपरोक्त तीनों सिद्धान्तों, मुख्य रूप से प्रथम दो दृष्टिकोणों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। वस्तुतः किसी दीर्घकालीन नियोजन में न केवल समस्त देश के विकास के प्रयत्न किए जाने चाहिए, अपितु पिछड़े हुए क्षेत्रों को भी अन्य क्षेत्रों के समान-स्तर पर लाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से विनियोग-आवंटन में पिछड़े हुए क्षेत्रों को कुछ रियायत दी जानी चाहिए। किन्तु फिर उन प्रदेशों और क्षेत्रों को अधिक राशि आवंटित की जानी चाहिए, जिनमें विकास की सम्भावनाएँ (Growth Potential) अधिक हों। विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में इस प्रकार की नीति और भी आवश्यक है, क्योंकि सीमित साधन होने के कारण अधिक विकास के कार्यक्रमों को ऐसे केन्द्रों पर स्थापित किया जाना चाहिए, जहाँ विनियोजन के अनुकूल फल प्राप्त होते हैं। बाद की अवस्थाओं में संतुलित प्रादेशिक विकास की दृष्टि से विनियोगों का आवंटन किए जाने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

भारतीय-नियोजन और संतुलित प्रादेशिक-विकास

भारत के विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक विकास के स्तर में पर्याप्त भिन्नता है। देश के विभिन्न राज्यों में ही नहीं, अपितु एव राज्य के अन्दर भी विभिन्न क्षेत्रों में

आर्थिक प्रगति के स्तर में पर्याप्त अन्तर है। भारतीय नियोजन में देश के सन्तुलित विकास के प्रयत्न किए गए हैं। पिछड़े हुए क्षेत्रों को उन्नत करने के लिए विशेष कार्यक्रम अपनाए गए हैं, किन्तु विकास की दृष्टि से अधिक सूक्ष्म क्षेत्रों में विनियोगों की ओर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार, विनियोग-नीति का आधार जहाँ समस्त अर्थ व्यवस्था और देश की दृष्टि से आर्थिक विकास को गति देने वाले क्षेत्रों में अधिक विनियोग करना रहा है, वहाँ सन्तुलित प्रादेशिक विकास की दृष्टि से भी विनियोग कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। देश की प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक प्रगति की दृष्टि में क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने और क्षेत्रीय सन्तुलन स्थापित करने की ओर भी, योजना-निर्माताओं का ध्यान गया है। यद्यपि, प्रथम पंचवर्षीय योजना में हम दिशा में विशेष उपाय प्रयास में नहीं लाए जा सके, किन्तु द्वितीय एवं तृतीय विकास योजनाओं में क्षेत्रीय-विषमताओं को दूर करने की आवश्यकता पर विशेष दल दिया गया और इस उद्देश्य से कुछ कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं।

सरकार ने अपनी लाइसेंस आदि नीतियों द्वारा सन्तुलित विनियोगों को प्रभावित किया है। मोटरगाड़ियाँ रसायन उद्योग, कागज उद्योग आदि के लिए दिए गए ला सेन्सों से पता चलता है कि इनमें पिछड़े क्षेत्रों का अनुपात बढ़ गया है। सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक-परियोजनाओं के बारे में जो निश्चय किए गए, उनसे स्पष्ट होता है कि वे दूर-दूर हैं एवं उनसे विभिन्न प्रदेशों में औद्योगिक विकास होगा। उड़ीसा में हवेली इस्पात कारखाना और उर्वरक कारखाने का विस्तार, असम में दूनमाटी तेलशोधन कारखाना व उर्वरक कारखाना और प्राकृतिक गैस का उपयोग एवं वितरण, केरल में फाइटो रासायनिक कारखाना, उर्वरक कारखाने की क्षमता का विस्तार तथा एक जहाजी यार्ड का निर्माण, आन्ध्र प्रदेश में रासायनिक औषध कारखाना, विशाखापट्टनम् की सूखी गोदी, हिन्दुस्तान शिपयार्ड का विस्तार प्राग टूल्स और आन्ध्र पेपर मिल्स का विस्तार, मध्य प्रदेश में नोटो के कागज का कारखाना, मुनिय दी ऊष्म सह कारखाना परियोजना, नेपा पेपर मिल्स का विस्तार, भिलाई इस्पात कारखाना और बिजली के भारी सामान की परियोजना, उत्तर-प्रदेश में कीटाणुनाशक औषधियों का उत्पादन, उर्वरक कारखाना, ऊष्म सह कारखाना तथा यन्त्रों के कारखाने का विस्तार, राजस्थान में ताँबे तथा जस्ते की खानों का विस्तार एवं परिद्रावकी की स्थापना, सूक्ष्म-यन्त्र-कारखाना, पंजाब में मशीनी औजारों का कारखाना, मद्रास में शल्य उपकरणों, निवेली लिग्नाइट उच्च ताप कार्बनीकरण कारखाना, टेलीप्रिन्टर कारखाना और इस्पात ढलाई कारखाना, गुजरात में तेल-शोधक कारखाना और जम्मू कश्मीर में सीमेन्ट के कारखानों आदि की स्थापना से पिछड़े क्षेत्रों को विकसित होने का अवसर मिलेगा। विकास योजना में निजी-क्षेत्र में कारखानों की स्थापना पर किया गया पूँजी-विनियोग भी सन्तुलित औद्योगिक विकास में सहायक होगा। जैसे उत्तर-प्रदेश में एल्यूमीनियम कारखाना, राजस्थान में उर्वरक, नाइलोन, कास्टिक सोडा, पी. वी. सी. आदि के कारखाने, असम में नकसी रबड़, पोलियिलीन तथा कार्बन ब्लेक की परियोजनाएँ और कागज की लुगदी तैयार करने

का कारखाना तथा केरल में मोटरो के रबड़-टायर तैयार करने के कारखाने देश में सन्तुलित औद्योगिक विकास में सहायक होंगे ।

इसी प्रकार ग्रामीण कार्यक्रम (Rural Works Programme) के लिए क्षेत्रों का चुनाव करते समय उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, जहाँ जनसंख्या का दबाव अधिक हो और प्राकृतिक साधन कम विकसित हो । तृतीय योजना में तो पिछड़े क्षेत्र में 'औद्योगिक क्षेत्र' (Industrial Development Areas) की स्थापना का भी कार्यक्रम था । चतुर्थ योजना में भी विनियोग आवंटन में पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया ।

किन्तु इतना सब होते हुए भी भारतीय नियोजन में 'विकासमान बिन्दुओं' (Growing Points) की उपेक्षा नहीं की गई है । ऐसी परियोजनाओं को, चाहे वे पिछड़े क्षेत्रों में हों या समृद्ध क्षेत्रों में, विनियोगों के आवंटन में प्राथमिकता दी गई है ।

निजी और सार्वजनिक-क्षेत्रों में विनियोगों का आवंटन

(Allocation of Investment Between Private
and Public Sectors)

प्राचीन काल में यह मत याप्त था कि राज्य को देश की आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और व्यक्तियों और संस्थाओं को आर्थिक क्रियाओं में पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए। सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी में आर्थिक जगत में परम्परावादी अर्थशास्त्रियों के निहस्तक्षेप के सिद्धान्त को मान्यता मिली हुई थी। न केवल आर्थिक क्षेत्र में किन्तु अन्य क्षेत्रों में भी सरकारी कार्यों को सीमित रखने पर ही बल दिया गया था। लोगों का विश्वास था कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो न्यूनतम शासन करे (The Government is best which governs the least)। इसके साथ ही लोगों का यह भी विचार था कि राज्य आर्थिक क्रियाओं का संचालन सुचारु रूप से मितव्ययितापूर्वक नहीं कर सकता है। अर्थशास्त्र के एडम स्मिथ (Adam Smith) का विश्वास था कि 'सम्राट् और व्यापारी से अधिक दो अर्थ विरोधी चरित्र नहीं होते' (Not two characters are more inconsistent than those of a sovereign and the trader) किन्तु 19वीं शताब्दी में सरकारी-नियन्त्रण तथा नियमन का मार्ग प्रशस्त होने लगा। 20वीं शताब्दी के आरम्भ में स्वतन्त्र उपक्रम वाली अर्थ-व्यवस्था के दोष स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगे। राज्य हस्तक्षेप-मुक्त उपक्रम के कारण गलघोटूँ प्रतियोगिता (Cut throat Competition), आर्थिक शोषण, व्यापार-चक्र, आर्थिक-संकट एवं अन्य सामाजिक कुरीतियों आदि का प्रादुर्भाव हुआ। स्वतन्त्र उपक्रम पर आधारित अर्थ-व्यवस्था के इन दोषों ने इसकी उपयुक्तता पर से विश्वास उठा दिया। अब यह स्वीकार किया जाने लगा कि आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियमन एवं नियन्त्रण-मात्र ही पर्याप्त नहीं हैं, अपितु अब सरकार को आर्थिक क्रियाओं में प्रत्यक्ष रूप से भी भाग लेना चाहिए। इस प्रकार अब सरकारें भी, आर्थिक क्रियाओं को संचालित करने लगीं और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रादुर्भाव हुआ। आज लगभग सभी देशों में किसी न किसी रूप में सार्वजनिक-क्षेत्र पाया जाता है। इस प्रकार, कई देशों में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था (Mixed Economy) का जन्म हुआ है।

सार्वजनिक और निजी-क्षेत्र का अर्थ (Meaning of Public and Private Sector)

निजी क्षेत्र और निजी-उद्यम पर्यायवाची शब्द हैं। निजी-क्षेत्र का आशय उन समस्त उत्पादन इकाइयों से होता है जो किसी देश में निजी-व्यक्तियों के स्वामित्व, नियन्त्रण और प्रबन्ध में सरकार के सामान्य नियमों के अनुसार संचालित की जाती हैं। इस क्षेत्र में सभी प्रकार के निजी-उद्यम जैसे—घरेलू और विदेशी निजी-उद्योग तथा कम्पनी-क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। निजी-क्षेत्र में वे सभी व्यापारिक, औद्योगिक और व्यावसायिक कारोबार शामिल होते हैं, जो व्यक्तिगत पहल के परिणाम हैं। इसके विपरीत सार्वजनिक क्षेत्र का आशय समस्त राजकीय उपक्रमों से है। राजकीय-उपक्रम का अर्थ ऐसी व्यावसायिक संस्था से होता है, जिस पर राज्य का स्वामित्व हो अथवा जिसकी प्रबन्ध व्यवस्था राजकीय मन्त्र द्वारा की जाती हो या स्वामित्व और नियन्त्रण दोनों ही राज्य के अधीन हो। सार्वजनिक क्षेत्र में मुख्यतः सरकारी कम्पनियाँ, राजकीय विभागों द्वारा संचालित उद्योग और सार्वजनिक निगम आते हैं। निजी-क्षेत्र का अविकाश भाग छोटे-छोटे असरय उत्पादकों एवं कतिपय बड़े उद्योग-पतियों से मिलकर बनता है, जो देश में सर्वत्र फैले हुए होते हैं। निजी-क्षेत्र में मुख्यतः एकाकी व्यापारी, साझेदारी संगठन, प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कम्पनियाँ आदि के रूप में उत्पादक इकाइयाँ आती हैं।

भारत सरकार ने निजी और सार्वजनिक-क्षेत्र को निम्न प्रकार परिभाषित किया है—

सार्वजनिक-क्षेत्र—समस्त विभागीय उपक्रम, कम्पनियाँ और परियोजनाएँ, जो पूर्ण रूप से सरकार (केन्द्रीय या राज्य) के स्वामित्व और संचालन में हों, समस्त विभागीय-उपक्रम, कम्पनियाँ या परियोजनाएँ, जिसमें सरकारी पूँजी का विनियोग 51% या इससे अधिक हो, समस्त विधान द्वारा स्थापित संस्थाएँ और निगम सार्वजनिक क्षेत्र में माने जा सकते हैं।

निजी-क्षेत्र—संस्थापित व्यापार और उद्योग में सलग्न प्राइवेट पार्टियाँ और वे कम्पनियाँ एवं उपक्रम, जिसमें सरकारी (केन्द्र अथवा राज्य) विनियोग 51% से कम है निजी-क्षेत्र में मानी जा सकती है।

आर्थिक विकास में निजी-क्षेत्र का महत्त्व (Importance of Private Sector in Economic Development)

1. **आर्थिक विकास का आदि स्रोत**—विश्व के आर्थिक इतिहास को देखने से, ज्ञात होता है कि उसकी इतनी अधिक आर्थिक प्रगति का श्रेय निजी-क्षेत्र को है। अमेरिका, फ्रांस, नार्वे, स्वीडन, जर्मनी आदि देशों ने निजी क्षेत्र द्वारा ही इतनी अधिक प्रगति की है। अमेरिका को तो निजी-उद्यम-पद्धति पर गर्व है। अमेरिका अपनी अर्थ-व्यवस्था में निजी-उद्यम को प्रधानता देने के लिए वचनबद्ध है। वहाँ राष्ट्रीय संकट के समय भी सार्वजनिक पहल को दूसरा स्थान दिया जाता है। वस्तुतः वह इतनी तीव्र गति से आर्थिक उन्नति करने में निजी-उद्यम के द्वारा ही

सफल हुआ है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् जर्मनी में भी अर्थ-व्यवस्था के प्रबन्ध में राज-मत्ता का प्रयोग कम से कम करने की नीति अपनाई गई है। डॉ. इराहर्ड ने, जिनका दावा है कि युद्धोत्तरकाल में जर्मनी प्रतियोगिता द्वारा समृद्ध होने में सफल हुआ है सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध आवाज उठाई है। जापान की आर्थिक उन्नति में निजी-क्षेत्र का विशेष योगदान रहा है। फ्रांस, नीदरलैंड, नावें, स्वीडन और ब्रिटेन में भी निजी-क्षेत्र का योग कुल राष्ट्रीय आय में 75% से 80% के लगभग है। आधुनिक विश्व में भी सोवियत संघ, पूर्वी यूरोप के देश, चीन, उत्तरी कोरिया और वियतनाम आदि साम्यवादी देशों को छोड़कर अन्य देशों में निजी-उपक्रम की प्रधानता है। यहाँ तक कि पूर्वी-यूरोपीय देशों में भी, कृपि कुछ सीमा तक निजी क्षेत्र के व्यक्तियों के हाथ में ही है।

आधुनिक प्रगट-विकसित देशों में भी निजी-उपक्रम का बहुत महत्त्व है। इससे आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। लेबनान और उरगोय में स्वतन्त्र बाजार पद्धति के आधार पर अर्थ-व्यवस्था कार्य कर रही है। पाकिस्तान, थाइलैंड, फारमोसा वंशणी कोरिया, मनेशिया, नाईजीरिया, प्रजेंटोइना, ब्राजील, चिली, कोलम्बिया, वेनेजुएला इत्यादि देशों में सामान्यतः मिश्रित अर्थ-व्यवस्था है, जिसमें निजी-क्षेत्र की ओर अधिक झुकाव है। इन देशों की अर्थ-व्यवस्था में राज्य नियन्त्रण बहुधा केवल उन क्षेत्रों पर है जिनमें निजी उद्यम कार्य करने के लिए या तो तैयार नहीं है अथवा उसमें इनकी सामर्थ्य नहीं है, किन्तु मैक्सिको और भारत में सरकारी-क्षेत्र एक विशाल निजी क्षेत्र के साथ कार्य कर रहा है।

2 जनतान्त्रिक विचारधारा—विश्व के जनतान्त्रिक देश राजनीतिक स्वतन्त्रता के समान आर्थिक स्वतन्त्रता के भी दृढ़ समर्थक हैं। प्रजातान्त्रिक शासन में नागरिकों को कुत्र सीमाओं के साथ आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान की जाती है। उन्हें निजी-सम्पत्ति का अधिकार होता है और उत्पादन साधनों को क्रय करने, अपनी सम्पत्ति का इच्छा-नुसार उपयोग करने, विक्रय आदि की स्वतन्त्रता होती है। ऐसी स्थिति में, निजी-उपक्रम का होना स्वाभाविक ही है। निजी उपक्रम की पूर्ण समाप्ति केवल साम्यवादी देशों में ही हो सकती है। अतः विश्व का जो भी देश जनतान्त्रिक मूल्यों में विश्वास करता है, वहाँ निजी-उपक्रम का आर्थिक विकास में योगदान महत्त्वपूर्ण होता है।

3 सरकार के पास उत्पादन साधनों की सीमितता—यदि ऐसे देश नियोजित अर्थ-व्यवस्था के संचालन हेतु ममस्त उत्पत्ति के साधनों को सावजनिक-क्षेत्र में लेना चाहें तो सरकार को उसके उपलब्ध साधनों का बहुत बड़ा भाग दीर्घकाल तक मुद्राबजे के रूप में देना पड़ेगा। इससे अन्य क्षेत्रों के लिए सरकार के पास साधनों की कमी पड़ेगी और आर्थिक प्रगति अवरोध हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, जब निजी-उपक्रमियों को राष्ट्रीयकरण करके क्षतिपूर्ति दी जाती है तो उनके पास अन्य उत्पादन के साधनों को क्रय करने और अन्य उपक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए धन पहुँच जाता है, इस प्रकार निजी क्षेत्र का अस्तित्व बना रहता है। प्रगट-विकसित देशों में वस्तुतः उद्योग, उत्पादन तथा उपक्रम के इतने अधिक क्षेत्र होते हैं कि सरकार अपने समस्त साधनों

से भी इन्हें स्थापित नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में, उचित नीति यही है कि निजी-क्षेत्र के व्यवसायों को कार्य करने दिया जाए और राज्य ऐसे नवीन व्यवसायों को प्रारम्भ एवं विकसित करे जिनकी देश को अधिक आवश्यकता हो।

4 निजी-उपक्रम की क्षमता का लाभ—निजी उपक्रम प्रणाली में निजी सम्पत्ति (Private Property) और निजी लाभ की छूट होती है। पूँजीपतियों को लाभ कमाने और उसका उपयोग करने की स्वतन्त्रता होती है अतः वे अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए वे उत्पादन कार्यों को अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययिता और कुशलतापूर्वक संचालन करते हैं। इसके विपरीत, सार्वजनिक क्षेत्रों की कार्य-क्षमता इतनी अधिक नहीं होती क्योंकि उनका प्रबंध आदि ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिनका हित उनसे बहुत अधिक नहीं बढ़ा होता। भारत के कई सार्वजनिक उपक्रम भारतीय अर्थ व्यवस्था पर भार बने हुए हैं। वास्तव में सार्वजनिक क्षेत्र की अपेक्षा निजी क्षेत्र की कार्यक्षमता अधिक श्रेष्ठ होती है। लाभ कमाने की छूट के कारण पूँजीपतियों में उत्पादन प्रेरणा उत्पन्न होती है और वे अधिक बचत और विनियोग करने को तत्पर होते हैं। निजी-क्षेत्र का अस्तित्व सामान्य जनता में सरकार के प्रति विश्वास जाग्रत करता है और व्यक्तिगत अर्थ साधन राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध होते रहते हैं।

5 विदेशी पूँजी और वित्तीय साधनों की प्राप्ति—योजनाओं के लिए निर्धारित विशाल कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था केवल आन्तरिक साधनों से ही सम्भव नहीं हो सकती। कुछ अपवादों को छोड़कर प्रत्येक देश के आर्थिक विकास में विदेशी पूँजी और वित्तीय साधनों से पर्याप्त सहायता मिली है। अर्द्ध विकसित राष्ट्रों को योजनाओं को पूर्ण करने के लिए विदेशी पूँजी की आवश्यकता है किन्तु विदेशी पूँजीपति और उद्योगपति उन देशों में ही पूँजी विनियोजित करने को प्रस्तुत होते हैं जहाँ राष्ट्रीयकरण का भय न हो, जहाँ निजी उपक्रम विद्यमान हो और उसको उचित सुविधाएँ तथा प्रेरणाएँ प्राप्त हो तथा जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र के साथ बड़ी प्रतियोगिता न करता हो। अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाएँ भी वित्तीय सहायता देते समय इस बात पर विचार करती हैं कि उनकी सहायता द्वारा स्थापित व्यवसायों से न केवल उस देश के निवासी ही लाभान्वित हो अपितु अन्य देशों को भी उनसे लाभ मिल सके। इस उद्देश्य पूर्ति हेतु उपक्रमों का स्वतन्त्र संचालन आवश्यक है।

6 कुछ व्यवसायों की प्रकृति निजी उपक्रम के अनुकूल होना—कुछ व्यवसायों की प्रकृति निजी उपक्रम के अधिक अनुकूल होती है और उनके कुशल संचालन के लिए व्यक्तिगत पहल की आवश्यकता होती है। इस वर्ग में वे व्यवसाय सम्मिलित किए जा सकते हैं, जिनमें उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत रुचि की ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है। ललितकलायें इसके उदाहरण हैं। कृषि भी एक ऐसा ही व्यवसाय है, जिसे निजी उपक्रम के लिए पूर्णतया छोड़ा जा सकता है।

7 निजी क्षेत्र की बुराइयों को दूर किया जाना सम्भव—सार्वजनिक-क्षेत्र के समर्थकों के अनुसार, निजी क्षेत्र में शोषण तत्त्व की प्रधानता होती है। इनसे श्रमिकों

तथा उपभोक्ताओं के शोषण के साथ-साथ धन और आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण होता है और सामाजिक तथा आर्थिक विषमता उत्पन्न होती है; किन्तु यह तभी सम्भव है, जब इसे निरकुश रूप से कार्य करने का अवसर दिया जाए। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में राज्य निजी-क्षेत्र को उचित नियन्त्रण और नियमन द्वारा कल्याणकारी राष्ट्रीय नीतियों के अनुकूल चलने के लिए बाध्य कर सकता है। इस प्रकार, निजी-क्षेत्र का उपयोग आर्थिक विकास के लिए किया जा सकता है।

आर्थिक विकास में सार्वजनिक-क्षेत्र का महत्त्व (Importance of Public Sector in Economic Development)

वस्तुतः आधुनिक विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है, जहाँ पूर्णरूप में निजी-उद्यम का अस्तित्व हो या जहाँ सार्वजनिक उपक्रम का किसी न किसी रूप में अस्तित्व न हो। निजी-उपक्रम के प्रबल समर्थक संयुक्तराज्य अमेरिका में भी अणु उत्पादन, रॉकेट-रिसर्च, सुरक्षा-उत्पादन आदि सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत हैं। पश्चिमी यूरोप कई देशों में भी वायुयान-निर्माण-उद्योग और सार्वजनिक उपयोगिताएँ सरकारों के हाथों में ही हैं। आधुनिक अर्द्ध-विकसित देशों में, जिन्होंने आर्थिक नियोजन को प्रारम्भ करके नियोजित आर्थिक विकास की पद्धति को अपनाया है, स्वयं सरकार वृहत् पैमाने पर पूँजी लगाकर आर्थिक विकास प्रक्रिया को बल पहुँचाने की आवश्यकता है। इन अर्थ-व्यवस्थाओं में सार्वजनिक-क्षेत्र का विस्तार मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है—

1. नियोजित अर्थ-व्यवस्था की देन—नियोजित अर्थ-व्यवस्था का प्रारम्भ, सर्वप्रथम, सोवियत रूस में हुआ था और वहाँ धीरे-धीरे समस्त अर्थ-व्यवस्था को सार्वजनिक-क्षेत्र के अन्तर्गत ले लिया गया। अतः अनेक व्यक्तियों का विचार है कि नियोजित अर्थ-व्यवस्था और उत्पादन साधनों का पूर्णरूप से सरकारी स्वामित्व और संचालन समानार्थक है, अर्थात्, नियोजित अर्थ-व्यवस्था में एकमात्र सार्वजनिक-क्षेत्र ही होता है। नियोजन सम्बन्धी यह मत उचित प्रतीत नहीं होता और प्रजातन्त्रवादी नियोजन में निजी-क्षेत्र का अस्तित्व भी होता है, किन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि नियोजित अर्थ-व्यवस्था में, सार्वजनिक-क्षेत्र का महत्त्व बढ़ जाता है। नियोजन का अर्थ, देश के साधनों का सामाजिक हित में अधिकाधिक विवेकपूर्ण उपयोग से है और ऐसा निजी-क्षेत्र द्वारा बिल्कुल सम्भव नहीं है। अतः नियोजन के इस उद्देश्य पूर्ति हेतु सार्वजनिक-क्षेत्र का विस्तार नितान्त आवश्यक है। वस्तुतः, सार्वजनिक-क्षेत्रविहीन नियोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

2 योजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए—आर्थिक नियोजन में विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु विशाल कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों को सम्पन्न करने और परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए विशाल मात्रा में पूँजी-विनियोग की आवश्यकता है। इस समस्त पूँजी का प्रवन्ध केवल निजी-क्षेत्र द्वारा नहीं हो सकता। अतः विशाल योजनाओं के विशाल कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए सरकार को आगे आना ही पड़ता है।

3 बड़ी मात्रा में पूँजी वाले उद्योगों की स्थापना—प्राधुनिक युग में कई उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर संचालित किए जाते हैं और इनमें करोड़ों रुपये की पूँजी की आवश्यकता होती है। लोहा एवं इस्पात, खनिज-तेल और तेल-शोधन हवाई-जहाज, रेलें, मोटर्स, विद्युत-सामग्री, मशीनें आदि के उद्योग इसी प्रकार के हैं और नियोजन की सफलता के लिए इनमें से अधिकांश की स्थापना और विकास आवश्यक है। इसी प्रकार, योजनाओं में विशाल नदी-घाटी परियोजनाएँ प्रारम्भ की जानी हैं, जिनमें करोड़ों रुपये की पूँजी लगाने की आवश्यकता होती है। निजी व्यक्तियों के लिए इतने बड़े उद्योग और परियोजनाओं को हाथ में लेना अमम्भव-सा है—विशेष रूप से, भारत जैसे अर्द्ध-विकसित देश के लिए जहाँ अधिक और द्वितीय सत्थाएँ बहुत अल्प विकसित हैं इसी कारण, भारत में लोहा और इस्पात उद्योग आदि की स्थापना के लिए सरकार को आगे आना पड़ा और सभी बड़े-छोटे नदी-घाटी योजनाएँ केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा प्रारम्भ की गईं। बोकारो जैसी विपुल व्यय साध्य योजना के लिए निजी-क्षेत्र सक्षम नहीं होता। ऐसी परियोजनाओं में सार्वजनिक-क्षेत्र द्वारा विनियोग अनिवार्य-सा है।

4 अधिक जोखिम वाली परियोजनाओं का प्रारम्भ—कुछ व्यवसायों में न केवल अधिक मात्रा में पूँजी की आवश्यकता होती है, अपितु जोखिम भी अधिक होती है। अधिक विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में तो यह बात विशेष रूप से लागू होती है। इसी स्थिति में, निजी उद्यमी ऐसे क्षेत्रों और उद्योगों में पूँजी नहीं लगाते, क्योंकि देश में पूँजी सीमित होती है और पूँजी-विनियोजन के अन्य कई लाभदायक क्षेत्र होते हैं। अतः सरकार के लिए ऐसी परियोजनाओं में पूँजी-विनियोजन करना अनिवार्य हो जाता है, जिनमें जोखिम अधिक होती है। सड़कें, विशाल नदी घाटी योजनाएँ, मू-सुरक्षण तथा वनारोपण आदि इस प्रकार की योजनाएँ हैं।

5 लोकोपयोगी सेवाओं का संचालन—यातायात एवं सदेशवाहन के साधन, डाक-तार, विद्युत तथा गैस आदि का उत्पादन तथा वितरण, पेयजल की पूर्ति आदि कई व्यवसाय एवं सेवाएँ अत्यन्त आवश्यक और एकाधिकारिक प्रवृत्ति की होती हैं और उनको निजी क्षेत्र में देने से उपभोक्ताओं का शोषण और निजी लाभ की दृष्टि से इनका संचालन होता है। वस्तुतः ये आवश्यक सेवाएँ हैं और इनका संचालन व्यापक सामाजिक लाभ की दृष्टि से किया जाना चाहिए। जैसे भी निजी-एकाधिकार सरकारी एकाधिकार की अपेक्षा अच्छा नहीं समझा जाता। इन सेवाओं का योजना के लक्ष्यों को पूरा करने की दृष्टि से भी सरकार के नियन्त्रण में होना आवश्यक है। इसीलिए इन व्यवसायों को सरकारी-क्षेत्र में चलाना चाहिए और इनके लिए विनियोगों की पर्याप्त राशि आवंटित की जानी चाहिए।

6 राजनीतिक तथा राष्ट्रीयकरण—कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिन्हें राजनीतिक और राष्ट्रीयकरण से, निजी-क्षेत्र के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता। सुरक्षा और सैनिक महत्त्व के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ही सुरक्षित रखे जाने चाहिए, अन्यथा इनकी गोपनीयता को सुरक्षित रखना कठिन होगा साथ ही अपेक्षित

कुशलता नहीं आ पाएगी। इसी प्रकार कुछ ऐसे उद्योग होने हैं, जिनका अर्थव्यवस्था पर नियन्त्रण रखने की दृष्टि से सार्वजनिक-क्षेत्र में संचालन करना आवश्यक होता है।

7 तकनीकी दृष्टिकोण—अर्द्ध-विकसित देशों में तकनीकी ज्ञान का स्तर नीचा होता है। यह ज्ञान उन्हें विदेशों से प्राप्त करना है। कभी-कभी यह तकनीकी-ज्ञान विदेशियों द्वारा उनकी साझेदारी में उद्योग स्थापित करने पर ही प्राप्त होता है किन्तु इन विदेशियों की कार्यवाही पर उचित नियन्त्रण आवश्यक है, जो निजी-क्षेत्रों की अपेक्षा उद्योगों के सार्वजनिक क्षेत्र में होने पर अधिक प्रभावशाली होता है। इसके अतिरिक्त, रूस आदि समाजवादी देशों में उद्योग और औद्योगिक अनुसंधान सरकारी-क्षेत्र में होता है। ऐसे देश बहुधा, सभी अन्य देशों को तकनीकी-ज्ञान तथा सहयोग देते हैं, जबकि ये परियोजनाएँ सम्बन्धित देश की सरकार द्वारा चलाई जाएँ। भारतीय योजनाओं में इस्पात, विद्युत्-उपकरण, खनिज तेल की खोज और तेल शोधन सूक्ष्म एवं जटिल उपकरण, भारी मशीन निर्माण, भिन्न वायुयान निर्माण योजनाओं के सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए जाने के कारण ही रूस, रूमानिया, चेकोस्लोवाकिया आदि देशों से तकनीकी-ज्ञान और सहयोग मिल सका।

8. योजना के समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति—कई आधुनिक अर्द्ध विकसित देशों की योजनाओं का एक प्रमुख उद्देश्य समाजवाद या समाजवादी पद्धति का समाज स्थापित करना है। वे देश में धन और उत्पादन के साधनों के केन्द्रीयकरण को कम करने और आर्थिक विषमता को कम करने को कृत सक्षम है। इन उद्देश्यों की पूर्ति में सार्वजनिक-क्षेत्र का विस्तार अत्यन्त सहायक होता है। उपक्रमों पर किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं होने से उस उपक्रम का लाभ किसी एक व्यक्ति की जेब में नहीं जाकर, सार्वजनिक-हित में प्रयुक्त किया जाता है। इससे व्यक्तिगत एकाधिकार, सम्पत्ति का केन्द्रीयकरण कम होता है और आर्थिक समानता की स्थापना होती है।

9 योजना के लिए आर्थिक साधनों की प्राप्ति—सार्वजनिक क्षेत्र में संचालित उपक्रमों का लाभ सरकार को प्राप्त होता है, जिससे सरकार की आर्थिक स्थिति सुधरती है और वह देश के आर्थिक विकास के लिए अधिक धन व्यय कर सकती है। अतः योजना के संचालन के लिए वित्तीय साधनों की प्राप्ति की आशा से भी, कई सरकारी उपक्रम स्थापित किए जाते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों में श्रमिकों को अधिक वेतन, कार्य की अच्छी दशाएँ, शिक्षा, आवास, चिकित्सा आदि की अधिक सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार इनका उपयोग समाज कल्याण के लिए किया जा सकता है।

10 द्रुत आर्थिक विकास के लिए—नियोजन में द्रुत आर्थिक विकास के लिए भी सार्वजनिक-क्षेत्र का विस्तार आवश्यक है। उदाहरणार्थ सावियन रूस ने पूर्णरूप से सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ही गत अर्द्ध-शताब्दि में अभूतपूर्व तथा आश्चर्यजनक

आर्थिक प्रगति की है। इसका यह आशय नहीं है कि निजी-क्षेत्र आर्थिक विकास के अनुपयुक्त है। इंग्लैण्ड, अमेरिका, जापान आदि में निजी-क्षेत्र के अन्तर्गत ही आर्थिक विकास की उच्च दरें प्राप्त की हैं, किन्तु सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा आर्थिक विकास कम समय लेता है।

11. अच्छे प्रशासन के लिए—नियोजित अर्थ-व्यवस्था में अच्छे प्रशासन के लिए साधनों का अच्छा वितरण और उपयोग होना चाहिए। इसके लिए व्यवसायों के अच्छे प्रशासन की भी आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र के व्यवसाय इस दृष्टि से अच्छे होते हैं। इनसे कर-वसूली, मूल्य-नियम, पूंजीगत और उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण आदि में सुविधा होती है। सरकारी उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी नीतियों को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए भी सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार आवश्यक है।

विनियोगों का आवंटन (Allocation of Investment)

अत स्पष्ट है कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की अपनी-अपनी उपयोगिताएँ और लाभ हैं। अत आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत दोनों की ही अच्छाइयों का लाभ उठाने के लिए दोनों ही क्षेत्रों से युक्त मिश्रित-अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) को अपनाना चाहिए। इससे पूर्णरूप से निजी उत्पन्न वाली अर्थ-व्यवस्था और पूर्णरूप से सार्वजनिक उत्पन्न अर्थ-व्यवस्था दोनों ही आपत्तियों से सकेगा। जनतान्त्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले, अर्द्ध-विकसित देशों के लिए तो बचा जायही एकमात्र उपयुक्त मार्ग है। अत इन देशों के नियोजन में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाना चाहिए और दोनों क्षेत्रों के लिए ही विनियोगों का आवंटन किया जाना चाहिए। किस अनुपात में इन दोनों क्षेत्रों का स्थान दिया जाए या पूंजी विनियोगों का उभरदायित्व सीपा जाए, इसके बारे में कोई एक सर्वमान्य सिद्धान्त नहीं बनाया जा सकता। विभिन्न देशों की परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं। अत प्रत्येक देश को अपनी परिस्थितियों के अनुसार, विनियोगों का निजी और सार्वजनिक-क्षेत्र में वितरण करना चाहिए, किन्तु नियोजित अर्थ-व्यवस्था में सार्वजनिक-क्षेत्र का विस्तार अपेक्षाकृत अधिक गति से होता है। इस सम्बन्ध में भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि "सरकारी-क्षेत्र का विस्तार तीव्रता से होना है। जिस क्षेत्र में निजी-क्षेत्र प्रवेश करने की तत्पर न हो, राज्य को केवल ऐसे क्षेत्र में विकास कार्य ही शुरू नहीं करना है बल्कि अर्थ-व्यवस्था में पूंजी-विनियोग के पैटर्न को रूप देने में प्रधान भूमिका अदा करनी है। विकासशील अर्थ-व्यवस्था में, जिसमें विविधता उत्तरोत्तर उत्पन्न होने की गुँजाइश है, लेकिन यह आवश्यक है कि यदि विकास कार्य अपेक्षित गति से किया जाना है और वृहत् सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रभावशाली ढंग से योग देना है, तो सरकारी क्षेत्र में वृद्धि समग्र रूप में ही नहीं, अपितु निजी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होनी चाहिए।"

तृतीय और चतुर्थ योजना में यह तर्क और भी अधिक बल के साथ स्पष्ट रूप में रखा गया और योजना में कहा गया कि "समाजवादी समाज का उद्देश्य रखने वाले देश की अर्थ-व्यवस्था में सरकारी क्षेत्र को उत्तरोत्तर प्रमुख स्थान ग्रहण करना है।" मनुभाई शाह का भारत के सम्बन्ध में यह कथन समस्त अर्द्ध-विकसित देशों के लिए उपयुक्त है कि "हमारे गरीब देश में पूँजीवाद निरर्थक, निष्फल तथा उपयोगिताहीन है। ऐसे देश में जहाँ गिच्छड़ापन गहरा पहुँच चुका है, जहाँ गरीबी भरी पड़ी हो, जहाँ करोड़ों बच्चों को शिक्षा उपलब्ध नहीं हो, वहाँ समाज का संचालन अधिक हिस्से में शासन के पास ही रहना चाहिए।" भारत में सार्वजनिक-क्षेत्र का महत्त्व निजी-क्षेत्र की अपेक्षा अधिक बतलाने हुए एक बार भूतपूर्व राष्ट्रपति जवाहर लाल नेहरू ने लिखा था कि "यदि सार्वजनिक क्षेत्र की अपेक्षा निजी क्षेत्र को प्रधानता दी जाती है, तो वह हमारे समाजवादी समाज के विकास के लिए घातक होगा।"¹

अतः नियोजित अर्थ-व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का निरन्तर विस्तार होना चाहिए। किसी सीमा तक सार्वजनिक-क्षेत्र को विनियोगों का उत्तरदायित्व सौंपा जा सकता है, यह सम्बन्धित देश की आर्थिक परिस्थितियों, आर्थिक औद्योगिक नीति, राजनीतिक विचारधारा (Political Ideology), निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की अब तक की कुशलता और भविष्य के लिए क्षमता आदि बातों पर निर्भर करता है, किन्तु इस सम्बन्ध में सिद्धान्तों की अपेक्षा व्यवहारिकता पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। कृषि, लघु एवं ग्रामीण उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, आन्तरिक व्यापार आदि में पूँजी निजी क्षेत्र द्वारा विनियोग की स्वतन्त्रता होनी चाहिए, किन्तु जनोपयोगी सेवाएँ, नदी घाटी योजनाएँ, वित्तीय संस्थाएँ, भारी और आधारभूत उद्योग तथा अन्य देश और अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण उद्योगों में सार्वजनिक-क्षेत्र को ही पूँजी-विनियोग करना चाहिए।

भारत में निजी और सार्वजनिक-क्षेत्रों में विनियोग (Investment in Private & Public Sector in India)

नियोजित विकास के पूर्व

स्वतन्त्रता के पूर्व भारत के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास का इतिहास देश में निजी-क्षेत्र के विकास का इतिहास है। उस समय भारत में सार्वजनिक-क्षेत्र नाम-मात्र की ही था। उस समय सरकारी क्षेत्र में, रेलें, डाक तार, आकाशवाणी, पोस्ट-ट्रस्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, ऑर्डिनन्स फैक्ट्रीज और कलियम ऐयर-क्राफ्ट, नमक और कुनेन आदि के कारखाने ही थे। इनके अतिरिक्त, सारा व्यवसाय निजी उद्योगपतियों द्वारा संचालित किया जाता था। स्वतन्त्रता के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार ने देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास की ओर ध्यान देना प्रारम्भ किया और इस सदर्भ में, सार्वजनिक उपक्रमों के महत्त्व को समझा। सन् 1947 से प्रथम योजना के प्रारम्भ होने तक सिन्दरी में रासायनिक उर्वरक कारखाना, बितरजन में

रेल के इन्जिन बनाने का कारखाना, बगलौर में यन्त्रोपकरण बनाने का कारखाना एवं दामोदर घाटी विकास निगम आदि सरकारी उपक्रम प्रारम्भ किए गए। परिणामस्वरूप 1952 में प्रकाशित प्रथम पञ्चवर्षीय योजना के समय केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों का कार्यशील पूँजी सहित कुल स्थिर आदेयों का पुस्त मूल्य (Book Value of Gross Fixed Assets) सन् 1947-48 के 875 करोड़ रु. से बढ़कर 1,272 करोड़ रु. हो गया। इसके अतिरिक्त पोर्टे ट्रस्ट नगरपालिका में एवं अन्य अर्द्ध-सार्वजनिक अभिकरणों की उत्पादक आदेय राशि 1,000 करोड़ रु. थी। इसके विपरीत, निजी क्षेत्र की कुल उत्पादन आदेय राशि, कृषि, सधु-स्तरीय उद्योग, यातायात एवं आवास भवनों के अतिरिक्त, सन् 1950 में 1,474 करोड़ रु. अनुमानित की गई थी।¹

नियोजित अर्थ-व्यवस्था में

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में औद्योगिक नियामकों के निजी और सार्वजनिक क्षेत्र विभाजन के मार्ग-प्रदर्शक के रूप में, सन् 1948 की औद्योगिक नीति ने कार्य किया, जिसके अनुसार, कुछ उत्पादन-क्षेत्र तो पूर्णरूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ही निर्धारित कर दिए गए थे और कई अन्य क्षेत्रों में भी सरकारी क्षेत्र का विस्तार की चर्चा की गई थी। अतः उद्योगों में कई परियोजनाएँ सरकारी-क्षेत्र में स्थापित की गईं। साथ ही, अन्य क्षेत्रों में भी, जैसे नदी-घाटी योजनाएँ, कृषि-विकास-कार्यक्रम, यातायात एवं संचार आदि में भी सरकारी क्षेत्र ने कार्यक्रम शुरू किए। परिणामस्वरूप योजनावधि में, जहाँ निजी-क्षेत्र ने पर्याप्त प्रगति की, वहाँ सार्वजनिक-क्षेत्र का भी पर्याप्त विस्तार हुआ। इस योजना में अर्थ-व्यवस्था में कुल पूँजी-विनियोग 3,360 करोड़ रु. हुआ, जिसमें से 1,960 करोड़ रु. अर्थात् 46.4% विनियोग सरकारी क्षेत्र में हुआ और शेष 1,800 करोड़ रु. अर्थात् कुल का 53.6% निजी-क्षेत्र में हुआ। योजना के पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में सार्वजनिक-क्षेत्र के भाग की देखते हुए पूँजी-विनियोग बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार, इस योजना में सार्वजनिक-क्षेत्र में पूँजी निर्माण प्रति वर्ष बढ़ता रहा। सार्वजनिक क्षेत्र में पूँजी-निर्माण सन् 1950-51 में 267 करोड़ रु. से बढ़कर 1955-56 में 537 करोड़ रु. हो गया। इसी अवधि में निजी-क्षेत्र में पूँजी निर्माण 1,067 करोड़ रु. से बढ़कर 1,367 करोड़ रु. हुआ।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना—इस योजना में 792 करोड़ रु. औद्योगिक विकास हेतु निर्धारित किए गए थे, जिसमें से 179 करोड़ रु. सार्वजनिक क्षेत्र में, उद्योग और खनिज विकास पर, व्यय किए जाने थे। इसमें से 94 करोड़ रु. का उद्योगों में विनियोग के लिए प्रावधान था। किन्तु वास्तविक विनियोग 55 करोड़ रु. ही हुआ। इस अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र में, अनेक बड़े कारखानों का निर्माण या विस्तार हुआ, जैसे—हिन्दुस्तान शिपयार्ड, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री, बगलौर, जलयान एवं

वायुयान कारखाने, हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स, चितरजन का रेल इजिन कारखाना, बगलौर की टेलीफोन फैक्ट्री, कलकत्ता की बेबिल फैक्ट्री आदि। राज्य सरकारों द्वारा भी सार्वजनिक-क्षेत्र के लिए प्रयत्न किया गया, जिसमें प्रमुख है—मैसूर के भद्रावती वर्क्स में इस्पात का निर्माण एवं मध्यप्रदेश में नेपा नगर में अखबारी कागज का उत्पादन, उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र कारखाना। इसके अतिरिक्त, बहुदेशीय नदी-घाटी योजनाओं में भी पर्याप्त पूँजी-विनियोग सरकारी-क्षेत्र में किया गया।

इस योजना के पाँच वर्षों में निजी क्षेत्र का विनियोग 1,800 करोड़ रु. हुआ, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में यह 1,560 करोड़ रु. ही था। इस प्रकार इस योजना में निजी क्षेत्र में विनियोग कुल मिलाकर सार्वजनिक-क्षेत्र की अपेक्षा अधिक हुआ किन्तु सापेक्ष रूप से कम हुआ। इस योजना में उद्योगों के सम्बन्ध में निजी क्षेत्र द्वारा 707 करोड़ रु. के कार्यक्रम बनाए गए थे जिनमें से 463 करोड़ रु. उद्योगों के विस्तार, आधुनिकीकरण, प्रतिस्थापन एवं चालू ह्रास पर और 150 करोड़ रु. कार्यशील पूँजी पर विनियोग किए जाने थे। योजनाकाल में निजी-क्षेत्र में इन 463 करोड़ रु. के विरुद्ध 340 करोड़ ही व्यय हुए। इस प्रकार, निजी-क्षेत्र में भी विनियोग पिछड़ गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना—द्वितीय योजनाकाल में दोनों क्षेत्र का कुल विनियोग 6 800 करोड़ रु. हुआ। सार्वजनिक-क्षेत्र का विनियोजन 3,700 करोड़ रु. और शेष 3 100 करोड़ रु. निजी क्षेत्र का विनियोजन रहा। अतः स्पष्ट है कि इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का विनियोजन निजी क्षेत्र के विनियोजन की अपेक्षा अधिक है, जबकि प्रथम योजना में स्थिति ठीक इसके विपरीत थी। इसी प्रकार, इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में पूँजी-निर्माण भी निरन्तर बढ़ता ही गया। इस अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र में पूँजी निर्माण 537 करोड़ रु. से बढ़कर 912 करोड़ रु. हो गया। इसी अवधि में निजी-क्षेत्र में पूँजी-निर्माण 1,367 करोड़ रु. से बढ़कर 1,789 करोड़ रु. हो गया। द्वितीय योजना में सार्वजनिक-क्षेत्र के विस्तार का एक मुख्य कारण सार्वजनिक क्षेत्र में कई विशाल कारखानों की स्थापना किया जाना था। सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए, इस योजना में 770 करोड़ रु. व्यय किए गए थे जबकि मूल अनुमान 560 करोड़ रु. का था। इस अवधि में दुर्गापुर, हरकेला एवं भिलाई में विशाल इस्पात कारखानों का निर्माण हुआ, इसके अतिरिक्त एनिज तेल की खोज के लिए इंडिया आइल लिमिटेड तेल-शोधन के लिए इण्डियन रिफाइनरीज लिमिटेड और विशुद्ध तेल वितरण के लिए इण्डियन आयल लिमिटेड की स्थापना की गई। अन्य कई कारखाने, जैसे—भोपाल का भारी बिजली का कारखाना, हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, हैवी इन्जीनियरिंग कॉरपोरेशन, रांची फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया, नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड आदि की स्थापना की गई जिनके अधीन कई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की गईं। उद्योगों से सम्बन्धित इन इकाइयों के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र में कई अन्य व्यावसायिक संस्थाओं का भी निर्माण किया गया, जैसे—1958 में सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, 1959 में एक्सपोर्ट क्रेडिट एवं गारंटी

कारपोरेशन, 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम, 1957 में नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, 1958 में उद्योग पुनर्वित्त निगम एवं सन् 1956 में राज्य व्यापार निगम आदि। इन सब संस्थाओं में करोड़ों रुपये की पूँजी विनियोजित की गई। इसके अतिरिक्त, रेलों एवं अन्य यातायात साधनों तथा नदी घाटी योजनाओं के विकास के लिए सार्वजनिक-क्षेत्र में आयोजन किया गया। परिणामस्वरूप, द्वितीय योजना में सार्वजनिक-क्षेत्र का पर्याप्त विकास हुआ।

इस योजना में कार्यक्रम, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अनुसार, बनाए गए थे, जिसमें सार्वजनिक-क्षेत्र की पर्याप्त वृद्धि के लिए व्यवस्था की गई थी; किन्तु फिर भी इस योजना में निजी क्षेत्र का काफी विस्तार हुआ। इस योजना में निजी क्षेत्र में कुल पूँजी-विनियोग 3,100 करोड़ रु., सार्वजनिक-क्षेत्र में होने वाले विनियोग की राशि से 700 करोड़ रु. कम है। निजी-क्षेत्र द्वारा ग्रंथ-व्यवस्था में पूँजी निर्माण भी रहा। इस योजना में औद्योगिक विकास के लिए निजी-क्षेत्र को केवल 620 करोड़ रु. विनियोजित करना था, किन्तु वास्तविक विनियोजन 850 करोड़ रु. का हुआ। इस योजना में निजी-क्षेत्र में इस्पात, सीमेंट, बड़े और मध्यम इंजीनियरिंग उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ। इसके अतिरिक्त, निजी-क्षेत्र में औद्योगिक मशीनें, जैसे—सूती वस्त्र-उद्योग, शक्कर-उद्योग, कागज एवं सीमेंट-उद्योग की मशीनें तैयार करने वाले उद्योग और उपभोक्ता उद्योगों में पूँजी विनियोजित की गई।

अत स्पष्ट है कि इस योजना में सरकारी-क्षेत्र और निजी-क्षेत्र दोनों का विकास हुआ, किन्तु सार्वजनिक-क्षेत्र का अपेक्षाकृत अधिक विकास हुआ। योजनावधि में इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया और जीवन-बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण तथा राजकीय व्यापार निगम आदि संस्थाओं की स्थापना को मूल-रूप देने का प्रयत्न किया गया। द्वितीय योजना में सार्वजनिक विनियोगों में वृद्धि का कारण 1956 में सरकार द्वारा औद्योगिक नीति का मंजीनीकरण करना और उसमें ग्रंथ व्यवस्था एवं उद्योगों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सरकारी क्षेत्र में संचालित किए जाने की व्यवस्था है। साथ ही, देश की तीव्र औद्योगीकरण की आकांक्षा तथा अधिक समानता और धन के विदेशीकरण पर आधारित समाजवादी समाज की स्थापना की राष्ट्रीय उत्कठा के कारण भी इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला।

तृतीय पंचवर्षीय योजना—इस योजना में आर्थिक क्रियाओं के, सरकार तथा व्यक्तियों में, विभाजन का आधार सन् 1956 की औद्योगिक नीति को ही माना गया। यद्यपि बाद में उत्पादन वृद्धि के दृष्टिकोण में इसमें निजी-क्षेत्र के पक्ष में थोड़ा समर्थन किया गया। परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की राष्ट्रीय सरकारी नीति के कारण इस योजना में भी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विनियोग-राशि अधिक आवंटित की गई। निजी-क्षेत्र में भी विनियोगों की मात्रा में वृद्धि हुई, क्योंकि, उसे भी निर्धारित क्षेत्रों में विवसित होते रहने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिए जाने की नीति को जारी रखा गया। इस योजना के कुल विनियोग 12,767 करोड़ रु. हुआ जिसमें से 7,129

करोड़ रु (1,448 करोड़ रु चातु व्यय सहित) सार्वजनिक क्षेत्र में और 4,100 करोड़ रु निजी-क्षेत्र में व्यय हुआ। द्वितीय योजना में यह राशि क्रमशः 3,700 और 3,100 करोड़ रु थी अतः स्पष्ट है कि सार्वजनिक-क्षेत्र का कुल विनियोग में भाग 60.6 / तक पहुँच गया था।

इन योजनाओं में, द्वितीय योजना में प्रारम्भ किए गए उद्योगों को पूरा किया जाने एवं मिलाई, दुर्गापुर, हरकेला आदि कारखानों की स्थापित क्षमता में वृद्धि करने के अतिरिक्त अनेक नए कारखाने स्थापित किए गए जिनमें प्रमुख हैं—निवेली, ट्राम्बे, गोरखपुर में उर्वरक के कारखाने, होशंगाबाद (मध्य-प्रदेश) में सेक्यूरिटी पेपर मिल, बगलौर में घड़ी बनाने का कारखाना, दुर्गापुर में खनिज मशीनों का कारखाना, कोयली (गुजरात) में तेल-शोधक कारखाना, ऋषिकेश में औषधियाँ निर्माण करने वाला कारखाना, रानीपुर तथा रामचन्द्रपुर में भारी बिजली के सामान बनाने का कारखाना, पिंजौर (पंजाब) में मशीनी औजार बनाने का कारखाना आदि। तृतीय योजना में ही भारत पर चीनी आक्रमण हुआ और सरकारी क्षेत्र में प्रतिरक्षा उद्योगों पर विशाल मात्रा में पूँजी लगाई गई। राज्य सरकारों द्वारा भी मैसूर आइरन एण्ड स्टील वर्क्स आन्ध्र पेपर मिल आदि में पूँजी विनियोग किया गया।

सार्वजनिक-क्षेत्र में स्थापित उपरोक्त औद्योगिक परियोजनाओं के अतिरिक्त आर्थिक क्रियाओं के संचालन हेतु अनेक अन्य संस्थाओं का निर्माण किया गया, जैसे—1962 में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया 1963 में भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम और राष्ट्रीय बीज निगम 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास निगम आदि। परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक विनियोगों में वृद्धि हुई।

इस योजना में निजी क्षेत्र में 4,190 करोड़ रु का विनियोग किया गया। किन्तु समस्त विनियोजित राशि में निजी-क्षेत्र का भाग निरन्तर घटता हुआ था, क्योंकि इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के विनियोगों में वृद्धि होती रही। योजनावधि में सरकार ने औद्योगिक नीति को निजी-क्षेत्र के पक्ष में थोड़ा संशोधित किया और उर्वरक उत्पादन में निजी-क्षेत्र का सहयोग लिया गया।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना—प्रारम्भ में चतुर्थ योजना के लिए 24,882 करोड़ रु का प्रावधान रखा गया जिसमें सार्वजनिक-क्षेत्र के लिए 15,902 करोड़ रु और निजी-क्षेत्र के लिए 8,980 करोड़ रु की व्यवस्था थी। 1971 में योजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया गया और सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय को बढ़ाकर 16,201 करोड़ रु कर दिया गया। योजना का पुनः मूल्यांकन किया गया और अब अन्तिम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, चतुर्थ योजना में सार्वजनिक-क्षेत्र में कुल व्यय 15,724 करोड़ रु आँका गया है।¹ यदि सार्वजनिक उपक्रमों को ल, तो 31 मार्च, 1974 को केन्द्र सरकार के 122 उपक्रमों में कुल 6,237 करोड़ रु की पूँजी लगी हुई थी। पंचवर्षीय योजनाओं में सरकारी उपक्रमों में पूँजी निवेश का विस्तार अग्रलिखित सारणी द्वारा स्पष्ट है²—

1 India 1976 p 172

2 Ibid, p 262

वर्ष	उपक्रमों की संख्या	कुल पूँजी निवेश (करोड़ ₹)	औसत वार्षिक विकास दर (प्रतिशत में)
प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में	5	29	—
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में	21	81	36
तृतीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में	48	953	133
तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में (31 मार्च, 1966)	74	2,415	31
31 मार्च, 1970	91	4,301	10
31 मार्च, 1972	101	5,052	8
31 मार्च, 1973	113	5,571	10
1974 (चतुर्थ योजना के अन्त में)	122	6,237	12

विदेशी-विनिमय का महत्व और आवश्यकता (Importance and Necessity of Foreign Exchange)

आर्थिक नियोजन के लिए विशाल साधनों की आवश्यकता होती है। अर्द्ध-विकसित देश पूँजी, यन्त्रोपकरण, तकनीकी-ज्ञान आदि में अभावग्रस्त होते हैं। इसलिए एक निर्धन देश केवल अपने साधनों द्वारा ही आधुनिक रूप में विकसित नहीं हो सकता। अतः उन्हें नियोजन कार्यक्रमों की सफलता के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री विदेशों से आयात करनी पड़ती है। नियोजन की प्रारम्भिक अवस्थाओं में अत्यधिक मात्रा में पूँजीगत पदार्थों, मशीनों, कलपुर्जों उद्योग और कृषि के लिए आवश्यक उपकरण, औद्योगिक कच्चा माल, रासायनिक सामग्री और तकनीकी विशेषज्ञों का आयात करना पड़ता है। विद्युत् और सिंचाई की विशाल नदी घाटी योजनाओं के लिए विभिन्न प्रकार के यन्त्र, इस्पात तथा सेमेट आदि का विदेशों से आयात करना पड़ता है। कृषि-विकास के लिए उर्वरक, कीटनाशक औषधियाँ और उन्नत यन्त्र आदि का भी विदेशों से आयात करना पड़ता है, क्योंकि अर्द्ध-विकसित देशों में इनका उत्पादन भी कम होता है और कृषि व्यवसाय पिछड़ा हुआ भी होता है। ये विकासोन्मुख देश जब योजनाएँ अपनाते हैं, तो विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में आयात और सदृशवाहन के साधनों का भी द्रुत विकास करना चाहते हैं क्योंकि विकास के लिए यह प्रथम आवश्यकता होती है। इनसे सम्बन्धित सामग्री का भी विदेशों से आयात करना पड़ता है। विभिन्न विकास योजनाओं में औद्योगिक विकास को भी महत्व दिया जाता है और इस्पात, भारी रसायन, इंजीनियरिंग, मशीन-निर्माण, खनिज-तेल, विद्युत् उपकरण आदि उद्योगों के विकास के लिए भारी मात्रा में मशीनरी, कच्चा माल, मध्यवर्ती पदार्थ, ईंधन, रसायन और कलपुर्जों का आयात करना पड़ता है। इन सब परियोजनाओं के निमाण और कुछ समय तक संचालन के लिए विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों का भी आयात आवश्यक है। परिणामस्वरूप, देश की आय में वृद्धि होती है। इस बड़ी हुई आय का बहुत बड़ा भाग आधुनिक जीवन

की नवीन वस्तुओं के उपभोग पर व्यय किया जाता है, जिनकी पूर्ति भी विदेशों से मंगाकर की जाती है। अनेक अर्द्ध-विकसित देश कृषि-प्रधान होते हुए भी कृषि व्यवसाय और उत्पादन-पद्धतियों के अवनत होने के कारण देश की आवश्यकतानुसार खाद्यान्न और उद्योगों के लिए कृषि-जनित कच्चा माल भी उत्पन्न नहीं करते। अतः उन्हें खाद्यान्न और ऐसे कच्चे माल का भी आयात करना पड़ता है। भारतीय योजनाओं में ऐसा ही हुआ। अधिकांश अर्द्ध-विकसित देश अधिक जनसंख्या से ग्रसित होते हैं और इनकी जनसंख्या-वृद्धि की दर भी अधिक होती है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक मात्रा में उपभोग सामग्री और उत्पादक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति के लिए आयातों का आश्रय लेना पड़ता है। कई अर्द्ध-विकसित देशों में आयातों के बढ़ने का यह भी एक कारण है। इस प्रकार, विकासार्थ नियोजन के प्रारम्भिक वर्षों में आयातों के बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। इन देशों को परिपोषक आयात (Maintenance Imports), विकासारम्भक आयात (Developmental Imports) और अस्फीतिकारी आयात (Anti-inflationary Imports) करने पड़ते हैं। इन सब आयातों के भुगतान हेतु विदेशी-विनिमय की आवश्यकता होती है।

निर्यात और विदेशी-विनिमय का अन्तर्ग—स्पष्ट है, कि विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था में वृद्धिमान दर से आयात करने पड़ते हैं। विदेशों से इन पदार्थों का आयात करने के लिए इनका भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है जिसे ये देश अपनी वस्तुओं का निर्यात करके प्राप्त कर सकते हैं। अधिक मात्रा में वस्तुएँ आयात की जा सकें, इसके लिए यह आवश्यक है, कि ये देश साधकाधिक मात्रा में अपने देश से पदार्थों का निर्यात करके अधिकाधिक विदेशी मुद्रा या विदेशी-विनिमय अर्जित करें। इन निर्यातों में दृश्यगत और अदृश्य (Visible and Invisible Exports) दोनों निर्यात सम्मिलित हैं। इस प्रकार, विकासोन्मुख देशों के लिए निर्यातों में वृद्धि करना आवश्यक होता है। किन्तु, दुर्भाग्यवश, इन देशों में नियोजन की प्रारम्भिक अवस्थाओं में निर्यात क्षमता बहुत अधिक नहीं होती है। एक तो स्वयं देश के विकास-कार्यक्रमों के लिए वस्तुओं की आवश्यकता होती है। दूसरे, आर्थिक विकास के कारण बड़ी हुई आय को भी जनता, उपभोग पर ही व्यय करना चाहती है, क्योंकि इन देशों में उपभोग की प्रवृत्ति अधिक होती है। अतः निर्यात-योग्य आधिव्यय (Exportable Surplus) कम बच पाता है। योजनावद्ध आर्थिक विकास में जो कुछ उत्पादन किया जाता है, वह उपभोग की बढ़ती हुई आवश्यकता में प्रयुक्त कर लिया जाता है। परिणामस्वरूप, इतनी अतिरिक्त निम्न-स्तरीय उत्पादकता और मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियों के कारण उत्पादन लागत अधिक होती है और विश्व के बाजारों में वे प्रतिस्पर्धा में प्रारम्भिक वर्षों में नहीं टिक पाते; फलस्वरूप, व्यापार प्रतिकूल हो जाता है क्योंकि, एक ओर आयातों में वृद्धि होती है तथा दूसरी ओर उनके भुगतान के लिए निर्यात अधिक नहीं बढ़ पाते। इस प्रकार विदेशी-विनिमय का सकट पैदा हो जाता है। किन्तु एक पूर्णतः केन्द्रित अर्थ-व्यवस्था में विशेष-रूप से सीवियत एस जैसी

अर्थ-व्यवस्था में, विदेशी व्यापार के क्षेत्र में ऐसी कठिनाईयाँ कम पैदा होती हैं, परन्तु भारत जैसी आंशिक रूप से नियोजित या मिश्रित अर्थ-व्यवस्था (Mixed Economy) में विदेशी व्यापार में इस प्रकार का भुगतान-प्रसतुलन उत्पन्न होना सामान्य बात है।

विदेशी विनिमय के आवंटन की आवश्यकता—स्पष्ट है कि विकासाध्य नियोजन में विशाल मात्रा में विविध प्रकार की सामग्री का आयात करना पड़ता है किन्तु उसका भुगतान करने के लिए निर्यातों से पर्याप्त मात्रा में आवश्यकानुसार विदेशी विनिमय उपलब्ध नहीं हो पाता। यद्यपि स्वदेश में ही उत्पादन में वृद्धि करके आयात प्रतिस्थापन के पर्याप्त प्रयत्न किए जाते हैं और निर्यातों में वृद्धि के लिए भी अथक् प्रयास किए जाते हैं किन्तु विदेशी विनिमय की स्वल्पता ही रहती है इसीलिए, उपलब्ध विदेशी विनिमय के समुचित उपयोग की समस्या उदय होती है। यदि देश के लिए बाँझनीय सभी पदार्थों के आयात के लिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी विनिमय उपलब्ध हो जाए तो फिर इस प्रकार की समस्या ही उत्पन्न न हो, किन्तु जिस प्रकार से अन्य आर्थिक क्षेत्रों में वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों से अनन्त उद्देश्या की पूर्ति हेतु चयन (Choice) की समस्या उदय होती है उसी प्रकार, विभिन्न उद्योगों में इन विदेशी मुद्रा कोषों के सीमित साधनों के उचित और विवेकपूर्ण आवंटन की समस्या उदय होती है, जिसके समुचित समाधान से नियोजन की सफलता का अंश बढ़ जाता है।

विदेशी-विनिमय का आवंटन (Allocation of Foreign Exchange)

अतः यह आवश्यक है कि योजनाओं में आयात-कार्यक्रम, एक सुविचारित योजना के आधार पर संचालित किया जाए, जिससे दुर्लभ विदेशी मुद्रा का अधिकतम उपयोग हो सके।

इस सम्बन्ध में तनिक संशोधन के साथ वही सिद्धान्त अपनाया जा सकता है जो देश में विनियोगों के आवंटन (Allocation of Investment) के लिए अपनाया जाता है। इस संदर्भ में 'सीमान्त-सामाजिक लाभ का सिद्धान्त' (Principle of Marginal Social Benefit) बड़ा सहायक हो सकता है। इस सिद्धान्त के अनुसार विभिन्न उद्योगों में विदेशी मुद्रा का आवंटन इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि इनसे प्राप्त सीमान्त लाभ समान हो। तभी इस विदेशी मुद्रा से देश को अधिकाधिक लाभ मिल सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि विदेशी मुद्रा के आवंटन में देश के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्षेत्रों और परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। अर्द्ध-विकसित देशों के आयात की निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है—

- (अ) सुरक्षा सामग्री का आयात (Import of Defence Equipment)
- (ब) निर्वाह सम्बन्धी आयात (Maintenance Imports)
- (स) विकासात्मक आयात (Developmental Imports)
- (द) अदृश्य आयात (Invisible Imports)

(अ) सुरक्षा सम्बन्धी आयात (Imports of Defence Equipment)—सुरक्षा, किसी भी देश की सर्वोपरि आवश्यकता होती है। कोई भी देश इस कार्य में उदासीनता नहीं बरत सकता। इन नियोजन में सुरक्षा सामग्री के आयातों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कई देशों के नियोजन का तो मुरा उद्देश्य ही देश की रक्षा या आक्रमण (Defence or Offence) के लिए सुरक्षा को ढ़ढ करना होता है। वैसे भी इनमें से अधिकांश अढं विकसित देश अभी गत कुछ वर्षों से ही स्वतन्त्र ढ़ढ हैं और सुरक्षा की दृष्टि में ढ़ढं हैं। इन देशों के पडोसियों में सीमा सम्बन्धी झगडे भी रहते हैं जिनके कारण, ये देश युद्ध की आशंका से ग्रस्त रहते हैं और सुरक्षा के लिए आतुर रहते हैं। यहाँ तकभीकी ज्ञान का भी इतना अधिक विकास नहीं ढ़ढा है, जिससे सारी सुरक्षात्मक सामग्री का उत्पादन वे स्वयं कर सकें। इन इढे विदेशों से भारी मात्रा में अस्त्र शस्त्र, गोला-बारूद तथा सुरक्षा उद्योगों के लिए आवश्यक सामग्री का आयात करना आवश्यक होता है जिनके अभाव में इन देशों की सुरक्षा ही खतरे में पड सकती है। अतः इस कार्य में लिए विदेशी-विनिमय के आवढन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। देश का अस्तित्व देश की सुरक्षा पर निर्भर करता है जो विकासवाद की एक वस्तु है। सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक सामग्री के आयात में उपेक्षा करने के दुष्परिणाम हो सकते हैं। अतः सुरक्षा की दृष्टि से आयात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्णतः से विदेशी विनिमय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(ब) निर्वाह सम्बन्धी आयात (Maintenance Imports)—निर्वाह सम्बन्धी आयात या परिपोषक आयातों में आयात की जाने वाली उन वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं जो अर्थ-व्यवस्था के वर्तमान स्तर पर सुचारु रूप से संचालन के लिए आवश्यक हैं। भारत जैसे अढं विकसित देशों के सढर्न में इसमें निम्नलिखित वर्ग सम्मिलित किए जा सकते हैं—

(1) खाद्यान्न—अधिकांश अढं-विकसित देश कृषि-प्रधान हैं, किन्तु कृषि की पिछडी हुई दशा और जनसंख्या की अधिकता होने के कारण, यहाँ खाद्यान्नो का अभाव होता है और इसकी पूर्ति विदेशों से ख ञ ओ का आयात करके की जाती है। खाद्यान्न किसी भी देश की बुनियादी आवश्यकता है और इसकी पूर्ति चाहे किसी भी सोन से हो, आवश्यक रूप से की जानी चाहिए। इन देशों का जीवन-स्तर पहले से ही अत्यन्त न्यूनतम स्तर पर है और उसमें कटौती किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती। अतः यद्यपि इन देशों में खाद्यान्नो का उत्पादन में तुरन्त वृद्धि के प्रयत्न किए जा सकते हैं जिसकी यहाँ बहुत बडी गुंजायश है, किन्तु यदि इसमें तुरन्त इतनी वृद्धि नहीं हो पाए तबसे देश की खाद्यान्नो की आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो, तो निश्चित रूप से खाद्यान्नो का भी आवश्यक मात्रा में आयात किया जाना चाहिए और उसके लिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी-विनिमय आवढिन किया जाना चाहिए। भारत का उदाहरण इन सम्बन्ध में स्पष्ट है।

(2) औद्योगिक कच्चा माल—इस वर्ग में कच्चा माल, मुख्यतः कृषि-उत्पाद

कच्चा माल, सम्मिलित किया जा सकता है। अनेक अर्द्ध-विकसित देशों में, स्वयं के उद्योगों के लिए, कच्चा माल उत्पन्न नहीं होता है अथवा कम मात्रा में होता है, जिसकी पूर्ति विदेशों से इन पदार्थों का आयात करके की जाती है। उदाहरणार्थ, भारत कृषि-सम्बन्धी कच्चे माल में, रालें, तोपरा, कच्ची रबड़, कच्ची कपास, कच्चा जूट, अनिर्मित तम्बाकू आदि का आयात करता है। इन सभी वस्तुओं के आयात को देश में ही उत्पादन में वृद्धि करके कम किया जाना चाहिए। साथ ही, इस बात के भी प्रयास किए जाने चाहिए कि इन आयातित वस्तुओं के स्थान पर उपयुक्त देशी वस्तुओं का उत्पादन हो। अतः इन वस्तुओं के लिए विदेशी-विनिमय कम उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस वर्ग की अधिकांश में उन्हीं वस्तुओं के लिए विदेशी मुद्रा आवंटित की जानी चाहिए जो निर्यातित वस्तुओं के निर्माण में सहायता दे तथा जिनके स्थान पर देश में उत्पादित वस्तुओं का उपयोग नहीं हो सकता हो।

(iii) खनिज तेल—अधिकांश अर्द्ध-विकसित देशों में खनिज तेल का अभाव है। उदाहरणार्थ, भारत में खनिज तेल की आवश्यकता का कुछ भाग ही उत्पन्न होता है। शेष तेल विदेशों से आयात करना पड़ता है। वैसे भी खनिज तेल की आवश्यकता उद्योग-वन्धो और यातायात आदि की वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है। सुरक्षा के लिए भी इसका महत्त्व होता है। अतः इस मद के आयात में कटौती करना तब तक संभव नहीं है, जब तक देश में नए खनिज भण्डारों का पता लगाकर उनसे अधिक तेल निकाला जाए या वर्तमान तेल भण्डारों से ही अधिक तेल निकाला जाए और उसके शोधन की उचित व्यवस्था की जा सके, किन्तु तब की खोज करना और तेल-शोधन संस्थाएँ स्थापित करने के लिए भी विदेशों से मशीनें अन्य सामग्री एवं तकनीशियन आयात करने पड़ते हैं जिनके लिए विदेशी मुद्रा चाहिए।

(iv) रासायनिक पदार्थ—प्रत्येक देश को रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, किन्तु अधिकांश अर्द्ध-विकसित देशों में रासायनिक उद्योग अत्यन्त अविकसित होते हैं। कृषि-उद्योग आदि की प्रगति हेतु रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। सुरक्षा उद्योगों के लिए भी रासायनिक उद्योग आवश्यक हैं। इसलिए इस मद में कटौती करना अनुचित है। अतः इस मद के लिए भी आवश्यक विदेशी-विनिमय आवंटित किया जाना चाहिए।

(v) निर्मित वस्तुएँ—अर्थ व्यवस्था में चालू उत्पादन को बनाए रखने के लिए भी कुछ निर्मित पदार्थ विदेशों से आयात करने पड़ते हैं उदाहरणार्थ, भारत में इस वर्ग के प्रतिस्थापन और मरम्मत के लिए मशीनें कागज, अखबारी कागज, लोहा एवं इस्पात, अलौह धातु आदि आते हैं। इन वस्तुओं का उत्पादन देश में नहीं होता है तथा ये वस्तुएँ देश के वर्तमान उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। अतः इसके लिए भी पर्याप्त विदेश विनिमय का आवंटन किया जाना चाहिए।

(स) विकास-सम्बन्धी आयात (Developmental Imports)—आर्थिक नियोजन और विकास की दृष्टि से इस प्रकार के आयात सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं। योजनाओं में कई प्रकार की परियोजनाएँ और विपणन कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाते

हैं। प्रत्येक देश की योजनाओं में विशाल नदी-धाटी योजनाएँ, इस्पात कारखाने, भारी विद्युत उपकरण, मशीन निर्माण, इन्जीनियरिंग, रासायनिक-उर्वरक, कृषि-उपकरण तथा विविध प्रकार के कच्चे, मध्यवर्ती और निर्मित माल की आवश्यकता होती है। विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में उक्त पदार्थों का भारी मात्रा में आयात करना पड़ता है। इस स्थिति में इन परियोजनाओं के प्रारम्भ और क्रियान्वयन के लिए विदेशों से विशेषज्ञों का भी आयात करना पड़ता है। अतः इसके लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। अन्य बातें समान रहने पर विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में जितने अधिक इन पदार्थों का आयात सम्भव होगा और परियोजनाएँ पूरी की जाएँगी, उतना ही अधिक तीव्र गति से आर्थिक विकास सम्भव होगा। अनेक बार इन पदार्थों का आयात सम्भव नहीं हो पाने के कारण विकास में बाधाएँ उपस्थित होती हैं। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना, विदेशों से सामग्री आयात करने के लिए विदेशी विनिमय की कठिनाई के कारण ही भवर में पड़ गई थी। अतः विकास सम्बन्धी आयात भी आवश्यक है और इसके लिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा आवंटित की जानी चाहिए।

(द) अन्य कार्य या अदृश्य आयात (Other Work or Invisible Imports)—प्रत्यक्ष रूप से पदार्थों के आयात के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी विदेशी-विनिमय की आवश्यकता होती है। विदेशों से लिए हुए ऋण और उसकी अदायगी के लिए भी विदेशी मुद्रा चाहिए। इस प्रकार का भुगतान प्रत्येक राष्ट्र का नैतिक कर्तव्य है। साथ ही, इन अर्द्ध-विकसित देशों को भविष्य में भी विदेशों से ऋण लेना आवश्यक होता है। इसके लिए, इनकी साख और प्रतिष्ठा तभी बनी रह सकती है, जबकि ये पूर्व ऋणों का भुगतान कर दें। अतः अर्द्ध-विकसित देशों को विदेशों से लिए हुए ऋण और ऋण सेवाओं (Debt and Debt Services) के लिए भी विदेशी मुद्रा का प्रावधान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त, अर्द्ध-विकसित देशों के अनेक व्यक्ति विकसित देशों में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव द्वारा विशेषज्ञता प्राप्त करने जाते हैं, जो वहाँ से लौटकर देश के आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। चूँकि देश में विविध क्षेत्रों में तकनीशियनों और विशेषज्ञों की अत्यन्त दुर्लभता होती है अतः इन व्यक्तियों की, विदेशों में शिक्षा-दीक्षा के लिए भी पर्याप्त विदेशी मुद्रा का आवंटन किया जाना चाहिए, किन्तु इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिए कि ये व्यक्ति उन विकसित देशों में विशेषज्ञ बनकर स्वदेश आएँ और देश हित में ही कार्य करें। कई बार यह होता है कि इनका स्वदेश के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है और वे वही बस जाते हैं। इससे देश की दुर्लभ मुद्रा द्वारा विकसित बुद्धि का बहाव (Intellectual drain) होता है, इसे रोका जाना चाहिए। विभिन्न देशों में प्राथिक सहयोग की सम्भावनाओं में वृद्धि तथा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय आदि के लिए कई प्रतिनिधि-मण्डल और अध्ययन दल विदेशों को भेजे जाते हैं। उदाहरणार्थ व्यापार-प्रतिनिधि-मण्डल, उद्योग-प्रतिनिधि-मण्डल, निर्यात-सम्भावना अध्ययन-दल आदि। इनके लिए भी विदेशी मुद्रा आवंटित की जानी चाहिए। किन्तु इसके गठन और इनकी

सख्या सावधानीपूर्वक निर्धारित की जानी चाहिए। इन दलों में न्यूनतम आवश्यक व्यक्तियों को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए। साथ ही, सख्या भी कम होनी चाहिए तथा निश्चित लाभ होने की स्थितियों में ही ऐसा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, कई सांस्कृतिक-प्रतिनिधि मण्डल, सद्भावना-मण्डल, खेलकूद प्रतिनिधि मण्डल आदि विदेशों में भेजे जाते हैं। यद्यपि, पारस्परिक सद्भावना और सूझ-बूझ पैदा करने के लिए इनका भी अपना महत्व है, किन्तु इन कार्यों के लिए विदेशी-विनिमय अत्यन्त सीमित मात्रा में ही उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

आवंटन में प्राथमिकता—अत स्पष्ट है कि दुर्लभ विदेशी-विनिमय आवंटन में सर्वोच्च प्राथमिकता सुरक्षा और खाद्यान्नों को दी जानी चाहिए क्योंकि इनके साथ देश की जनता के जीवन-मरण का प्रश्न सम्बन्धित होता है। निर्वाह और विकास-सम्बन्धी कार्यों हेतु विदेशी मुद्रा, आवश्यक अपरिहार्य आयातों के लिए आवंटित की जानी चाहिए। इनमें मुख्यतः लोहा एवं इस्पात, कोयला, रेलें, विशिष्ट शक्ति योजनाएँ, उर्वरक, मशीनें आदि की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसी परियोजनाओं, जिनके कार्य में काफी प्रगति हो चकी हो या जो पूर्णता के नजदीक हो, सर्वप्रथम, विदेशी-मुद्रा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विदेशी-विनिमय के इस आवंटन में आवश्यकतानुसार केन्द्रित कार्यक्रमों (Core Projects) को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। विशेषतः उन वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी-विनिमय प्रदान किया जाना चाहिए, जो ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में सहायक हो, जिनका या तो निर्मात किया जाए या जो आयातित वस्तुओं के स्थान पर काम आकर आयातों में कमी करे। इस विदेशी-विनिमय के आवंटन और आयातों की स्वीकृति का केन्द्रित उद्देश्य निर्यातों में वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन होना चाहिए। विदेशी मुद्रा का उपयोग अधिकतर उपभोक्ता उद्योगों के लिए नहीं अपितु पूँजीगत-पदार्थों के आयात हेतु किया जाना चाहिए। नियोजन में वैसी ही परियोजनाएँ सम्मिलित की जानी चाहिए जो आवश्यक हो, जिनमें विदेशी-विनिमय की न्यूनतम आवश्यकता हो और विदेशी-विनिमय उत्पादन अनुपलब्ध कम हो। ऐसी परियोजनाओं के लिए ही विदेशी-विनिमय का आवंटन किया जाना चाहिए जो झूठी प्रतिष्ठा वाली नहीं, अपितु देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हो।

भारतीय नियोजन में विदेशी-विनिमय का आवंटन (Allocation of Foreign Exchange in Indian Planning)

अलक घोष के अनुसार, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत की विदेशी व्यापार नीति के प्रमुख तत्त्व, निर्यातों को उच्च स्तर पर बनाए रखना और उन्हीं वस्तुओं का आयात करना था जो राष्ट्र-हित में आवश्यक हो या जो विकास और नियोजन की आवश्यकताओं को पूरी करें तथा देश के पास उपलब्ध विदेशी-विनिमय साधनों तक ही भुगतान के अस्तुलन को रखा जाय। अतः इस योजना के प्रारम्भिक वर्षों में आयात से सम्बन्धित प्रारम्भ में नियन्त्रण नीति अपनाई गई, किन्तु बाद में मशीनें एवं अन्य आवश्यक उपभोग सामग्री के आयात में ऋर उदारता बरती गई। वर्ष

1953-54 में खाद्यान्नों के आयात में कमी हुई, कच्चे माल की आवश्यकताओं की पूर्ति भी स्वदेशी साधनों से करने की चेष्टा की गई। अतः कपास और कच्चे जूट का आयात भी कम किया गया। किन्तु योजना के लिए आवश्यक मशीनों के लिए विदेशी विनिमय की स्वीकृति देने में अनुदारता नहीं दिखाई गई। वर्ष 1954-55 में औद्योगिक विकास में सहायता करने हेतु अधिक उदार-आयात-नीति अपनाई गई। कच्चे माल, मशीनें तथा उपभोक्ता वस्तुओं के आयात के लिए भी विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराई गई, किन्तु ऐसी वस्तुएँ, जो देश में उत्पन्न की जाती थी, उनके आयात में कटौती की गई। 1955-56 में योजनाओं के लिए आवश्यक मशीनों और लोहे एवं इस्पात के लिए विदेशी-विनिमय अधिक आवंटित किया गया। प्रथम योजनावधि में वार्षिक औसत आयात 724 करोड़ रु रहा, जिसमें से उपभोग की औसत 235 करोड़ रु तथा कच्चे माल एवं अर्द्ध-निर्मित वस्तुओं का औसत 364 करोड़ रु था।¹ पूँजीगत वस्तुओं का औसत 125 करोड़ रु प्रति वर्ष रहा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी एवं आधारभूत औद्योगिक विकास पर काफी बल दिया गया। अतः पूँजीगत-वस्तुओं के आयात में वृद्धि हुई। प्रथम योजना के औसत वार्षिक आयात से द्वितीय योजना में वार्षिक आयात 50% अधिक हो गया। इस योजना में पूँजीगत वस्तुओं, कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुओं एवं वस्तु-पुर्जों के आयात के लिए बहुत अधिक विदेशी मुद्रा व्यय की गई। इस योजना में पूँजी वस्तुओं के आयात के लिए प्रतिवर्ष 323 करोड़ रु की विदेशी मुद्रा व्यय की गई। प्रथम योजनावधि में आयातों के लिए व्यय किए गए कुल विदेशी-विनिमय में पूँजीगत-वस्तुओं पर व्यय का भाग 17% था, जो दूसरी योजनावधि में बढ़कर 30.0% हो गया। प्रथम एवं द्वितीय योजना में व्यापारिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पदार्थों पर निम्न प्रकार विदेशी-विनिमय व्यय हुआ—

आयातित वस्तुओं की श्रेणी	प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना
	वार्षिक औसत	वार्षिक औसत
1. उपभोग वस्तुएँ	235 करोड़ रु.	247 करोड़ रु.
2. कच्चा एवं अर्द्ध-निर्मित माल	364 करोड़ रु.	502 करोड़ रु.
3. पूँजीगत-वस्तुएँ	125 करोड़ रु.	323 करोड़ रु.
योग	724 करोड़ रु.	1,072 करोड़ रु.

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि द्वितीय योजना में विदेशी-विनिमय की अधिक राशि, पूँजीगत-वस्तुओं की आवंटित की गई। द्वितीय योजना में प्रथम योजना की अपेक्षा उपभोग-वस्तुओं के आयात में केवल 12 करोड़ रु. की वृद्धि हुई जबकि पूँजीगत-वस्तुओं के आयात में 198 करोड़ रु की वृद्धि हुई। द्वितीय योजना

के दौरान विदेशी-विनिमय की बड़ी कठिनाइयाँ महसूस हुईं, अतः जुलाई, 1957 से प्रथम में कटौती की कठोर नीति को अपनाया गया, जिसके अनुसार विदेशी-विनिमय अत्यन्त आवश्यक कार्यों के लिए ही उपलब्ध कराया गया। साथ ही, अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन और रोजगार के स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक आयातों के लिए भी स्वीकृति दी गई।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी विशाल विनियोजन कार्यक्रम जारी रहे एवं भारी और पूँजीगत उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। इस योजना में आयातों हेतु बच 5,750 करोड़ रु. अनुमान लगाया गया। इसमें से 1,900 करोड़ रु. तृतीय योजना की परियोजनाओं के लिए आवश्यक मशीनें एवं साज-सज्जा के लिए आवंटित किए गए। शेष 3,650 करोड़ रु. आयात प्रतिस्थापन की सम्भावनाओं को ध्यान में रखने के पश्चात् भी आवश्यक कच्चे माल मध्यवर्ती उत्पादन, प्रतिस्थापन के लिए पूँजीगत-वस्तुएँ एवं आवश्यक उपभोग वस्तुओं के आयात के लिए आवंटित किए गए। इस प्रकार इस योजना में 1,900 करोड़ रु. की विदेशी-मुद्रा, विकासात्मक आयातों के लिए और 3,650 करोड़ रु. परिणामक आयातों के लिए आवंटित की गई। विदेशी-विनिमय के आवंटन में निर्यात-उद्योगों के लिए आवश्यक आयातों को प्राथमिकता दी गई किन्तु आयातों की वृद्धि के परिणामस्वरूप होने वाले विदेशी सकट से मुक्ति के लिए आयातों के लिए सीमित मात्रा में विदेशी-विनिमय उपलब्ध कराने की नीति जारी रही। आयात-निर्यात नीति समिति के अनुसार आयात नियन्त्रण की कार्यवाही औद्योगिक-विकास, विदेशी-विनिमय के संरक्षण और निर्यात संवर्द्धन के माधन स्वरूप अपनाई गई।

चतुर्थ योजना इस प्रकार निर्मित की गई, ताकि द्रुत आर्थिक विकास हो। इसलिए, यह योजना गत योजनाओं से भी विशाल बनाई गई। परिणामस्वरूप, अर्थव्यवस्था के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और इस योजना में सम्मिलित की गई नई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मशीनें और उपकरणों की भारी मात्रा में आयात की आवश्यकता अनुभव की गई। विदेशी ऋण सेवाओं के भुगतान के लिए भी इस योजना में अधिक व्यवस्था की गई।

नियोजित अर्थव्यवस्था के विषय में एक प्रमुख तर्क यह है कि इसमें स्वतन्त्र और प्रतिस्पर्द्धापूर्ण मूल्य-प्रक्रिया के अभाव में साधनों का विवेकपूर्ण आवंटन नहीं होता। वस्तुन मूल्यरूप में नियोजित समाजवादी अर्थव्यवस्था के समान मूल्य-प्रक्रिया नहीं होती। वहाँ मूल्य स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था में मूल्यों के प्रमुख कार्य-साधनों के आवंटन तथा माँग और पूर्ति के सन्तुलन का कार्य नहीं करते। स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था में मूल्य-पदाथों और सेवाओं की माँग और पूर्ति में साम्य स्थापित करने का प्रमुख कार्य करते हैं। इस प्रकार, सन्तुलन न केवल पदाथों और सेवाओं में, बल्कि उत्पादन के साधनों के बारे में भी स्थापित किया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी मूल्य पर किसी वस्तु की माँग, उसकी पूर्ति से बढ़ जाती है तो मूल्यों में वृद्धि होती है, परिणामस्वरूप एक ओर तो माँग कम होने की ओर उन्मुख होती है और दूसरी ओर उस वस्तु के उत्पादन की अधिक प्रेरणा मिलने से उसकी पूर्ति बढ़ती है। इन प्रकार, माँग और पूर्ति में साम्य स्थापित हो जाता है। यह साम्य उस मूल्य पर हो सकता है, जो मूल्य, मूल्य-स्तर से कुछ ऊँचा हो, किन्तु यह निश्चित रूप से उस स्तर से नीचा होता है, जो नए सन्तुलन के पूर्व था। इस प्रकार, एक बार की मूल्य वृद्धि, आगे मूल्य-वृद्धि को रोकती है और ऐसा करने पर ही मूल्य आगे अधिक कार्य को सम्पन्न करते हैं। इस प्रकार स्वतन्त्र उपक्रम वाली अर्थव्यवस्था में मूल्य एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की मूल्य-नीतिकता नहीं होती, न ही वहाँ मूल्य साधनों के आवंटन और माँग तथा पूर्ति में सन्तुलन का कार्य करते हैं। वहाँ भी मूल्य-नीतिकता का अस्तित्व तो हो सकता है, किन्तु वह पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के समान 'स्वतन्त्र' और 'प्रतिस्पर्द्धापूर्ण' नहीं होती। वहाँ मूल्य-निर्धारण, बाजार की शक्तियों के द्वारा नहीं होता, क्योंकि समाजवादी नियोजित व्यवस्था में स्वतन्त्र बाजार भी नहीं होते। अतः वहाँ 'प्रदत्त मूल्य' (Assigned Prices) होते हैं जिनका निर्धारण केंद्रीय नियोजन अधिकारी द्वारा किया जाता है। पदाथों के मूल्य ही नहीं, अपितु उत्पादन साधनों के मूल्य भी केंद्रीय नियोजन सत्ता द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, क्योंकि सरकार ही वहाँ एकमात्र

एकाधिकारी होनी है और उत्पादन साधनों का स्वामित्व और नियन्त्रण उसी में ही निहित रहता है। इस प्रकार पूर्ण नियोजित अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक जानबूझ कर बनाई हुई मूल्य प्रणाली होती है।

मूल्य-नीति का महत्त्व (Importance of Price-Policy)

विकासोन्मुख राष्ट्रों की नियोजित अर्थव्यवस्था में उचित मूल्य नीति अत्यन्त आवश्यक होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत तो इसका और भी अधिक महत्त्व होता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ स्वतन्त्र बाजार सहित विशाल निजी क्षेत्र भी क्रियाशील रहता है। व्यवस्थाओं में सरकारी नीति, पूँजी विनियोगकर्त्ताओं और उपभोक्ताओं के व्यवहार पर मूल्यों की घटा बढ़ी निर्भर करती है। निजी उद्यमियों या पूँजी-विनियोजकों का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। उनकी रुचि सदैव मूल्यों में वृद्धि करने में रहती है। ये वस्तुओं के कृत्रिम अभावों का सृजन करके भी ऐसा करते हैं। दूसरी ओर उपभोक्ताओं का प्रयत्न अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने का रहता है। उक्त दोनों वर्ग इस समस्या से सम्बन्धित आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते। ऐसी स्थिति में योजना अधिकारी को बड़ी तत्परता से मूल्यों पर नियन्त्रण करके और तत्सम्बन्धी उचित नीति को अपनाना आवश्यक होता है। मूल्यों की अधिक वृद्धि से न केवल सामान्य जनता को ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है अपितु योजना-सद्व्य, आय व्यय सम्बन्धी अनुमान भी गलत सिद्ध हो जाते हैं और योजना को उमी रूप में क्रियान्वित करना असम्भव हो जाता है। इसके विपरीत मूल्यों में अधिक गिरावट भी उचित नहीं कही जा सकती क्योंकि इससे उत्पादकों की उत्पादन प्रेरणा समाप्त हो जाती है। उत्पादन वृद्धि के लिए प्रेरणास्त्रद मूल्य होना भी आवश्यक है। अतः मिश्रित अर्थव्यवस्था में उचित मूल्य-नीति को अपनाया जाना आवश्यक होता है। यही नहीं पूर्ण नियोजित अर्थव्यवस्था में भी नियोजन सत्ता द्वारा विभिन्न वर्गों की वस्तुओं के मूल्य, सावधानी और विचारपूर्वक निर्धारित किए जाते हैं।

मूल्य-नीति का उपयोग सरकार द्वारा एक महत्त्वपूर्ण अस्त्र के रूप में किया जाता है। राज्य की मूल्य-नीति द्वारा अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र, उद्योग फर्म या व्यक्तिगत उत्पादक का हित या अहित हो सकता है। यदि देश की मूल्य नीति में कुछ त्रुटि हो, तो समग्र देश को इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ सकता है। मूल्य-स्तर को घटा-बढ़ा कर आय-वितरण को भी प्रभावित किया जा सकता है, क्योंकि मूल्य वृद्धि की अवधि में समस्त पदार्थों के मूल्य एक ही अनुपात में नहीं बढ़ते। व्यक्तिगत पदार्थों के मूल्यों में परिवर्तन को प्रभावित करके इन पदार्थों के उत्पादन और उपभोग की मात्रा को भी घटाया बढ़ाया जा सकता है। सार्वजनिक-क्षेत्र के व्यवसायों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को थोड़ा ऊँचा रख कर आर्थिक विकास हेतु पर्याप्त साधन जुटाए जा सकते हैं। इस प्रकार नियोजित

अर्थ-व्यवस्था में मूल्य-नीति बहुत महत्वपूर्ण है। डॉ. बी. के. आर. वी. राव¹ के अनुसार “साम्यवादी देशों में भी आधुनिक चिन्तनधारा से माँग और पूर्ति में बाँझनीय परिवर्तन लाने के लिए विशेषतः सरकार की शक्ति और प्रशासन पर निर्भर रहने की अपेक्षा कम से कम कुछ सीमा तक मूल्य-प्रक्रिया के उपयोग के महत्व का प्रमाण मिलता है। इस प्रकार नियोजित अर्थव्यवस्था में भी मूल्यों का घनात्मक योगदान होता है और एक बुद्धिमत्तापूर्ण नीति में व्यक्तिगत पदार्थों की माँग और पूर्ति में इन परिवर्तनों को लाने के लिए, जो अर्द्ध-विकास से विकास में हस्तान्तरण के लिए इतना आवश्यक है, मूल्य प्रक्रिया का उपयोग करना होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के भूतपूर्व गवर्नर एच. बी. आर. आयागर के अनुसार 17 वर्ष पूर्व आयोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ करने में भारत का मुख्य उद्देश्य था—ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि करना और उनके लिए जीवनयापन के विविध और अधिक समृद्ध नए मार्ग खोलना। यदि आयोजित वृद्धि का फल जनसाधारण तक पहुँचाना है, तो हमें एक मूल्य-नीति निर्धारित करनी होगी और एक सुनियोजित मूल्य ढाँचा तैयार करना होगा। मूल्य नीति का सम्बन्ध केवल किसी एक वस्तु ही नहीं, अपितु वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य और सापेक्ष मूल्यों से भी है।

मूल्य-नीति का उद्देश्य (Aims or Objectives of Price Policy)

विकासशील नियोजित अर्थव्यवस्था में, मूल्य नीति निम्नलिखित उद्देश्यों पर केन्द्रित होनी चाहिए—

- (1) योजना की प्राथमिकताओं एवं लक्ष्यों के अनुसार मूल्यों में परिवर्तन होने देना।
- (2) न्यून आय वाले उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग-वस्तुओं के मूल्यों में अधिक वृद्धि को रोकना।
- (3) मूल्य-स्तर में स्थिरता बनाए रखना।
- (4) मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्तियों पर रोक लगाना और मुद्रा-स्फीति के दोषों को बढ़ने से रोकना।
- (5) उत्पादकों हेतु प्रेरणास्त्रोच मूल्यों को बनाए रखना।
- (6) मुद्रा-प्रसार और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में उचित सम्बन्ध बनाए रखना।

मूल्य-नीति और आर्थिक विकास (Price Policy and Economic Development)

मूल्य वृद्धि आवश्यक—सामान्यतः यह माना जाता है कि आर्थिक विकास की अवधि में मूल्य-वृद्धि न केवल अपरिहार्य है, अपितु अनिवार्य भी है। विकास के

मूल्यो में ऊपर की ओर दबाव तो निहित ही है क्योंकि नियोजन हेतु भारी मात्रा में पूँजी निवेश किया जाता है। इससे तुल्य मौद्रिक आय बढ़ जाती है, किन्तु उसके अनुसार वस्तु उत्पादन नहीं बढ़ता, क्योंकि किसी परियोजना के प्रारम्भ करने के एक अवधि पश्चात् ही उससे उत्पादन प्रारम्भ होता है। अतः मौद्रिक आय की अपेक्षा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन पिछड़ जाता है और मूल्य बढ़ जाते हैं। यह मूल्य-वृद्धि विनियोग माना और परियोजनाओं के उत्पादन प्रारम्भ करने में लगने वाले समय पर निर्भर करती है। अधिक मूल्यों से उत्पादकों को भी प्रेरणा मिलती है। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य जनसाधारण का जीवन स्तर उच्च बनाना है। अतः श्रमिकों के जीवन स्तर को उच्च बनाने के लिए उनकी मजदूरी और अन्य सुविधाओं में वृद्धि की जाती है। अर्द्ध-विकसित देशों में श्रम-प्रधान तकनीकों अपनाए जाने के कारण लागत में मजदूरी का भाग अधिक होता है। अतः मजदूरी बढ़ जाने से लागतों और मूल्यों का बढ़ जाना स्वाभाविक होता है। इस प्रकार यह माना जाता है कि अधिक विकास की दृष्टि से मूल्यों में थोड़ी वृद्धि हितकर ही नहीं, अनिवार्य भी है, क्योंकि अर्द्ध-विकसित देशों के आर्थिक विकास में एक बड़ी बाधा, बचत के अभाव के कारण उपस्थित होती है। विदेशों से प्राप्त मात्रा में बचत की प्राप्ति नहीं होने पर देश में ही 'विश्रुतापूर्वक बचत' (Forced Saving) के द्वारा साधन प्राप्त किए जाते हैं। ऐच्छिक बचत मात्रा न्यूनतम उपभोग स्तर और आय में नकारात्मक अन्तर या स्वरूप अन्तर के कारण बहुत थोड़ी होती है। मूल्य-वृद्धि आय वितरण को उच्च आय वाले वर्ग के पक्ष में पुनर्वितरण करके बचत वृद्धि करने में सहायता करती है, क्योंकि इस वर्ग की बचत करने की सीमान्त-प्रवृत्ति (Marginal Propensity to Consume) अधिक होती है। परिणामस्वरूप साधनों को विकास हेतु अधिक गतिशील बनाया जा सकता है।

मूल्य वृद्धि के पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि यह विनियोग के लिए उचित वातावरण का निर्माण करती है, किन्तु इस सम्बन्ध में यह सब मुख्यतः इस बात पर निर्भर करना है कि मूल्य-वृद्धि की गति क्या है? यदि मूल्य तीव्रता से बढ़ रहे हों और अति मुद्रा प्रसार का भय हो, तो विनियोजक हतोत्साहित होंगे। कम से कम सामाजिक दृष्टि से वांछनीय परियोजनाएँ तो नहीं अपनाई जाएँगी; हाँ बहुत कम मूल्य-वृद्धि की आशा इस दृष्टि से विकास के लिए हितकर होगी।

मूल्य वृद्धि के पक्ष में एक तर्क यह भी है कि मुद्रा-प्रसार उन मौद्रिक आय का सृजन करता है, जो पहले नहीं थी। इससे देश के सुपुष्ट ससाधनों, विशेषतः जनशक्ति को गतिशील बनाने और इन्हीं उत्पादक कार्यों में नियोजित करने में सहायता मिलती है। इससे आर्थिक विकास में सहायता मिलती है।

मूल्य-वृद्धि आवश्यक नहीं—किन्तु अनेक विचारक, विकासशील अर्थ-व्यवस्था में विकास हेतु मूल्य-वृद्धि आवश्यक नहीं मानते। इस मत के समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं—

(1) बचत पर विपरीत प्रभाव—मूल्य-वृद्धि से बचत पर विपरीत प्रभाव

पड़ता है। निरन्तर मूल्य वृद्धि अधिकांश व्यक्तियों की, बचत की इच्छा और योग्यता पर विपरीत प्रभाव डालती है। मूल्य-वृद्धि देश की मुद्रा और चलन में जनता के विश्वास को डगमगा देते हैं। देश की अधिकांश बचत करने वाले अपनी बचत को बैंक-जमा, बीमा-पॉलिसियों या सरकारी-प्रतिभूतियों (Government Securities) के रूप में रखते हैं। मूल्य वृद्धि अथवा मुद्रा-प्रसार के कारण, जब इन लोगों के इस रूप में रखी हुई मुद्रा मूल्य घटता जाता है तो व्यक्तियों में बचत के स्थान पर व्यय करने की इच्छा बलवती हो उठती है, या फिर वे अपनी बचत को सोना, जमीन-जायदाद या विदेशी-विनिमय कर करने में उपयोग में लाते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में पूँजी निर्माण को धक्का लगता है। अधिकांश अपनी बचत को विदेशों में लगाते हैं।

मूल्य वृद्धि से जिस प्रकार बचाने की इच्छा पर बुरा प्रभाव पड़ता है उसी प्रकार बचाने की क्षमता भी कुप्रभावित होती है। मुद्रा प्रसार से कृषकों, औद्योगिक श्रमिकों छोटे व्यापारियों और मध्यवर्ग की वास्तविक आय में भारी कमी होती है और उनका व्यय आय से भी अधिक बढ़ जाता है। इसके विपरीत मूल्य स्थायित्व से बचत मात्रा बढ़ती है। कम से कम वे ऋणात्मक बचत को समाप्त करने या उ-हे कम करने में तो अवश्य सहायक होती है। यह एक तथ्य है कि मूल्य वृद्धि के समय में राष्ट्रीय आय में पारिवारिक क्षेत्र की बचत का भाग घट जाता है किन्तु मूल्य-स्थायित्व की स्थितियों में इस अनुपात में तीव्र वृद्धि होती है।

(ii) विकास की दृष्टि से लाभदायक विनियोग नहीं—मुद्रा प्रसार से सदैव ही लाभ और लाभदायक विनियोगों में वृद्धि हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। चिली के अनुसार वहाँ सन् 1950 और 1957 की अवधि में 10 गुनी मूल्य-वृद्धि हुई, किन्तु स्थिर-पूँजी में विनियोगों की मात्रा गिर गई। बहुधा, मूल्य-वृद्धि विनियोगों को प्रोत्साहित करती है किन्तु इस समय इस बात की बहुधा सम्भावना होती है कि विनियोक्ता विवेकपूर्ण एवं दीर्घकालीन दृष्टिकोण से विनियोग सम्बन्धी निर्णय नहीं ले पाते, तुरन्त फलदायक और अधिकाधिक लाभदायक परियोजनाएँ ही बहुधा हाथ में ले जाती हैं जो दीर्घकालीन आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होती। इस प्रकार ये विनियोग आर्थिक विकास की दृष्टि से, अधिक लाभप्रद नहीं हो पाते।

(iii) विदेशी विनिमय पर विपरीत प्रभाव—आर्थिक विकास की गति प्रारम्भ में बहुत कुछ विदेशी विनिमय साधनों पर निर्भर करती है। यह विदेशी-विनिमय या तो आयातों की अपेक्षा अधिक निर्यात करके अथवा विदेशी-पूँजी के आयात द्वारा उपलब्ध होता है। मूल्य-वृद्धि से विदेशी विनिमय के इन दोनों ही स्रोतों पर कुप्रभाव होता है। मूल्य-वृद्धि से देश में वस्तुओं की उत्पादन-लागत बढ़ जाती है और इससे निर्यात हतोत्साहित होते हैं। इससे विदेशी-विनिमय का अभाव है और ऐसी स्थिति में विनिमय नियन्त्रण, विदेशी विनिमय में सट्टे की प्रवृत्ति और विदेशी विनिमय-दर में गिरावट आती है, परिणामस्वरूप, निजी विदेश-पूँजी भी हतोत्साहित होती है।

(iv) आर्थिक विषमता में वृद्धि—निरन्तर मूल्य-वृद्धि से आर्थिक विषमता में वृद्धि होनी है क्योंकि इस समय लाभों में अधिक वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में, मूल्य-वृद्धि कतिपय व्यक्तियों को ही धनवान बनाती है और अधिकांश को निर्धनता की ओर ले जाती है। अतः आर्थिक विकास की वित्त-व्यवस्था बनाने का मुद्रा-प्रसारिक पद्धति से सामाजिक तनाव और संघर्ष बढ़ता है। यदि आर्थिक विकास का आशय आय के न्यूनतम स्तर पर रहने वाले लोगों की सहाय में कमी करना है तो तीव्र मूल्य-वृद्धि ऐसे आर्थिक विकास के कदापि अनुकूल नहीं है।

(v) अनेक देशों के उदाहरण—यदि आर्थिक विकास का आशय राष्ट्रीय आय में वृद्धि से लें तो भी मूल्य-वृद्धि आर्थिक विकास में अनिवार्य रूप से सहायक नहीं है। मूल्य-वृद्धि के बिना भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सकती है और अधिक वृद्धि होने पर भी राष्ट्रीय आय में बहुत कम वृद्धि हो सकती है। उदाहरणार्थ भारत की प्रथम योजना में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में 5% की कमी हुई, किन्तु राष्ट्रीय आय 18.4% बढ़ी। इसके विपरीत, द्वितीय योजना में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में 29.3% की वृद्धि हुई, जबकि राष्ट्रीय आय में 21.5% की ही वृद्धि हुई। तृतीय योजना में तो मूल्य 36% बढ़े, किन्तु राष्ट्रीय आय में केवल 14% की ही वृद्धि हुई। अतः मूल्य-वृद्धि आर्थिक विकास की कोई आवश्यक शर्त नहीं हो सकती। पश्चिमी जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली आदि के अनुभवों से भी यही बात सिद्ध होती है। सन् 1953-59 की अवधि में पश्चिमी जर्मनी की राष्ट्रीय आय में 12% वार्षिक दर से वृद्धि हुई, किन्तु इसी अवधि में मूल्यों में केवल 1% वार्षिक की दर से वृद्धि हुई। जापान में 1950 और 1959 की उक्त अवधि में राष्ट्रीय आय 12.3% वार्षिक की दर से बढ़ी, किन्तु इस समस्त अवधि में मूल्य केवल 2% ही बढ़ पाए। इटली में तो इस अवधि में मूल्य स्तर में 1 प्रतिशत की कमी आई, किन्तु फिर भी राष्ट्रीय आय 4 प्रतिशत बढ़ गई। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार “युद्धोत्तर वर्षों में अल्प विकसित देशों में औसत रूप से प्रति व्यक्ति उत्पादन में 4% की वृद्धि उस अवधि में हुई। जब उन्होंने अपने यहाँ मौद्रिक स्थायित्व बनाए रखा। इन देशों में मुद्रा-प्रसार के समय उत्पादन में केवल प्रथम अवधि की अपेक्षा आधी ही वृद्धि हुई। तीव्र मुद्रा-प्रसार के समय तो उत्पादन-वृद्धि की प्रवृत्ति उससे भी कम रही।”

निष्कर्ष

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मूल्य-वृद्धि आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य नहीं है। किन्तु फिर भी अधिकांश लोगों का मत है कि आर्थिक विकास को तीव्र गति देने के लिए मूल्यों में अत्यल्प वृद्धि (Gently or Moderately Increasing Prices) लाभदायक है। मूल्यों में 1 या 2% वृद्धि या ‘रेगता हुआ मुद्रा प्रसार’ (Creeping Inflation) अपरिहार्य है। किन्तु, इस बात की सावधानी बरतना

आवश्यक है कि यह 'रेंगता हुआ मुद्रा प्रसार' (Creeping Inflation) बृद्धते हुए और जुड़कते हुए (Galloping Inflation) मुद्रा-प्रसार में परिवर्तित नही हो जाए। इस प्रकार की स्थिति होने पर सब आर्थिक प्रगति प्रवरद्ध हो जाती है। भारत जैसे विकासोन्मुख देशों में इस प्रकार का भय अवश्यम्भावी है, जहाँ उद्योग और मुख्य रूप से भारी तथा आधारभूत उद्योग क्रमिक कीचड़ गति से विकसित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में खाद्य और, उपभोक्ता-वस्तुओं और औद्योगिक कच्चे माल की कमी उत्पन्न होकर, इनके मूल्य तेजी से बढ़ सकते हैं। अन्य कई वस्तुओं और अन्य सेवाओं के मूल्य भी इन वस्तुओं के मूल्यों पर निर्भर करते हैं, अतः मजदूरी और अन्य पदार्थों के मूल्य बढ़ेंगे। इस प्रकार, मजदूरी मूल्य वृद्धि (Wage-Price Spiral) चक्र चलता रहेगा, योजनाओं के अनुमान गलत हो जाएंगे और विकास की आशाएँ धूमिल हो जाएँगी।

इस प्रकार एक ओर यह मन व्यक्त किया जाता है कि मूल्य-प्रक्रिया को उत्पादन-वृद्धि करने और उत्पादन संरचना को वांछित दिशा निर्देशन के उपयोग किए जाने के लिए मूल्य नीति में कुछ लोच होनी चाहिए। दूसरी ओर, आर्थिक विकास में निहित भारी पूर्जा विनियोग के कारण उत्पन्न मुद्रा प्रसारिक-प्रवृत्तियाँ, मुख्य रूप से, आवश्यक उपभोग वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए मूल्य-स्थायित्व वांछनीय है। किन्तु, दोनों ही स्थितियों में आधारभूत वांछनीय बात यह होनी चाहिए कि बुनियादी उपभोक्ता-वस्तुओं और पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि वांछनीय है। जो मूल्य-नीति इस उद्देश्य की पूर्ति करे वही आर्थिक विकास के लिए उचित नीति है। डॉ. बी. के. आर. वी. राव के मतानुसार "जिस सीमा तक मूल्यों वृद्धि उत्पादन-वृद्धि नहीं करे, उस सीमा तक मूल्य-वृद्धि अनुचित है और इसे रोकने के लिए यथामुम्भव प्रयत्न किए जाने चाहिए। किन्तु जिस सीमा तक मूल्य-वृद्धि उपभोग या अनावश्यक दिशाओं में साधनों के उपयोग में कमी लाती है, यह वांछनीय है और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मूल्य-वृद्धि उत्पन्न-वृद्धि नहीं करने पर भी उस समय स्वीकार्य है, जबकि यह वांछनीय क्रियाओं में माँग का पुनर्निर्देशन, उत्पादन-शक्तियों का पुनर्वितरण और उत्पादन का नवीनीकरण करे।"

मूल्य-नीति के दो पहलू (Two Aspects of Price Policy)

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि नियोजित अर्थ-व्यवस्था में आर्थिक विकास के लिए सहायक उचित मूल्य-नीति अंगनाए जाने की आवश्यकता है। डॉ. बी. के. आर. वी. राव के अनुसार इस नीति के बृहत् और सूक्ष्म (Macro and Micro) दोनों पहलू होने चाहिए।

बृहत् पहलू (Macro Aspect)—बृहत् पहलू में, मूल्य-नीति, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। आर्थिक विकास में भारी विनियोगों के कारण एक ओर तो समाज के सीमित साधनों की माँग बढ़ने से मूल्य-वृद्धि होती

है, दूसरी ओर रोजगार-वृद्धि के परिणामस्वरूप, व्यक्तियों की मौद्रिक आय में वृद्धि होती है जिसका परिणाम व्यय में वृद्धि के कारण मूल्य-वृद्धि होता है। मूल्य-वृद्धि से रोजगार-आय और माँग पुनः बढ़ती है जिसके कारण पुनः मूल्य बढ़ते हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए बुनियादी उपभोक्ता वस्तुओं और आधारभूत विनियोग वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाया जाना आवश्यक है। विनियोग वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि, दीर्घकाल में, अधिक प्रभावशाली होती है, जबकि उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि मूल्य-वृद्धि को रोकने का तात्कालिक उपाय सिद्ध होती है। इसके विपरीत अनावश्यक उपभोक्ता-वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि या साधनों के अनावश्यक उपभोक्ता और पूँजीगत वस्तुओं के निर्माण हेतु उपयोग मुद्रा-प्रसारक-प्रवृत्तियों को बल देता है, क्योंकि साधन सीमित होते हैं। इस प्रकार, उनका मूल्य-वृद्धि को रोकने के लिए समुचित उपयोग नहीं हो पाता, किन्तु, विकासमान अर्थ-व्यवस्था से ऐसा होना स्वाभाविक ही है। अतः कुछ मौद्रिक और राजकोषीय उपायों की आवश्यकता होती है, जो आय तथा व्यय के उपयोग को सुप्रभावित करके वांछित दिशा प्रदान कर सकें।

भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट के अनुसार मूल्य-नीति के प्रमुख अंग मौद्रिक और राजकोषीय-अनुशासन है। “मौद्रिक नीति द्वारा व्यय और सृजनित आय को गलत व्यक्तियों के हाथों में जाने से रोकना चाहिए।” इसके द्वारा वस्तुओं का सट्टे के लिए सग्रह और उन्हें छिपाकर रखने की प्रवृत्ति पर काबू पाना चाहिए। इस सब में उचित ‘व्याज-दर की नीति’ और ‘व्यवसायिक साख नियन्त्रण’ (Selective Credit Control) के द्वारा सहायता ली जानी चाहिए। मौद्रिक-नीति के साथ-साथ ही राजकोषीय-नीति का उपयोग भी किया जाना चाहिए। मौद्रिक-नीति बैंकों आदि के द्वारा अतिरिक्त क्रय-शक्ति के सृजन को नियमित और नियन्त्रित करती है, तो राजकोषीय नीति में करारोपण (Taxation) इस प्रकार किया जाना चाहिए, जिससे व्यय किए जाने के लिए जन-साधारण के पास, विशेष रूप से ऐसे लोगों के पास जो अप्रयत्न करें, आय कम हो जाए। इस उपभोग को सप्रेम और सीमित करने तथा बचत को अधिक प्रभावकारी ढंग से गतिशील बनाने में समर्थ होना चाहिए। इस प्रकार मौद्रिक और राजकोषीय दोनों नीतियों का उद्देश्य जनता के हाथ में कम आय और क्रय-शक्ति पहुँचाना तथा इस आय में से भी अधिकाधिक बचत की प्रेरणा देना होना चाहिए। प्रो बी के आर. बी. राव ने बृहत्-नीति (Macro Policy) के कार्य-बहन को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि “मूल्यों के सम्बन्ध में बृहत् नीति व्यक्तिगत मूल्यों पर प्रत्यक्ष प्रभाव के रूप में ही नहीं, अपितु अप्रत्यक्ष रूप से आय सृजन और आय के उपयोग इन दो चल तत्वों पर अपने प्रभाव द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संचालित होती है, जो मूल्यों में समस्त परिवर्तनों के लिए मौद्रिक-संरचना को निर्धारित करते हैं।”¹ इस नीति का सार

अतिरिक्त आय के सृजन और उसके व्यय को प्रतिबन्धित करना है, जिससे माँग कम हो और मूल्य वृद्धि न हो पाए।

सूक्ष्म पहलू (Micro Aspects)—मूल्य-नीति के इस पहलू के अन्तर्गत अर्थ-व्यवस्था में आधारभूत विनियोग-वस्तुओं और आवश्यक उपभोक्ता-वस्तुओं के उत्पादन में अविकाषित वृद्धि की जाए, ताकि वह अतिरिक्त विनियोजन के परिणामस्वरूप बढ़ी हुई आय एवं उपभोग व्यय के अनुरूप हो जाए। इस उद्देश्य से नियोजन अधिकारी को इस प्रकार की नीति अपनानी पड़ेगी, ताकि एक ओर साधनों का उपयोग आर्थिक विकास के लिए आधारभूत विनियोजन वस्तुओं और बुनियादी उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में लगे तथा दूसरी ओर इन वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के उत्पादन में साधनों का उपयोग हतोत्साहित हो अर्थात् प्रथम स्थिति में मूल्य-तान्त्रिकता का उपयोग 'उत्तेजक' (Stimulant) के रूप में और द्वितीय स्थिति में 'प्रवरोधक' (Deterrent) के रूप में किया जाए। परन्तु इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिए कि ऊँचे मूल्यों के रूप में मूल्य-तान्त्रिकता का अनावश्यक वस्तुओं के उपभोग को हतोत्साहित करने के रूप में उपयोग से साधन इन आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की ओर अकर्षित नहीं होने लगे। इसी प्रकार, ऊँचे मूल्यों के रूप में मूल्य-तान्त्रिकता का आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में 'उत्तेजक' के रूप में उपयोग का परिणाम यह नहीं होना चाहिए कि इससे वांछित विनियोग वस्तुओं की माँग में कमी की प्रवृत्ति और बुनियादी उपभोक्ता वस्तुओं में मुद्रा-प्रसारिक लागत-प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाए। ऐसा होने पर मूल्य-वृद्धि द्वारा प्रोत्साहन तथा हतोत्साहन के परिणामस्वरूप वांछनीय उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकेगी। अतः सूक्ष्म पहलू का इस प्रकार से उपयोग किया जाना चाहिए ताकि कम से कम अवांछनीय बातों के साथ अधिकतम वांछनीय परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

इसके लिए अनावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की जानी चाहिए, किन्तु साथ ही, इन क्षेत्र में ऊँचे कर लगाए जाने चाहिए और साधनों का नियन्त्रित आवंटन किया जाना चाहिए। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि के लिए मूल्य-वृद्धि द्वारा प्रोत्साहन देने की प्रवृत्ति इनका उत्पादन सांख्यिक-क्षेत्र में किया जाना चाहिए। जहाँ यह सम्भव नहीं हो वहाँ भी उत्पादन-वृद्धि के लिए ऊँचे मूल्यों की प्रेरणा की अपेक्षा करो में रियायत देना अधिक श्रेयस्कर है। जहाँ कर सम्बन्धी रियायतों से भी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता हो वहाँ विक्रय-अनुदान (Sales Subsidies) दिए जाने चाहिए। आधारभूत उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित देने के लिए इनकी मूल्य-वृद्धि को रोकना चाहिए और इसके स्थान पर इनकी उत्पादन-लागत को कम करने के लिए उत्पादन में प्रयुक्त आदानों (Inputs) के मूल्य कम किए जाने चाहिए, किन्तु यदि मूल्यों में वृद्धि से किसी प्रकार बचना सम्भव नहीं हो तो मूल्य-नियन्त्रण और वितरण राज्य को अपने हाथों में ले लेने चाहिए और जनता को इन आधारभूत उपभोक्ता वस्तुओं की एक न्यूनतम आवश्यक मात्रा स्थिर मूल्यों पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए और

इस हानि की पूर्ति, न्यूनतम आवश्यक मात्रा से अतिरिक्त पूर्ति के मूल्यों में वृद्धि द्वारा की जानी चाहिए।

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में मूल्य-नीति के सिद्धान्त (Principles of Price-Policy in Mixed Economy)

आर्थिक विकास और नियोजन के सन्दर्भ में मूल्य-नीति से सम्बन्धित उपरोक्त सिद्धान्तिक विवेचन के आधार पर डॉ. बी. के. आर. बी. राव ने मूल्य-नीति सम्बन्धी निम्नलिखित सिद्धान्तों का निरूपण किया है—

1. विकासायं नियोजन में भारी पूँजी विनियोग के कारण जनता की आय में वृद्धि होती है। आय की इस वृद्धि के अनुरूप ही उत्पादन-वृद्धि होनी चाहिए अन्यथा मूल्य-वृद्धि होगी। इस उत्पादन में वृद्धि का जितना भाग अर्द्ध-निमित्त अवस्था में हो या विक्रय के लिए उपलब्ध नहीं हो, आय के उसी भाग के अनुरूप नकद सग्रह (Cash holdings) में वृद्धि होनी चाहिए। संक्षेप में, किसी ऐसे व्यय की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए जिससे या तो उत्पादन में अथवा नकद सग्रह में वृद्धि न हो।

2. अर्थ-व्यवस्था के किसी भी क्षेत्र या समूह की आय में वृद्धि के अनुरूप उस क्षेत्र या समूह के उत्पादन में वृद्धि अथवा अन्य क्षेत्रों या समूह से हस्तान्तरण होना चाहिए अन्यथा मूल्य-वृद्धि की प्रवृत्ति प्रारम्भ हो जाएगी।

3. विनियोगों में वृद्धि के अनुरूप ही वचत में वृद्धि करने के प्रयत्न किए जाने चाहिए। यदि यह सम्भव नहीं हो तो विनियोगों में भावी वृद्धि को वचत में सम्भावित वृद्धि तक सीमित कर देना चाहिए।

4. बुनियादी उपभोक्ता-वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकने का प्रयत्न करना चाहिए, भले ही सामान्य मूल्य-स्तर को रोकने का प्रयत्न आवश्यक नहीं है, क्योंकि मूल्य-स्तर में प्रत्येक वृद्धि मुद्रा-प्रसारिक नहीं होती। केवल आधारभूत उपभोक्ता-वस्तुओं की मूल्य-वृद्धि ही लागत-मुद्रा-प्रसार (Cost-inflation) के द्वारा तीव्र मूल्य वृद्धि को जन्म देती है।

5. आर्थिक विकास की अवधि में बुनियादी उपभोक्ता वस्तुओं की माँग की पूर्ण सम्भावना होती है। अतः इन वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के प्रयत्न तभी सफल हो सकते हैं, जबकि इन वस्तुओं के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो। यदि इन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हेतु मूल्य-वृद्धि को प्रोत्साहन देना आवश्यक हो तो अल्पकालीन नीति के रूप में इसका अवलम्बन किया जा सकता है। किन्तु इस बीच मूल्य स्थिर रखने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 'मूल्य-नियन्त्रण' और 'नियन्त्रित-वितरण' आदि उपायों को भी अपनाया जाना चाहिए।

6. जब तक अर्थ-व्यवस्था स्वयं-स्फूर्त अवस्था में नहीं पहुँच जाए, तब तक विकासशील अर्थ-व्यवस्था में मूल्य-वृद्धि की प्रवृत्ति जारी रहती है। किन्तु कभी-कभी से प्राकृतिक आपदाओं या कमी वाले क्षेत्रों पर कम ध्यान दिए जाने के कारण अन्य कारणों से यह प्रवृत्ति बहुत दृढ़ हो जाती है और मूल्यों में विभिन्न मौसमों,

क्षेत्रों या प्रदेशों में भारी तेजी आ जाती है। इस प्रकार की समस्याओं के निराकरण हेतु 'बफर स्टॉक' (Buffer Stock) का निर्माण किया जाना चाहिए। 'बफर स्टॉक' द्वारा सरकार अल्पकाल में पूति को माँग के अनुकूल समायोजित करने में सफल होती है। इस प्रकार, इनके द्वारा अल्पकालीन और अस्थायी वृद्धियों को रोक जा सकता है।

विभिन्न प्रकार के पदार्थों से सम्बन्धित मूल्य-नीति

कृषि पदार्थ—गठ्ठ-विकसित अर्थ व्यवस्थाओं में आर्थिक विकास के लिए उचित कृषि पदार्थ सम्बन्धी नीति का बड़ा महत्व होना है। इन पदार्थों के मूल्य माँग और पूति की स्थितियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। अधिकांश पठ्ठ-विकसित देशों में राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि-जन्य उत्पादन का भाग लगभग 50% होता है। अतः देश में सामान्य मूल्य-स्तर पर कृषि पदार्थों के मूल्य परिवर्तनों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। साथ ही, भारत जैसे गठ्ठ-विकसित देशों में उपभोक्तागण अपनी आय का अधिकांश भाग खाद्य-पदार्थों पर व्यय करते हैं जो मुख्यतः कृषि-जन्य होते हैं। जब इन पदार्थों के मूल्यों में अधिक वृद्धि होती है, तो व्यक्तियों में अप्मनोष बढ़ता है। मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए मगठित होते हैं। महुँगाई-भत्ते में वृद्धि के लिए दबाव बढ़ जाता है। कई उद्योगों के लिए कच्चा माल भी कृषि द्वारा प्राप्त होता है। इनके मूल्य बढ़ने से इन उद्योगों की लागत बढ़ जाती है और देश-विदेश में इनकी प्रतिस्पर्द्धा-शक्ति कम हो जाती है। अतः इन विकासशील देशों की योजनाओं की सफलता के लिए कृषि-पदार्थों के मूल्यों में स्थायित्व और तीव्र वृद्धि को रोकना आवश्यक है। साथ ही, मूल्य इसने कम भी नहीं होने चाहिए जिससे उत्पादकों का प्रोत्साहन समाप्त हो जाए। इस दृष्टि से बहुधा कृषि-पदार्थों के अधिकतम और न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर देने चाहिए। कृषकों को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यकतानुसार 'Price Support' की नीति को अपनाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इन पदार्थों के मूल्यों में अधिक उतार-चढ़ाव नहीं हो। इन सब दृष्टिकोणों से कृषि-पदार्थ सम्बन्धी मूल्य-नीति बहुत व्यापक होनी चाहिए जिसमें उत्पादन से लेकर वितरण तक की उचित व्यवस्था सन्निहित हो। उत्पादन वृद्धि के प्रयत्न किए जाने चाहिए और इस हेतु भूमि-सुधार, प्रकृति पर कृषि की निर्भरता में कमी तथा उर्वरक, खन्व, सास आदि आवश्यक आदानों की व्यवस्था की जानी चाहिए। मुख्य कृषि पदार्थों, विशेष रूप से खाद्यान्नों की न्यूनतम और अधिकतम मूल्य निर्धारित कर देने चाहिए। न्यूनतम मूल्य इस प्रकार के होने चाहिए ताकि कृषकों में अधिक उत्पादन की प्रेरणा बनी रहे और अधिकतम मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए जाने चाहिए जिससे उपभोक्ताओं पर अधिक भार नहीं पड़े। कृषि सम्बन्धी मूल्य-नीति का एक महत्वपूर्ण तत्त्व सरकार द्वारा 'बफर स्टॉक' का विस्तृत पैमाने पर निर्माण है। यदि स्वदेश में उत्पादन कम हो तो उचित मूल्य पर इन पदार्थों को विदेशों से आयात की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कृषि पदार्थों के उचित वितरण हेतु थोक-स्तर पर राज्य व्यापार का विस्तार, खुदरा

बिक्री के लिए स्थान-स्थान पर सहकारी और सरकारी वितरण एजेंसियों की स्थापना की जानी चाहिए। संक्षेप में कृषि पदार्थों की मूल्य-नीति से सम्बन्धित निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

- (1) मूल्य-नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे उत्पादक और उपभोक्ता दोनों पक्षों को लाभ हो।
- (2) मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- (3) विभिन्न कृषि पदार्थों के मूल्यों में सापेक्ष समानता रहनी चाहिए।
- (4) कृषि पदार्थों और औद्योगिक पदार्थों के मूल्यों में भी समानता रहनी चाहिए।
- (5) कृषि पदार्थों के उत्पादन-वृद्धि के सब सम्भव उपाय किए जाने चाहिए।
- (6) कृषि पदार्थों के वितरण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें राज्य-व्यापार, सहकारी तथा सरकारी एजेंसियों का विस्तार किया जाना चाहिए।

औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य—प्रभावशाली उपभोक्ता पदार्थ, जो विलासिता और आरामदायक वस्तुओं की श्रेणियों में आते हैं, का मूल्य निर्धारण बाजार-तान्त्रिकता पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो इनमें भी मूल्य-वृद्धि की स्वीकृति दी जानी चाहिए, किन्तु साथ ही ऊँचे कर और साधनों का नियन्त्रित वितरण किया जाना चाहिए। किन्तु औद्योगिक कच्चे माल जैसे सीमेंट, लोहा एवं इस्पात, कोयला, रासायनिक पदार्थ आदि के मूल्यों को नियन्त्रित किया जाना चाहिए। औद्योगिक निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए मूल्य नियमन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सम्बन्धित मूल्य-नीति इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे मुद्रा प्रसारित प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं हो। साथ ही, इनका उचित उपयोग और वितरण हो। घरेलू उपयोग को कम करने, निर्यात में वृद्धि करने, उत्पादन और वित्तियों के प्रोत्साहन के लिए औद्योगिक पदार्थों के मूल्यों में तनिक वृद्धि की नीति को स्वीकार किया जा सकता है, किन्तु साथ ही, मूल्य ऐसे होने चाहिए जिनसे उत्पादकों को अत्यधिक लाभ (Excessive Profit) नहीं हो। वस्तुतः औद्योगिक पदार्थों के क्षेत्र में भी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों वर्गों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। कृषि-क्षेत्र में न्यूनतम मूल्य अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कृषकों की मोल भाव करने की शक्ति कम होती है। इसके विपरीत औद्योगिक क्षेत्र में अधिकतम मूल्य अधिक महत्वपूर्ण हैं। फिर भी, न्यूनतम मूल्यों को भी निश्चित करना होगा। निर्यात योग्य पदार्थों के मूल्य, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अधिक रखे जा सकते हैं, जिससे उनका आन्तरिक उपभोग कम हो। साथ ही, बिना हानि उठाए उसे विदेशियों को सस्ते मूल्यों पर बेचा जा सके। भारत में चीनी के मूल्य निर्धारण की नीति इसी प्रकार की रही है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का मूल्य¹—निजी व्यक्तियों द्वारा उत्पादित

वस्तुओं और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्य-निर्धारण के लिए अपनाई गई नीतियाँ भिन्न हो सकती हैं। निजी-उपक्रमों में मूल्य-निर्धारण इस प्रकार होना चाहिए जिससे कर-सहित उत्पादन लागत निकलने के पश्चात् इतना लाभ प्राप्त हो ताकि पूँजी तथा उपक्रम आकर्षित हो सकें। किन्तु सरकारी उपक्रमों के समस्त मूल्य-निर्धारित करते समय व्यावसायिक दृष्टिकोण की अपेक्षा जन-कल्याण का ध्येय प्रमुख होता है। इसीलिए, सार्वजनिक उपक्रमों की स्थिति बहुधा एकाधिकारिक होते हुए भी इनके मूल्य कम हो सकते हैं क्योंकि सरकार का विचार इस रूप में उपभोक्ता को रियायत देना हो सकता है। किन्तु विभिन्न विचारकों में इस बात पर मतभेद नहीं है कि सार्वजनिक उपक्रमों की मूल्य-नीति लाभ के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए अथवा नहीं।

मूल्य-नीति से उपक्रम को लाभ—कुछ विचारकों के मतानुसार सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए जाने चाहिए जिससे उन पर विनियोजित पूँजी पर पर्याप्त लाभ हो सके। इससे जहाँ सरकार को विकास के लिए पर्याप्त धनराशि प्राप्त हो सकेगी, वहाँ मुद्रा प्रसारित प्रवृत्तियों के दमन में भी सहायता मिलेगी। इन उपक्रमों पर हानि पर चलाने से मुद्रा प्रसारित प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, क्योंकि इस प्रकार कम मूल्य वसूल करने से जनता के पास व्यय करने के लिए अधिक राशि रह जाती है। साथ ही, राजकोष में कम राशि पहुँचती है, जिनकी पूर्ति जनता से अधिक बार वसूल कर की जाती है। इन उपक्रमों द्वारा उत्पादित वस्तुएँ और सेवाएँ कम मूल्य पर बेचने से इसका शोभ सम्मान्य जनता पर पड़ता है, जबकि उसका लाभ उस वस्तु का उपभोग करने वाले कुछ व्यक्तियों को ही मिलता है। उपभोक्ताओं को एक वर्ग के रूप में इस प्रकार रियायत देना उपयुक्त नहीं है। अतः इन उपक्रमों द्वारा उत्पादित पदार्थों और सेवाओं में मूल्य इतने होने चाहिए जिससे उन्हें सन्तोषप्रद लाभ मिल सके। इससे देश की विकास योजनाओं के लिए सहज ही साधन उपलब्ध किए जा सकते हैं, यदि किन्हीं कारणों से किसी उद्योग को आर्थिक सहायता देना भी हाँ तो भी लाभ-हानि का लेखा-जोखा स्पष्ट रूप से दिखाया जाना चाहिए और उपक्रम को दी गई सहायता को अलग दिखाया जाना चाहिए।

लाभ-रहित स्थिति में भी संचालन—उन विवरण से स्पष्ट है कि इन उपक्रमों की कुशलता का मापदण्ड इनके द्वारा प्राप्त लाभ है, किन्तु ऐसा अनिवार्य नहीं है। रामा गोपालदास के मतानुसार "एक सार्वजनिक व्यवसाय हानि पर चलाया जा रहा है, किन्तु वह सस्ती गैस, बिजुत, यातायात या डाक व्यवस्था के रूप में हानि से भी अधिक सामाजिक कल्याण में वृद्धि कर रहा हो।" सार्वजनिक व्यवसायों के लिए यह बाँझनीय है कि वे स्वावलम्बी हों किन्तु व्यापक सामाजिक हितों की दृष्टि से कम मूल्य की नीति अपनाकर उन्हें 'नियोजित हानि' पर भी संचालित किया जाना अनुचित नहीं है। वस्तुतः सरकार का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं प्रसिद्ध अधिकारिक सामाजिक कल्याण होता है। अतः सरकार द्वारा उत्पादित ऐसी वस्तुओं और सेवाओं

के मूल्य कम लिए जाने चाहिए जिनका उपयोग मुख्यतः समाज के निर्धन, शोषित और पीडित व्यक्ति करें।

किन्तु इसका यह आशय कदापि नहीं है कि सरकारी उपक्रम कुशलतापूर्वक नहीं संचालित किए जाने चाहिए। उपक्रम की कुशलता एक अन्य वस्तु है जिसका मूल्य-निर्धारण से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। उत्पादन लागत से कम मूल्य पर इनकी वस्तुएँ विक्रय किए जाने पर भी उपक्रम को निजी क्षेत्र की ऐसी ही इकाई की कुशलता के स्तर पर संचालित करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लाभ-रहित स्थिति में संचालन के समर्थक इस तर्क को भी सम्योपपन्न नहीं मानते कि लाभ-मूल्य-नीति (Profit-Price-Policy) अपनाने से उपभोक्ताओं के पास व्यय के लिए कम राशि बचेगी जिससे व्यय कम होगा और मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियों का दमन होगा। ऐसा तभी सम्भव है, जबकि वह उद्योग एकाधिकारिक हो और उसकी माँग बेजोब हो।

अतः कभी-कभी यह विचार प्रस्तुत किया जाता है कि सार्वजनिक उपक्रमों की मूल्य-नीति का आधार 'न लाभ, न हानि' (No Profit, No Loss) होना चाहिए। किन्तु नियोजन द्वारा विकासशील निर्धन देशों के लिए यह नीति अनुचित है। अर्द्ध-विकसित देशों में वित्तीय साधनों की जुटाने की समस्या होती है और अधिक मूल्य की नीति अपना कर सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ योजनाओं की वित्त-व्यवस्था का एक बड़ा स्रोत बन सकते हैं। यही कारण है कि नियोजन पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ऊटी में होने वाले सेमिनार में डॉ० बी. के. राव ने 'न लाभ, न हानि' की नीति को अस्वीकार करते हुए लाभ-मूल्य नीति का समर्थन किया। आजकल भारत में योजना-आयोग भी इसी नीति पर चल रहा है और उसकी प्रत्येक योजना में सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभों पर उत्तरोत्तर अधिक निर्भरता प्रदर्शित की गई है। अन्य अर्द्ध-विकसित देशों के लिए भी यही मूल्य-नीति उचित है।

वस्तु नियन्त्रण (Commodity Control)

नियोजित अर्थ-व्यवस्था में नियन्त्रण निहित है। कई बार नियोजित अर्थ-व्यवस्थाओं में भेद, उनमें व्याप्त नियन्त्रण की प्रकृति और लक्षणों के आधार पर किया जाता है। नियन्त्रण जितने अधिक और कठोर होते हैं वहाँ नियोजन भी उतना ही कठोर होता है। इसके विपरीत जहाँ नियन्त्रण कम और सरल होते हैं, वहाँ नियोजन अधिक जनतान्त्रिक और कम कठोर होता है। इस प्रकार 'नियन्त्रण' नियोजन की एक प्रमुख विशेषता है। थॉमस विल्सन के अनुसार, "नियोजन और भौतिक नियन्त्रण इतने अधिक सम्बन्धित हैं कि इन्हें लगभग अभिन्न माना जा सकता है।"¹ इस प्रकार, नियोजन में कई प्रकार के नियन्त्रण होते हैं। वस्तुतः नियोजित अर्थ व्यवस्था का आशय ही नियोजन अधिकारी द्वारा निश्चित सामाजिक उद्देश्यों के

लिए नियन्त्रित अर्थ-व्यवस्था है पूर्ण नियोजित अर्थ-व्यवस्था अधिक नियन्त्रित रहता है, किन्तु मिश्रित जनतांत्रिक-नियोजन में नियन्त्रण अधिक व्यापक नहीं होते। किन्तु फिर भी नियोजित अर्थ-व्यवस्थाओं में वस्तु नियन्त्रण आवश्यक हो जाता है। इन अर्द्ध-विकसित देशों में नियोजन अवधि में उपभोक्ता और पूंजीगत दोनों प्रकार की वस्तुओं की मांग बढ़ती है। विकास कार्यक्रमों के लिए कई परियोजनाएँ संचालित की जाती हैं, जिनके लिए विशाल मात्रा में पूंजीगत वस्तुएँ चाहिए। ये वस्तुएँ स्वदेशों तथा आयातित दोनों प्रकार की हो सकती हैं। जिस प्रकार विकास के लिए यह आवश्यक है कि ये वस्तुएँ उचित मूल्यों पर प्राप्त हों, उसी प्रकार यह भी आवश्यक है कि अच्छी किस्म की, पर्याप्त मात्रा में और समय पर निरन्तर ये वस्तुएँ उपलब्ध हों। आवश्यकतानुसार, विभिन्न क्षेत्रों, उद्योगों, व्यक्तियों आदि में इनका उचित आवंटन हो और अनुकूलतम उपयोग हो, इसके लिए इन वस्तुओं का नियन्त्रण आवश्यक है। इसमें इनके निश्चित मूल्यों पर बिजली के साथ-साथ विभिन्न फर्मों तथा उद्योगों का कोटा (Quota) भी निर्धारित किया जा सकता है।

नियोजन के अन्तर्गत बहुधा उपभोक्ता वस्तुओं का भी अभाव रहता है। उत्पादन के अधिकांश साधनों का अधिकाधिक भाग विनियोग कार्यक्रमों में लगाया जाता है। अधिकांश उपलब्ध, वित्तीय और भौतिक साधनों का उपयोग पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में लगाया जाता है। सिंचाई, विद्युत, सीमेंट, इस्पात, मशीन और मशीनी औजार भारी विद्युत सामग्री, भारी रसायन आदि परियोजनाएँ प्रारम्भ की जाती हैं। इस प्रकार, नियोजित अर्थ व्यवस्था में साधन पूंजीगत परियोजनाओं में लग जाते हैं और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन की ओर कम ध्यान दिया जाता है। देश के आर्थिक विकास को गति देने और उसे स्वयं-सफूर्त-व्यवस्था में पहुँचाने के लिए यह आवश्यक भी है, किन्तु इससे उपभोक्ता वस्तुओं की कमी पड़ जाती है। साथ ही, नियोजन के परिणामस्वरूप व्यक्तियों की आय भी बढ़ती है, जिसे उपभोग पर व्यय किया जाता है। इससे उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। इन देशों की तीव्रता से बढ़ती हुई जनसंख्या भी इनकी मांग में वृद्धि कर देती है। ऐसी स्थिति में इनके मूल्य-वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। बहुधा उद्योगपति वर्ग वस्तु की स्वल्पता के कारण परिस्थितियों का नाजायज लाभ उठाकर अधिकाधिक मूल्य लेने का प्रयास करते हैं। इसके लिए कृत्रिम अभावों का सृजन भी किया जाता है। काला बाजार और मुनाफाखोरी को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे निर्धन वर्ग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें इन पदार्थों की आवश्यक न्यूनतम मात्रा भी प्राप्त नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में इन उपभोक्ता वस्तुओं, विशेष रूप से आवश्यक पदार्थों जैसे, खाद्यान्न, चीनी, खाद्य, तेल मिट्टी का तेल, साबुन वस्त्र आदि का नियंत्रण तो आवश्यक सा हो जाता है। केवल मूल्य नियंत्रण या मूल्य निर्धारण ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यदि कम मूल्य निश्चित कर दिए गए तो वस्तुएँ छिपा ली जाएँगी और काला बाजार (Black Market) में बेची जाएँगी या वे अच्छी किस्म की नहीं होंगी या फिर उनके उत्पादकों को पर्याप्त प्रेरणा नहीं मिलने के कारण उत्पादन

बम होगा। अतः उचित मूल्य-नीति अपनाई जाने के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि इन वस्तुओं के उत्पादन, उपभोग-विनिमय और वितरण पर पूर्ण नियन्त्रण रखा जाए। उत्पादन-स्तर पर इनके उत्पादन में कोई शिथिलता नहीं बरती जाए और क्षमता का पूरा उपयोग करके अधिकतम उत्पादन किया जाए। साथ ही, उसे बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध कराया जाए। इन वस्तुओं की बिक्री भी नियन्त्रित रूप से स्वयं सरकार द्वारा या सहकारी समितियों द्वारा नियन्त्रित एजेंसियों द्वारा की जाए। जो कुछ उपलब्ध हो उसके उचित वितरण की व्यवस्था की जाए। यदि उचित वितरण व्यवस्था न हो, जैसे कुछ लोगों को कम और कुछ लोगों को अधिक वस्तुएँ मिल सकें तो यह बात अधिक सहन नहीं की जा सकती। इन वस्तुओं के वितरण में राशनिंग (Rationing) नीति भी अपनाई जा सकती है।

भारतीय नियोजन में मूल्य और मूल्य-नीति (Prices and Price-Policy during Planning in India)

प्रथम पंचवर्षीय योजना—भारतीय नियोजन में प्रारम्भ से ही मूल्य नियमन की ओर ध्यान दिया गया है। प्रथम योजना द्वितीय विश्वयुद्ध और विभाजन जनित वस्तुओं की कमी को दूर करने और मुद्रा प्रसारिक प्रवृत्तियों को रोकने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी तथा अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने में यह सफल भी हुई। इस योजनावधि में मुद्रा-पूति में भी 13% की वृद्धि हुई और 330 करोड़ रुपये की घाटे की अर्थ-व्यवस्था की गई किन्तु मानसून की अनुकूलता के परिणामस्वरूप उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। खाद्यान्नों का उत्पादन 20%, कपास का उत्पादन 45% और तिलहन का उत्पादन 8% बढ़ गया। योजनावधि में कृषि-उत्पादन निर्देशांक 1949-50 वर्ष का आधार मानते हुए 96% से बढ़कर 117% हो गया। औद्योगिक उत्पादन में 18.4 पाइन्ट की वृद्धि हुई। उत्पादन में इस वृद्धि के साथ-साथ सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों, कोरिया-युद्ध की समाप्ति के कारण मूल्यों में गिरावट आई। सन् 1952 में थोक-मूल्य-निर्देशांक में कमी आई और कुछ समय तक मूल्यों में लगभग स्थिरता रही। सन् 1953-54 में बहुत अच्छी फसल हुई जिसके कारण मूल्यों में बहुत गिरावट आई। कुल मिलाकर योजना-काल में थोक मूल्यों के निर्देशांक में 20%, खाद्य-पदार्थों के मूल्य निर्देशांक में 25%, निर्मित-पदार्थों के मूल्य निर्देशांक में 36% और औद्योगिक सच्चे भास के मूल्य-निर्देशांक में 32% की कमी आई। योजनावधि में मूल्यों की इस गिरावट के जवाबदारी में राज्य ने यथोचित मूल्य निर्धारित करने और अनेक कार्यवाहियों द्वारा मूल्यों को इस स्तर से नीचे नहीं गिरने देने के लिए प्रयास प्रारम्भ किए ताकि उत्पादकों को मूल्यों के गिरने से हानि न हो।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना—यह योजना प्रथम योजना की अपेक्षा बहुत बड़ी थी। सांख्यिक क्षेत्र में 4,600 करोड़ रुपये व्यय किए गए। निजी क्षेत्र में 3,100 करोड़ रुपये का विनियोग हुआ। योजनावधि में 948 करोड़ रुपये की घाटे की अर्थ-व्यवस्था की गई जो समस्त योजना व्यय का 20% था। साथ ही इस

अवधि में मुद्रा पूर्ति 2,216 करोड़ रुपये से बढ़कर 2 868 करोड़ रुपये हो गई। इस प्रकार मुद्रा पूर्ति में 29% की वृद्धि हो गई। दुर्भाग्यवश कृषि-उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकी अपितु कई वर्षों में तो विगत वर्षों की अपेक्षा उत्पादन में कमी आई। उदाहरणार्थ, सन् 1957-58 में खाद्यान्नों का उत्पादन गत वर्ष की अपेक्षा 60 लाख टन कम हुआ। सन् 1959-60 में भी खाद्यान्नों के उत्पादन में इसके पिछले वर्ष की अपेक्षा 40 लाख टन की गिरावट आई। इसी वर्ष जूट, कपास और तिलहन के उत्पादन में क्रमशः 12%, 18% और 12% की गिरावट आई। इस प्रकार योजना अपने उत्पादन लक्ष्यों में काफी पिछड़ गई। परिणामस्वरूप, द्वितीय योजना में मूल्य वृद्धि होना स्वाभाविक था। जनभरपा वृद्धि ने भी इसे सहारा दिया। इस योजना में मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होती रही। योजनावधि में थोक मूल्यों का सामान्य निर्देशांक (General Index of Wholesale Prices) 33% बढ़ गया। इसी प्रकार, खाद्यान्नों, औद्योगिक बच्चे माल, निम्न वस्तुओं के मूल्य निर्देशांकों में क्रमशः 48%, 45% तथा 25% की वृद्धि हुई।

योजनावधि में मूल्य नीति के अन्तर्गत खाद्य तथा अन्य सामग्रों में उचित सन्तुलन बनाए रखने पर बल दिया गया। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रेरणास्त्रद मूल्य स्तर आवश्यक था और सरकार इस नीति को अपनाती रही। इस योजना में मूल्यों के अत्यधिक उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए खाद्यान्नों के बफर-स्टॉक के निर्माण का आयोजन किया गया। साथ ही, आयात निर्यात कोटे भी मात्रा की समय से पूर्व घोषणा, अग्रिम सोदी पर नियन्त्रण साख का नियन्त्रण एवं अन्य वित्तीय कार्यवाहियों को अपनाया गया। इसके बावजूद भी मूल्य वृद्धि को नहीं रोका जा सका। वस्तुतः योजना के अन्तर्गत उद्योग खनिज यातायात विद्युत आदि पर अधिक विनियोजन के साथ-साथ मूल्य वृद्धि रोकने के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि आवश्यक है। किन्तु भारत में कृषि उत्पादन की मात्रा मौसम और मानसून की अनुकूलता पर निर्भर करती है जो अनिश्चित है। अतः मूल्य नीति का आधार कृषिगत वृद्धियों के भंडार पर्याप्त मात्रा में बनाए रखना है ताकि कमी के समय मूल्यों को नियंत्रित रखा जा सके। द्वितीय योजना में मूल्य-नीति की निम्नलिखित कमियाँ थी—

(i) मूल्य नीति की प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं किया गया और उसके क्रियाम्वयन पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया।

(ii) मूल्य नीति से सम्बन्धित कार्यवाहियों में पारस्परिक समन्वय का अभाव था।

(iii) मूल्य-नीति की दीर्घकालीन दृष्टिकोण और आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित नहीं किया गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना—द्वितीय योजना के प्रारम्भ और तृतीय योजना के प्रारम्भ के बातावरण में पर्याप्त अन्तर था। जहाँ प्रथम योजना में मूल्यों में गिरावट आई थी वहीं अन्य योजनाओं में मूल्य 35% बढ़ गए थे। इसलिए तृतीय योजना में

मूल्य नियमन-नीति की ओर विशेष ध्यान दिया गया था। द्वितीय योजना में मूल्य-नियमन के लिए सुदृढ़ नीति को कोई विशेष महत्त्व नहीं दिया गया, किन्तु इस बात का अवश्य अनुमान लगा लिया गया था कि विकास कार्यक्रमों के लिए विनियोजन की नई माँगों की तुलना में पूर्ति कम हो होगी और इसलिए मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियों की संभावना और उनके नियन्त्रण की समस्याएँ उत्पन्न होगी। इसके बावजूद भी योजना-आयोग ने इन कठिनाइयों के भय से विकास कार्यक्रमों को कम करना उचित नहीं समझा। इस प्रकार द्वितीय योजना-निर्माण में विकास को अधिक महत्त्व दिया गया और मूल्यों की स्थिरता को आधारभूत आवश्यकता नहीं माना गया।

चिन्तु तृतीय योजना के समय परिस्थितियाँ भिन्न थीं। देश का विदेशी मुद्रा-कोष भी बहुत कम हो गया था और इसलिए विदेशों से अधिक मात्रा में पदार्थों का आयात करके वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाना भी कठिन था। विदेशी-विनिमय की स्थिति में सुधार हेतु निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी करना आवश्यक था। मूल्य-वृद्धि से योजना के कार्यक्रमों पर भी अत्यन्त दुष्प्रभाव पड़ता है। योजना की सफलता सदिग्ध हो जाती है। फिर तृतीय योजना में तो विकास कार्यक्रमों और विनियोजन की राशि द्वितीय योजना की अपेक्षा बहुत अधिक थी। तृतीय योजना में 10,400 करोड़ रुपये के विनियोजन का लक्ष्य था। ऐसी स्थिति में मूल्य-वृद्धि की सभी सम्भावनाएँ थी। अतः तृतीय योजना में एक सुदृढ़ मूल्य नीति की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था और मूल्य नियमन की आवश्यकता अनुभव की गई थी। किन्तु मूल्य-नियमन का आशय मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं होने देने से नहीं है। भारी पूँजी विनियोजन के कार्यक्रम वाली विकासोन्मुख अव्यवस्था में थोड़ी-बहुत मूल्य वृद्धि अप्रत्याशित और हानिकारक नहीं है, किन्तु मूल्यों में अधिक वृद्धि को तथा उससे आने वाले उच्चावचनों को रोकने हेतु उचित मूल्य-नीति आवश्यक थी।

तृतीय योजना में इसी आधार पर मूल्य-नीति बनाई गई थी, जिसमें कर-नीति, मौद्रिक-नीति, व्यापारिक-नीति, पदार्थ-वितरण नीति आदि को समन्वित रूप से अपनाने का आयोजन था। कर-व्यवस्था इस प्रकार की करनी थी जिससे उपभोग को योजना के अनुकूल प्रतिबन्धित और सीमित किया जा सके तथा विनियोजन हेतु पर्याप्त साधन जुटाए जा सकें। मौद्रिक-नीति द्वारा साख्त का नियमन तथा नियन्त्रण, सट्टे की सीदेवाजी तथा इस उद्देश्य से पदार्थों का सग्रह हतोत्साहित हो। व्यापारिक नीति द्वारा विदेशों से आवश्यक वस्तुओं का आयात करके बुनियादी वस्तुओं की कमी को दूर करना था। किन्तु इसके लिए दीर्घकालीन आयात को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। कुछ अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं का मूल्य-नियन्त्रण अपनाया जाना था और इनके मूल्यों को एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ने देना था। साथ ही इनके समुचित वितरण के लिए राशनिप पद्धति को भी अपनाया जा सकता था। इस योजना में मध्यस्थों और उनके लाभों को सीमित करने या समाप्त करने लिए सरकारी या सहकारी संस्थाओं द्वारा इनके वितरण को प्रोत्साहित किए जाने पर अधिक बल दिया गया था। अर्द्ध-विकसित देशों में खाद्य-पदार्थों के मूल्यों में स्थिरता

साना बहुत आवश्यक होता है। अतः इस योजना में भी खाद्यान्नों के मूल्यों में यथोचित स्थिरता लाना आवश्यक था। इसके लिए सरकार द्वारा खाद्यान्नों के मग्नह को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाना था। साथ ही, मूल्य-वृद्धि को रोकने लिए कृषि और औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि का माग्नह था।

इनके बावजूद भी इस योजना में निरन्तर तेजी से मूल्य वृद्धि हुई। मुख्यतः कृषि पदार्थों के मूल्य काफी बढ़ गए। योजना के प्रथम दो वर्षों में तो मूल्य-वृद्धि नगण्य थी। सन् 1961-62 में समस्त पदार्थों के मूल्य निर्देशांक में 4.6 पाइंट की गिरावट आई। किन्तु सन् 1962-63 से मूल्य-वृद्धि शुरू हुई और यह वृद्धि योजना के अन्त तक जारी रही। तृतीय योजना के इन पाँच वर्षों में खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित थोक मूल्य निर्देशांक 48.4% बढ़ गया। औद्योगिक कच्चे माल, निर्मित माल और समस्त पदार्थों के थोक मूल्य निर्देशांक में क्रमशः 32.6%, 22.1% और 36.4% की वृद्धि हो गई। परिणामस्वरूप, भविल भारतीय उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक (All India Consumer Price-Index) (आधार वर्ष 1949=100) योजना के प्रारम्भ में 125 से सन् 1965-66 में 174 हो गया। इसी प्रकार तृतीय योजना में भी मूल्यों में बहुत वृद्धि हुई। इस मूल्य-वृद्धि के लिए पदार्थों की मांग और पूर्ति दोनों से सम्बन्धित घटक उत्तरदायी थे। इस योजनावधि में चीनी और पाकिस्तानी आक्रमण के कारण सुरक्षा-अपग्र में भारी वृद्धि हुई। सावजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में वैसे भी पर्याप्त पूर्ति विनिर्भोजन की गई। जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही, किन्तु कृषि-उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकी। साथ ही 1.150 करोड़ रुपये के हीनाय-प्रवर्धन का सहारा लिया गया। मुद्रा-पूर्ति में भी 51.8% की वृद्धि हुई। योजनावधि में करो द्वारा भी पर्याप्त राशि एकत्रित की गई। विशेषतः अप्रत्यक्ष करो का अधिक आश्रय लिया गया। इसी कारण मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई।

योजनावधि में इस वृद्धि को रोकने के लिए प्रयत्न किए गए। खाद्यान्नों के मूल्यों को नियन्त्रित करने की ओर विशेष ध्यान दिया गया। उचित मूल्य की दुकानों (Fair Price Shops) की संख्या बढ़ाई गई। सरकार ने अनुदान देकर खाद्य नों को कम मूल्य पर जनता को उपलब्ध कराने के प्रयत्न किए। इन उचित मूल्य वाली दुकानों से जनता को विनिरित प्रताज की मात्रा निरन्तर बढ़ती गई। यह सन् 1962 में 43 लाख से बढ़ कर 1965 में दुगुने से अधिक हो गई। खाद्यान्नों के मग्नह के अग्रिक और अच्छे प्रयत्न किए गए। विदेशों से पर्याप्त मात्रा में अन्न का आयात किया गया। बड़े-बड़े नगरीयों में उचित विनरण के लिए खाद्यान्नों के राजनिग का सहारा दिया गया। खाद्यान्नों और आवश्यक पदार्थों के मूल्यों को निरंतरित किया गया और उन्हें वसूत किए जाने का माग्नह किया गया। आवश्यक उपभोग वस्तुओं के अधिक मूल्य लेने और उनके अनावश्यक मग्नह को रोकने के प्रयत्न किए गए। रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर साव नीति में इस प्रकार के परिवर्तन किए गए जिनसे बुनियादी उपभोग-वस्तुओं के अनावश्यक मग्नह को रोकता जा सके। इसके लिए भारत सुरक्षा नियमों (Defence of India Rules) का सहारा लिया गया और

अनधिकृत सग्रहकर्ताओं दण्डित करने का आयोजन किया गया। किन्तु इसके बावजूद भी तृतीय योजना में मूल्य-वृद्धि को रोका नहीं जा सका। निम्नलिखित सारणी में विभिन्न पदार्थों की वार्षिक वृद्धि दरें दी गई हैं—

मूल्य-निर्देशों की मे वार्षिक वृद्धि दरें (प्रतिशत में)¹

पदार्थ	द्वितीय योजना	तृतीय योजना	1960-67
1 सम्पूर्ण वस्तुएँ	7.0	6.4	15.0
2. खाद्यान्न	7.7	8.1	18.4
3 औद्योगिक कच्चा माल	9.4	6.6	20.8
4 निर्मित वस्तुएँ	4.9	4.1	9.2

एकवर्षीय योजनाओं मे मूल्य—उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि द्वितीय योजना में शुरू हुआ मूल्य-वृद्धि का क्रम तृतीय योजना में भी जारी रहा और प्रथम एकवर्षीय योजना सन् 1966-67 में तो मूल्यों में वृद्धि-दरें सर्वोपरि रही। केवल इसी वर्ष में समस्त वस्तुओं के मूल्यों में 15% और खाद्यन्नों के मूल्यों में 18.4% की वृद्धि हुई। औद्योगिक कच्चे माल के मूल्यों में भी तेजी से वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण सूना था। सन् 1967-68 में, थोक मूल्यों में 11% और खाद्य पदार्थों के मूल्यों में 21% की वृद्धि हुई। परन्तु सन् 1968-69 की अवधि में मूल्यों में अपेक्षाकृत स्थिरता आई। कुछ पदार्थों के मूल्यों में गिरावट आई। इसका एक प्रमुख कारण मानसून और मौसम की अनुकूलता के कारण कृषि-उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होना है।

चौथी और पाँचवीं योजनाएँ—चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना में स्वायत्त के साथ प्राथमिक विकास (Growth with Stability) करने का उद्देश्य रखा गया। योजना से सम्बन्धित 'Approach Paper' में स्वायत्त को निम्नलिखित दो उद्देश्यों से सम्बन्धित किया गया—

(i) कृषि पदार्थों की भौतिक उपलब्धि में घटने वाले अधिक उच्चावचनो को रोकना।

(ii) मूल्यों में निरन्तर मुद्रा-प्रसारित वृद्धि को रोकना।

प्रथम उद्देश्य से सम्बन्धित मुख्य कार्यक्रम कृषि पदार्थों के 'बफर-स्टॉक' का निर्माण करना था। अतः चतुर्थ योजना में पर्याप्त बफर-स्टॉक का निर्माण करने का निश्चय किया गया। मुख्य रूप से घनाजों के बफर-स्टॉक बनाने पर अधिक ध्यान दिए जाने की बात कही गई। यह आशा व्यक्त की गई कि सरकार मुख्य कृषि-पदार्थों की सापेक्षिक मूल्य-परचना को स्थिर बनाने और इन्हें इस प्रकार नियमित करने की स्थिति में होगी ताकि योजना के कई उद्देश्यों को पूरा करने में योग मिले।²

दूसरे उद्देश्य के बारे में यह मत व्यक्त किया गया कि मूल्यों में निरन्तर मुद्रा प्रसारित वृद्धि को रोकना मुख्य रूप से हीनार्थ प्रबन्धन में समय पर निर्भर करता है।

1 रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन, जून 1967, पृष्ठ 742

2 Notes on Approach to the Fourth Plan, Growth

साथ ही, मूल्यों में सम्भावित वृद्धि को रोकने हेतु अन्य उपाय और नीतियाँ भी अपनाई जाएँगी। 'उचित मूल्य की दूकानें' और 'उपभोक्ता सहकारी भण्डारों' का पर्याप्त माना में विस्तार किया जाएगा और उनकी परिधि में अनेक नई वस्तुएँ भी लाई जाएँगी। इससे आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में स्थायित्व लाया जा सकेगा। इस प्रकार की व्यवस्था, विशेष रूप से मौसमी उतार-चढ़ावों को रोकने और आकस्मिक दबावों (Sudden pressures) का सामना करने के लिए अधिक सहायक होगी। इस ओर किए गए पूर्व प्रयत्नों का एकीकरण और विस्तार किए जाने का निश्चय किया गया ताकि पर्याप्त व्यापक और कुशल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public system of distribution) को जन्म दिया जा सके। विदेशों से वस्तुओं का आयात और अर्थव्यवस्था के सुचालन हेतु आवश्यक विदेशी पदार्थों की प्राप्ति सार्वजनिक अभिकरणों द्वारा किए जाने पर भी बल दिया गया।

उक्त योजना में यह माना गया कि मूल्य स्तर को स्थिर बनाए रखने में कृषि-उत्पादन का महत्वपूर्ण भाग होता है। यह कहा गया कि हाल ही के अनुभवों से ज्ञात होता है कि जीवन-स्तर की लागत में निर्देशांक (Cost of Living Index Number) में खाद्यान्नों के मूल्य निर्णायक महत्व रखते हैं। अतः रहन सहन के व्यय को स्थिर बनाए रखने हेतु खाद्यान्नों के मूल्यों को स्थिर रखना आवश्यक है। अतः योजना में खाद्यान्नों के उत्पादन और मुख्य रूप से कृषि-उत्पादन में वृद्धि की अनिवार्यता स्वीकार की गई। चतुर्थ योजना में कृषि-उत्पादन में 5% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया। साथ ही, औद्योगिक उत्पादन में 9% प्रतिवर्ष की वृद्धि तथा अन्य क्षेत्रों में पर्याप्त वृद्धि का लक्ष्य रखा गया।

पाँचवी योजना में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि आर्थिक विकास इस ढंग से हो ताकि मुद्रा-स्फीति न होने पाए, मूल्यों के बढ़े हुए स्तर में गिरावट आए निर्धन व्यक्तियों के लिए उचित मूल्यों पर उपभोग वस्तुएँ प्राप्त हो सकें—इसके लिए पर्याप्त वसूली और उचित वितरण प्रणाली स्थापित की जाए।

सरकारी प्रयत्न—सम्पूर्ण नियोजन की अवधि में मुद्रा-प्रसारित प्रवृत्तियों के दमन हेतु सरकारी प्रयत्न दोनों दिशाओं से किए गए हैं। इसमें आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाने और अत्यधिक माँग को संयमित करने के प्रयत्न किए हैं। आवश्यक वस्तुओं की उत्पादन वृद्धि के लिए सभी उपाय किए गए हैं। कृषकों को उत्पादन हेतु आवश्यक प्रेरणा प्रदान करने हेतु वस्तुओं के न्यूनतम मूल्य निर्धारित किए गए हैं। खाद्यान्नों के बफर-स्टॉक का निर्माण, उसमें अधिक प्रच्छा सग्रहण (Procurement), इनका राजकीय व्यापार और भारी मात्रा में विदेशों से आयात की व्यवस्था की गई है। आन्तरिक वितरण के लिए सम्पूर्ण देश को खाद्यान्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया और गेहूँ, चावल आदि आवश्यक वस्तुओं के स्वतन्त्र रूप से लाने से जाने को नियन्त्रित किया गया। उपभोग वस्तुओं की उचित वितरण व्यवस्था के लिए 'सहकारी उपभोक्ता भण्डार' सुपर बाजार (Super Markets) और पर्याप्त मात्रा में 'उचित मूल्य की दूकानें' स्थापित की गईं। सरकार को कृषि पदार्थों के सम्बन्ध

में सलाह देने के लिए सन् 1965 में 'कृषि मूल्य आयोग' (Agricultural Price Commission) नियुक्त किया गया। वस्त्र, साबुन, वनस्पति घी, मिट्टी का तेल, खाद्य, तेल दूध, टायर आदि सामान्य उपयोग की वस्तुओं के मूल्यों को नियन्त्रित और नियमित किया गया। सीमेन्ट, इस्पात, कोयला, चीनी आदि के वितरण और मूल्यों के बारे में भी नियन्त्रण की नीति अपनाई गई। उपभोग को सीमित करने के हेतु मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ अपनाई गईं। राजकोषीय नीति में बर-वृद्धि, गैर-विकास व्यय में कटौती, कर-चोरी को रोकना, काले धन का पता लगाना, ऐन्ड्रूड बचन में वृद्धि करना आदि के उपाय अपनाए गए। मौद्रिक-नीति के अन्तर्गत साख-नियन्त्रण हेतु खुले बाजार की नीति (Open Market Operations), बैंक-दर (Bank Rate) में वृद्धि, चयनात्मक साख नियन्त्रण (Selective Credit Control) और मुरक्षित कोष की आवश्यकताओं में परिवर्तन आदि के सब उपाय अपनाए गए। इसके बावजूद भी नियोजित विकास अवधि में भारत में मूल्यों में स्थायित्व नहीं लाया जा सका और मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई। सन् 1972-73 और 1973-74 में तो थोक और फुटकर मूल्यों में भारी वृद्धि हुई जिससे जन-साधारण के लिए जीवन-निर्वाह भी कठिन हो गया।

सरकार ने मूल्य-वृद्धि को रोकने के लिए समुचित और तर्क सगत मूल्य-नीति को कठोरतापूर्वक लागू करने का निश्चय किया। उत्पादन वृद्धि के लिए बचत दर अधिक करने और मुद्रा-स्फीति को निष्प्रभावी बनाने के लिए 'हीनार्थ प्रश्नवन' की व्यवस्था पर अकुश लगाने का निश्चय किया गया। मूल्य नियन्त्रण के लिए प्रशासकीय मशीनरी को अधिक प्रभावशाली बनाने पर ध्यान दिया गया। खाद्यान्नों के उत्पादन के सम्बन्ध में व्यावहारिक अनुमान लगाने और मूला-ग्रस्त क्षेत्रों में समय-समय पर खाद्यान्नों को पहुँचाने की नीति पर अधिक प्रभावी रूप से अमल किया जाने लगा। सन् 1975-76 में मूल्य-नीति इस बात को ध्यान में रख कर बनाई गई कि कृषि गत वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता आ सके। इसी दृष्टि से सन् 1975-76 के विक्री के मोनम (अप्रैल मार्च) के लिए गेहूँ की वसूली का मूल्य गन वर्ष के स्तर पर अर्थात् 105 रुपये प्रति क्विन्टल रखा गई। 'कृषि-मूल्य आयोग' ने भी महसूस किया था कि सरकार ने गत वर्ष जो वृद्धि स्वीकार की है, वह उस समय से कृषि उत्पादन सामग्री में हुई वृद्धि की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त है। अधिक वसूली के लिए बोनस स्कीम पर अधिक व्यवस्थित रूप से अमल किया गया। मूल्य स्तर को रोकने के उपायों को मुश्किल करने के लिए खरीफ के अनाज के भूखण्डों के बारे में मूल्य-नीति निर्धारित की गई। 'कृषि मूल्य आयोग' की सिफारिशों के अनुरूप खरीफ के अनाज की वसूली का मूल्य 1974 के स्तर पर ही रखा गई। आयोग के सुझाव पर विचार किया गया कि चावल की वसूली के सम्बन्ध में दो प्रकार की प्रोत्साहन बोनस स्कीमों को जारी किया जाए और मिला दिया जाए ताकि लक्ष्य पूर्ति को सुनिश्चित करने में सहायता मिले। कृषि-मूल्य-आयोग ने अनाज की वसूली के मूल्यों में तो कोई परिवर्तन करने की सिफारिश नहीं की थी, लेकिन अपनी रिपोर्ट में गन्ना, जूट और

कपास के न्यूनतम समर्थित मूल्यों में वृद्धि करने का सुझाव दिया था। सरकार ने स्थिति पर पूर्णरूप से विचार करने के पश्चात् गन्ने का मूल्य ज्यों का त्यों रखने का फैसला किया क्योंकि कृषकों के हित को ध्यान में रखते हुए गान्धूनी न्यूनतम मूल्य महत्वहीन था। निर्धारित न्यूनतम मूल्य में वृद्धि करने का सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ता, कि लेवी चीनी की लागत और मूल्य बढ़ाने पड़ते और उपभोक्ता के लिए चीनी का मूल्य बढ़ाना पड़ता। सन् 1974-75 के मौसम में भी लेवी चीनी का अनुपात 70 से घटा कर 65 करके लेवी चीनी की एक समान अखिल भारतीय कीमत बनाए रखी गई थी, जिससे चीनी मिल उद्योग को जो लाभ मिलता है, वह कम न हो। लेवी चीनी का अनुपात घटाने से सरकारी वितरण प्रणाली पर कोई बुझाव नहीं पड़ा, क्योंकि सन् 1974-75 में 48 लाख मेट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ। कपास और जूट के समर्थित मूल्यों के बारे में सरकार ने 'कृषि मूल्य आयोग' की सिफारिशें मान लीं। कपास का उत्पादन अधिक होने पर इसके मूल्य तेजी से नहीं गटे और चालू वर्ष में भी कपास की अच्छी फसल होने पर मूल्यों में गिरावट नहीं आई। इसके लिए आवश्यक कार्यवाही करने के प्रति सरकार सतर्क है। यद्यपि 1975-76 में विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप मूल्यों को स्थिर रखने पर अधिक जोर दिया गया है, तथापि उत्पादन लागत में हुई अनिवार्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह सम्भव नहीं हो सका है कि मूल्यों में कोई परिवर्तन न किया जाए। उपभोग वस्तुओं के मूल्यों में जमा-खोरी, तस्करी आदि के कारण वृद्धि न हो, इसके प्रति सरकार आपात्काल के दौरान बहुत अधिक सज्जित हुई है और इसके परिणाम भी सामने आए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, मूल्य-वृद्धि को रोकना सरकारी-नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। जहाँ तक अनाज और चीनी का सम्बन्ध है, इस व्यवस्था के अन्तर्गत इन चीजों के वितरण का कार्य उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम द्वारा किया जाता है। सम्पूर्ण देश में इन दुकानों का एक जाल सा बिछा हुआ है। अधिक समीक्षा 1975-76 के अनुसार, इस समय ऐसी दुकानों की संख्या 2 लाख 23 हजार है और ये 45 36 करोड़ व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं।

परियोजना मूल्यांकन के मानदण्ड;
विशुद्ध-वर्तमान मूल्य और प्रतिफल
का आन्तरिक-दर, प्रत्यक्ष और
अप्रत्यक्ष लागत एवं लाभ

(Criteria for Project Evaluation; Net Present
Value and Internal Rate of Return; Direct
and Indirect Costs and Benefits)

परियोजना मूल्यांकन के मानदण्ड
(Criteria for Project Evaluation)

विनियोजक के समक्ष अनेक विनियोग-विकल्प होते हैं। सर्वाधिक लाभदायक विनियोग सम्बन्धी निर्णय अत्यन्त कठिन होते हैं। विनियोजक के लिए यह निर्णय लेना कि किस परियोजना में पूँजी विनियोग करे, अनेक मानदण्डों पर निर्भर करता है। विनियोग सम्बन्धी निर्णय लेने की अनेक विधियाँ हैं। इन विधियों के अन्तर्गत विनियोग परियोजना के 'लागत प्रवाह' (Cost flows) तथा 'आय प्रवाह' (Income flows) का विचार किया जाता है। इन प्रवाहों के विश्लेषण द्वारा विनियोग निर्णय लिए जाते हैं। प्रवाहों के विश्लेषण की तकनीकी को प्रायः 'लाभ-लागत विश्लेषण विधि' (Cost Benefit Method) कहा जाता है। इस विधि का मुख्य आधार विनियोग के प्रतिफल की आन्तरिक दर को ज्ञात करना होता है। यह दर अनेक विधियों द्वारा ज्ञात की जा सकती है। इसे छ कल्पित विनियोग परियोजनाओं के एक उदाहरण द्वारा अप्रलिखित सारणी में समझाया गया है।

सारणी 1

परियोजना लागत एवं प्रतिफल दर¹
(Project Costs and Rate of Returns)

परियोजना (Project)	0	1	2	3	4	5	शुद्ध अवधि 1—5 (Net Periods)	शुद्ध आय 0—5 (Net returns Periods)
A	—100	100	10	—	—	—	110	10
B	—100	50	50	10	10	—	120	20
C	—100	40	30	30	20	—	130	30
D	—100	28	28	28	28	—	140	40
E	—100	10	20	30	40	—	150	50
F	—100	—	—	—	40	—	160	60

उक्त सारणी के माध्यम में परियोजना मूल्यांकन की निम्न तीन प्रकार की प्रतिफल-दरों की गणना की गई है—

(1) औसत प्रतिफल-दर (Average rate of return)

(2) मूल-राशि की प्राप्ति से सम्बन्धित अवधि वाली प्रतिफल-दर (Pay off period rate of return)

(3) आन्तरिक प्रतिफल-दर (Internal rate of return) ।

(a) प्रत्येक योजना का मूल लागत व्यय 100 रुपये है । (b) प्रत्येक की परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है । (c) प्राप्त लाभों के पुन विनियोग की सम्भावना पर विचार नहीं किया गया है ।

1 से 5 तक के कॉलमों में प्रति वर्ष होने वाले आय-प्रवाहों को प्रदर्शित किया गया है । शून्य अवधि वाले कॉलम में प्रत्येक परियोजना की लागत कम बताई गई है । अन्तिम कॉलम में कुल लाभों में से मूल लागत व्यय को घटाकर विद्युद्ध लाभ बताए गए हैं । अन्तिम से पूर्व वाले कॉलम में परियोजना की पूरी 5 वर्ष की अवधि वाले कुल लाभ बताए गए हैं ।

(A) औसत प्रतिफल-दर विधि

(Average Rate of Return Method)

औसत प्रतिफल-दर निम्नलिखित दो प्रकार की होती है—(a) प्रारम्भिक विनियोग पर कुल औसत प्रतिफल दर, (b) प्रारम्भिक विनियोग पर शुद्ध औसत प्रतिफल दर । प्रारम्भिक विनियोग पर कुल औसत प्रतिफल दर को प्रत्येक परियोजना के कुल लाभों की योजनावधि से विभाजित करके निकाला जाता है । इस प्रकार A, B, C, D, E, F परियोजनाओं के लिए यह दर क्रमशः 22, 24, 26, 28,

30, 32 होगी। प्रारम्भिक वित्तियोग पर शुद्ध औसत प्रतिफल दर अन्तिम कॉलम में दिए गए शुद्ध लाभो को अवधि से विभाजित करके ज्ञात की जाती है। उक्त परियोजनाओं के लिए यह दर क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 व 12 है।

(B) मूल लागत की प्राप्ति वाली प्रतिफल दर (Pay off Period Rate of Return)

मूल लागत की प्राप्ति जिस अवधि में होती है उसकी गणना करते हुए प्रतिफल दर इस प्रकार ज्ञात की जाती है—उन लाभो को जोड़ लिया जाता है, जो मूल लागत के बराबर होते हैं। जिस अवधि तक लाभो का योग मूल लागत के बराबर होता है, उस अवधि के आधार पर प्रतिफल-दर का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। उक्त उदाहरण में परियोजना A के लिए केवल एक ही वर्ष में इसका लागत व्यय प्राप्त हो जाता है। अतः इसे 100% के रूप में व्यक्त किया जायेगा। B परियोजना में चूँकि मूल लागत दो वर्षों में प्राप्त होती है, अतः प्रतिवर्ष औसत प्राप्ति दर 50% होगी। C परियोजना में मूल लागत की प्राप्ति में 3 वर्ष लगते हैं। अतः प्रतिवर्ष की औसत प्राप्ति-दर $\frac{100}{3}$ या 33 $\frac{1}{3}$ % होती है। इस प्रकार, सभी परियोजनाओं के प्रतिशत में औसत दर ज्ञात की जा सकती है, वह क्रमशः 28%, 25%, तथा 22 $\frac{2}{9}$ % होगी।

उक्त विधियों में एक गम्भीर दोष यह है कि इनमें शुद्ध लाभो की प्रत्येक अवधि का विचार नहीं किया जाता। केवल वार्षिक औसत निकाला जाता है। यद्यपि मूल्य राशि की प्राप्ति से सम्बन्धित अवधि वाली प्रतिफल दर (The Pay off Period Rate of Return) में समय का विचार किया जाता है, तथापि उस अवधि को छोड़ दिया जाता है, जिसमें पूर्व लागत व्यय की वसूली हान के पश्चात् भी लाभो का मिलना जारी रहता है।

(C) आन्तरिक प्रतिफल दर (Internal Rate of Return)

प्रान्तरिक प्रतिफल दर वाली विधि इन सभी से थोड़ा मानी जाती है, क्योंकि इसमें उन समस्त वर्षों की गणना में विचार किया जाता है, जिनमें लागत घोर लाभ होते रहते हैं। आन्तरिक प्रतिफल-दर की परिभाषा उस कटौती-दर के रूप में की जाती है, जो लाभ व लागत के प्रवाहों के वर्तमान कटौती मूल्य को शून्य के बराबर कर देती है। आन्तरिक प्रतिफल-दर (IRR) विभिन्न परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है—

$$-Y_0 + \frac{Y_1}{(1+r)} + \frac{Y_2}{(1+r)^2} = 0$$

जिसमें $-Y_0$ = मूल लागत तथा Y_1 व Y_2 प्रथम व द्वितीय वर्ष के लाभ प्रकट करते हैं। r = आन्तरिक प्रतिफल-दर। $\frac{1}{(1+r)} = x$ रखते हुए उक्त

समीकरण को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

$$-Y_0 + Y_1x + Y_2x^2 = 0$$

इस समीकरण में परियोजना A के लाभ-आगत राशियों को रखकर इस योजना की आन्तरिक प्रतिकल दर निम्न प्रकार निकाली गई है—

$$-100 + 100x + 10x^2 = 0$$

$$\text{या } 10x^2 + 100x - 100 = 0$$

$$\text{या } x^2 + 10x - 10 = 0$$

$$\therefore x = \frac{-10 \pm \sqrt{(10)^2 - 4 \times -10}}{2}$$

$$x = .916 \text{ मान को, } r = \frac{1-x}{x} \text{ रखने पर आन्तरिक प्रतिकल दर}$$

9.1% या 09 आती है। इसी प्रकार अन्य परियोजनाओं की दर ज्ञात की जा सकती है, जो क्रमश 10.7, 11.8, 12.4, 12.0 व 10.4 है।

उक्त परिणामों को निम्नलिखित सारणी में स्पष्ट किया गया है—

सारणी 2

परियोजना प्रतिकल दर
(प्रतिशत में)

	(A)		(B)	(C)
	ओसत प्रतिकल-दर		मूल-राशि की प्राप्ति से	आन्तरिक
परियोजना	(i) विनियोग पर कुल प्रतिकल	(ii) विनियोग पर शुद्ध प्रतिकल	सम्बन्धित अवधि वाली प्रतिकल दर (Pay off period rate of return)	प्रतिकल-दर (IRR)
A	22	2	100	9.1
B	24	4	50	10.7
C	26	6	33½	11.8
D	28	8	28	12.4
E	30	10	25	12.0
F	32	12	22⅔	10.4

उक्त विधियों के अतिरिक्त, वर्तमान मूल्यों के आधार पर भी विभिन्न परियोजनाओं के तुलनात्मक लाभ देखे जा सकते हैं। परियोजना के वर्तमान मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है—

$$\text{वर्तमान मूल्य} = \frac{R_1}{(1+r)} + \frac{R_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{R_n}{(1+r)^n} + \dots$$

*Quadratic समीकरण के सूत्र $-b \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ के अनुसार x का मूल्य ज्ञात किया गया है।

इस समीकरण में r का अर्थ ब्याज की बाजार-दर से है। R परियोजना से प्राप्त लाभों को प्रकट करते हैं। दी हुई परियोजनाओं के वर्तमान मूल्य $2\frac{1}{2}\%$, 8% तथा 15% के आधार पर निकाले गये हैं। इन परिणामों को सारणी 3 में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 3

विभिन्न ब्याज दरों पर परियोजनाओं के वर्तमान मूल्य¹
(Project Present Values at Different Interest Rates)

परियोजना	$2\frac{1}{2}\%$	8%	15%
A	7.1	1.2	— 5.4
B	14.8	4.5	— 6.4
C	22.4	8.0	— 6.4
D	30.1	11.8	— 6.2
E	37.1	13.6	— 8.7
F	42.3	11.1	— 17.4

सारणी के आधार पर विभिन्न परियोजनाओं को उनके प्रतिकल की अधिकता के क्रम में विभिन्न श्रेणियों में विभक्त कर, यह देखा जा सकता है कि कौनसा विनियोग विकला अन्य विकला से कितना अधिक लाभदायक है।

सारणी 4 में इन श्रेणियों को दर्शाया गया है।

सारणी 4

नियोजन की वैकल्पिक विधियों द्वारा परियोजनाओं को प्रदत्त श्रेणी²

श्रेणी	स्रोत प्रतिकल दर	प्रविधि (Pay off Period)	आन्तरिक ब्याज दरों पर वर्तमान मूल्य प्रतिकल-दर	$9\frac{1}{2}\%$	8%	15%
1	F	A	D	F	E	A
2	E	B	E	E	D	D
3	D	C	C	D	F	B
4	C	D	B	C	C	C
5	B	E	F	B	B	E
6	A	F	A	A	A	F

इन श्रेणियों को ध्यान में रखकर विनियोजक विनियोग-विकल्प का चुनाव करता है। सर्वप्रथम वह प्रथम श्रेणी के विनियोग में अपनी पूंजी लगाता है। उदाहरणार्थ वह स्रोत प्रतिकल-दर विधि का प्रयोग करता है तो सर्वप्रथम F परियोजना में विनियोग करेगा। Pay off प्रविधि विधि के अन्तर्गत

1 Ibid, p 161

2 Ibid, p 162.

A परियोजना में तथा आन्तरिक प्रतिफल-दर विधि में D परियोजना को विनियोग के लिए चुनेगा। इसी प्रकार, वर्तमान मूल्य विधि में विभिन्न विनियोग विकल्पों के चुनाव किए जा सकते हैं।

परियोजना मूल्यांकन की वर्तमान कटौती-मूल्य-विधि (The Present Discounted-Value Criteria of Evaluation)

लाभ-लागत विश्लेषण (Benefit-Cost Analysis) परियोजना मूल्यांकन की एक आधुनिक तकनीकी है। सवप्रथम इसका विकास व प्रयोग अमेरिका में किया गया। इस विधि द्वारा अनेक विकास परियोजना प्रस्तावों का आर्थिक मूल्यांकन किया गया है। लाभ लागत विश्लेषण की अनेक विधियाँ हैं, जिनमें मुख्य (1) विशुद्ध वर्तमान मूल्य विधि (Net Present Value Criteria) (2) आन्तरिक प्रतिफल दर (Internal Rate of Return) आदि हैं।

विशुद्ध वर्तमान-मूल्य-विधि (Net Present-Value-Criteria)

परियोजना मूल्यांकन की इस विधि में परियोजना के आय प्रवाह (Income Flows), लागत व्यय (Cost-outlay) तथा ब्याज अथवा कटौती दर का विचार किया जाता है। इन तत्वों के आधार पर किसी भी परियोजना के वर्तमान कटौती मूल्य की गणना निम्नलिखित सूत्र के आधार पर की जा सकती है—

$$PV = -Y_0 + \frac{Y_1}{(1+r)} + \frac{Y_2}{(1+r)^2} + \frac{Y_3}{(1+r)^3} + \dots + \frac{Y_n}{(1+r)^n} + \dots$$

$$\text{अथवा } PV = -Y_0 + \sum_{t=1}^n \frac{Y_t}{(1+r)^t}$$

सूत्र में

PV = दी हुई परियोजना का वर्तमान कटौती मूल्य

$-Y_0$ = प्रारम्भिक लागत व्यय

Y_1, Y_2, \dots, Y_n क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा n वर्षों की आय को प्रकट करते हैं

r = ब्याज अथवा कटौती दर।

मान लीजिए किसी परियोजना से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचनाएँ दी हुई हैं—

आय प्रवाह = -100, 50, 150

कटौती दर = 10% अथवा 1 (मूल-राशि के इकाई होने पर)

-100 = प्रारम्भिक लागत व्यय तथा 50 व 150 क्रमशः प्रथम व द्वितीय वर्षों की आय प्रकट करते हैं, अर्थात् $Y_1 = 50$ व $Y_2 = 150$

इन सूचनाओं को उक्त सूत्र में रखते हुए 2 वर्षों की अवधि पर्यन्त परियोजना का वर्तमान शुद्ध कटौती मूल्य निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है—

$$-100 + \frac{50}{1+1} + \frac{150}{(1+1)^2} = 66.5$$

वास्तव में, परिस्मृति का कुल वर्तमान मूल्य (Gross Present Value) उक्त उदाहरण में 166.5 होगा, किन्तु इसमें से लागत व्यय 100 के घटाने पर शेष

मूल्य को 'विशुद्ध वर्तमान-मूल्य' (Net Present Value) कहा जाता है। अतः विशुद्ध वर्तमान मूल्य $166.5 - 100 = 66.5$ है—

यदि एक लाभ के स्रोत (Benefit Stream) को $B_0, B_1, B_2 \dots B_n$ के रूप में प्रकट किया जाता है तथा जिसमें सभी B घनात्मक अथवा शून्य या ऋणात्मक हो सकते हैं। निम्नलिखित सूत्र द्वारा वर्तमान कटौती-मूल्य प्रकट किया जा सकता है—

$$B_0 + \frac{B_1}{(1+r)} + \frac{B_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{B_n}{(1+r)^n}$$

संक्षेप में,

$$\sum_{t=0}^{t=n} \frac{B_t}{(1+r)^t}$$

जिसमें r कटौती दर को प्रकट करता है।¹

इस अवधि में r का उपयुक्त चुनाव करना विशेष महत्त्व रखता है। सामान्यतः यह माना जाता है कि व्याज की सही दर वह है जो समाज के समय अधिमान की दर (Rate of Social Time Preference) को दर्शाती है। उदाहरणार्थ यदि कोई समाज वर्तमान वर्ष के 100 रु को दूसरे वर्ष के 106 रु के समान महत्त्व देता है तो उस समाज की समय अधिमान दर 6% प्रति वर्ष होगी।

उक्त विधि के सम्बन्ध में निम्नलिखित तीन उल्लेखनीय प्रस्थापनाओं (Proposition) पर विचार करना आवश्यक है—

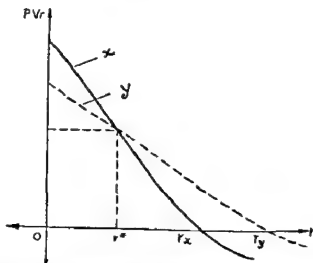
1 विशुद्ध वर्तमान मूल्य अथवा लागत पर वर्तमान मूल्य का अतिरिक्त कटौती-दर पर निर्भर करता है। यदि विशुद्ध लाभों का प्रवाह —100, 0 150 है, तो इनका वर्तमान-मूल्य $r=1$ होने पर 48 से कुछ कम होगा तथा $r=5$ की स्थिति में यह मूल्य $-\frac{100}{3}$ होगा।

2 विनियोग का कौन सा प्रवाह अधिकतम वर्तमान कटौती-मूल्य उत्पन्न करता है, इस प्रश्न का उत्तर सामान्यतः कटौती दर पर निर्भर करता है। यदि प्रथम प्रवाह —50 20 और 80 तथा दूसरा प्रवाह —60, 20 तथा 70 हो तो प्रथम प्रवाह के अधिशासी (Dominant) होने की स्थिति में, किसी भी कटौती दर के, इसका कटौती मूल्य दूसरे प्रवाह के कटौती मूल्य की अपेक्षा अधिक होगा। यदि दो प्रवाह —100, 0 180 और —100, 165 और 0 हो तो 1% की कटौती-दर की स्थिति में प्रथम कटौती मूल्य लगभग 76 तथा दूसरे का 63 होगा। अतः प्रथम प्रवाह को प्रथम श्रेणी (Rank First) तथा दूसरे को द्वितीय श्रेणी (Rank Second) मिलेगा। $r=5$ की स्थिति में प्रथम प्रवाह का कटौती-मूल्य —20 तथा इसको श्रेणी द्वितीय होगी, जबकि दूसरा प्रवाह वर्तमान मूल्य के 10 होने के कारण प्रथम श्रेणी प्राप्त करेगा।

उक्त उदाहरणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि 1% व 5% के मध्य एक निश्चित सामाजिक कटौती-दर होती है, जिस पर दोनों प्रवाहों का वर्तमान कटौती-मूल्य एक दूसरे के बराबर होता है। इस दर को हम r^* से प्रकट कर सकते हैं। r^* को दोनों प्रवाहों के वर्तमान मूल्यों को एक दूसरे के समान समीकरण में रखते हुए सरलता से मान्य किया जा सकता है अर्थात् उक्त प्रवाहों को निम्न प्रकार रखने पर—

$$-100 + \frac{180}{(1+r)^2} = -100 + \frac{165}{(1+r)}$$

चित्र-7



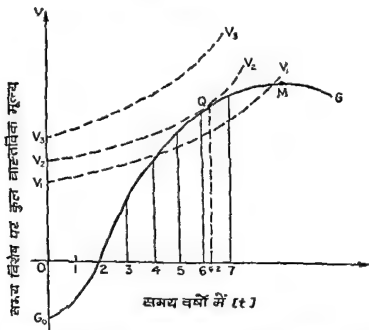
सामान्यतः हम किसी एक विशेष विनियोग प्रवाह का कटौती-दर के अनुरूप वर्तमान-मूल्य निर्धारित करते हैं। उक्त चित्र में X परियोजना का उदाहरण लिया जा सकता है। चित्र में सम्बन्ध पर PV_r या विनियोग का वर्तमान मूल्य दर्शाया गया है तथा क्षितिजीय अक्ष पर सामाजिक कटौती-दर दिखाई गई है। X प्रवाह का वर्तमान-मूल्य r के आकार का विपरीत होगा अर्थात् जितना अधिक r होगा उतना ही विनियोग प्रवाह का वर्तमान मूल्य कम होगा। इसीलिए X चक्र ऋणात्मक ढाल वाला है। ऋणात्मक ढाल का क्षितिजीय अक्ष को काट कर नीचे की ओर बढ़ना यह प्रकट करता है कि 50% कटौती-दर पर प्रवाह का वर्तमान मूल्य ऋणात्मक हो जाता है (जैसे $-100, 0, 180$ का 50% से कटौती-मूल्य $= -20$) इसी प्रकार का सम्बन्ध Y प्रवाह के लिए स्थापित किया जा सकता है।

यदि दोनों प्रवाहों में से किसी एक प्रवाह की स्थिति प्रधिशासी (Dominant) होती है, तो प्रत्येक कटौती-दर पर इस प्रवाह की स्थिति सभी अन्य प्रवाहों से ऊँची

होगी। अधिशासन की अनुपस्थिति में X और Y एक दूसरे को चित्र के या तो घनात्मक क्वाड्रेंट (Quadrant) अथवा ऋणात्मक क्वाड्रेंट (Quadrant) में काटेंगे। केवल r^* की स्थिति के अतिरिक्त अन्य सभी स्थितियों में दोनों प्रवाहों के वर्तमान मूल्य विभिन्न कटौती-दरों के अनुसार भिन्न-भिन्न होंगे। r^* पर दोनों के मूल्य समान होते हैं तथा r^* से कम पर X का मूल्य Y से अधिक होता है। अन्त में चित्र r_x व r_y कटौती-दरों को देखा जा सकता है, जिन पर दोनों प्रवाहों की कटौती-दर शून्य है।

पूर्व वर्णित निष्कर्षों के अतिरिक्त इस विधि से किसी परिसम्पत्ति के विकास-पथ के दिए हुए होने की स्थिति में वह अवधि (Optimal gestation period) जिसमें सम्पत्ति का अधिकतम शुद्ध वर्तमान-मूल्य प्राप्त किया जा सकता सम्भव है, ज्ञात की जा सकती है। यह पथ निम्न चित्र में दर्शाया गया है।

चित्र-8



चित्र में कटौती-दर द्वारा किसी परिसम्पत्ति की उस अनुकूलतम या इष्टतम परिपक्वता अवधि (Optimal gestation period) का निर्धारण समझाया गया है, जिसमें सम्पत्ति का वर्तमान-मूल्य अधिकतम होता है।

तब उसका मूल्य पैड की वृद्धि के अनुपात में बढ़ता जाता है। उदाहरणार्थ, जब टिम्बर का पौधा लगाया जाता है।

G_0G द्वारा विकास-पथ प्रकट किया गया है, OG_0 टिम्बर के प्रारम्भिक लागत को प्रकट करता है। इसलिए इसे एक ऋणात्मक मात्रा के रूप में चित्र में

प्रदर्शित किया गया है। क्षिणिकीय अक्ष से OG वक्र पर डाले गए लम्ब किसी समय विशेष पर टिम्बर के मूल्यों को दर्शाते हैं। दो वर्ष की अवधि वाले बिन्दु पर टिम्बर का शुद्ध-मूल्य होना है। विभिन्न लम्बों की ऊँचाइयाँ वैकल्पिक विनियोगों के प्रवाह (Alternative Investment Stream) को प्रकट करती है। यदि $OG_0 = 50$ मानी जाती है, तो 4 वर्ष की अवधि वाला लम्ब टिम्बर के मूल्य को 100 के बराबर प्रकट करेगा। इसी प्रकार चित्र की सहायता से विभिन्न विनियोग विकल्पों के आय-प्रवाहों को निम्न प्रकार प्रकट किया जा सकता है—

जब	आय-प्रवाह
$t=5$	50,0,0,0,112
$t=6$	50,0,0,0,0,120

इसी प्रकार $t=7,8,9$ आदि की स्थिति में विभिन्न विनियोग विकल्पों को प्रकट किया जा सकता है। किन्तु समझना यह है कि इन विनियोग विकल्पों में से कौनसा विकल्प सर्वाधिक लाभदायक होगा। इसे हम सामाजिक कटौती-दर के आधार पर विभिन्न कटौती-वक्रों की रचना करके ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए $r=5\%$ दिया हुआ है। इससे V_1V_1 कटौती वक्र की रचना की गई है। इस वक्र में यदि हम OV_1 पर 80 का माप करते हैं तो $t=1$ के बिन्दु पर लम्ब की ऊँचाई 84, $t=2$ पर 88.2 और इसी प्रकार एक एक वर्ष से बढ़ती हुई अवधि में 5% की अधिकता से लम्बों की ऊँचाइयाँ अधिक होनी चली जाएँगी। इस उदासीन वक्र का प्रत्येक बिन्दु समाज के लिए समान महत्त्व रखेगा, क्योंकि $r=5\%$ होने पर वर्तमान वर्ष के 100 व आगामी वर्ष के 105 में विनियोजक कोई अन्तर नहीं करेगा। समान सन्तोष की अनुभूति करते हुए इन बिन्दुओं के प्रति वह उदासीन रहेगा।

इसी प्रकार लम्ब अक्ष पर अन्य उदासीनता वक्रों की रचना की जा सकती है। चित्र में V_2V_2 व V_3V_3 इसी प्रकार के दो अन्य उदासीन वक्र दिए हुए हैं। इन उदासीनता वक्रों में से हमको उच्चतम वक्र का चुनाव करना चाहिए जो विकास-पथ के वक्र को स्पर्श करता है। V_2V_2 चित्र में उच्चतम उदासीन वक्र है। Q स्पर्श बिन्दु है, जहाँ $t=6.2$ वर्ष है। निष्कर्षतः शुद्ध लाभों के प्रवाह का 5% की कटौती-दर पर अधिकतम वर्तमान-मूल्य OV_2 ऊँचाई द्वारा प्रकट होगा तथा परिपक्वता अवधि 6.2 वर्ष होगी। विशुद्ध वर्तमान मूल्य $OV_2 - OG_0$ द्वारा प्रकट होगा।

आन्तरिक प्रतिफल-दर

(Internal Rate of Return or IRR)

आन्तरिक प्रतिफल दर (The Internal Rate of Return) विनियोग मूल्यांकन की एक श्रेष्ठ विधि है। विनियोजक के समक्ष अनेक विनियोग विकल्प होते हैं। अपनी पूँजी को किस विनियोग में लगाए, यह उसके सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। उदाहरणार्थ, दो विनियोग हैं—(1) एक ट्रक का, बाड़ी का।

सन्	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
पनवाडी	500	500	500	500	500	500	500
ट्रक	5000	5000	6000	10,000	200	100	20

ट्रक से समान आय प्राप्त नहीं हो रही है, किन्तु पनवाडी से प्राप्त होने वाली आय की राशि सभी वर्षों में समान है। अतः समस्या यह है कि उक्त दोनों विनियोगों से प्राप्त आय की परस्पर तुलना किस प्रकार की जाए। इस प्रश्न का उत्तर आन्तरिक प्रतिफल दर द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिफल की आन्तरिक दर की सहायता से आय-प्रवाह को वर्तमान-मूल्य में परिवर्तित किया जा सकता है। तत्पश्चात् प्रत्येक परियोजना का वर्तमान मूल्य व उसकी लागत का अनुपात $= \frac{V-C}{C}$ के रूप में निकाला जाता है। जिस परियोजना का उक्त अनुपात अधिक होगा, उसे श्रेष्ठतर समझा जाएगा।

अतः आन्तरिक प्रतिफल दर वह दर होती है, जो विनियोग के आय-प्रवाह व वर्तमान मूल्य को विनियोग की लागतों के वर्तमान मूल्य के ठीक बराबर कर देती है, अथवा यदि लाभ-लागत प्रवाहों के वर्तमान-मूल्यों को जोड़ा जाता है, तो योगफल शून्य के बराबर होगा।¹

इस दर को निम्नलिखित सूत्र-से ज्ञात किया जा सकता है—

$$-Y_0 - \frac{Y_1}{(1+r)} - \frac{Y_2}{(1+r)^2} + \frac{Y_3}{(1+r)^3} + \dots + \frac{Y_n}{(1+r)^n} + \dots$$

सक्षेप में

$$-Y_0 - \sum_{t=1}^n \frac{Y_t}{(1+r)^t}$$

$\frac{1}{(1+r)} = x$ रखते हुए पूरे प्रवाह में r का मान ज्ञात किया जा सकता है। r का मान ही आन्तरिक प्रतिफल दर कहलाती है। इसे कुछ विनियोग परियोजनाओं के उदाहरण लेकर गणितीय रूप में भी अप्रकट प्रकार से समझाया जा सकता है—

1. "The internal rate of return is that rate of discount which makes the present value of the entire stream-benefits and costs—exactly equal to zero"

—E J. Mishan: Cost-benefit Analysis, p 198.

परियोजना	सागत (रु. में) ($-Y_0$)	I वर्ष की आय (रु.) (Y_1)	II वर्ष की आय (रु.) (Y_2)
A	10,000	10,000	0
B	10,000	10,000	1100

उक्त सूचनाओं को दिए हुए सूत्र में रखने पर

परियोजना A

$$-10,000 + 10,000x = 0$$

$$x = 0$$

$$r \text{ या } IRR = 0$$

परियोजना B

$$-10000 + 10000x + 1100x^2 = 0$$

$$\text{अथवा } -100 + 100x + 11x^2 = 0$$

$$\text{या } \frac{-100 + \sqrt{(100)^2 + 11 \cdot 1004}}{2 \cdot 11}$$

$$\therefore x = 90$$

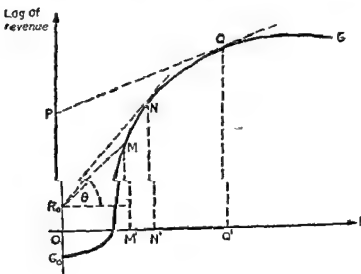
$$\therefore r \text{ या } IRR = 10$$

$$\text{संक्षेप में } r \text{ or } IRR = \frac{1-x}{x}$$

इसी प्रकार अन्य परियोजनाओं की प्रतिक्रम दर ज्ञात की जा सकती है। जिस क्रम में यह दर विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति में अधिक होगी, उसी क्रम में विनियोजक अपनी पूँजी का विनियोग करेगा। उक्त उदाहरण में परियोजना A की अपेक्षा परियोजना B श्रेष्ठ है। अतः पूँजी विनियोजन परियोजना B में दी होगी।

आन्तरिक प्रतिफल दर को चित्र द्वारा भी समझाया जा सकता है—

चित्र-9



चित्र में G_0G विकस-पथ दिया हुआ है। इस पर R_0 से एक सीधी रेखा खींची गई है। इस रेखा का विकासवक्र के किसी भी बिन्दु पर जो ढाल (Slope) है, वही आन्तरिक प्रतिफल दर (IRR) को प्रकट करती है। चूँकि ढाल निर्धारण स्पर्श बिन्दु में किया जाता है जो NN' में प्रकट किया गया है। M बिन्दु पर R_0 से डाली गई सीधी रेखा $OR_0 = OG_0$ अर्थात् लाभ लागत-प्रवाहों के वर्तमान मूल्यों को परस्पर बराबर प्रकट करती है। OG_0 परियोजना की प्रारम्भिक लागत को प्रकट करता है तथा OR_0 परियोजना के लाभों के प्रवाह के वर्तमान-मूल्य को प्रकट करता है।

चित्र में—

OX पर समय

OY पर आयम (लॉग स्केल)

$OP =$ उच्चतम वर्तमान मूल्य 5% की वार्षिक कटौती दर के अनुसार

$OQ' =$ परिकृतम परियोजना अवधि (Optimum Gestation Period)
वर्तमान मूल्य वाले मापदण्ड (Present Value Criterion) के अनुसार।

इसी परिणाम को आन्तरिक प्रतिफल दर वाले मापदण्ड द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है लेकिन इससे पूर्व हमें यह देखना है कि इस चित्र में आन्तरिक प्रतिफल दर को किस प्रकार दर्शाया जा सकता है।

हम यह जानते हैं कि आन्तरिक प्रतिफल दर के अनन्त लाभ-प्रवाह के वर्तमान मूल्य में लागत-प्रवाह के वर्तमान-मूल्य को घटाने से शून्य शेष रहता है।

चित्र में हम OG_0 व OR_0 के निरपेक्ष मूल्य समान मानते हैं, तो विकास-वक्र G_0G पर R_0 बिन्दु से खींची गई सीधी रेखा (M बिन्दु पर) का ढाल को आन्तरिक प्रतिफल-दर का प्रतीक माना जा सकता है।

ढाल को ज्ञात करने के लिए हम $\tan \theta$ निकालते हैं।

$$\tan \theta = \frac{\text{लम्ब}}{\text{आधार}} = \frac{MK}{R_0K} = \frac{M'M - M'K}{OM'}$$

$$= \frac{\text{कुल आयम (Total Compounded Benefit)—लागत}}{OM' \text{ अवधि}}$$

$\tan \theta$ द्वारा व्यक्त कटौती-दर को हम इसलिए आन्तरिक प्रतिफल दर मानते हैं क्योंकि यह दर $M'M$ आबी लाभों को OR_0 के बराबर वर्तमान-मूल्य में बदल देती है, जो प्रारम्भिक लागत OG_0 के बराबर होता है। उच्चतम सम्भव आन्तरिक प्रतिफल दर (Highest Possible Internal Rate of Return) R_0 से N बिन्दु पर विकास-पथ G_0G पर डाली गई स्पर्श-रेखा (Tangent) से निर्धारित होती है, क्योंकि R_0N की तुलना में किसी भी अन्य विकास-पथ पर डाली गई सीधी रेखा का ढाल अधिक नहीं हो सकता है। यदि उच्चतम प्रतिफल दर वाली अवधि को 'अनुकूलतम विनियोग अवधि' (Optimum Investment Period) के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो यह चित्र में ON' द्वारा प्रकट होता है, जो स्पष्टतः

OQ' से कम है। यह वर्तमान-मूल्य मापदण्ड वाली विधि की अनुकूलतम अवधि को दर्शाता है।

IRR व NPV मापदण्डों की तुलना

विनियोग विकल्पों के दोनो मापदण्ड—आन्तरिक प्रतिफल दर (IRR) तथा शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) वैज्ञानिक हैं। विनियोग निर्णय में दोनों का ही सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। दोनो विधियों की अपनी कुछ ऐसी निजी विशेषताएँ हैं कि स्पष्टतः यह कह देना कि दोनो में से कौन श्रेष्ठ है, अत्यधिक कठिन है। इन विधियों में बड़ा भूल अन्तर है—

1 आन्तरिक प्रतिफल दर वाले मापदण्ड में प्रयुक्त कटौती दर का पूर्व ज्ञान नहीं होता है। यह दर स्वयं-सम्पत्ति के कलेवर में अन्तर्निहित होती है (This rate is built in the body of the asset itself)। वर्तमान मूल्य वाले मापदण्ड में कटौती-दर पहले से ज्ञात होती है। प्रायः बाज़ की बाज़ार दर के अनुसार, इस मापदण्ड में सम्पत्ति का मूल्य ज्ञात किया जाता है।

2 आन्तरिक प्रतिफल-दर, एक ही विनियोग प्रवाह के लिए, एक से अधिक हो सकती है। उदाहरणार्थ,

विनियोग प्रवाह (Investment Stream) = - 100, 350, - 400
IRR की परिभाषा के अनुसार—

$$-100 + \frac{350}{(1+\lambda)} - \frac{400}{(1+\lambda)^2} = 0$$

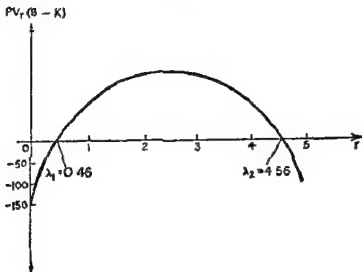
दो दर प्राप्त होगी—

$$\lambda_1 = 46\%$$

$$\lambda_2 = 456\%$$

इस स्थिति को चित्र में निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है—

चित्र-10



दो आन्तरिक प्रतिकर दरों का उक्त उदाहरण एक विशेष प्रकार का उदाहरण है। n^{th} मूल्य वाले (of n^{th} roots) विनियोग प्रवाह (Investment Stream) की n ही आन्तरिक प्रतिकर दरें सम्भव हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी इस तथ्य को अस्वीकार नहीं कर सकता कि इस दृष्टि से वर्तमान मूल्य मापदण्ड का पक्ष आन्तरिक प्रतिकर दर वाले पक्ष से अपेक्षाकृत अधिक सशक्त प्रतीत होता है।

दोनों मापदण्डों में से किसका चुनाव किया जाए, इसमें कठिनाई यह आती है कि अनेक स्थितियों में दोनों मापदण्ड विनियोग प्रवाहों को समान श्रेणी (Same Ranks) प्रदान करते हैं। इस स्थिति में किस मापदण्ड को श्रेष्ठ समझा जाए, यह समस्या सामने आती है।

इस समस्या के समाधान हेतु अर्थशास्त्री Mc Kean ने यह सुझाव प्रस्तुत किया है कि एक निश्चित बजट सीमा में कुछ विनियोग परियोजनाओं का चुनाव इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि विनियोजित राशि का प्रत्येक परियोजना पर इस प्रकार वितरण हो कि उस विनियोग प्रवाह की आन्तरिक प्रतिकर दर (IRR) वर्तमान मूल्य की कटौती दर से अधिक हो। इस तथ्य को निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 5

परियोजनाएँ	समय			आन्तरिक प्रतिकर दर (IRR)	$PV, \frac{(B-K)}{K}$ ($r=0.03$) 3% से वर्तमान मूल्य
	t_0	t_1	t_2		
A	-100	110	0	10%	$\frac{7}{100}$
B	-100	0	115	7%	$\frac{8}{100}$
C	-100	106	0	6%	$\frac{3}{100}$
D	-50	52	0	4%	$\frac{1}{100}$
E	-200	2	208	2%	$\frac{-2}{200}$

A, B, C, D व E पाँच परियोजनाएँ दी हुई हैं। प्रत्येक की आन्तरिक प्रतिकर दर घटते हुए क्रम में दिखाई गई हैं। वर्तमान मूल्य के अनुसार शुद्ध लाभ का अनुपात 3% की कटौती दर के आधार पर दिया हुआ है।

यदि 1000 रुपये का बजट दिया हुआ है और उसमें से केवल 350 रुपये का विनियोजन करना है तो A, B, C व D परियोजनाओं का चुनाव किया जाना

चाहिए, क्योंकि E परियोजना की आन्तरिक प्रतिकूल दर बेबल 2 / . है, जो वर्तमान मूल्य की कटौती दर 3 / . से कम है। यद्यपि दोनों मापदण्डों के आधार पर चारों परियोजनाओं का श्रेणीक्रम (Ranking) समान नहीं रहेगा, तथापि दोनों ही मापदण्डों के अन्तर्गत प्रथम चार विनियोग विकल्प ही अपनाए जा सकते हैं।

यदि 200 ₹ का बजट हो तो IRR व NPV दोनों मापदण्डों के परिणाम A व B परियोजनाओं की समान श्रेणियाँ प्रदान करते हैं। किन्तु यदि बजट केवल 100 रुपये हैं, तो IRR के अनुसार A का तथा NPV के अनुसार परियोजना B का चुनाव किया जाना उपयुक्त समझा जाएगा।

परियोजना मूल्यांकन की लागत-लाभ विश्लेषण विधि की आलोचना (A Critique of Cost-benefit Analysis)

यद्यपि लागत-लाभ विश्लेषण विधि परियोजना मूल्यांकन की एक थोड़ा विधि है, तथापि अनेक अर्थशास्त्रियों ने इस विधि की निम्न आलोचनाएँ की हैं—

- (1) परियोजनाओं की उचित प्रमाणित करने की दृष्टि से सकारात्मक लाभों को बढ़ाकर दिखाती है तथा अनेक उचित लागतों की उपेक्षा करती है (Govt. inflates benefits and ignores costs)।
- (2) वास्तव में संचालित शुद्ध लाभ (Calculated net benefits) परियोजना की लाभदायकता को प्रमाणित नहीं करते हैं। उनकी संपूर्णता यह ध्यान में रखने हुए भी जाती है कि परियोजना के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय उचित है।
- (3) लाभ-लागतों की मंगलता में आर्थिक-तत्त्वों की उपेक्षा भी जाती है तथा राजनीतिक लक्ष्यों को अधिक ध्यान में रखा जाता है।
- (4) आर्थिक कुशलता की अपेक्षा सामाजिक मूल्यों पर अधिक बल दिया जाता है (The value of social goals is stressed more than economic efficiency)।

उक्त आलोचनाओं के बावजूद, परियोजना मूल्यांकन की यह उत्तम विधि है। विनियोग निर्णयों में कुछ अवरोधों का आना स्वाभाविक है। इस प्रकार के अवरोध (Constraints), कुछ भौतिक (Physical), कुछ प्रशासनिक (Administrative), कुछ राजनीतिक (Political), कुछ वैधानिक (Legal) तथा कुछ वित्तीय (Financial) होने हैं। भौतिक अवरोधों के कारण तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त (Technically feasible) विनियोग विकल्पों का चुनाव भी सीमित हो जाता है, वैधानिक अवरोधों के कारण कानून में बिना संशोधन के उचित विनियोग निर्णय लेने में कठिनाइयाँ आती हैं, प्रशासनिक अवरोध-निर्णयों में विलम्ब के लिए उत्तरदायी होते हैं, राजनीतिक अवरोध, आर्थिक कुशलता की उपेक्षा करते हैं तथा वित्तीय अवरोध व्यय राशि की एक निश्चित सीमा से बाहर निर्णय लेने के प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं।

प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लागतें व लाभ (Direct and Indirect Cost and Benefits)

सिंचाई, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि परियोजनाओं का मूल्यांकन इन से एक विशेष अवधि में प्राप्त लाभों तथा इन पर व्यय की गई लागतों के आधार पर किया जाता है। किन्तु परियोजना-मूल्यांकन में जो लाभ व लागतें ली जाती हैं, वे सामान्य बाजार मूल्यों के आधार पर नहीं आंकी जाती हैं उनके अंकन का आधार सामान्य लेखा विधि नहीं होगी, अपितु 'छाया-मूल्य' (Shadow Prices) की अवधारणा होती है। सामान्य लेखा-विधि द्वारा बाजार मूल्य के आधार पर सगणित लाभ व लागत प्रायः प्रत्यक्ष लाभ व लागतों की श्रेणी में लिए जाते हैं। किन्तु, इस प्रकार की सगणना से कोई आर्थिक निष्कर्ष निकालना सम्भव नहीं होता, क्योंकि लेखांकन लागतों के अतिरिक्त अनेक ऐसी लागतें भी होती हैं जिनकी प्रविष्टि यद्यपि लेखा-पुस्तकी में नहीं होती, किन्तु उनकी गणना में लाए बिना लागत-प्रवाह का वर्तमान मूल्य निकालना आर्थिक दृष्टि से अनुपयुक्त समझा जाता है। ठीक इसी प्रकार, लाभों के अन्तर्गत भी परियोजनाओं से प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त लाभों के अतिरिक्त बाह्य वधतें आदि से सम्बन्धित लाभ होते हैं। लाभों के सम्पूर्ण प्रवाह की सगणना में अन्य लाभों की भूमिका अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण होती है। ऐसे लाभों को सामान्यतः 'अप्रत्यक्ष लाभों' की संज्ञा दी जाती है। इनकी सगणना 'छाया-मूल्यों' (Shadow Price) के आधार पर की जाती है।

प्रत्यक्ष लाभ (Direct Benefit)—प्रत्यक्ष अथवा प्राथमिक लाभ उन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को प्रकट करते हैं, जिनका परियोजना द्वारा उत्पादन होता है। जो लाभ परियोजना से शीघ्र व प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने हैं 'प्रत्यक्ष लाभ' कहलाते हैं। उदाहरणार्थ सिंचाई-परियोजना में बाट नियन्त्रण सिंचाई, विद्युत्-उत्पादन कृषि-उत्पादन में वृद्धि पेयजल की सुविधा, इन लाभों का स्वरूप प्रायः भौतिक होता है तथा इनकी माप-मुद्रा में लेखा मूल्यों के आधार पर की जाती है। विशेष अवधि में होने वाले मूल्यों के परिवर्तनों का अवश्य ध्यान रखा जाता है। अतः मूल्य निर्देशकों के आधार पर इन मूल्यों की सङ्कुचित या प्रसारित (Deflated or Inflated) अवश्य किया जाता है। इसी प्रकार, किसी यातायात परियोजना से कई प्रत्यक्ष लाभ हो सकते हैं जैसे—यात्रियों की आने-जाने की सुविधा, माल ढोने की सुविधा, व्यापार में वृद्धि, कुछ मात्रा में रोजगार-वृद्धि आदि।

अप्रत्यक्ष लाभ (Indirect Benefit)—तकनीकी परिवर्तन के कारण उत्पन्न बाह्य प्रभाव 'अप्रत्यक्ष लाभ' होते हैं। बाह्य-प्रभाव परियोजना के उत्पादन अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा इसके उपयोग के परिणाम होते हैं। जो लाभ परियोजना से सीधे प्राप्त नहीं होते, बल्कि जिनकी उत्पत्ति परियोजना के कारण होने वाले आर्थिक कारण विकास से प्राप्त होती है, उनको 'अप्रत्यक्ष लाभ' कहते हैं। उदाहरणार्थ, सिंचाई परियोजना के कारण सड़कों का निर्माण, नई रेलवे लाइनों का विद्युदायित करना, नए नगरों का विकास, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, नए उद्योगों की स्थापना,

आदि अप्रत्यक्ष लाभ के उदाहरण हैं। इनके अतिरिक्त विनियोग की दर, जनसंख्या वृद्धि दर, श्रम की कुशलता, लोगों के सामाजिक व सांस्कृतिक विकास आदि पर पड़ने वाले परियोजना-प्रभावों को भी अप्रत्यक्ष लाभों की श्रेणी में लिया जा सकता है।

अप्रत्यक्ष लाभ उत्पादन की अग्रिम कड़ियों (Forward Production Linkages) से भी उत्पन्न होते हैं, ये कड़ियाँ उन व्यक्तियों की आय में वृद्धि करती हैं, जो परियोजना के उत्पादन की मध्यवर्ती-प्रक्रियाओं में सलग्न होते हैं। उदाहरणार्थ, किसी सिचाई परियोजना के अन्तर्गत उत्पादित कपास, बाजार में विक्री हेतु प्रस्तुत होने से पूर्व अनेक मध्यवर्ती प्रक्रियाओं में से गुजरता है। प्रत्येक मध्यवर्ती प्रक्रिया-कक्षा बड़ी हुई व्यावसायिक प्रक्रियाओं से लाभ उठाता है।

‘अप्रत्यक्ष लाभ’, उत्पादन की पीछे वाली कड़ियों (Backward Production Linkages) के कारण भी प्राप्त होते हैं। इन कड़ियों के कारण उन व्यक्तियों की आय में वृद्धि होती है, जो परियोजना-क्षेत्र में वस्तु और सेवाएँ प्रदान करते हैं। उदाहरणार्थ, परियोजना द्वारा उत्पादित कपास के लिए मशीनरी, खाद तथा अन्य सामग्रियों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की एक शृंखला उत्पन्न होती है। सभी व्यक्ति, जो इस शृंखला के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कार्य करते हैं, परियोजना से अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होते हैं।

लागत (Costs)—परियोजना पर होने वाले प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष व्यय, ‘लागत’ कहलाती है।

प्रत्यक्ष लागत (Direct Costs)—प्रत्यक्ष लागत वह लागत होती है जो परियोजना के निर्माण व कार्यान्वित करने में उचित रूप से उठाई जाती है। मुख्यतः ये लागतें निम्नलिखित होती हैं—(i) निर्माण लागतें, (ii) अभियान्त्रिक व प्रशासनिक लागतें, (iii) परियोजना के लिए काम में ली जाने वाली भूमि की अवसर लागत, (iv) परियोजना की क्रियान्वित के लिए सड़कें, रेलवे लाइनें, पाइप लाइनें, बिद्युत् लाइनें पुल-निर्माण यदि आवश्यक हो तो इन पर होन वाली लागतें, (v) परियोजना के संचालन, सुरक्षा एवं पुनर्स्थापन सम्बन्धी लागतें।

अप्रत्यक्ष लागत (Indirect Costs)—जो लागत अप्रत्यक्ष लाभों की प्राप्ति हेतु दी जाती है, उसे अप्रत्यक्ष लागत कहा जाता है। उदाहरणार्थ, परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए आवास-सुविधाएँ, अच्छी सड़कें, बच्चों की शिक्षा के लिए पाठशाला, अस्पताल इत्यादि।

भाग-2

भारत में आर्थिक नियोजन

(ECONOMIC PLANNING IN INDIA)

स्वतन्त्रता के बाद भारत में तीव्र गति से आर्थिक विकास करने के लिए नियोजन का मार्ग अपनाया गया, किन्तु यह भारत के लिए नया नहीं था। स्वतन्त्रता से पूर्व भी भारत में अनेक योजनाएँ प्रस्तुत की गईं जिनमें 'विश्वेश्वरैया योजना', 'बम्बई योजना', 'जन-योजना', 'गांधीवादी योजना', आदि के नाम उल्लेखनीय हैं, तथापि ये योजनाएँ कोरी कागजी रही, वास्तविक नियोजन कार्य राष्ट्रीय सरकार द्वारा ही प्रारम्भ किया जा सका।

विश्वेश्वरैया योजना (Visvesvaraya Plan)

सर एम. विश्वेश्वरैया एक विख्यात इंजीनियर थे। उन्होंने आर्थिक नियोजन पर सन् 1934 में 'भारत में नियोजित व्यवस्था' (Planned Economy for India) नामक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक में भारत के आर्थिक विकास के लिए एक दस-वर्षीय आर्थिक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय आय को दस वर्ष की अवधि में दुगुना करना था। 'विश्वेश्वरैया योजना' में उद्योगों को विशेष महत्त्व दिया गया और साथ ही व्यवसायों में सन्तुलन स्थापित करके आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य रखा गया। 1934-35 में भारतीय आर्थिक सभा (Indian Economic Conference) की वार्षिक बैठक में इन प्रस्तावों पर काफी विचार-विमर्श किया गया किन्तु परिस्थितियाँ प्रतिकूल होने के कारण इस योजना के आर्थिक कार्यक्रमों की क्रियाम्विति के प्रयत्न नहीं हो सके। परन्तु इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि इस योजना ने भारत में आर्थिक-नियोजन की सैद्धान्तिक आधार-शिला रखी तथा विचारकों को नियोजन की दिशा में चिन्तन के लिए प्रेरित किया।

आर्थिक नियोजन पर प्रारम्भिक साहित्य के रूप में कुछ अन्य कृतियाँ भी प्रकाशित हुईं जिनमें पी. एम. लोकनाथन् की 'नियोजन के सिद्धान्त' (Principles of Planning), एन. एस. मुखर्जा की 'नियोजन के कुछ पहलू' (Some Aspects of Planning), और के. एन. सेन की 'आर्थिक पुनर्निर्माण' (Economic Reconstruction) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

राष्ट्रीय आयोजन समिति (National Planning Committee)

भारत में आर्थिक नियोजन की दिशा में दूसरा कदम राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना करना था। अक्टूबर, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष श्री सुभाषचन्द्र बोस ने दिल्ली में प्रांतीय उद्योग मन्त्रियों का सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में देश की आर्थिक प्रगति के लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए। इन सुझावों को त्रिदिव्यस्त करने के लिए श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय योजना समिति' का गठन किया गया। प्रो. के. टी. शाह इसके महासचिव मनोनीत किए गए। इस योजना समिति ने विभिन्न आर्थिक विषयों का अध्ययन करके विकास योजनाएँ प्रस्तुत करने के लिए कई उप-समितियाँ नियुक्त की। किन्तु द्वितीय विश्व युद्ध तथा कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों के त्याग-पत्रों के बाद की राजनीतिक हलचल के कारण समिति का कार्य रुक गया और सन् 1948 में ही 'भारत में नियोजन' पर समिति के कुछ प्रतिवेदन सामने आ सके। इन प्रतिवेदनों में औद्योगीकरण, सार्वजनिक-क्षेत्र के विस्तार, श्रमिकों के उचित प्रतिफल, निजी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, गृह-उद्योगों के विकास, सहकारिता को प्रोत्साहन सिंचाई व विद्युत सुविधाओं के विस्तार, वनों की सुरक्षा और भू-संरक्षण आदि से सम्बन्धित आर्थिक सुझाव प्रस्तुत किए गए।

बम्बई योजना (Bombay Plan)

स्वतन्त्रता से पूर्व भारत में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में 'बम्बई योजना' एक महत्वपूर्ण प्रयत्न थी। 1944 में भारत के आठ प्रमुख उद्योगपतियों—घनश्यामदास बिडला, जे. आर. डी. टाटा, जॉन मथाई, ए. डी. थोफ, कस्तूरभाई लालभाई, सर आर्देशीर दलाल, सर पुरुषोत्तमदास, ठाकुरदास और सर थीराम ने भारत के आर्थिक विकास की एक योजना प्रस्तुत की। यही योजना 'बम्बई योजना' के नाम से प्रसिद्ध है। यह पन्द्रह-वर्षीय योजना थी। इस योजना का अनुमानित व्यय 10 हजार करोड़ रुपये था। इसका लक्ष्य योजनावधि में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना अर्थात् 65 रुपये से बढ़ाकर 130 रुपये करना और राष्ट्रीय आय को 2200 से बढ़ाकर 6600 करोड़ रुपये करके तिगुना करना था। इस योजना के अन्तर्गत 1944 के अकी पर कृषि-प्रदा (Agriculture Output) में 130 प्रतिशत, औद्योगिक प्रदा (Industrial Output) में 500% और सेवाओं के उत्पादन (Output of Services) में 200% वृद्धि के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे।

बम्बई योजना एक प्रकार से उत्पादन योजना थी। योजना के सम्पूर्ण व्यय का 45% भाग उद्योगों के लिए निर्धारित किया गया था। उद्योग प्रधान होते हुए भी इस योजना में कृषि के विकास पर समुचित ध्यान दिया गया था। कृषि के लिए 1240 करोड़ रुपये के व्यय का आवंटन किया गया। कृषि-उत्पादन में 130% के वृद्धि के लक्ष्य के साथ ही सिंचाई-सुविधाओं में 200% वृद्धि का लक्ष्य भी रखा गया।

कृषि एवं उद्योग के अतिरिक्त इस योजना में यातायात के विकास पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया। इस योजना में 453 करोड़ रुपये के व्यय से 4001 मील लम्बी रेल लाइनों को 6200 मील तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया तथा इसके अतिरिक्त 2,26,000 मील कच्ची सड़कों को पक्का बनाने, मुख्य गाँवों को महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों से जोड़ने और बन्दरगाहों की सहाय में पर्याप्त वृद्धि करने का प्रस्ताव भी था। यातायात की मद पर कुल व्यय 940 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया।

योजना की समीक्षा

इस योजना में निजी क्षेत्र को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया। योजना की वित्त-व्यवस्था के अनुमान भी महत्वाकांक्षी थे। गृह-उद्योगों के विकास के लिए इस योजना में निश्चित कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया गया। व्यापार-सन्तुलन से छ सौ करोड़ रुपये, पीड पावने से 1000 करोड़ रुपये और विदेशी सहायता से 700 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त करने के अनुमान भी सदिग्ध थे। इन सब कमियों के बावजूद इस योजना ने राष्ट्रीय आर्थिक पुनर्निर्माण की दिशा में एक समन्वित प्रयास और साहसिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

जन योजना (People's Plan)

'वम्बई योजना' के तीन माह बाद ही इण्डियन फंडेशन ऑफ लेबर की ओर से श्री एम. एन. राय द्वारा जन-योजना प्रकाशित की गई। यह दस-वर्षीय योजना थी जिसके लिए अनुमानित व्यय की राशि 15000 करोड़ रुपये निर्धारित की गई। जन-योजना का मूल उद्देश्य जनता की तत्कालीन मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। इस योजना के प्रथम पाँच वर्षों में कृषि पर तथा अगले 5 वर्षों में उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए भूमि में 10 करोड़ एकड़ की वृद्धि, सिंचाई के साधनों में 400% की वृद्धि तथा अधिक मात्रा में अच्छे खाद और बीज के उपयोग के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। राजकीय सामूहिक कृषि के विस्तार, भूमि के राष्ट्रीयकरण और राजकीय कृषि-फार्म की स्थापना का सुझाव भी इस योजना में रखा गया था। इसके अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादन में 600% की वृद्धि का लक्ष्य इस योजना में रखा गया था और निजी उद्योगों में लाभ की दर को 3% तक सीमित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

यातायात के अंतर्गत इस योजना में सड़कों व रेलों की लम्बाई में क्रमशः 15% एवं 50% की वृद्धि के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। सड़कों की लम्बाई में 45,00,00 मील और रेलमार्गों में 24,000 मील की वृद्धि करने का आयोजन था। जहाजी यातायात के विकास के लिए 155 करोड़ रु. निर्धारित किए गए थे।

जन-योजना में ग्रामीण-क्षेत्रों की आय में 300% और औद्योगिक क्षेत्र की आय में 200% वृद्धि का अनुमान किया गया था। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन

वित्तीय संस्थाओं पर राश्व का नियन्त्रण, धन व व्यापार का समान वितरण, गृह-निर्माण योजना आदि कार्यक्रम भी इस योजना में सम्मिलित थे।

योजना की समीक्षा

इस योजना में कृषि को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया था। कृषि की तुलना में औद्योगिक विकास की उपेक्षा की गई थी। कुटीर-उद्योगों की ओर इस योजना में यथोचित ध्यान नहीं दिया गया था, किन्तु इस योजना में प्रस्तावित कृषक वर्ग की ऋण-प्रस्तुता तथा लाभ की भावना के नियन्त्रण सम्बन्धी ग्रामिक सुभाष स्वागत योग्य थे।

गांधीवादी योजना (Gandhian Plan, 1944)

इस योजना के निर्माता वर्धा के गांधीवादी नेता श्रीमन्नारायण अग्रवाल थे। यह योजना एक आदर्शवादी योजना थी, जिसका निर्माण गांधीजी के सिद्धान्तों के आधार पर किया गया था। इस योजना का अनुमानित व्यय 3500 करोड़ रु निर्धारित किया गया। इस योजना का मुख्य लक्ष्य ऐसे विकेन्द्रित आरम्भ-निर्भर कृषि-समाज की स्थापना करना था जिसमें गृह उद्योगों के विकास पर बल दिया गया हो।

यह योजना दस वर्षीय थी। इस योजना के लिए निर्धारित 200 करोड़ रु की आवर्त्तक राशि (Recurring Amount) को सरकारी उपक्रमों तथा 3500 करोड़ रु की अनावर्त्तक राशि (Non-Recurring Amount) को आन्तरिक मुद्रा-प्रसार और करारोपण द्वारा प्राप्त किया जाना था।

इस योजना में 175 करोड़ रु के अनावर्त्तक और 5 करोड़ रु के आवर्त्तक व्यय से सिंचाई सुविधाओं को दुगुना करने का कार्यक्रम बनाया गया था। योजना का लक्ष्य दस वर्षों में कृषि की आय को दुगुना करना था। योजना में गृह और ग्रामीण उद्योगों को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया था। साथ ही सुरक्षा, उद्योग, खानें, जल-विद्युत-शक्ति, मशीन और मशीनरी औजार, रसायन इन्जीनियरिंग आदि बड़े और आधारभूत उद्योगों के विकास के लिए भी कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। इसके अतिरिक्त रेल यातायात में 25% की वृद्धि ग्रामीण-क्षेत्रों में 2,00,000 मील लम्बी अतिरिक्त सड़कों का निर्माण तथा चिकित्सा व शिक्षा सुविधाओं में पर्याप्त विकास कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे।

योजना की समीक्षा

इस योजना के दो पक्ष थे—एक ग्रामीण क्षेत्र का विकास ग्रामीण जीवन के अनुसार व दूसरा नगरीय क्षेत्र जिसका विकास बड़े उद्योगों द्वारा किया जाना था। परन्तु इस प्रकार का समन्वय असम्भव था। योजना में होनार्थ प्रयत्न (Deficit Financing) को भी आवश्यकता से अधिक महत्त्व दिया गया किन्तु एक विशेषता यह थी कि इसमें भारतीय आदर्शों को समाविष्ट करने का प्रयत्न किया गया।

अन्य योजनाएँ (Other Plans)

सन् 1944 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने सर आर्दशोर दलाल की अध्यक्षता में योजना विभाग स्थापित किया। इस विभाग ने अल्पकालीन व दीर्घकालीन कई योजनाएँ तैयार की जिनको युद्ध के पश्चात् क्रियान्वित किया जाना था। किन्तु युद्ध की समाप्ति के बाद परिस्थितियाँ बदल गईं, अतः किसी भी योजना पर कार्य नहीं किया जा सका।

सन् 1946 में भारत की अन्तरिम सरकार ने विभिन्न विभागों द्वारा तैयार की गई परियोजनाओं पर विचार करने तथा उनके सम्बन्ध में रिपोर्टें देन के लिए एक Planning Advisory Board की स्थापना की जिसके अध्यक्ष श्री के. सी. नियोगी नियुक्त हुए। मण्डल ने नियोजन के मुख्य उद्देश्यों के रूप में जनता के जीवन-स्तर को उठाने और पूर्ण रोजगार देने पर बल देने का सुझाव रखा। मण्डल ने एक प्राथमिकता बोर्ड (Priorities Board) तथा एक योजना कमिशन (Planning Commission) की स्थापना के सुझाव भी दिए।

स्वतन्त्रता के बाद नियोजन (Planning after Independence)

सन् 1947 में राजनीतिक स्वतन्त्रता ने आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए मार्ग प्रशस्त किया। कृषि, मिचार्ड और खनिज सम्पदा के अनदोहित साधनों और उपलब्ध साधनों का आवंटन करने की ज़रूरत थी। आयोजन के द्वारा सुनिश्चित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के ढाँचे के अन्तर्गत तेज और सन्तुलित विकास सम्भव हो सकता था। नवम्बर, 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने श्री नेहरू की अध्यक्षता में Economic Programme Committee की स्थापना की जिसने 25 जनवरी, 1948 को अपने विस्तृत सुझाव प्रस्तुत किए और यह अनुशंसा दी कि एक स्थायी योजना आयोग की स्थापना की जाए।

भारत सरकार ने देश के साधनों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास का ढाँचा तैयार करने के लिए मार्च, 1950 में योजना आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने मोटे तौर पर भारत में नियोजन के दो उद्देश्य बतलाए—

- 1 उत्पादन में वृद्धि करना और जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना।
- 2 स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक मूल्यों पर आधारित ऐसी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का विकास करना जिसमें राष्ट्रीय जीवन की सभी समस्याओं के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्राप्त हो।

आर्थिक नियोजन के लक्ष्य इस प्रकार रखे गए—

1. राष्ट्रीय आय में अधिकतम वृद्धि करना ताकि प्रति व्यक्ति औसत आय बढ़ सके।
2. तीव्र औद्योगीकरण एवं आधारभूत उद्योगों का शीघ्र विकास।
3. अधिकतम रोजगार।

4. आय की असमानताओं में कमी एवं धन का अधिक समान वितरण ।

5. देश में समाजवादी ढंग पर आधारित समाज (Socialistic Pattern of Society) का निर्माण ।

इन सभी लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए देश में पंचवर्षीय योजनाओं का सूत्रपात हुआ । अभी तक तीन पंचवर्षीय योजनाएँ (1951-52 से 1965-66), तीन एकवर्षीय योजनाएँ (1966 से 1969) तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (अप्रैल, 1969 से मार्च, 1974) समाप्त हो चुकी हैं और 1 अप्रैल, 1974 से चालू की गई पाँचवी पंचवर्षीय योजना के तीन वर्ष बीत चुके हैं ।

प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाएँ¹
(First Three Five Year Plans)

उद्देश्य (Objectives)—प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-52 से 1955-56) के दो उद्देश्य थे । पहला उद्देश्य युद्ध और देश के विभाजन के कारण उत्पन्न आर्थिक असंतुलन को ठीक करना था । दूसरा उद्देश्य था, साथ ही साथ सर्वांगीण, समन्वित विकास की प्रक्रिया शुरू करना जिससे निश्चित रूप से राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो और जीवन-स्तर में सुधार हो । 1951 में देश को 47 लाख टन साधन आयात करना पड़ा था और अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रा स्फीति का प्रभाव था । इसलिए योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचाई और बिजली परियोजना सहित कृषि को दी गई और इनके विकास के लिए सरकारी क्षेत्र के 2,069 करोड़ रु के कुल परिव्यय (जो बाद में बढ़ाकर 2,356 करोड़ रु कर दिया गया) का 44.6% रखा गया । इस योजना का उद्देश्य निवेश को राष्ट्रीय आय के 5% से बढ़ाकर लगभग 7% करना था ।

दिसम्बर, 1954 में लोकसभा ने घोषित किया कि आर्थिक नीति का व्यापक उद्देश्य 'समाज के समाजवादी ढाँचे' की प्राप्ति होना चाहिए । समाज के समाजवादी ढाँचे के अन्तर्गत प्रगति की रूपरेखा निर्धारित करने की आधारभूत कसौटी निजी मुनाफा नहीं, बल्कि सामाजिक लाभ और आय तथा सम्पत्ति का समान वितरण होना चाहिए । इस बात पर बल दिया गया कि समाजवादी अर्थ-व्यवस्था, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रति कुशल तथा प्रगतिशील दृष्टि अपनाएँ और उस स्तर तक क्रमिक प्रगति के लिए सक्षम हो कि आम जनता खुशहाल हो सके ।

द्वितीय योजना (1956-57 से 1960-61) में भारत में समाजवादी समाज की स्थापना की दिशा में विकास-ढाँचे को प्रोत्साहित करने के प्रयत्न किए गए । इस योजना में विशेष बल इस बात पर दिया गया कि आर्थिक विकास के अधिकाधिक लाभ समाज के अशिक्षाकृत कम साधन-प्राप्त वर्गों को मिलें और आय, सम्पत्ति और आर्थिक शक्ति के घन्द हाथों में सितमटे की प्रवृत्ति में लगातार कमी हो । इस योजना के उद्देश्य थे—(1) राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि, (2) आधारभूत

और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष बल देते हुए द्रुत औद्योगीकरण, (3) रोजगार के अवसरों में वृद्धि और (4) आय और सम्पत्ति की विषमताओं में कमी तथा आर्थिक शक्ति का और अधिक समान वितरण। इस योजना का उद्देश्य निवेश-दर को राष्ट्रीय आय के लगभग 7% से बढ़ा कर 1960-61 तक 11% करना था। योजना में औद्योगीकरण पर विशेष बल दिया गया। लोहे तथा इस्पात और नाइट्रोब्रन उर्वरकों सहित रसायनों के उत्पादन में वृद्धि और भारी इन्जिनियरी तथा मशीन निर्माण उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। योजना में सरकारी क्षेत्र का कुल परिव्यय 4,800 करोड़ रु. था। इसमें से 3,650 करोड़ रु. निवेश के लिए था और निजी क्षेत्र का परिव्यय 3,100 करोड़ रु. था।

तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-62 से 1965-66) शुरू हुई जिसका मुख्य उद्देश्य स्वयं-सूचित विकास की दिशा में निश्चित रूप से बढ़ना था। इसके तात्कालिक उद्देश्य ये थे—(1) राष्ट्रीय आय में 5% वार्षिक से अधिक की वृद्धि करना और साथ ही ऐसा निवेश ढाँचा तैयार करना कि यह वृद्धि-दर आगामी योजना अवधियों में बनी रहे, (2) खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और कृषि-उत्पादन बढ़ाना जिससे उद्योग तथा निर्यात की जरूरतें पूरी हो सकें, (3) इस्पात, रसायनों, ईंधन और बिजली जैसे आधारभूत उद्योगों का विस्तार करना और मशीन निर्माण-क्षमता स्थापित करना ताकि आगामी लगभग 12 वर्षों में औद्योगीकरण की भावी माँगों को मुख्यतः देश के अपने साधनों से पूरा किया जा सके, (4) देश की जन-शक्ति के साधनों का अधिकतम उपयोग करना और रोजगार के अवसरों का पर्याप्त विस्तार करना, और (5) उत्तरोत्तर अवसरों की समानता में वृद्धि करना और आय तथा सम्पत्ति की विषमताओं को कम करना और आर्थिक शक्ति का और अधिक समान वितरण करना। राष्ट्रीय आय में लगभग 30 प्रतिशत वृद्धि कर के 1960-61 में 14,500 करोड़ रु. से बढ़ाकर (1960-61 के मूल्यों पर) 1965-66 में 19,000 करोड़ रु. करना और प्रति व्यक्ति आय में लगभग 17% वृद्धि कर के 330 रु. के बजाय इस अवधि के दौरान लगभग 385 रु. करना।

परिव्यय और निवेश (Out-lay and Investment)—पहली योजना में, सरकारी क्षेत्र में 2,356 करोड़ रु. के सशोधित परिव्यय के मुकाबले व्यय 1960 करोड़ रु. हुआ। दूसरी योजना में, सरकारी क्षेत्र में 4,800 करोड़ रु. की व्यवस्था के मुकाबले वास्तविक खर्च 4,672 करोड़ रु. रहा जबकि निजी क्षेत्र में 3,100 करोड़ रु. का विनियोग हुआ। तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र के लिए 7,500 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रावधान था। इसके मुकाबले सरकारी क्षेत्र में वास्तविक खर्च 8,577 करोड़ रु. रहा। निजी क्षेत्र में 4,000 करोड़ रु. से अधिक का विनियोजन हुआ।

तीनों योजनाओं में उपलब्धियाँ (Achievements During the Three Plans)—पन्द्रह वर्षों के आयोजन से, समय-समय पर बाधाओं के बावजूद अर्थ-व्यवस्था में सर्वांगीण प्रगति हुई। आधारभूत सुविधाएँ जैसे सिंचाई, बिजली और

परिवहन में काफी विस्तार हुआ और छोटे बड़े उद्योगों के लिए बहुमूल्य खनिज भण्डार स्थापित किए गए।

पहली योजना में मुख्यतः कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी से, राष्ट्रीय आय में निर्धारित लक्ष्य 12 / से अधिक यानी 18 / वृद्धि हुई। दूसरी योजना में राष्ट्रीय आय में 25 / के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 20 / वृद्धि हुई और तीसरी योजना में राष्ट्रीय आय (संशोधित) 1960-61 के मूल्यों पर पहले चार वर्षों में 20% बढ़ी और अन्तिम वर्ष में इसमें 5.7% की कमी आई। जनसंख्या में 25 / की वृद्धि के कारण 1965-66 में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय वही रही जो 1960-61 में थी।

पहली दो योजनाओं में कृषि-उत्पादन लगभग 41 / बढ़ा। तीसरी योजना में कृषि उत्पादन संतोषजनक नहीं था। 1965-66 और 1966-67 में सूखा पड़ा और कृषि-उत्पादन तेजी से गिरा। इससे अर्थ-व्यवस्था की विकास दर में ही कमी नहीं आई, बल्कि खाद्यान्नों के आयात पर भी हमारी निर्भरता बढ़ी। तीसरी योजना में देश ने 250 लाख टन खाद्यान्नों का आयात किया। हमें कपास की 39 लाख और पटसन की 15 लाख गांठें भी आयात करनी पड़ी।

पहली दो योजनाओं में संगठित निर्माता उद्योगों में शुद्ध उत्पादन लगभग दुगुना हुआ। इसमें सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का योग, जो पहली योजना के शुरू में 15 प्रतिशत था, दूसरी योजना के अन्त तक बढ़ कर 84 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि अधिकतर इस्पात, कोयला, खान, भारी रसायन जैसे आधारभूत उद्योगों में हुई। तीसरी योजना के पहले चार वर्षों में संगठित उद्योग का उत्पादन 810 प्रतिशत वार्षिक बढ़ा। लेकिन योजना के अन्तिम वर्ष में भारत-पाकिस्तान युद्ध से हुई गड़बड़ी और विदेशी सहायता में आई बाधाओं के कारण वृद्धि दर घट कर 5.3 प्रतिशत रह गई। कुल मिलाकर तीसरी योजना में संगठित उद्योगों की वृद्धि-दर 11 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 82 प्रतिशत रही लेकिन इस काल में एक उल्लेखनीय बात उत्पादन-क्षमता में वृद्धि तथा विविधता रही। यह बात प्रमुख रूप से इस्पात और अल्यूमीनियम, मशीनी औजार, औद्योगिक मशीनें बिजली और परिवहन उपकरण, उर्वरकों, औषध, औषधियों और पेट्रोलियम के उत्पादन में हुई। इन सब ने औद्योगिक ढांचे को सुबढ़ बनाने में योग दिया।

आयोजन के इन वर्षों में स्वास्थ्य और शैक्षणिक सुविधाओं का उल्लेखनीय विस्तार हुआ। 1950-51 में जन्म पर अपेक्षित आयु 35 वर्ष थी जो 1971 में 50 वर्ष हो गई। स्कूलों में प्रवेश की संख्या 1950-51 में 235 लाख थी जो 1965-66 तक बढ़कर 663 लाख हो गई। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की दशा सुधारने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए गए जिनसे उन्हें अनेक लाभ मिले और उनकी दशा बेहतर हुई।

तीन वार्षिक योजनाएँ (Three Annual Plans)

तीसरी योजना के बाद तीन एक वर्षीय योजनाएँ (1966-69) कार्यान्वित की गईं। भारत-पाकिस्तान युद्ध से उत्पन्न स्थिति, दो वर्षों के लगातार भीषण सूखे,

मुद्रा अवमूल्यन, मूल्यों में वृद्धि और योजना के लिए उपनब्ध साधनों में कमी के कारणों से चौथी योजना को अन्तिम रूप देने में बाधा पड़ी। इस दौरान चौथी योजना के मसविदे को ध्यान में रखते हुए तीन एकवर्षीय योजनाएँ बनाई गईं। इनमें तत्कालीन परिस्थितियों का ध्यान रखा गया। इस अवधि में अर्थ व्यवस्था की स्थिति और योजना के लिए वित्तीय साधनों की कमी से विकास व्यय कम रहा।

वार्षिक योजनाओं में विकास की मुख्य मंशों का व्यय इस प्रकार रहा (करोड़ रु में) कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र 1 166 6, सिंचाई और बाढ़-नियन्त्रण 457 1, बिजली 1,182 2, ग्राम और लघु उद्योग 144 1, उद्योग और खनिज 157 0, परिवहन और संचार 1,239 1, शिक्षा 322 4, वैज्ञानिक अनुसन्धान 51 1, स्वास्थ्य 140 1, परिवार नियोजन 75 2, पानी की सप्लाई और सफाई 100 6, आवास शहरी और क्षेत्रीय विकास 63 4 पिछड़ी जातियों का कल्याण 68 5, समाज कल्याण 12 1, थम कल्याण और कारीगरों का प्रशिक्षण 32 5 और अन्य कार्यक्रम 123 5। तीन वार्षिक योजनाओं का कुल व्यय 6,756 5 करोड़ रुपये रहा।

चौथी और पाँचवी पंचवर्षीय योजनाएँ (Fourth and Fifth Five Year Plans)

चौथी पंचवर्षीय योजना अप्रैल, 1969 से शुरू होकर मार्च 1974 तक रही और तत्पश्चात् 1 अप्रैल, 1974 से पाँचवी पंचवर्षीय योजना चालू की गई जिसके तीन वर्ष पूरे होने की हैं। इन दोनों ही योजनाओं का विस्तृत विवेचन अगले अध्याय में किया गया है।

भारत में नियोजन : समाजवादी समाज का आदर्श (Planning in India Ideal of Socialistic Pattern of Society)

नियोजन का अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण है जिसमें व्यक्ति तथा समाज के लिए सुरक्षा, स्वतन्त्रता और अवकाश के लिए स्थान हो—जिसमें व्यक्ति को उत्पादक दृष्टि से, नागरिक की दृष्टि से और उपभोक्ता की दृष्टि से समुचित सम्मेलन मिले। स्वतन्त्रता के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार के लिए अनिवार्य हो गया कि एक निश्चित जीवन-स्तर, पूर्ण रोजगार, आय का समान वितरण आदि की व्यवस्था करके देशवासियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। यह सभी सम्भव था जब उत्पादन के मुख्य साधनों पर समाज का अधिकार हो, उत्पादन की गति निरन्तर विकासात्मक हो और राष्ट्रीय आय का उचित वितरण हो। अतः देश की भावी नीति को और देश के आर्थिक नियोजन को इन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति के हेतु आवश्यक मोड़ देने का निश्चय किया गया। ऐसे उपाय खोजे जाने लगे जिनसे अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण हो सके। 1947 में दिल्ली कांग्रेस की बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया था—“हमारा उद्देश्य एक ऐसे आर्थिक ढाँचा का नव निर्माण और विकास होना चाहिए जिसमें धन के एक ही दिशा में एकत्र होने की प्रवृत्ति के बिना अधिकतम

उत्पादन किया जा सके, जिसमें नागरिक एवं ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में उचित सामञ्जस्य हो।" 1954 के अजमेर अधिवेशन में स्वर्गीय नेहरू ने कहा था कि वर्तमान भारत की समाजवादी व्यवस्था वस्तुतः गांधीवादी समाज और विकासार्थक व्यवस्था के समन्वय का नया रूप है और देश के आर्थिक पुनर्निर्माण तथा देश में समाजवादी समाज की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि शीघ्रातिशीघ्र आय के असमान वितरण को दूर किया जाए, प्राप्त साधनों का विदोहन किया जाए, पूँजी को बाहर निकाला जाए, बेरोजगारी की समस्या को हल किया जाए तथा देश का तीव्र गति से आर्थिक विकास किया जाए। 1954 में ही लोक सभा में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि जन-समुदाय के भौतिक कल्याण से ही देश की उन्नति सम्भव नहीं है, इसके लिए सामाजिक व्यवस्था में संस्थागत (Institutional) परिवर्तन करने होंगे। तत्पश्चात् 22 जनवरी, 1955 को अवाड़ी अधिवेशन में आर्थिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ जिसमें ऐसे समाज की स्थापना पर बल दिया गया जो समाजवादी समाज के निर्माण में सहायक हो। उपर्युक्त प्रस्ताव में समाजवादी समाज के इन मौलिक सिद्धान्तों को ध्यान में रखा गया—

- (1) पूर्ण रोजगार, (2) राष्ट्रीय धन का अधिकतम उत्पादन, (3) अधिकतम राष्ट्रीय आत्म-निर्भरता, (4) सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, (5) अन्तिमपूर्ण अहिंसात्मक और लोकतान्त्रिक तरीकों के प्रयोग, (6) ग्राम पंचायतों की समितियों की स्थापना, एवं (7) व्यक्ति की सर्वोच्चता एवं उसकी आवश्यकताओं को अधिकतम प्राथमिकता।

समाजवादी समाज के इन सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए अवाड़ी अधिवेशन में समाज की स्थापना के लिए ये लक्ष्य रखे गए—(1) जन साधारण के जीवन-स्तर में वृद्धि, (2) उत्पादन स्तर में वृद्धि, (3) दस वर्ष में पूर्ण रोजगार की व्यवस्था, (4) राष्ट्रीय धन का समान वितरण, एवं (5) व्यक्ति तथा समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति आदि। योजना आयोग द्वारा इन सिद्धान्तों का समर्थन किया गया और इस प्रकार की व्यवस्थाएँ की गईं जो समाजवादी समाज की आधारशिला बन सकें। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मूल आधार समाजवादी समाज का निर्माण रखा गया और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के मुख्य निर्माता विख्यात अयंशास्त्री महालनोबिस ने निम्नलिखित आठ उद्देश्यों पर विशेष बल दिया—

- (1) सावजनिक क्षेत्र के महत्त्व और उसकी सीमा को विस्तृत करना।
- (2) आर्थिक सुदृढता के लिए आधारभूत उद्योगों का विकास।
- (3) गृह उद्योगों एवं हस्तकला वस्तुओं का अधिकतम उत्पादन।
- (4) भूमि सुधारों की गति में तेजी एवं भूमि का समान वितरण।
- (5) छोटे उद्योगों का बड़े उद्योगों से रक्षण करना और उन्हें पूरक बनाना।
- (6) जन-साधारण के लिए आवास, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा सेवाओं का विस्तार।

(7) बेरोजगारी समस्या की दस वर्षों में समाप्ति ।

(8) इस अवधि में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि तथा राष्ट्रीय आय का समान व उचित वितरण ।

1973-74 तक नियोजन और समाजवादी आदर्श की प्राप्ति का मूल्यांकन

स्पष्ट है कि भारत में नियोजन का आधार समाजवादी समाज का निर्माण रहा और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए नियोजन में विभिन्न कदम उठाए गए । प्रगति भी हुई, राष्ट्रीय आय बढ़ी जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है—

आर्थिक प्रगति आँकड़ों में¹

	1960-61	1965-66	1973-74
राष्ट्रीय आय .			
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन	13,300 करोड़ रु.	20,600 करोड़ रु.	49,300 करोड़ रु.
वर्तमान मूल्यों पर			
स्थिर मूल्यों पर	13,300 करोड़ रु.	15,100 करोड़ रु.	19,700 करोड़ रु.
प्रति व्यक्ति आय			
वर्तमान मूल्यों पर	306 रु.	426 रु.	850 रु.
स्थिर मूल्यों पर	306 रु.	311 रु.	340 रु.
औद्योगिक उत्पादन का सूचक (1960=100)	100 रु.	154 रु.	201 रु.
भुगतान सन्तुलन			
विदेशी मुद्रा की कमी	304 करोड़ रु.	298 करोड़ रु.	947 करोड़ रु.
विदेश व्यापार			
निर्यात	660 करोड़ रु.	810 करोड़ रु.	2,483 करोड़ रु.
आयात	1,140 करोड़ रु.	1,394 करोड़ रु.	2,921 करोड़ रु.

लेकिन नियोजन की वास्तविक उपलब्धियों को समाजवादी समाज के दर्पण में देखने पर अधिकांशतः निराशा ही हाथ लगी । इसमें सन्देह नहीं कि सरकार ने समाजवादी समाज की स्थापना के लिए प्रयत्न किए और योजनाओं को इस दिशा में मोड़ने तथा गति देने के लिए विभिन्न कदम उठाए, लेकिन विभिन्न कारणों से इसमें अपेक्षित सफलता न मिल सकी । व्यवहार में समाजवादी तत्वों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल पाया और न ही आय तथा सम्पत्ति का कोई उचित वितरण हो सका । चार पंचवर्षीय योजनाओं, तीन एक वर्षीय योजनाओं और पाँचवी योजना के प्रारम्भिक डेढ़ वर्ष के सम्पन्न होने के बाद भी यह देखकर सभी क्षेत्रों में निराशा छाई रही कि आय और धन की असमानताओं में भारी वृद्धि हुई है तथा राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग उद्योगपतियों और पूँजीपतियों को मिला है । यद्यपि निम्न वर्गों के रहन-सहन के स्तर में कुछ सुधार अवश्य हुआ है, लेकिन तुलनात्मक रूप से

यह निराशाजनक है और असमानताओं की खाई पहले से बड़ी है। समाजवाद लाने की आशा जगाने वाले अनेक सरकारी सस्यानों में भी पूंजीपतियों का प्रभुत्व छाया हुआ है। देश में न तो समाजवादी मनोवृत्ति ही जाग्रत हुई है और न व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा ही प्राप्त हो सकी है। पूर्ण रोजगार की बात तो दूर रही, बेरोजगारों की फौज निरन्तर बढ़ती जा रही है जिसका सम्पूर्ण राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। देश की श्रम-शक्ति का सदुपयोग न हो पाने से और बड़ी मात्रा में उसके व्यर्थ पड़े रहने से राष्ट्र को कितनी आर्थिक, सामाजिक और नैतिक हानि होती है इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। सावर्जनिक क्षेत्र के विकास द्वारा निजी-क्षेत्र पर कुछ रोक अवश्य लगी है, लेकिन आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। क्षेत्रीय असमानताएँ भी बहुत कुछ यथापूर्व बनी हुई हैं और एकाधिकारी शक्तियों में वृद्धि हो रही है।

वस्तुतः, समाजवाद की कल्पना कोरे कागजों पर ही हुई। देश में जिस दर से महँगाई बढ़ी, वस्तुओं के भाव आकाश छूने लगे और साधारण जनता जीवन-निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं में भी जितने कष्ट का अनुभव करने लगी, उससे समाजवादी समाज का निर्माण कौसो दूर दिखाई देता था। मूल्य-वृद्धि का सामना करने के लिए सबसे सरल उपाय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि और तदनुसार घाटे की अर्थव्यवस्था समझा जाता रहा है। लेकिन इससे स्वभावतः मुद्रा-प्रसार होता है और मुद्रा-प्रसार से हमें पुनः मूल्य-वृद्धि के भवर म फँसना पड़ता है। फलस्वरूप हमारे गरीबी के कष्ट और अधिक बढ़ जाते हैं। इसीलिए शहरों में पाए जाने वाला गरीब-धमीर का अन्तर गाँवों में भी काफी गहरा होता गया। जैसा कि योगेशचन्द्र शर्मा ने 22 अप्रैल, 1973 के योजना-ग्रक में प्रकाशित एक लेख में लिखा—“गाँवों में एक ओर तो बड़े-बड़े भू-पति हैं, जिनके पास स्वयं अपने नाम पर या रिश्तेदारों के नाम पर दूर-दूर तक फैली हुई कृषि-भूमि है और दूसरी ओर ऐसे किसान हैं जिनके पास केवल एक या दो बीघा जमीन है। बड़े भू-पतियों में या तो शहर के पूंजीपति और पुराने जमींदार हैं अथवा ऐसे राजनीतिक नेता हैं जिन्होंने अपने प्रभाव से काफी जमीन अपने पास बटोर ली है। ये भू-पति निश्चित रूप से मूल्य-वृद्धि से काफी लाभान्वित हुए हैं और बड़ी हुई राष्ट्रीय आय की दोनों हाथों से बटोर रहे हैं। दूसरी ओर किसान हैं जो इस स्थिति में भी नहीं हैं कि पैदा हुई फसल को कुछ समय तक रोक कर अपने पास रख लें। उन्हें तो तत्काल अपनी फसल को बाजार में ले जाकर बेचना पड़ता है, ताकि अपने लिए आवश्यकता की वस्तुएँ जुटा सकें।”

योजनाओं के आँकड़ों से पता चलता है कि भूमि का वितरण भी उचित रूप से नहीं हुआ। उपर्युक्त लेख के अनुसार “देश भर में जुलाई, 1972 तक लगभग 24 लाख एकड़ भूमि पर सरकार ने कब्जा किया, जिसमें लगभग आधा भाग ही वितरित किया जा सका।” यथार्थ रूप से कृषि-मजदूरों और पट्टेदारों की संख्या में भी सन्तोषप्रद कमी नहीं आई। ग्रामीण जीवन पर सहकारी सिद्धान्त का प्रभाव व्यवहार में निराशाजनक रहा। गाँवों में जो भूमिहीन व्यक्ति हैं, उन्हें रोजगार देने

के लिए बहुत कम सोचा गया तथा उसके व्यावहारिक स्वरूप को और भी कम महत्व दिया गया। न्यूनतम जीवन-स्तर की कल्पना कागजी ही अधिक रही। डॉ० राव ने ठीक ही विचार व्यक्त किया कि 'यदि समाजवाद के प्रश्न पर सरकारी दृष्टि से विचार किया जाए अथवा केवल आँकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होना है कि इस दिशा में काफी प्रगति हुई है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जिनकी उम्मीद थी उतनी भी आर्थिक उन्नति नहीं हुई है।' "देश में समाजवादी मनोवृत्ति एवं प्रवृत्ति का स्पष्ट रूप कहीं देखने को नहीं मिलता और न इस प्रकार की प्रवृत्ति पैदा करने की दिशा में कोई कार्यवाही की जा रही है। इसके विपरीत पूँजीवादी मनोवृत्ति एवं प्रवृत्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और सरकारी नीति तथा कार्यक्रम भी इनका उत्साह भग करने में सफल नहीं हो पाए हैं।" डॉ० राव का यह विचार निश्चय ही सारपूर्ण था कि "समाजवादी समाज के लिए आयोजन व्यवस्था और तकनीक में मूल तत्त्व का अभाव रहा है। मूल तत्त्व ये हैं कि हमजन-साधारण में आस्था पैदा करने और जन-सहयोग प्राप्त करने में सफल नहीं हो रहे हैं।"

भारत में समाजवादी समाज की दिशा में नियोजन की सफलता का मूल्यांकन देग में व्याप्त 'गरीबी' के आधार पर किया जाना चाहिए और इस कसौटी पर नियोजन एकदम फीका सिद्ध हुआ। एस. एच. पिटवे ने 7 मार्च, 1973 के योजना-अंक में प्रकाशित अपने एक लेख में ठीक ही लिखा कि "गरीबी के स्तर को मापने का सरल निर्देशांक यही हो सकता है कि कुल उपभोक्ता व्ययों का बँटवारा प्रमुख मदों में किया जाए, जैसे अन्न, ईंधन, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन आदि। भारत में इनमें से भोजन पर सर्वाधिक व्यय होता है। अनुमान है कि भारत में उपभोक्ता के कुल व्यय का 70 से 80 प्रतिशत तक मात्र भोजन पर व्यय होता है।" प्रो० दाण्डेकर ने भारत में गरीबी का जो विद्वतापूर्ण अध्ययन किया उससे भी यह स्पष्ट है कि पिछले दशक के आर्थिक विकास का अधिकतम लाभ ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में उच्च, मध्यम श्रेणी तथा अमीर वर्ग को ही हुआ और गरीब वर्ग इससे कुछ भी लाभान्वित नहीं हो सका, बल्कि उसके उपभोग में गिरावट हुई। इस अध्ययन का स्पष्ट एवं तार्किक निष्कर्ष यह निकलता है कि 1973-74 तक आय की असमानता में और वृद्धि होकर अमीर तथा गरीब के बीच की खाई और भी विस्तीर्ण हो गई।

1974 से अगस्त 1976 तक का मूल्यांकन

आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगतियों के बावजूद दुर्भाग्यवश हम समाजवादी समाज की स्थापना के उद्देश्य में असफल रहे। लेकिन राष्ट्र ने बड़े सोच विचार के बाद एक ऐसे उद्देश्य को पकड़ा है जिसकी पूर्ति को असम्भव नहीं माना जा सकता। वास्तव में सबसे बड़ी कमी सरकार के दृढ़ निश्चय की रही। सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं को उन सभी तत्त्वों ने सरकार की कमजोरी समझा जो सभी स्तरों पर आर्थिक अव्यवस्था लाना चाहते थे और सम्भवतः उनकी यह भावना ही राजनीतिक

क्षेत्र में व्याप्त नियन्त्रणीयता का प्रतिबिम्ब था। यह स्थिति पैदा हो गई कि देश की स्थिरता को कमजोर किया जाना लगा, देश के कई भागों में हिंसा का वातावरण फैलाया गया, स्थिरता और प्रगति के विरोधी राजनीतिक तत्वों ने अस्त-व्यस्तता और साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काया। जब यह स्पष्ट हो गया कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता एवं प्रगति खतर में पड़ गई है तो सरकार ने 26 जून, 1975 को राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा की जो अभी अबतक 1976 तक जारी है और निम्नलिखित अवधि में जब तक कि राष्ट्र एकदम सुव्यवस्थित नहीं हो जाता, इसका समाप्त होना की सम्भावना नहीं दिखाई देती। इस आपात स्थिति ने तोड़ फोड़ और हिंसा की प्रवृत्तियों को रोकथाम कर दी और अनुशासन का एक नया वातावरण पैदा किया है जो भारत के विकास के लिए विशाल सम्भावनाओं को फिर से सही दिशा प्रदान करने के लिए और सामाजिक तथा आर्थिक भ्रष्टाचार के दबावे में तेजी से वृद्धि के कार्यक्रम को लागू करने के लिए आवश्यक है।

वास्तव में 1974 के मध्य से ही सरकार समाजवादी समाज के घोषित लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में विशेष रूप से सक्रिय हो गई। इन्दिरा सरकार द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने सरकार के इरादों को पहले ही स्पष्ट कर दिया था, 1974 के मध्य मुद्रा स्थिति को गंभीरता के लिए कुछ कठोर कदम उठाए गए (यन्त्रियाँ जमा योजना लागू करना आदि)। इसी प्रकार जुलाई 1974 में ही सभी बैंकों के सबसे बड़े खानों पर रिजर्व बैंक के कठोर निगरानी सम्बन्धी आदेश लागू किए गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि पाँचवी पंचवर्षीय योजना को समाजवादी लक्ष्य की दिशा में समाजवादी बनाने का प्रयास किया गया। पाँचवी योजना जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती है वे इस प्रकार हैं—

1 एक ऐसा विकास कार्यक्रम, जिसके द्वारा पिछड़े तथा शोषित समुदायों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरा बढन का उपयुक्त अवसर मिले और वे भी सबके कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों में हाथ बँटा सकें।

2 एक इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना जिसमें प्रत्येक घटसक नागरिक को उसके योग्यतानुसार पूरा रोजगार प्राप्त हो सके और वह राष्ट्र की प्रगति में सहयोग दे सके।

3. धन उगाड़ने करने की एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना जिसके द्वारा अमीर-गरीब के बीच की खाई को कुछ समाप्त किया जा सके।

4 एक ऐसी जीवन धारा का निर्माण राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समानता अर्थपूर्ण और वास्तविक रूप में रहे।

समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य की प्रगति के लिए सरकार को अपनी शिथिलता का परित्याग करना होगा और अपनी नीतियों को कठोरतापूर्वक अमलीजामा पहिनाना होगा। नीति निर्माण का उद्देश्य तब विफल हो जाता है जब उस नीति का अनुचित ढंग में क्रियन्वयन नहीं हो पाता। सरकार से अपेक्षित है कि—

1 विलासिताओं पर भारी कर लगाया जाए। जब हम आर्थिक स्थिरता

प्राप्त करने और एक न्यायोचित समाज का निर्माण करने के लिए प्रयत्नशील हैं तो यह अनुचित है कि समाज का एक विशेष वर्ग प्रदर्शन उपभोग में व्यस्त रहे। न्याय-सिद्धान्त का तर्काज है कि समाज का जो व्यक्ति जितना अधिक कमाता है वह आनुपातिक रूप से सामाजिक जिम्मेदारियों का भी उतना ही अधिक भार वहन करे और अधिक कर देते समय कोई असमन्वीय महसूस न करे।

2 सरकार कृषिबद्ध होकर उत्पादन के सभी साधनों भूमि श्रम पूंजी साहज्य और माऊन को एकजुट करके राष्ट्रीय आय में तीव्र वृद्धि के लिए प्रयत्नशील हो और राष्ट्रीय आय का उचित वितरण कर आय की असमानता कम करने के लिए युद्ध स्तरीय ठोस कदम उठाए।

3 खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से अधिकाधिक वृद्धि के लिए ठोम और युद्ध-स्तरीय कदम उठाए जाएँ। मिच ई खाद जोन आदि के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाएँ। नहरो बायो कुप्रो आदि का बड़ी संख्या में निर्माण कर मौसम पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति को टुकराया जाए।

4 औद्योगिक विकास तीव्र गति से हो तथा कुछ समय के लिए पूंजी का निर्यात बंद करके उससे अपने ही देश में औद्योगिक विकास किया जाए।

5 घाटे की प्रवृत्तिवस्था और मुद्रा प्रसार की प्रवृत्ति पर अकुश लगाया जाए।

6 काले धन को बाहर निकालने के लिए कठोर वैधानिक कदम उठाए जाएँ।

7 सम्पन्न किसानों की आय पर ऊँची दर से करारोपण किया जाए और प्राप्त आय से ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार पैदा किए जाएँ।

8 देश के बड़े बड़े पूंजीशक्तियों और उद्योगपतियों पर बेरोजगारी टैक्स लगा कर उस धन से बे रोजगार व्यक्तियों को समुचित आर्थिक सहायता दी जाए।

9 हड़तालों आदि पर कुछ वर्षों के लिए कठोरतापूर्वक रोक लगाकर देश के उत्पादन को बढ़ाया जाए और श्रम शक्ति का पूरा पूरा उपयोग किया जाए। यदि आवश्यक हो तो इसके लिए संविधान में भी संशोधन किया जाए।

10 उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से सरकार नए उत्तरदायित्वों से विरगई है। सरकार इन उत्तरदायित्वों को कुशलतापूर्वक निभाए और सावजनिक क्षेत्र की कार्यक्षमता पर लोगों को सन्देश न होने दे। आधुनिक प्रबंध को प्रभावशाली बनाने के लिए सभी स्तरों पर सार्वजनिक अनुशासन का पूरा ध्यान रखा जाए। यह भली प्रकार समझ लिया जाए कि यदि जन जीवन में सामान्यताही विशेषता घर करने लगेगी तो समाजवादी समाज की स्थापना के लिए आवश्यक सामाजिक परिवर्तन के अस्तित्व का आधार ही समाप्त हो जाएगा।

11 सरकार लघु योजनाओं और कार्यक्रमों का जाल बिछाए ताकि बेकार पड़ी श्रम शक्ति का उपयोग किया जा सके। बेरोजगारी को दूर करने के प्रत्येक सम्भव उपाय किए जाएँ।

12 सामाजिक सेवाओं का तेजी से विस्तार किया जाए पर इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि साधारण जनता और पिछड़े वर्गों को उनका

समुचित लाभ मिल सके। वस्तुओं के उत्पादन और उचित वितरण, दोनों पर प्रभावशाली टंग से ध्यान दिया जाए।

13. बैंक राष्ट्रीयकरण के प्रसंग में जो कमियाँ घर कर गई हैं उनका यथाशीघ्र निराकरण किया जाए। प्रशासनिक व्यय को घटाया जाए। जो 'नए जमींदार और जागीरदार' बन हैं, जो 'नए-नए राजा-महाराजा' बन गए हैं—उनकी आकस्मिक समृद्धि का पूरा लेखा-जोखा लिया जाए और सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को खाड़ कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएँ। उच्च पदाधिकारियों की वेतन वृद्धि की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाए और छोटे राजा कर्मचारियों की वेतन-वृद्धि पर इस रूप में ध्यान दिया जाए कि उससे मूल्य-वृद्धि को प्रोत्साहन न मिले। इस दिशा में सक्रिय रूप से विचार किया जाए कि ग्यूननम वेतन लगभग 250 रुपए हो और अधिकतम वेतन लगभग 2000 रुपए से अधिक न हो। रेलों में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी समाप्त कर दी जाए।

यदि इन सभी और इसी प्रकार के अन्य उपायों पर प्रभावी रूप में धमक दिया जाए तो इनमें सन्देह नहीं है कि हम नियोजन के माध्यम से समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सकेंगे। इस लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में 2 जुलाई, 1975 को 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की गई जिसने देश का ध्यान राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास के अग्रगण्य कार्य पर केन्द्रित किया और जिसका समाज के सभी वर्गों ने स्वागत किया। इससे जनता में नई आशा जाग्रत हुई है।

नया आर्थिक कार्यक्रम¹

यह नया कार्यक्रम अधिक से अधिक तेजी और कुशलता के साथ प्रयत्न में लाया जा रहा है और लगभग एक वर्ष की अल्पावधि में ही इसके प्रभावशाली परिणाम प्राप्त होने हैं। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कम करने के लिए जो उपाय किए गए थे उन पर जोर दिया जा रहा है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रयत्न में लाने में उत्तेजनपूर्ण सुधार हुआ है। जन-उपभोग की कई आवश्यक वस्तुओं के मूल्य काफी गिर गए हैं और वे अब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने लगी हैं। इससे जन-साधारण को बड़ी राहत मिली है। इस वर्ष खरीफ की फसल रिकार्ड स्तर पर हुई है और आग वाली रबी की फसल की सम्भावनाएँ भी बहुत अच्छी हैं। प्राया है कि 1975-76 में भारत में पूर्वापेक्षा सर्वाधिक खाद्यान्नों का उत्पादन (114 करोड़ मी. टन) होगा। नवाधिक मात्रा में खाद्यान्न की वसूली और उनके पर्याप्त भण्डार जमा करने का भरपूर प्रयत्न किया जा रहे हैं।

सभी राज्यों में सहकारी समितियों के द्वारा छात्रावासों में आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त सप्लाई करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। इसी प्रकार नियंत्रित मूल्यों पर किरावों और स्टेशनरी की सप्लाई के लिए भी प्रयत्न किए गए हैं।

पाठ्य पुस्तकों और स्टेशनरी को तैयार करने तथा वितरण के लिए रियायती दरों पर केन्द्रीय सरकार न राज्य सरकार को कागज दिया है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए पुस्तकों के मूल्य निश्चिन करने के लिए भी कार्रवाई की गई है और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहकारी स्टोर खोले गए हैं। विद्यार्थियों की सहायता के लिए विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचिन आदिम जातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों की मदद के लिए 70 हजार से अधिक पुस्तक-कोष देश में कार्य कर रहे हैं। इन कार्यों से विद्यार्थियों में काफी सन्तोष उत्पन्न हुआ है। विश्वविद्यालयों में अब अनुशासनहीनता का वातावरण नहीं है।

कृषि उत्पादन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए नए आर्थिक कार्यक्रम में इस बात की व्यवस्था की गई है कि 50 लाख हेक्टेयर अधिक जमीन में सिंचाई की जाएगी। बिजली के उत्पादन में भी तेजी लाई जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र में अर्थ व्यवस्था के विभिन्न कमजोर क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। उदाहरणार्थ, अप्रैल से अक्टूबर, 1975 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा कोयले के उत्पादन में 11.6% बिक्री योग्य इस्पात में 16.4%, प्रत्युमीनियम में 38.2%, नम्र जनित्र रासायनिक खादों में 29.9% सीमेंट में 15.3% और बिजली के उत्पादन में 9.5% की वृद्धि हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के क्रियाकलापों में हुआ सुधार जारी रहा और उत्पादन में वृद्धि की समग्र दर अप्रैल अक्टूबर, 1975 की अवधि में पिछले वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा 15% अधिक रही। रेलों और बन्दरगाहों की कार्य प्रणति में सुधार हो जाने के कारण अब हमारे औद्योगिक उत्पादन में यातायात की कोई बाधा नहीं रही।

जबकि सार्वजनिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का नियन्त्रण करता है वही निजी क्षेत्र को भी देश के विकास के लिए एक विशिष्ट भूमिका सौंपी गई है। हाल ही में कुछ ऐसे परिवर्तन किए गए हैं जिससे कि ये क्षेत्र विशेष रूप से इस भूमिका को पूरा कर सकें। औद्योगिक लाइसेंसिंग नीतियां और प्रणालियां सरल की गई हैं ताकि छोटे-छोटे उद्यमों में निवेश कर सकें और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में वृद्धि हो सके। सरकार ने आयात और निर्यात प्रणालियों को भी सरल कर दिया है और नई वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं।

मजदूरों ने भी प्रधान मंत्री की 'औद्योगिक शान्ति की अपील पर शानदार ढंग से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। औद्योगिक शान्ति के कारण आपात् स्थिति के बाद जिन व्यक्तियों की हानि हुई है वह पिछले वर्ष की इसी अवधि के व्यक्तियों की हानि के 1/10 भाग से भी कम है। इसी प्रकार अनुचित तालाबन्दियों, छूटनियों और जबरन छुट्टी को रोकने के लिए सरकार द्वारा उचित कदम उठाए गए हैं। प्रबन्ध में मजदूरों को सम्मिलित करने की दृष्टि से समग्र स्तर पर और बिक्री स्तर पर उद्योगों में श्रमिकों को सम्बद्ध करने के लिए एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। रोजगार और प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए अग्रेंटिसशिप योजना की समीक्षा

की गई और एक तिहाई से अधिक जो स्थान खाली रह जाये थे वे भ्रष्ट भरे जा रहे हैं।

साथी बुनकरों की सहायता के लिए हाथकरघा उद्योग के लिए एक विकास योजना बनाई गई है जिसमें अधिकांश भाग सहकारी समितियों का होगा और इसके द्वारा आवश्यक चीजों की सप्लाई और निर्यात आदि को प्रोत्साहन दिया जाएगा। हाथकरघों के लिए एक पृथक् विकास आयुक्त का संगठन बनाया गया है। मिलों के क्षेत्र में नियन्त्रित कपड़े की योजना में सुधार किया जा रहा है ताकि कपड़े की किस्म बढ़िया हो सके।

कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए और ग्रामीण समुदाय में आय तथा सम्पत्ति की विषमताओं को घटाने के लिए भूमि सुधार आवश्यक है। कई राज्यों ने विभिन्न प्रकार के भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यों पर तेजी से अमल करने के लिए और अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन लोगों को देने के लिए कार्रवाई की है। आदिम-जाति के लोगों की जो जमीनें हैं वे उनसे न ली जा सकें, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं और उनको अपनी धरलू जमीनों के स्वामित्व के अधिकार दिए जा रहे हैं। इसके अलावा भूमिहीन और कमजोर वर्गों को 60 लाख से अधिक मकान बनाने की जमीनें दी गई हैं। ग्रामीण मजदूरों का शोषण रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार ने एक अध्यादेश द्वारा देश में सभी प्रकार की बंधुवा मजदूरी समाप्त कर दी है। न्यूनतम मजदूरियों में सशोधन किया गया है। साहूकारों के शिकजे से छोटे किसानों और भूमिहीन लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए ऋणों पर पाबन्दी लगा दी गई है। कई राज्यों ने इन ऋणों को समाप्त करने के लिए कानून भी बनाया है। इनके साथ-साथ सहकारी ऋण संस्थानों को मजबूत किया जा रहा है और 50 ग्रामीण बैंकों की योजना बनाई गई है जिसमें प्रत्येक बैंक की 100 शाखाएँ होंगी। इस प्रकार ग्रामीण कारीगरों और कृषकों को ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 5 हजार बैंक होंगे। ऐसे 5 बैंक हरियाणा के भिवानी में, राजस्थान के जयपुर में, पश्चिमी बंगाल के मालदा में और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और गोग्रखपुर में स्थापित हो चुके हैं।

राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में सुस्ती और असोय्यता को दूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं। मनोवृत्तियों और प्रणालियों को बदलने के लिए प्रशासनिक ढाँचे में कई सुधार किए जा रहे हैं। निरक्षरों और बेईमान तत्वों को हटाया जा रहा है। सभी सार्वजनिक एजेंसियों में ग्राहक सेवा का सुधार किया जा रहा है। इस समय का नारा है—“जनता की सेवा—काम करके दिखलाना।” देश में उदासीनता और बेबसी का वातावरण अब ‘विश्वास और पक्के इरादे’ में बदल रहा है। एक समझदार और साहसी नेतृत्व में राष्ट्र शक्तिशाली ढंग से आत्मनिर्भर और कुशल अर्थ-व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है।

योजनाओं में विकास, बचत एवं विनियोग दरें-नियोजित तथा वास्तव में प्राप्त

(Growth-rates and Saving [Investment] Rates—Planned
and Achieved in the Plans)

भारत में चार पंचवर्षीय योजनाएँ और तीन एकवर्षीय योजनाएँ पूर्ण करने के बाद 1 अप्रैल 1974 से पाँचवी पंचवर्षीय योजना लागू हो गई है। अब तक पूरी की गई योजनाओं में विकास-दर, बचत तथा विनियोग दरों की क्या स्थिति रही है, इसका परीक्षण करने से पूर्व विकास दर का अर्थ समझ लेना आवश्यक है। प्रायः विकास-दर को निम्न प्रकार से फार्मुला द्वारा ज्ञात किया जाता है—

$$\text{विकास-दर} = \frac{\text{बचत}}{\text{पूँजी गुणांक या पूँजी-प्रदा-अनुपात}}$$

उदाहरणार्थ, किसी अर्थ-व्यवस्था में पूँजी-प्रदा-अनुपात 4 है तथा जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2% है और बचत एवं विनियोग दर 8% है। इस स्थिति में उम राष्ट्र की राष्ट्रीय आय $8/4 = 2\%$ वार्षिक दर से बढ़ेगी। किन्तु जनसंख्या की वृद्धि भी 2% होने के कारण प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं होगी और इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से देश की अर्थ-व्यवस्था स्थिर बनी रहेगी। चूँकि आर्थिक विकास का अर्थ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है, इसीलिए विकास में वृद्धि के लिए बचत एवं विनियोग की दर 8% से अधिक आवश्यक होगी। विकास-दर की उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि भारत की योजनाओं में नियोजित विकास-दर के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम इस देश की बचत एवं विनियोग की स्थिति जानना आवश्यक है। यह देखना जरूरी है कि भारत की योजना में बचत एवं विनियोग दरें किस प्रकार रही हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय नियोजन और अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में विविध स्रोतों के आंकड़ों में प्रायः ग़ुनाहिक भिन्नता पायी जाती है। प्रस्तुत अध्याय देश की पंचवर्षीय योजनाओं और विख्यात अर्थशास्त्री प्रो. विल्फ्रेड मेलनबाम (Wilfred Malenbaum) के अध्ययन पर आधारित है। प्रो. मेलनबाम का अध्ययन प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं और चतुर्थ योजना प्रारूप (1966) के सन्दर्भ में है। यद्यपि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रारूप बाद में संशोधित किया गया तथापि अध्ययन के लिए कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता।

भारत में नियोजित बचत एवं विनियोग की स्थिति

यदि घरेलू बचतों को राष्ट्रीय आय के भाग के रूप में देखें तो 1951-52 में घरेलू बचतें राष्ट्रीय आय का केवल 5.3% थी। यह दर 1955-56 में बढ़कर 7.5% हो गई तथा 1960-61 में इस दर की स्थिति 8.5% थी। 1965-66 में ये बचतें कुल राष्ट्रीय आय का 10.6% थीं किन्तु 1968-69 में यह घटकर 8.8% हो गई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष 1973-74 में इस दर की परिकल्पना 13.2% की गई।

जहाँ तक विनियोजन का प्रश्न है, 1950-51 में विनियोजन राष्ट्रीय आय का 5.6% था जो बढ़कर 1955-56 में 7.3% हो गया, 1960-61 में 11.7%, 1965-66 में 13% तथा 1968-69 में यह कम होकर 11.2% हो गया। 1973-74 में यह दर 13.8% अनुमानित की गई थी। बचत व विनियोजन की उपरोक्त दलों को नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किया गया है¹—

वर्ष	बचत राष्ट्रीय आय का (प्रतिशत)	विनियोजन राष्ट्रीय आय का (प्रतिशत)
1950-51	—	5.6
1951-52	5.3	—
1955-56	7.5	7.3
1960-61	8.5	11.7
1965-66	10.6	13.0
1968-69	8.8	11.2
1973-74	13.2	13.8 (अनुमानित)

सितम्बर, 1972 की योजना के अंक में भी प्रचलित मूल्य-दर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के प्रतिशत के रूप में बचत और विनियोग की दरें प्रकाशित हुई थीं, वे निम्न प्रकार हैं²—

बचत और विनियोग की दरें

प्रचलित मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत

वर्ष	विनियोग	देशी बचत	विदेशी बचत
1960-61	12.0	8.9	3.1
1965-66	13.4	11.1	2.3
1966-67	12.2	9.0	3.2
1967-68	10.6	7.9	2.7
1968-69	9.5	8.4	1.1
1969-70	9.2	8.4	0.8
1970-71	9.6	8.3	1.3

1. पंचवर्षीय योजनाएँ
2. योजना (सितम्बर, 1972)

तालिका से स्पष्ट है कि 1960-61 अर्थात् द्वितीय योजना के अन्तिम वर्ष में विनियोग दर 12.0% तक पहुँच चुकी थी, जो 1965-66 अर्थात् तृतीय योजना के अन्तिम वर्ष तक बढ़कर 13.4% हो गई। किन्तु इसके बाद विनियोग दर बजाए बढ़ने के घटती ही चली गई और 1969-70 में यह निम्न स्तर 9.2% तक गिर गई। विनियोग दर में कमी का प्रमुख कारण बचत दर में गिरावट है। 1965-66 में बचत दर अपने चरम स्तर 11.1% तक पहुँच गई। योजना आयोग का अनुमान था कि 1968-69 में विनियोग-दर 10.0% तक बढ़ेगी और 1973-74 तक 13.1% तक पहुँच जाएगी।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने भी भारत में बचत की स्थिति का अध्ययन किया है। इस अध्ययन के अनुसार बचत आय-अनुपात 1951-52 में 5.1% और 1955-56 में 9.1% था। 1951-52 से 1958-59 तक देश की औसत-बचत आय-अनुपात 7.2% रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह अनुपात 6.6% और द्वितीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में 7.9% रहा है। इस प्रकार यदि इस दृष्टि से विचार करें तो बचत-अनुपात आशाप्रद है किन्तु सीमान्त बचत आय अनुपात की दृष्टि से विचार करें तो भिन्न स्थिति प्रकट होती है। उदाहरणार्थ 1953-54 से 1955-56 की अवधि में सीमान्त-बचत आय अनुपात (Marginal Saving-Income Ratio) 19.1 था जो 1956-57 से 1958-59 तक की अवधि में घट कर 14.2% रह गया। इस प्रकार कुल बचत में वृद्धि हुई किन्तु बड़ी हुई आय के अनुपात में बचतों में वृद्धि नहीं हुई है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बचत अनुपात को 1955-56 के 7.3% से बढ़ाकर 11.0% करने का लक्ष्य रखा गया था। यह लक्ष्य कुछ महत्वाकांक्षी था किन्तु जैसा कि प्रो. शितार्थ ने पहले ही कह दिया था कि इस योजनावधि में घरेलू बचत के उक्त लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकी। तृतीय योजना में विनियोजन की राशि को राष्ट्रीय आय 11.0% से बढ़ाकर 14% से 15% करने का लक्ष्य रखा गया था और उसके लिए घरेलू बचत को 8.5% से बढ़ा कर 11.5% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1965-66 में बचत की दर 10.4% रही जो अगले वर्ष अर्थात् 1967-68 में इसमें और कमी आई। योजना आयोग के अनुसार 1967-68 में बचत की दर राष्ट्रीय आय का 8% थी। परन्तु इसमें फिर से वृद्धि होने लगी है। 1968-69 में यह 9% थी।

विनियोग का क्षेत्रीय आवंटन

अर्थ-व्यवस्था के कृषि, उद्योग, संचार आदि सेवा-क्षेत्रों में भारत की विभिन्न योजनाओं में परिकल्पित विनियोग किस प्रकार आवंटित हुआ है, तथा सांख्यिक क्षेत्र की इस दिशा में सापेक्ष भूमिकाएँ क्या रही हैं, उसका विश्लेषण विख्यात अर्थशास्त्री विल्फ्रेड मेलनबाम (Wilfred Malenbaum) द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सांख्यिकी अंकों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है—

महत्वपूर्ण अंक—भारत की विकास योजनाएँ¹
(Important Number—India's Plans for Development, 1951-71)

मद	प्रथम योजना (1951-56)	द्वितीय योजना (1956-61)	तृतीय योजना (1961-66)	चतुर्थ योजना प्रारूप (1966-71)
10 कुल शुद्ध विनियोग (करोड़ रु)	3500	100%	6200	100%
11 कृषि (सिंचाई सहित)	875	25	1180	19
12 बड़े उद्योग (शक्ति व खनन सहित)	805	23	1810	29
13 अन्य छोटे उद्योग	175	5	270	4
14 यातायात संचार	775	22	1360	22
15 अन्य	870	25	1580	26
20 सार्वजनिक/कुल विनियोग अनुपात	53%	61/	61/	64/.
30 रोजगार				
31 प्रतिरिक्त (मिलियन व्यक्ति)	उपलब्ध नहीं	96	14	19
32 थम शक्ति	9	12	17	23

मद	प्रथम योजना (1951-56)	द्वितीय योजना (1956-61)	तृतीय योजना (1961-66)	चतुर्थ योजना प्रारूप (1966-71)
40 राष्ट्रीय आय शुद्ध (करोड़ रु०)				
41 नियोजन से पूर्व का वर्ष	8870	10800	14140	15930
42 गत योजना वर्ष	10000	13480	18460	23900
43 वृद्धि (/)	112 /	250 /	340 /	500 /
50 औसत शुद्ध विनियोग (राष्ट्रीय आय का अनुपात)	74 /	102 /	128 /	214 /
60 औसत घरेलू वचतें (राष्ट्रीय आय का अनुपात)	57 /	81 /	98 /	150 /
70 शुद्ध आयत/शुद्ध विनियोग	210 /	180 /	250 /	320 /
80 सीमा त पूँजी/प्रदा अनुपात	31	23	24	27
90 चोक मूल्य स्तर (1952-53=100)				
91 वास्तविक औसत	103.4	108.1	142.8	205.2 (1966-69)
92 योजनाओं में प्रयुक्त औसत	104.0 (1948-49)	100.1 (1952-53)	127.5 (1960-61)	186.1 (तक 1966)

दी गई सारणी से स्पष्ट है कि योजनाओं में आवश्यक विनियोग की वृद्धि वास्तविक अंको में (In real terms) सारणी की पंक्ति 10 में प्रदर्शित कुल विनियोग दर से बहुत कम रही है। तृतीय योजना में द्वितीय योजना की अपेक्षा 70% अधिक विनियोग की आवश्यकता परिकल्पित की गई है, और ड्रॉपट चतुर्थ योजना (1966) में तृतीय योजना से दुगुनी मात्रा में विनियोग के अनुमान लगाए गए हैं। मुख्य स्तर में विस्तार के समायोजनों के पश्चात् भी इन योजनाओं के लिए निर्धारित विनियोग में 30 से 40% तक की वृद्धि अनुमानित की गई है। महत्त्वपूर्ण तथ्य वास्तविक तथा नियोजित कुल विनियोग राशि के अंतर (Gap) पर कीमती का प्रभाव है। सारणी की 91 व 92 पंक्तियों में दिए गए कीमत अनुपातों पर आधारित अंकों को एक उदाहरण के रूप में देखने पर तृतीय योजना में नियोजित 10,400 करोड़ रु. की विनियोग दर की पूर्ति लगभग 11,500 करोड़ रु. के विनियोगों द्वारा ही की जा सकती है।

जहाँ तक विनियोग के क्षेत्रीय आवंटन का प्रश्न है, सारणी की पंक्तियाँ 11 से 15 विनियोग के क्षेत्रीय आवंटन में एकरूपीय प्रवृत्ति (Consistency) प्रदर्शित करती हैं। कृषि में कुल विनियोग का अनुपात उत्तरोत्तर कम होता गया है जब कि उद्योग में यह अनुपात बढ़ता गया है। तृतीय योजना में अर्थव्यवस्था के इन दोनों मूल-क्षेत्रों के लिए कुल विनियोग का 55% निर्धारित किया गया। इसमें से उद्योग का अनुपात कृषि की अपेक्षा 75% अधिक रहा। यातायात और संचार के विनियोग में अनुपात द्वितीय योजना की तुलना में तृतीय योजना में 22% से घट कर केवल 17% रह गया। सेवा-क्षेत्र का विनियोग 47% के स्थान पर 41% रह गया किन्तु सरकारी सेवा व वस्तु-वितरण सम्बन्धी सेवाओं के लिए विनियोग के अनुपात में निरन्तर वृद्धि होती गई।

सारणी पंक्ति 10-15 में दिए गए विनियोग के अंकड़ों में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र सम्मिलित हैं, दोनों क्षेत्रों का अन्तर भारत की विकास नीतियों पर प्रकाश डालता है। पंक्ति 20 में सार्वजनिक क्षेत्र के बढ़ते हुए सापेक्ष महत्त्व को देखा जा सकता है। 1951-56 में सार्वजनिक क्षेत्र का जो प्रतिशत 53 था वह घट कर 1966-71 में 64 प्रतिशत हो गया। अर्थात् सारणी में कृषि, उद्योग, सेवा आदि क्षेत्रों में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की सापेक्ष स्थिति को प्रदर्शित किया गया है—

नियोजित विनियोग का विवरण

(Planned Investment Allocations)

मद	प्रथम सावजनिक	(1951 56) निजी	योग	द्वितीय (1956 61) सावजनिक	निजी	योग	तृतीय (1961 66) सावजनिक	निजी	योग	चतुर्थ (1966-71) सावजनिक	निजी	योग
10 शुद्ध विनियोग (करोड़ ₹)	1850	1650	3500	3800	2400	6200	6300	4100	10400	13600	7750	21350
11 कृषि (सिंचाई सहित)	525	350	875	780	400	1180	1310	800	2110	2539	900	3439
12 शरा उद्योग (कृषि व खनन सहित)	380	425	805	1190	620	1810	2532	1100	3632	5966	2400	8366
13 अन्य छोटे उद्योग	25	150	175	120	150	270	150	275	425	230	230	550
14 यातायात व संचार	650	125	775	1235	125	1360	1486	250	1736	3010	630	3640
15 अन्य	270	600	870	475	1105	1580	822	1675	2497	1855	3509	5305

विकास-दर (Growth Rate)

यद्यपि विकास-दर का निर्धारण आर्थिक दृष्टि से सांख्यिकी अंको पर निर्भर करता है तथापि व्यावहारिक रूप में इस दर का निर्धारण मूलतः एक राजनीतिक निर्णय है, अथवा यह निर्णय देश की जन-धारणा के अनुसार लिया जाता है। किस गति के साथ एक देश के निवासी अपनी प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना चाहते हैं अथवा गरीबी-उन्मूलन की आकांक्षा रखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर उस देश की जन धारणा अथवा राजनेताओं से सम्बन्धित है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, इसकी प्रत्येक योजना के साथ प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने का प्रश्न जुड़ा रहा है। भारत की प्रत्येक योजना के मूल में यह प्रश्न अन्तर्निहित है कि कितने वर्षों में इस देश को अपनी प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना आवश्यक है। यह प्रश्न आज भी निरुत्तर है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 600 रु से कुछ अधिक है, जबकि अमेरिका की प्रति व्यक्ति 4000 डॉलर पर विचार किया जा सकता है, अर्थात् हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की तुलना में लगभग 1/50वाँ भाग है। इसी पृष्ठभूमि में भारत की योजनाओं में नियोजित नया वास्तव में प्राप्त विकास-दरों का अध्ययन किया जा सकता है। E C A F E साहित्य में प्रति व्यक्ति आय के दुगुना होने सम्बन्धी एक दिलचस्प सारणी प्रस्तुत की गई है, जिसका एक अर्थ निम्न प्रकार है—

विकास-दर	जनसंख्या-वृद्धि-दर	प्रति व्यक्ति विकास-दर	अवधि जिसमें यह दुगुनी होता है
4½%	2½%	2%	35 वर्ष
5½%	2½%	3%	23 वर्ष
3½%	2½%	1%	70 वर्ष

यदि प्रति व्यक्ति आय 3% की दर से बढ़ती है तो इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीय आय 5½% की दर से बढ़ रही है। यह वह विकास-दर है जिसकी चतुर्थ योजना में परिकल्पना की गई थी। इस दर के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 23 वर्ष में दुगुनी हो सकती है। विकास की यह दर विशेष महत्वाकांक्षी नहीं है क्योंकि इस दर से भी हम अपनी प्रति व्यक्ति आय को 23 से 25 वर्ष की अवधि में दुगुना कर सकेंगे। पूर्व-योजनाओं की उपलब्धियों को देखने पर तो इस दर को भी स्थिर बनाए रखना असम्भव प्रतीत होता है, क्योंकि प्रथम योजना में प्रति व्यक्ति विकास-दर 1%, द्वितीय में 1.7% और तृतीय में केवल 0.4% रही है। 18-19 वर्ष की दीर्घावधि में भी प्रति व्यक्ति अधिकतम विकास-दर हम केवल 1.7% प्राप्त कर सके, जिसे भी स्थायी नहीं रखा जा सका। इस स्थिति में जब तक परिवार-नियोजक किसी प्रकार का कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं तब तक 5 से 5½% विकास दर को प्राप्त करना और उसे स्थायी बनाए रखना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। यदि हम प्रथम तीन योजनाओं में अधिकतम प्राप्त 1.7% की विकास-दर को भी स्थिर रखें

पाते हैं तब भी हम 46½ वर्षों में अपनी प्रति व्यक्ति आय को दुगुना कर सके। इसका यह अर्थ है कि सन् 2016 में हम इस स्थिति को प्राप्त कर पाएँगे। इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए 4% विकास दर सम्भव व प्राप्ति योग्य प्रतीत होती है तथा 5 या 5½% विकास दर का प्राप्त किया जाना उच्च उपलब्धि की श्रेणी में आएगा। विकास दर के अनुभागों के रूप में कतिपय वृद्धि सूचक अंकों को ध्यान में रखना आवश्यक है जो आगे दिये जा रहे हैं।

वृद्धि सूचक अंक

1950-51 से 1970-71 तक भारत की आय वृद्धि दर का अनुमान वई सूचको से लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आय की दर में 36% वृद्धि हुई जबकि कृषि उत्पादन व औद्योगिक उत्पादन में क्रमशः 32 / और 64 / की वार्षिक दर से वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय के रूप में राष्ट्रीय आय में 15 / प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई है जबकि अनाज के उत्पादन में 14 / वार्षिक वृद्धि हुई। प्रति हेक्टर अनाज के उत्पादन में 19 / की वार्षिक दर से वृद्धि हुई। बचत आय अनुपात 57 / से बढ़ कर 100 / अर्थात् लगभग दुगुना हो गया। प्रथम तीन योजनाओं में हुई विकास दर का संक्षेप में पहले ही विवेचन किया जा चुका है। इन योजनाओं के अनुभवों के आधार पर निम्न चतुर्थ एवं पंचम पंचवर्षीय योजनाओं में विकास दरों का विश्लेषण आगे प्रस्तुत किया जा रहा है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की आय वृद्धि दर

चौथी योजना में विकास की वार्षिक चक्रवृद्धि दर का लक्ष्य 55 / से अधिक अर्थात् लगभग 56 / था जब कि 1969-70 में अव्यवस्था की वृद्धि दर 53 / व 1970-71 में 48 / रही। इस प्रकार अर्थ व्यवस्था की औसत वार्षिक चक्रवृद्धि दर योजना में प्रस्तावित लक्ष्य की तुलना में केवल 5 / ही रही।

कृषि में 5 / वार्षिक दर निर्धारित की गई थी पर वास्तविक वृद्धि दर 1969-70 में 51 / और 1970-71 में 53% रही। इस प्रकार कुल मिलाकर कृषि क्षेत्र की उपलब्धि लक्ष्यों के अनुरूप रही।

खनन और विनिर्माण (Mining and Manufacturing) में 77% वृद्धि का प्रावधान था लेकिन 1969-70 में 5% और 32% की ही वृद्धि हुई। इस प्रकार दोनों वर्षों की औसत वृद्धि दर 41% रही।

बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन का लक्ष्य 93% था किंतु वार्षिक वृद्धि-शुद्ध मूल्य के रूप में 1969-70 में 59% और 1970-71 में 36% रही। इस प्रकार दो वर्षों की वार्षिक औसत वृद्धि 47% रही।

विद्युत, गैस और जल आपूर्ति क्षेत्र में 95% वृद्धि दर रही और 1970-71 में 79%। इन प्रकार औसत वृद्धि दर 87% रही जो योजना के लक्ष्य 93% से कुछ कम थी।

परिवहन और संचार के क्षेत्र में योजना का 64% वार्षिक वृद्धि का था लेकिन 1969-70 में परिवहन व संचार की वार्षिक वृद्धि 59% रही और 1970-71 में

केवल 3.8% रही। इस प्रकार दो वर्षों की औसत वार्षिक-वृद्धि दर 4.9% रही। अभी मुख्यतः इसलिए हुई कि रेलों में शुद्ध-वृद्धि की दर केवल 0.4% रही।

बैंकिंग और बीमा के क्षेत्र में वृद्धि योजना के अनुमान से अधिक रही। योजना का लक्ष्य 4.7% वार्षिक-वृद्धि का था लेकिन 1969-70 में वास्तविक वृद्धि 9.2% रही और 1970-71 में 8.6% थी। इस प्रकार दो वर्षों के वृद्धि का औसत 8.9% रहा जो कि योजना के वार्षिक-वृद्धि के लक्ष्य से लगभग दुगुना था। संक्षेप में चौथी योजना में परिकल्पित 5.7% की कुल वृद्धि-दर की तुलना में अर्थव्यवस्था में 1969-70 में वृद्धि-दर 5.2% रही। इसके बाद 1970-71 में यह घट कर 4.2% और 1972-73 में 0.6% रह गई। आवश्यकताओं को देखते हुए चौथी योजना की अवधि की वृद्धि-दर बहुत कम और अपर्याप्त रही। पाँचवी योजना में 5.5% की वृद्धि-दर का लक्ष्य रखा गया है।

पाँचवी पंचवर्षीय योजना की वृद्धि-दर

चौथी योजना का लाभ उठाते हुए, पाँचवी योजना में 5.5% की वृद्धि-दर का जो लक्ष्य रखा गया है, उसके लिए आयोजन और प्रमेल में कहीं अधिक कुशलता के अतिरिक्त कठिन निर्णयों, कठोर अनुशासन और बहुत त्याग की आवश्यकता होगी।

पाँचवी योजना के इस 5.5% की वृद्धि-दर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए (क) पहले से अधिक पूँजी-निवेश, (ख) अधिक कुशलता, (ग) पहले से अधिक बचत, आमदनी की प्रसमानताएँ दूर करने और उपभोग को इस ढंग से घटाने की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे समृद्ध वर्गों पर अधिकाधिक बचत करने का भार पड़े।

योजना के लक्ष्य का इस ढंग से विकास करना है कि मुद्रा-स्फीति न होने पाए। कुछ क्षेत्रों जैसे इस्पात, कोयला, लोह-धातुएँ, सीमेंट और उर्वरक, उद्योगों में पूँजी बहुत उद्योगों के विकास के लिए तो पूँजी जुटाना अनिवार्य है ही क्योंकि इससे ऐसी वस्तुओं का उत्पादन होता है जो रोजगार देने वाली है और जिनका कृषि में बहुत इस्तेमाल हो रहा है। इसी प्रकार उन क्षेत्रों पर भी अकुश रखना होगा जो न तो आदमी के उपभोग की वस्तुओं में आते हैं और न ही जिनसे निर्यात-वृद्धि में सहायता मिलती है। मुद्रा-स्फीति के बिना विकास करने की नीति के अनुसार दीर्घ अवधि में और उत्पादधि में फल देने वाली परियोजनाओं का सन्तुलित मेल रखने और रोजगार देने वाले माल तैयार करने के उद्योगों और परमावश्यक मध्यवर्ती वस्तुएँ व पूँजीगत सामान बनाने वाले उद्योगों में लगाई जाने वाली पूँजी का भी सन्तुलित और उचित वितरण आवश्यक है।

भारत के विकास की स्थिति के सिंहावलोकन के लिए राष्ट्रीय उत्पादन में वास्तविक वृद्धि तथा उत्पादन के तीन मुख्य क्षेत्रों—कृषि-उद्योग, व्यापार तथा संचार के उत्पादन के अंशों को एक सारणी में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम तीन योजनाओं में वृद्धि के निर्धारित लक्ष्य 11.2%, 25% व 34% थे। लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि का प्रतिशत क्रमशः 18, 21 व 13 रहा। प्रथम योजना को छोड़ कर अन्य योजनाओं में प्राप्त वृद्धि-दर से कम रही।

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन : कुल और बड़े मूल उत्पादन क्षेत्रों
(Net National Product : Total and Major Originating Sectors)

वर्ष (1)	जनसंख्या (2)	एन एन पी राष्ट्रीय आय (3)	हफि (4)	उद्योग (5)	व्यापार व संचार (6)
	सूचकांक	योग	योग	योग	योग
1950-51	100	9325	5150	610	2510
1951-52	101.7	9400	5250	640	2620
1952-53	103.5	9775	5410	660	2715
1953-54	105.4	10325	5875	685	2790
1954-55	107.4	10625	5925	735	2890
1955-56	109.5	11000	5960	825	3020
	सूचकांक	योग	योग	योग	योग
1950-51	100	100	100	100	100
1951-52	102	102	102	105	104
1952-53	105	105	105	108	108
1953-54	111	111	114	112	111
1954-55	114	114	115	120	115
1955-56	118	118	116	135	120
घोषित विकास दर					
प्रथम योजना	(1.7%)	(3.4%)	(3.0%)	(6.2%)	(3.7%)
1956-57	111.7	11550	6125	895	3190
1957-58	114.0	11450	5925	945	3300
1958-59	116.4	12300	6450	970	3460
1959-60	118.7	12475	6375	1040	3640
1960-61	121.5	13294	6857	1215	3870

वर्ष (1)	जनसंख्या (2)	एन एन पी राष्ट्रीय आय (3)	कृषि (4)	रस्दों (5)	व्यापार व संचार (6)
श्रीमत् विकास दर द्वितीय योजना	(2.1%)	(3.9%)	(2.8%)	(8.1%)	(5.1%)
1961-62	124.1	13763	6925	1320	4070
1962-63	127.2	14045	6747	1463	4280
1963-64	130.3	14845	6940	1610	4570
1964-65	133.5	15917	7558	1723	4880
1965-66	136.9	15021	6520	1777	5130
श्रीमत् विकास दर तृतीय योजना	(2.2%)	(2.2%)	(-0.9%)	(7.9%)	(5.8%)
1966-67	140.0	15123	6442	1794	5265
1967-68	143.5	16583	7629	1799	5453
1968-69	147.0	16943	7558	1899	5700
श्रीमत् विकास दर एन वपीय योजनाएँ	(2.5%)	(4.1%)	(5.0%)	(2.2%)	(3.6%)

सारणी में जनसंख्या के वृद्धि-सूचकांक और औसत विकास-दर को प्रदर्शित किया गया है, जो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं तथा एक वर्षीय योजनाओं में क्रमशः 1.7 /, 2.1 /, 2.2 / व 2.5 / रही। निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या भारत की आर्थिक प्रगति में बड़ी बाधक है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का वृद्धि-सूचकांक सारणी के तीसरे खाने में प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रदर्शित अंकों से स्पष्ट है कि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय उत्पादन की औसत वृद्धि दर अधिक रही, किन्तु तीसरी योजना में यह बहुत कम हो गई, किन्तु पुनः एकवर्षीय योजनाओं में 2.2 / से बढ़ कर 4.1 / हो गई। यह एक अच्छी स्थिति का संकेत थी। सारणी के शेष खानों में अर्थ व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों—कृषि उद्योग तथा व्यापार-संचार आदि की विकास-दरों को दर्शाया गया है। कृषि की विकास-दर तीसरी योजना तक निरन्तर गिरती गई। प्रथम योजना में यह दर जो 3.0% थी, द्वितीय योजना में 2.8 / रह गई और तीसरी योजना में तो इसका प्रतिशत ऋणात्मक (—0.9 /) हो गया, किन्तु एकवर्षीय योजनाओं में यह पुनः बढ़ कर 5 / हो गई। दूसरी ओर उद्योग के क्षेत्र में विकास-दर द्वितीय योजना के बाद गिरती गई। द्वितीय योजना में यह दर 8.1% थी जो घटकर तीसरी योजना में 7.9% और एकवर्षीय योजनाओं में केवल 2.2% रह गई। यह चिन्ताजनक स्थिति का संकेत थी जिसमें सुधार के लिए औद्योगिक उत्पादन की दर को बढ़ाना अनावश्यक था। व्यापार व संचार के क्षेत्र में प्रगति का सूचकांक सन्तोषप्रद स्थिति को प्रकट करता है।

प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाएँ-क्षेत्रीय लक्ष्य, वित्तीय आवंटन तथा उपलब्धियाँ

(First Three Five Year Plans—Sectoral Targets, Financial Allocation and Achievements)

योजनाओं के उद्देश्यों को जब सरयात्मक स्वरूप प्रदान किया जाता है तब उद्देश्य बन जाते हैं। किसी ग्रंथ-व्यवस्था के कृषि, उद्योग, परिवहन तथा भवार आदि क्षेत्रों से सम्बन्धित विकास लक्ष्य (Growth Targets) को क्षेत्रीय लक्ष्य (Sectoral Targets) कहते हैं। इन लक्ष्यों के अन्तर्गत मूलतः क्षेत्रों से सम्बन्धित भौतिक उत्पादन के लक्ष्य, क्षेत्रीय विकास दर, वित्तीय परिव्यय आदि लिए जाते हैं। भारतीय ग्रंथ-व्यवस्था को आधिक नियोजन के सन्दर्भ में कृषि, शक्ति, खनिज उद्योग, परिवहन तथा संचार, सामाजिक सेवाएँ आदि क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है।

योजनाओं में वित्तीय आवंटन (Financial Allocation in the Plans)

योजनाओं में विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित निर्धारित विकास-लक्ष्यों तथा इनकी उपलब्धियों के विश्लेषण से पूर्व यह उपमुक्त होगा कि इन क्षेत्रों पर आवंटित परिव्यय तथा इन परिव्यय की वित्त-व्यवस्था को जान लिया जाए। इस सदर्भ में सर्वप्रथम हम विभिन्न सारणियों द्वारा विनियोग, परिव्यय एवं वित्त-व्यवस्था को स्पष्ट करेंगे। प्रथम तीन योजनाओं में विनियोग

सारणी-1 में दिए गए विनियोग के अंकों से सरकारी और निजी क्षेत्र के विस्तार की सापेक्ष स्थिति स्पष्ट होती है। निरपेक्ष रूप में यद्यपि दोनों ही क्षेत्रों में विनियोग दर में काफी वृद्धि हुई किन्तु दोनों क्षेत्रों का अनुपात प्रथम तीन योजनाओं में क्रमशः लगभग 15 18 37 31 तथा 71 49 रहा। इन अनुपातों से स्पष्ट है कि उत्तरोत्तर निजी क्षेत्र की तुलना में सरकारी क्षेत्र का अधिक विस्तार हुआ। यह स्थिति देश के समाजवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है।

सारणी-1

तीन योजनाओं में सरकारी और निजी क्षेत्र में विनियोग

(करोड़ रु में)

योजना	सरकारी क्षेत्र का परिव्यय			निजी क्षेत्र में		
	योजना प्रावधान	वास्तविक व्यय	चालू व्यय	विनियोग	विनियोग	योजना का कुल व्यय
प्रथम पंचवर्षीय योजना	2,356	1,960	400	1,560	1,800	3,760
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	4,800	4,672	941	3,731	3,100	7,772
तृतीय पंचवर्षीय योजना	7,500	8,577	1,448	7,129	4,190	12,767

तीन योजनाओं के परिचय

सारणी-2 में योजनाओं के वास्तविक सार्वजनिक परिचय (Outlay) को दर्शाया गया है। योजना-परिचय में राज्य व केन्द्र के भाग को पृथक् पृथक् रखा गया है तथा कुल परिचय का विभिन्न प्राधिक क्षेत्रों पर आवंटन तथा कोष्ठकों में राशि के आवंटन का प्रतिशत दर्शाया गया है—

सारणी-2

प्रथम तीन योजनाओं में सरकारी क्षेत्र का परिचय

(करोड़ रु में)

विकास की मंड	प्रथम पंचवर्षीय योजना		द्वितीय पंचवर्षीय योजना		तृतीय पंचवर्षीय योजना		
	योग	केन्द्र*	राज्य	योग	केन्द्र	राज्य	योग
1 कृषि और सम्पन्न क्षेत्र	290 (148) 434 (222)	53 (97) 55 (128)	496 (903) 375 (872)	549 (117) 430 (92)	117. (107) 10 (15)	972 (89.3) 655 (98.5)	1089 (127) 665 (78)
2 सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	149 (7.6)	28 (6.2)	424 (93.8)	452 (9.7)	113 (90)	1139 (910)	1252 (146)
3 बिजुल	62 (2.1)	106 (56.7)	81 (4.3)	187 (40)	203 (103)	241 (28)	241 (28)
4 गाँव और लघु उद्योग							
5 खनिज और उद्योग	55 (28)	898 (95.7)	40 (4.3)	938 (201)	1764 (897)		1726 (201)

विकास की मद	प्रथम पंचवर्षीय योजना	द्वितीय पंचवर्षीय योजना		तृतीय पंचवर्षीय योजना	
	योग	केन्द्र	राज्य	योग	केन्द्र
6 यातायात और संचार	518 (264)	1092 (866)	169 (134)	1261 (270)	1818 (861)
7 अन्य	472 (241)	357 (418)	498 (58.2)	855 (18.3)	590 (39.6)
जिसमें					
(अ) शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान	149 (76)	—	—	273 (58)	—
(ब) स्वास्थ्य	98 (50)	—	—	216 (46)	—
(स) परिवार नियोजन					
					660 (7.7)
					226 (2.6)
					25 (0.3)
योग	1960 (100.0)	2589 (55.4)	2083 (46)	4672 (100.0)	4412 (51.4)
					4165 (48.6)
					8577 (100.0)

* स्रोत जाँचें। जिस हद तक राज्य के हितों से कुछ का परिणाम 4600 करोड़ रुपये (जो बाद में संशोधित कर 4672 करोड़ रुपये कर दिया गया और जिसके लिए केन्द्र और राज्य वार स्वीकारा उपलब्ध नहीं है) से है उस हद तक केन्द्र का परिणाम अधिक हो सकता है। केन्द्र और राज्य मंत्री (कासमी) के बीच चर्चा के लिए गए आँकड़े सम्बद्ध लेखों में परिणाम का प्रतिफल बताते हैं।

Source : India 1913 & 1974

योजना-परिणाम की वित्त-व्यवस्था

विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए आवश्यक परिणाम के वित्तीय सम्बन्ध सारणी-3 से स्पष्ट हैं—

सारणी-3

सरकारी क्षेत्र में योजना परिवर्धन की वित्त-व्यवस्था

(करोड़ रु में)

मद	प्रथम पंचवर्षीय योजना		द्वितीय पंचवर्षीय योजना		तृतीय पंचवर्षीय योजना	
	आरम्भिक अनुमान	वास्तविक	आरम्भिक अनुमान	वास्तविक	आरम्भिक अनुमान	वास्तविक
1. मुख्यतया अपने साधनों से	740 (357)	725 (384)	1350 (281)	1230 (263)	2810 (375)	2908 (339)
(1) कराधान की योजना पूर्व दरों पर चाय राजस्व से बचत	570	382	350	11	550	419
(2) अतिरिक्त कराधान, जिसमें सार्वजनिक उद्यमों की बचत बढ़ाने के उपाय शामिल हैं	घ	255ब	850ब	1052ब	1710	2892
(3) रिजर्व बैंक से लाभ	—	—	—	—	—	—
(4) योजना के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए उठाए गए उपायों से हुई आय को छोड़कर सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की बचत	170ई फ	115ई फ	150ई फ	167ई फ	100 650	62 373
(क) रेल (ख) अन्य						

मह	प्रथम पंचवर्षीय योजना		द्वितीय पंचवर्षीय योजना		तृतीय पंचवर्षीय योजना	
	आरम्भिक अनुमान	वास्तविक	आरम्भिक अनुमान	वास्तविक	आरम्भिक अनुमान	वास्तविक
2. मुख्यतया घरेलू ऋणों के जरिए						
(1) सार्वजनिक ऋण, बाजार और जीवन बीमा निगम से सरकारी उद्यमों द्वारा लिए गए ऋणों सहित शुद्ध	808 (39.1)	1019 (52.0)	2650 (55.2)	2393 (51.2)	2490 (33.9)	3246 (37.9)
(2) छोटी बचतें	115ह	208ह	700ह	756ह	800	823
(3) वापिसी जमा, प्रतिवार्य जमा, इनामी बॉन्ड और स्वर्ण बोंड	225	243	500	422	600	565
(4) राज्य भविष्य निधियों के	—	—	—	—	—	117
(5) इस्पात सभाकेरए निधि (शुद्ध)	45	92	250	175ज	265	336
(6) विविध पूंजीगत प्राप्तियों (शुद्ध)	—	—	—	40	105	34
(7) घाटे का वित्त इ	133	147	—	46	170	238
3. कुल घरेलू साधन (1+2)	290	333	1200	954	550	1133
	1546 (74.8)	1771 (90.4)	4000 (83.3)	3623 (77.5)	5300 (70.7)	6154 (71.8)

मद	प्रथम पंचवर्षीय योजना		द्वितीय पंचवर्षीय योजना		तृतीय पंचवर्षीय योजना	
	आरम्भिक अनुमान	वार्षिक	आरम्भिक अनुमान	वार्षिक	आरम्भिक अनुमान	वार्षिक
4. विदेशी सहायता न	521 (25.2)	189 (96)	800 (167)	1049 (22.5)	2200 (29.3)	2423 (28.2)
5. कुल साधन (3+4)	2069 (100.0)	1960 (100.0)	4800 (100.0)	4672 (100.0)	7500 (100.0)	8577 (100.0)

नोट—काष्ठों में दिए गए आँकड़े कुल के प्रतिशत हैं।

(घ) मद 1 (1) और 1 (4) के अन्तर्गत शामिल। (व) रेल किराए और भाड़े में वृद्धि से हुई आय भी छोड़कर। (ई) रेल किराए और भाड़े में हुई वृद्धि से आय समेत। (फ) मद 1 (1) और 2 (6) के अन्तर्गत शामिल। (ह) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा बाजार से ऋण (र) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा भी एल 480 कोषों का निवेश शामिल है (क) प्रथम और द्वितीय योजनाओं के आँकड़े प्रतिशत हैं। (ड) तृतीय योजना अवधि और उसके बाद के लिए दर्शाए गए घाटे के विस्तार के आँकड़े सरकारी की रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के प्रति ऋण (दीर्घावधि और लघु अवधि दोनों) में परिवर्तन को दर्शाते हैं। पूर्व योजनाओं के लिए ये घाटे के बजट की ओर संकेत हैं। प्रथम और द्वितीय योजना अवधियों में घाटे का वित्त क्रमशः 260 करोड़ रु और 1,170 करोड़ रुपये था। (घ) राज्य सविषय निधियों से भिन्न बिना खर्च किए गए ऋण शामिल है। (न) नई विनियम-दर के अनुसार।

प्रथम योजना का परिव्यय तथा वित्त व्यवस्था

सारणी-2 (परिव्यय 2) के अनुसार प्रथम योजना पर सरकारी क्षेत्र में 1960 करोड़ रु की राशि व्यय की गई। सारणी में दिए गए व्यय के आवंटन से स्पष्ट है कि इस योजना में कृषि को सर्वाधिक महत्त्व मिला क्योंकि योजना की कुल राशि का 37% भाग कृषि, सिंचाई और बाढ़-नियन्त्रण पर व्यय किया गया। योजना में शक्ति, परिवहन तथा संचार को भी आवश्यक महत्त्व दिया गया, जो इन मदों पर व्यय के क्रमशः 76% और 26.4% से परिलक्षित होता है। शक्ति तथा परिवहन व संचार को दी गई प्राथमिकता का उद्देश्य भावी विकास के लिए आधार-ढाँचे (Infra-structure) का निर्माण करना था। सभी प्रकार के उद्योगों व खनिजों पर कुल व्यय का बेटल 49% ही व्यय किया गया। शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान तथा स्वास्थ्य पर कुल राशि का क्रमशः 76% व 5% व्यय हुआ। इन मदों पर व्यय का यह प्रतिशत यह प्रदर्शित करता है कि नियोजकों का इस योजना में शिक्षा व स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं के विस्तार की ओर भी यथेष्ट ध्यान रहा।

1960 करोड़ रु के व्यय की वित्तीय-व्यवस्था के लिए निजी साधनों से 752 करोड़ रु, घरेलू ऋणों से 1010 करोड़ रु तथा विदेशी सहायता से 189 करोड़ रु प्राप्त किए गए। प्रतिशत के रूप में इन मदों का कुल राशि में योगदान क्रमशः 38.4%, 52% तथा 9.6% रहा। घरेलू ऋणों की मद में घाटे के वित्त के 333 करोड़ रु भी सम्मिलित हैं। प्रथम योजना के अन्तिम वर्षों में घाटे की वित्त-व्यवस्था का अधिक तेजी से उपयोग किया गया किन्तु योजना की अवधि के दौरान उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने के कारण मूल्य-स्तर योजना की पूर्व अवधि की तुलना में 13% कम रहा तथा भुगतान समुल्लन की स्थिति भी अनुकूल रही।

द्वितीय योजना का परिव्यय तथा वित्त-व्यवस्था

द्वितीय योजना के लिए 4,800 करोड़ रु के व्यय का लक्ष्य रखा गया किन्तु वास्तव में कुल व्यय 4,672 करोड़ रु हुआ, जिसमें से राज्यों ने 2,589 करोड़ रु तथा केन्द्र ने 2,083 करोड़ रु व्यय किए। 4,800 करोड़ रु की प्रस्तावित राशि का कृषि व सामुदायिक विकास के लिए 11.8%, सिंचाई के लिए 7.9%, शक्ति के लिए 8.9%, बाढ़-नियन्त्रण व ग्रन्थ परियोजनाओं के लिए 2.2%, उद्योग व खनिज के लिए 18.5%, परिवहन व संचार के लिए 28.9%, सामाजिक सेवाओं के लिए 19.7% तथा शेष 2.1% विविध कार्यों के लिए निर्धारित किया गया। इन मदों पर प्रस्तावित राशि की तुलना में जो राशि वास्तव में व्यय हुई उसे 'परिव्यय सारणी' की कालम मर्यादा पाँच में बताया गया है। प्रस्तावित तथा वास्तविक व्यय प्रतिशतों की तुलना को सारणी-4 में प्रस्तुत किया जा रहा है—

सारणी-4

द्वितीय योजना की मदों पर प्रस्तावित तथा वास्तविक व्यय के प्रतिशत

मद	प्रस्तावित व्यय का प्रतिशत	वास्तविक व्यय का प्रतिशत
1. कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र	11.8	11.7
2. सिंचाई और बाढ़-नियंत्रण	10.1	9.2
3. शक्ति (Power)	8.9	9.7
4. उद्योग व खनिज	18.5	24.1
5. परिवहन व संचार	28.9	27.0
6. सामाजिक सेवाएँ	19.7	10.4
7. अन्य	2.1	7.9
कुल	100.0	100.0

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि उद्योग व खनिज पर प्रस्तावित व्यय से वास्तविक व्यय की राशि अधिक रही तथा सामाजिक सेवाओं पर वास्तविक व्यय की राशि प्रस्तावित व्यय की राशि की तुलना में काफी कम रही। अन्य मदों के प्रतिशत को मिला कर भी सामाजिक सेवाओं के वास्तविक व्यय का प्रतिशत प्रस्तावित व्यय के प्रतिशत से काफी कम रहा है। इस योजना में सर्वाधिक प्राथमिकता यद्यपि उद्योग व खनिज क्षेत्र को दी गई, किन्तु कुल निरपेक्ष-राशि की दृष्टि से कृषि के लिए प्रथम योजना की तुलना में द्वितीय योजना में काफी बड़ी राशि का प्रावधान रखा गया। इसका अभिप्राय है कि उद्योग व खनिज के क्षेत्र पर अत्यधिक बल दिए जाने पर भी कृषि के महत्त्व को इस योजना में पर्याप्त स्थान मिला।

जहाँ तक योजना के परिव्यय की वित्त-व्यवस्था का प्रश्न है, 4,800 करोड़ रु. के प्रस्तावित व्यय के लिए 1,200 करोड़ रु. की राशि का घाटे के वित्त के अन्तर्गत प्रावधान रखा गया तथा 400 करोड़ रु. के घाटा (Uncovered Deficit) के रूप में घरेलू साधनों में वृद्धि के अतिरिक्त उग्रायो द्वारा पूर्ण के लिए छोड़ दिया गया। 800 करोड़ रु. विदेशी सधनों से तथा योजना की शेष 2,400 करोड़ रु. की राशि को कर, जमता से ऋण, रेन व भविष्य-निधि आदि घरेलू साधनों से प्राप्त करने का प्रावधान किया गया। सरकारी क्षेत्र के 4,800 करोड़ रु. के अनिर्दिष्ट 2,400 करोड़ रु. का विनियोग निजी क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया।

तृतीय योजना का परिचय तथा वित्त-व्यवस्था

सारणी—3 के अनुसार तृतीय योजना में सरकारी क्षेत्र के लिए 7,500 करोड़ रुपये तथा निजी क्षेत्र के लिए 4,100 करोड़ रुपये के परिचय का लक्ष्य रखा गया। 7,500 करोड़ रुपये के सरकारी व्यय का विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए निम्न प्रकार आवंटन किया गया—

सारणी—5

तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित सरकारी व्यय का विभिन्न आर्थिक मंदों पर आवंटन

मंदें	प्रस्तावित व्यय (करोड़ रुपये में)	कुल का प्रतिशत
1 कृषि व सामुदायिक विकास	1068	14
2. बड़े व मध्यम सिंचाई के साधन	650	9
3 शक्ति	1012	13
4. ग्रामीण व लघु उद्योग	264	4
5 संगठित उद्योग व खनिज पदार्थ	1520	20
6 परिवहन व संचार	1486	20
7. सामाजिक सेवाएँ व विविध	1300	17
8 इन्वेन्टरीज	200	3
कुल	7500	100

तृतीय पंचवर्षीय योजना के कुल प्रस्तावित व्यय का कृषि, सिंचाई और सामुदायिक विकास के लिए 25% व्यय निर्धारित किया गया। इन मंदों को इस योजना में सर्वाधिक महत्व दिया गया। इस प्राथमिकता का मूल कारण द्वितीय योजना में कृषिगत उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जाना था। इसीलिए इस योजना में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता विशेष रूप से अनुभव की गई। संगठित उद्योगों तथा खनिजों व परिवहन और संचार की मंदों को समान प्राथमिकता प्रदान की गई। इन मंदों में से प्रत्येक के लिए कुल व्यय का 20% व्यय निर्धारित किया गया।

योजना की प्रस्तावित 7,500 करोड़ रुपये की राशि की वित्त-व्यवस्था के लिए चालू राजस्व की बचत से 550 करोड़ रुपये अतिरिक्त कराधान से 1,710

करोड़ रुपये, रेलों से 100 करोड़ रुपये, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से 450 करोड़ रुपये, सार्वजनिक ऋण से 800 करोड़ रुपये, छोटी बचतों से 600 करोड़ रुपये, राज्य की भविष्य निधियों से 265 करोड़ रुपये, इस्पात-समानीकरण निधि से 105 करोड़ रुपये, विविध पूंजीगत प्राप्तियों से 170 करोड़ रुपये, घाटे के वित्त से 550 करोड़ रुपये तथा विदेशी सहायता से 2,200 करोड़ रुपये, प्राप्त करने का प्रावधान रखा गया। इन अंशों को सारणी-3 में तृतीय पंचवर्षीय योजना के शीर्षक के अन्तर्गत आरम्भिक अनुमान वाले कॉलम में दर्शाया गया है।

उपरोक्त वित्तीय मदों की मुख्य विशेषता 1,710 करोड़ रुपये का अतिरिक्त करामान तथा घाटे की वित्त-व्यवस्था की राशि की द्वितीय योजना की तुलना में कम किया जाना है। इसके अतिरिक्त विदेशी सहायता की आवश्यकता को अधिक अनुभव किया गया। इस मद के अन्तर्गत द्वितीय योजना के आरम्भिक अनुमान जहाँ 800 करोड़ रुपये के थे वहाँ इस योजना में इस मद से प्राप्त की जाने वाली राशि 2200 करोड़ रुपये अनुमानित की गई।

उपरोक्त विवेचन के अन्तर्गत सरकार अथवा सार्वजनिक व्यय का ही विश्लेषण किया गया है। सार्वजनिक व्यय के अतिरिक्त भारत की प्रथम तीन योजनाओं में निजी क्षेत्र का जो विनिमय हुआ है उसे सारणी 13.1 में प्रदर्शित किया गया है। इन योजनाओं में निजी क्षेत्र का विनिमय क्रमशः 1,800 करोड़ रुपये 3,100 करोड़ रुपये व 4,190 करोड़ रुपये रहा। इस क्रम में यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में 1960 के कुल व्यय में से 400 करोड़ रुपये चालू व्यय पर खर्च हुए और इस प्रकार सरकारी क्षेत्र का इस योजना में शुद्ध विनिमय 1,560 करोड़ रुपये का हुआ। इसी प्रकार द्वितीय योजना के 4,672 करोड़ रुपये में से चालू व्यय के 941 करोड़ रुपये निकालने पर इस योजना की अवधि में सरकारी क्षेत्र का विनियोग 3,731 करोड़ रु तथा तृतीय योजना में व्यय की वास्तविक राशि 8,577 करोड़ रुपये में से चालू व्यय की 1,448 करोड़ रुपये की राशि निकालने पर इस योजना में सरकारी क्षेत्र का विनियोग 7,129 करोड़ रुपये हुआ।

योजनाओं में क्षेत्रीय लक्ष्य (Sectoral Targets in Plans)

प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं के वित्तीय आवंटन के अन्तर्गत अब हम इस योजनाओं के क्षेत्रीय लक्ष्यों का अध्ययन करेंगे। इन योजनाओं में भारत के आर्थिक विकास की क्या स्थिति रही, विभिन्न आर्थिक मंशों के अन्तर्गत क्या उपलब्धियाँ रही, उत्पादन के प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया जा सका, प्रादि प्रश्नों से सम्बन्धित तथ्यों को कृषिगत तथा औद्योगिक मदों के मन्दर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। सर्वप्रथम कृषिगत मदों के लक्ष्यों तथा इनकी उपलब्धियों को सारणी-6 में दिया जा रहा है।

सारणी-6

चुनी हुई कृषिगत वस्तुओं के उत्पादन-सम्य तथा प्रगति

समय	1950-51	1955-56		1960-61	1965-66	
	वास्तविक	प्रस्तावित सम्य	वास्तविक में प्राप्त सम्य	वास्तविक	प्रस्तावित सम्य	वास्तविक में प्राप्त सम्य
खाद्यान्न (मि टन)	54 92	61 60	69 22	82 0	72 29	72 0
फलहूँ (मि टन)	5 09	7 07	5 63	7 0	10 7	6 3
रत्ता शुद्ध (मि टन)	6 92	6 32	7 29	1 12	13 5	12 0
कपास (मि गांठ)	2 62	4 23	4 03	5 3	8 60	4 8
जूट (मि गांठ)	3 51	5 39	4 48	4 1	4 48	6 5

Source (i) Economic Survey 1969-70 pp 66-67

(ii) Paul Streeten op cit p 32.

प्रथम योजनाकाल में कृषि उत्पादन में वृद्धि कृषिगत भूमि के क्षेत्रफल में विस्तार करके आ गई। किन्तु द्वितीय योजना काल में कृषि की उत्पादकता में वृद्धि जल, रासायनिक खाद कीटनाशक दवायों शक्ति आदि कृषिगत साधनों की पूर्ति बढ़ा कर की गई। इन साधनों की पूर्ति के विस्तार को सारणी-7 में प्रदर्शित किया गया है—

सारणी-7

कृषिगत साधन

समय	1950-51	1965-66
खाद (हजार टन नाष्पावन)	56	600
विद्युत् (मि किलोवाट घंटा)	203	1730
मिथाइल गैस (म)	3500	32499
इंधन तेल (मिलियन किलो ग्राम)	45	277

Source Economic Survey 1969-70 pp 66-67

सारणी 7 से स्पष्ट है कि 1950-51 की तुलना में 1965-66 में कृषिगत साधनों में प्रयोग में वृद्धि हुई है। खाद का उपयोग दस गुना विद्युत् का पाठ गुना बढ़ा। गैस का उपयोग दस गुना अधिक वृद्धि हुई तथा इंधन-तेल का उपयोग भी दस गुना अधिक किया जाने लगा।

सारणी-8

कुछ भौद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन-लक्ष्य

वर्ष	1950-51	1955-56		1960-66	
		प्रस्तावित वास्तविक		प्रस्तावित वास्तविक	
1 तैयार इस्पात (मि टन)	1 04	1.4	1 3	4 6	4 51
2 अल्यूमिनियम धातु (हजार टन)	4 0	12 0	7 3		62 1
3 डीजल इंजन (हजारों में) स्टेशनरी	5 5		10 0	85.0	93.1
4 कुन मोटरगाडियाँ (हजारों में)	16 5		25 3	68 5	70 7
5 मशीनी औजार (मिलियन रु में)	3 0		7.8	230 0	294 0
6 चीनी मिल मशीनरी (मिलियन रु में)			1 9	80 0	77 0
7 साइकिल (हजारों में)	99 0		513	1700	1574
8 सल्फ्यूरिक एसिड (हजार टन)	101				662
9 सीमेन्ट (मि टन)	2 7	4 8	4.6		10.8
10 नाइट्रोजन उर्वरक (हजार टन में)	9 0			233	232
11 क स्मिंक मोडा (हजार टन)	12 0				218
12 कोयला (मि टन) (लिग्नाइट सहित)	32 8		38 4		70 3
13 कच्चा लोहा (मि टन) (गोपा को छोड़कर)	3 0		4 3		18 1
14 परिशुद्ध पेट्रोल पदार्थ (मिलियन टन)	0 2		3 6		9 4
15 उत्तरज विद्युत् (बिलियन कि घंटा)	5 3				32 0

Source (i) Economic Survey 1969-70 pp 66-67

(ii) Paul Streeten op cit p 301

पर्य्य व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के भौतिक लक्ष्यों को निरपेक्ष रूप में उपरोक्त सारणियों में प्रदर्शित किया गया है। लक्ष्यों की सापेक्ष स्थिति को और अधिक स्पष्ट करने की दृष्टि से विकास लक्ष्यों को वार्षिक औषत विकास-दरों के रूप में सारणी-9 में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह अध्ययन Paul Streeten एवं Michael Lipton का है। इन विकास-दरों के माध्यम से यह सरलता से जाना जा सकता है कि कृषि, शक्ति, खनिज, उद्योग, यातायात और संचार आदि आर्थिक क्षेत्रों के विकास की सापेक्ष प्रवृत्ति प्रत्येक योजना अवधि में किस प्रकार की रही है।

सारणी-9

चुने हुए लक्ष्य और उपलब्धियाँ—आर्थिक औसत विकास दरें

(Selected Targets and Achievements—Annual Average Growth Rates)

वर्ष (Items)	भौतिक सूचकांक (Physical Indicator)	1950-51 के लक्ष्य (Targets 1950-51)	1950-51 के वास्तविक पर (Actuals 1950-51)	1955-56 के लक्ष्य (Targets 1955-56)	1955-56 के वास्तविक पर (Actuals 1955-56)	1960-61 के लक्ष्य (Targets 1960-61)	1960-61 के वास्तविक पर (Actuals 1960-61)	1965-66 के लक्ष्य (Targets 1965-66)	1965-66 के वास्तविक पर (Actuals 1965-66)	1970-71 के लक्ष्य (Targets 1970-71)	1970-71 के वास्तविक पर (Actuals 1970-71)
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
I कृषि											
(1) कृषिगत उत्पादन											
खाद्यान्न	वजन	34	47	41	35	40	20	51			
कपास	गाँठें	77	66	102	05	58	06	80			
गन्ना गुंड	वजन	24	14	54	90	—	24	16			
तिलहन	वजन	15	19	63	44	70	44	43			
रूट	गाँठें	104	49	55	—	28	99	69			
बाग	वजन		07	19	24	46	32	38			
(II) कृषिगत उत्पादक कारक											
नैऋजन खाद का उपयोग	वजन	—	138	na	144	na	20	238			
फास्फेट खाद का उपयोग	वजन	—	131	na	400	na	206	374			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 शक्ति								
विद्युत् क्षमता का उत्पादन	मि किलोवाट	94	81	149	105	178	113	151
3 खनिज								
बच्चा लोहा	वजन	59	75	238	206	178	83	236
कोयला	वजन	58	35	93	74	117	37	87
4 उद्योग								
इस्पात	वजन	106	50	278	121	242	165	121
मशीन यंत्र	मूल्य	—	167	306	543	338	300	318
मल्टीमीनियम	वजन	246	128	313	199	342	312	352
नेत्रजन खाद	वजन	574	540	298	43	520	250	430
फॉस्फेट खाद	वजन	272	59	574	351	494	240	403
कागज तथा कागज के पृष्ठे	वजन	119	104	133	130	149	90	105
सीमेंट	वजन	122	112	231	113	103	53	124
सूती कपड़ा	सम्बाई	48	65	02	—	27	61	54
चीनी	वजन	60	107	39	94	31	18	55
साइकिलें	संख्या	398	390	143	158	138	77	61
विद्युत् गले	संख्या	116	76	153	298	187	46	184

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 यातायात और संचार								
(i) रेलें		—						
यात्री	ट्रेनमील	—	27	28	45	na	47	41
वितरण	भारत में	—						
(ii) सड़कें (पब्ली)		—	45	73	61	98	56	81
(iii) जहाजरानी	मील	—	46	31	51	30	40	36
(iv) डाक		—	42	134	123	78	129	135
डाकघर	संख्या	—	88	64	70	41	59	112
टेलीफोन	संख्या	—	106	106	107	87	134	121
6 सामाजिक सेवाएँ								
(i) शिक्षा		—						
छात्र-संख्या		—						
प्राथमिक	छात्र	—	56	55	68	89	81	62
माध्यमिक		—	66	55	33	55	104	115
उच्च माध्यमिक,		—						
तत्पश्चात्		—	92	79	93	127	121	114
(ii) स्वास्थ्य		—						
अस्पताल शैया	संख्या	—	20	44	83	52	53	46
डॉक्टर	संख्या	—	30	15	12	30	40	81
परिवार नियोजन		—						
वैज्ञानिक	संख्या	—	na	780	620	378	470	358

na—not available

Source: Paul Streeten and Michael Lipton (Eds)—The Crisis of Indian Planning pp 382-83

प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों का मूल्यांकन (An Evaluation of the Achievements of the First Three Five Year Plans)

प्रथम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में 18% वृद्धि हुई। वृद्धि का लक्ष्य 11% रखा गया था। द्वितीय योजना में राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि के विरुद्ध वास्तविक वृद्धि केवल 20% हुई। तृतीय योजना में 30% वृद्धि के लक्ष्य के स्थान पर राष्ट्रीय आय में 13.8% वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से प्रथम पंचवर्षीय योजना में 11% वृद्धि हुई, द्वितीय योजना में 18% वृद्धि के लक्ष्य के स्थान पर 11% वृद्धि हुई। 1960-61 के मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 1960-61 में 306.7 रुपये थी। यह बढ़ कर 1964-65 में 333.6 रुपये हो गई किन्तु 1965-66 में पुन घट कर 307.3 रुपये रह गई। इससे स्पष्ट है कि तृतीय योजना के अन्त में प्रति व्यक्ति आय लगभग वही रही है जो योजना के प्रारम्भ में थी।

1950-51 से 1964-65 तक राष्ट्रीय आय में 65% वृद्धि हुई तथा प्रतिवर्ष चक्र-वृद्धि दर के हिसाब से लगभग 3.8% की वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति वास्तविक औसत दर लगभग 1.8% रही। इन अंकों की दृष्टि से यह कहना उपयुक्त नहीं है कि प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं की 15 वर्षीय अवधि में भारत में आर्थिक विकास नहीं हुआ। किन्तु यह कहना सही है कि लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि का स्तर कम रहा।

कृषि

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के उत्पादन में 18% वृद्धि हुई। खाद्यान्नों का उत्पादन 54.92 मिलियन टन से बढ़ कर 69.22 मिलियन टन हो गया। द्वितीय योजना के अन्तिम वर्ष 1960-61 में खाद्यान्न का उत्पादन 82.0 मिलियन टन हो गया किन्तु तृतीय योजना में खाद्यान्नों का उत्पादन घट कर केवल 72 मि. टन ही रह गया। औसत वार्षिक विकास-दर की दृष्टि से प्रथम पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्नों के उत्पादन में 3.4% औसत वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य के स्थान पर 4.7% औसत वार्षिक वृद्धि हुई। किन्तु तृतीय योजना में 4.0% औसत वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 2.0% की ही वृद्धि हुई। खाद्यान्नों के उत्पादन की सफलता तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता को प्रकट करते हैं। कुल मिलाकर खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धि में वृद्धि हुई। 1951 में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धि जो 13.0 औंस थी वह 1965 में बढ़ कर 16.8 औंस प्रति व्यक्ति हो गई।

तिनहन गन्ना, जूट व जमास के उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि-दर प्रथम योजना में क्रमशः 19.1, 4.9 व 6.6% रही। अधिकांश कृषि-उपजों की औसत वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य से अधिक रही, किन्तु तृतीय योजना में जूट को छोड़ कर लगभग इन सभी कृषि-उपजों की औसत वार्षिक वृद्धि-दर कम हो गई। इस तथ्य को सम्बन्धित सारणी में देखा जा सकता है।

सिंचाई की दृष्टि से प्रथम तीन योजनाओं में बड़ी व मध्यम धरोहरों की सिंचाई के प्रानर्गन 13.8 मिलियन एकड़ क्षेत्र व लघु सिंचाई के प्रानर्गन 31.6 मिलियन एकड़ क्षेत्र की वृद्धि हुई। शक्ति के क्षेत्र में 1950-51 में जो प्रस्थापित क्षमता (Installed Capacity) 23 लाख किलोवाट थी वह 1965-66 में बढ़ कर 102 लाख किलोवाट हो गई। विद्युत् क्षमता में इस प्रकार पाँच गुनी वृद्धि हुई।

संक्षेप में भारत की तीन पञ्चवर्षीय योजनाओं के दौरान कृषिगत उत्पादन का सूचनांक काफी ऊँचा रहा। 1950-51 में 95.6 (1949-50=100) से 1965-66 में बढ़ कर 169 हो गया। इस तरह वृद्धि का प्रतिशत लगभग 65 रहा। औद्योगिक क्षेत्र

दृष्टि की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियाँ प्रथम तीन योजनाओं की पन्द्रह वर्षीय अवधि में अधिक हुई। औद्योगिक उत्पादन का सूचनांक 1951 में 100 से बढ़ कर 1961 में 194 हो गया। 1955-56 में यह सूचनांक 139 तथा औद्योगिक उत्पादन का यह सूचनांक 1956 के 100 से बढ़ कर 1965-66 में 182 हो गया। उपभोग वस्तुओं के उत्पादन का मूल्य 1950-51 में (1960-61 के मूल्यों पर) जो 200 करोड़ रुपये था वह 1965-66 में बढ़ कर 488 करोड़ रुपये हो गया। मध्यवर्ती वस्तुओं का उत्पादन मूल्य 90 करोड़ रुपये से बढ़ कर 620 करोड़ रुपये तथा मशीनी उत्पादन का मूल्य 31 करोड़ रुपये से बढ़ कर 316 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि मशीनी उत्पादन में हुई।

प्रमुख उद्योगों की प्रगति का उल्लेख सारणी 8 व 9 में किया जा चुका है। सारणी के अनुसार आर्थिक नियोजन के प्रथम 15 वर्षों में डीजन इजन, मशीनी औजार, नेत्रजन खाद, पेट्रोल पदार्थों, अल्यूमीनियम आदि के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। अल्यूमीनियम का उत्पादन 1950-51 में केवल 4000 टन था। 1965-66 में बढ़ कर यह 62.1 हजार टन हो गया। डीजन इजन 1950-51 में 5.5 हजार थे। उनका उत्पादन 1965-66 में बढ़ कर 93.1 हजार हो गया। मशीनी औजारों का मूल्य 1950-51 में जो केवल 3 मिलियन था वह 1965-66 में बढ़ कर 294 मिलियन हो गया। सीमेंट के उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई। 1950-51 में इसका उत्पादन 2.7 मिलियन टन था। 1965-66 में बढ़ कर यह 10.8 मिलियन टन हो गया। नेत्रजन खाद का उत्पादन 1950-51 के 9 हजार टन के मुकाबले 1965-66 में 232 हजार टन हो गया। आर्थिक नियोजन की इस पन्द्रह वर्षीय अवधि में तैयार इस्पात का उत्पादन लगभग चार गुना बढ़ा। डीजन इजनों की संख्या 17 गुना बढ़ी। मशीनी औजारों में 98 गुना अधिक वृद्धि हुई। नाइट्रोजन खाद का उत्पादन 26 गुना अधिक होन लगा। पेट्रोल से बने पदार्थों का उत्पादन 47 गुना अधिक हुआ।

घोषित वार्षिक विकास-दरों की दृष्टि से दृष्टि की तुलना में औद्योगिक वस्तुओं में वृद्धि की घोषित वार्षिक दरें अपेक्षाकृत कहीं अधिक रही हैं। इन वार्षिक दरों को सम्बन्धित सारणी से देखा जा सकता है। मशीनी-यन्त्रों की घोषित वार्षिक वृद्धि दर

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में 16.7% थी। तृतीय योजना के अन्त में यह 38% हो गई। अल्पसूत्रीनियम की औसत वार्षिक विकास-दर 1953-56 में 12.8% थी। 1965-66 में बढ़ कर यह 21.2% हो गई। इसी प्रकार ग्रन्थ औद्योगिक मंदी की स्थिति को झंका जा सकता है।

द्वितीय योजना मुख्य रूप से औद्योगीकरण की योजना थी। इस योजना की अवधि में लोहा एवं इस्पात के तीन कारखाने भिलाई (मध्य प्रदेश), हरकेला (उड़ीसा) और दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) में स्थापित किए गए। इस योजना में चिनरजन, टाटा, लोड उद्योग में विस्तार और इञ्जीनियरिंग उद्योगों का विकास किया गया। लघु उद्योगों के विकास पर 180 करोड़ रुपये व्यय किए गए तथा विभिन्न उद्योगों के विकास के लिए अखिल भारतीय बोर्डों की स्थापना हुई।

सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार

आर्थिक योजनाओं के माध्यम से भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का अत्यधिक विस्तार हुआ। अब देश में एक सुदृढ़ सार्वजनिक क्षेत्र की स्थिति विद्यमान है। सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिष्ठानों की संख्या में हुई उत्तरोत्तर वृद्धि को सारणी-10 में निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

सारणी-10
सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की स्थिति

प्रारम्भ में	प्रतिष्ठानों का संख्या	कुल निवेश (मिलियन रुपये में)
प्रथम योजना	5	290
द्वितीय योजना	21	810
तृतीय योजना	48	9530
चतुर्थ योजना	85	39020

1971-72 तक सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को कोई लाभ नहीं हुआ अपितु भारी हानि हुई। 1971-72 में विशुद्ध हानि की राशि 191.5 मिलियन थी किन्तु 1972-73 में 101 प्रतिष्ठानों में से 67 प्रतिष्ठानों में 1044.6 मिलियन रुपये का विशुद्ध लाभ हुआ और 74 प्रतिष्ठानों में 867.6 मिलियन रुपये की हानि हुई। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र का विशुद्ध लाभ 177.6 मिलियन रुपये रहा। भारी उद्योग मंत्रालय के 1973-74 के प्रतिवेदन के अनुसार 14 सार्वजनिक प्रतिष्ठानों ने 1973-74 के वर्ष में 4090 मिलियन रुपये के उत्पादन मूल्य का मानदण्ड स्थापित किया। विकास दर की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र की विकास-दर जहाँ 5.5% रही वहीं निजी क्षेत्र की विकास दर 1971-72 में 1% और 1972-73 में 2.5% रही। औद्योगिक उत्पादन में सरकारी क्षेत्र का अंश 1951 में केवल 2% था वह 1970 में बढ़ कर 5% हो गया।

यातायात एवं संचार-क्षेत्र की उपलब्धियाँ

यातायात एवं संचार-व्यवस्था का विकास औद्योगीकरण की आधारशिला

है। प्रथम प्रथम योजना में रेल की 380 मील लम्बी नई लाइनें बिछाई गईं और रेल-ट्रेफिक में 24.8% की वृद्धि हुई। 636 मील लम्बी सड़कों का निर्माण हुआ। जहाजरानी की क्षमता 39 लाख जी. ग्रार. टी. से बढ़ा कर 48 लाख जी. ग्रार. टी. कर दी गई। 1950-51 में रेल ट्रकों का वार्षिक उत्पादन 27 से बढ़ कर 1955-56 में 179 इकाई हो गया।

द्वितीय योजना में रेलों सड़कों और जहाजरानी के विकास के लिए विस्तृत विकास-कार्य किए गए। 8000 मील लम्बी रेलवे लाइनों का सुधार, 1,300 मील लम्बी लाइनों का दोहराकरण और 500 मील लम्बी लाइनों का विद्युतीकरण किया गया जिससे माल ढोने की क्षमता 11.6 करोड़ टन से बढ़ कर 15.6 मेट्रिक टन हो गई। रेलों के विकास पर 1044 करोड़ रुपये व्यय हुआ। सड़क-विकास पर 224 करोड़ रुपये व्यय करने से कच्ची व पक्की सड़कों की लम्बाईयाँ क्रमशः 294,000 मील और 147,000 मील हो गई। इस प्रकार कच्ची एवं पक्की सड़कों में क्रमशः 37,000 मील और 22,000 मील की वृद्धि हुई। जहाजरानी की क्षमता 48 लाख जी. ग्रार. टी. से बढ़ कर 86 लाख जी. ग्रार. टी. हो गई।

तृतीय योजना में मानायात एवं संचार के लिए 1,486 करोड़ रुपये (कुल का 20%) निर्धारित किया गया जब कि वास्तविक व्यय 2110.7 करोड़ रुपये हुआ। अधिक व्यय का कारण सैनिक दृष्टि से भौतिक संशोधन एवं कार्यक्रमों में परिवर्तन था। रेलों के माल ढोने की क्षमता 1450 लाख टन से बढ़ा कर 2540 लाख टन करने का (59% वृद्धि) लक्ष्य था पर योजना के अन्त में यह क्षमता सिर्फ 2050 लाख टन ही थी। सड़कों के निर्माण में 292 करोड़ रुपये का व्यय कर 2,70,400 मील लम्बी कच्ची-पक्की सड़कें बनाई गईं। जहाजरानी की क्षमता 86 लाख टन से बढ़ कर 154 लाख टन कर दी गई। इस प्रकार लगभग 7 लाख जी. ग्रार. टी. की वृद्धि हुई।

सामाजिक सेवासो के क्षेत्र की उपलब्धियाँ

सामाजिक सेवासो पर प्रथम योजना में कुल योजना व्यय का 25% भाग व्यय किया गया। प्राथमिक शालाओं की संख्या 209 लाख से बढ़ कर 2.8 लाख हो गई। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 30 से बढ़ कर 42 और विद्यालयों की संख्या 2,500 से बढ़ कर 3,500 हो गई। अस्पतालों की संख्या में 1,400 की वृद्धि हुई और डॉक्टरों की संख्या 59,000 में बढ़ कर 70,000 हो गई।

द्वितीय योजना में शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार एवं विकास से छात्रों की संख्या 3.13 करोड़ से बढ़ कर 4.35 करोड़, चिकित्सालयों की संख्या 10,000 से बढ़ कर 1,26,000, मेडिकल कॉलेजों की संख्या 42 से बढ़ कर 57, परिवार नियोजन केन्द्रों की संख्या 147 से बढ़ कर 1649 कर दी गई। श्रृंखला निर्माण-कार्य पर 250 करोड़ रुपये व्यय किए गए जिसमें आवास-गृहों की संख्या में 5 लाख की वृद्धि हुई। निम्नलिखित वर्गों में 4800 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

तृतीय योजना में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा पर 1300 करोड़ रुपये व्यय

करने का प्रावधान था पर वास्तविक व्यय 1355.5 करोड़ रुपये हुआ। जिससे स्कूलों व शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या 4 लाख और 4.5 करोड़ से बढ़ कर 5 लाख तथा 6.8 करोड़ हो गई। अस्पतालों की संख्या में 2000 की वृद्धि हुई। परिवार-नियोजन केन्द्रों की संख्या 1649 से बढ़ कर 11,474 हो गई। मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 30 की वृद्धि हुई जिससे मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या देश में इस योजना के अन्त में 87 हो गई।

वचत व विनियोग

भारत में आर्थिक-नियोजन के प्रथम 15 वर्षों में वचत व विनियोग के क्षेत्र में रही स्थिति को सारणी-11 में प्रदर्शित किया गया है—

सारणी-11

वर्ष	वचत-राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में	विनियोग राष्ट्रीय-आय के प्रतिशत के रूप में
1950-51	5.53	5.44
1955-56	9.26	9.86
1960-61	9.45	12.88
1965-66	10.5	14.00

1965-66 के सूचनांक से स्पष्ट है कि विनियोगों के लगभग 3.5 / भाग के लिए हमें विदेशी साधनों पर निर्भर रहना पड़ा है। घरेलू वचतों में वृद्धि आवश्यक विनियोगों के अनुरूप नहीं हुई।

इस प्रकार आर्थिक नियोजन की प्रथम 15 वर्षीय अवधि में कृषि, उद्योग, यातायात और संचार, सामाजिक-सेवाएँ आदि क्षेत्रों में उक्त उपलब्धियाँ रही। आर्थिक नियोजन की इस अवधि में देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ और गतिमान हुई है तथा विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों की उपलब्धियाँ उल्लेखनीय रही हैं तथापि योजनाओं के लक्ष्यों और वास्तविक उपलब्धियों में पर्याप्त अन्तर रहने, मुद्रा-स्फीति के कारण मूल्य-स्तर के असामान्य रूप से बढ़ने, बेरोजगारी में निरन्तर वृद्धि, विदेश-विनिमय-संकट और उत्पादन के केन्द्रीकरण से सर्वसाधारण का जीवन-स्तर अभी तक भी बहुत निम्न स्तर पर है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के होते हुए भी खाद्यान्नों के क्षेत्र में आवश्यकता की पूर्ति आयातों में करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में सर्वसाधारण के जीवन-स्तर को उठाने और गरीबी का उन्मूलन करने के लिए हमको योजना के क्रियान्विति पक्ष पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रशासनिक-कुशलता एवं ईमानदारी में वृद्धि करनी होगी। गत वर्षों के योजनावद्ध आर्थिक विकास ने भारत की अर्थव्यवस्था को स्वयं-सूक्त तथा आत्म-निर्भरता की स्थिति की ओर बढ़ाया है, किन्तु आयोजन के फलस्वरूप कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रों में हुए रचनात्मक परिवर्तनों का लाभ उठाने के लिए हमको आर्थिक आयोजन के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा।

रही। दूसरी योजना में भी विनियोग-दर की दृष्टि से स्थिति आशाजनक रही। यह दर 11% के लगभग रही जो निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप थी। किन्तु तृतीय योजना में विनियोग बचत दर में प्रगति असन्तोषजनक रही। 1965-66 में 14 से 15% के लक्ष्य की तुलना में विनियोग-दर 13.4% के लगभग रही। पांचे की तीन वार्षिक योजनाओं में भी स्थिति उत्तरोत्तर असन्तोषजनक होती गई। विनियोग-दर निरन्तर गिरती गई। 1966-67 में यह गिर कर 12.2%, 1967-68 में 19.6% और 1968-69 में 9.5% रह गई। विनियोग-दर की इस गिरती हुई स्थिति पर चौथी योजना में विशेष ध्यान दिया गया। फलस्वरूप स्थिति में पुन मुधार हुआ और विनियोग-दर बढ़ कर 1970-71 में 10.5% तथा 1971-72 में 11.5% के लगभग हो गई।

यदि आँकड़ों से हटकर भी देखें तो देश में उत्पादकता और मुद्रा प्रसार की जो स्थिति है उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि राष्ट्रीय उत्पादन अपेक्षित स्तर से बहुत कम है, और इसके लिए विनियोग की असन्तोषजनक स्थिति भी एक सीमा तक उत्तरदायी मानी जा सकती है। अत आवश्यकता इस बात की है कि एक ओर विनियोजित पूँजी की उत्पादकता में वृद्धि की जानी चाहिए तथा दूसरी ओर उत्पादन में वृद्धि के लिए विनियोगों की दशा में ऐसे प्रयत्न किए जाने चाहिए जिनसे विनियोगों में वृद्धि हो सके। इससे पूर्व कि हम विनियोगों में वृद्धि के लिए सम्भावित उपायों पर विचार करें, उन तकनीकियों की जानकारी कर लेना उपयुक्त है जिनके द्वारा देश की योजनाओं के लिए बचतों को विनियोग-क्षेत्रों में आकर्षित करने के प्रयत्न किए गए। योजनाओं के विनियोग-विश्लेषण से स्पष्ट है कि बचतों को प्राप्त करने के लिए निम्न तीन तकनीकियाँ अपनाई गई—

- (1) प्रत्यक्ष हस्तांतरण विधि (Technique of Direct Transfer)
- (2) अप्रत्यक्ष हस्तांतरण विधि (Technique of Indirect Transfer)
- (3) अनिवार्य हस्तांतरण विधि (Technique of Forced Transfer)

प्रत्यक्ष हस्तांतरण—बचतकर्त्ताओं से साधनों के समूह के लिए पहली विधि जो योजनाओं में प्रयुक्त हुई वह प्रत्यक्ष हस्तांतरण की विधि थी। इस विधि के अन्तर्गत किए गए प्रयत्नों का मूल उद्देश्य बचतकर्त्ताओं को वित्तीय सम्पत्तियों के क्रय के लिए प्रेरित करना था। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डाकघर जमा योजनाएँ आदि शुरू की गई। इस विधि के अन्तर्गत विशेष रूप से यह प्रयत्न किया गया कि बचतों का उपयोग उत्पादन-क्षेत्रों (Productive Channels) में हो तथा निजी क्षेत्र की अपेक्षा लोगों की बचतें सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवाहित हो।

अप्रत्यक्ष हस्तांतरण—जनता की बचतों को विनियोजन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दूसरी विधि अप्रत्यक्ष हस्तांतरण की अपनाई गई। इस विधि के अन्तर्गत कुछ राजकोषीय तरीकों (Fiscal Measures) को प्रयोग में लाया गया। इन तरीकों के अन्तर्गत कराधान, अनिवार्य जमा आदि के माध्यम से बचतों को विनियोग के लिए उलबल कराने के प्रयत्न हुए तथा साथ ही जीवन-बीमा भुगतान,

प्रोवीडेंट-फंड आदि (Contractual Savings) के परिणाम को बढ़ाने के प्रयत्न किए गए। इन सत्र प्रयत्नों का मुख्य लक्ष्य उपभोग्य आय (Disposal Income) को कम करके बचतों का सृजन करना तथा इन बचतों को अनिवार्य एवं अर्द्ध-अनिवार्य तरीकों के माध्यम से सरकारी क्षेत्र पर पहुँचाना था। द्वितीय योजना में इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया कि, पहला अनिवार्य बिन्दु यह है कि क्या निजी बचतें, निजी विनियोगों की आवश्यकता को पूरा करने के उपरान्त, इतनी अधिक हो सकती है कि राज्य की सम्भावित आवश्यकताओं को पूरा कर सके। बचतों में पर्याप्तता की स्थिति तभी सम्भव है जब कि उपभोग को आवश्यक प्रतिबन्धों में रखा जाए। करो के रूप में या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लाभों के रूप में जितनी कम मात्रा में बचतें प्राप्त होगी, उतनी ही अधिक आवश्यकता उपभोग को नियन्त्रित रखने की महसूस की जाएगी। परिणामस्वरूप उपभोग पर नियन्त्रण रखने के लिए अन्य तरीके काम में लिए जाएंगे।

अनिवार्य हस्तांतरण—बचतों को विनियोजन के लिए उपलब्ध कराने की तीसरी विधि अनिवार्य हस्तांतरण की प्रयोग में ली गई। यदि सरकारी प्रतिभूतियों की सीधी खरीद के द्वारा निजी बचतें सार्वजनिक क्षेत्र के लिए प्राप्त नहीं होती हैं तो बचतों की उपलब्धि के लिए स्वीकृत माना से अधिक मात्रा में निजी क्षेत्र से बैंक नकदी तथा जमाओं को अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्ति करने का प्रयत्न करते हैं।

विनियोगों में वृद्धि के लिए उपरोक्त सैद्धान्तिक तकनीकियों के प्रतिरिक्त समय पर सरकार द्वारा तथा रिज़र्व बैंक द्वारा राजकोषीय और मौद्रिक तरीके घोषित किए जाते हैं। साख, ऋण, कर आदि नीतियों में संशोधन किए जाते हैं, बैंक-दर को घटाया-बढ़ाया जाता है। अनेक प्रकार के नए कर लगाए जाते हैं और पुरानी कर-व्यवस्था में सुधार किए जाते हैं। बैंक-दर, खुले बाजार की क्रियाएँ, नकद बोप अनुपात में परिवर्तन आदि विनियोग तथा बचतों को प्रभावित करने वाली विधियों तथा कर, ऋण एवं व्यय-नीति सम्बन्धी राजकोषीय तरीकों से प्रायः सभी परिचित हैं। इन नीतियों के सैद्धान्तिक पहलुओं में जाकर हमको यह मान्यता लेते हुए कि विनियोग का वर्तमान स्तर देश की आवश्यकताओं से बहुत कम है, उन उपायों की देखना चाहिए जिनसे भविष्य में विनियोग की दर में देश की आवश्यकताओं के अनुरूप वृद्धि की जा सके।

विनियोग-वृद्धि के उपाय

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में विनियोगों की वृद्धि के लिए साधन-संग्रह के कुछ सुझाव दिए गए हैं—

1. सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोगिता प्रतिष्ठान और राजकीय क्षेत्र के अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान लिए जा सकते हैं। नियोजन काल में सार्वजनिक क्षेत्र का योजनाओं में निरन्तर विस्तार किया गया है और लगभग 5 हजार करोड़ से भी अधिक की राशि इस क्षेत्र में विनियोजित की गई है किन्तु इस भारी विनियोजन के यथेष्ट लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र से मिलने वाले

लाभ विनियोग योग्य साधन-मग्न के लिए सर्वाधिक महत्त्व रखते हैं। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में नियुक्त कुछ समितियों ने इन उपक्रमा के लिए निश्चित प्रतिफल दर की सिफारिश की है।

2 जिन क्षेत्रों पर अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जा सकता है, उनमें राजकीय विद्युत सस्थानों का प्रमुख स्थान है। वैकट रमन समिति की सिफारिशों के अनुसार विद्युत् सस्थानों से कम से कम 11% की दर से प्रतिफल मिलना चाहिए। जहाँ यह दर 11% से कम है, वहाँ इसे कम से कम 11% तक बढ़ाया जाना चाहिए। धीरे धीरे शुरू में वृद्धि अपेक्षित है तथापि बिजली दरों को इस प्रकार मिश्रित करना चाहिए जिससे आर्थिक दृष्टि से अच्छी स्थिति वाले उपभोक्ताओं को अधिक दाम चुकाना पड़े।

3 सिचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में नियुक्त निर्जलितप्पा समिति की यह सिफारिश भी विनियोग वृद्धि की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है कि सिचाई की दरें सिंचित फसलों से कृषकों को प्राप्त अतिरिक्त विशुद्ध लाभ के 25-40 % पर निश्चित की जानी चाहिए। कृषकों के उस वर्ग से साधन जुटाने के प्रयास बढ़ाने होंगे जिन्हें सिचाई योजनाओं से प्रत्यक्ष लाभ मिलता है।

4 चतुर्थ योजना में अतिरिक्त साधन व्यवस्था की दृष्टि से इस बात को भी महत्त्वपूर्ण समझा गया कि सार्वजनिक उपयोग के लिए संचालित उद्योगों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में लगी पूँजी पर होने वाली आय को धीरे धीरे बढ़ा कर 15 प्रतिशत करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

5 साधनों को बढ़ाने तथा साधनों में वृद्धि से विनियोगों का विस्तार करने का एक बड़ा उपाय करारोपण सम्बन्धी राजकोषीय साधन है। कृषि क्षेत्र अभी तक कम-मुक्त है। यद्यपि इस क्षेत्र में योजना काल के दौरान अरबों रुपयों का विनियोजन किया गया है और इस क्षेत्र में आय में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। अनेक बड़े किसान समृद्ध पूँजीपति बन गए हैं। अतः बढ़ती हुई आय विपमताओं को रोकने तथा विनियोगों के लिए आवश्यक धन जुटाने के लिए कृषि-आय पर कर लगाया जाना चाहिए। वस्तुओं पर भी करारोपण की इस रूप में प्रभावशाली व्यवस्था होनी चाहिए अथवा अप्रत्यक्ष करों का ढाँचा इस प्रकार का होना चाहिए कि प्रदर्शनकारी उपभोग (Conspicuous Consumption) या विलासी उपभोग (Luxury Consumption) प्रतिबन्धित रहे। विक्री कर की दरों में पायी जाने वाली विभिन्न राज्यों में विषमता को दूर किया जाना चाहिए। विक्री दरों में समानता लाने से भी एक बड़ी राशि प्राप्त की जाना सम्भव है। शहरी सम्पत्ति के मूल्यों में अनाजित वृद्धि (Unearned increase) पर कर लगाया जाना चाहिए तथा आय और धन पर करों को अधिक प्रभावकारी बनाया जाना चाहिए। मृत्यु कर तथा पूँजी लाभ करों को शक्ति से क्रियाशील बनाया जाना चाहिए।

6. करों के सम्बन्ध में करारोपण की अपेक्षा करों की चोरी (Tax evasion) को रोकने के प्रयत्न अधिक आवश्यक हैं।

7. ग्रामीण बचतों से विनियोग के लिए बहुत बड़ी राशि प्राप्त हो सकती है। ग्रामीण बचत को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण ऋण-पत्र निर्गमित किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त ग्रामीण जनता को ग्रामीण उद्योग, सिंचाई कार्यक्रम, ग्राम-विद्युत्करण, भावास एवं पेय-जल की प्रभावी व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष लाभ पहुँचा कर उनसे समुचित मात्रा में धन संग्रह किए जाने पर बल दिया जाना चाहिए।

8. काले धन की वृद्धि को रोकथाम करने और काले धन को बाहर निकलवा कर विनियोग के लिए प्रयुक्त करने की नीतियों पर पुनर्विचार आवश्यक है। ऐसा करते हुए इन उपायों पर विशेष बल देना होगा—तस्करी की रोकथाम, महत्वपूर्ण कृषि मन्त्रों की सप्लाई पर और अधिक मात्रा में सामाजिक नियन्त्रण, उचित शहरी भूमि सम्बन्धी नीति पर अमल आदि। अनुमान है कि देश में लब्ध भाग उसी मात्रा में लोगों के पास काला धन छिपा हुआ है जिस मात्रा में देश में मुद्रा प्रचलन में है। अतः भौतिक तथा राजकोपीय नीतियों पर पुनर्विचार करके उन्हें इस रूप में प्रभावी बनाया जाना चाहिए कि काले धन में वृद्धि सम्भव न रहे। साथ ही काले धन को बाहर निकालने के लिए कठोर वैधानिक उपायों का आश्रय लिया जाना चाहिए। इससे विनियोगों के लिए एक बड़ी राशि प्राप्त की जा सकती है।

9. वित्त-व्यवस्था में घाटे को इस स्तर तक कम किया जाना चाहिए कि जनता के पास धन-वृद्धि होने से वह अर्थ-व्यवस्था की माँगों से अधिक नहीं बढ़े ताकि योजना के लिए धन की व्यवस्था करने में मुद्रा-स्फीति की स्थिति न आए।

10. राज सहायता पर पुनर्विचार किया जाकर इसमें यथासम्भव कमी से भी विनियोग-वृद्धि के लिए भारी राशि प्राप्ति की जा सकती है।

11. निर्धनता में तेजी से वृद्धि और आयात प्रतिस्थापन की दिशा में कमजोर बिन्दुओं को दूर किया जाना चाहिए।

12. कुछ विदेशी सहायता की राशि को यथाशीघ्र इस स्तर तक घटाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए कि केवल ऋणों के भुगतान के लिए आवश्यक राशि ही विदेशी सहायता के रूप में स्वीकार की जाए।

उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि योजनाओं के लिए विनियोग-वृद्धि की दृष्टि से हमें कई दिशाओं में एक साथ काम करना होगा। लोगों की बढ़ती हुई आय का एक बड़ा भाग विकास-कार्यों के लिए संग्रहीत करना होगा। घरेलू बचत की दर में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी, क्योंकि लगभग 88 प्रतिशत विनियोगों की पूर्ति घरेलू बचतों से की जाती है। उपायों की श्रिय गति के लिए प्रशासनिक यन्त्र में कुशलता लानी होगी। अनुत्पादक व्यय पर नियन्त्रण लगाना होगा तथा उत्पादक व्यय की उत्पादकता में वृद्धि करनी होगी। एक ओर उत्पादकता (वृद्धि के प्रयत्न तथा दूसरी ओर अनुत्पादक व्यय पर नियन्त्रण से ही योजनाओं के लिए आवश्यक विनियोग की पूर्ति सम्भव होगी।

उत्पादकता-सुधार के उपाय¹ (Measures to Improve Productivity)

भारत में उत्पादकता आन्दोलन का इतिहास लगभग 17 वर्ष पुराना है किन्तु इसका प्रारम्भ अमेरिका में कई दशकों पहले हो चुका था। द्वितीय महायुद्ध के अन्त में उत्पादकता की विचारधारा को पश्चिमी जगत में व्यापक स्वीकृति मिली। जापान ने अमेरिका में जन्मी उत्पादकता की विचारधारा का पूरा लाभ उठाया। उसने अपने सभी स्तरों के औद्योगिक कर्मचारियों को अमेरिका भेजा ताकि वे वहाँ के औद्योगिक मयत्रों से अनुभव प्राप्त कर सकें तथा अपने देश में मयत्रों की कार्य-प्रणाली में क्रांति ला सकें। भारत ने भी इसका अनुमरण किया और एक शिष्टमण्डल जापान यह ज्ञात करने भेजा कि किस प्रकार उस देश ने अपनी उत्पादकता में शीघ्र वृद्धि की है। शिष्ट-मण्डल के प्रतिवेदन के आधार पर भारत में 1958 में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् (National Productivity Council = NPC) की स्थापना की गई। विख्यात अर्थशास्त्री पी एस लोकनाथन् इसके अध्यक्ष मनोनीत किए गए।

उत्पादकता का अर्थ

भारतीय नियोजन के सन्दर्भ में उत्पादकता-सुधार के उपायों पर आने से पूर्व उत्पादकता का अर्थ समझ लेना उपयुक्त है। उत्पादकता से आशय केवल बड़े हुए उत्पादन से ही नहीं है और न ही श्रमिक की उत्पादकता से सम्बन्धित है। वास्तव में उत्पादकता का अर्थ कम से कम उपकरणों के साथ उत्पादन बढ़ाने की एक विधि के रूप में लयाया जाना उपयुक्त है। यह पूँजी के विनियोग, बिजली और ईंधन की खपत, वस्तु सूची, वित्त तथा अन्य साधनों के रूप में मापी जा सकती है।

प्रायः उत्पादकता, मादा व प्रदा के अनुपात के रूप में परिभाषित की जाती है। उत्पादकता के उच्च स्तर के लिए लागत को कम करने तथा उत्पादन को बढ़ाने पर बल दिया जाता है। न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन साधनों के कुशल उपयोग (Efficient utilization) पर निर्भर करता है। किन्तु लागत की कमी व उत्पादन की वृद्धि वस्तु की बिस्म को गिरा कर बी जानी चाहिए। उत्पादकता के अन्तर्गत कम लागत तथा अधिक उत्पादक के अतिरिक्त माल की श्रेष्ठ बिस्म का भी ध्यान रखा जाना है। उत्पादकता की इस अवधारणा में भी एक कमी रह जाती है। वह यह है कि उत्पादकता की उपरोक्त परिभाषा वितरण पक्ष की व्याख्या नहीं करती है। एक विकासशील देश में उत्पादकता वृद्धि का परीक्षण उन वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के रूप में किया जाना चाहिए, जो सामान्य व्यक्ति के माँग-ढाँचे के अधिक अनुकूल होती हैं। उत्पादकता के विश्लेषण के अन्तर्गत इस प्रकार की वस्तुओं पर लगे साधन तथा इन साधनों के कुशलतम उपयोग को लिया जाना

- 1 (a) योजना, 7 सितम्बर 1972—विकास के दो दशक (डों की बी मेट्ट)
- (b) योजना, फरवरी 1971—उत्पादित-विक्षेपक
- (c) Ind a 1973, India 1974, India 1976
- (d) योजना, 13 फरवरी 1972 (उत्पादित के सिद्धान्त)

चाहिए। उत्पादकता और उत्पादन दो भिन्न तत्त्व हैं। इन्हें समान ग्रंथों में प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिए। उत्पादकता तथा उत्पादन में एक महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि उत्पादन शब्द वस्तुओं के उत्पादन की भौतिक मात्रा के लिए प्रयुक्त होता है जबकि उत्पादकता शब्द का प्रयोग साधनों के उपयोग में दिखाई गई कुशलता तथा श्रेष्ठता के लिए किया जाता है।

उत्पादकता का विचार उत्पादन-साधनों तथा आर्थिक विकास के कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रों के सम्बन्ध में किया जाता है। उत्पादन के साधन-श्रम का प्रति इकाई उत्पादन-श्रम की उत्पादकता तथा प्रति इकाई पूँजी का उत्पादन पूँजी की उत्पादकता कहलाता है। प्रति एकड़ अथवा प्रति हेक्टेयर कृषि के उत्पादन को कृषि उत्पादकता कहा जा सकता है। इसी प्रकार प्रति इकाई पूँजी के रूप में अथवा प्रति मानव घंटे (Man Hour) के रूप में औद्योगिक उत्पादन को प्रायः औद्योगिक उत्पादकता कहते हैं।

भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा उत्पादकता वृद्धि के प्रयत्न

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् श्रमिकों, मालिकों और सरकार के प्रतिनिधियों का एक ऐसा स्वायत्त संगठन है, जिसका उद्देश्य देशभर में उत्पादकता की चेतना उत्पन्न करना और उत्पादकता के जरिए देश को प्रगति के पथ पर ले जाना है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके आठ क्षेत्रीय निदेशालय बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर, फानपुर, दिल्ली, अहमदाबाद और चण्डीगढ़ जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक नगरों में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त 49 स्थानीय उत्पादकता परिषदें भी हैं, जिनके निकट सहयोग से उत्पादकता-कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् की स्थापना सन् 1958 में हुई थी और तब से अब तक उसका उद्देश्य रहा है कि कैसे उत्पादकता को राष्ट्रीय जीवन का अभिन्न अंग बना दिया जाए, ताकि लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठे और देश सुगम हो। प्रबन्ध तथा उत्पादकता के क्षेत्रों में गत 16 वर्षों से राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने अपनी सेवाओं को विकसित किया है और उन्हें एक मानक रूप प्रदान किया है। इन क्षेत्रों में परिषद् प्रशिक्षण तथा परामर्श सेवाएँ देती रही है। इसके अलावा इसने नए क्षेत्रों में अपनी उत्पादकता तथा विशिष्ट सेवाओं को विकसित करने का प्रयास किया है। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्नलिखित हैं—

- (1) 'इंजन क्षमता' में दो वर्ष का प्रशिक्षण-कार्यक्रम
- (2) 'आवरण विज्ञान' में दो वर्ष का प्रशिक्षण-कार्यक्रम
- (3) 'वित्तीय प्रबन्ध' में दो वर्ष का प्रशिक्षण कार्यक्रम
- (4) (क) निगमित योजना, (ख) उद्देश्यों के अनुसार प्रबन्ध, (ग) सम्भाव्यता अध्ययन, (घ) यातायात उद्योग, (ङ) नागरिक पूर्ति निगम तथा (च) अस्पतालों में विशिष्ट सेवाओं के विकास के लिए विशेषज्ञों के दलों का गठन।

(5) औद्योगिक स्नेहन, कम्पन तथा ध्वनि, औद्योगिक विद्युत यन्त्र, सयन्त्र रख-रखाव उपकरण तथा प्रक्रिया-नियन्त्रण में औद्योगिकी सेवाओं का विकास आदि विषयों में कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन ।

एशियायी उत्पादकता संगठन के कार्यक्रमों को हिन्दुस्तान में कार्यान्वित करने तथा विभिन्न फौजिप कार्यक्रमों के अन्तर्गत विदेशों में प्रशिक्षण के लिए प्रत्याशियों को प्रायोजित करने का काम राउप कर रही है । राउप के परामर्शदाताओं को समय समय पर प्रवक्ता मिलना है कि वे देश तथा विदेशों में प्रशिक्षण लेकर अपने ज्ञान और कुशलता में वृद्धि करें ।

आपाव स्थिति की घोषणा में सभी क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था की उत्पादक तथा वितरण सम्बन्धी प्रणाली को कुशल बनाने के लिए जोरदार प्रयास की जरूरत पर जोर दिया गया है । देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए जिम्मे कि वह अनवरत वृद्धि करता हुआ तथा मुद्रा-स्थिति से बचकर राष्ट्रीय एकता की सामान्य स्थिति प्राप्त कर सके, अर्थव्यवस्था के सभी आधारभूत क्षेत्रों में उत्पादक सामर्थ्य के पूरे उपयोग, सभी तरह के नुकसान से बचने, व्यापार के स्रोतों को प्रवाही बनाने, मजदूरी और प्रदत्तकों सभी के द्वारा समय का पूरा-पूरा उपयोग करने, काम को पूरी लगन और सामाजिक दृष्टि से करने समयनिष्ठा प्रवृत्ति-सम्बन्धी निर्णयों को उद्देश्यपूर्ण ढंग से और शीघ्र लेने तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की प्राप्ति के लिए सम्पूर्ण रूप से आवश्यकता अनुभव करने की भावना पर जोर दिया गया है । राउप के प्रयासों का प्रभाव उसके वित्तीय खर्चों और आय को सामने रखकर नहीं मापा जा सकता, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक संगठनों की कुशलता और प्रणाली में सुधार करना है । अतः लाभ उन संगठनों में दूँडा जा सकता है न कि राउप के वित्तीय बजट में । राउप ने उत्पादकता-वृद्धि के प्रयास में जो कुछ व्यय किया है, वह सकल राष्ट्रीय उत्पाद का थोड़ा सा अंश है, जबकि उत्पादकता वृद्धि का कार्य अर्थव्यवस्था में कुशलता का विकास करने का एक बुनियादी तत्त्व है । उत्पादन और वितरण और देश के सीमित वित्तीय तथा भौतिक साधनों के इस्तेमाल में कुशलता बढ़ाना अन्तर्गतत्वा उन सभी लोगों की कुशलता और रविव्य पर निर्भर है जो उत्पादन तथा वितरण के कार्यों में लगे हुए हैं । राउप की भूमिका तो यह है कि वह प्रशिक्षण कार्यक्रमों, समस्याओं का निदान तथा तथ्यों को स्पष्ट करके मानव-तत्त्व की इस प्रकार सहायता करे कि कार्य को बेहतर ढंग से किया जा सके ।

उत्पादकता योजना को राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं से समन्वित करने की जरूरत है जिसे कि अर्थव्यवस्था के विस्तार और वृद्धि के लिए एक मुहूर्त आधार प्रदान करने में उत्पादकता-प्राम्दोलन अपनी भूमिका अदा कर सके और राष्ट्रीय आर्थिक विकास में अपना कारगर योगदान दे सके । राउप अपने कार्यक्रमों का विस्तार और विकास करने की योजना राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं की जरूरतों के अनुसार करती है । इसके 1975-76 के कार्यक्रमों की योजना को पहले ही

अन्तिम रूप दे दिया है, जिसका लक्ष्य है देश में उत्पादकता-ग्रान्दोलन की वृद्धि और विकास तथा उत्पादकता के माध्यम से राष्ट्र के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में सहायता करने की चुनौतीभर भूमिका और बढ़ती हुई जिम्मेदारी को सम्भालना।

उत्पादकता-ग्रान्दोलन का प्रभाव

योजनावद्ध कार्यक्रमों के पश्चात् अब यह कहा जा सकता है कि विकास के लिए विस्तृत स्तर पर आधारभूत औद्योगिक-ढाँचे का निर्माण किया जा चुका है तथा अनेक प्रकार के नवीन आर्थिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 25,000 करोड़ रु की महत्वाकांक्षी चौथी पञ्चवर्षीय योजना तथा 50 000 करोड़ रु से अधिक की वर्तमान पञ्चवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था के उत्पादक-स्वरूप के ही प्रतिफल हैं। 1968-69 की अवधि में औद्योगिक उत्पादन में 60% की वृद्धि विनियाम की किसी विशिष्ट वृद्धि के परिणामस्वरूप न हो कर उपयुक्त औद्योगिक क्षमता में वृद्धि के कारण ही सम्भव हो सकी थी।

आज हम लोहा इस्पात, खाद, रसायन, मशीनी-यन्त्र, पेट्रो-रसायन भारी इन्जीनियरिंग आदि उद्योगों की स्थापना करके देश के आधारभूत औद्योगिक ढाँचे का निर्माण करने में हम समर्थ हो सके हैं। भारत इन वस्तुओं को उन्हीं देशों को निर्यात कर रहा है जिनसे वह 20 वर्ष पूर्व आयात करता था। 20 वर्ष पूर्व सूती वस्त्र, इट, सीमेन्ट आदि कुछ एक उद्योगों को छोड़कर अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति विदेशों आयातों से होती थी। शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य आदि से सम्बन्धित सुविधाएँ प्रायः नगण्य थीं। कुछ आवश्यक वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धि इस प्रकार है—

विद्युत्	0 0063 किलोवाट
मशीनी यन्त्र	0 0083 मि क
इस्पात	0 0027 टन
रेल	0 0001 किलोमीटर
कूड तेल	0 0007 टन

भारतीय राष्ट्रीय उत्पादक परिषद् के प्रयत्नों तथा पञ्चवर्षीय योजनाओं में किए गए प्रयासों के बावजूद उत्पादकता कमी बहुत कम है। कुछ प्रपवादों को छोड़कर भारत में निर्मित प्रत्येक वस्तु की लागत अन्तर्राष्ट्रीय लागत की तुलना में बहुत ऊँची है। इसके अतिरिक्त हमारी उत्पादन-क्षमता का भी पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया। अतः उत्पादकता वृद्धि के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण उपाय प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

कृषि-उत्पादकता बढ़ाने के उपाय

गत कुछ वर्षों से कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि हुई है। कृषि-उत्पादकता एक प्रच्छेद स्तर पर पहुँच गई है। नई कृषि-नीति का पैकेज-समयक्रम कृषिगत ढाँचे में उत्पादकता की ओर सचेत करता है। इस समय लगभग मिलियन से अधिक हैक्टेयर भूमि पर उन्नत सिस्म के बीजों का प्रयोग होता है। गेहूँ की कुछ किस्मों में 5 से 6 टन प्रति हैक्टेयर उत्पादन होने लगा है। जबकि

इससे पूर्व सिंचित भूमि में भी केवल 2 टन की पैदावार होती थी। उन्नत किस्म के बीजों के कारण अन्य अनाजों की पैदावार में भी काफी वृद्धि हुई है। चावल के क्षेत्र में 'Break Through' की स्थिति है। इसलिए यह दावा उचित प्रतीत होता है कि खाद्यान्नों में 20 से 50 मिलियन टन की वार्षिक वृद्धि कृषि उत्पादकता में सुधार के कारण ही सम्भव हुई है।

इस स्थिति से प्रोत्साहित होकर ही योजना आयोग ने कृषि क्षेत्र में विज्ञान व तकनीकी प्रयोग को चतुर्-योजना की व्यूह-रचना (Strategy) में महत्व दिया था। हम उत्तरोत्तर इस तथ्य का अनुभव कर रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता की वृद्धि के लिए सबसे अधिक अवसर प्राप्त है तथा वास्तविक मजदूरी में वृद्धि के रूप में और राष्ट्रीय बाजारों के विस्तार के रूप में कृषि-उत्पादकता में वृद्धि में आर्थिक विकास के अनेक अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होते हैं। भारत में कुछ भागों में देखे जाने वाले ट्रैक्टर कृषि उपकरण तथा उच्चतर जीवन-स्तर कृषि के क्षेत्र में नवीन उत्पादकता तकनीकियों के प्रयोग के ही परिणाम हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता में कृषि-क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि के लिए नियोजित विनियोग की राशि को बढ़ाना आवश्यक है।

उत्पादक वृद्धि के लिए निम्नलिखित सुझाव है—

1 अनुसंधान उत्पादकता वृद्धि का मूल आधार है। अतः वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देकर तथा उसे व्यवहार में लाकर उत्पादकता में वृद्धि की जानी चाहिए। योजना आयोग ने कृषि क्षेत्र में विज्ञान व तकनीकी प्रयोग को चौथी और पाँचवी योजना की व्यूह-रचना में अत्यधिक महत्व दिया है।

2 कृषि के लिए नियोजित विनियोग (Planned Investment) के अंश को बढ़ाया जाना चाहिए। जब-कभी योजनाओं के परिव्यय में कमी करना आवश्यक समझा गया, योजना परिव्यय में कटौतियाँ कृषि के भाग को कम करके की गईं तथा कृषि का वास्तविक भाग संगोषित अनुमानों में नियोजित अथवा प्रस्तावित राशि से बहुत कम रहा। विनियोग की अपर्याप्तता के कारण कृषि-उत्पादकता में अपेक्षित वृद्धि नहीं की जा सकी। प्रथम तीन योजनाओं में कृषि-विनियोग की स्थिति कुछ इसी प्रकार की रही।

3 मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए तथा सहकारी खेती को और अधिक प्रभावपूर्ण बनाया जाकर पैमाने, विनियोग और संगठन (Scale, Investment and Organization) के समस्त लाभ कृषि क्षेत्र में लेने चाहिए।

4. आवश्यक प्रशिक्षण द्वारा कृषि-श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि की जानी चाहिए तथा कृषि के नए उपकरणों और नई तकनीकी प्रयोग के लिए इन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए।

5. कृषि मूल्य नीति इस प्रकार की होनी चाहिए कि किसान को अपनी उर्जा का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। कृषि मूल्यों से अनिश्चितता की स्थिति दूर की जानी चाहिए।

6 कृषि शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। देश के कृषि विश्वविद्यालयों को प्रयोगात्मक ज्ञान के ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए कि जिनसे कृषि के छात्रों को कार्य करने का अवसर मिले तथा वे व्यवहार में लाकर कृषि-उत्पादकता वृद्धि में योग दे सकें। पाँचवी योजना में 25 500 कृषि स्नातक, 4200 पशु चिकित्सक और 1400 कृषि इंजीनियरों के बतने का अनुमान है। कृषि के लिए प्रशिक्षित इस वर्ग से कृषि-उत्पादकता में वृद्धि की भारी आशाएँ हैं।

7 रासायनिक खाद का प्रयोग बढ़ाया जाना चाहिए। पाँचवी योजना के आचार वर्ष 1973-74 में रासायनिक खाद की खपत लगभग 19.7 लाख टन थी। योजना के अन्त तक यह खपत 52 लाख टन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। आशा की जाती है कि रासायनिक खाद के बढ़ने हुए इस प्रयोग से कृषि उत्पादित में आवश्यक वृद्धि सम्भव हो सकेगी। मिट्टी परीक्षण की पर्याप्त सुविधाएँ बढ़ायी जानी चाहिए, क्योंकि मिट्टी के आधार पर ही फसलों के उगाए जाने का नियोजन किया जा सकता है। पाँचवी योजना में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने और उनका उपयोग बढ़ाने के अनिवार्य 150 स्थायी मिट्टी परीक्षा प्रयोगशालाएँ स्थापित किए जाने का प्रावधान है।

8 छोटे और सीमान्त किसानों (Marginal Farmers) को शामिल किया जाना चाहिए। बाराही खेती बड़े पैमाने पर शुरू की जानी चाहिए। शुष्क खेती के विस्तार की भी बड़ी आवश्यकता है।

9 पाँचवी योजना में कृषि-उत्पादकता बढ़ाने के लिए खेती को रोकने तथा शुष्क भूमि के उचित उपयोग और बीहड़ों, तारी तथा रेतीली भूमि को खेती योग्य बनाने का भी सुझाव है।

10 विश्वविद्यालयों और अन्य शोध संस्थानों में किए अनुसन्धानों पर प्रयोग करने में जो कठिनाइयाँ सामने आई हैं उन्हें दूर करने के प्रयत्न किए जान चाहिए। इसके लिए विश्वविद्यालयों अनुसन्धान-संस्थानों और सरकार के बीच समन्वय स्थापित किया जाना आवश्यक है।

11. शुष्क क्षेत्रों में घास, फसलों के पेड़ और वन लगाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में सौर शक्ति के उपयोग तथा हवा भरे पोलिथिलीन के तम्बुओं में खेती करने का पाँचवी योजना में सुझाव दिया गया है। कुछ रेगिस्तानी इलाकों में इस तरह से खेती की भी जा रही है।

12 ऊँचाई वाले इलाकों में भूमि के उचित उपयोग पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उर्वर भूमि क्षरण और भूमि खेती की स्थानीय समस्याओं को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक होगा।

13 कृषि के आधुनिकीकरण के लिए बड़ी मात्रा में Industrial Inputs की आवश्यकता है।

14 कृषि ऋण व साथ सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। कृषि वित्त नियम, सहकारी बैंक एवं राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंको आदि वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण देने की सुविधाएँ हैं। इन सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता है।

सक्षेप में कृषि-उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि-प्रशासन व संगठन को सुदृढ़ बनाने, प्रामाणिक बीजों की पैदावार बढ़ाने, रासायनिक खाद का अधिक मात्रा में और भली भाँति प्रयोग करने सिखाई की उचित व्यवस्था, कटाई के बाद कृषि उपज रखने की समझ-व्यवस्था, बाजार-व्यवस्था आदि की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्रम-उत्पादकता में वृद्धि के उपाय

भारतीय श्रम उत्पादकता का स्तर विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। अतः श्रम-उत्पादकता बढ़ाने के लिए कुछ उपाय आवश्यक हैं—

श्रमिक की Working Conditions असन्तोषप्रद हैं। कार्य करने के लिए अच्छी मशीनें और औजार श्रमिक को नहीं मिलते। कारखानों में श्रमिक की प्राथमिक आवश्यकताओं का अभाव है। अतः श्रमिकों को अच्छे वेतन, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा आदि की सुविधाएँ मिलनी चाहिए ताकि उनकी कुशलता व उत्पादकता में अपेक्षित वृद्धि हो सके।

2. कार्य अध्ययन तथा प्रोत्साहन पुरस्कारों (Work Studies and Incentives) द्वारा भी श्रम-उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है।

3. उत्पादकता-वृद्धि के लिए पर्याप्त कार्यशील पूँजी (Working Capital) आवश्यक है।

4. उत्पादकता-वृद्धि में मानव तत्त्व (Human element) भी एक महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए समय के फेन होने (Plant breakdown), बिजली न मिलने, आवश्यक निर्देशों के अभाव के कारण व्यर्थ में खोए जाने वाले कार्य के घण्टों पर सामयिक रोक लगाई जानी चाहिए साथ ही पदार्थ व यन्त्र सम्बन्धी नियन्त्रण (Scientific material & tool control) और उपयुक्त वर्क-शॉप सुविधाओं की व्यवस्था (Provision for work-shop services) भी श्रम की कुशलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

5. कच्चे माल तथा आधुनिक मशीनरी के अभाव को दूर किया जाना चाहिए। समय पर कच्चा माल न मिलने के कारण बहुत से मानव घण्टे (Man-hours) बेकार हो जाते हैं।

6. श्रम-उत्पादकता के लिए अच्छे औद्योगिक सम्बन्धों का होना अत्यावश्यक है। प्रबन्ध पक्ष की ओर से श्रमिकों को अच्छे वेतन, सुविधाएँ तथा कार्य करने की प्रगती अवस्थाएँ प्रदान कर उनकी प्रगति में रुचि रखना है और श्रमिकों की ओर से सज्जिव सहयोग देना है ताकि उद्योग के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। दोनों ओर से अच्छे औद्योगिक सम्बन्धों के कारण औद्योगिक एकता (Industrial Harmony) विकसित

होती है। सामान्यतः इस प्रकार की पृष्ठभूमि में दोनों वर्गों के हित साधन की दृष्टि से निम्नलिखित क्षेत्रों को लिया जाना चाहिए—

- (1) अधिक उत्पादन,
- (2) सुरक्षापूर्ण व स्वास्थ्य काय-दशाएँ,
- (3) कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण,
- (4) औद्योगिक इकाइयों का उचित विस्तार और स्थायित्व।

इस प्रकार श्रम उत्पादकता में वृद्धि के लिए जहाँ एक ओर श्रमिकों के लिए कार्य की श्रेष्ठ अवस्थाओं और आवश्यक प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था करना आवश्यक है वहीं दूसरी ओर कार्यशील पूँजी का पर्याप्त प्रावधान तथा उत्पादन के सत्र की क्षमता का नियमित रूप से कुशलतम उपयोग करना भी अत्यन्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय उत्पादना परिषद् ने श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण और निरीक्षण सभाओं के विकास, कार्य अध्ययन विधि, उत्पादित-सर्वेक्षण आदि की दिशा में किए गए प्रयत्न महत्वपूर्ण हैं।

औद्योगिक उत्पादकता वृद्धि के उपाय

कृषि उत्पादकता तथा श्रम उत्पादकता के अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादकता का विश्लेषण भी आवश्यक है। औद्योगिक उत्पादकता का सामान्य अर्थ उद्योग में लग साधनों की प्रति इकाई उत्पादकता से लिया जाता है। औद्योगिक उत्पादकता से सम्बन्धित उपायों में मुख्य हैं—Waste Control। वेस्ट कंट्रोल की प्रभाव-शाली व्यवस्था द्वारा उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। पहला आवश्यक कदम हर प्रकार Waste का लेखा करके उसके कारण तथा उसके प्रति उत्तरदायित्व का विश्लेषण करना है। यह सिद्धान्ततः सरल प्रतीत होता है, किन्तु व्यवहार में स्थिति विचरीन देखने का मिलती है। अधिकांश लघु उद्योग इकाइयों के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती जिसके द्वारा यह अनुमान लगाया जाए कि उनके साधन किस सीमा तक बर्बाद जाते हैं। साधनों की बर्बादी के नियन्त्रण के दो प्रभाव होते हैं। एक ओर यह लागत को कम करता है तथा दूसरी ओर उत्पादन-वृद्धि में सहायक होता है। साधनों की बर्बादी के मुख्य रूप हो सकते हैं—(i) व्यर्थ में जान वाले प्रयत्न (Lost efforts), (ii) गति में ह्रास (Lost motions) (iii) अवधारणाओं की अस्पष्टता (Ambiguity of Concepts), एवं (iv) वस्तुओं की अनावश्यक किस्म (Undue variety of materials and products)। इन सभी प्रकार की 'Wastes' को स्टैंडर्डाइजेशन (Standardisation) से नियन्त्रित किया जा सकता है।

'स्टैंडर्डाइजेशन तथा उत्पादितता' (Standardisation and Productivity) की दृष्टि से एक औद्योगिक प्रतिष्ठान के कार्यक्रम को तीन बड़ी श्रेणियों में रखा जा सकता है—प्रबन्ध, इंजीनियरिंग और क्रय (Management, Engineering and Purchase)। प्रबन्ध के अन्तर्गत नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियन्त्रण व प्रशिक्षण सम्बन्धी क्रियाएँ आती हैं। यदि प्रबन्ध-व्यवस्था इन उत्तरदायित्वों को ठीक से निभाती है तो वह उत्पादितता वृद्धि में सहायक होती है।

इन्जीनियरिंग प्रक्रिया के अन्तर्गत उत्पादन से सम्बन्धित डिजाइनिंग, निर्माण-कार्य, किस्म नियन्त्रण (Quality Control) आदि तकनीकी फजन आते हैं। इन तकनीकी फलनों पर उत्पादित निर्भर करती है। अतः उत्पादकता वृद्धि के लिए इन्जीनियरिंग पहलुओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

क्रय नीति का भी उत्पादकता पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आधुनिक उत्पादन-तकनीकी अधिकांश कच्चे माल के स्तर पर निर्भर करती है। यदि स्टैंडर्डिजेशन को ध्यान में रखकर कच्चे माल की खरीद की जा सकती है, तो उत्पादन-व्यवस्था में एक अनिश्चितता व असन्तुलन का तत्त्व आ जाता है। सामान्यतः बिना स्टैंडर्ड की वस्तुएँ खरीदने पर उत्पादकता इस प्रकार प्रभावित होती है—

- (i) समय पर ठीक ढंग का सामान न मिलने से कार्य में दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन रुकावट,
- (ii) किसी काम की बार बार अस्वीकृति तथा उसे बार बार करना (Excessive rejection and re working),
- (iii) दोष पूर्ण वस्तुओं (Defective Products) के उत्पादन को रोकने के लिए अतिरिक्त निरीक्षण कार्य
- (iv) उपरोक्त कारणों से ऊपरी लागत में वृद्धि (Increasing Overhead charges for the above)।

भारत अब क्रेता से विक्रेता में बदलता जा रहा है। दिन प्रतिदिन प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। अतः व्यावसायिक संस्थानों के लिए श्रेष्ठ बिक्री-व्यवस्था करना आवश्यक है। बिक्री में वृद्धि से लागत कम आती है और लागत में कमी से उत्पादकता बढ़ती है।

भारतीय योजना-परिचय के आवंटन का मूल्यांकन

(*Criticisms of Plan Allocation in India*)

योजना परिचय के आवंटन का प्रश्न मूलतः प्राथमिकताओं (Priorities) का प्रश्न है। प्रायः प्रत्येक देश में साधन सीमित होते हैं अतः योजनाओं में किस मद (Item) को कम या अधिक महत्त्व दिया जाए प्रश्न ही योजनाओं में प्राथमिकताओं का प्रश्न है। प्राथमिकताओं की समस्या में दो पक्ष हैं—प्रथम, वित्तीय साधनों की उपलब्धि (Resource Availability); और द्वितीय, उपलब्ध वित्तीय साधनों का आवंटन (Resource Allocation) समस्या के दूसरे पक्ष का विश्लेषण प्रायः देश की क्षेत्रीय आवश्यकताओं (Regional needs), उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी आवश्यकताओं (Production & Distribution needs), प्रौद्योगिक स्थिति (State of Technology), उपभोग तथा विनियोग सम्बन्धी आवश्यकताओं (Consumption and Investment needs) तथा सामाजिक आवश्यकताओं (Social needs) को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इन्हीं के आधार पर योजना में प्राथमिकताएँ निर्धारित की जाती हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएँ (Priorities of First Five Year Plan)

प्रथम योजना में परिचय की राशि प्रारम्भ में 2069 करोड़ रुपये प्रस्तावित की गई सशोधित अनुमानों में यह राशि बढ़ा कर 2378 करोड़ रुपये कर दी गई। योजना पर वास्तविक व्यय 1960 करोड़ रुपये हुआ।

कृषि व सिंचाई

कृषि व सिंचाई के लिए प्रथम योजना के प्रारूप में 823 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए थे, जो कुल प्रस्तावित व्यय का 3.5% था, किन्तु इस मद पर वास्तविक व्यय 724 करोड़ रुपये हुआ जो प्रस्तावित व्यय से 99 करोड़ रुपये कम था। किन्तु योजना के कुल वास्तविक व्यय (1960 करोड़ रु.) में इस मद का प्रतिशत 37% रहा जो प्रस्तावित प्रतिशत से 2% अधिक था।

इस प्रकार प्रथम योजना में कृषि और सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। यह प्राथमिकता उचित थी तथा योजना की पूर्वनिर्धारित व्यूह-रचना (Strategy) के अनुकूल थी, क्योंकि प्रथम योजना की व्यूह-रचना का मूल लक्ष्य देश में प्रौद्योगिकीकरण के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि तैयार करना था। कृषि के विकास से ही अच्छे माल

की आवश्यक पूर्ति प्राप्त हो सकती थी तथा देश की अतिरिक्त श्रम-शक्ति (Surplus labour force) को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते थे। कृषिगत विनियोग की गर्भविधि (Gestation Period) भी औद्योगिक विनियोग की तुलना में बहुत छोटी होती है। कृषिगत विनियोगों से शीघ्र प्रतिफल मिलने लगते हैं। अतः देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए भी कृषि के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता का दिया जाना उचित था तथा ग्रन्थ मदों की तुलना में इस मद पर आवंटित राशि का प्रायोजन योजना के उद्देश्यों के अनुकूल था।

परिवहन और सामाजिक सेवाएँ

परिवहन तथा संचार के लिए इस योजना में 570 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए जो कुल प्रस्तावित व्यय का 24 / था। इस मद पर वास्तविक व्यय 518 करोड़ रुपये का हुआ जो कुल वास्तविक व्यय का 26 / था। सामाजिक सेवाओं के लिए प्रस्तावित व्यय 532 करोड़ रुपये का रखा गया था लेकिन वास्तविक व्यय 412 करोड़ रुपये हुआ। इस प्रकार प्रथम योजना में परिवहन तथा संचार का द्वितीय तथा सामाजिक सेवाओं का तीसरा स्थान रहा।

परिवहन तथा सामाजिक सेवाओं की प्राथमिकता को सरकारी क्षेत्रों में उचित ठहराया गया। परिवहन तथा संचार को दी गई प्राथमिकता को उचित कहा जा सकता है, क्योंकि आर्थिक विकास में परिवहन तथा संचार की सुविधाओं के विस्तार का बड़ा महत्व है। कृषि, उद्योग आदि किसी भी क्षेत्र में प्रगति के लिए कुशल परिवहन तथा संचार सेवाएँ आवश्यक हैं। बाजारों के विस्तार तथा देश के विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़ने में और नवीन आर्थिक क्रियाओं के संचालन में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। किन्तु सामाजिक सेवाओं के लिए निर्धारित व्यय तथा इसको दी गई प्राथमिकता को उचित नहीं कहा जा सकता। यह तो उचित है कि देश के विकास के लिए मानव-तत्त्व की कुशलता को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाएँ मिलनी चाहिए। किन्तु भारत जैसे देश में इस मद पर किए जाने वाले व्यय का अधिकांश भाग प्रशासनिक व्यय के रूप में जाता रहा। सामाजिक कल्याण के नाम पर देश में करोड़ों रुपये का अपव्यय हुआ इस मद में से कटौती कर उद्योग तथा खनिज के विकास पर व्यय की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए थी। विकास की प्रारम्भिक अवस्था में आर्थिक ऊपरी पूंजी (Economic over-heads) का निर्माण सामाजिक ऊपरी पूंजी (Social over-heads) की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है।

उद्योग तथा खनिज

उद्योग तथा खनिज पर इस योजना में 188 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित किया गया था किन्तु वास्तव में केवल 97 करोड़ रुपये ही व्यय हुए। इस मद पर इतना कम राशि का आवंटन अनुचित था।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएँ (Priorities of the Second Five Year Plan)

द्वितीय योजना में 4800 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया।

इस प्रस्तावित राशि के मुक़ाबले वास्तविक व्यय 4672 करोड़ रुपये का हुआ। यह उद्योग-प्रधान योजना थी। इस योजना में कृषि की प्राथमिकता को कम किया गया तथा प्रथम योजना की तुलना में उद्योग तथा खनिजों के लिए एक बड़ी राशि निर्धारित की गई।

कृषि तथा सिंचाई

कृषि तथा सिंचाई के लिए योजना में 1101 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई थी जो कुल प्रस्तावित व्यय का 23 प्रतिशत थी। इस मद पर वास्तविक व्यय 979 करोड़ रुपये का हुआ जो कुल योजना-परिव्यय का 21 प्रतिशत था। प्रथम योजना में इस मद पर व्यय का प्रतिशत जहाँ कुल व्यय का 37 था, वहाँ यह प्रतिशत घट कर इस योजना में केवल 23 रह गया। कृषि के विनियोग को कम करना नियोजकों की अदूरदर्शिता को दर्शाता है। पहली योजना के दौरान खाद्यान्न की अछड़ी स्थिति होने का कारण अछड़ी वर्षा का होना था, किन्तु नियोजकों ने योजना की सफलता मान कर, द्वितीय योजना में कृषि पर कम ध्यान दिया। कृषि विनियोगों में कमी का यह परिणाम निकला कि दूसरी योजना में कृषि के लक्ष्य पूर्ण रूप से असफल रहे और खाद्यान्नों का उत्पादन गिर गया।

परिवहन तथा संचार

परिवहन तथा संचार के लिए योजना में 1385 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए थे कुल परिव्यय के 29 प्रतिशत थे। इस मद पर वास्तविक व्यय 1261 करोड़ का हुआ जो कुल वास्तविक व्यय का 27 प्रतिशत था। जहाँ तक व्यय के प्रतिशत का प्रश्न है, पहली योजना की तुलना में इसमें कोई विशेष अन्तर नहीं आया। पहली योजना में यह प्रतिशत 26 था। किन्तु निरपेक्ष अंकों के रूप में पहली योजना में जहाँ इस मद पर हुए वास्तविक व्यय की राशि केवल 518 करोड़ रुपये थी, वहाँ इस योजना में यह राशि 1261 करोड़ रुपये हो गई। इस मद के लिए इस बड़ी राशि का प्रावधान इस योजना में परिवहन व संचार को दिए गए ऊँचे महत्त्व को स्पष्ट करता है। इस योजना में परिव्यय की दृष्टि से सर्वोच्च प्राथमिकता इसी मद को दी गई। यह प्राथमिकता उचित थी, क्योंकि आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए परिवहन तथा संचार के कुशल तथा तेज रफ्तार वाले साधनों के रूप में आर्थिक ऊपरी पूँजी का होना अत्यावश्यक था।

उद्योग तथा खनिज

द्वितीय योजना में इस मद के लिए 825 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई। वास्तविक व्यय की राशि तो इससे बड़ी अधिक (1125 करोड़ रुपये) थी। कुल प्रस्तावित व्यय में इस मद के प्रस्तावित व्यय का प्रतिशत 19 तथा कुल वास्तविक व्यय में इस मद के वास्तविक व्यय का प्रतिशत 24 रहा। इन प्रकार वास्तविक व्यय का प्रतिशत प्रस्तावित व्यय के प्रतिशत से 5 अधिक रहा। ये आँकड़े इस योजना में उद्योग तथा खनिजों को दिए गए महत्त्व को प्रकट करते हैं। इस मद की योजना में दूसरा स्थान मिला। उद्योगों के क्षेत्र में भी मूल व भारी उद्योगों जैसे

लोहा व इस्पात, मशीन, इंजीनियरी, रासायनिक आदि उद्योगों को विशेष स्थान दिया गया। निर्धारित विनियोगों का अधिकांश भाग इन उद्योगों के लिए प्रस्तावित किया गया। औद्योगीकरण की गति में तीव्रता लाने के लिए इस मद के लिए बड़ी राशि का आवंटन उचित था। पहली योजना में इस मद की उपेक्षा की गई थी जिसके कटु-अनुभव का लाभ उठाते हुए इस योजना में इस मद के लिए किया गया वित्तीय आवंटन (Financial Allocation) सर्वथा उचित था।

सरकारी क्षेत्र में किए गए उल्लेखित व्यय के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में संगठित उद्योग और खनिजों पर 575 करोड़ रुपये व्यय किए गए। देश को औद्योगिक दिशा देने के लिए प्राथमिकता का यह परिवर्तन योजना के उद्देश्यों के अनुकूल था।

सामाजिक सेवाएँ तथा विविध

सामाजिक सेवाओं के मद के लिए योजना में 1044 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया गया था। इस मद पर वास्तविक व्यय 855 करोड़ रुपये का हुआ जो कुल वास्तविक योजना परिचय का 18 प्रतिशत था। प्राथमिकताओं की दृष्टि से इस मद का योजना में काफी ऊँचा स्थान रहा। पहली योजना में सामाजिक सेवाओं के व्यय का प्रतिशत जहाँ 21 था, वहाँ इस योजना में इस मद के व्यय का प्रतिशत 18 रहा। पहली योजना की तुलना में व्यय के प्रतिशत में यह गिरावट उचित थी, क्योंकि प्रथम योजना के सन्दर्भ में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि देश के विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में साधनों का अधिक भाग सामाजिक मदों की अपेक्षा आर्थिक मदों पर अधिक लगाया जाना चाहिए। सामाजिक सेवाओं के व्यय में अनेक प्रकार की 'Leakages' का रहना स्वाभाविक है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएँ (Priorities of the Third Five Year Plan)

तृतीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का परिचय 7509 करोड़ रुपये का निर्धारित किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में इस योजना के दौरान वास्तविक व्यय 8577 करोड़ रुपये का हुआ।

कृषि और सिंचाई

कृषि और सिंचाई के लिए 1718 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए। कुल प्रस्तावित व्यय का यह 23 प्रतिशत था। इस मद पर वास्तविक व्यय 1753 करोड़ रुपये हुआ जो कुल वास्तविक व्यय का 21 प्रतिशत था। प्रतिशत व्यय की दृष्टि से योजना में इस मद को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। 25 प्रतिशत पर प्रथम परिवहन व संचार को तथा 23 प्रतिशत पर द्वितीय स्थान उद्योग और खनिज को मिला।

इस योजना में कृषि-क्षेत्र को द्वितीय योजना की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया गया। कृषि विकास के लिए 1068 करोड़ रुपये तथा सिंचाई-विकास के लिए 650 करोड़ रुपये का निर्धारण इस स्थिति को स्पष्ट करता है कि इन योजना में समस्त व्यय का एक चौथाई भाग कृषि विकास के लिए रखा गया। यह वित्तीय प्रावधान उचित था। देश की बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकता-पूर्ति के लिए

खाद्यान्नो के उत्पादन में भारी वृद्धि अपेक्षित थी। कृषि के क्षेत्र में रही द्वितीय योजना की असफलताओं की पूर्ति के लिए भी तृतीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दिया जाना उचित था।

उद्योग और खनिज

द्वितीय योजना की भांति इस योजना में भी उद्योग और खनिज को प्राथमिकता दी गई। इस मद के लिए 1784 करोड़ रु. प्रस्तावित किए गए जो कुल प्रस्तावित व्यय का 24 प्रतिशत था तथा वास्तविक व्यय इस मद पर 1967 करोड़ रु. हुआ जो कुल वास्तविक व्यय का 23 प्रतिशत था। द्वितीय योजना में देश द्रुत औद्योगीकरण (Rapid Industrialisation) के लिए लोहा व इस्पात खाद, भारी मशीनरी आदि के कारखानों के रूप में ऊपरी आर्थिक पूँजी (Economic overheads) का एक सुदृढ़ आधार निर्मित हो चुका था। अतः इस ऊपरी आर्थिक पूँजी के अपेक्षित उपयोग के लिए यह आवश्यक था कि अधिक से अधिक उद्योग स्थापित किए जावें और औद्योगिक आधार को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए नए खनिजों की खोज की जावे तथा पुराने खनिजों का उत्पादन बढ़ाया जावे। इसलिए इस योजना में उद्योग तथा खनिज पर किया गया वित्तीय आवंटन उचित था। इस मद पर बड़ी राशि का प्रावधान तीव्र आर्थिक विकास और आत्म निर्भरता के लिए आवश्यक था।

परिवहन तथा संचार

परिवहन तथा संचार के लिए 1486 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए, किन्तु वास्तविक व्यय 2112 करोड़ रु. का हुआ जो सभी मदों की अपेक्षा अधिक था। किन्तु वास्तविक व्यय के प्रतिशत की दृष्टि से इस मद का स्थान पहला रहा। तीव्र औद्योगीकरण के उद्देश्य की दृष्टि से परिवहन तथा संचार को अधिक महत्व दिया जाना आवश्यक था। अतः इस मद के लिए किया गया वित्तीय आयोजन उचित था। सामाजिक सेवाएँ

सामाजिक सेवाओं पर योजना में 1493 करोड़ रु. व्यय किए गए जबकि प्रस्ताव 1300 करोड़ रु. का रखा गया था। इस योजना में सामाजिक सेवाओं को वित्तीय आवंटन की दृष्टि से चौथा स्थान दिया गया। दो योजनाओं के बाद कृषि तथा उद्योग का जो आधारभूत ढाँचा निर्मित हुआ, उसके अनुरूप कार्यक्रमों को लागू बढ़ाने के लिए अधिक सहाय्य में कुशल धर्मिकों, इंजीनियरों एवं कृषि विशेषज्ञों की आवश्यकता थी अतः इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सामान्य तथा तकनीकी शिक्षा आदि सामाजिक सेवाओं के लिए निर्धारित 1300 करोड़ रु. की राशि उचित ही थी।

विद्युत् शक्ति

तीव्र औद्योगीकरण के लिए विद्युत् शक्ति को भी प्राथमिकता दिया जाना उचित था। इस मद के लिए प्रथम योजना में 179 करोड़ रु., द्वितीय योजना में 380 करोड़ रु. तथा इस योजना में 1012 करोड़ रु. निर्धारित किए गए। प्रथम योजना की तुलना में इस योजना में देश में बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 6 गुना व्यय वृद्धि का प्रावधान आवश्यक था।

शक्ति विनियोग के आधिकारिक (Indian Energy Survey Committee) द्वारा परीक्षण किया गया। इस समिति के रिपोर्ट की अनुसार देश के सम्मुख औद्योगिक तथा पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्युत् शक्ति उत्पादन के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता थी।

चतुर्थ योजना में प्राथमिकताएँ (Priorities in the Fourth Five Year Plan)

चतुर्थ योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में 15 902 करोड़ रु. का व्यय प्रस्तावित किया गया। तृतीय योजना की भाँति इसमें उद्योग तथा खनिजों का महत्त्वपूर्ण स्थान रखा गया। कृषि तथा उद्योग को लगभग समान महत्त्व दिया गया। तृतीय योजना की अवधि में आर्थिक सकटों के परिणामस्वरूप 'योजना अवकाश' (P'an-holiday) की स्थिति हो गई तथा पंचवर्षीय योजना के स्थान पर तीन वार्षिक योजनाएँ अतः कृषि और उद्योग पर लगभग समान विनियोग के कार्यक्रम योजना के उद्देश्यों के अनुरूप थे। कृषि तथा सिंचाई के लिए 3815 करोड़ रु तथा उद्योग और खनन के लिए 3631 करोड़ रु प्रस्तावित किए गए।

परिवहन तथा संचार को दूसरा स्थान दिया गया। विद्युत् शक्ति के लिए 2448 करोड़ रु का प्रस्ताव किया गया तथा सामाजिक सेवाओं के लिए 2771 करोड़ रु प्रस्तावित किए गए। इन मदों पर प्रस्तावित व्यय की उपरोक्त राशियाँ प्राथमिकता के क्रम में अनुरूप थी, किन्तु मूल्य-स्तर की दृष्टि से इन राशियों को देश की आवश्यकताओं के उचित नहीं कहा जा सकता। विशेष रूप से विद्युत् शक्ति के विकास के लिए अधिकतम साधनों की आवश्यकता थी।

6

चतुर्थ योजना का मूल्यांकन (अप्रैल 1969 से मार्च 1974)

(Appraisal of the Fourth Plan)

उद्देश्य (Objectives)

चतुर्थ योजना का लक्ष्य स्थिरतापूर्वक विकास की गति को तीव्र करना, कृषि के उत्पादन में उतार-चढ़ाव को कम करना तथा विदेशी महापन्ना की अनिश्चितता के कारण उसके प्रभाव को घटाना था। इसका उद्देश्य ऐसे कार्यक्रमों द्वारा लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा करना था जिससे समानता और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन भी मिले। इस योजना में रोजगार और शिक्षा की व्यवस्था द्वारा कमजोर और कम सुविधा प्राप्त वर्ग की दशा को सुधारने पर विशेष बल दिया गया। इस योजना में सम्पत्ति आय और आर्थिक शक्ति को अधिकाधिक लोगों में प्रसार करने और उन्हें कुछ ही हाथों में एकत्र होना से रोकने के प्रयत्न भी किए गए।

योजना का लक्ष्य शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को, जो सन् 1969-70 में 29,071 करोड़ रु था, बढ़ाकर सन् 1973-74 में 38,306 करोड़ रु करने का था। इसका अर्थ था कि सन् 1960-61 के मूल्यों पर 1968-69 के 17,351 करोड़ रु के उत्पादन को सन् 1973-74 में 22,862 करोड़ रु कर दिया गया। विकास की प्रस्तावित औसत वार्षिक चक्रवृद्धि दर 5.7 प्रतिशत थी।¹

परिव्यय और निवेश (Outlay and Investment)

प्रारम्भ में चतुर्थ योजना के लिए 24,882 करोड़ रु का प्रावधान रखा गया था। इसमें सरकारी क्षेत्र के लिए 15,902 करोड़ रु (इसमें 13,655 करोड़ रु का निवेश शामिल है) और निजी क्षेत्र में लगाने के लिए 8,980 करोड़ रु की राशि थी। सन् 1971 में इस योजना का मध्यवर्षीय मूल्यांकन किया गया और सरकारी क्षेत्र के परिव्यय को बढ़ाकर 16,201 करोड़ रु कर दिया गया।

चतुर्थ योजना में सरकारी क्षेत्र का परिव्यय¹

(करोड़ रु० में)

मंड	केन्द्र	राज्य	योग
1 कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र	1,235 (76)	1,508 (9.3)	2 743 (16.9)
2 सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण	17 (0.1)	1,188 (7.3)	1,205 (7.4)
3. बिजली	510 (3.2)	2,370 (14.6)	2,880 (17.8)
4. ग्रामीण और लघु उद्योग	132 (0.8)	122 (0.7)	254 (1.5)
5. उद्योग और खनिज	2,772 (17.1)	211 (1.4)	2,983 (18.5)
6 यातायात और संचार	2,345 (14.5)	638 (3.9)	2,983 (18.4)
7. अन्य	541 (9.6)	1,612 (9.9)	3 153 (19.5)
जिसमें से			
(प्र) शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान	375 (2.3)	529 (3.3)	904 (5.6)
(ब) स्वास्थ्य	151 (0.9)	186 (1.1)	337 (2.0)
(स) परिवार नियोजन	262 (1.6)	—	262 (1.6)
योग	8 552 (52.9)	7,649 (47.1)	16,201 (100.0)

कोष्ठों में दिए गए आंकड़े सम्बद्ध क्षेत्रों से परिव्यय का प्रतिशत बताते हैं।

शेष आंकड़े जिस हद तक राज्यों के हिस्से का कुल परिव्यय 4,600 करोड़ रुपये (जो बाद में संशोधित कर 4,672 करोड़ रुपये कर दिया गया) जिसके लिए केन्द्र और राज्य-द्वारा ब्योरा उपलब्ध नहीं है, उस हद तक केन्द्र का परिव्यय अधिक हो सकता है।

परिव्यय की वित्त-व्यवस्था

(Financing of Plan Outlay)

चतुर्थ योजना में सरकारी क्षेत्र में परिव्यय की वित्त-व्यवस्था अप्रानुसार रही—

चतुर्थ योजना में सरकारी क्षेत्र में योजना परिव्यय की वित्त-व्यवस्था¹
(करोड़ रु० में)

मद	आरम्भिक अनुमान	अन्तिम उपलब्ध अनुमान
1. मुख्यतया अपने साधनों से	7,102 (44.7)	5,475 (33.9)
(1) कराधान की योजना पूर्व दरों पर चालू राजस्व से बचत	1,673	(-) 236
(2) अतिरिक्त कराधान, जिसमें सार्वजनिक उद्यमों की बचत बढ़ाने के उपाय शामिल हैं	3,198	4,280
(3) रिजर्व बैंक के लाभ	202	296
(4) योजना के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए किए गए उपायों से हुई आय को छोड़कर सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की बचत	2,029	1,135
(क) रेल	265	(-) 165
(ख) अन्य	1,764	1,300
2 मुख्यतया घरेलू ऋणों के जरिए	6,186 (38.9)	8,598 (53.2)
(1) सार्वजनिक ऋण, बाजार और जीवन बीमा निगम से सरकारी उद्यमों द्वारा लिए गए ऋणों सहित (शुद्ध)	2,326	3,145
(2) छोटी बचतें	769	1,162
(3) वापिकी जमा, अनिवार्य जमा, इनामी बोंड और स्वयं बोंड	(-) 104	(-) 98
(4) राज्य भविष्य निधियाँ	660	874
(5) इस्पात समानकरण निधि (शुद्ध)	—	—
(6) विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ (शुद्ध)	1,685	1,455
(7) घाटे का वित्त	850	2060
3. कुल घरेलू साधन (1+2)	13,288	1,4073 (87.1)
4. विदेशी सहायता	2 614 (16.4)	2087 (12.9)
5 कुल साधन (3+4)	15 902 (100.0)	16 160 (100.0)

कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े कुल के प्रतिशत हैं।

उपलब्धियाँ (Achievements)¹

चतुर्थ योजना के अन्तर्गत वृद्धि की दर का लक्ष्य 5.7% वार्षिक था, परन्तु 1969-70 में यह 5.7% रही। 1970-71 में यह घटकर 4.9%, 1971-72 में 1.4%, 1972-73 में (-) 0.9 और 1973-74 में 3.1% रह गई। योजना के प्रत्येक वर्ष में कृषि और उद्योग जैसे मुख्य क्षेत्रों में भिन्न प्रकार के हल दिखाई दिए।

चौथी योजना में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 12.9 करोड़ टन था। अन्तिम अनुमानों के अनुसार 1973-74 में यह उत्पादन 10.4 करोड़ टन था। उत्पादन कम होने का मुख्य कारण मौसम था। योजना में अपनाई गई नई कृषि नीतियों से गेहूँ के उत्पादन में नई सफलताएँ मिलीं। हालाँकि चावल का उत्पादन सम्मोषजनक था, परन्तु इस क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय तकनीकी सफलता प्राप्त नहीं हुई। दालों और तिलहनो के उत्पादन में वृद्धि की दर योजना में अपेक्षित वृद्धि की दर से कम थी।

जब चौथी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी तब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और औद्योगिक क्षेत्र की बहुत क्षमता का उपयोग भी नहीं हो रहा था। इसलिए मौजूदा क्षमता का भली प्रकार प्रयोग इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य था। योजना के वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि की दर आँके गए 8 से 10% से कम थी। योजना के पहले चार वर्षों में यह क्रमशः 7.3, 3.1, 3.3 और 5.3% थी। 1973-74 में केवल नाममात्र की वृद्धि (एक प्रतिशत से भी कम) हुई। कुछ उद्योगों में तो उत्पादन की क्षमता कम थी, परन्तु कई अन्य प्रमुख उद्योगों—जैसे इस्पात और उर्वरक की उत्पादन क्षमता का उपयोग करने में बिजली और बच्चे माल की कमी और संचालन की समस्याओं के कारण रुकावट पड़ी।

वाघाओ के बावजूद योजना काल की उपलब्धियाँ सराहनीय रही और राष्ट्र शक्तिशाली ढंग से आत्मनिर्भर तथा कुशल अर्थ-व्यवस्था की ओर बढ़ा। 1 जुलाई, 1975 को 20-सूनी आर्थिक कार्यक्रम के बाद तो देश ने एक नई करवट ली ही है, लेकिन इससे पूर्व की प्रगति को भी हमे स्वीकार करना होगा।

आर्थिक प्रगति आँकड़ों में²

वर्ष	1960-61	1965-66	1973-74
राष्ट्रीय आय			
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन			
वर्तमान मूल्यों पर	13,300 करोड़ रु.	20,600 करोड़ रु.	49,300 करोड़ रु.
स्थिर मूल्यों पर	13,300 करोड़ रु.	15,100 करोड़ रु.	19,700 करोड़ रु.
प्रति व्यक्ति आय वर्तमान			
मूल्यों पर	306 रु.	426 रु.	850 रु.
स्थिर मूल्यों पर	306 रु.	311 रु.	340 रु.

1. India 1976, p 174.

2. भारत सरकार, सङ्ग्रह के दस वर्ष (1966-1975), पृष्ठ 47-53.

376 भारत में आर्थिक नियोजन

मद	1950-61	1965-66	1973-74
कृषि			
कुल बोया गया क्षेत्र	13 करोड़ 30 लाख हैक्टेयर	13 करोड़ 60 लाख हैक्टेयर	14 करोड़ 10 लाख हैक्टेयर
एक से अधिक फसलों वाला क्षेत्र	2 करोड़ हैक्टेयर	1 करोड़	2 करोड़
शुद्ध सिंचित क्षेत्र	2 करोड़ 50 लाख हैक्टेयर	2 करोड़ 70 लाख हैक्टेयर	3 करोड़ 20 लाख हैक्टेयर
उर्वरकों की खपत	3 लाख 6 हजार टन	7 लाख 28 हजार टन	28 लाख 39 हजार टन
खाद्यान्नों का उत्पादन	8 करोड़ 20 लाख टन	7 करोड़ 20 लाख टन	10 करोड़ 36 लाख टन
पशुओं की संख्या	33 करोड़ 60 लाख	34 करोड़ 40 लाख	35 करोड़ 50 लाख
सहकारी ऋण प्राथमिक कृषि सहकारियाँ			
संस्था	2 लाख	2 लाख	2 लाख
सदस्य संख्या	1 करोड़ 70 लाख	2 करोड़ 61 लाख	3 करोड़ 68 लाख
दिए गए ऋण (अल्पावधि और मध्यावधि)	203 करोड़ रु	342 करोड़ रु	315 करोड़ रु.
उद्योग और खनन कोयले का उत्पादन	5 करोड़ 60 लाख टन	7 करोड़	8 करोड़ 10 लाख टन
शुद्ध पेट्रोलियम	4 लाख 54 हजार टन	30 लाख 22 हजार टन	71 लाख 98 हजार टन
लोह अयस्क	1 करोड़ 10 लाख टन	1 करोड़ 80 लाख टन	3 करोड़ 40 लाख टन
अल्युमीनियम	18 हजार टन	62 हजार टन	1 लाख 48 हजार टन
चीनी	26 लाख 99 हजार टन	33 लाख 88 हजार टन	37 लाख 45 हजार टन
घनस्पति	3 लाख 40 हजार टन	4 लाख 1 हजार टन	4 लाख 49 हजार टन
चाय	32 करोड़ किग्रा.	37 करोड़ 46 30 लाख किग्रा	46 करोड़ 50 लाख किग्रा.

वर्ष	1960-61	1965-66	1973-74
काफी	54 हजार टन	62 हजार टन	92 हजार टन
सूती कपड़ा	670 करोड़ मीटर	740 करोड़ मीटर	780 करोड़ मीटर
	5 करोड़	6 करोड़	5 करोड़
जूते (चमड़े और रबड़ के)	40 लाख जोड़े	90 लाख जोड़े	40 लाख जोड़े
कागज और गत्ता	3 लाख	5 लाख	6 लाख
(पेपर बोर्ड)	50 हजार टन	58 हजार टन	51 हजार टन
टायर (साइकिल, ट्रैक्टर और विमानों के)	1 करोड़	1 करोड़	2 करोड़
	12 लाख	86 लाख	21 लाख
टयूब (साइकिल, ट्रैक्टर, और विमानों के)	1 करोड़	1 करोड़	1 करोड़
	33 लाख	87 लाख	46 लाख
अमोनियम सल्फेट	80 हजार टन	84 हजार टन	1 लाख
			21 हजार टन
सुपर फास्फेट	52 हजार टन	1 लाख	1 लाख
		10 हजार टन	20 हजार टन
साबुन	1 लाख	1 लाख	2 लाख
	45 हजार टन	67 हजार टन	11 हजार टन
सीमेन्ट	80 लाख टन	1 करोड़	1 करोड़
		8 लाख टन	47 लाख टन
तैयार इस्पात	24 लाख टन	45 लाख टन	47 लाख टन
डीजल इंजन	55,50 लाख	1 लाख 1,200	1 लाख 37,700
शक्ति वालित पम्प	1 लाख, 9,000	2 लाख 44 हजार	3 लाख 27 हजार
सिलाई मशीनें	3 लाख 3,000	4 लाख 30 हजार	3 लाख
घरेलू रिक्रिजरेटर	11,700	30,600	1 लाख 13,300
बिजली के मोटर	7 लाख	17 लाख	29 लाख
	28 हजार	53 हजार	8 हजार
अश्व शक्ति	अश्व शक्ति	अश्व शक्ति	अश्व शक्ति
बिजली के लैम्प	4 करोड़	7 करोड़	13 करोड़
	85 लाख	21 लाख	32 लाख
बिजली के पखे	10 लाख	13 लाख	23 लाख
	59 हजार	58 हजार	20 हजार
रेडियो सेट	2 लाख	6 लाख	17 लाख
	82 हजार	6 हजार	74 हजार
साइकिलें	10 लाख	15 लाख	25 लाख
	71 हजार	74 हजार	77 हजार

मद	1960-61	1965-66	1973-74
विजली उत्पादन	1,700 करोड़ केडब्ल्यूएच.	3,682 करोड़ केडब्ल्यूएच.	7 275 करोड़ केडब्ल्यूएच
औद्योगिक उत्पादन का सूचक (1960=100)	100	154	201
सामान तैयार करने वाले उद्योग			
पजीकृत कारखाने	43 हजार	48 हजार	80 हजार
उत्पादन पूंजी	2,700 करोड़	8 000 करोड़ रु	14,800 करोड़ रु
रोजगार में लगे मजदूर	33 लाख	39 लाख	60 लाख
व्यावसायिक शिक्षा पाने वाले व्यक्ति (इजीनियरिंग)			
स्नातक	7,500	12,900	14,300
स्नातकोत्तर	500	1,000	1,400
चिकित्सा			
स्नातक	4,700	7,300	10,200
स्नातकोत्तर	500	1,100	1,900
कृषि			
स्नातक	2,600	4,900	4,600
स्नातकोत्तर	600	1,200	1,700
पशु चिकित्सा			
स्नातक	813	889	924
स्नातकोत्तर	104	90	244
रेले			
रेलमार्ग की लम्बाई	57 हजार किमी	59 हजार किमी.	60 हजार किमी.
यात्री किलोमीटर	7,800 करोड़	9,700 करोड़	13,600 करोड़
माल भाड़ा (टन किलोमीटर)	8,800	11,700 करोड़	12,200 करोड़
चालू रोलिंग स्टॉक इंजन	11 हजार	12 हजार	11 हजार
यात्री डिब्बे	28 हजार	33 हजार	36 हजार
माल के डिब्बे	3 लाख	3 लाख	3 लाख
	8 हजार	70 हजार	88 हजार
सड़के			
पक्की	2 लाख	3 लाख	4 लाख
	63 हजार किमी.	43 हजार किमी	74 हजार किमी.
सड़की पर मोटर	6 लाख	10 लाख	20 लाख
गाड़ियों की सख्या	94 हजार	99 हजार	88 हजार

मद	1960-61	1965-66	1973-74
जहाजरानी			
जहाज	172	221	274
सकल रजिस्टर्ड टन-भार	8 लाख	15 लाख	30 लाख
	58 हजार	40 हजार	90 हजार
डाक और अन्य सेवाएँ			
डाकघर	77 हजार	97 हजार	1 लाख 17 हजार
तार घर	12 हजार	13 हजार	17 हजार
टेलीफोन	4 लाख	8 लाख	16 लाख
	63 हजार	58 हजार	37 हजार
समाचार-पत्रों की			
प्रचार संख्या	2 करोड़	2 करोड़	3 करोड़
	10 लाख	50 लाख	31 लाख
रेडियो लाइसेंस	20 लाख	40 लाख	1 करोड़
			40 लाख
टेलीविजन लाइसेंस	—	200	1 लाख
			63 हजार
भुगतान सन्तुलन			
विदेशी मुद्रा कोष	304 करोड़ रु	298 करोड़ रु	947 करोड़
विदेशी व्यापार			
निर्यात	660 करोड़ रु	810 करोड़ रु	2,483 करोड़ रु
आयात	1 140 करोड़ रु	1,394 करोड़ रु.	2,921 करोड़ रु

नोट—1973-74 के आंकड़े स्थायी हैं।

पाँचवी पंचवर्षीय योजना, (1974-79) 1 अप्रैल 1974 से लागू हुई है। योजना अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है तथापि, विभिन्न कठिनाइयों के कारण, योजना के मसौदे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। भारत सरकार की पाँच सितम्बर 1976 की सूचना के अनुसार योजना आयोग ने 4 सितम्बर, 1976 को पाँचवी पंचवर्षीय योजना के मसौदे के अन्तिम रूप पर विचार किया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने की जो योजना आयोग की अध्यक्ष भी हैं। मसौदे पर अन्तिम रूप से विचार करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक दिल्ली में 24 और 25 सितम्बर को बुलाई गई और आवश्यक निर्णय लिए गए। योजना के उद्देश्य

पाँचवी योजना के दृष्टिकोण पत्र को 'आर्थिक स्वतन्त्रता का घोषणा-पत्र' कहा गया है। इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य हैं—गरीबी का उन्मूलन और आत्म-निर्भरता। इस योजना का उद्देश्य है कि जो 30 / लोग इस समय 25 रु प्रतिमास के न्यूनतम उपभोक्ता स्तर पर हैं, उनका स्तर बढ़ाकर 40 68 प्रतिमास (1972-73 के मूल्यों पर) कर दिया जाए यह न्यूनतम बाँछरीय स्तर है। मुख्य प्रयत्न यह होगा कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए—विशेषतया खेतिहर मजदूरों और छोटे और अति लघु किसानों के लिए बड़े स्तरों पर रोजगार उपलब्ध कराया जाय।

राज्यों की योजनाओं के सम्बन्धित भाग में कुछ विशेष कार्यक्रम हैं। उनमें ऐसी उपयोजनाएँ तैयार की गई हैं जिनसे पिछड़े वर्गों का उत्थान हो और पिछड़े क्षेत्रों का विशेषतया पर्वतीय तथा आदिम जातियों के क्षेत्रों का विकास हो। अधिक निर्धन लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी बनाया गया है। योजना का लक्ष्य एक और तो कृषि और औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि को दर की तेजी से बढ़ाना है और दूसरी ओर विकास के बायों में इस तरह धन लगाना है कि मुद्रा स्थिति न हो। राष्ट्रीय उत्पादन में वार्षिक वृद्धि की दर का लक्ष्य 5.5 % रखा गया है।

अन्य बातों के अलावा पाँचवी योजना की रीति-नीति में ये बातें और उल्लेखनीय हैं—(1) उत्पादन बढ़ाने वाले रोजगार का विस्तार, (2) समाज कल्याण कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाना, (3) गरीब लोगों के लिए उचित भागों पर उपभोग वस्तुएँ मिल सकें, इसके लिए पर्याप्त बमूली और वितरण की प्रणाली (4) निर्यात की वृद्धि और आयात होने वाली चीजों की जगह देशी चीजें पैदा करने का ज़ोरदार प्रयत्न, (5) अन्निर्वाह उपभाग पर कड़ाई से पाबन्दी, (6) कीमतों, वेतनों और आयों का समुचित सन्तुलन तथा (7) सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय असमानताएँ घटाने के लिए सहायक, वित्तीय तथा अन्य उपाय।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

पाँचवी योजना में सम्मिलित करने के लिए जो राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम सोचा गया है, उसके अनुसार साधन चाहे कितने हों, फिर भी सामाजिक उपभोग के सब क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ससाधन भी रखे जाएँगे। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में निम्नलिखित प्रावधान हैं—

- (1) 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधाएँ (701 03 करोड़ रुपये),
- (2) रोगों की रोकथाम, परिवार नियोजन, पोषाहार, बाल-मृत्यु के कारण पता लगाने और गम्भीर रोगियों को अच्छे इलाज की सुविधाएँ जुटान समेत सार्वजनिक स्वास्थ्य की न्यूनतम और समान सुविधाएँ (821 67 करोड़ रुपये),
- (3) जिन गाँवों में पानी की हमेशा से किल्लत रही है, या जहाँ शुद्ध जल नहीं मिलता, उनके लिए पीने के पानी की सुविधा (554 करोड़ रुपये),
- (4) 1,500 या इससे अधिक आबादी वाले गाँवों में हर मौसम में काम देने वाली सड़कें (498 करोड़ रुपये),
- (5) भूमिहीन मजदूरों के वास्ते मकान बनाने के लिए विकसित शमीन (107 95 करोड़ रु)
- (6) गन्दी बस्तियों की सफाई और सुधार (94 63 करोड़ रुपये),
- (7) लगभग 40% देहाती आबादी को लाभ पहुँचाने के लिए बिजली देने का प्रयत्न (276 03 करोड़ रुपये जिसमें केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए नियत राशि भी शामिल है)।

वृद्धि-दर

चौथी योजना के अनुभवों से लाभ उठाते हुए, पाँचवी योजना में 5.5% की वृद्धि-दर का जो लक्ष्य रखा गया है, उसके लिए आयोजन और अमल में कहीं अधिक कुशलता के अलावा कठिन निर्णयों, कठोर अनुशासन और बहुत त्याग की आवश्यकता होगी।

पाँचवी योजना के इस 5.5% वृद्धि-दर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले से अधिक पूँजी निवेश, अधिक कुशलता और पहले से अधिक बचत करनी होगी। इस ढंग से आय की असमानताएँ दूर करने और उपभोग की असमानता को घटाने की जरूरत पड़ेगी, जिससे समृद्ध वर्गों पर अधिकाधिक बचत करने का भार पड़े।

योजना का लक्ष्य यह है कि मुद्रा-स्फीति न होने पाए। इस्पात, वीथला, अलुमिना घातुएँ, सीमेंट और उर्वरक उद्योगों जैसे पूँजी-बहुल उद्योगों के विकास के लिए तो पूँजी जुटाना अनिवार्य है ही क्योंकि इनसे ऐसी वस्तुओं का उत्पादन होता है, जो रोजी देने वाली है और जिनका खेती-बाड़ी में भी बहुत उपयोग होता है। इसी प्रकार उन वस्तुओं पर नियन्त्रण रखना होगा, जो न जनसाधारण के उपभोग में आती हैं और न जिनसे निर्यात-वृद्धि में सहायता मिलती है।

पाँचवी योजना में उत्पादन वृद्धि इन बातों पर निर्भर करेगी—(1) जो परियोजनाएँ हाथ में ली जा चुकी हैं, उनका पूरा होना, (2) उत्पादन-क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग, (3) अर्थ-व्यवस्था को ऐसा रूप देना कि जिससे तकनीकी तौर-तरीकों और लोगों के आम व्यवहार में परिवर्तन आए तथा (4) और अधिक निर्यात करने की हमारी क्षमता।

सार्वजनिक उपभोग 7% वार्षिक औसत से बढ़ेगा।

विकास परिव्यय

पाँचवी योजना के लिए 53,411 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित है। इसमें 37,250 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र के लिए और 16,161 करोड़ रुपये निजी क्षेत्र के लिए हैं।

(क) सार्वजनिक क्षेत्र—सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न मदों और क्षेत्रों के लिए निर्धारित परिव्यय की राशि तालिका के अनुसार है—

सार्वजनिक (सरकारी) क्षेत्र के लिए परिव्यय¹

(करोड़ रु में)

मद	केन्द्र (क)	राज्य	सघ राज्य क्षेत्र	योग
1. कृषि	1946	2717	67	4730
2. सिंचाई	140	2515	26	2681
3. बिजली	738	5343	109	6190
4. खनन तथा उत्पादन	8180	742	17	8939
5. निर्माण	25	—	—	25
6. परिवहन तथा संचार	5727	1297	91	7115
7. व्यापार तथा भण्डारण	194	11	—	205
8. आवास तथा सम्पत्ति	237	338	25	600
9. वैज्ञानिक तथा बीमा	90	—	—	90

मद	केन्द्र (क)	राज्य	सघ राज्य क्षेत्र	योग	
10	सावजनिक प्रशासन तथा सुरक्षा	60	30	8	98
11	ग्रन्थ सेवाएँ	1953	3580	257	5790
	(i) शिक्षा	484	1155	87	1726
	(ii) स्वास्थ्य	253	517	26	796
	(iii) परिवार नियोजन	516	—	—	516
	(iv) पोषण	70	330	—	400
	(v) नगर विकास	252	272	19	543
	(vi) जल प्रदाय	16	924	82	1022
	(vii) समाज कल्याण	200	26	3	229
	(viii) पिछड़े वर्गों का कल्याण	55	167	4	226
	(ix) धार्मिक कल्याण	15	38	4	57
	(x) ग्रन्थ	92	151	32	275
12.	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (ख)	419	—	—	419
13	पर्वतीय व आदिम जाति क्षेत्र	—	500	—	500
योग	19577	17073	600(ग)	37250(घ)	

(ख) निजी (गैर-सरकारी) क्षेत्र—पाँचवी योजना के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र में 16161 करोड़ रु व्यय किए जाने का प्रावधान है। खान और विनिर्माण क्षेत्र में कुल मिलाकर 6 250 करोड़ रु. लगाए जाएँगे जिनमें से 5,200 करोड़ रु. बड़े और मध्यम पैमाने के कार्यों में और 1,050 करोड़ रु छोटे और ग्रामोद्योगों में लगाए जाएँगे।

वित्तीय स्रोत

पाँचवी योजना के लिए 53 411 करोड़ रु के परिव्यय के लिए वित्तीय स्रोतों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है—

1	चालू परिव्यय के लिए बजट व्यवस्था	5 850 करोड़ रु
2	देशीय बचत (सरकारी क्षेत्र)	15 075 करोड़ रु.
3	देशीय बचत (गैर सरकारी क्षेत्र)	30 055 करोड़ रु
4	कुल विदेशी सहायता	2 431 करोड़ रु,
योग		53 411 करोड़ रु

सरकारी क्षेत्र में योजना परिव्यय की वित्त व्यवस्था

सरकारी क्षेत्र में योजना परिव्यय की वित्त व्यवस्था इस प्रकार की गई है—

मद	करोड़ रु में 1972-73 के मूल्यों पर
1 1973 74 के करो की दरों पर केन्द्र और राज्य	
सरकार के राजस्व खाता साधन	7348
(क) चालू राजस्व से बचत	5612
(ख) चालू राजस्व से निधियों की स्थानान्तरण	1736
(i) शोधन निधि (सिक्किम फण्ड)	1484
(ii) अन्य निधि (शुद्ध)	252

रुप	करोड़ रु. में 1972-73 के मूल्यों पर
2. सरकारी उद्यमों से कुल बचत	5988
(क) केन्द्र	4331
(ख) राज्य	1657
3. अतिरिक्त माधन जुटाने से	6850
(क) केन्द्र	4300
(ख) राज्य	2550
4. सरकारी, सरकारी उद्यमों तथा स्थानिक निकायों द्वारा बाजार से लिए गए ऋण	7232
5. छोटी बचतें	1850
6. राज्य भविष्य निधियाँ	1280
(क) केन्द्र	680
(ख) राज्य	600
7. वित्तीय संस्थाओं से लिए गए सावधिक ऋण (शुद्ध)	895
(क) जीवन बीमा नियम और रिजर्व बैंक से लिये गए ऋण	755
(ख) अन्य सावधिक ऋण	500
(ग) घटा वित्तीय संस्थाओं की प्रदायगी	(-) 360
8. बैंकों से लिए गए व्यापारिक ऋण (शुद्ध)	1185
(क) बैंकों के बकाया ऋण में वृद्धि	1500
(ख) घटा बैंकों में जमा रकम में वृद्धि	(-) 315
9. एवं जमा पूंजी तथा अन्य	1008
(क) ऋण वित्तीय संस्थाओं द्वारा सावधिक ऋणों की प्रदायगी	128
(ख) अन्य प्राप्तियाँ (शुद्ध)	880
10. जनता में निक्को की खपत (शुद्ध)	81
(क) जनता में खपे कुल निक्का	100
(ख) घटा खजानों और सरकारी संस्थाओं की नकदी में वृद्धि	(-) 19
11. रिजर्व बैंक से दृष्टियों के एवज में लिया गया ऋण	1000
12. सांकेतिक बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाओं के साधनों का भवन-निर्माण कार्यों में निवेश	90
13. समार के अन्य देशों से प्राप्तियाँ (शुद्ध)	2443
(क) देश में आए पण्ड आने से	2243
(ख) अमेरिका की 'रूपया-राशि' से	200
कुल योग	37250

नोट—इसके समान देने बाधों से मिला 400 करोड़ रु. का उधार शामिल है।

निर्देशक सिद्धान्त

(1) परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना, (2) वर्तमान क्षमता का भरपूर उपयोग, (3) मुख्य क्षेत्रों में आवश्यक न्यूनतम लक्ष्यों की प्राप्ति और (4) आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए एक निश्चित न्यूनतम विकास-स्तर की प्राप्ति।

विदेशी सहायता

अनुमान है पाँचवी योजना में विदेशी सहायता कुल पूँजी निवेश का केवल 31 प्रतिशत होगी और सार्वजनिक निवेश का 46 प्रतिशत, जबकि चौथी योजना में यह क्रमशः 82 और 136 प्रतिशत थी। आशा है कि 1985-86 तक देश इस स्थिति में होगा कि अपने साधनों से ऋण सेवाओं और विदेशी मुद्रा की अन्य आवश्यकताएँ पूरी कर सके। लेकिन सामान्य व्यावसायिक शर्तों पर विदेशी पूँजी देश में आने की गुंजाइश रहेगी। 1985-89 तक आर्थिक विकास के मामले में आत्मनिर्भर हो जाने और 62 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से विकास करने की परिकल्पना की गई है।

अनुमान है कि देश के विदेशी मुद्रा कोष में 1978-79 में 100 करोड़ रुपये रह जाएगी और 1985-86 तक यह बिल्कुल समाप्त हो जाएगी।

निर्यात

पाँचवी और छठी योजनाओं में निर्यात में 76 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होने का अनुमान किया गया है और इसके पश्चात् 7 प्रतिशत की दर से। दूसरे शब्दों में देश का निर्यात 1973-74 के 2,000 करोड़ रु से बढ़कर 1978-79 में 2890 करोड़ रु और 1983-84 में 4,170 करोड़ रु और 1985-86 में 4770 करोड़ रु का होने की सम्भावना है। इन वस्तुओं के निर्यात में बहुत अधिक बढोत्तरी की आशा है इजीनियरी का सामान, खनिज, लोहा, दस्तकारियाँ (मोती, रत्न और जेवरों के समेत), सूती कपड़ा, इस्पात, मछली और मछली से बनी चीजें, और चमड़ा तथा चमड़े का सामान। पाँच वर्षों की अवधि में जिस 890 करोड़ रु. की निर्यात वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है, उसमें से लगभग दो तिहाई इन्हीं सात वस्तुओं से प्राप्त होगा।

आयात

पाँचवी योजना के प्रास्ताव में आशा की गई है कि घरेलू उत्पादन में वृद्धि और विकास द्वारा अनेक वस्तुओं जैसे मुलायम इस्पात, नाइट्रोजन और फॉस्फेट युक्त उर्वरक तथा कारखानों के लिए कई सामानों तथा उपकरणों का आयात बन्द किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कई वस्तुओं—जैसे अलौह वस्तुओं का आयात कम किया जा सकता है। देश में ही उदात्त कोयले और पनबिजली का बड़े पैमाने पर आयातित तेल के स्थान पर ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकेगा। तंबाकू के स्थान पर अल्यूमीनियम का प्रयोग किया जा सकता है।

धातुओं, खनिजों और धातु की छीलन का आयात 1978-79 के 380 करोड़ रु से घटकर 1983-84 में 340 करोड़ रु रह जाने का अनुमान है, लेकिन इस्पात

के आयात में कमी की सम्भावना नहीं है। अलौह धातुओं के आयात में वृद्धि होने की सम्भावना है।

मशीनों और परिवहन उपकरणों का आयात 1978-79 के 964 करोड़ रु से बढ़कर 1983-84 में 1010 करोड़ रु और 1985-86 में 1035 करोड़ रु हो जाने का अनुमान है।

द्वितीय साफ किए पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से बने पदार्थों और मशीनों बिजली रखने वाले पदार्थों के कुल आयात में भी वृद्धि की सम्भावना है जो 1978-79 के 811 करोड़ रु से बढ़कर 1983-84 में 1,240 करोड़ रु और 1985-86 में 1,500 करोड़ रु का हो जाने का अनुमान है।

उर्वरकों और उर्वरकों के लिए कच्चे माल के आयात में भी बढ़ोतरी की बल्लना की गई है। इनका आयात 1978-79 के 270 करोड़ रु से बढ़कर 1983-84 में 330 करोड़ रु होने की सम्भावना है।

अन्य आयातित वस्तुओं में महत्वपूर्ण वस्तुएँ रस्ते आदि और कच्चा काजू है। इनका आयात हमारे यहाँ से निर्यात होने वाले तैयार जवाहरानों और काजू की गिरी के लिए आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति के लिए अनुमान किया गया है। हम 1983-84 तक अलवारी कागज और लुग्दी के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। कपास और वस्त्रोत्पत्ति क्षेत्र के मामले में हम लगभग आत्मनिर्भर बन गए हैं।

जड़ाजरानी और पर्यटन का विकास किया जाएगा और प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाले धन में होने वाली गड़बड़ी रोकने का प्रयास किया जाएगा।

वचन और विनियोग

योजनावधि में पूँजी निर्माण की दर में लगातार वृद्धि होने की आशा है। अनुमान है कि पूँजी निर्माण की दर भी कुछ राष्ट्रीय उत्पादन के 13.7% से बढ़कर 1978-79 में 16.3%, 1983-84 में 18.7% और 1985-86 में 19.7% हो जाएगी।

वचन दर भी बढ़ने की आशा है। यह 1973-74 के कुल राष्ट्रीय उत्पादन के 12.2/ से बढ़कर 1978-79 में 15.7/ 1983-84 में 19% और 1985-86 में 20/ हो जाएगी।

इस अवधि में वचन का अनुमान बहुत कुछ जनसाधारण की वचन पर आधारित है। कुल वचन में 7.8/ की वृद्धि का जो अनुमान लगाया गया है उसमें 5.4/ अग्र जन साधारण की वचन का होगा। अनुमान है कि मार्गद्विक वचन दर 1973-74 के कुल राष्ट्रीय उत्पादन के 2.8/ से बढ़कर 1985-86 में 8.2/ हो जाएगी।

काले धन की वृद्धि की रोकथाम

काले धन की उत्पत्ति रोकने के लिए प्रणामनीय, वित्तीय और मूल्य सम्बन्धी नीतियों पर कार्य किया जा रहा है—(क) गहरी भूमि सम्बन्धी नीति जिसमें भूमि का समाजीकरण शामिल है, (ख) कपास या तिलहन जैसी महत्वपूर्ण वृषि ज़िम्मे

के विवरण पर और अधिक परिमाण में सामाजिक नियन्त्रण, और (ग) तस्करी की रोकथाम के लिए कारगर उपाय ।

पर्यटन

पाँचवी योजना में विदेशी पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए होटल परिवहन और अन्य सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है । इसके साथ ही इस बात के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं कि पर्यटन से होने वाली आय गैर-सरकारी हाथों में न चली जाए । ऐसा निर्णय किया गया है कि भारतीय होटलों में ठहरने वाले पर्यटकों को अपने बिल विदेशी मुद्रा में चुकाने होंगे । अनुमान है कि विदेशी पर्यटकों से होने वाली आय जो 1973-74 में 34 करोड़ रु. थी, वह 1978-79 में बढ़कर 49 करोड़ रु. हो जाएगी । पाँचवी योजना की अवधि में विदेशियों के भारत यात्रा करने से कुल 100 करोड़ रु. की प्राप्ति होने का अनुमान है ।

कृषि

पाँचवी योजना में अनाजों की उपज में वार्षिक वृद्धि-दर 4.2% रखी गई है जो चौथी योजना की दर से बहुत कम है । यही बात अधिकांश फसलों पर लागू होती है । योजना में फसलों की उपज के मुख्य लक्ष्य पूरे पाँच वर्षों के लिए निर्धारित किए गए हैं, जबकि अब तक कि योजनाओं में ऐसा नहीं किया गया था । ये लक्ष्य निम्नांकित तालिका में स्पष्ट है—

क्रम	फसल	इकाई	चौथी योजना के पाँच वर्षों की सम्भावित उपज	पाँचवी योजना के पाँच वर्षों के लक्ष्य
1.	चावल	लाख टन में	2,080 00	2,540 00
2	गेहूँ	"	1,260 00	1,680 00
3	मक्का	"	300 00	370 00
4	ज्वार	"	420 00	510 00
5	बाजरा	"	300 00	370 00
6	अन्य अनाज	"	290 00	330 00
7	दाले	"	550 00	650 00
		कुल धान अनाज	5 200 00	6,450 00
8	तिलहन	लाख टन में	415 00	550 00
9.	गन्ना	"	6,350 00	7,750 00
10.	कपास	लाख गॉर्ड	281 00	360 00
11.	पटसन और सन	,	320 00	360 00

फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है—(1) किसी विशिष्ट समस्याओं को सुलझाने के लिए अनुसंधान में वृद्धि, (2) कृषि विस्तार और प्रशासन को मजबूत करना, (3) प्रमाणित बीजों की पैदावार बढ़ाना तथा इन्हें और अधिक किसानों को देना, (4) रासायनिक खाद का

अधिक मात्रा में और भली भाँति प्रयोग, (5) पानी प्रवण, (6) वित्त सस्याओं द्वारा ऋण देने की सुविधाएँ बढ़ाना, (7) बटाई के बाद फसल रखने आदि की सुविधाएँ बढ़ाना तथा इसकी विक्री का प्रबन्ध करना, (8) बाजार व्यवस्था के समर्थन के लिए फसल रखने के लिए पर्याप्त गोदामों की व्यवस्था ।

कार्य पद्धति—कृषि की कार्य पद्धति में भी क्रान्तिकारी सुधार किए जा रहे हैं । पिछले अनुभवों के परिणामस्वरूप खेती में छोटे और सीमांत किसानों को शामिल करने के दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाएगा । बारानी खेती बड़े पैमाने पर शुरू की जाएगी । छोटे किसानों और सीमांत किसानों से सम्बद्ध योजनाएँ मिलान का विचार है । इन योजनाओं को बढ़ाया भी जाएगा । पिछली योजनाओं के दौरान अधिक पैदावार देने वाली जो किस्में विकसित की गईं और जो अच्छी भी साबित हो चुकी हैं, उन्हें पाँचवी योजना के दौरान सिंचाई के कमाण्ड क्षेत्रों के और अधिक इलाकों में बोया जाएगा । पाँचवी योजना में सिंचाई वाले कमाण्ड क्षेत्रों का समन्वित विकास करने के लिए विशाल कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है । यह कार्यक्रम 50 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर लागू होगा और इससे 14 करोड़ हेक्टर भूमि में सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी । इससे न केवल चावल की उपज बढ़ाने में अपितु कई फसलें बोने में सहायता मिलेगी । सिंचाई वाले इन इलाकों में व्यापारिक फसलें बोने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ।

योजना के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं में 'भूमि' खेती रोकना तथा 'भूमि' भूमि का उचित उपयोग प्रायोगिक योजनाओं के अधीन बोहड़ो, खारी और नमकीन तथा रेतीली जमीनों को खेती योग्य बनाना भी है ।

पहाड़ों, विशेषकर हिमालय के इलाकों में और दक्षिण भारत के मालनाड इलाकों में बागवानी बड़े पैमाने पर बढ़ाई जाएगी । बागों में पैदा हुए फलों आदि की विक्री तथा इनसे अन्य लाभ प्रदाय बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा ।

विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं में किए गए अनुसंधानों पर अमल करने के बारे में जो कमियाँ और कठिनाइयाँ सामने आई हैं, उन्हें दूर किया जाएगा । इसके लिए विश्वविद्यालयों अनुसंधान संस्थाओं और सरकार के विस्तार विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा । कृषि अनुसंधान के मुख्य उद्देश्य होंगे—(1) पैदावार बढ़ाकर घनाजों की उपज बढ़ाते जाना, (2) भूमि और जल का वैज्ञानिक ढंग से उपयोग कर परिस्थितियों तथा आर्थिक लाभ को ध्यान में रखकर फसलें बोने का क्रम निश्चित करना, (3) उर्वर भूमि की देखभाल और इसे उपजाऊ बनाए रखना, (4) जल प्रवण, और (5) विरारत को जान बाली फसलों की किस्म और उपज में सुधार ।

रासायनिक खाद—पाँचवी योजना के आधार वर्ष (1973-74) में रासायनिक खाद की खपत लगभग 19.7 लाख टन होने का अनुमान था । पाँचवी योजना के अन्त तक यह खपत 52 लाख टन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है । रासायनिक खाद का समुचित प्रयोग बढ़ाने के लिए मिट्टी-परीक्षा की सुविधाएँ काफी बढ़ाने का विचार है ।

शटिपा धीज—पाँचवी योजना में बीज टेक्नोलॉजी में अनुमधान करने पर काफी ध्यान दिया जाएगा ताकि अच्छे धीज मिल सकें। पाँचवी योजना में 4 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये प्लांट मुख्य रूप से सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्रों में होंगे।

कृषि उपकरण और मशीनें—अनुमान है कि पाँचवी योजना के दौरान देश में ट्रैक्टरों की संख्या 2 लाख से बढ़कर 5 लाख हो जाएगी। इसी तरह शक्ति चालित जुताई की मशीनों की संख्या 10 हजार से बढ़कर लगभग एक लाख हो जाएगी। कृषि उपकरणों और मशीनों का उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए पाँचवी योजना में कृषि इंजीनियरिंग की नई केन्द्रीय संस्था खोलन का विचार है। इन मशीनों को चलाने वालों और इनकी मरम्मत करने वालों को ट्रेनिंग देने के लिए सुविधाएँ बढ़ाई जाएँगी।

उर्वर भूमि और पानी संरक्षण—पाँचवी योजना में लगभग 90 लाख हेक्टर क्षेत्र में उर्वर भूमि और पानी के संरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा। इस प्रकार पाँचवी योजना के अन्त तक उर्वर भूमि और पानी संरक्षण उपायों से लाभान्वित इलाका एक करोड़ 80 लाख हेक्टर से बढ़कर ढाई करोड़ हेक्टर हो जाएगा। सारे देश की भूमि और जल के बारे में सूचना एकत्रित करने और इनका विश्लेषण करने के लिए 'केन्द्रीय उर्वर भूमि सर्वेक्षण संगठन' बनाया जाएगा। पाँचवी योजना के दौरान बड़ी मिर्चाई योजनाओं के नौ नए जलग्रह क्षेत्रों में उर्वर भूमि के संरक्षण का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

कृषि ऋण—अनुमान है कि पाँचवी योजना के अन्त तक उपज के लिए प्रतिवर्ष लगभग 3 हजार करोड़ रुपये के अत्यावधि ऋणों की जरूरत होगी। 1978-79 में सहकारी और व्यावसायिक बैंकों द्वारा लगभग 1700 करोड़ रुपये के अत्यावधि उत्पादन ऋण दिए जाने लगेंगे। पाँचवी योजना में पूँजी लगाने के लिए ऋण लेने का योजना के पाँच वर्षों के लिए सक्षम 2400 करोड़ रुपये रखा गया है। योजना के अन्तिम वर्ष में सहकारी और व्यावसायिक बैंकों द्वारा 1700 करोड़ रुपये के जो अत्यावधि ऋण दिए जाएँगे उनमें से 680 करोड़ रुपये छोटे किसानों को दिए जाएँगे। व्यावसायिक बैंक देश के और अधिक देहाती इलाकों में अपनी शाखाएँ खोलन की नीति जारी रखेंगे। आशा है पाँचवी योजना के दौरान कृषि वित्त निगम कृषि विकास कार्यों के लिए 600 करोड़ रुपये से अधिक रुपये लगाने की सुविधाएँ दे सकेगा।

कृषि मूल्य नीति—योजना के दौरान अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद मूल्यों में अन्तर बनाए रखना होगा। उत्पादन लागत और अन्य बातों को ध्यान में रखकर सभी महत्वपूर्ण फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बुझाई शुरू होने से पहले घोषित कर दिया जाएगा। बाढ़ में खरीद मूल्य की घोषणा की जाएगी और यह आमतौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक ही होगा। कपास, पदसन महत्वपूर्ण तिलहन और अन्य व्यापारिक फसलों के लिए पाँचवी योजना में न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित कर दिया जाएगा।

गोदाम भरना—योजना में विभिन्न सगठनों की सप्रह-क्षमता योजना के प्रारम्भ में लगभग 131 लाख टन से बढ़ाकर योजना के अन्त तक लगभग 218 लाख टन करने का लक्ष्य है। खेती में अन्न सुरक्षित रखने की सुविधाएँ बढ़ाई जाएंगी।

सहकारिता और सामुदायिक विकास

पाँचवी योजना में सहकारी विकास के चार विशेष उद्देश्य होंगे—(1) कृषि सहकारी समितियों (ऋण, सप्लाई, विपणन और तैयारी) को सुदृढ़ करना, जिससे सम्बन्धित समय तक कृषि का विकास होता रहे, (2) विकास क्षम उपभोक्ता सहकारी प्रवृत्ति का निर्माण जिससे उपभोक्ताओं को ठीक भाव पर सामान मिलता रहे, (3) सहकारी विकास के स्तर में, विशेषकर कृषि ऋण के क्षेत्र में, क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करना, और (4) सहकारी समितियों के पुनर्गठन की दिशा में विशेष प्रयास, जिससे वे छोटे और सीमान्त किसानों तथा गरीब लोगों के लाभ के लिए काम कर सकें। योजना में अनुसूचित जनजातियों की भलाई के लिए काफी कार्यक्रम होंगे।

पाँचवी योजना के ग्राम-विकास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य खेती की पैदावार बढ़ाना और गाँव वालों को और अधिक रोजगार जुटाना है। अलग-अलग कार्यों के बजाए 'समूचे गाँव' के विकास के लिए कार्यक्रम बनाए जाएँगे ताकि सभी ग्रामवासियों को उनका लाभ पहुँचे। इस दृष्टि से कार्यक्रम में इन उपायों को प्रमुख स्थान दिया गया है—(1) जमीनों की चकबन्दी, (2) पानी के इस्तेमाल पर अधिकतम नियन्त्रण और सूखे इलाकों में जमीन की नमी कायम रखने की दृष्टि से भूमि का समग्र विकास, (3) सिंचाई का अधिकतम विकास और (4) सारे गाँव के लिए फसलों का कार्यक्रम और यह ध्यान रख कर कि सिंचाई का सबसे अधिक उपयोग कैसे हो। समूचे गाँव सम्बन्धी इस कार्यक्रम को आजमाइशी तौर पर बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के 29 गाँवों में शुरू करने का विचार है।

ग्राम विकास

पाँचवी योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक देहान्तों के रहने वाले सबसे गरीब 30 प्रतिशत लोगों की भासिव खर्च करने की प्रतिव्यक्ति सामर्थ्य बढ़ाना है। इसका अभिप्राय है कि लगभग ढाई करोड़ परिवारों की आमदनी काफी बढ़नी ही चाहिए। यह कार्य निम्नलिखित तीन दिशाओं में यत्न कर पूरा किया जाएगा—

1. छोटे और सीमान्त किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर दुधारू पशु पालने का कार्यक्रम। पशुपालन और मत्स्य पालन के कार्यक्रमों में इस प्रकार के परिवर्तन किए जाएँगे ताकि इनसे कुल उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ छोटे और सीमान्त किसानों तथा कृषि मजदूरों की आर्थिक अवस्था भी सुधरे।

2. शीतकालीन योजना में कुली हुई सिंचाई परियोजनाओं के क्रमशः क्षेत्र विकसित किए जाएँगे तथा देश के जिन इलाकों में अक्सर सूखा पड़ता है उनकी हालत सुधारने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

3. कृषि अर्थ-व्यवस्था के अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों की हालत सुधारने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रमों की बढ़ावा तथा इन पर पूरी तरह ध्यान देकर प्रमत्त करना।

सिंचाई तथा बाढ़-नियन्त्रण

सिंचाई क्षमता में पर्याप्त वृद्धि की जाएगी। विशेष तौर पर सूखे से ग्रस्त इलाकों में। योजना में बड़ी और मझौली योजनाओं के लिए 2,401 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है और उनसे 62 लाख हेक्टर और भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इसमें चालू योजनाओं से होने वाली सिंचाई भी सम्मिलित है।

पाँचवी योजना के आरम्भ में 235 लाख हेक्टर कृषि भूमि में छोटी सिंचाई योजनाओं से खेती की जा रही होगी। योजना के दौरान 60 लाख हेक्टर अतिरिक्त भूमि में लघु सिंचाई योजनाओं से सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी।

निमित्त सिंचाई क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए पाँचवी योजना में कुछ नहरी सिंचाई क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यवाहियों द्वारा एकीकृत क्षेत्र विकास के लिए प्रायोगिक परियोजनाएँ प्रारम्भ किए जाने का प्रस्ताव है—(1) जोतो की तकनीकी (2) भूमि को समतल बनाना और सही आकार देना, (3) पानी की धारा को निर्धारित करना, (4) नालों की सफाई और उनका नियन्त्रण (5) खाद्यों की सफाई की व्यवस्था, (6) जहाँ कहीं आवश्यक हो, वहाँ भूमिगत जल से पूरक सिंचाई व्यवस्था की व्यवस्था, (7) उत्पादन बढ़ाने में अडचन डालने वाले और पुराने सिंचाई नियमों और कानूनों में संशोधन।

पाँचवी योजना में बाढ़-नियन्त्रण के लिए 301 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है, इससे 18 लाख हेक्टर भूमि के बचाव की व्यवस्था हो सकेगी।

विद्युत्

इस क्षेत्र में देश को बड़ी चुनौती का सामना करना है। इसी उद्देश्य में पाँचवी योजना में ये लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं—विजली पूर्ति का स्थिरीकरण, कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रगति, इस्पात उर्वरक तथा कोयला जैसे प्राथमिक उद्योगों के लिए विजली-पूर्ति सुनिश्चित करना, सामाजिक उद्देश्यों के अनुकूल विजली-विकास का नवीनीकरण तथा विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास में तालमेल रखते हुए छठी योजना के लिए पर्याप्त रूप से अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करना। यह प्रस्ताव किया गया है कि पाँचवी योजनावधि में 1655 लाख किलोवाट की नई क्षमता योजना के अन्तिम वर्ष में 330 लाख किलोवाट की क्षमता के प्रभावी संचालन के साथ बढ़ा दी जाए।

उद्योग तथा खनिज

औद्योगिक और खनिज क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित क्षेत्रों के विकास के लिए पाँचवी योजना के दौरान कुल परिव्यय 1 खरब 35 अरब 28 करोड़ रुपये रखा गया है जिसमें 83 अरब 28 करोड़ रुपये अर्थात् कुल का लगभग 62 प्रतिशत परिव्यय सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए है और शेष 52 अरब रुपये निजी तथा सहकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए। सार्वजनिक क्षेत्र में 78 अरब 29 करोड़ रुपये केन्द्रीय परियोजनाओं में तथा 4 अरब 49 करोड़ रुपये राज्यों और केन्द्र प्रशासित प्रदेशों की परियोजनाओं में खर्च करने का प्रस्ताव है।

सार्वजनिक क्षेत्र में केन्द्रीय निवेश की अधिकतम राशि इस्पात, अलौह धातुएँ, उर्वरक, कोयला, पेट्रोलियम और औद्योगिक मशीनरी जैसे उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में खर्च की जाएगी।

हल्के इस्पात से सम्बन्धित प्रमुख कार्यक्रमों में भिलाई का 40 लाख मीट्रिक टन तक विस्तार, एक निर्धारित आधार पर बोकारो का 47.5 लाख मीट्रिक टन तक विस्तार और विशाखापत्तनम् और बिड़नगरम् इस्पात परियोजनाओं के कार्यान्वयन में उन्मुखनीय प्रगति शामिल है। मिश्रित इस्पात के लिए सानेम, दुर्गापुर और मैसूर की परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा। सरकारी क्षेत्र के इस्पात कार्यक्रमों के लिए 16 अरब 22 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

अलौह धातुओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में 443 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। पाँचवी योजना में जो नई परियोजनाएँ शुरू की जाएँगी, उनसे ताँबा, जस्ता, सीसा और अल्यूमीनियम के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने की सम्भावना है। इन्जीनियरी उद्योगों के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं उनके परिणामस्वरूप उत्पादनों में काफी वृद्धि होगी। इनका उत्पादन 1973-74 में 2700 करोड़ रुपये से बढ़कर 1978-79 में 5200 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है। इस वृद्धि का अर्थ आयात में कमी होने के साथ निर्यात बढ़ाना भी है।

वास्तव में पाँचवी योजना में औद्योगिक विकास के कार्यक्रमों के लिए आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय के साथ विकास इन दो उद्देश्यों को सामने रखा गया है। औद्योगिक तथा खनिज क्षेत्र से सम्बन्धित योजना का लक्ष्य वार्षिक विकास दर 8.1 प्रतिशत प्राप्त करना है। इसमें एक ऐसा निवेश तथा उत्पादक प्रणाली की कल्पना की गई है, जो निम्नलिखित बातों पर बल देती है—

- (1) आधारभूत औद्योगिक क्षेत्र का तीव्र गति से विकास,
- (2) निर्यात उत्पादन
- (3) ग्राम उपभोग की वस्तुओं की पर्याप्त सप्लाई,
- (4) अनावश्यक वस्तुओं के उत्पादन पर नियन्त्रण,
- (5) ग्राम तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहन,
- (6) औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास और
- (7) औद्योगिक विकास के लिए विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी का प्रयोग।

ग्रामोद्योग और लघु उद्योग

योजना में लघु उद्योगों पर कुल मिलाकर लगभग 1960 करोड़ रुपये व्यय किए जाएँगे। पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और यह भाशा है कि 60 लाख अनिर्भर लोगों को रोजगार मिल सकेगा। यह विश्वास प्रकट किया गया है कि गरीबी और उपभोग में असमानता कम करने की दिशा में लघु और ग्रामोद्योगों का विकास बड़ा सहायक होगा। इस सम्बन्ध में, योजना में, नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं—

- (1) सही उद्योगों का चुनाव किया जाएगा और उन्हें सलाहकार और

विपणन सेवाओं की सहायता दी जाएगी, (2) लघु उद्योगों और बड़े उद्योगों के बीच समुचित सम्पर्क स्थापित किया जाएगा। इसमें सरकार उपयोगी भूमिका निभाएगी, (3) वित्तीय रियायतें देकर पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, (4) औद्योगिक विकास के लिए दुनियादी अवस्थापना का विस्तार किया जाएगा और बरानी खेती की नई विधियाँ अपनाकर तथा सिंचाई की नई क्षमताओं के उपयोग से उपज बढ़ाई जाएगी और पूंजी विनियोग की बाधाएँ दूर की जाएँगी।

लघु और ग्रामीण उद्योगों के विकास की दशा में की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण कार्यवाहियाँ निम्नलिखित होंगी—

- (1) उद्यमियों को प्रोत्साहन देना और उनके लिए विभिन्न सलाहकार सेवाओं की व्यवस्था जिससे रोजगार के लिए अधिकतम अवसर मिल सकें, विशेषकर स्वयं-रोजगार के अवसर।
- (2) वर्तमान जानकारी और उपकरणों के भरपूर उपयोग की सुविधा।
- (3) उत्पादन तकनीक में सुधार और इसे विकसित करना।
- (4) पिछड़े इलाकों सहित कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों के चुने विकास केंद्रों में लघु उद्योगों को बढ़ावा देना।

आधुनिक लघु उद्योगों का बड़े उद्योगों के सहायक के रूप में और विस्तार किया जाएगा।

परिवहन

पाँचवी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में परिवहन पर कुल परिव्यय 5697 करोड़ रुपये रखा गया है जिसमें 4343 करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र में और 1354 करोड़ रुपये राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों में होगा। परिवहन सम्बन्धी अर्थव्यवस्था में रेलों का स्थान सर्वोपरि बना रहेगा और अब तक की मुख्य प्रवृत्तियाँ भविष्य में भी जारी रहेंगी। परिवहन प्रणालियों में समन्वय पर जोर दिया जाएगा और सभी परिवहन दिशाओं में विकास किया जाएगा। सड़क सम्बन्धी उन कामों को प्राथमिकता दी जाएगी जो चौथी योजना से चले आ रहे हैं।

शिक्षा

पाँचवी योजना में पिछले अनुभवों से सबक लेने और शिक्षा के ढाँचे में कुछ अनिवार्य परिवर्तन करने का प्रयत्न है। शिक्षा व्यूह-रचना में मुख्य जोर चार बातों पर रहेगा—(1) शिक्षा सम्बन्धी अवसरों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की समग्र योजना का अंग समझना, (2) शिक्षा-प्रणाली, विकास की आवश्यकताओं और रोजगार के बीच निकट का तात्सम्य रखना, (3) शिक्षा स्तर में सुधार, और (4) विद्यार्थियों समेत शिक्षा से सम्बद्ध समुदाय को सामाजिक और आर्थिक विकास के काम में शामिल करना।

शिक्षा और रोजगार में निकट सम्बन्ध स्थापित करने के लिए पाठ्यक्रम में ऐसे सुधार किए जाएँगे जिनसे विद्यार्थियों में रोजगार के अनुकूल प्रवृत्ति पैदा हो और

वे कुछ हुनर सीख सकें। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक रूप दिया जाएगा और विश्वविद्यालय स्तर पर भी कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रम चालू किए जाएंगे तथा व्यावसायिक शिक्षा को देश की जनशक्ति सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुसार ढाला जाएगा।

प्रमुख गुरु सुधार-कार्यक्रमों में, पाठ्यक्रम तथा परीक्षा में सुधार, अध्यापन तथा शिक्षा ग्रहण के तरीकों में सुधार, अध्यापकों का प्रशिक्षण, पाठ्य-पुस्तकों में सुधार, शिक्षा प्रक्रिया में जन संचार साधनों का अधिकाधिक उपयोग और भौतिक सुविधाओं में सुधार उल्लेखनीय कदम होंगे।

पाँचवी योजना में प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है और इसके लिए चौथी योजना में जहाँ 237 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान रखा गया था, पाँचवी योजना में 743 करोड़ रुपये का प्रावधान है। पिछड़े हुए इलाकों और देश के सबसे असुविधाग्रस्त वर्गों में शिक्षा के विस्तार पर मुख्य जोर दिया गया है। पाँचवी योजना में शिक्षा के लिए 1,726 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसमें 743 करोड़ रुपया आरम्भिक शिक्षा 241 करोड़ रुपया माध्यमिक शिक्षा और 164 करोड़ रुपया तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए है।

विज्ञान और टेक्नोलॉजी

वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में प्रगति अपर्याप्त और असन्तोषजनक रही है। इस सन्दर्भ में पाँचवी योजना के मुख्य उद्देश्य ये हैं—(1) अर्थव्यवस्था के आधारभूत क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रयत्नों का समर्थन, (2) परमाणु ऊर्जा, बाह्य अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में और अधिक प्रगति की व्यवस्था, (3) मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि जनता की आधारभूत आवश्यकताएँ पूरी करने में योगदान, (4) जिन चुने हुए क्षेत्रों में सामर्थ्य है, उनकी क्षमता बढ़ाना, (5) डिजाइन इंजीनियरी और सलाह, प्राकृतिक साधनों का अनुमान लगाने तथा इनका उपयोग करने कीयले का उचित उपयोग करने और विश्वविद्यालयों में युवकों को प्रशिक्षित करने जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की कमियाँ दूर करना।

वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जहाँ चौथी योजना में कुल 373.57 करोड़ रु (योजना=142.27 करोड़ रुपये + गैर योजना=231.30 करोड़ रुपये) व्यय किए गए वहाँ पाँचवी योजना में कुल 1568.22 करोड़ रुपये (योजना=1033.29 करोड़ रुपये + गैर योजना=534.92 करोड़ रुपये) का प्रावधान रखा गया है।

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और पोषाहार

चौथी योजना में स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर कुल 433.53 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी जिसमें से वास्तव में लगभग 343.91 करोड़ रुपये ही खर्च हुए, जबकि पाँचवी योजना में स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर 796 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों पर पाँचवी योजना के मुख्य उद्देश्य ये हैं—

- (1) न्यूनतम सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था, जो परिवार-नियोजन और गर्भवती माताओं तथा बच्चों के लिए पोषक आहार की सुविधाओं से सम्बद्ध हैं।

- (2) देहाती इलाको में और खासकर पिछड़े तथा जन-जातियो वाले इलाको में स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि तथा प्रादेशिक असन्तुलन दूर करना ।
- (3) छून की बीमारियो, विशेषकर मलेरिया और चेचक पर नियन्त्रण पाने और उन्हें समाप्त करने के प्रयत्नों में वृद्धि ।
- (4) स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बद्ध व्यक्तियों की शिक्षा और ट्रेनिंग में गुणात्मक सुधार ।
- (5) विशेषज्ञ सेवाओं का विशेषकर देहाती इलाको में विस्तार ।

योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम इस प्रकार रखा गया है—

- (1) प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (2) 10,000 की आबादी पर एक उप-केन्द्र, (3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमियाँ समन्वित रूप से दूर करना, (4) प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए और अधिक दवाइयों की व्यवस्था, (5) चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से एक को 30 रोगी शैया वाला ग्राम चिकित्सालय बनाना ।

शहरी विकास, आवास और पीने का पानी

शहरी विकास—पाँचवी योजना में शहरी विकास के लिए कुल 578.55 करोड़ रुपये रखा गया है । 252 करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र में और 326.55 करोड़ रुपये राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए हैं । इसके मुकाबले चौथी योजना में 708 करोड़ रुपये रखा गया था ।

शहरी विकास परियोजनाओं में ग्रन्थ बातों के अलावा बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण और विकास का कार्यक्रम शामिल होगा । गन्दी बस्तियों के वातावरण को सुधार कार्यक्रम पर विशेष बल दिया जाएगा । अनुमान है कि लगभग 7 लाख गन्दी बस्ती-वासिया को लाभ पहुँचेगा ।

आवास—पाँचवी योजना में आवास पर कुल 4,670 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा । इसमें 580.16 करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र में और 3,640 करोड़ रुपये निजी क्षेत्र में होगा । इसके अलावा रेल, डाक तार आदि विभागों द्वारा 450 करोड़ रुपये और खर्च किया जाएगा । योजना के मुख्य उद्देश्य हैं—(1) वर्तमान मकानों की सुरक्षा और सभाल-सुधार, (2) भूमिहीनों को गाँवों में मकानों के लिए करीब 40 लाख प्लॉट देने की व्यवस्था, (3) समाज के कुल दुर्बल वर्गों के लिए मकान बनाने के लिए सहायता देने की वर्तमान योजनाओं को जारी रखना, (4) ऐसी सस्थाओं या अभिकरणों जैसे कि आवास तथा शहरी विकास निगम को जारी निम्न आय और मध्य आय वर्ग के लोगों को सहायता देने की योजनाओं के लिए मदद जारी रखना, और (5) सस्ते इमारती सामान के विकास और अनुमोदन को और तेज करना ।

जलपूर्ति—इस क्षेत्र में योजना के मुख्य उद्देश्य हैं—(1) 1.16 लाख समस्याग्रस्त गाँवों में पीने के पानी की व्यवस्था करना, (2) शहरी इलाकों में

जलपूर्ति योजना जल्दी पूरी करना विशेषकर अछूरी योजनाएँ पूरी करना, (3) जिन इलाकों में सीवर व्यवस्था नहीं है, वहाँ आम शौचालयों की जगह सफाई वाले शौचालय बनाना, (4) कूड़ा इकट्ठा करने और इसको फैकने के आधुनिक तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहन।

रोजगार, श्रम-शक्ति और श्रमिक कल्याण

पाँचवी योजना में कारीगरों के प्रशिक्षण, रोजगार सेवाओं और श्रमिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए 57 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। रोजगार नीति में (1) बेतन पर रोजगार और (2) स्वयं रोजगार सुविधाओं के विकास दोनों पर बल दिया जाएगा।

भारतीय श्रमिक संस्था का पुनर्गठन कर और इसका विस्तार कर राष्ट्रीय श्रमिक संस्था बनाई जाएगी। यह संस्था श्रमिकों से सम्बद्ध मामलों में अनुसंधान के द्वारे में समन्वय स्थापित करने वाली संस्था होगी।

समाज कल्याण

इस क्षेत्र में कुल परिव्यय 229 करोड़ रुपये का है। इसमें से 200 करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र के लिए रक्षे गए हैं। योजना का लक्ष्य कल्याण और विकास सेवाओं का समायोजन करना है और इसके लिए ये उपाय सोचे गए हैं—(क) समाज-कल्याण के विकास और रक्षा के कार्यक्रमों का विस्तार, (ख) दुर्बल वर्गों, विशेषकर बच्चों और स्त्रियों के लिए किए जाने वाले सामाजिक और आर्थिक आयोजनों में समन्वय, (ग) रोजगार के कार्यक्रमों के जरिए कल्याण सेवाओं की वृद्धि, (घ) परिवारों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया कराना, और (ङ) जिन स्त्रियों और बच्चों को संरक्षण की आवश्यकता है, उनके लिए कल्याण के कार्यक्रम और वृद्धों तथा अशक्तों के लिए सहायता।

पुनर्वास

विभिन्न प्रकार के विस्थापितों की समस्याएँ सुलझाने के लिए पाँचवी योजना में अस्थायी रूप से 70 करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई है।

पाँचवी योजना के कुछ प्रश्न चिह्न

देश के अर्थशास्त्रियों और विचारकों ने पाँचवी योजना के दृष्टिकोण-पत्र और प्रारूप की गहराई से जाँचा और उसकी कुछ आधारभूत भ्रान्तियों तथा कमियों की ओर संकेत किया। डॉ. ईश्वरदत्तमिश्र ने अपने एक लेख 'पाँचवी योजना कुछ प्रश्न-चिह्न' के अन्तर्गत इन भ्रान्तियों की ओर अग्रच्छा संकेत दिया। आर्थिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में ऐसी शकाएँ प्रकट की गईं कि पाँचवी योजना भी सम्भवतः पिछली योजनाओं की तरह 'बात बड़ी और काम छोटा' वाली कहावत चरितार्थ करेगी। आलोचना के कुछ प्रमुख बिन्दु ये रहे हैं—

1. योजना में प्रस्तावित व्यय के आधार पर प्राप्त किए जाने वाले भौतिक संसाधनों का संकेत किया गया है पर "बढ़ती हुई कीमतों के कारण परिव्यय और

भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के सम्बन्ध में किए जा रहे आंकलन मृग-मरीचिका के सदृश दीख पड़ते हैं।" कीमतें जिस तेजी से बढ़ रही हैं, वह प्रस्तावित लक्ष्यों को निरर्थक सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं।

2. योजना के मूल में यह मान्यता निहित है कि गरीबी निवारण के लिए तीव्र दर से आर्थिक विकास आवश्यक है। योजना-काल में 5.5 प्रतिशत वार्षिक विकास की दर का लक्ष्य रखा गया है। पिछले दो दशकों में विकास की दर लगभग 3.8 प्रतिशत रही है और विकास की दर का कम होना देश की गरीबी का एक बड़ा कारण रहा है। वास्तव में, गरीबी को आधारभूत आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए 5.5 प्रतिशत विकास की दर (यदि प्राप्त भी हो जाए तो) अपर्याप्त दिखाई देती है। दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार पाँचवी योजना में कम-से-कम 6.2% विकास की दर होनी चाहिए थी।

3. योजना-प्रारूप में आय की विषमताओं को घटाने की बात की गई, पर जब तक आर्थिक विकास की गति तीव्र न हो, सम्भव समानता के सिद्धान्त पर आधारित नीतियाँ भी परिस्थितियों में बुनियादी परिवर्तन नहीं ला सकती। डॉ. ईश्वरदत्तसिंह का तर्क है कि यदि विकास की दर भुक्तिकल से 5.5 प्रतिशत तक ही प्राप्त की गई और समानता के सिद्धान्त पर आधारित नीतियाँ भी परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं ला सकेंगी तो गरीबी-निवारण कैसे होगा? वास्तव में 'गरीबी निवारण' का नारा देना और गरीबी निवारण के लिए कार्य करना दो अलग बातें हैं।

4. योजना-प्रारूप में कीमत मजदूरी-आय नीति का संकेत है तथा इन तीनों में एक उचित सन्तुलन बनाए रखने की बात कही गई है। व्यापार, वसूली और विक्रय के कार्यों में सार्वजनिक क्षेत्र के हस्तक्षेप को बढ़ाकर कीमतों में स्थायित्व लाने की चर्चा सशोधित परिकल्पना में है। एक राष्ट्रीय मजदूरी ढाँचा बनाने की भी बात की गई है। काले धन की मात्रा को भी घटाने का भी संकेत किया गया है। इस प्रकार ये विचार निश्चित रूप से अच्छे हैं, लेकिन प्रश्न व्यावहारिकता का है। व्यापार एवं विक्रय के कार्यों को सरकारी कर्मचारियों के हाथ में देने से कीमतों का क्या हाल हो सकता है, कहना कठिन है। डॉ. ईश्वरदत्तसिंह के शब्दों में, 'सरकारी प्रशासन में पसले हुए भ्रष्टाचार, कार्यकुशलता एवं व्यापारिक अनुभवों की कमी और प्ररणा के अभाव वाले वातावरण में राजकीय व्यापार से सामाजिक कल्याण बढ़ेगा, यह नहीं कहा जा सकता। समान राष्ट्रीय मजदूरी का प्रश्न भी अभी तो दिवा-स्वप्न सा हो लगता है। वैसे कानूनी तौर पर तो निम्नतम मजदूरी अधिनियम भी बहुत दिनों से लागू है, लेकिन बहुत से क्षेत्र इससे अछूते हैं। अभी तो इसका भी ठीक-ठीक व्योरा उपलब्ध नहीं है कि देश में काला धन कितना है। सरकारी अफसरों और कर्मचारियों की छत्र छाया में ही काले धन का बहुत कुछ अर्जन एवं सवर्द्धन होता है। यदि काले धन पर अकुश लगाना है तो सरकारी तन्त्र पर स्पष्ट और कड़े अकुश की आवश्यकता है।'

5. बेकारी निवारण के प्रश्न पर योजनाकारों का स्वर बहुत ऊँचा नहीं दिखाई पड़ता। कहा गया है कि गैर-कृषि क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार के अवसर देने के प्रयास होंगे। लेकिन बहुतों को स्वयं अपने को साकार बनाने के लिए लघु उद्योगों, कृषि, सेवाकार्य, निर्माण-कार्य आदि में अवसर ढूँढ़ने होंगे। शिक्षित बेकारों के बारे में योजनाकार निराश लगते हैं कि सार्वजनिक सेवाओं में तो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से नए निकलने वाले को भी जगह देना मुश्किल होगा। वर्तमान बेरोजगारों का तो प्रश्न ही अलग है।

6 13 जनवरी, 1974 के साप्ताहिक दिनमान में रामावतार चौधरी के लेख 'पाँचवी योजना के लक्ष्य कब पूरे होंगे?' में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की तर्जसगत रूप में आलोचना की गई। योजना आयोग की गणनाओं के अनुसार देश की लगभग 30 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी के अत्यन्त खौफनाक दायरों में है, कुछ अन्य अनुमानों के अनुसार यह प्रतिशत 50 से 55 के बीच है। गरीबी की सरकारी माप को हम सही मान भी ले तो वही 17 करोड़ लोगों को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएँ प्रदान करनी होगी। यह निश्चय ही एक दुष्कर कार्य है। पिछले बीस वर्षों में आर्थिक विपन्नता सूचक अंक में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए पहले तीन योजना कालों में यह सूचक अंक क्रमशः 0.35, 0.30 तथा 0.30 रहा है। अहर्गै क्षेत्र के लिए यह 0.38 (पहली योजना), 0.36 (दूसरी योजना) व 0.36 (तीसरी योजना) था। इन तथ्यों से जाहिर है कि सामाजिक न्याय के अन्तर्गत नाप के बावजूद असमानता में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ है। पाँचवी योजना काल के दौरान आय के पुनर्वितरण के कार्यक्रम इस कल्पना पर आधारित हैं कि यह विपन्नता सूचक अंक 0.32 (1973-74) से घट कर 0.20 (1978-79) हो जाएगा। अब तक की उपलब्धियों की पृष्ठभूमि में तो यह असम्भव ही लगता है। 18 करोड़ लोगों की रोजी-रोटी की ज़रूरतें केवल राष्ट्रीय आय के संकल्पित अतिरिक्त उत्पादन से ही नहीं पूरी हो पाएँगी। इसके लिए समाज के उच्चतम 10 प्रतिशत लोगों को अपने बिलासी उपभोग में भारी कमी करनी पड़ेगी। यह सत्ताशील वर्ग ऐसा होने देगा, इसमें सन्देह है।

7 श्री चौधरी के अनुसार ही, योजना के प्रारूप में सरकारी खर्च में भारी कमी करने की बात भी की गई है। यह कहा गया है कि मावजनिष्ठ उपभोग व्यय केवल 7 प्रतिशत की सालाना रफ्तार से बढ़ेगा पर पिछले दशक का अनुभव तो कोई और ही कहानी कहता है। सार्वजनिक उपभोग व्यय इस दौरान 15 प्रतिशत की वार्षिक की गति से बढ़ रहा है।

8. कृषि की पाँच प्रतिशत सालाना वृद्धि के लिए प्रवृत्ति की कृपा पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ेगा। पिछले बीस वर्षों में कृषि उत्पादन तीन प्रतिशत सालाना से अधिक नहीं बढ़ा है।

9 प्रारूप के अनुसार यदि आय के पुनर्वितरण का क्रम सम्भव हो गया तो भी 1978-79 के अन्त तक 8 करोड़ 64 लाख लोग गरीबी की सीमा से नीचे ही रहेंगे। गरीबी समाप्त नहीं हो पाएँगी।

10. योजना प्रारूप में आयात माँगों का अल्पानुमान किया गया है। कच्चे माल, मशीनी उपकरण तथा विद्युत् और परिवहन उपकरणों की आयात माल अल्पानुमानित हैं। पुनश्च, भारतीय आयातों का ढाँचा ऐसा है कि पाँचवी योजना के पाँच वर्षों में आयातों में केवल 1.5 प्रतिशत की कमी होने की आशा की जा सकती है। निर्यातों की 7.5 प्रतिशत वृद्धि-दर भी कल्पनातीत लगती है। इसके अतिरिक्त निर्यातों को अन्तर्राष्ट्रीय मण्डलों में प्रतिस्पर्द्धा बनाने की बात दबकर रह गई है। कई बार तो निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की कीमत उनके निर्माण हेतु आयात किए गए कच्चे माल की लागत से कम होती है। इस प्रक्रिया में हम विदेशी मुद्रा अर्जित करने की बजाए खोते हैं।

11 योजना में जो विपुल राशि सरकार को देश के अन्दर जुटानी होगी, उसमें करो का आश्रय लिया जाना बड़ा असन्तोषजनक होगा। रिजर्व बैंक की 'रिपोर्ट ऑन कैरेन्सी एण्ड फाइनेन्स' में कहा गया कि आय एवं निगम करो को पुन बढ़ाने से करो की घोरी को प्रश्रय मिलेगा। रिपोर्ट के अनुसार देश में अप्रत्यक्ष करो को लगाने की अब कोई गुँजाइश नहीं रह गई है। उन्हें बढ़ाने से सरकार को घनराशि घटती हुई दर पर प्राप्त होगी। करो को बढ़ाने से एक ओर तो लोगों पर करो का बेतहाशा बोझ बढ़ेगा और दूसरी ओर कीमतों का भी बोझ बढ़ेगा क्योंकि घाटे की वित्त-व्यवस्था अपनाती होगी।

कुछ सुझाव

यद्यपि योजना में अनेक भ्रान्तियाँ एवं कमियाँ हैं तथापि पिछली योजनाओं की अपेक्षा यह अधिक दूरदर्शी है, इसमें सन्देह नहीं और फिर सरकार इस बात को बारम्बार दोहरा रही है कि इस बार योजना के क्रियान्वयन में पोल नहीं की जाएगी। फिर भी, योजना की सफलता के मार्ग में उपस्थित बाधाओं का तो निराकरण करना ही होगा। इस दृष्टि से निम्नलिखित उपाय करने होंगे—

1. सरकार भूत्यों को नियन्त्रित करके मूल्य-स्थिरता प्रदान करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए।

2. जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावशाली ढंग से रोक लगाई जाए और यदि उचित हो तो कानूनी व्यवस्था का भी आश्रय लिया जाए।

3. मजदूरी तो दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है लेकिन उसके अनुपात में उत्पादन बहुत कम हो रहा है। अतः सरकार को पूर्ण सजग रहना होगा कि देश में औद्योगिक हड़तालें न हों। यह उचित होगा कि सरकार पाँच वर्षों के लिए हड़तालों को अवैधानिक ठहरा दे।

4. नौकरशाही की सकीर्ण मनोवृत्ति भी सार्वजनिक क्षेत्र की असफलता का एक प्रमुख कारण रही है। सरकार नौकरशाही के इस दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास करे कि केवल नियम और स्वीकृति के पालन से ही कर्तव्य की इतिथी नहीं हो जाती।

5. योजना की सफलता के मार्ग में एक प्रमुख बाधा यह भी है कि राज्य

केन्द्रीय सहायता की माँग में एक दूसरे से प्रतियोगिता में पड़ते हैं। आँकड़ों को बड़ा-चढ़ा कर पेश करके केंद्र से अधिकाधिक सहायता की माँग की जाती है। केंद्र को चाहिए कि वह राज्यों की इस मनोवृत्ति पर अकुल लगाए। राज्य-सरकारों को भी चाहिए कि वे समय से काम लें और योजना के लाभकारी ढंग से क्रियान्वयन पर बल दें।

6. एकाधिकारी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना भी योजना की सफलता की दिशा में और आर्थिक न्याय की स्थापना की दिशा में एक उपयोगी कदम होगा।

7. खाद्यान्नों का पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए।

वास्तव में कोई भी योजना तभी सफल हो सकती है जब देश में उपलब्ध साधनों का समुचित विदोहन और उपयोग किया जाए। योजना के निर्धारित लक्ष्य तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब जनता केन्द्रीय शासन, राज्य प्रशासन और निजी क्षेत्र परस्पर सहयोग से काम करें। 26 जून 1975 को राष्ट्रीय आवाज की उद्घोषणा और 1 जुलाई, 1975 से 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम लागू करने के बाद से देश में बहुमुखी प्रगति और अनुशासन का एक नया वातावरण बना है और एक वर्ष के अल्पकाल में ही उल्लेखनीय उल्लिख्यता हासिल की गई है। पाँचवी योजना के मसौदे पर पुनर्विचार कर उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

1974-75 और 1975-76 के लिए वार्षिक योजनाएँ (Annual Plans for 1974-75 and 1975-76)

पाँचवी पंचवर्षीय योजना के अग्र के रूप में 1974-75 के लिए जो वार्षिक योजना बनाई गई, उसके परिचय के रूप में 4,844 करोड़ रु की राशि रखी गई। योजना का मुख्य उद्देश्य था—देश के भीतर और बाहर से उठते हुए उन दबावों का सामना करना, जो हमारी अर्थ-व्यवस्था को आघात पहुँचा रहे थे। बढ़ती हुई महंगाई और मुद्रा स्फीति पर प्रभावी अकुल रखने के लिए योजनाकाल में कुछ कठोर कदम उठाए गए। इस वार्षिक योजना में इस्तात, विद्युत् उत्पादन, यातायात और कोयला-उत्पादन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। अन्तर्राष्ट्रीय तेल स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक भी था। अधिक निर्धन व्यक्तियों की गहनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम की पूर्ति की दिशा में भी प्रभावशाली कदम उठाए गए। परिणामस्वरूप, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, पेय-जल, गन्दी वस्तियों की सफाई, ग्रामीण सड़कों तथा विद्युतीकरण की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ।

सन् 1975-76 की वार्षिक योजना के लिए परिचय की राशि 5,978 करोड़ रु रखी गई। इस योजना का मुख्य लक्ष्य स्थायित्व के साथ आर्थिक विकास को गति देना था। विकास रणनीति की व्यूह रचना करते समय वितरणात्मक स्थितियों पर विशेष ध्यान दिया गया। इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि सभी क्षेत्रों में उपलब्ध क्षमताओं का पूर्ण उपयोग हो, भायात में बचत और निर्यात में वृद्धि की जाए। उन परियोजनाओं की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, जो दीर्घकालीन परियोजनाओं की अपेक्षा अल्पकाल में ही लाभ देने वाली हो। सन् 1975-76 की

वार्षिक योजना में विभिन्न मदों पर परिच्यय की राशियाँ निम्न सारणी द्वारा स्पष्ट हैं।

वार्षिक योजना (1975-76) के अन्तर्गत विभिन्न मदों के लिए परिच्यय
(करोड़ रु० में)

विकास की मद	केंद्रीय और कर्ष प्रस्तावित योजनाएँ	राज्य	संघीय-क्षेत्र	योग
1 कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र	278 56	400 26	12 59	691 41
2 सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	11 21	453 18	3 83	468 32
3 विद्युत्	119 01	966 41	16 16	1101 58
4 ग्रामीण और लघु-उद्योग	40 49	30 73	2 67	73 89
5 उद्योग और खनिज	1534 19	109 35	0 48	1644 02
6 यातायात और संचार	835 08	190 43	14 93	1040 44
7 शिक्षा	92 07	110 37	11 65	184 09
8 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	71 27	—	—	71 27
9 स्वास्थ्य	44 09	45 80	5 26	95 15
10 परिवार नियोजन	63 20	—	—	63 20
11 पोषण	3 95	14 95	0 46	19 36
12 जल प्रदाय	1 03	123 28	13 51	137 82
13 आवास और नगर विकास	34 59	98 64	8 93	142 16
14 पिछड़े वर्गों का कल्याण	17 00	31 34	0 79	49 13
15 समाज-कल्याण	11 00	2 38	0 40	13 78
16 श्रम और श्रमिक-कल्याण	1 51	4 88	0 47	6 86
17 अन्य	22 26	44 98	3 97	71 21
18 रोजगार-वृद्धि कार्यक्रम	10 00	44 50	—	54 50
19 पशुधन व प्रादिम जाति क्षेत्र	—	40 00	—	40 00
20 उत्तरी पूर्वी परिपद	—	—	—	10 00
योग	3,106 51	2,711 48	96 10	5 978 09

1976-77 के लिए वार्षिक योजना का दस्तावेज¹

“26 मई को संसद के समक्ष जो वार्षिक योजना का दस्तावेज रखा गया, उसमें पूर्वपेक्षा अधिक आर्थिक विकास दर के साथ साथ 11 करोड़ 60 लाख टन अनाज के उत्पादन तथा औद्योगिक शान्ति की आशा व्यक्त की गई है। योजना आयोग के अनुसार, यदि मूल्य स्थिर रहे, तो वार्षिक योजना से सांख्यिक क्षेत्र में तीव्र विकास होगा। कुल योजना का लक्ष्य 7,852 करोड़ रुपये रखा गया है। सांख्यिक

1 एनू 1976-77 की वार्षिक योजना का दस्तावेज (दिनांक 6-12 जून 1976)—योजना मन्त्री डॉ. शंकर घोष।

क्षेत्र के अतिरिक्त निजी-क्षेत्र में भी तीव्र विकास करने के सम्बन्ध में उठाए गए कदमों को महत्वपूर्ण समझा जा रहा है और यह आशा की जाती है कि पिछले दशक में अर्थतन्त्र में जिस दर से पूँजी सगाई गई थी प्रत्यक्ष अपेक्षाकृत अधिक दर से लग सकती है। उद्योग में इस प्रकार का प्रस्तावित विकास मूल्यों के वर्तमान टाँचे में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि देश में पर्याप्त द्रव्य का भण्डार बन गया है और विदेशी मुद्रा की स्थिति भी सन्तोषजनक है। मूल्यों को स्थिर रखने हेतु आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि में काफी सुधार आ गया है तथा उद्योगों में जाने वाले कच्चे माल जैसे लोहा, कोयला, बिजली इंधन तथा परिवहन आदि तत्वों में पर्याप्त सुधार आ गया है, इनके अतिरिक्त, सरकार द्वारा उठाए गए वित्तीय कदम मुद्रा स्फीति रोकने के लिए पर्याप्त समर्थ जाते हैं।

संसद में योजना मन्त्री डॉ. शंकर घोष द्वारा रखे गए दस्तावेज के अनुसार आपान्-स्थिति तथा बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के कारण औद्योगिक शान्ति पैदा हो गई है। वर्तमान वार्षिक योजना के लिए पूँजी देश में आर्थिक खोतों के द्वारा ही प्राप्त की गई है। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में जो अनुमान लगाया गया था, प्रथम तीन वर्षों में स्थायी खोतों से प्राप्त पूँजी कर दर उससे काफी अधिक रही है। ऐसा अनुमान है कि केन्द्रीय और राज्य-सरकारों के सरकारी उद्यम से 1974-75 और 1975-76 के बीच 2,450 करोड़ रु. वर्तमान वर्ष के लिए और 6 850 करोड़ रु. पंच-वर्षीय योजना की पूरी अवधि के लिए प्राप्त होंगे। वार्षिक योजना में बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के लिए कुल 2,337 करोड़ रु. रखे गए हैं।

इस सन्दर्भ में विभिन्न मुद्दों पर व्यय का आवण्टन इस प्रकार है—भूमि सुधार 37 26 करोड़, छोटी सिंचाई 149 04 करोड़, बृहद् और मध्यम सिंचाई 613 63 करोड़, सहकारिता 57 52 करोड़, विद्युत् 1289 69 करोड़, हाथकरघा-उद्योग 11 70 करोड़, मूमिहीनों के लिए भवन-निर्माण 9 97 करोड़, नव-उद्यमी योजनाएँ 95 लाख गरीब बच्चों के लिए मुफ्त किताबें वागज आदि और पुस्तक बैंक 4 21 करोड़ रुपया।

इसके अतिरिक्त, राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों की योजना से 163 करोड़ से अधिक रुपये निश्चित किए गए हैं। दस्तावेज में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को सामान्य आयोजना का विकल्प नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि यह समर्थक है।

देश में आर्थिक-विकास और मूल्य-वृद्धि पर तथा आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि हेतु जो कदम उठाए गए हैं, उनमें आर्थिक प्रवृत्तियों, कानूनाद्वारा नियंत्रित, जमाखोरी और तस्करी का दमन, सभी प्रकार के माल का निश्चित मूल्य घोषित करने की कानूनी व्यवस्था आदि भी शामिल हैं। इसके साथ-साथ 1975-76 में देश में कृषि-उत्पादन में काफी वृद्धि ने एक अच्छा वातावरण पैदा कर दिया। इस सन्दर्भ में मूल्य-वृद्धि पर रोकथाम का हवाला देते हुए बताया गया है कि इस वर्ष थोक मूल्य निर्देशांक में 9 1% की गिरावट आ गई। औद्योगिक कार्यकर्ताओं के लिए

‘अखिल भारतीय उपभोक्ता-मूल्य-सूचकांक’ में गत वर्ष जून से इस वर्ष के बीच 12.8 प्रतिशत की कमी हुई और कृषि-मजदूरी के लिए 22.1% की।

खरीफ की अच्छी फसल के साथ-साथ पर्याप्त माना में अनाज की वसूली का कार्यक्रम इस वर्ष सफलतापूर्वक चल पड़ा है। 7 मई तक खरीफ की फसल का 66 करोड़ 70 लाख टन वसूल किया गया, जबकि इसी अवधि में गत वर्ष 34 करोड़ 50 लाख टन ही खरीदा जा सका था। अर्थात् देश में अन्न का पर्याप्त भण्डार स्थापित हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में भूमि-सुधार पर बल दिया जा रहा है, और ग्रामों में अधिक रोजगार उत्पन्न करने की योजनाओं पर कार्य हो रहा है। इस सम्बन्ध में, राज्यों में कहा जा रहा है कि भूमि सुधार और अतिरिक्त भूमि के बटवारे का कार्य तेज करें। कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सिंचाई के विकास पर बल दिया जा रहा है। 1975-76 में 25 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त-भूमि को सिंचाई के प्रसंगत लाया गया। अब 50 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त-भूमि की सिंचाई योजना पर अमल हो रहा है।

विभिन्न औद्योगिक उत्पादनो में उत्पादों की वृद्धि रही है। इस सन्दर्भ में कोयला, इस्पात, अल्युमीनियम, नाइट्रोजन उर्वरक, सीमेंट तथा विद्युत् महत्त्वपूर्ण हैं। सावजनिक क्षेत्र के उद्योगों ने अच्छी प्रगति दर्शायी है। इसमें राष्ट्रीय टेक्सटाइल कारपोरेशन के कारखाने भी सम्मिलित हैं। रेलों, बन्दरगाहों के कुशल कार्य के कारण अब व्यापार के प्रवाह में भी गति आ गई है। अब रेलमार्गों से पूर्वाधिका 12% अधिक बर्तन गुजरते हैं। केन्द्रीय सरकार ने स्थानीय सड़क परमिट जारी करने की नीति अपनाई है। अभी तक 5300 परमिट दिए जा चुके हैं।

औद्योगिक वातावरण में कान्तिकारी परिवर्तन आया है, परिणामस्वरूप, उत्पादन बढ़ गया है। मजदूरों को उद्योगों में अपनत्व का महसास दिलाने के लिए मजदूरों की सहूलियत का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है ताकि उद्योगों के सञ्चालन में भी उनका पूरा-पूरा हिस्सा हो।

पिछड़े क्षेत्रों और वर्गों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में 95.4 करोड़ रुपये पिछड़े वर्गों के प्राथिक विकास हेतु निश्चित किए गए हैं। इनमें जनजाति सम्बन्धी छोटी योजनाओं पर 40 करोड़ का व्यय भी शामिल है। 4 करोड़ 14 लाख अनुसूचित वर्ग और जनजातियों के छात्रों को इस योजना से लाभ पहुँचाने वाला है। इसके अन्तर्गत उन्हें विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ मिलगी। इस पर 14 करोड़ रुपये व्यय होंगे। राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को इसी कार्य के लिए 39 करोड़ 49 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। प्रोफेसर दाँतवाला की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो सम्पूर्ण देश में विभिन्न ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के सामाजिक आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करेगी।

यद्यपि वन इसी बात पर दिया जा रहा है कि योजनाओं के लिए घरेलू स्रोतों से धन प्राप्त किया जाए, तथापि विकासशील देश होने के नाते विश्व बैंक की सहायता से भी बहुत सी योजनाएँ और विकास-सम्बन्धी कार्यों को चलाने की आशा

करना अस्वाभाविक नहीं है। इस वर्ष भारत में आर्थिक विकास की अभूतपूर्व प्रगति को देखते हुए विदेशों में भी भारत को आर्थिक सहायता देने के बारे में अच्छा वातावरण बन रहा है। भारत को सहायता देने वाले सहयोगी संगठन ने 1976-77 के लिए 170 करोड़ डॉलर देने का निश्चय किया है। 13 सदस्यीय सहयोगी समिति के सदस्यों ने कुल 100 करोड़ डॉलर देने की घोषणा की है, जबकि घोष 70 करोड़ डॉलर विश्व बैंक ने देने का वायदा किया है। यद्यपि यह गत वर्ष की राशि से 20 करोड़ डॉलर कम है, तथापि वास्तव में सभी देशों ने गत वर्ष की अपेक्षा अपना हिस्सा बढ़ाया है। किन्तु अमेरिकी डॉलर की मजबूत स्थिति के कारण डॉलरों में यह कुल राशि कम हो जाएगी। इस सम्बन्ध में यह महत्वपूर्ण है कि अधिसंख्य देशों ने किसी न किसी रूप में अधिक रियायतें देने की घोषणा की है। उदाहरणार्थ, बेल्जियम ने ऋण पर व्याज 2 से 1% कर दिया है। पश्चिम जर्मनी का कर्जा 10 वर्षों की ब्याज मुक्त अवधि के आधार पर दिया जा रहा है जबकि इसकी प्रदायगी की अवधि 50 वर्ष है। फ्रांस ने सहायता की राशि में 8% की वृद्धि की है। पहले के समान ही ब्रिटेन, डेनमार्क और नार्वे की सहायता पूर्णरूप से अनुदान के रूप में है। स्वीडन ने प्रथम बार अन्य स्कैंडेनेवियाई देशों का अनुसरण किया है। जापान ने सहायता की राशि में कुछ वृद्धि की है। यद्यपि अमेरिका ने इस प्रकार की कोई वृद्धि की घोषणा नहीं की है, तथापि उसने भारत के साथ पी एल 480 का एक समझौता अवश्य किया है।

इस अन्तर्राष्ट्रीय समूह ने आर्थिक क्षेत्र में प्रगति और मूल्य वृद्धि की रोकथाम की सलाहना करते हुए यह आशा व्यक्त की है कि भारत सरकार अपने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, जैसे—निर्यात, कृषि और ऊर्जा पर अधिक ध्यान देनी रहेगी तथा परिवार नियोजन के कार्यक्रम को भी बढ़ावेगी।

इसने इस बात पर जोर दिया है कि भारतीय आर्थिक विकास में कमजोर वर्गों का सहयोग आवश्यक है। 13 राष्ट्रों की इस बैठक में सभी देशों ने भारत के बारे में अनिश्चित जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया। भारतीय प्रतिनिधि श्री एम. जी. कोल ने इस प्रश्नोत्तर को मित्रतापूर्ण बताया। विश्व बैंक के उपाध्यक्ष श्री ग्रैन्स्टेन ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि आर्थिक क्षेत्र में भारतीय कार्यक्रमों की सफलता के प्रसंग में सभी सदस्य देश एकमत थे।

राज का आयोजन

1976-77 की वार्षिक योजना, जिसके मसौदे का विवरण ऊपर दिया जा चुका है, अर्थव्यवस्था में हुए सुधारों की पृष्ठभूमि में तैयार की गई है और इसका मूल मुद्दा स्थिरता तथा सामाजिक न्याय के साथ सम्बृद्धि को प्रोत्साहन देना है। योजना मंत्री डॉ. शंकर घोष ने योजना परिषद के 7 जुलाई, 1976 के अद्यक्ष प्रकाशित अपने लेख 'राज का आयोजन' में योजनाओं की रणनीति, 1976-77 की योजना की सम्भावित सफलताओं और 1975-76 की उपलब्धियों का मूल्यांकन प्रस्तुत किया है। इस लेख के आधार पर हम सुगमतापूर्वक यह अनुमान लगा सकते

हैं कि पाँचवी योजना के शेष वर्षों में आयोजन के प्रति सरकार की नीति क्या होगी। अतः उपयुक्त होगा कि हम, कुछ पुनरावृत्ति के दोष का खतरा उठाकर भी, डॉ. घोष के इस लेख का अवलोकन करें।

भारत ने नियोजित आर्थिक-विकास के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सन् 1951 में हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हुई थी। तब से चार पंचवर्षीय योजनाएँ और तीन वार्षिक योजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। पाँचवी पंचवर्षीय योजना का तीसरा वर्ष चल रहा है। ये सभी योजनाएँ निरन्तर विकास-प्रक्रिया की कड़ी हैं। ये मूलभूत सामाजिक आर्थिक नीतियों में विकास क्रम की एक तस्वीर पेश करती हैं। योजना के प्रत्येक चरण में, बदलती स्थितियों नये अनुभवों व मूल्यांकन के बाद परिवर्तन हुए हैं।

प्रत्येक पंचवर्षीय योजना एक दूरगामी परिप्रेक्ष्य को दृष्टि में रखकर तैयार की गई है। प्रथम योजना 1951 में 1981 तक 30 वर्षों के आर्थिक विकास के आधारभूत रूप में बनाई गई थी। द्वितीय योजना का आयाम 1976 तक का था और तृतीय योजना 1961-76 की 15 वर्षीय योजना के प्रथम चरण के रूप में बनाई गई थी।

इसके पश्चात् 1965 के युद्ध में सहायता देने वाले देशों ने सहायता करने से इन्कार कर दिया। इस कारण 1965-66 तथा 1966-67 की फसले खराब हो गई। उन स्थितियों में नियमित पंचवर्षीय योजना के स्थान पर तीन (1966-69) वार्षिक योजनाएँ बनाई गईं। उसके बाद ही अगली पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ करने की अनुकूल स्थितियाँ उभर सकीं।

आजकल पाँचवी पंचवर्षीय योजना का तीसरा वर्ष चल रहा है। इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि देश 1971-72 से ही आर्थिक विपन्नता के दौर से गुजर रहा है। बंगलादेश की मुक्ति से पूर्व वहाँ से बहुत अधिक शरणार्थी भारत आए, फिर देश के बड़े भागों में अनावृष्टि और बाढ़ का प्रकोप आया। खनिज पेट्रोलियम के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य एकाएक आसमान छूने लगे। साथ ही अनेक वस्तुओं के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में भी खूब उछाल आया। तस्करी, काला बाजारी, कानून व व्यवस्था के प्रति घटती आस्था से स्थिति और भी बिगड़ गई।

लेकिन आपात-स्थिति लागू होने और प्रधानमंत्री द्वारा बीस-सूत्री आर्थिक-कार्यक्रम की घोषणा से आर्थिक तथा राजनीतिक अनुशासनहीनता पर अकुश लग गया। देश की व्यवस्थित प्रगति के लिए उचित परिस्थितियाँ बन गईं। 1975-76 में सबसे उल्लेखनीय घटना मुद्रास्फीति पर काबू पाना था। अक्टूबर, 1974 से मूल्यों में गिरावट का रुख आया था, वह 1975-76 के दौरान भी बना रहा और अक्टूबर, 1975 के बाद से गिरावट-दर और भी तेज हो गई। मार्च, 1976 के प्रथम में थोक-मूल्य निर्देशांक 282.9 था जो पूर्व वर्ष की अपेक्षा 7.9% और सितम्बर, 1974 की अपेक्षा 14.4% कम था। 1975-76 का औसत निर्देशांक 1974-75 की अपेक्षा 3.3% कम था। राष्ट्र की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सन्दर्भ में मुद्रास्फीति का बढ़ाव उलट जाना कोई छोटी उपलब्धि नहीं।

1974 के मध्य मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण हेतु कुछ कदम उठाए गए थे। आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात् कुछ नए कदमों की घोषणा की गई, ताकि मूल्य-स्थिरता बनी रहे। ये निम्नलिखित थे—कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, और तस्करी के विरुद्ध जेहाद, कासे धन के उपयोग पर अकुग, व्यापारियों के लिए कुछ अनिवार्य वस्तुओं की मूल्य-सूची टांगना और स्टॉक की स्थिति बताना कानूनन अनिवार्य किया जाना, चीनी, दनस्पति, सीमेंट, कागज, जैसे उद्योगों में सोल सेलिंग एजेंसी प्रणाली की समाप्ति आदि। साथ ही सरकार ने जखीरेबाजों के विरुद्ध विस्तृत पैमाने पर अभियान चलाया। इससे व्यापारी वर्ग और उपभोक्ता वर्ग दोनों की मनोवृत्ति बदली है।

आवश्यक उपभोक्ता-वस्तुओं की सार्वजनिक-वितरण-प्रणाली को और भी मजबूत किया गया है ताकि गांवों, पहाड़ों और बंसी वाले तटीय क्षेत्रों में रहने वाले समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों व छात्रों को लाभ पहुँचे। वितरण-प्रणाली में सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की भूमिका बड़ी है। नागरिक आपूर्ति विभाग कुछ विशेष अनिवार्य वस्तुओं के उत्पादन, मूल्य और आपूर्ति-व्यवस्था की देखरेख कर रहा है। दिल्ली व नैनीताल में एक 'मॉडल योजना' प्रारम्भ की गई है, जिसे बाद में अन्य स्थानों पर भी लागू किया जाएगा।

रबी और खरीफ फसलों के बमूली मूल्य गत वर्ष जितने ही रहे गए। ये स्थिर-मूल्य-नीति के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। साथ ही, सरकार यह भी चाहती है कि कृषकों को उनकी मेहनत का उचित फल मिले। इसलिए रबी की, जो बचने की फसलों के लिए भी समर्थन दिया गया। ईल, पटसन और नियन्त्रित कपड़े का मूल्य भी अपरिवर्तित रहे। इसके अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न व खाद्य तेलों के आयात की भी व्यवस्था की गई, ताकि सुरक्षित भण्डार बनाकर उन वस्तुओं की उपलब्धि बढ़ाई जा सके।

सन् 1976-77 की वार्षिक योजना, अर्थ-व्यवस्था में हुए इन सुधारों की पृष्ठभूमि में तैयार की गई है। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि योजना व्यय में वृद्धि से मुद्रास्फीति को प्रोत्साहन न मिले।

इस वार्षिक योजना का मूल मुद्दा, स्थिरता और सामाजिक न्याय के साथ सम्बृद्धि को प्रोत्साहन देना है। इसके लिए 78 अरब 52 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जो गत वर्ष की अपेक्षा 31.4% अधिक है। इसमें कृषि, सिंचाई, ऊर्जा, उद्योगों और खनिज-क्षेत्रों के लिए विशेष व्यवस्था है। ये अर्थ-व्यवस्था के आधारभूत क्षेत्र हैं। कृषि व सम्बद्ध सेवाओं पर पूर्व वर्ष के 6 अरब 91 करोड़ 41 लाख रुपये की अपेक्षा 8 अरब 96 करोड़ 22 लाख रुपये, सिंचाई व बाढ़ नियन्त्रण पर 4 अरब 68 करोड़ 22 लाख रुपये की अपेक्षा 6 अरब 86 करोड़ 79 लाख रुपये और ऊर्जा पर 11 अरब 1 करोड़ 58 लाख रुपये की अपेक्षा 14 अरब 53 करोड़ 40 लाख रुपये के परिणाम की व्यवस्था की गई है।

सन् 1976-77 में साधान 11 करोड़ 60 लाख टन, ईल 15 करोड़ टन,

कपास 75 लाख गॉटों (प्रत्येक 170 कि.ग्रा की), पटसन व सन 65 लाख गॉटों (प्रत्येक 180 कि.ग्रा. की) का उपज लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यदि मौसम गत वर्ष के समान ही अनुकूल रहा, तो सम्भव है, उत्पादन लक्ष्य से भी अधिक हो। इसके लिए यह नीति तय की गई है कि उर्वरकों की खपत बड़े, सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र बड़े, अधिक उपज देने वाली किस्मों को अधिक विस्तृत पैमाने पर उगाया जाए और सरक्षस के उन्नत तरीके अपनाए जाएँ।

छोटी, मझुली व बड़ी सिंचाई योजनाओं से 20 लाख हैक्टेयर प्रतिरिक्त भूमि में सिंचाई-व्यवस्था की जाएगी। 1975 में 40 जिलों में दालों का सघन विकास-कार्यक्रम चल रहा है। इसके प्रतिरिक्त तिलहन, कपास, पटसन आदि प्रमुख नकदी फसलों के साथ-साथ, चीनी मिलों के आस पास के क्षेत्र में गन्ना विकास का कार्यक्रम भी तेज किया जाएगा।

छोटे व सीमान्त-किसानों, विशेष रूप से घर्दशुष्क क्षेत्रों के, की उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न विकास कार्यों पर 93 करोड़ 83 लाख रु व्यय किए जाएंगे।

उद्योगों व खनिजों के लिए गत वर्ष, जहाँ 16 अरब 44 करोड़ 2 लाख रुपये व्यय किए थे, वहाँ इस वर्ष 21 अरब 85 करोड़ 34 लाख रु की व्यवस्था की गई है।

औद्योगिक विवास के तेज होने के आसार हैं। इस्पात कोयला सीमेंट, ऊर्जा व यातायात जैसे उत्पादनों में पूर्वापेक्षा सुधार आया है। स्थिति के और भी सुधरने की आशा है। 1976-77 में विद्युत् उत्पादन की स्थापित क्षमता में 25 लाख किलोवाट की वृद्धि होने की सम्भावना है। रेलों में भी पूरी तैयारी है कि गत वर्ष की 21 करोड़ 40 लाख टन माल दुनाई की अपेक्षा इस वर्ष 22 करोड़ 50 लाख टन माल की दुलाई का लक्ष्य पूरा किया जाए। इन सबसे यह आशा बधती है कि इस वर्ष आर्थिक वृद्धि की दर गत वर्ष की अपेक्षा अधिक रहेगी।

इस वार्षिक योजना में बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अनेक मुद्दों को विशेष महत्व मिला है। इन कार्यक्रमों को वर्तमान योजनाओं में समाहित करने के प्रयास किए गए हैं। बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम से सम्बद्ध विभिन्न योजनाओं के लिए 1 अरब 63 करोड़ 71 लाख रु रखे गए हैं। हमारी योजना-नीति में खाद्य व कृषि क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण है। खाद्यान्न की उपज व वितरण, स्वावलम्बी होने के लक्ष्य में अतिव्यापक जुड़े हैं और ग्राम व रोजगार के वास्तविक स्तर जुड़े हैं हमारे पुनर्वितरण के लक्ष्यों से।

वर्तमान योजना में इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बड़ी, मझुली व छोटी सिंचाई योजनाओं में हर मामले की जाँच करके खर्च की स्वीकृति दी जा रही है, ताकि चालू योजनाएँ शीघ्रता से पूरी की जा सकें। भूगत जल के अन्वेषण व उपयोग पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान स्थिति में ऊर्जा के अन्य स्रोतों को ढूँढना राष्ट्रीय आयोजना का अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके लिए कोयला क्षेत्र में और अधिक पूंजी लगानी होगी तथा इस क्षेत्र का समन्वित विकास

करना होगा। साथ ही पेट्रोलियम की खपत घटानी होगी। यह उद्देश्य पेट्रोलियम का विकल्प ढूँढ कर, आर्थिक उपाय अपनाकर और देश में पेट्रोलियम के बड़े हुए उत्पादन द्वारा प्राप्त करना होगा।

आयोजना की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि राज्य व उप क्षेत्रीय स्तर पर आयोजना तन्त्र को सुदृढ़ किया जाए और राष्ट्रीय व प्रादेशिक योजनाओं में निश्चित कृषि-नीतियों को ध्यान में रखते हुए, फसलों की योजना पर तथा कृषि पर आधारित क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाए। भारत में रोजगार देने की योजनाओं को ग्रन्थ योजनाओं से सम्बद्ध करना होगा तथा यह भी ध्यान रखना होगा कि उत्पादन पर इनका अनुकूल प्रभाव पड़े। हमारी योजना में छोटे व सीमान्त कृषकों व भूमिहीन मजदूरों की सामर्थ्य बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है ताकि योजना-कार्यों में लगने वाले धन का लाभ कमजोर वर्गों को मिल सके। बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में भूमि मुआवज़े पर विशेष बल दिया गया है और ग्रामीण जनसंख्या के दलित वर्गों के अधिकारों की रक्षा पर भी ध्यान दिया गया है।

हमारी आज की नियोजित प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य ग्रन्थ-व्यवस्था के मूलभूत लक्ष्यों को पूरा करना है। ये हैं—गरीबी उन्मूलन और स्वावलम्बन की उपलब्धि।

आर्थिक कार्यापलट के प्रति निराशा का कोई कारण नहीं

1972-74 हमारे देश के लिए घोर आर्थिक संकट के दिन थे। इन दिनों उत्पादन में ठहराव के साथ-साथ स्फीतिकारी परिस्थितियाँ पैदा हो गई थी। इस संकट पर विजय प्राप्त करने में हमारे देश को जो सफलता मिली, उससे हमारे देश की ऐसी क्षमता का संकेत मिलता है कि यदि राजनीतिक सफलता बना रहे तो वह संकट की प्रत्येक स्थिति का डटकर सामना कर सकता है। श्रवतूवर, 1975 से मूल्यों के गिरते रहने, वर्ष 1975-76 में वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियों के उत्पन्न होने और नए आर्थिक कार्यक्रम के लागू किए जाने के कारण आर्थिक समय पर बहुत अधिक जोर देने से अधिक उद्देश्यपूर्ण रीति से विकासोन्मुख नीति अपनाए के लिए हमारा माग अब साफ हो गया है।

यद्यपि विजली उर्वरक और अच्छे बीजों की सप्लाई में सामान्यतः सुधार होता 1976-77 में खेती की अच्छी पैदावार होने की दिशा में एक शुभ लक्षण है, तथापि खेती की पैदावार में हर वर्ष घट-बढ़ का होना स्वाभाविक है। किन्तु, आगामी वर्षों में 50 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में सिंचाई के बड़े और मध्यम दर्जे के साधनों की व्यवस्था किए जाने के लक्ष्य को, जो नए आर्थिक कार्यक्रम का एक आवश्यक अंग है, सफलतापूर्वक प्राप्त करने से कृषि की पैदावार में न केवल वृद्धि होने लगेगी, बल्कि पैदावार में बहुत अधिक घट-बढ़ होने की जो प्रवृत्ति है, वह भी कम हो जाएगी। हाल में अन्तर्राष्ट्रीय जल विवादों का जिस गति से निपटारा हुआ है, उससे राष्ट्रीय जल साधनों के तेजी से और युक्ति सगत विरास में सहायता मिलनी चाहिए। अधिक गाँवों में विजली लगाने से सिंचाई सम्बन्धी छोटे निर्माण कार्यों, जैसे—पम्पिंग-सेट लगाने में और अधिक धन लगाने की और बढ़ावा मिलेगा।

विद्युत, लोहा, इस्पात तथा सीमेंट के उत्पादन में उत्साहवर्धक वृद्धि होने के कारण, यह आशा बंध गई है कि उद्योगों में काम आने वाली वस्तुओं की कमी से 1976-77 और बाद के औद्योगिक उत्पादन में कोई विशेष बाधा नहीं पड़ेगी। कृषि से प्राप्त होने वाले औद्योगिक कच्चे मान का जितना भण्डार मिलेगा उससे आशा है कि कृषि पर आधारित मुख्य उद्योगों के विकास पर कच्चे माल की कमी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वर्तमान स्थिति में 1976-77 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की सम्भावना काफी आशाजनक है। अनाज की वसूली और अनाज के आयात की सम्भावित मात्रा को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि देश के पास अब प्रभूत मात्रा में अनाज का स्टॉक होना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों की अनिश्चितता और मन्दी की स्थिति के कारण, निर्यात की सम्भावनाएँ हालाँकि यद्यपि कुछ अनिश्चित बनी हुई हैं, लेकिन देश की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित-निधि की स्थिति ऐसी है कि निवेश के क्षेत्र में और अधिक वृद्धि करने के लिए सुनियोजित तरीके से कुछ उपाय किया जा सकता है। इस समय देश में और विदेशों में ऐसी परिस्थितियाँ हैं, कि भविष्य में उत्पादन के लिए काफी पूँजी लपटाई जा सकती है।

वर्तमान संकेतों के अनुसार 1976-77 में पाँचवी योजना के शेष वर्षों में और अर्थ-व्यवस्था में वृद्धि की समग्र दर में विगत 15 वर्षों की दीर्घ अवधि से चली आ रही दर की अपेक्षा स्पष्ट सुधार होना चाहिए। लेकिन हमें समग्र विकास-दर को 5.5% के सुनियोजित लक्ष्य के आस-पास तक स्थिर करने के लिए अभी लम्बा रास्ता तय करना है। भविष्य की अपनी नीति निर्धारित करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 1975-76 और 1976-77 में जो इतना अधिक आर्थिक विकास हुआ है, वह बहुत हद तक मौसम के अनुकूल रहने के कारण भी हुआ है। इसीलिए अधिक गतिशील अर्थ-व्यवस्था प्राप्त करने के लिए जो कार्य करना है, उसकी गुरुता के बारे में हमें किमी भ्रम में नहीं पड़े रहना चाहिए।

वर्तमान के वर्षों में भारत में जो आर्थिक प्रगति हुई है, उसके विश्लेषण से प्रकट होता है कि आगामी वर्षों में, आर्थिक विकास की दर को अपेक्षाकृत अधिक ऊँचे स्तर पर बनाए रखने हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों में और अधिक प्रयत्न करने होंगे—

- (क) घरेलू बचत-दर में उत्तरोत्तर वृद्धि,
- (ख) निर्यात-संवर्धन का और जोरदार कार्यक्रम बनाकर तथा विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं के प्रयोग को प्रोत्साहन देकर देश की भुगतान-क्षमता को और दृढ़ करना,
- (ग) बुनियादी विन्नी-धोष्य वस्तुओं का और अधिक उत्पादन तथा उनके समान रूप से वितरण की अधिक कारगर व्यवस्था; और
- (घ) इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए और ज्यादा कारगर उपाय करना कि हमारे समाज के निर्धन वर्गों के व्यक्तियों को आर्थिक विकास से प्राप्त लाभों में पर्याप्त हिस्सा मिले।

इस बात पर जितना जोर दिया जाए उतना ही कम है क्योंकि सुनियोजित विकास के किसी कार्य को सोद्देश्य रूप में पुनः प्रारम्भ करने हेतु देश में पर्याप्त रूप से प्राथमिक बचन के जुटाए जाने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र के बड़े हुए परिणय की वित्त-व्यवस्था करने के लिए पिछले अनुभव के आधार पर, घाटे की वित्त व्यवस्था पर बहुत अधिक निर्भर करना उत्पादन के विरुद्ध और हानिकारक सिद्ध हो सकता है। मुद्रा-स्फीति किए बिना पर्याप्त घरेलू साधन न जुटा पाना ही हमारी विकास-प्रक्रिया की सबसे बड़ी कमजोरी रही है। अतः वर्तमान वर्षों में, मूल्यों की स्थिरता के सम्बन्ध में आर्थिक विकास में तेजी लाना मुख्यतः देश में प्राथमिक-बचन के साधन जुटाने के लिए नई नीतियाँ बनाने की हमारी क्षमता पर काफी अधिक निर्भर करता है।

हमारी नई नीति में बचत करने पर ही अधिक बल नहीं दिया जाता चाहिए, बल्कि उन निजी-बचन की प्रोत्साहन राशि को उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर लगाने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए, जो इस समय ऐश्वर्या की व्यवस्था करने वाले प्रकानों के निर्माण, भूमि के पट्टे के सौदे और जंगलों जैसे कम प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर खर्च हो जाया करता था। हमारी आर्थिक नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए ताकि उनसे बाला धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति में न केवल कमी ही आए, बल्कि ग्राम्य के शेष भाग को सामाजिक हित के उत्पादक कार्यों पर लगाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन भी मिले। संगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के वेतन में वृद्धि की जाए, वह राष्ट्रीय उत्पादकता में होने वाली वृद्धि के एक निश्चित अनुपात से होनी चाहिए। आर्थिक प्रगति के कार्य से जो बोझ पड़ता है वह बोझ भी एक समान पड़ना चाहिए और आर्थिक प्रगति से जो लाभ मिलते हैं वे भी सबको समान रूप से मिलने चाहिए।

सरकारी बचत में वृद्धि करने से निवेश-दर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी और उससे आय तथा सम्पत्ति की विषमता भी नहीं बढ़ेगी। हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि सरकारी बचत में सब तक अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती, जब तक सरकारी क्षेत्रों में किए गए निवेश से हमें अधिक आय प्राप्त न हो। कुछ हद तक इसके लिए उत्पन्न क्षमता का अधिक अच्छे ढंग से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अनिवार्य अर्थ मुक्ति समत मूल्य नीति निर्धारित करने की भी आवश्यकता है। पहले भी, इन प्रश्नों पर प्रायः चर्चा की गई है और उनकी अनेक बार तदर्थ आधार पर अग्रगण्य तरीके से निपटाया गया है। विगत दो वर्षों में, सरकारी-क्षेत्र के उद्यमों की आय में वृद्धि करने के लिए काफी अधिक प्रयत्न किए गए हैं और इन प्रयत्नों के अनेक सुपरिणाम प्राप्त होने लगे हैं। अब समय आ गया है कि हम सभी सरकारी उद्यमों की मूल्य-उत्पादन-नीतियों की सुव्यवस्थित समीक्षा करें तथा उस समीक्षा के आधार पर एक ऐसी मुक्तिमय नीति तैयार करें जो काफी हद तक स्थायी रह सके।

इस बात पर ठीक ही जोर दिया गया है कि हमारी योजना का प्रमुख उद्देश्य

आरम्भितता प्राप्त करना चाहिए। लेकिन इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में और प्रगति अभी की सकती है, जब हम घरेलू निर्यात के परिमाण में 8 से 10 / तक की वार्षिक वृद्धि कर सकें ताकि हम विदेशों से ऊर्जा आयात करने पर कम से कम निर्भर रह सकें। देश में तेल की खोज और विकास कार्यक्रम को मुम्तदी और तेजी से किया जा रहा है। अब तक जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, वह काफी उत्साहजनक हैं। विगत दो वर्षों में निर्यात-सम्बन्धी नीतियों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए गम्भीर रूप से प्रयत्न किया गया है। परिणामस्वरूप 1974-75 और 1975-76 में भारत के निर्यात के परिणाम में दीर्घावधि औसत से लगभग 40 / की वृद्धि हो जाने की सम्भावना है। निर्यात के सम्बन्ध में मन्त्रिमण्डल समिति की स्थापना किए जाने के फलस्वरूप निर्यात के लगातार विकास के लिए सक्षम नीति का आधार निर्धारण करने के लिए नए सिरे से विचार करने में सहायता मिली है। लेकिन अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है जिससे निर्यात के नए क्षेत्रों में पर्याप्त गति से वृद्धि होनी सुनिश्चित की जा सके।

भारत जैसे घटते विकसित देश में विकास की गति को तीव्र करने में श्रमिक-वस्तुओं की कमी को दूर किया जाना बुनियादी तौर पर कृषि क्षेत्र में की गई प्रगति पर निर्भर है। यह भी एक सर्वसम्मत राष्ट्रीय उद्देश्य है कि देश की सबसे निम्न वर्गों की 40 / जनता की और हमारी आयोजना सम्बन्धी नीतियों और प्रक्रियाओं में सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। यह भी सर्वमान्य है कि भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में ग्रामीण विकास के एकीकृत कार्यक्रम के माध्यम से ही इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन गाँवों में एकीकृत विकास तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक विस्तृत राष्ट्रीय आयोजन के पूरक के रूप में निचले स्तर से आयोजन करने पर जोर दिया जाए। प्रायः सभी यह मानते हैं कि हमें पर्याप्त परिणाम तब तक प्राप्त नहीं हो सकते जब तक हम स्थानीय आवश्यकताओं साधनों और सम्भवनाओं की विस्तृत जानकारी के आधार पर अपनी योजनाएँ तैयार न करें। इन क्षेत्रों में अभी तक प्राणातीत प्रगति नहीं हुई है। पहले कृषि की पैदावार में वृद्धि के जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते थे, वे काफी हद तक वास्तविक नहीं होने थे, क्योंकि वे खेती में काम आने वाली वस्तुओं और उत्पादन के ब्यौरेवार विश्लेषण तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में फसलों की अनुकूलतम वास्तविक स्थिति तथा फसलों के क्रम के आधार पर नहीं निर्धारित किए जाते थे। इन कमियों को दूर करने के लिए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के महत्वपूर्ण साधन के रूप में बिके द्रिकृत आयोजन पर अधिक बल देना चाहिए।

अतिरिक्त जन शक्ति और अन्य उपलब्ध स्थानीय साधनों का पूर्ण उपयोग न किया जाना हमारे ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक बड़ी कमजोरी रही है। कृषि के काम आने वाली वस्तुओं को विदेशों से विशाल मात्रा में मगाकर प्रयोग करने के स्थान पर भविष्य में हमें स्थानीय जनशक्ति और उपलब्ध स्थानीय साधनों के अधिनाधिक उपयोग पर अधिक जोर देना पड़ेगा। यह आवश्यक नहीं है कि

कठिनाइयाँ जिन खा में राष्ट्रीय स्तर पर मामले आनी हैं, उसी रूप में स्थानीय स्तर पर भी आईं, जहाँ उपर्युक्त साठनात्मक और आयोजनात्मक उपायों द्वारा स्थानीय स्तरों की पड़ायन से केन्द्रीय आयोजना में उपलब्ध स्वर्मी का प्रयोग इस क्षेत्र की समस्यो को ब्राह्मपूर्ण तरीके से हल करने में किया जा सकता है। छोटे और सीमान्तिक कृषि तथा कृषि मजदूरी के लिए बनाई गई विशेष योजनाओं से, ग्रामीण समाज के अशिक्षित निचले वर्ग के व्यक्ति के मामले आने वाली समस्याओं का व्यावहारिक हल ढूँढ़ने में प्रत्यक्ष उपयोगी महायना मिली है। लेकिन अनुभव से निम्न होता है कि इस प्रकार की योजनाओं से सर्वोत्कृष्ट परिणाम सभी निम्न सरते हैं जब उन योजनाओं को एक क्षेत्र-विशेष के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम का अनिवार्य अंग बना दिया जाए। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि स्थानीय आवश्यकताओं साधनों तथा सम्भावनाओं का व्यापक सर्वेक्षण कर, उसके आधार पर ग्रामीण विकास के कार्य को समेकित प्रयास से पूरा किया जाए। कृषि के आधुनिकीकरण के प्रत्येक सफल कार्यक्रम के अन्तर्गत, उत्पादन-सम्बन्धी तकनीक में उत्तरोत्तर सुधार लाने तथा कृषकों द्वारा उक्त तकनीक के अपनाए जाने के लिए समुचित आर्थिक प्रोत्साहनों की व्यवस्था पर बल दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में अधिक महत्त्व इस बात को दिया जाएगा कि अनाज की खेती भूमि की उत्पादकता में वृद्धि की जाए और अधिक उत्पादन कई किस्मों के गेहूँ की खेती की भूमि की उत्पादकता की वृद्धि में रुकावट को, जिसका आभास वर्तमान में ही मिला है, समाप्त कर, उसकी उत्पादकता में वृद्धि की जाए।

यद्यपि 1950 के पश्चात् के कुछ वर्षों में देश की सिंचाई-प्रणाली में काफी विस्तार हुआ है, तथापि देश की सिंचाई-क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका है। इस कमी को सिंचाई के बड़े बड़े निर्माण-कार्यों के अन्तर्गत आने वाले सिंचित-क्षेत्रों के समेकित विकास कार्यक्रम के द्वारा पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। आगामी कुछ वर्षों में सिंचित-क्षेत्रों की विकास-क्षमता का उपयोग करना, कृषि की पैदावार बढ़ाने और सार्वजनिक-वितरण हेतु अधिक से अधिक अनाज की खरीद करने के लिए बनाई जाने वाली कृषि-नीति का प्रमुख अंग होना चाहिए। इस कार्यक्रम में आजानुकूल प्रगति नहीं हुई है। इसलिए यह आवश्यक है कि सिंचित-क्षेत्र के विकास प्राधिकरणों की शीघ्र स्थापना किए जाने के सम्बन्ध में जो वाचाएँ आ रही हैं, उनको दूर किया जाए।

यदि हम चाहते हैं कि सक्षम सार्वजनिक वितरण-प्रणाली, हमारी अर्थव्यवस्था का स्थाई अंग बन जाए तो हमें अनाज की खरीद के कार्यक्रम को भी काफी कारगर बनाना होगा। विश्व की अनाज की पैदावार तथा व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति के कारण दीर्घावधि के लिए पर्याप्त-मात्रा में विदेशों में अनाज प्राप्त करना अनिश्चित हो गया है, चाहे हमारे पास उसे खरीदने के लिए साधन ही क्यों न हों, यद्यपि सरकारी-वितरण प्रणाली का बनाए रखने के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर रहने की प्रवृत्ति को निरुत्साहित किया जाना चाहिए।

अगर अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर को, 5 से 6% के प्रास-नास रखना है,

तो औद्योगिक उत्पादन में विगत वर्षों में जो वृद्धि हुई है, उससे दुगुनी वृद्धि करनी होगी। अभी कुछ अंश तक औद्योगिक उत्पादन की भावी प्रगति पर सरकारी क्षेत्र की सम्भावित निवेश दर का प्रभाव पड़ना रहेगा। फिर भी विदेशों से वस्तुओं के आयात करने के स्थान पर देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग किए जाने के पहलुओं के समाप्त हो जाने से भविष्य में औद्योगिक उत्पादन में बराबर वृद्धि प्रायः तभी की जा सकती है जब सर्व-साधारण के प्रयोग की उपभोक्ता-वस्तुओं की माँग में वृद्धि हो, यह कृषि की उपज बढ़ा कर और औद्योगिक माल के निर्यात में तेजी से वृद्धि करके की जा सकती है। औद्योगिक-विकास में तीव्र वृद्धि करने हेतु आयोजन करते हुए उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

फिर भी, सदियों पुरानी गरीबी और जड़ता अल्प समय में दूर नहीं की जा सकती, लेकिन यदि आवश्यक राजनीतिक सकल्प बना रहे और आर्थिक अनुशासन का कठोरतापूर्वक पालन किया जाए, तो हम काफी हद तक घोर निर्धनता की खाइयों को पाट देने की आशा कर सकते हैं। यही नवीन आर्थिक कार्यक्रम का वास्तविक उद्देश्य है। इसलिए अब यह आवश्यक हो गया है कि हाल के महीनों में जो ठोस सफलता मिली है, उसे उसके आधार पर हम आगे बढ़ें, और आत्मनिर्भरता से विकास करने हेतु मध्यम अवधि की एक व्यापक नीति बनाएँ।



भारत में योजना-निर्माण-प्रक्रिया और क्रियान्वयन की प्रशास्तकीय मशीनरी

(The Administrative Machinery for Plan Formulation
Process and Implementation in India)

यदि अर्द्ध-विकसित देश दुनू आर्थिक विकास करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी आवश्यक योजनाएँ बनाकर क्रियान्वित करनी चाहिए। सोवियत रूस ने भी आर्थिक योजनाओं द्वारा ही आर्थिक प्रगति की है। किन्तु आर्थिक विकास हेतु जहाँ योजनाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है वहाँ इनके विवेकपूर्ण निर्माण और उनके उचित क्रियान्वयन का भी कम महत्व नहीं है। वस्तुतः योजना की सफलता उसके युक्तियुक्त निर्माण तथा उसकी क्रियामयि पर निर्भर करती है। उदाहरणार्थ योजना निर्माण और क्रियान्वयन में अधिनाधिक व्यक्तियों को भागीदार बनाए जाने पर इसकी सफलता का अंश बढ़ जाता है। किन्तु यदि योजना के लक्ष्य और कार्यक्रम सरकार द्वारा केवल ऊपर से जनता पर लादे जायें तो योजना की सफलता संदिग्ध हो जाती है। भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी. डार गडगिल के अनुसार "किसी योजना के निर्माण की अवस्था और सत्परचाज् इसके क्रियान्वयन में जितना अधिक प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होगा उतना ही अधिक अच्छा हमारा नियोजन होगा।"¹ अतः योजना के निर्माण और क्रियान्वयन में अपनाई गई प्रणालियों का भी बहुत महत्व है।

भारत में योजना-निर्माण की प्रक्रिया (Planning Formulation-Process in India)

भारत में योजना-निर्माण का कार्य 'भारतीय योजना आयोग' द्वारा किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय योजना में एक ओर केन्द्र और राज्य सरकारों की योजनाएँ तथा दूसरी ओर निजी क्षेत्र की योजनाएँ सम्मिलित होती हैं। भारत में योजना स्वीकार किए जाने से पूर्व निम्नलिखित अवस्थाओं में होकर गुजरती है—

सामान्य दिशा निर्देश (General Approach)—प्रथम अवस्था में योजना-निर्माण हेतु सामान्य दिशा निर्देश पर विचार किया जाता है। योजना प्रारम्भ

1. Dr. D R Gadgil Formulating the Fourth Plan in Yejna, 23 Feb, 1969

योजना-आयोग इन सभी समस्याओं द्वारा प्रस्तुत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों सम्बन्धी कार्यक्रमों के आधार पर 'संक्षिप्त ड्राफ्ट मेमोरेण्डम' (Draft Memorandum) तैयार करना है। इन मेमोरेण्डम में योजना के आकार, नीति सम्बन्धी मुख्य विषय, अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की अपेक्षा योजना के प्रयत्नों में कम पड़ने वाले सम्भावित क्षेत्रों आदि को भी प्रस्तुत किया जाता है। ड्राफ्ट मेमोरेण्डम में निजी-क्षेत्र के कार्यक्रमों का अधिक ब्योरा नहीं रहता है। योजना-आयोग द्वारा यह ड्राफ्ट मेमोरेण्डम केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है, तत्पश्चात् यह 'राष्ट्रीय विकास परिषद्' (National Development Council) में प्रस्तुत किया जाता है।

ड्राफ्ट प्रारूप का निर्माण—इस अवस्था का सम्बन्ध ड्राफ्ट आउट-लाइन (Draft Outline) के निर्माण से है। राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों तथा परिवर्तनों आदि के आधार पर योजना की ड्राफ्ट आउट-लाइन तैयार की जाती है। ड्राफ्ट मेमोरेण्डम की अपेक्षा यह अधिक व्यापक और बड़ा दस्तावेज (Memorandum) होता है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों (Sectors) के लिए विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं का ब्योरा तथा मुख्य नीति सम्बन्धी विषय, उद्देश्य और उनकी प्राप्ति के तरीके दिए होते हैं। इस दस्तावेज को विभिन्न मन्त्रालयों और राज्य सरकारों के पास समीक्षार्थ भेजा जाता है। इस पर केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में भी विचार किया जाता है। इसके पश्चात् राष्ट्रीय विकास परिषद् इस पर विचार करती है, जिसकी सहमति के पश्चात् योजना की इस ड्राफ्ट आउट-लाइन का जनता एवं विभिन्न संस्थाओं, विश्वविद्यालयों द्वारा विचार-विमर्श एवं समालोचना के लिए प्रकाशित किया जाता है और जनता के सुझाव और विचार आमन्त्रित किए जाते हैं। राज्यों में राज्य-स्तर पर और जिला-स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर संसद् के दोनों सदनों द्वारा विचार किया जाता है। संसद् में पहले इस पर कुछ दिनों तक सामान्य विचार-विमर्श चलता है उसके पश्चात् कई संसदीय समितियों द्वारा अधिक विचारपूर्वक विचार किया जाता है।

राज्य सरकारों से विचार-विमर्श—इस बीच जबकि योजना के इस प्रारूप पर देश भर में विचार होना रहता है, योजना आयोग विभिन्न राज्यों से उनकी योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत वार्तालाप करता है। वार्ता के मुख्य विषय उनके विकास की विस्तार योजनाएँ, वित्तीय साधन और अतिरिक्त साधनों के जुटाने सम्बन्धी उपाय आदि होते हैं। योजना-आयोग और राज्य सरकारों या महं परामर्श विशेषज्ञ और राजनीतिज्ञ दोनों स्तरों पर चलता है। अन्तिम निर्णय राज्य के मुख्य मन्त्री से सलाह-मशविरे के पश्चात् ही लिए जाते हैं।

नया मेमोरेण्डम—इस अवस्था की मुख्य बात योजना-आयोग द्वारा योजना के सम्बन्ध में नया मेमोरेण्डम तैयार करना है, जो राज्य-सरकारों के साथ गतिमान वार्तालाप जनता और संगठित मण्डलों द्वारा की गई समीक्षा तथा विभिन्न पैल एवं कार्यशील दलों द्वारा दिए गए विस्तृत सुझावों के आधार पर तैयार किया जाता

है। इस दस्तावेज में योजना की मुख्य विशेषताओं, नीति-सम्बन्धी निर्देश, जिन पर बल दिया जाता है तथा उन विषयों का वर्णन होता है जिन पर योजना के अन्तिम रूप से स्वीकार किए जाने के पूर्व विचार की आवश्यकता है। इस मेमोरेण्डम पर पुनः केन्द्रीय-मन्त्रिमण्डल और राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा विचार किया जाता है।

योजना को अन्तिम रूप दिया जाना—केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल और राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर योजना आयोग याजना की अन्तिम रिपोर्ट तैयार करता है। यह अन्तिम रिपोर्ट बहुत व्यापक होती है और इसमें योजना के उद्देश्य, नीतियों, कार्यक्रम और परियोजनाओं का विस्तृत वर्णन होता है। यह अन्तिम योजना पुनः केन्द्रीय-मन्त्रिमण्डल और राष्ट्रीय विकास परिषद् के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, जिसकी सहमति क पश्चात् इसे ससद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। दोनों सदनों में कई दिनों के बाद विवाद के पश्चात् दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति मिल जाने के बाद इसे लागू कर दिया जाता है तथा राष्ट्र से इसके क्रियान्वयन और उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपील की जाती है।

योजना निर्माण—भारत में उपरोक्त प्रकार से ऊपर से केन्द्र द्वारा योजना बनाने के साथ-साथ सगठन की निचली इकाइयों की आवश्यकताओं, उनके द्वारा लक्ष्यों के मूल्यांकन तथा सुझावों के अनुसार सरकार इस योजना में परिवर्तन या संशोधन करती है। विभिन्न राज्यों, जिलों और विकास-खण्डों द्वारा योजना के प्रारूप में निर्धारित व्यापक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए योजनाएँ तैयार करने के लिए कहा जाता है। उनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करके अन्तिम योजना में समायोजन कर लिया जाता है। योजना-आयोग, राज्यों, जिलों और पंचायत समितियों द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताओं, प्रस्तावों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं की आर्थिक और तकनीकी दृष्टियों से सावधानीपूर्वक जाँच करता है और उनके आधार पर याजना-निर्माण किया जाता है।

समय समय पर पुनरावलोकन—योजना-निर्माण में काफी समय लगता है और इस बीच तथा योजना की पंचवर्षीय अवधि में भी परिस्थितियों में परिवर्तन हो सकता है। अतः योजना-आयोग एक बार पंचवर्षीय योजना बना देने के पश्चात् भी देश और प्रत्येक क्षेत्र में समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों पर निगरानी रखता है, तत्सम्बन्धी अध्ययन करता है और आवश्यकतानुसार योजना में परिवर्तन और संशोधन करता रहता है। इससे अतिरिक्त पंचवर्षीय योजना को वार्षिक योजनाओं में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष नवम्बर या दिसम्बर में योजना-आयोग और केन्द्रीय-मन्त्रालयों तथा राज्य-सरकारों के बीच गत प्रगति की समीक्षा, संसाधनों की स्थिति, लक्ष्यों के समायोजन की तकनीकी सम्भावनाओं और आगामी वर्ष की योजना की आवश्यकताओं पर विचारार्थ परामर्श चलता रहता है। केन्द्र और राज्य सरकारों के बजट इन्हीं वार्षिक योजनाओं को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष फरवरी में बनाए जाते हैं। ये वार्षिक योजनाएँ अब भारतीय नियोजन की विशेषता बन गई हैं।

भारत में योजना-निर्माण की तकनीक (Techniques of Plan-formulation in India)

भारत में योजना आयोग द्वारा मध्यम और दीर्घकालीन योजनाओं के निर्माण में निम्नलिखित तकनीकों का प्रयोग किया जाता है—

1 अर्थव्यवस्था की स्थिति का सांख्यिकीय विश्लेषण—पर्याप्त और विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव में कोई नियोजन सफल नहीं हो सकता। सांख्यिकी आधारशिला पर ही नियोजन के प्रासाद का निर्माण होता है। अतः भारत में पंचवर्षीय योजना के निर्माण में सर्वप्रथम अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का सांख्यिकी विश्लेषण किया जाता है। आंकड़ों के आधार पर भूतकालीन प्रवृत्तियों और प्रगति की समीक्षा की जाती है और मुख्य आर्थिक समस्याओं का अनुमान लगाया जाता है। इन सबके लिए देश की अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों के बारे में सांख्यिकी एकत्रित किए जाते हैं। यह कार्य भारत में कई सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है और योजना-निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। भारत में सांख्यिकी सम्बन्धी स्थिति सुधारने हेतु विगत वर्षों में बहुत प्रयत्न किए गए हैं। 'केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन' (Central Statistical Organisation) सन् 1948-49 से राष्ट्रीय आय के आंकड़े तैयार करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया और केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अर्थव्यवस्था में वृद्धि और विनिर्धन के अनुमान तैयार किए जाते हैं। रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापक मौद्रिक और वित्तीय सांख्यिकी एकत्रित किए जाते हैं। कृषि और औद्योगिक सांख्यिकी सूचनाओं के सुधार के लिए भी विगत वर्षों में अच्छे प्रयास किए गए हैं। योजना आयोग की 'अनुसंधान कार्यक्रम समिति' द्वारा भी विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में अध्ययन अनुसंधान किए जाते हैं तथा यह विकास से सम्बन्धित अध्ययन अनुसंधानों के लिए विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थाओं को अनुदान भी देती है। योजना आयोग के 'कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन' (Programme Evaluation Organisation) द्वारा भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अनेक विशिष्ट संस्थाएँ जैसे— 'केन्द्रीय जल और शक्ति आयोग' (Central Water and Power Commission), 'जियोलॉजीकल सर्वे ऑफ इण्डिया' (Geological Survey of India), 'ब्यूरो ऑफ माइन्स' (Bureau of Mines), जनगणना विभाग, फाइल एण्ड नेचुरल गैस कमिशन (Oil and Natural Gas Commission) प्राकृतिक संपत्तियों सम्बन्धी समिति (Committee on Natural Resources) आदि ने सम्बन्धित साधनों एवं समस्याओं के बारे में विस्तृत अध्ययन किए हैं और करती रहती है। इसके प्रतिरिक्त प्रत्येक मंत्रालय में सांख्यिकी-वर्क होते हैं जो अपने विषय पर सभी प्रकार की सूचनाएँ एकत्रित करते हैं। योजना-आयोग इन सभी स्रोतों द्वारा सांख्यिकी सूचनाओं और अध्ययनों के आधार पर अर्थव्यवस्था की स्थिति का विश्लेषण करता है और योजना-निर्माण प्रक्रिया में आगे बढ़ती है।

2 आर्थिक विकास की सम्भावनाओं का अनुमान लगाना—उपरोक्त अध्ययन

के आधार पर देश की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है। इस पर विचार किया जाता है कि विकास की वांछनीय दर क्या होनी चाहिए। साथ ही नियोजन की प्रमुख प्राथमिकताएँ तथा नीतियों के बारे में निश्चय किया जाता है। उदाहरणार्थ जनसंख्या और उसकी आयु-मरचना सम्बन्धी भावी अनुमान योजना के दौरान खाद्यान्न, वस्त्र, निवास आदि की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार विकास की वांछनीय दर के आधार पर योजनावधि में बचत और विनियोग की आवश्यकताओं पर निर्णय लिया जाता है। तत्पश्चात् योजना निर्माण सम्बन्धी इन आवश्यकताओं की योजनावधि में उपलब्ध होने वाले वित्तीय साधनों के सन्दर्भ में छानबीन की जाती है। इस प्रकार, वित्तीय साधनों का अनुमान लगाया जाता है। निजी-क्षेत्र के वित्तीय साधनों का अनुमान रिजर्व बैंक के द्वारा और सार्वजनिक क्षेत्र के साधनों का अनुमान योजना-आयोग और वित्त मन्त्रालय द्वारा लगाया जाता है। साथ ही इस बात की सम्भावना पर भी विचार किया जाता है कि योजनावधि में केन्द्र और राज्य-सरकारें अतिरिक्त करारोपण द्वारा कितनी राशि जुटा सकेंगी। भारत जैसे अर्द्ध-विकसित देश में, जहाँ जन-साधारण का जीवन-स्तर बहुत नीचा है, मनमाने ढंग से कर नहीं लगाए जा सकते, अतः इस बात पर सावधानीपूर्वक विचार करना होता है। योजना आयोग विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं और सम्भावित विदेशी सहायता के बारे में भी अनुमान लगाता है। सार्वजनिक उपक्रमों के लाभों से नियोजन को कितनी वित्त-व्यवस्था हो सकेगी तथा किस सीमा तक हीनार्थ-प्रबन्धन (Deficit Financing) का लाभपूर्वक आश्रय लिया जा सकता है। हीनार्थ प्रबन्धन को कम से कम रखने का प्रयत्न किया जाता है अन्यथा मुद्रा प्रसारित मूल्य-वृद्धि होने से योजना-निर्माण के प्रयत्न विफल हो जाते हैं। इस प्रकार पहले विनियोग की आवश्यकताओं और उसके पश्चात् वित्तीय साधनों का अनुमान लगाया जाता है। तत्पश्चात् योजना आयोग किसी एक को दूसरे से या दोनों में संशोधन करके समायोजन करता है। साथ ही, योजना आयोग विभिन्न प्रकार से इस बात की जाँच करता है कि तैयार की जाने वाली योजना में कहीं असंगति तो नहीं है। उदाहरणार्थ, यह देखा जा सकता है कि प्रस्तावित विनियोग उपलब्ध बचतों के अनुरूप है या नहीं, विदेशी विनिमय की आवश्यकता के अनुरूप इसकी उपलब्धि हो सकेगी या नहीं, आधारभूत कच्चे माल की आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन होगा या नहीं। इस प्रकार, योजना आयोग विभिन्न कार्यक्रमों की संगति की जाँच करता है ताकि अर्थव्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न नहीं होने पाए।

3 आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों का निर्धारण—योजना निर्माण के लिए प्रमुख आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों के निर्धारण का कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, अतः भारत में योजना निर्माता इन उद्देश्यों के निर्धारण पर भी बहुत ध्यान देते हैं। इन उद्देश्यों के निर्धारण में उपलब्ध समय तथा भौतिक और वित्तीय दोनों प्रकार के साधनों के सन्दर्भ में विचार किया जाता है, विभिन्न उद्देश्यों में परस्पर विरोध होता है उनमें समायोजन किया जाता है। उदाहरणार्थ, अल्पकालीन और

दीर्घकालीन उद्देश्यो तथा बड़े आर्थिक तथा गैर-आर्थिक उद्देश्य परस्पर विरोधी होते हैं। आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण, ये दो उद्देश्य भी परस्पर विरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। आर्थिक विकास पर अधिक महत्व देने से सामाजिक कल्याण की अवहेलना हो सकती है और सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम अधिक प्रारम्भ करने पर आर्थिक विकास की गति धीमी भी हो सकती है। अतः योजना-निर्माता इन उद्देश्यों में सामंजस्य और समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं।

4 विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य निर्धारण—इसके पश्चात् विभिन्न क्षेत्रों जैसे—कृषि, उद्योग, विद्युत्, सिंचाई, यातायात, समाज-सेवाओं आदि में लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है और यह कार्यशील दलों (Working Groups) द्वारा किया जाता है। इन कार्यशील दलों के सदस्य, विभिन्न मन्त्रालयों और ग्रन्थ संगठनों से लिए गए विशेषज्ञ होते हैं। लक्ष्य निर्धारण करते समय यह कार्यशील दल योजना आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों और पथ-प्रदर्शन के अधीन कार्य करते हैं तथा जनमत पर भी ध्यान देते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य निर्धारण के इस कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् योजना आयोग समस्त ग्रन्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से इन लक्ष्यों की जाँच करता है और देखता है कि विभिन्न लक्ष्यों में परस्पर असंगति (Inconsistency) तो नहीं है। योजना के लक्ष्यों के निर्धारण की विधि का वरुण पिछले अध्याय में किया जा चुका है।

योजना को अन्तिम रूप दिया जाना—ग्रन्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे—कृषि, उद्योग, विद्युत्, सिंचाई, यातायात, समाज-सेवाओं आदि में भिन्न भिन्न लक्ष्यों के निर्धारण के पश्चात् इन सबको मिलाया जाता है और मूल अनुमानों से तुलना की जाती है। इस अवस्था में उपलब्ध होने वाले पूँजीगत साधनों और विदेशी मुद्रा के सन्दर्भ में इन लक्ष्यों पर विचार किया जाता है तथा साधनों को और अधिक गतिशील बनाने या लक्ष्यों को घटाने-बढ़ाने की गुंजाइश पर विचार किया जाता है। साथ ही, योजना के रोजगार-सम्बन्धी प्रभावों तथा बुनियादी भौतिक पदार्थों, जैसे—लोहा, इस्पात, सीमेंट आदि की आवश्यकताओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है। इन सबके आधार पर सरकार और योजना आयोग द्वारा योजना की नीति, आकार, क्षेत्र, विनियोगों के आवंटन, प्राथमिकताओं के निर्धारण आदि के सम्बन्ध में निर्णय लिए जाते हैं और योजना को अन्तिम रूप दिया जाता है, जिसे क्रमशः केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल, राष्ट्रीय विकास परिषद् और ससद् द्वारा स्वीकृति दिए जाने पर लागू किया जाता है।

चतुर्थ योजना निर्माण तकनीक—चतुर्थ योजना के निर्माण में अपनाई गई तकनीक के अध्ययन से भारतीय नियोजन निर्माण की तकनीक स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है। चतुर्थ योजना पर प्रारम्भिक विचार योजना आयोग के दीर्घकालीन नियोजन समान (Perspective Planning Division : P.P.D.) में 1962 में शुरू हुआ। योजना निर्माण के समय एक महत्वपूर्ण निर्णय इस सम्बन्ध में लेना होता है कि राष्ट्रीय आय का कितना भाग बचाया जाए और कितने का विनियोजन

किया जाए ? बचत-दर अधिक बढ़ाने पर जनता को उपभोग कम करना पड़ता है इस प्रकार, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । अतः इस सम्बन्ध में बहुत सोच-विचार की आवश्यकता होती है । दीर्घकालीन नियोजन सभाग ने योजना निर्माण की प्रारम्भिक अवस्था में, मुख्य रूप से इसी समस्या पर विचार-विमर्श किया कि योजना में विनियोजन-दर क्या हो ? विनियोजन-दर के निर्धारण हेतु जनता के लिए उपभोग-स्तर का निर्धारण भी आवश्यक है । योजना आयोग के दीर्घकालीन नियोजन सभाग (P. P. D) ने इस बात का निर्णय किया कि जनसंख्या को न्यूनतम जीवन-स्तर उपलब्ध कराने के लिए 1960-61 के मूल्य स्तर पर 35 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह आवश्यक होंगे । अतः यह निर्णय लिया गया कि नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य जनता के जीवन-स्तर को उक्त 35 रुपये के स्तर तक ऊँचा करना है । किन्तु यदि इस उद्देश्य को 1975 तक प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय-आय में 40% या वर्ष 1961-75 में 10% से 20% वार्षिक वृद्धि आवश्यक थी । किन्तु ये लक्ष्य अत्यन्त महत्वाकांक्षी थे । अतः न्यूनतम 35 रुपये के जीवन-स्तर प्रदान करने का लक्ष्य छोड़ना पड़ा । इसके पश्चात् प्रमुख अर्थ-शास्त्रियों और राजनीतिज्ञों का एक अन्य अध्ययन-दल नियुक्त किया गया, जिसने 5 व्यक्तियों के परिवार के लिए 100 रुपये अर्थात् 20 रुपये प्रति व्यक्ति के न्यूनतम जीवन-स्तर का प्रबन्ध किए जाने की सिफारिश तथा यह लक्ष्य 1975-76 तक अर्थात् 1965-66 से 10 वर्षों में प्राप्त करने थे । इस आधार पर दीर्घकालीन नियोजन सभाग ने चतुर्थ और पाँचवी योजना में राष्ट्रीय आय में 75 या 77% वृद्धि के लक्ष्य का सुझाव दिया । समग्र राष्ट्रीय आय सम्बन्धी निर्णय कर लेने के पश्चात् दूसरा कार्य अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में तत्सम्बन्धी निर्णय लेना और उत्पादन-वृद्धि के लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु आवश्यक विनियोगों का विस्तृत अनुमान लगाना था । इसके पश्चात् दीर्घकालीन नियोजन सभाग ने असरय सूक्ष्म योजनाओं (Micro Plans) को ममस्त अर्थ-व्यवस्था के लिए एक पूर्णतःगत योजना में समावेशित करने का कार्य किया । इसके लिए निम्नलिखित तकनीक अपनाई गई—

- (i) सूक्ष्म या व्यक्ति स्तर (Micro-Level) पर सभी प्रकार के भावी अनुमान लगाना,
- (ii) सूक्ष्म या व्यक्ति स्तर पर बड़ी मात्रा में भौतिक सतुलनों का प्रयास करना ।

प्रथम तकनीक के अन्तर्गत कुल घरेलू उत्पादन और व्यय तथा इसके प्रमुख भागों के सम्बन्ध में गणनाएँ की गईं । चतुर्थ और पाँचवी योजना में विदेशी-सहायता, शुद्ध विनियोग-दर, सार्वजनिक उपभोग-स्तर और व्यक्तिगत उपभोग के अनुमान लगाए गए । इसके पश्चात् 'समय-समय पर कुल घरेलू माँग की वृहत् वस्तु संरचना' (Broad Commodity Pattern of the Gross Domestic Demand at Various Points of Time) को ज्ञात करने के लिए कदम उठाया गया । दीर्घ-कालीन नियोजन सभाग ने विभिन्न व्यक्तिगत पदार्थों के लिए लक्ष्यों को ज्ञान किया ।

निर्मित वस्तुओं में 165 वस्तुओं, खनिज-पदार्थों में 16 वस्तुओं और कृषि-पदार्थों में 40 से अधिक पदार्थों के लक्ष्य निर्धारित किए। जिस प्रकार 'दीर्घकालीन नियोजन सभाग' (P. P. D.) न उत्पादन-लक्ष्य निर्धारित किए, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्तिगत पदार्थ उत्पन्न करने के दौरान उत्पन्न होने वाली राष्ट्रीय आय होगी। इस प्रकार दीर्घकालीन नियोजन सभाग ने समस्त अर्थ-व्यवस्था और उसके विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। सूक्ष्म या व्यष्टि स्तर (Micro-Level) पर भौतिक सतुलनों के लिए अनेक पदार्थ चुने गए। एक पदार्थ के लिए भौतिक सतुलनों का आशय उस विस्तृत ब्योरे से है जिसमें मुख्य उद्योगों में, जिनमें उस पदार्थ का उपयोग होता है, भाग दिखाई देता है। साथ ही, इस बात का भी संकेत होता है कि किस प्रकार उस पदार्थ की उतनी मात्रा का उत्पादन किया जाएगा या विदेशों से आयात किया जाएगा। चतुर्थ योजना में कोयला, पेट्रोल के पदार्थ, विद्युत, कच्चा-लोहा, मैंगनीज, सीमट, रबर आदि कई वस्तुओं के लिए 'भौतिक सतुलन' तैयार किए गए थे।

इन सभी विस्तृत अध्ययनों एवं तैयारियों के पश्चात्, एक ओर योजना आयोग तथा दूसरी ओर केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में परामर्श और विचार-विमर्श प्रारम्भ हुआ। योजना का आकार निश्चित करने में वित्त मंत्रालय का महत्त्वपूर्ण योगदान था। परिणामस्वरूप, चतुर्थ योजना की प्रमुख रूपरेखाएँ प्रकट हुईं, जिनके आधार पर चतुर्थ योजना का मेमोरेण्डम (दस्तावेज) तैयार हुआ, तब राष्ट्रीय परिषद् ने इस मेमोरेण्डम पर विचार किया। इसने कृषि, सिंचाई, उद्योग शक्ति, यातायात, सामाजिक सेवाएँ, रसायन और पहाड़ी क्षेत्रों के विकासार्थ पाँच समितियाँ नियुक्त की, जिन्होंने योजना पर विचार किया और अगस्त, 1966 में चतुर्थ योजना का प्रारूप प्रकाशित किया गया, किन्तु अनेक कारणों से यह योजना लागू नहीं की जा सकी। चतुर्थ योजना का निर्माण पुनः किया गया। इस नई चतुर्थ योजना की नीतियों और कार्यक्रमों का दिशा-निर्देशन (Approach to the Fourth Five Year Plan) 17 व 18 मई को राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया गया। उसके आधार पर नई चतुर्थ योजना 1969-74 का निर्माण किया गया, जिसे 21 अप्रैल, 1969 को संसद में प्रस्तुत किया गया।

योजना-निर्माण और क्रियान्वयन की प्रशासकीय मशीनरी (The Administrative Machinery for Plan Formulation and Implementation)

भारत में योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए प्रशासकीय मशीनरी तथा योजना-तन्त्र के मुख्य अंग निम्नलिखित हैं—

- (1) योजना-आयोग (Planning Commission)
- (2) राष्ट्रीय योजना परिषद् (National Planning Council)
- (3) योजना-आयोग के विभिन्न सम्भाग (Divisions of Planning Commission)
- (4) अन्य संस्थाएँ (Other Institutions)

योजना आयोग (Planning Commission)

भारत में योजना-निर्माण सम्पन्नी उत्तरदायित्व योजना आयोग का है, जिसकी स्थापना मार्च, 1950 में की गई थी। योजना आयोग ही हमारे नियोजन तन्त्र का महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय संविधान में योजना आयोग की नियुक्ति की कोई व्यवस्था नहीं है, अतः इसकी स्थापना भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी।

आयोग के प्रमुख कार्य—योजना-आयोग की स्थापना के समय ही आयोग के प्रमुख कार्यों का स्पष्ट संकेत दिया गया था। तदनुसार आयोग के मुख्य कार्य संक्षेप में निम्नलिखित हैं—

1 प्रथम महत्वपूर्ण कार्य देश के साधनों का अनुमान लगाना है। योजना-आयोग देश के भौतिक, पूँजी-सम्बन्धी और मानवीय साधन का अनुमान लगाता है। वह ऐसे साधनों की बढोत्तरी की सम्भावना का पता लगाता है जिनका देश में अभाव होता है। साधनों का अनुमान और उनमें अभिवृद्धि का प्रयत्न अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि इसके अभाव में कोई भी नियोजन असम्भव है।

2 योजना-आयोग का दूसरा कार्य है योजना-निर्माण। योजना-आयोग देश के साधनों के सर्वाधिक प्रभावशाली और सन्तुलित उपयोग के लिए योजना-निर्माण करता है।

3. योजना-आयोग का तीसरा कार्य है—योजना को पूरा किए जाने की अवस्थाओं को परिभाषित करना तथा योजना की प्राथमिकताओं का निर्धारण करना।

4 इसके पश्चात् योजना-आयोग इनके आधार पर देश के साधनों का समुचित आवंटन करता है।

5 योजना-आयोग का पाँचवाँ कार्य है, योजना-तन्त्र का निर्धारण। आयोग योजना की प्रत्येक अवस्था के सभी पहलुओं में सफल क्रियान्विति के लिए योजना-तन्त्र की प्रकृति को निर्धारित करता है।

6. योजना-आयोग समय-समय पर योजना की प्रत्येक अवस्था के क्रियान्वयन में की गई प्रगति का मूल्यांकन करता है। इस मूल्यांकन के आधार पर वह नीतियों और प्रयत्नों में परिवर्तन या समायोजन की सिफारिश करता है।

7 योजना-आयोग का सातवाँ कार्य सुभाव और दिशा निर्देश सम्बन्धी है। योजना-आयोग आर्थिक विकास की गति अवरोध करने वाले घटकों को बताता है और योजना की सफलता के लिए आवश्यक स्थितियों का निर्धारण करता है। योजना-निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु आर्थिक परिस्थितियों, नीतियों, विकास-कार्यक्रमों आदि पर योजना-आयोग सरकार को सुभाव देता है। यदि राज्य या केन्द्रीय सरकार किसी समस्या विशेष पर सुभाव माँगे तो आयोग उस समस्या विशेष के समाधान के लिए भी अपने सुभाव देता है।

अपने कार्य के सफल-सम्पादन की दृष्टि से योजना-आयोग को कुछ अन्य कार्य भी सौंपे गए हैं, जैसे—

(1) सामग्री, पूँजी और मानवीय साधन का मूल्यांकन, संरक्षण तथा उनमें

वृद्धि की सम्भावनाओं आदि को ज्ञान करना। इस सम्बन्ध में योजना-आयोग का कर्तव्य है कि वह वित्तीय साधनों, मूल्य-स्तर, उन्मोग प्रतिमान आदि का निरन्तर अध्ययन करता रहे।

(ii) साधनों के सन्तुलित प्रयोग की दिशा में योजना-आयोग को इस प्रकार की विधि अपनानी चाहिए जिससे एक ओर तो विकास की अधिकतम-दर प्राप्त की जा सके तथा दूसरी ओर सामाजिक न्याय की स्थापना भी हो सके।

(iii) योजना-आयोग, योजनाओं की सफलता के लिए, सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन करता रहे।

(iv) योजना आयोग आर्थिक एवं अन्य नीतियों का सामयिक मूल्यांकन करे और यदि नीतियों में किन्हीं परिवर्तनों की आवश्यकता हो तो इसके लिए मन्त्रिमण्डल को सिफारिश करे।

(v) नियोजन की तकनीक का आवश्यक अध्ययन करते हुए उसमें सुधार का प्रयत्न करे।

(vi) योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जन-सहयोग प्राप्त करे ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी दायित्व महसूस करते हुए योजना के कार्यों में भागीदार बन सके।

संगठन—योजना-आयोग की रचना करते समय यह उद्देश्य रखा गया था कि आयोग और मन्त्रि-परिषद् में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध हो। यही कारण है कि आरम्भ से ही आयोग में अन्य सदस्यों के अनिर्दिष्ट मन्त्रि-परिषद् के केबिनेट स्तर के कुछ मन्त्रियों की सदस्यता प्रदान की गई। प्रधान मन्त्री आयोग का अध्यक्ष होता है। सितम्बर, 1967 में पुनर्गठन के बाद से प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री के प्रतिनिधित्व सभी सदस्य पूर्णकालीन (Whole time) रहे हैं और वे सरकार के मन्त्री नहीं होते। यद्यपि योजना आयोग के सभी सदस्य एक निकाय (Body) के रूप में कार्य करते हैं तथापि सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक सदस्य को एक या अधिक विषयों का उत्तरदायित्व भी दिया जाता है। वित्त मन्त्री योजना-आयोग के आर्थिक सम्भाग (Economic Division) से निकटतम सम्पर्क रखता है।

यह प्रश्न विवादास्पद है कि मन्त्रियों को योजना आयोग का सदस्य बनाना कहां तक उचित है। कुछ का मत है कि योजना आयोग का पूर्णतः स्वतन्त्र संगठन होना चाहिए। योजना आयोग का प्रमुख कार्य देश की आर्थिक समस्याओं पर सरकार को परामर्श देना है, अतः यह उचित है कि इसका सदस्य उन्हीं को बनाया जाए जो कृपाति प्राप्त हों। साथ ही सदस्यों को स्वतन्त्र किन्तु सदुक्त रूप से कार्य करने का अधिकार दिया जाए। प्रधान मन्त्री व अन्य मन्त्रियों को आयोग का सदस्य बनाना उचित नहीं है, क्योंकि इससे आयोग की स्वतन्त्रता कम होती है।¹ लेकिन

1. Also see * Estimate Committee, 957-59, Twenty First Report (Second Lok Sabha), Planning Commission, p 21.

इस प्रकार का मत धजनी नहीं रखता है। वास्तव में मन्त्री जनता के निकट सम्पर्क में रहते हैं और जनता की मन्त्र को अधिक अच्छी तरह पहिचानते हैं, अतः जनता के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं और योजना-मशीनरी से उनका निकट-सम्पर्क होना चाहिए। वैसे भी अधिक प्रभावशाली मत यही रहा है कि मन्त्रियों का आयोग के साथ निकटतम सम्पर्क होना चाहिए ताकि मन्त्रिमण्डल और आयोग के मध्य ताल में बन रहा है। इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए अन्तिम उत्तरदायित्व मन्त्रिमण्डल पर ही होता है। प्रशासन ही वह यन्त्र है, जो योजना को सफल बनाने और क्रियान्वयन की दिशा में सर्वोपरि भूमिका निभाना है। अतः नियोजन आयोग में मन्त्रियों को सदस्यता देना वांछित है। बी टी कृष्णमाचारी के मतानुसार योजना का क्रियान्वयन उसी स्थिति में अच्छा हो सकता है, जब मन्त्रिमण्डल के सदस्य भी आयोग के विचार विवेचन और निर्णयों में भाग लें।

प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों और योजना आयोग का पुनर्गठन—
सितम्बर, 1967 में योजना-आयोग का पुनर्गठन किया गया। योजना-आयोग का यह पुनर्गठन प्रशासनिक सुधार आयोग (Administrative Reforms Commission) की सिफारिशों के आधार पर किया गया था, जो निम्नलिखित थी—

(i) आयोग के उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्य केन्द्रीय मन्त्रियों में से नहीं लिए जाने चाहिए।

(ii) योजना आयोग केवल विशेषज्ञों की ही सस्या नहीं होनी चाहिए और इसके सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान और अनुभव होना चाहिए।

(iii) राष्ट्रीय नियोजन परिषद् योजनाओं के निर्माण में बुनियादी निर्देश देती रहे। उसकी और उसके द्वारा नियुक्त विभिन्न समितियों की नियमित रूप से अधिक बैठकों की जानी चाहिए।

(iv) योजना आयोग को सलाहकार समितियों की नियुक्ति में मितव्ययिता करनी चाहिए और उनकी स्थापना सोच विचार करके की जानी चाहिए। नियुक्ति के समय ही समितियों के कार्यक्षेत्र और कार्य-संचालन विधि निर्धारित कर दी जानी चाहिए। योजना आयोग को अपने कार्य के लिए केन्द्रीय मन्त्रालयों में कार्य कर रही सलाहकार समितियों का अधिकाधिक सहयोग लेना चाहिए।

(v) लोकसभा की सार्वजनिक उपक्रम समिति के समान लोकसभा के सदस्यों की एक अन्य समिति बनाई जानी चाहिए जो योजना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन तथा योजनाओं के मूल्यांकन से सम्बन्धित प्रतिवेदनों पर विचार करे।

(vi) आयोग के लिए सलाहकार विषय-विशेषज्ञ एवं विश्लेषणकर्त्ता इस प्रकार के तीन पूर्ण स्तरीय अधिकारी होने चाहिए।

(vii) विकास से सम्बन्धित विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण देने हेतु दिल्ली में एक प्रशिक्षण-मस्थान स्थापित किया जाना चाहिए।

(viii) उद्योगों के लिए स्थापित विभिन्न विकास परिषदों के साथ एक योजना समूह मन्त्र रहना चाहिए जो निजी क्षेत्र के उद्योगों से योजना निर्माण में परामर्श एवं सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।

(ix) एक स्टेन्डिंग कमेटी की स्थापना की जानी चाहिए जो केन्द्रीय सरकार के विभिन्न आर्थिक सलाहकार कक्षों में अधिक समन्वय और सम्पर्क का कार्य करे। इसके सदस्य भिन्न-भिन्न मन्त्रालयों तथा योजना-आयोग के आर्थिक एवं सांख्यिकीय कक्षों के अध्यक्ष होने चाहियें।

(x) प्रत्येक राज्य में निम्न प्रकार के त्रि-स्तरीय नियोजन तन्त्र स्थापित किए जाना चाहिए—

(a) राज्य योजना परिषद्—यह विशेषज्ञों की सस्था होनी चाहिए। यह परिषद् राज्य में योजना-आयोग के समान योजना सम्बन्धी कार्य करे, (b) विभागीय नियोजन सस्थाएँ—ये सम्बन्धित विभागों की भिन्न-भिन्न विकास परियोजनाओं में समन्वय स्थापित करने और उनके क्रियान्वयन की देखभाल करने का कार्य करे, (c) क्षेत्रीय तथा जिला-स्तरीय नियोजन सस्थाएँ—इसके लिए प्रत्येक जिले में एक पूर्णकालीन योजना और विकास अधिकारी तथा एक जिला-योजना समिति होनी चाहिए। समिति में पंचायतों और नगरपालिकाओं के प्रतिनिधि एवं कुछ व्यावसायिक विशेषज्ञ भी होने चाहियें।

अप्रैल, 1973 में पुनर्गठन—योजना आयोग की रचना और कार्य विभाजन में 1 अप्रैल, 1973 को पुनः परिवर्तन किया गया। तदनुसार आयोग के गठन की रूपरेखा इस प्रकार रही—

- (1) प्रधान मन्त्री, पदेन अध्यक्ष।
- (2) एक उपाध्यक्ष (योजना मन्त्री स्वर्गीय दुर्गाप्रसाद धर उस समय उपाध्यक्ष थे)।
- (3) उपाध्यक्ष के अतिरिक्त आयोग के 4 और सदस्य (जिनमें कोई भी मन्त्री शामिल नहीं था, यद्यपि वित्त मन्त्री आयोग की बैठकों में भाग ले सकता था। ये सभी सदस्य पूर्णकालिक थे)।

जुलाई, 1975 में आयोग का गठन—जुलाई, 1975 में आयोग का गठन इस प्रकार था—

1. श्रीमती इन्दिरा गांधी	प्रधान मन्त्री तथा अध्यक्ष
2. पी. एन. हक्तर	उपाध्यक्ष
3. सी. सुब्रह्मण्यम	वित्त मन्त्री
4. इन्द्रकुमार गुजराल	योजना राज्य मन्त्री
5. एस. चक्रवर्ती	सदस्य
6. बी. शिवरामन	सदस्य

आयोग में कार्य विभाजन

प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझाव के अनुसार, आयोग के कार्यों को तीन भागों में विभाजित किया जाना अपेक्षित है—याजना-निर्माण-कार्य, मूल्यांकन कार्य

एवं प्रतिष्ठापन-कार्यें। विकास से सम्बन्धित विषयो में प्रशिक्षण देने हेतु एक प्रतिष्ठान सस्थान भी अपेक्षित है। वर्तमान में दिल्ली में स्थापित इन्स्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक प्रोद्य, कार्य कर रहा है। 1973 के मध्य आयोग के सदस्यो में कार्य-विभाजन की रूपरेखा इस प्रकार थी—

- (1) सदस्य डॉ. मिन्हास के पास सामाजिक सेवाएँ (शिक्षा को छोड़कर), गृह-निर्माण और शहरी-विकास, धर्म, रोजगार एवं मानव शक्ति, यातायात एवं सन्देशवाहन तथा पर्वतीय विकास सम्बन्धी कार्य थे।
- (2) सदस्य प्रो. चक्रवर्ती के पास दीर्घकालीन नियोजन, आर्थिक-विभाग, शिक्षा और बहुस्तरीय नियोजन सम्बन्धी कार्य थे।
- (3) सदस्य श्री शिवरामन के पास कृषि और सिंचाई तथा योजना-क्रियान्वयन के प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य थे।
- (4) सदस्य श्री एम. एस. पाठक के पास उद्योग, खनिज एवं शक्ति-सम्बन्धी कार्य थे।

योजना आयोग के कार्यों के संचालन हेतु आन्तरिक संगठन की दृष्टि से विभिन्न विभाग हैं, जो चार भागों में विभाजित हैं—

1. समन्वय विभाग (Co-ordination Division)—इसके दो उप-विभाग हैं—योजना समन्वय विभाग (Plan Co-ordination Section) तथा कार्यक्रम प्रशासन विभाग (Programme Administrative Division)। जब आयोग को विभिन्न विभागों में सहयोग की आवश्यकता होती है, तो समन्वय विभाग अपनी भूमिका निभाता है। प्रशासन विभाग के कार्य आर्थिक और पंचवर्षीय योजनाओं में समन्वय, अविकसित क्षेत्रों का पता लगाना, प्रदेशों की केन्द्रीय सहायता के तरीकों तथा योजना को कुशल प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में परामर्श देना आदि हैं।

2. साधारण विभाग (General Division)—योजना से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों के लिए अनेक साधारण विभाग हैं। प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष एक निदेशक होता है। मुख्य साधारण विभाग ये हैं—दीर्घकालीन योजना विभाग, आर्थिक विभाग, धर्म एवं रोजगार विभाग, प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग, सांख्यिकी तथा सर्वेक्षण विभाग, प्रबन्ध एवं प्रशासन विभाग।

3. विषय विभाग (Subject Division)—आर्थिक गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विषय-विभाग 10 हैं जो अपने विषय से सम्बन्धित योजना के लिए कार्य और शोध करते हैं—कृषि विभाग, भूमि सुधार विभाग, सिंचाई और शक्ति विभाग, ग्राम और लघु उद्योग विभाग, समाज सेवा विभाग, गृह विभाग, यातायात एवं संचार विभाग, उद्योग एवं खनिज पदार्थ विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग।

4. विशिष्ट विकास कार्यक्रम विभाग (Special Development Programme Division)—वर्तमान विशेष कार्यक्रमों के लिए 'विशेष विकास कार्यक्रम विभाग' बनाए गए हैं। ये दो हैं—ग्रामीण कार्य विभाग, एवं जन-सहकारिता विभाग।

योजना आयोग से सम्बद्ध अन्य संस्थाएँ

1. राष्ट्रीय नियोजन परिषद् (National Planning Council)—इस संस्था की स्थापना सरकार द्वारा फरवरी 1965 में योजना आयोग के सदस्यों की सहायता से की गई। जिसमें सावधानीपूर्वक चुने हुए सीमित सदस्यों में विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं। 'राष्ट्रीय नियोजन परिषद्' योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्य करता है।

2. कार्यशील दल (Working Groups)—योजना आयोग समय-समय पर 'कार्यशील समूह' नियुक्त करता है, जिनका कार्य ग्रहण्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए योजना-निर्माण में योजना आयोग और विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों में समन्वय करना है। इन कार्यशील समूहों के सदस्य योजना आयोग और विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों से लिए गए तकनीकी विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री और प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ उप-समूह (Sub groups) भी नियुक्त किए जाते हैं।

3. परामर्शदात्री संस्थाएँ (Advisory Bodies)—इन्हें Panel or Consultative Bodies भी कहते हैं। ये स्याई संस्थाएँ होती हैं जो सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों पर सुझाव देती हैं। इसके अतिरिक्त, संसद सदस्यों से परामर्श लेने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए Consultative Committee of Members of Parliament for Planning Commission तथा Prime Minister's Informal Consultative Committee for Planning बनाई गई है।

4. एसोसिएटेड बॉडीज (Associated Bodies)—इनमें से प्रमुख केन्द्रीय मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया और केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (Central Statistical Organisation) हैं। रिजर्व बैंक के आर्थिक विभाग से योजना आयोग निकट-सम्पर्क रखता है तथा उसके द्वारा किए गए अध्ययन योजना आयोग के लिए उपयोगी होते हैं। रिजर्व बैंक के इस विभाग का संचालक योजना आयोग के लिए अर्थ-शास्त्रियों के पैनल का मददगार होता है। आयोग के लिए आवश्यक सांख्यिकी एकत्रित करने का कार्य केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन करती है।

5. मूल्यांकन समितियाँ (Evaluation Committees)—योजनान्तर्गत प्रारम्भ की गई विभिन्न परियोजनाओं के कार्य-संचालन के मूल्यांकन हेतु 'मूल्यांकन समितियाँ' नामक विशिष्ट संस्थाओं का निर्माण किया गया है। Committee on Plan Projects इस प्रकार का उदाहरण है।

6. अनुसंधान संस्थाएँ (Research Institutions)—योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में 'अनुसंधान कार्यक्रम समिति' (Research Programme Committee) नामक विशिष्ट संस्था की स्थापना की है, जिसका अध्यक्ष आयोग का उपाध्यक्ष होता है। इसमें देश के रूपाति प्राप्त समाज वैज्ञानिकों को भी सदस्य नियुक्त किया जाता रहा है। इसी प्रकार प्राकृतिक साधनों के संरक्षण, विकास और उचित विक्षेपण आदि के लिए प्राकृतिक ससाधन समिति (Committee of Natural Resources) स्थापित की गई। इसके अतिरिक्त, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय व्यावहारिक

आर्थिक अनुसंधान परिषद् (Indian Council of Applied Economic Research) और आर्थिक विकास संस्थान (Institute of Economic Growth) यदि सन्ध्याएँ महत्वपूर्ण आर्थिक-सामाजिक अनुसंधान कार्य करती हैं जिसका उपयोग योजना आयोग करता रहता है।

7. राष्ट्रीय विकास परिषद् (National Development Council)—राष्ट्रीय विकास परिषद् योजना आयोग की सर्वोच्च नीति-निर्धारक संस्था है। यह योजना आयोग और विभिन्न राज्यों में समन्वय स्थापित करने का भी कार्य करती है। इसके मुख्य कार्य हैं—

- (i) समय-समय पर राष्ट्रीय योजना के कार्य-संचालन का पर्यावलोकन करना।
- (ii) राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक-नीति-सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना।
- (iii) राष्ट्रीय योजना में निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपाय सुझाना।
- (iv) जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना।
- (v) प्रशासनिक सेवाओं की कुशलता में वृद्धि करना।
- (vi) ग्रन्थ विकसित समाज के वर्गों और प्रदेशों के पूर्ण विकास के लिए प्रयत्न करना।
- (vii) समस्त नागरिकों के समान त्याग के द्वारा राष्ट्रीय विकास के लिए संसाधनों का निर्माण करना।

योजना आयोग की तरह राष्ट्रीय विकास परिषद् के पीछे भी सांविधानिक या कानूनी सत्ता नहीं होती, किन्तु इसकी सिफारिशों का केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा आदर किया जाता है। इस परिषद् में देश के प्रधान मंत्री और योजना आयोग के सदस्य होते हैं।

योजना का क्रियान्वयन (Implementation of the Plan)

भारत में योजना आयोग विशुद्ध रूप से परामर्शदात्री संस्था है। इसका कार्य योजनाओं का निर्माण करना और उनका मूल्यांकन करना है। इसके पास कोई प्रशासनिक शक्ति नहीं है अतः योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकारों का है। योजना निर्माण के पश्चात् केन्द्रीय और राज्य सरकारें अपने विभिन्न मन्त्रालयों और उनके अधीन विभागों द्वारा योजना के लिए निर्धारित कार्यक्रमों और लक्ष्यों की प्राप्ति की कार्यवाही करती हैं। कृषि, सिंचाई, सहकारिता, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से राज्य सरकारें क्रियान्वित करती हैं क्योंकि ये राज्य-सूची में आते हैं। अन्य विषयों जैसे—वृहत्-उद्योग, रेलें, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रमुख बन्दरगाह, जहाजरानी, नागरिक उड्डयन, संचार आदि से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर होता है।

भारत में नियोजन सम्बन्धी परियोजनाओं में से कुछ का केवल केन्द्रीय सरकार क्रियान्वित करती है कुछ को राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है और कुछ को केन्द्रीय और राज्य सरकारों दोनों मिलकर करती हैं। उदाहरणार्थ, भारत में पिछले नदी-घाटी योजनाओं में से कुछ का निर्माण और संचालन पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा, कुछ का केवल राज्य सरकारों द्वारा और कुछ केन्द्र और राज्य सरकारों ने तथा एक से अधिक राज्य सरकारों ने मिलकर किया है। निजी-क्षेत्र की योजनाओं का क्रियान्वयन निजी-क्षेत्र द्वारा किया जाता है यद्यपि सरकार इस कार्य में निजी क्षेत्र को आवश्यक वित्तीय, तकनीकी तथा अन्य प्रकार की सहायता देती है। सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओं का क्रियान्वयन सरकार द्वारा किया जाता है। कई अन्य देशों के समान भारत में भी योजनाकरण में विवेकीकरण की प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैं। लोकतांत्रिक विवेकीकरण द्वारा अन्तःस्तर पर जिला-परिषदें तथा खण्ड स्तर पर पंचायत समिति है, जो खण्ड-स्तर पर योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन का कार्य करती है।

इस प्रकार भारत में योजना का क्रियान्वयन केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभिन्न मन्त्रालयों और उनके अधीनस्थ विभागों द्वारा किया जाता है। योजना की सफलता इन विभागों के अधिकारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों की कुशलता, कर्तव्यपरायणता तथा ईमानदारी पर निर्भर करती है। योजनाओं की सफलता सामान्यतः जनता के सहयोग पर निर्भर करती है।

प्रगति की समीक्षा—योजना के क्रियान्वयन के लिए उनका निरन्तर निरीक्षण और प्रगति की समीक्षा आवश्यक है ताकि योजना की असफलताओं और उसके क्रियान्वयन के मार्ग में आने वाली बाधाओं का पता लगाया जा सके। भारत में योजना आयोग का योजना निर्माण के अतिरिक्त एक प्रमुख कार्य "योजना की प्रत्येक अवस्था के क्रियान्वयन द्वारा प्राप्त प्रगति का समय समय पर ब्यौरा रखना तथा उसके अनुसार नीति में समायोजन तथा अन्य उपायों के लिए सिफारिशें करना है।" अतः योजना आयोग समय समय पर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन और सफलता का पर्यवेक्षण करता है। जब वापिक योजना का निर्माण किया जाता है और उसे वापिक बजट में सम्मिलित किया जाता है तो आयोग केन्द्र और राज्य सरकारों से गत वर्ष की प्रगति के प्रतिवेदन मांगता है। इसके आधार पर योजना आयोग गत वर्ष की प्रगति प्रतिवेदन तैयार करता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय मन्त्रालयों और राज्य-सरकारों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विकास-कार्यक्रमों के व्यक्तिगत सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती है। कार्यक्रम मूल्यांकन समूह तथा योजना की परियोजना समिति योजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन करती है। इन अध्ययनों का उद्देश्य परियोजनाओं की विलम्ब पूर्ति, अपर्याप्त सफलता, ऊँची लागतों आदि के कारणों की जाँच करना और इन्हें दूर करने के उपाय बतलाना होता है। योजना आयोग योजना अवधि के मध्य में ही विभिन्न क्षेत्रों में योजना कार्यक्रमों की पूर्ति के सम्बन्ध में 'Mid Term' प्रतिवेदन भी

प्रकाशित करती है जिसमें ग्रामों की कार्यवाही की दिशाओं का भी संकेत होता है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के अन्त में योजना आयोग अवधि की समग्र समीक्षा, विकास सम्बन्धी तथ्यों तथा आई हुई बंठियाइयों और भविष्य के लिए सुझावों सहित प्रकाशित करता है। निजी-क्षेत्र में योजना की प्रगति की समीक्षा और मूल्यांकन के लिए और अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता है।

भारतीय नियोजन की विशेषताएँ—भारतीय नियोजन की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं—

- (i) भारतीय नियोजन जनतान्त्रिक नियोजन है।
- (ii) भारतीय नियोजन सोवियत रूस और चीन की तरह पूर्ण या व्यापक (Comprehensive) नियोजन नहीं है।
- (iii) भारतीय नियोजन का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना है।
- (iv) भारतीय नियोजन केन्द्रित और विकेन्द्रित दोनों प्रकार का है।

भारतीय योजना-निर्माण प्रक्रिया की समीक्षा

1. कई आलोचकों ने योजना आयोग को 'समानान्तर सरकार' (Parallel Government), 'सुपर कैबिनेट' (Super Cabinet) और 'गाडी का पांचवाँ पहिया' (The Fifth Wheel of the Coach) कहा है। किन्तु इस प्रकार की आलोचनाएँ अतिरिक्त हैं। भारत में सम्पूर्ण आयोजन इस प्रकार का है कि राष्ट्रीय योजना भी कार्यान्वित होती है और राज्यिक योजनाएँ भी। इस प्रकार, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति भी होती है और प्रांतीय एवं स्थानीय हितों की भी। मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक बनें। यदि इस उद्देश्य की पूर्ति में केन्द्रीकरण को कुछ प्रोत्साहन मिलता है और केन्द्र और राज्य सम्बन्ध एकात्मकता के लक्षणों से प्रभावित होते हैं तो इसमें 'अशुभ' कोई बात नहीं है। इसके अतिरिक्त योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था रहा है, इसके पास प्रशासनिक अधिकार नहीं हैं। योजना आयोग केन्द्र तथा राज्यों के विभिन्न स्तरों पर व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात् ही निर्णय पर पहुँचता है। इस प्रकार राज्य के सम्बन्ध में आयोग नियोजन-क्षेत्र में जो कुछ भी कहता है, उसमें राज्यों की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त होती है।

2. कुछ आलोचकों के अनुसार, योजना आयोग एक स्वतन्त्र और परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य नहीं कर पाता। मन्त्रियों को योजना आयोग का सदस्य नियुक्त किया जाता रहा है। इस प्रकार, यह संस्था राज्यनीति केन्द्रित है और यह विशेषज्ञ संस्था नहीं है। योजना आयोग की इस परम्परा का भी प्रतिरोध किया जाता है कि जब कभी किसी मन्त्रालय से सम्बन्धित विषय पर आलोचकों का सुझाव है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् और मन्त्रिमण्डल को तो राष्ट्रीय योजना सम्बन्धी प्रमुख रेखाओं और विनिष्ट सीमाओं का ही निरूपण करना चाहिए। इसके पश्चात् योजना निर्माण और विस्तृत ब्यौरा तैयार करने, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों का

निर्धारण करने विभिन्न वैकल्पिक उपायों में से विकास की किसी विशिष्ट पद्धति को अपनाने आदि के कार्य पूर्णरूप से योजना आयोग पर छोड़ दिए जाने चाहिए, क्योंकि ये तकनीकी मामले हैं। योजना आयोग के सदस्य सुविख्यात तकनीकी विशेषज्ञ होने चाहिए।

मन्त्रियों की सदस्यता न होने सम्बन्धी आयोग का तर्क सैद्धान्तिक रूप में अशुद्ध है और कुछ वर्षों पूर्व प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी सिफारिश की थी कि मन्त्रियों को आयोग का सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन व्यावहारिक स्थितियों का तर्काज है कि आयोग में मन्त्रिमण्डल को स्थान दिया जाए, क्योंकि नीतियों और निर्णयों के क्रियान्वयन का अन्तिम उत्तरदायित्व मन्त्रियों पर होता है। योजना की असफलता के लिए जनता प्रधानमंत्री और योजना मन्त्री को ही दोषी ठहराएगी, आयोग के विशेषज्ञों को नहीं। मन्त्रियों का जनता से निकट सम्पर्क होता है, वे जनता की आकांक्षाओं से परिचित होते हैं अतः आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के विचारों को अपनी सलाह से अधिक व्यावहारिक और जनानुकूल बना सकते हैं। एक परामर्शदात्री सस्था में परामर्श के श्रेष्ठ जितने प्रभावशाली होंगे निश्चय उतने ही अच्छे हो सकेंगे। हाँ, इस प्रकार के रक्षा कवच अवश्य होने चाहिए ताकि मन्त्रियों की उपस्थिति से आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों और स्वतन्त्र सदस्यों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशका न रहे।

3 यह धारणा की जाती है कि आयोग का आकार अनावश्यक रूप से काफी बड़ा हो गया है और इसके पदाधिकारियों, कर्मचारियों, विभिन्न समितियों और सस्थाओं में पर्याप्त मितव्ययिता किए जाने की गुंजाइश है। आयोग की कई विभागीय शाखाओं में कार्यों का स्पष्ट वर्गीकरण नहीं है और उनके कार्य एक दूसरे की परिधि में आ जाते हैं। अतः प्रत्येक विभाग में विवेकीकरण किया जाना चाहिए। विषय सम्भागों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए और साधारण सम्भागों की संख्या कम की जानी चाहिए।

4 अधिकांश राज्य सभाओं को गतिशील बनाने और उनके एकीकरण के मामले में राष्ट्रीय और दीर्घकालीन दृष्टिकोण से कार्य नहीं करते हैं। अनेक राज्य सरकारों में योजना के सम्बन्ध में सम्बन्धी प्राथमिक विचारों का भी अभाव है और योजना आयोग को दूध देने वाली गाय समझते हैं। उनमें से अधिकांश के लिए आयोग ऋण का अग्रिम नहीं प्रथम आवश्यकता है। अब तक राज्य सरकारें योजना आयोग से अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रही हैं और स्वयं न कम प्रयास किए हैं।

बहुधा ऐसे अवसर भी आते हैं जबकि योजना आयोग को राज्यों के मुख्य-मन्त्रियों को, सभाओं के आवंटन को गतिशील बनाने के सम्बन्ध में अप्रसन्न करना पड़े और ऐसा तभी हो सकता है जबकि आयोग के सदस्य और राजनीतिक क्षेत्र से लिए गए हों। तृतीय योजना में कृषि पर कर द्वारा सभाओं के एकीकरण के बारे में एक भी बात नहीं बही गई यद्यपि ऐसा करना नितान्त आवश्यक था। यह बहस जाता है कि आयोग ने ऐसा राजनीतिक कारणों से नहीं किया।

5. इसके अतिरिक्त पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में और भी कई कमियाँ हैं। कई आलोचकों के अनुसार सरकारी नीतियों और योजना के उद्देश्यों के बीच पर्याप्त अन्तर रहता है। सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियाँ और किए गए उपाय योजना के सामाजिक न्याय-क्षेत्र को और अधिक व्यापक बनाने की योजना के उद्देश्य के विपरीत पड़ती है। यह भूमि-सुधारों को क्रियान्वित करने, निजी-क्षेत्र में कारपोरेट उपक्रम के विकास और मुद्रा प्रसारिक प्रवृत्तियों के नियन्त्रण आदि से सम्बन्धित समस्याओं को हल करने के सरकारी विधियों के बारे में अधिक मही हैं। राज्य-सरकारों ने बहुधा योजना के क्रियान्वयन में निर्धारित प्राथमिकताओं का अनुपालन नहीं किया। बहुधा विनिष्ट परियोजनाओं हेतु राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता का उपयोग निश्चित उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया। योजना के क्रियान्वयन में एक और कमी यह अनुभव की गई कि योजना व्यय को सम्पूर्ण योजनावधि में समान रूप से वितरित नहीं किया गया। बहुधा योजना के प्रथम दो-तीन वर्षों में कार्य धीरे-चलता और अन्तिम वर्षों में निर्धारित व्यय शीघ्रता से पूरा किया जाता है। इससे सरकारों का ध्यान योजना के भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की अपेक्षा निर्धारित राशि को योजनावधि में व्यय करने पर अधिक केन्द्रित रहता है। परिणामस्वरूप, उतनी ही राशि व्यय करने पर भी अपेक्षाकृत कम लाभ रहता और प्रगति की दर कम रहती है। अब पंचवर्षीय योजनाओं को एक वर्षीय कार्यक्रमों में विभाजित करके क्रियान्वित करने का निश्चय किया गया है जिससे उपरोक्त समस्या का उचित समाधान हो जाएगा। योजना आयोग के अध्यक्ष श्री गाडगिल ने इसकी अनुपस्थिति के अनुसार "होता यह है कि पंचवर्षीय योजनावधि के प्रारम्भ में प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक प्राप्त करने और अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए ढोड़-धूप करता है, क्योंकि यह कार्य अभी नहीं होने पर पाँच वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इससे तनाव बढ़ता है। इससे योजना निर्माण में एक कठिन स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे हम बचना चाहते हैं"¹ और एक वर्षीय योजनाएँ इससे बचने का एक उपाय हैं।

6. भारतीय नियोजन में अब तक भी प्राथमिकताओं के मूल्यांकन के लिए कोई कसौटी उदाहरणार्थ, लागत-लाभ विश्लेषण (Cost benefit Analysis) आदि का व्यवहार अभी तक नहीं किया गया। है यह आवश्यक है कि इस प्रकार के मापदण्ड का उपयोग किया जाए, अन्यथा प्रत्येक विशेषज्ञ अपने विभाग के लिए कुछ न कुछ प्राप्त कर लेता है। *डॉ. एम्. एन. भारतीय नियोजन, सभी प्रकार की दिशाओं में*, बनाई गई विभिन्न योजनाओं का संग्रह है। इसका कारण यह है कि हमारे पास परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए कोई उपयुक्त मापदण्ड नहीं है जिससे विभिन्न विकल्पों में से कुछ विकल्पों का चयन किया जा सके। इस प्रकार, हमारे साधनों का अप-व्यय होता है। उदाहरणार्थ, सामाजिक कल्याण में बाल अपराध (Juvenile delinquency), परित्यक्त बच्चे, भिक्षुक, वेश्याएँ, अपंग व्यक्ति, तथा अन्य कई प्रकार के पहलू आते हैं और यदि हम इस सम्बन्ध में अपने देश की अन्य देशों से

1 D. R. Gadgil. Formulating the Fourth Plan, Yojna, Feb. 23, 1969, p. 8.

तुलना करें, तो हमारे विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से यही कहेंगे कि ये सब पहलू अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, किन्तु यदि हमारे साधन सीमित हैं तो हमें इनमें चुनाव करना पड़ेगा। उदाहरणार्थ, हम पहले बाल अपराधियों और परिव्यक्त बच्चों पर सारी राशि व्यय कर सकते हैं और भित्तिारियों और वेश्याओं के लिए अधिक चिन्ता नहीं करें। यद्यपि कुछ वर्गों की इस प्रकार उपेक्षा करना एक कठोर निर्णय है, किन्तु हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। इस प्रकार सभी क्षेत्रों में सब कार्यक्रमों को अपनाने की अपेक्षा कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में अधिकाधिक साधन लगाए जाने चाहिए अन्यथा विशेष परिणाम नहीं निकल पाएंगे।

7. हमारे योजना निर्माण की एक कमी यह है कि यद्यपि हमारा देश एक अत्यन्त निर्धन देश है किन्तु वित्त मन्त्रालय और योजना आयोग के प्रतिरिक्त नियोजन के सभी स्तरों पर साधनों के उपयोग में समय की आवश्यकता को अनुभव नहीं किया गया है और साधनों का कई जगह अपव्यय किया गया है। हमें इस बात को अनुभव करना चाहिए कि हमारा देश विश्व के निर्धनतम देशों में से एक है, अतः हमें देश के साधनों का अत्यन्त मितव्ययितापूर्वक कार्य करना चाहिए। साथ ही, प्रबन्धात्मक प्रयत्नों (Management Efforts) में अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। राज्यों को सहायता देने की प्रणाली भी उचित नहीं कही जा सकती। प्रशासनिक सुधार आयोग ने विभिन्न प्रकार के 'प्रमुख अनुदान' (Matching Grants) और सहायता की वर्तमान पद्धति में परिवर्तन का सुझाव दिया है। सोभाय्य से इसे राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय ने भी स्वीकार कर लिया है। अब राज्यों को 'प्रमाणित योजनाओं' (Standard Schemes) से युक्त योजनाओं को बनाने की आवश्यकता नहीं है। वे अपनी इच्छानुसार योजनाएँ बना सकते हैं। केवल उन्हें योजना आयोग को उनके उद्देश्य बताने, और यह बताने की आवश्यकता है कि वे उन योजनाओं को किस प्रकार क्रियान्वित करेंगे? अब राज्यों को निश्चिन्त रूप से यह बता दिया जाएगा कि उन्हें कितनी सहायता मिलने वाली है? उसके पश्चात् उन्हें अपने प्रयत्नों द्वारा प्राप्त राशि का अनुमान लगाना होगा और उसके अनुरूप वे अपनी योजनाएँ बना सकेंगे। अब राज्यों की योजनाओं का आधार उनके स्वयं के प्रयासों द्वारा साधनों की गतिशील बनाने पर निर्भर करेगा क्योंकि उन्हें केन्द्रीय सहायता का स्पष्ट अनुमान पहले ही प्राप्त हो जाएगा और राज्य 'Inflated Plans' प्रस्तुत नहीं करेंगे।

वास्तव में इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आयोग के गठन और योजनाओं के क्रियान्वयन में अनेक गम्भीर दाप रहे हैं और राष्ट्र को इनकी कीमत चुकानी पड़ी है। लेकिन 26 जून, 1975 को राष्ट्रीय आपात् स्थिति की उद्घोषणा और 1 जुलाई, 1975 से बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम लागू किए जाने के पश्चात् राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था ने एक नया मोड़ लिया है। चट्टीपुखी सुधार और प्रगति की एक लहर चल पड़ी है। योजना आयोग का पुनर्गठन किया गया है, पंचवर्षीय योजना का पुनर्प्रस्तुत किया जा रहा है और आशा है कि सितम्बर, 1976 में राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक के बाद निवृत्त भविष्य में योजना का जो नया रूप जनता के समक्ष रहेगा वह विगत वर्षों की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक रहेगा।

भारत में गरीबी और असमानता इस हद तक व्याप्त है कि विश्व के आर्थिक रणमंच पर भारत की भूमिका के महत्व की बात करना हास्यास्पद लगता है। आर्थिक धाँकड़े, देशवासियों का जीवन स्तर, आर्थिक विषमताओं की गहरी खाई, गरीबी के मुँह बोलने चिह्न इस बात की स्पष्ट झलक देते हैं कि भारत विश्व का एक अत्यधिक गरीब देश है। भारत में गरीबी की व्यापकता और भयावहता का अनुमान सरकार के 'गरीबी हटाओ' के नारे से भी व्यक्त होता है। देश की पाँचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य ही गरीबी और असमानता पर प्रहार करना तथा देश को आत्म-निर्भरता के स्तर पर पहुँचाना है। योजना-प्रारूप में यह निश्चय व्यक्त किया गया है कि अति-भयावह निर्धनता अथवा गरीबी का जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर को एक न्यूनतम स्तर पर लाया जाएगा।

भारत में गरीबी और विषमता की एक झलक

विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित सूचना के अनुसार, विश्व के लगभग 122 देशों में प्रति व्यक्ति आय के सम्बन्ध में भारत का स्थान 102वाँ है। हमारे देश में प्रति धर्माक्त औसत वार्षिक आय 825 रु. है और विगत दस वर्षों में देश के आर्थिक विकास में मात्र 1.2% प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई है।¹ एक अन्य अध्ययन के अनुसार विश्व में 25 देश ऐसे हैं, जो बहुत ही गरीबी की स्थिति में हैं और इन देशों में भारत का स्थान प्रमुख है। इन गरीब देशों में उद्योगों का राष्ट्रीय आय में अंशदान 10% से भी कम है तथा 15 साल से बड़ी उम्र की 20% से भी अधिक जनसंख्या अशिक्षित है। संयुक्तराष्ट्र के अनुसार इन देशों के 20% व्यक्तियों को पूरा भोजन नहीं मिलता और 60% लोगों को अप्रौष्टिक भोजन प्राप्त होता है। प्रतिवर्ष 30 लाख टन प्रोटीन वाल औद्योगिक राष्ट्र इन देशों में खाद्यान्न भेजते हैं।² भारत, जो गरीब देशों में

1. डॉ. रामधन राय, निदेशक भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद् का लेख 'देश के जिले और विकास के आयाम'—साप्ताहिक हिन्दुस्तान 23, सितम्बर, 1973, पृष्ठ 13
2. श्री आर. बर्मा 'समाजवादी समाज की स्थापना के लिए गरीबी हटाना आवश्यक' योजना 22 मार्च, 1973, पृष्ठ 21.

प्रमुख है, विश्व की 15% जनसंख्या का उसके 1/7 क्षेत्रफल में भरण पोषण कर रहा है, किन्तु राष्ट्रीय उत्पादन की दृष्टि से विश्व के 122 देशों में उसका स्थान 95वाँ तथा एशिया के 40 देशों में 30वाँ है। भारत की 45 करोड़ जनता किसी न किसी रूप में बेरोज़गार है। 38 करोड़ 60 लाख व्यक्ति निरक्षर हैं। प्रत्येक भारतीय लगभग 1,314 रु. के विदेशी-ऋणभार से दबा हुआ है।¹ रुपये की क्रय-शक्ति मई, 1974 में, मात्र 339 पैसे (आधार 1959 वर्ष) थी।² देश के लगभग 22 करोड़ व्यक्ति अत्यन्त गरीबीपूर्ण जीवन बिता रहे हैं। देश में आर्थिक विषमता चौड़ा देने वाली है। जहाँ एक ओर गगनचुम्बी अट्टालिकाएँ हैं और वैभव छछेलियाँ करता है वही दूसरी ओर व्यक्तियों के पास रहने को भोरेडी भी नहीं है। वे सड़क पर ही जन्म लेते हैं, सड़क पर ही पलते हैं और सड़क पर ही मर जाते हैं।

(क) दांडेकर एवं नीलकण्ठ रथ का अध्ययन

दांडेकर एवं रथ ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक 'भारत में गरीबी' में देश की निर्धनता (1960-61 की स्थिति) का चित्र खींचा है और यह चित्र वर्तमान स्थिति में भी बहुत कुछ सही उतरता है। इसके अनुसार, देश की निर्धनता ही देश की गरीबी का प्रमुख कारण है। ससार के सभी देशों में भारत अत्यन्त निर्धन देश है। अफ्रीका, दक्षिणी-अमेरिका तथा एशिया के अनेक अक्रिय देशों की अपेक्षा भी भारत गरीब है। निर्धनता में भारत की बराबरी केवल दो ही देश—पाकिस्तान और दण्डोनेशिया कर सकते हैं। यदि इस गरीबी को आंकड़ों में स्पष्ट करना हो तो लोगों का जीवन-स्तर देखना होगा। सन् 1960-61 में देश का औसत जीवन-स्तर अर्थात् प्रति व्यक्ति वार्षिक निर्वाह-व्यय लगभग केवल 275 से 280 रुपये तक ही था। अर्थात् प्रति दिन औसतन 75-76 पैसे में लोग जीवन-यापन करते थे। इस औसत को ग्रामीण एवं शहरी भागों के लिए भिन्न-भिन्न करके बताना हो तो यह कहा जा सकता है कि देहाती भाग में प्रति व्यक्ति वार्षिक निर्वाह व्यय लगभग 260 रुपये था, वार्षिक तौर पर देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि शहरी भाग का जीवन स्तर ग्रामीण भाग के जीवन-स्तर की अपेक्षा लगभग 40% अधिक था। परन्तु जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों में ग्रामीण एवं शहरी भागों में विद्यमान अन्तर को ध्यान में रखा जाए तो दोनों विभागों का औसत जीवन स्तर लगभग समान हो जाता है। सन् 1960-61 में ग्रामीण जनता प्रतिदिन लगभग 75 पैसे में और शहरी जनता लगभग 1 रुपये में जीवन-यापन करती थी।

“समाज में विद्यमान असमानताओं को ध्यान में रखा जाए तो स्पष्ट है कि आने से अधिक व्यक्ति गरीब से नीचे होंगे बल्कि लगभग 2/3 व्यक्ति गरीब से नीचे होंगे। अर्थात् ग्रामीण भाग में दो-तिहाई व्यक्तियों का दैनिक खर्च 75 पैसे से भी कम था और शहरी भाग में दो तिहाई लोगों का दैनिक व्यय एक रुपये से भी कम था।

1. वही, पृष्ठ 2।

2. केन्द्रीय वित्त मन्त्री श्री चट्टाण की सूचना—हिन्दुस्तान, 27 जुलाई 1974।

इनमें से अनेक व्यक्तियों का दैनिक व्यय इस औसत से बहुत ही कम था। सक्षेप में 40 प्रतिशत ग्रामीण जनता प्रतिदिन 50 पैसे से भी कम खर्च में जीवन-यापन करती थी। इसमें घर का अनाज या अन्य कृषि-उपज, दूध वगैरह का जो प्रयोग घर में किया जाता है उसका बाजार मूल्य शामिल है। शहरी भाग में 50 प्रतिशत जनता प्रतिदिन 75 पैसे से भी कम खर्च में निर्वाह चलाती थी। दोनों भागों के बाजार-मूल्यों के अन्तर को ध्यान में रखा जाए तो ग्रामीण भाग के 50 पैसे और शहरी भाग के 75 पैसे लगभग समान थे।¹

इस गरीबी का जिन लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, उन्हें इन आँकड़ों पर सहमा विश्वास नहीं होगा। स्वर्गीय डॉ. राममनोहर लोहिया ने कुछ वर्ष पूर्व लोकसभा में यह कह कर सनसनी उत्पन्न कर दी थी कि भारतीय ग्रामीण की औसत आय 19 पैसे प्रतिदिन है। जैसा होना चाहिए या सरकारी स्तर पर इसका प्रतिवाद किया गया। परन्तु कुछ समय पश्चात् सरकारी स्तर पर ही यह माना गया कि भारतीय ग्रामीण की औसत आय 37 पैसे प्रतिदिन है और यह माना जा सकता है कि सरकारी आँकड़ों और वास्तविक आँकड़ों में कितना अन्तर होता है।² डाँडिकर एव रथ की टिप्पणी है कि “अनेक व्यक्तियों को इसका विश्वास ही नहीं होता था और अब भी अनेक लोग इसकी सच्चाई में सन्देह करते हैं। परन्तु देश की गरीबी का यह सच्चा स्वरूप है, इन आँकड़ों में पैसे-दो पैसे का अन्तर पड़ सकता है। प्रतिशत में एक-दो अंकों का अन्तर हो सकता है किन्तु स्थूल रूप में यह आँकड़े तथ्य-प्रदर्शक हैं।”³

“प्रश्न उठना है कि इतने से खर्च में ये लोग कैसे निर्वाह करते हैं? एक दृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर बड़ा सरल है। इन लोगों के सामने यह सवाल कभी खड़ा नहीं होता कि पैसे का क्या किया जाए? शरीर की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ही उनका सारा पैसा खर्च हो जाता है। उदाहरणार्थ 1960-61 साल के मूल्यों को ध्यान में रखा जाए तो ग्रामीण भाग में प्रति व्यक्ति 50 पैसे में निर्वाह करना हो तो 55 से 60 प्रतिशत खर्च केवल गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा आदि खाद्यान्नों पर, 20 से 25 प्रतिशत तेल, नमक, मिर्च, चीनी, गुड़ आदि साध वस्तुओं पर, और 7 से 3 प्रतिशत ईंधन, दीपा बत्ती आदि पर करना पड़ता है अर्थात् कुल निर्वाह व्यय का 35 प्रतिशत भाग केवल जीवित रहने पर ही व्यय होता है। उसमें यह सोचने के लिए अवसर ही नहीं होना कि क्या खरीदा जाए और कौन-सी वस्तु न ली जाए। शेष 15 प्रतिशत में कपड़ा, साबुन, तेल, पान, तम्बाकू, दवा-दारू आदि का खर्च चलाना पड़ता है। उसी में कुछ कमी-बेसी हो सकती है।”³

डाँडिकर एव रथ ने अपने अध्ययन से निष्कर्ष निकाला है कि “1960-61 में उस समय के मूल्यों को ध्यान में रखा जाए तो ग्रामीण भाग में न्यूनतम आवश्यकता

1. डॉ. रामाधय राय वही, पृष्ठ 13.

2. डाँडिकर एव रथ वही, पृष्ठ 2

3. वही, पृष्ठ 3

को पूर्ण करने के लिए प्रतिदिन 50 पैसे या वार्षिक 180 रु लगते थे और इस हिमाय से 1960-61 में देश की 40 प्रतिशत जनता गरीब थी। इन लोगों को साल भर में दो जून भोजन नहीं मिलता था अर्थात् उसका विश्वास नहीं था। शहरी भाग से जीवनोंयोगी वस्तुओं के मूल्यों को ध्यान में रखा जाए तो वहाँ प्रतिदिन 75 पैसे या वार्षिक 240 रुपये लगते थे। शहरी जनता में से 50 प्रतिशत व्यक्तियों को वे उपलब्ध नहीं थे। संक्षेप में गरीबी की इस ग्यूनतम परिभाषा के अनुसार भी 1960-61 में अर्थात् स्वाधीनता-प्राप्ति के 10-12 वर्ष बाद और आर्थिक विकास की पचवर्षीय योजनाओं के पूरा हो जाने के बाद भी देश की 40 प्रतिशत देहाती जनता और 50 प्रतिशत शहरी जनता गरीब थी। इन सभी व्यक्तियों का हिमाय लगाया जाए तो उनकी संख्या 18 करोड़ से अधिक हो जाती है। 1960-61 में देश के लगभग 43 करोड़ लोगों में से 18 करोड़ लोग गरीब थे, अर्थात् भूखे थे।”¹

“गरीबी की यह मात्रा देश के सभी भागों में न समान थी और न है। साधारणतया उत्तरी भारत में, अर्थात् पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में गरीबी कम है। इस प्रदेश की देहाती जनता में गरीबी की मात्रा 20-25% से अधिक नहीं है। इसके विपरीत दक्षिणी भारत में अर्थात् तमिलनाडु, केरल, आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों की देहाती जनता में गरीबी की मात्रा 50-60% या उससे भी अधिक है। पूर्वी भारत में, अर्थात् बिहार, उड़ीसा पश्चिमी बंगाल, असम आदि राज्यों में भी देहाती जनता में गरीबी की मात्रा 40-50% है। देहाती व्यक्तियों में से अधिकतर व्यक्ति रोटी की तलाश में शहरों की ओर आते हैं, इसलिए भारत के विभिन्न प्रदेशों में शहरी जनता में गरीबी की मात्रा भी उसके अनुसार कम या अधिक है।

“रोटी की आशा में यही गरीबी जब शहरों में पहुँच जाती है तब उसका स्वरूप घृणित हो जाता है। गन्दी बस्तिया या फुटपाथ पर बैठकर सामने की आलीशान इमारतों की तडक-भटक देखने हुए, वहाँ के बिलासी-जीवन के सुरों को सुनते हुए, इससे पैदा होने वाली लालसा एवं ईर्ष्या को दबाते हुए या उसका शिखर बन कर यह गरीबी बुरे मार्ग पर चलने लगती है।

“सन् 1960-61 में, अर्थात् योजनावद्ध विकास की दो पचवर्षीय योजनाओं के पूरे हो जाने के पश्चात् भी देश की 40% देहाती और 50% शहरी जनता इस ग्यूनतम जीवन-स्तर की यन्त्रणा में फँसी हुई थी।”²

सन् 1960-61 की स्थिति का चित्रण करने के उपरान्त डॉक्टर और रथ ने आगामी दस वर्षों के आर्थिक विकास पर दृष्टि डाली है और बताया है कि ‘1960-61 से 1968-69 तक विकास की गति प्रतिवर्ष 3% से अधिक नहीं होती अर्थात् राष्ट्रीय उत्पादन में प्रतिवर्ष 3% से अधिक वृद्धि नहीं हुई। राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि

1. वही, पृष्ठ 3

2. वही, पृष्ठ 4

की यह गति या दर देश की गरीबी को हटाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि के हिसाब से हो या 3 % के हिसाब से, जनसंख्या अलग से अपनी स्वतन्त्र गति से बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त विकास योजनाओं में से अनेक उत्पादन कार्यक्रम प्राशानुकूल फलदायी नहीं हुए हैं। दाढ़िकर एव रथ ने अपना निष्कर्ष व्यापक शब्दों में अभिव्यक्त करते हुए लिखा है कि "1960-61 में जिस गरीब का दैनिक व्यय 50 पैसे था वह 8 वर्षों के अंतराल 1968-69 में 52 पैसे हुआ है, यह उस बेचारे के समझने में कैसे आए ? और 1960-61 में जिसका दैनिक व्यय 50 पैसे भी नहीं था, जो घबरेट रहता था, उसे यदि कोई आँकड़ों का यह जादू बताकर यह पूछे कि, अरे बाबा बहुत आर्थिक प्रगति हुई है, विकास हो रहा है, हरित क्रान्ति का नारा बुलन्द हुआ है, फिर भी तुम इस तरह उदास क्यों हो ? क्या तुम यह नहीं जानते कि दस साल पहले तुम 50 प्रतिशत भूखे रहते थे, जबकि अब केवल 48 प्रतिशत ही भूखे रहते हो ? तो यह सब उस गरीब की समझ में कैसे आए ? देश की निर्धनता का यह स्वरूप देखने पर ऐसा लगता है कि मानो आर्थिक विकास के चूहे ने पहाड़ खोदना शुरू कर दिया है।"

(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का अध्ययन

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने प्रति-व्यक्ति उपभोक्ता व्यय सम्बन्धी आँकड़े सकलित करके देशवासियों के जीवन-स्तर पर और इस प्रकार देश में गरीबी की व्यापकता पर प्रकाश डाला है। इस अध्ययन को संक्षेप में एस. एच. पिटवे ने योजना में प्रकाशित अपने एक लेख में व्यक्त किया है¹—

"राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का अनुमान है कि 1960-61 में प्रति व्यक्ति उपभोक्त-व्यय 278 8 रु. वार्षिक था। प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय के ये आँकड़े ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों से अलग-अलग उपलब्ध किए गए हैं। 1960-61 में 43.27 करोड़ जनसंख्या में से 35.54 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में और 7.73 करोड़ शहरी क्षेत्र में रहती थी। अनुमान के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का औसतन प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय 261 2 रु. था और ग्रामीण क्षेत्र की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या इस औसत स्तर से नीचे का जीवन व्यतीत कर रही थी। शहरी जनसंख्या का प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय औसत 359 2 रु. था और ग्रामीण क्षेत्र के समान ही शहरी क्षेत्र की भी दो-तिहाई जनसंख्या इस स्तर से नीचे का जीवन व्यतीत कर रही थी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उक्त निम्नस्तरीय उपभोक्ता व्यय ही इस बात के सूचक हैं कि भारत एक अत्यधिक गरीब देश है और जनसंख्या का एक बड़ा भाग निम्न स्तर पर जीवन व्यतीत कर रहा है।

"गरीबी की व्यापकता का यह एक बहुत ही दुःखदायी तथ्य है कि 1960-61 में ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 2.27 करोड़ व्यक्तियों में प्रति व्यक्ति मासिक व्यय 8 रु.

1. योजना दिनांक 7 मार्च, 1973, पृष्ठ 19—एस. एच. पिटवे का लेख 'भारतीय गरीबी का विश्लेषण, रहन-सहन का स्तर तथा जीवन-यापन की दशा'

से भी कम या अर्थात् 27 पैसे प्रतिदिन से भी कम। यदि हम पाँचवी पंचवर्षीय योजना की छरेखा में निर्धारित गरीबी के न्यूनतम उपभोक्ता व्यय (1960-61 के मूल्यों के अनुसार 20 रु. प्रतिमास और अक्तूबर 1972 के मूल्यों के अनुसार लगभग 40 रु.) को यहाँ लागू करें तो विदित होगा कि 1960-61 में ग्रामीण क्षेत्र के 22.49 करोड़ व्यक्ति अथवा लगभग 63% जनसंख्या उस स्तर से भी नीचे का जीवन यापन कर रही थी। शहरी क्षेत्र का भी यही हाल था, किन्तु उनकी स्थिति उतनी बदतर नहीं थी। सन् 1960-61 में 8 रु. प्रतिमाह तक अर्थात् 27 पैसे प्रतिदिन से भी कम खर्च करने वाले व्यक्तियों की संख्या वहाँ 17 लाख अथवा 2.20 प्रतिशत थी। इसे भी यदि गरीबी की परिभाषा के उसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो विदित होगा कि शहरी क्षेत्र की लगभग 44% जनसंख्या निम्न-स्तर पर अपना गुजारा कर रही थी। उन व्यक्तियों को जो जनसंख्या के इन गरीब वर्गों तथा ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 63% और शहरी क्षेत्र के 44% से अछूने हैं, उन्हें यह अत्यन्त आश्चर्यजनक व कल्पनातीत लगेगा कि ये अत्यधिक गरीब लोग इस स्तर पर किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। इसीलिए जब कोई व्यक्ति गरीबी के ये तथ्य जनता के सामने उजागर करता है तो कुछ व्यक्ति स्वयं रह जाते हैं और सम्यक् दृष्टि से उन पर अपना रोष प्रकट करते हैं तथा कुछ लोग तो इस पर विषवास ही नहीं कर पाते। फिर भी, इस देश में इस प्रकार गरीबी एक भयावह सत्य है।¹

(ग) डॉ. रामाश्रय राय का आर्थिक विषमता पर अध्ययन

देश में व्याप्त आर्थिक विषमता का बड़ा विद्वत्पूर्ण अध्ययन डॉ. रामाश्रय राय (निदेशक, भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद्) ने साप्ताहिक हिन्दुस्तान दिनांक 23 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित अपने लेख 'देश के जिले और विकास के आयाम' में प्रस्तुत किया है। इस अध्याय के कुछ मुख्य उद्धरण नीचे प्रस्तुत किए जा रहे हैं—

1. समाज के विभिन्न वर्गों, देश की भौगोलिक इकाइयों में सुलभ आर्थिक साधनों एवं सुविधाओं के वितरण के ढंग में यह विषमता ठीक प्रकार परिलक्षित होती है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि भारतीय जनता का जीवन स्तर बहुत ही निम्न है। जहाँ अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय का औसत 6000 डॉलर (लगभग 43,000 रु.) है, वहाँ हमारे देश में मात्र 100 डॉलर (लगभग 725) है। ऐसी विषमता की स्थिति में यदि प्राप्य साधनों के वितरण में विषमता हो तो स्थिति कितनी शोचनीय हो जाएगी, इसकी कल्पना मात्र से सिहरन उत्पन्न हो जाएगी।

साधनों के वितरण की विषमता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 1960-61 के मूल्यों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति औसत उपभोक्ता व्यय केवल 258.8 रु. मात्र था और 1967-68 तक इसमें मात्र

10 रु की वृद्धि हुई जबकि तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा उसके पश्चात् दो वार्षिक योजनाओं में कुल मिलाकर लगभग 15,000 करोड़ रु देश के विकास पर व्यय किए गए। अर्थात् प्रति व्यक्ति औसतन 300 रु व्यय किए गए। अतः स्पष्ट है कि विकास का लाभ सम्मत्त वर्ग ने उठाया। इसका एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जिनकी आय की मात्रा जिनकी अधिक है उनको विकास स्वरूप प्राप्त लाभ में से उतना ही अधिक अंश प्राप्त होता है।

2. आर्थिक साधनों एवं सुविधाओं के विकास के साथ साथ घनहीन एवं धनी वर्ग के अन्तराल में वृद्धि हुई है। ऐसी बात नहीं कि यह विषमता ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित हो। शहरी क्षेत्रों में भी इस अन्तराल में व्यापक वृद्धि हुई है। एक ओर जहाँ आलीशान कोठियों का निर्माण हुआ है, जहाँ एक वर्ग अत्यधिक आधुनिक एवं सम्मत्त नज़र आ रहा है वहाँ भूखे पेट या आधा पेट खा कर सोने वालों की संख्या में भी आशातीत वृद्धि हुई है।

3. यदि भौगोलिक इकाइयों के सम्बन्ध में विषमता को लें तो भी बड़े रोचक स्थितियाँ सामने आती हैं। देश के सभी राज्यों में लगभग 350 जिले हैं। इनमें 303 जिलों में किए गए सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि केवल 130 जिले ही ऐसे हैं जिन्हें औद्योगिक एवं विकास की दृष्टि से शीर्षस्थ माना जा सकता है। कुल 134 जिले ऐसे हैं, जिन्हें कृषि-विकास की दृष्टि से उच्चकोटि का माना जा सकता है। औद्योगिक एवं कृषि-क्षेत्र में विकास की दृष्टि से सम्मत्त जिलों की संख्या मात्र 53 है और औद्योगिक दृष्टि से मध्यम किन्तु कृषि विकास की दृष्टि से उच्चकोटि में रखे जाने वाले जिलों की संख्या केवल 86 है।

अतः स्पष्ट है कि कृषि विकास की प्रक्रिया केवल उन्हीं जिलों में चल पाती है, जिनमें औद्योगिक विकास द्वारा कृषि विकास में सहायक ढाँचे का निर्माण हो चुका है अर्थात् औद्योगिक दृष्टि से विकसित जिलों में ही कृषि-विकास का कार्य होता है। कुछ ऐसे भी जिले हैं जो औद्योगिक दृष्टि से कम विकसित हैं परन्तु कृषि क्षेत्र में काफी विकसित हैं। लेकिन ऐसे जिले केवल वही हैं जिनके निकटवर्ती जिलों में औद्योगिक एवं कृषि विकास हो चुका है और वे निकटवर्ती होने का लाभ उठा रहे हैं। जो जिले आरम्भ से ही आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए थे उनमें पिछड़ी दोनो दशावस्थियों में विकास क्रम या तो आरम्भ ही नहीं किए गए या बहुत कम किए जा सके हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विषमता आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं, भौगोलिक-क्षेत्र में भी व्यापक रूप से व्याप्त है।

4. हम एक अन्य तरीके से भी इस विषमता को मान लें कि हम इन 303 जिलों को 6 वर्गों में बाँट लें और प्रत्येक वर्ग का 6 विशेषताओं के आधार पर अध्ययन करें। ये 6 वर्ग हो सकते हैं—औद्योगिक विकास, आयुस्तर, कृषि-विकास, वार्षिक विविधता एवं आर्थिक हीनता, प्रचल जनसंख्या तथा सामाजिक पिछड़ापन। यो चाहे तो अन्य वर्ग भी हो सकते हैं।

प्रथम वर्ग में 58 जिले हैं जिनमें औद्योगिक विकास नाममात्र को भी नहीं

हृष्या और कृषि-विकास के नाम पर भी इन 58 में से केवल 18 जिलों में थोड़ी-बहुत प्रगति की है। आप्रभुवनरण की दृष्टि से श्रम-शायं हेतु मानव-शक्ति का अभाव है, और जो मानव-शक्ति सुलभ है, वह केवल जिन में ही रोजगार खोजती है। जिले के बाहर जाना उनके स्वभाव के विरुद्ध है। सामाजिक दृष्टि से इन जिनो के निवासी एकलप हैं।

द्वितीय वर्ग में 54 जिले हैं। जिनमें औद्योगिक विकास तो काफी दृष्टा है, परन्तु कृषि-विकास के नाम पर थोड़ा-बहुत हो कार्य हो पाया है। मानव-सम्पदा भी कम है। फिर इनमें से 40% जिलों की श्रम-शक्ति कार्य की खोज में अग्र्यत्र चली जाती है। सामाजिक दृष्टि से पर्याप्त माना न जायक विविधता विद्यमान है और काफी जिलों में समाज के पिछड़े वर्गों की समस्या अधिक है।

तृतीय वर्ग में 68 जिले हैं, जो कृषि-क्षेत्र में काफी विकसित हैं। इनमें से 30 जिले ऐसे हैं, जो औद्योगिक विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। यहाँ श्रम-शक्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। केवल 4 जिलों को छोड़ कर शेष जिलों के श्रमिक अपने जिलों से अन्य कहीं नहीं जाते। सामाजिक दृष्टि से 23 जिलों में सामाजिक विविधता पाई जाती है और 53 जिलों में पिछड़े वर्ग के व्यक्ति अधिक संख्या में हैं।

चतुर्थ वर्ग में 45 जिले हैं। यह औद्योगिक विकास की दृष्टि से उन्नत है, परन्तु 18 जिले कृषि विकास में पिछड़े हुए हैं। 11 जिले ऐसे हैं जहाँ श्रम-शक्ति का अभाव है, फिर भी प्रायः से अधिक जिलों में श्रमिक कार्य की खोज में इधर-उधर चले जाते हैं। सामाजिक दृष्टि से सामिक विविधता बहुत अधिक पाई जाती है और 19 जिलों में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या अधिक है।

पाँचवीं श्रेणी के 45 जिलों में से 11 जिले औद्योगिक विकास की दृष्टि से तथा 5 जिले कृषि-विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इस श्रेणी के अधिकांश जिलों में श्रम शक्ति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और 13 जिलों के केवल थोड़े से अधिक आजीविका की खोज में इधर-उधर जाते हैं। सामाजिक दृष्टि से 42 जिलों में बामिन विविधता बहुत अधिक है और 29 जिलों में पिछड़े वर्गों की संख्या काफी है।

अन्तिम वर्ग में 33 जिले आते हैं। इन सभी जिलों में औद्योगिक दृष्टि से काफी प्रगति नहीं है। कृषि-विकास में भी केवल 2 जिले ही पीछे हैं। श्रम-शक्ति भी सभी जिलों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन आर्थिक विकास के बावजूद अधिक माजीवता के लिए उचित क्षेत्रों में आते रहते हैं। केवल 8 जिलों में घास-पौड़ी विविधता अधिक है और 26 जिलों में पिछड़े वर्गों की संख्या अधिक है।

आर्थिक असमानता दहाँ तक बढ़ गई है कि सरकारी क्षेत्र में इस बात पर चिन्ता प्रकट की जाती है कि देश के गिने चुने हाथों में आर्थिक शक्ति का सन्त्रण होता जा रहा है। अत्यन्त ग़ल्प-संरुपक वर्ग उत्पादन के यन्त्रों पर एकाधिकार रखे हुए है तथा एकाधिकारी-पूँजी का तीव्र विकास होता जा रहा है। निषाजन का एक मूलभूत उद्देश्य देश में व्याप्त आर्थिक विषमताओं को अधिकाधिक कम करके

समाजवादी ढंग में समाज की स्थापना की ओर आगे बढ़ना है। हमारे देश में एक ओर तो कुछ प्रतिशत लोग वैभव का जीवन बिता रहे हैं तो दूसरी ओर जनता का अधिकांश भाग अभाव की छाया में पल रहा है। न उन्हें भोजन की निश्चिन्ता है और न आवास की। खाने और तन ढकने की पुविधा भी देश के कंगेडो लोगों को ढग से उपलब्ध नहीं है। लाखों लोग “कुट-पाथी पर पैदा होते हैं पनपते हैं, मुक्ति, मर जाते हैं।”¹

(घ) भारतीय व्यापार एवं उद्योग मण्डलों के महासंघ द्वारा किया गया अध्ययन

भारतीय व्यापार एवं उद्योग मण्डलों के महामण ने जो अध्ययन किया तदनुसार अंग्रेजों का जादू कुछ भिन्न बैठता है। इस अध्ययन का सारांश 16 अक्टूबर, 1972 के दैनिक हिन्दुस्तान में निम्नानुसार प्रकाशित हुआ था—

देश में दस व्यक्तियों में से चार से अधिक व्यक्ति गरीबी की निर्धारित सामान्य सीमा से भी नीचे है। वे प्रतिमास देहात के लिए अपेक्षित राष्ट्रीय न्यूनतम राशि 27 रुपये प्रति मास और शहरों के लिए 40.5 रुपये प्रतिमास से भी कम व्यय करते हैं। 1969 के अन्त में कुल 52 करोड़ 95 लाख की जनसंख्या में 21 करोड़ 83 लाख व्यक्ति अर्थात् 41.2 प्रतिशत गरीबी की निर्धारित सीमा से नीचे हैं।

संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश और बिहार में सर्वाधिक गरीब व्यक्ति हैं। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 86 लाख व्यक्ति गरीब हैं। देश के गरीबों का 30 प्रतिशत इन दोनों राज्यों में रहता है। परन्तु प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक गरीब लोग उड़ीसा में हैं। वहाँ 64.7 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी की निर्धारित सीमा से नीचे हैं। इसके पश्चात् अरुणाचल प्रदेश का स्थान है। वहाँ 57.4 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी की सीमा से नीचे हैं। नागालैण्ड में 52.9 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी की सीमा से नीचे हैं। दस अन्य राज्यों में गरीबी की सीमा से नीचे वाले व्यक्तियों का प्रतिशत 40 से 50 के बीच है। अन्य राज्यों का प्रतिशत इस प्रकार है—आन्ध्रप्रदेश 42.9, असम 40.6, बिहार 49.4, जम्मू व कश्मीर 44.6, मध्य प्रदेश 44.9, मणिपुर 42.7, मैसूर (कर्नाटक) 41.3, राजस्थान 45.6, उत्तर प्रदेश 44.8 और तमिलनाडु 40.4। राजधानी दिल्ली में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम अर्थात् 12.2 प्रतिशत है। गोवा, दमन और दीव का प्रतिशत 14.8 है। प्रति व्यक्ति वार्षिक आय दिल्ली में सर्वाधिक 1,185 रुपये, और गोवा, दमन व दीव में 1,130 प्रतिशत है जबकि सम्पूर्ण देश की औसत प्रति व्यक्ति आय 589 रुपये है। पंजाब व हरियाणा में प्रति व्यक्ति औसत आय क्रमशः 1,002 रुपये और 903 रुपये है जबकि वहाँ गरीबी की सीमा के नीचे अपेक्षाकृत कम लोग अर्थात् 20.8 प्रतिशत हैं।

1. सी एम चन्द्रशेखर (संयुक्त मध्य नगर नियोजक, सेन्ट्रल टाउन एण्ड कस्ट्री प्लानिंग ब्यूरो/इंजिनियर) से वार्ता पर आधारित लेख के अनुसार—प्रस्तुतवर्ती पुष्पेश पत—साप्ताहिक-हिन्दुस्तान, दिनांक 23 नवम्बर, 1973, पृष्ठ 33.

अन्य राज्यों के आंकड़े इस प्रकार हैं—

राज्य	प्रति व्यक्ति वार्षिक आय (रुपये)	गरीबी की सीमा (प्रतिशत में)
गुजरात	746	33.3
हिमाचल प्रदेश	725	34.1
केरल	645	37.9
महाराष्ट्र	739	33.5
त्रिपुरा	680	36.0
पश्चिम बंगाल	705	34.9
अण्डमान व निकोबार द्वीप	800	30.5
दादर व नागर हवेली	792	30.7
चण्डीगढ़	812	29.8
सक्षदीव द्वीप	746	32.9
पाण्डिचेरी	770	31.8

(ड) भारत में गरीबी की 1974-75 में स्थिति

भारत में व्याप्त गरीबी और असमानता के जो विभिन्न अध्ययन ऊपर प्रस्तुत किए गए हैं उनके आंकड़ों में थोड़ा-बहुत अन्तर अवश्य है, लेकिन उनसे इस तथ्य की निर्विवाद रूप से पुष्टि होती है कि देश भयावह गरीबी की स्थिति में है। 1960-61 में देश जिस भयानक गरीबी से ग्रस्त था, लगभग उतनी ही भयावह गरीबी से आज भी है। नियोजन का अधिकांश लाभ सम्पन्न वर्ग को मिला है, विपन्न वर्ग को बहुत कम, और लाभ का यह वितरण कुछ इस रूप में हुआ है कि आर्थिक विपन्नता की साईं पूर्वापेक्षा अधिक चौड़ी हो गई है। केन्द्रीय सरकार के भूतपूर्व योजना-राज्य मन्त्री श्री मोहन धारिया ने 1 अगस्त, 1974 को राज्य-सभा में स्वीकार किया था कि भारतीय जनता का छु भाग (पर्याप्त 67 प्रतिशत भग) गरीबी की सीमा-रेखा से नीचे (Below Poverty line) जीवन व्यतीत कर रहा है—यदि 1960-61 के मूल्यों पर 20 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग को लिया जाए।¹

संयुक्त राष्ट्रसंघ की 3 अगस्त, 1974 की सूचना के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासचिव कुतं वाल्महीम न भारत की गणना विश्व के 28 निर्धनतम देशों में की है। दैनिक हिन्दुस्तान, दिनांक 4 अगस्त, 1974 में यह जानकारी इस प्रकार प्रकाशित हुई थी²—

1. The Economic Times, Friday, August 2, 1974—“Two-thirds of India's population was now living below poverty line, taking the monthly per capita private consumption, of Rs 20 at 1960-61 prices as the standard”.
2. हिन्दुस्तान, 4 अगस्त, 1974, पृष्ठ 4.

"संयुक्तराष्ट्र महासचिव कुर्ते व हद्दहीम ने भारत, पाकिस्तान तथा बंगालदेश को उन 28 देशों की सूची में रखा है जो खाद्य तथा ईंधन की महँगाई से घुरी तरह पीड़ित हैं। डॉ. वाल्डहीम ने बताया कि एक ही आर्थिक घरातल पर स्थित ये देश अधिक सकट के परिणामस्वरूप उत्पन्न कठिनाइयों का मुकाबला कर रहे हैं।

"24 देशों की जिनका प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन 200 डॉलर से नीचे है तथा चार देशों का 200 से 400 डॉलर के बीच है, सूची संयुक्तराष्ट्र के आपात् सहायता कार्यक्रम में दानदानाओं के सूचनार्थ प्रदान की गई। आँकड़े 1971 से हैं। संयुक्तराष्ट्र महासचिव ने बताया कि यद्यपि प्रत्येक देश की वास्तविक स्थिति भिन्न है लेकिन विश्वास किया जाता है कि वे सभी गम्भीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं तथा कुछ मामलों में तो स्थिति इतनी चिन्ताजनक है कि लोगों को अत्यधिक छीना-झपटी तथा भुखमरी का सामना करना पड़ता है। 24 देश जिनका प्रति व्यक्ति वार्षिक राष्ट्रीय उत्पादन 200 डॉलर से कम है उनमें . केम्बून, मध्य अफ्रीका गणतन्त्र, चाँद, इथोपिया, केनिया, लेसोथो, मालागामी गणतन्त्र, माली, मेरिटानिया नाइजर, सिएरा Leone, सोमालिया, सूडान तन्जानिया तथा अपर वोल्टा। एशिया में बंगलादेश, भारत, खमेर गणतन्त्र, लाओस, पाकिस्तान, श्रीलंका, उत्तरी यमन तथा दक्षिणी यमन।

"चार अतिरिक्त देश जिनका प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन 200 से 400 डॉलर तक है, उनमें सेनेगल, एच साल्वा डोर, गुयाना तथा होन्डुरास है।"

गरीबी का मापदण्ड और भारत में गरीबी

गरीबी एक सापेक्षिक चीज है। वस्तुतः गरीबी का मापदण्ड देश और काल के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। "1964 में अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए गए एक सरकारी प्रतिवेदन के अनुसार वहाँ के 20 प्रतिशत लोग गरीबी की स्थिति में जीवन-यापन कर रहे थे। यदि गरीबी जाँचने के उसी पैमाने को यहाँ भी लागू किया जाए तो कतिपय व्यक्तियों के अतिरिक्त देश की सम्पूर्ण जनसंख्या गरीब सिद्ध होगी।" विवरण को अधिक स्पष्ट रूप में लें तो अमेरिका जैसे समृद्ध देश में भी गरीबी विद्यमान है। अमेरिकी शासन ने मुहरत-यह निर्धारित किया है कि यदि किसी परिवार की वार्षिक आय 3,000 डॉलर से कम है तो उसे 'गरीब' परिवार माना जाएगा। अमेरिका 'आर्थिक अवसर' के संघ कार्यालय ने अनुमान लगाया है कि 1967 में अमेरिका में कुल 2 करोड़ 20 लाख व्यक्ति गरीबी की श्रेणी में आते थे। अमेरिका सामाजिक सुरक्षा प्रशासन के अनुसार पाँच व्यक्ति वाले एक गरीब खेतिहर परिवार की न्यूनतम आवश्यक आय 2,750 डॉलर वार्षिक अर्थात् लगभग 21,000 रुपये वार्षिक आँकी गई है। यदि इस आँकड़े को भारत के सम्दर्भ में देखें तो यहाँ के इस आय वाले पाँच सदस्यीय खेतिहर परिवार को देश के सशक्त सम्पन्न परिवारों की श्रेणी में रखा जाएगा अर्थात् अमेरिका में गरीबी

की जो सीमा रेखा है, भारत में वह अमीरी की सीमा रेखा है।¹ अतः स्पष्ट है कि हमें अपने देश की स्थिति के अनुरूप अपने आँकड़े रखने होंगे, भले ही अप्रिय और कटु लगें।

देश में विगत कुछ वर्षों से गरीबी को मापने हेतु उचित आँकड़े खोजने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके आधार पर देश की गरीबी का आँकड़न किया जा सके और उसका समाधान ढूँढा जा सके। योजना आयोग ने 'न्यूनतम मासिक उपभोक्ता-व्यय की आवश्यकताओं' के आधार पर प्रतिमान को स्वीकार किया है, और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण-पत्र में गरीबी की परिभाषा और समस्या निम्न प्रकार से दी गई है²—

उपभोग के निम्नतम स्तर के रूप में गरीबी के स्तर को स्पष्ट करना है। चतुर्थ योजना दस्तावेज में, 1960-61 के मूल्यों के अनुसार 20 रुपये प्रतिमास निजी-उपभोग को वांछित निम्नतर स्तर माना गया था। वर्तमान (अक्टूबर, 1972) के मूल्यों के अनुसार यह राशि लगभग 40 रुपये होगी। अतः गरीबी के उन्मूलन के लिए यह आवश्यक है कि हमारे असरूप देशवासी जो इस समय गरीबी के स्तर से, भी निम्न जीवन-निर्वाह कर रहे हैं उन्हें ऊपर दर्शाए गए निम्नतम निजी-उपभोग का स्तर प्राप्त हो सके। समस्या की प्रचण्डता और प्रभावित लोगों की संख्या प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न-भिन्न है। परन्तु प्रत्येक क्षेत्र में गरीबी प्रमुख समस्या है।

गरीबी और असमानता के मापदण्ड

गरीबी और असमानता एक सापेक्ष भाव है, जिसका ठीक-ठीक पता लगाना कठिन होता है। किन्तु लोगों के जीविकोपार्जन से सम्बन्धित क्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके हम अमीरी और गरीबी के बीच एक सम्भावित सीमा-रेखा खींच सकते हैं। कुल गरीबी सूचक-स्तर निम्नलिखित है³—

(1) आय-व्यय स्तर—गरीबी सूचक पहला स्तर आय व्यय पर आधारित होता है। भारत में सर्वाधिक सम्पन्न वे माने जा सकते हैं, जिनकी वार्षिक-आय 20,000 रु से अधिक है, किन्तु अमेरिका में इस आय से कम वाले गरीब समझे जाते हैं, अर्थात् अमेरिका में जो गरीबी की सीमा रेखा है वह हमारे देश में अमीरों की सीमा-रेखा है। दांडेकर और रथ के अध्ययन के अनुसार 1960-61 में गाँवों में 50 पैसे और शहरों में 85 पैसे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति व्यय था। उस समय ग्रामीण जनसंख्या की 40% और शहरी जनसंख्या की 50% जनसंख्या गरीबी का जीवन बिता रही थी। 1967-68 के सरकारी आँकड़ों के अनुसार 5% व्यक्ति प्रतिदिन 20 पैसे, 5-10 % व्यक्ति प्रतिदिन 27 पैसे और 40-50 % व्यक्ति प्रतिदिन के

1. एस एच पिटवे वही पृष्ठ 19.

2. भारत सरकार योजना आयोग पाँचवी योजना के अति दृष्टिकोण 1974-79 पृष्ठ 1.

3. जी आर वर्मा ना लेख—'समाजवादी समाज की स्थापना के लिए गरीबी हटाना आवश्यक'—योजना, 22 मार्च, 1973 पृष्ठ 21-22

51 पैसे व्यय करने है। यदि प्रति व्यक्ति 20 रुपये मासिक खर्च मानें तो 60% ग्रामीण और 40% शहरी जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे आएगी।

(2) उपभोग और पोष्टिकता का स्तर एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए सामान्यतः 2,250 कैलोरी खुराक प्रतिदिन आवश्यक मानी गई है, किन्तु रिजर्व बैंक के एक अध्ययन, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 1100 और 1500 कैलोरी खुराक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यक मानी गई है, के अनुसार 1960-61 में गाँवों में 52 जनसंख्या इससे कम भोजन पाती थी। सरकारी आँकड़ों के अनुसार वर्तमान में 70% ग्रामीण जनसंख्या खुराक के सम्बन्ध में गरीबी में पल रही है तथा शहरी जनसंख्या का 50 से 60% भाग भोजन और पोषण की कमी में पलता है।

(3) भूमि-जोत-स्तर—देश की जनसंख्या का 80 प्रतिशत या 44 करोड़ व्यक्ति गाँवों में बसते हैं, जिनमें से 70 प्रतिशत कृषि पर निर्भर हैं। इनमें 5 एकड़ से कम जोत वाले 5 करोड़ 31 लाख या 74 प्रतिशत हैं। 2.5 करोड़ एकड़ से कम जोत वाले 4 करोड़ 15 लाख या 58 प्रतिशत हैं और 1 करोड़ 58 लाख या 22 प्रतिशत बिल्कुल भूमिहीन हैं। इस प्रकार भूमिहीनो से लेकर 5 एकड़ से कम जोत वाले 11 करोड़ से भी अधिक लोग हैं, जो प्रत्यन्त गरीबी की हालत में जीवन बिता रहे हैं।

(4) रोजगार-स्तर—सम्पन्न या विकसित देश वे हैं, जहाँ रोजगार-स्तर ऊँचा होता है अथवा उत्पादन के सभी माधनों को उनकी योग्यतानुसार रोजगार प्राप्त होता है, किन्तु भारत में पिछले 25 वर्षों में बेरोजगारी 10 लाख से बढ़कर 45 करोड़ तक पहुँच गई है। इनमें लगभग 23 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं। बेरोजगारी और अर्द्ध-बेरोजगार के कारण देश की लगभग 22 करोड़ जनता की आमदनी एक रुपया रोज से भी कम है। विनियोग और रोजगार के अभाव में 70 प्रतिशत औद्योगिक क्षमता बेकार पड़ी है। विनियोग, आय और रोजगार की यदि यही स्थिति रही तो 'गरीबी हटाओ' का स्वप्न 20वीं शताब्दी तक भी साकार नहीं हो सकेगा।

भारत में गरीबी और असमानता के कारण

योजना आयोग ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण 1974-79 में गरीबी के दो मुख्य कारण बताते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की है—

"गरीबी के दो मुख्य कारण हैं—(1) अपूर्ण विकास तथा (2) असमानता। इन दोनों पक्षों में से किसी एक को कम मानना या उपेक्षा करना उचित नहीं है। अधिकांश जन-समुदाय दैनिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाता। क्योंकि प्रथम बहुत बड़ी जनसंख्या को देखते हुए कुल राष्ट्रीय आय और इस प्रकार कुल उपभोग बहुत ही कम है। द्वितीय इस आय और उपभोग का वितरण एक समान नहीं है। केवल एक ही दिशा में प्रयत्न करने से इस समस्या पर काबू नहीं पाया जा सकता। यदि असमानता उतनी ही विकट रही, जितनी कि इस

समय है, तो वास्तविक रूप से परिकल्पित विकास दर से इस समस्या का समाधान सम्भव नहीं। इसी प्रकार, विकास दर में तीव्र वृद्धि किए बिना सम्भावित समतामय नीतियाँ स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं ला सकती। अतः व्यापक गरीबी को दूर करने के लिए विकास करना तथा असमानताएँ घटाना आवश्यक है।”

गरीबी और असमानता के उपरोक्त प्रमुख कारणों से सम्बद्ध अन्य सहायक कारण भी हैं। संक्षेप में अन्य कारण निम्नलिखित हैं—

(1) यद्यपि पिछले दशक में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन दुगुने से भी अधिक हो गया किन्तु इसी अवधि में वस्तुओं के मूल्यों में भी दुगुनी वृद्धि हो गई तथा मूल्यों में वृद्धि की गति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से बहुत अधिक है। जनसंख्या में 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होना, जबकि प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में अनुकूल रूप में विशेष वृद्धि न हो पाना देश की आर्थिक अवनति और गरीबी के प्रसार का परिचायक है।

(2) नियोजन के फलस्वरूप जो भी आर्थिक विकास हुआ है, उस अल्प-वृद्धि का लाभ सम्पन्न वर्ग को अधिक हुआ है अर्थात् सम्पन्नता में वृद्धि हुई है और विपन्नता पूर्वपिक्षा अधिक बढ़ी है।

(3) जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए कुल राष्ट्रीय आय और इस प्रकार कुल उपभोग बहुत ही कम है। इसके अतिरिक्त आय और उपभोक्ता वितरण एक समान नहीं है। व्यावहारिक रूप में आन्तरिक उत्पादन-दर में वृद्धि के साथ-साथ जनसंख्या की वृद्धि दर को घटाने के प्रयत्न अधिकांशतः असफल ही रहे हैं। चतुर्थ योजनावधि में भी अर्थव्यवस्था का वास्तविक संचालन इसी प्रकार हुआ जिससे आन्तरिक उत्पादन दर काफी घट गई।

(4) पिछले पृष्ठों में दिए गए आंकड़े सिद्ध करते हैं कि देश में ग्रामीण और शहरी दोनों ही जनसंख्या के सभी वर्गों में उपभोक्ता व्यय में गिरावट हुई है। वास्तव में प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय ही व्यक्तियों का जीवन स्तर प्रदर्शित करता है। गाँवों और शहरों दोनों में ही गरीब वर्ग बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार आय की असमानता में कमी होने की अपेक्षा वृद्धि ही हुई है। द ठिकर एच रय के अनुसार अधिक विकास का अधिकतम लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में उच्च मध्यम श्रेणी तथा अमीर वर्ग को ही हुआ है और निर्धन वर्ग को इससे कुछ भी लाभ नहीं हुआ है, बल्कि उनके उपभोग में गिरावट ही हुई है।

(5) प्रति व्यक्ति अन्न उपभोग को जीवन निर्वाह का मापदण्ड लिया जाय और पौष्टिक स्थिति देखी जाय तो भी 1960-61 की अपेक्षाकृत स्थिति बदतर हुई है। 1960-61 में ग्रामीण क्षेत्र में पौष्टिक न्यूनता ग्रामीण जनसंख्या का 52 प्रतिशत थी जो बढ़कर 1967-68 में 70 प्रतिशत तक पहुँच गई। इसके पश्चात् भी स्थिति उत्तरोत्तर गिरी ही है। अतः स्पष्ट है कि देश की गरीब ग्रामीण जनसंख्या और अपोषण की स्थिति में जीवन निर्वाह बर रही है।

(6) राष्ट्रीय आय में वृद्धि को बड़ी हुई जनसंख्या वृद्धि खा गई है या वह देश के बड़े-बड़े पूँजीपतियों, व्यापारियों और एकाधिकारियों की जेबों में चली गई है। इसके अतिरिक्त, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, महंगाई और निश्चिन्ता ने जनता की कमर तोड़ डाली है। उत्पादन को तहखानों में छिपाकर काला-बाजारी करने, मूल्य वृद्धि करने और मुनाफा कमान की प्रवृत्ति ने विषमता को बढ़ाया है। इसलिए सहकारियाँ, मुरार बाजार और सस्ते मूल्य की दूकानें असफल रही हैं। सम्पत्ति की असमानता और गरीबी को बढ़ाने में हड़तालें, तालाबन्दी, धेराव आदि की घटनाएँ भी सहायक रही हैं।

(7) साधनों का अभाव भी गरीबी और असमानता को बढ़ाने में सहायक रहा है। योजना बनाते समय साधन एकत्र करने के सम्बन्ध में बढ़ा-चढ़ा कर अनुमान लगाए जाते हैं और अनेक प्रशासकीय तथा राजनीतिक बाधाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। परिणामस्वरूप प्रस्तावित कार्यक्रमों का एक भाग कार्यान्वित नहीं हो पाता और जो कार्यक्रम लागू होते भी हैं, उनका वह प्रभाव और परिणाम नहीं हो पाता जो अधिक नियंत्रित और सतर्क दृष्टिकोण अपनाने से होता।

(8) पूँजी और भूस्वामित्व में अन्तर आर्थिक विषमता का एक प्रमुख कारण है। अधिक भूमि और पूँजी वाले को बिना विशेष परिश्रम किए ही लगान, ब्याज, लाभ आदि के रूप में आय प्राप्त होती है और उनकी आय भी काफी अच्छी होती है। भारत में जमींदारी-प्रथा के उन्मूलन से पूर्व कृषक-क्षेत्र में घोर विषम वितरण था। जमींदारी-प्रथा के उन्मूलन के पश्चात् नतीजा और पूँजीपति नए जमींदार और भूपति बन गए हैं, जिनमें से अधिकांश का कार्य है रुपया उधार देना, डटकर ब्याज लेना और निर्धनों का शोषण करना। औद्योगिक क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि देश के प्रमुख उद्योगों पर कतिपय लोगों का ही एकाधिकार है, जो प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों का लाभ अर्जित करते हैं।

(9) आर्थिक विषमता का द्वितीय प्रमुख कारण उत्तराधिकार है। प्रायः धनिक पुत्र, उसकी सम्पत्ति बिना किसी परिश्रम के उत्तराधिकार में प्राप्त कर लेते हैं और धनी बन जाते हैं। इस प्रकार, उत्तराधिकार के माध्यम से, आय की विषमता फलती-फूलती आती है। दूसरी ओर निर्धन बच्चों को न तो समुचित शिक्षा ही मिल पाती है और न ही उनके लिए कमाई के लाभकारी उत्पादन-क्षेत्र ही सुलभ होते हैं।

(10) आर्थिक विषमता का एक बड़ा कारण धनी व्यक्तियों की बचत-क्षमता का अधिक होना है। उनकी आय प्रायः इतनी अधिक होती है कि आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् भी उनके पास पर्याप्त धन बचा रहता है। धनिकों की यह बचत आर्थिक विषमता को बढ़ाती है। यह बचत विभिन्न उत्पाद-क्षेत्रों में पूँजी का रूप धारण करती है तथा किराए, ब्याज या लाभ के रूप में आय को और अधिक बढ़ाती है। दूसरी ओर निर्धन शोषण की चक्की में पिसते रहते हैं, अतः उनकी बचत-क्षमता नगण्य होती है।

(11) आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति आर्थिक विषमता का प्रबल कारण है। श्रमिकों की सौदा करने की शक्ति कम होने के कारण आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ और पूँजीपति इसी कारण उनकी उनकी सीमन्त उत्पादकता से कम मजदूरी देकर उनका आर्थिक शोषण करते हैं। फलस्वरूप पूँजीपतियों का लाभ दिन प्रतिदिन बढ़ता है जबकि श्रमिकों की स्थिति प्रायः दोन हीन (विशेषकर अर्द्ध विकसित समाजों में) बनी रहती है। इस प्रकार आर्थिक असमानता निरन्तर बढ़ती जाती है।

गरीबी एवं असमानता को दूर प्रथमा कम करने के उपाय

भारत सरकार देश की गरीबी और आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए कृण मकल्य है। श्रीमती गांधी ने भारतीय गरीबी की तस्वीर को पहचाना है और 'गरीबी हटाओ' का सक्ल्य लिया है। भारतीय इतिहास में अपने ढंग का यह पहला और महत्त्वपूर्ण सक्ल्य है और इसी नारे को साकार बनाने के लिए सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है तथा पाँचवी पंचवर्षीय योजना को इसी रूप में ढालने की प्रयत्न किया गया है कि वह गरीबी और असमानता को दूर करने वाली तथा देश को आत्म निर्भरता की सीढ़ियों पर चढ़ाने वाली सिद्ध हो। गरीबी और असमानता को मिटाने अथवा यथासाध्य कार्य करने के स्वप्न को साकार बनाने हेतु श्री भारत सरकार ने 14 बड़े बँकों का राष्ट्रीयकरण किया। राजा महाराजाओं को दिया जाने वाला मुद्राबन्ध प्रीवीयस बन्द किया है। भूमि की अधिकतम जोन सीमा तथा शहरी सम्पत्ति-निर्धारण के क्रान्तिकारी कदमों पर सक्रिय विचार हो रहा है और कुछ दिशाओं में आवश्यक कदम भी उठाए गए हैं। पाँचवी योजना 'गरीबी हटाओ' के उद्देश्य को लेकर चली है। आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण को रोकने हेतु सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं—जैसे औद्योगिक लाइसेंस नीति में समुचित सशोधन करना जमाखोरी और कालेबाजारी के विषुद्ध कठोर वैधानिक कदम उठाना रिजर्व बैंक द्वारा देश के बैंकों को '50 बड़े खातों' पर सनकं दृष्टि रखने के आदेश देना आदि।

गरीबी और असमानता को कम करने की दिशा में निम्नलिखित प्रपेक्षित कदमों को उठाना आवश्यक है—

1 निजी-सम्पत्ति की सीमा कठोरतापूर्वक निर्धारित कर दी जाए। ऐसे कानून बना दिए जाएँ ताकि भूमि, नकद पूँजी मकान आदि के रूप में एक सीमा से अधिक सम्पत्ति कोई नहीं रख सके। विषमता का मूल आधार ही निजी सम्पत्ति का स्वामित्व है अतः इसकी सीमा रेखा निर्धारित करना अनिवार्य है।

2 इस प्रकार के वैधानिक उपाय किए जिनसे निजी सम्पत्ति के उत्तराधिकार और सम्पत्ति प्रन्तरण की प्रथा समाप्त हो जाए अथवा वांछित रूप से सीमित हो जाए। यह उपयुक्त है कि उत्तराधिकार में सम्पत्ति प्राप्त करने वालों पर भारी उत्तराधिकार कर लगा दिया जाए। धनिकों पर ऊँची दर से मृशु कर लगाया जाए। सम्पत्ति प्रन्तरण पर भेंट कर लगा दिया जाए ताकि किसी भी धनिक द्वारा अपनी सम्पत्ति अन्य के नाम अन्तरित करते समय उसे कुछ अंश सरकार को देना पड़े।

3. यद्यपि वर्तमान कर-नीति समाजवादी समाज की स्थापना की दिशा में सहयोगी है, तथापि यह अपेक्षित है कि धनिकों पर अधिकाधिक कठोरतापूर्वक आरोही कर लगाए जाएँ। दूसरी ओर निर्धनों को करों में अधिकाधिक छूट दी जाए, लेकिन उद्देश्य तब निष्फल हो जाएगा यदि बसूली ठीक ढंग से न की गई।

4. यद्यपि सरकार एकाधिकारी प्रवृत्ति पर निषेध के लिए प्रयत्नशील है, तथापि अपेक्षित है कि बिना किसी हिचक के कठोर एकाधिकार विरोधी कानून लागू किया जाए और मूल्य-सन्धियों को रोका जाए। जो कदम उठाए जा चुके हैं उन्हें इस दृष्टि से अधिकाधिक प्रभावी बनाया जाए जिससे धनी व्यक्ति एकाधिकार-गुट का निर्माण न कर सकें। यह उपाय भी विचारणीय है कि सरकार एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु का अधिकतम मूल्य निर्धारित करे।

5. विभिन्न साधनों के अधिकतम और न्यूनतम मूल्य निर्धारण की नीति द्वारा आय की असमानताएँ कम की जा सकती हैं। इस नीति का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से होना पर आय की असमानताओं का कम होना निश्चित है। लेकिन साथ ही, इस नीति से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के प्रति सजग रहना भी आवश्यक है।

6. आय और सम्पत्ति की विषमता को कम करने हेतु अनाजित आयों पर अत्यधिक उच्च दर से प्रगतिशील करारोपण आवश्यक है। भूमि के मूल्यों में वृद्धि अथवा लगान से प्राप्त आय, आकस्मिक व्यावसायिक लाभ, काला बाजारी से प्राप्त आय, एकाधिकारी लाभ, आदि पर अत्यधिक ऊँची दर से कर लगाया जाना चाहिए।

7. सरकार को निजी-सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण करके आय विषमता का निराकरण करना चाहिए। लेकिन यह उपाय एक बड़ा उग्र-प्रश्न है, जिसे भारत जैसे अर्द्ध-विकसित और रूढ़िवादी समाज के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस बात का भय है कि इस उग्र उपाय से देश में व्यावसायिक उद्यम को भारी आघात पहुँचे। भारत की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ निजी सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण के प्रतिकूल हैं।

8. सामाजिक सुरक्षा-सेवाओं का विस्तार किया जाए। यद्यपि सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है, तथापि कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी रूप में लागू करना अपेक्षित है। बेरोजगारी, बीमारी वृद्धावस्था, दुर्घटना और मृत्यु—इन सड़कों का सर्वाधिक दुष्प्रभाव निर्धन वर्ग पर ही पड़ता है, अतः इनसे सुरक्षा हेतु सरकार को विस्तृत सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वित करनी चाहिए ताकि निर्धनों की आय में वृद्धि हो सके।

9. यह भी कहा जाता है कि सरकार को निर्धन-वर्ग को कार्य की गारण्टी देनी चाहिए। सरकार को रोजगार-वृद्धि की प्रभावशाली योजना अपनाकर यह निश्चित करना चाहिए कि बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो और यदि वह सम्भव न हो तो न्यूनतम जीवन स्तर निर्वाह करने हेतु उन्हें अनिवार्य आर्थिक-सहायता सुलभ हो सके।

10 सरकार कानूनी रूप से अधिक सन्तानोत्पत्ति पर नियन्त्रण लगाए। यह निश्चिन कर देना उम्मुक्त होगा कि तीन बच्चों से अधिक सन्तान उत्पन्न करना कानूनी अपराध माना जाएगा। परिवार नियोजन के कार्यक्रम में शिक्षिता-विन्दुओं को दूर करने की प्रभावी चेष्टा की जाए।

11. उत्पादन-वृद्धि दर और सार्वजनिक निजी क्षेत्रों की बचत-दर अन्वोपजनक है, अतः उसमें वृद्धि करने के लिए सम्भव उपाय किए जाएँ और यदि इस दृष्टि से कटु और अप्रिय साधनों का प्रयोग करना पड़े, तो उसमें भी हिचकन की जाए।

12 ठोस कार्यक्रमों को लागू किया जाए। विकास की रोजगार बहुल मर्दों जैसे छोटी सिंचाई योजनाएँ भू संरक्षण, कृषि विकास, दुग्ध-उद्योग और पशुपालन, वन-उद्योग, मत्स्य-उद्योग गोदाम व्यवस्था पणन कृषि आधारित उद्योगों समेत लघु-उद्योग, सड़कें, तथा अन्य विशेष-कार्यक्रमों पर अधिकाधिक बल दिया जाए। दंडिकर एव रथ के अनुसार "उन समस्त व्यक्तियों को जो कार्य करने को तैयार हैं, तत्काल शुरू हो सकने वाले कामों में न्यूनतम मजदूरी देकर लगा दिया जाए जैसे भूमि-विकास, कृषि, वन-वृद्धि, सड़क-निर्माण आदि।

13 नैतिकता और न्याय की माँग करते हुए दंडिकर एव रथ ने गरीबी हटाने की दिशा में समाज के समृद्ध वर्गों से त्याग की माँग की है। उनके अनुसार समाज के समृद्ध वर्गों को जो आज उस न्यूनतम स्तर से वहीं अधिक ऊँचे स्तर पर जीवनयापन कर रहे हैं, जिसका हम आज गरीबों को आश्वासन देना चाहते हैं, इस कार्यक्रम का बोझ उठाना ही पड़ेगा। गाँव और शहर की जनसंख्या के समृद्ध वर्ग में से पहले 5% लोगों के प्रतिदिन के व्यय में 15 / की कटौती तथा उससे बाद के (कम समृद्ध) 5 / लोगों के प्रतिदिन के व्यय में 7½ / कटौती कर देने से ही काम चल जाएगा। यह बोझ बड़ा नहीं है, बसतें कि अमीर लोग इन्फ्राफ और बुद्धि से काम लें। साथ ही आवश्यक विनीय-उपाय भी करने होंगे ताकि उन अमीरों से आवश्यक अधिक साधन प्राप्त किए जा सकें।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण में गरीबी और असमानता को दूर या कम करने सम्बन्धी नीति

देश की पाँचवी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों में गरीबी उन्मूलन और असमानताओं में कमी के सन्दर्भ में कुछ नीति सम्बन्धी पहलुओं का उल्लेख 'पाँचवी योजना के प्रति दृष्टिकोण 1974-79' में निम्नलिखित दिए गए हैं—

1. असमानताओं में कमी—व्यापक गरीबी उन्मूलन हेतु आवश्यक है कि विकास उससे अधिक दर पर किया जाए जिस पर उस वर्ष के दौरान रुपा है। यह भी पर्याप्त नहीं है। चतुर्थ योजना के दम्नावेज में यह स्वरूप कर दिया गया था कि यदि उपभोग स्तर में उसी प्रकार असमानता बनी रही, जो कि 1967-68 में थी, तो 1969-70 से 1980-81 की अवधि के लिए विकास के उच्चतर की ओर कल्पना की गई है, उसके बावजूद 1968-69 के मूल्यों के अनुसार जनसंख्या के दूसरे गरीब

दर्शाश का प्रति व्यक्ति उपभोग 27 रुपये प्रतिमास होगा। यदि 1960-61 के मूल्यों के अनुसार, उपभाग-स्तर 15 रुपये प्रति मास होगा। इस प्रकार, एक दशक तक तीव्र विकास करने पर भी दूसरे दर्शाश को 1960-61 के मूल्यों के अनुसार 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति मास उपभोग का स्तर प्राप्त करना सम्भव न होगा, जो निम्नतम वांछित उपभोग का स्तर माना गया था। अतः स्पष्ट है कि विकासोन्मुख नीति में पुनर्वितरण के उपाय भी दिए गए हों। इसके लिए न केवल उच्च-दर से आयोजन की आवश्यकता है, बल्कि उस विशेष वस्तु, जिस समाज के निम्न वर्ग चाहते हैं, की उत्पादन वृद्धि भी आवश्यक है। इस प्रकार वांछित विकास बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने की नीति का अनुसरण कर किया जा सकता है। इससे जन-उपभोग के समान और सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी। सामाजिक उपभोग और विनियोजन में वृद्धि भी आवश्यक है। जिससे वृहद जन-समुदाय की कुशलता और उत्पादकता का स्तर बना रहे तथा उनके जीवन-स्तर में भी सुधार हो। सामाजिक उपभोग रोजगार उत्पन्न करने वाले इन कार्यक्रमों को तैयार करते समय यह जरूरी है कि पिछड़े क्षेत्रों और जातियों को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाए। वास्तव में, जो असमानता कम करने के लिए बनाए जाने वाले किसी भी कार्यक्रम की नीति का आवश्यक पहलू यह होना चाहिए कि वे पिछड़े क्षेत्रों और जातियों पर विशेष रूप से कार्यान्वित हों। अतः विकास के उचित स्वरूप की परिभाषा में केवल वस्तुओं और सेवाओं ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि विकास की परिभाषा में यह भी निश्चित किया जाना चाहिए कि तुलनात्मक रूप से पिछड़े क्षेत्रों और जातियों को वृद्धिशील उत्पादन और बढ़ती आय में उचित भाग प्राप्त होगा।

2 जनसंख्या वृद्धि को रोकना—निरन्तर जनसंख्या वृद्धि हो रही है। जनसंख्या का इस प्रकार बढ़ना गरीबी उन्मूलन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इसका आंतरिक बचत पर कुप्रभाव पड़ता है और विकास हेतु घातक है। इसके अतिरिक्त, विकास प्रक्रिया पर कुप्रभाव पड़े बिना नहीं रहता, क्योंकि जीवन-निर्वाह के लिए वांछित आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक ध्यान देना पड़ता है। राष्ट्रीय आय वृद्धि की किसी विशेष दर के अनुसार जितनी अधिक जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ही प्रति व्यक्ति आय घटती जाएगी। इन सभी कारणों से, गरीबी-उन्मूलन के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या की वृद्धि को ठीक ढंग से रोका जाए। अतः, परिवार-नियोजन कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं की सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है ताकि इस प्रकार की व्यवस्था की जा सके जो सुखद भविष्य का सकेत देता है। पाँचवी पंचवर्षीय योजना में परिवार-नियोजन कार्यक्रम के लिए विनाश राशि अर्थात् 500 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इससे प्रभावी कार्यक्रम आसानी से चलाया जा सकता है।

3 गरीबी उन्मूलन—भारत में गरीबी की समस्या बहुत व्यापक तथा जटिल है। अतः इसका किसी एक योजनावधि में समाधान करना सम्भव नहीं परन्तु वर्तमान परिस्थिति हमें इस बात के लिए मजबूर करती है कि पाँचवी योजना को

इस प्रकार का मोड़ दिया जाए ताकि गरीबी-उन्मूलन की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके और जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। ऐसी परिस्थितियों में जबकि मानवीय संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है, यदि आयोजना और कार्यान्वयन ठीक आधार पर चलाना है तो विकास दर और उद्योग के अनुसार अधिक समानता प्राप्त करना दोनों अन्वोन्याश्रित हैं। दृष्टिकोण, दस्तावेज में दी गई प्रस्तावित विकास दर व प्रणाली विकास प्रक्रिया को विदेशी सहायता की निर्भरता से मुक्ति, अधिक कारगर और समेकित जनसंख्या पर धन, रोजगार के अवसरों पर धन, निम्नतम आवश्यकताओं के राष्ट्रीय कार्यक्रम की व्यवस्था, पिछड़े वर्गों की उन्नति और पिछड़े क्षेत्रों का विकास और सार्वजनिक धमूली तथा बँटवारे की पद्धति की इस प्रकार व्यवस्था की गई जिसमें गरीब जनता को अन्वोन्याश्रित नीति-तत्त्वों के रूप में आवश्यक सामग्री उचित एवं स्थिर मूल्यों पर प्राप्त हो सके। निश्चित अवधि में गरीबी उन्मूलन करना पाँचवी योजना की मुख्य कार्य नीति है।

4 गरीबी-उन्मूलन की दिशालता को ध्यान में रखना आवश्यक है। जब तक कठिण शर्तों की पूर्ति नहीं की जाती तब तक योजना चाहे कितनी भी अच्छी हो देश अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकता। सबसे बड़ी आवश्यकता दृढ़ स्वावलम्बन की भावना से कृषि, फँकटरी और कार्यालय में कार्य करने की है। जीवन और कार्यकलाप के सभी क्षेत्रों में सामाजिक अनुशासन बनाए रखना भी आवश्यक है। इसके लिए बलिदान करना पड़ेगा। विशेषकर उन व्यक्तियों को जो अच्छी स्थिति में हैं। इन मामलों पर काफी अनजानता पैदा हो चुकी है और गरीबों की चुनौती का सामना करने के लिए प्रत्येक नागरिक को अपना योगदान करना पड़ेगा। सम्बन्धित बाधाओं को देखते हुए काफी चैर से कार्य करना होगा। शताब्दियों पुरानी गरीबी को दूर करना कोई आसान काम नहीं है। अतः राष्ट्र को सुनिश्चित कार्यवाही द्वारा, अपने स्वल्प की पूर्ति हेतु तत्पर हो जाना चाहिए।

बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम और गरीबी पर प्रहार

26 जून, 1975 को राष्ट्रीय आपात् की उद्घोषणा के तुरन्त बाद 1 जुलाई, 1975 को प्रधान मंत्री श्रीमती गाँधी द्वारा बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम घोषित किए जाने से पूर्व तक भारत की गरीब जनता निराशा में डूबी रही और गरीबी का कुचक्र अपने पाँव पसारता रहा। लेकिन नवीन आर्थिक कार्यक्रम लागू किए जाने के पश्चात् एक समतापूर्ण नवीन समाज की रचना और गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक के बाद एक कठोर, किन्तु रचनात्मक, कदम उठाए गए और कुछ ही महीनों में भारत के पिछड़े और गरीब वर्ग में यह आशा बस गई कि सम्भवतः उनके बुरे दिन निकट भविष्य में समाप्त हो जाएँगे, वे निधनता का कुचक्र तोड़ने में सफल हो सकेंगे। देश में व्याप्त गरीबी को समाप्त कर देना कोई एक दिन का अथवा कुछ महीनों की बात नहीं है, इसके लिए धैर्यपूर्वक वर्षों तक निरन्तर प्रयास करने होंगे। प्रयास पहले भी किए गए थे लेकिन उनमें दम नहीं था, प्रशासनिक शिथिलता और समाज के धनिक वर्ग के शोषण का बोलबाला था। लेकिन 1975

के उत्तरार्द्ध से अनुशासन और जागृति का नया वातावरण बनाने और फलस्वरूप सरकार के कानूनों को ठोस रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत की वर्तमान स्थिति में गरीबी हटाने का प्रमुख रूप से यह अर्थ है कि गाँवों के गरीब लोगों, विशेषकर भूमिहीन मजदूरों, छोटे और सीमान्त-किसानों तथा गाँवों के कारीगरों की स्थिति सुधारी जाए। इसीलिए प्रधान मंत्री ने नए आर्थिक कार्यक्रम में और अपने विभिन्न भाषणों में इन बातों पर जोर दिया है—भूमि के कागजात स्थानीय लोगों के सहयोग से तैयार किए जाए, जोत की अधिकतम सीमा कानून का परिपालन किया जाए, भूमिहीनों को आवास हेतु स्थान दिए जाए, कृषि के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतनों पर पुनः विचार किया जाए, जागीरदारी प्रथा के अन्तर्गत बन्धक मजदूरों की प्रथा समाप्त की जाए, गाँवों में महाजनों के लिए ऋण की अदायगी में छूट दी जाए, आदि। इन सभी बातों पर जोर देना का अर्थ यही है कि गाँवों में सामाजिक और आर्थिक शक्तियाँ सुविधाहीन वर्गों के हित में अधिकाधिक कार्य करने लगे।

श्रीमती गांधी के कार्यक्रम को साकार रूप देने हेतु न केवल सरकारी मशीनरी, बल्कि समाज की रचनात्मक शक्तियाँ पूर्णरूप में सक्रिय हो उठी हैं। निजी-क्षेत्र को जमाखोरी, कालाबाजारी और सरचना आदि समाज विरोधी प्रवृत्तियों से मुक्त करने हेतु कठोर कानून बनाए गए हैं। आर्थिक अपराधों के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था भी की गई है। तस्करी की कमर तोड़ दी गई है। बेकार भूमि के स्वामित्व को और कब्जे की सीमा को निश्चित कर देने के लिए तथा ग्रामीण और शहरीकरण के योग्य भूमि को सार्वजनिक सम्पत्ति बनाने के हेतु कानूनी व्यवस्था की जा रही है। औद्योगिक गति की स्थापना कर प्रत्येक दिशा में औद्योगिक उत्पादन तीव्रता से बढ़ाया जा रहा है ताकि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ-साथ प्रति व्यक्ति आय भी तेजी से बढ़े और व्यक्ति गरीबी के न्यूनतम स्तर से ऊंचा उठे। राज्यों में भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमों पर तेजी से अग्रसर किया जा रहा है प्रतिरिक्त भूमि को भूमिहीन लोगों को देने के लिए सक्रिय रूप में कार्यवाही की जा रही है। अदिम जाति के लोगों को अपने घरेलू जमीनों के स्वामित्व के अधिकार दिए जा रहे हैं। भूमिहीन और कमजोर वर्गों को भवन निर्माण हेतु भूमि दी जा रही है। ग्रामीण मजदूरों का शोषण रोकने के लिए सभी प्रकार की बन्धुग्रा मजदूरी कानूनन समाप्त कर दी गई है। न्यूनतम मजदूरियों में संशोधन किया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी, किसान, शिक्षक, कठोर कानूनी कदम उठाए गए हैं। सहकारियों के शोषणकारी ऋणों पर पाबन्दी लगा दी गई है तथा सहकारी ऋण सत्याघों को मजबूत किया जा रहा है। ग्रामीण कारीगरों और सीमान्त कुपकों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण बैंकों का जाल बिछाया जा रहा है। ये सब कार्यवाहियाँ बोरी कामजी नहीं हैं, व्यवहार में कठोरतापूर्वक इन बदलों को अमल में लाया जा रहा है फलस्वरूप, सुपरिणाम भी सामने आने लगे हैं। यही कारण है कि देश में उदासीनता और बेवसी का वातावरण अब विश्वास और पक्के इरादे की लहर में बदल रहा है।

प्रधान मंत्री का आर्थिक कार्यक्रम हमारे चिर-अभिलाषित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रयत्न है। यदि इसे सही ढंग से कार्यान्वित किया गया तो उससे भारत को विशाल जन और भौतिक साधनों का उपयोग राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में हो सकेगा। प्रधान मंत्री का कहना है कि समृद्धि पाने का कोई छोटा रास्ता नहीं है। उन्होंने बताया है कि केवल एक ही जादू है जो गरीबी दूर कर सकता है, वह है, कड़ी मेहनत जिसके साथ जरूरी है—दूर-दृष्टि, पक्का-इरादा और कड़ा अनुशासन। प्रधान मंत्री ने एक कार्यक्रम तैयार किया है जिससे समग्र राष्ट्र एक-सूत्र में आवद्ध हो सकता है भले ही राजनीतिक विचारधारा भिन्न क्यों न हो। यह संदेश बड़ा स्पष्ट और बलगाली है। उनका आह्वान है कि सभी देशभक्त भारतीय देश को शोषण और अभाव से मुक्त करने हेतु मिलजुल कर कार्य करें।

भारत में बेरोजगारी-समस्या का स्वरूप तथा वैकल्पिक रोजगार नीतियाँ

(The Nature of Unemployment Problem and
Alternative Employment-Policies in India)

भारत एक विकासमान किन्तु अर्द्ध-विकसित देश है जहाँ बेरोजगारी का स्वरूप औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों की अपेक्षा भिन्न है। देश में काफी बड़ी समस्या में श्रमिक और शिक्षित बेरोजगार हैं अथवा अल्प-रोजगार की स्थिति में हैं। ऐसे श्रमिकों की समस्या में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है, जो वर्ष के कुछ महीनों में तो कार्यरत होते हैं और शेष महीनों में बेकार रहने हैं। भारत में बेरोजगारी की समस्या इतनी विकराल बन चुकी है कि उससे हमारा सम्पूर्ण अर्थ तन्त्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। समाजवादी समाज की स्थापना के लिए, लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए, देश की बहुमुखी प्रगति और समृद्धि के लिए बेरोजगारी की समस्या के प्रभावी हल ढूँढना भारत के लिए निस्संदेह एक आवश्यक शर्त और गम्भीर चुनौती है। इस ओर पूरा-पूरा ध्यान दिया जाना परमावश्यक है, तथा समस्या का विन्ताजनक पहलू यह है कि अब तक किए गए प्रयत्न बेरोजगारी की बढ़ती पंज पर अनुश्रु नहीं लगा सके हैं। कुछ दृष्टियों से सफलता मिली है, पर कुल मिलाकर वह लगभग निष्प्रभावी ही मानी जानी चाहिए क्योंकि प्रत्येक योजना के अन्त में बेरोजगारी की कुल समस्या पूर्वापेक्षा अधिक ही मिलती है।

भारत में बेरोजगारी का स्वरूप और किस्में (Nature and Types of Unemployment in India)

भारत में बेरोजगारी के कई रूप हैं। इनमें खुली बेरोजगारी, आंशिक बेरोजगारी, ग्रामीण अल्प-रोजगारी, शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी, औद्योगिक-क्षेत्र में बेरोजगारी आदि प्रमुख हैं। इन्हें दो मोटे वर्गों में रखा जा सकता है—ग्रामीण बेरोजगारी एवं शहरी बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी के जो विभिन्न रूप उपलब्ध हैं, वे कृषि प्रधान अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्थाओं में प्रायः देखने को मिलते हैं।

संरचनात्मक बेरोजगारी (Structural Unemployment)—भारत में बेरोजगारी का विशेष पहलू यह है, कि यह बेरोजगारी 'संरचनात्मक' (Structural)

किम्मा की है अर्थात् इसका सम्बन्ध देश के पिछड़े आर्थिक ढाँचे के साथ है। इसीलिए यह बेरोजगारी दीर्घकालिक प्रकृति (Chronic Nature) की है। अर्थात् भारत में श्रमिकों की सहाय की अनेक रोजगार के अवसर अथवा रोजगार-मात्रा न केवल बहुत कम है वरन् यह कमी देश की पिछड़ी अर्थव्यवस्था से सम्बन्ध भी है। पूँजी निर्माण दर बहुत नीची होने से रोजगार-मात्रा का कम पाया जाता स्वाभाविक है। इस दीर्घकालिक प्रकृति की बेरोजगारी का हल यही है कि देश का तेजी से आर्थिक विकास किया जाए।

द्वितीय या प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment)—भारत में बेरोजगारी के इस रूप से श्रमिकों का बड़ा भाग प्रभावित है। यह बेरोजगारी मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। ऊपर से तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति कामरत है किन्तु वास्तव में वह बेरोजगार होता है अर्थात् कार्यरत रहने के बावजूद उनसे उत्पादन में कोई वास्तविक योगदान नहीं मिलता। प्रो नर्कसे के मतानुसार अर्द्ध-विक्षिप्त अर्थव्यवस्थाओं में कृषि क्षेत्र में सलग्न अधिकांश श्रमिक ऐसे होते हैं जिन्हें यदि कृषि-कार्य से हटा लिया जाए तो कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी। आर्थिक दृष्टि से ऐसे श्रमिकों को बेरोजगार ही कहा जाएगा, क्योंकि यह उत्पादन-कार्य में कोई योग नहीं देते अथवा इनका सीमान्त उत्पादन शून्य होता है। चूँकि ऊपर से देखने पर ये श्रमिक काम में लगे होते हैं किन्तु वास्तव में उत्पादन कार्य में कोई योग न देने से ये बेरोजगार होते हैं। इसीलिए इनकी बेरोजगारी को 'प्रच्छन्न बेरोजगारी' कहा जाता है। ऐसी बेरोजगारी के सम्बन्ध में यह कहना बहुत कठिन होता है कि कितना व्यक्ति इस रूप में बेरोजगारी के शिकार हैं।

अल्प-रोजगार (Under-employment)—बेरोजगारी का 'अल्प रोजगारी' स्वरूप भी देश में पाया जाता है। इसके अन्तर्गत वे श्रमिक आते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत काम मिलता है और वे थोड़ा बहुत उत्पादन में योगदान भी देने हैं, किन्तु जिन्हें वस्तुतः अपनी क्षमतानुसार कार्य नहीं मिलता अथवा पूरा कार्य नहीं मिलता। ये श्रमिक उत्पादन में अपना कुछ न कुछ योगदान तो करते हैं, लेकिन उतना नहीं कर पाते जितना कि वे वस्तुतः कर सकत हैं। बेरोजगारी का यह रूप भी एक प्रकार से प्रच्छन्न बेरोजगारी का ही एक अंग है।

मौसमी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment)—बेरोजगारी का यह स्वरूप भी मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है। कृषि में सलग्न अधिकांश श्रमिक ऐसे होते हैं, जिन्हें वर्ष के कुछ महीनों में काम उपलब्ध नहीं होता। ये श्रमिक वर्ष के कुछ मौसम में तो पूर्णरूप से कार्य में व्यस्त रहते हैं और कुछ मौसम में विलकुल बेरोजगार हो जाते हैं। साथ ही कृषि छोड़कर दूसरे काम की तलाश में बाहर भी नहीं जा पाते।

खुली बेरोजगारी (Open Unemployment)—इसका अनिप्राय ऐसी बेरोजगारी से है जिसमें श्रमिकों को कोई रोजगार नहीं मिलता, वे पूर्ण रूप से बेरोजगार रहते हैं। गाँवों से अनेक व्यक्ति रोजगार की तलाश में जहरो में जाते हैं, लेकिन कार्य न मिल पाने के कारण बेरोजगार पड़े रहते हैं।

शिक्षित बेरोजगारी (Educated Unemployment)—शिक्षा के प्रसार के साथ साथ इस प्रकार की बेरोजगारी का कुछ वर्षों में अधिक प्रसार होने लगा है। शिक्षित व्यक्तियों या श्रमिकों की शायं के प्रति प्रत्याशाएँ अल्प सी होती हैं और वे विशेष प्रकार के कार्यों के योग्य भी होते हैं। शिक्षित बेरोजगारों में अधिकांश ऐसे हैं जो ग्रामीण रोजगार की स्थिति में हैं और विशाल संख्या में ऐसे हैं जो खुली बेरोजगारी की अवस्था में हैं। शिक्षित बेरोजगार अधिकतर शहरों में पाए जाते हैं। शिक्षित ग्रामीण भी रोजगार की तलाश में प्रायः शहरों में ही भटकते रहते हैं।

बेरोजगारी की माप

(Measurement of Unemployment)

भारत में बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों को देखते हुए प्रश्न उठता है कि बेरोजगारी की कौन सी किस्म में कितने बेरोजगार हैं अथवा देश में कुल बेरोजगारों की वास्तविक संख्या कितनी है? लेकिन इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है क्योंकि देश में बेरोजगारी की उचित माप असम्भव सी है। हमारे यहाँ बेरोजगारी कुछ इस प्रकार की है कि अभी तक ठीक ढंग से इसकी माप नहीं की जा सकी है और इस सम्बन्ध में उपस्थित विभिन्न कठिनाइयों को देखते हुए ही 1971 की जनगणना में बेरोजगारों के आगमन का कार्य बन्द कर दिया गया है। दाँतेवाला समिति की 1970 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी के सम्बन्ध में जो भी अनुमान लगाए गए हैं वे विश्वसनीय हैं और समुचित प्रवधारणाओं तथा विधियों के सहारे नहीं लगाए गए हैं।

भारत में कृषि क्षेत्र में प्रचलित बेरोजगारी को मापना एक बहुत ही कठिन समस्या है क्योंकि इस बात का पता लगाना लगभग असम्भव ही है कि कृषि क्षेत्र में कितने व्यक्तियों की वस्तुतः आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त देश में कृषि मौसम पर निर्भर है और काम काज मौसम के अनुसार चलता है अर्थात् वर्ष के कुछ भाग में अत्यधिक श्रमिकों की आवश्यकता है तो कुछ भाग में बहुत कम। अतः जो श्रमिक किसी एक समय में उत्पादन-दृष्टि से बहुत आवश्यक होने हैं वे किसी दूसरे समय में गैर जरूरी हो जाते हैं। यह भी एक बड़ी कठिनाई है कि ग्रामीण बेरोजगारी के सम्बन्ध में सही आँकड़ों का अभाव है। शहरी बेरोजगारी के सम्बन्ध में भी आँकड़ों का अभाव है जो आँकड़े उपलब्ध हैं वे रोजगार कार्यालयों द्वारा तैयार किए गए हैं। इन कार्यालयों में मुख्यतः शहरी लोग ही अपना नाम दर्ज कराते हैं और वह भी प्रायः कम संख्या में। देश में बेरोजगार व्यक्तियों के लिए इन कार्यालयों में नाम दर्ज कराना अनिवार्य नहीं है, अतः विशाल संख्या में लोग अपना नाम इन कार्यालयों में दर्ज नहीं कराते। एक अध्ययन के अनुसार, भारत में लगभग 25% बेरोजगार हैं—और वे भी शहरी—इन कार्यालयों में अपना नाम दर्ज कराते हैं। अधिकांश व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कार्यरत तो होते हैं लेकिन बेरोजगारी की सूची में अपना नाम इसलिए दर्ज करा देते हैं कि उन्हें अधिक अच्छी नौकरी का अवसर मिल सके। सक्षेप में बेरोजगारी की माप सम्बन्धी विषय कठिनाइयों के परिणामस्वरूप ही देश में बेरोजगारी के सम्बन्ध में अधिक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं और जो थोड़े बहुत हैं उनमें भी परस्पर बहुत अन्तर है।

भारत में बेरोजगारी के अनुमान (Estimates of Unemployment in India)

यद्यपि बेरोजगारी के बारे में विषयस्त अनुमान और आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तथापि इसमें सन्देह नहीं कि देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में बहुत अधिक सख्या में श्रमिक और शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार हैं। दानेवाला समिति के जो भी विचार रहे हों, लेकिन ये विचार श्रम बाजार में विद्यमान परिस्थितियों पर आधारित नहीं हैं और इस निष्कर्ष से बहुत कम लोगों की सहमति होगी कि 'ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या गम्भीर नहीं है।' बेरोजगारी के सम्बन्ध में सही अनुमान न होते हुए भी इस तथ्य पर पूर्णतः विश्वास किया जा सकता है कि पंचवर्षीय योजनाएँ बेरोजगारी-समाधान का उद्देश्य प्राप्त करने में असमर्थ रही हैं। इसके विपरीत, प्रत्येक उत्तरोत्तर योजना के साथ बेरोजगारी की सख्या में बढ़ोत्तरी होती गई है। एक अध्ययन के अनुसार, प्रथम योजना के अन्त तक कुल श्रम शक्ति में से केवल 29% व्यक्ति बेरोजगार थे, तृतीय योजना के अन्त तक बेरोजगारी की मात्रा बढ़कर 4.5% हो गई और माच, 1969 तक यह 9.6% के आसपास बढकर आँकड़े तक पहुँच गई।¹ चतुर्थ योजना के प्रारम्भ में ही लगभग 100 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे और यह अनुमान था कि चतुर्थ योजना के दौरान लगभग 230 लाख नए श्रमिक श्रम-बाजार में प्रवेश कर जाएँगे। अतः नौकरियाँ प्राप्त करने वालों की सख्या 330 लाख हो जाएगी। नौकरियों की इस माँग के विरुद्ध, 185 से लेकर 190 लाख तक नौकरियाँ कायम की जाएँगी, जिनमें से 140 लाख गैर-कृषि क्षेत्र में और 43 से 50 लाख कृषि-क्षेत्र में होगी। चतुर्थ योजना के अन्त पर 140 लाख बेरोजगार व्यक्ति शेष रह जायें की सम्भावना व्यक्त की गई।

भगवती समिति की रिपोर्ट मई, 1973 में प्रकाशित, तथ्यों के अनुसार सन् 1971 में देश में बेरोजगार व्यक्तियों की सख्या लगभग 187 लाख थी। इनमें से 90 लाख तो ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास कोई रोजगार नहीं था और 97 लाख ऐसे थे, जिनके पास 14 घण्टे प्रति सप्ताह का कार्य उपलब्ध था और जिन्हें बेरोजगार ही माना जा सकता था। इनमें से 161 लाख बेरोजगार व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों से थे और 26 लाख शहरी क्षेत्रों से। कुल श्रम-शक्ति के प्रतिशत के रूप में बेरोजगार व्यक्तियों की मात्रा 10.4 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की मात्रा 10.9/ और शहरी क्षेत्रों में 8.1/ थी। यह विवरण निम्नलिखित सारणी में स्पष्ट है—

1971 में भारत में बेरोजगार श्रमिक

(लाखों में)

मद	कुल	ग्रामीण	शहरीय
कुल बेरोजगार व्यक्तियों की सख्या	187	161	26
कुल श्रम शक्ति	1803.7	1483.7	320
बेरोजगार श्रम शक्ति के प्रतिशत रूप में	10.4	10.9	8.1

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-मण (I L O) के एशिया सम्प्रन्धी एक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में 1962 में 90 प्रतिशत बेरोजगारी विद्यमान थी, किन्तु 1972 में कुल श्रम शक्ति के अनुपात के रूप में 11 प्रतिशत व्यक्ति बेरोजगार थे। यत स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-मण का यह अनुरात भगवती समिति के अनुमान के अनुरूप ही है।

जहाँ तक शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी की समस्या का सम्बन्ध है एक अध्ययन के अनुसार, 1951 में यह समस्या लगभग 24 लाख थी, जो 1972 में 328 लाख हो गई प्रर्थात् इसमें 13 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई। 1970-72 के बीच शिक्षित बेरोजगारी की समस्या में लगभग 146 लाख की तीव्र वृद्धि हुई।

पञ्चवर्षीय योजनाओं के दौरान रोजगार-विनियोग अनुपात

रिजर्व बैंक के विनियोग और रोजगार के अनुमान के अनुसार प्रथम याजना के दौरान एक नई नौकरी कायम करने के लिए औसतन 5,854 रुपये का विनियोग करना पडा और द्वितीय योजना में एवं अतिरिक्त नौकरी कायम करने के लिए 7031 रुपये का विनियोग करना पडा। तृतीय योजना में एक अतिरिक्त नौकरी कायम करने के लिए औसतन 6939 रुपये का विनियोग हुआ। प्रथम तीन योजनाओं के 15 वर्षों में कुल 315 लाख नई नौकरियाँ कायम की गईं जिनमें से 225 लाख अर्थात् लगभग 72/ गैर कृषि क्षेत्र में कायम की गईं। प्रथम तीन पञ्चवर्षीय योजनाओं के दौरान रोजगार और विनियोग का यह चित्र निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट है¹—

पञ्चवर्षीय योजनाओं के दौरान रोजगार और विनियोग

मद	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना
1 स्थापित अतिरिक्त रोजगार (लाखों में)			
(क) गैर-कृषि क्षेत्र	55	65	105
(ख) कृषि क्षेत्र	15	35	40
कुल (क+ख)	70	100	145
2 कुल विनियोग (करोड रुपये)	3,360	6,750	11,370
3 1960-61 के मूल्यों पर विनियोग का सूचकांक	82	96	118
4 1960-61 के मूल्यों पर विनियोग (करोड रुपये)	4,098	7,331	10,062
5 रोजगार विनियोग अनुपात	1 5854	1 7031	1 6939

1 रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन, दिसम्बर, 1969—छद्मदत्त एवं सुन्दरम् से उद्धृत, पृष्ठ 646

भारत में ग्रामीण बेरोजगारी (Rural Unemployment in India)

भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के सम्बन्ध में तथ्य न तो स्पष्ट है और न यथार्थ ही। ग्रामीण बेरोजगारी के सम्बन्ध में रहस्य अब भी बना हुआ है परन्तु कई बातें अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं¹—

(क) परम्परागत अर्थ में इतनी बेरोजगारी नहीं है जितनी कि हम कल्पना करते हैं। सम्भवतः हम ऐसी परिस्थिति में हो जबकि बेरोजगारी तो कम हो परन्तु रोजगार में आमदनी का स्तर बहुत निम्न हो।

(ख) परम्परागत बेरोजगारी और गरीबी सम्भवतः इतने घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध न हो जैसा कि विशुद्ध तार्किक दृष्टि से लगता है—यह एक ऐसी सम्भावना है जिसके सत्य होने की स्थिति में बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।

(ग) ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार और बेरोजगारी के स्वरूप की तह में जाने और छान-बीन करने की आवश्यकता अब भी बनी हुई है और हमें यह मान कर चलना होगा कि हम इस समस्या को मात्र 'श्रम शक्ति' की धारणा से, चाहे वह कितनी ही परिष्कृत हो नहीं सुलझा सकेंगे।

रोजगार सृजन की योजनाएँ

ग्रामीण बेरोजगारी के सम्बन्ध में छान-बीन तो जारी है परन्तु सरकार ने ग्रामीण रोजगार के लिए अनेक योजनाएँ चालू की हैं, जिनमें से निम्नलिखित अधिक महत्वपूर्ण हैं—

1. **ग्रामीण रोजगार योजना**—यह योजना 1971-72 में एक तीन वर्षीय योजना के रूप में आरम्भ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य श्रम-प्रधान परियोजनाएँ चलाकर देश के प्रत्येक जिले में रोजगार के नए अवसर पैदा करना और स्थानीय विकास योजनाओं के माध्यम से टिकाऊ परिसम्पत्तियाँ पैदा करना है। योजना आरम्भ करते समय इसका लक्ष्य प्रत्येक जिले में प्रति वर्ष 300 दिनों के लिए कम से कम एक हजार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का था। देश में कुल 355 जिले हैं और इस प्रकार 3 55 000 लोगों को 300 दिनों के लिए अर्थात् 10,65,00 000 जन दिनों का रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। योजना को पूर्णतया केन्द्रीय क्षेत्र योजना का रूप दिया गया और इसके लिए 50 करोड़ रु की राशि का प्रावधान रखा गया।

ग्रामीण रोजगार योजना, जो 1971-72 में एक तीन वर्षीय योजना के रूप में आरम्भ की गई, काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई। 1973-74 तक की प्रगति का ब्योरा निम्न सारणी से स्पष्ट है²—

1. योजना—22 मार्च, 1973—'बेरोजगारी' पर व्यावहारिक अर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् के निदेशक श्री आई जेड भट्टी का लेख।
2. कुक्षेत्र—अप्रैल, 1974—'ग्रामीण रोजगार योजना' पर थी टी सी पाण्डे का लेख।

निधि का आवंटन व्यय और रोजगार

वर्ष	निधि का आवंटन (लाख रु मे)	दी गई राशि (लाख रु मे)	किया गया वास्तविक व्यय (लाख रु मे)	पैदा किया गया रोजगार (लाख जन दिनों मे)
1971-72	5 000 00	3 373 43	3,116 58	789 66
1972-73	4 885 00	4 711 395	5,339 57	1322 51
		(बाद में 5 040 745 हो गया)		
1973-74 (30.9.73 तक)	4 745 55	1 595 74	976 13	256 31

ग्रामीण रोजगार की प्रभावशाली योजना से क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत बेरोजगार जन शक्ति का उचित उपयोग करने तथा उन्हें उत्पादक और निर्माणात्मक कार्यों में लगाने की दिशा में सफल अनुभव हुआ है। असम, मेघालय, तमिलनाडु, केरल, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 40 से अधिक जिलों का पर्यवेक्षण यही सिद्ध करता है कि ग्रामीण रोजगार योजना काफी सफल रही है और इसे समाप्त न करके अधिक प्रभावी रूप में आगे भी जारी रखा चाहिए।

2 छोटे किसानों की विकास एजेंसी—इस योजना का लक्ष्य छोटी सहायता देकर छोटे किसानों को अपने पैरों पर खड़ा होने के योग्य बनाना है। छोटे किसानों के अन्तर्गत वे किसान आते हैं जिनके पास 2.5 से 3 एकड़ सिंचित (या सिंचाई के योग्य) या 7.5 एकड़ तक असिंचित भूमि है। यह सहायता आदानों या ऋण के रूप में होती है ताकि किसान नए बीजों और खादों का पूरा पूरा लाभ उठा सकें।¹

3 सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक एजेंसी—इस योजना के भी वही लक्ष्य हैं जो छोटे किसानों की विकास एजेंसी के हैं। अन्तर केवल इतना है कि यह योजना छोटे किसानों की विकास एजेंसी के अन्तर्गत न आने वाले छोटे किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए है। इसलिए यह छोटे किसानों की विकास एजेंसी की पूरक है। ग्रामीण कार्यों के माध्यम से कृषि श्रमिकों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना और छोटे किसानों को उसी प्रकार ऋण आदान तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना जिस प्रकार वे छोटे किसानों की विकास एजेंसी के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाती है इस योजना का लक्ष्य है।²

1 योजना दिनांक 22 मार्च 1973—‘बेरोजगारी पर आई जैड मट्री (व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् के निष्कर्ष) का लेख पृष्ठ 6

2 वही, पृष्ठ 6

4 सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम—ग्राम्य निर्माण कार्यक्रम नामक योजना के लिए यह नया नाम है, जो 54 सूखाग्रस्त जिलों तक सीमित है। इस योजना का लक्ष्य 'उत्पादन प्रधान' ऐसे निर्माण-कार्यों को हाथ में लेना है जिनमें धर्म-प्रधान तकनीकों का प्रयोग हो, ताकि सूखे के कारण पैदा होने वाली कमी की भीषणता को कम किया जा सके।¹

उपरोक्त विभिन्न रोजगार-सृजन-योजनाएँ काफी उपयोगी सिद्ध हुई हैं। व्यावहारिक आर्थिक अनुमानों की राष्ट्रीय परिषद् के निदेशक श्री आर्. जैड भट्टी ने 22 मार्च, 1973 के योजना-ग्रन्थ में तर्क प्रस्तुत किया है कि यदि हम परम्परागत बेरोजगारी के स्थान पर रोजगार की प्रभावशालिता पर विचार करें तो ग्रामीण बेरोजगारी सम्बन्धी रहस्य बाकी माना तक लुप्त हो जाएगा और हम गरीबी की समस्या से भी अधिक प्रचण्डी तरह निपटने में समर्थ होंगे। उपचार की दृष्टि से हम स्वयं उत्पादन के सृजन पर उतना बल नहीं देंगे जितना कि समाधानों के विकास पर। उपरोक्त सरकारी योजनाओं में यद्यपि दोनों ही तत्त्व हैं, तथापि समाधानों का विकास वस्तुतः इनमें गौण महत्व रखता है। श्री भट्टी के अनुसार गाँवों की गरीबी की समस्या का सही दशन हमें इस बात के लिए प्रेरित करे कि हम समाधानों के विकास और तत्काल ही सहायक ढाँचे के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इसके लिए नीति सम्मन्धी कुछ अस्थायी परिवर्तन करने होंगे।

ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के उपाय

ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने और ग्रामीण जन-शक्ति का समुचित उपयोग करने के लिए सरकारी क्षेत्र में योजनाओं द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के अन्तर्गत सघन कृषि-कार्यों में मजदूरों का उपयोग करना, निर्माण-मुविधाओं की बढाना, गाँवों में लघु और ग्राम्य उद्योगों को मण्डित करना आदि अनेक कार्य सम्मिलित हैं। सरकार की यह नीति रही है कि जहाँ तक हो सके मानव-श्रम-श्रमता का पूर्ण उपयोग किया जाए तथा आधुनिक मशीनों और यन्त्रों का उपयोग केवल उन्हीं क्षेत्रों में किया जाए जहाँ मानव-श्रम विकास-कार्यक्रमों को पूरा करने में समर्थ न हो। लेकिन इन सब बातों के बावजूद ग्रामीण बेरोजगारी कम होने के स्थान पर ही है। अतः आवश्यक है कि पूरी ग्रामीण शक्ति का उचित उपयोग करने के लिए विशाल पैमाने पर कार्य किए जाएँ। इसके लिए कुछ उपयोगी सुझाव निम्नलिखित हैं—

1 ग्राम-पंचायतों के अन्तर्गत जो विभिन्न कार्यक्रम (नालियाँ खुदवाना, तालाब खुदवाना, सड़कें बनाना, छोटे-छोटे पुल बनाना, भवन निर्माण करना आदि) चल रहे हैं उन्हें अधिक व्यापक स्तर पर और अधिक प्रभावी स्तर में आगे भी जारी रखा जाए।

2 पंचायतों को सीने गए कार्यों के अतिरिक्त स्थायी रूप से चलने वाले ग्राम्य रोजगार-साधन भी गाँवों में प्रारम्भ किए जाने चाहिए तथा इनके लिए

सेवा-सहकारी मस्याओं को उत्तरदायी बनाया जाए। देश का समस्त ग्रामीण क्षेत्र सेवा-सहकारी संस्थाओं से सम्बद्ध है। उनका उपयोग कृषि-ऋण वितरण के लिए तो किया ही जाता है, किन्तु इनके अनिर्दिष्ट ग्रामीण उद्योगों-जैसे पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मछली-पालन, मुर्गीपालन, टोकरी बनाना, साबुन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनकर उद्योग, लुहारी, सुनारी, आदि के लिए साख की पूर्ति तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इन ग्रामीण उद्योगों एवं व्यवसायों का व्यापक रूप से विस्तार किया जाए। अधिक से अधिक ग्रामीण जन-शक्ति का स्थायी उपयोग उन्हें इन उद्योगों में लगाकर ही किया जा सकता है। इससे गांव में रोजगार के अवसरों के साथ ही उत्पादन में भी वृद्धि होगी।

3. सहकारी संयुक्त कृषि समिति या सामूहिक सहकारी कृषि समिति, मछली पालन समिति, सिंचाई समिति, भ्रम-निर्माण समिति, औद्योगिक एवं बुनकर समिति आदि की स्थापना अलग से भी गांवों में करना उपयोगी है। इन समितियों द्वारा गांवों में रोजगार की व्यवस्था की जा सकती है।

4. गांवों के 10 से 18 वर्ष तक के बच्चों को इस प्रकार के काम देने चाहिए, जिन्हें वे अपने विद्या-अध्ययन करने के साथ-साथ कर सकें। इससे उन्हें और उनके परिवार को अनिर्दिष्ट आय प्राप्त हो सकेगी। पाठशाला भवन की सफाई, उमकी भस्म, उममें फूलों का बाग लगाना, गांव में मन्दिरों तथा पंचायत घर आदि के आस-पास बाग बगीचा लगाना, मिट्टी के खिलौने बनाना, काष्ठ की वस्तुएँ एवं खिलौने बनाना, कढ़ाई, ड्राइंग, सिलाई, कटाई, महिला एवं बच्चों के बचत बैंक खोलना, पाठशाला में सहकारी उपभोक्ता भण्डार खोलना एवं उसका संचालन करना आदि अनेक कार्य हैं, जो विद्याध्ययन के साथ-साथ किए जा सकते हैं।

5. भूमि के चक्रबन्दी-कार्यक्रम को तेजी से अमल में लाया जाए ताकि किसान उसमें कुम्हा बनाकर डीजल-इंजन या बिजली की मोटर से सिंचाई कर सकें। सिंचाई की व्यवस्था होने से किसान वर्ष में दो या तीन फसल तैयार करके अपने बेकार समय का पूरा उपयोग कर सकेंगे। साथ ही, एक जगह सारी भूमि इकट्ठी होने से भूमि की देखभाल भी अच्छी तरह हो सकेगी।

6. सरकार ऋण प्रणाली को सुगम बनाए। सरकार ने कृषि की उन्नति के लिए ऋण व्यवस्था तो की है परन्तु उसकी विधि इतनी पेचीदा, उलझनपूर्ण और जटिल है कि साधारण कृषक 6 माह तक अथवा परिश्रम करने के पश्चात् भी ऋण प्राप्त नहीं कर सकता। अतः सरकार को चाहिए कि ऋण स्वीकार करने की विधि को अधिक सरल बनाया जाए। प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक ऐसा चलता-फिरता कार्यालय बनाया जाए जो निश्चित तिथि पर गांव में आए और पटवारी, ग्राम सेवक तथा सहकारी समितियों से आवश्यक सूचना एकत्रित करके ऋण उसी स्थान पर स्वीकार करे। किसान को उसकी जमीन सम्बन्धी जानकारी के लिए पास बुक दी जाए, जिसमें ऋण, यदि कोई लिया हो, तो वह भी लिखा जाए।

7. शिली बगें जिसमें लुहार, खाती, बुनकर, चर्मकार आदि सम्मिलित हैं,

बहुत दयनीय अवस्था में है। इस वर्ग के लोगों के अपने धनो बन्द होने जा रहे हैं फलस्वरूप ये लोग शहरों में जाकर नौकरी की तलाश में भटकते फिरते हैं या गाँवों में रहकर अपना निर्वाह बड़ी ही दुःखद स्थिति में करते हैं अतः आवश्यक है कि इस वर्ग के लोगों को उचित ट्रेनिंग देकर उनकी अपनी सहकारी समितियाँ बनवाई जाएँ तथा उनके धनो का आधुनिकीकरण करने में उन्हें धन और आवश्यक साज-सामान की सुविधा दी जाए।

8 जो ग्राम शहरों के पास स्थित हैं, जहाँ आवागमन के साधन सुलभ हैं, वहाँ पूर्ण पालन और डेरी उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। भारत सरकार द्वारा गठित भगवती समिति ने भी अपनी सिफारिश में यह सुझाव दिया था।

शिक्षित बेरोजगारी (Educated Unemployment)

भारत जैसे अर्द्ध विकसित किन्तु विकासशील देश में जहाँ 3/4 जनसंख्या अशिक्षित है, सामान्य लिखन पढ़ने वाले व्यक्ति को भी शिक्षित कहा जा सकता है। लेकिन शिक्षित बेरोजगारी के अन्तर्गत वे ही व्यक्ति माने जाएँगे जिन्होंने कम से कम मेट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करली हो। भारत में अधिकांश शिक्षित व्यक्ति बेरोजगारी के किम्वीन किसी रूप से पीड़ित हैं। परकार के पाम इतने साधन नहीं हैं कि वह अल्पकाल में सभी शिक्षितों को अथवा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार या पर्याप्त बेकारी भत्ता आदि दे सके। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार 1972 में लगभग 32.8 लाख शिक्षित बेरोजगार थे। 1970 में लगभग 63 हजार इंजीनियर बेरोजगार थे। कुछ वर्षों पूर्व प्रकाशित पुस्तक 'भारत में प्रशिक्षितों की बेरोजगारी' में यह बताया गया है कि मार्च 1970 में 34.5 लाख शिक्षित व्यक्ति रोजगार की तलाश में थे जिनकी सट्टा मार्च, 1971 तक 44.4 लाख हो गई अर्थात् 1 वर्ष में 22.2 प्रतिशत की वृद्धि हो गई। इस पुस्तक के अन्तिम अध्याय में चेतावनी देते हुए लिखा गया है, 'हमारे शिक्षित युवकों में बढ़ती हुई बेरोजगारी हमारे राष्ट्रीय स्थायित्व के लिए जबरदस्त खतरा है। उसे रोकने के लिए यदि समयोचित कदम नहीं उठाया गया तो भारी उथल-पुथल का अन्धशा है।' ¹

शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के उपाय

देश में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को दूर करने के लिए सरकार यद्यपि विभिन्न तरीकों से प्रयत्नशील है, तथापि निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं—

1 देश में शिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक कि द्रुत औद्योगिक विकास नहीं हो। यद्यपि सरकार औद्योगिक विकास के लिए सचेष्ट है, लेकिन उच्च स्तर के कराधान की नीति इस मार्ग में एक बड़ी बाधा है। अधिक कराधान से वचन को प्रोत्साहन नहीं मिलता और जब तक

1. योजना, 22 मार्च, 1972 जी.पी.आयनवाल का लेख 'शिक्षित बेरोजगारों की समस्या राष्ट्रीय स्थायित्व के लिए खतरा है?' पृष्ठ 18

बचत नहीं होगी तथा उमर का उचित विनियोग नहीं होगा, तब तक रोजगार नहीं बड़ेगा। अतः आवश्यक है कि कराधान दर को कम करके औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दिया जाए।

2 देश में उत्पादन-क्षमता का ह्रास ही के वषों में हुआ है। उत्पादन क्षमता तो विद्यमान है, लेकिन विभिन्न कारणों से उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता। साथ ही, उसमें उदात्तता की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। अतः इस प्रकार के उपाय किए जाने चाहिए कि उत्पादन क्षमता के अनुसार पूरा उत्पादन हो सके ताकि अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। देश में अनेक ऐसे औद्योगिक संस्थान हैं जिनमें पूर्ण उत्पादन नहीं हो रहा है। सार्वजनिक-क्षेत्र इस रोग का सबसे बुरा शिकार है।

3 देश में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास अपेक्षित गति से नहीं हो पा रहा है, जबकि इन उद्योगों की रोजगार-क्षमता काफी अधिक होती है। जापान जैसे देश में लघु उद्योगों में लगभग 70 प्रतिशत लोगों की रोजगार मिलता है तो भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ इन उद्योगों के प्रसार की गुंजाइश है, बहुत बड़े प्रतिशत में रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं।

4 इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास भारत के लिए नया है। यदि इसका विस्तार किया जाए तो हजारों इंजीनियरों या डिप्लोमा होल्डरों को रोजगार मिल सकता है।

5. तकनीकी विशेषज्ञों के लिए सेवा-क्षेत्र, रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान कर सकता है। वर्तमान में ट्रांजिस्टर्स, डीजल-इंजनों, वाहनों, रेफ्रिजरेटर्स आदि क्षेत्रों में उपयुक्त सेवा एवं सुधार की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। अतः इस सेवा-क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

6 रोजगार की दृष्टि से वनों का समुचित प्रयोग नहीं किया जाता है। अन्य राज्यों को चाहिए कि वे भी पश्चिमी बंगाल राज्य के समान दैन्यगहन प्रशिक्षण, जंगली जड़ी बूटी की खोज, पशुपालन एवं चिकित्सा जैसे कार्यों को प्रोत्साहन देकर शिक्षित व्यक्तियों के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करें।

7. सरकार सभी शिक्षित लोगों को न तो नौकरी प्रदान कर सकती है और न ही बेरोजगारी का भत्ता दे सकती है। यह बात प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी एक बार नहीं कई बार कह चुकी है। अतः विभिन्न क्षेत्रों के तकनीकी विशेषज्ञों को चाहिए कि वे अपना रोजगार स्वयं खोलें तथा अन्य संस्थाओं से पूँगी तथा कच्चे माल की व्यवस्था करें।

8 19वीं शताब्दी की शिक्षा प्रणाली को यथाशीघ्र बदला जाए, क्योंकि यह नौकरशाही वर्ग को पैदा करने वाली है जो वर्तमान स्थिति में निष्क्रिय सिद्ध हो चुकी है। नवीन शिक्षा पद्धति में श्रम की महत्ता प्रतिष्ठित की जानी चाहिए तथा नौकरियों के पीछे दौड़ने वाली शिक्षा को तिलांजलि दी जानी चाहिए।

9. एक परिवार में जितने कम बच्चे होंगे, उनकी शिक्षा दीक्षा का उत्तम ही उचित प्रबन्ध हो सकेगा तथा उचित नौकरी मिल सकेगी। जहाँ बच्चे अधिक

वहाँ शिक्षा अपूर्ण होगी और अल्प शिक्षित लोग शिक्षित बेरोजगारों की सख्या को बढ़ाएंगे। अतः परिवार सीमित होना आवश्यक है।

10. शिक्षित बेरोजगारों द्वारा स्वयं के उद्योग धन्धे चालू करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए उन्हें कम व्याज-दर पर बैंक एवं अन्य संस्थाओं से ऋण दिलाए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार द्वारा उन्हें सुविधाएँ भी दी जानी चाहिए, जैसे आयकर की कुछ छूट, कच्चे माल की सुविधा, लाइसेंस की व्यवस्था आदि।

11. देश में कृषि-शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए, विशेष रूप से ग्रामीण-क्षेत्रों में, ताकि शिक्षित लोग कृषि-व्यवस्था की ओर अप्रसर हो सकें।

12. सरकार द्वारा चालू किए गए कार्यक्रमों की उपलब्धियों से सम्बन्धित पर्याप्त आँकड़े एकत्रित किए जाने चाहिए और उनके आधार पर भविष्य के लिए इस समस्या से सम्बन्धित कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए तथा उन्हें कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

यदि इन विभिन्न उपायों पर प्रभावी रूप में अमल किया जाए और जो उपाय किए जा रहे हैं उन्हें अधिकाधिक व्यावहारिक तथा प्रभावशाली बनाया जाए तो शिक्षित बेरोजगारों की समस्या दूर की जा सकती है।

बेरोजगारी के कारण

(Causes of Unemployment)

भारत में फैली व्यापक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

1 जनसंख्या-वृद्धि की तुलना में अल्प आर्थिक विकास—देश में प्रतिवर्ष 2.5% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन द्रुत आर्थिक विकास न हो पाने के कारण जनसंख्या-वृद्धि के अनुपात में रोजगार की सुविधाओं में वृद्धि नहीं हुई है। परिणामस्वरूप, अम-शक्ति के बाहुल्य की समस्या उत्पन्न हो गई है। स्वतन्त्रता से पूर्व कई दशान्दियों तक देश की अर्थ-व्यवस्था के स्थिर रहने, परम्परागत उद्योगों का पतन होने और साथ ही आधुनिक ढंग के विस्तृत पैमाने के उद्योगों के विकसित न हो सकने के कारण देश में बेरोजगारी बढ़ती गई। स्वतन्त्रता के पश्चात् यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के आर्थिक विकास के प्रयत्न किए गए हैं, लेकिन आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी रही है। साथ ही योजनाओं में रोजगार प्रदान करने के सम्बन्ध में कोई व्यापक एवं प्रगतिशील नीति अपनाई जाने सम्बन्धी कमी भी रही है। फलस्वरूप, देश में बेरोजगारी का निरन्तर विस्तार हुआ है। आयोजित विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत बढ़ रहे रोजगार के अवसर अमिक सख्या में हो रही वृद्धि की तुलना में कम हैं अतः बेरोजगारी कम नहीं हो पाती, बल्कि निरन्तर बढ़ती जाती है। जनसंख्या-वृद्धि का एक प्रभाव यह हुआ है कि उपभोग व्यय में भारी वृद्धि होने लगी है और पूँजी निवेश के लिए बचत आवश्यकतानुसार उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

2 दोषपूर्ण आयोजन—रोजगार की दृष्टि से भारतीय आयोजन मुख्यतः

दो प्रकार से दोषपूर्ण रहा है। प्रथम, रोजगार नीति से सम्बन्धित है और द्वितीय, परियोजनाओं का चयन। पञ्चवर्षीय योजनाओं में एक व्यापक प्रभावी और प्रगतिशील रोजगार नीति का बहुत बड़ी सीमा तक अभाव रहा है। प्रारम्भ में यह विचार प्रबल रहा कि आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप रोजगार में वृद्धि होगी, अतः विकास नीतियाँ बनाते समय रोजगार के उद्देश्य को लेकर अलग से विचार नहीं किया गया और न ही इस बात के लिए कोई नीति निर्धारित की गई कि योजनावधि में कितने लोगों को रोजगार दिए जाने हैं। रोजगार को योजना के मूल उद्देश्यों में अवश्य सम्मिलित किया गया, लेकिन इसे उच्च प्राथमिकता नहीं दी गई। रोजगार को केवल परिणाम के तौर पर समझने और मापने की नीति रही। केवल योजना-कार्यक्रमों के फलस्वरूप उपलब्ध होने वाले रोजगार के अनुमान लगाए गए। यह सोचकर नहीं चला गया कि योजनाओं के माध्यम से इतनी सख्या में लोगों को निश्चित रूप से रोजगार दिया जाना है। अब आगे चलकर द्वितीय योजनावधि में लघु उद्योगों पर जोर दिया गया तो रोजगार के अवसर बढ़ने लगे, लेकिन इस योजना के दौरान भी मूलतः रोजगार-उद्देश्य को सामने रखकर इन उद्योगों को महत्व नहीं दिया गया। आयोजन की दूसरी गम्भीर त्रुटि परियोजनाओं के चयन सम्बन्धी रही। कुछ विशेष उद्योगों को छोड़कर, जहाँ पूँजी प्रधान तकनीक का अपनाया जाना अनिवार्य था, अन्य बहुत से उद्योगों के सम्बन्ध में वैकल्पिक उत्पादन-तकनीकों के बीच चयन करने की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। विदेशी तकनीकों पर निर्भरता बनी रही और कम श्रम प्रधान उत्पादन विधियों को मान्यता दी जाती रही। चतुर्थ योजना काल से सरकार ने रोजगार नीति में स्पष्ट और प्रभावी परिवर्तन किया। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया और ऐसी योजनाएँ चालू की गईं जिनकी रोजगार देय क्षमता अधिक हो। रोजगार के लक्ष्य निर्धारित करके निवेश कार्यक्रम तैयार किए जाने और उसे कार्यरूप देने की दिशा में सक्रिय कदम उठाए गए। पाँचवी योजना का मुख्यतः रोजगार सचिर्द्ध बनाने की चप्टा की गई है।

3 दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति—भारतीय शिक्षा पद्धति, जो मूलतः ब्रिटिश देन है अपनी 'बाबुओं' को जन्म देती है। यह शिक्षा पद्धति छात्रों की रचनात्मक कार्यों की ओर नहीं मोड़ती तथा स्वावलम्बी बनने की प्रेरणा भी नहीं देती। यह शिक्षा-पद्धति 'कुर्सी का मोह' जाग्रत करती है, इस प्रकार की भावना पैदा नहीं करती कि सभी प्रकार का श्रम स्वागत योग्य है।

4 कृषि का पिछड़ापन—भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ की कृषि पिछड़ी हुई है और कृषि उत्पादन अन्य देशों की अपेक्षाकृत बहुत कम है। कृषि-व्यवसाय में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 70% लोग लगे हुए हैं और प्रायः दूसरे व्यवसायों से प्रायः दूर भागते हैं। इस प्रकार भूमि पर ही लोगों की आत्म निर्भरता बढ़ती जा रही है फलस्वरूप देश में अल्प रोजगार, प्रच्छन्न बेरोजगारी आदि में काफी वृद्धि हो रही है।

बेरोजगारी के उपरोक्त मूलभूत कारणों में ही अन्य सहायक ग्रन्थवा भीण करण निहित हैं। अतिवृष्टि अथवा अनावृष्टि, अल्प प्राकृतिक प्रकोप, लोगों में आनसोपन की प्रवृत्ति, सयुक्त परिवार प्रणाली, 'घर से चिपके रहने' की बीमारी, आदि कारण भी बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी हैं।

बेरोजगारी : उपाय और नीति (Unemployment : Measures and Policy)

बेरोजगारी की समस्या के निदान हेतु आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों से विभिन्न सुझाव दिए जाते रहे हैं और सरकार द्वारा भी निरन्तर प्रयत्न किए जाते रहे हैं। ग्रामीण बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी निवारण के सदर्भ में निम्नलिखित सुझाव विचारणीय है—

(1) अधिकतम आय स्तर पर अधिकतम रोजगार की व्यवस्था करने के लिए जनसंख्या-वृद्धि पर तेजी से और कठोरता से नियन्त्रण लगाना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रमों को व्यापक बनाना और कठोरतापूर्वक लागू करना होगा। यह भी उचित है कि कानूनी रूप से तीन से अधिक सन्तान उत्पन्न करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाए।

(2) लघु एवं कुटीर उद्योगों के तीव्र विकास के साथ ही मिश्रित कृषि को अपनाया जाए अर्थात् कृषि के साथ-साथ पशुपालन और मृगीपालन आदि उद्योग भी अपनाए जाएं।

(3) मानवीय धर्म पर अधिकाधिक बल दिया जाए, जहाँ मशीनीकरण से कोई विशेष अक्षत न होती हो, वहाँ मानवीय धर्म का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए।

(4) अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किसी बड़े विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बाद भी यदि बेरोजगार अस्ति बचे रहे तो उन्हें एक बड़ी सत्पा में काम सिखा कर उन क्षेत्रों में भेजा जाए, जहाँ ऐसे प्रशिक्षित कारीगरों की कमी हो। इसके लिए प्रशिक्षण एवं मर्ग-दर्शन योजनाएँ प्रारम्भ की जानी चाहिए।¹

(5) ग्रामीण औद्योगीकरण एवं विद्युतीकरण का तेजी से प्रसार किया जाए। प्रत्येक क्षेत्र में औद्योगिक विकास का एक-एक केन्द्र कायम किया जाए और इन्हे परिवहन तथा अन्य समुचित सुविधाओं के माध्यम से एक कड़ी के रूप में जोड़ दिया जाए। ऐसे केन्द्र उन शहरों या गाँवों में स्थापित किए जाएँ, जो कुशल कारीगरों तथा उद्योगपतियों को खींच सकें और उन्हें बिजली तथा अन्य सुविधाएँ दी जा सकें।²

(6) शिक्षा-पद्धति को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाय जिससे कर्मचारियों की आवश्यकताओं के बदलने हुए ढाँचे से उसका मेल बैठ सके। कुछ चयनित क्षेत्रों

1. जोरदा, दिनांक 22 मार्च, 1973 में चन्द्रप्रसाद माहेश्वरी का लेख 'बेरोजगारी की समस्या पर एक विहंगम दृष्टि', पृष्ठ 25.

2. वही, पृष्ठ 25.

में जन-शक्ति सम्बन्धी अध्ययनों का आयोजन और तकनीकी शिक्षा-क्षेत्रों का विस्तार करने की नीति पर तेजी से प्रयत्न किया जाए।

(7) कृषि-क्षेत्र में वृद्धि की जाए। भारत में लाखों एकड़ जमीन बंजर और बेकार पड़ी है जिसे अल्प प्रयास से ही कृषि-योग्य बनाया जा सकता है। इससे एक ओर तो श्रमिकों को रोजगार मिलेगा तथा दूसरी ओर कृषि-क्षेत्र में वृद्धि होकर कृषि-उत्पादन बढ़ेगा।

(8) आयोजन के निवेश-ढाँचे में, रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, मुख्यतः दो प्रकार के परिवर्तन लाना आवश्यक है—(क) उद्योगों का चयन-आधारमूलक ढाँचे पर अब तक काफी निवेश हो चुका है और अब आवश्यकता इस बात की है कि अन्य उद्योगों—विशेष रूप से उपभोग-वस्तु-उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। ऐसे उद्योगों की रोजगार देय क्षमता अधिक होती है। इनके अन्तर्गत उत्पादन के अतिरिक्त वस्तुओं के वितरण आदि सेवाओं में भी रोजगार के अवसर बढ़ने हैं। (ख) तकनीक का चयन-रोजगार-दृष्टि से श्रम-प्रधान तकनीकों के चयन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इन दोनों प्रकार के परिवर्तनों द्वारा निवेश-ढाँचे को प्रभावित करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार की विकास-नीति को मोड़ दिया जाए। उत्पादन पर बल देने की नीति के साथ ही साथ रोजगार बढ़ाने वाले उद्योगों और तकनीकों को प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई जाए।

(9) रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए सप्ताहों का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाए जाएँ। अल्प रोजगार में लगे लोगों के काम-काज को बढ़ाया जाए ताकि पहले से लगे समाधानों का अधिक उत्पादक प्रयोग सम्भव बन जाए। कृषि सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए अधिक काम-काज की व्यवस्था की जाए ताकि उनकी अल्प रोजगार की स्थिति को दूर किया जा सके।

(10) विकेंद्रित उद्योग नीति अपनाई जाए ताकि बड़े बड़े शहरों की ओर बेरोजगार लोगों का जाना रुके अथवा कम हो। यह उचित है कि गाँवों और छोटे-छोटे शहरों के आस पास उद्योगों का विकास किया जाए। उद्योगों के विकेंद्रीकरण का फलस्वरूप दो बातें मुख्य रूप से होंगी—प्रथम, श्रमिकों का स्थानान्तरण हकेगा और द्वितीय, अल्प-रोजगार में लगे उन श्रमिकों की स्थिति सुधरेगी, जो बाहर नहीं जाते।

बेरोजगारी दूर करने के लिए उपरोक्त उपाय इस प्रकार के हैं कि रोजगार-नीति केवल रोजगार-नीति न बनी रह कर एक बहुमुखी नीति का रूप धारण कर लेनी है और इस प्रकार की रोजगार की उपलब्धि हमारी अर्थ-व्यवस्था के व्यापक विकास-कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग बन जाती है।

बेरोजगारी सम्बन्धी 'भगवती समिति' की सिफारिशें (Recommendations of Bhagwati Committee)

भारत सरकार ने बेरोजगारी के सम्बन्ध में दिसम्बर, 1970 में जो 'भगवती समिति' नियुक्त की थी, उसने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में आगामी दो वर्षों में सभी

क्षेत्रों में 40 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने की विभिन्न योजनाओं के लिए 20 अरब रुपये की व्यवस्था का सुझाव दिया था। इस विशेषज्ञ समिति ने अन्तरिम रिपोर्ट में जो प्रमुख सिफारिशों की वे बेरोजगारी-निवारण की दिशा में आज भी महत्वपूर्ण मार्गदर्शक ग्रन्थ हैं। इन प्रमुख सिफारिशों का सारांश मार्च, 1972 के योजना प्रक्र. में श्री वेदरनाथ गुप्त के एक लेख में दिया गया है, जो निम्न है—

(1) छाटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों की दुग्धशालाओं, मुर्गीपालन और सूअर पालन केन्द्रों के उत्पादनों के विधायन और हाट व्यवस्था के लिए आवश्यक संगठन बनाए जाने की आवश्यकता पर राज्यों को विचार करना चाहिए।

(2) किसानों को सहायता देने वाली संस्थाओं को, बटाईदारों और पट्टेदारों को कृषि और अन्य सहायक उद्योगों के लिए अल्प अवधि के और मध्यावधि वर्ग दिलाने में सहायता करनी चाहिए।

(3) प्रत्येक जिले के गाँवों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने वाले कार्यक्रमों के लिए राशि, उसकी अनुसरण, वहाँ कृषि विभाग की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रख कर नीति पुनर्निर्धारित की जानी चाहिए।

(4) कुछ चुने हुए जिलों में प्रायोगिक परियोजनाएँ शुरू की जानी चाहिए ताकि उस क्षेत्र का बहुमुखी विकास हो सके।

(5) कृषि-संवर्धन-केन्द्रों की स्थापना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत से इन्जीनियरों को काम मिलेगा।

(6) लघु सिंचाई योजनाओं में अनेक लोगों को रोजगार मिल सकता है, अतः अधिकारिक अतिरिक्त भूमि योजना के अन्तर्गत लाई जानी चाहिए। समिति का सुझाव था कि आगामी दो वर्षों में एक अरब रुपये की लागत से 5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि योजना के अन्तर्गत लाई जाना अपेक्षित है। यह योजना चतुर्थ योजना में निर्धारित कार्यक्रम के अतिरिक्त होनी चाहिए।

(7) समिति ने सुझाव दिया कि चतुर्थ योजना में निर्धारित लक्ष्यों के अतिरिक्त 37 हजार और गाँवों में बिजली एवं 3 लाख नए कुएँ को बिजली दी जानी चाहिए।

(8) गाँवों में बिजली लगाने के कार्यक्रम को इस प्रकार लागू किया जाना चाहिए ताकि अपक्षायित पिछड़े राज्यों में अधिक विकास हो सके और वे राष्ट्रीय स्तर पर लाए जा सकें।

(9) राज्य सरकार सड़क-निर्माण-कार्य के लिए निर्धारित रकम उसी काम में खर्च करें और उस रकम को अन्य मदों में व्यय न करें।

(10) अन्तर्देशीय जल-परिवहन-योजना से भी अनेक लोगों को रोजगार मिलेगा, अतः सरकार को चाहिए कि वह अन्तर्देशीय जल-परिवहन-समिति की सिफारिशों पर अमल करे।

(11) गाँवों में आवास की विकट समस्या को देखते हुए सरकार को तेजी से भवन-निर्माण कार्यक्रम शुरू करना चाहिए।

(12) सरकार को गाँवों में मकान बनाने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू करना चाहिए तथा प्रचार साधनों के माध्यम से इस कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना चाहिए।

(13) प्रत्येक राज्य में एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में वह कार्य करेगी जो कार्य इस समय आवास-मण्डल नगरों में कर रहे हैं। ये कार्य हैं—भूमि का अधिग्रहण और विकास करना तथा आवास योजनाएँ तैयार करके उन्हें क्रियान्वित करना।

(14) जीवन बीमा निगम को भी गाँवों में आवास-कार्यक्रमों के लिए सहायता देनी चाहिए।

(15) गाँवों में पेयजल सप्लाई करने की चालू योजनाओं को तुरन्त क्रियान्वित करना चाहिए तथा इनको अधिकाधिक क्षेत्रों में लागू करना चाहिए।

(16) प्रत्येक राज्य में एक ग्रामीण आवास वित्त-निगम बनाया जाना चाहिए जो सहकारी समितियों, पंचायती-राज संस्थाओं तथा व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता देगा।

(17) प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए एक व्यापक कार्यक्रम जल्दी ही प्रारम्भ करना चाहिए।

(18) जन साक्षरता के लिए जल्दी ही एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाना चाहिए।

(19) औद्योगिक क्षेत्र में व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए कारखानों की वास्तविक उत्पादन क्षमता को अधिकतम सीमा तक बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है।

(20) आर्थिक दृष्टि से अक्षम मिलों के बन्द होने की समस्या से निपटने हेतु सरकार को एक संस्था बनानी चाहिए, जो बन्द हो जाने वाले कारखानों की आर्थिक स्थिति तथा अन्य पहलुओं की जाँच करे। इस संस्था को एक ऐसी विधि अपनानी चाहिए, जिसके अन्तर्गत कारखाने के बन्द होने के सम्बन्ध में समय-समय पर सूचना दी जा सके।

(21) बैंकों को भी चाहिए कि वे अपना धन्धा स्वयं शुरू करने वाले लोगों को वित्तीय सहायता दे। बैंक अधिकारियों को चाहिए कि वे अधिक रोजगार देने वाली योजनाएँ शुरू करें और बैंक की प्रत्येक शाखा के लिए निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें, जो उन्हें पूरा करना होगा। अतिरिक्त साधनों का काफी हिस्सा इन योजनाओं के लिए निर्धारित कर देना चाहिए। बड़े हुए कुल साधनों की 25 से 30 % राशि इन योजनाओं के लिए निश्चित की जा सकती है।

(22) बैंकों को स्वयं धन्धा शुरू करने वाले लोगों की वित्तीय सहायता करने में अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि किसी भी श्रेणी के व्यक्ति को अपना धन्धा अथवा व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए ऋण लेने में कठिनाई न हो।

(23) विशेष वित्तीय सहायता का अधिकाधिक लाभ उठाया जा सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि व्याज-दर, धन लौटाने की अवधि आदि ऋण की शर्तों

और अधिक उदार बनाई जाएं। इसके अतिरिक्त ऐसे नए लेने वाले की आवश्यकता तथा उसकी मजदूरियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। समिति का विचार है कि सम्बन्धित अधिकारियों को पृथक् ब्याज-दरों से सम्बद्ध समिति की सिफारिशें तुरन्त लागू करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए।

(24) उद्योगपतियों को विशेष क्षेत्र या उद्योग में कच्चे माल के सम्बन्ध में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनको दूर करने के लिए उद्योगपति अपने सघ बना सकते हैं, जो सघ उद्योगों की कच्चे माल, धन, उत्पादित वस्तुओं की बिक्री आदि समस्याओं का समाधान कर सकते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर मामले को उपयुक्त अधिकारियों के पास ले जा सकते हैं। सरकार को भी इस तरह के संगठन बनाने की दिशा में प्रोत्साहन देना चाहिए।

(25) बेरोजगार व्यक्तियों के लिए आवेदन-पत्र नि शुल्क होना चाहिए। यात्रा व्यय देने के सम्बन्ध में भी विशेष परिस्थितियों पर ध्यान रखा जाना चाहिए। केवल उस मामले में, जहाँ चुनाव के लिए भाषास्कार आवश्यक है, बेरोजगार व्यक्तियों को यात्रा-व्यय दिया जाना चाहिए, ताकि वे साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकें। हाँ, यदि चुनाव के सम्बन्ध में सभी प्राप्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आवश्यक है तो सभी उम्मीदवारों को यात्रा व्यय देना आवश्यक नहीं है।

भगवती समिति की अन्तिम रिपोर्ट, 1973

(Final Report of the Bhagwati Committee, 1973)

भगवती समिति ने 16 मई, 1973 को अपनी अन्तिम रिपोर्ट भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दी जिसमें आंकड़ों के आधार पर 1971 में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 187 लाख आंकी गई। इनमें से 90 लाख व्यक्ति तो ऐसे थे जिनके पास कोई रोजगार नहीं था और 97 लाख व्यक्ति ऐसे थे जिनके पास 14 घण्टे प्रति सप्ताह का कार्य उपलब्ध था अर्थात् वे बेरोजगार-से ही थे। अन्तिम रिपोर्ट के अन्तर्गत बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए मुख्यतः निम्नलिखित सुझाव दिए गए¹—

1. बेरोजगारों को काम की गारण्टी देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया जाए। जो व्यक्ति रोजगार में सलग्न है उन्हें रोजगार की हानि (Loss of Employment) की स्थिति में बीमा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।

2. कार्यधिकार योजना (Right to work Scheme) सम्पूर्ण देश में लागू की जाए।

3. देहातो के विद्युतीकरण, सड़क-निर्माण, ग्रामीण मकानों और लघु सिंचाई योजनाओं को आगामी दो वर्षों में तेजी से लागू किया जाए। रोजगार कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने में कोई हिचक न की जाए और यदि आवश्यक हो तो विशेष करों तथा चालू करों में वृद्धि का मार्ग अपनाया जाए।

4. काम के घण्टों को सप्ताह में 48 से घटा कर 42 किया जाए और फैक्टरियों को सप्ताह में पूरे 7 दिन तक प्रभावी रूप में चालू रखा जाए ताकि रोजगार में वृद्धि हो।

5. रोजगार एवं श्रम-शक्ति-नियोजन पर एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया जाए।

6. विवाह-आयु लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष कर दी जाए।

भगवती समिति ने अपनी सिफारिशों में लघु सिंचाई और ग्रामों के विद्युतीकरण के कार्यक्रमों को सर्वाधिक महत्व दिया। समिति का विचार था कि इन कार्यक्रमों और सड़क-निर्माण, ग्रामीण आवास आदि की योजनाओं से ग्रामीण बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार की समस्याओं पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। समिति ने सुझाव दिया कि श्रम-प्रधान उद्योगों के लिए कगरे में छूट और रियायत की व्यवस्था की जाए तथा बड़े-बड़े नगरों से उद्योगों का विकिरण किया जाए। यह सिफारिश भी की गई कि कृषि-क्षेत्र में श्रम बचाने वाली भारी मशीनों के प्रयोग पर नियन्त्रण लगाया जाए, विशाल पैमाने पर ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों का संचालन किया जाए (जिसका सकेत ऊपर किया जा चुका है), वानूनों द्वारा इन्जीनियरों एवं तकनीकी श्रमिकों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। समिति का एक महत्वपूर्ण सुझाव यह भी था कि शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में वार्षिक दर से 5 लाख नौकरियों के लिए प्रबन्ध किया जाए। रोजगार एवं श्रम शक्ति नियोजन के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के अतिरिक्त केन्द्र एवं राज्य स्तर पर ऐसे पृथक् विभाग खोले जाएँ, जिनका कार्य केवल रोजगार एवं श्रम शक्ति-नियोजन सम्बन्धी कार्यों की देखभाल हो। जा पिछड़े इलाके हैं उनक लिए पृथक् विकास-मण्डल (प्रादेशिक विकास बोर्ड) बनाए जाएँ। बेरोजगारी पर विभिन्न समितियों और अध्याय में दिए गए अन्य सुझावों पर ध्यान देने तथा उन्हें आवश्यकतानुसार प्रभावी रूप में क्रमशः लागू करने पर ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगारी की समस्या का प्रभावी समाधान सम्भव है।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना और बेरोजगारी

(Fifth Five Year Plan & Unemployment)

1951 के पश्चात् प्रथम बार देश की इस योजना में बेरोजगारी दूर करने पर विशेष बल दिया गया है और विकास के अतिरिक्त अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य का एक मूल उद्देश्य माना गया है। पाँचवीं योजना में रोजगार के महत्व की ठीक परिदृश्य में रखने हुए इस तथ्य को स्पष्टतः स्वीकार किया गया है कि बेकार श्रम-शक्ति को समुचित रूप में प्रयोग में लाने पर विकास-क्षेत्र में पर्याप्त मदद मिलेगी। योजना के दृष्टिकोण-पत्र में रोजगार-विषयक महत्वपूर्ण पहलू संक्षेप में अनुसूचित हैं¹—

1. (अ) भारत सरकार, योजना आयोग : पाँचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण, 1974-79, पृष्ठ 3-8

(ब) योजना, दिनांक 22 दिसम्बर, 1973 (पाँचवीं योजना प्रारूप विवेचना), पृष्ठ 36.

1 देश को रोजगार के इच्छुक लोगों की बढ़ती हुई समस्या की भीषण समस्या से निपटने के लिए योजना बनानी होगी ताकि विकास के मार्ग में यह भयकर खतरा न बने और इनका देश की प्रगति तथा खुशहाली के सशक्त सहायक के रूप में उपयोग किया जा सके।

2 विकास की गति बढ़ाने तथा असमानताएँ घटाने के लिए उत्पादक रोजगार का विस्तार करना बहुत महत्वपूर्ण है। बेकार जन-शक्ति बेरोजगार, अपूर्ण रोजगार पर रहे तथा केवल अशकालीन रोजगार कर रहे लोग, विकास का ऐसे सक्षम साधन हैं जिनका यदि उचित उपयोग किया जाए तो द्रुत विकास किया जा सकता है। इसके साथ-साथ असमानताओं का मुख्य कारण व्यापक बेरोजगारी, अपूर्ण रोजगार का विस्तार कर उसे उचित आय-स्तरों पर सुलभ किया जाए। रोजगार ही एक ऐसा निश्चित तरीका है, जिसके द्वारा गरीबी के स्तर से नीचे जीवन-निर्वाह करने वालों का स्तर ऊँचा उठाया जा सकता है। आय का पुनर्बँटवारा करने के लिए जो प्रचलित कर-नीतियाँ हैं वे स्वयं में इस समस्या पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल सकती।

3 रोजगार नीति इस प्रकार की होनी चाहिए, जिससे बेतन पर मिलने वाला रोजगार तथा अपना धन्धा प्रारम्भ करने का रोजगार, इन दोनों का विस्तार हो सके और उनकी उत्पादकता बढ़े। पाँचवी योजना में कृषि-क्षेत्रों यानी निर्माण, खनन और निर्मित माल का उत्पादन, परिवहन और वितरण परिवहन और संचार, व्यापार भण्डारण, बैंकिंग बीमा तथा समाज सेवाओं में बेतन पर मिलने वाले रोजगार में काफी वृद्धि होने की सम्भावना है। कृषि, कुटीर उद्योग, सड़क परिवहन, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में अधिक पूर्ण और उत्पादक धन्धा प्रारम्भ करने की सम्भावनाएँ हैं।

4 उत्पादन प्रणाली को चुन कर ही विशेष विकास की दर पर रोजगार का विस्तार किया जा सकता है। परन्तु यह प्रणाली श्रम-संचन होनी चाहिए। अथवा ऐसी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए, जो दुर्लभ पूँजी या श्रम द्वारा कृषि करने का स्थान ले। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए चतुर्थ योजना में अनेक रोजगार उन्मुख कार्यक्रमों का सूत्रपात किया गया। आशा है कि इन स्कीमों की पाँचवी योजना में ऐसा रूप दिया जाएगा जिससे अधिकाधिक स्थायी उत्पादक परिणामों के निर्माण के साथ-साथ इनमें सुलभ होने वाले रोजगार के अवसरों में कमी न आए। इन दो उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के कार्यक्रम तैयार करने होंगे, जिससे वर्तमान किस्मों को प्रत्येक क्षेत्र की विकास-प्रक्रिया का अनिवार्य अंग बनाया जा सके।

5. निर्माण कार्य में बहुत अधिक मजदूर कार्य करते हैं। अतः रोजगार वृद्धि के दृष्टिकोण से निर्माण को महत्वपूर्ण क्षेत्र मानना चाहिए। निर्माण कार्यक्षेत्र का विस्तार कुल नियतकालीन पूँजी-निर्माण के विस्तार से सम्बन्धित है।

6. वेतन वाले रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जाएगी तथा अपना धन्धा शुरू करने के लिए अधिक व्यापक स्तर पर सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। समस्त कृषि-क्षेत्र के विकास पर बल दिया जाएगा और अतिरिक्त स्व-रोजगार की सम्भावनाओं का विकास किया जाएगा। बढ़ती हुई श्रम-शक्ति को कृषि-क्षेत्र में ही रोजगार पर लगाए जाने का प्रयास किया जाएगा।

7. कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए भूमि उत्पादन का बुनियादी आधार है। परन्तु इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः जिन लोगों के पास अत्यल्प भूमि है उन्हें भूमि देने का एक ही तरीका है कि जिनके पास बहुत अधिक भूमि है या जो ग्राम्य काम कर रहे हैं, उनसे भूमि लेकर इन लोगों को दे दी जाए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उच्च प्राथमिकता के आधार पर भूमि-सुधार पर बल दिया गया है। दूसरे, यह निश्चय किया गया है कि जो बेकार भूमि प्राप्त हो उसे भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को देने के काम की प्राथमिकता दी जाए। तीसरे, जिन लोगों को भूमि दी जाए उन्हें भरपूर सगठन, ऋण, निवेश तथा विस्तार की सुविधाएँ प्रदान की जाएँ ताकि ये कृषि-कर्म सफलतापूर्वक कर सकें।

8 योजना में बड़ी, मझोली और छोटी सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, अनुसंधान और विस्तार, फसल की कटाई के बाद के काम तथा नई प्रौद्योगिकी को समर्थन प्रदान करने और उसका विस्तार करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पशुपालन, दुग्ध उद्योग और मछलीपालन जैसे जिन कामों के लिए भूमि होनी आवश्यक नहीं है, को बढ़ावा देने पर बल दिया जाएगा। आशा है कि कृषि-क्षेत्र में रोजगार को प्रोत्साहन देने को ध्यान में रखते हुए अनाप-शनाप यन्त्रीकरण नहीं किया जाएगा। केवल इस प्रकार यन्त्रीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा, जो केवल श्रम को बचत करने की अपेक्षा भूमि के प्रति एक समस्त उत्पादन में वृद्धि करेगा।

9 कतिपय विशेष कार्यक्रम, जैसे—लघु कृषक-विकास अभिकरण और नाममात्र कृषि-श्रमिक परियोजनाएँ, ग्रामीण रोजगार की त्वरित स्कीम और सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम चतुर्थ योजना में आरम्भ किए गए। कुल मिलाकर, इन कार्यक्रमों को पृथक्-पृथक् तैयार किया गया तथा इनका संचालन भी स्थिति के अनुसार छितरा पड़ा रहा। पाँचवी योजना में, न केवल इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी लानी होगी बल्कि विशिष्ट संचारात्मक सुधार भी करने होंगे। इन कार्यक्रमों में प्राप्त अनुभव, यह बताया है कि यदि प्रभाव, परिलक्षित करता है, तो सामान्यतया विकास कार्यक्रम और विशेष रूप से विशेष कार्यक्रमों को एक साथ मिलाना होगा। इन क्षेत्रीय लघु और सीमान्त कृषक तथा कृषि-श्रमिकों की श्रम-व्यवस्था में सुधार लाने के लिए यह आवश्यक होगा कि समेकित-क्षेत्र विकास की दिशा में प्रयत्न किया जाए।

10 कतिपय क्षेत्रों में, शारीरिक श्रम करने वालों को रोजगार की गारन्टी देने की दिशा में छोटा-सा प्रयास किया गया है।

11. ग्रामीण और लघु उद्योग, सड़क परिवहन, फुटकर व्यापार व सेवा

व्यवसाय ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें अपना धन्धा आरम्भ करने की सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। अतः जनसंख्या के महत्वपूर्ण अंश अर्थात् शहरी जनसंख्या, शिक्षित व तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित, ग्रामीण कारीगर और ग्रामीण क्षेत्र में ग्रन्थ भूमिहीन तत्त्व ऐसे हैं जिनके लिए पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करने के लिए उपयुक्त क्षेत्रों में रोजगार का विस्तार करना होगा।

12. अर्थ व्यवस्था में यदि रोजगार के साधन तथा अन्य क्षेत्रों के मध्य बेडगा विकास होता रहा, तो इससे रोजगार बढ़ने की अपेक्षा रोजगार कम होगा। अतः रोजगार और अन्त क्षेत्रीय सन्तुलन में तालमेल होना चाहिए। सुविचारित रोजगार-उन्मुक्त योजना के रोजगार-सघन तथा पूँजी सघन क्षेत्रों के मध्य ठीक प्रकार का तालमेल अपेक्षित है।

13. रोजगार वृद्धि की सामान्य नीतियों को विशिष्ट कार्यक्रमों के साथ जोड़कर उनका तालमेल बिठाना होगा ताकि शिक्षित बेरोजगारों की उत्पादन कार्य पर लगाया जा सके। इस प्रयोग के लिए कुशलता प्राप्त तथा अन्य सामान्य वर्गों में अन्तर करना होगा।

14. द्रुत औद्योगिक विकास करने और उत्पादक अनुसंधान तथा विकास कार्यकलापों को कारगर ढंग से आगे बढ़ाने से वैज्ञानिकों इन्जीनियरों और तकनीशियनों को पूर्ण रोजगार दिया जा सकेगा। यदि परिकल्पित औद्योगिक विकास की दर और प्रणाली सही उतरती है और अनुसंधान और विकास के कार्यकलाप सम्भावना के अनुकूल विस्तार करते हैं तो इन्जीनियरों तकनीशियनों और सुयोग्य वैज्ञानिकों को रोजगार देने की समस्या नहीं रहेगी। प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए जो कार्यक्रम बनाया जा रहा है, उससे भी रोजगार के अवसर सुलभ होने की सम्भावना है।

15. सार्वजनिक सेवाएँ, प्रशासनिक सेवाएँ तथा समाज सेवाएँ शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार देने के मुख्य केन्द्र हैं। पाँचवी योजना के दौरान समाज सेवाओं में तीव्र विस्तार करने का विचार है। परन्तु इस पर कि इस अवधि के दौरान रोजगार के इच्छुक शिक्षित लोगों की संख्या इससे काफी अधिक होगी। यह मानना अभ्यावहारिक होगा कि रोजगार की स्थिति में केवल सार्वजनिक सेवाओं के विस्तार से कोई सुधार किया जा सकता है, क्योंकि अर्थ-व्यवस्था के सामग्री तथा सेवा क्षेत्रों में भी समुचित सन्तुलन बनाए रखना जरूरी है। अतः विशेष प्रशिक्षण द्वारा कुशलता प्रदान कर तथा अन्य नीति सम्बन्धी परिवर्तन कर इन्हें समान बनाने वाले क्षेत्रों में काम देना होगा।

16. दीर्घकालीन सम्भावनाओं के अनुसार, नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों की समस्या का निदान केवल माँग पक्ष से विचार कर नहीं किया जा सकता। जहाँ तक कुशल कर्मचारियों का सम्बन्ध है, प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों में प्रवेश की संख्या घटानी पड़ रही है, ताकि समस्या को सुलझाया जा सके। जहाँ तक ग्राम लोगों का सम्बन्ध है, इस बारे में और भी तीव्रता से कार्यवाही करनी होगी ताकि

समस्या पर बाध पाया जा सके। विश्वविद्यालय की शिक्षा को इस प्रकार विनियमित करना होगा जिससे उनकी ही सहाय में शिक्षा प्राप्त कर लोग विश्वविद्यालय से निकलें, जितने लोगों को रोजगार पर लगाया जा सके। इसके लिए न केवल विश्वविद्यालय शिक्षा पर रोक लगानी होगी बल्कि माध्यमिक शिक्षा को अधिक विविधता प्रदान कर उसे व्यावसायिक बनाना होगा ताकि उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं में प्रवेश की भीड़-भाड़ को घटाया जा सके। इसके अतिरिक्त वे सभी नियमित उपाय अन्यायपूर्ण हैं जो समान शिक्षा अवसर मुलभ करने से इनकार करते हैं। समतल गतिशीलता प्रदान करने में शिक्षा, शक्तिशाली तत्व के रूप में कार्य कर सकती है। वर्तमान शिक्षा इस सम्बन्ध में कारगर न होने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि ठोस निरूपण लेकर उचित नीति-नीतियाँ अपनाई जाएँ।

यदि निर्धारित नीति और कार्यक्रमों को प्रभावी रूप में क्रियान्वित किया गया तो, कठिन परिस्थितियों के बावजूद यह आशा है कि पाँचवी योजना की समाप्ति से पूर्व रोजगार की स्थिति में बहुत सुधार हो चुका होगा।

भारत के संगठित क्षेत्र में रोजगार (1974-75)¹ (Employment in the Organised Sector in India)

संगठित क्षेत्र में, 1974-75 में रोजगार में लगभग 2 प्रतिशत वृद्धि हुई। यह सारी वृद्धि लगभग सरकारी क्षेत्र में ही हुई। सभी मुख्य उद्योग-समूहों ने (निर्माण को छोड़कर) रोजगार की इस वृद्धि में योगदान दिया। सेवा क्षेत्र में जिसके अन्तर्गत कुल रोजगार के लगभग 2/5 भाग के रोजगार की व्यवस्था है रोजगार में 2.3% वृद्धि हुई है। निर्माण सम्बन्धी उद्योग समूह के क्षेत्र में रोजगार में 0.7% की मामूली वृद्धि हुई और वह भी सरकारी क्षेत्र के कारण हुई, किन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगार में कुछ कमी हुई। लेकिन खानों तथा पत्थर की खानों के क्षेत्रों में रोजगार में (+7.6%) तथा व्यापार और वाणिज्य में (+8.8%) रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, खानों में रोजगार में वृद्धि मुख्यतः कोयले के उत्पादन में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि हो जाने के कारण माल का लदान करने तथा माल उतारने के लिए अधिक मात्रा में कार्मिकों की आवश्यकता हो जाने के कारण और व्यापार तथा वाणिज्य क्षेत्र के रोजगार-वृद्धि, बैंकिंग सम्बन्धी क्रियाकलाप में विस्तार होने के कारण हुई। बागानों तथा वनों आदि क्षेत्रों में, रोजगार में 0.5% वृद्धि हुई, जो सबसे कम थी। मकान निर्माण के कार्य में लगे हुए कार्मिकों की संख्या में 2.4% की कमी हुई क्योंकि निर्माण-कार्य पर, विशेषतः सरकारी-क्षेत्र में निर्माण के कार्य में प्रयोग की जाने वाली सीमेंट और इस्पात जैसी बुनियादी चीजों की कमी हो जाने के कारण पाबन्दी लगा दी गई थी।

प्रादेशिक क्षेत्रों के अनुसार, 1974-75 में संगठित क्षेत्र में रोजगार में सर्वाधिक वृद्धि पूर्वी क्षेत्र में (+2.5%) हुई और उसके बाद रोजगार में सर्वाधिक वृद्धि दक्षिणी क्षेत्र में (2.4%) हुई। लेकिन पश्चिमी क्षेत्र (+1.6 प्रतिशत),

उत्तरी क्षेत्र (+1.5 प्रतिशत) और मध्यपूर्वी क्षेत्र (1.3 प्रतिशत) रोजगार में जो वृद्धि हुई, वह प्रखिल भारतीय स्तर की रोजगार की औसत वृद्धि से कम थी। उत्तरी क्षेत्र में, राजस्थान, हरियाणा तथा जम्मू और कश्मीर में, रोजगार में, क्रमशः 5.2 प्रतिशत, 4.8 प्रतिशत और 2.8 प्रतिशत वृद्धि हुई, किन्तु दक्षिणी क्षेत्र में, कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेश में क्रमशः 3.9 प्रतिशत तथा 3.8 प्रतिशत वृद्धि हुई। पश्चिमी क्षेत्र में (जिसमें गोवा, दमन और दीव को शामिल नहीं किया गया है) गुजरात सबसे आगे रहा, जहाँ रोजगार में 3.0 प्रतिशत वृद्धि हुई। इसी प्रकार पूर्वी क्षेत्र में, उड़ीसा में रोजगार में सर्वाधिक वृद्धि (+4.1 प्रतिशत) हुई और इसके बाद पश्चिमी बंगाल में सर्वाधिक वृद्धि (+3.0 प्रतिशत) हुई।

सितम्बर, 1975 के अन्त में रोजगार कार्यालयों में नौकरी के लिए नाम लिखवाने वालों की संख्या 92.54 लाख थी, जो एक वर्ष पहले से 7.1 प्रतिशत अधिक थी। इससे रोजगार में कुछ कमी होने का पता चलता है, क्योंकि पिछले 12 महीनों में 5.4 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। यह कमी, निस्संदेह 1975 के मध्य तक उद्योग की धीमी गति के विकास से जुड़ी हुई है। तब से औद्योगिक उत्पादन में सुधार हुआ है जिसका पता, अधिसूचित खाली स्थानों और दी गई नौकरियों के आँकड़ों से चलता है, जो जुलाई-सितम्बर, 1975 में 1974 की इसी तिमाही की अपेक्षाकृत अधिक थी।

नए आर्थिक कार्यक्रम में रोजगार के अवसर में, अप्रेंटिसों के मौजूदा सभी रिक्त स्थानों को तेजी से भर कर, रोजगार में वृद्धि की, विशेष रूप से शिक्षित युवकों के रोजगार की, परिकल्पना की गई है। जब यह कार्यक्रम घोषित किया गया था, उस समय एक लाख उपलब्ध स्थानों में से केवल लगभग 2/3 स्थान वास्तव में भरे थे। सितम्बर, 1975 को समाप्त हुए तीन महीनों की अवधि में लगभग सभी रिक्त स्थानों में नियुक्तियाँ कर दी गईं। अभी हाल में, अधिसूचित उद्योगों और व्यवसायों की सूची में वृद्धि की गई है। परिणामस्वरूप, अप्रेंटिसों की संख्या में काफी वृद्धि होने की सम्भावना है।

राष्ट्रीय रोजगार सेवा

(National Employment Service. N.E.S.)

राष्ट्रीय रोजगार सेवा 1945 में शुरू की गई थी। इसके अन्तर्गत प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा चलाए जाने वाले अनेक रोजगार कार्यालय खोले गए हैं। ये रोजगार कार्यालय रोजगार की तलाश में सभी प्रकार के व्यक्तियों की सहायता करते हैं, विशेषकर शारीरिक रूप से बाधित व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों, अनुसूचित जातियों और जन-जातियों, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों तथा व्यावसायिक और प्रबंधक पदों के उम्मीदवारों की। रोजगार सेवा अन्य कार्य भी करती है जैसे रोजगार सम्बन्धी सूचनाएँ एकत्र और प्रचारित करना तथा रोजगार और धनो सम्बन्धी अनुसंधान के क्षेत्र में सर्वेक्षण और अध्ययन करना। ये अनुसंधान तथा अध्ययन ऐसे आधारभूत आँकड़ें उपलब्ध कराते हैं, जो जन-शक्ति के कुछ पहलुओं पर नीति निर्धारण में सहायक होते हैं।

रोजगार कार्यालय अधिनियम 1959 (रिक्त-स्थान सम्बन्धी अनिवार्य ज्ञापन) के अन्तर्गत 25 या 25 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले मालिकों के लिए रोजगार कार्यालयों को अपने यहाँ के रिक्त स्थानों के बारे में कुछ अपवाद के साथ ज्ञापित करना और समय-समय पर इस बारे में सूचना देते रहना आवश्यक है।

31 दिसम्बर, 1974 को देश में 535 रोजगार कार्यालय (जिनमें 54 विश्वविद्यालय रोजगार तथा मार्ग दर्शन ब्यूरो भी शामिल हैं) थे।¹ निम्नलिखित सारणी में रोजगार कार्यालयों की गतिविधियों से सम्बन्धित आँकड़े दिए गए हैं—

रोजगार कार्यालय तथा अभ्यर्थी²

वर्ष	रोजगार कार्यालयों की संख्या	पंजीकृत सङ्ख्या	रोजगार पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	चालू रजिस्टर में अभ्यर्थियों की संख्या	रोजगार कार्यालयों का लाभ उठाने वाले मालिकों का मासिक औसत	स्थापित रिक्त स्थानों की संख्या
1956	143	16,69,985	1,89,855	7,58,503	5,346	2,96,618
1961	325	32,30,314	4,04,707	18,32,703	10,397	7,08,379
1966	396	38,71,162	5,07,342	26,22,460	12,908	8,52,467
1971	437	51,29,857	5,06,973	50,99,919	12,910	8,13,603
1972	453	58,26,916	5,07,111	68,96,238	13,154	8,58,812
1973	465	61,45,445	5,18,834	82,17,649	13,366	8,71,398
1974	481	51,76,274	3,96,898	84,32,869	12,175	6,72,537

नवम्बर, 1956 से रोजगार कार्यालयों पर दैनिक प्रशासनिक नियन्त्रण का कार्य राज्य सरकारों को सौंपा गया है। अप्रैल, 1969 से राज्य-सरकारों को जन-शक्ति और रोजगार योजनाओं से सम्बद्ध वित्तीय नियन्त्रण भी दे दिया गया। केन्द्रीय सरकार का कार्य-क्षेत्र अखिल भारतीय स्तर पर नीति-निर्धारण, कार्य-विधि और मानकों के समन्वय तथा विभिन्न कार्यक्रमों के विकास तक सीमित है।

229 रोजगार कार्यालयों तथा सारे विश्वविद्यालय रोजगार सूचना तथा मार्ग दर्शन ब्यूरो में युवक-युवतियों (ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें काम का कोई अनुभव नहीं है) और प्रौढ व्यक्तियों (जिन्हें खास-खास काम का ही अनुभव है) को काम-धन्धे से सम्बद्ध मार्ग-दर्शन और रोजगार सम्बन्धी परामर्श दिया जाता है।

शिक्षित युवक-युवतियों को लाभदायक रोजगार दिलाने की दिशा में प्रवृत्त करने के लिए रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के कार्य-मार्गदर्शन और आजीविका परामर्श कार्यक्रमों को विस्तृत और व्यवस्थित किया गया है। रोजगार सेवा अनुसंधान और प्रशिक्षण के केन्द्रीय संस्थान में एक आजीविका अध्ययन केन्द्र स्थापित किया गया है जो युवक-युवतियों तथा अन्य मार्गदर्शन चाहने वालों को व्यवसाय सम्बन्धी साहित्य देता है।

1 India 1976, p. 343.

2 Ibid, p. 343.

राजस्थान में आर्थिक-नियोजन का सक्षिप्त सर्वेक्षण

(A Brief Survey of Economic-Planning in Rajasthan)

मुनाबी नगर जयपुर राजधानी वाला राजस्थान भारत मध्य के उन्नत राज्यों की श्रेणी में आने के लिए योजना-बद्ध आर्थिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,214 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 1971 की जनगणना के आधार पर 2,57,65,806 है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ ही 1951 में राजस्थान राज्य में भी आर्थिक नियोजन का सूत्रपात हुआ। राजस्थान राज्य मात्र तक चार पंचवर्षीय योजनाएँ और तीन वार्षिक योजनाएँ पूरी कर चुका है। 1 अप्रैल, 1974 से राज्य में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना लागू हो चुकी है। 1974-75 से जो एक वर्षीय योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं, वे राज्य की पाँचवीं योजना के अंग रूप में हैं।

राजस्थान में आर्थिक नियोजन के सर्वेक्षण को निम्न शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है—

- (1) राजस्थान की प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाएँ,
- (2) राजस्थान की तीन वार्षिक योजनाएँ,
- (3) राजस्थान की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना,
- (4) राजस्थान की पाँचवीं पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजनाएँ
(1974-75, 1975-76, 1976-77)
- (5) राजस्थान में सम्पूर्ण योजना-काल में आर्थिक प्रगति।

राजस्थान में प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाएँ

राजस्थान की तीनों पंचवर्षीय योजनाओं की प्रस्तावित और वास्तविक व्यय राशि इस प्रकार रही—

योजना	प्रस्तावित व्यय-राशि (करोड़ रुपये में)	वास्तविक व्यय-राशि (करोड़ रुपये में)
1. प्रथम योजना	64.50	54.14
2. द्वितीय योजना	105.27	102.74
3. तृतीय योजना	236.00	212.63

पूर्वोक्त सारणी से स्पष्ट है कि योजना-व्यय की राशि उत्तरोत्तर बढ़ती गई। प्रथम योजना में सार्वजनिक-क्षेत्र में व्यय की राशि लगभग 54 करोड़ रुपये से बढ़कर द्वितीय योजना में लगभग 103 करोड़ रुपये और तृतीय योजना में लगभग 213 करोड़ रुपये हुए।

तीनों योजनाओं में सार्वजनिक-व्यय की स्थिति

राजस्थान की प्रथम तीनों योजनाओं में विकास के विभिन्न शीर्षकों पर सार्वजनिक व्यय की स्थिति (संख्या और प्रतिशत दोनों में) निम्न सारणी से स्पष्ट है—

(करोड़ रुपये में)

विकास के शीर्षक	प्रथम योजना		द्वितीय योजना		तृतीय योजना	
	रुपये (वास्तविक)	कुल व्यय से प्रतिशत	रुपये (वास्तविक)	कुल व्यय से प्रतिशत	रुपये (वास्तविक)	कुल व्यय से %
1	2	3	4	5	6	7
1 कृषि एवं सामुदायिक विकास	6 99	12 90	25 45	24 77	40 65	19 11
2 सिंचाई	30 24	55 86	23 10	22 57	76 23	35 85
3. शक्ति	1 24	2 27	15 15	14 74	39 64	18 64
4 उद्योग तथा खनिज	0 46	0 85	3 38	3 29	3 31	1 50
5 सड़कें	5 55	10 25	10 17	9 90	9 75	4 59
6 सामाजिक सेवाएँ	9 12	16 84	24 31	23 67	42 03	19 77
7 विविध	0 55	1 01	1 09	1 06	1 02	0 48
योग	54 14	100 00	102 74	100 00	212 63	100 00

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि राजस्थान की आर्थिक योजनाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचाई एवं शक्ति को दी गई है। प्रथम योजना में कुल व्यय का लगभग 58 /, द्वितीय योजना में लगभग 37 / और तृतीय योजना में कुल व्यय का लगभग 54 / सिंचाई एवं शक्ति पर व्यय किया गया है। प्रथम योजना में द्वितीय प्राथमिकता सामाजिक सेवाओं को रही जिस पर कुल वास्तविक व्यय का लगभग 17% खर्च किया गया। द्वितीय योजना में इस मद पर लगभग 24 / व्यय हुआ और इस दृष्टि से यह व्यय कृषि एवं सामुदायिक विकास में किए गए व्यय (लगभग 25 प्रतिशत) के सन्निकट रहा। तृतीय योजना में भी सामाजिक सेवाओं और कृषि एवं सामुदायिक विकास पर लगभग बराबर व्यय किया गया। सामाजिक सेवाओं पर 20 / से कुछ कम तथा कृषि एवं सामुदायिक विकास पर 19 / से कुछ अधिक व्यय किया गया।

सार्वजनिक व्यय के इस आवंटन से स्पष्ट है कि राजस्थान ने अपनी तीनो योजनाओं में एक ओर तो सिंचाई एवं विद्युत-विकास का पूरा प्रयत्न किया और दूसरी ओर वह जन-वस्थापन के लिए सामाजिक सेवाओं के विस्तार को भी ऊँची प्राथमिकता देता रहा। परिवहन में प्रथम दोनो योजनाओं में सड़कों के विकास पर काफी बल दिया गया और तृतीय योजना में भी कुल-व्यय का 6/ से कुछ कम इस कार्यक्रम पर व्यय किया गया।

प्रथम तीनो योजनाओं में आर्थिक प्रगति

राजस्थान की तीनो पंचवर्षीय योजनाओं में प्रस्तावित नियोजन के 15 वर्षों में (1951-66) हुई कुल उपलब्धियों का सामूहिक सिद्धावलोकन करना अध्ययन की दृष्टि से विशेष उपयुक्त होगा। इन तीनो योजनाओं में सिंचाई एवं शक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और उनके बाद प्राथमिकता में सामाजिक सेवाओं, कृषि कार्यक्रमों सहकारिता एवं सामुदायिक विकास, यातायात एवं संचार तथा उद्योग और खनिज का क्रमशः द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम् स्थान आता है।

इन प्राथमिकताओं पर आर्थिक विकास व्यय से ग्रहणव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का विकास निम्न तथ्यों से स्पष्ट है—

राज्य की आय एवं प्रति व्यक्ति आय—राजस्थान राज्य की 1954-55 में कुल आय (1961 के मूल्यों के आधार पर) 400 करोड़ रुपये थी। वह प्रथम योजना की समाप्ति पर 456 करोड़, द्वितीय योजना की समाप्ति पर 636.6 करोड़ रु और तृतीय योजना के अंत में बढ़कर 841.8 करोड़ रु हो गई। प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 260 रु, 323 रु और 381 रु हो गई। 1966-67 में राज्य की कुल आय 1,015 करोड़ तथा प्रति व्यक्ति आय 449 रु हो गई।

कृषि-विकास—कृषि-विकास को भी इन तीनो योजनाओं में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। भूमि-व्यवस्था में कानूनीकारी एवं प्रगतिशील सुधारों के परिणामस्वरूप जमींदारी तथा जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। छोटे-छोटे और बिखरे खेतों की समस्या के लिए कानून तथा 18.81 लाख हेक्टर भूमि की चकबन्दी का कार्य पूरा किया गया।

कृषि उत्पाति में वृद्धि के लिए सुधरे बीज, रासायनिक खाद तथा वैज्ञानिक कृषि को प्रोत्साहन मिला। राज्य में 50 बीज-विकास-फार्म स्थापित किए गए और 30.29 लाख हेक्टर में सुधरे बीजों का प्रयोग होने लगा। नए औजारों और यंत्रोकरण को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि मंत्रालय की स्थापना और रूस की सहायता से 1956 में भूरतगढ़ में कृषि फार्म, जैतसार में कृषि-फार्म का दूसरा प्रयास योजनाओं की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ रही।

कृषि के लिए प्रशिक्षित अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए उदयपुर में कृषि-विश्वविद्यालय, जोबनेर में कृषि महाविद्यालय का विस्तार, बीकानेर में पशुचिकित्सालय प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना कृषि-विकास की दिशा में लाभदायक बरत रहे।

पशु धन के विकास के लिए 17 केन्द्रीय ग्रामखण्ड स्थापित किए गए। जहाँ राजस्थान के निर्माण के समय पशुधन के रोगों की रोकथाम के लिए राज्य में 57 औपचारिक, 88 चिकित्सालय और 2 चल चिकित्सालय थे, वहाँ उनकी संख्या तृतीय योजना के अन्त में क्रमशः 204, 129 और 24 हो गई।

सारांशित राजस्थान के आर्थिक नियोजन के 15 वर्षों में राजस्थान में खाद्यान्न की उत्पादन क्षमता लगभग दुगुनी, तिलहन की तिगुनी, कपास की दुगुनी हो गई। राजस्थान में जहाँ सामान्य समय में भी 50 हजार से एक लाख टन खाद्यान्न का अभाव रहता था, वहाँ अब आत्मनिर्भर होकर अन्य राज्यों को निर्यात करने की क्षमता हो गई। पशु-रोग निवारण, विकास तथा बीजों के सुधार की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की गई।

सिंचाई एवं शक्ति—राज्य के आर्थिक नियोजन में सिंचाई साधनों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। तीनों योजनाओं के कुल वास्तविक व्यय 369.58 करोड़ रुपये में से 129.66 करोड़ रु केवल सिंचाई पर व्यय किया गया। फलस्वरूप, सिंचाई-क्षेत्र 11.74 लाख हेक्टर (1950-51) से बढ़ कर तृतीय योजना के अन्त तक 20.80 लाख हेक्टर तक पहुँच गया।

शक्ति के साधनों पर कुल व्यय की गई राशि 56.62 करोड़ रु के बराबर थी। सन् 1950-51 में विद्युत् उत्पादन-क्षमता 7.48 मेगावाट थी, जो 1967-68 में बढ़कर 163 मेगावाट हो गई। 1950 में केवल 23 बिजली-घर थे जो 1967-68 में 70 हो गए। प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग भी 1965-66 तक 3.06 किलोवाट से बढ़कर 15.37 किलोवाट हो गया।

सहकारिता एवं सामुदायिक विकास—राजस्थान में जनता के सर्वांगीण विकास और जनसहयोग वृद्धि के लिए 2 अक्टूबर, 1962 को सामुदायिक विकास कार्य प्रारम्भ हुआ। अब राज्य की समस्त ग्रामीण जनसंख्या सामुदायिक विकास की परिधि में आ गई। राज्य में 1965-66 तक 232 विकास खण्डों की स्थापना हो चुकी थी। इनमें 83 प्रथम चरण खण्ड, 95 द्वितीय चरण खण्ड और 66 उत्तर द्वितीय चरण विकास खण्ड थे।

विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत योजनाओं की समाप्ति पर 26 जिला परिषद्, 232 पंचायत समितियाँ और 7,382 ग्राम पंचायतें काम कर रही थी।

सहकारिता का क्षेत्र भी बहुत बढ़ा है। जहाँ 1950-51 में राज्य में सहकारी समितियों की संख्या 3,590 थी और सदस्य संख्या 1.45 लाख थी, वहाँ 1965-66 में क्रमशः 22,571 तथा सदस्य संख्या 14.33 लाख हो गई है। तृतीय योजना के अन्त तक 33 प्रतिशत ग्रामीण परिवार सहकारिता आन्दोलन के अन्तर्गत आए जा चुके थे जबकि 1950-51 में यह 1.5% ही था।

प्रशिक्षण के लिए जयपुर में सहकारिता प्रशिक्षण स्कूल तथा कोटा, डूंगरपुर व जयपुर में प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किए गए।

सामाजिक सेवाएँ—तीनों पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सामाजिक सेवा

क्षेत्र पर 75.46 करोड़ रु व्यय किए गए अर्थात् कुल व्यय का 20.42% भाग शिक्षा, चिकित्सा व श्रम कल्याण आदि पर व्यय किया गया। फलस्वरूप, शिक्षण-संस्थाओं की संख्या 6,029 (वर्ष 1950-51) से बढ़ कर 32,826 (वर्ष 1965-66) हो गई। इसी प्रकार, चिकित्सालयों व डिस्पेंसरियों की संख्या भी 366 से बढ़कर 535 हो गई। जल-पूर्ति की योजनाएँ भी 72 ग्रामीण और शहरी केन्द्रों में पूरी की गई। इसके अतिरिक्त, राज्य में 3 विश्वविद्यालय, 5 मेडिकल कॉलेज, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज और 4 कृषि-कॉलेज भी स्थापित हुए। लगभग 10 स्थानों पर पंचायतीराज प्रशिक्षण केन्द्र कार्य करने लगे और 5 ग्राम सेवक प्रशिक्षक केन्द्र भी कार्यरत हुए।

योजनाकाल में गृह-निर्माण के कार्यों में काफी प्रगति की गई। अल्प-आय-गृह-निर्माण-योजना के अन्तर्गत 7,162 गृह-निर्माण किए गए। औद्योगिक गृह योजना के अन्तर्गत 3,974 मकान बनाए गए।

पिछड़े वर्गों की जनसंख्या राज्य की जनसंख्या का लगभग 1/4 भाग है। एकीकरण के समय इनकी स्थिति आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से बहुत पिछड़ी हुई थी। इनकी स्थिति सुधारने के लिए छात्रवृत्तियाँ, गृह निर्माण, आवास व्यवस्था और अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। तृतीय योजना के अन्त में इस क्षेत्र के अन्तर्गत 1 रिमोड होम, एक प्रमाणित शाला, 1 आपटर बेयर होम, 1 वृद्ध एवं दुर्बलों के लिए एव 3 रेस्क्यू होम काम कर रहे थे। इसके अतिरिक्त 19 परिवीक्षा अधिकारी भी परिवीक्षा सेवाएँ कर रहे थे।

परिवहन एवं संचार—राज्य के बहुमुखी विकास के लिए सड़क निर्माण पर ध्यान देना बहुत आवश्यक था, क्योंकि राज्य के पुनर्गठन के समय प्रति 100 वर्ग मील पर 5.35 मील लम्बी सड़कें थी। सन् 1951 में कुल मिलाकर सड़कों की लम्बाई 18,300 किलोमीटर थी, वह तृतीय योजना की समाप्ति पर बढ़कर 30,586 कि.मी. हो गई। प्रथम, द्वितीय और तृतीय योजनाओं में क्रमशः 5.5 करोड़ रु., 10.2 करोड़ रु. और 9.7 करोड़ रु. व्यय से प्रत्येक योजना के अन्त में सड़कों की कुल लम्बाई 1955-56 में 22,511 किलोमीटर, 1960-61 में 25,693 किलोमीटर और तृतीय योजना के अन्त 1965-66 में 30,586 किलोमीटर हो गई, अर्थात् तीन योजनाओं में 25.4 करोड़ रु. के विकास व्यय से सड़कों की कुल लम्बाई में 12,000 किलोमीटर से अधिक वृद्धि हुई। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 5 किलोमीटर लम्बी सड़कें हो गई। इस प्रकार लगभग कुछ तहसील मुख्यालयों को छोड़कर सभी तहसील मुख्यालयों को जिला मुख्यालयों से जोड़ दिया गया।

केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत रेल परिवहन में फतहपुर-चुरु, उदयपुर-हिम्मतनगर और गगानगर-हिन्दू मल कोट रेल लाइनें बनाई गईं।

उद्योग—तीनों योजनाओं की अवधि में उद्योग एवं खनन पर 7.15 करोड़ रु. व्यय किए गए। योजना के दौरान कई औद्योगिक नगरों, जैसे—कोटा, गगानगर, जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर, डीडवाना, खेतड़ी आदि का विकास हुआ। रजिस्टर्ड फंड्रियों की संख्या जहाँ प्रथम योजना के अन्त में 368 थी वहाँ द्वितीय योजना

के घन में 856 और तृतीय योजना के घन में 1564 हो गई। राज्य में औद्योगिक इकाइयों की कुल संख्या नियोजन अवधि में लगभग 76% बढ़ी।

रोजगार—प्रत्येक योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से अपनी मानव-शक्ति का पूर्ण उपयोग करने का होता है। राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाओं में भी इस उद्देश्य की ओर उचित ध्यान देने की चेष्टा की गई है। द्वितीय योजना में 3.77 लाख व्यक्तियों को और तृतीय योजना में 6.50 लाख व्यक्तियों को अनिवारित रोजगार प्रदान किया गया।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजस्थान ने विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद भी आर्थिक नियोजन के 15 वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की। नियोजन काल में की गई सर्वांगीण प्रगति के आधार पर ही राजस्थान ज़मन: तेज़ी से आर्थिक व सामाजिक समृद्धि के मार्ग पर बढ़ रहा है। यह आशा है कि निकट भविष्य में राजस्थान औद्योगिक एवं सामाजिक दृष्टि से विकसित होकर देश के अन्य उन्नत राज्यों की श्रेणी में आ सकेगा।

राजस्थान की तीन वार्षिक योजनाएँ (1966-69)

तृतीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के उपरान्त, विकट राष्ट्रीय संकटों और भारत-पाक संघर्ष आदि के कारण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1966 से लागू नहीं की जा सकी, किन्तु नियोजन का क्रम न टूटने देने के लिए, 1966-69 की अवधि में तीन वार्षिक योजनाएँ कार्यान्वित की गईं। तीनों वार्षिक योजनाओं में कुल व्यय लगभग 137 करोड़ रुपये हुआ। पहले ही की भाँति सिंचाई एवं शक्ति की प्राथमिकता दी गई और कुल व्यय का लगभग 61% इस मद पर खर्च हुआ। सामाजिक सेवाओं पर लगभग 15.5% व्यय हुआ और इस प्रकार प्राथमिकता की दृष्टि से इस मद का द्वितीय स्थान है। कृषि-कार्य पर कुल व्यय का लगभग 15% व्यय हुआ। परिवहन, सड़क आदि पर लगभग 3% व्यय किया गया। इन वार्षिक योजनाओं में कृषि सिंचाई व शक्ति की पहले से दी जाने वाली प्राथमिकता में और भी वृद्धि कर दी गई, जबकि सामाजिक सेवाओं पर किया गया प्रतिशत व्यय द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं की अपेक्षा कम रहा। वास्तव में साधनों के अभाव में वार्षिक योजनाओं की प्राथमिकताओं में कुछ परिवर्तन करना स्वाभाविक था।

विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद वार्षिक योजनाओं में कुछ क्षेत्रों में प्रगति जारी रही। 1968-69 के अन्त में विद्युत-उत्पादन 174 मेगावाट तक जा पहुँचा। खाद्यान्नों के उत्पादन में प्रथम वार्षिक योजना में स्थिति आशानुभूति नहीं रही, द्वितीय वार्षिक योजनाओं में खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 66 लाख टन हुआ, किन्तु तृतीय वार्षिक योजनाओं में खाद्यान्नों का उत्पादन प्रथम वार्षिक योजना के लगभग 43.5 लाख टन से भी घटकर केवल 35.5 लाख टन पर आ गया। सामाजिक सेवा क्षेत्र में प्रगति हुई, परिवार-नियोजन कार्यक्रम प्रायः बढ़ा और ग्रामीण तथा शहरी जल-पूर्ति कार्यक्रम भी सन्तोषजनक रूप में आगे बढ़े।

राजस्थान की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74)¹

राज्य की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल, 1969 से आरम्भ हो गई, लेकिन कुछ कारणों से इसे अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। योजना आयोग ने पाँचवें वित्त-आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए देश के विभिन्न राज्यों की योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन किया और 21 मार्च, 1970 को राजस्थान राज्य की संशोधित चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का आकार 302 करोड़ रुपये निर्धारित किया जबकि राज्य-सरकार ने 316 करोड़ रुपये की योजना प्रस्तुत की थी।

इस योजना में राज्य द्वारा प्रस्तावित व्यय-राशि का आवंटन (प्रतिशत सहित) इस प्रकार था।²

(करोड़ रुपये में)

विकास की भेद	चतुर्थ योजना का व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत
व्यय		
1	2	3
1 कृषिगत कार्यक्रम	23	7.3
2. सहकारिता एवं सामुदायिक विकास	9	2.8
3 सिंचाई एवं शक्ति	189	59.8
4. उद्योग तथा खनन	9	2.9
5. परिवहन एवं संचार	10	3.2
6 सामाजिक सेवाएँ	73	23.1
7 अन्य	3	0.9
कुल	316	100.0

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि चतुर्थ योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचाई एवं शक्ति को दी गई तथा दूसरे स्थान पर सामाजिक सेवाएँ रही। कृषिगत कार्यक्रम का इनके बाद स्थान रहा और इन पर कुल व्यय का 7.3% व्यय करने की व्यवस्था की गई। चतुर्थ योजना समाप्त होने के पश्चात् जब इसके व्यय और उपलब्धियों का अन्तिम मूल्यांकन किया गया तो योजना के उपरोक्त प्रस्तावित व्यय तथा वास्तविक व्यय में कोई विशेष अन्तर नहीं था। राजस्थान राज्य के आय-व्यय के अध्ययन (वर्ष 1976-77) के अनुसार वास्तविक व्यय की राशि 308.79 करोड़ रु रही। चतुर्थ योजना की विभिन्न विकास भेदों पर कितना वास्तविक व्यय हुआ, यह पाँचवी योजना से सम्बन्धित एक सारणी में (जिसमें दोनों योजनाओं के तुलनात्मक आँकड़े दिए गए हैं) दर्शाया गया है।

1. चौथी योजना का यह विवरण मुख्य रूप से तीन स्रोतों पर आधारित है—(क) पाँचवी योजना का प्रारूप जो जुलाई, 1973 में राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया, (ख) वित्त-मन्त्री राजस्थान का बजट भाषण, 1973-74, एवं (ग) वित्त-मन्त्री का बजट भाषण, 1974-75.
2. Draft Fifth Five Year Plan 1974-79, p. 13

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आर्थिक प्रगति

राज्य की आय-वृद्धि—चतुर्थ योजना में किए गए विभिन्न प्रयत्नों से राज्य की आय में वृद्धि हुई। 1971-72 के मूल्यों के अनुसार योजना समाप्ति के समय प्रति व्यक्ति आय 600 रुपये अनुमानित की गई। 1971 एवं 1974 के बीच राज्य की जनसंख्या में 8.51 प्रतिशत तक की दर से वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है।

कृषिगत कार्यक्रम—चतुर्थ योजना के दौरान कृषिगत कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया। अधिक उन्नत किस्मों के बीजों, रासायनिक उर्वरकों और लघु सिंचाई के माध्यम से कृषि-कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। 1971-72 के अन्न में अधिक उपज वाली फसलों की किस्म का क्षेत्रफल 8 लाख हेक्टेयर था जो 1972-73 के अन्त तक लगभग 12.34 लाख हेक्टेयर तक और 1973-74 में लगभग 13.20 लाख हेक्टेयर पहुँच गया। उर्वरकों का वितरण 1971-72 में 2.89 लाख टन था जो 1972-73 में लगभग 3.18 लाख टन तक पहुँच गया। ऋषि-नियोजन से 1972-73 तक की समाप्ति तक 5.75 लाख टन खाद्यान्नों, 0.36 लाख टन निलहन एवं 90 लाख टन कपास की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बढ़ने की आशा थी। 1973-74 में 71 लाख टन खाद्यान्न उत्पन्न होने का अनुमान था जबकि चौथी योजना के प्रारम्भ में उत्पादन-क्षमता का आधार-स्तर 63 लाख टन था। चतुर्थ योजनावधि में दुग्ध उत्पादन भी 22.70 लाख टन से बढ़कर 23.70 लाख टन तक हो गया। पौध संरक्षण की व्यवस्थाओं एवं गतिविधियों को विस्तृत किया गया। भूमि समतलन सम्बन्धी कार्य भी हाथ में लिए गए। 1968-69 की तुलना में सहकारी साख में दुगुने से भी अधिक वृद्धि हो गई।

सिंचाई एवं बिजली—चतुर्थ योजनावधि की समाप्ति तक 7 मध्यम सिंचाई योजनाएँ अर्थात् पारवती, मेजा, मोरेल बेडच (बडगाँव), बेडच (बल्लभनगर), ओराई एवं खारी फीडर लगभग पूरी हो गई। इसके अतिरिक्त 30 अन्य लघु सिंचाई योजनाओं पर भी कार्य प्रारम्भ हो गया। सिंचित क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई। 1968-69 में जो सिंचित क्षेत्र 21.18 लाख हेक्टेयर था, वह 1973-74 में बढ़कर लगभग 25.67 लाख हेक्टेयर हो गया। राजस्थान नहर क्षेत्र में बड़ी तेजी से प्रगति हुई और योजना की समाप्ति तक इस नहर परियोजना पर कुल व्यय लगभग 104 करोड़ रुपये का हुआ। 1968-69 में इसकी सिंचाई-क्षमता केवल 1.64 लाख हेक्टेयर थी जो योजना की समाप्ति तक बढ़कर लगभग 2.80 लाख हेक्टेयर हो गई।

शक्ति अर्थात् विद्युत्-उत्पादन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जवाहर-सागर परियोजना एवं राणाप्रताप सागर अणु विद्युत्-शक्ति प्लांट की यूनिट एक का काम पूरा हो गया। अन्न स्थायी विद्युत्-उत्पादन जो 1968-69 में 174 मेगावाट था, बढ़कर 1973-74 में 400 मेगावाट तक हो गया। योजनावधि में प्रति व्यक्ति के पीछे खर्च होने वाली बिजली के ग्राँकड़े 26 किलोवाट प्रति व्यक्ति

से बढ़कर 60 किलोमीटर तक हो गया। 1968-69 तक केवल 2,247 ग्रामीण वस्तिधो में विद्युतीकरण हुआ था, जो योजना के अन्त तक बढ़कर लगभग 5,850 वस्तिधो तक पहुँच गया। विद्युतीकरण किए गए कुप्रो की संख्या भी 18,795 से बढ़कर लगभग 73,000 हो गई। इस प्रकार चतुर्थ योजना-काल में 54,000 से भी अधिक कुप्रो को बिजली दी गई।

उद्योग एवं खनन—योजना-काल में औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। वनस्पति, तेल, सीमेंट, पावर केबल्स, सूती धागे, मशीन टूल्स, चीनी एवं नाइलोन के धागे आदि के उत्पादन हेतु अनेक महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित किए गए। कुछ वस्तुधो के उत्पादन में बहुत समीपप्रद वृद्धि हुई। 1973 के अन्त तक वनस्पति तेलो तथा उर्वरको के उत्पादन में 1969 की तुलना में क्रमशः 480 प्रतिशत एवं 96 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नाइलोन के धागे, सीमेंट, माइका इन्स्यूलेशन ब्रिक्स एवं बालविद्युति के उत्पादन में भी 1968 की तुलना में क्रमशः 28 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 65 प्रतिशत एवं 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

राज्य वित्त निगम ने उद्योगो को अपनी ऋण-सहायता में भी काफी वृद्धि की। 1964-65 से 1968-69 की पाँच वर्ष की अवधि में 156 औद्योगिक इकाइयो को 450 करोड़ रुपये की कुल ऋण सहायता दी गई थी और चतुर्थ योजनावधि में 1,065 इकाइयो को लगभग 1536 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा सकने की सम्भावना थी। राज्य सरकार ने आधारभूत सुविधाएँ देने की प्रणाली जारी रखी। योजना समाप्ति तक 13 औद्योगिक क्षेत्रों में 1814 एकड़ औद्योगिक भूमि का विकास हो जाने तथा 252 औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण-कार्य पूरा हो जाने की आशा थी। राज्य ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सेन्ट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज) में किया गया विनियोजन 1966-67 में 1686 करोड़ रुपये से बढ़कर 1973-74 में लगभग 100 करोड़ तक पहुँच गया। रजिस्टर्ड फॅक्टरियो की संख्या भी योजनावधि में 1,846 से बढ़कर लगभग 2,800 हो गई।

खनिज क्षेत्र में सबसे उल्लेखनीय घटना भाभरकोटडा में रॉक फॉस्फेट की उपलब्धि रही। चतुर्थ योजना की समाप्ति तक इन खानों से 795 लाख टन कच्चा धातु निकाले जा चुकने की आशा थी। योजना-काल में तांबा व कच्चे लोहे के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। 1973 के समाप्ति होने तक कच्चा माइका, सिल्वर, लैंड क्रसस्ट्रेट, कैल्साइट एवं फॅल्स्डार के उत्पादन में 1968 के स्थान पर क्रमशः 114 प्रतिशत, 48 प्रतिशत, 114 प्रतिशत, 91 प्रतिशत एवं 42 प्रतिशत की अधिक वृद्धि हुई।

परिवहन व संचार—योजना-काल में परिवहन और संचार-क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। लगभग 2,500 किलोमीटर लम्बी सड़कें और बनीं। 25 प्रतिशत भागों का योजनावधि की समाप्ति तक राष्ट्रीयकरण किया गया। पाँचवी योजनावधि में शत-प्रतिशत बस-मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर देने की आशा वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में व्यक्त की। सड़कों के विकास के फलस्वरूप 1973-74 के अन्त

तक राज्य में कुल सड़कों की संख्या लगभग 33,880 किलोमीटर हो जाने की आशा थी।

सामाजिक सेवा—चतुर्थ योजना-काल में सामाजिक सेवाओं और सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि हुई। राज्य में 2,100 से अधिक प्राथमिक शालाएँ, 3,000 मिडिल स्कूल, 290 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा 7 नए कॉलेज खोले गए। 1968-69 में ग्राम-जल-प्रदाय योजना 225 ग्रामों में चालू थी, किन्तु 1973-74 में उनकी संख्या बढ़कर 1,427 हो गई। राजस्थान आवासन बोर्ड के तत्वावधान में गृह-निर्माण कार्य में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। 1974 के अन्त तक 2,655 भवनों का निर्माण-कार्य पूरा हो जाने की आशा वित्त-मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में व्यक्त की।

रोजगार—बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में भी काफी प्रयत्न किए गए। योजनावधि में लगभग 8 लाख लोगों को रोजगार की सुविधाएँ प्रदान की गईं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एवं शिक्षित युवकों के लिए रोजगार प्रदान करने वाले अनेक कार्यक्रमों को हाथ में लिया गया, जिनमें से अधिकांश कार्यक्रम भारत सरकार की सहायता से प्रारम्भ हुए। 1973-74 में भारत सरकार द्वारा आवंटित 276 करोड़ रुपये की राशि से एक 'हाफ-ए-मिलियन जॉब्स प्रोग्राम' प्रारम्भ किया गया जिसके अन्तर्गत 20 हजार शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकेगा।

अतः स्पष्ट है कि चतुर्थ योजनावधि में राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हुई। तथापि योजना-काल के अन्तिम दो वर्षों से राज्य को एक नाजुक आर्थिक स्थिति के दौर से गुजरना पड़ा, क्योंकि दश की समूची अर्थव्यवस्था में मुद्रा-स्फीति का दबाव बढ़ गया। जबर्दस्त सूखे के कारण अन्न-उत्पादन को और विद्युत्-उत्पादन में कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन को भारी आघात पहुँचने, विश्व में तेल-मूल्यों में असाधारण वृद्धि होने तथा अन्य संकटों के कारण देश की समूची अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव व असर पड़ता रहा।

राजस्थान की पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप एवं 1974-75 की वार्षिक योजना

राजस्थान सरकार के नियोजन विभाग द्वारा जुलाई, 1972 में राज्य की पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण-पत्र प्रकाशित किया गया। इस दृष्टिकोण-पत्र में पाँचवीं योजना में अपनाई जाने वाली आधारभूत नीतियों, विनियोग की मात्रा, विकास-दर आदि के सवन्ध में कतिपय प्रस्ताव रखे गए। विकास-दर 7% वार्षिक प्रस्तावित की गई। सावजनिक क्षेत्र में व्यय के लिए 775 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए जिनमें से 600 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त की जानी थी। दृष्टिकोण-पत्र में सिंचाई व शक्ति को सर्वाधिक महत्त्व देते हुए कुल प्रस्तावित राशि 775 करोड़ रुपये का 60% निश्चित किया गया। कृषि-कार्यक्रमों के लिए 13%, उद्योग एवं खनन के लिए 4.5% तथा सामाजिक सेवाओं के लिए 15% व्यय नियत किया गया। दृष्टिकोण-पत्र में आर्थिक विषयताओं को दूर करने के

सम्बन्ध में कोई ठोस सुझाव नहीं दिए गए और वित्तीय साधनों के अभाव की समस्या पर भी समुचित ध्यान नहीं दिया गया।

जुलाई, 1973 में राज्य सरकार द्वारा पाँचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप (Draft) तैयार किया जा कर योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दृष्टिकोण-पत्र में सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय के लिए 775 करोड़ रुपये का प्रावधान था किन्तु प्रारूप में योजना का आकार 635 करोड़ रुपये ही रखा गया। राजस्थान राज्य के आय व्यय का अध्ययन 1976-77 के अनुसार पाँचवी योजना का कुल परिव्यय (Outlay) 691 47 करोड़ रुपये रखा गया है। भारत सरकार की पाँचवी पंचवर्षीय योजना का अन्तिम रूप से पुनर्मूल्यांकन अक्टूबर, 1976 में प्रकाशित होने की सम्भावना है और स्वाभाविक है कि राज्यों की पंचवर्षीय योजनाओं में भी न्यूनाधिक हेरफेर सामने आएँगे।

पाँचवी योजना (1974-79) पिछली योजनाओं की तुलना में अधिक व्यावहारिक और देश में समाजवादी ढाँचे के समाज की स्थापना के सक्षम के अधिक अनुकूल है। इसका संकेत राज्य के मुख्य मंत्री हरिदेव जोशी के इन शब्दों से भी मिलता है कि, 'चार पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात् अब यह अनुभव किया जाने लगा है कि आर्थिक विकास पर बल देने मात्र से स्वतः ही न तो जनता के कमजोर वर्गों का जीवन स्तर ऊँचा होता है और न ही आमदनी और अन्य आर्थिक लाभों का व्यापक वितरण ही होता है। साथ ही, हम यह भी पाते हैं कि पिछली पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के उपरान्त भी हम अन्य राज्यों की अपेक्षा विकास के निम्नतर स्तर पर हैं। इस स्थिति में हमारे लिए यह आवश्यक है कि पाँचवी पंचवर्षीय योजना में हम ऐसे प्रयास करें कि राज्य के विकास की गति में अधिकाधिक विकास हो ताकि राजस्थान और अन्य राज्यों के बीच विकास के स्तरों का अन्तर कम हो सके।'¹

पाँचवी योजना के उद्देश्य और मूल नीति

प्रमुख रूप से पाँचवी योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं—

- (1) आर्थिक विपत्ति कम से कम रहे
- (2) प्रत्येक को जीवन-यापन का साधन मिले
- (3) सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा हो
- (4) क्षेत्रीय असमानता में कमी हो
- (5) मानव-मूल्यों का विकास हो।

इन उद्देश्यों का संकेत मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी ने किया। स्पष्टतः उनके ये कोई कूटनीति-प्रेरित वाक्य नहीं हैं अपितु योजना-प्रारूप में उल्लिखित उद्देश्यों का सक्षिप्तीकरण है। प्रारूप के प्रथम पृष्ठ के प्रथम पैरा में ही स्पष्ट रूप में उल्लेख है

1. राजस्थान विकास, दिसम्बर, 1973 में मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी का लेख 'पाँचवी योजना का आधार,' पृष्ठ 3

2 Ibid, p 13

कि, "राज्य की पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य विकास की स्थितियों को उत्पन्न करने में समर्थ विभिन्न क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहन देकर आर्थिक आधार को मजबूत बनाना है। प्रयत्न यह होगा कि आर्थिक विकास के लाभ जनता के अधिकाधिक बड़े भाग को मिल सकें और जनता के बहुमत के जीवन स्तर में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, महत्वपूर्ण सुधार हो सके।"¹ प्रारूप के प्रथम अध्याय में योजना के मूलभूत उद्देश्यों और योजना की व्यवस्था-रचना अथवा मूल नीति को विस्तार से स्पष्ट किया गया है। स्पष्टता के लिए मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं—

1. अर्थ-व्यवस्था के उन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा जो विकास की गति को तीव्र करने और अधिकतम उत्पादन दे सकने में समर्थ हो।

2. विभिन्न क्षेत्र में विकास कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किए जाएंगे जिससे समाज के कमजोर वर्गों को योजना के अधिकाधिक लाभ उपलब्ध हो सके। उन कार्यक्रमों को वरियता दी जाएगी जो रोजगार के अवसरों को बढ़ा सकें। यह प्रयास किया जाएगा कि शिक्षा सुविधाओं, स्वास्थ्य-कार्यक्रमों, जल-पूर्ति, विद्युतीकरण, सड़कों, गन्दी वस्तुओं के सुधार आदि के सम्बन्ध में ग्रामीण जनता की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

3. उन कार्यक्रमों को अपनाया जाएगा जिनके द्वारा प्राथमिक उत्पादकों, कृषि-श्रमिकों और जनता के कमजोर वर्गों की आय में वृद्धि हो सके।

4. कृषि-नीति को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। यह प्रयास किया जाएगा कि प्रति एकड़ उत्पादन बढ़े। साथ ही, अधिक गहन कृषि पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा, क्योंकि राज्य में नई भूमि पर कृषि विस्तार की सम्भावनाएँ सीमित हैं। राज्य में पशुपालन के विकास की भारी सम्भावनाओं को देखते हुए इसके लिए चरागाहों तथा चारे के विकास की दिशा में सक्रिय प्रयास किए जाएंगे।

5. भूमिगत-जल (Ground water) का विशेष रूप से प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि राज्य में सतही जल (Surface water) की मात्रा सीमित है।

6. सिंचाई क्षमता का अधिकतम उपयोग करते हुए कृषकों के लिए कृषि और पशुपालन विकास के लिए साल-सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। भूमि को समतल बनाने तथा भू-संरक्षण और शुष्क कृषि-कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इनके लिए चम्बल एवं राजस्थान नहर परियोजनाओं के सिंचाई-क्षेत्रों का समन्वित ढंग से विकास किया जाएगा। इस विकास-कार्यक्रमों में सड़कों और मण्डियों का निर्माण, विद्युतीकरण, वैज्ञानिक कृषि-पद्धतियाँ आदि विभिन्न बातें सम्मिलित हैं।

7. राज्य में बड़े मध्यम एवं लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस बात का पूरा प्रयास होगा कि औद्योगिक विकास निगमों के माध्यम से 'आधारित संरचना' (Infra-Structure) के विकास को गति मिले।

1 Draft Fifth Five Year Plan (Rajasthan) 1974-79, p. 1.

2 Ibid, pp. 8-12

योजना के प्रारूप में प्रस्तावित राशियों और आय-व्यय के अध्ययन 1976-77 में दिखाई गई राशियों में हुआ विशेष अन्तर नहीं आता। योजना प्रारूप में सर्वोच्च प्राथमिकता (49.9 प्रतिशत) सिंचाई एवं शक्ति को दी गई है, दूसरा स्थान सामाजिक सेवाओं का है, जिनके 23.1 प्रतिशत राशि निर्धारित की गई है। कृषि-कार्यक्रम को तीसरा स्थान दिया गया है जिस पर 10.2 प्रतिशत राशि व्यय करने का प्रस्ताव है। यदि परिव्यय को भिन्न राशि में लें तो प्रारूप के अनुसार कुल 635 करोड़ रुपये के परिव्यय में से सिंचाई एवं शक्ति पर 316 करोड़ रु., सामाजिक सेवाओं पर 147 करोड़ रु. और कृषि-कार्यक्रमों पर 65 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान है और ये राशियाँ आय-व्यय अध्ययन 1976-77 की राशियों से कुछ ही अन्तर रखती हैं। आय-व्यय के अध्ययन में भी सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचाई एवं शक्ति को, दूसरा स्थान सामाजिक सेवाओं को और तीसरा स्थान कृषि-कार्यक्रमों को दिया गया है।

राज्य की वार्षिक योजना (1974-75)

राजस्थान सरकार के आयोजना विभाग द्वारा 1974-75 की वार्षिक योजना (पाँचवी योजना के अग्र के रूप में) के प्रारूप में 98 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान रखा गया लेकिन योजना आयोग द्वारा 79.80 करोड़ रुपये का परिव्यय ही स्वीकार किया गया। 1974-75 की इस वार्षिक योजना के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी हमें राजस्थान के वित्त मन्त्री के 1974-75 के बजट भाषण में मिलती है। अग्रिम विवरण इसी बजट भाषण के आधार पर दिया गया है।¹

वर्ष 1974-75 की वार्षिक योजना के परिव्यय (79.80 करोड़ रुपये) की वित्तीय व्यवस्था निम्न उपलब्ध स्रोतों से की जाने की व्यवस्था की गई।

	(करोड़ रुपये में)
1. केन्द्रीय सरकार से सहायता	45.06
2. राज्य द्वारा जुटाए गए अतिरिक्त साधन	5.00
3. आवासन हेतु जीवन-बीमा निगम से ऋण	1.00
4. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से ऋण	0.80
5. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का डिप्रिसिएशन रिजर्व	2.98
6. राज्य विद्युत मण्डल द्वारा ऋण	13.95
(क) सार्वजनिक	4.95
(ख) जीवन-बीमा निगम से	4.00
(ग) ग्राम-विद्युत निगम से	5.00
7. सार्वजनिक ऋण	2.20
(क) राज्य आवासन-मण्डल	1.10
(ख) राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम	1.10

8. राजस्थान राज्य पथ परिवहन नियम का

डिप्रिस्सिएशन रिजर्व

1 49

9 नगरपालिकाओं की जल प्रदाय स्कीमों के

लिए जीवन-बीमा निगम से ऋण

1 50

योग

7 98

वार्षिक योजना में घाटा

5 82

चूँकि 79.80 करोड़ रुपये की योजना परिव्यय की वित्तीय व्यवस्था करने में 5.82 करोड़ रुपये की कमी पूरी नहीं हो पाती, अतः इसके लिए अतिरिक्त साधन जुटाए जाना का निश्चय किया गया।

इस वार्षिक योजना में 79.80 करोड़ रुपये के परिव्यय का विभिन्न मदों के अनुसार आवंटन इस प्रकार रखा गया—

1 कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएँ

6 49

2 सहकारिता

1 09

3 उद्योग एवं खान

3 26

4 परिवहन एवं संचार

6 10

5 सामाजिक एवं ग्रन्थ सामुदायिक सेवाएँ

20 88

6 जल एवं विद्युत विकास

40 55

7 ग्रन्थ सेवाएँ

1 43

योग

79 80

उपरोक्त 79.80 करोड़ रुपये के परिव्यय के अतिरिक्त सांस्थानिक वित्तीय एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न राज्य निगमों, मण्डलों, राज्य एजेंसियों, सहकारी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों द्वारा विकास की गतिविधियों में लगभग 72 करोड़ रु के व्यय का और विनियोजन करण का अनुमान था। इसके अतिरिक्त, केन्द्र संचालित स्कीमों पर कम से कम 20.08 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान था। इस प्रकार, 1974-75 में सार्वजनिक क्षेत्र में विकास पर होना वाला कुल परिव्यय 171.88 करोड़ रुपये होने का अनुमान था।

राज्य की वार्षिक योजना (1975-76)

राज्य की वार्षिक योजना 1975-76 के लिए योजना आयोग द्वारा 105.50 करोड़ रुपये का र्षी व्यय अनुमोदित किया गया, किन्तु कुछ अनुभाग जैसे शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रामीण विद्युतीकरण तथा ब्रह्माण्ड विकास-यंत्र की नितान्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परिचय की राशि अधिक रही और 1976-77 के आय व्यय अध्ययन में दी गई एक सारणी के अनुसार सम्भावित व्यय 135.38 करोड़ रुपये है।

योजना का परिचय और सम्भावित व्यय

निम्नांकित सारणी में राज्य की वार्षिक योजना 1975-76 के परिचय और सम्भावित व्यय की राशियों के साथ ही सम्पूर्ण पाँचवी योजना के परिचय की दर्शाया गया है। साथ ही, राज्य की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के परिचय और व्यय सम्बन्धी आँकड़े भी दिए गए हैं। इस प्रकार हमारे समक्ष चतुर्थ और पंचम योजना का एक तुलनात्मक चित्र उपस्थित हो जाता है—

(करोड़ रुपये)

विभाग	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना		परिचय (1974-79)	पंचम पंचवर्षीय योजना	
	परिचय (1969-74)	व्यय		परिचय	सम्भावित व्यय (1975-76)*
1	2	3	4	5	6
1 कृषि एवं सम्बन्धित सेवाएँ	25 10	22 55	73 93	10 79	11 56
2 सहायता	8 20	8 12	8 30	1 10	1 14
3 सिंचाई एवं शक्ति	178 83	186 95	327 47	63 29	69 25
4 उद्योग तथा खनन	7 95	8 55	27 99	4 53	5 10
5 यातायात एवं संचार	9 78	10 00	57 77	7 35	24 91
6 सामाजिक सेवाएँ	73 38	71 65	189 27	23 31	22 95
7 अन्य	2 97	0 97	6 75	0 47	0 47
योग	306 21	308 79	691 47	110 84	135 38

* प्रावधानिक

योजना के लक्ष्य और उपलब्धियाँ

राजस्थान राज्य के आर्थिक अध्ययन 1976-77 में राज्य की वार्षिक योजना (1975-76) के लक्ष्य और उपलब्धियों का जो विवरण दिया गया है, वह निम्नानुसार है—

“राज्य अर्थव्यवस्था में कृषि अनुभाग की महत्ता को देखते हुए संचित क्षेत्रफल में वृद्धि तथा अन्य साधन जैसे खाद्य एवं उन्नत बीजों की उपलब्धि कराने के प्रयत्न किए गए। अधिक उपज देने वाले उन्नत बीज कार्यक्रम को 13.92 लाख हेक्टर भूमि तक विस्तारित करने, रासायनिक खाद का उपयोग 1.59 लाख में टन तक बढ़ाने तथा 55 लाख हेक्टर भूमि में पौध संरक्षण उपायों के विस्तार किए जाने का प्रावधान रखा गया। खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 1975-76 में 1974-75 के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 1.5 लाख में टन अधिक रखा गया।

वर्ष 1975-76 में लघु सिंचाई योजना के लिए भूमि-विकास बैंकों के द्वारा वितरित ऋण की राशि बढ़ा कर 12.40 करोड़ रुपये कर दी गई थी जिसमें 7.15

करोड़ रुपये की कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा दी गई राशि भी शामिल है। वर्ष 1975-76 के प्रारम्भ में 30 ए. आर. सी योजनाएँ चालू रही एवं 20 नवीन योजनाओं को प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित था। सिचाई विभाग द्वारा अधिकांश चालू योजनाओं को ही पूर्ण करने का कार्यक्रम था। विश्व बैंक महायता तथा डी पी ए पी के कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि विकास के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को राजस्थान नहर एवं चम्बल के कनाबड एरिया में प्रारम्भ किया गया।

कृषि-विस्तार को पुनः सक्रिय करने, खेतों में तकनीकी प्रयोग अपनाने, भू संरक्षण कार्यक्रमों का अधिकाधिक सामञ्जस्य, शुष्क कृषि-प्रसार तथा लघु सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिकों में सम्बन्धित उल्लेखनीय कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए, जैसा कि ग्रामीण वर्ष की समीक्षा में दृष्टिगोचर होता है। राज्य में इन कार्यक्रमों के क्रियान्वित होने से कृषि-क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

वर्ष 1975-76 में पशु-पालन के अन्तर्गत एक आधार ग्रामकेन्द्र 11 घातु एकत्रण उप इकाइयाँ, 6 पशु चिकित्सालय तथा दो नवीन भ्रमणशील इकाइयाँ पर्याप्त पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ कराने हेतु ग्रामीण वर्ष में खोली गईं।

राज्य के मूलाग्रस्त क्षेत्रों के व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में सुधार एवं आय में वृद्धि करने हेतु दुग्ध-विकास योजना पर निरन्तर मूल्त्व दिया गया। वीकानेर, अजमेर व जोधपुर की दुग्ध शालाओं का एवं जयपुर में नया सयन्त्र लगाने का कार्य लगभग समाप्ति पर है। डेरी-विकास कार्य मुख्यतः सहकारी क्षेत्र में होने से दुग्ध उत्पादक सहकारी इकाइयों को अनुदान देना तथा उनकी हिस्सा पूँजी को बढ़ाने का भी प्रावधान रखा गया।

राज्य की अन्य योजनाओं में से नहर एवं सड़क के किनारे वृक्षारोपण व चारागाह विकास के कार्यक्रम लिए गए। 6500 हैक्टर भूमि में गिरे हुए कूपों की फेसिंग तथा भवन व ग्रहरी स्तम्भ इत्यादि का निर्माण परिभाषित चनों के पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया।

सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत कमजोर सहकारी बैंकों के पुनरोद्धार व हिस्सा पूँजी, जो कि सहकारी साल सस्थाओं का आधार है, में वृद्धि करने का कार्य किया गया। अल्प एवं मध्यकालीन साल को प्रभावी कृषि हेतु जो 1974-75 में 41.93 करोड़ रुपये की थी, बढ़कर वर्ष 1975-76 में 62.32 करोड़ रुपये की हो गई, विशेष अभियान के अन्तर्गत वर्ष 1975-76 में कृषि परिवारों के विस्तार में लगभग 50/ की वृद्धि हुई, जबकि वर्ष 1974-75 में यह वृद्धि 42/ थी। सामुदायिक विकास क्षेत्र में, कृषि-उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं और पुरस्कार दिए गए। उसग्रह शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रम को राजस्थान के 385 गाँवों में कार्यान्वित करना एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

सिचाई क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्थान नहर, व्यास इकाई प्रथम एवं द्वितीय, चम्बल प्रथम चरण, माही बजाज व जालम तथा चार मध्यम सिचाई योजनाएँ, जैसे सेई डाईवर्शन, मेजा फीडर, जैतपुरा व गोपालपुरा चालू सिचाई योजनाएँ थीं।

वर्ष 1975-76 में सभी वृद्ध व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से 110 40 हेक्टर हैक्टर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई होने की आशा है। इस प्रकार कुल सिंचाई क्षेत्र गत वर्ष के 9 40 लाख हैक्टर से बढ़कर 10.34 लाख हैक्टर हो जाएगा। वर्ष 1975-76 में राजस्थान नहर और चम्पल के सिंचित क्षेत्र में से क्रमशः 2 84 लाख हैक्टर और 1 80 लाख हैक्टर की वृद्धि की आशा है। समस्त साधनों के माध्यम से सिंचित क्षेत्र वर्ष 1974-75 के 27 57 लाख हैक्टर से बढ़कर वर्ष 1975-76 में 28 59 लाख हैक्टर होने की सम्भावना है।

उद्योग एवं खनिज क्षेत्र में राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम के स्क्रूटर एवं दूरदर्शन यन्त्र सम्बन्धित प्लांट इस वर्ष उत्पादन-स्तर पर आ जाने की सम्भावना है। बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत हाथ-कच्चा उद्योग के विकास हेतु राजस्थान हाथ-कच्चा बोर्ड की स्थापना की गई है। खानों के अन्तर्गत राजन की सोडियम सल्फेट प्लांट डीडवाना की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया है। डेरी वेग मेटल, जिसमें जस्ता एवं ताँबे की 12 / मिश्रित मात्रा है, का अनुमानित 10 लाख मैन टन का भण्डार समन्वेषण स्तर पर था। ग्रूम बेस मेटल भण्डार पर अनुसंधान कार्य जारी रहा। भामरकोटरा के प्रमाणित फास्फेट भण्डार की क्षमता वर्ष 1974-75 के 375 लाख मैन टन से बढ़ कर वर्ष 1975-76 में 395 लाख मैन टन हो जाने की सम्भावना है। सड़क क्षेत्र में राज्य एवं केन्द्रीय योजनाओं तथा अकाल प्रसूत कार्यों के अन्तर्गत विशेष महत्त्व चालू योजनाओं को पूर्ण करने पर रहा। मिनीयम नोड कार्यक्रम के अन्तर्गत 2500 एवं उससे अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों को नई सड़कों से जोड़ने का कार्य प्रारम्भ किया गया।

राजस्थान एवं चम्पल नहर के कमाण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत बस्तियों भण्डियों व उपज केन्द्रों को जोड़ने हेतु सड़क निर्माण के लिए प्रावधान किया गया। वर्ष 1975-76 में 395 किलोमीटर नवीन सड़कों का निर्माण करने का निश्चय किया गया। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बसों में वृद्धि की गई तथा यात्रियों को सुविधाएँ प्रदान की गई हैं व लगभग 40 प्रतिशत सड़क भागों को निगम ने अपने अधीन ले लिया। पर्यटन क्षेत्र के अन्तर्गत दो नए डाक बगलों के निर्माण वर्तमान पर्यटन बगलों में अधिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा पर्यटक स्थलों के विकास ज़िम्मे जयपुर को सुन्दर बनाने व भाउण्ट आर्य के विकास के लिए राशि का प्रावधान किया गया।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत नए प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण, अपूर्ण भवनों को पूर्ण करने एवं औषधि वितरण के कार्यक्रम किए गए। चिकित्सा शिक्षा-कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 चिकित्सा महाविद्यालय एवं इनमें सम्बन्धित चिकित्सालयों में अनिर्दिष्ट स्टाफ नियुक्त कर इन्हें मजकूर किया गया। वर्ष 1975-76 में आयुर्वेदिक पद्धति के अन्तर्गत 101 औषधालय खोलकर ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार किया गया।

जल वितरण योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1975-76 तक, शहरी क्षेत्रों में

बढ़ा कर क्रमशः 50 करोड़ रु. एवं 10 करोड़ रुपये कर दी गई है ताकि साहूकारों पर लगाए गए प्रतिबन्ध के फलस्वरूप ऋण सुविधा में ग्राह्यी कमी की पूर्ति हो सके।

खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा कर अतिरिक्त क्षेत्रों में 4.25 रुपये, पंचित क्षेत्रों में 5.00 रुपये एवं बृहत् नहरी परियोजना क्षेत्र में 6.00 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है तथा पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए समान मजदूरी निर्धारित की गई है।

नहरी एवं भूमिगत जल सिंचाई तथा पेय-जल हेतु सर्वेक्षण कार्य उत्साहपूर्वक किए गए। लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत दिसम्बर, 1975 के अन्त तक कुओं को खोदने तथा उन्हें गहरा करने के कार्य का गति प्रदान की गई व ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम चालू रहा।

शिक्षण संस्थाओं में गठित की गई 151 सहकारी समितियों के माध्यम से 1,204 छात्रावासों तथा किराए के मकानों में रह रहे 51,000 छात्रों को प्रति माह प्रति छात्र 8 किलोग्राम गेहूँ तथा एक किलोग्राम चीनी उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। अक्टूबर, 1975 से ग्रन्थास पुस्तिकाओं के मूल्य म 5 से 12 प्रतिशत की और कमी की गई है तथा 3,216 बुक बैंकों की स्थापना की गई, जिनमें 5 लाख 49 हजार पुस्तकें उपलब्ध हैं। राज्य सरकार द्वारा स्थापित छात्रावासों के लगभग 5,700 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को नि:शुल्क भोजन, वस्त्र एवं आवास की सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।

1,300 ट्रेड, 250 तकनीकी एवं 50 स्नातक प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न स्थानों पर लगाया गया तथा शेप डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों के सीधी भर्तियाँ या उच्च अध्ययन हेतु चले जाने के कारण रिक्त रहे।

अक्टूबर, 1975 में गठित हाथ-करघा परियोजना मण्डल ने भारत सरकार को 1.32 करोड़ रुपये की एक योजना प्रस्तुत की है। जनता कपड़े का वितरण 3,209 खुदरा दुकानों एवं 299 अधिकृत मिल दुकानों के माध्यम से सुलभ कराया गया।

कर-चोरी उन्मूलन अभियान के अन्तर्गत 14,000 प्रकरणों की जाँच की गई तथा 21 लाख रुपये दण्ड के रूप में वसूल किए गए। 8,000 रुपये की सीमा तक आय कर में छूट दी गई। विभिन्न आर्थिक अपराधों की शीघ्र सुनवाई तथा विशेष न्यायालय स्थापित करने हेतु राजस्व से सम्बन्धित विभिन्न अधिनियमों में संशोधन किया गया। मार्च, 1976 के अन्त तक सड़क परिवहन के लिए 250 राष्ट्रीय परमिट प्रदत्त कर दिए जाएँगे।

राज्य प्रशासन में सुधार लाने की दृष्टि से भ्रष्ट एवं अकर्मण्य कर्मचारियों को सेवा मुक्त करने की कार्यवाही की गई, जिससे 1,906 कर्मचारियों को सेवा मुक्त किया गया।

निर्धन व्यक्तियों को नि:शुल्क कानूनी सहायता एवं सलाह देने के लिए उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश व अन्य सदस्यों सहित कानूनी सहायता एवं सलाहका बोर्ड की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई है।

राज्य की वार्षिक योजना (1976-77)¹

योजना आयोग ने वर्ष 1976-77 की वार्षिक योजना का आकार 135 00 करोड़ रुपये निश्चिन किया है किन्तु आयोग द्वारा राज्य परिवहन निगम के आन्तरिक स्रोतों से उपलब्ध साधनों की तुलना में आर्थिक परिव्यय ही सम्मिलित करने के कारण योजना का आकार 138 19 करोड़ रुपये होगा। उक्त विसंगति की ओर योजना आयोग का ध्यान भी आकषित किया गया है।

जहाँ वर्ष 1971-72 में प्रति व्यक्ति योजना व्यय केवल 23 रुपये था, 1-3 72 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर वर्ष 1976-77 में यह व्यय दुगुने से भी अधिक बढ़कर 47 रुपये प्रति व्यक्ति होगा। इससे सकेत मिलता है कि विकास कार्यक्रमों पर राजस्थान किस गति से विनियोजन कर रहा है।

वार्षिक योजना के 138 19 करोड़ रुपये के परिव्यय का आवंटन इस प्रकार है—

	(करोड़ रुपये में)	
	परिव्यय	प्रतिशत
1 सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएँ	24 74	17 9
2 कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएँ	13 09	9 5
3 सहायता	1 26	0 9
4 उद्योग एवं खनिज	4 44	3 2
5 परिवहन एवं संचार	10 92	7 9
6 सिंचाई एवं विद्युत विकास	83 15	60 2
7 अन्य	0 59	0 4
योग	138 19	100 0

उक्त योजना व्यय की वित्तीय व्यवस्था निम्न स्रोतों से होगी—

	(करोड़ रुपये में)
1 केन्द्रीय सरकार से सहायता	49 57
2 अतिरिक्त साधनों से आय	33 52
3 साव्यंजनिक एवं वित्तीय प्रतिष्ठानों से ऋण	20 55
4 परिवहन निगम के उपलब्ध आन्तरिक स्रोत	1 73
	105 37
वार्षिक योजना में घाटा	- 32 82
योग	138 19

1 वित्त मन्त्री (राजस्थान) का बजट भाषण 1976-77

इस प्रकार 138 19 करोड़ रुपये की योजना व्यय की वित्तीय व्यवस्था में 32 28 करोड़ रुपये की कमी रह जाती है ।

वार्षिक योजना के अन्तर्गत 138 19 करोड़ रुपये के अतिरिक्त, सांस्थानिक वित्तीय एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न राज्य निगमों, मण्डलों, राज्य एजेंसियों, सहकारी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों द्वारा विकास की गतिविधियों में लगभग 116 00 करोड़ रुपये के व्यय का और वित्तियोजन करने का अनुमान है । इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष में केन्द्र संचालित स्कीमों पर 20 33 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है । इस प्रकार वर्ष 1976-77 में, सार्वजनिक-क्षेत्र में विकास पर होने वाला कुल परिव्यय 274 52 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है ।



भारी उद्योगों का विकास

औद्योगीकरण का पहला दौर आजादी के बाद तुरन्त ही शुरू हुआ। उसमें बिजली, इस्पात, रासायनिक खाद, अत्युमिनियम, सीमेन्ट तथा अर्थ-व्यवस्था के लिए अत्यन्त ही आवश्यक अन्य चीजों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया। यह सर्वथा स्वाभाविक है कि इन चीजों के उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें दुर्लभ विदेशी मुद्रा की बड़ी राशि खर्च करके विदेशों से पूँजीगत सामान मगाना पड़ा।

दूसरा दौर दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ शुरू हुआ, जब हमने आत्मनिर्भर औद्योगिक विकास के लिए पूँजीगत सामान का उत्पादन करने की कई योजनाएँ अपने हाथ में लीं। ऐसी योजनाओं के लिए बहुत अधिक पूँजी की आवश्यकता हुई, इनमें उत्पादन शुरू होने में भी काफी समय लगा और तुलनात्मक दृष्टि से, जहाँ तक मुनाफे का प्रश्न है, मुनाफा भी कम होने वाला था। इन सभी कारणों के अतिरिक्त, सरकार की नीति सार्वजनिक क्षेत्र को विकसित करने की थी, जिससे देश की अर्थ-व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। इसलिए, सरकारी क्षेत्र में कई बड़े-बड़े कारखाने लगाने की योजना तैयार की गई। आज भारत में भारी उद्योग के बड़े सरकारी कारखाने निम्नलिखित हैं—

सरकारी क्षेत्र के कारखाने

1. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड—थर्मल पावर, थर्मल व हाइड्रोइलैक्टिक सेटो, भारी रोटेटिंग मशीनों, बड़े आकार के ट्रान्सफार्मरों तथा स्विचगियर के निर्माण के लिए इसके कारखाने तिरुची, भोपाल हरिद्वार तथा रामचन्द्रपुर में हैं।

2 भारी इञ्जीनियरी निगम (हेवी इञ्जीनियरिंग कारपोरेशन)—भारी डलाई तथा गढ़ाई, इस्पात संयंत्रों के लिए संयंत्र तथा मशीनें, क्रैशर तथा ग्राइन्डर, बड़ी क्षमता वाले एक्सकेवेटर, ड्रिलिंग रिंग तथा भागी मशीनों के क्लपुर्ज बनाने के लिए निगम ने रांची में तीन कारखाने स्थापित किए हैं।

3 भार्द्वाज तथा समवर्गी मशीनरी निगम (भार्द्वाज एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन)—इस परियोजना के कारखाने दुर्गापुर में हैं और इन कारखानों में भूमिगत कोयला-खनन के काम में आने वाली मशीनें तथा बड़ा सामान उठाने धरने वाले उपकरणों का उत्पादन किया जा रहा है।

4. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स—क्रिस्म क्रिस्म के सामान्य तथा विशेष उपयोगों में आने वाले मशीनी औजारों, छापेखानों, ट्रैक्टरों तथा घड़ियों आदि के निर्माण के लिए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने बगलौर, हैदराबाद, कलामासरी, पिजौर तथा थ्रीनगर में कारखाने स्थापित किए हैं।

5. भारत हेवी प्लेट्स तथा वेल्ड्स—विशाखापटनम् स्थित यह कारखाना हेवी प्रेसरवेसलें, हीट एक्सचेंजर, एम्बर सेपरेशन यूनिटें तथा पाइपिंग बनाता है। ये उपकरण रसायन तथा परिष्करण उद्योगों जैसे उर्वरकों, तेल शोधक कारखानों तथा पेट्रोकेमिकल संयंत्रों के लिए बनाए जाते हैं।

6. त्रिवेणी स्ट्रक्चरस—इलाहाबाद के नजदीक नैनी में स्थित इस कारखाने में जटिल ढाँचों, पेनस्टाक (अवधारक नलों), दरवाजों तथा सामान्य प्रकार के भांडों का निर्माण होता है।

इसके साथ साथ सरकार के अन्य प्रयोक्ता मंत्रालयों के अन्तर्गत भारी उपकरण व संयंत्र बनाने के लिए कारखाने स्थापित करने की भी कार्यवाही की गई जैसे रेल मंत्रालय के अन्तर्गत इजिन व रेल के डिब्बे, जहाजरानी व परिवहन मंत्रालय के अन्तर्गत जहाज निर्माण के कारखाने तथा प्रतिरक्षा की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत अर्थ मूविंग तथा अन्य उपकरण।

निजी क्षेत्र

संयंत्र तथा मशीनों के विभिन्न उपकरण तथा पुर्जों का उत्पादन करने एवं बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया गया। सीमेंट चीनी, कागज, रसायन, औषधियों के निर्माण, कलपुर्जों, डीजल इंजन, पम्प, बिजली के मोटर, ट्रान्सफार्मर तथा स्विचगियर, माल गाड़ी के डिब्बे तथा रेल के अन्य उपकरण, ट्रेक्टर बस व ट्रक आदि यात्री कारें, स्कूटर, मोटर साइकिल, मोपेड तथा मोटर गाड़ियों के किस्म-किस्म के पाटपुर्जों, सूती तथा जूट मिलों में काम आने वाली मशीनें तथा वास्टिंग, फोर्जिंग, वाल बेयरिंग, पाइप तथा ट्यूबों जैसी संकड़ों किस्म की चीजों के उत्पादन के लिए औद्योगिक मशीनों की क्षमता को तेजी से बढ़ाया गया है।

क्षमता का उपयोग और तेजी से विकास तथा उपलब्धियाँ

क्षमता का उपयोग—भारी उद्योग विभाग का शुरू से ही यह प्रमुख उद्देश्य रहा है कि कारखानों की वर्तमान उत्पादन क्षमता से ही अथवा उसमें न्यूनतम बढ़ोतरी करके अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाए।

इसलिए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई कदम उठाए गए। मुख्य रूप से इसका अर्थ था कि सरकार इनके विनियमन की अपेक्षा इन कारखानों के विकास की ओर अधिक ध्यान दे तथा निर्णयों की प्रक्रिया में तेजी लाकर नीति सम्बन्धी निर्णयों की कार्यान्विति के लिए यथेष्ट सूचना पद्धति की व्यवस्था करे। उत्पादन एकांशों को, अपने कारखानों के उत्पादन में विविधता लाने तथा अपनी अधिकतम उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक अधिकार देना भी जरूरी था।

सरकार ने एक ओर उत्पादनकर्ताओं पर अपने-अपने कारखानों की व्यवस्था कुशलतापूर्वक करने तथा उत्पादन खर्च को घटाने के लिए दबाव डाला, दूसरी ओर मूल्य नियन्त्रण तथा वोनस के भुगतान तथा ऋण लेने सम्बन्धी नीतियों को व्यावहारिक तरीके से लागू किया गया। इससे उत्पादन में वृद्धि होने के साथ-साथ

लागत में कमी होगी और हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपना सामान सफलतापूर्वक बेच सकेंगे। इसके साथ-साथ सरकार का यह उद्देश्य रहा है कि उत्पादन के खर्च में कमी होने का फायदा समाज को मिले और मुनाफे की रकम व्यर्थ के कामों में नहीं लगाई जाकर उत्पादन को बढ़ाने व कारखानों को विस्तार देने के काम में लगाई जाए। सरकारी क्षेत्र के कारखानों की व्यवस्था विशेषज्ञों के हाथ में देने की ओर भी यथोचित ध्यान दिया गया। इसी के साथ अधिकारों के इस तरह प्रतिनिधायन एवं विकेन्द्रीकरण की ओर भी ध्यान दिया गया जिससे सभी स्तरों पर लोगों को प्रोत्साहन मिलने के साथ उन्हें यह भी महसूस हो कि उत्पादन में हम सभी सहभागी हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि विभाग ने प्रधान सम योजनाक का कार्य स्वयं सभाला तथा कारखानों के लिए कच्चे माल, पाटपुर्तों उपकरणों तथा वित्तीय सहायता की ही व्यवस्था नहीं की बल्कि कारखानों को दी जाने वाली सहायता और सरकार के अन्य मन्त्रालयों के निर्णय जल्द से जल्द करार कर कारखानों की मदद करने का भी काम शुरू किया।

सरकारी क्षेत्र की उपलब्धि—इस सबका परिणाम अत्यन्त ही सन्तोषप्रद रहा। सरकारी कारखानों में सन् 1971-72 में जहाँ 2 अरब 8 करोड़ रुपये मूल्य का उत्पादन हुआ था, वह सन् 1973-74 में प्रायः दुगुना 4 अरब 9 करोड़ रुपये मूल्य का हुआ तथा सन् 1974-75 में उत्पादन और बढ़कर 5 अरब 51 करोड़ रुपये का हुआ। इसी अवधि में सन् 1972-73 में सरकारी कारखानों की जहाँ 13 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था, सन् 1974-75 में इन कारखानों ने 31 करोड़ रुपये का लाभ हुआ और इस प्रकार इन कारखानों ने 44 करोड़ रुपये कमाए। अब इस प्रवृत्ति को बनाए रखने की पूरी आशा है।

इन कारखानों की उपलब्धियों से प्रोत्साहित होकर, विभाग ने अपने लक्ष्य बढ़ा दिए और 1975-76 में 7 अरब 25 करोड़ मूल्य का उत्पादन करने का लक्ष्य है। आपात् स्थिति के कारण अनुशासन तथा कर्तव्यनिष्ठा का अनुकूल वातावरण तैयार हो जाने के फलस्वरूप अब सरकारी क्षेत्र के कारखानों ने अप्रैल, 1975 के स्तर पर मूल्यों को स्थिर करने, अनुत्पादक खर्चों में दश प्रतिशत की कटौती करने तथा साथ में ली हुई योजनाओं की तत्परता तथा तेजी के साथ पूरा करने के साथ उत्पादन का लक्ष्य 7 अरब 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 8 अरब रुपये कर देने का निश्चय किया है।

उत्पादन में यह वृद्धि, यद्यपि कुछ कम मात्रा में, निजी क्षेत्र के कारखानों में भी हुई है। मशीन टूल्स, सूती मिलों की मशीनों, ट्रैक्टरों, स्कूटरों, मोटर साइकिलों तथा मोपेड, डीजल इंजनों तथा औद्योगिक मशीनों का उत्पादन काफी बढ़ा है। आत्मनिर्भरता की ओर

देश के आर्थिक विकास में भारी उद्योगों ने महत्वपूर्ण योगदान और सहायता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बिजली उत्पादन के 85 प्रतिशत उपकरणों का विदेशों में आयात किया जाना

था जबकि पाँचवी योजना में बिजली परियोजनाओं के 85 प्रतिशत उपकरण देशों में बनने लगेंगे। 15 प्रतिशत उपकरण भी, जो विदेशों से मंगाए जाएंगे, वे हैं, जिनके आर्डर पहले ही दिए जा चुके हैं। हमारी बिजली उत्पादन की कुल क्षमता 1974 में 13 लाख किलोवाट थी, जबकि सन् 1975 में हम एक वर्ष में ही लगभग 26 लाख किलोवाट अधिक बिजली उत्पादन करने में सफल हुए। साथ ही सन् 1973-74 के अन्त में बिजली उत्पादन की हमारी कुल क्षमता प्रायः 1 करोड़ 9 लाख किलोवाट थी, जो आशा है 1978-79 के अन्त तक 3 करोड़ 40 लाख किलोवाट हो जाएगी और यह सब प्रायः देश में बने उपकरणों से सम्भव होगा। 1947 में हमारे देश के गाँवों में बिजली नहीं थी। सन् 1973-74 में 1,48,000 गाँवों तक बिजली पहुँच गई तथा बिजली से चलने वाले पम्पों की संख्या 24,35,000 हो गई। प्रायः अतिरिक्त पूँजी निवेश के बिना तथा वर्तमान उत्पादन क्षमता का ही उपयोग करके हमारे सरकारी क्षेत्र के कारखाने, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने इन यन्त्रों (ड्रिलिंग रिगों) के उत्पादन का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। इसी प्रकार थोड़ी सी अतिरिक्त पूँजी लगाकर ड्रिलिंग प्लेटफार्मों का उत्पादन भी शुरू किया जाने वाला है।

इसी प्रकार हम अन्य उद्योगों में भी आत्म-निर्भरता की दिशा में बढ़ रहे हैं। अब हम अपनी सीमेन्ट तथा चीनी मिलों के कुछ प्रायः नगण्य पाटपुर्जों का छोड़कर सभी सयंत्रों तथा उपकरणों का निर्माण देश में कर रहे हैं। हमारे इन उद्योगों के कारखानों की उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि की गई है। सीमेन्ट के कारखानों की उत्पादन क्षमता 600 मी टन प्रतिदिन से बढ़कर 1,200 मी टन प्रतिदिन तथा चीनी उत्पादन के लिए गन्नों की पेराई की 600 मी टन प्रतिदिन की क्षमता को बढ़ाकर 1,250 मी. टन प्रतिदिन कर दी गई है। हमारी रेलगाड़ियों मालगाड़ियों तथा सड़क यातायात के सभी प्रकार के वाहनों का सामान अब देश में ही तैयार किया जा रहा है। इनमें सभी प्रकार के माल डिब्बे, यात्री डिब्बे, इंजन रेलें, स्लीपर, प्वाइंट, क्रासिंग, फास्नर तथा सिग्नलिंग उपकरण सम्मिलित हैं। अब हमारी सड़कों के निर्माण में स्वदेशी रोड रोलर्स तथा अन्य उपकरणों का प्रयोग हो रहा है तथा इन पर चलने वाले वाहन सभी इसी देश में निर्मित हैं।

कोयला, धातुकर्मों सयंत्र तथा मशीनरी—प्रौद्योगिकी की चुनौतियों के बावजूद, इस्पात कारखानों के लिए सयन और मशीनरी के उत्पादन तथा कोयले और अन्य खानों का तेजी से विकास हुआ है और हम प्रायः अपने ही प्रयासों से बोकारो इस्पात कारखाने की क्षमता 17 लाख से बढ़ाकर 47.5 लाख मी. टन तथा भिलाई कारखाने की क्षमता 25 लाख मी. टन से 40 लाख मी टन करने जा रहे हैं। सन् 1973-74 में 7 करोड़ 80 लाख मी टन कोयले के उत्पादन की तुलना में सन् 1978-79 में 13 करोड़ 50 लाख मी टन उत्पादन का लक्ष्य स्वदेशी उपकरणों पर ही निर्भर रहकर पूरा किया जाएगा, जिनका उत्पादन माइनिंग एण्ड अलायड मशीनरी कारपोरेशन तथा निजी क्षेत्र के कुछ कारखाने मिलजुल कर करेंगे।

पाट पुर्जे तथा सूती वस्त्र मशीनरी—हमारे विकासमान इजीनियरिंग तथा सूती वस्त्र उद्योगों की अधिकांश आवश्यकताएँ अथवा उनके आधुनिकीकरण तथा

पुनर्स्थापना के लिए पाटपुर्जे तथा उत्तराखण्ड तथा सूनी वस्त्र कारखानों के अधिकांश सयंत्र अब देश में ही उपलब्ध हैं। पिछले दो तीन वर्षों में इन दोनों उद्योगों में तेजी के साथ उत्पादन बढ़ा है। सन् 1972-73 में जहाँ 53 करोड़ रुपये मूल्य के पाट पुर्जों का निर्माण देश में हुआ था, सन् 1974-75 में यह उत्पादन बढ़कर 77 करोड़ रुपये का हुआ। जहाँ तक सूनी वस्त्र के कारखानों के लिए मशीनों का प्रश्न है, सन् 1972-73 में 31 करोड़ रुपये की मशीनें तैयार हुई जबकि 1974-75 में 81 करोड़ रुपये मूल्य की मशीनें तैयार हुईं।

रासायनिक तथा प्रक्रिया सयंत्र तथा मशीनरी—जहाँ तक रासायनिक उर्वरकों के लिए सयंत्र तथा मशीनों, रासायनिक सयंत्रों तथा शोध (तेल) कारखानों का सम्बन्ध है, हमारा प्रयास इनके लिए ऐसे उपकरणों का तेजी के साथ निर्माण करने का रहा है जो इन कारखानों के काम में सके और इस क्षेत्र में वास्तव में बड़ी तेजी के साथ प्रगति हुई है। पहली बार, सितम्बर, 1975 में बोकारो इस्पात कारखाने को 550 मी टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता का एक टनेज प्राक्सीजन सयंत्र तैयार करके दिया गया है। एक अन्य सरकारी कारखाना, भारत हेवी एलेट्स एण्ड वेंसेल्स सन् 1977 के अन्त तक पाँच ऐसे सयंत्र तैयार करके उनकी डिलीवरी दे देगा। रासायनिक उर्वरक सयंत्रों के लिए नाइट्रोजन वाश यूनिटों का उत्पादन शुरू किया जा चुका है और इनकी डिलीवरी जल्दी ही की जाने लगेगी।

भारी उद्योग तथा निर्यात—भारी इजिनियरिंग उपकरणों का उत्पादन तेजी के साथ बढ़ाने अत्याधुनिक उपकरणों का उत्पादन शुरू करने में तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में देश तेजी के साथ बढ़ रहा है। अब हम अपने उत्पादनों का विदेशों को निर्यात कर सकते हैं तथा दूसरे देशों के विकास में हाथ बँटा सकते हैं। ताम्र बिजली घर सयंत्रों के हिस्से के रूप में हमारे उच्च दाब वाले वाइलर मलेशिया तथा अन्य देशों में लगाए जा चुके हैं। कई एजिपाई व अफ्रीकी देशों में हमारे देश में बनी हुई बसें सड़कों पर चल रही हैं तथा सारे ससार के कई रेल-व्यवस्था में हमारी मालगाड़ियों तथा यात्री गाड़ियों का उपयोग किया जा रहा है। सोमेट, चीनी, छोटे इस्पात कारखानों, सूनी वस्त्रों के कारखानों तथा अन्य प्रकार की चीजों का उत्पादन करने वाले विभिन्न कारखानों के लिए हमने अपने सयंत्र तथा मशीनों का निर्यात विदेशों में किया है जिससे उनकी ग्रंथ व्यवस्था के विकास में सहायता मिली है। हमारे इजिनियर-परामर्शदाता ससार के विभिन्न भागों में फैले हुए देशों, जैसे चीनिया, सजानिया ईराक, ईरान, इण्डोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया तथा एशिया एव अफ्रीका के कई अन्य देशों में कारखाने लगाने की योजनाएँ तैयार करने तथा कारखाने स्थापित करने में लगे हुए हैं।

निजी क्षेत्र

जहाँ तक निजी क्षेत्र के कारखानों का प्रश्न है, इस बात में सुनिश्चित होना अनिवार्य था कि प्रमुख रूप से जनता के पैसों (वित्तीय सहायता तथा जनता से शेयर के रूप में प्राप्त) से जिस सम्पत्ति का निर्माण हुआ है, उसका उपयोग उन

Appendix—2

लघु उद्योगों का विकास

छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास 1966-75 के दशक में वस्तुन उत्प्रेक्षनीय है। यह विशेष रूप से रोजगार के अवसरों और छोटे कारखानों के उत्पादन के वित्तीय मूल्य से प्रकट होता है। निम्न आंकड़ों से पाठक को इस महान् उपलब्धि के बारे में पता चल जाएगा—

राज्यों के उद्योग निदेशालयों के साथ पंजीयित	1966	1974
कारखानों की संख्या (लाखों में)	1 20	4 09
रोजगार (लाखों में)	29 30	50 40
स्थिर विनियोग (करोड़ रुपये में)	548 00	814 00
उत्पादन का मूल्य (करोड़ रुपये में)	2,954 00	6 249 00

छोटे उद्योगों की इस प्रगति का कारण सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियाँ और विशेष कार्यक्रम हैं। छोटे पैमाने के उद्योगों में वस्तुओं की क्वालिटी में सुधार और उत्कृष्टता के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के निर्यात में उत्प्रेक्षनीय वृद्धि हुई है, विशेष रूप से इस दशक के अन्तिम भाग में, जबकि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य सन् 1970-71 में 119 करोड़ रुपये से बढ़कर सन् 1973-74 में 400 करोड़ रुपये हो गया। निर्यात की वस्तुओं में आधुनिक एव जटिल किस्म की वस्तुएँ काफी थीं, जैसे हल्का इंजीनियरिंग का सामान, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ, दवाइयाँ, तैयार चमड़ा और चमड़े का सामान, हीमरी, सिलाई की मशीनें, साइकिल इत्यादि। इसके अलावा अनुमान है कि छोटे पैमाने के कारखानों द्वारा ऐसी बहुत सी वस्तुएँ देश में तैयार की जा रही हैं जो पहले बाहर से मँगवाई जानी थीं। इस प्रकार बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत होती है।

यह बड़ी उत्प्रेक्षनीय बात है कि छोटे पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र में विकास, बड़े पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र में विकास का पूरक है। यह सम्बन्ध उप-उत्प्रेक्षकों के रूप में प्रकट होता है, जो दोनों क्षेत्रों के लिए लाभदायक है। सहायक कारखानों की संख्या सन् 1971 में 7,000 से बढ़कर सन् 1974 में 22,760 हो गई।

छोटे पैमाने के क्षत्र द्वारा जन-उपभोग की विभिन्न वस्तुओं की बड़ी मात्रा में पूर्ति की जाती है, जैसे चमड़ा और चमड़े का सामान, प्लास्टिक और रबड़ का सामान, रेडीमेड कपड़े, घातु की चादरो से बनने वाला सामान, स्टेशनरी की वस्तुएँ, साबुन और साफ करने के पाउडर, इत्यादि। इस दशक में छोटे पैमाने के क्षेत्र ने उत्पादन के नवीन और अधिक उत्कृष्ट क्षेत्रों में प्रवेश किया है जिनमें ग्रन्थ वस्तुओं के साथ-साथ टेलिविजन सेट, हृदय गति-नियामक (कार्डियक पेस मेकर), ई.सी.जी. मशीनें, श्रवण यन्त्र, टेप और केसैटी रिकार्डर, इन्टर काम सेट, माइक्रोवेव यन्त्र, मशीनी यन्त्र, औपधियाँ इत्यादि हैं। पाँचवी पंचवर्षीय योजना में उन वस्तुओं के विकास पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है, जो कृषि के साथ प्राधुनिकीकरण तथा कृषि उपज के विधायन के लिए आवश्यक हैं। इसके साथ-साथ जन-उपभोग की वस्तुओं, सहायक एकको में निर्मित वस्तुओं तथा निर्यात की दृष्टि से उपयोग की वस्तुओं पर भी विशेष बल दिया जा रहा है।

पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास

उद्योगों के छितराव सम्बन्धी सरकारी नीति के कारण गाँवों और पिछड़े हुए क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य न केवल वर्तमान कारीगरों की आय में वृद्धि और प्रतिरिक्त उत्पादक रोजगार के उद्देश्य से उनकी दक्षताओं में सुधार करना है बल्कि इन क्षेत्रों में प्राधुनिक उत्कृष्ट चोटि के उद्योगों का विकास भी है। केन्द्र-प्रायोजित योजना के रूप में, ग्रामोद्योग परियोजना कार्यक्रमों के शीर्षलेश द्वारा, नीति को एक निश्चित रूप प्रदान किया गया और इसके लिए राज्य सरकारों को शत-प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है। नव स्थापित कारखानों की सख्या और रोजगार के अवसरों के समुर्ध में उत्साहवर्द्धक परिणामों को दृष्टि में रखते हुए यह कार्यक्रम 1974 में 49 से 111 जिलों में फैला दिया गया। निम्न आँकड़े स्वयं अपनी प्रगति की कहानी कह रहे हैं—

मद	1965-66	1973-74
ग्रामोद्योग परियोजनाओं की सख्या	49	111
सहायता प्राप्त एकको की सख्या (सचयी)	7,886	48,206
रोजगार (सचयी)	48,775	2,07,136
उत्पादन का मूल्य (करोड़ रूपयों में)	32	7027

सन् 1974 में 87 परियोजनाओं में से 40 परियोजनाओं में, जहाँ दोनों कार्यक्रम चल रहे थे ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम का क्रिशान्वयन ग्रामोद्योग परियोजना कार्यक्रम के साथ मिला दिया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परम्परागत शिल्पों और प्राधुनिक व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे पम्प सेटों, बिजली की मोटरों की मरम्मत और ढलाई तथा खरीद आदि का काम इत्यादि। इसके बाद सहायता कार्यक्रम शुरू होता है, ताकि कारीगर अपने-अपने व्यवसायों में लाभदायक ढंग से रोजी कमा सकें।

विकास के अधिन न्यायसंगत ढाँचे की स्थापना की दृष्टि से सन् 1971 में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक सशक्त नीति अपनाई गई ताकि ये क्षेत्र भी विकसित क्षेत्रों की बराबरी कर सकें। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिए जाते हैं जिनमें औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए 244 जिलों में वित्तीय सहायता द्वारा रियायती दर पर वित्त उलान करना भी शामिल है। लगभग 104 चुने हुए जिलों में, नए कारखानों के स्थिर पूंजी विनियोग पर और वर्तमान कारखानों के विस्तार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 15 प्रतिशत सहायता दी जाती है। दुर्लभ और आयातित कच्चे माल की पूर्ति तथा किश्तों पर मशीनें खरीदने में भी रियायतें दी जाती हैं। इसके अलावा कुछ चुने हुए पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ रेल की सुविधाएँ नहीं हैं, कारखानों को कच्चे माल और निमित्त वस्तुओं के परिवहन व्यय का 50 प्रतिशत सहायता के रूप में दिया जाता है। 1974-75 में स्थिर विनियोग पर सहायता के रूप में 4 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, जबकि 1973-74 में यह राशि 56.90 लाख रुपये और 1972-73 में 11.76 लाख रुपये थी। 1974-75 वर्ष के लिए अनुमानित सहायता 9 करोड़ रुपये थी। यह पिछड़े हुए क्षेत्रों में औद्योगिक विकास का सूचक है। बहरहाल, इसमें छोटे सीमान्त और मध्यम उद्योगों को दी जाने वाली सहायता शामिल है।

विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम

छोटे उद्योगों के विकास के कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य कारखानों की इस दंग से सहायता करना है कि वे एकीकृत सहायता कार्यक्रम के माध्यम से क्षमता का अधिकतम स्तर प्राप्त कर सकें। इस एकीकृत सहायता कार्यक्रम में तकनीकी सेवाओं और सुविधाओं की अधिकाधिक उपलब्धि, प्रशिक्षण सम्बन्धी परामर्श और प्रशिक्षण, स्वदेश में माल की बिक्री और निर्यात में सहायता इत्यादि सम्मिलित हैं। लघु उद्योग विकास सगठन लगभग 100 लघु उद्योग सेवा संस्थानों, शाखा संस्थानों, प्रसार केन्द्रों और उत्पादन केन्द्रों के माध्यम से इस प्रकार की व्यापक सेवाओं की व्यवस्था करता है। तकनीकी सहायता के लिए छोटे उद्यमियों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए लघु उद्योग विकास सगठन ने अपनी तकनीकी सेवाओं को और अधिक बढ़ाया है। पिछले दस वर्षों के दौरान उद्यमियों को लगभग 5,000 मॉडल स्कीमों, सयंत्र, मार्गदर्शिकाओं, परियोजना मार्गदर्शिकाओं तथा अन्य स्कीमों आदि के अलावा 1,25,000 डिजाइन, ड्राइंग और खाके दिए गए। औद्योगिक विकास सगठन द्वारा प्रदत्त तकनीकी सेवाओं की लोकप्रियता का प्रमाण यह है कि सगठन के तकनीकी अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले उद्यमियों की संख्या सन् 1965-66 में 57,000 से बढ़कर सन् 1974-75 में 1,30,000 हो गई। इसके अलावा तकनीकी अधिकारियों ने एक वर्ष में औसतन लगभग 70,000 कारखानों का उनके स्थान पर जाकर मार्गदर्शन करने के लिए निरीक्षण किया। उद्यमियों ने लघु उद्योग विकास सगठन द्वारा प्रदत्त वर्कशॉप सुविधाओं से भी व्यापक पैमाने पर लाभ उठाया। लघु उद्योग सेवा संस्थानों की वर्कशॉपों द्वारा किए गए कार्यों की

वापिक सख्या सन् 1965-66 में 21,000 से बढकर सन् 1974-75 में लगभग 50,000 हो गई।

तेजो से बढने और विविधता लिए हुए लघु उद्योग क्षेत्र की नई आवश्यकताओं को पूरने के लिए लघु उद्योग विकास सगठन ने अपनी तकनीकी सेवाओं को सरल बनाने एवं सुधारने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए। नई मशीन और उत्कृष्ट सेवाओं के समावेश, चार क्षेत्रीय परीक्षा-केन्द्रों की स्थापना और चुने हुए उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए एक विशेष कार्यक्रम के संचालन द्वारा लघु उद्योग सेवा संस्थानों के साथ सलग्न वर्कशॉप्स का आधुनिकीकरण, इनमें सम्मिलित था। छोटे पैमाने के उद्योगों की प्रतियोगी शक्ति के विकास को दृष्टि में रखते हुए इस कार्यक्रम के अंगों में, प्राथमिकता के आधार पर कुछ चुने हुए उद्योगों को मशीन, वित्त, कच्चा माल, प्रशिक्षण तथा तकनीकी प्रबन्ध सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। पाँचवी योजना-अवधि में 40 प्रकार के उद्योगों के लगभग 40,000 कारखानों को सेवाएँ उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

नई वस्तुओं के उत्पादन या वर्तमान औद्योगिक कारखानों के विस्तार के लिए अनेक उद्यमियों, कारीगरों, तकनीकी विशेषज्ञों और दूसरे निवेशकर्ताओं को लघु उद्योग विकास सगठन द्वारा सम्पादित उद्योगवार और क्षेत्रवार सर्वेक्षणों के आधार पर विस्तृत आर्थिक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। औसतन, लगभग 80,000 छोटे उद्यमी प्रति वर्ष इन सेवाओं से लाभ उठाते हैं।

लघु उद्योग प्रसार प्रशिक्षण संस्थान ने प्रबन्ध विकास, वित्तीय प्रबन्ध, बिक्री सहायक एकाई के विकास और क्षेत्रीय विकास इत्यादि के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करने की दृष्टि से अपनी गतिविधियों को कई गुना बढा दिया है। संस्थान ने कई विकासशील देशों के प्रशिक्षणार्थियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम भी आयोजित किए हैं।

छोटे पैमाने के क्षेत्र के लिए आयातित और स्थानीय कच्चा माल अधिकतम मात्रा में उपलब्ध कराने की दृष्टि से लघु उद्योग विकास सगठन ने सम्बद्ध मन्त्रालयों और दूसरे सगठनों से घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित किया है। दुर्लभ कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने तथा स्थानीय और दुर्लभ कच्चा माल प्रयोग करने वाले कुछ उद्योग समूहों की आवश्यकताओं का ठीक ठाक आकलन करने की दृष्टि से लघु उद्योग विकास सगठन ने बैज्ञानिक आधार पर औद्योगिक कारखानों की क्षमता का आकलन शुरू किया है।

जुलाई, 1969 में प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप छोटे एकाई को काफी बड़ी मात्रा में ऋण दिए गए। दूसरे जो कदम उठाए गए, उनमें छोटे उद्योगों के लिए बैंकों से ऋण लेने की प्रक्रिया को सरल बनाना, पिछड़े क्षेत्रों में कारखानों तथा इन्जीनियरिंग के स्नातकों के लिए उदार योजनाएँ इत्यादि हैं।

बढता क्षितिज

गत दशक में सरकार के लघु उद्योग कार्यक्रम का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है। हाल के वर्षों में छोटे पैमाने के क्षेत्र के विकास में सहायता की दृष्टि से बहुत सी नई योजनाएँ बनाई गई हैं।

सहायक कार्यक्रम के रूप में, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने किस्तों में लगीद के आधार पर छोटे पैमाने के कारखानों की आधुनिकतम सयन और मशीनें उपलब्ध कराने में सहायता दी। लगभग 15,000 कारखानों को 80 करोड़ रुपये की 30,000 आधुनिक मशीनें अब तक उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। इस योजना का एक मुख्य पहलू यह है कि छोटे पैमाने के कारखानों द्वारा अपेक्षित, स्थानीय और आयातित दोनों प्रकार की मशीनें, आमतान किस्तों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। यदि बहुत सस्ती से भी अम्दाजा लगाया जाए तो भी किस्तों में सरीद पद्धति के अन्तर्गत 600 करोड़ रुपये से अधिक की मशीनें लगाई गई हैं और 4 लाख लोगों को रोजगार मिला है।

लघु उद्योग विकास कार्यक्रम का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू फैक्टरियों के लिए स्थान की व्यवस्था, सामान्य सेवा सुविधाओं और अन्य विशिष्ट सेवाओं की व्यवस्था करके छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से औद्योगिक वस्तियों की स्थापना है। कुल मिलाकर 612 औद्योगिक वस्तियाँ आयोजित की गई हैं जिनमें से 455 ने मार्च, 1974 तक काम करना शुरू कर दिया था और इनमें 10,139 फैक्टरियाँ स्थापित हो चुकी थीं।

तुलनात्मक चित्र नीचे प्रस्तुत है—

	मार्च 1964 तक	मार्च 1974 तक
उन औद्योगिक वस्तियों की संख्या जो पूरी बन चुकी हैं	181	499
निर्माण शेड	4,303	13,351
जिन शेडों में काम चालू है	2,635	9,465
रोजगार में लगे व्यक्तियों की संख्या	29,227	1,75,700
वार्षिक उत्पादन	28 करोड़ रु	352 करोड़ रु.

पिछले दशक में छोटे पैमाने के उद्योगों के आनन्दार विकास का दृष्टि में रखते हुए कई विकासशील देश अपने-अपने देशों में छोटे पैमाने के उद्योगों के समर्थन और आयोजित विकास में सहायता के लिए हमसे प्रार्थना कर रहे हैं।

छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के जरिए विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनेक सख्यों की प्राप्ति की दृष्टि में रखते हुए, योजनाओं के अन्तर्गत इस क्षेत्र के लिए निर्धारित धनराशि में जो उत्तेजनीय वृद्धि हुई है वह अप्रामाणिक तालिका से स्पष्ट है—

व्यय (करोड़ रुपये में)

पहली योजना	5 20
दूसरी योजना	56 00
तीसरी योजना	113 06
वार्षिक योजनाएँ (1966-69)	53 48
चौथी योजना	96 76
पाँचवी योजना (परिचय)	287 23

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में छोटे पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी धनराशि निर्धारित की गई है। पाँचवी योजना का एक उल्लेखनीय पहलू यह है कि इस योजना के लिए स्वीकृत कुल धनराशि का लगभग 60 प्रतिशत पिछड़े हुए और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए है।

पिछले दशक में लघु उद्योगों के विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा है कि इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया है और देश भर में फैले हुए बटुसहक उद्यमियों में भात्म विश्वास की भावना पैदा की है। संस्थागत सहायता के साथ-साथ इस क्षेत्र की अन्तर्निहित गतिशीलता ने इसे राष्ट्र के आर्थिक विकास में प्रचुर मात्रा में योगदान करने योग्य बनाया है।

ग्राम और लघु उद्योग उत्पादन में वृद्धि (1975-77)

सूती हाथकरघा और विद्युत् करघा हस्त का उत्पादन 1976-77 के दौरान 420 करोड़ मीटर और सूती हाथकरघा वस्त्र और उत्पादन के लगभग 107 करोड़ रुपये मूल्य के होने की आशा है। चालू वर्ष के दौरान 37 लाख 7 हजार विलोयाम कच्चे रेशम के अतिरिक्त लगभग 53 लाख रुपये मूल्य की 6 करोड़ 2 लाख मीटर खादी के उत्पादन की आशा है। रेशमी वस्त्र और उच्छिष्ट के 15 करोड़ 50 लाख रुपये मूल्य के और नारियल तूट उत्पादन के लगभग 18 करोड़ 50 लाख रुपये मूल्य के 40 हजार टन के निर्यात किए जाने की सम्भावना है। इसी अवधि के दौरान ग्राम उद्योगों के उत्पादन के 173 करोड़ रुपये मूल्य के और हस्त-शिल्प के लगभग 201 करोड़ रुपये मूल्य के निर्यात किए जाने का अनुमान है।

1976 77 के दौरान विभिन्न लघु उद्योगों के विकास के कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू योजनाओं विशेष रूप से हाथकरघा उद्योग और गलीचा बुनने में प्रशिक्षण तथा हिस्म सुधार, आवश्यक सामान्य सेवा सुविधाओं के अन्य कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। केन्द्रीय लघु उद्योग विकास समिती द्वारा अपनी सेवा संस्थाओं और विस्तार केन्द्रों के माध्यम से चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। अधिकांश राज्य सरकारों ने चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों में उद्यमियों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की है।

सार्वजनिक क्षेत्र में विभिन्न लघु उद्योगों के लिए 1976-77 के लिए 95 करोड़ 2 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है। इसमें से केन्द्र के लिए 51 करोड़ 68 लाख रुपये और राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए 43 करोड़ 34 लाख रुपये का प्रावधान है। लघु उद्योगों के लिए 1976-77 की अवधि के लिए केन्द्रीय प्रावधान 11 लाख 30 हजार रुपये का और खादी तथा ग्राम उद्योगों के लिए 25 करोड़ 20 लाख रुपये का है। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजनाओं के लिए व्यय भी शामिल है। इन प्रावधानों के अतिरिक्त पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ साधन उपलब्ध किए जाएंगे। कुछ लोग अपने साधनों से भी धन जुटाएंगे।

सूती, ऊनी और रेशमी खादी वस्त्र में उन्नत डिजाइन अपनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण उद्योगों के विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के अन्तर्गत धान से चावल निकालने और उन्हें पालिश करने के लिए विद्युत् चालित उपकरणों का अपनाया जाना, विद्युत् चालित धानियों की अधिक संख्या में सप्लाई, मधुमक्खी पालन का विस्तार, ग्राम कुम्हारी का परम्परागत वस्तुओं में भवन-निर्माण सामग्रियों के उत्पादन में बदला जाना आदि शामिल हैं।

हाथकरघा उद्योग का नवीनीकरण और विकास आरम्भ किया जाएगा। यह हाथकरघा उद्योग सम्बन्धी उच्च अधिकार प्राप्त अध्ययन दल की सिफारिशों पर आधारित होगा। इसमें 13 प्रोत्साहन विकास और 20 निर्यातानुसृत उत्पादन परियोजनाओं की योजनाएँ, हाथकरघा का आधुनिकीकरण, सशोधन सुविधाएँ, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को आर्थिक सहायता और शीप सोसायटियों एवं राज्य हाथकरघा विकास निगमों का सशस्त्रीकरण शामिल है।

केन्द्र द्वारा ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं की योजना की प्रगति पर विचार किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास

भारत अपने लाखों गाँवों में रहता है। देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर करती है और देश की लगभग आधी राष्ट्रीय आय कृषि से प्राप्त होती है। स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर काफी जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में भी इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

ग्रामीण विकास के लिए अनेक दिशाओं से प्रयत्न करने की जरूरत है। ग्रामीण विकास के किसी कार्यक्रम में भूमि और पानी जैसे प्रकृतिक साधनों के विकास और संरक्षण एवं ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधार पर विशेष जोर दिया जाता है। इस दूसरे कार्य को पूरा करने के लिए कृषि और मिर्चाई मन्त्रालय में अक्टूबर, 1974 में ग्रामीण विकास का एक नया विभाग बनाया गया। इस विभाग को पुर्णतः सामुदायिक विकास विभाग और कृषि ऋण, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्जदारी की मर्यादा और कृषि क्षेत्र में सहकारियों का कार्य सौंपा गया। इस विभाग की मुख्य जिम्मेदारियों में ये विषय शामिल हैं—

- (क) सामुदायिक विकास और पंचायती राज सहित ग्रामीण विकास के सभी पहलू।
- (ख) समाज के दुर्बल वर्गों जैसे छोटे और सीमान्त (नाममात्र के) किसानों की भलाई सूखा पड़ने वाले, जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों का विकास और ग्रामीण जनशक्ति का आयोजन और रोजगार।
- (ग) कृषि ऋण और बिक्री, जिसमें किस्म नियन्त्रण (एगमार्क) और विनियमित मण्डियों का विकास शामिल है।

सामुदायिक विकास और पंचायती राज

सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसे अब ग्रामीण विकास के समन्वित कार्यक्रम में बदला जा रहा है, 2 अक्टूबर, 1952 को शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण जनता के साधनों और सांस्कृतिक एवं आर्थिक पहलुओं को देखते हुए गाँवों का समग्र विकास करना है। इस समय देश में 5,123 सामुदायिक विकास खण्ड हैं। प्रत्येक खण्ड में दो सक्रिय स्टेजों में काम होता है, अर्थात् स्टेज I और स्टेज II। एक विकास खण्ड 5 वर्ष तक स्टेज I में रहता है और इसके बाद दूसरे पाँच वर्ष के लिए स्टेज II खण्ड हो जाता है। पाँचवी योजना में सभी राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों के लिए सामुदायिक विकास और पंचायती राज के प्रन्तर्गत

129 80 करोड़ रुपये की राशि मन्त्र की गई है। 1975-76 के लिए 13 65 करोड़ रुपये का खर्च मन्त्र किया गया है।

तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अब स्थानीय प्रशासन की विकास व्यवस्था के नमूने के रूप में स्वीकार की जा चुकी है। 15 राज्यों में अर्थात् ग्राम्य प्रदेश, प्रथम बिहार (केवल 8 जिलों में), गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इस तरह की व्यवस्था पहले ही लागू की जा चुकी है तथापि जम्मू कश्मीर केरल, मणिपुर और त्रिपुरा में केवल गाँव पंचायतें कार्य कर रही हैं। नागालैण्ड और मेघालय में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, लेकिन नागालैण्ड में क्षेत्र, रेंज और जन जातीय परिषदें हैं। केन्द्रशासित क्षेत्र मण्डलान तथा निकोबार द्वीपसमूह, दिल्ली और गोवा, दमन और दीव में केवल ग्राम पंचायतें कार्य कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़ तथा नागर हवेली में क्रमशः तीन और दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। पाण्डिचेरी में 'ग्राम और कम्प्यूत पंचायती अधिनियम' की कुछ व्यवस्थाएँ लागू होने के बाद, वहाँ पहली बार पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई है। वहाँ वर्तमान म्यूनिसिपल कम्प्यूनों को अन्तरिम व्यवस्था के रूप में कम्प्यूत पंचायतें परिष्कृत बना दिया गया है।

इस समय देश में 2,19 892 गाँव पंचायतें हैं। इनके अन्तर्गत 5,44,355 गाँव और 40 68 करोड़ जनसंख्या है। इसके अलावा देश में 3,863 पंचायत समितियाँ और 201 जिला परिषदें भी कार्य कर रही हैं।

प्रशिक्षण

यह अनुमान लगाया गया है कि ग्रामीण विकास के कार्यक्रम में लगे हुए 25 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। देश में ग्रामीण विकास के कार्यों में लगे विभिन्न वर्ग के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए 200 से अधिक प्रशिक्षण केन्द्र हैं। इसके अलावा हैदराबाद में सामुदायिक विकास का राष्ट्रीय संस्थान है जो 9 जून, 1958 को मसूरी में स्थापित किया गया था। यह संस्थान सामुदायिक विकास और पंचायती राज विचारधारा और उद्देश्यों को नई दिशा और प्रशिक्षण देने वाली शीर्ष संस्था के रूप में बताया गया है। यहाँ सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के प्रमुख सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाता है, व्यावहारिक समाज विज्ञान में अध्ययन एवं अनुमान के कार्यक्रम हाथ में लिए जाते हैं जिनमें सामुदायिक विकास द्वारा नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर जोर दिया जाता है, प्रशिक्षण केन्द्रों के कर्मचारियों का शैक्षिक मार्गदर्शन किया जाता है और यह संस्थान सामुदायिक विकास और पंचायती राज सम्बन्धी सूचना देने के केन्द्र के रूप में भी कार्य करता है। यहाँ राज्य सरकारों को सलाह-सेवा देने का कार्य भी किया जाता है।

स्वेच्छिक कार्यों को प्रोत्साहन

पाँचवी योजना में एक नई स्कीम 'स्वेच्छिक कार्यों को प्रोत्साहन' कार्यान्वित करने के लिए शामिल की गई है। इस योजना के लिए 1 78 करोड़ रुपये खर्च की

व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम के अधीन विभिन्न प्रकार के सहयोगी संगठनों का बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ग में 25 एंजनों जैसे आदर्श माठों का विकास ग्रामीण स्वेच्छिक माठों की रजिस्ट्रेशन की सरल व्यवस्था, उनको निश्चित कार्य हाथ में लेने के लिए सहयोग देना, रख रखाव प्रनुदान का विवरण और प्रयोगात्मक आधार पर सहयोगी संगठनों का सघ बनाना, एवं इसी तरह के अन्य कार्य।

दुर्गल वर्गों के लिए कार्यक्रम

छोटे किसानों के विकास की एंजनी एवं सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों के विकास की एंजनी—सरकार ने चौथी योजना के दौरान समय के दुर्गल वर्गों के जिनमें छोटे और सीमान्त किसान प्रमुख हैं फायदे के लिए दो नई स्कीम—छोटे किसानों के विकास की एंजनी और सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों के विकास की एंजनी शुरू की। इन एंजनीयों के प्रमुख कार्य हैं—समाज के ऐसे दुर्गल वर्गों का पता लगाना, उनकी समस्याओं का अध्ययन करना, उनके विकास की उपयुक्त योजनाएं तैयार करना, उन्हें सहायता दिलाना या प्रबंध करना, विस्तार सेवाओं की व्यवस्था करना और इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए पर्यवेक्षण की व्यवस्था करना। पिछले तीन चार वर्षों से 87 परियोजनाएँ—46 छोटे किसानों के विकास की एंजनीयों और 41 सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों की एंजनीयाँ काम कर रही हैं। आशा है कि 1975-76 तक पाँच वर्ष की अवधि में प्रत्येक छोटे किसानों की एंजनी 50 000 छोटे किसानों और प्रत्येक सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों के विकास की एंजनी 20 000 सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों की सेवा करने लगेगी।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अधीन छोटे किसानों के विकास की एंजनीयाँ सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों के विकास की एंजनीयों की कुल संख्या बढ़ाकर 160 की जा रही है और इनके लिए अस्थायी रूप से योजना खर्च के रूप में 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए दोनों कार्यक्रमों—छोटे किसानों के विकास की एंजनी सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों के विकास की एंजनी—का अन्तर समाप्त कर दिया गया है और छोटे एवं सीमान्त किसानों तथा कृषि मजदूरों की सहायता के लिए निश्चित क्षेत्रों में कार्य करने का दृष्टिकोण अपनाया गया है। अब किसी क्षेत्र के समन्वित विकास पर जोर दिया जाता है और कार्यक्रम में भी खेती, पशु-पालन और इनको बढ़ावा देने वाले अन्य कार्यक्रमों जैसे छोटी सिंचाई, भूमि का विकास, पशु पालन, डेरी उद्योग, मुर्गी पालन, सूअर पालन और भेड़ पालन—के विकास को अधिक महत्व दिया जाता है।

जन-जातीय विकास के लिए आज़माइशी परियोजनाएँ—1970-71 में जन जातीय विकास खण्डों के अलावा आन्ध्रप्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 6 जिलों में 5 वर्ष के लिए आज़माइशी परियोजनाएँ शुरू करने का निर्णय किया गया। जून, 1975 के अन्त तक इन जन जातीय विकास एंजनीयों को प्रनुदान के

रु० में 690 करोड़ रुपये दिए जा चुके थे। पाँचवी योजना में उड़ीसा में दो और परियोजनाएँ मंजूर की गई हैं। सरी 8 परियोजनाओं में पाँचवी योजना में इस कार्यक्रम के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जन-जातीय विकास की एजेंसी ने 1975 तक 1,88,000 जन-जातीय लोगों का पता लगाया है, जिनमें से लगभग 1,43,000 लोगों को आर्थिक कार्यक्रमों के अधीन लाभ पहुँचाया गया है। लगभग 2,009 लाख एकर भूमि को सुधरी हुई खेती की विधियों के अधीन लाया गया है। इस आर्थिक कार्यक्रम की नई सम्पत्तियों और प्रमुख सड़कों के निर्माण कार्यक्रम द्वारा बढ़ाया जा रहा है।

व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम—व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम, जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, खाद्य और कृषि संगठन और विश्व संगठन जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। ग्रामीण जनता की सुधरे किस्म के पोषक भोजन से परिचित कराने का कार्यक्रम है। यह एक शिक्षा और उत्पादन बढ़ाने वाला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में पाँच वर्ष की उम्र से कम के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बच्चे वाली माताओं के लिए पोषित आहार की व्यवस्था करने पर विशेष जोर दिया गया है। युवक और महिला मण्डलों को पोषित आहार तैयार करने के कार्यक्रम में सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है।

इस कार्यक्रम के अधीन 1973-74 के अन्त तक 1,181 विवास खण्ड लाए जा चुके थे। पाँचवी योजना में व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम 700 नए विवास खण्डों में शुरू किया जाएगा।

सूखा पीडित क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम—देश के 13 राज्यों में 74 ऐसे जिलों का पता लगाया गया है, जो या तो पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से सूखे से पीड़ित रहते हैं। इनमें 6 करोड़ जनसंख्या रहती है। राजस्थान में लगभग 56% भौगोलिक क्षेत्र, जिनमें 33% जनसंख्या रहती है, और आन्ध्र प्रदेश में 33% भौगोलिक क्षेत्र, जिसमें 22% जनसंख्या रहती है, सूखा पीड़ित है। सूखा पीड़ित क्षेत्र कार्यक्रम 1970-71 में इन जिलों में 100 करोड़ रु. की लागत से शुरू किया गया था। उद्देश्य यह था कि इन जिलों में सिंचाई, भूमि-संरक्षण, वन लगाने और सड़क निर्माण का कार्यक्रम शुरू किया जाए, जिससे और विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा मिले। पाँचवी योजना में सूखा पीड़ित क्षेत्र कार्यक्रम के अधीन कृषि और सम्बन्धित क्षेत्रों के समन्वित ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया है। आशा है इन कार्यक्रमों से लगभग 70 लाख छोटे और सीमान्त किसान परिवारों को लाभ होगा। कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में भी किसानों के लाभ की अनेक योजनाओं को कार्यान्वित किया जाएगा।

ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजना—क्षेत्र विशेष के समन्वित विकास के लिए वहाँ लाभप्रद रोजगार के अवसर बढ़ाने और आर्थिक विकास के लाभों का समान वंटवारा करने के लगातार प्रयत्न आवश्यक हैं। 1971-72 में ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार लोगों की तत्काल सहायता पहुँचाने के लिए ग्रामीण रोजगार की त्वरित

योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले में प्रतिवर्ष 1,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा करना है। देश के 350 ग्रामीण जिलों में प्रतिवर्ष कुल मिलाकर 875 लाख जन-दिवसों के बराबर रोजगार पैदा किया जाएगा।

ग्राममाइशी सघन ग्रामीण रोजगार परियोजना—ग्राममाइशी सघन ग्रामीण रोजगार परियोजना 1972-73 में शुरू की गई और अभी जारी है। इस परियोजना का उद्देश्य बेरोजगारी की समस्या की व्यापकता, विस्तार और स्थिति एवं इसे हल करने की सम्भावित लागत का पता लगाना है। बुनियादी रूप से यह एक अनुसन्धान और त्रियान्वयन परियोजना है और देश के 15 चुने हुए विकास खण्डों में, जिनकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति सम्बन्धी अवस्था अलग-अलग है, लागू की जा रही है। इस परियोजना का अन्तिम उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगार और अर्द्ध-रोजगारी की समस्या को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका खोजना है।

कृषि ऋण और बिजली—रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने 1960 के आसपास ग्रामीण ऋण की समस्या का अध्ययन करने के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की स्थापना की थी। इस समिति ने सिफारिश की कि सहकारी आन्दोलन को मजबूत बनाया जाना चाहिए ताकि कृषि का समन्वित विकास हो सके। तब से यह आन्दोलन विभिन्न क्षेत्रों में फैल गया है जैसे कृषि उत्पादन, छोटी सिंचाई, खाद, बीज, उर्वरक और अन्य पदार्थों का वितरण एवं सप्लाई तथा किसानों के लिए तकनीकी और अन्य सेवाओं की व्यवस्था। पिछले कुछ वर्षों में कृषि ऋण नीति को उदार बना दिया गया है। हाल ही में जो नवीनतम कदम उठाया गया है वह है अनेक राज्यों द्वारा ग्रामीण ऋणों की समाप्ति के लिए की गई कार्यवाही, जो 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में एक प्रमुख सूत्र है। इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा ऋण देने की अन्य व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। अब तक सहकारियाँ कृषि ऋण के लिए प्रमुख सहायक स्रोत हैं। सरकार न किसानों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की एक नई योजना भी शुरू की है। इन बैंकों का कार्य वाणिज्यिक बैंकों से अलग है। यह बैंक विशेष रूप से छोटे और सीमान्त किसानों, कृषि मजदूरों, ग्रामीण दस्तकारों, छोटे उद्यमियों और व्यापार एवं अन्य उत्पादक कार्यों में लगे समान हैसियत के लोगों को ऋण और पेशगियाँ देते हैं। शुरू में 2 अक्टूबर, 1975 को ऐसे 5 बैंक उत्तरप्रदेश में मुरादाबाद और गोरखपुर, हरियाणा में भिवानी, राजस्थान में जयपुर (लवाण) और पश्चिम बंगाल में मालदा में स्थापित किए गए। 1975 के अन्त तक अन्य केन्द्रों में 10 और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए जाने थे। 1969 में 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद इन बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिया जाने वाला ऋण जो 1969 में 40.21 करोड़ रु था, 1974 के अन्त में बढ़कर लगभग 540 करोड़ रुपये हो गया। राष्ट्रीय कृषि आयोग किसानों की सेवा समितियाँ भी ग्राममाइशी आघार पर संगठित की जा रही हैं। ये समितियाँ किसानों को समन्वित ऋण, बीज, खाद, उर्वरक और अन्य सेवाएँ उपलब्ध कराएँगी।

कृषि पुनर्वित्त निगम—इस निगम की गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में पूँजी निवेश की गति को बढ़ाना और इसके उद्देश्यों में विविधता लाना है, ताकि विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अधिक न्यायपूर्ण पूँजी-निवेश किया जा सके।

कृषि उपज की बिक्री—पिछड़े क्षेत्रों की चुनी हुई विनियमित मण्डियों को ऋण देने की योजना चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। पाँचवी योजना के अधीन 'कमाण्ड' क्षेत्रों में स्थित और विशेष किस्म की व्यापारिक फसलों, जैसे जपास, पटसन और तम्बाकू की मण्डियों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को अपनी उपज की किस्म के अनुसार दाम मिलें, कृषि उपज (वर्गीकरण और बिक्री) अधिनियम के अधीन वर्गीकरण शुरू किया गया। एगमार्क के अधीन वर्गीकरण के मानकों का स्तर बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक परीक्षणों की अधिक प्रयोगशालाएँ बनाई जा रही हैं।

ग्राम ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। ग्रामीण जनता की दशा सुधारने के लिए नई सड़कें बनाई जा रही हैं, नए स्कूल खोले जा रहे हैं, नई सहकारी समितियाँ स्थापित की जा रही हैं। लेकिन इन लाभजनक उपलब्धियों के अलावा एक बात और है, जो अधिक महत्वपूर्ण है यद्यपि उसकी माप तोल नहीं की जा सकती है और वह है लोगों की भावनाओं में महान् परिवर्तन। लोगों के विचारों और कार्यों में अकर्मण्यता समाप्त हो गई है। लोग मिल-जुल कर राष्ट्रीय कार्य कर रहे हैं और राष्ट्र निर्माण के इस महान् कार्य में साभोदारी की भावना स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है।¹

सिंचाई का विकास

हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई को सदैव महत्व दिया गया है लेकिन बार-बार सूखा और अकाल पड़ने से सिंचाई के विकास की गति में वृद्धि करने की ओर विशेष ध्यान केन्द्रित हुआ। प्रत्येक तीसरी योजना के बाद से 1966 में, इन प्रयासों को बढ़ाया गया। सिंचाई योजना-कार्य तीन वर्गों, बड़े (5 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले), मध्यम (मैदानी इलाकों में 25 लाख रु. से लेकर 5 करोड़ रु. तक की लागत वाले और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 लाख रु. से लेकर 5 करोड़ रु. की लागत वाले) तथा छोटे (मैदानी इलाकों में 25 लाख रु. से कम लागत वाले तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 30 लाख रु. से कम लागत वाले) में विभाजित किए गए हैं। अनुमान है कि बड़ी तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं की प्रतिशत क्षमता 5 करोड़ 70 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई करने की है, परन्तु 1974-75 तक हमने 2 करोड़ 18 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई करने की क्षमता ही अब तक पैदा की है।

पहली तीन योजनाओं में अर्थात् 1951 में लेकर 1966 तक लगभग 500 बड़े और मध्यम दर्जे के योजना कार्यों को क्रियान्वयन के लिए हाथ में लिया गया। चौथी योजना में, जो 1969 को शुरू हुई, 60 बड़े और 157 मध्यम दर्जे के, योजना कार्यों पर काम जारी रहा और 18 बड़े तथा 59 मध्यम दर्जे के योजना कार्यों को मंजूरी दी गई। पहले के खर्चों के अनुमानों में वृद्धि होने के कारण 3 मध्यम दर्जे के योजना कार्यों को बड़े योजना-कार्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया। इस प्रकार चौथी योजना के दौरान 81 बड़े और 213 मध्यम दर्जे के, सिंचाई योजना कार्यों पर काम चल रहा था। इनमें से 6 बड़ी और 58 मध्यम दर्जे की योजनाओं पर काम पूरा किया गया। इस प्रकार पाँचवी योजना में 75 बड़ी तथा 155 मध्यम दर्जे की योजनाओं पर काम अभी चल रहा है।

1966 के बाद से अब तक की हुई प्रगति विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि इस अवधि में पैदा की गई 52 लाख हेक्टर भूमि की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सुनियोजित विकास के पहले के 15 वर्षों में पैदा की गई कुल क्षमता का लगभग 80% है। सभी फसलों के अन्तर्गत सिंचित भूमि लगभग दुगुनी हो गई है—यानी 4 करोड़ 50 लाख हेक्टर के स्तर पर। नलकूपों और पम्पसेटों के माध्यम से भूमिगत जल ससाधनों के अधिकाधिक उपयोग से सिंचाई के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। किसानों ने अपनी बमाई से या ऋण देने वाली संस्थाओं से उधार लेकर बहुत अधिक संख्या में नलकूप अथवा कुएँ आदि लगवाए हैं। कम गहराई वाले नलकूपों की संख्या 1973-74 में 7 82 लाख हो गई जबकि 1968-69 में केवल

2.45 लाख ही थी। इसी प्रकार पम्पसैंटो (विजली और डीजन से चलने वाले—दोनों) की संख्या 1968-69 के 16.11 लाख से बढ़कर 1973-74 में 41.93 लाख तक पहुँच गई। जुलाई, 1975 में प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पाँचवी योजना के अन्त तक 50 लाख हेक्टर और कृषि योग्य भूमि में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी।

परिव्यय और उपयोग

पिछले 9 वर्षों में सिंचाई पर हुए परिव्यय और अर्जित क्षमता के उपयोग के रूप में जो पूँजी-निवेश हुआ है वह उससे पहले के 15 वर्षों के पूँजी-निवेश से वही अधिक है। 1951 और 1966 के बीच बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं पर 1,336 करोड़ रु खर्च किया गया, जबकि पिछले 9 वर्षों में अर्थात् 1966 और 1975 के बीच 1,682 करोड़ रु खर्च हुए। इस खर्च का एक बड़ा हिस्सा चालू परियोजनाओं पर खर्च किया गया जिससे पाँचवी योजनाओं के दौरान महत्वपूर्ण लाभ होंगे। इस योजना में 62 लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षमता की परिकल्पना की गई है, इसमें से 55 लाख हेक्टर क्षमता चालू योजना कार्यों से ही प्राप्त होगी। हमारे देश की नदियों में कुल 18 खरब 81 अरब घन मीटर जल उपलब्ध है, इनमें से 5 खरब 67 अरब घन मीटर जल बड़े और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजना के जरिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। पहली योजना के शुरू में 93 खरब घन मीटर जल ही इस्तेमाल में लाया जाता था। तीसरी योजना के अन्त में यह बढ़कर 1 खरब 52 अरब घन मीटर हो गया। अर्थात् 15 वर्षों में 58 अरब घन मीटर की बढ़ोतरी हो गई। पिछले 9 वर्षों में जल का इस्तेमाल 2 खरब 5 अरब घन मीटर तक पहुँच गया है। इसका मतलब यह हुआ कि 53 अरब घन मीटर की और बढ़ोतरी हुई है। पिछले 9 वर्षों में बहुत सी ऐसी परियोजनाएँ पूरी की गई हैं जिनमें बहुत ऊँचे दर्जे की तकनीक और दक्षता से काम लिया गया। इन परियोजनाओं में आन्ध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर बाँध, बिहार में सोन बराज का नया स्वरूप देना, और गुजरात की बनास और हातमती परियोजनाएँ और उर्कई बाँध, मध्यप्रदेश का हंसदेव बराज, राजस्थान में चम्बल नदी पर बाँध और उत्तर प्रदेश में रामगंगा बाँध के नाम उल्लेखनीय हैं।¹



राष्ट्रीय विकास और आंकड़े

सामाजिक न्याय लाने की दृष्टि से अर्थ-व्यवस्था को नया रूप देने के लिए एक कल्याणकारी राज्य की योजना बनानी होती है और विकास के लिए आयोजन को सामग्री एवं मनुष्य के रूप में संसाधनों एवं आवश्यकताओं सम्बन्धी तथ्यों एवं आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए। तथ्य एवं आंकड़े एकत्र करने और इस आधार सामग्री का विश्लेषण करने की तकनीक वाले विज्ञान को सांख्यिकी कहते हैं। इस प्रकार सांख्यिकी-वेत्ता को देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। अगर हमें यह पता नहीं है कि देश में खाद्य उत्पादन कितना हुआ है और कितनी आवश्यकता है तो लाखों लोगों को भारी कष्ट पहुँचने का खतरा हो सकता है। बाँध बनने से पहले इजीनियर को यह जानना होता है कि जलाशय में कितना पानी प्रवाहित होगा और प्रस्तावित निर्माण कितने दबाव को सह सकेगा।

कार्य पद्धति

लेकिन सांख्यिकी के क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति जनता के सामने कम ही दिखाई देता है। वह व्यावहारिक रूप से लोगों से अपरिचित रह कर प्रबाध रूप से काम करता है। उसे पहले तथ्य एकत्र करने होते हैं। ऐसा करने से पहले उसे यह भी जानना चाहिए कि वह कौन सी जानकारी चाहता है वह कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी? काफी सोच विचार के बाद एक प्रस्तावली तैयार की जाती है और क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता उन लोगों से सम्पर्क करता है जो उत्तर देंगे। किसी परियोजना में, अगर हजारों नहीं तो सैकड़ों ऐसे कार्यकर्त्ताओं की सेवाओं की आवश्यकता होती है। इस प्रकार एकन विपुल आधार सामग्री अथवा आंकड़ों का विधायन एवं विश्लेषण आधुनिकतम तकनीकों से किया जाता है और इसके मूल्यांकित परिणामों से देश की आर्थिक समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है।

मूल आधार सामग्री का विश्लेषण कई दृष्टिकोणों से करना होता है। यह काम हाथ से किया जा सकता है, लेकिन यह श्रम साध्य प्रक्रिया है। सांख्यिकी-विदों की मदद के लिए कम्प्यूटर आ गया है। इससे मित्र समय की बचत हो नहीं होती, बल्कि वह गणना करना भी सम्भव है जो किसी दूसरे तरीके से नहीं हो सकती।

भारत में व्यवस्था

स्वतन्त्रता के बाद सरकारी आँकड़ों को एकत्र करने और उनके प्रकाशन में विशिष्ट सुधार हुआ है। कई विश्वविद्यालयों में सांख्यिकी में पाठ्यक्रम हैं। भारत में समस्त सरकारी सांख्यिकी सम्बन्धी गतिविधि के शिखर पर सांख्यिकी विभाग है। इसकी स्थापना मन्त्रिमण्डल सचिवालय में 1961 में की गई थी, लेकिन अब यह योजना मन्त्रालय के अन्तर्गत है। सांख्यिकी विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय सांख्यिकी सङ्गठन (सी. एस. ओ.), राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एन एस एस.) और कम्प्यूटर केन्द्र आते हैं। हर राज्य का अपना सांख्यिकी ब्यूरो है जो केन्द्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। सन् 1961 में एक पृथक् सेवा 'भारतीय सांख्यिकी सेवा' का गठन किया गया था जिससे भारत सरकार में सांख्यिकी के विशेष ज्ञान वाले पदों की व्यवस्था की जा सके। इसमें इस समय लगभग 400 व्यक्ति हैं।

केन्द्रीय सांख्यिकी सङ्गठन—सी. एस. ओ. के वर्षों से चले आ रहे मुख्य कार्य क्षेत्र इस समय इस प्रकार हैं—(1) राष्ट्रीय लेखा तैयार करना, (2) औद्योगिक आँकड़ों का विधायन, सारणीकरण एवं विश्लेषण, (3) सांख्यिकीय प्रशिक्षण; और (4) मानकों को कायम रखना और समन्वय।

केन्द्रीय सांख्यिकी सङ्गठन सभी सांख्यिकीय मामलों पर अन्तर्राष्ट्रीय सङ्गठनों के साथ और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय तथा एशिया एवं प्रशांत की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् के सांख्यिकी डिवीजन के साथ सम्पर्क स्थापित करता है। केन्द्रीय सांख्यिकी सङ्गठन में विभिन्न विषयों की अलग अलग यूनिटें हैं जहाँ इन विषयों के विशेषज्ञ काम करते हैं। यह यूनिटें केन्द्रीय विभागों और राज्य सांख्यिकी ब्यूरो के साथ सम्पर्क रखती हैं। बहुत सी स्थायी समितियाँ कार्यकारी दलों का गठन करके सी. एस. ओ. ने सांख्यिकी मामलों पर केन्द्रीय मन्त्रालयों के साथ समन्वय करने के लिए किया है। सी. एस. ओ. ने दूसरे विभागों को उनके द्वारा एकत्र आँकड़ों की गुणवत्ता को सुधारने में मदद दी है। केन्द्रीय सांख्यिकी सङ्गठन और राज्य सांख्यिकी ब्यूरो के बीच निकट सम्पर्क स्थापित किया गया है जिससे सांख्यिकी के विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाई जा सके। देश और राज्यों की पंचवर्षीय योजनाओं में सांख्यिकी कार्यक्रम शामिल करने की दृष्टि से राज्य सांख्यिकी ब्यूरो के निदेशकों की बैठकें समय समय पर होती रहती हैं। योजना आयोग के सांख्यिकी एवं सर्वेक्षण डिवीजन के माध्यम से सी. एस. ओ. योजना की स्कीमों का समन्वय करता है और उन्हें पंचवर्षीय योजनाओं एवं वार्षिक योजनाओं में शामिल करने में मदद देता है। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों की सांख्यिकी गतिविधियों का सञ्चालन योजना की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और कुछ ताजा सर्वेक्षण—इसका उद्देश्य भारतीय जनता के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर, जिनमें औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र भी शामिल हैं, निरन्तर आधार पर बड़े स्तर के नमूना सर्वेक्षण करना

था। इसका मुख्य उद्देश्य योजना की आवश्यकताओं को पूरा करना था। यह देश में सबसे बड़ा सांख्यिकी संगठन है। प्रबन्ध परिषद् ने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों का दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाया है जिसमें रोजगार, भूमि की जोत, ऋण एवं निवेश, जनसंख्या के अध्ययन और परिवार नियोजन जैसे विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी। आपात स्थिति लागू होने पर प्रधान मन्त्री द्वारा घोषित आर्थिक कार्यक्रमों के सन्दर्भ में उनमें से बहुत से कार्यक्रमों को अत्यधिक महत्व मिला है।

कुछ ताजा सर्वेक्षण निम्न आधार पर किए गए हैं—

भूमिहीन खेतिहर मजदूरों एवं छोटे कृषकों की आर्थिक स्थिति (1970-71),

भूमि जोतो का ढाँचा और ऋण एवं निवेश (1971-72),

देश में रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति (1972-73),

जनसंख्या के पहलू और परिवार नियोजन की स्थिति (1973-74),

गैर कृषि उद्यमों में अपने रोजगार;

ग्रामीण श्रमिक जाँच पड़ताल के परिशिष्ट सहित (1974-75), और

देश में पशुधन उत्पादों का उत्पादन एवं पशुधन उद्यमों का अर्थशास्त्र (1975-76), यह अध्ययन इस समय चल रहा है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की अपूर्व विशेषता यह रही है कि इसके कार्यक्रम में राज्य सरकारों ने भाग लिया है। हर सर्वेक्षण के लिए नमूने के एक भाग से सम्पर्क करने और सारणी बनाने का काम राज्य सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और राज्य ब्यूरो समान प्रक्रियाएँ ही अपनाते हैं। जल्दी ही राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के काम को सिक्किम तक फैला दिया जाएगा। राष्ट्रीय आपात सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने के अलावा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन को औद्योगिक एवं कृषि आंकड़े एकत्र करने का काम भी सौंपा गया है।

कम्प्यूटर केन्द्र—इसकी स्थापना 1967 में सांख्यिकी विभाग के सम्बद्ध कार्यालय के रूप में की गई थी। तीन हनीवेल—400 कम्प्यूटरों को लगाया गया था और ये चौबीस घण्टे काम करते हैं। आधार सामग्री की छानबीन करने और कुशल विश्लेषण करने में कम्प्यूटर बहुत मदद करते हैं। यह केन्द्र दिल्ली में और दिल्ली के आस पास सभी सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्रों के सस्वानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसका उपयोग करने वाले में प्रमुख नाम इस प्रकार हैं—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केन्द्रीय आवकरी एवं सीमा शुल्क बोर्ड, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय वायुसेना, थलसेना, सीमा सुरक्षा दल, नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक, गृह मन्त्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग और दिल्ली टेलीफोन। सरकार के बड़े आर्थिक क्षेत्रों के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी इलेक्ट्रॉनिक आधार सामग्री के विधायन के लिए व्यापक क्षेत्र हैं—जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सामुदायिक विकास, पर्यटन, पर्सनल एवं कैरियर मैनेजमेंट, वेतन एवं लेखा और सूचियाँ आदि।

भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता—भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कलकत्ता में 1932 में स्वर्गीय प्रोफेसर पी सी महालनोबिस की पहल पर वैज्ञानिक ज्ञान समिति के रूप में की गई थी। जीवनपर्यन्त इसके निर्देशक एवं सचिव प्रो महालनोबिस और वर्तमान निदेशक एवं सचिव डी सी एस राव ने इसके लिए अथक प्रयत्न किए हैं जिससे यह संस्थान बड़ा संगठन बन गया है और जिसके कलकत्ता (मुख्यालय), बंगलौर, बड़ोदा, बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, मद्रास और त्रिवेंद्रम में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र हैं। संस्थान ने सिद्धान्त और व्यावहारिक सांख्यिकी में अनुसंधान के लिए बहुत ख्याति प्राप्त की है और भारत को विश्व के सांख्यिकी मानचित्र पर बिठा दिया है। 1955 में संसद में पास एक अधिनियम के अन्तर्गत इसे राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान घोषित किया गया है। संस्थान की मुख्य गतिविधियाँ इस प्रकार हैं—

- (1) विभिन्न गणित एवं सांख्यिकी सम्बन्धी शिक्षा रूपों में अनुसंधान,
- (2) ये पाठ्यक्रम चलाना—बी स्टेट (ग्रान्स), एम स्टेट, पी एच डी की डिग्रियाँ : सांख्यिकी सांख्यिकी गुणवत्ता नियन्त्रण, आपरेशनल रिसर्च आदि में डिप्लोमा पाठ्यक्रम और बाहरी छात्रों के लिए व्यावसायिक परीक्षाओं का आयोजन और
- (3) सांख्यिकी गुणवत्ता नियन्त्रण में परामर्श एवं प्रशिक्षण सेवाएँ प्रदान करना।

यह संस्थान यूनेस्को एवं भारत सरकार के तत्त्वावधान में इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट दि हेग के सहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय सांख्यिकी शिक्षा केन्द्र का संचालन करता है। प्रतिवर्ष नियमित एवं विशेषीकृत पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं और दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, सुदूर पूर्व के विभिन्न देशों तथा अफ्रीका के राष्ट्रमण्डल के देशों के प्रशिक्षणार्थी भी इनमें शिक्षा पाते हैं।¹

1. भारत सरकार आँकड़ों का महत्त्व, दिसम्बर 1975.

राष्ट्र के आर्थिक कायाकल्प के लिए परिवार नियोजन

आज देश के सामने मुख्य चुनौती गरीबी की समस्या है और प्रत्येक योजना या गतिविधि केवल तभी महत्वपूर्ण समझी जाती है जब वह इस समस्या को हल करने में सहायक होती है। जनसंख्या और परिवार नियोजन के प्रश्न को इसी सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए।

परिवार नियोजन कार्यक्रम को अब एक अलग कार्यक्रम के रूप में देखना सम्भव नहीं है। इस कार्यक्रम को देश के सम्पूर्ण स्वास्थ्य और पोषण आहार कार्यक्रमों के साथ मिलकर चलाया जाना है और इसकी पहुँच दूर-दूर के देहाती क्षेत्रों और शहर की गन्दी वस्तियों में रहने वाले हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या तक होनी चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाँचवी योजना में ग्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, पोषण और परिवार नियोजन सेवाएँ एक कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इसको पूरा करने के लिए निस्सन्देह प्रशासन, प्रशिक्षण और संगठन की प्रक्रियाओं में मुख्य परिवर्तन करने होंगे। इस में अन्तिकारी कदम उठाए बिना नए दृष्टिकोण को सफलता मिलने की आशा नहीं है।

स्वास्थ्य, पोषण और परिवार नियोजन सेवाओं का एकीकरण करने के साथ-साथ परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारत सरकार के कार्यक्रम की जगह वास्तविक जन आन्दोलन के रूप में बदलना आवश्यक है। इस दिशा में श्रीमती गाँधी और सजय गाँधी ने दिगुल फूँक दिया है और भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने इसे एक राष्ट्रीय कार्यक्रम मानते हुए आवश्यक कदम उठाए हैं। देश भर में 16 सितम्बर, 1976 से 30 सितम्बर, 1976 तक मनाया गया परिवार नियोजन पखवाड़ा राष्ट्र के हृदय-संकल्प का परिचायक है। जनता के सभी वर्गों से अपेक्षित है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाएँ। न केवल भारत सरकार बल्कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने भी स्पष्ट कर दिया है कि 'मुसलमानों को परिवार नियोजन अपनाना चाहिए। पवित्र कुरान में परिवार नियोजन की मनाही नहीं की गई है।'। ईरान में उलमाओं ने अपना एक फतवा जारी किया था जिसमें यह स्पष्ट कहा गया था कि इस्लाम में परिवार नियोजन या अधिक सन्तानों के जन्म पर नियन्त्रण के बारे में कोई बन्धन नहीं है।

1976-77 में परिवार नियोजन का जोरदार आयोजन

लगभग एक करोड़ एक लाख तीन हजार व्यक्तियों को 1976-77 में परिवार नियोजन के अन्तर्गत लाने का फैसला किया गया है जबकि 1975-76 में यह लक्ष्य 75,10,000 व्यक्तियों को परिवार नियोजन के अन्तर्गत लाने का था। 1976-77 के निर्धारित अनुमानों के अनुसार 43 लाख नसबन्दियों की जाएंगी, 11,40,000 लूप लगाए जाएंगे। परम्परागत गर्भ निरोधकों तथा अन्य तरीकों का नियमित रूप से प्रयोग करने वालों की संख्या 46 लाख 90 हजार होगी।

परिवार नियोजन के लक्ष्यों के बारे में हाल ही में हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार नियोजन परिषदों की बैठक में समीक्षा की गई थी और इसे अन्तिम रूप दिया गया था। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 5,62,000 नसबन्दियों का लक्ष्य रखा गया है जबकि 1975-76 के दौरान इस राज्य में 3,18,300 नसबन्दियों का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद तमिलनाडु की भारी प्राप्ति है जहाँ 5,00,000 नसबन्दियों का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश दोनों राज्यों के लिए लगभग 4,00,000 नसबन्दियों का लक्ष्य रखा गया है।

जहाँ तक परिवार नियोजन के अन्तर्गत लाए जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 12,02,9000 व्यक्तियों को परिवार नियोजन के अन्तर्गत लाया जाएगा। महाराष्ट्र में 8,55,800; तमिलनाडु में 8,30,000; पश्चिम बंगाल में 6,46,000, आन्ध्र प्रदेश में 5,87,800, मध्य प्रदेश 5,82,400 और बिहार में 5,27,000 व्यक्तियों को परिवार नियोजन के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है।

केन्द्रशासित प्रदेशों में दिल्ली का सबसे पहला स्थान है जहाँ 1976-77 के दौरान 29,000 नसबन्दियों का लक्ष्य रखा गया है। गोवा, दमन और दीव के लिए 8,000 और पाण्डिचेरी के लिए 5,300 नसबन्दियों का लक्ष्य रखा गया है।

परिवार नियोजन के बारे में ये लक्ष्य राज्यों में पिछले वर्ष हुई प्रगति के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। 1976-77 में परिवार नियोजन सम्बन्धी नीति की अपेक्षाकृत मुख्य विशेषता नसबन्दी पर जोर देना है। राज्यों से परिवार नियोजन कार्य की हर महीने समीक्षा करने को कहा गया है और साथ ही परिवार नियोजन कार्य में पाए जाने वाले दोषों को जीव करने तथा शीघ्रता से रुकावटों को दूर करने पर भी बल दिया गया है।

1976-77 के दौरान परिवार नियोजन के लिए 70 करोड़ 14 लाख रुपये का बजट परिच्यय रखा गया है।

1976-77 के दौरान जन्म दर कम करने के राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिक कठोर और जोरशोर से कार्य किया जाएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार पांचवीं योजना के अन्त तक जन्म दर 30 प्रति हजार तक लाई जाएगी।¹

भारत सरकार की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की विशेषताएँ

- (1) विवाह की आयु बढ़ाकर लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18 वर्ष की जा रही है।
- (2) 30 साल तक लावसभा और राज्य विधान सभाओं के प्रतिनिधित्व 1971 की जनगणना के स्तर पर ही रहेगा।
- (3) राज्यों की योजनाओं में केन्द्रीय सहायता का 8 प्रतिशत भाग विशेष रूप से परिवार नियोजन कार्यों के लिए रखा जाएगा।
- (4) परिवार नियोजन आपरेशन कराने के लिए पुरुष और महिलाओं को दी जाने वाली रकम में बढ़ोत्तरी की जाएगी।
- (5) फिलहाल अनिवार्य नसबन्दी के प्रश्न पर कोई केन्द्रीय कानून नहीं बन रहा है।
- (6) पचायतो, ग्राम्यापको और श्रमिकों के लिए सामूहिक प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी।
- (7) परिवार नियोजन को जन आन्दोलन बनाने के उद्देश्य से इसमें स्वयं-सेवी संगठनों को सम्मिलित किए जाने की योजना का विस्तार किया जाएगा।
- (8) महिला शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए विशेष उपाए किए जाएंगे।
- (9) बालपोषक आहार कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। जिससे कि बाल मृत्यु के मामलों में काफी कमी हो सके।
- (10) शिक्षा प्रणाली में जनसंख्या समस्या को शामिल किया जाएगा।
- (11) केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों की सेवा और आचरण नियमों में परिवर्तन किए जा रहे हैं जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे छोटे परिवार के सिद्धान्तों पर चलें।

“हमारे देश के आम आदमी को यह समझना होगा कि अपने देश से गरीबी और बेरोजगारी का नामो-निशान मिटाने के लिए हमने जो योजना बनाई है, परिवार नियोजन उसका एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है। अगर वे परिवार नियोजन को अपने जीवन का अंग बना लेते हैं तो यह निश्चित है कि उनकी और उनके बच्चों की जिन्दगी बेहतर बन सकती है। उन्हें यह समझना होगा कि कोई माँ स्वस्थ नहीं रह सकती, यदि वह बार-बार और जल्दी जल्दी गर्भवती होती है। उन्हें यह भी मानना होगा कि बहुत सारे बच्चे पैदा करके उनका उचित तरह सालन-पालन न करना उनके साथ बेइम्साली करना है।”

—राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद (18 अगस्त, 1976)

“हम अपने अनुभव से अच्छी तरह जानते हैं कि गरीबी दूर करने के प्रयत्नों में तभी सफलता मिल सकती है जब हमारे परिवार सुगठित हों। एक ही पीढ़ी में हमारी जनसंख्या में 25 करोड़ की वृद्धि हो गई है। यह वृद्धि ब्रिटेन की आबादी का 5 गुना है। हम अपने विकास कार्यों के अच्छे परिणाम दिखा सकते हैं बशर्ते कि

हमारी जनसंख्या इतनी तेज रफ्तार से न बढ़ी होती। हमारी जनसंख्या नीति राजनीतिक मन्थनाओं पर आधारित नहीं है। इसका उद्देश्य बच्चे-बच्चे की बेहतर तन्दुस्ती है तथा शिक्षा और रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान करना है।”

—प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए परिवार नियोजन

केन्द्रीय प्रमैनिंक सेवा आचरण नियमों में संशोधन करके एक नई धारा जोड़ी गई है जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी भी परिवार नियोजन अपनाएँगे।

नई धारा इस प्रकार है—

“प्रत्येक केन्द्रीय कर्मचारी को विश्वास दिलाना होगा कि उसके तीन से अधिक बच्चे नहीं होंगे, परन्तु 30 सितम्बर, 1976 तक जिन कर्मचारियों के तीन से अधिक बच्चे होंगे, उन पर यह धारा लागू नहीं होगी। यदि वे इस बात का विश्वास दिलाएँ कि उनके बच्चों की संख्या उस दिन तक के मौजूदा बच्चों से अधिक नहीं होगी। यह नई धारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कार्य रूप देने की दृष्टि से जोड़ी गई है। यह सभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर जिनकी संख्या लगभग 30 लाख है, उन पर लागू होगी।”

—भारत सरकार: 5 सितम्बर, 1976

Appendix—7

जनगणना 1971 तथ्य एक दृष्टि में¹

भारत की जनसंख्या	व्यक्ति	54 80 करोड़
	पुरुष	28 40 करोड़
	स्त्रियाँ	26 40 करोड़
दशवार्षिक वृद्धि (1961-71)	24 80 प्रतिशत	
जन-घनत्व ²	178 प्रति वर्ग कि. मी.	
स्त्री पुरुष अनुपात	930 स्त्रियाँ प्रति 1000 पुरुष	
साक्षरता दर (0-4 आयु वर्ग मिलाकर)	व्यक्ति	29.45 प्रतिशत
	पुरुष	39 45 प्रतिशत
	स्त्रियाँ	18 70 प्रतिशत
कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात	19 91 प्रतिशत	
कुल जनसंख्या में कामगारों का प्रतिशत (केवल मुख्य धन्या)	व्यक्ति	32.92
	पुरुष	52 50
	स्त्रियाँ	11 85
कामगारों के वर्ग	कुल कामगारों का प्रतिशत	
(1) कृषक	कुल	43 34
	पुरुष	38 20
	स्त्रियाँ	5.14
(2) कृषि मजदूर	कुल	26 33
	पुरुष	17 57
	स्त्रियाँ	8 76
(3) पशुधन, वन, मत्स्य पालन, शिकार और बागान, फल उद्यान तथा सम्बद्ध धंधे	कुल	2 38
	पुरुष	1.95
	स्त्रियाँ	0 43

1. India 1979 pp 16-17

2. घनत्व जम्मू और काश्मीर के आँकड़े छोड़कर निकाला गया है क्योंकि युद्ध विराम रेखा के उस पार के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(4) खनन और खदान	कुल	0 51
	पुरुष	0 44
	स्त्रियाँ	0 07
(5) उत्पादन उपयोगीकरण सेवाएँ (सर्वांगीण) और मरम्मत		
(क) घरेलू उद्योग	कुल	3 52
	पुरुष	2 78
	स्त्रियाँ	0 74
(ख) गैर घरेलू उद्योग	कुल	5 94
	पुरुष	5 46
	स्त्रियाँ	0 48
(6) निर्माण	कुल	1 23
	पुरुष	1 12
	स्त्रियाँ	0 11
(7) व्यापार और वाणिज्य	कुल	5 57
	पुरुष	5 26
	स्त्रियाँ	0 31
(8) परिवहन भण्डारण	कुल	2 44
और संचार	पुरुष	2 36
	स्त्रियाँ	0 08
(9) अन्य कामगार	कुल	8 74
	पुरुष	7 50
	स्त्रियाँ	1 24



Appendix—8

राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय¹ (कारक मूल्यों पर)

विवरण	1960-61	1971-72	1973-74
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन (करोड़ रु)			
चालू मूल्यों पर	13,267	36,599	49,290
1960-61 के मूल्यों पर	13,267	19,299	19,724
प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन (रु)			
चालू मूल्यों पर	305.7	660.6	849.8
1960-61 के मूल्यों पर	305.7	348.4	340.1
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का सूचकांक (आधार वर्ष . 1960-61)			
चालू मूल्यों पर	100.0	275.9	371.5
1960-61 के मूल्यों पर	100.0	145.5	148.7
प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन का सूचकांक (आधार वर्ष . 1960-61)			
चालू मूल्यों पर	100.0	216.1	278.0
1960-61 के मूल्यों पर	100.0	114.0	111.3
कुल राष्ट्रीय आय (करोड़ रु)			
चालू मूल्यों पर	14,003	38,899	52,193
1960-61 के मूल्यों पर	14,003	20,672	21,214
कुल राष्ट्रीय आय का सूचकांक			
चालू मूल्यों पर	100.0	277.8	372.7
1960-61 के मूल्यों पर	100.0	147.6	151.5

Appendix—9

मूल उद्योग के अनुसार निचले राष्ट्रीय उत्पाद के अनुमान-प्रतिशत विभाजन¹ (1960-61 की कीमतों के आधार पर)

उद्योग वर्ग	1960-61	1970-71	1974-75
1 कृषि, वन और लट्ठा उद्योग, मीन उद्योग, खनन और पर्यटन की खुदाई उद्योग	52.5	45.8	41.2
2 मैन्यूफैक्चरिंग, निर्माण, बिजली, गैस तथा जल पूर्ति	19.2	22.6	23.8
3. परिवहन संचार और व्यापार	14.1	15.9	16.4
4 बैंक और बीमा, भू-सृष्टि सम्पदा तथा आवासों का स्वामित्व और व्यापारिक सेवाएँ	4.2	4.1	4.4
5 सरकारी प्रशासन और रक्षा तथा अन्य सेवाएँ	10.5	12.6	14.8
6 उत्पादन लागत पर वास्तविक घरेलू उत्पादन	100.5	101.0	100.6
7 विदेशों से वास्तविक अभिकर्ता आय	(—) 0.5	(—) 1.0	(—) 0.6
8 उत्पादन लागत पर वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद	100.0	100.0	100.0

Appendix-10

सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा निवल राष्ट्रीय उत्पाद (अर्थात् राष्ट्रीय आय)¹

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (करोड़ रुपये)			निवल राष्ट्रीय उत्पाद (करोड़ रुपये)		प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद (रुपये)	
मोज्जा कीमतों के आधार पर	1960-61 के मूल्यों पर		मोज्जा कीमतों के आधार पर	1960 61 के मूल्यों पर	मोज्जा कीमतों के आधार पर	1960-61 के मूल्यों पर
1	2	3	4	5	6	7
1960 61	13999	13999	13263	13263	305 6	305 6
1961 62	14799	14513	13987	13729	315 0	309 2
1962 63	15727	14880	14795	13993	325 9	308 2
1963 64	17978	15686	16977	14771	365 8	318 3
1964 65	21113	16870	20001	15885	422 0	335 1
1965 66	21866	16113	20636	15082	425 5	311 0
1966 67	25279	16324	23883	15240	482 5	307 9
1967 68	29652	17640	28102	16494	555 4	326 0
1968 69	30417	18184	28729	16991	554 6	328 0
1969 70	33669	19350	31770	18092	600 6	342 0
1970 71	36558	20334	34476	19033	637 3	351 8
1971 72	38814	20708	36535	19367	660 7	350 2
1972 73	42077	20460	39573	19077	700 4	337 6
1973 74	51902	21403	49148	20034	851 8	347 2
1974-75	63375	21478	60120	20075	1022 4	341 4
तीसरी आयोजना में वार्षिक वृद्धि						
दर	9 3	2 9	9 2	2 6	6 9	0 3
1966 67	15 6	1 3	15 7	1 0	13 4	(—) 1 0
1967 68	17 3	8 1	17 7	8 2	15 1	5 9
1968 69	2 6	3 1	2 2	3 0	(—) 0 1	0 6
1969 70	10 7	6 4	10 6	6 5	8 3	4 3
1970 71	8 6	5 1	8 5	5 2	6 1	2 9
1971 72	6 2	1 8	6 0	1 8	3 7	(—) 0 4
1972 73	8 4	(—) 1 2	8 3	(—) 1 5	6 0	(—) 3 6
1973 74	23 4	4 6	24 2	5 0	21 6	2 8
चौथी आयोजना में वार्षिक वृद्धि						
दर	11 3	3 3	11 3	3 3	9 0	1 2
1974 75	22 1	0 4	22 3	0 2	20 0	(—) 1 7

Appendix—11

चुने हुए उद्योगों में उत्पादन¹

विवरण	इकाई	1960-61	1971-72	1974-75
1	2	3	4	5

I खनिज

1. कोयला (लिग्नाइट सहित)	दस लाख मीट्रिक टन	55.7	76.3	90.7
2. कच्चा लोहा	दस लाख मीट्रिक टन	11.0	34.7	35.5

II धातु उद्योग :

3. ढला लोहा	दस लाख मीट्रिक टन	4.31	6.80	7.64
4. इस्पात के ढले	दस लाख मीट्रिक टन	3.42	6.41	6.43
5. तैयार इस्पात	दस लाख मीट्रिक टन	2.39	4.79	4.91
6. इस्पात की ढली हुई वस्तुएँ	हजार मीट्रिक टन	34	54	64
7. अल्युमिनियम (प्राकृतिक धातु)	हजार मीट्रिक टन	18.3	181.5	126.6
8. ताँबा (प्राकृतिक धातु)	हजार मीट्रिक टन	8.5	8.3	15.6

III यान्त्रिक इंजीनियरी उद्योग

9. मशीनों और जोर	दस लाख रुपये	70	550	925
10. सूती कपड़ा बनाने की मशीनें	दस लाख रुपये	104	338	773
11. चीनी मिलों की मशीनें	दस लाख रुपये	44	177	270
12. सीमेंट बनाने की मशीनें	दस लाख रुपये	6	22	93
13. रेल के डिब्बे	हजार की संख्या में	11.9	8.5	11.1
14. मोटर गाड़ियाँ (कुल)	हजार की संख्या में	55.0	91.3	81.7
(I) वाणिज्यिक गाड़ियाँ	हजार की संख्या में	28.4	39.5	40.7
(II) कारें, जीपें और सैड रीवर	हजार की संख्या में	26.6	51.8	41.0

1	2	3	4	5
15. मोटर साइकिल और स्कूटर	हजार की संख्या में	19.4	112 7	149 0
16 विद्युत चालित पम्प	हजार की संख्या में	109	208	282
17. डीजल इंजन (स्थिर)	हजार की संख्या में	44 7	69 9	114 3
18. डीजल इंजन (मोटर गाड़ियों के)	हजार की संख्या में	10 8	1.5	2 9
19. बाइसिकिल	हजार की संख्या में	1071	1766	2341
20 सिलाई की मशीनें	हजार की संख्या में	303	312	335

IV बिजली इंजीनियरी उद्योग :

21. विद्युत् ट्रान्स्फार्मर	हजार किलोवाट एम्पियर	1413	8871	12439
22. बिजली की मोटरें	हजार अश्व शक्ति	728	2348	3684
23 बिजली के पंखे	हजार की संख्या में	1059	2067	2247
24. बिजली के लैम्प	दस लाख की संख्या में	43 5	120 6	134 0
25 रेडियो रिसेवर	हजार की संख्या में	282	2004	1966
26. बिजली केबल				
(i) प्रल्यूमिनियम के तार	हजार मीट्रिक टन	23 6	79 7	28 6
(ii) ताँबे के खुले तार	हजार मीट्रिक टन	10 1	0 7	1 3

V रासायनिक और सम्बद्ध उद्योग

27. नाइट्रोजनी उर्वरक (एन)	हजार मीट्रिक टन	98	952	1182
28 फास्फेटी उर्वरक (पी ₂ पी ₅)	हजार मीट्रिक टन	52	278	323
29. गंधक का तेजाब	हजार मीट्रिक टन	368	975	1434
30 सोडा ऐश	हजार मीट्रिक टन	152	489	516
31. कार्बिक सोडा	हजार मीट्रिक टन	101	385	426
32 कागज और गत्ता	हजार मीट्रिक टन	350	803	825
33. रबर के टायर ट्यूब				
(i) मोटर गाड़ियों के टायर	दस लाख की संख्या में	1 44	4 33	4.83
(ii) मोटर गाड़ियों के ट्यूब	दस लाख की संख्या में	1 35	4 24	4 18
(iii) बाइसिकिलों के टायर	दस लाख की संख्या में	11 15	22 36	25 00
(iv) बाइसिकिलों के ट्यूब	दस लाख की संख्या में	13 27	14 35	18 53

1	2	3	4	5
34 सीमेंट	दस लाख मीट्रिक टन	8 0	15 0	14 7
35 उच्चतापसह्य वस्तुएँ	हजार मीट्रिक टन	567	808	753
36 परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद	दस लाख मीट्रिक टन	5 8	18 6	19.5

VI वस्त्र उद्योग :

37 जूट कपड़ा	हजार मीट्रिक टन	1071	1274	1049
38 सूती घागा	दस लाख किलोग्राम	801	902	1025
39 सूती कपड़ा (कुल)	दस लाख मीटर	6740	7549	8268
(i) मिल क्षेत्र	दस लाख मीटर	4649	4039	4450
(ii) विवेन्द्रीकृत क्षेत्र	दस लाख मीटर	2091	3510	3817
40. रेयन का घागा	हजार मीट्रिक टन	43 8	102.3	115 9
41 नकली रेशम का कपड़ा	दस लाख मीटर	544	968	862

VII खाद्य उद्योग

42 चीनी	हजार मीट्रिक टन	3029	3113	4793
43 चाय	दस लाख किलोग्राम	332	431	493
44. काफी	हजार मीट्रिक टन	54 1	95 6	86 1
45 बनस्पति	हजार मीट्रिक टन	340	594	352

VIII बिजली (उत्पादित)	अरब कि वा घ.	16 9	60 7	69 4
-----------------------	--------------	------	------	------

गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगार¹

उद्योग प्रभाग/मक्षिप्त व्यौरा	मार्च 1961	मार्च 1971	मार्च 1973	मार्च 1975
1	2	3	4	5
0 बागान, वन आदि	6.7	8.0	8.1	8.2
1 खानों और पत्थर की खानों की खुदाई	5.5	4.1	2.5	1.2
2. और 3. वस्तु निर्माण	30.2	39.7	41.0	41.3
4 इमारतों का निर्माण	2.4	1.4	1.8	1.3
5 बिजली, गैस और जल आदि	0.4	0.5	0.5	0.4
6 व्यापार और वाणिज्य	1.6	3.0	3.1	3.5
7 परिवहन और संचार	0.8	1.0	0.8	0.8
8 सेवाएँ	2.8	10.0	10.8	11.3
जोड़	50.4	67.6	68.5	68.0

Appendix—13

सरकारी क्षेत्र में रोजगार¹

मार्च 1961 मार्च 1971 मार्च 1973 मार्च 1975
(प्रतिम)

सरकारी क्षेत्र के वर्गों के अनुसार

	1	2	3	4	5
1	केन्द्रीय सरकार	20 90	27 71	29 18	29 86
2	राज्य सरकार	30 14	41 52	45 79	47 44
3	श्रद्ध सरकारी	7.73	19 29	25.78	31 68
4	स्थानीय निकाय	11 73	18 78	19 00	19 39
	जोड़	70 50	107 31	119 75	128 38

20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम

1. आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में गिरावट के रुझान को बनाए रखना, उत्पादन की गति तेज करना, आवश्यक उपभोक्ता पदार्थों की वसूली व वितरण व्यवस्था को प्रभावशाली बनाना, सरकारी खर्च में कमी करना ।
2. कृषि भूमि की हदबन्दी को तेजी से लागू करना, अतिरिक्त भूमि को ज्यादा तेजी से बाँटना तथा भूमि सम्बन्धी प्रलेख तैयार करना । इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि जनजातीय लोगों को उनकी भूमि से वंचित न किया जाए ।
3. देहाती क्षेत्रों में भूमिहीनों व समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवास भूमि के आवंटन को तेजी से लागू करना ।
4. मजदूरों से जबरन काम कराने को, जहाँ कहीं ऐसा होता हो, गैर-कानूनी करार दिया जाएगा ।
5. ग्रामीणों के कर्ज की समाप्ति की योजना । भूमिहीन मजदूरों, दो हैक्टेयर से कम भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों व देहाती दस्तकारों से कर्ज की वसूली पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया जाएगा ।
6. खेतिहर मजदूरों के निम्नतम मजदूरी सम्बन्धी कानूनों में सशोधन होगा और जहाँ आवश्यक होगा, न्यूनतम वेतन को उचित रूप से बढ़ाने के लिए कार्यवाही की जाएगी ।
7. 50 लाख हैक्टेयर भूमि में और सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी । भूमिगत जल के उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाए जाएँगे और पीने के पानी की व्यवस्था के लिए, विशेष रूप से सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों में और अधिक सर्वेक्षण किए जाएँगे ।
8. बिजली उत्पादन कार्यक्रमों में तेजी लाई जाएगी । केन्द्र के नियन्त्रण में सुपर ताप बिजलीघरों की स्थापना की जाएगी ।
9. हाथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए नए कार्यक्रम लागू किए जाएँगे । बुनकरों को और अधिक सुरक्षा प्रदान करने की नीति को अधिक युक्तिसंगत बनाया जाएगा ।
10. नियन्त्रित मूल्य पर बिकने वाले कपड़े की बवालिटो सुधारी जाएगी और उसके वितरण की उचित व्यवस्था की जाएगी ।

- 11 शहरी भूमि व शहर बसाने योग्य भूमि का समाजीकरण, खाली छोड़ी गई अतिरिक्त भूमि पर कब्जा करने तथा नए आवासों में चौकी क्षेत्र को कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
- 12, दिखावे की शानदार सम्पत्ति के मूल्यांकन के लिए और कर चोरी पकड़ने के विशेष दस्ते कायम किए जाएंगे। आर्थिक अपराधियों के खिलाफ तुरन्त नियोयक मुकदमा चलाया जाएगा तथा कड़ा दण्ड दिया जाएगा।
- 13 तस्करो की सम्पत्ति जब्त करने के लिए विशेष कानून बनाया जाएगा।
- 14 पूँजी निवेश प्रक्रिया को उदार बनाया जाएगा। आयात लाइसेंस का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
- 15 उद्योगों में, विशेष रूप से कारखानों के काम में कर्मचारियों की शिरकात से सम्बन्धित नई योजनाएँ और उत्पादन कार्यक्रमों की शुरुआत।
- 16 सड़क परिवहन के लिए राष्ट्रीय परमिट याजना शुरू की जाएगी।
17. मध्यम वर्ग के आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर 8 हजार रुपये कर दी जाएगी।
- 18 छात्रावासों में छात्रों के लिए नियन्त्रित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था की जाएगी।
- 19 छात्रों को नियन्त्रित मूल्य पर पुस्तकें व स्टेशनरी के सामान उपलब्ध कराए जाएंगे तथा पुस्तक बाँकी की स्थापना की जाएगी।
- 20 नई एग्जेंटिंगशिप योजना शुरू की जाएगी जिसमें रोजगार व प्रशिक्षण के अवसर बढ़ेंगे। एग्जेंटियों की भर्ती करते समय अनुसूचित जाति और जनजाति, अल्पसंख्यकी और विकलांगों का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

(राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री द्वारा 1 जुलाई 1975 के प्रसारण से)

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप

(25 सितम्बर 1976 को राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्वीकृति)¹

राष्ट्रीय विकास परिषद् ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को 25 सितम्बर, 1976 को अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया है। इस योजनाकाल के अब दो ही वर्ष शेष रह गए हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि योजना की यह अन्तिम स्वीकृति बहुत विलम्बित हो गई है। परन्तु योजना के अब तक गुजरे काल में कुछ ऐसी अस्थिरता की परिस्थितियाँ और मजबूतियाँ रही कि योजना का अन्तिम ढाँचा स्वीकार करने में विलम्ब होना स्वाभाविक ही था। वास्तव में, जैसा कि प्रधान-मंत्री ने कहा है, यह समझ जाना चाहिए कि पंचवर्षीय योजना की यह मध्यावधि समीक्षा हुई है और प्रारम्भ के तीन वर्षों में प्राप्त अनुभवों और देश में लाई गई स्थिरता के फलस्वरूप इसके शेष वर्षों के लिए सुविचारित आयोजन किया गया है।

परिषद् के योजना को स्वीकार करने वाले प्रस्ताव में कहा गया है कि पाँचवीं योजना के प्रारूप पर विचार करते हुए आत्मनिर्भरता व गरीबी दूर करने के उद्देश्यों पर जोर देते हुए, मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति पर अकुश के लिए उठाए जाने वाले कदमों का समर्थन करते हुए कृषि, सिंचाई ऊर्जा व सम्बन्धित आधारभूत क्षेत्र की योजनाओं पर जोर देते हुए, नए आर्थिक कार्यक्रम को लागू करने की इच्छा में राष्ट्र की क्षमता में विश्वास व्यक्त करते हुए, पूँजी निवेशों से अधिक आय प्राप्त करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए राष्ट्रीय विकास परिषद् सितम्बर, 1976 की अपनी बैठक में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को स्वीकार करती है तथा जनता के सभी वर्गों से अपील करती है कि योजना में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में पूर्ण सहयोग दें।

राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा स्वीकृत पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में 39303.24 करोड़ रु. खर्च करने का प्रावधान है। यह प्रारूप योजना से लगभग 2000 करोड़ रु. अधिक है। अगले दो वर्षों में इस क्षेत्र पर 19903 करोड़ रु. खर्च होने वाला है। जहाँ तक अलग-अलग मदों की बात है व्यय का आवंटन इस प्रकार रखा गया है—

1. हिन्दुस्तान दि. 26 एवं 27 सितम्बर, 1976 के आधार पर

मद	व्यय राशि
कृषि तथा इससे सम्बन्धित विषय	4643 50 करोड़ रु.
मिर्चाई तथा बाढ़ नियन्त्रण	3440 18 करोड़ रु.
बिजली	7293 90 करोड़ रु.
उद्योग तथा खनन	10200 60 करोड़ रु.
परिवहन तथा संचार	6881 43 करोड़ रु.
शिक्षा	1284 29 करोड़ रु.
समाज तथा सामुदायिक सेवाओं पर	4759 77 करोड़ रु.
पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों पर	450 00 करोड़ रु.
अन्य विविध क्षेत्रों पर	333 73 करोड़ रु.

पाँचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में जिन विषयों को प्राथमिकता मिली थी, उन्हें अपरिवर्तित रखा गया है।

पाँचवी योजना की 39303 24 करोड़ रु की राशि में केन्द्र का योगदान 19954 10 करोड़ रु, राज्यों का 18265 08 करोड़ रु, तटीय क्षेत्र का 634 06 करोड़ रु तथा पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों को 450 करोड़ रु. रहेगा।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री हक्सर ने कहा कि सही मायनों में पाँचवी पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष तो तैयारी में ही चला गया। अतः हमें अपना वास्तविक कार्य शेष चार वर्षों में ही विभाजित करना पड़ा। यही कारण है कि योजना के अगले दो वर्षों में 19902 करोड़ रु खर्च करने की व्यवस्था की गई है जबकि पहले तीन वर्षों के लिए पहले 19401 करोड़ रु खर्च करने का अनुमान था।

श्री हक्सर ने कहा कि योजना आयोग का अनुमान है कि हमारा कृषि उत्पादन कम से कम 12½ करोड़ टन तथा अधिक से अधिक 13 करोड़ 20 लाख टन होगा। उसके आधार पर कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत तथा उद्योग के क्षेत्र में 7 10 प्रतिशत विकास की आशा रखी जा सकती है। हमारे निर्यात में भी 8 5 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।

योजना आयोग का अनुमान है कि इस पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र भी 24000 करोड़ रु खर्च कर सकेगा।

हक्सर ने कहा कि यह योजना यथार्थवादी है और इसमें मूल्यों में स्थिरता पर विशेष जोर दिया गया है।

योजना में कोयले का उत्पादन लक्ष्य 12 करोड़ 40 लाख टन, तैयार इस्पात का 88 लाख टन, रासायनिक खाद (नाइट्रोजन) का 29 लाख टन और फास्फेट खाद का 7 लाख 70 हजार टन रखा गया है। श्री हक्सर ने बताया कि योजना में नए इस्पात कारखाने के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। लेकिन यह कारखाना कहाँ लगाया जा सकता है, इसकी जाँच-पड़ताल अभी चल रही है और निर्णय बाद में ही हो सकेगा।

आयोग के सदस्य प्रो एस चक्रवर्ती ने बताया कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण सपठन द्वारा बेरोजगारी सम्बन्धी सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर अभी विचार हो रहा है। यह हमारी सबसे विकट समस्या बन सकती है।

उन्होंने बताया कि योजना में मध्यम और बड़ी सिचाई योजनाओं से 58 लाख हेक्टेयर और लघु सिचाई से 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिचाई का प्रावधान किया गया है। योजना के अग्रन तक 31000 मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें छद्मी योजना के लिए अग्रिम कार्रवाई शुरू करने का प्रावधान भी रखा गया है।

उन्होंने बताया कि योजना में अगले दो वर्षों में लगभग 1600 करोड़ रुपये के अतिरिक्त साधन जुटाने का प्रावधान है, जिसमें से 900 करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र से और 700 करोड़ रुपये राज्य क्षेत्र में मुहैया किए जाएंगे। 14700 करोड़ के अतिरिक्त साधनों में से लगभग 13,000 करोड़ रुपये के साधन पहले तीन वर्षों में जुटाए जा चुके हैं।

परिपद ने योजना को स्वीकार करते हुए जनता के सभी वर्गों से निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में पूर्ण सहयोग देने की अपील की है। योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता तथा गरीबी को दूर करना है, इसलिए जनता का सहयोग तो इसमें आवश्यक है ही और वह मिलना चाहिए। आपात् स्थिति की घोषणा के बाद देश में जो अनुशासन और कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा की भावना आई है और सामाजिक प्रवृत्तियाँ रुकने से जो उत्साह पैदा हुआ है, वह बना रहना चाहिए ताकि उत्पादन बढ़े, ठीक ढंग से वितरण हो और योजना के लक्ष्य पूरे हो सकें। इसके अलावा प्रधानमन्त्री ने ग्रामीणों से उनकी बचत को सग्रह करने के लिए ग्रामीण ऋण पत्र जारी करने, राज्यों से ओवर ड्राफ्ट लेने की प्रवृत्ति रथाने, समुचित वितरण द्वारा किसी वस्तु का अभाव न होने देने, मूल्यों को न बढ़ने देने तथा एक राष्ट्रीय वेतन नीति निर्धारित करने आदि के जो सुझाव दिए हैं, उन पर भी अमल किया जाना चाहिए। इनसे देश में आवश्यक आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने तथा योजना के लक्ष्यों को मूर्त रूप देने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा हो सकेंगी।

प्रश्न-कोश (QUESTION BANK)

खण्ड-1. आर्थिक विकास के सिद्धान्त

अध्याय 1

- 1 आर्थिक विकास की परिभाषा दीजिए। आर्थिक विकास की प्रकृति एवं उसके मापदण्ड के बारे में बताइए।
Define economic growth. Mention the nature and measurement of economic growth.
- 2 "आर्थिक विकास के तीन पहलू हैं—समग्रिकृत राष्ट्र के कुल और प्रति व्यक्ति उत्पादन में निरन्तर वृद्धि, सर्वनात्मक विकास प्रक्रिया के दौरान अर्थव्यवस्था में जो विचरण (अथवा परिवर्तन) आते हैं, अन्तर राष्ट्रीय देश में बदलती हुई सरकारों के साथ ही साथ, इस के, और शेष विश्व के बीच आर्थिक प्रवाहों का अनुक्रमिक प्रतिरूप बनाना।" उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। (1972)
'Economic growth has three aspects—the aggregative sustained increase in a nation's total and per capita product, the structural the shifts that occur in any economy during the growth process, the international : the changing domestic structure is supplemented by a sequential pattern of economic flows between it and the rest of the world' Elaborate with the help of illustrations
- 3 आर्थिक विकास के सत्त्वों की ओर उनके सुलनात्मक महत्त्व की विवेचना करो। आप आर्थिक विकास की दर किस प्रकार मापोगे? (1973)
Discuss the factors that are responsible for economic growth and their relative importance. How would you measure the rate of growth
- 4 आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास और आर्थिक प्रगति में भेद कीजिए। आर्थिक विकास की माप-हनु आय-समको का प्रयोग किस सीमा तक किया जा सकता है?
Distinguish between economic growth, economic development and economic progress. How far Income Data may be used to measure economic growth?
- 5 "हम आर्थिक विकास की परिभाषा एक प्रक्रिया के रूप में करेंगे जिससे कि किसी देश के प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविक आय दीर्घकालीन अवधि में बढ़ती है।" (मेयर) स्पष्ट कीजिए। (1975)
"We shall define economic development as the PROCESS whereby the REAL PER CAPITA INCOME of a country increases over a long period of time" (Meier) Elucidate

अध्याय 2

- 1 अर्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था के मुख्य लक्षण लिखिए। एक अर्ध-विकसित और एक विकसित राष्ट्र के आयोजन में क्या भिन्नताएँ होती हैं?
Critically examine the characteristic features of an undeveloped economy. How economic planning in an under developed country differs from that of a developed country?

- 2 आप की राय में भारत जैसे अल्प-विकसित देश के आर्थिक विकास में कौनसी मुख्य बाधा है पूँजी की कमी, तकनीकी परिवर्तन और अभिनवीकरण प्रक्रिया की धीमी दर अथवा उपयुक्त संस्थागत और सामाजिक ढाँचे का अभाव ? उदाहरण दीजिए । (1972)
What would you consider the main barrier to economic development of a less developed country such as India paucity of capital, slow rate of technological change and innovation or absence of an appropriate institutional and social structure ? Give illustrations.
- 3 अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएँ हैं ? ऐसी अर्थव्यवस्था में आधारभूत समस्याएँ क्या होती हैं ? इनकी विवेचना भारत के सन्दर्भ में करो । (1973)
What are the main characteristics of an under-developed economy ? What are the basic problems to planning in such an economy ? Discuss them with reference to India
- 4 “अल्पविकसित देशों से सम्बन्धित आँकड़ों एवं वर्णनात्मक जानकारी का अध्ययन करने से प्रकट होता है कि राष्ट्रीय निर्धनता एवं देश की अर्थव्यवस्था के अन्य लक्षणों में अवश्य ही सहसम्बन्ध है ।” (हिगिंस) ये अन्य लक्षण क्या हैं ? (1974)
“Examination of statistics and descriptive information pertaining to under-developed countries reveals that there is indeed a correlation between national poverty and other features of the country's economic and social organization” (Higgins) What are these other features ?
- 5 विकसित, अविकसित तथा अर्द्ध-विकसित देशों में उसके आर्थिक विकास की दशाओं में क्या अन्तर पाया जाता है ? प्रत्येक का उपयुक्त उदाहरण देते हुए समझाइए ।
Describe how states of economic development in developed, undeveloped and under-developed countries differ from one another, giving suitable examples of each
- 6 अर्द्ध विकसित देशों की समस्याओं की परीक्षा कीजिए ।
Examine the problems of under-developed countries
- 7 “आर्थिक प्रगति की वास्तविक आधारभूत समस्याएँ गैर-आर्थिक हैं ।” विवेचना कीजिए ।
“The really fundamental problems of economic development are non-economic”. Comment

अध्याय 3

- 1 विकास के अन्तर्गत संरचनात्मक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं ? उत्पादन के संयोजन में परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए ।
What do you understand by ‘structural changes under development’ ? Explain changes in the composition of production.
- 2 विकास के अन्तर्गत संरचनात्मक परिवर्तन को समझाते हुए उपभोग में परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए ।
Explain ‘Structural changes under development’ and show how do you understand by the changes in consumption
- 3 रोजगार निवेश और व्यापार के संगठन में विकास के दौरान संरचनात्मक परिवर्तन की विवेचना कीजिए ।
Discuss the structural changes in the composition of employment, investment and trade
- 4 “आधुनिक युग में, मुख्य संरचनात्मक परिवर्तनों का लक्ष्य कुचि मंदों के स्थान पर औद्योगिक मंदों का उत्पादन (औद्योगीकरण की प्रक्रिया), ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण

- 5 रोस्टव के आर्थिक विकास की अवस्थाओं के सिद्धान्त का विश्लेषण कीजिए तथा इसकी सीमाएं बताइए।
Elucidate Rostow's Theory of economic growth and point out its limitations
- 6 स्वचालित विकास क्या है ? इसकी क्या सीमाएँ हैं ?
What is self sustained growth ? What are its problems ?
- 7 आर्थिक वृद्धि की परिभाषा दीजिए। रोस्टव के अनुसार आर्थिक वृद्धि के विभिन्न काल क्या हैं ?
Define Economic growth ? What are according to Rostow the different stages of economic growth ?
- 8 आर्थिक विकास की पूर्व आवश्यकताएँ क्या हैं ? आर्थिक विकास के अध्ययन ने आधुनिक समय में विशय महत्व क्यों प्राप्त किए हैं ?
What are the pre requisites of economic growth ? Why has the study of economic growth assumed special importance in modern times ?
- 9 "आर्थिक विकास कोई जादू नहीं है वह एक निश्चित गणित पर आधारित होना चाहिए।" भारतीय अनुभव के आधार पर टिप्पणी कीजिए।
'Economic development is not a miracle It is based on a definite arithmetic' Comment in the light of Indian experience
- 10 विकास दर के विभिन्न तत्वों के योगदान पर डेनिसन के विश्लेषण का विवरण दीजिए।
Examine D'nison's estimates of the contribution of different factors to the growth rate

अध्याय 5

- 1 आर्थिक विकास का विश्लेषण कीजिए और महत्वपूर्ण मॉडलों को बताइए।
Analyse economic growth and point out important growth models
- 2 आर्थिक विकास के लेविस मॉडल को परीक्षा कीजिए।
Examine Lewis Model of economic growth
- 3 लेविस के असीमित श्रम पूति के वृद्धि-सिद्धान्त की विवेचना कीजिए। बताइए कि अ-विकसित देशों में असीमित श्रम पूति के द्वारा पूँजी निर्माण सम्भव भी है और लाभदायक भी।
Discuss Lewis theory of growth with unlimited labour supply Do you agree that Capital formation with unlimited supplies of labour is possible and profitable in under developed countries ?
- 4 हेरार्ड डोमर मॉडल स्वयं में विश्लेषण का एक अक्षर और काम चलाऊ साधन है और इससे बहुत अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। (मु. चक्रवर्ती) अल्पविकसित देशों के लिए नीति सम्बंधी तत्वों की दृष्टि से हेरार्ड-डोमर मॉडल की सफलता एवं सीमाओं को समझाइए।

या

असीमित श्रम पूति की परिस्थिति में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को निरूपित कीजिए।

(1974, 75)

Harrod-Domar Model is 'a very rough tool in itself and not too much should be expected from it' (S Chakravarty) Explain the relevance and limitations of Harrod-Domar model in relation to its policy implications for under-developed countries

OR

Outline the process of economic development under conditions of unlimited labour supply

- 5 हैरॉड-डोमर के आर्थिक वृद्धि के विश्लेषण के प्रमुख अंश स्पष्ट कीजिए। इसके व्यावहारिक प्रयोग की विवेचना कीजिए।
Explain the main point of Harrod—Domar analysis of economic growth Discuss its practical application
- 6 अल्पविकसित देशों की आर्थिक विकास की समस्या के लिए हैरॉड डोमर विश्लेषण के महत्त्व का विवेचन कीजिए।
Discuss the significance of Harrod—Domar analysis for the problem of economic development of under developed countries
- 7 महालनोबिस के आर्थिक वृद्धि के मॉडल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on The Mahalanobis Model of economic growth
- 8 महालनोबिस के नियोजित विकास के मॉडल की व्याख्या कीजिए। महालनोबिस के आर्थिक वृद्धि के सहाय्य मॉडल के मुख्य दोष क्या हैं ?
Explain the Mahalanobis Model of planned development What are the important flaws in the operational model of economic growth by Mahalanobis ?
- 9 उन वैज्ञानिक ढाँच को पूरी तरह समझाइए और उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए जो कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार था। (1975)
Explain fully and evaluate critically the theoretical framework which formed basis of India's Second Five-year Plan

अध्याय 6-9

- 1 'आर्थिक विकास के लिए नियोजन' पर आलोचनात्मक निबन्ध लिखिए।
Write a critical essay on "Planning for Economic Development"
- 2 एक नियोजन अथ व्यवस्था के पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्कों की आलोचनात्मक परीक्षा कीजिए।
Critically examine the arguments advanced for and against a planned economy
- 3 'नियोजित अर्थ व्यवस्था मुक्त अर्थ व्यवस्था से अग्रसर क्यों मानी जाती है?' विवेचना कीजिए।
Why is 'Planned economy' considered superior to 'Free enterprise—economy' ? Discuss fully
- 4 बचत दर को प्रभावित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए।
Discuss the factors affecting the saving rate
- 5 सम्पूर्ण विकास दर को प्रभावित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए।
Discuss the factors affecting the over-all growth rate
- 6 'विकास योजना केवल एक हद तक अर्थशास्त्रीय कला है, एक महत्त्वपूर्ण हद तक यह राजनैतिक समझौते का प्रयोग है।' (लुइस) व्याख्या कीजिए। (1974)
"Development planning is only in part an economic art, to an important extent it is also an exercise in political compromise" (Lewis) Elucidate
- 7 कितनी विकास योजना में वृद्धि दर किस प्रकार निर्धारित की जाती है ? वृद्धि दर को परिसीमित करने वाले तत्व कौन-कौन से हैं ? पूरी तरह समझाइए। (1974)
How is the rate of growth determined in a development-plan ? What are the constraints on the rate of growth ? Explain fully
- 8 साधनों की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं ? गतिशीलता को निर्धारित करने वाले कारणों की विवेचना कीजिए।
What do you understand by 'Resource Mobilisation'

- 9 आन्तरिक साधनों और बाह्य साधनों के विभिन्न रूपों की आलाचनात्मक समीक्षा कीजिए।
Critically examine the various forms of internal resources and external resources
- 10 'योजना के लिए वित्तीय साधनों की गतिशीलता' पर विचार लिखिए।
Write an essay on "Mobilisation of Financial Resources."
- 11 उपभोक्ता वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए माँग के अनुमान से आप क्या समझते हैं ? स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए।
What do you understand by the demand projections for consumptions goods and intermediate goods ? Explain fully
- 12 माँग के अनुमानों में आदा-प्रदा गुणों के उपयोग को समझाइए।
Explain the use of the input-output co-efficients
- 13 बताइए कि आदा-प्रदा विश्लेषण की तकनीक कुशल आर्थिक नियोजन के लिए कहीं तक ग्रहणीय है ? क्या भारत में इस तकनीक के प्रयोग में कोई व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं ?
Discuss how far the technique of input-output analysis is adoptable for efficient economic planning—Are there any practical difficulties in applying this technique in India ?

अध्याय 10-16

- 1 विभिन्न क्षेत्रों के सन्तुलित उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करने की विधि समझाइए। असन्तुलित विकास के पक्ष में क्या तर्क हैं ? (1973)
Explain the method of determining balanced growth targets for different sectors. What are the arguments for unbalanced growth ?
- 2 आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विनियोग के अन्तर-क्षेत्रीय आवंटन के महत्त्व का विश्लेषण कीजिए। इस सम्बन्ध में बचत की सर्वात्म्य दर की धारणा की विवेचना कीजिए।
Analyse the significance of inter-sector allocation of investment for promoting economic growth. Discuss in this connection the concept of the 'Optimum' rate of savings
- 3 वे कौन से सिद्धांत हैं जिनके अनुरूप विनियोग करने योग्य कोषों को एक नियोजित अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वितरण करना चाहिए ?
What are the principles in accordance with which investable funds should be distributed among the various sectors of a planned economy ?
- 4 एक योजना बनाते समय कुल विनियोग वा क्षेत्रीय आवंटन आप कैसे निश्चित करेंगे ? (1973, 75)
How would you determine the sectoral allocation of investment in making a plan ?
- 5 किसी योजना में विनियोग की प्राथमिकताओं और तरीके का निश्चय करने में किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए ? क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारतीय योजना निमात्राओं ने भारी और पूँजीय उद्योगों, शक्ति तथा यातायात की बहुत अधिक ऊँची प्राथमिकता दी है तथा सामाजिक सेवाओं को बहुत कम प्राथमिकता दी है।
What considerations should be kept in view in deciding the priorities and pattern of investment in a plan ? Do you think that Indian planners have given too much high priority to heavy and capital goods industries, power and transport and too low priority to social services ?
- 6 अर्द्ध-विकसित देशों में आर्थिक विकास की योजनाओं में प्राथमिकता के निर्धारण के मानदंड की विवेचना कीजिए।
Discuss the criteria for determination of priorities in plans for the economic development of developed countries

- 7 एक अर्द्ध-विकसित देश के आर्थिक विकास में 'विनियोग चुनायो और व्यूह रचनायो' पर एक निबन्ध लिखिए।
Write an essay on 'Investment Choices and Strategies' in the economic developments of an under developed country
- 8 'उत्पादन लक्ष्यों के निर्धारण' पर आलोचनात्मक निबन्ध लिखिए।
Write a critical essay on Determination of output Targets "
- 9 'विनियोग विकल्प की आवश्यकता' की व्याख्या कीजिए। अर्द्ध-विकसित देशों की विनियोजन सम्बन्धी विशिष्ट समस्याएँ क्या हैं ?
Explain Need for Investment choice " What are special investment problems in under developed countries ?
- 10 'विनियोग मानदण्ड' और उसकी व्यावहारिक उपयोगिता की विवेचना कीजिए।
Discuss Investment Criterion' and its practical utility
- 11 बाजार संयत के अभाव में एक समाजवादी अर्थ व्यवस्था में विभिन्न उद्योगों के बीच साधनों के आवंटन का निर्धारण किस प्रकार होता है ? क्या इस मामले में समुलनकारी दशाएँ उन दशाओं से आधारभूत रूप में भिन्न होती हैं जो एक प्रतिस्पर्धी पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में पायी जाती हैं ?
How is the allocation of resources between different uses determined in a socialist economy in the absence of a market mechanism ? Are the equilibrium conditions in this case basically different from those in a competitive capitalist economy ?
- 12 अर्द्ध-विकसित देशों में आर्थिक विकास को वित्तीय प्रवर्ध देने वाले विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। क्या आप एक नियोजित अर्थ व्यवस्था में होनार्थ प्रवर्धन को अनिवार्य मानते हैं ?
Describe the various methods of financing development in under-developed countries Do you consider deficit financing in a planned economy
- 13 ऐसा क्योंकर है कि अनेक अर्द्ध विकसित देशों के मूल्य-स्तर में अत्यधिक वृद्धि की छिपे स्रोतों को समुचित रूप से शक्तिशाल बनाने में असफल रही है ? प्रति-लोच में सुधार के लिए राज्य द्वारा क्या कदम उठाए जा सकते हैं ?
How is it that even a tremendous rise in the price level of many under-developed countries has failed to mobilize adequately the hidden resources? What steps can be taken by the state to improve the supply elasticity?
- 14 किसी देश की किन आधारा पर अपने दुर्लभ साधनों का विभिन्न उद्योगों में वितरण करना चाहिए ?
On what basis should a country distribute its scarce resources among different industries ?
- 15 भारत में लोक सत्त की क्या मूल समस्या है ? इसे अधिक लाभपूर्ण बनाने के उपाय सुझाइए।
What are the basic problems of the public sector in India ? Suggest measures for improving its profitability
- 16 एक दृष्टिकोण यह है कि नियोजित मूल्य व्यवस्था कीमतों को नीचा रखने तथा अधिक लाभों को रोकने के अपने दोनो मुख्य उद्देश्यों में अधिकांशत स्वयं असफल रहती है। क्या हाल ही का भारतीय अनुभव इसे सिद्ध करता है ?
There is a point of view that a controlled price system is largely self defeating in two of this Principal objectives keeping costs low & preventing excess profits Does recent Indian experience bear this out ?
- 17 टिप्पणी लिखिए—
(अ) बढ़ते हुए मूल्यों के दुष्प्रभाव।
(ब) तृतीय योजना की मूल्य नीति।

Write a note on —

(a) Implications of rising prices

(b) Price policy for the Third Plan

- 18 “मूल्य केवल साधनों का आवंटन ही नहीं करते आय का वितरण का निर्धारण भी करते हैं।” क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? इस कथन के प्रकाश में उस कुपि मूल्य नीति का पुन-मूल्यांकन कीजिए जो देश में हाल ही के वर्षों में अपनाई गई है।
“Price not only allocate resources they also determine the distribution of incomes” Do you agree ? In the light of this statement review the Agricultural price policy pursued in the country in recent years
- 19 एक विकासशील अर्थ-व्यवस्था में मूल्य-नीति के विशिष्ट लक्षणों को बताइए।
Mention the salient features of price policy in a developing economy
- 20 एक नियोजित विकासशील अर्थ-व्यवस्था में मूल्य नीति के विभिन्न मुख्य सिद्धान्तों को लिखिए।
Write the various principles of price policy in a planned developing economy
- 21 व्यक्तिवादी और समष्टिवादी अध्ययन से क्या अभिप्राय है ? एक विकासशील अर्थ-व्यवस्था में मूल्य-नीति में व्यक्तिवादी और समष्टिवादी पहलुओं को स्पष्ट कीजिए।
What is meant by micro and macro studies ? Mention clearly the micro and macro aspects in price policy in a developing economy
- 22 मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में मूल्य-नीति के सिद्धान्तों की विवेचना कीजिए।
Discuss the principles of price policy in a mixed economy
- 23 ‘मूल्य-नीति और पदार्थ-नियन्त्रण’ पर एक निबन्ध लिखिए।
Write an essay on “Price Policy and Commodity Control”
- 24 विदेशी-विनिमय की महत्ता और आवश्यकता की विवेचना कीजिए।
Discuss importance and necessity of foreign exchange
- 25 भारतीय नियोजन में विदेशी विनिमय के आवंटन की परीक्षा कीजिए।
Examine allocation of Foreign exchange in Indian planning
- 26 उपयुक्त सहायक उदाहरण की सहायता से समझाइए कि आप किसी योजना का वित्तीय समति की दृष्टि से परीक्षण कैसे करेंगे। (1974)
Explain with the help of suitable illustrations, how you will test a plan for financial consistency
- 27 सकल लाभदायक विश्लेषण को सामाजिक लागत-लाभ विश्लेषण में बदलने के लिए कौन से सुधार आवश्यक हैं ? (1974)
What modifications must be made to turn gross profitability analysis into a social cost-benefit analysis ?

Miscellaneous

- 1 “आर्थिक विकास बहुत हद तक मानवीय गुणों, सामाजिक प्रकृतियों, राजनैतिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक संयोगों से सम्बन्ध रखता है।” विवेचना कीजिए।
“Economic development has much to do with human endowments, social attitudes, political conditions and historical accidents” Discuss
- 2 “यदि बचाना चाहे, तो कोई राष्ट्र इतना द्रिद्ध नहीं होता कि अपनी राष्ट्रीय आय का 12 प्रतिशत न बचा सके, दरिद्रता ने राष्ट्रों को युद्धों का सूत्रपात करने से अथवा दूसरी तरह अपनी सम्पत्ति लुटाने से कभी नहीं रोका है।” व्याख्या कीजिए।
“No nation is so poor that it could not save 12% of its national income if it wanted to poverty has never prevented nations from launching upon wars or from wasting their substances in other ways,” Discuss.

- 3 प्रदर्शनकारी प्रभाव से आप क्या समझते हैं ? यह अल्पविकसित देशों में पूँजी-निर्माण पर कैसे बुरा प्रभाव डालता है ?
What do you mean by the demonstration effect ? How it affects adversely capital formation in under-developed countries ?
- 4 इस बात की जाँच कैसे की जा सकती है कि प्रस्तावित वृद्धि-दर के लिए आवश्यक धन उपलब्ध है या नहीं ? (1975)
How can one check whether the required funds are available to finance the postulated rate of growth ?
- 5 'राजनीतिक दृष्टि से कर लगाने के स्थान पर मुद्रा-स्फीति आरम्भ करना आसान हो सकता है लेकिन मुद्रा स्फीति का नियन्त्रण करने, उसकी उपादेयता अधिक से अधिक करने और उसकी हानियाँ कम से कम करने के लिए आवश्यक उपाय निर्धारित और लागू करना करो से वृद्धि से अधिक आसान नहीं है।' (लुइस) समझाइए। (1975)
"It may be easier politically to start an inflation than to tax but the measures which control inflation, maximize its usefulness and minimize its advantage are no easier to adopt or administer than would be an increase in taxation" (Lewis)
- 6 "अनेक कारणों से लाभ कई बार किसी प्रयोजना के सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान को मापने का ठीक पैमाना नहीं हो सकता। लेकिन लाभ को इस स्थिति से विस्थापित करना हो तो निर्णय के लिए कोई अन्य आधार उसके स्थान पर स्थापित करना होगा।" (लिटल और मिरलीज)। यह अन्य आधार क्या है ? उसकी मुख्य विशेषताएँ समझाइए। (1975)
"There are many reasons why profits may not be a very good measure of a project's contribution to social ends..... But if profits are to be dethroned some other guide to decision making must be put in their place" (Little Mirrlees) What is other guide ? Explain its salient Features
- 7 लीबेन्स्टीन के 'क्रिटिकल-मिनिमम थिसिस' सिद्धान्त की विवेचना कीजिए। 'प्रबल प्रयास' सिद्धान्त और इस सिद्धान्त में क्या अन्तर है ?
Discuss Liebenstein's "Critical Minimum Thesis" What is the difference between this theory and the 'Big Push' theory ?
- 8 आर्थिक विकास के सिद्धान्त पर हर्षमैन के दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए।
Discuss Hirschman's approach to the theory of development
- 9 'सन्तुलित विकास' पर नर्क्स और लेविस के विचारों के विशेष संदर्भ में प्रकाश डालिए।
Elucidate the concept of 'Balanced Growth' with special reference to Nurkse and Lewis
- 10 आर्थिक विकास के सिद्धान्त पर मिड के दृष्टिकोण की समीक्षा कीजिए।
Examine Mid's approach to the theory of development
- 11 निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए—
(अ) निर्धनता का दुष्चक्र।
(ब) सन्तुलित विकास।
(स) 'मम गृह' बनाम 'पूँजी-गृह' तकनीकें।
(द) भारत में मानवीय शक्ति का नियोजन।
Write notes on the following :—
(a) Vicious Circle of Poverty.
(b) Balanced Growth
(c) Labour-intensive v/s Capital-intensive Techniques
(d) Man Power Planning in India

खण्ड-2. भारत में आर्थिक नियोजन

अध्याय 1 से 7

- 1 स्वतन्त्रता से पूर्व भारत में आर्थिक नियोजन के विचार की मुख्य प्रवृत्तियों का संक्षेप में पुनः-निरीक्षण कीजिए ।
Briefly review the main trends of thought on economic planning in India before Independence
- 2 भारत में आर्थिक नियोजन के विकास को बताइए ।
Trace the evolution of economic planning in India.
- 3 भारत की द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य तथा उपलब्धियों की तुलना कीजिए और उनमें अन्तर कीजिए । (1969)
Compare and contrast the objectives and the achievements of India's Second and Third Five Year Plans
- 4 तृतीय योजनाकाल में भारतीय अर्थ व्यवस्था की धीमी प्रगति के कारणों पर प्रकाश डालिए । (1968)
Account for the slow growth of India's economy during the Third Plan Period
- 5 प्रथम तीन योजनाओं के उद्देश्य, लक्ष्य, वित्तीय स्रोतों और दोषों तथा उपलब्धियों को बताइए ।
Point out the objectives, targets, resources and defects and achievements of the First Three Plans
- 6 भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों और कठिनाइयों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए । (1967, 69)
Examine critically the achievements and difficulties of India's Third Five Year Plan.
- 7 चतुर्थ योजना पिछली योजनाओं से किन अर्थों में भिन्न थी ? इस योजना की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए ।
In what way the Fourth Plan was different from previous plans ? Critically examine the Fourth Plan.
- 8 भारत में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में वित्त साधनों की व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिए । ऐसे कौन से वित्त साधन स्रोत हैं जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है ? (1973)
Make an appraisal of resources mobilisation during the Fourth Five Year Plan in India. What are the main sources of additional development funds which have not been utilised so far ?
- 9 चतुर्थ योजना के उद्देश्य, लक्ष्य एवं वित्तीय साधनों की संक्षेप में आलोचनात्मक विवेचना कीजिए ।
Critically examine the objectives targets and resources of the Fourth Five Year Plan
- 10 तृतीय व चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं में निनियोग के आवंटन पर संक्षेप में मत व्यक्त कीजिए । (1975)
Comment briefly on the allocation of investment funds in the Third and Fourth Five Year Plans

558 भारत में आर्थिक नियोजन

- 11 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य और पूँजी लगाव के ढंग का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
Briefly explain the targets and capital outlay of the Fourth Five Year Plan.
- 12 चार पंचवर्षीय योजनाओं में क्षेत्रीय आवंटन का मिश्रणालोकन कीजिए। इससे आर्थिक विकास के गतिवर्द्धन में किस सीमा तक मदद मिली है ? (1974)
Review the sectoral allocation in the Four Five Year Plans. How far has it been helpful in accelerating the pace of economic development ?
- 13 बचत बढ़ाने के प्रयत्नों में एक बड़ा प्रयत्न सावधानिक बचत की दर बढ़ाने का होना चाहिए (चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन)। इन मत की पुष्टि करने वाले तर्क समझाइए और यह बताइए कि यह कार्यान्वित कहाँ तक सफल रहे हैं। (1975)
"A major thrust of savings efforts must be towards raising the rate of public savings" (Mid-term Appraisal of the Fourth Plan) Explain the arguments which substantiate this view and state how far this strategy has been successful.
- 14 प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं में 'विकास बचन एवं विनियोग-दरें—नियोजित तथा वास्तव में प्राप्त' की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।
Critically examine the growth rates and saving (investment) rates planned and achieved in the first three Five Year Plans.
- 15 प्रथम तीन योजनाओं में वित्तीय आवंटन की परीक्षा कीजिए।
Critically examine the financial allocation in the first three Five Year Plans.
- 16 प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं में क्षेत्रीय लक्ष्यों की विवेचना कीजिए।
Discuss the sectoral targets in the first three Five Year Plans.
- 17 प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए।
Discuss the achievements of the first three plans.
- 18 'निर्धनता पर विशेष अगर ढाल करने में योजना की असफलता का एक कारण अपर्याप्त वृद्धि दर रही है।' (एश्वि दू. काश्यप प्लान) क्या आप सहमत हैं ? याचना की पिछली दो दशकियों के निर्धनता पर पड़े प्रभाव की विवेचना कीजिए और इस मामले में असफलता के कारण बताइए। (1974)
"One reason for the failure of planning to make a major dent on poverty has been the inadequate rate of growth" (Approach to the Fifth Plan) Do you agree ? Discuss the impact that the last two decades of planning has had on the poverty in India and give reasons for our failure on this front.
- 19 भारत में नियोजन आवंटनों पर आलोचनात्मक निबन्ध लिखिए।
Write a critical essay on "Plan allocation in India".
- 20 भारतीय योजनाओं में विनियोग वृद्धि के उपाय बताइए।
Suggest measures to increase investment in Indian plans.
- 21 भारतीय नियोजन के सदर्भ में उत्पादकता सुधार के उपाय बताइए।
Suggest measures to improve productivity with reference to Indian Planning.
- 22 "भारत में गत दो दशकों में आर्थिक नियोजन की उपलब्धियाँ" विषय पर एक आलोचनात्मक निबन्ध लिखिए।
Write a critical essay on "Economic Planning in India during the last two Decades".
- 23 पाँचवी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। क्या आप इस योजना की पूर्ववर्ती योजनाओं की तुलना में अधिक अक्षम और व्यावहारिक समझते हैं ?
Discuss the main features of the Fifth Five Year Plan. Do you regard it more effective and practical in comparison to the previous plans ?

- 24 भारतीय नियोजन जिस रूपरेखा पर आधारित है उसकी व्याख्या कीजिए तथा नियोजनतन्त्र की तकनीक में जो परिवर्तन हुए हैं उनकी व्याख्या कीजिए ।
 Explain the plan frame underlying plans in India and trace the developments in the techniques of plan formulation that have been introduced recently

अध्याय 8

- भारत में योजना निर्माण और क्रियान्वयन के लिए जो प्रशासन-तंत्र है, उसका वर्णन कीजिए ।
 Describe the administrative machinery for plan formulation and implementation in India
- भारतीय नियोजन आयोग को 'सुपर कैबिनेट' कहा गया है । क्या यह आरोपना सही है ? नियोजन आयोग और कैबिनेट के मध्य आदर्श सम्बन्ध क्या होना चाहिए ?
 India's Planning Commission has been described as a Super Cabinet Is this criticism correct ? What would be the ideal relationship between the planning Commission and the Cabinet
- सक्षप म उस तरीक का उल्लेख कीजिए जिसके अनुसार केन्द्र में भारतीय योजना का निर्माण होता है । क्या आप राज्यों के लिए वृद्धि नियोजन-आयोगों की स्थापना का समर्थन करेंगे ?
 Indicate briefly the manner in which the Indian plan at the centre is formulated Would you advocate establishment of separate Planning Commissions for the states
- भारतीय योजना तन्त्र में क्या दोष हैं ? इन दोषों को दूर करने हेतु सुझाव दीजिए ।
 What are the defects of Indian Planning Machinery ? Give suggestions for the removal of these defects
- केंद्रीय तथा प्रादेशिक प्रशासनों के (अ) योजना बनाने तथा (ब) उन्हें कार्यान्वित करने के सापेक्ष कार्य बताइए ।
 वर्तमान व्यवस्था में आप किन सुधारों का सुझाव देंगे ? (1973)
 Discuss the relative roles of the Union and state Government in the formulation and implementation of plans in India What improvements would you suggest in the existing relationship

अध्याय 9 एवं 10

- भारत में गरीबी की समस्या का स्वरूपन कीजिए । (1975)
 Delineate the problem of poverty in India
- भारत में गरीबी एवं असमानता के लिए हरित क्रान्ति के निहितार्थों पर विचार कीजिए । (1975)
 Discuss the implications of "Green Revolution" for poverty and inequality in India
- चौथी योजना में अधिकतम रोजगार-अवसर पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था । इस दिशा में कौन से कदम उठाए गए और उनमें कहीं तक सफलता प्राप्त हुई । (1972)
 The Fourth Plan has laid emphasis on the need for generating more and more employment opportunities What steps have so far been taken and with what success to achieve this orientation ?
- रोजगार के क्षेत्र में पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों का आकलन कीजिए । (1974)
 Assess the achievements of Five Year Plans in respects of employment

- 5 भारत में बेरोजगारी की समस्या की प्रकृति पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। आप रोजगार नीतियों के सन्दर्भ में क्या सुझाव देंगे।

Write a critical essay on the nature of unemployment problem in India
What would you like to suggest regarding the employment policies?

अध्याय 11

- 1 राजस्थान में औद्योगीकरण की प्रगति का वर्णन कीजिए। इसकी गति बढ़ाने के सुझाव दीजिए।

Discuss the progress of industrialisation in Rajasthan Suggest measures for its acceleration

- 2 राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की विवेचना कीजिए। क्या आप राजस्थान के सन्तुलित विकास के लिए उपाय सुझाएंगे ?

Discuss different aspects of Rajasthan's Economy. What measures would you suggest for her balanced development

- 3 राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों की विवेचना करो। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के विकास में इन्होंने क्या योगदान दिया है ? (1973)

Discuss the achievements of Rajasthan's Five Year Plans What has been the contribution of the public sector industries to the development of the state ?

- 4 "राजस्थान की आर्थिक विकास योजनाओं में औद्योगिक विकास की सर्वथा उपेक्षा की गई है।" क्या आप इस आरोप को ठीक मानते हैं ? अपने उत्तर के कारण बताइए। (1972)

"Industrial development has been grossly neglected in the development plans for Rajasthan " Would you agree with this charge ? Give reasons for your answer

- 5 राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाएँ अधिकतर आर्थिक ऊपर की ढाँचा बनाने में लगी रही हैं।" आप इस पर बल देने को कहीं तक उपयुक्त मानते हैं ? (1972)

"Rajasthan's Five Year Plans have been largely concerned with the creation of economic overheads " How far do you think that this emphasis was justified

- 6 राजस्थान में योजना की दो दशकियों की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। (1974)

Discuss the achievements of the two decades of planning in Rajasthan

- 7 राजस्थान की तृतीय एवं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताओं का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (1974)

Give a critical appraisal of the priorities in Rajasthan's Third and Fourth Five Year Plans

- 8 राजस्थान की तीसरी व चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के क्षेत्रीय आवंटन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (1975)

Critically evaluate the sectoral allocation in the Third and Fourth Five Year Plans of Rajasthan.

- 9 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान राजस्थान में कृषि सुधार के प्रयत्नों का वर्णन कीजिए। (1975)

Describe the efforts for agricultural improvement made in Rajasthan during the Five Year Plans

ग्रन्थ-कोश
(BOOK BANK)

खण्ड-1

1. *Agrawala & Singh (Eds)* : Economics of Under-development
2. *Adelman* : Theories of Economic Growth and Development.
3. *Bright Singh, D.* : Economics of Development
4. *Bauer, P. T. and Yamey, B. S.* : The Economics of Under-Developed Countries.
5. *Baljeet Singh and V.B. Singh* : Social and Economic Change.
6. *Bonne, Alfred* : Studies in Economic Development.
7. *Baran, Paul* : The Political Economy of Growth.
8. *Baumol* : Economic Dynamics.
9. *Chakrawarti, S* : Logic of Investment Planning
10. *Coale and Hoover* : Population and Economic Development in Low Income Countries.
11. *Domar, Evsey* : Essays in the Theory of Economic Growth
12. *Das, Nabagopal* : The Public Sector in India
13. *Durbin, E. F. M* : Problems of Economic Planning
14. *Edward, F Denison* : Sources of Post War Growth in Nine Western Countries
15. **Five Year Plans.**
16. **Five Year Plans of Rajasthan**
17. *Gupta, K. R.* : Economics of Development.
18. *Ghosh, Alak* : New Horizons in Planning.
19. *Higgins, B* : Economic Development.
20. *Hirschman, A. O* : The Strategy of Economic Development,
21. *Harrod, R F* : Towards Dynamic Economics.
22. *Hoselutz, B F* : Theories of Stages of Economic Growth.
23. *Hoselitz, Beri, F* : Sociological Aspect of Economic Growth.
24. *Hanson, A. H* : Public Enterprise and Economic Development
25. *Heyek, F. A.* : Collectivist Economic Planning.
26. *Hussian, I Z* : Economic Factors in Economic Growth.
27. *Henderson, P. D* : Investment Criteria for Public Enterprises in Public Enterprises edited by R Turvey.

- | | | |
|----|-----------------------------------|---|
| 28 | <i>Jacob Viner</i> | Economics of Development |
| 29 | <i>Kaldor, N</i> | Essays of Economic Stability and Growth |
| 30 | <i>Kalecki</i> | Theory of Economic Dynamics |
| 31 | <i>Kindleberger, C P</i> | Economic Development |
| 32 | <i>Leibenstein, Harvey</i> | Economic Backwardness and Economic Growth |
| 33 | <i>Lewis W A</i> | • The Theory of Economic Growth. |
| 34 | <i>Lewis W A</i> | Development Planning |
| 35 | <i>Lester, W A</i> | The Theory of Economic Growth, |
| 36 | <i>Little and Mirrless</i> | Social Cost-Benefit Analysis |
| 37 | <i>Mishan, E J</i> | Cost Benefit Analysis |
| 38 | <i>Meter G M and Baldwin, R E</i> | Economic Development |
| 39 | <i>Meyr G</i> | Leading Issues in Development Economics |
| 40 | <i>Myrdal Gunnar</i> | Economic Theory and Under-developed Regions |
| 41 | <i>Mehta, J K</i> | Economics of Growth |
| 42 | <i>Meade, J E A</i> | : A Neo classical Theory of Economic Growth |
| 43 | <i>Marx Black (Ed)</i> | The Social Theories of Talcott Parsons |
| 44 | <i>Nag D S</i> | Problems of Under developed Economy |
| 45 | <i>Nurkse, Ragnar</i> | Some Problems of Capital Formation in Under developed Countries |
| 46 | <i>Ncaer's Paper</i> | Price Policy and Economic Growth |
| 47 | Publication U N | Measures for the Economic Development of Under developed Country |
| 48 | Publication U N | Development Decade |
| 49 | Publication, U N | Determinants and Consequences of Population Trends |
| 50 | <i>Rostow, W W</i> | The Process of Economic Growth |
| 51 | <i>Robinson</i> | : (i) Exercises in Economic Analysis
(ii) The Accumulation of Capital
(iii) An Essay on Marxian Economics |
| 52 | <i>Reddaway</i> | The Development of the Indian Economy |
| 53 | <i>Singh V B</i> | Theories of Economic Development |
| 54 | <i>Stanely, Bober</i> | The Economics of Cycles and Growth |
| 55 | <i>Simon Kuznets</i> | Economic Growth and Income Inequality |
| 56 | <i>Steiner G A</i> | • Government's Role in Economic Life |
| 57 | <i>Seth, M L</i> | Theory and Practice of Economic Planning |
| 58 | <i>Sen, A K</i> | The Choice of Techniques |
| 59 | <i>Singh, V B.</i> | Essays in Indian Political Economy |
| 60 | <i>Simon Kuznets</i> | Six Lectures on Economic Growth |

61. *Simon Kuznets* : Modern Economic Growth.
62. *Tinbergen J.* : The Design of Development.
63. *Ursulla Kickt* : Learning about Economic Development.
64. U. N. Statistical Year Book.
65. U N Economic Survey of Asia and Far East.
66. *V K R V Rao* : Essays in Economic Development.
67. World Economic Survey
68. *Williamson, H F and Buttrick J A* : Economic Development-Principles & Patterns
69. वार्षिक समीक्षा, 1975-76.
70. योजना
71. भारत 1975,76 (Eng)

खण्ड-2

1. *Bhagwati, Jagdish & Desai Padma* : Indian Planning for Industrialisation.
2. *Bhattacharya K. N.* : Indian Plans
3. *Bhattacharya, K N* : India's Fourth Plan, Test in Growthmanship.
4. *Brij Kishore and Singh, B P* : Indian Economy through the Plans
5. *Chatterji, Amiya* : The Central Financing of State Plans in the Indian Federation
6. *Gadgil D R.* : Planning and Economic Policy in India.
7. Indian Planning Commission : Basis Statistics Relating to Indian Economy 1950-51 to 1968-69.
8. Indian Planning Commission : Five Year Plans
9. Indian Planning Commission : Fourth Plan : Mid-term Appraisal.
10. Indian Planning Commission : Draft Fifth Five Year Plan, 1974-79.
11. *Iyengar, S K* : Fifteen Years of Democratic Planning
12. India 1974, 1975, 1976
13. *Mehta, Asoka* : Economic Planning in India.
14. *Maleubaulm* : The Crisis of Indian Planning.
15. *Paranjape, H K.* : Re-organised Planning Commission.
16. Planning Depts Govt. : Five Year Plans (Rajasthan) of Rajasthan
17. Planning Depts Govt. : Draft—Fifth Five Year Plan, 1974-79, of Rajasthan

- 18 *Venkatasubbiah* *Author of Indian Planning*
Hiranyappa
 - 19 *The Economic Times*
 - 20 योजना
 - 21 राजस्थान विवरण
 - 22 हि दुस्तान
 - 23 साप्ताहिक हि दुस्तान
 - 24 राजस्थान का व्यपक अध्ययन, 1970-77
 - 25 भारत सरकार योजना मन्त्रालय रिपोर्ट 1975 76
-